





○  
一  
二  
三  
四  
五

100







COMPILED



077705

077705

Stock Verification-2024

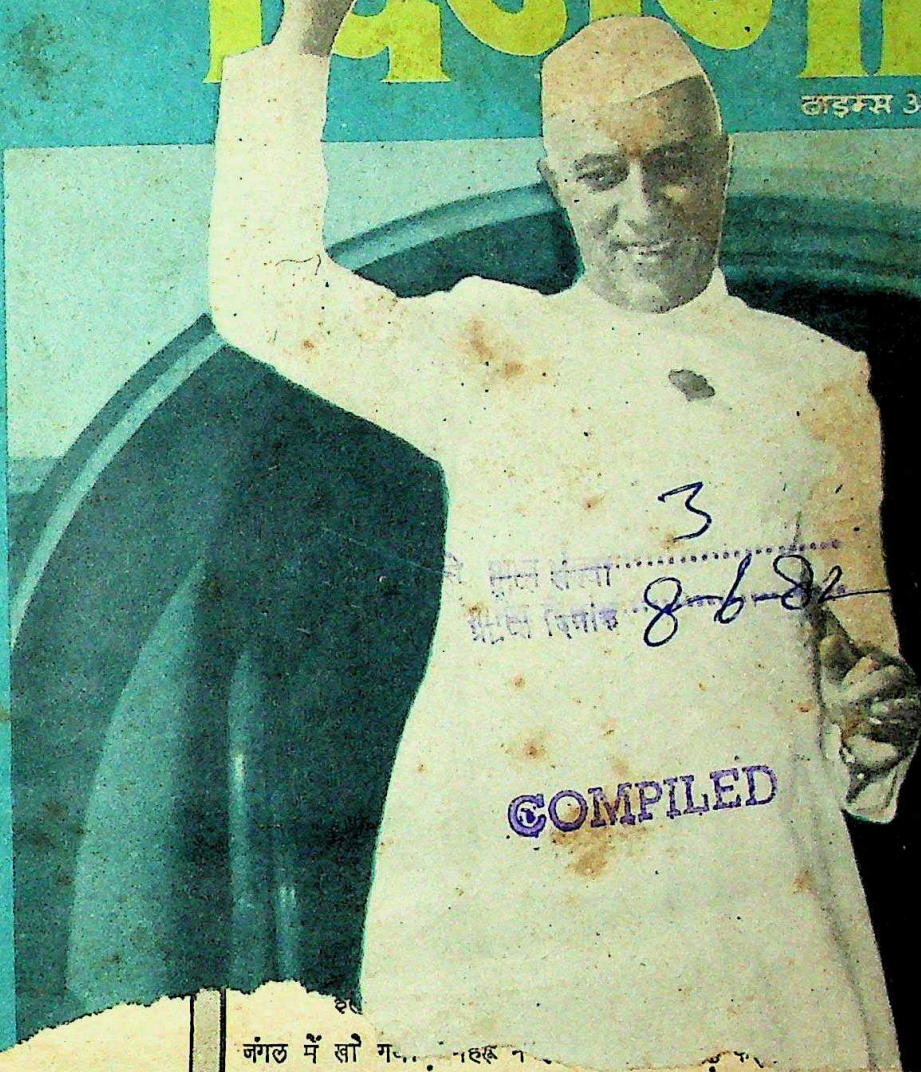






# दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन



COMPILED

हनुके  
खोजे  
हुए  
भा

जंगल में लौ गये... इतिहास से आखिरी मूँद कर भारत को खोजना और बनाना चाहते हैं।

इस बार नेहरू की स्मृति में 'दिनमान' ने नेहरू के खोजे हुए भारत की खोज को वैचारिक धरातल पर जांचने-परखने के लिए तीन विभिन्न धाराओं के प्रतिनिधि लेखकों को आमंत्रित किया। एक का कहना है कि नेहरू ने भारत की खोज शेक्सपियर के हैमलेट की तरह दृष्टि में की, दूसरे का कहना है नेहरू के सामने विकल्प था कि वे आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विवेक को गांधी जी की मान्यताओं के साथ जोड़ते और तीसरे का कहना है कि नेहरू को कल तक उपेक्षा की निगाह से देखने वाले आज नेहरू की दुहाई-सिर्फ हंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए दे रहे हैं। ये और ऐसे ही कुछ और अत्यंत बहसतलज मुद्दे इस अंक में पाठकों के सामने हैं। पाठकों की प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।

म. सुधाकर

जो रोड,  
कार्यालय :  
मन रोड, अहमदाबाद-9  
दूरभाष : 77631  
कलकत्ता कार्यालय :  
105/7 ए, एस. एन. बनर्जी रोड,  
कलकत्ता-700014  
दूरभाष : 244243  
मद्रास कार्यालय :  
63, मोंटियस रोड, एमबोर,  
मद्रास-8 दूरभाष : 83661  
पुणे कार्यालय :  
407-1, तीरथमवन, क्वार्टर रोड,  
पुणे-411002  
दूरभाष : 25447  
लंदन कार्यालय :  
26, स्टेशन एप्रोच, सडबरी  
वेबले, मिडिलसेक्स, लंदन, यू.के.  
लंदन दूरभाष : 01-903-9696





संपा  
कन्है

राहाय

जिते

मुख्य

संवर्ध

संपादक

श्याम

जवाह

श्वल

त्रिलो

महेश

प्रयाग

वनव

विनो

सुषम

विशेष

रामस

सज्जा

रवि

●

संपादक

10

1100

दूरभाष

व्यवस्था

7, बह

नयी

दूरभाष

वंबई

डा. व

वंबई-4

दूरभाष

अहमदा

139,

दूरभाष

कलकत्ता

105/

कलकत्ता

दूरभाष

मद्रास

63, मो

मद्रास-

पुणे का

407-1

पुणे-41

दूरभाष

लंदन

26, स्

बंबले,

लंदन



# दिनमान

भाग 18. 6-12 जून, 1982  
अंक 21. 16-22 ज्येष्ठ, 1904

संपादक

कन्हैयालाल नंदन

सहायक संपादक

जितेंद्र गुप्त

मुख्य उपसंपादक

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

संपादकीय सहकर्मी

श्यामलाल शर्मा

जवाहरलाल कौल

शुक्ला रुद्र

त्रिलोक दीप

महेश्वरदयालु गंगवार

प्रयाग शुक्ल

बनचारी

विनोद भारद्वाज

सुषमा पाराशर

हिरोन संवाददाता

रामसेवक श्रीवास्तव

सज्जा

रवि शर्मा

संपादकीय कार्यालय :

10 दरियागंज, नयी दिल्ली-

110002

दूरभाष : 271911

व्यवस्था, विज्ञापन तथा प्रसार :

7, बहादुरशाह जफर मार्ग,

नयी दिल्ली-110002

दूरभाष : 270161

बंबई कार्यालय :

डा. वादाभाई नोरोजी रोड,

बंबई-400001

दूरभाष : 268271

अहमदाबाद कार्यालय :

139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9

दूरभाष : 77631

कलकत्ता कार्यालय :

105/7 ए, एस. एन. बनर्जी रोड,

कलकत्ता-700014

दूरभाष : 244243

मद्रास कार्यालय :

63, मोटियस रोड, एम्वोर,

मद्रास-8 दूरभाष : 83661

पुणे कार्यालय :

407-1, तौरपसवन, क्वार्टर गेट,

पुणे-411002

दूरभाष : 25447

लंदन कार्यालय :

26, स्टेशन एप्रोच, सडबरी

बंबले, मिडिलसेक्स, लंदन, यू.के.

लंदन दूरभाष : 01-903-9696

संपादक की ओर से

नेहरू के निधन दिवस (२७ मई) पर नेहरू की समाधि 'शांतिन' में पुष्पांजलि अर्पित करने की खानापुरी के समाचार अखबारों में आ गये और नेहरू

भारत के निर्माण में नेहरू की

H.L. उनके कुछ शब्द भी

DIYMAN COMPILED

1982

G. K. V.

Lib

HARDWARE

एक समय होता

है, अगर आप

हैं, और मुझे

काम को जीवन

और उस बात के

सामने विनम्रता

कि आजादी के

हमेशा भविष्य

का रंग गहरा

रखने के लिए नेहरू ने उन संस्थाओं की बुनियाद रखी जो भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार बन सकें। लेकिन बुनियाद रखने के बाद उन संस्थाओं की सतत जागरूक देखरेख की बुनियाद भी रखी जानी चाहिए थी। नेहरू की ७२वीं वषगांठ पर प्रख्यात पत्रकार गिरिलाल जैन की पंक्तियाँ थीं : 'हम लापरवाह रहे, घटनाओं के दबाव भले जिम्मेदार रहे लेकिन उन संस्थाओं के कारण को देखकर भी आँखें मूंद लेने की जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। इस खतरे की उपेक्षा उस खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है।'

इसी लापरवाही में हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तात्कालिक प्रलोभनों के जंगल में खो गया। नेहरू ने इतिहास को पढ़ कर 'भारत की खोज' की थी, हम इतिहास से आँखें मूंद कर भारत को खोजना और बनाना चाहते हैं।

इस बार नेहरू की स्मृति में 'दिनमान' ने नेहरू के खोजे हुए भारत की खोज को वैचारिक घराऊ पर जांचने-परखने के लिए तीन विभिन्न धाराओं के प्रतिनिधि लेखकों को आमंत्रित किया। एक का कहना है कि नेहरू ने भारत की खोज शेक्सपियर के हैमलेट की तरह दुश्चित्तों में की, दूसरे का कहना है नेहरू के सामने विकल्प था कि वे आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विवेक को गांधी जी की मान्यताओं के साथ जोड़ते और तीसरे का कहना है कि नेहरू को कल तक उपेक्षा की निगाह से देखने वाले आज नेहरू की दुहाई-सिर्फ इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए दे रहे हैं। ये और ऐसे ही कुछ और अत्यंत बहसखल मुद्दे इस अंक में पाठकों के सामने हैं। पाठकों की प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।

on 27/10/2008



## इस सप्ताह



15

27 मई को नेहरू के निधन दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलियां जलूर अर्पित की गयीं लेकिन यह सवाल भी कुछ बुद्धिजीवियों ने उठाया कि नेहरू ने जिस भारत की खोज अपनी 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में की थी, वह है कहाँ? डा. लक्ष्मीनारायण लाल कहते हैं कि "नेहरू ने जिस भारत को खोजा है उस से नेहरू के व्यक्तित्व का दुर्चित्तापन प्रकट होता है. ऐसा लगता है हैमलेट की भांति नेहरू विशाल जनसमूह के सामने स्वगत भाषण करने लगते हैं."

जपा सोसल सुरेंद्र मोहन मानते हैं: "उन्होंने प. यूरोप और बाद में सोवियत रूस के औद्योगीकरण को आदर्श स्वरूप समझने की गलती की."

लेकिन इंदिरा कांग्रेस के प्रचार नियामक श्रीकांत वर्मा कहते हैं: "यह इंदिरा विरोधी क्लब की साजिश है."

4

मत सम्मत

5-6

पिछले सप्ताह

7

थैंक्यू अमेरिका (पत्रकार संसद)

8

क्या विधायकों की बिक्री बंद होगी (प्रतिपक्ष)

11

दिल्ली के रंग

12

गंगा में रोज रोज घुलता हुआ जहर (विज्ञान)

13

गंदगी, शोर और पाखंड (चरचे और चरखे)

14

न्यायालयों में हिंदी पर न्यायविदों का मत (कानून)

15

नेहरू के खोजे हुए भारत की खोज, यह इंदिरा विरोधी क्लब की साजिश है. (आवरण कथा)

19

मुझे तकल्लुफ के टूटने का इंतजार है (आमने सामने)

22

जहरत है कि राष्ट्रपति के अधिनियम परिभाषित किये जायें (समय चक्र)

24

तारा क्यों मारी गयी (वन्य जीवन)

25

उम्र की धांधली बहुत महंगी पड़ रही है. (युवा कांग्रेस)

26-27

चित्रों के आइने में

29

राज्यमंत्रिमंडलों का गठन, मध्यप्रदेश: जबलपुर; पंजाब: फिर आतंक के साथे में

34

नेपाल: दमन के विरोध में नयी पार्टी और अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष से बातचीत; सोवियत संघ; द. अफ्रीका; फाकलैंड

39

दुनिया भर की

40

रमा जैन ब्रिज और एशियाड संयोजन समिति के महासचिव एस. एस. गिल से बातचीत (खेल और खिलाड़ी)

42

समकालीन समस्याओं से जूझने की गवाही (साहित्य)

43

कथा नौटंकी की और एक नौटंकी कलाकार को (रंगमंच)

44

पुरातात्विक निधियों की चोरी; सूजा के साथ एक शाम (कला)

46

दूरदर्शन

47

अमिताभ बच्चन एंग्री यंगमैन नहीं है (फिल्म)

48

संस्कृति समाचार

49

चरित चर्चा

50

मिस्टर फाकलैंड की तलाश (इति श्री)

## सवाल शल्लिसयत का नहीं, सोच का है

16-22 मई: तीन अलग अलग शीर्षकों के तहत एक ही कहानी में परस्पर विरोधी स्थितियों का जिक्र किया गया है. देश के युवा वर्ग और मानसिकता पर जो बयान छपे हैं वे देखने में छोटे और सहूलियत के लिए अखबारी (अल्पकालीन) भले ही दिखाई पड़ें लेकिन वे एक दस्तावेज हो सकते हैं. एक युवा नेता से हुई बातचीत का गैरअखबारी बयान छपा गया है: वह भी बगैर नाम के. इस साक्षात्कार के लिए दिनमान को बधाई. लेकिन कम से कम नाम और दल का हवाला दे देना चाहिए था. सत्ता दल का एक जिम्मेदार व्यक्ति कितना सटीक और सच बोल सकता है और बोलता है, इसी साक्षात्कार से अनुमान लगाया जा सकता है. लेकिन उसकी आवाज जब सार्वजनिक रूप से प्रगट होती है तो कितनी दोगली और सड़ांध से भरपूर होती है.

सत्ता दल के जिम्मेदार (?) युवा नेता संजय सिंह, जिन्हें यह मालूम था कि उनका बयान सार्वजनिक रूप से छपने वाला है और उनके नाम से जाने वाला है, का साक्षात्कार पढ़ कर गुस्सा नहीं आया (बेरीढ़ के लोगों पर तरस आता है). अखबारों में छपने वाले बयानों के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा परिहास था. आत्मप्रचारक मिलोना जिलास के बाद तीसरी दुनिया का यह पहला नाम है जो अपने कर्मों (?) के चलते उत्तर-प्रदेश के चुनाव क्षेत्र गढ़वाल को स्वर्ण बनाने की घोषणा करता है. व्यक्तिगत रूप से संजय सिंह को जानता हूँ, लिहाजा उनके व्यक्तिगत चलन पर चरचा चलाना बेमानी होगा. लेकिन उनके द्वारा राजनीति में जोड़े गये नये शब्द 'स्वर्ण' पर जरूर कुछ बोलना चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि इस सवाल को मात्र चुनाव तक ही न सीमित किया जाये, अपितु इस पर बहस उठायी जाये. जिस स्वर्ण से चल कर स्वर्ण निवासी संजय सिंह गढ़वाल तक पहुँचे हैं एक लंबे अरसे तक उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है और मैंने उस स्वर्ण अमेठी को अंदर तक झाँक कर देखा है. यदि उसी स्वर्ण की तरह गढ़वाल को बनाना ही संजयसिंह का सपना है तो एक संभ्रांत नागरिक के नाते मैं गढ़वालवासियों से निवेदन करूँगा कि आप इसे गढ़वाल ही रहने दें, 'स्वर्ण' न बनायें, क्योंकि इनके अपने स्वर्ण को मैंने देखा है, जहाँ 6375 हेक्टेयर जमीन पर मात्र 6 नलकूप पानी गिराते हैं. (सरकारी आँकड़ों के मुताबिक कुल ग्यारह नलकूप हैं जिन में से 5 खड़ चुके हैं—पानी नहीं देते) आजादी के चौथे दशक में पहुँचने तक इस स्वर्ण की कुल एक तिहाई ही जमीन सिंचित है बाकी या तो ऊसर है या फिर बंजर. पूरी आबादी

के तीन स्वर्ण से उ याना, दि तरह बिक (अमेठी थ की रफट थानेदार 'लड़की स्वर्ण के स्वर्ण के सरकार फीसदी ल जीते हैं. मैंने अपनी खाते हुए सपना ज ताँलियाँ माँगा जा पत्रिका, रही है, मैं सकती. इ राजनीति है जब तव बनाने वा में होंगे अ जाति कर संजय की मैं नहीं ज को बचना



हम खुश नेतृत्व क

दिनमान



21-27 मई, 1982

देश

- 21 मई : प. बंगाल में माकपा को पूर्ण बहुमत. भारत गंगाजल मुद्दे पर बंगला देश से बातचीत को उत्सुक. फिली-स्तीनी नेता यासिर अराफत द्वारा प्रधानमंत्री को प. एशिया की स्थिति की जानकारी.
- 22 मई : गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से हेमवती नंदन बहुगुणा विजयी. हरयाणा के राज्यपाल जी. डी. तपासे द्वारा लोकदल विधायक दल के नेता देवीलाल से अपने समर्थक प्रस्तुत करने का आदेश.
- 23 मई : भजनलाल द्वारा हरयाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण. वड़ौदा जल संयंत्र अनिश्चित काल के लिए बंद. गोदावरी नदी में नाव उलट जाने से 27 की मृत्यु. गुजरात 'वस रोको' आंदोलन में 30000 भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार.
- 24 मई : इका विधायक दल के नेता रामलाल द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण. हरयाणा में देवीलाल द्वारा अपने समर्थन में 45 विधायक प्रस्तुत. विरोधी दलों द्वारा राष्ट्रपति से हरयाणा के राज्यपाल तपासे और मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाये जाने की मांग.
- 25 मई : नयी दिल्ली के पालिका बाजार में मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा रखे टाइम बम प्राप्त. हरयाणा के मामले पर स्पष्टीकरण के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति से मेट. नयी दिल्ली हरयाणा भवन में इका और लोकदल नेताओं में सत्ता को ले कर संघर्ष.
- 26 मई : प. बंगाल में ज्योतिबसु द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण. राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के आग्रह पर हरयाणा विधानसभा सत्र शीघ्र. नयी दिल्ली के ओडियन सिनेमा में बम की आशंका से भगदड़. कोयले के दामों में भारी वृद्धि.
- 27 मई : हरयाणा में 8 निर्दलीय विधायक इका मंत्रिमंडल में शामिल. राजधानी में दो अन्य जगहों पर बम पाये गये. कर्नाटक में जपा द्वारा सीमेर घाटाले में मुख्यमंत्री गृधराय पर मुकदमा.

च का है

शीर्षकों के विरोधी श के युवा छपे हैं वे अखबारी लेकिन वे नेता से हुई ग गया है. र के लिए कम नाम था. सत्ता ना सटीक है, इसी सकता है. नक रूप से सड़ांध से

युवा नेता क उनका ग है और शाखाकार लोगों पर अपने वाले का सबसे मिलोना यह पहला पते उत्तर-बनाने की

संजय सिंह गत चलन केन उनके 'स्वर्ग' पर भी चाहता तक ही न इस उठायी निवासी लबे अरसे मिली है तक झांक ह गढ़वाल तो एक वासियों से ही रहने अपने स्वर्ग पर जमीन (सरकारी) बलकूप है, नहीं देते) इस स्वर्ग चित हैं; य आबादी

जून '82

के तीन फीसदी लोग शिक्षित हैं. इसी स्वर्ग से आया हुआ आदमी पटियाला, लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, बंबई में जानवरों की तरह विकता है और खटता है. इसी स्वर्ग (अमेठी थाने) में लड़की के लिए पड़ी डकैतियों की रफ्त आज भी उसी तरह पड़ी है जिस के थानेदार ने मुझसे एक पते की बात कह कर 'लड़की खुद बदचलन थी' चाहता था कि इस स्वर्ग के कानून को ज्यों का त्यों रहने दूँ. इस स्वर्ग के बारे में विश्वनाथप्रताप सिंह की सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र के सत्तर फीसदी लोग गरीबी की सीमारेखा के नीचे जीते हैं. इसी स्वर्ग में आज कुछ जातियों को मैंने अपनी आँख से गोबर से दाना निकाल कर खाते हुए देखा है. विकास और स्वर्ग बनाने का सपना जबानी तौर पर जनता के बीच दे कर तालियाँ बजवायी जा सकती हैं, या फिर वोट मांगा जा सकता है, लेकिन एक राजनैतिक पत्रिका, जिसकी अपनी एक अलग की पहचान रही है, में तस्वीर छपवा कर बेमानी नहीं की जा सकती. इस चिट्ठी को लिखने के पीछे चुनावी राजनीति का कोई मसला नहीं है. हमें मालूम है जब तक यह चिट्ठी छपेगी स्वर्ग और असम बनाने वाले लोग दिल्ली के वातानुकूलित कमरे में होंगे और जनता अपनी उँगली का इस्तेमाल कर चुकी होगी. दिनमान के मुखपृष्ठ पर संजय की तस्वीर छापने के पीछे क्या तर्क था, मैं नहीं जानता. इतने बड़े जोखिम से दिनमान को बचना चाहिए; विशेष रूप से दिनमान की

प्राप फरमाते हैं

व्यंग्य चित्र : लक्ष्मण



हम खुशकिस्मत हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हमारी पार्टी में एक फिल्मी हीरो है.

दिनमान

अपनी एक गंभीरता है, वह किसी फूहड़ मजाक से ठुकने न पावे. साक्षात्कार के बाकी हिस्से पर कोई टिप्पणी करने के लिए मेरे पास फिलहाल कोई संसदीय शब्द नहीं है. इतना और इस विषय पर लिखे जाने पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है. जनेवि की रफ्त सटीक है.—चंचल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्रसभा, 15 विंडसर प्लेस, नयी दिल्ली.

संजय सिंह से विशेष भेंटवार्ता पढ़ने को मिली. 8 मई से 14 मई तक के अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान मैंने स्वयं कोटद्वार, लैंसडाउन, कांसखेत, पौड़ी, पावो, थौलीसेण एवं अन्य कई स्थानों का भ्रमण किया. वहाँ की जो वास्तविक स्थिति मैंने देखी उसके बारे में मैं जनसाधारण को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे संजय सिंह के आरोपों की सत्यता का पता चल सके. संजय सिंह कहते हैं कि हम गढ़वाल को स्वर्ग बनाना चाहते हैं. क्या गढ़वाल को स्वर्ग बनाने की याद उन्हें इन्हीं चुनावों में आयी है? श्री बहुगुणा पर जो यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गढ़वाल में बाहरी लोगों को एकत्रित किया है वह सरासर झूठ है. क्या संजय सिंह इस बात का जवाब दे सकते हैं कि गढ़वाल के सभी डाक बंगलों, स्कूलों, कॉलेजों एवं होटलों पर मैदान से आये हुए युवा कांग्रेसियों का कब्जा नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति हथियारों से लैस नहीं है?

संजय सिंह कहते हैं बहुगुणा गढ़वाल को असम बनाना चाहते हैं. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनके कार्यकर्ता राजपूत बनाम ब्राह्मण, पहाड़ी बनाम गैरपहाड़ी जैसे प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या इसी प्रकार के कुप्रचार से गढ़वाल को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? संजय सिंह कहते हैं कि पहाड़ों के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट दिया गया है. केवल बजट देने से ही पहाड़ का विकास नहीं हो सकता. अमेठी के राजकुमार पहाड़ की वास्तविक समस्याओं को समझें : केवल डाक बंगलों और होटलों में ठहरने से गढ़वाल को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता.—राजकुमार इस्टवाला, म. न. एच. 665 गांधीनगर, जयपुर.

## भूल सुधार

16-22 मई : दिनमान का यह अंक केवल एक त्रुटि को छोड़ कर अत्यंत रोचक था. हिमाचलप्रदेश की राजनीति पर 'साधनों और उपलब्धियों का संघर्ष' के अंतर्गत दिया गया वर्तमान मुख्यमंत्री का चित्र उन का अपना (रामलाल का) नहीं लगता.—वीरसिंह, शिमला.

(भूल के लिए हमें खेद है.—सं.)



21-27 मई, 1982

विदेश

- 21 मई : ब्रिटेन-फाकलैंड के बीच भीषण युद्ध. ब्रिटेन अब भी आर्जेंटीना से वार्ता को तैयार. चीन द्वारा रूस पर भारत-चीन के बीच सुघरते संबंधों को बिगाड़ने का आरोप. भारत से सेशेल्स को अधिक सहायता देने को तैयार. अमेरिकी तेल कंपनियों द्वारा तेल कीमत में वृद्धि.
- 22 मई : ढाका में विदेशमंत्री पी. वी. नरसिंह राव की बंगलादेश के मार्शल-ला प्रशासक ले. जनरल एच. एम. इरशाद से मेंट. ग्वातेमाला में दमनात्मक कार्रवाई जारी. भारत और साऊदी अरब के बीच दीर्घकालीन तेल समझौता. अमेरिका पर पोलैंड के मामलों में दखलंदाजी का आरोप.
- 23 मई : पाक राष्ट्रपति जनरल जिया द्वारा अमेरिकी यात्रा का निमंत्रण स्वीकार. भारत और बंगलादेश द्वारा आर्थिक तकनीकी सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के गठन का निश्चय. इराक द्वारा ईरान के खुर्रम-शहर में प्रवेश करने की कोशिश नाकाम.
- 24 मई : बेरूत में कार विस्फोट से 14 मरे. अमेरिका द्वारा द. अफ्रीका को परमाणु सामग्री बेचना जारी रखने का निर्णय. टोक्यो में 3 लाख 70 हजार नागरिकों द्वारा परमाणु अस्त्रों के विरोध में प्रदर्शन. इस्राइली प्रधानमंत्री बेगिन द्वारा अमेरिका से जोर्डन को अस्त्र न बेचने की अपील.
- 25 मई : इस्राइली विमानों द्वारा दो सीरियाई मिग विमान ध्वस्त. ब्रिटेन द्वारा बिना शर्त युद्ध विराम से इंकार. अमेरिका में शुक्राणु बैंक के सहयोग से प्रथम बच्चे का जन्म. अमेरिका सोवियत संघ से वार्ता को तैयार.
- 26 मई : पाकिस्तान में 24 विपक्षी दलों के नेता गिरफ्तार. भारत, इथियोपिया द्वारा हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के पक्षों के मुझाबों का विरोध. अमेरिका द्वारा फाकलैंड के मामले में वृद्धि की संभावना. भारत द्वारा फाकलैंड मुद्दे पर स. रा. सु. प. में शांति वार्ता का सुझाव.
- 27 मई : बहरीन और अमन द्वारा ईरान-इराक से युद्धबंदी का अनुरोध. फाकलैंड युद्ध में ब्रिटेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई. विट्सी फेदोशुक के जी. वी. के नये प्रमुख.

क्या मुस्लिम स्त्री श्रबला है ?

9-15 मई : "मुस्लिम स्त्री के हक कुरान में बंद हैं" शीर्षक से लिखित लेख में मुस्लिम स्त्रियों की जिस दुखद स्थिति का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है निश्चय ही वह भारतीय संविधान की भावनाओं के विरुद्ध तथा देश के समतावादी आदर्श के प्रतिकूल है. आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस समय भारत समेत दुनिया के अनेक देशों, विशेषतः मुस्लिम देशों में जिस प्रकार मुस्लिम नारियों को पर्दे तथा बुर्के में बापस जाने के लिए विवश किया जा रहा है तथा उन्हें वैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक उपलब्धियों से वंचित रखा जा रहा है वह चिंता तथा खेद का विषय है. पता नहीं संयुक्तराष्ट्र ऐसा विश्वसंगठन इस पर क्यों मौन है? जहाँ तक भारत का संबंध है आज आवश्यकता है कि जिस संविधान के अंतर्गत भारत के अल्प-संख्यक मुसलमान भारत के हिंदुओं के बराबर समी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हुए. उसी के अनुरूप मुस्लिम नारियों को मुस्लिम पुरुषों की भांति समी अधिकार प्रदान किये जायें. शकुनचंद गुप्त विशारद, विशारद मेडिकल स्टोर्स, पोस्ट लालगंज, जिला राय बरेली.

अपने शोध द्वारा श्रीमती कृष्णा राजवाड़े इस नतीजे पर पहुँची कि भारत में किसी भी तबके की स्त्री दुर्बलता में शायद ही मुस्लिम औरत के सामने खड़ी हो सके. परंतु इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिस में औरत को इतने हक दिये गये हैं, जैसे मुस्लिम स्त्री अपने बाप की जायदाद में भी हिस्सेदार होती है, जिसे तिरका बोलते हैं. अगर मियाँ बीवी में कोई ऐसी बात हो जिससे कि उसे बीवी के हक छिनते हों तो उस को हक है कि वह अदालत के जरिये माँग कर सकती है. पति की संपत्ति पर उस का भी पूरा हक होता है. तलाक और सौत की दो तलवारों के बारे में यह कहना है कि मियाँ बीवी में तलाक तब ही होता है जब स्थिति बहुत ही नाजुक हो. तलाक से पहले तक वे सुलह कर सकते हैं. तलाक पति किसी मजबूरी में देता है और अगर वह बिना किसी कारण के तलाक देता है तो इस्लाम में दूसरी शादी का भी हक है स्त्री को. अगर पति इस काबिल हो कि वह दोनों पत्नियों के साथ एक सा व्यवहार करे तभी सौत आ सकती है, वरना नहीं. जहाँ तक अपने पैरों पर खड़े होने की बात है मैं समझ नहीं पाया कि पैरों पर खड़ी होने से शोधकर्ता का क्या आशय है.

उत्तरप्रदेश में उर्दू

उ. प्र. सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श एवं द्वितीय राजभाषा विरोधी आंदोलन को नयी दिशा देने के लिए आगामी 23 मई को लखनऊ में विधानसभा मार्ग स्थित सहकारिता भवन में प्रदेश के बहिष्शील नागरिकों का एक सम्मेलन हुआ, जिस में सभी जिलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महादेवी वर्मा, पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी, ठाकुर जयदेव सिंह, डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल, डॉ. विद्यानिवास मिश्र आदि साहित्य कमियों एवं महंत अवैद्यनाथ, डॉ. कृष्णापति त्रिपाठी जैसे अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया.

राज्यपाल द्वारा जारी इस अध्यादेश के संदर्भ में संघर्ष समिति की यह मान्यता है कि राज्यपाल ने विवेकहीन एवं असंवैधानिक ढंग से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. प्रश्न यह है कि 5 अप्रैल तक चलने वाली विधानसभा में अपने वादे के अनुसार सरकार उर्दू संबंधी विधेयक लाने में असमर्थ रही तो दो दिनों में वह कौन-सी परिस्थिति पैदा हो गयी थी जिस के कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा, जब कि विधानसभा का सत्र समाप्त होने की घोषणा राज्यपाल ने बाद में की और अध्यादेश का क्रियान्वयन भी बाद में किया गया. क्यों कि राज्यपाल ने यह अध्यादेश जारी कर अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है अतः उक्त अध्यादेश को न्यायालय के माध्यम से चुनौती दिये जाने की तैयारी की जा रही है.

1951 के राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर एक तरह से सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाये जाने का ही प्रयास किया है. संघर्ष समिति का यह स्पष्ट मत है कि जहाँ एक तरफ सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वालों के दबाव में, जिन का संबंध तेल के देशों से है, जो पेट्रोलॉल के सहारे राजनीति करते हैं, उर्दू को प्रतिष्ठित किया जा रहा है वहाँ इस प्रदेश की नीकरशाही भी हिंदी उर्दू का विवाद खड़ा कर अंग्रेजी वर्चस्व को बनाये रखना चाहती है.

प्रदेश की जनता भाषा के प्रश्न पर विदेशों एवं दूषित राजनीति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी. अंततः सरकार को यह निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा. यदि सरकार ने यह निर्णय अगस्त मास तक वापस नहीं लिया तो सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया जायेगा.

—अशोककुमार राय, संयोजक, द्वितीय राजभाषा विरोधी संघर्ष समिति, उ. प्र., लखनऊ.



ती कृष्ण  
भारत में  
शायद ही  
सके. पर  
औरत को  
स्त्री अपने  
ती है, जिसे  
नी में कोई  
वी के हक  
ह अदालत  
की संपत्ति  
लाक और  
यह कहना  
ही होता है  
तलाक से  
लाक पति  
वह बिना  
ने इस्लाम  
को. अगर  
मलियों के  
आ सकती  
पर खड़े  
पा कि पैरों  
आशय है.

ति पर  
गाामी  
गरिकों  
मी, पं  
मित्र  
गमान्य

हे कि  
प्रश्न  
संबंधी  
जस के  
वोषणा  
ज्यापाल  
श को

द्वितीय  
जहाँ  
संबंध  
मा जा  
व को

वर्दीशत  
निर्णय  
रिया.  
वनम.

जून '82

जब वह घर की आधी मालिक है तो फिर पैरों पर खड़े होने से क्या अर्थ है? आर्थिक या सामाजिक? मुस्लिम स्त्री की घर में ही इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वहीं वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित करती है.

और अंत में कौन कहता है कि मुस्लिम स्त्री शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाती. क्या मुस्लिम देशों, जैसे पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मिस्र की स्त्रियाँ अपनी शिक्षा से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं होती हैं और अब तो भारत में भी कई मुस्लिम स्त्रियाँ अग्रसर हुई हैं. —गुल हमीद खान, गाँव गगवाना, ज़िला अजमेर.

### विभूति बाबू के स्मारक की दुर्दशा

घाटशिला बिहार और बंगाल की सीमा पर अवस्थित है. यहीं बंगला के अमर कथा-शिल्पी विभूतिमूषण बंद्योपाध्याय ने "पथेर पाँचाली" की रचना की थी. यहाँ उन का एक स्मारक भी है. गत मास मैंने स्मारक की दुर्दशा देखी. सामग्रियाँ गायब होती जा रही हैं. भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है. सामने की पहाड़ी, जो कभी सुरम्य रही होगी, अब लोगों के मल त्याग के कारण दुर्गन्धयुक्त हो रही है.

एक बात और. सन् 1980 में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन ने मुझे गौर-बंगलामापी साहित्यकार की हिंदी सेवा के लिए "अमृत पुरस्कार" से सम्मानित किया था. मैं उन का कृतज्ञ हूँ. पर अनुरोध करता हूँ कि बंगला साहित्य के एक कालजयी साहित्यकार के स्मारक में रुचि लें. अगर सरकार दिलचस्पी न ले तो साहित्यकार ही यह पुण्य कार्य करें. —डॉ. बच्चन पाठक 'सलिल', अध्यापक, जमशेदपुर वीमेन कॉलेज.

### दाम बढ़ा कर काम सुधारिये

मेरा निवास ग्रामीण क्षेत्र बोरगाँव में है तथा मेरा डाकघर बोरगाँव मार्फत बोरी अरब, ज़िला यवतमाल, महाराष्ट्र है. यहाँ पिछले हफ्ते में कई दिनों से हमें डाक ही प्राप्त नहीं हुई है. स्थानीय डाकघर बोरगाँव में हम पता लगाते हैं, तो यहाँ के पोस्टमास्टर साहब कहते हैं कि कई दिनों से डाक की थैली ही नहीं आती है. भारत सरकार डाक सेवा का शुल्क प्रतिवर्ष बढ़ाती जाती है, तो सरकार को भी तुरंत एवं नियमित सेवा देश के नागरिकों को उपलब्ध करवानी ही चाहिए. नयी नयी योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष नये नये डाकघर खोलने के लक्ष्य घोषित किये जाते हैं, तो उस के साथ ही जो नवस्थापित चालू डाकघर हैं उन की सुव्यवस्था, नियमितता एवं तुरंत सेवा की तरफ समुचित एवं संपूर्ण ध्यान देना भी उतना ही या उस से ज्यादा आवश्यक है. —सच्चिदानंद गनेडीवाला, डाकघर बोरगाँव, मार्फत बोरी अरब, ज़िला यवतमाल. (विदग्ध)

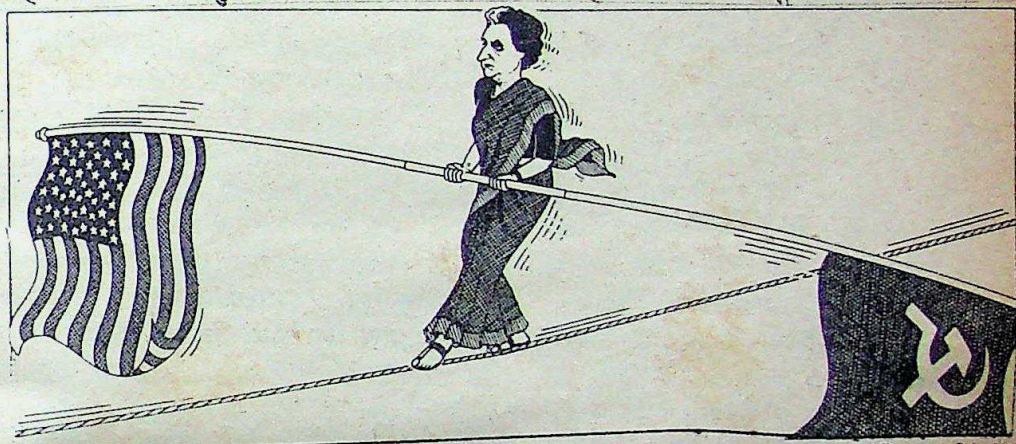
दिनमान

## 'थैंक यू अमेरिका'

पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सैनिक सहायता और इसी आधार पर पाकिस्तान अमेरिकी संबंधों की चर्चा भारतीय तथा विश्व के अन्य समाचारपत्रों में प्रायः देखने को मिलती है लेकिन अभी पिछले दिनों कराची के, एक निष्पक्ष अंग्रेजी दैनिक "मुस्लिम" ने इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी राजदूत श्री रोनाल्ड आई. स्पेटर का एक भाषण विस्तार से प्रकाशित किया है. अमेरिकी राजदूत के भाषण पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक उपलब्ध नहीं है. लेकिन दैनिक 'मुस्लिम' ने भाषण पद "थैंक

अमेरिका में बहुत कम हो जायेगी.

अमेरिकी राजदूत के विचार से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का है. अमेरिकी लोकमत इस प्रश्न को ले कर पाकिस्तान के खिलाफ है लेकिन आंतरिक राजनैतिक मामलों में अमेरिका पाकिस्तान को सलाह देना नहीं चाहता पर राजनैतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार तो लोगों को होना ही चाहिए. पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों में एक सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने की है. अमेरिकी राजदूत ने अपने भाषण में



—'इंडिया टुडे' से

यू अमेरिका" शीर्षक से जो टिप्पणी प्रकाशित की है उसमें पाकिस्तानियों को एहसास कराने की कोशिश की गयी है. कि अमेरिकी न कभी किसी के मित्र रहे हैं और न होंगे.

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा संबंध सन् 1950 से चले आ रहे हैं. इस संबंध में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी राजदूत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना भारत के साथ संबंध खराब करना है जब कि भारत को भी हम अपना एक अभिन्न मित्र मानते हैं. पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार आत्मरक्षा के लिए ही दिये गये हैं. और अमेरिका को यही विश्वास होना चाहिए कि वह इनका इस्तेमाल किसी आक्रमण के लिए नहीं करेगा. हम नहीं समझते कि पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण करने या भारत का पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कोई इरादा है लेकिन साथ ही अमेरिकी राजदूत के शब्दों में अमेरिका यह भी नहीं मानता कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जायेगा. अमेरिकी राजदूत के विचार से अगर भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान को समर्थन देने की अमेरिकी नीति की आलोचना

यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में भारत की अनदेखी नहीं की जा सकती.

**भारतीय राजनीति की चर्चा के संबंध में**  
इस बार साप्ताहिक "इकानामिस्ट" ने राजीव गांधी को ले कर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है. पत्र के विचार में:

"श्रीमती गांधी की कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम हुआ है यह अब पहले जैसी प्रभावशाली पार्टी नहीं रह गयी है. श्री राजीव गांधी पायलट रहे हैं इसलिए पार्टी को भी वह तकनीकी कौशल से ठीक करना चाहते हैं आज जब भी कांग्रेस पार्टी में उनका नाम लिया जाता है तो संजय समर्थक सिर हिला कर हंसने लगते हैं. एक समर्थक ने तो कहीं यहाँ तक कहा "बेचारा राजीव न तो लोगों पर दबाव डालना जानता है न उसे किसी को डराना आता है. संजय गांधी के समर्थक अब मेनका गांधी से आशा लगाये हुए हैं. श्रीमती मेनका गांधी ने श्रीमती गांधी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है पर बहुत कम लोगों को यह पता है कि उसका असली निशाना तो राजीव है. जब तक उनकी माता प्रधानमंत्री हैं वह राजनीति से जाने वाले नहीं हैं. लेकिन अभी वह पार्टी के लिए एक बोझ ही साबित हो रहे हैं.



## वया विधायकों की बिक्री बंद होगी

(हमारे विशेष संचादक द्वारा)

राष्ट्रपति को भेजे अपने पत्र में हरयाणा के राज्यपाल श्री तपासे ने लिखा है : "मुझे यह सूचना मिली कि सीदेबाजी तेजी के साथ चल रही है और लोकदल के लोग विधायकों को पकड़ कर अज्ञात जगहों पर ले जा रहे हैं. हरयाणा में बदलती हुई राजनैतिक बफ़ादारी की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैंने भजनलाल को शपथ दिलायी क्योंकि सदन में वह स्पष्टतः सब से बड़े दल के नेता हैं. देवीलाल ने मुझ से राजभवन में कहा कि उन के साथ 45 सदस्य हैं. मुझ से पूछा कि जब भजनलाल को शपथ दिलायी थी तो उन्हें क्यों बुलाया... तरह तरह के आरोपों के साथ, हुल्लड़बाजी शुरू हो गयी. उन्होंने गुस्से में मुझे पकड़ कर झकझोर दिया. एक हाथ से मेरी ठुड्डी पकड़ी. दूसरे से कंधा... मुझे दुख के साथ लिखना पड़ता है कि ऐसी हुल्लड़बाजी, और गालीगलौज मैंने इस के पहले कभी नहीं देखी थी."

भजनलाल को शपथ दिलाने का जो फैसला श्री तपासे ने किया, वह व्यापक आलोचना का विषय बना है. प्रतिपक्षी दल इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं. 31 मई को दिल्ली में प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक हुई, उस की एक विशेषता अन्य प्रतिपक्षी दलों के साथ साथ संसद के बाहर की बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इंद्रीप सिन्हा की शिरकत रही है. उस में मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति के चुनाव पर विचार विमर्श था. लोकदल के महामंत्री मधु लिमये के अनुसार आम राय यह थी कि संघर्ष का रवैया अपना कर राष्ट्रीय सहमति को सामने लाया जाये. '77 में राष्ट्रपति के चुनाव में और '79 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो परंपरा जनता शासन काल में स्थापित की गयी उसी का निर्वाह वे प्रतिपक्षी दल के रूप में भी करना चाहते हैं. इस के लिए सभी नेताओं के हस्ताक्षर से युक्त एक पत्र श्रीमती गांधी को लिख कर माँग की गयी है कि वह प्रतिपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक बुलायें."

प्रतिपक्षी दलों के दिमाग में अभी कोई नाम नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वे श्री नीलम संजीव रेड्डी या श्री हिदायतुल्ला के पक्ष में हो सकते हैं. बहुत मुमकिन है कि इंदिरा कांग्रेस श्री रेड्डी के नाम पर सहमत न हो. श्री हिदायतुल्ला का नाम भी उसके लिए

दिनमान



गणपति दामोदर तपासे, भजनलाल और देवीलाल : अपनी अपनी व्याख्या

बहुत सुविधाजनक नहीं होगा. वैसे, विभिन्न राजनैतिक हलकों में शिक्षाविद बी.बी. जॉन से लेकर यशवंत राव चव्हाण, स्वर्ण सिंह, बासप्पा दाजप्पा जत्ती आदि के नामों की उस पद के लिए चर्चा है.

भजनलाल और देवीलाल दोनों ही देश के लाल हैं और उनमें से किसी एक को दूसरे से कम करके आँकना, उस के क्रद को छोटा करना होगा. दलबदल की ज़रूरत देवीलाल और भजनलाल दोनों को थी. दोनों इसमें हाथ आजमा रहे थे. देवीलाल मात खा गये. परिणाम यह है कि उनके समर्थकों ने सारा गुस्सा दलबदलों पर उतारना शुरू कर दिया. जिद में एक मंत्री ब्रजमोहन सिंगल के निवासस्थान पर किये गये पथराव और आक्रमण के कारण केंद्रीय आरक्षी पुलिस का एक दस्ता तैनात करना पड़ा.

देवीलाल आरोप को स्वीकार नहीं करते. उन्होंने कहा कि उन्होंने तपासे जी की ठुड्डी विरादराना मुहब्बत से छुई थी. अखबारी फोटोग्राफ़ों ने शरास्ती उद्देश्य से तस्वीर ही इस तरह खींच दी जो दुर्व्यवहार जैसी दीखी. अजीब बात है. इका नेता देवीलाल के उस प्रेम स्पर्श को आक्रमण मान रहे हैं.

चौधरी साहब, यानी चौधरी चरणसिंह अपनी ही ठुड्डी को अफसोस में दवाते हुए कहते सुने गये कि श्री तपासे को राज्यपाल बनाने की पहल उन्होंने खुद की थी. मोरारजी भाई को उन्होंने ही सहमत किया था. बहुगुणा जी तपासे जी से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते सुने गये जब वह पेट्रोलियम मंत्री थे. उद्देश्य इस नतीजे पर पहुँचना था कि जनता शासन के दौरान श्री तपासे की नियुक्ति में राजनैतिक अकलमंदी से काम नहीं लिया गया.

इसमें कोई शक नहीं कि राज्यपाल के रूप में श्री तपासे ने अपने विवेकाधीन अधिकार का इस्तेमाल जिस रूप में किया, उससे उनकी निष्पक्षता के सामने बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न

खड़ा हो गया है. देवीलाल ने राष्ट्रपति को दिये अपने स्मरणपत्र में श्री तपासे को बर्खास्त करने की माँग करते हुए कहा है : 'हम मानते हैं कि राज्यपाल ने हमारे साथ विश्वास भंग किया. उन्होंने केंद्रीय सरकार के दबाव में उस गुट को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जिसके पास बहुमत नहीं था. उन का यह काम असंवैधानिक है. चूँकि राष्ट्रपति की हैसियत से आप संविधान के रक्षक हैं अतः इस मामले में हस्तक्षेप करना आप का दायित्व है. केंद्रीय सरकार इस असंवैधानिक काम में खुद एक फरीक है अतः उसे इस मामले में आप को सलाह देने का नैतिक अधिकार नहीं है. सिर्फ आप का स्वतंत्र और साहसपूर्ण क्रदम ही इस असंगति को दूर कर सकता है.'

सुना जाता है कि उन के आरोपों को सुनने के बाद राष्ट्रपति ने लाचारी जाहिर करते हुए कहा. 'मैं क्या कर सकता हूँ. ऐसा कदम तो महज गृहमंत्रालय ही उठा सकता है.'

आपत्ति का मुख्य मुद्दा यह है कि नतीजों की घोषणा के बाद देवीलाल द्वारा बहुमत का दावा करने पर श्री तपासे ने उनसे कहा कि वह सोमवार को उस दावे की पुष्टि के लिए अपने समर्थकों को उन के सामने हाज़िर करें. वह अपनी तैयारी में लगे हुए थे लेकिन उसके एक दिन पहले यानी इतवार को ही श्री तपासे ने भजनलाल को सरकार बनाने का आमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. नैतिकता से जुड़े इस मुद्दे से अलग संबैधानिक मुद्दा यह है कि इतवार तक न तो पुरानी विधानसभा अंग की गयी थी, न ही निर्वाचन आयोग ने नयी विधानसभा के गठन की विज्ञप्ति जारी की थी. आयोग ने चारों राज्यों की विधानसभाओं के गठन की विज्ञप्ति सोमवार को जारी की. नयी विधानसभा के औपचारिक गठन की घोषणा के पहले राज्यपाल का भजनलाल को शपथ दिलाना असंवैधानिक है. सवाल उठाया गया कि देवीलाल को सोमवार तक का समय देने के बाद राज्यपाल को इंतज़ार



करना चाहिए था।

आपति यह भी हुई कि अगर उनके अनुसार सब से बड़ी पार्टी को निर्मन्त्रित किया जा सकता है तो चूंकि लोकदल, भाजपा और कांग्रेस (ज) की संख्या-शक्ति इका से अधिक थी अतः उन के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ पर एक राजनैतिक दल या कई दल मिल कर बहुमत बना सकते हों, वहाँ राज्यपाल के सामने सिवा उसे आमन्त्रित करने के कोई और विकल्प नहीं होता। जहाँ ऐसा बहुमत न हो, वहीं पर राज्यपाल को दूसरे विकल्प को स्वीकार करने की छूट होती है। यह उम्मीद करना उचित है कि सब से बड़ी पार्टी के रूप में किसी दल या कई दलों के प्रमाणित सब से बड़े समूह को ही सब से पहले सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए।

जाहिर है कि प्रतिपक्षी दल स्तब्ध और हताश हैं। लगता है कि इंदिरा कांग्रेस ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जिस के पीछे ऊँची दीवार है। चरणसिंह के नेतृत्व में उन के निवास पर आयोजित बैठकों में यह निर्णय किया गया कि इका विरोधी इस लड़ाई में श्री तपासे के असंवैधानिक आचरण राष्ट्रपति के चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति विधि को मुड़ा बनाया जायेगा।

लोकदल के महामंत्री मधु लिमये के अनुसार श्री तपासे का फैसला, राष्ट्रपति का चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की विधि तीनों ही मसलों का संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा से है।

उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनावों के निर्देश, नियंत्रण और निगरानी (अनुच्छेद 324) का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी निकालने की है लेकिन उन की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं हुई है। संविधानसभा में मौलिक अधिकार समिति में श्री नेहरू और श्री पटेल दोनों सदस्य थे। विषय के महत्व को देखते हुए इसे मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में रखने की योजना थी। बाद में उसे भाग 15 में रख दिया गया। श्री नेहरू और श्री पटेल दोनों ने कहा कि चुनाव संचालन और मतदाता सूची का निर्माण तत्कालीन कार्य समिति के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। संविधान के मसौदे में सुझाव यह था कि राज्यों की विधान-सभाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हों। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की धारा को बदल दिया गया। वजह यह मानना था कि मतदाता सूची और चुनाव संचालन का केंद्रीयकरण करना चाहिए क्योंकि भाषिक राज्य बनने के बाद खतरे पैदा हो सकते थे। सांस्कृतिक, दिनमान

## ‘संविधान शरीफ लोगों के लिए बना है’

जनता पार्टी के महामंत्री और एडवोकेट सैयद शहाबुद्दीन ने कहा :

“श्री तपासे का यह कदम लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता कि उन्होंने देवीलाल से अपने समर्थकों को हाजिर करने के लिए वक्त और तारीख मुकर्रर करने के बावजूद उससे पहले ही भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। संविधान में ऐसी किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। यह उनकी नैतिक कमजोरी का सबूत हो सकता है लेकिन उनका यह कहना कि उन्होंने भजनलाल को इसलिए चुना क्योंकि वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, संविधान की रोशनी में बिल्कुल गलत मालूम होता है। संविधान में कहीं पर किसी पार्टी का जिक्र नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ यह कहा होता कि मैं खुद इस बात से संतुष्ट हूँ कि भजनलाल का बहुमत संभावित है तो उतना ही काफी होता। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी चुनते वक्त यह नजरअंदाज कर दिया कि लोकदल और भाजपा ने एक दल होकर चुनाव लड़ा था। इस लिहाज से उन्हें देवीलाल को मौका देना चाहिए था। यदि तपासे जी का यह फार्मूला सही है तो केरल में बजाय श्री कृष्णाकरण के माकपा नेता श्री नयनार को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाना चाहिए था। मुझे याद आता है डॉक्टर अंबेदकर ने कहा था कि “यह संविधान शरीफ लोगों के लिए बना है।” उसमें मुख्यमंत्री बनाने के सिलसिले में अनुच्छेद 163(1) और 164(1-2-3) में दिये गये उपबंध स्पष्ट हैं।

संविधान की मंशा यह है कि चूंकि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति जवाबदेह है अतः राज्यपाल के लिए लाजिम है कि वह जिस किसी को मुख्यमंत्री बनाये वह विधानसभा का सामना कर सके। लेकिन जहाँ ‘आयाराम और गयाराम’ की सियासत चलती हो और जहाँ राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय सरकार से आदेश लेते हों, वहाँ संविधान के शब्द तो शायद ज़िदा रहते हैं, उस की आत्मा जरूर मर जाती है।

दरअसल सवाल व्यक्तियों का नहीं, संवैधानिक राजनैतिक परंपराओं का है। अगर

लोकतांत्रिक संस्थाएँ इस तरह तोड़ी-मरोड़ी गयीं तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास रह नहीं पायेगा। शायद इसके चलते यथा-स्थिति का विरोध करने वाली शक्तियों को हिंसा का रास्ता अपनाने की ताकत मिलेगी। —आप को याद होगा कि जब केंद्र में जनता सरकार गिरी तो दो मौके ऐसे आये जिन में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के फैसले आलोचना का विषय बने। पहली बार जब यशवंतराव चव्हाण ने मंत्रिमंडल का गठन करने में लाचारी व्यक्त की थी, उस वक्त उन्हें जगजीवनराम को आमन्त्रित करना चाहिए था। दूसरी बार जब उन्होंने जनता पार्टी के उस वक्त के नेता बाबूजी (जगजीवनराम) से उन के समर्थकों की सूची मांगी और बगैर उस का इंतजार किये चरणसिंह को आमन्त्रित कर दिया। वह भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि श्रीमती गांधी ने चौधरी जी को समर्थन देने का वायदा किया था।

मेरी नजर में अब यह जरूरी हो गया है कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया क्या होगी। मिसाल के तौर पर चुनाव के फौरन बाद हफ्ते भर के भीतर संसद या विधान-सभा की बैठक में सदन के अंदर ही नेता का चुनाव किया जाना चाहिए। उस के बाद ही राष्ट्रपति या राज्यपाल नेता विशेष को सरकार बनाने का आमंत्रण दें। लेकिन मैं सिर्फ तपासे जी को ही बुरा क्यों कहूँ। अभी हाल ही में असम में जो कुछ हुआ उसे सभी जानते हैं। संयुक्त मोर्चे के 62 सदस्य थे। पर? मैं तो यह भी मानता हूँ कि राज्यपालों के तबादले की रस्म गलत है। इस तरह केंद्र उन पर दबाव डाल सकता है। असल में केंद्रीय सरकार के बदलने के साथ साथ सभी राज्यपालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। नयी सरकार जिसे चाहे उसे रखे। किसी राज्यपाल को उस के 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही किसी और जगह नहीं भेजना चाहिए।

एक बड़ी मुसीबत यह है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध तो महाभियोग चलाया जा सकता है लेकिन राज्यपाल के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस के लिए राष्ट्रपति सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल के मशविरे पर ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब राज्यपाल खुद केंद्र की आज्ञा पर चलने लगें तो क्या इलाज बच जाता है।



## ‘कुछ भी असंवैधानिक नहीं है’

भूतपूर्व केंद्रीय विधिमन्त्री और प्रसिद्ध अधिवक्ता अशोक सेन जब यह कहते हैं कि चूंकि उन्होंने हरयाणा प्रसंग पर विचार नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकते तो आश्चर्य होता है। उन्हें बुखार था। (राजनैतिक नहीं) उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि “अगर राज्यपाल को यह उम्मीद हो कि किसी व्यक्ति विशेष को पूर्ण बहुमत मिल सकता है तो वह उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। गलत या सही ऐसी समस्याएँ पहले भी पैदा हुई थीं लेकिन विधानसभा की बैठक के बाद असलियत सामने आ गयी।”

लेकिन इका समर्थक एक अन्य विधि विशेषज्ञ के अनुसार राज्यपाल श्री तपासे का फैसला संविधान की अवमानना नहीं करता। स्थितियाँ पहले भी पैदा हुई थीं और उनमें ऐसे ही फैसले लिये गये। “संविधान ने राज्यपाल को ऐसे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने का अबाधित विवेकाधीन अधिकार दिया है जो बहुमत में हो। 1952 में तत्कालीन मद्रास राज्य में यही स्थिति पैदा हुई थी। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था लेकिन वह सब से बड़ी पार्टी थी। प्रतिपक्षी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बाद में टी. प्रकाशम् के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बनाया। चूंकि कांग्रेस के अनेक शीर्षस्थ नेता पराजित हो गये थे, अतः उच्चकमान ने राजा जी से प्रार्थना की कि वह नेतृत्व संभालें। राज्यपाल श्रीप्रकाश ने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और कुछ हफ्तों के बाद विधानसभा की बैठक में अपना बहुमत प्रमाणित कर दिया। 1967 में कांग्रेस कई राज्यों में हार गयी थी। राजस्थान में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आयी लेकिन बहुमत नहीं मिला था। प्रतिपक्षी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अतः 1952 की नज़ीर को सामने रखते हुए मोहनलाल सुखाड़िया से मंत्रिमंडल बनाने को कहा गया। सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करने के संदर्भ में केरल की जो मिसाल दी जा रही है, वह सही नहीं है। वहाँ पर श्री कृष्णाकरण को सरकार बनाने का आमंत्रण इसलिए दिया गया क्योंकि वह संयुक्त

लोकतांत्रिक मोर्चे के चुने हुए नेता थे, न कि कांग्रेस विधायक दल के। यह स्थिति भिन्न है। केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे और वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे ने अलग अलग मोर्चा बनाया था। एक ने मार्क्सवाद के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी जब कि दूसरे ने लोकतंत्र के प्रति। इन मोर्चों का गठन चुनाव के बहुत पहले हो गया था। हरयाणा में लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच की सहमति केवल सीटों संबंधी तालमेल थी। उसे समझौता नहीं कहा जा सकता। उनके कार्यक्रम एक नहीं थे। राज्यपाल ने देवीलाल से अपने समर्थकों को हाजिर करने को कहा। हालाँकि उस का इंतज़ार नहीं किया। असल में वैसा फैसला करते हुए वह प्रतिपक्ष के प्रति ज़रूरत से ज्यादा उदार हो गये। उनका सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी था कि वह सब से बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित कर रहे हैं। शायद उन्हें यह यकीन था कि देवीलाल के समर्थकों की संख्या 45 या 46 है लेकिन, जब उन्हें यह पता चला कि देवीलाल ने अपने समर्थकों को हवाखोरी के नाम पर कालका के पास किसी ऐसी जगह पर इसलिए रख छोड़ा है ताकि उनसे कोई मिल न सके तो उन्हें लगा कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। इससे राजनैतिक वातावरण दूषित होगा। तब उन्होंने अपना पहला फैसला बदल दिया। कहा जा सकता है कि राज्यपाल के फैसले में प्रक्रिया संबंधी दोष हो सकते हैं। राज्यपाल ने भजनलाल को आमंत्रित कर के कोई गलती नहीं की है। असम के राज्यपाल ने दो मौकों पर ऐसा ही फैसला किया था। दोनों ही मौकों पर इंदिरा कांग्रेस के नेता निश्चित समय के भीतर अपना बहुमत सिद्ध कर पाने में असफल रहे और त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह अगर भजनलाल भी अपना बहुमत सिद्ध कर पाने में असफल होते हैं तो उन्हें भी त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह ने राज्यपाल के फैसले को लोकतंत्र को सलीब पर चढ़ाने वाला कदम कहा है। उनको तो इस की शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति का फायदा उन्होंने खुद उठाया है। 1979 में जनता पार्टी के टूटने के वक्त चौधरी जी को राष्ट्रपति ने बहुमत सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक महीने का नहीं बल्कि तीन महीने का समय दिया। यह बात अलग है कि चौधरी साहब संसद में अपना बहुमत सिद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाये।

या क्षेत्रीय आधारों पर भेदभाव हो सकते हैं। एक योग्य और निष्पक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति लोकतंत्र की आत्मा है। उस नियुक्ति तथा निर्वाचन आयोग के गलत और निर्वाचन संबंधी सुधारों पर पूर्ण विचार होना चाहिए। वर्तमान आयुक्त शकधर को पदमुक्त करने की जगह उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाये। पिछले वर्षों में इस तरह का कार्यकाल बढ़ाया भी गया था।

दिलचस्प बात यह है कि श्री शकधर दलबदल करने वालों को सदन की सदस्यता के लिए अपात्र घोषित करने का जो सुझाव दिया उसे सत्ताधारी दल ने पसंद नहीं किया है।

दलबदल से चिंतित सभी हैं। श्रीमती गांधी कहती हैं कि सभी प्रतिपक्षी दल तैयार हों तो उसे रोकने का कानून बनाया जा सकता है। विडंबना यह है कि जिस दलबदल की विद्रूपता से सभी चिंतित हैं, उसकी धार दुहरी है। दलबदल का राजनैतिक पुरस्कार यदि मंत्रिपद हो तो वह आकर्षक तो हो ही जाता है, यह बात अलग है कि वैसा करने की छूट को अंतरात्मा की स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है।

दलबदल से चिंतित सभी हैं। श्रीमती गांधी कहती हैं कि अगर सभी प्रतिपक्षी दल तैयार हों तो उसे रोकने का कानून बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि सभी दल उसके लिए तैयार क्यों नहीं होते। वह एक ऐसा अस्त्र है जिससे इस्तेमाल का मोह छोड़ पाना किसी भी दल के लिए मुश्किल लग रहा है।

1973 में लोकसभा में एक विधेयक भी आया। वह उस सर्वदलीय समिति की रपट पर आधारित था जिसने दलबदल की समस्या पर विचार किया। उस समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृहमंत्री यशवंत राव चव्हाण सदस्य थे जयप्रकाशनारायण और हृदयनाथ कुंजरू। ताज़्जुब है कि सिफारिशों को लागू करने पर जोर देने वाले श्री चव्हाण खुद 1979 में चरणसिंह की सरकार में उपप्रधानमंत्री हुए। जयप्रकाश जी ने उसके खामियों को ओर इशारा किया था और दो कांग्रेस पर मढ़ा था। वह विधेयक अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है।

दलबदल की कुरूपताओं को नष्ट करने के जो फैसला कश्मीर में मुख्यमंत्री शेख अब्दुल ने किया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य चुनाव कानून में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि जो व्यक्ति एक पार्टी टिकट पर जीत कर आने के बाद पार्टी के विरोध बोट देता है या सदन में मतदान में हिस्सा न लेता है उसकी सदस्यता खत्म हो जायेगी। हालाँकि उस पर यह बंदिश नहीं लगी है। एक बार सदस्यता के खत्म होने पर पुनः चुनाव नहीं लड़ सकता।

दिल्ली

अम

हमारा

नाम है

सहज

के रूप में

मैंट की।

तारों मरे

तोले उड़ा

के प्रतीक

अंतरिक्ष

से प्रभावि

भी है।

रेखा जा

उमराव

लखनऊ

सचमुच

उपन्यासक

इस नाम

समय के

का एक

उसी का

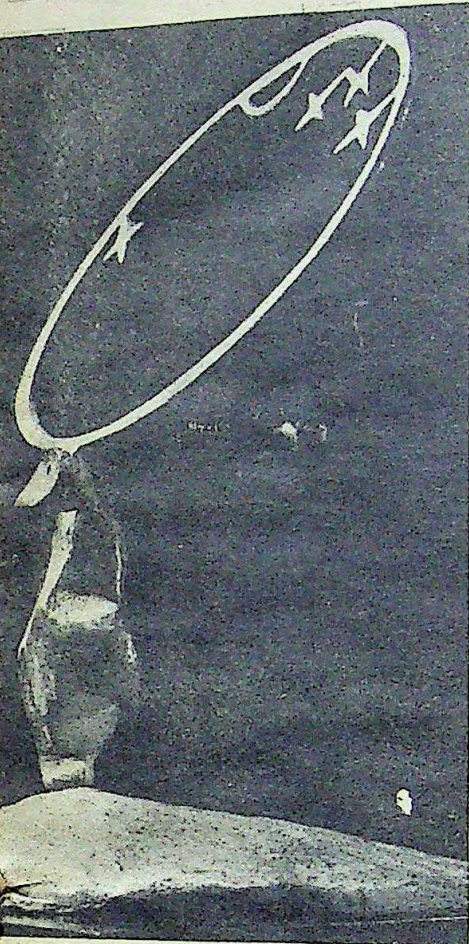
अली ने

उमराव

दिनमान



## दिल्ली के रंग



अमरनाथ सहगल का मूर्तिशिल्प

### हमारा आकाश

नाम है एक कृति का जो मूर्तिकार अमरनाथ सहगल ने बनायी और देश को उपहार के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी को भेंट की। एक पक्षी है जिसने चंद्रमा, सूर्य और तारों भरे आकाश को उठा रखा है और पर तोले उड़ान भरने को तैयार है। शिव महाराज के प्रतीक से पक्षी देव नृत्य की मुद्रा में है। कृति अंतरिक्ष की उड़ानों में भारत की सफलताओं से प्रभावित है और उन्हीं को एक श्रद्धांजलि भी है।

### रेखा जान

उमराव जान 'अदा' कितने ही वर्ष बीते लखनऊ की एक प्रसिद्ध नर्तकी थीं। थीं भी सचमुच या नहीं। यह तो उस समय के कवि-उपन्यासकार मिर्जा रसबा ही जानें जिन्होंने इस नाम से एक काव्य उपन्यास लिखा जो उस समय के अवध की डूबती और उमरती संस्कृति का एक विचित्र आईना बन गया। पिछले वर्ष अली ने एक फिल्म बनायी तो बस कल का उमराव जान की धाक आज की दिल्ली में भी दिनमान

बैठ गयी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सुशोभित हुई।

आधुनिक उमराव जान यानी अभिनेत्री रेखा और मुजफ्फर की फिल्म की दिल्ली के बाद बंबई में खोज शुरू हुई। क्योंकि वहां के चलचित्र आलोचकों ने जजों का पैल बनाया था अपने पुरस्कार के लिए—सर्वश्रेष्ठ चित्रों को आँकने के लिए। दो चित्रों की खोज थी उन्हें 'उमराव जान' और सत्यजित राय की 'सद्गति' की। दिल्ली और बंबई के बीच टेलीफोन और तारों तथा पत्र व्यवहारों का सिलसिला आठ दस दिन चला। दूरदर्शन तथा फिल्म समारोह निदेशालय के कर्मचारियों को संदेश पर संदेश भेजे गये। आखिर पता चला कि 'सद्गति' तो मांट्रियल यानी कॅनेडा चली गयी वहां के एक फिल्म समारोह के लिए और उमराव जान ताशकंद वहां पर एक रूसी फिल्म समारोह के लिए। साथ ही साथ गयी रेखा, उस फिल्म की अभिनेत्री और उस देश में लोकप्रिय भारतीय फिल्मी 'रकारो' की त्रिमूर्ति का एक रूप बन गयीं। एक रूसी मित्र के अनुसार रूस में राज-कपूर और राय (सत्यजित) तो ऐसे नाम थे जो बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। अब रेखा का नाम भी हर रूसी की जुबान पर है। ताशकंद में कुछ प्रशंसक उसे उमराव जान कह कर पुकारते हैं तो कुछ रेखा जान।

### श्वेत पताका क्रांति

जब युद्ध में कोई सेना हार जाती है तो सफेद झंडी दिखा कर शत्रु के सामने हथियार डाल देती है। मगर तीन लेखक चितक आज के ऐसे हैं जो श्वेत पताका को हथियार डालने का नहीं शांति और सुलह का प्रतीक बनाना चाहते हैं और उसका संदेश उनके मानस में है: 'आओ मिल कर बातचीत करें। और समस्याएँ निपटाएँ, झगड़े समाप्त करें।' ये तीन 'पताका प्रदर्शक' हैं प्रसिद्ध चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एक ओजस्वी अमेरिकी वैज्ञानिक सैन्-फर्ड रेडमंड और दिल्ली के एक जाने पहचाने पत्रकार लेखक और चितक जग मोहन (भूत-पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं) तीनों ने एक प्रकार की शांति-क्रांति संसार में चलाने के लिए अपने अपने विचार अक्षरबद्ध किये। सूजा ने लिखी 'श्वेत पताका क्रांति', रेडमंड ने लिखा 'बदले हुए परिप्रेक्ष्य में प्रकृति' और जगमोहन ने 'मानवता के लिए नयी आशा' अंग्रेजी में इन के शीर्षक थे, 'दी ह्वाइटफ्लैग रैवोल्यूशन', 'नेचर इन एन आल्टर्ड पर्सपेक्टिव' और 'ए न्यू होप फार दी मैनकाइंड'। तीनों को मिला कर एक ग्रंथ तैयार हो गया। इस का विमोचन हुआ पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नेशनल हेराल्ड के भूत-

पूर्व संपादक चेलापतिराव साहब के हाथों और समारोह की अध्यक्षता की मास्को में भारत के भूतपूर्व राजदूत इंद्र कुमार गुजराल ने। दोनों वक्ताओं ने युद्ध और हिंसा से घिरी मानवता पर विनाश की गहरी छाया का उल्लेख किया। और गहरी चिंता व्यक्त की। पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने और नये अंतरों और विवादों को ले कर चेलापति राव ने अणु बम के खतरे की ओर ध्यान दिलाया और कहा 'मान लिया माई कि पूर्व तो पूर्व है और पश्चिम भी पश्चिम, मगर बम तो बम है। बस बम ही है!'

इस पुस्तक में 'मगवान' 'धर्म एक ग्राम' 'धर्म, अधर्म तथा प्रकृति धर्म', 'मौलिक अणु तथा महा विस्फोट' 'मानव विज्ञान का विज्ञान' 'रेडमंड का विज्ञान स्कूली छात्रों का स्वर्ग' 'रेडमंडवाद' 'सूजावाद', 'शून्य तथा अनंत' 'जीवन के लिए ध्वनियाँ' आदि कई मुद्दों पर तीखे नये तर्क तथा दृष्टिकोण सामने रखे गये हैं। और यह विश्वास भी रखा गया है कि जो मानव धरती को बिगाड़ सकता है वह उसे सँवार भी सकता है और सँवारने का मार्ग श्वेत पताका मार्ग है। [पृष्ठ 45 भी देखें]

### पंडित जी की प्रतिमा

एक भारतीय पत्रकार मित्र ने एक रूसी पत्रकार मित्र को विदाई सहभोज दिया। गिने चुने अतिथियों में दोनों मित्रों के शुभचिंतक, प्रशंसक थे। इन में उड्डयन मंत्री अनंत प्रसाद शर्मा, सिंचाई मंत्री केदार पांडे और उनकी धर्मपत्नी तथा सूचना और प्रसार उपमंत्री मुहम्मद आरिफ खान तथा भारत में रूसी राजदूत भी थे। बातें राजनीति से हट कर जन जीवन के सौंदर्य तथा वैचित्र्य के बारे में हो रही थीं।

रूसी राजदूत ने कहा 'मैंने इस देश में यहाँ के महान नेताओं और नागरिकों की बड़ी बड़ी तथा प्रभावशाली प्रतिमाएँ देखी हैं। महात्मा गांधी की बहुत सी सुंदर प्रतिमाएँ देखी हैं, मगर पंडित जवाहर लाल नेहरू की कोई प्रभावित करने वाली प्रतिमा क्यों नहीं दिल्ली में अब तक स्थापित की गयी? मेरी समझ में नहीं आया?'

शर्मा जी और पांडे जी बोले 'विचार तो बहुत अच्छा है'। सोचा जाये तो सचमुच नये भारत के निर्माता के यूँ तो प्रकार प्रकार के स्मारक हैं मगर मूर्ति कलाकारों ने, जिन्हें पंडित जी से बहुत प्रोत्साहन मिलता था, अपनी कला द्वारा उचित साकार श्रद्धांजलि भेंट करने का प्रयास क्यों नहीं किया। अभी तक? भारतीय मूर्तिकारों के लिए यह विचार-णीय हो सकता है।



## गंगा में रोज़ रोज़ घुलता हुआ जहर

अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले शिव ने भले ही अपने कंठ में कालकूट भर लिया हो पर लगता है स्वयं गंगा औद्योगिक विकास का विष अब ज्यादा दिन तक नहीं सह पायेगी। जल प्रदूषण के निषेध और नियंत्रण के लिए बनाये गये केंद्रीय बोर्ड के वैज्ञानिक सन् 1979 से सात राज्यों में 30 जगहों से गंगा का जल ले कर उस की जाँच करते रहे हैं। इन की खोज की पूरी रपट तो दिसंबर 1982 तक छपेगी, पर उस के कुछ छीटे भी चौकाने के लिए काफी हैं।

गंगोत्तरी से निकल कर हरिद्वार तक ही गंगा अपना निर्मल स्वरूप बनाये रखती है और इस से आगे किनारे पर वसे 40 प्रथम श्रेणी के और 66 द्वितीय श्रेणी के शहरों का मल और कारखानों का कचरा ढोते ढोते कानपुर और वाराणसी तक यह नदी दम तोड़ देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार फिर इसका पानी आदमी के किसी काम का नहीं रहता। इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि मछलियों तथा अन्य जल जीवों का दम घुटने लगता है। कानपुर की कपड़ा और चमड़ा मिलों द्वारा गंगा में छोड़े गये जहरीले रसायनों के कारण आगे 5 किलोमीटर तक कोई मछली नहीं बची। आगे चल कर बिहार में मुकामा वरीनी क्षेत्र के पेट्रो-रसायन कारखानों से गंगा सबसे अधिक प्रदूषित होती है। मुकाम की बाटा शू कंपनी से फेंकी गयी चमड़े की छीजन मरी मछलियों के गलफड़ों में फँसी पायी गयी। आगे छह किलोमीटर तक यहाँ भी मछलियाँ नहीं रहीं। हाँ, रोगाणु ज़रूर तेज़ी से पनपते हैं और इस पानी को पीने पर हैजे जैसे संक्रामक रागों और आंत की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. बी. डी. त्रिपाठी ने काशी में गंगा जल के प्रदूषण का अध्ययन किया। उन का कहना है कि गंगा में अधजले शवों के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। हर साल करीब 3 हजार अधजले शव गंगा में केवल वाराणसी से ही प्रवाहित किये जाते हैं। इस के साथ ही 200 से 300 टन तक राख भी बहाई जाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर प्रति वर्ष लगभग 11 हजार टन लकड़ी जलाई जाती है। इस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए 95 से 115 हैक्टर जंगल का सफाया हो जाता है। मानव शवों के अतिरिक्त गंगा 6 हजार पशुओं के भी शव प्रति वर्ष ढोती है। कुल मिला कर लगभग 1500 औद्योगिक कारखाने इस नदी में अशोधित मलवा छोड़ते हैं।

यही हाल गंगा की सखी यमुना का भी है। राजधानी के मल-जल के शोधन के लिए ओखला, वजीरपुर और केशोपुर में संयंत्र लगे हैं। जो केवल 46.4 प्रतिशत मल-जल को ही शुद्ध कर पाते हैं। बाकी गंदा पानी 17 खुले नालों की मार्फत यमुना को पिलाया जाता है। इन में सब से ज्यादा मल-जल नज़फगढ़ नाले से आता है। लगभग 54 प्रतिशत वजीराबाद और ओखला के बीच 48 कि.मी. के क्षेत्र में यमुना सब से अधिक प्रदूषित पायी गयी है। गंदे नालों से यमुना में तीन लाख घन मीटर मल और 20 हजार घन मीटर जहरीला औद्योगिक कचरा मिलता है। जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार नज़फगढ़ नाले, यमुनापार के नाले और कालका जी के नाले की मार्फत यमुना को प्रदूषित करने वाले 3329 कारखानों में से 359 इतना जहरीला छीजन फेंकते हैं, जिस के लिए उचित कदम उठाया जाना ज़रूरी है। बोर्ड ने सिकांरिश की है कि यमुना को इस गंदगी से बचाने के लिए कम से कम 54 औद्योगिक इकाइयों को तुरंत ही प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाने चाहिए और नज़फगढ़, वाराणसी नालों के क्षेत्र में जल शोधन के संयंत्र लगाने के साथ साथ ओखला संयंत्र का विस्तार भी किया जाना चाहिए।

इन कार्यों पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गंगा-यमुना के अतिरिक्त ताप्ती, नर्मदा जैसी मध्यप्रदेश की नदियाँ, ओडीसा की रोपि कुल्या, केरल की चेलिआर और पल्लदा और कर्नाटक की घटप्रभा नदियाँ भी भयानक प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। आशा की कोई किरण दिखाई देती है तो यही कि बिगड़ते हुए हवा, पानी और मिट्टी को बचाने के लिए जनता भी अब जागरूक हो रही है और जगह जगह लोग सत्याग्रह और आंदोलन कर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाँव जिले में अल्पयुनियम बनाने का कारखाना कोई 14 साल पहले लगा था। सितंबर 1979 में इस की टंकी फट गयी। उस में भरा कारखाने की छीजन से लैस पानी दूर दूर तक फैल गया। आसपास के कुएँ, खेत, नदी-नाले सब प्रदूषित हो गये। खेतों में खड़ी फसल जल गयी। स्थानीय 'लोक समिति' ने किसानों और नागरिकों को इकट्ठा कर के सत्याग्रह करना शुरू किया। अंत में राज्य सरकार ने बीच बचाव कर के यह तय किया कि आस पास के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में कारखाना 13 लाख रुपये बाँटेगा जो कि बाद में घटते घटते एक लाख रुपये रह गये। यही नहीं, बाद में इस सत्याग्रह में शामिल हुए 14 किसानों

के खिलाफ किसानों ने मुकद्दमे भी चलाने चाहे। इस पर कारखाने की मजदूर यूनियन भी किसानों के साथ हो गयी। मामला अभी अदालत में है। कुछ समय पहले केरल में चेलिआर नदी में रेयन कारखाने से फेंके गये पारायुक्त छीजन के खिलाफ वहाँ के मलयाली विज्ञान लेखकों की संस्था केरल शास्त्र साहित्य परिषद् ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया था। उन्होंने कारखाने की चिमनी से हवा में फेंके जा रहे गंधक भरे धुएँ के खिलाफ भी आवाज़ उठायी। इस संस्था ने केरल की पल्लदा नदी में प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। मध्यप्रदेश में 'नर्मदा बचाओ' और 'ताप्ती बचाओ' समितियों ने दोनों नदियों को मरने से बचाने के लिए आंदोलन चलाये। ताप्ती नदी में नेपालनगर के कारखाने द्वारा अशोधित छीजन फेंके जाने के



विश्व वन्य पशु कोष के संस्थापक अध्यक्ष नोदर-लैंड के राजकुमार बर्नहार्ड ने 18 मई को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पर्यावरण की रक्षा में सफल नेतृत्व प्रदान करने और पशु तथा वनस्पति के संरक्षण में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए 'आर्डर आफ द गोल्डन आर्क' और 'कमांडर' सम्मान से सुशोभित किया।

खिलाफ जब अदालत में मुकद्दमा चला तो कारखाने को ढाई करोड़ रुपये की लागत से 'फिल्टर संयंत्र' लगाना पड़ा। ग्वालियर में 'स्वर्णरेखा' नदी के प्रदूषण की ओर वहाँ के मेडिकल कालेज के डॉक्टरों ने ध्यान खींचा। ओडीसा में गंजम जिले के किसान और मछुए एक रासायनिक कारखाने के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, जो उन की रोपिकुल्या नदी को खराब कर रही थी।

भारत सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1971 में एक अधिनियम बनाया था। जिस के अधीन कानून को लागू करने और जल प्रदूषण पर निगाह रखने के लिए प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया।

## गंदगी

सड़क पर मुदा

कह रहा

'मजन

'दूसरा

'देवी न हो

आखिर दे

देवी के लि

मजन से

'शोभा हो

हो जायेगी

अस्तित्व

वहस

सड़क पर

अच्छा नहीं

हुआ चल

में है कि ह

शर्मा जी

खुला तो दे

पर तिलक

कान में अ

देख कर

परी तरह

ही कहते

हैं। लौटने

इस बोर्ड

मुकद्दमे च

दंडित कर

विभाग के

स्थापना लि

सचिव डॉ.

यान के ब

बनाये गये

खुशू लाये

हाल में ही

गांधी को

को बचाने

पेड़ पौधों

'गोल्डन 3

उपाधि से

स्वयं भारत

को सम्मान

को बचाने

गुणा को:

जिम्मेदारी

दिनों विधा

की समस्य

मंत्रालय व

सचमुच बहु

दिनमान



## चरचे और चरखे

### गंदगी, शोर और पाखंड

सड़क पर दो आदमी खड़े बहस कर रहे थे। मुद्दा भजन और देवी को ले कर था। एक कह रहा था—

‘भजन न हो तो देवी का मतलब क्या है?’

दूसरा कह रहा था—  
‘देवी न हो तो भजन का मजा ही किरकिरा है। आखिर देवी के सामने ही भजन किया जाता है। देवी के लिए ही भजन बना है। देवी की शोभा भजन से ही है।’

‘शोभा होने से कोई चीज मुख्य वस्तु से बड़ी हो जायेगी। वह देवी ही है जिस से भजन का अस्तित्व है।’

बहस आगे चल रही थी। स्तंभकार को बीच सड़क पर दो आदमियों की बहस में टांग अड़ाना अच्छा नहीं लगा। शर्मा जी की ओर यह सोचता हुआ चल पड़ा कि देश कितने पवित्र माहौल में है कि हर मुख पर भजन और देवी की चर्चा है। शर्मा जी के कमरे का दरवाजा बंद था। जब खुला तो देखा शर्मा जी रामनामी ओढ़े, ललाट पर तिलक लगाये, रुद्राक्ष की माला पहने कान में अगरबत्तियाँ ठूँसे खड़े हैं। इस हालत में देख कर लगा लौट चले। अब इनका दिमाग भरी तरह फिर गया है। अभी तक उल्टी बातें ही कहते थे, अब उल्टी हरकतों पर उतर आये हैं। लौटने लगा तो आवाज आयी—

इस बोर्ड ने लगभग 100 कारखानों पर मुकद्दमे चलाये। जिनमें से केवल चार को ही दंडित करवाया जा सका। यह बोर्ड पर्यावरण विभाग के अधीन काम करता है, जिस की स्थापना पिछले साल ही की गयी। इस के पीछे सचिव डॉ. कासिम थे, जो एंटाकटिका अभियान के बाद सागर विकास विभाग के सचिव बनाये गये और उन की जगह लखनऊ के डॉ. खुशू लाये गये हैं। (देखें डॉ. खुशू से भेंट) हाल में ही हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को नीदरलैंड के प्रिंस बर्नहार्ड ने बाघ को बचाने और भारतीय जीव-जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के कदम उठाने के लिए ‘गोल्डन आर्क’ और ‘कमांडर’ की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया है। इससे पहले को सम्मानित कर चुकी है। जैसे कि हिमालय गंगा को। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की दिनों विधायकों के एक सम्मेलन में पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की माँग की गयी थी। जिस की सचमुच बहुत जरूरत है।

दिनमान



‘जाते कहाँ हो हजरत, अभी खाली हुआ जाता हूँ।’

ध्यान से देखा तो कोने में बैठा एक चित्रकार इस धज में उन की छवि आँक रहा था। हैरत में पड़ा देख बोले—

‘भारत माता का चित्र देखा है? यह भारतपिता का चित्र है। मैं उसके इस रूप का प्रचार चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ कि भारत यही है जैसा मैं देख रहा हूँ।’ स्तंभकार ने गौर से देखा, हिचकते हुए पूछा—‘इतना बड़ा मुँह क्यों बाये है?’ ‘सब कुछ पेट में समो लेने के लिए। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने भी मुँह खोल कर विराट रूप दिखा दिया था। तुम भी देखो दीखता है कुछ?’ ‘कुछ नहीं।’

‘गौर से देखो गंदगी भरी है गंदगी—झूठ, गाली, डींग सब भरा है इस में। मैं चाहूँ तो तुम्हें हजार गालियाँ दे कर कह सकता हूँ कि मेरी राजनीति संसार में सब से शुद्ध पवित्र राजनीति है और मैं हरयाणा ही नहीं, इस देश को परसों ही अमेरिका और रूस से कहीं ज्यादा विकसित देश बना दूँगा।’

‘और यह कान में अगरबत्तियाँ?’ ‘यह अगरबत्तियाँ नहीं, लाउडस्पीकर हैं। मेरी अंतरात्मा का शोर इस से निकल रहा है। सुनायी नहीं देता। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ मैं करूँगा सब भलाई के लिए है। चाहे मैं तुम्हें गोलियों से भून डालूँ, चाहे तपासे की तरह तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूँ, चाहे तुम्हें अपने समर्थन के लिए कमरे में बंद रखूँ, खरीदने के लिए लाखों रुपये दूँ, चाहे मार मार कर मुरता बना दूँ। चिल्ला चिल्ला कर मेरी अंतरात्मा कह रही है, मैं ठीक कर रहा हूँ।’ ‘और यह रामनामी, रुद्राक्ष तिलक?’ ‘यह तो मेरा साधुरूप है। हर छल, हर ढोंग, हर

पाखंड कपट इस से दोषमुक्त हो जाता है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें गोली मार कर कह दूँ यह मुठभेड़ में मारा गया, मैं सारी घाँघली कर के किसी चुनाव में तुम्हें विधायक बना दूँ और कह दूँ निष्पक्ष निर्वाचन हुआ है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कहूँ और तुरंत घोषित कर दूँ यह आदमी मेरी बात गलत सुन रहा है, गैरजिम्मेदार अखबारवाला है और तुम्हें नौकरी से निकलवा कर अंदर करा दूँ। गंदगी, शोर और पाखंड इसी का नाम भारत है। मैं भारत की यह छवि साफ साफ छपवा कर सब के हाथों में दे देना चाहता हूँ। ताकि इसी भारत की लोग पूजा करें, भक्ति करें और इसी के लिए भगतसिंह, आजाद जैसे क्रांतिकारियों की तरह अपने को उत्सर्ग कर दें।’

स्तंभकार की समझ में काफी कुछ आ गया। बोला—

‘आप बहुत नाराज लग रहे हैं हरयाणा की घटना से?’

‘यह तो बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ जो घट रहा है उस का छोटा-सा हिस्सा है। जब धूल भरी आँधी चल रही हो तो धूल का जो कण आँख में पड़ जाता है वही करकता है, वही दुखाता है और अपने यहाँ तो जहर की आँधी चल रही है। एक एक साँस भारी हो रही है।’

‘आप भावुक हैं?’

‘इसी जुमले की मैं तुम से उम्मीद कर रहा था। यह इस युग का जुमला है जो सत्य, नाराजगी, दुख को नकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैंसते रहो, अपना स्वार्थ साधते रहो तो विवेकशील हो, नाराज होओ, दुख करो, सच कहो तो भावुक हो! अपने देश में आप जैसे विवेकशील बहुत हैं जो बड़ी से बड़ी घिनौनी बात पर भी कुछ नहीं करते, खुश रहते हैं और चहबच्चे में पैर रख कर निकल जाने पर इतराते हैं। मैं भावुक आदमी हूँ! अभी तक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़ियों की गंदगी से, ईश्वर, भाग्य, साधुओं, अखाड़ों, मंदिरों, कीर्तनों के शोर से, पैसे वालों की दया, परोपकार, दान-दक्षिणा के ढोंग से परेशान था अब आज की राजनीति की गंदगी, शोर और पाखंड से उकता गया हूँ। इसी लिए यह छवि भारत की आप सब के जेहन पर उकेर देने के लिए आतुर हूँ। यह जानते हुए भी कि यह जान कर आप चुप रहेंगे कुछ करेंगे नहीं। जैसे इस समय हरयाणा, हिमाचलप्रदेश में जो कुछ हो रहा है। उसे देख कर विवेकशील बने हुए हैं। लेकिन आशा तो है ही कि विवेक का रूप बदलेगा और कभी वह सामूहिक संगठित कर्म से जुड़ेगा। रुक जाओ जाते कहाँ हो, अब छवि पूरी हो गयी है। लेते जाओ।’

पर स्तंभकार उन्हें अलविदा कह कर चला आया।



## न्यायालयों में हिंदी पर न्यायविदों का मत

**राज**र्षि जन्मशती के वर्ष उत्तरप्रदेश सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के साथ साथ विधि और न्यायालयों में हिंदी को लागू कराने के लिए द्वि-दिवसीय अनुष्ठान किया जिस में न्यायालयों के न्यायविदों ने भी भाग लिया।

विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी के प्रचलन की समस्याएँ विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामवृक्ष मिश्र ने कहा—'जब तक शासक और शासित की एक भाषा नहीं होगी तब तक न तो सामान्य जन के मन में विधि के प्रति आदर की भावना आयेगी और न ही विधि कार्य का संपादन सुचारु रूप में हो पायेगा।' हिंदी की संवैधानिक स्थिति की ऐतिहासिक क्रम में व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि 'इस से बड़ा अपवाद क्या हो सकता है कि जिस विधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने हिंदी को सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा बनाया वह आज़ादी के तीन दशक बाद भी दयनीय स्थिति में है।' सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और हिंदी की समस्या पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 'मिश्र मिश्र क्षेत्रों के मुकदमों में क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी में आते हैं। इस से कठिनाई तो होती है किन्तु कठिनाई कोई बहाना नहीं हो सकती। हिंदी को सर्वोच्च न्यायालय में अविलंब प्रयोग में लाना चाहिए।' उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि अगर प्रादेशिक भाषाएँ नागरी में लिखी जायें तो सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में काम करना सरल हो जायेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रेमशंकर गुप्त ने कहा कि 'आज इस बात पर संतोष का अनुभव किया जा सकता है कि उत्तरप्रदेश के सभी मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समस्त कार्य हिंदी में करें और नवीनतम चुनना के अनुसार उनका अधिकतम कार्य हिंदी में हो भी रहा है। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं परंतु उन की कठिनाई दूर करने के लिए अब उन को हिंदी के आशुलिपिक प्रदान कर दिये जायें। जहाँ तक सत्र न्यायालयों और अधीनस्थ अपीलीय व्यवहार न्यायालयों का प्रश्न है उनमें हिंदी के कार्य में अभी तक यथोचित प्रगति नहीं हुई है। अब भी 30 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में नहीं किया जा रहा, व्यावहारिक रूप से उच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी का वर्चस्व अब भी स्थापित है। यद्यपि संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से हिंदी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है



राजर्षि जन्मशती समारोह पर साहित्य सम्मेलन में आयोजित गोष्ठी में न्यायविद

फिर भी कुछ असुविधाओं के कारण और कुछ आदतन अंग्रेज़ी ही मुख्य रूप से प्रयोग में आती है। हिंदी भाषी उच्च न्यायालयों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व स्थापित है क्योंकि इस संबंध में एक कठिनाई यह है कि हिंदी में दिये गये निर्णयों आदि का अधिकृत अंग्रेज़ी अनुवाद धारा 7 राजभाषा नियम के अंतर्गत रखना आवश्यक है। यह प्रावधान अनर्गल है। सभी निर्णयों के अंग्रेज़ी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस संबंध में उचित संशोधन की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 348(1) का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति गुप्त ने कहा कि 'यह एक अजीब-सी बात है कि एक ओर तो भारत संघ की राजभाषा अनुच्छेद 341(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी रखी गयी है वहीं उच्चतम न्यायालय जो उस का विशिष्ट अंग है, की भाषा अंग्रेज़ी रखी गयी है। इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है कि अंग्रेज़ी तथा हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। इस से अहिंदी भाषी राज्यों के हितों की पूरी रक्षा होगी, उन को किसी तरह हिंदी के प्रयोग करने की पाबंदी नहीं होगी।

मृतपूर्व विधिमंत्री श्यामनाथ कक्कड़ ने शिकायत की कि 'वर्तमान सरकार हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। यही कारण है कि न्यायालयों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व आज भी कायम है।' लखनऊ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाबीर सिंह ने कहा 'यह विडंबना है कि भारत की राजभाषा हिंदी है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए जिस से हिंदी सर्वोच्च न्यायालय की भी भाषा बन सके। जहाँ तक उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रश्न है वह क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर खास संदर्भों में ही अंग्रेज़ी के प्रयोग की अनुमति देनी चाहिए। अदालतों से अंग्रेज़ी हटाने के लिए कानूनी दबाव ज़रूरी

है। जब तक कानून का दबाव नहीं पड़ेगा तब तक हिंदी पूर्णरूपेण लागू नहीं हो पायेगी।'

राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नाथूलाल जैन ने कहा—'हिंदी का प्रश्न केवल हिंदी का नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न है। साथ ही न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ज़रूरी है ताकि वह हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के अनुकूल बन सके। साथ ही एक ऐसी संस्था भी बनायी जानी चाहिए जो हिंदी में विधि पुस्तकों का मौलिक प्रारूपण कर सके व उचित प्रशिक्षण दे सके।'

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल ने कहा 'हिंदी में न्यायालय का निर्णय व्यावसायिक स्तर पर अधिवक्ता प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए उन्हें मजबूरन अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है।' वहीं के न्यायाधीश महेश प्रसाद मेहरोत्रा ने कहा—'हिंदी को न्यायालयों में स्थापित करने के लिए समुचित साहित्य का प्रकाशन आवश्यक है। जब तक वह उपलब्ध नहीं होगा तब तक यह विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी।' वहीं के न्यायमूर्ति रामसूरत सिंह ने देशी मन के साथ साथ देशी चिंतन और मानसिकता के आधार पर न्यायपालिका के गठन को ऐसा बनाने पर बल दिया जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मृतपूर्व न्यायाधीश रमेशचंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 'जब तक अंग्रेज़ी को हम अपनी जातीय पहचान से बड़ी मानेंगे तब तक उस का वर्चस्व बना रहेगा।'

इस गोष्ठी का आयोजन राजर्षि टंडन जन्मशती समारोह के अंतर्गत हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ने किया था जिसमें प्रभात शास्त्री, कमेश्वर प्रसाद, डॉ. एस. एन. मिश्र, कल्पनाथ राय, डॉ. मोती बाबू, डॉ. श्रद्धा कुमारी, डॉ. कृष्ण बहादुर आदि विधि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

—लक्ष्मीकांत वर्मा



उन्नीसवीं पुण्यतिथि (27 मई) पर  
नेहरू के खोजे हुए भारत की खोज  
तीन भिन्न विचारधाराएँ

## विशाल जनसमूह के सामने स्वागत भाषण

डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल

**श्री** जवाहरलाल नेहरू के भारत शोध, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी 'डिस्कवरी आफ इंडिया' के लिए 'हिंदुस्तान की कहानी' कहा है—उसको इतिहास कहना कदाचित अनुचित होगा, क्योंकि यह इतिहास की तरह मात्र एक इतिहास नहीं है। यह भारतीय जाति की अस्मिता की खोज है और शोध भी। साथ ही इस जाति के मूल स्रोतों, बुनियादों की जाँच पड़ताल के साथ इसके इतिहास की यह प्रथम और उत्कृष्ट व्याख्या है। जब से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ, तब से स्वभावतः भारतवर्ष के लोगों में अपने एक ऐसे इतिहास की इच्छा बढ़ी जो साधारणतः ऊपरी तौर वाला इतिहास ग्रंथ न हो कर हमारी जाति, हमारे अतीत को इस प्रकार खोजबीन कर सामने रखता कि हमें अपने भारत देश का पूरा-समग्र चित्र मिलता। साथ ही हमें अपने प्राचीन गौरव तथा सांस्कृतिक दाय का पूरा भास मिल सकता। यही अति महत्वपूर्ण काम नेहरू ने किया।

इससे पूर्व विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गयीं जितनी पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलीं, उनसे यही प्रकट होता था कि अंग्रेजों के आने के पूर्व यहाँ 'भारतवर्ष' ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं। यह तो अंग्रेजों की कृपा हुई कि उन्होंने हमारे लिए भारतवर्ष का निर्माण किया। ऐसी असंख्य पुस्तकों द्वारा अपने भारत देश के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् हम में से प्रत्येक को 'भारत का शोध' स्वयं करना पड़ता था।

इस तरह 'भारत वर्ष की कहानी' वास्तव में हम सबके लिए नेहरू की एक साहसपूर्ण तीर्थयात्रा और शोधयात्रा दोनों है। इसमें हमें भारतवर्ष के संपूर्ण, समग्र सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विकास के प्रति तर्कवादी मार्कसीय परंपरा की एक आधुनिक मेधा को सार्थक

शक्तिशाली प्रतिक्रिया मिलती है।

इसकी प्रमुख खोज यह है: भारतवर्ष की अपनी यह विशेषता है कि यह देश सदा उन अंतरराष्ट्रीय संपर्कों पर लगातार जोर देता रहा, जो उसके इतिहास के अभिन्न अंग बने रहे और बनते गये। नेहरू की कल्पना में भारतवर्ष की जो तस्वीर है उसकी पृष्ठभूमि मुख्यतया एशियाई है। भारत देश एशिया की सभ्यता की एक अनिवार्य कड़ी है। अतएव 'हिंदुस्तान की खोज' शुरू करते ही—अर्थात् हिंदुस्तान के अतीत की सभ्यता, हिंदुस्तान की मजबूती और कमजोरी, भारतमाता, भारत की विविधता और एकता, हिंदुस्तानी संस्कृति का अटूट क्रम, संस्कृति की जीवनशक्ति और स्थिरता आदि इन प्रारंभिक खंडों में सहज ही नेहरू का यह मंथन उभर कर आता है: 'यह हिंदुस्तान क्या है, जो मुझ पर छाया हुआ है और मुझे बराबर अपनी तरफ बुला रहा है और अपने दिल की किसी अस्पष्ट पर गहराई के साथ अनुभव की हुई इच्छा को हासिल करने के लिए काम करने का उत्साह दिला रहा है? अगर हम उसके भौतिक और मौगोलिक पहलुओं को छोड़ दें तो आखिर यह हिंदुस्तान है क्या?... ज्यों ज्यों मैंने इस बात का अनुभव किया कि हिंदुस्तान का और मुल्कों से अलग थलग रहना अनुचित है और असंभव भी, मेरा ध्यान इस प्रश्न के अंतरराष्ट्रीय पहलू की ओर बराबर जाता रहा।'

भारतीय जीवन तथा सभ्यता की एशियाई पृष्ठभूमि तथा एशियाई सभ्यताओं का परस्पर संबंध नेहरू की प्रधान चिन्ताधाराओं में से है। दक्षिणपूर्वी एशिया तथा बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार और चीन तथा सुदूर पूर्वीय देशों के जीवन में भारतीय बौद्ध धर्म की देन को नेहरू एशियाई सभ्यताओं के अंतः संबंध का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। नेहरू की चिन्ताधारा का यह पहलू एशिया की समकालीन इतिहास प्रगति का सूचक है। अखिल एशिया सम्मेलन के आयोजन अथवा एशियाई देशों की स्वतंत्रता के समर्थन की मूल प्रेरणा का स्रोत हमें यहाँ दिखता है और जिसकी प्रेरणा से नेहरू बार बार हिंदेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, उस सत्य के अनेक सुंदर उदाहरण इस 'खोज' में मिलते हैं।

नेहरू सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्यों के आगमन से लेकर ईरान, चीन, यूनान, अरबी सभ्यता और अंग्रेजों के संपर्क तक एक महत्वपूर्ण तथ्य सर्वत्र बराबर खोज रहे हैं कि इस देश में कहां तक कैसे एक साहसिक खोज यात्रा का, एक नयी दुनिया में प्रवेश करने का उत्साह और जिज्ञासा थी? वह अपनी 'खोज' में अबाध और अगाध रूप से यही ढूँढ़ रहे हैं कि किसी देश या राष्ट्र के हृदय में भविष्य के प्रति कितनी आशा और विश्वास है।

नेहरू सर्वदा भविष्य ही को महत्वपूर्ण समझते रहे हैं। विगत पाँच हजार वर्षों की कहानी, नेहरू के मानस में, उसी भविष्य की भूमिका प्रदान करती है। नेहरू की जो विचारधारा इस खोज के भीतर लगातार चलती रहती है, वह यह है कि मुख्य वस्तु अतीत नहीं भविष्य है। भविष्य की योजनाएँ हैं। किसी मर चुकी सभ्यता का वर्णन केवल अतीत तक ही सीमित रहेगा, "पर एक जीवित राष्ट्र के अतीत का वर्णन कितना ही गौरवपूर्ण तथा स्फूर्तिप्रद क्यों न हो, अंततः वह सब भूमिका मात्र है।"



नेहरू की समाधि पर सपरिवार श्रीमती इंदिरा गांधी : 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि



यह है नेहरू की इतिहास दृष्टि भारत की खोज में वास्तविक महत्त्व, नेहरू के विचार से जीवित वर्तमान तथा आने वाले भविष्य का है। इस संदर्भ में यह उद्धरण नेहरू की दृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है—

... कहा जाता है कि भारत धार्मिक है, दार्शनिक आध्यात्मिक है, कि वह सांसारिक चिन्ता से परे, भविष्य तथा परलोक की कल्पनाओं में डूबा रहता है। ऐसा ही हमें सिखाया जाता है, और शायद ऐसा सिखाने वाले यह भी चाहते हैं कि भारत अब भी विचार तथा कल्पना के इस सागर में डूबा रहे, ताकि इन कल्पनालोकवासियों से छुट्टी पा कर वे संसार का प्रभुत्व प्राप्त कर सकें और उसके सुख भोग सकें। भारत अवश्य ऐसा भी रहा है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ रहा है। उसने शैशव-काल का भोला अल्हड़पन, युवावस्था का उन्मुक्त आत्मदान तथा सुख-दुःख के लंबे अनुभव से प्राप्त होने वाला विदग्ध और परिपक्व ज्ञान, सभी जाना है। और बार बार इस शैशव, यौवन तथा वार्धक्य के चक्र को फिर चलाया है। युगभार और विस्तार से आक्रांत होकर वह कुप्रभावों तथा रुढ़ियों का शिकार हुआ; कितने परोपजीवियों ने उसका रक्त चूसा, पर इस सब से नीचे उसकी युगों युगों से शक्ति तथा एक प्राचीन जाति का अवचेतन विवेक बना रहा। ... उसकी प्रचंड जीवनशक्ति युगों से उसकी कला और वाङ्मय में प्रवाहित होती रही है। यद्यपि उसका अल्पांश ही हमें प्राप्त है और बाकी मानवीय बर्बरता या प्रकृति द्वारा विनष्ट किया जा चुका है। एलिफेंटा की गुफाओं की 'त्रिमूर्ति' मानो भारत की ही बहुमुखी प्रतिमा है—समर्थ, दीप्तचेतन, और ज्ञान विवेक योग। ...

श्री नेहरू द्वारा खोजे हुए भारत में सिंधु सभ्यता के युग से, जबकि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का पहला पन्ना खुलता है, अगस्त उन्नीस सौ ब्यालीस तक की कहानी आयी है। यह 'कहानी' नेहरू ने अहमदनगर किले के जेलखाने में, अप्रैल से सितंबर उन्नीस सौ चौवालीस के पाँच महीनों में लिखी थी। यह वह समय था जब कि कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 'भारत छोड़ो' का नारा उठाया था। उस परिस्थिति और उस मनःस्थिति में नेहरू ने जो खोज भारत देश और यहाँ की जाति के विषय में की, उसकी रूपरेखा पर आज के पाठकों और विशेषकर हमारी नयी पीढ़ी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

नेहरू ने जिस तरह हिंदुस्तान के अतीत का विहंगमालोकन किया है—उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की विविधता और एकता, हिंदुस्तान की मजबूती और कमजोरी की खोज पर अपनी निगाह रखी है। यह खोज नेहरू का 'हृदयमंथन' है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर चंद्रगुप्त, चाणक्य और अशोक तक के भारत को नेहरू ने 'हिंदुस्तान की खोज' की संज्ञा दी है। गुप्तकाल में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद से लेकर तेरहवीं सदी तक के हिंदुस्तान के मूल्यांकन को नेहरू ने 'युगों का चक्र' माना है। इस युग में उन्होंने हिंदुस्तान की उत्साह से भरा हुआ और दूर दूर तक फैला हुआ पाया है। और यह देखते हैं कि वह न केवल अपने विचारों बल्कि दूसरे आदर्शों, अपनी कला, अपने व्यापार, अपनी भाषा और साहित्य तथा अपने शासन के ढंग को सब जगह ले जाता है। हिंदुस्तानी सभ्यता ने विशेषकर दक्षिणी पूरबी एशिया के देशों में जड़ पकड़ी, और इसका प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंग्कोर, श्रीविजय, इंदोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, फिलीपीन, कंबुजिया में सर्वत्र हिंदुस्तानी कथाएँ, गथाएँ, कलाएँ, विधाएँ भरी पड़ी हैं, 'युगों के इस चक्र में हिंदुस्तान ने बहुत चढ़ाव और उतार देखे हैं। लेकिन इससे पूर्व कि वह सुनहला काल समाप्त हो, भारत के जीवन में कमजोरी और ह्रास के चिन्ह दिखायी देने लगते हैं।' नयी समस्याएँ आती हैं।

नेहरू के दिमाग के हिसाब से वे 'नयी समस्याएँ' थीं—अरब और अंगोल, अरबी सभ्यता से हिंदुस्तान के संपर्क से लेकर इस देश में अंग्रेजों के आगमन तक की ये सच्चाइयाँ, 'जिनके सामने ऐसा जान पड़ता है कि इस भयानक युग में लोग साधारणतया पस्त और कुचले हुए थे। दुर्भाग्य

के चक्र को चुपके से सहन कर लेते थे। एक चकाचौंध और उदासीनता का उन पर आलम छाया हुआ था।'

इस देश में अंग्रेजों की शक्ति प्रतिष्ठा को नेहरू ने 'साम्राज्य की विचारधारा' की स्थापना का चरण सिद्ध किया है। 'इंग्लिस्तान हिंदुस्तान में आया। सोलह सौ में, जब रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवान दिया। उस समय शेक्सपीयर जीवित था और उसका लिखना जारी था। एक इंग्लिस्तान था—बाइबिल, इंजील, मिल्टन शेक्सपीयर और रॉयल सोसाइटी का, दूसरा इंग्लिस्तान था हेंडन क्रॉमवेल और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने वाली पूँजीवादी साम्राज्यवादी का। ये दोनों इंग्लिस्तान एक दूसरे पर प्रभाव डालते-हुए साथ साथ आये भारत में। यह वही समय था जब संयुक्तराज्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी और हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता खो रहा था। तब से लेकर 'भारत छोड़ो' तक नेहरू ने 'अंतिम दर्शन' कहा है अपनी यात्रा का नेहरू का यह 'अंतिम दर्शन' हमारी जाति, हमारे बोध भाव को गहरी इतिहास दृष्टि देता है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की दृष्टि में जो वदमाश था वह हिंदुस्तानियों के लिए अक्सर एक शूरवीर होता था और वे लोग जिन्होंने अंग्रेजों ने प्रसन्न हो कर सम्मान दिये, अधिकतर हिंदुस्तानियों की दृष्टि में देशद्रोही रहे और वह कलंक उनके वारिस पर लग जाता है।

नेहरू ने इस सच्चाई को खोजा है कि कैसे हिंदुस्तान पर पश्चिम संस्कृति का आघात, 'एक गतिशील समाज' और 'आधुनिक चेतना का एक ऐसे गतिहीन समाज पर आघात था जो मध्ययुगीन विचारधारा से



लक्ष्मीनारायण लाल  
लेखक, विचारक

बँधा हुआ था और जो अपने ढंग से कितना ही उन्नत, या रंगा चुना हो अपनी जन्मजात वृद्धि के कारण उन्नति नहीं कर सकता था।' हिंदुस्तान के उद्योग धंधों और खेती की बरबादी, इस देश का राजनैतिक और आर्थिक हैसियत पहली बार एक दूसरे देश का पुछल्ला बनने हिंदुस्तान में ब्रितानी राज्य के विरोधाभास—इन संदर्भों में नेहरू की निगाह बड़ी तेज है। एक तरफ वह देखते हैं कि 'पश्चिम की असली टक्कर हिंदुस्तान से उन्नीसवीं सदी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी धक्का लगा और परिवर्तन हुआ और वह क्षितिज जो बहुत समय से एक सँकरे खोल में घिरा हुआ था विस्तृत हुआ।' दूसरी तरफ नेहरू यह भी देखते हैं कि 'हिंदू धर्म की सामाजिक प्रथाओं और रीतियों से असंतोष के कारण बहुत से हिंदू, ईसाई धर्म की ओर खिंचे' और बंगाल में राजा राममोहन राय ने इस बात का प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म को इस नये वातावरण के अनुरूप बनाया जाये। पर इस से अलग दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद और स्वामी दयानंद ने जिस भारत की खोज की उस ओर नेहरू ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। क्यों?

मध्य वर्ग की बेबसी से गांधी जी के आगमन का प्रसंग जोड़ के नेहरू गांधी के पूरे व्यक्तित्व को कहीं सीमित कर रहे थे, या गांधी को पश्चिमी मानस से समझने की कोशिश कर रहे थे, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तरफ नेहरू गांधी जी को 'ताज्जी हवा', 'अंधकार', 'रोशनी की किरण' के रूप में देख रहे थे, जिसने हमारी आँखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। दूसरी तरफ नेहरू गांधी जी को उस 'बवंडर' की तरह से देख रहे थे जिसने बहुत सी 'चीजों', 'विचारों' को उलटपुलट दिया। 'डरो मत' की आवाज दे कर गांधी जी ने लोगों के ऊपर से डर का काला लबादा हटा दिया।

गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक गतिशील संस्था, अल्पसंख्यकों के प्रश्न कांग्रेस और युद्ध, भारत की आजादी या स्वतंत्रता की लड़ाई—इस संबंध में नेहरू और गांधी के बीच में स्पष्ट कठिनाइयाँ थीं और इस संबंध में 'हमने गांधी जी से विस्तारपूर्वक बहस की। लेकिन हम एक दूसरे की राय न बदल सके। कठिनाइयाँ थीं और सक्रियता निष्क्रियता की



में ही भय था, जोखिम थी। अब सवाल उन में समतोल लाने का था और उन में से कम बुरी चीज को चुनना था। संसार के एक बड़े विचारक ने एक बड़ी बात कही है—'अगर दो बुराइयों में से छोटी बुराई को ही चुनने की स्थिति आये तो भी मैं दोनों में से किसी को भी नहीं चुनूंगा। बुरी चीज में जो कम बुरी चीज है उसको चुनने की नेहरू की विवशता एक कष्ट घटना है भारत की खोज की दिशा में। गांधी जी बड़ी बात की निष्ठावान जिदगी में विश्वास करते थे और वही जीवन जिया उन्होंने। वह पश्चिम की आधुनिक जिदगी के मूल्यों से बिल्कुल अलग थे। गांधी साक्षात् स्वयं भारतवर्ष की आत्मा थे। नेहरू—आधुनिक नेहरू एक श्रेष्ठ भारतीय थे, पर वह भारतवर्ष की आत्मा को 'खोज' रहे थे।

नेहरू के खोजे हुए भारत से नेहरू व्यक्तित्व के मुख्य तत्त्व जो उमरे हैं वे हैं उनकी अंतरराष्ट्रीयता, विश्व की भूमिका पर भारत की अपनी छाप, वर्तमान में परिणत हो कर भविष्य की ओर प्रवाहित होते हुए अतीत की उनकी अपनी परिकल्पना, तथ्यों पर अपना अधिकार, भारत के प्रति केवल उज्ज्वल और गौरवमय पक्ष देखने वालों के प्रति उनका घोर असंतोष, उनकी सजग राष्ट्रीयता तथा निर्मल आस्था।

ऐसे व्यक्तित्व द्वारा जिस भारत की खोज हुई है उस का चित्र ऐसा बनता है: पूर्व का आदर्श रहा है कुटुंब के धर्म को ही राष्ट्र में प्रसारित करना, जो कि सम्यता के आदर्श का आधार है। पश्चिम के आदर्श में व्यक्ति की परिकल्पना का चरमोत्कर्ष है कर्तव्य की भावना और अधिकार की भावना। पूर्व का आदर्श रहा है कर्तव्य-अधिकार दोनों का पूरक होना। इसी में पूर्व को संतुलन मिलेगा और पश्चिम में अशांति कलह का अंत होगा। पूर्व को पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम की अपेक्षा रहेगी। भारत एशिया का हृदय है। भारत की सम्मति और अपनी भव्य परंपरा और उच्च आदर्शों के कारण उस का सहयोग, पृथ्वी की सब जातियों के कल्याण के लिए चरम महत्व रखता है।

दूसरी ओर नेहरू ने जिस भारत को खोजा है उस से नेहरू के व्यक्तित्व का दुर्चित्तापन प्रकट होता है। ऐसा लगता है—हैमलेट की भांति नेहरू विशाल जनसमूह के सामने स्वगत भाषण करने लगते हैं। भारत के भविष्य के बारे में नेहरू द्विधाग्रस्त हैं—अस्थिर चित्त हैं। वह एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम के बीच दुभाषिये हैं। वह भारतीय हैं, पर उनका मुहावरा पारचात्य है, जिससे पश्चिम के लोग और भारत के अंग्रेजीवादी ही उन्हें आसानी से समझ पाते हैं शेष लोग केवल भारतभाता जय, नेहरू की जय के नारे लगाते रह जाते हैं। □



पालम हवाई अड्डे पर नेहरू (1960)

फोटो : रंगास्वामी सदगोपन

## यह 'इंदिरा विरोधी क्लब' की साजिश है

श्रीकांत वर्मा

औरों ने प्राचीन भारत की खोज की। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की। उन्होंने आधुनिक भारत की संरचना के लिए जिन मूल्यों को आवश्यक माना वे हैं सर्व धर्म समभाव, लोकतंत्र पर आधारित समाजवाद, विज्ञान और टेक्नालॉजी, औद्योगिक सम्यता, और गुट-निरपेक्ष विदेशनीति।

लगभग 25-30 वर्ष तक इन्हीं मूल्यों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। देश की सर्वतोन्मुखी प्रगति हुई। खेती उद्योग विज्ञान और टेक्नालॉजी, जाति और धर्म की बराबरी, उद्योगों के जबरदस्त विकास और संसार में एक नेकनीयत तथा गुटनिरपेक्ष देश के रूप में भारत की अपार प्रतिष्ठा। एक तरह से भारत संसार का एक विशिष्ट देश बन गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1975 तक श्रीमती गांधी ने इन मूल्यों को तथा जवाहरलाल नेहरू के स्वप्न को न केवल बरकरार रखा बल्कि उन्हें बढ़ाया। श्रीमती गांधी के शासनकाल में ही भारत में विज्ञान और टेक्नालॉजी ने अपूर्व सफलताएँ प्राप्त कीं, उद्योगों का और भी अधिक विकास हुआ। मुद्रास्फीति समाप्त हुई और देश की अखंडता कायम हुई। इतिहास में बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत की अखंडता को इस तरह कायम रखा है जिस तरह कि श्रीमती गांधी ने। इतिहास में केवल एक उदाहरण और मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जिसने भारत की अखंडता को कुछ इस तरह कायम किया कि फिर उसे सैकड़ों वर्षों तक चुनौतियाँ नहीं दी जा सकीं।

गुटनिरपेक्षता के क्षेत्र में भी श्रीमती गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की नीति को ही आगे धड़ाया। बीच के कुछ वर्षों में नेहरू, नासिर और टीटो की मृत्यु के फलस्वरूप गुटनिरपेक्षता का आंदोलन कमजोर हो गया था। इंदिरा गांधी ने दूरदृष्टि का सहारा लेते हुए गुटनिरपेक्षता के आंदोलन को पुनर्जीवित किया और आज फिर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज सुनी जाने लगी है। उसकी आवाज अब नक्कारखाने में तूती की आवाज नहीं रही।

जहाँ तक सर्व धर्म समभाव का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी ही इसकी सबसे बड़ी प्रवक्ता है और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही देश में बहुत हद तक सर्व धर्म समभाव बरकरार है। अन्यथा देश में ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि रातों रात खून की नदियाँ बहा दें।

क्या विडंबना है कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल में उनके सबसे बड़े विरोधी थे तथा जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और मूल्यों का कटुतम विरोध किया वे आज नकाब ओढ़ कर जवाहरलाल नेहरू के अलबरदार बन गये हैं और यह कहते फिरते हैं कि नेहरू के मूल्यों और आदर्शों को वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी स्थगित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की शकल में छिपा हुआ जनसंघ कब से सर्व धर्म समभाव का हिमायती बन गया? हिंसा, तोड़फोड़ और डिक्टेटरशिप में प्रबल आस्था रखने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कब से लोकतंत्र में यकीन करने लगी? दरअसल इंदिरा गांधी के विरोधी बुद्धिजीवियों और राजनीतिकों का एक 'क्लब' बन गया है जो कि जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में यह झूठ फैलाना चाहते हैं कि उनका नेहरू के आदर्शों में यकीन नहीं। यही वह क्लब था जिसने कि 1977 में तमाम दूतावासों से



## आवरण कथा

और सरकारी कार्यालयों से जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर उतरवा दी थी। यही वे लोग थे जो 'असली गुटनिरपेक्षता' के नाम पर भारत की विदेशनीति की बुनियाद को ही नष्ट करना चाहते थे। यही वे लोग थे जिनके अनुयायियों ने अलीगढ़ और जमशेदपुर में सांप्रदायिकता की एक ऐसी आग मड़कायी जिसे बुझाना मुश्किल हो गया। यही वे लोग थे जो खेती के विकास के नाम पर तमाम औद्योगिक विकास को अवरुद्ध कर देना चाहते थे। उन्होंने इतने सरल प्रश्न को भी समझने की कोशिश नहीं की कि खेती और उद्योग का विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। औद्योगिक विकास के बिना खेती का विकास संभव नहीं। अगर ट्रैक्टर और सिंचाई के आधुनिक उपकरण नहीं होंगे तो खेती का विकास संभव नहीं। यही वे लोग थे जिन्होंने कि लोकतंत्र को ताक पर रख कर इंदिरा गांधी को जेल में डाला और उनकी संसदीय सदस्यता को रद्द किया। यही वे लोग थे जो प्रतिहिंसा में इस कदर पागल हो गये कि उन्होंने इंदिरा गांधी के परिवार को नष्ट ही कर डालना चाहा। और यही वे लोग थे जिनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस कदर बौरा दिया कि उनकी सरकार 3 वर्ष भी चलने नहीं पायी।

इंदिरा गांधी को लोकतंत्र विरोधी करार देने के पहले इंदिरा विरोधी क्लब को यह सोचना चाहिए कि यदि 1977 में श्रीमती गांधी ने चुनाव नहीं कराये होते तो वे कहाँ होते? उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि 1980 में सत्ता में आने के बावजूद श्रीमती गांधी ने उन पर एक भी मुकद्दमा नहीं चलाया जब कि इन में से थोड़े ही लोग होंगे जिनके कपड़े काजल की कोठरी में काले नहीं हुए होंगे। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि यदि श्रीमती गांधी सचमुच अधिनायकवादी हैं तो वे लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज भी विरोधी दलों से या उनके प्रतिनिधियों से क्यों परामर्श करतीं। 1977 से 1980 के बीच अर्थात् जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान उस समय की सरकार ने कितनी बार विरोधी पार्टियों के साथ सलाह मशविरा किया?

देश आज भी जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर न केवल चल रहा है बल्कि तरक्की कर रहा है और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बरकरार रखा, श्री चरणसिंह या मोरारजी देसाई ने नहीं। चरण सिंह तो पहले भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और आदर्शों के विरोधी थे और अब भी उनके विरोधी हैं। इसलिए उनकी बात कुछ समझ में आती है। कम से कम उनमें पाखंड नहीं है, समझ की कमी जितनी भी हो लेकिन मोरारजी देसाई जैसे लोगों की बात समझ सकना कठिन है जो एक ओर तो जवाहरलाल नेहरू का दबी जुवान से नाम लेते हैं और दूसरी ओर न केवल नेहरू की तस्वीरों को उतरवाते हैं और उनकी होली जलाते हैं बल्कि नेहरू के आदर्शों को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं रखते।

राजनीति से हट कर अगर कुछ बातें की जायें तो इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि क्या आज देश की सामाजिक स्थिति वही है जो कि जवाहरलाल नेहरू के युग में थी? उस समय राजनीति पर प्रबुद्ध वर्ग हावी था। संसद सदस्यों में से अधिकतर नगरों के प्रतिनिधि होते थे, वकील, डाक्टर, पत्रकार, इंजीनियर या अन्य पेशे के लोग। लेकिन इधर कुछ वर्षों में गाँवों में जागरण हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में नयी नयी जातिर्या उपजातिर्या और नये नये वर्ग उपवर्ग उभर कर आये हैं। संसद में भी आज उनके प्रतिनिधियों की तादाद ज्यादा है। उनके सोचने समझने का तरीका भी काफी हद तक अलग है। इसलिए संसद की सूरत बदली नजर आती है लेकिन जहाँ तक नेहरू के बुनियादी आदर्शों और

स्वरूप का प्रश्न है वर्तमान सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने उनमें से किसी को भी आघात नहीं पहुँचाया है, बल्कि उनको आगे भी बढ़ाया है।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को सबसे अधिक क्षति श्री जयप्रकाश नारायण ने पहुँचायी। यद्यपि जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर बहुत वर्षों तक चलते रहे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में किन्हीं अज्ञात कारणों से, जिन्हें कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने उन शक्तियों के साथ समझौता कर लिया जो कि सांप्रदायिकता, तोड़ फोड़, हिंसा को वर्षों से बढ़ावा देती रही थीं और जिनका लोकतंत्र में कतई यकीन नहीं था, उनके सहयोग से श्री जयप्रकाश नारायण ने 1975 में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आपातस्थिति लागू करनी पड़ी। यदि आपातस्थिति लागू हुई तो इस के लिए भी मैं श्री जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों को ही जिम्मेदार मानता हूँ। और यदि आपातस्थिति उठी तो इसका श्रेय किसी को नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी को ही है। यदि इंदिरा गांधी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं होता तो आपातस्थिति कैसे समाप्त होती, यह बुद्धिजीवियों और विरोधी राजनीतिकों को सोचना चाहिए। द्वेष और पूर्वाग्रह को रखते हुए हम कभी भी सही निष्कर्षों पर नहीं पहुँच सकते। □

## नेहरू के सामने विकल्प था...

सुरेंद्र मोहन

पंडित नेहरू वन संपदा के प्रेमी थे। अधिक पेड़ों को लगाने के अभियान पर बल देते थे। किंतु गत 32 वर्षों में वन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 37 प्रतिशत से घट कर 31 प्रतिशत पर आ गया है। आधुनिक सौंदर्यकरण को बढ़ाने वाला हर एक कदम उनके सौंदर्यबोध का उपहास ही करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को उन्होंने ऐतिहासिक ज़रूरत बताया था। किंतु, एक ही व्यक्ति में पूरी राजनैतिक सत्ता केन्द्रित हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे जनता का प्रतिशत लगभग उसी परिमाण में बढ़ता जा रहा है, जिस परिमाण में पंचवर्षीय योजनाओं का आकार।

स्वतंत्र भारत को उनका सब से पहला आह्वान मिला था— उत्पादन करो अथवा विनाश होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए और पिछड़ेपन, दारिद्र्य और परनिर्मरता से बचने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था चाहिए। नेहरू के साथ समूचे राष्ट्र ने आर्थिक नियोजन का स्वागत किया। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की गयी। यूरोप और अमेरिका के अतीव उद्योगीकृत देशों की होड़ में बहुत बड़े बड़े कारखाने बनाने का लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया और काल के भारी अंतर को पाटने का भी प्रयास किया गया। यह तो स्पष्ट ही था कि सार्वजनिक क्षेत्र के गतिमान विस्तार के द्वारा ही यह संभव हो सकता था। अफसरशाही का उसी परिमाण में प्रसार भी हुआ। पूँजीकरण ज़रूरतों के फलस्वरूप जनता के ऊपर मुद्राप्रसार और करों का भार बराबर बढ़ता रहा, जनता को राष्ट्र की प्रगति के लिए उस भार को वहन करना पड़ा और लागत और बचत को अधिकतम बनाने की स्पर्धा में जनसाधारण के जीवन स्तरों में गिरावट आयी।

स्वयं पं. नेहरू ने 1960 के आसपास यह विवाद उठाया कि जो पूँजी पैदा होती है वह कहाँ जाती है। एकाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। उस की सिफारिशों के आधार पर निजी क्षेत्र पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये गये। किंतु तीव्रतर उद्योगीकरण की होड़ में निजी क्षेत्र का सहयोग अपरिहार्य माना गया ताकि राष्ट्र की समूची पूँजी व्यावसायिक प्रतिभा और प्राविधिक योग्यता को एक साथ जोड़ा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र ने उद्योगीकरण के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार किया। इससे



श्रीकांत वर्मा : इका के प्रचार संयोजक



से किसी  
या है।  
आदर्शों  
को। यद्यपि  
के आदर्शों  
ही अज्ञात  
वित्तियों के  
हिस्सा को  
कीन नहीं  
एक ऐसी  
आपात्-  
यण और  
पातस्थिति  
ही है। यदि  
स्थिति कैसे  
सोचना  
तर्कों पर  
□

था...

लगाने के  
क्षेत्र का  
आधुनिक  
उपहास  
क ज़रूरत  
त हो रही  
रिमाण में  
आकार.  
ला था—  
पिछड़ेपन,  
अर्थव्यवस्था  
गत किया।  
अमेरिका  
वनाने का  
र काल के  
पष्ट ही था  
व हो सकता  
पूँजीकरण  
का भार  
स भार को  
वनाने की

या कि जो  
की स्थापना  
हुछ प्रतिबंध  
जी क्षेत्र का  
व्यवसायिक  
सार्वजनिक  
रा. इत्यादि  
विनयान

विद्युत शक्ति और बड़े भारी कलपुर्जों के निर्माण में प्रगति हुई। इस बुनियादी ढाँचे को निजी क्षेत्र ने इस्तेमाल किया और अपना विपुल प्रसार किया। अर्थव्यवस्था पर सरकार ने अपने नियंत्रण को कसने और उसके नियमन को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किये। मंत्रियों और अफसरों की शक्ति बढ़ी। इन सब के साथ साथ बड़ा उनका और धनपतियों का मेलजोल। काला बाजार और कालाधन बढ़े। भ्रष्टाचार ने सामाजिक व्यवहार में अपने पाँव जमाये और अरबी यात्री और उसके ऊँट की कहानी चरितार्थ होने लगी।

केंद्रीय आर्थिक नियोजन, पश्चिमी शैली की यांत्रिकी वाले उद्योगीकरण, अफसरशाही द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में एकाधिकारियों की पूँजी और अर्थसत्ता में अद्वितीय वृद्धि और राजनैतिक शिखर तक पहुँचे हुए भ्रष्टाचार के कारण संपत्ति और राजसत्ता में केंद्रीकरण बढ़ता चला गया और उसने संविधान, दलीय राजनीति और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बुनियादी प्रक्रियाओं पर अपना असर दिखाया। केंद्र के मुकाबले राज्यों के अधिकारों में कमी आयी। स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों को अफसरशाही का गुलाम बनाया गया, चुनावों में कालेधन का विपुल प्रयोग होने लगा, राजनैतिक दलों पर काले धन के उपार्जन में अधिक सफल नेताओं और मंत्रियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, सभी प्रकार के सरकारी नियमों और नियंत्रणों को सत्ता और पूँजी के केंद्रस्थ प्रभुओं की प्रभुता के पक्ष में प्रयोग किया जाने लगा, और देश की नैसर्गिक संपत्ति की भी वैसी ही अवाध लूट मची जैसा कि जन साधारण का शोषण बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करके वचत एवं लागत को भी बढ़ाना था। सेवायोजकों और मजदूरों के संघर्षों में उत्पादन को बढ़ाने, वेतनों को जाम कर के ऊँचे मुनाफों के द्वारा पूँजी निवेश के उमर उठाने और जनता की खपत मुद्राप्रसार और चढ़ते दामों की रोक लगा कर इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने की रणनीति अपनायी गयी। कृषिक्षेत्र अपेक्षया घनी बना, मजदूरों का जीवन स्तर नीचे गिरा, जनसाधारण में दारिद्र्य बढ़ा, पर्यावरण दूषित होने लगा, पूँजीपति ठेकेदारों की हविस से वन्य संपदा नष्ट होने लगी और हस्तशिल्प, कला, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग खोखली नारेबाजी के वाग्जाल के शिकार हो गये क्योंकि उनकी उत्पादन शक्ति का मुकाबला भारी मशीनों और उन मशीनों के सत्ताधारी स्वामियों अथवा प्रबंधकों के साथ था।



सुरेंद्रमोहन  
जपा सांसद

भारत जैसे कृषिप्रधान देश में भारी उद्योगों के आधार पर उद्योगीकरण और कृषि की उपेक्षा के कुछ अन्य परिणाम भी सामने आये। औद्योगिक क्षेत्र में परनिर्भरता कम हुई और खाद्यान्न के लिए हमें विदेशों का मुँह ताकने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुटीर और लघु उद्योगों, विशेषकर कृषि आधारित और वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिला। बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ी। कृषि क्षेत्र में वाद यह संभव था कि अन्य औद्योगिक देशों की तरह यहाँ भी खेती में कुछ बुनियादी परिवर्तन ले आये जाते जो कि भूमि सुधार अधिनियमों में प्रस्तुत किये गये किंतु कागजी कार्रवाईयों तक ही सीमित रहे। वास्तव में, समाज में उभरती हुई यह प्रवृत्ति कि धनीमानी लोग ज्यादा धनीमानी बनें कृषि क्षेत्र में लाखों सीमांत किसानों की बेदखली का कारण बनी और दस प्रतिशत किसान तीन चौथाई कृषि क्षेत्र के स्वामी बन गये।

वर्तमान उच्चतर मध्यमवर्ग की नैतिक मान्यताएँ और सामाजिक व्यवहार ने पूरे समाज पर छा जाने में सफलता प्राप्त की। उनके लिए विशेष अवसर, विशेष शिक्षा संस्थाएँ, विशेष स्वास्थ्य चिकित्सा या

मनोरंजन-परिवहन-आवास व्यवस्था का प्रबंध होने लगा, सार्वजनिक संस्थाओं का जाल बिछाये जाने पर भी जनता को सुविधाएँ नहीं मिलीं। इस का कारण यही था कि जिन के पास सत्ता थी वे विशिष्ट वर्गों के ही और उनकी ही ज़रूरतों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी बरतते हैं। अतः जनता के लिए जो भी परिवहन, अस्पताल और स्कूल हैं वे उपेक्षित तो हैं ही, कुप्रबंध और भ्रष्टाचार से भी ग्रसित हैं। इस प्रकार पूरे समाजतंत्र में कुलीनतंत्र की झलक बढ़ती जा रही है। इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से न्यायालय अथवा पुलिस कहाँ बच पाते ?

अतः कानून और व्यवस्था भी इस घटनाचक्र की चपेट में आ ही गये। समाज के दुर्बल वर्गों को दबा कर रखना है। जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं उन की आवाज को घोंटे रखना है। जो प्रतिरोध करना चाहते हैं, उनको खरीद लेना है या खत्म कर देना है। निर्बलों में से एक ऐसे समूह का निर्माण कर के ये कार्य सरलता से सरंजाम दिये जा सकते हैं जो अपनी दरिद्रता से तंग आ कर धनवानों के अपराधों का हथियार बन सके।

जिस देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयता की प्रवृत्तियों को कमजोर करने के लिए समभाव और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करना था, उस में विषमता, भ्रष्टाचार, दारिद्र्य, घनाढ्यों का प्रभुत्व और केंद्रीकरण बढ़ा। समाज की उदारवादी और सुधार अथवा परिवर्तनवादी प्रवृत्तियों की क्षति होने लगी और मानवीय दृष्टि पर परदा पड़ने लगा। तंगदिली बढ़ी, संकीर्णता ने दरिद्र नारायण को भी जकड़ा। विपैलापन उभर कर आया और आपसी नफरत का दौरा होने लगा। महिलाओं, हरिजनों एवं अन्य कमजोर समूहों पर विपत्तियाँ आयीं।

इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या था जो गलत हो गया ? क्या आर्थिक नियोजन ? अधिक उत्पादन की आकांक्षा ? सार्वजनिक क्षेत्र ? आर्थिक व्यवस्था पर सरकार द्वारा नियमन नियंत्रण ? अलग से, इनमें से एक भी तत्त्व न तो हानिकारक है, और न ही अनावश्यक है। फिर भी, नतीजा सामने है। संभवतः इनके साथ जिन तत्त्वों पर बल देना अनिवार्य था, उनकी नितांत अवहेलना की गयी। उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रश्न था कि उस से जनता का जीवन स्तर बढ़ा कि नहीं। न्यायपूर्ण वितरण पर बल नहीं दिया गया, दरिद्रता हटाने के नारे नारे ही रहे। बेकारी को दूर करने की कोई ठोस योजना आरंभ से ही बननी चाहिए थी। कृषि के क्षेत्र में भी समता का आधार ग्रहण करना उचित होता। जनता से विमुख होकर एक विशाल विशिष्ट वर्ग को प्रोत्साहित कर के जो विकृति पैदा होने दी गयी उस को रोकना था।

इन सभी लक्ष्यों के लिए आरंभ में क्या करना था जो जवाहरलाल जी ने नहीं किया ? उन्होंने पश्चिम यूरोप और बाद में सोवियत संघ के उद्योगीकरण को आदर्श स्वरूप समझने की गलती की। पूँजी निर्माण की बैकल्पिक रणनीति भी अपनायी जा सकती थी जिस में उत्पादन बड़ी मशीनों के द्वारा भी होता किंतु जनता के द्वारा लघु उद्योगों की प्रविधि के इस्तेमाल से उस पर अधिक बल दिया जाता। विकेंद्रीकरण को सार्थक बनाना था। पंचायतराज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सत्ताशाली बनाना था। किंतु ग्रामीण समाज को स्वावलंबी कृषि, बेरोजगार जनसमूह और लघु उद्योगों पर स्थापित संपन्नता की ठोस नींव दिये बिना उस को सुदृढ़ घरातल देना असंभव था।

जवाहरलाल जी के सामने विकल्प था कि आधुनिक विज्ञान और सामाजिक विवेक को गांधीजी की समान नैतिक मान्यताओं के साथ जोड़ें—यह संभव था कि ग्रामीण समाज के अभ्युदय कृषि के विकास, पूर्ण रोजगार, न्यायपूर्ण वितरण और संपत्ति संबंधी संस्थागत परिवर्तनों के लक्ष्यों को अधिक उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार, आर्थिक नियोजन और अर्थव्यवस्था पर जनता द्वारा नियमन के साथ समन्वित कर दिया जाता। संभव था कि आज दूसरी तस्वीर सामने होती और हमारा भारत जवाहरलाल जी के सपनों का भारत बनता। □



आमने-सामने

# मुझे तक्रल्लुफ के टूटने का इंतज़ार है

हेमवती नंदन बहुगुणा से जवाहरलाल कौल की बातचीत

गढ़वाल का गढ़ जीतने के बाद वह टकराने की मुद्रा में ही है। यह विवाद विवाद ही नहीं है। और न ही यह बात राज की है कि इस उपचुनाव को हार कर इंदिरा कांग्रेस के भीतर अजब हलचल पैदा हो गयी है, चाहे सतह पर एक स्थिर झील की तरह कितनी ही शांति दिखायी दे। इसे समझने के लिए एक सीट कम या ज्यादा का अंक गणित पर्याप्त नहीं है क्योंकि वकालत, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र इलाहाबाद में रहने वाले इस गढ़वाली का मन गढ़वाल पर ही नहीं उत्तरप्रदेश पर भी नहीं पुरे देश पर आ गया। चमोली में भी वह सेलम और मिर्जोरम की बातें करते हैं। बात पहले गढ़वाल की ही करें।

31 हजार मतों का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। खास कर जब कि तराई के इलाकों में भी इका प्रत्याशी हार गया। मैंने इस का कारण बहुगुणा जी से पूछा। बातचीत उनके सोने के कमरे में हो रही थी क्योंकि कुछ दिन से उनकी तबीयत नासाज थी। बुखार, गला घंटा हुआ और कमर में पीड़ा।

इसका कारण है मतदाता के मन में अनिश्चय। 1980 में 60 प्रतिशत से कम मतदान नहीं हुआ था और अब की बार हुआ केवल 45 प्रतिशत, क्योंकि लोग डरे हुए थे। पहले लूटा फिर टाला। कौन ऐसे आतंकवादियों से दुश्मनी ले। पिछले दो वर्ष में क्या नहीं किया गया। जोशीमठ के एक सेनिटरी इस्पैक्टर की बदली केवल इस लिए हरदोई की गयी कि उसके नाम के साथ बहुगुणा लगा हुआ था। केंद्रीय विद्यालय के तीन अध्यापकों को क्रमशः अहणा-चल, अंडमान और मद्रास भेज दिया गया। कर्ज वसूली, कर वसूली और जुमनि का जबर्दस्त सिलसिला शुरू हो गया। आयकर, बिक्री कर, स्वास्थ्य निरीक्षण आदि के नाम पर गढ़वाल में इस्पैक्टर जैसे टिड्डी दल की तरह उभड़ कर आये। आतंक तो पैदा होना ही था। दस हजार नौजवान, जिन में स्वचालित बंदूकों और रिवाल्वरों से लैस कुछ बदमाश लोग भी शामिल थे, पहाड़ों में घूमने लगे। इस पर भी बँस नहीं हुआ। अंतिम दिनों पुलिस के नौ हजार जवान गढ़वाल आये तो लोगों को लगा कि अब यहाँ खून खराबा हो कर ही रहेगा। खून खराबे से पहाड़ी कोसों दूर रहते हैं। मेरे गाँव से सी मील के भीतर शायद ही किसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 107 या 117 के बारे में सुना। श्रीनगर के एक भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शास्त्री जी को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने मध्यप्रदेश के एक विधायक का अपहरण किया है। अदालत ने उनके विरुद्ध अभियोग खारिज कर दिया। कुर्की और नीलामी के इस आतंक में अगर मतदाता मतदान केंद्रों तक आये ही नहीं तो कौन दोष दे सकता है उन्हें।

मेरे पाँच हजार भोटिया मतों को अपने गाँवों से दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया। वे अपनी भेड़ बकरियाँ ले कर मई के शुरू में बदरीनाथ के आसपास अपने गाँव लौटते हैं। उन्हें यह कह कर टूकें नहीं दी गयी कि चुनाव में लगी हुई हैं। रही चंद्रमोहन सिंह नेगी की लैसडाउन में हारने की बात तो इस में आश्चर्य क्या है। 1980 के चुनाव में भी वह 131 मतदान केंद्रों पर हारे थे। केवल 40 पर जीते क्योंकि उन पर बलात् कब्जा किया गया। अब कब्जा नहीं कर पाये। बस।

युवा कांग्रेस के नेता संजयसिंह तो कहते हैं कि बहुगुणा गढ़वाल को असम बनाना चाहते हैं और वह स्वर्ग.... (देखें दिनमान 16-22 मई पृष्ठ 18)

संजयसिंह के बारे में बोलना मैं समय जाया करने के बराबर मानता हूँ। हाँ, गढ़वाल को असम बना सकता है यह बात बड़ी दिलचस्प है। मला कैसे। उत्तराखंड आंदोलन वाले मुझ से इस लिए नाराज हैं कि मैं उनका साथ नहीं देता। पंजाबियों को तराई के इलाके में जमीनों का हक दिलवाने वाला मैं हूँ जब कि मुझ से पहले तीन मुख्यमंत्री मना कर चुके थे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो समग्र देश के हित में न हो। संसद में आना भर मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे उस तस्वीर की चिंता है जो 2001 में मेरे देश की होनी चाहिए। मुझे वह नारा पसंद नहीं जो मुझे जिताये मगर देश को नुकसान पहुँचाये।

असम की समस्या इनकी बतायी समस्या है। जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था तब भी मैंने इंदिरा जी से कहा कि यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है राष्ट्रीय समस्या है। इस में सभी दलों को शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं सही हल निकालने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। आखिर असमी वहाँ की संपदा का औपचारिक शोषण क्यों वर्दास्त करें। क्या बंगाली यह पसंद करेंगे कि उनके यहाँ के पटसन की नीलामी बंबई में हो। अगर वे



‘मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो समग्र राष्ट्र के हित में न हो। मुझे वह नारा पसंद नहीं जो मुझे जिताये मगर देश को हानि पहुँचाये?’

पृथक्तावादी नहीं हुए तो असमी कैसे हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सब से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पर कितने पुल बनाये हैं इन्होंने और गंगा पर कितने। एक पुल के लिए भी असम के लोगों को आंदोलन करना पड़ा।

मुझे तो डर है कि ओडिसा में भी ऐसा ही विद्रोह न भड़के, बस्तर में न भड़के। वहाँ क्या मैं बैठा हूँ। यह दोष तो आर्थिक रणनीति का है जिसे यह लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। अगर गढ़वाल के कई इलाकों में गरीब लोगों को गेहूँ साढ़े तीन रुपये किलो के भाव से खरीदना पड़ रहा है तो क्या वे इनकी कथित कार्यकुशलता से संतुष्ट होंगे? अरे भाई, इंदिरा जी के आदमियों को तो यह भी नहीं मालूम कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए। यह सब सुविधाएँ जो चुनाव के दौरान उन्होंने दीं, जून के बाद ही देनी शुरू की होती तो उनकी विश्वसनीयता कुछ बढ़ जाती। अब तो लोग इन सुविधाओं को भी ‘बहुगुणा बोनस’ कहते हैं।

यह रहीं गढ़वाल की बात। राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति पर बहुगुणा जी बेबाक बात करते हैं। एक व्यक्ति का चुनाव जीत कर संसद में आना कोई जमाने हिलाने वाली घटना तो है नहीं। फिर भी इंदिरा जी इसको प्रत्यक्षतः जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही हैं। आपकी जीत का उनके लिए क्या अर्थ है? कौन सी बात है जिस से वह घबराती हैं?

जो काम के दिखाऊ पर्याप्त का के होसले रहीं, जहाँ उत्तरप्रदेश भी न क और आजी जीत भी ग अस के छ पहुँच गयीं। फिर

तब भी ए साहस नहीं मगर जब जीता था दम लिया। सिवाय अ रही हैं कि हैं और करती हैं म कार्यकर्ता दी गयी थी का आत्मनि जाये। यही इका ने को रोक पैदा क बढ़ावा

मेरे बिना वहाँ असंत अपने ऊपर चाहता हूँ की जरूरत को मुख्यमं जिन में न पकड़? जेल जनिक लड़ के विभिन्न कोई ऐसी पार्टी के व के लिए हर गांधी की उ हैं कि मेरे असल बात जो दिन म एक गंभीर जाना है।

कभी सु सरदार पटेल घबराये थे? सुनने के लि

दिनमान

दिनमान



877705

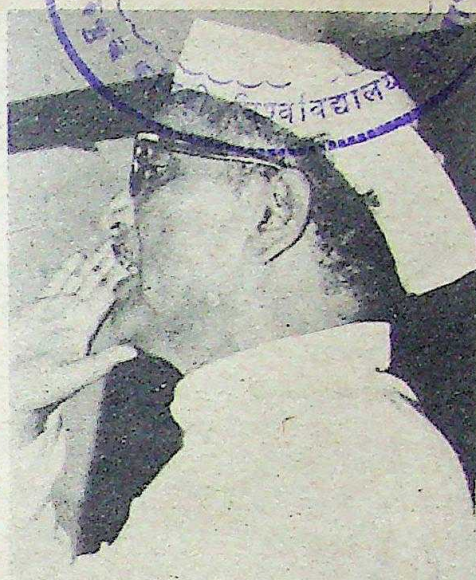
जो काम वह स्वयं नहीं कर सकीं वह मैं कर के दिखाऊँ यह उनके लिए आतंकित होने का पर्याप्त कारण है। 1977 में वह हारीं तो उन के हौसले इतने पस्त हुए कि जीवन भर जहाँ रही, जहाँ की राजनीति ने उन्हें बनाया उस उत्तरप्रदेश से दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत भी न कर सकीं यद्यपि दो स्थान फतेहपुर और आजमगढ़ खाली हो गये थे। एक में इंका जीत भी गयी। मगर वह खड़ी नहीं हुई। देवराज अर्स के छते के नीचे जा कर चिकमंगलूर पहुँच गयीं।

फिर से 1980 में जब चुनाव हुए तब भी एक मात्र रायबरेली से जीतने का साहस नहीं हुआ। मेदक में भी एक पाँव रखा। मगर जब मुझे चुनौती दी गयी तो जहाँ से मैं जीता था वहीं से लड़ा और फिर से जीत कर दम लिया। मुझे किसी की छतरी नहीं चाहिए, सिवाय आम लोगों के। प्रधानमंत्री मानती रही है कि सरकारें चुनाव का संचालन करती हैं और उन्हें जीतने की परिस्थितियाँ पैदा करती हैं मगर अब उन्हें लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसकी कमर जानबूझ कर तोड़ दी गयी थी कहीं फिर से खड़ा न हो, कहीं उस का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान लौट न जाये। यही डर है उन्हें।

इंका नेताओं को यह डर है कि यदि आप को रोका नहीं गया तो आप पार्टी में असंतोष पैदा करने की कोशिश करेंगे, विद्रोह को बढ़ावा देंगे?

मेरे बिना क्या वहाँ विद्रोह नहीं हो रहा है? वहाँ असंतोष नहीं है? अगर इंका नेतृत्व को अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ती है? क्यों ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाता है जिन में न प्रशासनिक क्षमता है, न राजनैतिक पकड़? जैलसिंह और दरबारा सिंह की सार्वजनिक लड़ाई मेरी पैदा की हुई है क्या? देश के विभिन्न भागों पर एक नजर दोड़ाइये तो कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे की टाँग खींचने के लिए हर समय तैयार नहीं रहते? श्रीमती गांधी की अपनी पैदा की हुई मुसीबतें इतनी हैं कि मेरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। असल बात तो यह है कि उनकी सत्ता का जो दिन भी गुजर जाये वही उनके लिए एक गंभीर रोगी के लिए शनिवार का गुजर जाना है।

कभी सुना है कि जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल की लोकप्रियता से महात्मा गांधी घबराये थे? कभी पढ़ा है कि इन नेताओं को सुनने के लिए उमड़ कर आने वाली भीड़ विनम्रान



**‘इंदिराजी लोगों के सामने जाने से डरती हैं। उनकी सरकार इसी लोकसभा में पराजित होगी। सरकार पहले गिरेगी चुनाव बाद में होंगे।’**

को देख कर गांधी के मन में जलन पैदा हो गयी थी? मगर आज हमारे पास ऐसा नेता है जिसे अपने साथियों की मामूली प्रगति भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं आप को एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ।

तब मैं डाकतार मंत्री था। दिल्ली से चुने

**‘अपने राजनैतिक जीवन में मैंने बहुत कम ऐसे राजनीतिक देखे हैं जो इंदिरा गांधी से अधिक डरपोक हों।’**



गये एक संसद सदस्य शशिभूषण ने वीएतनाम के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करवायी जिस में मेरे अतिरिक्त कमलापति त्रिपाठी और शंकरदयाल शर्मा को भी बुलाया गया। संयोग यह है कि और लोगों का भाषण तो श्रोताओं ने चुपचाप सुना, मेरे भाषण पर काफ़ी तालियाँ बजायी गयीं। अगले दिन जब मैं इंदिरा जी से मिला तो जो कुछ उन्होंने मुझ से कहा उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देश की प्रधानमंत्री मुझ से बोलीं कि सुना है कि कल आपने तालियाँ पिटवाने के लिए गाज़ियाबाद से काफ़ी लोग मँगाये थे। अपने पूरे राजनैतिक जीवन में मैं किसी भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को नहीं जानता जो श्रीमती इंदिरा गांधी से ज्यादा डरपोक और शंकालु हो।

मगर श्रीमती गांधी के साथ आपका मतभेद नया तो है नहीं। आपात्स्थिति से पहले जब आप उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आप के कुशल प्रशासन के बावजूद आप को हटा दिया गया। इस के पीछे क्या राज था?

राज क्या था, उन्हें लग रहा था कि बहुगुणा उत्तरप्रदेश में सफल हो रहा है। कहीं वह मुझ से अधिक लोकप्रिय न हो जाये।

मगर उन दिनों यह भी कहा जा रहा था कि आप ने सोवियत संघ के राजदूत से गुप्त रूप से मुलाकात की?

मुलाकात की थी इस में कोई गोपनीयता नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण देश का राजदूत आप के राज्य की राजधानी में आये तो मुख्यमंत्री के नाते आप का क्या कर्तव्य है। क्या उसे नजरंदाज कर देंगे। उनका सम्मान अगर हमने किया तो वह राष्ट्रीय नीति के विपरीत नहीं था। श्रीमती गांधी क्या यह कह सकती हैं कि सोवियत संघ से हमारी मित्रता नहीं है या सोवियत संघ के आधिकारिक प्रवक्ता का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि बहुगुणा ने राजदूत से मुलाकात क्यों की, यह नहीं कि उस का सम्मान क्यों किया। मगर यदि आप का आशय यह है कि सोवियत राजदूत के साथ मिल कर यदि मैंने कोई षड्यंत्र रचा हो तो यह केंद्रीय सरकार का कर्तव्य था कि वह जाँच कर के मुझे उचित सजा दिलवाती। आप क्या समझते हैं उनके पास यदि रत्ती भर भी प्रमाण होता तो मैं आप से बात करता होता। उसने मुझे ठिकाने नहीं लगा दिया होता।

मगर रूस के साथ जिस प्रकार के राजनैतिक संबंध हमारे हैं उसके संदर्भ में क्या श्रीमती गांधी सार्वजनिक रूप से ऐसा कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? नासिर ने नहीं किया?



दलमान



धान में राजा राष्ट्राध्यक्ष होता है और उत्तराधिकार की परंपरा के अनुसार ताजपोशी होती है।

भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है जो एक कार्यकाल के लिए पदारूढ़ रहता है और जिसे दुर्यवहार के आरोप में संविधान में लिखी प्रक्रिया के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है।

वास्तव में, 1950 में राष्ट्रपति भवन में जाने के तुरंत बाद ही राजेन बाबू और नेहरू के बीच राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर पहली बार विवाद उठा था। राजेन बाबू द्वारा उठाये गये मुद्दों को नेहरू ने तत्कालीन महा-विध्वक्ता एम. सी. सीतलवाड़ के पास भेजा और उन्होंने जो विचार व्यक्त किया वह आज भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीतलवाड़ ने यह मत व्यक्त किया था कि ब्रितानी सम्राट की तरह राष्ट्रपति अनिवार्यतः उपाधिधारी है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, सम्राट की तरह राष्ट्रपति 'परामर्श', चेतावनी और प्रोत्साहन देने के अधिकार' का प्रयोग कर सकता है। सीतलवाड़ का यह मत भी था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके नये चुनावों का आदेश दे सकता है।

अपने विवेक से चुनाव कराने का अधिकार कानून सम्मत नहीं है। फिर भी, एक सुरक्षित अधिकार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते राष्ट्रपति गहराई से यह अनुभव करते हों कि संसद देश में राजनैतिक संतुलन को प्रतिबिम्बित नहीं करती है (1977 में इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा चुनाव के बाद नौ विधानसभाएं भंग की गयी थीं)।

प्रथम राष्ट्रपति ने जब अपने विचार व्यक्त किये थे तब से बहुत कुछ हो चुका है। 1974 में शमशेरसिंह के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। दो वर्ष बाद श्रीमती गांधी ने संविधान में संशोधन करा कर इस मुद्दे से जुड़े सभी संदेहों को—उन संदेहों को जो वास्तव में 1969 में महान कांग्रेस के विभाजन का बायस बने थे—समाप्त कर दिया। संविधान के 42वें संशोधन में कहा गया है: "प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को, अपने कार्यों के करने में, इसके परामर्श के अनुसार चलना होगा।" परिणामतः 44वें संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति के हाथ-पांव बँधे नहीं हैं और वह 'मंत्रिपरिषद से ऐसे परामर्श पर सामान्यतया या

अन्य प्रकार से पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है।" किंतु यह अधिकार असीमित नहीं है। जनता सरकार द्वारा किये गये संशोधन में यह प्रावधान है कि 'राष्ट्रपति को ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गयी सलाह के अनुसार काम करना होगा।'

अनेक वर्षों के दौरान राष्ट्रपति के पद से जुड़े अन्य कई विवादों का समाधान करके स्वस्थ परंपराएँ डाली गयीं। उदाहरणार्थ, राजेन बाबू का यह विचार था कि प्रतिरक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति सेनाध्यक्षों को बुला सकता है और प्रतिरक्षा के मामलों में उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर भी सीतलवाड़ का मत था कि राष्ट्रपति सेनाध्यक्षों को नहीं बुला सकता है। बजाय इसके, वह प्रतिरक्षामंत्री को बुला कर उनसे जानकारी माँग सकता है। एक बार तो राजेन बाबू ने नेहरू से जोरदार शिकायत की थी कि उन्हें राजदूतों तथा राज्यपालों की नियुक्ति की जानकारी अखबारों से ही मिलती है और अधिकृत सूचना बाद में दी जाती है।

इस का असर हुआ और मंत्रिमंडल ने यह आदेश पारित किया कि उच्चस्तरीय नियुक्तियों से संबंधित सभी कागजात आदेश जारी किये जाने से पहले उनके पास भेजे जायेंगे। किंतु अब भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि संविधान के अनेक तरह से अर्थ लगाये जाते हैं और कुछ बेहूदा व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की जाती हैं।

राष्ट्रपति के पास एक और भी अधिकार है जिसका कभी कभार ही प्रयोग किया गया है। यह है प्रश्न करने और जानकारी पाने का अधिकार, जिससे संसद को कार्यपालिका पर अद्वितीय आधिपत्य मिलता है और जो दैनिक प्रश्नकाल को पवित्र बनाता है। कहा जाता है कि ब्रिटेन के महान नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के स्वाधीन होने पर गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने या न करने के बारे में लार्ड माउंटबेटन द्वारा सलाह माँगी जाने पर एक ही प्रश्न पूछा था: 'क्या तुम्हें जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है?' जब माउंटबेटन ने हाँ में उत्तर दिया तो चर्चिल ने कहा: 'उत्तम स्वीकार कर लो।'

कार्यकारी राष्ट्रपति बी. डी. जती ने 1977 में इस अधिकार का प्रयोग करके सनसनी और जनता सरकार के लिए, जो नौ राज्य सरकारों की बर्खास्तगी से संबंधित अध्यादेश पर उनके हस्ताक्षर चाहती थी, एक मारी समस्या पैदा कर दी। इस प्रकार राष्ट्रपति को प्रश्न पूछ कर, या अधिकारियों द्वारा पूरी तरह संतुष्ट न किये जाने तक किसी घोषणा

पर हस्ताक्षर करने से मना करके स्थापित परिपाटियों और परंपराओं को बनाये रखने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति हाल में असम में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने से संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते थे और अल्पमत गोगोई सरकार की स्थापना के आधार तथा औचित्य के बारे में संतुष्ट किये जाने की माँग कर सकते थे। वह यह आग्रह भी कर सकते थे कि नये मंत्रिमंडल से एक सप्ताह रके भीतर सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाये, न कि एक महीने में जसी की अनुमति दी गयी थी।

कुल मिला कर, राष्ट्रपति को अनेक अधिकार हैं जिन्हें राजेन बाबू स्पष्ट कराना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में नेहरू जी को अनेक पत्र लिखे और अंततः भारतीय विधि संस्थान में दिये गये ऐतिहासिक भाषण में अपने विचार व्यक्त किये। बात अविश्वसनीय लग सकती है, किंतु पत्र सूचना विभाग ने, आरोप है कि उस समय की सत्ता के आदेश पर, उस भाषण को प्रसारित नहीं किया था। किंतु जो मुद्दे उठाये गये उनका स्पष्टीकरण जरूरी है ताकि भविष्य में संदेहों की कोई गुंजाइश न रहे।

हम अपने अनुभव के आधार पर जितनी जल्दी राष्ट्रपति के अधिकारों तथा उसके क्षेत्र को परिभाषित कर सकेंगे, हमारे तथा हमारे युवा गणराज्य के लिए यह उतना ही अच्छा होगा।

वन्य जीवन

## तारा क्यों मारी गयी

तारा को मरे डेढ़ वर्ष से भी ज्यादा हो गया।

11 नवंबर 1980 को उसे गोली से उड़ा दिया गया था। मगर इतने दिनों बाद फिर से उस के साथ जड़ा हुआ विवाद उभर कर आया क्योंकि तारा के मालिक अर्जुनसिंह ने दावा किया कि तारा जिंदा है और अभी भी दुधवा असम-रण्य में मस्ती से घूम रही है। इतना ही नहीं यह भी दावा किया गया कि 1976 में तारा को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेंट किया गया था। इन दावों के बावजूद तथ्य यह है कि तारा का मसाला भरा हुआ शव लखनऊ चिड़िया घर के निदेशक रामलखन सिंह के कार्यालय में दर्शनार्थ मौजूद है। रामलखन सिंह के अनुसार इस विवाद के इतने आयाम हैं कि अब खामोश रहना राष्ट्रीय दृष्टि से अपने कर्तव्य से विमुख

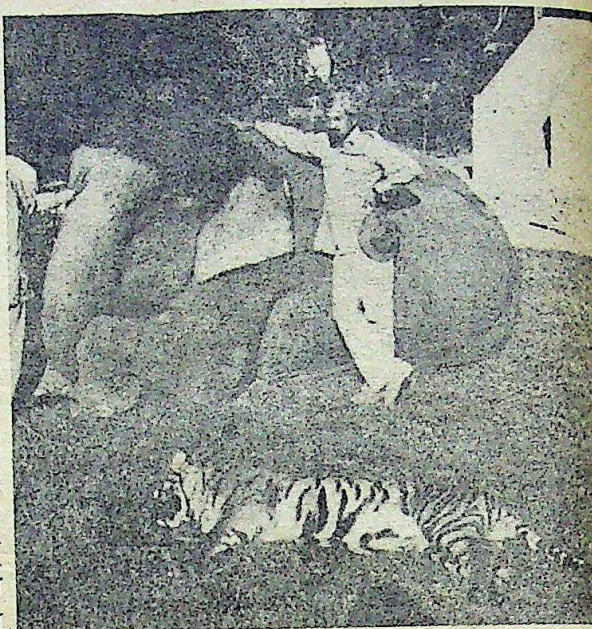


होने के बराबर है, खासकर जब कि देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें घसीटा जा रहा है।

तारा एक शेरनी थी। प्रजाति से 'बंगाल टाइगर' वर्ग में आती थी मगर जन्म से अंग्रेज। उस की कई पीढ़ियाँ ब्रिटेन के एक चिड़िया-घर में पलती आयी और उस से पहले उस के पूर्वजों को पूर्वी यूरोप के किसी देश से मँगाया गया था। पहली सितंबर 1976 को जब कि उस की उम्र साढ़े तीन मास की थी उसे हवाई जहाज से नेपाल लाया गया। और नेपाल से बिना किसी सरकारी आदेश या प्रमाण पत्र के चोरी छिपे उसे नेपाल की सीमा से कुछ ही दूर स्थित दुधवा अभ्यारण्य के पास पहुँचा दिया गया। असल में यह सौदा मध्य प्रदेश के एक जमींदार और शिकारी अर्जुनसिंह ने विदेश में आने दोस्तों के माध्यम से किया था। और इस के पीछे विश्व वन्य पशु कोष (वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड) जैसा शक्तिशाली संगठन भी काम कर रहा था। संगठन को एक परियोजना पेश की गयी थी कि यह अध्ययन किया जाय कि क्या शेर, जिसे कृत्रिम रूप से बंधन में पाला गया हो व्यस्क होने पर जंगल में छोड़ा जा सकता है? क्या वह पालतू शेर जंगल के कायदे कानून के अनुसार चलने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकता है? यह प्रयोग सफलतापूर्वक अभी तक नहीं हुआ है और विश्व वन्य पशु कोष का उद्देश्य ऐसे पशुओं का संरक्षण और अध्ययन है जिन के अस्तित्व को प्राकृतिक या मानवीय कारणों से खतरा पैदा हो गया है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक ऐसे पशु हैं जो इस खतरे की परिधि में आ चुके हैं। भारत में शेर पर भी यह खतरा आ गया है। इसलिए वह सरकारी तौर पर संरक्षित वन्य पशु घोषित किया गया है। योजना के अनुसार अर्जुन सिंह जंगल में छोड़े गये शेर के बच्चे के जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाने वाले थे। रामलखन सिंह के शब्दों में "प्राकृतिक परिस्थितियों में बंगाल शेर जैसे वन्य पशु पर वृत्त चित्र बनाना बहुत कठिन है क्योंकि यह पशु एकांत में रहना पसंद करता है, दिन के उजाले में इधर उधर नहीं भटकता और कैमरा के सामने आने का इसे कतई शौक नहीं है। इसलिए यदि किसी पालतू शेर को जंगल में डाल दिया जाय जिसे आदमी की सौहवत की आदत पड़ गयी हो, जिसे बंधा बंधाया खाना मिलता हो तो उस पर फिल्म बनाना कम मुश्किल काम है। बशर्ते कि वह जंगल के नियमों को सीखे और उसी तरह व्यवहार करे। मगर इस में एक मुश्किल यह भी है कि यदि शेर पालतू से जंगली हो गया तो वह आशुकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से रहा। परीक्षण और अध्ययन की बात तो मैं नहीं जानता और मुझे उस में विश्वास भी नहीं, हाँ वृत्तचित्र का लोभ बहुत बड़ा रहा होगा

क्योंकि ऐसे वृत्तचित्र पश्चिम में हाथोहाथ विक्रि जाते हैं।"

**आदमी का शिकार:** तारा जंगल में विचरने लगी। उसे अलग अलग स्थानों पर बंधा हुआ शिकार मिल जाता था। उसे मार कर घूमने निकल जाती थी। मगर कुछ समय बाद तारा कई कई दिन गायब रहने लगी। असल में वह जवान हो गयी थी। जवानी आते ही शेरनियों के शरीर में एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है। यह गंध हवा में दूर दूर तक फैलती है। गंध पा कर दुधवा के अन्य शेरों का चौकना स्वामाविक था। जंगल में एक अंग्रेज जवान शेरनी घूम रही हो और उन्हें पता ही नहीं। संपर्क हुआ और इस लिए तारा अपने किसी न किसी साथी के साथ दूर दूर तक निकल जाती। फिल्म बनाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो गयी, कहाँ खोजें? कभी कभी ता वह शिकार के पास भी दो दो दिन बाद आने लगी। फिल्म बनाने वालों को लगा कि तारा को अनुशासित करने के लिए सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कई बार शिकार बाँधना ही छोड़ दिया। भूखी रहेगी तो होश ठिकाने आयेंगे। मगर तारा की भूख ने उसे एक दूसरा ही रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया। अन्य शेरों की तरह आजादी के साथ स्वयं अपना शिकार पकड़ने की कोशिश की मगर कभी कभी उसने उसे सफलता मिलती थी। क्योंकि बचपन से उसे उन स्वामाविक विशेषताओं से वंचित रखा गया था जो वन्य पशुओं को जंगल में रहने और अपने माँ बाप के प्रशिक्षण से मिलती है। जन्म से ही शेरनी अपने बच्चों को सूँघने, भागने, घात लगाने, आक्रमण करने, छिप जाने के सभी गुण सीखाना शुरू कर देती है। तारा को ये गुण किसी ने नहीं सिखाये थे और उस से शिकार पकड़ा ही नहीं गया। जब भी उस ने कोशिश की उस के चंगुल से भाग गया। अब तक तारा के गर्भ के चार महीने पूरे हो चुके थे और उस ने दो बच्चों को जन्म दिया। अब परिवार को लेकर उस के लिए आहार की समस्या और भी गंभीर हुई। और पहली बार उस ने मजबूरी में एक आदमी पर आक्रमण किया। उसे लगा आदमी सब से आसान शिकार है। फिर आदमी उस का मुख्य भोजन बन गया। राह चलते हुए ग्रामीणों के लिए वह आतंक बन गयी। एक बार तो उसने अर्जुनसिंह के ही एक नौकर को शिकार बना दिया। शेरनी के डर से अकेला किसान घर से बाहर नहीं निकलता। "इसी अवसर पर मेरी नियुक्ति दुधवा अभ्यारण्य के निदेशक के रूप



मृत तारा और राम लखन सिंह : कल की चिंता

में हुई। अब तक तारा 18 आदमी खा चुकी थी। जवान शेरनी के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 किलोग्राम मांस की जरूरत होती है। अचानक उस ने 'फोरेस्ट बंगले' का रुख किया। भोर में ही वह एक मेहतरानी गंगाजली को उठा कर ले गयी। और रात को बंगले पर उस का फिर आक्रमण हुआ। और इस बार एक चौकीदार असगर उस का शिकार बना। किसी बाधा के कारण या भूख कम होने के कारण वह उसे उठा कर नहीं ले गयी। मैं डाक बंगले पर पहुँचा। 9 नवंबर यानी अगले दिन तारा असगर की आवी लाश को उठा कर ले जाने के लिए फिर आ गयी। उस के साथ उस के दोनों बच्चे थे। एक हथनी पर बैठ कर मैंने उस का पीछा किया। जब उसे पता चला कि उस का पीछा किया जा रहा है तो उस ने पलट कर मुझ पर आक्रमण किया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि हथनी ने अपने बचाव में शेरनी का मुकाबला किया। और तीनों बिना कोई विशेष नुकसान किए भाग गये। मैंने गोली नहीं चलायी। क्योंकि ऐसा करना कानूनी जुर्म होता। अभ्यारण्य वन्य पशु का देश होता है। वहाँ किसी पशु को मारना कानूनी जुर्म है, भले ही वह आप पर आक्रमण करे। इसलिए मुझे सरकार से इस बात की इजाजत माँगनी पड़ी कि तारा को मार दिया जाय, क्योंकि तारा पालतू पशु नहीं रह गयी थी और न ही जंगल के कायदे कानून वह सीख पायी थी। जीवन में पहली बार मैंने किसी शेर को दिन के उजाले में बस्ती की ओर शिकार की तलाश में आते हुए देखा। तारा का प्रत्येक व्यवहार अस्वामाविक था। जंगल में वह जीवित नहीं रह सकती थी अगर वह आदमी का शिकार नहीं करती। इसलिए 11 नवंबर

दिन के डेढ़ बहू खुल कर व्यवहार न अनुवां घटना कोई में विवाद दुधवा अभ्यारण्य देश में दो दुधवा में ही शेर की जस जो हम से इस प्रकार तस्करी द्वा बात पर म संगठन ऐसे कानूनी रूप हमें कुछ म उन से कहीं चेतना का अभ्यारण्य भी बन स और उस विभिन्न जी

युवा कांग्रेस उम्र व बिहार मोत चुनाव के संकट में ड सकता है। इसी मा युवा कांग्रेस अध्यक्ष ता कांग्रेस कमे प्रोत्त कर शांत नहीं हु अनवर बन चंदन बागच गुट के चंद के विरुद्ध बन कर बा गये तथा ज स्कूल के ना के प्राचार्य जीवनी लेख अध्यय की लो। इस ज कांग्रेस के स माध्यमिक उम्र प्रमाण दिनमान



दिन के डेढ़ बजे एक बंधे हुए शिकार के लिए वह खुल कर सामने आयी (जो कि शेरचित्त व्यवहार नहीं है) और यही उस का अंत था।

**अनुवांशिक प्रदूषण :** नरभक्षी को मारने की घटना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है फिर इस में विवाद क्या है? "पहली बात तो यह है कि दुधवा अभ्यारण्य में शेरों की संख्या पर्याप्त है। पूरे देश में दो हजार शेर हैं जिन में 120 तो केवल दुधवा में ही हैं। हमें किसी बाहरी देश से किसी शेर की जरूरत नहीं थी। खासकर ऐसे देश से जो हम से ही शेर लेता है। उल्टे बाँस बरेली को। इस प्रकार की इजाजत न मिलने पर तारा को तस्करी द्वारा भारत लाया गया। इसलिए इस बात पर गंभीर आपत्ति है कि विश्व वन्य पशु संगठन ऐसी विवादास्पद योजनाओं को गैर-कानूनी रूप से प्रश्रय देती है। यूरोप के विशेषज्ञ हमें कुछ भी सिखा लें प्रकृति को समझने में हम उन से कहीं आगे हैं। प्रकृति तो हमारी संस्कृतिक चेतना का अंग है। तारा संबंधी यह प्रयोग दुधवा अभ्यारण्य के लिए भयंकर विनाश का कारण भी बन सकता था। तारा का वंश यूरोपीय है और उस के जीन भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न जीवाणुओं के साथ समझौता करने की

क्षमता नहीं रखते। इस प्रकार की क्षमता पैदा होने में कई पीढ़ियाँ लगेगीं। इस बीच वह हमारे शेरों के संपर्क में आयेगी और जो बच्चे पैदा होंगे उन में भी प्राकृतिक विपदाओं को सह सकने की क्षमता पूरी तरह नहीं रहेगी। विश्व में इस प्रकार के उदाहरण कम नहीं हैं जहाँ बाहरी तौर पर आदर्श व्यवस्था के बावजूद आंतरिक क्षमता न होने के कारण पूरी की पूरी प्रजातियों का संहार हुआ है। क्या ऐसे खतरनाक प्रयोग की अधिकचरी योजना की कोई भी देश इजाजत दे सकता है? तारा का मामला यदि इस विवाद को समाप्त करता तो कोई बात नहीं थी। मगर इस बात की अफवाहें हैं कि एक और शेर के बच्चे को इसी प्रकार दुधवा में प्रवेश दिलाने की योजना है। शायद इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि तारा जिंदा है।

और अंत में : तारा के मरने के बाद उस के दोनों नवजात बच्चों को अभ्यारण्य के विशेष कक्ष में अलग से पाला जा रहा है ताकि हर संभव अनुवांशिक प्रदूषण को टाला जा सके। और उन बच्चों का नाम है रामलखन और लोलिता। —जवाहरलाल कौल

तारिक गुट का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जा कर इस मामले में फैसले की माँग करेगा। आला कमान अब तक अधिक उम्र के तीन युवा अध्यक्षों को (जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंबई प्रदेश के थे) हटा चुकी है। उपचुनाव तक दिल्ली तथा प. बंगाल के अधिक उम्र के युवा अध्यक्षों का मामला लंबित है। मुन्ना शाही का कहना है कि यह गंभीर संवैधानिक मसले के अलावा घोखाघड़ी का भी मामला है। 1981 में युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने बिहार समेत सभी प्रदेशों के युवा कांग्रेस पदाधिकारियों की उम्र का प्रमाणपत्र माँगा था। तब बागची जानबूझ कर प्रमाण पत्र भर कर भेजना भूल गये। इस विश्वास हनन के कारण आम युवा कांग्रेसी के बीच बागची को चुनने वाली इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की चयन क्षमता शंका में पड़ी है—यह एक तटस्थ युवा कांग्रेसी का मत है।

एक मशाल-जुलूस के कारण बागची और संकट में पड़े हैं। विपक्ष के छात्र युवा आंदोलन-कारियों के मुख्यमंत्री हटाओ अभियान के जवाब में जगन्नाथ बचाओ अभियान के दरम्यान बागची ने मई के प्रथम सप्ताह में पटना में युवा कांग्रेस का एक मशाल-जुलूस निकालने का निर्देश दिया। अदालतगंज से निकले इस मुख्यमंत्री समर्थक जुलूस में मात्र पंद्रह लड़के थे। बागची विरोधियों ने युवा कांग्रेस कार्यालय के एक कर्मचारी के इस कथन को शहर में चर्चा का विषय बना दिया : 'हुजूर आदमी से ज्यादा मशाल हो गया।' तारिकपंथियों का दावा है कि भारत बंद के अवसर पर हज्जार से ऊपर लड़के पटना में सक्रिय थे। अप्रत्यक्ष रूप से वे एक सैद्धान्तिक बात कहना चाहते हैं।

इधर संजय विचार मंच के अध्यक्ष ललित मोहन सिंह ने चंदन बागची को अविलंब हटाने की अप्रत्याशित माँग कर लोगों को विस्मय में डाला। बागची गुट के समर्थक युवा कांग्रेस नेता अशोक मेहता का आरोप है कि क्या संजय मंच तथा युवा कांग्रेस के एक गुट की माँग में साम्य अनायास है? यहाँ आ कर मामला षड्यंत्र सरीखा घोषित हो गया।

विवादास्पद चंदन बागची के साथ एक नया सिरदर्द जुड़ने वाला है। दिल्ली दरबार की माँग पर, यह रिपोर्ट लिखते वक्त पटना में गुप्तचर एजेंसियाँ तारिक अनवर का 'जीवन परिचय' भेजने में संलग्न हैं। जानकार, राजनैतिक अर्थ में इसे उस व्यक्ति के बड़े पद पर पदस्थापन का स्पष्ट संकेत मानते हैं। केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस महासमिति के कोषाध्यक्ष तथा बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कट्टर एवं मुखर विरोधी सीताराम केसरी अपने पटशिष्य तारिक अनवर को प्रदेश (शेष पृष्ठ 28 पर)

युवा कांग्रेस

## उम्र का फसाद महँगा पड़ रहा है

बिहार युवा कांग्रेस में उम्र-घोटाला कांड भीतर भीतर जोर पकड़ता जा रहा है। चुनाव के बाद यह मुद्दा आला कमान को धर्म संकट में डालने के अलावा काफी गुल खिला सकता है।

इसी मार्च में चंदन बागची बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नये अध्यक्ष मनोनीत हुए। पुराने अध्यक्ष तारिक अनवर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव बना कर प्रोत्त करने से युवा कांग्रेस का गुट विवाद शांत नहीं हुआ। अभी बिहार युवा कांग्रेस तारिक अनवर बनाम ज्ञानरंजन कुमुदरंजन झा—चंदन बागची गुट में विभक्त है। तारिक अनवर गुट के चंद लड़कों ने अप्रैल के अंत में बागची के विरुद्ध बकायदा जासूसी की। वे पत्रकार बन कर बागची के सरायकेला स्थित घर पर गये तथा जीवन परिचय के साथ बागची के स्कूल के नाम का पता लगा लाये। फिर स्कूल के प्राचार्य से ये तथाकथित पत्रकार बागची के जीवनी लेखक के रूप में मिले और उन से अपने ली। इस जासूसी अभियान के सरगना युवा कांग्रेस के संगठन सचिव मुन्ना शाही ने बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति से भी बागची का उम्र प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। दोनों प्रमाण-

पत्रों के अनुसार बागची की जन्मतिथि 8-7-45 है यानी उम्र 37 वर्ष। युवा कांग्रेस के संविधान के अनुसार पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। मुन्ना शाही का आरोप है कि 1969 में बागची ने राजा रामगढ़ की जनता पार्टी से सरायकेला विधान-सभा चुनाव लड़ा था। यानी तब बागची की उम्र निश्चित तौर पर 25 वर्ष होगी। इस हिसाब से भी उन की उम्र आज करीब 38 वर्ष हो जाती है।

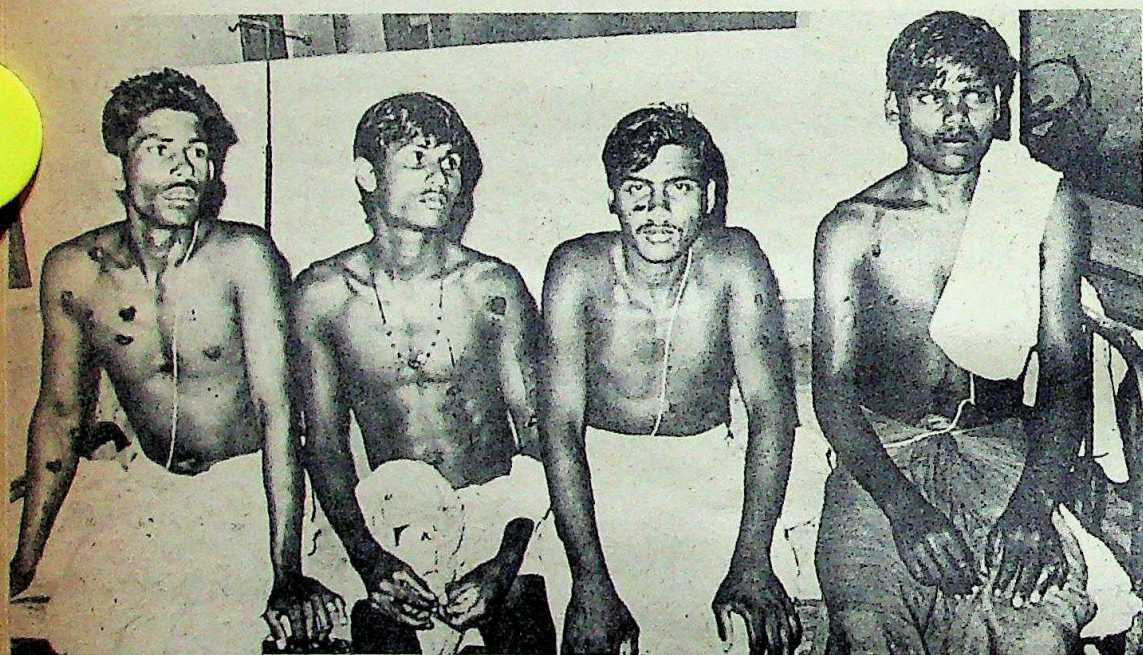
29-4-82 को मुन्ना शाही के नेतृत्व में युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा युवा कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद के पास 'असंवैधानिक अध्यक्ष' के विरुद्ध प्रमाणिक दस्तावेज देने गया। आला कमान ने उपचुनाव के उपरान्त इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। तब तक पटना में पाँच छुटमैया युवा कांग्रेसियों ने अधिक उम्र के अध्यक्ष के निष्कासन की सार्वजनिक माँग उठा दी। इस पर बागची गुट में 'माओ त्से दुंग' के नाम से चर्चित रांची के विधायक ज्ञानरंजन दिल्ली गये तथा आला कमान के पास कारगर हस्तक्षेप कर आये।

चुनाव के बाद, इस माह के अंत में फिर

दिनमान



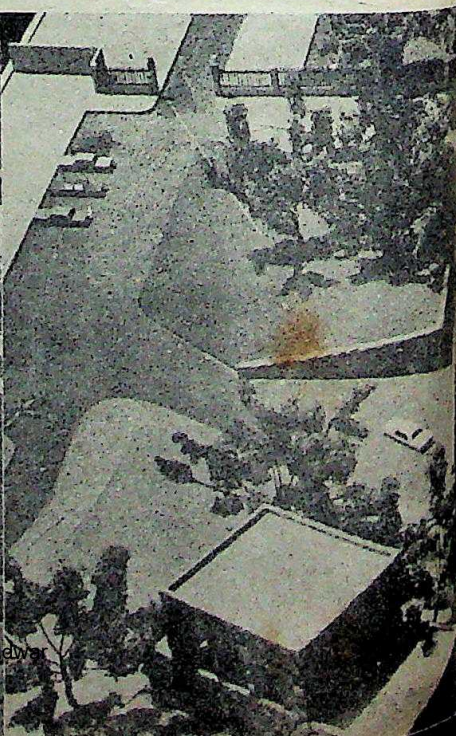
19 मई को भारत के राष्ट्र-पति नीलम संजीव रेड्डी की 70 वीं सालगिरह के अवसर पर जो उन्हें अपनी शुभ कामनाएँ देने राष्ट्रपति भवन पहुँचे उनमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थीं. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपति को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया. (दायें)



मुजफ्फरपुर (बिहार) से प्राप्त सूचना के अनुसार धारो पाली गाँव के कुछ मतदाताओं के जमींदारों ने हाल के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए उनकी पिटाई की. इनमें से कुछ घायल मतदाताओं को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अस्पताल में लाया गया. (बायें)

'हिम  
के 200  
ने नयी  
भवन के  
भारत के  
कर रहे  
घरे को  
(दायें)  
चौन के  
की और  
भारत व  
एक प्रति  
जाये, व  
की उपरि  
जा सकत  
ज्ञापन क  
को दी ग

हाल में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रस्तावित नक्षत्रमंडल की आधारशिला रखी. (दायें) इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता के साथ बिताये हुए समय को याद किया, कि किस तरह वह उनके साथ रात को देर तक तारों भरे आकाश को देखा करती थीं. नक्षत्रमंडल का नमूना, (घुर दायें) जिसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष की आर्थिक सहायता से किया जायेगा.







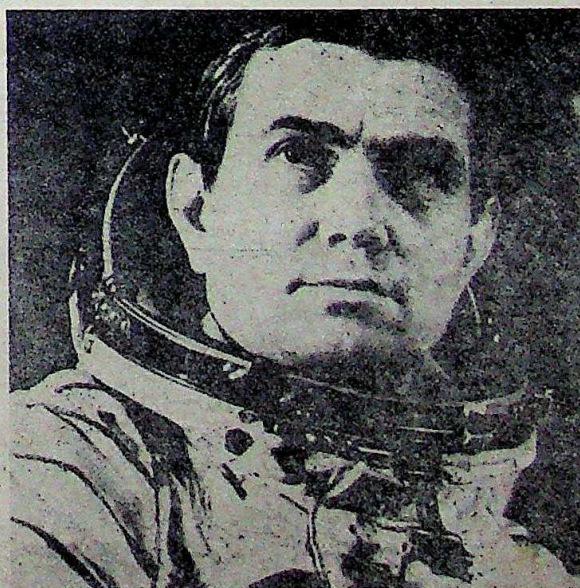
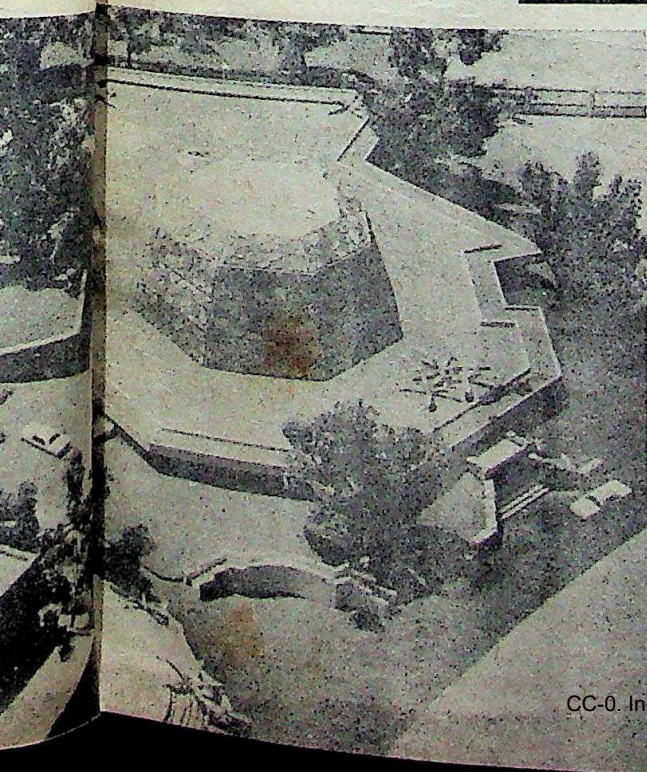
नयी दिल्ली स्थित राममनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा के लिए आये संसदसदस्य सुजानसिंह को, कनिष्ठ चिकित्सक सुनीता मेहता की शिकायत पर, पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। शिकायत दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में थी।

(बायें) अस्पताल के आपत्कालीन विभाग का दृश्य, जहाँ संसद-सदस्य के दुर्व्यवहार के विरोध में चिकित्सकों ने काम रोक दिया और मरीजों को कुछ समय के लिए केवल परिचारिकाओं (नर्सों) पर निर्भर करना पड़ा।

'हिमालय-बचाओ सम्मेलन' के 200 से भी अधिक समर्थकों ने नयी दिल्ली के हैदराबाद भवन के सामने, जहाँ चीन और भारत के शिष्टमंडल बात कर रहे थे, पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। (बायें) विरोध करते हुए उन्होंने चीन के आक्रामक रवैये की भर्त्सना की और यह मांग की कि चीन-भारत वार्ता में तिब्बत के भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाये, क्योंकि कि सीमा समस्या उसकी उपस्थिति में ही सुलझायी जा सकती है। इनकी मांगों के ज्ञापन की प्रति एक अधिकारी को दी गयी।



हार) से सार धारो नद ताओ क चुनाव में ने के लिए नमें से ओ को बगंज या. (बायें)



“हम घर पहुँच गये हैं”— यह संदेश रूसी अंतरिक्ष यान टी-5 सोयुज के यात्री आनातोले बेरेज़ोवोय (बायें) और उन के सहयात्री ने भूमि स्थित नियंत्रण कक्ष को उस समय दिया जब उनका यान, छोड़े जाने के 26 घंटे बाद, घुमंतू शोध स्टेशन सल्युत-7 से घाट लगा।





मुन्ना शाही



चंदन बागची



तारिक अनवर

कांग्रेस के अध्यक्ष पद तथा कालांतर में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। निकट भविष्य में बिहार में ये दोनों शीर्ष पद खाली होंगे। 14 मई को पटना में जब इस संवाददाता ने तारिक अनवर से पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं तो उन का स्पष्ट उत्तर था— 'नहीं, मैं संगठनात्मक कार्य करना चाहता हूँ। यह पूछे जाने पर कि क्या आप प्रदेश इकाई अध्यक्ष बनने वाले हैं, उन्होंने ज्यादा टाल-मटोल नहीं की। कहा : यह आला कमान पर निर्भर करता है। अगर तारिक प्रदेश अध्यक्ष बने तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष बागची को उन की अधीनता स्वीकार करनी होगी और मुख्यमंत्री को तो बाहरी भीतरी खतरों का सामना करना ही पड़ेगा। फिलहाल मुन्ना शाही तारिक गुट की ओर से भावी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किये जा रहे हैं।

चंदन बागची के समक्ष जब उम्र प्रमाणपत्रों की फोटोस्टेट प्रतियाँ प्रस्तुत कर दिनमान प्रतिनिधि ने उन का स्पष्टीकरण जानना चाहा तो थोड़ा उत्तेजित हो कर उन्होंने कहा— मुझे इस का कोई अंदाज़ नहीं है। यह ताज़ा पड़्यत्र लगता है क्यों कि आला कमान ने पूरी पड़ताल कर के मेरा मतोनयन किया है। प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा शुरू से ही मुझे अमान्य कराने की कोशिश है। मुझे गैर कांग्रेसी, दल से निष्कासित, समानांतर संगठन चलाने वाला, बाहरी व्यक्ति (बंगाली) कहा गया है। यह निराधार तथा गलत रिपोर्टिंग की नयी कड़ी है— उम्र संबंधी विवाद। मेरी गलती मात्र यह है कि मैंने एक माह में जेबी युवा संगठन को जीवंत बना दिया है। मैंने अठारह दिन में पूरे बिहार का दौरा कर लिया तो काफी हाउस में बैठ कर सम्मेलनों तक युवा कांग्रेस चलाने वालों में

बौखलाहट जायज है। आज मुझे अकेले विपक्षी छात्र आंदोलन से सरकार का बचाव करना पड़ रहा है।

युवा कांग्रेस के भूतपूर्व महासचिव तथा विधायक पंकज कुमार सिन्हा का आरोप है कि विपक्षी छात्र आंदोलन के दौर में बागची पर आक्रमण संगठन में अस्थिरता तथा पसोपेश पैदा करने की साजिश है। वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता सिद्धनाथ राय (विधायक) का कहना है कि बागची के बहाने प्रधानमंत्री तथा राजीव गांधी की चयन क्षमता पर अप्रत्यक्ष प्रहार करने वाले तत्त्व कौन हैं। इस की जांच होनी चाहिए। तारिक अनवर द्वारा बागची द्वारा लोहरदगा संसदीय चुनाव में नियुक्त युवा कांग्रेस पर्यवेक्षक को ऐन चुनाव की घड़ी में वापस बुलाना क्या कहा जायेगा?

बागची गुट की निगाह में इस समस्त कार्रवाई के पीछे सीताराम केसरी का हाथ है। यह गुट बंगलौर सत्र में पदाधिकारियों की न्यूनतम उम्र सीमा चालीस वर्ष करने का दावा करता है। वैसे तथ्य है कि उम्र सीमा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए बढ़ी थी न कि पदाधिकारियों के लिए। उन्हें 35 वर्ष में पद छोड़ना ही है।

तटस्थ प्रेक्षकों का मत है कि आला कमान नये अध्यक्ष चंदन बागची को तुरंत हटाना मुनासिब नहीं समझेगी। लेकिन उन के भविष्य पर उम्र सीमा की तलवार भी ज्यादा दिन तक लटकती छोड़ी नहीं जा सकती।

इस से आम युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता खासा पसोपेश में हैं। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वह चालीस वर्ष से ऊपर के राजीव गांधी, अरुण नेहरू को आये दिन बिना विवाद मौजूद जो देखता है। □

(पृष्ठ 46 का शेष)

दोनों के साथ अन्याय होगा। हाँ, बलशाली और सुडौल आवाजों में गायकी का सुंदर कार्यक्रम दूरदर्शन ने सिंह बंधुओं (सुरिंदर सिंह एवं तेजपाल सिंह) के जरिये जरूर पेश किया।

गत वर्ष सप्रू हाउस दिल्ली में जिन्होंने अमीर खाँ की गायकी के वारिस इन दोनों भाइयों का गायन सुना था, उन्हें दूरदर्शन का उनका कार्यक्रम सुनकर यह जरूर अनुभव हुआ होगा कि ये युगल गायक इस समय अपनी कला की चरम स्थिति पर हैं। दूरदर्शन इसके लिए बधाई का पात्र है।

लेकिन ऐसे इक्के दुक्के बधाई योग्य कार्यक्रम उसकी 'सब चलता है' शैली वाली कार्य-प्रणाली का मेल नहीं धो सकते। दूरदर्शन के गऊछाप महानिदेशक श्री शैलेंद्र शंकर को इस दिशा में तत्परता से सोचना चाहिए, लेकिन अभी वे 'एशियाड' के कार्यक्रम प्रसारण की तैयारियों के आकलन के लिए हुई 26 अप्रैल की बैठक में पड़ी अपनी झाड़ से अपना पल्ला नहीं झाड़ पाये। कहते हैं सूचना-प्रसारण मंत्री के साथ उस बैठक में खेल प्रेमी युवा सांसद राजीव गांधी भी उपस्थित थे। वह 'हाई पावर' मीटिंग जब शैलेंद्र शंकर से अनेक जानकारियों की जांच पड़ताल में लगी हुई थी, तभी एक तकनीकी जानकारी की जरूरत पड़ गयी। महानिदेशक महोदय उस जानकारी को। मुहैया करने के लिए समय की माँग कर ही रहे थे कि उनके एक अधिकारी ने पर्चा बढ़ा कर वह जानकारी मुहैया कर दी। दूरदर्शन के महानिदेशक से अधिक दूरदृष्टि वाले उस अधिकारी की दूरदृष्टि की धाक जमे, इसके पहले ही एक और सवाल उछल पड़ा। 'आपको हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर एशियाड के लिए कितने कमेंटेटर चाहिए होंगे?'

महानिदेशक के कार्यालय से माँग की गयी थी कुल 65-70 कमेंटेटरों की, लेकिन हड़बड़ी में महानिदेशक अपने सामने रखी अपनी ही माँग का पर्चा पढ़ना मूल गये और बोले, '65 हिंदी में और 70 अंग्रेजी में चाहिए होंगे.'

बस इतना कहना था कि महानिदेशक की शामत आ गयी और आखिर में साठे साहब को महानिदेशक की इज्जत बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। उत्तर में साठे साहब को सिर्फ इतना सुनता पड़ा 'साठे घोर ब्यायज नो नथिंग (साठे, आपके कर्मचारी खाक नहीं जानते)' बोलिए, अब साठे करें तो क्या करें! □

प्रदेश

नयी सर

हर क

खटव

विधानस

कुछ र

शुरू हुई उ

मंत्रिमंडल

रही। केरल

स्पष्ट होने

हरयाणा

उनका अस

पश्चिम वं

ग्रहण करने

"हरयाणा

व्यवहार वि

खतरे की

गणतंत्र की

पश्चिम ब

पश्चिम

वामपंथी म

की है औ

ही शायद

गया है। उ

जनमत क

स्वीकारने

स्वीकृति के

अभाव है?

है। बहरहा

मंत्रालयों

हुई वह इस

यहाँ भी स

विकल्प' अ

ईमानदारी

तो वामपंथ

है। सवाल

संवाददाता

में रपट:

"छब्बी

में राज

रूप से वं

मोर्चा की

सैमाल ल

मुख्यमंत्री

सहयोगियों

कुनाई म

चक्रवर्ती (

(साकपा)

दिलायी।

मंत्री जोड़े

दिनमान



## प्रदेश

नयी सरकारें

हर कहीं कुछ न कुछ  
खटक रहा है

विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कुछ राज्यों में जोड़तोड़ की जो राजनीति शुरू हुई उसमें अभी तक ठहराव नहीं आया है। मंत्रिमंडलों के गठन में भी यह उठापटक जारी रही। केरल और पश्चिम बंगाल में स्थिति स्पष्ट होने से वैसी दिक्कतें पैदा नहीं हुईं जो हरयाणा और हिमाचलप्रदेश में पेश आयीं, उनका असर अलबत्ता महसूस किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद ज्योति बसु ने बेबाक कहा: "हरयाणा के राज्यपाल ने जो लज्जाजनक व्यवहार किया है वह उस राज्य के लिए ही खतरे की बात नहीं है बल्कि संपूर्ण देश के गणतंत्र की जड़ पर कुठाराघात है।"

## पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार वामपंथी मोर्चे ने दूसरी बार सरकार गठित की है और इसी बड़े हुए मनोबल के कारण ही शायद मुख्यमंत्री का लहजा भी तुर्श हो गया है। उनके ऐसे सोच को बल मिला है उस जनमत का जिसने वामपंथी नीतियों को स्वीकारने की मुद्रा अपनायी है। क्या इस स्वीकृति के बीच किसी मजबूत विकल्प का अभाव है? यह बात अलबत्ता विचारणीय है। बहरहाल, वामपंथी मोर्चे की सरकार में भी मंत्रालयों के विभाजन को लेकर जो खींचतान हुई वह इस बात का आभास तो देती ही है कि यहाँ भी सब कुछ 'सुखकर' नहीं। अगर 'ठोस विकल्प' अभी से बनना और अपने आप को ईमानदारी से संगठित करना शुरू कर दे तो वामपंथी एकता में दरार पैदा कर सकता है। सवाल 'अगर' का है। कलकत्ता से 'दिनमान' संवाददाता की शपथ समारोह के बारे में रपट:

"छब्बीस मई की सुबह को कलकत्ता में राजभवन के अहाते में विशेष रूप से बने एक पंडाल के भीतर वामपंथी मोर्चा की दूसरी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाल ली। राज्यपाल भैरवदत्त पांडेय ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उनके चार अन्य सहयोगियों कृष्णपद घोष (माकपा), डॉ. कनौड़ भट्टाचार्य (फा. ब्लाक), जतीन चक्रवर्ती (क्रा. स. द.) और कनौड़ भौमिक (माकपा) को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायी। (मंत्रिमंडल का विस्तार कर 37 नये मंत्री जोड़े गये जिन्होंने 2 जून को शपथ

दिनमान

ग्रहण की। इस प्रकार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 42 हो गयी है)।

"इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मोर्चा के अध्यक्ष और मार्क्सवादी नेता प्रमोददास गुप्त भी राजभवन के अहाते में उपस्थित थे। चुनाव हारे हुए मंत्रियों में से केवल एक सुधीन कुमार संवाददाताओं की कतार में पीछे बैठे थे। कांग्रेस (इं) और कांग्रेस (श) का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। बाद में पता चला कि इन दलों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा और हमले की नीति के विरुद्ध प्रतिवादस्वरूप समारोह का बहिष्कार किया। लेकिन मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी नेता हार से शर्म के मारे नहीं आये। एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा "क्या वे मुंह दिखाने लायक रह गये हैं?"

"राजभवन से ज्योति बसु अन्य मंत्रियों के साथ राइटर्स विल्डिंग—राज्य सचिवालय—गये जहाँ मुख्य द्वार के सामने एक छोटा मंच उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और रहरह कर गोले छोड़ने के धमाके हो रहे थे। जैसे ही वह उतरे उन पर महिलाओं द्वारा पुष्पवर्षा की गयी और अनेक कर्मचारी संगठनों द्वारा पुष्पमालाएँ और पुष्पस्तवक प्रदान किये गये। प्रमुदित ज्योति बाबू ने चिलचिलाती धूप में खड़ी और बैठी भीड़ के प्रति अपना आभार प्रकट किया। पुनः भारी विजय के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद किया। फिर उन के लहजे में सख्ती आ गयी और उन्होंने हरयाणा के राज्यपाल के व्यवहार की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।

"निरंतर केंद्र विरोधी वक्तव्यों से वामपंथी मोर्चा ने अपनी धाक जमाये रखने की कोशिश की है और हाल के निर्वाचन में मिले भारी बहुमत से मोर्चा के नेताओं को विश्वास हो गया है कि उनकी यह नीति सही है। शायद यही कारण है कि श्री बसु ने चुनाव के बाद सत्ता की बागडोर संभालने के साथ अपने पहले वक्तव्य में केंद्र पर जोरदार बौछार की और इत्तिफाक

से उन्हें ऐसा विषय भी समय से मिल गया था जिसमें उनकी बात की अहमियत भी हो सकती है। उन्होंने हेमवतीनंदन बहुगुणा की जीत का भी उल्लेख किया और इसे प्रजातंत्र की विजय बताया।"

## हरयाणा

लेकिन हरयाणा में मतदान से लेकर चुनाव परिणामों तक रही अनिश्चय की छाया मंत्रिमंडल के गठन पर भी पड़ी। जिस प्रकार इका नेता भजनलाल ने केंद्र सरकार और राज्यपाल श्री तपासे के साथ अपनी गोठियाँ बिठायीं लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी समरनीति की मनक तक न पा सके। जब समझने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी और इस बीच वे अपने कुछ समर्थक भी खो चुके थे—शायद दूसरी ओर के प्रलोभन अधिक आकर्षक थे। प्रतिपक्ष दिल्ली और चंडीगढ़ में विरोधपत्र टाँगने और ठोकने भर की राजनीति ही कर सका और वह भी सटीक नहीं रही। भजनलाल ने 44 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत की थी जो सरकार के गठन तक 50 के आसपास पहुँच गयी है। इसमें 21 मंत्री हैं, वे सभी मंत्री बनाये गये जो बाद में आकर इका में शामिल हुए हैं। इनमें आठ निर्दलों के अलावा लोकदल की टिकट पर जींद से निर्वाचित बृजमोहन सिंगला भी हैं। बागी इका लछमनसिंह को उद्योगमंत्री बनाया गया है जिन्होंने कभी इस उम्मीद पर मुख्यमंत्री बनने का सुझाव उछाला था कि शायद बौखलाहट के कारण इका के विधायक उन्हें समर्थन प्रदान कर दें। भजनलाल विरोधी तत्त्व इका में उपस्थित हैं ही।

हरयाणा ने एक बार फिर दलबदल की अपनी पुरानी परंपरा का निर्वाह किया। क्या हुआ अगर पुराने दलबदलों को जनता ने नकार दिया। एक को हराओ, दूसरा हाजिर है। 19 मई के छोटे आम चुनाव में जनता ने

शपथ समारोह से पूर्व ज्योतिबसु अपनी पौत्री को प्यार करते हुए (दायें से) बसु की पत्नी धोमती कमल, पुत्र चंदन और बहू अपनी एक और बेटी के साथ





18 दलबदलुओं में से 16 को अस्वीकार कर दिया, 14 में से चार मंत्री भी हार गये, ऐन वक़्त पर भजनलाल द्वारा शामिल किये गये आठ में से एक भी उम्मीदवार विधायक नहीं बन सका। ये हारने वाले वही लोग थे जो 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर चुने गये थे और 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ पूरे दलबदल के साथ कांग्रेस (इं) में शामिल हो गये। केवल इन दलबदलुओं को ही नहीं, मतदाताओं ने लोकदल और भाजपा के पुराने उम्मीदवारों को भी नहीं बख़्शा। लोकदल के 13 में से छह पुराने विधायक नहीं जीत सके तो भाजपा के नौ में से चार विधायक हार गये। इस समय 61 नये विधायक चुनकर आये हैं। ऐसी अस्थिर स्थिति के बावजूद दलबदल के एक नये दौर की शुरुआत हुई जो शायद यहाँ के विधायकों को विरासत में मिली है। दलबदलुओं को मंत्री बनाये जाने पर जब कुछ लोगों ने वफादार इका विधायकों के सविष्य के बारे में भजनलाल की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो दोटूक उत्तर मिला: 'तमाम कारपोरेशन हैं, उनका अध्यक्ष भी तो किसी को बनना है।' लेकिन लोकदल के देवीलाल ने इन वफादारों को कल का 'सरकार गिराऊ तबका' करार दिया है। उनका तर्क है कि इनमें से अधिसंख्य विधायक बंसीलाल समर्थक हैं जो मौका मिलते ही भजनलाल की सरकार को गिरा देंगे। जरूरत चौकस रहने और इन लोगों में हिम्मत पैदा करने की है। देवीलाल के अनुसार 'पूरे कार्यकाल का दावा करने वाले भजनलाल अगर जून का महीना ही निकाल ले जायें तो बहुत बड़ी बात है'। बहरहाल, दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और प्रतिपक्ष विधानसभा अधिवेशन के दिन लाखों प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ लाने की बात कर रहा है। दलबदल की इस 'मगदड़' और 'पागलपन' पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर कुछ नेताओं ने दलबदल पर रोक लगाने की माँग की है। हरयाणा के राज्यपाल श्री तपासे ने भी राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा है कि भजनलाल को मंत्रिमंडल बनाने का दायित्व सौंपकर उन्होंने दलबदल पर रोक लगाने का प्रयास किया है।

### हिमाचलप्रदेश

वैशक हिमाचलप्रदेश में भी चुनाव परिणाम हरयाणा जैसे ही रहे लेकिन इका नेता रामलाल भजनलाल जैसे जल्दबाज़ नहीं। वह फूँक फूँक कर कदम रख रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल के गठन में भी उन्होंने सभी क्षेत्रों और संप्रदायों के लोगों का चुनाव करने में खासी सावधानी बरती। 2 जून को राज्यपाल अशोकनाथ वनर्जी



ज्योति वेंकटचलम : 'मैं तो राष्ट्रपति की प्रतिनिधि हूँ'

ने 14 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करायी। इन में सात काबीना मंत्री, चार राज्यमंत्री और तीन उपमंत्री हैं। इन में वे चारों निर्दल सदस्य भी हैं जो बाद में इका में शामिल हो गये। ये चार सदस्य हैं—गुलाबसिंह तथा मनसाराम (राज्यमंत्री) और मोतीराम और गंगूराम (उपमंत्री)। रामलाल पिछले पाँच बार से विधानसभा के लिए जीतते आये हैं। लेकिन 1980 में जिस प्रकार दलबदल करा कर उन्होंने सरकार गठित की थी, उससे उनकी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगा था। रामलाल सभी तबकों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उन्हें उस तरह के भीतरी खतरे का सामना न करना पड़े जो भजनलाल को हमेशा सालता रहा है।

### केरल

केरल में के. कृष्णाकरन ने बिना किसी होहल्ला के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की लेकिन सत्ता की बागडोर संभालने के बाद उनकी राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेंकटचलम से ठन गयी। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने उन सभी आदेशों पर अमल करने पर रोक लगा दी जो राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल द्वारा जारी किये गये थे। जिन निर्णयों पर स्थगन आदेश जारी किये गये हैं वे हैं: जाली अंकों के मामले में चिकित्सा छात्रों को निर्लंबित करने का आदेश, कोचीन के भूतपूर्व शाही परिवार की बहुमूल्य संपत्ति की खरीद-बिक्री आदेश आदि। इससे सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव में वृद्धि होगी। श्रीमती वेंकटचलम की नियुक्ति जनता सरकार के शासनकाल में हुई थी। कहीं उनकी नीतियों को उलटवा कर, जो वास्तव में राज्यपाल की अपनी न हो कर केंद्र सरकार

द्वारा नियुक्त विशेष सलाहकारों की सलाह से संपन्न होती हैं, कृष्णाकरन सरकार के घटक अपनी अपनी छवि सुधारने की फिराक में तो नहीं हैं! चुनाव परिणामों पर विभिन्न घटकों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए 'दिनमान' संवाददाता ने लिखा है:

"केरल विधानसभा के निर्वाचन परिणामों का विवेचन मोर्चों के आधार पर नहीं किया जा सकता। वामपंथी संयुक्त मोर्चा अथवा लोकतंत्रीय संयुक्त मोर्चा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रख कर बनाये गये संगठनों के नाम हैं। आज से छह मास पहले केरल कांग्रेस के दोनों गुट (मणि तथा जोसेफ) वामपंथी मोर्चों में थे, आज लोकतंत्रीय मोर्चों में हैं। वस्तुतः ये दोनों संगठन न कभी वामपंथी थे और न आज कांग्रेस (इं) की तरह लोकतंत्रीय हैं।

यदि मोर्चों की बात छोड़ कर चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि दोनों साम्यवादी दलों की लोकप्रियता गत पाँच-साढ़े पाँच वर्ष की अवधि में काफी घटी है। पिछली विधानसभा में भाकपा (मा) के विधायकों की संख्या 35 थी, किंतु इस बार यह संख्या 26 रह गयी है, इसी तरह भाकपा पिछली विधानसभा में 17 विधायकों को भेज सकी थी, इस बार वह केवल 12 प्रत्याशियों को विजयी बना सकी। दोनों साम्यवादी दलों के विधायकों की संख्या 14 घट गयी।

मोर्चों के आधार पर चुनाव परिणामों पर ध्यान दिया जाये तो कहा जा सकता है लोकतंत्री संयुक्त मोर्चों के 77 और वामपंथी मोर्चों के 63 प्रत्याशी विजयी रहे। यदि भाकपा (मा) और भाकपा पिछली स्थिति को भी कायम रखती तो वामपंथी मोर्चों के विधायकों की संख्या 63 की जगह 77 होती और लोकतंत्री मोर्चों के विधायकों की संख्या 63 रह जाती।

यहाँ के मतदाता राजनैतिक दलों के घोषणापत्रों से कम प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से मतदाताओं की एक बड़ी संख्या चुनावों के बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह प्रतिबद्धता सैद्धांतिक न हो कर जाति, संप्रदाय और समाज से जुड़ी हुई है। सिद्धांतों के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उतरने वाली साम्यवादियों की दोनों संस्थाओं के विधायकों की संख्या 14 कम हो गयी, किंतु अनेक गुटों में बँटने के बाद भी केरल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विधायकों की संख्या ज्यों की त्यों रही। केरल कांग्रेस को ईसाइयों और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। इस से कोई अंतर नहीं पड़ता कि केरल कांग्रेस या मुस्लिम लीग कितने गुटों में बँटती है और उस का कौन सा गुट किस मोर्चे में रहता है।



मध्यप्रदेश

## जबलपुर : तूफान से पहले ही शांति

सत्ताधारी कांग्रेस (इं) के प्रति तीव्र जनअसंतोष को जो आभास पिछली नवंबर के उजले, चमकीले दिनों में सागर के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस (इं) प्रत्याशी श्यामलाल ठक्कर के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के रामप्रसाद अहिरवार की विजय के रूप में नजर आया था, उसका चरम विस्फोट मई के जलते घघकते दिनों में, सागर से लगभग पौने दो सौ किलोमीटर दूर जबलपुर में हुआ, जहाँ कांग्रेस (इं) की प्रत्याशी और लगभग ढाई दशकों तक संसद में जबलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सेठ गोविंददास की कवयित्री पुत्री श्रीमती रत्नकुमारी देवी "काव्य-तीर्थ" भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जबलपुर के भूतपूर्व महापौर बाबूराव परांजपे से 13,238 मतों से पराजित हो गयीं।

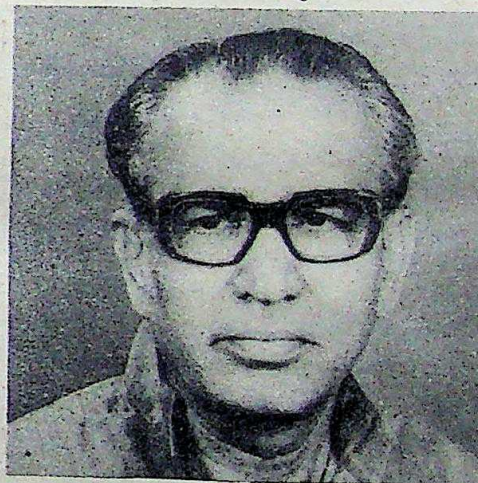
'ब्लैक डॉन' गेस्ट हाउस में शतरंज की चालें बिछाते हुए मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह, सैंकट हाउस में अपनी फौज के साथ सांसद विद्याचरण शुक्ल तथा रेलमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी अपने विश्राम कक्ष से भी इस सीट को नहीं बचा सके।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मध्यप्रदेश के इन तीनों दिग्गज नेताओं को स्पष्ट रूप से होशियार कर दिया था कि वे अपने मतभेदों को भुला कर जबलपुर की सीट को सुरक्षित रखें, अन्यथा तीनों को ही इसकी जिम्मेदारी वहन करनी होगी। तीनों नेताओं ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। 60 लाख रुपये का खर्च, सैंकड़ों जीपें, पचास विधायक, दो दर्जन मंत्री, आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री और एक दर्जन सांसद इस चुनाव मैदान में कूदे हुए थे।

विगत छह वर्षों से राज्यसभा की सदस्य रही आयीं, श्रीमती रत्नकुमारी को पिछली मार्च के अंतिम सप्ताह में दुबारा राज्यसभा के लिए चुना गया था लेकिन वे अपने पद की शपथ भी नहीं ले पायीं कि प्रदेश इंका के अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद मुंदर शर्मा के निधन से रिक्त हुई जबलपुर लोकसभाई सीट के लिए उन्हें इंका का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। श्रीमती रत्नकुमारी को राज्यसभा से त्यागपत्र देकर लोकसभा उपचुनाव का यह महासमर लड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह सागर में सत्ताधारी दल की पराजय के बाद जबलपुर के लोकसभा उपचुनाव के प्रति बेहद संयत और सतर्क थे और उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत तथा राजनैतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था। कांग्रेस (इं) की इस पराजय

से मध्यप्रदेश की सत्ता-राजनीति में निश्चय ही दूरगामी परिणाम होंगे।

1980 से मध्यप्रदेश की सत्ता-राजनीति में पुराने, ईमानदार, संकल्पी और जुझारू कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर भीड़तंत्र का जैसा अजीब और वीमत्स खेल शुरू हुआ, उसकी जड़ें न तो जनता में थीं और न ही जमीन के भीतर। यह भीड़ संगठित नहीं थी। विभिन्न गिरोहों में बँटे और अपने खुद के परिवेश से कटे इस सैलाब की प्रतिबद्धताएँ और वफादारियाँ मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह, रेलमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल को केंद्र बनाकर मोपाल से दिल्ली तक ही सिमट कर रह गयीं। नतीजा साफ था। अकर्मण्य कांग्रेसकर्मी न तो मतदाताओं द्वारा सौंपे गये विश्वास को पूरा कर पाये और न ही भ्रष्टाचार, महँगाई और अनियमितताओं के उस आलजाल से जनसामान्य को राहत दिला पाये, जिसे छिन्न-भिन्न कर देने का संकल्प लेकर वे 1980 के आम चुनाव के दिनों में



बाबूराव परांजपे : पहली बड़ी जीत

मतदाता के सामने आये थे। बदलती हुई फिजाँ में हवा के रुख से साफ जाहिर था कि आम आदमी ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बदलाव चाहा और जबलपुर में कांग्रेस (इं) को उसने गहरी शिकस्त दी।

यह अप्रत्याशित नहीं था कि श्रीमती रत्नकुमारी चुनाव हारें। चमत्कार तो तब होता, जब वे चुनाव जीततीं। सेठ गोविंददास की पुत्री होने के बावजूद जबलपुर के आम नागरिक के लिए से अजनबी ही थीं, क्योंकि चुनाव समाओं में अमी हाल में भाग लेने के अलावा वे आज तक न तो कभी जनता के सामने आयीं और न ही जबलपुर की किसी समस्या के प्रति कभी कोई दिलचस्पी ही उन्होंने प्रदर्शित की थी। राज्यसभा में जबलपुर की तरफ से पिछले छह साल तक प्रतिनिधित्व के बावजूद वे जबलपुर के सामाजिक और राजनैतिक परिवेश से गैरहाजिर और असंपृक्त ही रही

आयीं। वैसे भी, मुंदर शर्मा की अकाल मौत और सागर के लोकसभाई उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद यह साफ साफ महसूस किया जाने लगा था कि जबलपुर का आम नागरिक वर्तमान सत्तातंत्र और कांग्रेस (इं) की मौजूदा भ्रष्ट और निकम्मी कार्यशैली से बेहद खफा है। उसके इस विश्वास को बढ़ाया था इंदिरा कांग्रेस के आविपत्य में चल रहे जबलपुर नगरनिगम ने जिसने हरीतिमा और खूबसूरत पहाड़ियों के इस पत्थर शहर जबलपुर की गंदगी और अव्यवस्था के लिहाज से 'जिंदा नर्क' में तबदील कर दिया है। आवारा सुअरों, बजबजाती नालियों, बदबू देते कचड़े के ढेरों और अंधेरी गलियों-सड़कों से भरे, लगभग आठ लाख की आवादी वाले जबलपुर की जनता एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज है, जबकि जबलपुर तीन ओर से नर्मदा, गौर तथा हिरन नदियों से घिरा हुआ है। लोकदल की टिकट पर जीते युवा सांसद शरद यादव ने जबलपुर को नियमित वायुयान सेवा तथा जबलपुर से दिल्ली जाने वाली "नर्मदा-कुतुब एक्सप्रेस" मुहैया कर दी थी। लेकिन बाद के वर्षों में उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में जबलपुर बुरी तरह नेतृत्वशून्य हो गया। शहर की नुमाइंदगी उन चंद चेहरों और नामों तक ही सिमट कर रह गयी जिनकी कीमत मोपाल और दिल्ली के सत्ता दरबारों में खुशामदियों और चापलूसों से ज्यादा नहीं समझी गयी। यही कारण था कि जबलपुर का लोकसभाई उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर नगरनिगम की अक्षमता और जबलपुर के आठों इंकाई विधायकों द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की घोर उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लड़ा और वह इसमें कामयाब भी हुई। आम मतदाता खामोश जरूर था, लेकिन निष्क्रिय नहीं। उसके इस बदले हुए मिजाज का पता मई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगने भी लगा था। 12 मई को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी की सभा में जहाँ अस्सी हजार से लेकर एक लाख तक श्रोता मौजूद थे वहाँ दूसरे दिन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह, रेलमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी और सांसद विद्याचरण शुक्ल तथा एक दर्जन अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित की जाने वाली चुनाव सभा में दस हजार व्यक्ति भी नहीं थे, जो उपस्थित भी थे, उनमें बड़ी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सादी वर्दी पहने पुलिस वालों की होती थी। श्रोताओं के ही अभाव में कवि विधायक बालकवि वैरागी सभा तक नहीं कर पाये। विदेशमंत्री नरसिंहराव का आकर्षण भी सात-आठ हजार से अधिक की भीड़ नहीं जुटा पाया जबकि श्री आरिफ बेग और राजमाता सिधिया की सभाओं में दूरदराज



के देहातों में दस-दस हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी होती रही।

**जबलपुर** में पिछले दिनों हुए एक झगड़े में जबलपुर के विधायक और राज्य के जेलमंत्री हाजी इनायत की विवादास्पद भूमिका से उनके ही क्षेत्र में मतदाता इतने विक्षुब्ध थे कि मुस्लिम-बहुल उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही कांग्रेस (इ) भाजपा के मुकाबले लगभग पाँच हजार वोटों से पिछड़ गयी। हाजी इनायत की वजह से इंदिरा गांधी का नाम और आकर्षण भी मुसलमान मतदाताओं को भाजपा के खेमे में जाने से नहीं रोक पाया। लगभग यही स्थिति जबलपुर की हरिजन विधायिका श्रीमती माया सालवार की रही, जिनके अपने हरिजन मतदाताओं ने इंदिरा कांग्रेस के पंजे की बजाय भाजपा के कमल पर मुहर लगाना अधिक श्रेयस्कर समझा। बताया जाता है कि मतदाताओं के बदले हुए तेवरों को देखकर हाजी इनायत और श्रीमती माया सालवार को निर्देश दे दिये गये कि वे जनसंपर्क के लिए अपने अपने क्षेत्रों में न जायें। भितरघात की शिकायत जबलपुर के इंका विधायक चंद्रकांत भानोत के बारे में भी काफी मुखर रही, जिनके ठेकेदार पिता बनारसीदास भानोत खुद लोकसभाई उपचुनाव में इंका टिकट के इच्छुक थे।

जबलपुर की आठों विधानसभाई सीटों में कांग्रेस की स्थिति भाजपा के मुकाबले कटनी-मुड़वारा क्षेत्र में ही कुछ बेहतर रही। जहाँ श्रीमती रत्नकुमारी की श्री बाबूराव परांजपे के मुकाबले 2,268 मत अधिक मिले। मध्य-प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री मोतीलाल बोरा के प्रयासों से कटनी-मुड़वारा का कांग्रेसी गढ़ तो टूटने से बच गया लेकिन शेष सातों विधानसभाई क्षेत्रों—जबलपुर छावनी, जबलपुर पूर्व, पश्चिम तथा मध्य और पनागर, बहोरीबंद तथा सिहोरा में कांग्रेस (इ) अपनी साख नहीं बचा पायी। भाजपा कार्यकर्ताओं के सुदृढ़ अभियान तथा उनके शुरू अप्रैल से ही सैकड़ों की तादाद में पूरे जिले में झिंझर जाने से बाबूराव परांजपे को बड़ी शक्ति मिली। इंका का चुनाव अभियान पाँच मई के आसपास जब शुरू हुआ तब तक भाजपा जनसंपर्क के अपने दो दौर पूरे कर चुकी थी। इसके विपरीत मतदान के एक दिन पूर्व 18 मई तक इंका की तरफ से मतदाताओं के नाम की पर्चियाँ तक नहीं बँटी थीं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देश पर मध्यप्रदेश की सत्ता-राजनीति में तीन अलग अलग बिंदुओं पर खड़े अर्जुनसिंह, विद्याचरण शुक्ल तथा प्रकाशचंद्र सेठी को जबलपुर का लोकसभा उपचुनाव निकट तो लाया, लेकिन



(बायें से) अर्जुनसिंह, विद्याचरण शुक्ल और प्रकाशचंद्र सेठी : कितने पास, कितने दूर

समूचे प्रदेश कांग्रेस और जबलपुर के बदबू देते संगठन और म्रष्टतम तथा अक्षम नगर निगम के प्रति जबलपुर के मतदाता की नाराजगी को वे दूर नहीं कर पाये। ये तीनों राजनेता यदि एक साथ चुनाव अभियान में नहीं जुटे होते, तो श्रीमती रत्नकुमारी लगभग सत्तर-अस्सी हजार मतों से भी हार सकती थीं।

तीन बड़े नेताओं के एक साथ काम करने के बावजूद आपसी गुटबंदी में कहीं कमी नहीं थी। अगली कार्यवाही का फैसला बेशक तीनों मिल कर लेते थे लेकिन अमल उसी पर होता था जो मुख्यमंत्री चाहते थे। लिहाजा सतही सद्भावना और एका तो था जो भीतरी अविश्वास को दफन नहीं कर पाया। वहाँ के एक कार्यकर्ता के अनुसार "मुख्यमंत्री ने बिना श्री शुक्ल और श्री सेठी से परामर्श किये 90 विधायकों को जबलपुर पहुँचने का आदेश दिया जिस में से 50 विधायक पहुँच गये। मुख्यमंत्री की इस कार्यवाही पर दोनों नेता उखड़े और इस दरार को पाटने में इंका हाईकमान के पर्य-वेक्षक हरिकृष्णलाल भगत की सहायता लेनी पड़ी।" दिलचस्प बात यह है कि इन विधायकों को जबलपुर की राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जबलपुर में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की भीड़ तो जुटी थी जिस कालाम कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं ने उठाया। उन के जो काम महीनों और वर्षों से मंत्रियों के उपलब्ध न होने पर अटके रहते थे वे अब चुनाव के नाम पर तुरंत हो गये। इस से चुनाव में मदद तो नहीं मिली, कार्यकर्ताओं का फायदा हो गया।

मध्यप्रदेश के लौहपुरुष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र जबलपुर छोड़ कर स्वास्थ्यलाम के लिए पचमढ़ी चले गये थे। एक अन्य इंका संभव्य और बीड़ी उद्योग के सम्राट परमानंद माई पटेल का पूरा योगदान नहीं था। वैसे भी वे आजकल राजनीति में संन्यासी के रूप में ही अधिक जाने जा रहे हैं।

जबलपुर में समाजवादियों का भी खासा प्रभाव रहा है। अभी तक कांग्रेस को समाजवादी

ही हराते रहे हैं। भाजपा ने इंका को पहली बार मात दी। इंका और भाजपा के अतिरिक्त डॉ. के. एल. दुबे निर्दल उम्मीदवार थे। उन्हें शेष सभी प्रतिपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। इंका खेमा अपना मुकाबला डॉ. दुबे से मानता था। इस के कारण भी थे। बाबूराव परांजपे ने आज तक जितने भी चुनाव लड़े किसी में सफल नहीं हुए थे। इसलिए उन्हें 'पराजित परांजपे' कहा जाता है। लेकिन वर्तमान चुनाव में न केवल वह जीते ही बल्कि डॉ. दुबे की जमानत भी जब्त हो गयी।

मुख्यमंत्री विरोधी एक गुट उनका संबंध भाजपा के नेता सुंदराल पटवा से भी जोड़ता है। दोनों की घनिष्ठता के चरचे भी अक्सर सुनने में आते हैं। परांजपे भी पटवाप्रिय हैं। जनता पार्टी के शासन में वीरेंद्रकुमार सखलेचा के स्थान पर पटवा को मुख्यमंत्री बनाने में परांजपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। मुख्यमंत्री सखलेचा की नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए परांजपे ने 'जनाधिकार परिषद' नामक एक नया दल खड़ा कर दिया था। पार्टी में फूट के डर से तत्कालीन जनता पार्टी के घटक जनसंघ ने सखलेचा के स्थान पर पटवा को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय अर्जुनसिंह प्रतिपक्ष के नेता थे अब पटवा हैं। तब पटवा अर्जुनसिंह के प्रति उदार थे अब अर्जुनसिंह पटवा के प्रति हैं। मुख्यमंत्री विरोधी तो यहाँ तक कहते हैं कि परांजपे को जिता कर मुख्यमंत्री ने पटवा को अपनी मैत्री का परिचय दिया है। राजनीति तो राजनीति ही है, इस में सभी कुछ जायज है।

जबलपुर के लोकसभा उपचुनाव में इंका की पराजय के बाद भी मध्यप्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो अभी नजर नहीं आता लेकिन इतना तय है कि जबलपुर नगरनिगम और जबलपुर जिले के मौजूदा कांग्रेस संगठन को जरूर भंग कर दिया जायेगा। क्योंकि इनके निकम्मेपन की कीमत कांग्रेस (इ) को जबलपुर की सीट खोकर चुकानी पड़ी है। □



पंजाब

## फिर आतंक के साये में

कुछ महीने की खामोशी के बाद अमृतसर जिले के पट्टी कस्बे में 23 मई की रात्रि में हत्यारे मोटरसवारों ने फिर खून की होली खेली। कुछ माह पूर्व ही तो उन्होंने जालंधर और तरनतारन में कई लोगों को गोलियों से भून डाला था। अपेक्षाकृत शांत पट्टी कस्बे में शहीद मार्केट के थके-माँदे दुकानदार रात्रि को लगभग आठ बजे जब अपनी दुकानें बंद कर रहे थे तो निकटवर्ती दुकानों पर काली और नीली पगड़ियाँ पहने प्रतिबंधित दल खालसा के खूनी जत्थे के सदस्यों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलायीं शुरू कर दीं। इस गोलीकांड में तीन व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गये। घायलों को पट्टी और अमृतसर के अस्पतालों में दाखिल कराया गया।

बताया जाता है कि आक्रमणकारियों की संख्या 7-8 थी तथा वे दो-तीन टोलियाँ बना कर दुकानदारों पर टूट पड़े। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र रेडियोज की दुकान पर आकर उस दुकान के मालिक जसवंत और नरेंद्र पर गोलियाँ चलायीं। इन दोनों निरंकारी भाइयों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। बाद में आक्रमणकारियों ने आसपास की अन्य दुकानों पर भी अंधाधुंध गोलियाँ चलायीं जिससे एक अन्य व्यक्ति मिस्त्री पूरनसिंह मारा गया और कई घायल हुए।

कस्बे के भयभीत एवं आतंकित दुकानदारों के अनुसार दो आक्रमणकारियों के दोनों हाथों में पिस्तौल थीं। अनुमान है कि उन्होंने 100 से अधिक गोलियाँ चलायीं। ये हमलावर 15 मिनट तक पैदल बाजार में घूमते रहे और वहाँ से कैंरो मार्केट की ओर चले गये। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर गलियों या सड़कों पर खड़े कई युवकों को भी घायल कर गये। दुकानदारों के अनुसार यह आक्रमण पूर्व-नियोजित था। आक्रमणकारियों ने आते ही पहले सड़क के बिजली के खंभों पर लगी ट्यूबों को तोड़कर अँधेरा कर दिया तथा टेलीफोन के तार काट दिये। यह भी चर्चा थी कि ये आक्रमणकारी युवक जिनकी दाढ़ियाँ खुली थीं तथा सामान्य कपड़े पहने हुए थे, एक दो दिन पूर्व भी पट्टी के बाजार में सायंकाल घूमते हुए देखे गये थे।

बाजार के दुकानदारों में पुलिस को भूमिका को लेकर भारी रोष है तथा पुलिस की विफलता के विरोध में पट्टी के नागरिकों ने थाने का घेराव किया तथा अधिकारियों से माँग की कि वे जनता की रक्षा कर पाने में विफल रहे हैं। अतः अपने हथियार जनता को सौंप दे जिससे

कि वह अपनी रक्षा कर सके। नगर में भारी तनाव और आतंक की स्थिति है।

आक्रमणकारियों ने जिस स्थान पर से मुख्य बाजार में गोलियाँ चलायीं शुरू कीं वह स्थान थाने से सिर्फ 300 मीटर दूर है जबकि कोषागार, जहाँ सशस्त्र रक्षक रहते हैं, घटनास्थल से मात्र 200 मीटर की ही दूरी पर है। पुलिस 50 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँची।

आक्रमणकारी जिस प्रकार लापरवाही से पैदल चलते हुए गये उसे देखते हुए उन्हें आसानी से घेरा जा सकता था। बाद में सूचना मिलने पर अमृतसर के पुलिस प्रमुख तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। अमृतसर से और पुलिस वहाँ भेजी गयी तथा सारे क्षेत्र को घेरे में ले लिया गया। अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अमरसिंह बताया जाता है।

निरंकारी मंडल के प्रचार सचिव जोगेंद्र सिंह 'शांत' ने पट्टी से लौटने के बाद इस पर रोष प्रकट किया कि केंद्र और पंजाब की सरकारें निरंकारियों की रक्षा करने में विफल रही हैं।

हमलावरों द्वारा किस प्रकार अंधाधुंध गोलियाँ चलायीं गयीं उसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बाजार में सामान खरीदने आये युवकों तक

को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। 32 वर्षीय रमेशकुमार के पिता के अनुसार उनके बेटे पर दो सिख युवकों ने गोलियाँ चलायीं। उसकी छाती, पेट तथा बायें कंधे में घाव आये हैं। 62 वर्षीय दुकानदार मोहनलाल ने बताया कि वह जब अपनी दुकान में नकदी गिन रहा था तो उसकी पीठ में गोली लगी। दूसरी गोली गले में लगी। उसी समय एक सिख युवक ने नजदीक से उस पर गोली चलायी। उन्होंने अपनी हथेलियों में लगे गोलियों के निशान भी दिखाये। इसके अलावा हमलावरों ने एक 18 वर्षीय युवक नरेंद्र को भी गोलियों का निशाना बनाया। वह गोली लगते ही अपनी साइकिल से नीचे गिर गया। उसने बताया कि उसके नीचे गिरते ही एक सिख युवक पिस्तौल लहराते हुए उसके पास आया लेकिन उसे मरा समझकर चला गया। ये तीनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इस हत्याकांड के विरोध में पट्टी नगर में पूर्ण हड़ताल रही। नगर के सिख समुदाय ने भी इस घटना पर गहरा रोष प्रकट करते हुए हड़ताल में भाग लिया। एक थानेदार और दो सिपाहियों को निर्लंबित कर दिया गया है।

## “मैं एक अच्छा पंजाबी बनना चाहता हूँ”

पी. के. निशावन

“साफ कहूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। एक भारतीय के नाते मैं उस का समर्थक हूँ, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में उसका कोई विकल्प नहीं है। और भी, किसी अन्य शक्ति समूह ने मविष्य का आभास रखने वाले जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जैसे नेता पैदा नहीं किये। किंतु एक पंजाबी के नाते, जो घटनाचक्र को दूर से देख रहा है, मैं वहाँ की घटनाओं से दुखी हूँ। यदि आज की सत्ता राजनीति का परिणाम यथार्थ को विकृत करना और मुद्दों को मटकाना है तो मेरी जन्मभूमि का क्या बनेगा? और यदि आज पंजाब संकट में है तो कल भारत भी खतरे में होगा। मेरा मत है कि एक अच्छा हिंदू-सिख बने बिना आप एक अच्छे पंजाबी नहीं हो सकते और एक अच्छा पंजाबी बने बिना आप एक अच्छे भारतीय नहीं बन सकते। धर्मनिरपेक्ष होते हैं। जीवन मूल्य या विचार, धर्मांधता नहीं। पंजाब में वही लोग सच्चे धर्मनिरपेक्ष हैं जो मिलीजुली हिंदू-सिख संस्कृति को कद्र करते हैं।

“इस संस्कृति में विश्वास रखने वालों

का भारी बहुमत है। समस्या यह है कि वे घटनाओं के प्रति सतर्क नहीं हैं और यह कि उन्हें अपनी शक्ति का पता नहीं है। हनुमान को बार बार उन के बल की याद दिलानी पड़ती थी : खुद उन्हें अपनी ताकत का पता नहीं था। पंजाबी हिंदू-सिख समुदाय के बारे में भी क्या यही बात सच नहीं है?

“कुछ महीने पहले मेरी एक प्रतिष्ठित पंजाबी बुद्धिजीवी से बात हुई थी। उसने मुझसे पूछा था : ‘तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है?’ मैंने कहा : ‘एक अच्छा पंजाबी बनना।’ क्षणिक प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने कहा : ‘मेरी भी यही महत्वाकांक्षा रही।’ मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी जन्मभूमि से प्यार करने वाले हर विचारशील पंजाबी की यही महत्वाकांक्षा है—चाहे वह सिख हो या हिंदू।”

(श्री पी. के. निशावन एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं। पंजाब की समस्या पर उन का एक आलेख त्रैमासिक पत्रिका ‘मैन एंड डेवलपमेंट’ में छपा था जिसे ‘मैनस्ट्रीम’ ने अपने 22 और 29 मई के अंकों में छपा, उसी से सामार उद्धृत कुछ अंश।)



नेपाल

## राष्ट्रीयता का मतलब राजकीय टोपी पहनना नहीं है

नेपाल में पंचायती व्यवस्था का दमनचक्र चल रहा है। लोकतंत्र, जनमत संग्रह और चुनाव का ढोंग अब खुल कर प्रकट हो गया है। नेपाली शाह के निरंकुश शासन के अंतर्गत मूलभूत मानवाधिकारों और आजादियों को छीना जा रहा है। देश को पिछड़ेपन के अंधेरे से निकाल कर आर्थिक उत्थान और राष्ट्रनिर्माण के पथ पर अग्रसर करने में भी पंचायती व्यवस्था असफल रही है (बाक्स भी देखें)। ऐसी परिस्थितियों में पिछले दिनों जब काठमांडो में 29, 30 और 31 मार्च, 1982 को गुप्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाजवादी सम्मेलन में एक नये राजनैतिक दल की नींव रखी गयी तो आशा की एक नयी लहर पैदा हुई। नेपाली समाचार-पत्रों में इस की खूब चर्चा हुई।

सम्मेलन में नेपाल के सभी जिलों से एक एक प्रतिनिधि ने भाग लिया। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में युवा खून की प्रमुखता थी। लगभग 80 प्रतिशत लोग 40 साल से कम उम्र के थे। सम्मेलन ने एक 25 सदस्यीय केंद्रीय समन्वय समिति का चुनाव किया, जिस के अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य, संयोजक ऋषिकेश शाह, कोषाध्यक्ष तिलकराज शाही और सहसंयोजक दुर्गा सुबेदी बनाये गये।

सहसंयोजक दुर्गा सुबेदी एक उत्साही और समर्पित नवयुवक हैं, जो नेपाल की विद्यार्थी राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं और अनेक क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग ले चुके हैं। नयी पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इस वक्त नेपाल में निरंकुश राजशाही और पंचायती व्यवस्था के खिलाफ कोई प्रभावी आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया है। 1960 से नेपाली कांग्रेस जरूर इस का विरोध करती रही है। किन्तु व्यापक जनाधार न होने, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी और सीधी टकराहट से बचने की नेताओं की इच्छा के कारण वह कभी बहुत सफल नहीं हो पायी। दूसरी ओर साम्यवादी लोग हैं किन्तु वे भी अपनी व्यक्तिगत हत्या की राजनीति और आतंकवाद के चलते व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसलिए यह महसूस किया गया कि व्यापक जन आंदोलन और ठोस सिद्धांतों तथा कार्यक्रम पर आधारित एक दल की जरूरत है जो राजा

दिनमान

के निरंकुश शासन के खिलाफ सीधी टक्कर दे सके।

नया दल मुख्यतः कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन होगा। प्रत्येक जिले में फिलहाल 10-10 कार्यकर्ता तैयार करने की योजना है। सम्मेलन ने राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया है। उस का मत है कि राष्ट्रीयता का मतलब राजकीय टोपी या वेशभूषा पहनना या राजा के प्रति भक्ति रखना ही नहीं है, बल्कि जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग की राष्ट्रनीति निर्धारण में तथा सामाजिक शक्ति संरचना में न्यायसंगत भागीदारी नहीं होती तब तक लोगों में राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना जाग्रत करना और उसे राष्ट्रनिर्माण में लगाना असंभव है।

सम्मेलन ने जनता के सभी तबकों के बीच सुविधाओं और संपत्ति के समान वितरण की मांग की है और पिछड़े तबकों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए शासकीय सेवाओं तथा अन्य सुविधाओं में आरक्षण को जरूरी बताया है। इस वक्त नेपाल में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल कर राष्ट्रीय आय का 73 प्रतिशत उपभोग



दुर्गा सुबेदी



टंकप्रसाद आचार्य

करते हैं जब कि उन की आबादी सिर्फ 5 प्रतिशत है। जब कि राई, लिंबू, मगर तामां, थारू, राजवंशी जैसी पिछड़ी जातियाँ सभी क्षेत्रों में सुविधा-वंचित और उपेक्षित हैं। पंचायत व्यवस्था का, जिस के अंतर्गत पिछले तेईस सालों से राजनैतिक दलों पर प्रतिबंध लगा है और सभी बुनियादी अधिकार छीन लिये गये हैं, विरोध करते हुए इसने राजनैतिक आजादी की मांग की है और लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की है। नया दल विदेशनीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और दुनिया के देशों के बीच बराबरी में विश्वास रखता है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साम्राज्यवाद और शस्त्रों की होड़ की निंदा भी सम्मेलन ने की है। नये दल में अधिकतर वे लोग हैं जो पहले नेपाली कांग्रेस में थे किन्तु बाद में उसकी नीतियों से और वी. पी. कोइराला से मतभेद होने पर अलग हो गये। दल के अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य नेपाल की राजनीति के पुराने व्यक्तियों में से हैं और कोइराला के साथी रह चुके हैं।

## ‘नेपाल एक औपनिवेशिक अर्द्ध सामंती समाज है’

नेपाल की राजनीतिक गतिविधियों में वहाँ के छात्र संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। अखिल भारतीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन वहाँ का एक जुझारू प्रगतिशील और जनवादी छात्र संगठन है जिसकी सदस्य संख्या एक लाख है। नेपाल सरकार इस छात्र संगठन की लोकप्रियता से इतना अधिक आतंकित है कि उसने पिछले दिनों उसके राष्ट्रीय अधिवेशन पर न केवल रोक लगा दी बल्कि पंडाल भी नष्ट करा डाला। फिर भी यह अधिवेशन गुप्त रूप से हुआ। ऐसे जुझारू संगठन के अध्यक्ष और एशियाई छात्र महासंघ की कार्यकारिणी के सदस्य टंकप्रसाद कार्की से नेपाल की राजनीतिक स्थिति तथा छात्र संघ की गतिविधियों पर सिद्धार्थ चौधरी और राजेश राहुल की खुली बातचीत।

सर्वप्रथम, नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति कैसी है और उस के बारे में आप की राय क्या है?

नेपाल की राजनीतिक स्थिति जटिल है। 1960 से पूर्व नेपाल में एक तरह की संसदीय व्यवस्था थी, जिसके तहत जनता को चंद मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 1960 में फौजी मदद से नेपाल के शासक वर्ग ने निरंकुश शासन लागू किया और इस नये शासनतंत्र को ‘पंचायती व्यवस्था’ नाम दिया गया। पंचायती व्यवस्था ने सारे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और एकदलीय तानाशाही का दमनचक्र तेज हुआ। आज 60 प्रतिशत से भी अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है। पंचायती नेता (सामंत और गुंडे) ही विकास का सारा लाम हड़प रहे हैं। नेपाल एक औपनिवेशिक अर्द्ध सामंती समाज है। राष्ट्रीय आय का 87 प्रतिशत कृषि से आता है। 1937 के बाद जो कुछ भी औद्योगीकरण हुआ है, इसमें भारत के दलाल पूंजीपतियों के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और रूस की पूंजी लगी हुई है।

वर्तमान निरंकुश पंचायती शासन के विरोध

राजनीतिक संगठन करने के आरोप में उन्हें फाँसी की सजा हुई थी जिसे बाद में आजन्म कारावास में बदल दिया गया। वह अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। संयोजक श्री ऋषिकेश शाह ज्यादा विवादास्पद व्यक्ति हैं। वह नेपाली कांग्रेस के महामंत्री रह चुके हैं। कोइराला से मतभेद होने पर उन्होंने राजनीति छोड़ कर संयुक्तराष्ट्र संघ में नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। 1960 में संसदीय

6-12 जून '82



योशेक  
है

यों में वहाँ  
हिस्सा लेते  
थीं यूनिशन  
र जनवादी  
संस्था एक  
संगठन की  
कित है कि  
अधिवेशन  
पंडाल भी  
वेशन गुप्त  
गध्यक्ष और  
कारिणी के  
राजनीतिक  
धियों पर  
की खुली

राजनीतिक  
रे में आप

जटिल है.  
की संसदीय  
को चंद

में प्रतीति

कुश शासन  
नन्तंत्र को  
या गया.

क दलों पर  
तानाशाही

वश से भी

नेचे जीवन

रा (सामंत

प हड़प रहे

समाज

वे से आता

योगीकरण

पतियों के

र रूस की

के विरोध

प में उन्हें

में आजन्म

में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ हैं और इनका विकास किस प्रकार हुआ है. नेपाल के सारे विरोधी दल (सभी कम्युनिस्ट दल और नेपाल कांग्रेस) वर्तमान निरंकुश तंत्र के खिलाफ हैं, सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस को लीजिए, उसने 1961 में भारतीय हथियारों की सहायता से विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया और शासकों ने 'जनमतसंग्रह' की घोषणा की. वी. पी. कोइराला को भारत से सहयोग मिला किंतु ध्रुवीकरण तेजी से बदला और श्रीमती गांधी ने पंचायती शासकों को अपना समर्थन प्रदान कर दिया. भारत की अमेरिकापरस्त शक्तियों ने कोइराला को समर्थन देना जारी रखा. इसी दौर में संशोधन करके शासक वर्ग द्वारा उदारवादी होने का भ्रम फैलाया गया. भारत में आपत्काल लागू हो जाने पर कोइराला को भारत छोड़ना पड़ा और राष्ट्रीय मेल मिलाप का कार्यक्रम लेकर वह नेपाल लौटे. पंचायती शासकों और कोइराला ने समझौता कर लिया और एकजुट हो कर कम्युनिस्टों के खिलाफ जेहाद छेड़ दिया.

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (मा. ले.) तथा अन्य जनवादी शक्तियों के नेतृत्व में होने वाले संघर्षों के मुख्य कार्यक्रम क्या हैं? नेपाल की क्रांतिकारी और जनवादी शक्तियों के संघर्ष के मुख्य कार्यक्रम हैं—सामंती-निरंकुशता और पंचायती व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक संघर्ष, जो जनवाद की स्थापना करेगा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा. क्रांतिकारी और जनवादी ताकतों के खिलाफ राजसत्ता के दमन की वास्तविकता क्या है?

नेपाल में राजसत्ता का दमन बहुत तेज है. देश के समस्त राजनीतिकबंदियों में सर्वाधिक 90 प्रतिशत बंदी सी. पी. एम. (एन एल) से संबंधित हैं. जनमत संग्रह के समय सभी संगठनों के बंदियों को रिहा किया गया लेकिन ये लोग नहीं छोड़े गये. सी. पी. एन. (एम एल) देश का एक शक्तिशाली संगठन है, जो पूरी तरह गुप्त रूप से काम करता है.

नेपाल के जन आंदोलन में छात्र आंदोलन की भूमिका क्या रही?

सन् '60 से पूर्व नेपाल के छात्र आंदोलन का

व्यवस्था खत्म कर के निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में इन्होंने राजा का साथ दिया था. वर्तमान पंचायती व्यवस्था वाले संविधान का समीक्षा श्री शाह ने ही तैयार किया था. पंचायती सत्ता में 3 महीने मंत्री रहने के बाद नागरिक अधिकारों की बहाली के मुद्दे पर मतभेद होने से वे फिर विरोधी पक्ष में आ गये. किंतु उन का पिछला इतिहास देखते हुए श्री शाह कितने दिनों तक विपक्षी लड़ाई लड़

विनमान

नेतृत्व आल नेपाल स्टूडेंट्स फेडरेशन के हाथ में था. सन् '60 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. शासक वर्ग की ओर से एक नया छात्र संगठन खड़ा किया गया, जो पूरी तौर पर निष्क्रिय और छात्र विरोधी था. 1961 में जनवादी और प्रगतिशील छात्रों के नेतृत्व में छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा. 1965 में अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनिशन का सम्मेलन हुआ और सन् '68 में इसी नाम से यह संगठन क्रियाशील हो गया. तब से यह नेपाल के छात्रों की समस्याओं को लेकर जनता के विभिन्न वर्गों के साथ एकता कायम करके जुझारु संघर्ष कर रहा है.

अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनिशन के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन की वर्तमान दिशा क्या है?

1972 में नेपाल में व्यापक छात्र आंदोलन हुए जो मुख्य रूप से नयी शिक्षा योजना के विरोध में थे. 1975 में छात्र संगठनों को प्रतिबंधित और गैर कानूनी घोषित किये जाने के खिलाफ व्यापक संघर्ष हुए. 1979 में जनवाद की गारंटी और स्वतंत्र छात्र संगठन की मांग को लेकर आंदोलन हुए. शाही आयोग गठित हुआ, जिसने सभी छात्र संगठनों को कानूनी घोषित किया. मार्च 1981 में अ. ने. स्व. वि. यू. के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, जिसकी प्रमुख मांगें थीं—जनवादी अधिकारों की गारंटी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई. इस आंदोलन ने नेपाल के छात्र आंदोलन को एक नयी दिशा दी. चार महीने में लगभग 800 छात्र गिरफ्तार हुए. हमारे संगठन के 200 से अधिक छात्रनेता अभी भी नेपाल की जेलों में हैं. इतने दमन और यातना के बावजूद हमारा संगठन नेपाल के 67 कॉलेजों में से 63 कॉलेजों में छात्र संघ का नेतृत्व कर रहा है.

आपका संगठन प्रतिबंधित नहीं है, फिर आपका छात्र राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार ने क्यों नहीं होने दिया?

नेपाल में जनवादी अधिकारों का पूरी तरह गला घोट दिया गया है. छात्र यूनिशन के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन पर पाबंदी लगाता, इस बात का प्रमाण है. सम्मेलन शुरू होने के दो दिनों पूर्व ही लगभग 1500 सशस्त्र पुलिस दल ने

पायेंगे इस में संदेह है. अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य, सहसंयोजक दुर्गा सुबेदी जैसे लोगों की ज़रूर एक साफ और ईमानदार छवि है. दुर्गा सुबेदी ने वी. पी. के हिंसक आंदोलन से लेकर 1973 के हवाई अपहरण में भाग लिया और नेपाल और भारत दोनों जगह जेलों में कई साल बिताये हैं.

आज पूरा नेपाल सुलग रहा है और जन-असंतोष उभार पर है. तस्करी को शाही संरक्षण, जंगलों का विनाश, विकास और

पंडाल के भीतर से डेढ़ लाख रुपयों का सामान लूट लिया या बर्बाद कर दिया. कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. इतना ही नहीं उन्होंने हमारे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये विदेशी विद्यार्थी प्रतिनिधियों को भी विविध रूप से यंत्रणा का शिकार बनाया.

आपकी बातचीत से लगता है कि नेपाल जनवादी शक्तियों की एकता एक ऐतिहासिक ज़रूरत है. इस बारे में किसी व्यापक संयुक्त मोर्चे के निर्माण के लिए राजनीतिक पहलकदमी की जा रही है या नहीं?

हम पंचायती शासन और निरंकुशता के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता निरंतर महसूस करते हैं. यह एकता नेपाल के क्रांतिकारी और जनवादी घटकों के बीच होगी. नेपाली कांग्रेस इस मोर्चे में शामिल नहीं होगी. यदि मुद्दों पर वह साथ आती है तो अवश्य साथ देंगे. नेपाल में पंचायती शासकों और रूस समर्थक देशद्रोही शक्तियों को छोड़ कर सभी राजनीतिक शक्तियों का व्यापक मोर्चा निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष कर सकेगा.

भारत और नेपाल के छात्र आंदोलन की दिशा के समान और असमान (यदि कुछ है) मुद्दों के बारे में आपकी क्या राय है और कैसे दोनों देशों के जनवादी छात्र एकजुट हो सकते हैं?

भारतीय और नेपाली जनता के शत्रु एक ही तरह के हैं. हमारे संघर्ष को मुख्य दिशा सामंतवाद विरोधी साम्राज्यवाद विरोधी होगी. दोनों महाशक्तियों का विरोध अत्यंत आवश्यक है.

क्या क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद के खिलाफ क्षेत्रीय शांति स्थापना के लिए भारतीय और नेपाली छात्र एकजुट हो कर काम करेंगे?

हां, भारत में प्रगतिशील और जनवादी छात्रों के किसी एक राष्ट्रीय छात्र संगठन (राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि छात्र संगठन) के न होने से हमें बेहद दुःख होता है. भारत में छात्र आंदोलन को, जितना शीघ्र हो सके, एकजुट करना ज़रूरी है, जिससे नेपाल, भारत, भोटान, श्रीलंका पाकिस्तान और बंगलादेश के छात्र एकजुट हो कर प्रभुत्ववाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें. (इस भेंटवार्ता पर पाठकों की प्रतिक्रिया का दिनमान स्वागत करेंगे).

आर्थिक प्रगति का अभाव, गरीबी, उच्च वर्ग की विलासिता और सांस्कृतिक गिरावट ये सब चीजें लोगों को विरोध के स्वतः स्फूर्त रास्ते पर जाने को मजबूर कर रही हैं. देखना यह है कि किस हद तक असंतोष और विरोध एक रचनात्मक, आंदोलनात्मक और व्यवस्था विरोधी रूप ले पाता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिकसमाजवादी सम्मेलन और साम्यवादी संगठनों की उसमें क्या भूमिका होती है.



फॉकलैंड

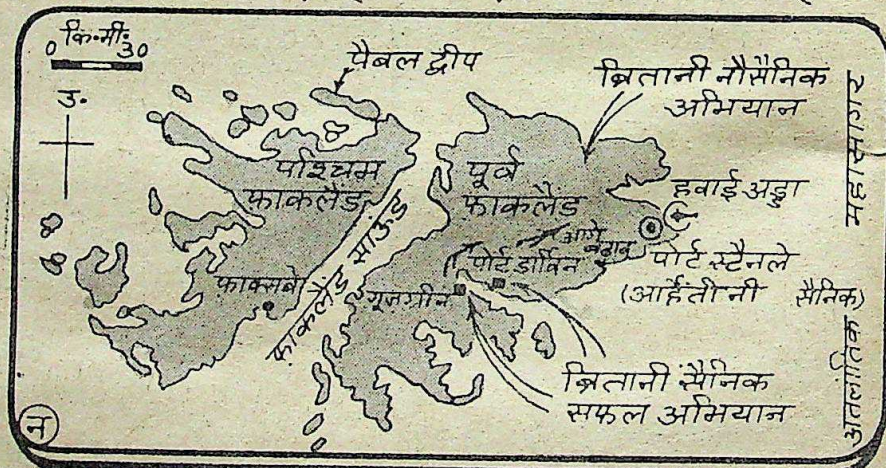
कहीं आहँतीना दूसरा कूबा  
न बन जाये

‘थल युद्ध अभियान’ शुरू करने के 26वें दिन ब्रिटेन जीत के बहुत करीब पहुँच गया है और ऐसी संभावना है कि जब तक दिनमान का यह अंक पाठकों के पास पहुँचेगा, ब्रिटेन का अर्ध संतुष्ट हो चुका होगा। 28 मई को पोर्ट स्टैनले के रास्ते में एक घमासान युद्ध के बाद जब ब्रितानी सैनिकों ने पोर्ट डार्विन और गूज ग्रीन पर कब्जा किया तभी यह स्पष्ट हो गया था कि आर्हुँतीनी सेना पोर्ट स्टैनले पर अधिक समय तक अपना अधिकार बनाये नहीं रख सकेगी और अब यह खबर है कि पोर्ट स्टैनले स्थित आर्हुँतीनी सैन्य अधिकारी ‘अंतिम क्षण तक लड़ने’ की बजाय, अगले तीन-चार दिन में कमी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

इस गैर बराबरी की लड़ाई में फ़तह ब्रिटेन को मिलेगी, इस बारे में शायद ही किसी को कोई संदेह रहा हो कि तु आर्हेतीना को घमकाने के लिए ब्रिटेन का शक्तिप्रदर्शन एक व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा ऐसा भी शायद ही किसी ने सोचा हो। बीच बीच में सोवियत हस्तक्षेप की आशंका अवश्य व्यक्त की गयी थी—कूवा द्वारा आर्हेतीना के समर्थन की घोषणा से यह आशंका बढ़ी ही थी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. आर्हेतीना को साम्यवादी खेमे का मौखिक समर्थन ही मिला और मिल रहा है. आर्हेतीना स्थित सोवियत राजदूत सेरगीज स्ट्रिगानोव ने ब्यूनस आयर्स में कहा है कि 'सोवियत संघ सुरक्षा परिषद् में आर्हेतीना को कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देगा.' सोवियत संघ का यह रुख स्वाभाविक ही है. गये वर्ष के अंत में जनरल गालतियरी अमेरिकी समर्थन से ही सत्तारूढ़ हुए थे और आज उनकी फौजें जिन हथियारों से ब्रितानी सेना से लोहा ले रही है वे उन्हें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से ही मिले थे. सोवियत खेमे के लिए इस से सुखद स्थिति और क्या हो सकती थी कि उसके दो विरोधी न केवल आपस में लड़ पड़े बल्कि उनकी इस लड़ाई ने उसके विरोधी खेमे को एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जिस से वह लड़ाई खत्म होने के बाद भी कई वर्षों तक निकल नहीं सकेगा.

कथित 'ब्रितानी युद्ध परिषद्' के सदस्यों के बीच इस लड़ाई को ले कर जो गंभीर मतभेद पैदा हुए हैं वे बहुत कुछ इसी उलझन के निम्नान

परिणाम है। विदेशमंत्री फ्रांसिस पिम और गृहमंत्री विलियम हिवटला जब यह कहते हैं कि 'अंतिम लड़ाई में उतरने से पहले आर्हेतीना को बातचीत का एक मौका दिया जाना चाहिए,' तो उनके मन में कहीं यह उलझन है कि ब्रिटेन युद्ध क्षेत्र में जीत कर भी यह लड़ाई जीत नहीं पायेगा। 12,000 कि. मी. से भी अधिक दूरी पर स्थित फॉकलैंड द्वीपसमूह पर शासन करना उसके लिए एक महंगा सौदा होगा। आर्हेतीना वहाँ लगातार छेड़छाड़ कर फॉकलैंड की मौजूदा लड़ाई को हार कर भी ब्रिटेन की नाम में दम किये रख सकता है, जिस के अंततः दूरगामी अंतरराष्ट्रीय परिणाम होंगे और उस से विश्व में ब्रिटेन की छवि बिगड़ेगी ही।



ब्रितानी संसद में विदेशमंत्री पिम ने इस बात को स्वीकारा है। उनके अनुसार 'आर्हेंतीना के भारी मानभर्दन के दूरगामी राजनीतिक तथा सैनिक परिणाम होंगे। इस से दक्षिण अतलांतिक में अमेरिकी प्रभाव कम होगा और सोवियत संघ को वहाँ दखल का अवसर मिलेगा। युद्ध में हारा आर्हेंतीना दक्षिण अतलांतिक में कूबा की भूमिका निभाने के लिए हाथ-पैर मारे तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्यों कि इस लड़ाई में अमेरिका समेत किसी भी 'नैटो' देश ने उसका समर्थन नहीं किया बल्कि ब्रिटेन के आह्वान पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहित पूरे पश्चिमी खेमे ने उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा कर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया।

किंतु आर्हेंतीना कूबा का रास्ता अपनाये  
यह न तो अमेरिका चाहेगा और न कोई अन्य

पश्चिमी देश. लातीनी अमेरिका पर सोवियत संघ की गिद्ध दृष्टि मुद्दत से लगी है. अगर आर्हेतीना को अपने पक्ष में करने में वह सफल हुआ तो उसे अन्य लातीनी अमेरिकी देशों को प्रभावित करने में सफलता मिल सकती है. ऐसा होने पर वह अमेरिका को दक्षिण अंत-लांतिक में उलझाये रख कर यूरोप और एशिया में अमेरिकी व्यूह रचना को कमजोर बना सकता है. यह न अमेरिका चाहेगा और न उसके यूरोपीय और पश्चिमेशियाई मित्र देश चाहेंगे.

संभवतः यही कारण है कि ब्रिटेन का एक तबका युद्ध में घन-जन की भारी हानि उठा कर भी आर्हेंतीना को सबक सिखाने के पक्ष में नहीं है। ब्रिटेन का उद्धत राष्ट्रवाद ही समझौते की बजाय रणभूमि में फैसला करने पर आमादा है। प्रधानमंत्री मारशेल् टैचर इन उद्धत राष्ट्रवादियों की नेता हैं जो यह मानती हैं कि 'युद्ध के इस चरण में आर्हेंतीना से समझौता वार्ता चलाने का मतलब आत्मसमर्पण होगा जिसे ब्रितानी जनमत कभी सहन नहीं करेगा। लडाई में ढील से फॉकलैंड में आर्हेंतीना अपनी

स्थिति मजबूत कर लेगा।' मानवता के लिए यह दुर्भाग्य की बात ही है कि इस समय ब्रिटेन का बहुमत लड़ाई के मैदान में फैसला करने के पक्ष में है। वह राष्ट्रवाद के उन्माद में यह मूल बैठा है कि 12,000 कि. मी. दूर लड़ी जा रही यह लड़ाई ब्रिटेन की पहले से ही खोखली अर्थव्यवस्था को और भी खोखला कर देगी जिस का खामियाजा न केवल ब्रितानी लोगों को भुगतना होगा बल्कि उसके कारण ब्रिटेन से आर्थिक सहायता पाने वाले विकासशील देशों का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होगा। फॉकलैंड की घेराबंदी के दौर में ही ब्रिटेन को प्रतिदिन 9 करोड़ रु. का खर्च उठाना पड़ रहा था, युद्ध छिड़ने के बाद तो यह खर्च कहीं अधिक बढ़ गया होगा। फिर युद्धपोतों और विमानों की क्षति के रूप में भी उसे इस बीच भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

यह क्षा  
व्यतिक्र  
आहे  
पड़ रही  
की उसव  
हैं लेकि  
गालतिय  
सत्ता में  
जारी र  
यह स्थि  
संभावन  
कि एक  
राजधान  
जाने प  
आहेँतीन  
जा सके  
ऐसा हल  
पक्षों को  
पर संयुक्  
करना भ  
सोविय

उत्तर  
सो विम  
कर  
बाद भी  
और देश  
लगायी  
दिल का  
कहा जा  
गंभीर ह  
घिकारी  
ब्रेज़नेव  
लिए उप  
रहे थे त  
सूत्रों के  
नेतृत्व में  
सोवि  
ग्रहण कर  
ऊपर पहुँ  
मृत्यु के व  
जा रहे  
बीमारी  
चुके थे उ  
हुई है. वा  
जा रहे हैं  
ऐसा नहीं  
पार्टी औ  
पार्टी को  
और किस  
दिया जा  
दिनमान



यह क्षति भी उसके आर्थिक कार्यक्रम में व्यतिक्रम लायेगी।

आर्हेतीना को भी युद्ध में भारी हानि उठानी पड़ रही है और ऐसा अनुमान है कि धन-जन की उसकी क्षति ब्रिटेन के मुकाबले कहीं अधिक है लेकिन चूंकि इस लड़ाई के साथ जनरल गालतियरी का भविष्य जुड़ गया है अतः वह सत्ता में बने रहने के लिए हार कर भी इसे जारी रखना चाहेंगे। पश्चिमी खेमे के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। ऐसी हालत में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बार लड़ाई थमने पर (फॉकलैंड की राजधानी पोर्ट स्टैनले पर ब्रितानी कब्जा हो जाने पर इसकी संभावना है) ब्रिटेन और आर्हेतीना को बातचीत के लिए राजी किया जा सके और उस बातचीत के दौरान कोई ऐसा हल खोजा जा सके जो फिलहाल दोनों पक्षों को स्वीकार हो। ऐसा एक हल द्वीपसमूह पर संयुक्तराष्ट्र संघ का अंतरिम शासन लागू करना भी हो सकता है। □

## सोवियत संघ

### उत्तराधिकारी की खोज

सोवियत राष्ट्रपति श्री ब्रेज्नेव के स्वस्थ हो कर अपने पद का कार्यभार सँभालने के बाद भी उनके उत्तराधिकारी के संबंध में देश और देश से बाहर तरह तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। मार्च के अंतिम दिनों में दिल का दौरा पड़ जाने की खबरों के बाद कहा जाने लगा था कि सोवियत राष्ट्रपति गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और उनके उत्तराधिकारी की खोज हो रही है। 75 वर्षीय श्री ब्रेज्नेव मई दिवस की परेड में सलामी लेने के लिए उपस्थित थे और स्वस्थ भी दिखाई दे रहे थे लेकिन फिर भी सोवियत संघ के ही सूत्रों के अनुसार सोवियत संघ के सर्वोच्च नेतृत्व में परिवर्तन होगा।

सोवियत नेताओं की आज की पीढ़ी अवकाश ग्रहण करने की कानूनी अवधि से भी दस साल ऊपर पहुँच गयी है। कहीं बीमारी तो कहीं मृत्यु के कारण इस पीढ़ी के लोग अब कम होते जा रहे हैं। श्री कोसिगिन हृदय की गंभीर बीमारी के कारण 1980 में अपना पद छोड़ चुके थे और श्री सुसलोव की मृत्यु जनवरी में हुई है। बाकी लोग भी धीरे धीरे अस्वस्थ होते जा रहे हैं। सोवियत व्यवस्था में कोई भी नेता ऐसा नहीं माना जाता जिसके हट जाने पर पार्टी और देश का काम न चले। कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में रखना सर्वोपरि नीति है और किसी को भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुँचने दिया जाता कि वह पार्टी से ऊपर हो जाये।



आंद्रोपोव : संभावित उत्तराधिकारी

सोवियत व्यवस्था के आज तक के इतिहास से स्पष्ट है कि पार्टी का कोई भी नेता अपनी इच्छा से पद छोड़ कर नहीं गया है। कब किसके हाथ से सत्ता छीन कर किसको दी जायेगी इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता।

**संभावित उत्तराधिकारी :** प्राप्त समाचारों के अनुसार श्री ब्रेज्नेव के उत्तराधिकारी का प्रश्न अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। लेकिन दो व्यक्तियों की इस पद के लिए चर्चा है। सोवियत राष्ट्रपति के बहुत पुराने सहायक श्री चेरनेनको और श्री आंद्रोपोव। आंद्रोपोव को हाल ही में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में लिया गया है। वह पहले के. जी. बी. के अध्यक्ष थे। श्री आंद्रोपोव को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के विख्यात नीति निर्वाहक और सिद्धांत प्रवर्तक श्री सुसलोव के स्थान पर केंद्रीय समिति में स्थान मिला है। श्री आंद्रोपोव के नाम की चर्चा इस लिए भी अधिक है कि वह सन् 1973 से पालित ब्यूरो के सदस्य चले आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय समिति में लिये जाने से पहले भी श्री ब्रेज्नेव के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम लिया जा रहा था। अभी दो अप्रैल को लेनिन की जन्मतिथि के अवसर पर क्रेमलिन समारोह में उन्होंने ही मुख्य भाषण दिया था। कहा जाता है कि यदि श्री आंद्रोपोव को श्री ब्रेज्नेव के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया तो सोवियत इतिहास की यह एक अभूतपूर्व घटना होगी। यह पहला अवसर होगा जब के. जी. बी. के किसी भूतपूर्व अध्यक्ष को सोवियत संघ का यह सर्वोच्च पद दिया जायेगा। सोवियत मामलों के विशेषज्ञों

के अनुसार इसका अर्थ अभी यह नहीं लगाया जा सकता कि सोवियत व्यवस्था में पार्टी का प्रभुत्व कम हो रहा है और के. जी. बी. का बढ़ रहा है। लेकिन इसे कोई साधारण बात भी नहीं माना जा सकता। सोवियत मामलों पर निगाह रखने वाले लोग बड़ी उत्सुकता से उत्तराधिकार का प्रश्न तय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचिव के रूप में अपने अठारह वर्ष के कार्यकाल में श्री ब्रेज्नेव के पास पार्टी के अन्य सदस्यों की तरह ही अधिकार रहे, स्तालिन की बात ही क्या उनके पास स्वर्गीय श्री ख्रुश्चेव जितने अधिकार भी नहीं रहे। वह सोवियत संघ के सामूहिक नेतृत्व का ही एक अंग रहे। इस लिए अपना उत्तराधिकारी चुनने का उन्हें अधिकार कैसे हो सकता है? इस संबंध में तो सोवियत संघ का सर्वोच्च नेतृत्व ही फैसला कर सकता है। सोवियत संघ के ही कुछ राजनीतिक सूत्रों के अनुसार श्री आंद्रोपोव को अधिक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कि पार्टी के लोग श्री चेरनेनको के पक्ष में नहीं हैं। अभी इस बारे में अटकलें ही लगायी जा रही हैं कि ब्रेज्नेव के निकट सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले सामने लाने में श्री आंद्रोपोव का हाथ था या नहीं। लेकिन अगर वह इन मामलों को सामने लाने में सहायक होते तो श्री ब्रेज्नेव पार्टी की केंद्रीय समिति में आने से उन्हें रोक सकते थे। सामूहिक नेतृत्व की सोवियत व्यवस्था में यह कहना कठिन है कि श्री आंद्रोपोव और श्री चेरनेनको में से कौन निकट भविष्य में श्री ब्रेज्नेव का उत्तराधिकारी बनता है। यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई तीसरा ही नेता उभर कर सामने आ जाये। पर इतना तो निश्चित है कि श्री ब्रेज्नेव के साथ सोवियत संघ की जो नीतियाँ जुड़ी हुई हैं वे तो रहेंगी ही भले ही श्री ब्रेज्नेव का युग समाप्त हो जाये। फिलहाल ब्रेज्नेव के उत्तराधिकारी के लिए अरसे तक उनकी उपस्थिति अनिवार्य बनी रहेगी। □

## इरीट्रिया

### सब अपनी स्वतंत्रता के लिए

इरीट्रिया में इथियोपिया को लगभग पिछले 21 वर्षों से विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए इथियोपिया ने जबर्दस्त सैनिक कार्रवाई की लेकिन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इथियोपिया सरकार को सफलता नहीं मिली है। वैसे सैनिक कार्रवाई की शुरुआत



तो फरवरी में ही हो गयी थी। लेकिन इस बीच इथियोपिया के कर्नल मैगिस्तु ने विद्रोहियों के लिए आम माफी का प्रस्ताव भी किया और साथ ही इरीट्रिया के लिए आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक विकास की गति तेज करने का वायदा भी किया। पर सैनिक कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी। इथियोपिया के ही सूत्रों के अनुसार रूसी सलाहकारों की मदद से इथियोपिया के कोई 90 हजार सैनिक चार मोर्चों पर विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में लगे हुए थे।

इथियोपिया सरकार ने अभी हाल ही में कुछ फ्रांसीसी पत्रकारों को इरीट्रिया प्रदेश के दौरे का निमंत्रण दिया था। उन्होंने अपनी रपट में कहा 'कि कुछ हिस्सों में विद्रोह शांत हो गया है। अस्मारा, केरन और मसावा नामक कस्बे इरीट्रिया सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में संघर्ष जारी है। यहाँ इथियोपिया



सेना का उद्देश्य नक़्सा नामक कस्बे पर कब्ज़ा करना है। लेकिन अभी तक भी इथियोपिया सरकार को इस में कामयाबी नहीं मिली है। इरीट्रिया की स्वतंत्रता के लिए 'इरीट्रिया मुक्ति मोर्चा' नामक संगठन काफी समय से संघर्ष कर रहा है। बताया जाता है इरीट्रिया इरीट्रिया में विद्रोह को दबाने के लिए 20 हजार इथियोपियाई सैनिक हटा-हट हुए हैं। इरीट्रिया मुक्ति मोर्चे के हताहतों की संख्या केवल 5 हजार ही है। खारतून में कुछ पश्चिमी राजनीयकों का विचार है इरीट्रिया के विद्रोह को दबाने के लिए इथियोपियाई सैनिकों में कोई खास उत्साह नहीं है। सन् 1978 में जब इरीट्रिया ने अपनी मुक्ति के लिए इथियोपिया पर पहली बार आक्रमण किया था तो इथियोपिया की मदद के लिए रूसी आये थे। इस युद्ध में इथियोपिया द्वारा रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग की भी पिछले दिनों खबर मिली थी।

इथियोपिया द्वारा वचनभंग : इरीट्रिया

दिनमान

सन् 1879 से सन् 1941 तक इटली का उपनिवेश रहा है। संयुक्तराष्ट्र के कहने पर 1952 तक ब्रिटेन इस का शासन प्रबंध चलाता रहा है। फिर यह इथियोपियाई संघ में एक स्वायत्त राज्य बन गया। लेकिन संघ के समझौते का इथियोपिया ने आज तक पालन नहीं किया है। सन् 1961 में इरीट्रिया ने अपनी स्वाधीनता के लिए सैनिक संघर्ष शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। उधर इथियोपिया स्वतंत्रता के इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए पिछले कई वर्षों से सैनिक कार्रवाई करता रहा है। इरीट्रिया के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कृत-संकल्प हैं। उनका संघर्ष जारी है। □

### दक्षिण अफ्रीका

## रियायत और अधिकार के बीच

संयुक्तराष्ट्र की जातिभेद विरोधी समिति एक ओर दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक सरकार की जातिभेद नीतियों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका को तेल तथा अन्य चीजें भेजने पर प्रतिबंध को और कड़ा करने के लिए अंतर-राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री बोथा कथित संवैधानिक सुधारों के नाम पर अपनी जातिभेद नीति को और भी सख्ती से लागू करने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। संविधान के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित एक सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि द. अफ्रीका में तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत अश्वेतों और भारतीय मूल के लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। पर दक्षिण अफ्रीका की शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था को संसद से भी अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही गयी है। प्रधानमंत्री श्री बोथा इन सिफारिशों से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी लोक-प्रियता गँवा कर भी मैं इन सुधारों को लागू करने की कोशिश करूँगा। यह पहला अवसर नहीं है कि जब दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने किन्हीं संवैधानिक सुधारों को लागू करने का अपना संकल्प व्यक्त किया। उनसे पहले प्रधानमंत्री श्री वोर्स्टर भी सुधारों के बारे में ऐसा ही उत्साह दिखा चुके हैं। पर श्री बोथा ने यहाँ तक कह दिया है कि उनकी सरकार को जातिभेद नियमों को लागू करने में अपनी जान तक की बाजी लगा देनी चाहिए।

कहने को सलाहकार समिति ने दक्षिण अफ्रीका की संसद को बहुजातीय संसद बनाने की सिफारिश की है जिस में अश्वेत तथा एशियाई मुख्यतः भारतीय भी होंगे। लेकिन

इन सिफारिशों में उन अफ्रीकियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है; जो कुल दक्षिण अफ्रीकी जनसंख्या का 70 प्रतिशत हैं।

दक्षिण अफ्रीका के सत्ताधारी दल नेशनल पार्टी ने राजनैतिक सुधारों के लिए कोई एक वर्ष पहले इस सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति की रपट के सुझावों से दक्षिणी अफ्रीकी सरकार को जातिभेद के मामले में और उदार बनाने की बात कही गयी है। लेकिन जातियों को अलग अलग रखने के कानून में कहीं कोई परिवर्तन का सुझाव नहीं है। इसी कानून के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार जातिभेद व्यवस्था बनाये हुए है। राजनैतिक सुधारों के सुझाव में मिश्रित जातियों और वहाँ रहने वाले भारतीयों के प्रतिनिधियों को राजनैतिक प्रक्रिया में शामिल होने की जो बात कही गयी है उस का उद्देश्य केवल यही दिखाई पड़ता है कि अफ्रीकियों के साथ किसी टकराव में ये जातियाँ गोरों का साथ दे सके। देखने में तो यह उदार प्रस्ताव लगता है लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के 70 प्रतिशत अफ्रीकियों को वही काले रंग का अछूत मान लिया गया है। इसलिए उनमें इन सुधारों के प्रति कोई उत्साह दिखाई नहीं पड़ता।

राजनैतिक सुधारों के अंतर्गत जो नयी प्रशासनिक व्यवस्था सुझायी गयी है वह श्री बोथा को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही ऐसे अधिकार देती है जिनसे वह जातिभेद नीति को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। श्री बोथा पिछले एक वर्ष से राजनैतिक सुधारों पर जोर दे रहे थे। लेकिन उन्हें लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में ये सभी सुधार कोई माने नहीं रखते। दक्षिण अफ्रीका के बहु-संख्यक अफ्रीकी अपने देश में ऐसा सुधार चाहते हैं जिससे वे अपने देश की काया पलट कर दें। लेकिन नये सुधारों में अफ्रीकियों को कोई ऐसा अवसर दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। पुरे अधिकार श्री बोथा के ही हाथ में हैं और ये सारे अधिकार ज्यों के त्यों उनके किसी उत्तराधिकारी के पास चले जायेंगे। किसी भी देश के संविधान में सुधार, प्रशासन को अधिकाधिक उदार बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह प्रस्तावित व्यवस्था को और भी कट्टर बनाने के लिए है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं ने प्रशासन पर नियंत्रण रखने की बात कभी सोची भी नहीं। निस्संदेह दक्षिण अफ्रीका का घटनाचक्र गोरी सरकार को वहाँ से काले अफ्रीकियों से अधिकाधिक समझौता करने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन गोरी सरकार अभी भी बहुसंख्यकों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। □

हाइटी

गरीब

कर फ्रांस

के रहने व

अन्यत्र व

हैं और

अमेरिका

लेकिन अ

वासियों

हो गयी है

खपाने की

रही है। इ

गया है—

में इन्हें

रहा है।

शरणाधि

के लिए

उन की

हाइटी के

के आप्रवा

कुछ कानू

हैं, जिन से

ही मुक्त

विदेशी

के मामले

अनुभव त

दीरान रा

के लिए अ

कर आने

बेलीज में

कुछ बाद

लेकिन जो

बेलीज स

व्यवस्था

संयुक्तराष्ट्र

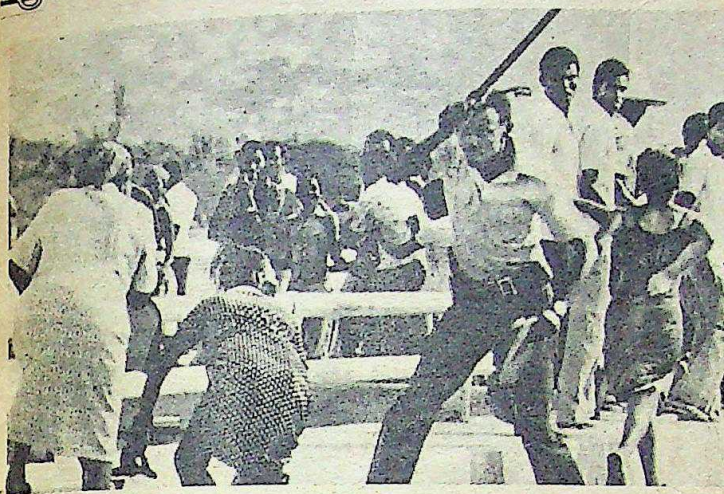
रही और

के शरणा

दिनमान



## दुनिया भर की



हाइटी से भागने वालों पर पुलिस का प्रहार

### हाइटी के शरणार्थी

गरीबी और अभाव से तंग आ कर फ्रांसीसीभाषी गणतंत्र हाइटी के रहने वाले अपना देश छोड़ कर अन्यत्र बसने की चेष्टा में लगे हुए हैं और उन का रुख अधिकांश अमेरिका की ओर ही होता है। लेकिन अब अमेरिका में हाइटी-वासियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गयी है कि रीगन सरकार उन्हें खपाने की समस्या का सामना कर रही है। इस का एक उपाय निकाला गया है—मध्य अमेरिका में बेलीज में इन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। बेलीज की सरकार इन शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हो गयी है, बशर्ते उन की संख्या नियंत्रण में रहे। हाइटी के शरणार्थियों ने अमेरिका के आप्रवासी अधिकारियों के लिए कुछ कानूनी अड़चनें पैदा कर दी हैं, जिन से बेलीज की सहायता से ही मुक्त हुआ जा सकता है।

विदेशी शरणार्थियों को बसाने के मामले में बेलीज की सरकार के अनुभव तीन वर्ष पुराने हैं। इस दौरान राजनैतिक हिंसा से बचने के लिए अल साल्वाडोर से भाग कर आने वाले 3,000 शरणार्थी बेलीज में ही बस गये। इन में से कुछ वाद में अन्य देशों में चले गये, लेकिन जो नहीं गये उन के लिए बेलीज सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था की। इस के लिए उसे संयुक्तराष्ट्र से सहायता मिलती रही और उम्मीद है कि हाइटी के शरणार्थियों को बसाने के

लिए भी संयुक्तराष्ट्र बेलीज की मदद करेगा।

### भूले बिसरे की याद

चीन में सर्वप्रथम परिवार नियोजन का प्रतिपादन करने वाले चीनी अर्थशास्त्री मा यिंचु, 101 वर्ष की उम्र में, पीकिङ में, परलोक सिंघार गये। 1950 वाले दशक के मध्य में उन्होंने चीन की जन-संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए परिवार नियोजन और विवाह की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस समय अध्यक्ष माओ त्से दुङ से मतभेद के कारण उन्हें मजबूर हो कर पृष्ठभूमि में जाना पड़ा। माओ का विश्वास था कि चीन को जनबल की आवश्यकता है, इस लिए परिवार नियोजन देश का अहित करेगा और 1970 के दशक में चीनवासियों ने अपने अध्यक्ष को निराश नहीं किया। उस समय चीन में जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ वह आज तक दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। माओ की मृत्यु के बाद ही चीन की सरकार मा यिंचु की फिर से सुध लेने के लिए हिम्मत बटोर पायी।

### राजनयिक संबंध का अंत

साऊदी अरब ने अफ्रीकी देश जायरे के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर देने की घोषणा की है, क्योंकि जायरे फिर से इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहता है। जायरे के इस फैसले पर खेद व्यक्त करते

हुए साऊदी अरब ने उस पर आरोप लगाया है कि जिन अफ्रीकी देशों ने 1973 में, अरब राष्ट्रों के अनुरोध पर, इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिये थे उन में जायरे भी शामिल था। लेकिन अब उस का यह आचरण वादाखिलाफी की मिसाल कायम करता है।

### ऑक्सफोर्ड की प्रतिभासंपन्न छात्रा

ब्रिटेन में उच्च शिक्षा और ज्ञान के सब से पुराने केंद्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ कर्णधार इस कोशिश में थे कि इस शिक्षा संस्थान में एक निर्धारित उम्र से कम के बच्चों को प्रवेश न दिया जाये, चाहे वह बच्चा कितना भी कुशाग्र बुद्धि वाला क्यों न हो। लेकिन हाल में गणितशास्त्री मैथ्यू गिसबर्ग का यह प्रस्ताव 10 वर्षीया रुथ लॉरेंस के प्रवेश के साथ रद्द कर दिया गया, जो अगले अक्तूबर से ऑक्सफोर्ड की छात्रा हो जायेगी। विश्वविद्यालय की परामर्श समिति के 1900 सदस्यों में से अधिकांश ने ऐसे प्रतिबंध के खिलाफ अपना मत जाहिर किया। रुथ को गणित की उच्च पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया है और वह विश्व-विद्यालय की सब से कम उम्र की विद्यार्थी होगी।

### समाज कल्याण के नाम पर

समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वीडन को अब तक एक आदर्श देश माना जाता रहा। लेकिन यहाँ के लोग समाज कल्याण के नाम पर दी जान वाली आर्थिक सहायता के इतने आदी हो चुके हैं कि उस से तरह तरह की सामाजिक और आर्थिक बुराइयाँ पैदा होने लगी हैं। इस संपन्न देश के लोग अब मेहनत से कमाने के बजाय सरकारी भत्ते पर अधिक निर्भर रहने लगे हैं। मार्च, 1981 से 1982 के मार्च तक, केवल स्टॉकहोम में, समाज कल्याण के नाम पर आर्थिक सहायता लेने वालों की संख्या में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई और इस साल पूरे वर्ष में समाज कल्याण के मद में खर्च

करने के लिए रखे हुए धन का 35 प्रतिशत साल के प्रथम तीन महीनों में ही खत्म हो गया है। अनुमान है कि वर्ष के अंत तक स्वीडन की सरकार को समाज कल्याण के लिए निर्धारित बजट से 1 करोड़ क्रोनर (स्वीडन की मुद्रा) अधिक खर्च करने पड़ेंगे।

### भारतीय उपग्रहों की शृंखला में अगली कड़ी

1985 के करीब छोड़ा जाने वाला भारतीय उपग्रह रूस से ही उड़ान भरेगा, ऐसा समझौता, मस्क्वा में, भारत और रूस के बीच हो चुका है। इस से पूर्व तीन और भारतीय उपग्रह—आर्यभट्ट, भास्कर-1 और भास्कर-2 भी रूस से ही छोड़े गये थे। भारत के हाल के उपग्रह इनसैट ने अमेरिका के केप कैनावराल से अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी।

### स्कूलों में प्रार्थना

अमेरिकी संविधान की एक धारा के अनुसार अब तक धर्म और राज्य को अलग रखना जरूरी था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति



रोनाल्ड रीगन

रीगन इस कानून में फेर बदल करने की बात सींच रहे हैं। उन्होंने—ने हाल में कुछ धर्मगुरुओं से इस बारे में चर्चा करते हुए सुझाव दिया है कि कांग्रेस को अब सार्वजनिक स्कूलों में प्रार्थना की इजाजत दे देनी चाहिए। राष्ट्रपति रीगन की पुरानी मान्यता है कि यह बात मानी नहीं जा सकती कि स्वेच्छा से प्रार्थना के दो शब्द बोल कर बच्चा अपना नुकसान कर लेगा, अथवा स्कूल या देश को उससे खतरा पैदा हो जायेगा। □

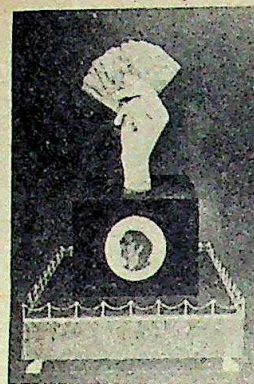


रमा जैन ब्रिज

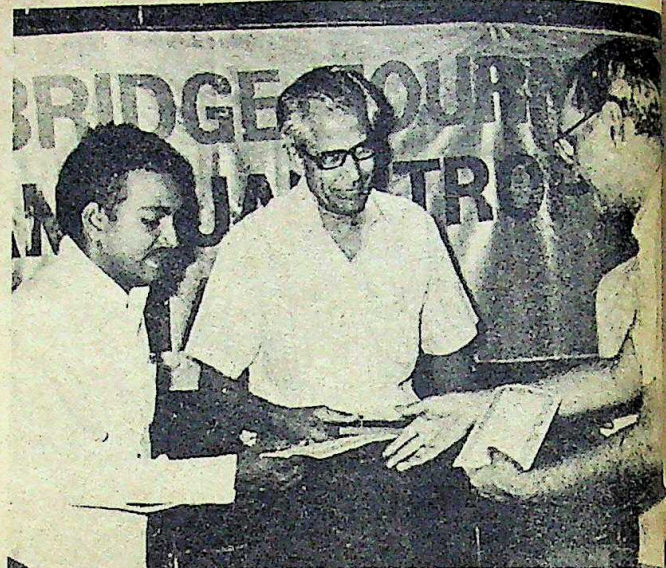
## अनुशासन के लिए

नयी दिल्ली में 23 और 24 मई को हुए प्रथम अखिल भारतीय रमा जैन ब्रिज ट्राफी टूर्नामेंट में आंध्रप्रदेश के अनुभवी खिलाड़ियों की जोड़ी (के. बी. कृष्णामूर्ति और मिनाजुल हसन) 15,000 रु. का प्रथम पुरस्कार लेने में सफल हुई है। भारत की अंतरराष्ट्रीय ब्रिज जोड़ी रवि राय और सुखरंजन घोष (पश्चिम बंगाल) दूसरे स्थान पर रही और उसे 7,500 रु. का पुरस्कार मिला। 3,500 रु. का तीसरा पुरस्कार तमिषनाडु की जोड़ी (जे. एम. शाह और कृपाकरण मूर्ति) को मिला बाई. एस. तयाल और के. सी. जैन की दिल्ली की जोड़ी ने पहले दिन काफी अच्छा खेल खेल कर आशाएँ जगायीं लेकिन फाइनल चक्र में उन की स्थिति मजबूत नहीं रही और उन्हें 1,500 रु. का नकद पुरस्कार और टूर्नामेंट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ।

दूसरे और तीसरे चक्र में अदभुत खेल दिखाने वाली दिल्ली की जोड़ी के खिलाड़ी बाई.



(ऊपर) रमा जैन ट्राफी :  
(दायें) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक जैन विजेताओं को पुरस्कार देते हुए



एस. तयाल ने अपनी पुरस्कार राशि भी दिल्ली ब्रिज फंड को दे दी।

इस टूर्नामेंट में देश की चुनी हुई 32 जोड़ियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में हुए फाइनल मुकाबलों के पहले देश भर में अनेकों खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।

उल्लेखनीय है कि टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह ने श्रीमती रमा जैन की स्मृति में एक आकर्षक रजत ट्राफी मेंट की है। कला और साहित्य के क्षेत्र में श्रीमती रमा जैन का योगदान सुपरिचित है। लेकिन यह बात शायद लोगों को न पता हो कि स्वयं श्रीमती रमा

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें। अपने विषय की विवरणी मंगाइये। कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। विवरणी हेतु लिखें। इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), पोस्ट बाक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विवरणी मंगाइये। पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

### एजेंट चाहिए

फिल्म, साहित्य व संगीत के हिन्दी मासिक राग, बहार को मंगाने हेतु न्यूजपेपर एजेंट संपर्क करें। व्यवस्थापक, राग बहार, 946, छोटा छीपीवाड़ा, चावडी बाजार, दिल्ली-6.

दिनमान

## एशियाड 1982 का कार्यक्रम

| खेल            | स्थल                       | बैठने की संख्या | तारीख           |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| उद्घाटन समारोह | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम    | 75,000          | 19 नवंबर        |
| तीरंदाजी       | अम्बेडकर स्टेडियम          | 25,000          | 21-22 नवंबर     |
| एथलेटिक्स      | ज. ल. ने. स्टेडियम         | 75,000          | 25 नव.-2 दिसंबर |
| बैडमिंटन       | इंद्रप्रस्थ स्टेडियम       | 25,000          | 25 नव.-3 दिसंबर |
| बास्केटबाल     | तालकटोरा स्टेडियम          | 4,000           | 20 नव.-3 दिसंबर |
| मुक्केबाजी     | प्रगति मैदान हाल           | 4,000           | 26 नव.-3 दिसंबर |
| साइकिल दौड़    | वेलोड्रोम, राजघाट          | 4,000           | 20 नव.-28 नव.   |
| घुड़सवारी      | हरबख्सा स्टेडियम           | 5,000           | 20-27 नवंबर     |
| फुटबाल         | फिरोजशाह कोटला मैदान       | 45,000          | 20 नव.-3 दिसंबर |
| जिम्नास्टिक    | इंद्रप्रस्थ स्टेडियम       | 25,000          | 20-23 नवंबर     |
| गोल्फ          | दिल्ली गोल्फ क्लब          | 5,000           | 21-24 नवंबर     |
| हैंडबाल        | दिल्ली विश्वविद्यालय मैदान | 7,000           | 22-29 नवंबर     |
| हॉकी (पुरुष)   | राष्ट्रीय स्टेडियम         | 25,000          | 20 नव.-1 दिसंबर |
| हॉकी (महिला)   | शिवाजी स्टेडियम            | 10,000          | 20-26 नवंबर     |
| नौकायन         | रामगढ़ झील (जयपुर)         |                 | 20-25 नवंबर     |
| निशानेबाजी     | शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद     | 5,000           | 22 नव.-2 दिसंबर |
| तैराकी         | तालकटोरा तरणताल            | 6,000           | 20-29 नवंबर     |
| टेबल टेनिस     | प्रगति मैदान हाल           | 4,000           | 19-25 नवंबर     |
| टेनिस          | हौजखास स्टेडियम            | 1,400           | 20 नव.-1 दिसंबर |
| बालीबाल        | इंद्रप्रस्थ स्टेडियम       | 25,000          | 20 नव.-3 दिसंबर |
| भारोत्तोलन     | एशियाई खेल गाँव            | 2,500           | 20-27 नवंबर     |
| कुश्ती         | अम्बेडकर स्टेडियम          | 25,000          | 25-30 नवंबर     |
| पाल नौकायन     | बंबई                       |                 | 20-28 नवंबर     |
| समापन समारोह   | ज. ल. ने. स्टेडियम         | 75,000          | 4 दिसंबर        |



एशियाड

## ‘नागरिकों की दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी’

एशियाड संयोजन समिति के महासचिव सूरिंदर सिंह गिल से ‘दिनमान’ की बातचीत

क्या निर्माणकार्य की प्रगति पर रोशनी डालेंगे?

‘एशियाई खेलों के बारे में ढाँचे 80 से 90 प्रतिशत तक तैयार हो चुके हैं। फिनिशिंग हो रही है। इस में भी नकली घास बिछाने का काम, एथलेटिक ट्रैक, रोशनी आदि का काम पूरा हो चुका है।’

‘ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफ खेल हो रहेंगे और दूसरी तरफ भजदूर लिपाई पुताई, मरम्मत में जुटे होंगे?’

‘नहीं, इस तरह के डर बेबुनियाद हैं। जिस गति के साथ सारा काम सही और पुख्ता हुआ है वह बेमिसाल है। विदेशी इंजीनियरों तक ने तारीफ की है।’

अक्सर मेजबान देशों में खेलों का पूर्वाभ्यास साल भर पहले शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ क्या कार्यक्रम है?

‘हमारे सभी स्टेडियम जुलाई के अंत तक बन कर तैयार हो जायेंगे। लिहाजा 12 से 20 सितंबर तक हम जम कर अभ्यास करायेंगे। ये अभ्यास चलते रहेंगे। इस बीच हमें स्टेडियम तथा उन की खामियों का हमें इत्म हो जायेगा।’

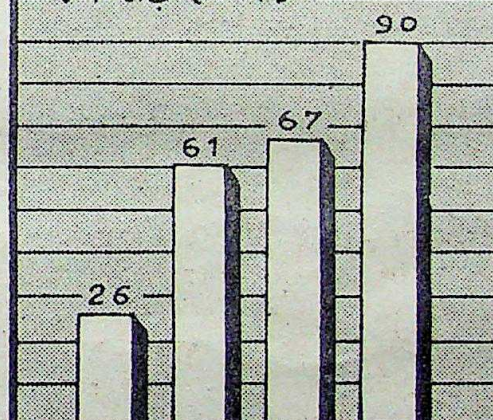
‘मैं अपने इंजीनियरों की कुशलता और परिश्रम की दाद भी दूँगा। अन्य देशों में जो काम छह बरस में पूरा होता है, हमारे इंजीनियरों ने उसे 18 से 21 महीनों के बीच कर दिखाया।’

निर्माणकार्यों पर जितना खर्च होने का अनुमान है? उस की वसूली की क्या व्यवस्था है?



एशियाड  
निर्माण-  
कार्य के  
खर्च-अनुमान

(करोड़ रु. में)



1977-78 1980 1981 1982

(मई)

(इसमें खेलगाँव शामिल नहीं)

(न)

‘हमें निर्माणकार्यों को तीन भागों में देखना होगा। पहले भाग में स्टेडियम आते हैं जो खेल के लिए अतिआवश्यक हैं। मूलतः इन पर 67 करोड़ रुपए खर्च होने थे। लेकिन हमारा अनुमान है कि अब 85 से 90 करोड़ रु. के बीच यह खर्च बैठेगा। दूसरे चरण में सात फ्लाईओवर, सड़कों का चौड़ा करना और मरम्मत, रेलवे का विद्युतीकरण, खेल ग्राम आते हैं जिन का प्रत्यक्ष तौर पर खेलों से संबंध नहीं। इन के बिना भी खेल संभव थे। इस मद पर 90 से 100 करोड़ रु. खर्च होगा। तीसरे चरण में होटल आते हैं जिन पर 200 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है। लेकिन होटलों का निर्माण निजी व्यवसाय के लोग कर रहे हैं। उन से हमारा वास्ता नहीं। आमदनी का जरिया इस प्रकार है : टेलीविजन प्रसारण के अधिकारों से ही एक करोड़ डॉलर प्राप्त होगा, खेलकूद के क्षेत्र में विज्ञापनों से 60 लाख डॉलर मिलने की संभावना है। लोगो और चिन्ह का उपयोग करने वालों से 15 करोड़ रु. प्राप्त होने की आशा है। टिकटों की बिक्री से केवल 10 प्रतिशत अर्थात् 1.5 करोड़ रु. की ही आमदनी होने की उम्मीद है। टिकटों की दर 3 से 5 रु. है, जो सिनेमा की टिकट दर से भी कम है।’

एशियाड के समय खाद्य पदार्थों की कमी के बारे में आप का क्या विचार है?

‘मेरा निश्चित मत है कि एशियाड की वजह से दिल्ली के नागरिकों की दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी। दिल्ली की 62 लाख की आबादी में तीन से चार लाख की आबादी को ‘चलताऊ’ आबादी ही कहा जा सकता है। एशियाड के समय एक लाख के आसपास लोगों के आने की संभावना है। इन लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए दिल्ली के निवासियों का हिस्सा कम नहीं होगा। □

जैन ब्रिज की अच्छी खिलाड़ी थीं। जैसा कि उद्घाटन समारोह वाले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अशोक जैन ने बताया कि वह अपने वचन में अपने माता पिता को अक्सर ब्रिज खेलता हुआ देखते थे।

इसलिए यह उचित ही है कि श्रीमती रमा जैन के नाम से एक अखिल भारतीय ब्रिज ट्राफी स्थापित की जाती। ब्रिज एक लोकप्रिय खेल है। इसलिए इस टूर्नामेंट में देश के कोने कोने में दिलचस्पी बनी रही। क्षेत्रीय स्तर की इन प्रतियोगिताओं में लगभग एक हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अकेले दिल्ली शहर में क्षेत्रीय स्तर पर 66 जोड़ियों ने हिस्सा लिया।

गोवा जैसे छोटे स्थान में भी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में 12 जोड़ियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी क्षेत्रीय स्तर पर काफी उत्साह की स्थिति बनी रही।

ब्रिज एक ऐसा खेल है जिसमें विशाल स्तर पर आम जनता हिस्सा लेती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में कोई बड़ा पुरस्कार भले ही न जीता हो लेकिन अब भारत के अनेक खिलाड़ी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली ब्रिज संघ के अध्यक्ष मुरलीधर डालमिया ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि अगर ब्रिज को राज-

नीतिक खेलना शुरू कर दें तो उन में अनुशासन आ जायेगा।

इस प्रथम इनामी ब्रिज ट्राफी टूर्नामेंट का उद्घाटन एशियाई खेलों के विशेष संचालन समिति के उपाध्यक्ष के. टी. सतारवाला ने किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों तो एशियाई खेलों के सिलसिले में नालियाँ और सड़कें खुदी पड़ी हैं। लेकिन एक जमाना था जब वह 1939 में लाहौर में ब्रिज खेला करते थे। आम जनता तक पहुँच सकने वाले इस खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं अपना काम खत्म कर के ब्रिज खेल सकूँगा। □



## समकालीन समस्याओं से जूझने की गवाही

‘कला का जोखिम’ निर्मल वर्मा का कला के मूलभूत प्रश्नों से गहराई तक जूझता हुआ चिंतनात्मक दृष्टि से स्वच्छ और पुष्ट निबंधों का संग्रह है। इस संग्रह से पूर्व प्रकाशित उन के निबंध संकलन ‘शब्द और स्मृति’ की मूल्यगत चिन्ताओं और कलात्मक पहलुओं के अनेक कोणों को यहाँ वैचारिक संपन्नता से और आगे विश्लेषित किया गया है। वास्तव में यह निबंध संकलन उनके पिछले कुछ वर्षों के दौरान किये गये चिंतन का निचोड़ लगता है। इस चिंतन ने एक ऐसी विशिष्ट शैली को जन्म दिया है जो उन के गद्य को काफी धारदार बनाता है और जिस में कला के उज्ज्वल सत्त्वों को बारीकी से अन्वेषित किया जा सकता है। इन निबंधों में वैचारिक घनता होने पर भी शैली इतनी आत्मीय रहती है कि इन्हें पढ़ना बड़े सुखद अनुभव से गुजरना है। प्रश्न और प्रश्नों से जुड़े प्रश्नों को उठा कर उन का मार्मिक विश्लेषण—विवेचन करना उन का स्वभाव प्रतीत होता है।

निर्मल वर्मा ने इन निबंधों को तीन उप-शीर्षकों में बांटा है—‘रचना-विधान’, ‘रचना कार’ और ‘रचना-यात्रा’। इस विभाजन के बावजूद इन निबंधों में अंतःसंबंध के अंतःसूत्र विद्यमान हैं, जिनमें नया कला चिंतन केंद्र में रहता है। निबंधों में देश विदेश के उदाहरणों ने प्रामाणिकता तथा तार्किकता को प्रबलता से रक्षित रखा है। ‘रचना चिंतन’ नामक उपशीर्षक के अंतर्गत पांच सैद्धांतिक ढंग के निबंध हैं—‘कला, मिथक और यथार्थ’, ‘परंपरा और इतिहास बोध’, ‘रचना की जरूरत’, ‘साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न’ और ‘संवाद की मर्यादाएँ’। इन सभी निबंधों में निर्मल वर्मा की चिन्ता और प्रश्नाकुलता आधुनिक सभ्यता के उस भयावह संकट को लेकर है जिसने आज की कला तथा कलाकार को जाने-अनजाने चारों ओर से घेरा हुआ है। उनका ध्यान बार बार इस बात पर जाता है कि आधुनिक सभ्यता के जटिल जाल में कला का स्थान कहाँ ठहरता है? बड़ी बेचैनी से निर्मल वर्मा प्रश्न उठाते हैं कि क्या आधुनिक कलाकार अपनी आत्मचेतना का अतिक्रमण कर सकता है? क्या कला में मिथक चेतना को हम वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध करा सकते हैं—एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जो मानव की भावात्मक ऊर्जा को ग्रस रही है और उस की भाव इंद्रियों का सिलसिलेवार संहार कर रही है, कला को क्या ऐसी आधुनिक सभ्यता में

विनयान • •



निर्मल वर्मा : चिंतन में नया खमीर

पुनर्जीवित किया जा सकता है जिसमें उस की चेतना प्रताड़ित, खंडित, निर्वासित, अमिश्रित तथा अजनबी है? वे इसी तथ्य को संकेतिक करते हुए कहते हैं—‘क्या आज हम एक ऐसी अंधी गली में नहीं पहुँच गये हैं जहाँ कला का मिथक बनने का स्वप्न अपने में ही संदिग्ध है क्योंकि जिस समाज व्यवस्था में हम रहते हैं, वहाँ कला के सामूहिक प्रयोजन का ही कोई अर्थ नहीं रह गया है?’ साथ ही युग का विशिष्ट अमिश्रण यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्य कलाप से विचलित हो गयी है वहाँ दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं बन सकी है जो स्वयं अपनी खंडित आस्था को अपनी स्वतंत्र गरिमा से अनुप्राणित कर सके। ‘कला की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के प्रश्न से कला तथा कलाकार का पूरा वर्तमान जुड़ा रहता है ऐसी स्थिति में कला की स्वायत्तता का सवाल ही कला का जोखिम है।’ यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कला का यह जोखिम ही ‘आज रचनात्मक क्रांति की मूल चिन्ता का विषय’ बनता जा रहा है। इन कलागत प्रश्नों में निर्मल वर्मा उन विचारकों की भाँति नहीं हैं जो दलबंदी की दलदल में फँस कर समसामयिक ज्वलंत प्रश्नों का अपनी पार्टी के हिसाब से उत्तर देते हैं। वह प्रश्नों का गोलमोल उत्तर न देकर उनसे सीधे मुठभेड़ करते हैं।

उन्हें यह परवाह एकदम नहीं है कि उनकी लाठी से अमेरिका का विचारक पिट रहा है या रूस का। विदेशी लेखकों को काफी विस्तार से पढ़ने पर भी वे उनके चिंतन के गुलाम नहीं बनते। उन का अपना चिंतन है जो जानता है कि भारतीयता के मूल तेज को कैसे थाहा जा सकता है। वे एक चिंतनशील भारतीय मनीषी की भाँति प्रश्न के सिंहासन पर उत्तर को बैठा कर चैन नहीं पा जाते। उन के चिंतन से मार्क्सवादी क्रोधित हो सकता है,

प्रतिगामी चितक मारपीट की तैयारी कर सकता है किंतु इन दोनों से ऊपर उठकर वह बोध को ही महत्त्व देते हुए लगते हैं। उनका चिंतन एक साथ पूर्व और पश्चिम के विचारकों को टटोलता है—चाहे वह परंपरा, आधुनिकता, इतिहास बोध, मिथक आदि जैसे कुछ प्रश्न हों या आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्रियों द्वारा दिये गये उत्तर हों। वह इस चिंतन में एक नया खमीर उठाते हैं। ‘परंपरा और इतिहास बोध’ नामक निबंध में वह कहते हैं ‘हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इतिहास का बोध प्रकृति की नैसर्गिक लय से प्राप्त किया था। पश्चिम के इतिहास आतंक से नहीं। इसीलिए वे व्यक्ति की मृत्यु को झरा हुआ पत्ता मानते थे जो खुद मिट्टी से मिल नये वृक्ष में अंकुरित होता है।’ (पृ. 26) निर्मल वर्मा ने परंपरा का रिश्ता ‘स्मृति’ से जोड़ा है—नॉस्टाल्जिया से नहीं। ‘मानव का यह आत्म निर्वासन उस आधुनिक बोध की देन है जिसमें यूरोप का खंडित काल बोध करा रहा है।’

‘रचनाकार’ उपशीर्षक में पाँच निबंध हैं—‘रेणु: समग्र मानवीय दृष्टि’, ‘अज्ञेय आधुनिक बोध की पीड़ा’, ‘मुक्तिबोध की गद्य कथा’, ‘हमारे समय का नाटक’, ‘नोबो कोव साहित्य शिक्षक के रूप में’। इन सभी निबंधों में सृजनात्मक समीक्षा की शक्ति का विस्तार मिलता है। अज्ञेय हों या मुक्तिबोध निर्मल वर्मा बेहद संतुलन से काम लेते हैं। अज्ञेय की चर्चा में लिखते हैं—‘शायद ही किसी लेखक ने अपने ऊपर इतने मूढ़, वैमनस्यपूर्ण, कर्कश प्रहार झेले हों, जितना अज्ञेय ने। फिर ‘शीत युद्ध’ के दिनों में वह ‘अमेरिकी एजेंट’ घोषित किये गये, बाद में उन्हें ‘गिराने’ के लिए समीक्षकों ने मुक्तिबोध को अस्त्र बनाया—वही मुक्तिबोध, जो अपने जीवन काल में इतने अधिक उपेक्षित बने रहे।’ (पृष्ठ 75-76) अज्ञेय तथा मुक्तिबोध के नाम से लगे जाने वाले समीक्षा समरों ने समसामयिक हिंदी समीक्षा को घायल कर दिया है। वैचारिक लड़ाई के नाम पर वैमनस्य भरी लड़ाई का यही परिणाम हो सकता था।

निर्मल वर्मा का रचनाकार और विचारक समकालीन सृजन और मूल्यांकन के प्रतिमात्र के प्रति बौद्धिक दृष्टि से कितना जागरूक है, और समकालीन समस्याओं से वह कितनी ईमानदारी के साथ जूझ रहे हैं, यह निबंध संकलन उसी की गवाही है।

—कृष्णदत्त पालीवाल

कला का जोखिम : निर्मल वर्मा; प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002. मूल्य-22 रु.



## कथा नौटंकी की और एक नौटंकी कलाकार की

डा. कृष्ण मोहन सक्सेना

एक पुराने टूटे-फूटे संकरी सीढ़ी से युक्त कमरे में कक्कू जी से कोई भी नौटंकी विषयक तरह तरह की बातचीत कर सकता है। वह ऊंचा सुनते हैं, चश्मा लगाते हैं किंतु स्मृति इतनी साफ सुथरी है कि एक युग का इतिहास वैसे का वैसे बताते चले जाते हैं और उजड़े लंबे कमरे के चारों ओर फ्रेमयुक्त नौटंकी कलाकारों के फोटुओं की ओर इंगित करते जाते हैं।

लखनऊ की नौटंकी परंपरा के प्रमुख स्तंभ पचासी वर्षीय सुनींद्र नाथ गोस्वामी उर्फ कक्कू जी आज भी नौटंकी के विकास में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। भारतेंदु नाट्य अकादेमी तथा प्रदेश व्यापी विभिन्न नौटंकी मंडलियों के प्रदर्शनों में वेशभूषा, व्यवस्था तथा नक्कारा वादन के साथ ही यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने वाले कक्कू जी अपने अहियागंज बर्तन वाली गली स्थित निवास पर नौटंकी केंद्र चला रहे हैं जिसमें उनके साथ श्रीमती मलका बेगम उर्फ 'अनारकली', राज बहादुर आदि प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 'नौटंकी केंद्र' प्रशिक्षण के अतिरिक्त परिरक्षण, प्रदर्शन, परिसंवाद, प्रकाशन आदि सभी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता है, किंतु समुचित स्थान, साधन सुविधा, अर्थ व्यवस्था तथा नौटंकी के प्रति शासन की एक साफ दृष्टि के अभाव में कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

कक्कू जी ने युवा गायक आशिक हुसैन को अपना शिष्य बनाया। नौटंकी मंच पर आशिक की शोहरत हुई और कक्कू जी के वह दाहिने हाथ हो गये। कक्कू जी ने उन्हें पुत्रवत् प्यार दिया। इलाहाबाद की एक अच्छे घराने की नौटंकी कलाकार मलका बेगम से उनकी शादी करायी। आशिक का सरी जवानी में आकस्मिक निघन हो गया और सरकार ने नौटंकी प्रदर्शन पर टैक्स लगा दिया। जिससे कक्कू जी का दिल टूट गया और नौटंकी मंडली भी बैठ गयी।

मलका बेगम को उन्होंने पुत्रवत् के रूप में संरक्षण दिया और बच्चों के पढ़ाने-लिखाने का दायित्व संभाला। मलका बेगम के मध्यप्रदेश में नौटंकी अनारकली के इतने सफल प्रदर्शन हुए कि मध्यप्रदेश के एक कार्यक्रम में उन्हें 'अनारकली' का खिताब मिला। मलका बेगम नौटंकी की गलत परंपराओं की विरोधी हैं और वह प्रदेश की स्तरीय नौटंकी मंडलियों में ही अब प्रदर्शन करती हैं।



(ऊपर) कक्कू जी  
तथा बायें से दायें :  
राजकुमार श्रीवा-  
स्तव, डॉ. गोविंद  
सत्यार्थी, आतमजीत



सिंह, मनोज कुमार, जितेंद्र मुग्ध, डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना और श्रीमती मलका बेगम : नौटंकी चर्चा

एक विशेष मेट में कक्कू जी ने बताया— लखनऊ में रहसलीला, इंदरसमा, स्वांग-सपेड़ा, भड़ती, भरथरी लोकनाट्यों का बोल-वाला रहा है। ब्रजभूमि से लखनऊ में जो भी रास मंडलियाँ आती रही हैं, वे स्वांग भी करती थीं। इस रासलीला से नवाब वाजिद अली शाह ने 'रहस' तथा अमानत ने इंदरसमा का रूप विधान तैयार किया और स्वांग से नौटंकी का विकास हुआ। जब नौटंकी का स्तर गिरने लगा तो रासलीला मंडलियों ने अपने शुद्ध धार्मिक रूप की रक्षा करने के लिए स्वांग करना छोड़ दिया। नौटंकी का इतना प्रभाव हो गया कि ब्रज से रासलीला मंडलियों का आना भी बंद हो गया। ब्रज में पहले स्वांगों में नक्कारा नहीं बजता था। लखनऊ के स्वांग-सपेड़ा में भी नक्कारा नहीं बजता था। लखनऊ में 'शाहजादी' नौटंकी-स्वांग में जब नक्कारा बजा और इसके नाम पर स्वांग का नया नामकरण नौटंकी हो गया तो फिर कानपुर में भी श्रीकृष्ण पहलवान की देखरेख में नौटंकी की शुरुआत हुई। फिर चौक के सोधी टोला के एक मंदिर में सांझी के मेले में तो नौटंकी की घूम मच जाती थी।

लखनऊ की पुरानी नौटंकी मंडलियों की चर्चा चलने पर कक्कू जी ने बताया—चौक, लखनऊ में आगरा के एक हलवाई उमराव सिंह की दुकान थी जो नौटंकी प्रेमी थे। रात में अपने दुकान के कर्मचारियों तथा मित्रों के सहयोग से वह नौटंकी किया करते थे। लखनऊ के एक दूसरे हलवाई पिम्पन के यहाँ भी हाथरस के नौटंकी के जानकार कर्मचारी थे। उसके यहाँ एक बार हाथरस के मुरलीधर माठ और उनके भाई भोला आये थे। उनकी प्रेरणा से नौटंकी शुरू हुई। इसी पिम्पन की मंडली के प्रदर्शनों के प्रेमी कक्कू जी के पिता चित्रकार पं. राम-नाथ गोस्वामी थे। कक्कू जी सन् 1915 के आसपास नौटंकी से जुड़े और जुड़े चले गये। कालांतर में लखनऊ में महबूब, बब्बन, शिव सहाय की मंडलियाँ बनीं, जो कुछ वर्षों तक चलती रहीं। कक्कू जी ने सन् 1930 के आस-

पास जो मंडली गठित की, वह दीर्घकाल तक जीवित रही। लखनऊ में रामनाथ ने नौटंकी मंडली गठित की जो कि अस्त-व्यस्त रूप में आज भी है। इसके प्रदर्शन क्षेत्र लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्न नाथ आदि नगर रहे हैं।

कक्कू जी ने 'वाह री किस्मत', 'लैला मजनू', 'श्रीमती मंजरी' आदि नौटंकियाँ लिखीं और प्रस्तुत करायीं। कक्कू जी की मंडली को बिहार राज्य से पर्याप्त निमंत्रण मिलते थे और यही इनका प्रिय क्षेत्र रहा है। कलकत्ता, करांची में भी कुछ प्रदर्शन किये। कक्कू जी ने ग्रामोफोन कंपनियों तक नौटंकी पहुँचायी। कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने कक्कू जी रचित 'राखा-बंजारा', 'लैला मजनू' तथा कानपुर के श्री कृष्ण पहलवान रचित 'मुल्ताना डाकू' तथा 'ऊदल का व्याह' की रिकार्डिंग की। हिज मास्टर वाइस ने 'बलिया का बलिदान', 'वीर अभिमन्यु' की रिकार्डिंग की। यह सब कार्य कक्कू जी की देखरेख में संपन्न हुआ। कलकत्ता की स्टार कंपनी ने दादरा तथा गजल की रिकार्डिंग की थी। लखनऊ आकाश-वाणी में जब अमृतलाल नागर नाट्य प्रस्तोता पद पर नियुक्त हुए तो कक्कू जी ने आकाश-वाणी में नौटंकी को गरिमापूर्ण स्थान दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने आकाश-वाणी के लिए तमाम लघु नौटंकियाँ भी लिखीं।

उन्होंने बताया हाथरस के छंद गायन का आधार ध्रुवपद गायन रहा है, जब कि कान-पुर का फिल्मी संगीत हो गया। अपनी मंडली मैंने हाथरस की शुद्ध गायकी और शुद्ध संवादों को ही स्थान दिया। कानपुर की नौटंकी मजदूरों की माँग पर भ्रष्ट होती गयी—नाच गाना और पारसी रंगमंच के प्रभाव से नौटंकी के नाम पर लोग नाक-भों सिकोड़ने लगे। हमारे यहाँ सही नाटकीय अभिनय और सादा मंच की ओर ध्यान दिया गया। कलकत्ता में मैंने नाटक तथा जात्रा देखी तो प्रभावस्वरूप अभिनय में बदलाव आया।

कक्कू जी ने संगीत-पक्ष की चर्चा चलने पर



बताया कि मैंने नौटंकी को समय के राग में प्रस्तुत कराया। रात को जब नौटंकी दस बजे से प्रारंभ होती तो देश राग प्रयुक्त करता। बाद में समय के अनुरूप रागों के स्वर गानों में लगवाता। लखनऊ के पुराने कलाकारों की चर्चा चलने पर वह बोले—ब्रज क्षेत्र की भीम-सेन मंडली की लखनऊ में बहुत धूम थी। इसमें वासुदेव, नत्थी, मुन्ना आदि लाजवाब कलाकार हुए। मथुरा के कलाकार घिस्सो का तो ब्रज में भी बड़ा नाम था। वह एक पांव से लंगड़े थे किंतु मंच पर उनकी गतिविधि और गायकी देखते ही बनती थी। लखनऊ के अब्दुल्ला अनवर, शंकर उर्फ फक्कड़, राज बहादुर आदि अच्छे कलाकार रहे हैं। पचासी वर्षीय फक्कड़ एक सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो कि एक खस्ताहाल मकान में रह रहे हैं, जो कि किसी भी समय घराशायी हो सकता है। गली गली धार्मिक पुस्तकें बेच कर वह दो-तीन रुपये कमा लेते हैं और इसी में संतुष्ट हैं। राज बहादुर कापी पेंसिल एक स्कूल के सामने बेच कर दो रुपये तक प्राप्त कर पाते हैं और कभी कभी वह भी नहीं। महिला-पात्रों में प्रमुख रही हैं—गुलाबबाई, कृष्णा बाई, अस्तरी, अन्नो, व्यामा, दुलारी, नूरजहाँ, रत्ना, अनवरी, छोटी, राधारानी, कमलेश, लता आदि। नवोदित कलाकारों में प्रमुख हैं—चंदारानी तथा राजोदेवी। नौटंकी में पहले सारंगी भी बजती थी। भूरे खाँ तथा मोहम्मद खाँ इस क्षेत्र के नामी/कलाकार हुए हैं।

नौटंकी की वर्तमान हालत के बारे में उन्होंने बताया—पहले स्वांग देखने हर वर्ग के दर्शक आते थे किंतु कानपुरी नौटंकी ने इस परंपरा को मिला कर दिया है। मंच पर कोरस में जहाँ सजी घड़ी युवतियाँ आयीं कि बस दर्शक फटियाँ कसने लगते हैं। फिल्मी गीतों की फरमाइशों का ऐसा दौर चलता है कि नौटंकी खेल एक तरफ रखा रह जाता है। यही आज की नौटंकी है। जो भी कलाकार हैं—उनका कुछ मालिकान जबर्दस्त शोषण कर रहे हैं। कलाकार भी कुंठित हैं, क्योंकि नौटंकी को संभ्रांत जन हीन भावना से देखते हैं और कलाकारों को पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता: कुछ नाच गाने वाली लड़कियाँ जो नौटंकी का ककहरा भी नहीं जानतीं, वे भी नौटंकी मंच पर उछल कूद कर के इस की बर्बादी करने में जुदी हैं। कलाकार अनपढ़ हैं और वे नयेबाजी में डूबे रहते हैं। उन्हें बस पैसे से मतलब है। यही हाल रहा तो कुछ दिनों में वह नौटंकी समाप्त हो जायेगी। क्योंकि कोई भी कलाकार अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लाना पसंद नहीं करता। नौटंकी में बहुत सी नसीहतें मरी पड़ी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और इस परंपरा का जीवित रहना जरूरी है। □

विनमान

## पुरातात्विक निधियों की चोरी

# वया विदेशी संग्रहालय ही कुमाऊँ की ऐतिहासिक मूर्तियों की नियति हैं?

आलेख : मुक्तेश पंत और आनंद बेल्लम उप्रेती

**19** अप्रैल को अल्मोड़ा जिले के गुणादित्य मंदिर से एक सूर्य की प्रतिमा, जिसका उस समय अष्टधातु का होना बताया गया, चोरी चली गयी। मूर्ति का वजन लगभग 80 कि. ग्राम था।

एक नाटकीय ढंग से 17 मई की प्रातः विकेनियाँ—(हल्द्वानी) में पुलिस द्वारा वही प्रतिमा एक मैटाडोर टैक्सी को घेर कर सनसनी खेज तौर पर बरामद कर ली गयी। पुलिस सूत्रों द्वारा मूर्ति का अनुमानित मूल्य उस समय 30 लाख रुपये कूता गया।

हालाँकि इस में संदेह नहीं कि स्थानीय पुलिस ने सकल इंस्पेक्टर गजराज सिंह के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही कर मूर्ति चोरों के अरमानों पर पानी फेर दिया, परंतु यह भी निर्विवाद है कि पुलिस को मौके पर सचेत करने वाले अनाम मोटर-मैकेनिक का कर्तव्य बोध ही मूर्ति की बरामदगी का आधार बना।

बरामदगी के समय तो एक भी व्यक्ति गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने अपनी आरंभिक असफलता के बाद तेजी दिखलायी और एक सूत्र की जानकारी के आधार पर, मूर्ति चोरों में से एक, लोहरियासाल (हल्द्वानी) निवासी नवयुवक, चतुरसिंह, को गिरफ्तार कर लिया। चतुर सिंह वारदात में प्रयुक्त मैटाडोर यू. टी. आई. 3655 में कंडक्टर रह चुका था।

गाड़ी के स्वामी एवं चालक जगदीश चंद्र बेलवाल को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन उसके नाम गिरफ्तारी वारंट

सूर्य प्रतिमा जो चुरा ली गयी थी। और वह मैटाडोर गाड़ी जिसके इंजन के पास मूर्ति को बरामद किया गया



तुरंत जारी कर दिया गया। सकल इन्स्पेक्टर गजराज सिंह के अनुसार प्रमुख अभियुक्त गिरफ्तारी में पुलिस को अधिक समय न लगेगा। चतुरसिंह से आरंभिक पूछताछ के बाद दोड़म (अल्मोड़ा) निवासी गिरीश को पुलिस ने घर पकड़ा।

पुलिस की नजर यू. टी. आई. 3655 पर पहले भी पड़ चुकी थी, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इसका इस्तेमाल गाँजा, चार तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के लिए समय-समय पर किया जाता रहा था। का का एक रोचक पहलू यह है कि अनेक व्यक्ति यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं। यू. टी. आई. 3655 पर जगदीश चंद्र का वैयक्तिक स्वामित्व प्रमाणित हो जाने के बावजूद वह स्वयं उसका नैतिक स्वामी भी है। उन अनुसार तस्करी की विसात में वह एक छोटे सा मुहरा भर है और दुस्साहस की श्रृंखला की कड़ियों में से एक अत्यंत क्षुद्र कड़ी—तो की सबसे निचली पायदान। सीढ़ी कहाँ तक किस तक पहुँचेगी इसका अभी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस स्वयं अपनी स्थिति मजबूत मानती है और शह को मात में बदलने देने के लिए हर चंद कोशिश कर रही है।

19 अप्रैल, कृष्ण पक्ष की घनी अंधियारा रात, मूर्ति चोर यू. टी. आई. 3655 पर गुणादित्य मंदिर में स्थापित सूर्य प्रतिमा चुराने की नियत से पहुँचे। एक सूत्र के अनुसार अपने हाथों से वे जब मूर्ति को टस से मस न कर पाये तब उन्होंने मैटाडोर के पिछले मडगाई रस्सी का एक सिरा बांध कर रस्सी के दूसरे सिरे से सूर्य प्रतिमा को लपेट लिया और मैटाडोर को मानो सूर्य का रथ बना कर मोटोस्टार्ट कर सूर्य को उसके स्थान से बलात् उखाड़ थोड़ी दूर तक गाड़ी के पीछे घसीट कर रात रहते ही 'सूर्य' को बाहर खींच निकाल दिया!

चोरी के बाद सीनाजोरी वाले अंदाज में चोरों ने सूर्य प्रतिमा के दायाँ हाथ का कुल्हाड़ा, शायद तस्करी को मूर्ति के सुव्यवस्थित दिखाने या कीमत लगवाने की नीयत से एक तेज औजार से काट डाला।

28 दिनों के इस अंतराल में मूर्ति के अनेक स्थानों में रखने की बात भी प्रकाश में आयी है। हल्द्वानी से लगभग 8 कि. मीटर दूर

लामाचोड़  
दिन तक  
यह तो  
सकती है  
का हाथ था  
हैं ही कि  
तब भी का

कुमाऊँ  
2500 से  
तम्यता के  
किंवदंतियों  
के सूर्यवंशी  
अधुनातन

स्पष्ट प्रमाण  
वंशी शासक  
प्राचीन काल  
ये।

कत्यूरिय  
संरक्षण एवं  
रहा। कत्यूर  
का निर्माण  
में दुर्गम से  
कलाकृतियाँ

मूर्ति का  
रखते हुए  
प्राचीन और  
कुमाऊँ में  
मूर्ति को चंद  
नहीं क्योंकि  
तो कत्यूरिय  
नवीं शत

कुछ भाग  
उनके शासन  
नहीं फिर भी  
इतिहासकारों  
जिनका नाम  
नामक स्थान  
अथवा आदि  
इस गाँव को  
आधार लग  
मूर्ति कल

प्रतिमा का  
निमित्त है। सू  
प्रदर्शित की  
द्वितीयतः रथ  
पदमपीठ पर  
और दायाँ अ  
उनके परिच  
हाथों से स्कं  
सुशोभित हैं  
प्रतिमा में घु  
गये हैं, जो  
निजी विशिष्ट

विनमान



हासि

किल इस्पे

अभियुक्त

क समय

छटाछ के

गरीश को

ई. 3655

क विश्वसनी

ग गांजा, च

स्करि के लि

रहा था. क

अनेक व्यक्

ही नहीं

श चंद्र का व

बावजूद व

मी है. उन

वह एक छो

न की शृंख

कड़ी-सी

कहाँ तक

कोई ठिका

पुलिस स्व

और शह को

चंद कोशिश

नी अधिया

3655 प

प्रतिमा चु

त्र के अनुस

से मस न क

ले मडगाई

स्सी के दू

लिया औ

ना कर मो

न से बला

पीछे घसी

नीच निक

ले अंदाज

हाथ का कु

सुच्चेपन

की नीयत

ग.

में मूर्ति

भी प्रकाश

क. मीटर

12 जून '82

लामाचोड़ नामक स्थान में भी मूर्ति को कुछ दिन तक गाड़े रखना बताया जाता है।

यह तो कुछ अनुमान की बात भी हो सकती है कि चोरी में दरअसल किन तत्वों का हाथ था लेकिन ये आशंकाएँ तो अपनी जगह हैं ही कि धर्म की आड़ में तस्करी करने वाले तत्व भी कहीं इनमें शामिल न हों।

कुमाऊँ प्रदेश में कत्यूरी सम्राटों ने ई.पू. 2500 से 700 ई. तक शासन किया। तार-तम्यता के अभाव के बावजूद इतिहासकारों ने किंवदंतियों का सहारा ले इनका संबंध अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों से जोड़ दिया, लेकिन अधुनातन खोजों के आधार पर इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि ये अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों के वंशज न होकर इस प्रदेश में प्राचीन काल से रह रही खस जाति से संबंधित थे।

कत्यूरियों का काल अप्रतिम मूर्ति कला के संरक्षण एवं मूर्तियों के निर्माण का काल रहा। कत्यूरी सम्राटों ने अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण कराया व समूचे उत्तराखण्ड में दुर्गम से दुर्गम स्थलों पर एक से बेजोड़ कलाकृतियाँ स्थापित करवाने में पहल की।

मूर्ति कला के इस आधार को ध्यान में रखते हुए गुणादित्य की चोरी गयी यह मूर्ति 11वीं और 12वीं शती की ठहरती है। यद्यपि कुमाऊँ में यह काल चंद शासकों का था। इस मूर्ति को चंद वंश का मानने का कोई औचित्य नहीं क्योंकि अधिक से अधिक यह चंद शासकों की कत्यूरियों की विरासत थी।

नवीं शताब्दी से 200 वर्षों तक कुमाऊँ के कुछ भागों में खसों का शासन रहा। यद्यपि उनके शासन काल की कोई भी घटनाएँ ज्ञात नहीं फिर भी 15 पीढ़ियों तक उनके शासन को इतिहासकारों ने स्वीकारा है। इनके नवें शासक जिनका नाम गुणा था, संभव है गुणादित्य नामक स्थान के लिए जिम्मेदार रहे हों। सूर्य अथवा आदित्य की प्रतिमा यहाँ होने के कारण इस गाँव को ही गुणादित्य कहलाने का समीचीन आधार लगता है।

मूर्ति कला की शैली के आधार पर गुणादित्य प्रतिमा का मुकुट स्पष्टतः कत्यूरी शैली में निर्मित है। सूर्य की प्रतिमाएँ प्रायः दो प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं—प्रथमतः पद्मपीठ व द्वितीयतः रथ पर आसीन। गुणादित्य की मूर्ति पद्मपीठ पर खड़ी है जिसके बाँयी ओर दण्ड और दायीं ओर पिगल स्थित है, जो दोनों ही हाथों में स्कंधों के ऊपर सनाल विकसित कमल सुशोभित हैं और पीछे की ओर कमलासन है। प्रतिमा में घुटने तक पहुँचने वाले बूट दर्शाये गये हैं, जो सूर्य की खड़ी प्रतिमाओं की एक निजी विशिष्टता है।

विनमान

## सूजा के साथ एक शाम

पिछले दिनों साहित्य कला परिषद, दिल्ली ने आइफैक्स में 'सूजा के साथ एक शाम' गोष्ठी का आयोजन किया। इसी के साथ परिषद के कला मंच की शुरुआत भी हुई। परिषद का एक साहित्यिक मंच पहले से ही है। सूजा को सुनने और उन का काम देखने के लिए दिल्ली के कलाकार, लेखक, पत्रकार एक भारी संख्या में उपस्थित हुए।

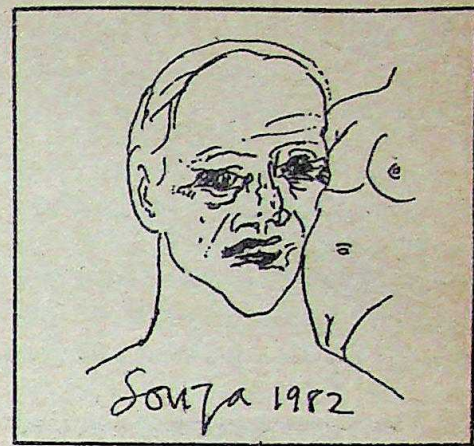
सुप्रसिद्ध चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा (दिनमान, 4 अप्रैल) 6 वर्षों बाद भारत आये हैं। फिल्म, कला समीक्षक जगमोहन ने इस ओर ठीक ही संकेत किया कि भले ही अब सूजा के पास विदेशी पासपोर्ट हो, और वह विदेश (न्यूयार्क) में रहते हों, वह भारतीय कला आंदोलन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े रहे हैं। सूजा, कला और अपनी कला पर बोलने की जगह 'झवेत पत्ताका क्रांति' (देखें पृष्ठ 11) पर ही अधिक बोले। इन दिनों वह इसी से आकांत लगते हैं। सूजा इस बार अपने साथ बहुत सा काम भी लाये हैं: छात्र जीवन से लेकर '70 तक का। अधिकतर काम वैसे छात्र जीवन और चालीस पचास के दशकों के ही हैं। इनकी पारदर्शियाँ दिखायीं। रेखा-गुण सूजा के काम में शुरू से रहे हैं और काली कलम और पेंसिल से किये हुए उनके कुछ पुराने रेखांकनों को देखना एक अच्छा अनुभव था। निर्वसनाओं और आकृतियों को लेकर किये गये उन के

पहले इस मूर्ति को अष्टधातु की सिद्ध किया जा रहा था, परंतु वास्तव में यह अष्टधातु की न होकर पाषाण की है। अष्टधातु की मूर्ति मान ली जाने के कारण ही संभवतः इसका मूल्य 30 लाख रुपये तक कूता जा रहा था।

पाषाण निर्मित होने के बावजूद निर्माण काल के आधार पर इसकी कीमत इस से भी कहीं अधिक लग सकती थी। उत्तराखण्ड की मूर्ति-कला में यह मूर्ति साधारण ही ठहरती है, भले ही तस्कर इसकी मनमानी कीमत वसूलते की स्थिति में होते। मूर्ति का वास्तविक भार 79.8 किलो ग्राम है व इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 91 व 45 सें. मी. है।

आदित्य की यह मूर्ति गुणादित्य नामक जिस ग्राम से चुरायी गयी है वह अल्मोड़ा से लगभग 40 (चालीस) किलो मीटर दूर है, जो पट्टी रंगोड़, धौलादेवी विकास खण्ड तथा तहसील अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा तहसील के इस ग्राम की राजस्व-ग्राम संख्या 1803 है, जिसे चंद राजाओं ने गूँठ पर दिया था।

कुमाऊँ में प्राचीन मूर्तियों तथा मंदिरों में जड़े सोने-चांदी अथवा कीमती पत्थरों की



सूजा : आत्मचित्र '82

रेखांकनों की रेखाएँ इकहरी हैं लेकिन पुष्ट और मांसलता को एक पैंनेपन के साथ बांधती हैं। उनके रेखांकनों का यह प्रमुख गुण है कि किन्हीं विदुओं या स्थलों में रेखा-खिचाव कुल रेखांकन को जैसे ऊपर उठा देता है—और उसमें मूर्ति-शिल्प के सदृश आयतन प्रकट होने लगते हैं। पचास के दशक में कैनवास पर किये हुए गोआनी सैरे और आकृतिमूलक चित्र सूजा की रंग-रेखा समझ का एक शक्तिशाली मिश्रण लगते हैं। तप्त और ऐंद्रिक रंग इन चित्रों को हमारे भीतर कई स्तरों पर बिछाते हैं।

सूजा के इन चित्रों-रेखांकनों की प्रदर्शनी धर्मोमल गैलरी (नयी दिल्ली) में सितंबर में आयोजित होने की संभावना है जो निश्चय ही कलाजगत की एक घटना होगी। —प्र.शु.

चोरियाँ पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ती जा रही हैं। कुछ वर्ष पूर्व जागेश्वर मंदिर से मूर्तियों का गायब होना आरंभ हुआ और पौन राजा की मूर्ति भी चोरी चली गयी। कटारमल सूर्य मंदिर की प्रसिद्ध सूर्य प्रतिमा की चोरी की घटना अभी ताजा है। गंगोलीहाट के महाकाली मंदिर की शक्ति में मढ़ा गया चांदी तथा छत्र भी चोरी कर लिये गये। छठी कुमाऊँ रेजीमेंट द्वारा भेंट की गयी चांदी-सोने से निर्मित मूर्ति भी चोरों के हाथ लगी।

बागेश्वर के बेड़चुला जंगल में पिताक मंदिर से राधाकृष्ण एवं दत्तात्रेय की मूर्तियों की चोरी और अभी हाल गुणादित्य मंदिर से सूर्य प्रतिमा की भी चोरी उसी दुस्साहस के तमूने हैं, जिसे आज पुरातात्विक महत्त्व की प्रतिमाओं व अन्य निधियों की उचित सुरक्षा व संरक्षण के अभाव में चोरों, तस्करों या उनके दलालों ने अपना लिया है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अकेले सरकार अथवा स्वयं अज्ञान में भटकता पुरातत्त्व विभाग ही पर्याप्त नहीं, स्थानीय लोगों का सक्रिय योगदान भी बहुत जरूरी है—उनके अपने सांस्कृतिक परिवेश को बचाने के लिए। □



## अब साठे करें तो क्या करें !

जिन दिनों लंदन में बीबीसी अपने देश की प्रधानमंत्री की टिप्पणी के जवाब में प्रसारण की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसका महानिदेशक स्पष्ट शब्दों में कह रहा था : 'हमें देशभक्ति का सबक ब्रिटिश सरकार से नहीं लेना. हमें मालूम है कि देशभक्ति क्या होती है।'—और यह भी कि 'आहुतीना और ब्रिटेन की विधवा की वेदना अलग अलग नहीं होती. हमें मानवीय वेदना की सच्चाई सामने लाने का हक है.' उन्हीं दिनों दिल्ली दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में किसी दर्शक के प्रश्न के जवाब में उत्तरदाता महोदय अकारण देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री वसंत साठे की प्रशंसा में प्रसारण का समय नष्ट कर रहे थे. सूचना प्रसारण मंत्री जी यह चिल्लाते थके जा रहे हैं कि 'हम चाहते हैं कि दूरदर्शन स्वायत्तशासी कार्यान्वयन का उदाहरण बने. रोजमर्रा के कामों में उन्हें पूरी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं.' लेकिन मंत्री क्या करें, अगर उनके दूरदर्शन अधिकारी उनकी प्रशंसा के पुल बांधना शुरू करते हैं. यहाँ तक कि किसी दर्शक ने पूछा कि वह अपने यहाँ के क्लब का क्या नाम रखें तो उत्तरदाता महोदय नाम सुझाते हैं : 'सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे क्लब.' अपनी ऐसी घिनौनी चाटुकारिता दूरदर्शन पर देखकर श्री साठे का सिर भी शर्म से झुक जाता है : 'इन कंबख्तों को कौन बताये कि मैं अपनी चापलूसी सुनकर खुश होने की बजाय शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ.'

शर्म से पानी पानी हो जाने वाले कार्यक्रम दूरदर्शन से रोज देखने को मिलते हैं. बी. बी. सी. पर 'देशद्रोह' का आरोप लगा कर सर विस्टन चर्चिल के नाती संसद सदस्य मिस्टर चर्चिल इंग्लैंड में कहते हैं 'इन सारे के सारे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए.' फिर भी बी. बी. सी. में किसी की निर्भीकता में कहीं कोई फर्क नहीं आता. यहाँ मंत्री कहता है कि 'बाबा, सरकार की चापलूसी बंद करो' तो भी उनका अधिकारी, कर्मचारी बाज नहीं आता. इतना ही नहीं, दूरदर्शन के 'आप और हम' कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुष और नारी स्वर जो अभी कुछ सप्ताह पहले कमलेश्वर के नाम से थिरक कर चहचहाने लगते थे, अब उनका जिक्र तक करते घबराते हैं. यहाँ तक कि दर्शकों के अनेक पत्रों में कमलेश्वर के कार्यक्रमों के प्रति उत्सुकता व्यक्त की हुई होती है तो उन पत्रों से वे इस प्रकार आतंकित हो जाते हैं, मानो

विनमन

वह पत्र न होकर ऐसे अंगारे हों, जिन्हें छूते हुए जल जाने की संभावना है.

यह मानसिकता रेडियो, टेलीविजन के अधिकारियों, कर्मचारियों की पर्याय बन गयी है. इस प्रक्रिया में इन महत्वपूर्ण माध्यमों की विश्वसनीयता की जो क्षति हो रही है उसका सही मूल्यांकन तो इतिहास ही करेगा. 'आप और हम' में पत्रोत्तर देने वालों के अपरिपक्व दर्शन में गहरी आस्था रखने वालों की बात छोड़ भी दें तो समाचार विभाग के सूत्रधारों को क्या कहें, जिन्होंने चुनाव परिणाम घोषित करने में इसी मानसिकता का परिचय दिया.

21 मई को समाचार पढ़ने वालों में वह महिला भी थीं जो पत्रोत्तर कार्यक्रम में सामने रखे पत्रों का मजमून बताने के सिलसिले में सही शब्दों के लिए मटकती फिरती हैं. समाचार-वाचन के क्रम में उन्हें सामने लिखे शब्दों को टटोलना पड़ता है. पी एल ओ के अध्यक्ष यासेर अराफ़ात को जब उन्होंने 'अराफ़त' पढ़ा तो इस दर्शक को लगा जैसे 'आफ़त' आ पड़ी. क्या दूरदर्शन वाले अपने समाचार वाचकों को यह नहीं बता सकते कि उन्हें समाचार पढ़ना नहीं, बोलना चाहिए जिसमें प्रवाह और संप्रेषण की हत्या न हो, साथ ही कम से कम शब्दों और नामों के सही उच्चारण में अटकना और हकलाना न पड़े.

समाचार लिखने वाले भी इंदिरा गांधी की सरकार की खिचाई कराने से बाज नहीं आते. जब सारे राष्ट्र को बहुगुणा की हार-जीत के चुनाव परिणाम जानने की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुँच रही थी दूरदर्शन के हिंदी समाचारों की हेड लाइन में उसे चौथे नंबर पर रखा गया था. पहला समाचार था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस (आई) की स्थिति सुधरने का. इस दल के उम्मीदवार कहाँ कितने वोट से आगे हैं, यह तो रेडियो और दूरदर्शन समाचारों में बड़े उत्साह से बताया जाता है, किंतु बहुगुणा जी कितने वोटों से आगे हैं यह बताना दूरदर्शन हिंदी समाचार बुलेटिन को मंजूर न था. रेडियो और टेलीविजन को ऐसा करने का आदेश क्या इंदिरा जी ने दिया अथवा साठे जी ने ? यदि नहीं तो ऐसा कर के सरकारी नियंत्रण वाले ये माध्यम किस की मलाई कर रहे हैं ? और यह किस मानसिकता का परिचय देते हैं ?

चुनाव परिणामों की सूचना के साथ उनकी समीक्षा के बारे में भी. और यहाँ आकर हिंदी की दयनीयता मुखर होकर सामने आयी. श्री अक्षय कुमार जैन की जानकारीयों और बोलने की शैली के आकर्षण ने हिंदी चुनाव समीक्षा की डूबती हुई नाव को ठेल कर जरूर किनारे लगा दिया, लेकिन हिंदी के दैनिक पत्रों के संपादकों का पत्रकारी दिवालि-

यापन ढका न रह सका. दिल्ली दूरदर्शन के निदेशक की पता नहीं कौन सी मजबूरी कि उन्हें हिंदी में अच्छे राजनीतिक समझ वाले लोग ढूँढ़े नहीं मिलते. इसी की तुलना में उन दिन अंग्रेजी समीक्षाकारों में इंदर मलहोत्रा के संयोजन का पहला समीक्षा कार्यक्रम अंग्रेजी पत्रकारिता की जागरूकता की मोख बन कर उभरा. अंग्रेजी की तारीफ न सुन सकने के आदी पाठकों को यह तथ्य बुरा लग सकता लेकिन सत्य को ढक कर रखने से भी तो को लाभ नहीं हो सकता.

दूरदर्शन के 'अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम' के कलाकार के चुनाव और उस प्रस्तुतिकरण दोनों में ही अभी संजीदगी नहीं आ पायी. जरूरी यह है कि ऐसे कार्यक्रम यदि कलाकार रिकार्डिंग के वक्त 'मूड' में न हो या दूरदर्शन के व्यवहार-दर्शन उसका अच्छा मला मूड खराब कर दिया हो तो उसे मना कर उसे दुबारा तकलीफ न जाये. यदि ऐसा किया गया होता तो पंडित भीमसेन जोशी का दूरदर्शन पर प्रसारित संगीत कार्यक्रम उनके स्तर के अनुरूप पता. शुरू के दस मिनट तक उनकी आवाज ही ठीक प्रकार से नहीं लग पायी. इस दिग्गज कलाकार को दुबारा गाने के लिए मनाया जा सकता था. दूसरी ओर ए. कानन को 'अखिल भारतीय कार्यक्रम' में लाना उन और इस कार्यक्रम दोनों की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है. एक समय था जब कानन साहिब प्रथम श्रेणी के गायक थे, अब उनकी आवाज उम्र की चपेट में आ चुकी है. उनसे अब उसी बुलंदी की उम्मीद करना उनके और संगीत

[ शेष पृष्ठ 28 पर देखें ]



सिंह बंधु सुरिंदर एवं तेजपाल : सुडौल और बलशाली आवाजें



## अमिताभ बच्चन 'एंग्री यंगमैन' नहीं है

अमेरिका की प्रख्यात फिल्म समीक्षक पॉलिन केल की व्यावसायिक सिनेमा पर नयी पुस्तक आयी है, जिसमें उन्होंने फिल्म माध्यम पर—विशेषकर व्यावसायिक फिल्म पर कई चुस्त टिप्पणियाँ की हैं। जहाँ एक ओर वह फिल्म माध्यम को सबसे 'ऊर्जावान कला' मानती है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसे 'दूसरे दर्जे की कला' भी कहा है। व्यावसायिक को उन्होंने 'मड़काऊ और भ्रष्ट दुनिया के लिए मड़काऊ और भ्रष्टकला' कहा है। व्यावसायिक सिनेमा में किसी कलाकार को किसी खास विशेषण से विभूषित करके प्रस्तुत करने की बाजारू मनोवृत्ति की ओर भी उन्होंने इशारा किया है कि किस तरह कुछ 'खास' शब्दों का फिल्म वाले 'उपयोग' करते हैं। 'पॉलिन केल' का पश्चिम के व्यावसायिक सिनेमा का अध्ययन भारत के व्यावसायिक सिनेमा पर भी उतना ही सटीक और सही बैठता है।

भारतीय सिनेमा उद्योग में भी कलाकारों को 'विशेषणों' से विभूषित करने की अपनी एक परंपरा रही है। दिलीपकुमार 'ट्रेजेडी किंग' हो गये, हेमामालिनी 'स्वप्न सुंदरी' के नाम से विख्यात हो गयीं। राजेन्द्रकुमार 'जुबलीकुमार' कहलाये तो राजकुमार को अंग्रेजी फिल्म समीक्षक 'प्रब्लम स्टार' कहने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा 'शॉटगन' कहे गये और अमी-अमी गयी एक नयी लड़की पद्मिनी कोल्हापुरे 'किस गल' हो गयी। धमेंद्र की 'ही मैन' छवि के बाद भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय विशेषण अमिताभ बच्चन का रहा जिसे लोगों ने 'एंग्री यंगमैन' की संज्ञा दी।

पैसे की तड़क मड़क और रंगीनी के आवरण में लपेटकर पैदा किये गये ये कथित विशेषण जनमानस पर किस कदर छा जाते हैं इसका अमिताभ एक ज्वलंत उदाहरण है। आज 'एंग्री यंगमैन' के जिन्ने होते ही लोगों के सामने अमिताभ बच्चन की गुस्सैल मुद्रा आ जाती है। क्या वाकई अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में जिस तरह की भूमिकाएँ निभायीं हैं वे 'एंग्री यंगमैन' की छवि से मेल खाती हैं? 'जंजीर', 'दीवार', 'अमर अकबर एंथोनी', 'त्रिशूल', 'नसीब', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'लावारिस' आदि फिल्मों का गरीब और बेसहारा नायक, जो फुटपाथ से महल तक की यात्रा करता है, क्या वाकई 'एंग्री यंगमैन' है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें 'एंग्री यंगमैन' शब्द को समझना होगा।

सबसे पहले 'एंग्री यंगमैन' विशेषण का विनयान



अमिताभ बच्चन : विद्रोही की मुद्रा

प्रयोग 1950 में इंग्लैंड के साहित्यिक क्षेत्र में एक पीढ़ी के लिए किया गया। इंग्लैंड के ये 'नाराज युवक' मुख्यतः निम्न मध्य वर्ग और श्रमजीवी वर्ग की संतानें थीं। जॉन आस्वान के नाटक 'लुक बैक इन एंगर' का नायक इस पीढ़ी का एक प्रतीक था। तथाकथित भद्रता, खोखले लेकिन सभ्य कहे जाने वाले आचरण और यथास्थितिवाद से बिस्वुध यह नायक ऊपर से अमानवीय लगते हुए गहरे में मानवीय था।

1950 की पीढ़ी के ये 'नाराज लेखक' अगर किसी बात पर एकमत थे तो वह था किसी भी 'उद्देश्य' का एक स्वर में अस्वीकार।

अपनी फिल्मी दुनिया का यह कथित 'एंग्री यंगमैन' सब कुछ अस्वीकार नहीं करता है। वह तो पैसा कमाना चाहता है। फुटपाथ से महल में जाना चाहता है; जिसने उसे ठोकर मारी है, उसे उसी 'स्टाइल' में ठोकर मारना चाहता है। यानी कि जैसे भी हैं, लेकिन उसके पास अपने कुछ उद्देश्य हैं, जिन तक वह फिल्म के अंत तक पहुँचना चाहता है और पहुँचता है।

'एंग्री यंगमैन' को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए समीक्षक वाल्टर एलन लिखते हैं—'एक' नये नायक का उदय हो रहा है। एक ऐसा शुष्क और बौद्धिक नायक जो तत्कालीन समाज द्वारा स्वीकृत सारी मान्यताओं, सभी मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। अपने हाथी दाँत के केबिन में बैठा शुद्ध अभिव्यंजना को ही सब कुछ समझने वाला सौंदर्यवादी वह नहीं, न ही वह मार्क्सवादी किस्म का बौद्धिक योद्धा है। वह तो बीसवीं सदी की परिस्थितियों द्वारा पैदा हुआ ऐसा मनुष्य है, जो व्यक्ति और हर वस्तु को संदेह की नजर से देखता है।'

'दीवार' और 'जंजीर' और 'नसीब' का नायक सब कुछ पर संदेह नहीं करता। वह अपने कुछ साथियों पर विश्वास करता है, जो दुश्मन

के अड़डों का सफाया करने में उसका साथ देंगे। इन फिल्मों का नायक प्यार भी करता है, गाने भी गाता है, नाचता भी है, यानी कि वह सब कुछ करता है, जो साधारण आदमी करना चाहता है।

'एंग्री यंगमैन' अस्वीकार के साथ-साथ 'स्क्वायर' (वह व्यक्ति जो जीवन को सुरक्षा के साथ जीना चाहता है) से घृणा भी करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए जिस तरह के अमिनय की जरूरत पड़ती है, उससे सख्त नफरत करता है। 'एंग्री यंगमैन' हर तरह से अपने को सुताकर, विभिन्न प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करके, नरक में अपने को फेंककर आत्मन्येवण करता है। उसका प्रमुख लक्ष्य यह पता लगाना है कि तत्काल अनुभूति के साथ उसका स्वयं का क्या संबंध है। 'एंग्री यंगमैन' अपना केवल एक ही दायित्व मानता है—अपनी इंद्रियों को अधिकाधिक संवेदनशील और तेज बनाना, ताकि वह जीवन को 'दिखाऊ' बनाने से बचा सके और तीव्रता से अनुभव कर सके। यह सब विवेचन 'एंग्री यंगमैन' की प्रमुख सामूहिक पुस्तक 'प्रोटेस्ट' की भूमिका से है।

इस विवेचन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन अर्थों में कभी 'एंग्री यंगमैन' मुहावरे का प्रयोग शुरू हुआ था वह अमिताभ बच्चन द्वारा अमिनीत नायक की भूमिकाओं से बिल्कुल उलट है। अमिताभ बच्चन की जबड़ा मिचाऊ, मुक्का तान और लातमारा मुद्रा से असली 'एंग्री यंगमैन' का कोई ताल्लुक नहीं है।

'दीवार' के इस कथित 'एंग्री यंगमैन' का संघर्ष जब खत्म हो जाता है तो वह अपने भाई शशिकपूर से कहता है—'मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बेलेंस है... क्या है तुम्हारे पास?' वह पैसे से प्यार करता है। वह अपनी माँ को वही बिल्डिंग खरीदकर देता है, जिसमें उसकी माँ मजदूरी किया करती थी। उसकी पंग-पग पर पैसे में 'आस्था' दिखायी देती है, जबकि 'एंग्री यंगमैन' निषेध करता है, इन सबका अमिताभ बच्चन का नायकत्व एक अंश भी 'एंग्री यंगमैन' से नहीं जुड़ा हुआ है।

भारत जैसे गरीब देश में पैसे, विज्ञापन और सेल्युलाइड का ऐसा जादू चल पड़ा है कि कब किस कलाकार को भगतसिंह का 'विशेषण' दे दिया जायेगा, नहीं मालूम? अगर ऐसा हुआ तो हम असली भगतसिंह को भूल जायेंगे और सेल्युलाइड के भगतसिंह को ही असली मानने लग जायेंगे? उसी तरह, जैसे आयर की चोरी करने वाले मनोजकुमार को 'भारत कुमार' कहा जाता है।

—कृष्ण कल्पित



## साहित्य और समाजशास्त्र

हैदराबाद में दक्षिण भारत हिंदी समा की हिंदी के उच्चस्तरीय अध्ययन की एक शाखा उच्चशिक्षा और शोध संस्थान के तत्वावधान में पिछले दिनों साहित्य का समाज-शास्त्रीय पक्ष पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उद्घाटन माननीय राज्य शिक्षा मंत्री के. केशवराव ने किया। संस्थान के अध्यक्ष डा. इन्द्रनाथ चौधरी ने विषय का उपस्थापन करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारतीय आलोचना में समाजशास्त्रीय पक्ष की चर्चा तो मिल जाती है पर स्वतंत्र अध्ययन के लिए उसका विकास ह्रस्व में ह्रस्वी क्रांति के बाद हुआ और भारत में आज भी शोध और आलोचना के क्षेत्र में इस पक्ष का विकास कम ही हो सका है। पाश्चात्य एवं बंगला साहित्य के विचारकों के उदाहरणों द्वारा उन्होंने विषय की पूर्व पीठिका प्रस्तुत की। दो प्रपत्रों में पहला प्रपत्र डा. आलम खंडेली (उस्मानिया विश्वविद्यालय) ने सैद्धांतिक पक्ष पर प्रस्तुत किया तथा लोक साहित्य और 'नरेशन' स्टोरी के संदर्भ में 'इपाक' की चर्चा की तथा समाजशास्त्र से इस विषय को जोड़ते हुए साहित्य अध्ययन में इस पक्ष की दिशाओं की ओर संकेत किया। दूसरा प्रपत्र डा. विजेंद्र नारायण सिंह, (हैदराबाद विश्वविद्यालय) का काव्य के समाज-शास्त्रीय पक्ष से संबद्ध था। डा. सिंह ने मध्य-कालीन तथा आधुनिक काव्य में इस पक्ष को रेखांकित करते हुए यह बताया कि लुकाच और गोलडमैन जैसे विद्वानों ने इस दृष्टि से साहित्य आलोचना को एक नयी दृष्टि दी है।

दूसरे सत्र के दो प्रपत्र डा. रामकुमार खंडेलवाल, (उस्मानिया विश्वविद्यालय) तथा डा. चंद्रभानु रावत (हैदराबाद विश्वविद्यालय) ने प्रस्तुत किये। डा. खंडेलवाल ने समाजशास्त्रीय पक्ष को समकालीन कहानियों के माध्यम से उजागर किया। नगरीय तथा ग्रामीण कहानी की चेतना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने भारती की 'गुलकी वनो' तथा कई अन्य कहानियों को कस्बाई मनःस्थिति से जोड़ा। डा. रावत ने शैली के समाजशास्त्रीय पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया। शैली और भाषा के संबंधों की सामाजिकता की चर्चा उन्होंने कई उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की। काव्य में कैटेसी, उपन्यास में शैली-वैविध्य तथा महाकाव्यों की गहनतर होती स्तरीकृत शैली के सामाजिक पक्षों को उन्होंने साहित्य के उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया तथा रूपगत और वस्तुगत शैलीय अध्ययन की चर्चा भी की।

—आंजनेय शर्मा

दिनमान

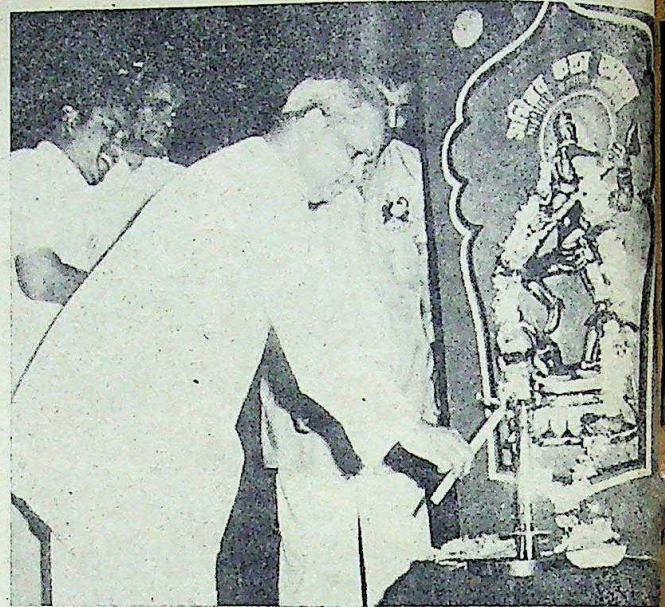
## इंदौर रंगकर्मी संघ

इंदौर में शीकिया रंगकर्मीयों की हिंदी मराठी दोनों की नयी पुरानी तमाम सक्रिय रंग संस्थाओं ने इंदौर रंगकर्मी संघ की स्थापना की है। तेरह संस्थाओं के सत्रह से लेकर सत्तर वर्ष की उम्र के कोई 250 कलाकार इस के सदस्य हैं। उद्देश्य रंगकर्म को गति देना और उसे नियमित बनाना तथा नयी प्रतिमाओं को प्रोत्साहन देना और निखारना है। नव स्थापित इस संस्था ने रवींद्र नाट्य गृह के किराये के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन किया और सफलता प्राप्त की तथा विश्व रंगमंच विवस के अवसर पर इंदौर रंगमंच समस्या और समाधान विषय पर रामविलास शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एक गोष्ठी की। साथ ही लिटिल थियेटर नाम से एक दर्शकों के समूह की स्थापना की जो कम खर्चीला हो और नियमित रूप से कार्य कर सके। इसमें प्रतिबद्ध समर्पित कलाकारों द्वारा हर माह एक नाटक खेले जाने का विधान है। प्रेक्षकों के लिए सदस्यता शुल्क कम है। लिटिल थियेटर का उद्घाटन 23 मई को रवींद्रनाट्य गृह में कुमार गंधर्व ने किया। इस अवसर पर नाट्य भारती ने बाबा डिके के शेक्सपीयर के नाटक 'ट्वेलथ-नाइट' का हिंदी रूपांतर खिलौने प्रस्तुत किया।

—अनिल कुमार घड़वईवाले

## कथक के युवा कलाकार

ऐसा बहुत कम होता है कि दक्षिण के लोग उत्तर भारत के नृत्यरूपों विशेषकर कथक को अपनाते हों जबकि उत्तर भारत के लोग दक्षिण के भरतनाट्यम जैसे नृत्यरूप को प्रचुरता से अपनाये हुए हैं। इस लिए पिछले दिनों महाराष्ट्र के नंद किशोर कपोत के नृत्य कार्यक्रम के प्रति इसलिए उत्सुकता थी। नंद किशोर ने रागरंग के तत्वा-धन में त्रिवेणी समागार में सुंदर कथक नृत्य प्रस्तुत किया। वह कथक केंद्र, दिल्ली के स्नातक हैं और बिरजू महाराज के शिष्य रह चुके हैं। उन का नृत्य अच्छी तैयारी की वानगी है और वह पूरे जोश से नाचते हैं—अच्छी



कुमार गंधर्व लिटिल थियेटर का उद्घाटन करते हुए

मेहनत और अच्छे रियाज का परिचय देते। उन के साथ उस शाम एकल मी और युगल रूप में भी कुमारी निरूपमा मिश्र कथक प्रस्तुत किया। निरूपमा का नृत्य बहुत जानदार था। वह बाज की तरह मंच पर झंकार आयीं और अपनी इस ओजस्विता को अतक निमाने में सफल रहीं। मंच पर बड़े आत्म विश्वास के साथ उन्होंने नृत्य पेश किया। सुदर्शना प्रतिभाशाली नृत्यांगना से जो उ शर्मा की शिष्या हैं, आगे पर्याप्त आशा की सकती है। अपनी हम उम्र युवा नृत्यांगनाओं में वह बहुत अच्छा नाचती है। दिल्ली में उन्हें और सार्वजनिक प्रदर्शन के मौके मिल चाहिए।



नंदकिशोर कपोते : शुभारंभ





## महाराजकृष्ण रसगोत्रा

महाराजकृष्ण रसगोत्रा ने, राम-चंद्र दत्तात्रेय साठे के बाद,

1 मई 1982 से भारत सरकार के विदेशमंत्रालय में विदेशसचिव का महत्वपूर्ण पद संभाल लिया है। 1949 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने जाने के बाद से श्री रसगोत्रा ऐसे देशों में, विभिन्न पदों पर रहे, जो भारत के लिए विशेष अहमियत रखते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में काम करने के बाद वह 1958 में चार वर्ष के लिए संयुक्तराष्ट्र में भारतीय मिशन के सदस्य नियुक्त हुए। उस समय उपनिवेशों की परंपरा को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे थे, जिस की गुंज संयुक्तराष्ट्र में भी सुनाई दे रही थी। उस समय श्री रसगोत्रा द्वारा औपनिवेशिकता से प्रभावित देशों, विशेष कर अफ्रीकी उपनिवेशों की स्वाधीनता की मांग को समर्थन दिया जाना आज भी उन नवस्वाधीन देशों में आदर के साथ याद किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से श्री रसगोत्रा फिर राष्ट्रीय क्षेत्र में लौटे और अगले पाँच वर्ष तक पाकिस्तान जैसे मुश्किल पैदा करने वाले पड़ोसी से जूझने का दायित्व उन्हें दिया गया। उस के बाद उनके जीवन में राजदूत की हैसियत से देश का प्रतिनिधित्व करने का दौर शुरू हुआ। 1967 से मोराको, तुनीसिया, लंदन, नेपाल, नोदर-लैंड और फ्रांस में रहने के बाद अब वह स्वदेश लौटे हैं। भारतीय विनयान

विदेश सेवा में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के रहते श्री रसगोत्रा का इस पद पर नियुक्त किया जाना इस बात का द्योतक है कि देश के नीति निर्धारकों को उन पर पूरा भरोसा है।

महाराजकृष्ण रसगोत्रा तरह तरह के शौक रखते हैं—मीलों पैदल चलना, योगाभ्यास करना, ध्यान लगाना, पढ़ना, लिखना—ये सभी कुछ वह करना चाहते हैं। कवि और आलोचक की हैसियत से वह कुछ आगे पहुँचे भी हैं—उनका एक कविता संग्रह 'दो परतें' 1958 में छपा था। लेकिन फिर यहाँ वहाँ छपे फुटकर लेखों को संकलित करने का उन्हें समय नहीं मिला।

—शु. र.



## डॉ. खुशू

अपने पूर्ववर्ती डा. कासिम की तरह ही लंबे, छरहरे, गोरे सुदर्शन व्यक्तित्व से संपन्न डा. खुशू राजधानी के सबसे सुंदर पर्यावरण—इंडिया गेट के मनोरम बीकानेर भवन में मिले। यहाँ से पहले वह लखनऊ में 'राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान' के निदेशक थे। लखनऊ की खुशबू डॉ. खुशू की हर बात से टपकती है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता पानी की है। पानी, मिट्टी, पेड़, हवा और जीव जंतु, ये सब एक अविच्छिन्न सूत्र में जुड़े हैं प्रकृति में। जब कुदरत के इस ताने बाने पर विकास की धुन में आदमी ने अंधाधुंध कुठाराघात किया, तभी से प्रकृति ने भी अपना कोप दिखाना शुरू किया। जंगल कटे, रेगिस्तान बने, वर्षा को अपनी बाँहों में भरने वाले लता

गुल्म हट गये तो पहाड़ नंगे हो गये और प्रलयकारी बाढ़ जो भी सामने पड़ा, उसे लीलती चली गयी।

डॉ. खुशू इसीलिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हैं। भारत शायद पहला देश था, जिसने एक वन नीति घोषित की कि 33 प्रतिशत भूमि में जंगल रहना चाहिए। पेड़ हमारे 'हरे फेफड़े' हैं। वे हमारी साँस के साथ बाहर फेंके गये जहर कार्बन डाइ आक्साइड को पी कर हमें अमृत वायु आक्सीजन देते हैं। डॉ. खुशू ने शोध के बाद पाया कि वटवृक्ष और पीपल तो भयानक प्रदूषण में भी हरे भरे बने रहते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि हमें बड़ी संख्या में इस देश की हवा, मिट्टी, पानी के अनुकूल और सदियों से आजमाये भारतीय वृक्षों के वन रोपने पर विशेष बल देना है। 33 प्रतिशत की बजाय अब भारत में वन क्षेत्र कुल 12 प्रतिशत ही रह गया है। इसके लिए पहले वह उस 70 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन पर ध्यान देंगे, जिस पर जल्दी उगने वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगाने के प्रयोग वह पहले ही कर चुके हैं।

—र. द. श.

## रमता जी

समस्त प्रगतिशील, जनवादी और देशभक्त संघर्षशील शक्तियों का व्यापक मोर्चा ही आज राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। 34 वर्षों के अनुभवों ने साबित कर दिया है कि सभी संसदीय दल और उनके नेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए समय की माँग है कि जुझारू शक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर एकताबद्ध किया जाये और नये जनवादी भारत के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी से कदम आगे बढ़ाया जाये—उपरोक्त कथन पिछले दिनों नयी दिल्ली में आयोजित 'निरंकुशता विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन' में गठित 'इंडियन पीपुल्स फ्रंट' के प्रथम अध्यक्ष रमता जी का है। जिन्होंने 'फ्रंट' की ओर से आयोजित फिरोजशाह कोटला मैदान में एक विशाल आमसभा को



संबोधित किया और एकताबद्ध संघर्ष का आह्वान किया।

'इंडियन पीपुल्स फ्रंट' देश के लगभग 220 संघर्षशील गैर-संसदवादी जन संगठनों का व्यापक मोर्चा है, जिसके सभी संगठनों की संपूर्ण सदस्य संख्या और आधार लाखों में है। रमता जी का पूरा नाम रमाकांत द्विवेदी 'रमता' है। बिहार के भोजपुर जिले के निवासी रमता जी एक किसान कार्यकर्ता और कवि के रूप में विख्यात हैं। वह बिहार प्रदेश किसान समा की भोजपुर जिला इकाई के अध्यक्ष और बिहार राज्य जनवादी देशभक्ति मोर्चे के अध्यक्ष हैं। रमता जी 11 वर्ष की अल्पायु में ही स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय सिपाही बन गये। ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत की जेलों में कई वर्ष गुजारने वाले रमता जी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और जगदीश महतो की परंपरा में आज बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय किसान नेता हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किसान आंदोलनों को मूमिहीन किसानों के नेतृत्व के तहत विकसित करने के पक्षधर हैं, जिसके लिए उनका संगठन बिहार प्रदेश किसान समा राज्य स्तर पर सक्रिय है। 'इंडियन पीपुल्स फ्रंट' के अध्यक्ष के नाते वह राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलनों को मजदूरों और अन्य शोषित तबकों के संघर्ष से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनके अनुसार 'इंडियन पीपुल्स फ्रंट' इसे अपना प्राथमिक कार्य मानता है।

—सि. चौ.



## मिस्टर फॉकलैंड की तलाश

प्रिय नंदन,

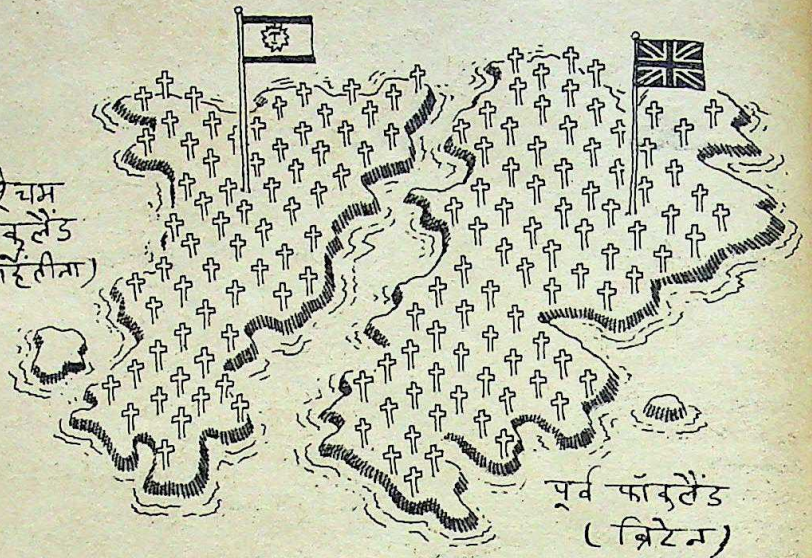
जब से तुम 'दिनमान' के 'संपादक' बने हो रह कर एक ही बात मन में उठती है कि अब इस देश का क्या होगा? फिर यह सोच मन को मना लेता हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने पर इस देश का कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे संपादक हो जाने से ही क्या हो जाएगा. 'पतनोन्मुखता' के इस प्रहर में तुम्हें यह पद मिल जाना मन में निराशा की नयी वैराइटी जगाता है. यों ही कन्फ्यूज़न काफी है तिस पर तुम्हारा मार्गदर्शक हो जाना हमें कहाँ ले जाएगा, किस गढ़ में उतारेगा, समझ नहीं पा रहा हूँ. इस निराशा के साथ एक किसम का कर्तव्यबोध भी जागता है कि तुम्हारा और तुम्हारे साप्ताहिक का जीवन सुधारने के लिए मैं तुम्हें नियमित पत्र लिख कर पथप्रदर्शन किया करूँ. भावना जागी है और मैं मजबूर हूँ. आदतवश कहीं इसे रद्दी की टोकरी में मत डाल देना नहीं देश रसातल को चला जाएगा. तुम में और मुझ में एक गुण समान रहा है कि ज्ञान की चाह कमी हो, इतमीनान की कमी इस में कमी नहीं रही. 'दिनमान' का मामला है अतः थोड़ा अहं होना लेखन के साथ जरूरी है. बंदे का इतिहास रहा है कि लेखन में बीसियों बार गड़बड़ी हुई हो, अहं बरकरार रहा है. उस में गिरावट कभी नहीं आयी. तुम मेरे पत्र को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें शुरू में यों लगेगा कि तुम बोधिवृक्ष के नीचे बैठे बोर हो रहे हो. बोरियत पर नहीं, वृक्ष पर ध्यान दो. फल मिलेगा. प्रति सप्ताह एक की गति से टपकेगा.

अब फॉकलैंड का ही मामला लो. मुझे खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि तुम पर्याप्त बौद्धिक जिज्ञासा उत्पन्न करने अथवा उत्पन्न हो गयी हो तो शांत करने में असमर्थ रहे हो. पत्रकार के नाते कभी तुमने सोचा कि ये मिस्टर फॉकलैंड कौन हैं जिन के नाम पर आर्हेतीना के पास द्वीप समूह हैं और बंबई में एक सड़क है. वे कौन वीर थे जो उधर द्वीपों पर विजय पा उन का नामकरण अपने नाम पर करते हैं और कूटनीति की उस्तादी का रंग यह कि बरसों से दो देशों को लगातार यह खुशफहमी रही कि जमीन उन की है. इस के बाद मिस्टर फॉकलैंड भारत आते हैं और बंबई में फॉकलैंड रोड बनाते हैं, वहाँ वेश्याओं को बसाते हैं. आज जो रोड बंबई में है वह उन्हीं फॉकलैंड महोदय की स्मृति संजोये है

दिनमान

6/11/11, 11/11/11, 11/11/11  
11/11/11, 11/11/11, 11/11/11  
11/11/11, 11/11/11, 11/11/11

पश्चिम  
फॉकलैंड  
(आर्हेतीना)



'द गार्डियन वीकली' में वाशिंगटन पोस्ट का व्यंग्य चित्र

जिन के लिए इंग्लैंड और आर्हेतीना हाथापाई कर रहे हैं. क्या 'दिनमान' के संपादक के नाते तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम फौरन फॉकलैंड महोदय की जीवनी फोटो सहित प्रकाशित करो और इस संदर्भ में भारत आर्हेतीना के संबंधों पर प्रकाश डालो? 'पड़ताली पत्रकारिता' के इस युग में तुम कितने पिछड़े हुए हो! आज तक हमारा विदेश विभाग फॉकलैंड के मामले में शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण नहीं स्पष्ट कर पाया, उस के मूल में 'दिनमान' की लापरवाही है. कल से इंग्लैंड और आर्हेतीना हमारी फॉकलैंड रोड पर अपने दावे पेश करने लगेंगे तो भारत के पास अपने हित में दलील क्या है? राष्ट्रीयता का तकाजा तो यह है कि हम फटे में टांग फँसाएँ और कहें कि रोड जिस की, द्वीप उस के. मामला गर्म है, दावा पेश करने का यह सही समय है. फॉकलैंड द्वीप न भी हाथ आए, फॉकलैंड रोड तो बचेगी. नहीं दुविधा में दोनों जाएँगे.

मेरा पत्रकार जागा और मैं फौरन घर से निकल फॉकलैंड रोड पहुँचा. संपादक नहीं हूँ तो क्या हुआ सुस्त तो नहीं बैठा रह सकता. मैंने सोचा जिन के नाम पर रोड है उन का घर वहीं कहीं होगा. अगर मिस्टर फॉकलैंड संसार में नहीं हों तो उन की विधवा, कोई बूढ़ी प्रेमिका या वच्चे तो होंगे. उन से बात करूँगा और पता लगाऊँगा कि मरहूम फॉकलैंड अगर आज जिंदा होते तो इस मामले में क्या कहते? वे तब क्या कहा करते थे? चुप्पी मार जाते थे तो किस डर से? मिस्टर फॉकलैंड औलाद किसकी थे? आज क्यों टैचर को लगता है

कि द्वीप समूह हमारा है? चक्कर क्या है अर्थात् 'पड़ताली पत्रकारिता' के तहत माम का पूरा तूल दे ब्योरा पेश करना चाहता है. अरे सब से भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगति. हम ठहरे बुद्धिमान. हमें तो व्यापती सारा दिन फॉकलैंड रोड के चक्कर काटना है जिस प्रकार महात्मा गांधी रोड पर चक्कर काटने से गांधीवाद के बारे में जानकारी न मिलती उसी तरह फॉकलैंड रोड पर चक्कर काटने से मिस्टर फॉकलैंड के विषय में नहीं जानता. जनाब फॉकलैंड जिन्होंने वर्षों पूर्व महानगर की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रख रोड को बसाया और बंबई की वेश्याओं को जगह दी आज पूरी तरह मुला दिये गये हैं. मैंने जिस हसीना, जानकी या बिब्वो से शादी की वही बेशरम सी मुस्कराने लगी. हाँ फॉकलैंड तुम कहाँ खो गये?

अब यह दायित्व तुम्हारा है. पाठक मिस्टर फॉकलैंड के विषय में जानना चाहते हैं. बंबई के मुंसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर भारत सरकार तक फॉकलैंड को ले कर अनेक भ्रम फैले हैं. मैं आशा करता हूँ अगले ही अंक में फॉकलैंड की जीवनी प्रकाशित कर दूँगा तब तक मैं तुम्हारे हित में कुछ और सोचता हूँ

तुम्हारा,

2/3/11

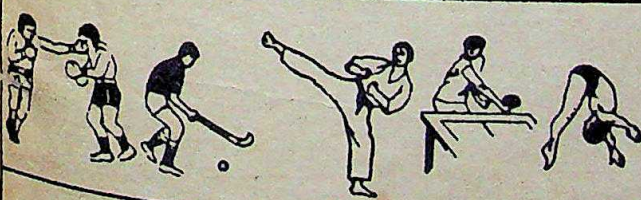


# टाइम्स हाउस द्वारा खेल पत्रकारिता के मैदान में एक बंपर उछाल

हिंदी में सम्पूर्ण खेल पत्रिका

# खेल भारती

जिसका लाखों पाठक न जाने कब से  
इंतजार कर रहे थे. अब हर महीने की  
पहली और १६ वीं तारीख को प्रकाशित



पहले ही अंक में आप इसमें पायेंगे : • भारत के ही नहीं  
विश्व भर के प्रमुख खेल आयोजनों का आंखों देखा हाल.  
• मशहूर खेल सितारों और खिलाड़ियों के जीवंत इंटरव्यू  
• विभिन्न खेलों के नये-से-नये कीर्तिमानों की जानकारी.  
• भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की व्यावहारिक सूचनाएं.  
• खेलों के रोमांचक क्षणों के अनूठे अचूक छायाचित्र.  
इतना ही नहीं, और बहुत-सी ऐसी सामग्री जिसकी  
आपने कल्पना भी न की होगी.

हर खेल प्रेमी के लिए जरूरी है

# खेल भारती

A GREAT NEW AD. MEDIUM.

12 जून '88

कोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचंद्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स. 10 बरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
कार्यालय : डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएँ : 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9;  
7/7 ए.एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700014. कार्यालय : 13/1, गुरुकुल प्रेस ईस्ट, कलकत्ता-700069; 63, मोटियथ रोड, इगमोर, मद्रास-8;  
-1, तीर्थ भवन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन एप्रोच, सडबरी, बंबई, मिडिलसेक्स, लंदन, यू. के., लंदन टेलीफोन : 01-903-9696.



# 100 रु. दीजिए



## केवल 37.20 रु. दीजिए

यदि आप अपनी रकम को  
तिगुना करने का रहस्य जानना  
चाहते हैं तो पी एन बी आइए।  
इसका सबसे आसान तरीका है  
पी एन बी की नकदी प्रमाण पत्र  
योजना। आप हमें सिर्फ  
37.20 रु. दीजिए, हम आपको

100.00 रु. का नकदी प्रमाण  
पत्र देंगे जिसे आप 10 वर्ष बाद  
भुना सकते हैं। 100.00 रु.  
के गुणितों में 3 वर्ष से 10 वर्ष  
की अवधि के लिए ये नकदी  
प्रमाण पत्र पी एन बी की सभी  
शाखाओं में उपलब्ध हैं।

# पंजाब नैशनल बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

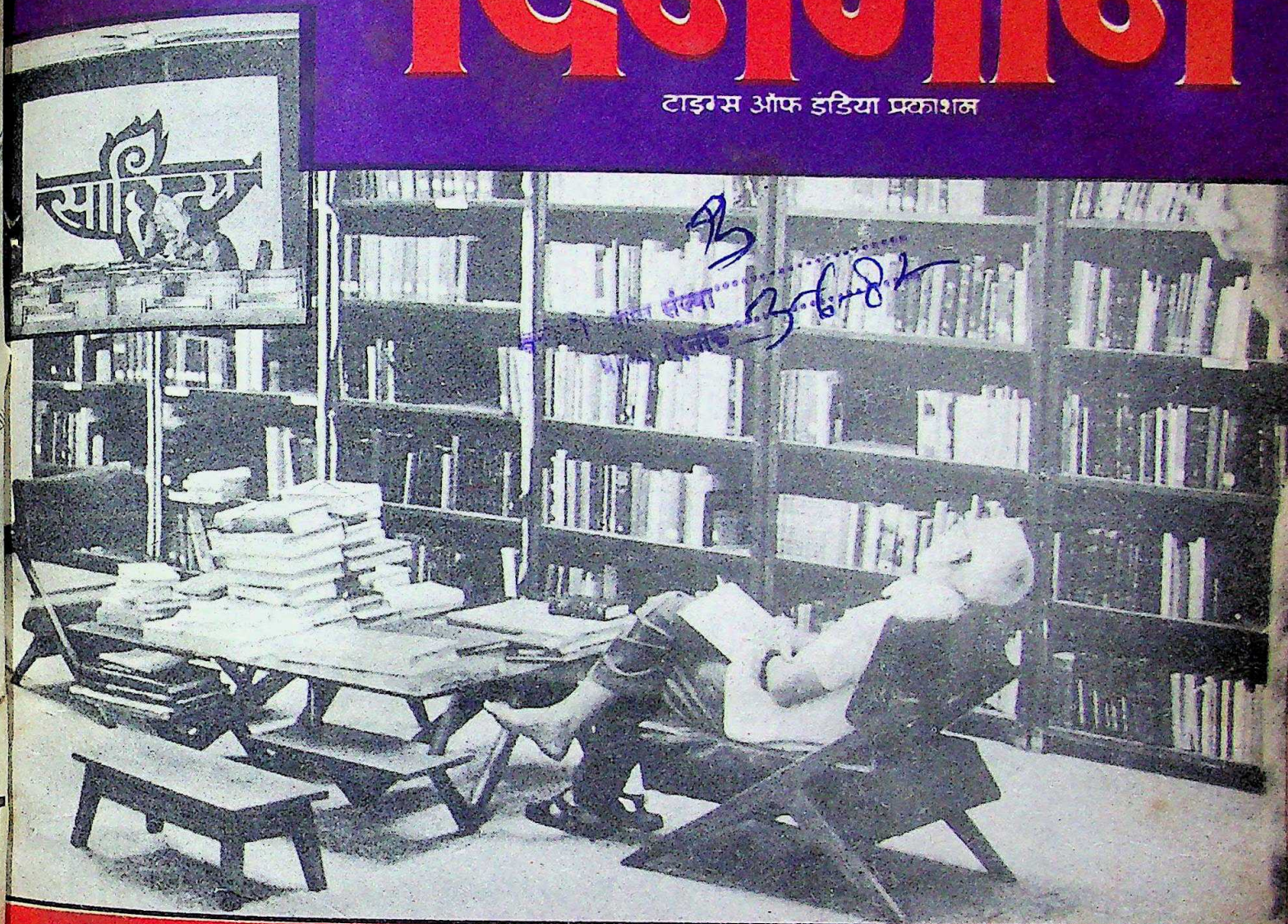
...भरोसे का प्रतीक!

आपके लिए उपयोगी निवेश



# साप्ताहिक दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन



# हृत्य अकादेमी उर्फ साहित्य का कब्रिस्तान

[illegible]

चुनाव के अनोखे  
नतीजों के  
चोखे  
विश्लेषण

के

प

दिल्ली पालिका बाजार में बम  
बिक्री का पुस्तक-युद्ध • हाकी का बुरा हाल

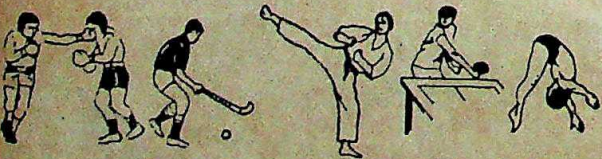
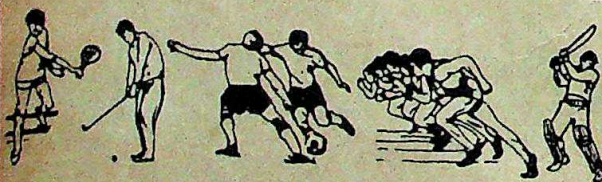


# टाइम्स हाउस द्वारा खेल पत्रकारिता के मैदान में एक बंपर उछाल

हिंदी में सम्पूर्ण खेल पत्रिका

# खेल भारती

जिसका लाखों पाठक न जाने कब से  
इंतजार कर रहे थे. अब हर महीने की  
पहली और १६ वीं तारीख को प्रकाशित



पहले ही अंक में आप इसमें पायेंगे : • भारत के ही नहीं  
विश्व भर के प्रमुख खेल आयोजनों का आखों देखा हाल.  
• मशहूर खेल सितारों और खिलाड़ियों के जीवंत इंटरव्यू  
• विभिन्न खेलों के नये-से-नये कीर्तिमानों की जानकारी.  
• भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की व्यावहारिक सूचनाएं.  
• खेलों के रोमांचक क्षणों के अनूठे अचूक छायाचित्र.  
इतना ही नहीं, और बहुत-सी ऐसी सामग्री जिसकी  
आपने कल्पना भी न की होगी.

हर खेल प्रेमी के लिए जरूरी है

# खेल भारती

A GREAT NEW AD. MEDIUM.

नेट, कोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, 10 बरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
पंजी. कार्यालय : डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएँ : 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001.  
105/7 ए. एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700014. कार्यालय : 13/ ब्रिज रोड, कलकत्ता-700069; 63, मोटियथ रोड, इगमोर, मद्रास-605001.  
407-1, तीर्थ भवन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन एग्रोच, सबरी, वेंबले, मिडिलसेक्स, लंदन, यू. के., लंदन टेलीफोन : 01-903-8444.



# दिनमान

भाग 18, 30 मई - 5 जून, 1982  
अंक 20, 9-15 ज्येष्ठ, 1904

संपादक  
कन्हैयालाल नंदन

तहायक संपादक  
जितेंद्र गुप्त  
मुख्य उपसंपादक  
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना  
संपादकीय सहकर्मी  
श्यामलाल शर्मा  
जवाहरलाल कौल  
शुक्ला ह्रद  
त्रिलोक दीप  
महेश्वरदयाल गंगवार  
प्रयाग शुक्ल  
बनवारी  
विनोद भारद्वाज  
सुषमा पाराशर  
विशेष संवाददाता  
रामसेवक श्रीवास्तव  
सज्जा  
रवि शर्मा

● संपादकीय कार्यालय :  
10 बरियामंज, नयी दिल्ली-  
110002  
दूरभाष : 271911  
व्यवस्था, विज्ञापन तथा प्रसार :  
7, बहादुरबाह जफर मार्ग,  
नयी दिल्ली-110002  
दूरभाष : 270161  
बंबई कार्यालय :  
डा. वाढामाई नोरोजी रोड,  
बंबई-400001  
दूरभाष : 268271  
अहमदाबाद कार्यालय :  
139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9  
दूरभाष : 77631  
कलकत्ता कार्यालय :  
105/7 ए, एन. बनर्जी रोड,  
कलकत्ता-700014  
दूरभाष : 244243  
मद्रास कार्यालय :  
63, मॉडियस रोड, एम्फोर,  
मद्रास-8 दूरभाष : 83661  
पुणे कार्यालय :  
407-1, तीर्थभवन, क्वार्टर गेट,  
पुणे-411002  
दूरभाष : 25447  
लंदन कार्यालय :  
26, स्टेशन एग्रोच, सडबरी  
बंबेले, मिडिलसेक्स, लंदन, यू.के.  
लंदन दूरभाष : 01-903-9696

## संपादक की ओर से

भारत सरकार की स्वायत्तशामी संस्था साहित्य अकादेमी भारत की नेईस भाषाओं के साहित्य और लेखकों की प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है, लेकिन जब सुधी साहित्यकारों से मिल कर बात कीजिए तो वे इसे 'सरकारी साहित्यकारों की संस्था' कह कर अकादेमी की अंदरूनी कलई खोलने लगते हैं कि अकादेमी पर भारत सरकार के शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय की जकड़ इतनी मजबूत है कि नौकरशाही ने इसे अपने हथकंडों का अखाड़ा बना लिया है। 12 मार्च, 1954 को जब अकादेमी का उद्घाटन हुआ था तो उस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था : 'सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करना।' लेकिन अकादेमी के कर्मचारी ही कहते हैं कि साहित्य और संस्कृति के उन्नयन की जगह सचिव को अपनी ही सुविधाओं का उन्नयन प्रिय है।

अकादेमी साहित्यिक उन्नयन के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार बांटती है, लेकिन उसके ये पुरस्कार लगातार विवाद का विषय बनते चले आ रहे हैं। गोपनीय अनुसंधान अभिमत तक चर्चा का विषय बन जाते हैं, पुरस्कृत कृति की तो बात ही और है। डॉ. राही मासूम रजा का उपन्यास 'आधा गाँव' इसी संदेहास्पद गोपनीयता की चर्चा का शिकार हो गया था। इस के बावजूद अभी तक यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि घोषित किये जाने वाले पुरस्कारों की जानकारी प्रायः लोगों को पहले ही कैसे हो जाती है। यह सवाल करने वाले अकादेमी पुरस्कारों के संबंध में गोपनीयता और गुटबाजी दोनों पहलुओं को समेट लेते हैं। "यह गुटवाद का ही परिणाम है कि हिंदी के विरिष्ठ लेखक विष्णु प्रभाकर का कृति 'आवारा मसीहा' को पुरस्कार योग्य नहीं समझा गया। इस से 'आवारा मसीहा' को आँच नहीं आयी, अकादेमी पर भाई भतीजावाद की परत चढ़ी। 'रेणु' को साहित्य अकादेमी ने पुरस्कार योग्य नहीं माना, महादेवी वर्मा साहित्य अकादेमी के लिए अपुरस्करणीय व्यक्तित्व हैं... ऐसा हिंदी के साथ ही होता है ऐसा भी नहीं है। इस वर्ष पंजाबी और तेलुगु की पुरस्कृत पुस्तकों के बारे में जो विवाद उठा है उस ने सभी भाषाओं के लोगों की आँखें खोल दी हैं। लेकिन अकादेमी की नींद नहीं टूटती। अपने अपने स्वार्थों की खिचड़ी में साहित्य को थोड़ी बहुत जूठन मिल जाये तो साहित्य का अहोभाग्य! ऐसे मामलों में भी अकादेमी के मनोनीत सदस्यों की समूची भीड़ शांतिप्रियता का ही उदाहरण बनना पसंद करती है "होना जाना तो कुछ है नहीं, तो फिर अपनी जवान खराब करने से क्या फायदा" इसी शांतिप्रियता के क्रोड़ में अकादेमी सड़ांध का शिकार हो गयी है। नये लेखकों के लिए अकादेमी के दरवाजे सत्र दर सत्र बंद रखे जाते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं : "ऐसे साहित्यकारों को इस संस्थान से सक्रिय रूप से जोड़ना बहुत आवश्यक है जो अपनी साहित्यिक दृष्टि में तटस्थ हों, रचनाधर्मी हों और निर्भीक ढंग से अपनी बात कह सकते हों। ऐसे लोगों की देश में अब भी कमी नहीं है।" और अगर ऐसे लोग आ गये तो फिर अधिकारी क्या करेंगे, उनके अपने 'निजी उन्नयन अभियान' का क्या होगा, उन की विदेश यात्राओं का क्या होगा? एक युवा हिंदी लेखक ने अकादेमी के सचिवों की विदेश यात्राओं का एक रोचक उदाहरण देते हुए बताया कि "प्रत्यक्ष दृष्टा के नाते हाइडेलबर्ग में सचिव (कार्यक्रम) के लिए आयोजित एक गोष्ठी में वक्ता तथा संयोजक के अतिरिक्त सिर्फ तीन लोग और थे उन में से एक तो ऐसा था जिसे सिर्फ इसलिए बैठाया गया था कि श्रोताओं की कमी कुछ तो कम लगे। आखिर ये सचिव विदेशों में कौन सा ऐसा काम करते हैं कि उनकी एक विदेश यात्रा से दुमछल्ले की तरह दूसरी विदेशयात्रा निकल आती है!"

नयी पीढ़ी सवाल करना जानती है। उसके ऐसे अनेक सवाल आज फिर साहित्य अकादेमी को चर्चा के घेरे में ले आये हैं... क्यों साहित्य अकादेमी से सही लेखक कतराता है। क्यों साहित्य अकादेमी के जरिये भारतीय कर्दाता का करोड़ों रुपया कितानों का कब्रिस्तान बन कर गोदामों में सड़ रहा है। क्यों साहित्य अकादेमी देश में व्यापक साहित्यिक जागरण के बजाय आपसी स्वार्थसिद्धि का साहित्यिक अनाथालय बनती गयी है... तमाम ऐसे सवालों की तह में जाने के लिए 'दिनमान' ने इस बार अपनी आवरण कथा के लिए अकादेमी को ही चुना जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जुटाये कथाकार-पत्रकार भाई असगर वजाहत ने। उनके तथ्यों और अपनी निजी खोजबीन पर आधारित प्रयाग शुक्ल का अलिख साहित्य अकादेमी की नींद और सड़ांध की असली तस्वीर पेश करता है और उस में भी विस्मयकारी तथ्यों का उद्घाटन करती है श्रीमती महादेवी वर्मा, अजेय और नामवर सिंह के साथ हुई वार्ताचीत तथा अकादेमी के भूतपूर्व सचिव प्रभाकर माचवे के अनुभव। आखिर देश का जनमानस माहित्य अकादेमी के बारे में कब तक चपे रहेगा?

कन्हैयालाल नंदन



## इस सप्ताह



8  
आवरण कथा : साहित्य अकादेमी के '81 के तेलुगु, अंग्रेजी, पंजाबी पुरस्कारों को लेकर तीव्र विवाद उठ खड़े हुए हैं जिन में तेलुगु और अंग्रेजी के पुरस्कारों का विवाद तो स्वयं अकादेमी की पत्रिका ने खड़ा किया है। अकादेमी के 28 वर्षों के इतिहास में और भी कई विवाद दबे पड़े हैं। अकादेमी की कार्यपद्धति, वर्तमान स्थिति उस की नीतियों का तीखा विश्लेषण और सर्वेक्षण।



24

तिकोना पुस्तक युद्ध : "माउंटबेटन ऐंड पार्टिशन आफ इंडिया" पर पाकिस्तान की आपत्ति और आंग्ल तथा भारतीय प्रकाशकों से उनकी तकरार। तकरार के मुद्दे हैं वे अपशब्द जो माउंटबेटन ने कायदेआजम जिज्ञा के लिए इस्तेमाल किये।

|     |                                        |    |                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | मत सम्मत                               | 34 | जलते प्रश्न : एक पिता की व्यथा कथा                                                                      |
| 5-6 | पिछले सप्ताह                           | 35 | फाकलैंड; पाक-सोवियत संबंध का नया दौर; चीन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति; बंगला देश में परिवर्तन; अफगानिस्तान |
| 7   | सुनो, टंचर सुनो. . . (पत्रकार संसद)    | 39 | दुनिया भर की                                                                                            |
| 16  | लोक से हटने का पुरस्कार (युवा जगत)     | 40 | भारतीय हाकी (खेल और खिलाड़ी)                                                                            |
| 16  | उनका कहना है                           | 43 | मौसम विज्ञानी भी किसानों का जोखिम कम नहीं कर पा रहे (विज्ञान)                                           |
| 17  | थपकियाँ और चपत (चरचे और चरखे)          | 44 | बंधुआ बंध (चिकित्सा)                                                                                    |
| 18  | विल्ली के रंग                          | 45 | भारतीय राजनीति का नया मोड़ (किताबें)                                                                    |
| 19  | ईदिरा कांग्रेस के अगले कदम             | 46 | गद्दी : यह जगह और अच्छी हो सकती है (कला)                                                                |
| 21  | तपासे का तमाशा (समयचक्र)               | 47 | रंग आंदोलन और विश्वविद्यालय (रंगसंच)                                                                    |
| 23  | फिलिस्तीनी नेता अराफत                  | 48 | तमाशा गलतफहमियों का (फिल्म)                                                                             |
| 29  | फाकलैंड युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं  | 49 | संस्कृति समाचार                                                                                         |
| 33  | चुनाव के अनोखे नतीजों के खोले विश्लेषण | 50 | चरित चर्चा                                                                                              |
|     | नारी जगत : बर दूँगे और जबरन पकड़ लो    |    |                                                                                                         |

## मत और सम्मत

### इंद्रजाल का शब्दजाल

16-22 मई: ज. ने. वि. की प्रवेशनीति का इंद्रजाल जहाँ एक ओर इस विश्वविद्यालय के चरित्र, इस की स्थापना के कारणों और प्रगतिशील नौकरशाहों की जनविरोधी साजिशों का पर्दाफाश करता है वहाँ दूसरी ओर प्रवेशनीति संबंधी राजनैतिक सवालों पर अस्पष्ट, हवाई और गलत धारणाएँ भी प्रस्तुत करता है।

प्रवेशनीति में परिवर्तन के लिए नये उप-कुलपति के प्रस्ताव के साथ दो तरह के विचारों के इर्दगिर्द बातें शुरू हुईं। एक तरफ उप-कुलपति, मा. क. पा. समर्थक एस. एफ. आई. एवं फ्री थिंक्स (दोनों छात्र संगठन छात्रसंघ के मुख्य घटक हैं) प्रवेशनीति में नकारात्मक बदलाव चाहते थे। उन का मुख्य तर्क था (1) ज. ने. वि. का शैक्षिक स्तर गिर रहा है (2) सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन के लिए दिये जाने वाले विशेष अंक हटा दिये जायें, क्योंकि उन में भारी घपला है। दूसरी ओर 'प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (पी. एस. ओ.) सहित अन्य जनतांत्रिक छात्रों और संगठनों का मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन के लिए दिये जाने वाले विशेष अंक में कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 'असमान समाज' में खुली प्रतियोगिता की अवधारणा कोरी कल्पना मात्र है, एक फसाद है, जिस का लाभ हमेशा सुविधासंपन्न वर्ग उठाता है। ऐसे समाज में खुली प्रतियोगिता के दरवाजे हमेशा एक निश्चित वर्ग के लिए बंद होते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रवेशनीति में इस अवधारणा का विरोध किया और 'विशेष अंक' की सुविधा को पूर्ववत् बनाये रखने की माँग की। 19 मार्च, 82 को होने वाली विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों की आम सभा ने उपकुलपति और एस. एफ. आई. फ्री थिंक्स संत्रय को पराजित करते हुए हमारे इस विचार का समर्थन किया। उस समय आम छात्रों में यह चर्चा का विषय था कि पुनः ज. ने. वि. को आमिजात्य वर्ग का भारतीय कैंब्रिज या शासन भक्त प्रगतिशील नौकरशाहों का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

दिनमान में प्रकाशित लेख में यह कहा गया है कि 'विशेष योग्यता अंक' का समर्थन करने वाले या विरोध करने वाले सभी 'विशेष अंक' प्राप्त करने वाले छात्रों का योग्यता स्तर कुछ बुनियादी दृष्टियों से कम मानते हैं। लेखक की यह धारणा वास्तविकता से दूर है। हम विशेष अंक की माँग सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से पिछड़े छात्रों के लिए करते हैं और इस संदर्भ में हमारा पर्येक्ष्य

उपपुस्तक है  
विशेष अं  
वे या तो  
बकालत क  
सामान्य  
संदर्भ में  
किया गया  
अधिकारि  
मनमानी  
आम छात्र  
विवन 19  
कि 'इंटरव  
लिखित प  
इस के सा  
सी के प्रति  
दरअस  
लगातार  
जनता के  
आदि का  
सामने ला  
का लगाय  
दंग से बद  
पर निष्का  
सी. वेयरम  
की प्रकृति  
राहुल, क  
स्टूडेंट्स अ  
यूनिट)



'अच्छा हु  
की माँग व  
तुम 2,7  
3,77  
दिनमान



# पिछले सप्ताह

15-20 मई, 1982

## देश

- 15 मई: 11 सदस्यीय चीनी प्रतिनिधि-मंडल नयी दिल्ली में, पटियाला के गुरुद्वारे में पुलिस दल की पिटाई, हरयाणा सरकार द्वारा किसानों का वर्षा से खराब गेहूं खरीदने का निश्चय, चुनाव आयुक्त एस. एल. शकधर द्वारा मतदान मशीनों के प्रयोग की हिमायत, उ. प्र. में विद्युत संयंत्र निर्माण में ब्रिटेन द्वारा मदद.
- 16 मई: भारत चीन सीमा संबंधी विवाद सुलझाने के इच्छुक, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के बाहर पथराव से 50 घायल, प्रामाण क्षेत्रों में पानी पहुँचाने की योजना के लिए 13 करोड़ रुपये, असम सरकार द्वारा बंगलादेश असम सीमा असुरक्षित होने के असम छात्र संघ के आरोप का खंडन.
- 17 मई: भारत चीन वार्ता में कोई नया प्रस्ताव नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा पाक को अमेरिकी शस्त्र दिये जाने को पाक के लिए ही घातक बताया जाना, नयी दिल्ली तीस हजारी अदालत में वकील हड़ताल पर, पं. बंगाल में दो विधान-सभा उम्मीदवारों का नक्सलवादियों द्वारा अपहरण किये जाने की आशंका.
- 18 मई: सीमा संबंधी मुद्दों पर चीन से अभी तक बात नहीं, ज्योतिवसु विधान सभा उम्मीदवारों के अपहरणकर्ताओं से बातचीत को तैयार, भारत नेपाल व्यापार सुविधाओं और तस्करी रोकने संबंधी वार्ता को तैयार.
- 19 मई: प. बंगाल, केरल, हिमाचलप्रदेश, हरयाणा राज्यों तथा 7 लोकसभा और 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव, प. बंगाल और हरयाणा में चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएँ, सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत चीन के प्रतिनिधियों की वार्ता.
- 20 मई: केरल में इका समर्थित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे को स्पष्ट बहुमत, केरल में कलपाकरण को मुख्यमंत्री बनाये जाने की संभावना, प. बंगाल में माकपा आमो, हिमाचल, हरयाणा में स्थिति अस्पष्ट, दो लोकसभा, पाँच विधान सभा सीटों पर इका की जीत, थाणे में राजपा विजयी, भारत-चीन सीमा वार्ता जारी रखने पर सहमति.

30 मई-5 जून '82

## जनवादी नाटक

2-8 मई : स. द. स. का लिखा जनवादी नाटक पढ़ा. आम आदमी किसी वाद, सिद्धांत या विचारधारा की मिल्कियत नहीं है, जिस के चलते उसे अपने अपने मुहावरों में बाँधने की कोशिश की जाये. ऐसी कोशिश अगर पूरी तरह 'एक्सर्ड' नहीं तो कम से कम अनुचित जरूर है. इस सामान्य जन की स्थिति, समस्याएँ और इस के दुख दर्द की भाषा एक है. अंधेरे का स्वरूप एक ही है, चाहे वह जिस का भी हो. इस अंधेरे में खोये होने की छट-पटाहट, कुंठा, तड़प, जलन हर कहीं एक ही सी है. वक्त के आईने पर जमी धूल की पत्त को झाड़ कर चेहरा देखने की जरूरत है, अन्यथा अक्स बेढंगे और कुरूप तो दिखेंगे ही. यह कोशिश तभी संभव है जब कि खुद को भी यही महसूस होता हो कि मेरा अपना चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है. दोहरे संदर्भों में अपनी पहचान कायम करने की लालसा 'खूबसूरती' की तरफ भले ही ले जाये इमान-दारी की हद अछूती ही रह जायेगी. अपने आप के प्रति यह गैरईमानदारी साहित्य में बिल्कुल साफ है. जनवादी कवि होने का दावा यही झूठा पड़ता है, किंतु संतोष यही है कि इस वर्ग की स्थिति आज 'जलकुंभी' सी हो उठी है.

बिना टूटे या बिना जुड़े दर्द का अहसास नहीं हो सकता—सिर्फ दर्द का ढिंढोरा पीटा जा सकता है. पर यह सुनने वालों की आँख में आँसू भी नहीं ला पायेगा. आज जरूरत इस बात की है कि आँख से टपके हर कतरे को शोलों की जुवान दे दी जाये, ताकि आने वाला वक्त किसी की 'दरियादिली' का मोहताज न रहे. इस के लिए यह भी जरूरी है कि दुखती रग पर पट्टी न बाँधी जाये, उसे तीखे नशत्रों से चीर कर उस के रूबरू हुआ जाये. कविता यहाँ छोटी पड़ जाती है. नाटक ही वह जमीन है जहाँ यह 'मुठभेड़' मुमकिन है. यहाँ नाटक किसी भी विरादरी का हो सकता है—राजनैतिक, जन या जनवादी. यह भी तय है कि इस मुठभेड़ में किसी एक को तो मारना ही होगा. —सर्वेद विक्रम, 2, सर. पी. सी. बी.

छात्रावास, इलाहाबाद.

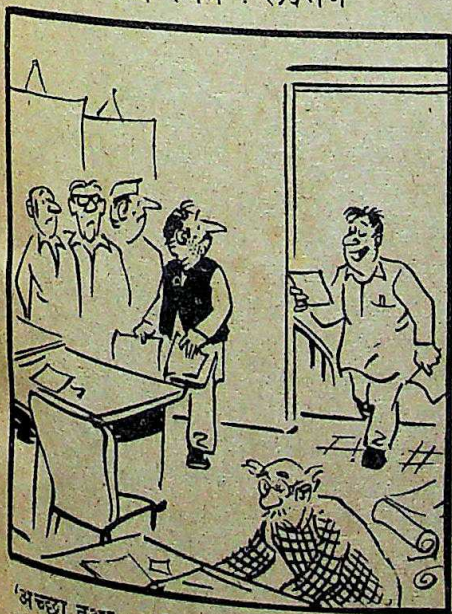
'जनवादी नाटक' पर सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की टिप्पणी विकासशील और जन-पक्षधर किंतु जनवाद के प्रति गुमराह नाटक-कारों, रंगकर्मीयों, कवियों और लेखकों को न केवल जनवाद का असली मांयने बताती है वरन उन्हें उस ओर ले चलने के लिए प्रेरित भी करती है. किंतु एक कमी खली—राजनैतिक नाटक, जननाटक के उदाहरणों के साथ जनवादी नाटक के उदाहरण की कमी. क्या

उपर्युक्त है. हम समझते हैं कि जो लोग इस विशेष अंक दिये जाने का विरोध करते हैं वे या तो समाज के सुविधासंपन्न लोगों की वकालत करने हैं. या फिर समाज विज्ञान का सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते. प्रवेशनीति के संदर्भ में जिस समस्या पर लेख में विचार नहीं किया गया है वह है 'इंटरव्यू' के नाम पर अधिकारियों और सुविधासंपन्न अध्यापकों की मनमानी. इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के आम छात्रों की यह समझ है (जिस का प्रति-विवन 19 मार्च की आम सभा में भी हुआ) कि 'इंटरव्यू' के अंक कम कर दिये जायें और लिखित परीक्षा के अंकों में वृद्धि कर दी जाये. इस के साथ ही मौखिक परीक्षा में एस. एफ. सी के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाये.

दरअसल शिक्षा संस्थानों में भी प्रशासन लगातार निरंकुशता की ओर उन्मुख है. जनता के अधिकारों पर एन. एस. ए., एसमा आदि का हमला निरंकुश शासनतंत्र का चेहरा सामने लाता है. विद्या मंदिरों में पुलिस कैपों का लगाया जाना, प्रवेशनीति को मनमाने ढंग से बदलना, छात्रों को राजनैतिक आधारों पर निष्कासित या निलंबित करना, यू. जी. सी. चेयरमैन का अभी ताजा बयान निरंकुशता की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं. —राजेश राहुल, कार्यकारिणी सदस्य, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन, दिल्ली (ज. ने. वि. यूनिट)

## आप फरमाते हैं

व्यंग्य चित्र : लक्ष्मण



'अच्छा हुआ तुमने दोबारा मतों की गिनती की माँग की—काफी गलतियाँ पकड़ी गयी हैं. तुम 2,71,473 मतों से नहीं बल्कि 3,72,586 मतों से पराजित हुए हो'

विनयान



## पिछले सप्ताह

15-20 मई, 1982

### विदेश

- 15 मई: ब्रिटेन द्वारा आर्जेंटीना के 10 विमान नष्ट: ईरान द्वारा अरब देशों को इराक का साथ न दिये जाने संबंधी चेतावनी: बागदाद देश द्वारा गवाज के मुद्दे को नैतिकी परावरण सम्मेलन में उठाये जाने पर भारत की आपत्ति
- 16 मई: भारत पाक समस्याओं के हल के लिए संयुक्त आयोग के बैठक का पाक द्वारा स्वागत: पाक-इंड मुद्दे पर ब्रिटेन का कड़ा रुख: ईरान द्वारा सीधे पड़ोसी की आवाज विजय अमतराज जापान में गुजरे विदेश हेतु मित्रता में विजयी: अफगानिस्तान प्रायद्वीप में अमेरिकी फौजी को ले कर जापान में प्रवेशन
- 17 मई: ईरान द्वारा खुमैनशहर पर पुनः कब्जा करने की कोशिश: ब्रिटेन पाक-इंड पर आक्रमण द्वारा समस्या के हल का उल्लेख: रूस मास्को वातावरण के लिए दोबारा उल्लेख: जिया द्वारा भारत की ओर से दोस्तों के औपचारिक प्रस्ताव का खंडन
- 18 मई: संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सभा 19 जून को भारत परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने के पक्ष में रूस के राष्ट्रपति जेनरल द्वारा रूस में मिसाइलों के निर्माण पर रोक की घोषणा: ब्रिटेन में भारी आक्रमण के आदेश के लिए तैयार गवाजदश द्वारा गवाजदश विवाद पुनः उठाया गया: फ्लोरिडा में माइकल गेनस की पुत्र आदिल गवाजदश की जेल
- 19 मई: अमेरिका द्वारा भारत के साथ संबंधों का पुनर्मिलान: रूस द्वारा पाक को वापस आ प्रस्ताव: ब्रिटेन पाक-इंड मुद्दे पर शांति वातावरण में अमेरिका प्रसिद्ध अमेरिका मोफिया लार्सन को जेल दो मेटाल इंडियन कार्य में सेवाओं को जेल
- 20 मई: संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पाक-इंड युद्ध रोकने के अनिम प्रयत्न: रूस द्वारा चीन से संबंध सुधार करने के लिए वापस प्रस्ताव: स्वातिमाला के शासन में आक्रमणों द्वारा 43 की हत्या: जेल द्वारा इस्तेमाल में संबंध गवाजदश पर अरब देशों से साराजगी: फ्रांस द्वारा पाक को विरोध विमान रूस अमेरिका सार्वजनिक पुनः आरंभ

जनवादी नाटक लिखे और खेले नहीं जा रहे हैं और यदि हैं (नहीं का सवाल ही नहीं है) तो टिप्पणी में उन का उल्लेख होना चाहिए था. —मदनमोहन, 32 रीडस धर्मशाला कालोनी, गोरखपुर.

### ‘हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़’

मैं श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर का छात्र हूँ. आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, मगध मेडिकल कॉलेज, गया, पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद एवं भागलपुर मेडिकल कॉलेज इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़ कर किसी के पास अपना अस्पताल नहीं है. भागलपुर की विडंबना तो यह है कि वह भाड़े के कॉलेज की इमारत के सहारे आज तक चल रहा है, जब कि वह शुरू से ही सत्कारी नियंत्रण में था. भारतीय चिकित्सा परिषद ने, मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के लिए, कुछ निश्चित नियम बना रखे हैं. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कोई कॉलेज मान्यता के योग्य नहीं था. फिर भी भारतीय चिकित्सा परिषद उन्हें सालाना अस्थायी मान्यता प्रदान कर रही थी. वह विगत पाँच सालों से बिहार सरकार के चिकित्सा विभाग को मशविरा दे रही थी कि वह शर्तों को पूरा कर लें. लेकिन

सरकार के कान पर जू नहीं गेंगी और नतीजा सामने है. मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ वह हम छात्रों पर ध्यान दे कर हमारा भविष्य बचाये. —देवेन्द्र सेंगर, 119 श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर.

गोरखपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास एवं शांतिप्रिय वातावरण में, विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध कुलपति गिरीशचंद्र चतुर्वेदी द्वारा हुआ. समारोह में विश्वविद्यालय विद्वत्परिषद, कार्यपरिषद, शिक्षकमंडल, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रतिभाशाली एवं उच्च उपाधि अर्जित करने वाले विद्यार्थी आमंत्रित थे, जब कि विश्वविद्यालय के दो तिहाई नियमित विद्यार्थियों को इस समारोह को देखने से भी वंचित किया गया. अधिकारियों द्वारा पदक वितरण में व्यापक पैमाने पर धांधलियों की गयीं. स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उस की जगह रजत पदक प्रदान किया गया तथा साथ ही वाणिज्य के विद्यार्थी को हिंदी का पदक, उर्दू के विद्यार्थी को संस्कृत का पदक, मनोविज्ञान के विद्यार्थी को वाणिज्य का पदक, विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पदक की जगह खाली डिब्बे वितरित किये गये. कुछ मेधावी विद्यार्थी अपने नाम की प्रतीक्षा अंत तक करते रहे. किंतु उन्हें रंगमंच तक बुलाया भी नहीं गया. साथ ही पी. एच. डी. की उपाधियों का वितरण खिड़कियों के

### कर्तव्यपालन के बदले

ग्राम गगवा, गोरखपुर, उ. प्र. निवासी रणजीत सिंह आजमगढ़ पुलिस लाइन में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज की हैसियत से तैनात थे. 30 जलाई, 1960 को जब वह आजमगढ़ चौक पर तैनात थे उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रक पर कुछ तस्करी का सामान लदा हुआ है. श्री सिंह ट्रकों को रोक कर जाँचते रहे, लेकिन एक ट्रक चालक यह देख कर तेजी से ट्रक ले कर भागने लगा. श्री सिंह ने दौड़ कर ट्रक का दाहिना फाटक पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए चालक ने श्री सिंह के हाथ पर लोहे की छड़ द्वारा प्रहार करना शुरू कर दिया. फिर भी श्री सिंह ने फाटक नहीं छोड़ा. क्रुद्ध हो कर ट्रक चालक ने वेसली इंटर कॉलेज, आजमगढ़ के पास अपनी गाड़ी एक दूसरी खड़ी ट्रक में रगड़ दी, जिस के फलस्वरूप श्री सिंह बुरी तरह जखमी हो गये. उन की हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती गयी और अंततः बलरामपुर अस्पताल (लखनऊ) में 19 अक्टूबर, 1960 को उन का देहांत हो गया. श्री सिंह के परिवार में बची उन की पत्नी श्रीमती राजपति देवी और चार अल्पवयस्क बच्चे. परिवार की दशा अत्यंत खराब हो गयी. आजमगढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के. डी. शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने सरकार से श्री सिंह की विधवा तथा अल्पवयस्क बच्चों के लिए अतिरिक्त पेंशन और तत्काल राहत राशि देने का अनुरोध किया और इस की भी सिफारिश की जब श्री सिंह के बच्चे वयस्क हो जायें तो उन्हें उन की योग्यता के अनुसार पुलिस सेवा में ले लिया जाये. परंतु 8 रु. मासिक सहायता के अलावा कुछ भी नहीं मिला. चार वर्षों के बाद इस राशि को भी बंद कर दिया गया. 15 मई, 1965 को श्रीमती सिंह स्वर्ग सिधार गयीं. श्री सिंह के निराश्रित बच्चे कई बार संबंधित अधिकारियों एवं मंत्रियों से मिले, परंतु उन्हें भी कोरे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला और न ही उन के किसी बच्चे को पुलिस सेवा में लिया गया. श्री सिंह को अच्छी सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है. —मधुसूदन सिंह, संवाददाता ‘आज,’ बड़हलगांज, गोरखपुर.



## पत्रकार संसद

## सुनो टैचर सुनो

**फाँ** कलैंड के संकट को ले कर विश्व के समाचार पत्रों में इस समय ब्रिटेन की कड़ी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के अपने मित्रों में प्रमुख फ्रांस के प्रसिद्ध समाचारपत्र ल सॉंद ने ब्रिटेन को आक्रमणकारी की संज्ञा दे दी है। अपने ताजा संपादकीय में पत्र ने ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टैचर को ले कर स्त्री प्रधान मंत्रियों के स्वभाव और प्रवृत्तियों का ही विश्लेषण कर डाला है। इस प्रसंग में आर्हेतीना के समूचे क्षेत्र की नाकाबंदी को ल सॉंद ने बहुत खतरनाक बताया है। पत्र ने सीधे प्रश्न किया है।

‘राष्ट्रीयता का उन्माद दिखाने की बात आये तो क्या स्त्री प्रधानमंत्री अधिक आक्रामक सिद्ध होती है? भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस्राइल की प्रधानमंत्री श्रीमती गोलडा मायरने दिखा दिया लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और कैसे जीती जाती है? अब श्रीमती मारगरेट टैचर की बारी आयी। 1956 के स्वेज संकट जैसी चुनौती उन के सामने आयी। नुकसान पहुँचाने में ब्रितानी सेनाएँ बढ़ चढ़ कर हिंसा ले रही हैं। श्रीमती टैचर ने ऐसा निर्णय लिया है जिस ने संकट को और भी गहरा बना दिया और फिर उन्होंने बंदूक तान ली।

यह सब आर्हेतीना की मुख्य भूमि पर आक्रमण करने की तैयारी है इसके विरुद्ध ब्रिटेन के लोग श्रीमती टैचर को चेतावनी भी दे चुके हैं, चाहे जो भी है श्रीमती टैचर दोहरा खतरा मोल ले रही हैं। अपने देश में हाल ही के संसदीय उपचुनावों में भले ही उन्हें या उन की पार्टी की सफलताएँ मिल गयी हों लेकिन कोई नहीं कह सकता कि इस तरह की सैनिक जोखिम को वहाँ के लोग कहाँ तक पसंद करते हैं? जब कोई लोकतांत्रिक देश युद्ध का संचालन करता तो उस के सामने यह समस्या आती ही है।

ब्रिटेन से बाहर ब्रिटेन के अपने ही मित्र श्रीमती टैचर के इस रास्ते को पसंद नहीं करेंगे। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि युद्ध का विस्तार हो जाये। अनेक यूरोपीय देशों ने भले ही, विनम्र रूप से श्रीमती टैचर के इस फैसले को नापसंद किया है। अगर श्रीमती टैचर उन की बात नहीं सुनती हैं तो शायद उन्हें कुछ और जोर से अपनी बात सुनानी पड़ेगी।

**ब्रि** तानी साप्ताहिक इकनामिस्ट में फाकलैंड संकट पर आर्हेतीना और ब्रितानी दोनों ही पाठकों के पत्र छपे हैं जिन में फाकलैंड



श्रीमती टैचर लगाव की दृष्टि में

पर उन्होंने अपनी अपनी बात कही है।

“दक्षिण एटलांटिक के उपनिवेश ब्रिटेन के कर्जों में पिछले डेढ़ सौ वर्ष से चले आ रहे हैं। सन् 1833 से ही हम इन उपनिवेशों पर अपना दावा पेश करते रहे हैं पर ब्रिटेन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। विश्व फाकलैंड पर हमारे दावे की स्वीकार करता है और अब भी कर रहा है।

**एडाडो जे कासुलो—ज्युनिस आधरस**  
फाकलैंड को लेकर सैनिक कार्रवाई पर ब्रितानी जनता चिंतित जरूर है पर इसे औपनिवेशिक उन्माद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। राजनीति की जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति श्रीमती टैचर की इस कार्रवाई का समर्थन करेगा।

चार्ल्स जॉनसन, लंदन

सुरक्षा के सहयोगी

**वि** देशमंत्री के रूप में पाकिस्तान के श्रीसाहिब-जादा याकूब खाँ की प्रथम चीन यात्रा को ले कर पाकिस्तान टाइम्स ने चीन और पाकिस्तान के पुराने संबंधों की दुहाई दी है और चीन को याद दिलाया है कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का वायदा बहुत पहले ही कर चुका है। पत्र का कहना है।

‘अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और लाखों अफगानियों के शरणार्थी बन कर पाकिस्तान चले आने की जानकारी चीन को भी है। आज पाकिस्तान को चीन की मित्रता की सब से अधिक जरूरत है पाकिस्तानी विदेशमंत्री की यह यात्रा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को ले कर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और चूँकि चीन और पाकिस्तान के मित्र संबंध हैं इस लिए पाकिस्तान की सीमाओं पर खतरे की चिंता चीन को होना स्वाभाविक ही है।

30 मई-5 जून '82

माध्यम से किया गया, जिसमें भी अत्यधिक अनियमितताएँ हुईं। संस्कृत के छात्र को अंग्रेजी की उपाधि, समाजशास्त्र के छात्र को मनो-विज्ञान की उपाधि, वनस्पतिशास्त्र के छात्र को गणित की उपाधि तथा अपने नाम की जगह छात्र के पिता या मित्र के नाम वाली उपाधियाँ भी प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालय प्रशासन लड़कों के स्वर्णिम अविष्य के साथ खिलवाड़ काय तक करता रहेगा? —बुबाण चंद्र दाबल, 82 गौतम बुद्ध छात्रावास, गोरखपुर विश्वविद्यालय।

## अभद्र पुलिस के कारण

बुंदेलखंड कॉलेज, झांसी में 30 अप्रैल की परीक्षा दे रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कॉलेज के परिसर में लाठीचार्ज के कारण बहुत से छात्र और छात्राएँ परीक्षाएँ नहीं दे सके एवं पुलिस द्वारा कॉलेज के बाहर सड़क पर छात्रों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है इस से छात्रों में असंतोष की भावना व्याप्त है। प्रशासन से याँग है कि इस अभद्र व्यवहार को रोका जाये एवं जो छात्र छात्राएँ परीक्षा नहीं दे सके हैं उन की परीक्षाएँ दोबारा ली जायें। —सहेज कुमार, बुंदेलखंड कॉलेज, झांसी।

## बेबुनियाद दावा

2-8 मई : केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री भागवत सा आजाद का यह दावा बेबुनियाद है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के संबंध में श्रममंत्रालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। यह उपलब्धि मात्र सरकारी घोषणा एवं नीकर-शाही की फाइलों में है। भले ही कानून के माध्यम से खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गयी हो पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेत मजदूर आज भी दो तीन रुपये दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून का वही प्रभाव है जो कि दहेज विरोधी कानून का है। आवश्यक तो यह है कि आजादी के पैंतीस वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार बंधुआ मजदूरों का पता लगाने में असमर्थ रही है।

—डा. रामबहादुर चर्मा, प्रवक्ता, त्रिरोज-गांधी कॉलेज, रायबरेली।

## खेल और राजनीति

“इस्राइल को नवें एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं” यह वक्तव्य एशियाई खेलों के विशेष आयोजन समिति के अध्यक्ष नूयसिह ने 6 मई को अमृतसर में दिया था। क्या यहाँ पर खेल और राजनीति को एक साथ नहीं घसीटा जा रहा है? कुछ ही दिन हुए विश्व के कोने कोने से आवाज आयी थी कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए।

—अशोक कुमार, बाँकीपुर, पटना।

विनयान



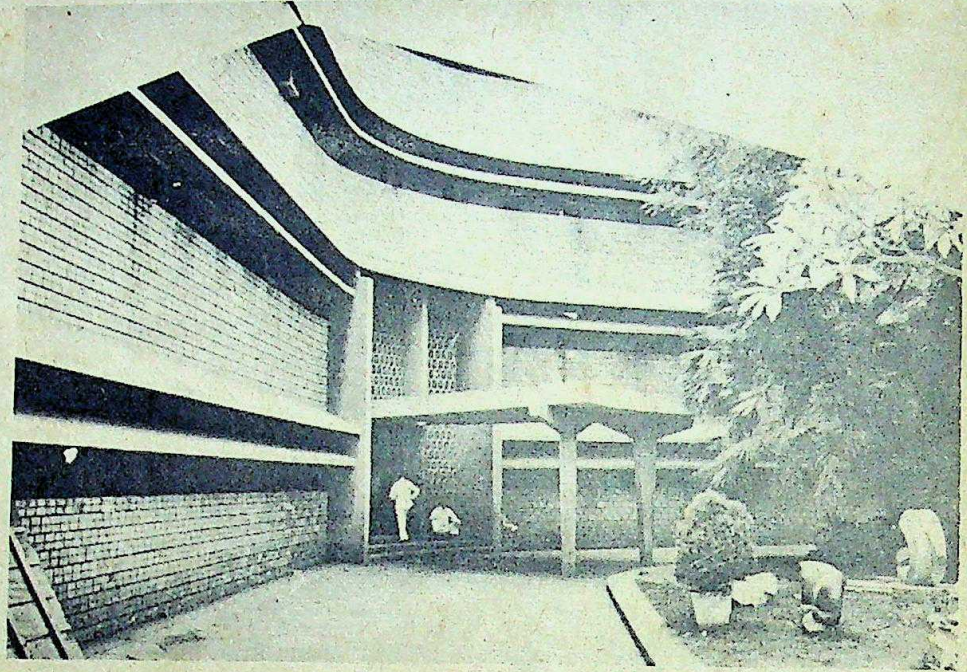
## आवरण कथा

# साहित्य अकादेमी सड़ांध, बीमारी और नींद की शिकार

‘उन के तर्क कालेज की वाद विवाद प्रति-योगिता में हिस्सा ले रहे एक विशार्थों की तरह लगते हैं... किताब फाड़ कर फेंक देने की जगह साहित्य अकादेमी ने उसे तेलुगु भाषा में पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित सर्व-श्रेष्ठ कृति माना है और पुरस्कृत किया है।’

स्वयं साहित्य अकादेमी की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन लिटरेचर के मई-जून 1982 के अंक में '81 के लिए पुरस्कृत तेलुगु लेखक व्यंकटेश्वर राव नाला की पुस्तक सीता जोस्यम के बारे में लिखी गयी इन पंक्तियों के लेखक अकादेमी के ही सहायक संपादक डी. एस. राव हैं। इस समीक्षा को पढ़ने के बाद नाला व्यंकटेश्वर राव ने साहित्य अकादेमी के पुरस्कार को ही लौटाने की धमकी दी। इसी अंक में भारतीय अंग्रेजी के लिए '81 के हो पुरस्कृत कवि जयंत महापात्र की पुस्तक रिलेशनशिप की समीक्षा भी डी. एस. राव ने की है। इस समीक्षा को भी शैली कहीं कहीं बहुत अनुदार है। और इसमें भी यह कटाक्ष निहित है कि अकादेमी ने उसे क्यों पुरस्कृत किया! साहित्य अकादेमी ने जिन लेखकों को पुरस्कृत किया उन्होंने के बारे में अकादेमी के एक अधिकारी समीक्षा के नाम पर तरह तरह के व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपों पर उतर आये।

यह घटना यही बताती है कि अकादेमी लेखकों का सम्मान और अधमान करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझती। इन समीक्षाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होनी थी, वह हुई भी। अकादेमी अध्यक्ष उमाशंकर जोशी और सचिव ने नाला से क्षमायाचना की और राववासन दिया कि इंडियन लिटरेचर में ही समीक्षा को ले कर उन का अमिमत प्रकाशित किया जायेगा। लेकिन विश्वस्त, सूत्रों के अनुसार जब साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष और सचिव नाला से क्षमायाचना कर रहे थे तब उसी समय इंडियन लिटरेचर के संपादक, जयंत महापात्र से एक और ही तरह का चरताव कर रहे थे जयंत महापात्र ने नहीं लिखा था कि मैंने समाचारपत्रों में इन समीक्षाओं को लेकर हुए विवाद के बारे में



रवींद्र भवन (नयी दिल्ली) : साहित्य अकादेमी का प्रवेश द्वार

पढ़ा है और मुझे इंडियन लिटरेचर की एक प्रति चाहिए। इंडियन लिटरेचर के संपादक (केशव मलिक) ने इस पर जयंत महापात्र को केवल यही लिखा 'पत्र मिला, अंक की प्रति भिजवा रहे हैं'। मानों कुछ हुआ ही न हो। संपादक केशव मलिक को लेकर यह बात अब केवल हंसी में नहीं कही जाती है कि वह अंक की समाप्ति बिना पढ़े ही प्रेस भेज देते हैं!

28 बरस बीते जब साहित्य अकादेमी बनी थी, इतने लंबे अरसे में अकादेमी अपनी गति-विधियों के कारण कम हो जानी गयी और कम ही चर्चा का विषय बनी है—अक्सर ऐसे विवादों के समय ही वह चर्चित हो पाती है। यह स्थिति यही बताती है कि वह अक्सर सोयी ही रहती है जब तक कि ऐसा कोई विवाद उसे थोड़ी देर के लिए जगा न दे। पिछले दिनों साहित्य अकादेमी को लेकर कुछ अन्य विवाद भी हुए जो उस के पुरस्कारों से ही ज्यादा संबंधित हैं। पंजाबी भाषा के '81 के पुरस्कार विजेता विश्वनाथ तिवारी की पुस्तक को लेकर भी पंजाबी साहित्यजगत में खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। और कई सम्माननीय पंजाबी साहित्यकारों ने यह बात खुल कर कही कि यह पुरस्कार साहित्येतर कारणों से दिया गया है। इस विवाद की अगुगूज राज्यसभा में भी सुनायी पड़ी। राज्यसभा में खुशवंत सिंह ने अपनी खास शैली में अकादेमी को ही समाप्त कर देने की मांग की। जब शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल ने पुरस्कारों की प्रक्रिया बतानी शुरू की तो डा. रफीक जकरिया ने कहा 'यह तो बहुत ही ठेठोमेठी है।' बहस के दौरान अध्यक्ष श्री हिदायतुल्ला ने कहा कि अगर

पुरस्कार कहीं भी निजी संबंधों के आधार पर दिये गये हों तो उन सदस्यों को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

जहाँ तक अकादेमी की पत्रिका में छपी उप-युक्त समीक्षाओं का सवाल है यह बात साहित्य जगत में स्वीकार की गयी कि पुरस्कृत कृति की आलोचना भी की जा सकती है। और कोई कृति आलोचना के परे नहीं होती। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि आलोचना तटस्थ होनी चाहिए। जाहिर है कि कोई भी लेखक पाठक जब इन समीक्षाओं को पढ़ेगा तो वह यही मानेगा कि बहुत से मामलों में साहित्य अकादेमी की स्थिति और बदतर होती गयी है और उसके अपने भीतरी संगठन में ही दरारें पड़ चुकी हैं। विभिन्न विभागों में कोई तालमेल ही नहीं है।

जब मार्च 1954 में साहित्य अकादेमी की स्थापना हुई थी तो अकादेमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 'वह भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, जिस का उद्देश्य होगा ऊँचे साहित्यिक कार्यों को अग्रसर करना और उन का समन्वय करना तथा उन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का उन्नयन करना।' साहित्य अकादेमी भारत की 23 भाषाओं तथा लेखकों की संस्था मानी जाती है। लेकिन अब तक के अनुभव यही रहे हैं कि लगभग सभी भाषाओं के साहित्य जगत में उस की विश्वसनीयता बढ़ने के बजाय कम ही होती गयी है। वह इस आरोप से बरी नहीं हो पाती कि घोषित किये जाने वाले पुरस्कारों की जानकारी प्रायः लोगों को पहले



ही कैमे हो जाती है। अटकलों और अंदाजों का इस कदर सच निकलना लोगों को कई बार अकादेमी की 'गोपनीयता' पर प्रश्न चिन्ह लगाने को बाध्य करता है। राही मासूम रजा का उपन्यास **आधा गाँव** अकादेमी की इसी संदेहास्पद गोपनीयता का शिकार हो कर चर्चा का विषय बन गया था।

साहित्य अकादेमी की जो थोड़ी बहुत चर्चा विभिन्न भाषाओं के साहित्य जगत में होती है वह प्रमुखतः उस के पुरस्कारों के कारण ही होती है। लेकिन जब पुरस्कारों की विश्वसनीयता भी एक हद तक कम होने लगे तो एक तरह से उस के कुल अस्तित्व के आगे ही प्रश्न-चिन्ह सा लग जाता है। खास कर तब जब कि धीरे धीरे साहित्य अकादेमी एक ऐसी संस्था बनती गयी है जिस का काम मानों साल में विभिन्न भाषाओं में पुरस्कार देना ही है। उसके अन्य कार्यक्रमों की चर्चा हो भी क्यों कर! यह एक चौकाने वाला तथ्य है कि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जब काफी धन खर्च न किये जाने के कारण बच जाता है तो उसे अकादेमी-प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण के काम में ही खर्च कर दिया जाता है। अकादेमी पदाधिकारियों के कृपापात्र कुछ विशेष प्रकाशकों को लाखों रुपये के पुनर्मुद्रण का ठेका हर वर्ष दिया जाता है—अन्य कल्पनाशील कार्यक्रमों के अभाव में। कहने के लिए साहित्य अकादेमी संपादन, लेखन, प्रकाशन की कुछ मध्य योजनाएँ भी बनाती रहती हैं जिन में एक योजना **भारतीय साहित्यकार परिचय** की भी है, जो 1961 में छपा था। संशोधित और परिवर्तित संस्करण छापना है लेकिन इन 20 वर्षों में यह काम पूरा नहीं हो सका। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। मान लीजिए 1970 में किसी लेखक के परिचय संबंधी सूचनाएँ जमा की गयी हों और उन को 1982 में छपा जाना हो तो 12 साल पुरानी सूचनाएँ तथा जानकारीयाँ कितनी अव्ययी होंगी।

1980 की वार्षिक रपट के अनुसार भारतीय साहित्यकार परिचय के काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात् अभी काम पूरा हुआ नहीं है। इसी रपट में यह भी लिखा गया कि '1981 में काम पूरा कर के प्रेस को दिये जाने की संभावना है।' काम में हुई देर का एक कारण यह भी बताया जाता है कि बहुतेरे लेखकों ने परिचय पत्र भर कर वापस नहीं लौटाया। यानी साहित्य अकादेमी लेखकों के परिचय के लिए पूरी तरह से जगह बना ही मोहताज है। यह सवाल अपनी भाषाओं के लेखकों के परिचय और जरूरी विवरण अकादेमी स्वयं ही तैयार कर लेती।

अगर हिंदी की ही बात करें तो प्रमुख और युवा लेखकों के लगभग संपूर्ण परिचय प्रायः उन की प्रकाशित पुस्तकों में ही दिये रहते हैं जो वहाँ से भी लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी योजना **भारतीय विश्व साहित्य कोष** तैयार करने की है। यह योजना मार्च 1976 में त्रिवेंद्रम में शुरू की गयी। और इस एक वर्ष बाद दिल्ली में प्रारंभ कर दिया गया था। इस के संबंध में भी 1980 की वार्षिक रपट में है कि यह 1981 तक प्रेम को दे दी जायेगी। और रपट के अनुसार 'योजनानुसार यह कार्य धीरे धीरे प्रगति कर रहा है।' लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि 1979-80 के वर्ष में इस योजना पर 66 हजार 555 रुपये और 99 पैसे खर्च आया है। और योजना 1976 से चल रही है। यदि 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भी जोड़ें तो इस योजना पर अब तक करीब 2 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। रपट कुछ भी कहती हो अभी हाल तक इसके संपादक **शीतानु यशश्चंद्र** ने लेखकों के पास इस आशय की चिट्ठियाँ भेजी हैं कि वह अमुक अमुक विषय पर विश्व कोष के लिए प्रविष्टियाँ भेज दें। यह चिट्ठियाँ बिल्कुल गश्ती चिट्ठियों की तरह हैं जिन में इस बात तक का उल्लेख नहीं है कि प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पारिश्रमिक क्या होगा। दिल्ली में रहने वाले ही लेखकों के पास ऐसी गश्ती चिट्ठियाँ यही बताती हैं कि इस कोष की कागजी कार्रवाई भर जैसे वर्षों से दर्ज की जा रही है क्योंकि दिल्ली के जिन लेखकों को यह चिट्ठियाँ मिली हैं न उनकी इच्छा जानी गयी न उन से व्यक्तिगत रूप से भी कोई संपर्क किया गया।

अगस्त 1981 में अकादेमी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन (हिंदी), सूची में 34 उपन्यास हैं। पर दुखद आश्चर्य की बात यह है कि इन में से केवल दो अनूदित उपन्यास **चिराग** ले. श्र. सु. वरदराजन और **कनह कुगादूति** ले. श्री कुवेस्य को छोड़ कर अन्य सभी उपन्यास पिछले वर्षों में छपे या पुनर्मुद्रित हैं। 1981 में साहित्य अकादेमी ने हिंदी में केवल दो उपन्यास छापे। कहानी संग्रहों की सूची में 13 संग्रह और संकलन हैं जिन में से एक भी 1980-81 में प्रकाशित नहीं है। हाँ पुनर्मुद्रित अवश्य हैं। नाटकों की सूची में भी 11 नाटक हैं जिन में से कोई भी 1980-81 में नहीं छपा। कविता संकलनों या संग्रहों की सूची में 16 पुस्तकें हैं जिन में से एक भी 1980-81 के बीच नहीं छपी। इन में से भी मूल हिंदी में लिखी गयी पुस्तकें पाँच से अधिक नहीं हैं। विविध प्रकाशनों की सूची में 27 पुस्तकें हैं जिन में से केवल एक 1980 में प्रकाशित हुई है। साहित्य के इतिहास की चार पुस्तकों में कोई

भी पुस्तक पिछले तीन वर्षों में नहीं छपी। अकादेमी ने 1954 में ले कर 1981 तक हिंदी में 174 पुस्तकें छपी हैं—ज्यादातर अनुवाद। इस तरह अनुपात दस पुस्तकें प्रति-वर्ष का भी नहीं पड़ता। पुनर्मुद्रण में ही अकादेमी की दिलचस्पी यही जाहिर करती है कि पुनर्मुद्रण का एक छोटा मोटा उद्योग ही अकादेमी में खड़ा कर दिया है।

अकादेमी साहित्य गोष्ठियों तथा साहित्य सम्मेलनों का आयोजन करती है। लेकिन इस के आँकड़े भी चौकाने लायक हैं। 1980 के ही आँकड़े देखें तो साहित्य अकादेमी ने पूरे भारत में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय नयी दिल्ली में कुल 19 साहित्य गोष्ठियाँ तथा अनौपचारिक साहित्य सम्मेलन आयोजित किये। इन में से केवल 10 संगोष्ठियाँ मुख्यालय में थीं। हाँ, इधर गोष्ठियों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में आयोजित होने वाली गोष्ठियों में (जिनमें श्रोताओं की उपस्थिति प्रायः 20-25 से अधिक नहीं होती) अकादेमी के सचिव वर्ष में शायद एकाध बार ही दिखायी पड़ते हों। यहाँ तक कि अकादेमी किसी लेखक के निधन पर जो शोक समा आयोजित करती है उस में भी वह शायद ही कभी उपस्थित होते हैं। इसके बावजूद हालत यह है कि जब उन की सेवा अवधि बढ़ाने का समय आया तो सेवा मुक्ति से 6 महीने पहले ही उन की सेवा अवधि बढ़ा दी गयी। यह बात स्वयं अकादेमी के कर्मचारी कहते हैं कि साहित्य के 'उन्नयन' की जगह सचिव को अपनी ही सुविधाओं का उन्नयन प्रिय है। साहित्य अकादेमी के पास अब एक स्टाफकार है जिसे रखने का प्रस्ताव दो बार नामंजूर कर दिया गया था लेकिन सचिव ने तीसरी बार प्रस्ताव पास करा लिया। और एक आरोप यह भी है कि वह इस का इस्तेमाल प्रायः निजी कामों के लिए ही करते हैं। अकादेमी के किसी कर्मचारी के बीमार हो जाने पर भी उसे अस्पताल ले जाने की आज्ञा स्टाफ कार को नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जब से सचिव दिल्ली में अपना मकान बनवा रहे हैं तब से उन्हें अकादेमी के कार्यों के लिए समय कम ही मिल पाता है। स्वयं तो वह दफ्तर को कम समय देते ही हैं, अकादेमी के कई कर्मचारियों को भी उन्होंने इस काम में लगा दिया है। और शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीतता हो जब सचिव विदेश यात्राओं से वंचित रहते हों। ये यात्राएँ विदेशों में भारतीय साहित्य को लोकप्रिय बनाने के 'पवित्र उद्देश्य' से की जाती हैं पर क्या कारण है कि अकादेमी को प्राप्त निमंत्रणों का उपयोग सचिव और कभी-कभी उनकी कृपा से कुछ अधिकारी ही कर पाते हैं। दूसरी ओर साहित्य अकादेमी



## आवरण कथा

के कर्मचारियों में अमुरक्षा की भावना बनी रहती है। दो कर्मचारी नौकरी से निकाले जा चुके हैं जिन में से एक वहाँ के कर्मचारियों को यूनियन के सचिव, दूसरे श्री जे. सी. शर्मा संपादन सहायक थे। यह दोनों मुकदमे लेबर कोर्ट में चल रहे हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति की भी कोई नीति अकादेमी के पास नहीं है। जिस को जिस प्रकार इच्छा हुई आगे बढ़ा दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में साहित्य अकादेमी की एक अन्य उपलब्धि रेखांकित करने योग्य है। कार्यकारिणी मंडल की बैठकें जो पहले दिल्ली में हुआ करती थीं वह अब दिल्ली में न हो कर देश के दूसरे मनोरम शहरों में होती हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों के वहाँ आने जाने तथा रहने आदि का व्यय अकादेमी वहन करती है।

उपसचिव (कार्यक्रम) कवि विष्णु खरे ने ए. भारत भूषण अग्रवाल की साहित्यिक दृष्टि

अपनायी कि वह पुरस्कार का निर्णय करने वाले अंतिम तीन सदस्यों के नाम घोषित किया करेगी। यह स्वागत योग्य नीति है लेकिन स्वयं अकादेमी के संगठन यानी परिषद और भाषाओं के परामर्श मंडल को लेकर कार्यकारी मंडल के गठन को ले कर, कई सवाल बचे रहते हैं। अकादेमी के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार की सलाह पर एक सदस्य परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है। आठ व्यक्ति साहित्य जगत से परिषद और कार्यकारिणी की सलाह से सीधे चुने जाते हैं। इस के अतिरिक्त संविधान में परिगणित भाषाओं में से एवं साहित्य अकादेमी द्वारा मान्य भाषाओं में प्रत्येक से एक एक प्रतिनिधि को नियमों के अनुसार साहित्यिक संस्थाओं की संस्तुति पर कार्यकारी मंडल चुनता है। फिर विश्वविद्यालय के 20 प्रतिनिधि होते हैं जिन का चयन कार्यकारी मंडल द्वारा तदर्थ बने नियमों के अनुसार

यशवंत शुक्ल परिषद, कार्यकारी मंडल में गुजराती के प्रतिनिधि और गुजराती परामर्श मंडल के संयोजक हैं। देखें तो परामर्श मंडल के 60 प्रतिशत सदस्य 1973-77 से 1978-82 के सत्र में जैसे के तैसे ले लिये गये हैं। जाहिर है कि इस स्थिति में अकादेमी के कार्यक्रमों में नयापन आना कुछ असंभव सा है। यह कहना उन वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लेखकों की अवमानना करना नहीं है, जो अपनी अपनी भाषाओं में जाने माने जाते हैं। बल्कि इस ओर संकेत करना है कि अन्य प्रतिष्ठित और युवा प्रतिभाओं का समावेश कम ही मात्रा में होता है।

एक समय था जब अकादेमी के प्रकाशनों की सज्जा किसी कदर सुरक्षितपूर्ण हुआ करती थी। रामकुमार जैसे प्रख्यात चित्रकारों ने अकादेमी की पुस्तकों के आवरण भी बनाये थे। इधर फिर कुछ एक अच्छे आवरण देखने में आये जरूर है लेकिन उन की संख्या नगण्य



अपने अस्तित्व की शर्तों से उदासीन साहित्य अकादेमी : वाचनालय (बायें) और बिक्री विभाग (दायें)

संपन्न परंपरा कायम रखी है और साहित्यकारों को कुछ अच्छे प्रकाशन कार्यक्रमों से जोड़ा है। यह भी कोशिश की है कि हिंदी लेखकों पर मूल हिंदी में मोनोग्राफ लिखाये जायें बाद में उन का अंग्रेजी अनुवाद किया जाये—यह नहीं कि पहले पुस्तकें अंग्रेजी में हों फिर उन का हिंदी अनुवाद किया जाये। गोष्ठियों की संख्या भी उन्होंने बढ़ायी है।

लेकिन किन्हीं कारणों से साहित्य मंच के कार्यक्रम अब तक बहुत लोकप्रिय नहीं हो सके। और यह बात भी कई क्षेत्रों में की ही जाती है कि साहित्य मंच की गोष्ठियों में विदेशी लेखकों की संख्या कुछ अधिक ही रहती है और वे सब स्तरीय भी नहीं होते। इस पर अकादेमी का कहना है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कई गोष्ठियाँ अकादेमी पर थोप देती है। वह स्थल जो भी हो साहित्य मंच, कुछ अपवादों को छोड़ कर, अभी कोई जीवंत स्वरूप नहीं बना पाया है।

पिछले वर्ष से अकादेमी ने यह नीति

उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन की संस्तुति विश्वविद्यालयों ने की हो। संगीत नाटक अकादेमी, ललित कला अकादेमी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से एक एक प्रतिनिधि लिया जाता है। परिषद का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है। उक्त सूची से स्पष्ट है कि सीधे लेखक समुदाय में से लिये गये सदस्य कम ही होते हैं। यही नहीं कई बार किन्हीं कारणों से पांच वर्ष के बाद भी कई सदस्य पुनः निर्वाचित या मनोनीत कर दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए 1973-77 के सत्र में श्री नीलांबर देव शर्मा (डोंगरी) तथा प्रोफेसर बसंत बापट (मराठी) कार्यकारी मंडल, परिषद और परामर्श मंडल के सदस्य थे और 1978-82 के सत्र के लिए यही लोग इन भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1973-77 में प्रोफेसर यशवंत शुक्ल परिषद में तथा कार्यकारी मंडल में गुजराती का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और गुजराती परामर्श मंडल के संयोजक थे। 1978-82 के सत्र में भी प्रोफेसर

हैं। अकादेमी की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन लिटरेचर तो बरसों से एक जैसी रूप सज्जा में निकल रही है—अगर उसे रूप सज्जा कहें तो! अकादेमी की हिंदी पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य (संपादक: शानी) में इधर जरूर चित्रकारों के बनाये हुए आवरण देखने में आये हैं। सज्जा की बात से ही यह याद आया कि अकादेमी के कार्यालय की दीवारें बिल्कुल खाली लगती हैं। अकादेमी के वाचनालय को छोड़ दें जहाँ कुछ लेखकों की तस्वीरें टंगी हुई हैं तो अन्यत्र साहित्यिक संस्थान जैसा वातावरण नहीं मिलता। यह आकस्मिक नहीं है कि स्वयं अपने अस्तित्व की शर्तों से उदासीन अकादेमी के प्रति साहित्य जगत भी उदासीन होता गया है।

[और अब आगे पढ़िये : हिंदी के तीन कृती साहित्यकारों महादेवी वर्मा, अज्ञेय और नामवरसिंह के अकादेमी पर विचार और अकादेमी के मृतपूर्व सचिव प्रभाकर माचवे के अनुभव तथा वर्तमान सचिव से बातचीत।]





महादेवी वर्मा : 'पुस्तकें जनसाधारण के लिए सुलभ हों'

## निस्तेज होती हुई मुहर

प्रख्यात हिंदी कवियत्री श्रीमती महादेवी वर्मा से केशवचंद्र वर्मा की बातचीत

केशव : पिछले दिनों केंद्रीय साहित्य अकादेमी के कार्यक्रमों को ले कर विभिन्न भाषाओं के लेखकों में काफी उत्तेजना रही है और बहुत कुछ उस की प्रतिक्रिया देश के प्रमुख अखबारों में भी आयी है। आप साहित्य अकादेमी को इस देश के साहित्यिक प्रतिमान निर्मित करने में कहाँ तक सार्थक मानती हैं?

महादेवी : साहित्य अकादेमी के क्रिया कलाओं को ले कर अब कोई उत्तेजना भी निरर्थक है। उस के किसी कार्य का कोई प्रभाव जीवंत साहित्य या कृतिकार पर नहीं है। उस के कार्यों पर कोई अब ध्यान भी नहीं देता। ये लोग क्या कर रहे हैं—क्या करेंगे, इसे कौन पूछता है? आगे आने वाले समय में साहित्य अकादेमी की मान्यता का कहीं कोई उल्लेख भी करेगा—मुझे इस में भारी संदेह है।

केशव : साहित्य अकादेमी के वार्षिक भाषायी पुरस्कार कुछ समय के लिए साहित्यकारों के बीच चर्चा के विषय बनते हैं। लेकिन क्या उनकी विशिष्ट पहचान अलग से बनती है?

महादेवी : पहली बात तो यह कि अब ये पुरस्कार चर्चा के विषय भी नहीं बनते। दूसरी बात यह कि इन पुरस्कारों से कृति की भी विशिष्टता प्रकाशित नहीं होती।

केशव : क्या आप सोचती हैं कि कृति या कृतिकार का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं होता?

महादेवी : 'मूल्यांकन' ही नहीं होता 'सही ढंग' की तो बात ही अलग है। इन पुरस्कृत कृतियों और कृतिकारों से केवल आपसी संबंध उजागर होते हैं—अमुक व्यक्ति का अमुक व्यक्ति से क्या संबंध है। वह इस का प्रिय मित्र है या वह उस व्यक्ति से अपने निजी स्वार्थ के टकराव के

कारण नाराज है—बस अकादमी के पुरस्कार घूम फिर कर यही कथा दुहराते रहते हैं।

केशव : क्या कृतियों का निर्णायक मंडल ईमानदार नहीं होता है या वे अपने दायित्व को नहीं समझते?

महादेवी : विगत कुछ वर्षों में साहित्य अकादेमी के निर्णायक मंडल में ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का वर्चस्व रहा है जो साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं—वे दल विशेष के लेखकों को पोषित करते रहे हैं। कम से कम हिंदी साहित्य के संबंध में तो यह जानी मानी बात है। तब फिर ऐसी दशा में उस पुरस्कृत कृति की साख साहित्य में कैसे बनेगी? भले ही वे साहित्य समालोचक उन्हें सब के शीर्ष पर बिठाने का अपना 'पराक्रम' हर वर्ष दिखाते रहें।

केशव : क्या आप समझती हैं कि साहित्य अकादमी के ढाँचे के गठन में कुछ बुनियादी बदलाव करना जरूरी है?

महादेवी : उस के संविधान को देखूँ तो कुछ कह सकती हूँ। मैं तो साहित्य अकादमी के जन्म से उसके साथ संबद्ध रही हूँ। जब तक जवाहरलाल नेहरू उस में सक्रिय रहे तब तक उस का एक स्वरूप बनता जा रहा था। संभवतः साहित्य से गहरा लगाव रखने वाले लोग उसी क्रम में बने रहते तो अकादमी का स्वरूप अपनी छाप अवश्य छोड़ता। परंतु उस का दुर्भाग्य यह रहा कि उस संस्था में ऐसे लोग कार्यशील हुए जो मूलतः हिंदी भाषा और साहित्य के प्रच्छन्न विरोधी थे। अकादमी के निकष पर शंकाओं का जन्म तभी हो गया था। अपने पुरस्कारों के संबंध में इस व्यवस्था को अधिक गंभीरता से सोचना चाहिए। निर्णायक मंडल को हमेशा बदलना चाहिए। ये लोग न्यस्त स्वार्थी वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अभी जो लोग इस मंडल में रहे हैं उन के पूर्वग्रह बहुत स्पष्ट रहे हैं।

केशव : ढाँचे के गठन में और क्या परिवर्तन हो सकते हैं?

महादेवी : ऐसे साहित्यकारों को इस संस्थान से सक्रिय रूप से जोड़ना बहुत आवश्यक है जो अपनी साहित्यिक दृष्टि में तटस्थ हों। रचनाधर्मी हों और निर्भीक ढंग से अपनी बात कह सकते हों। ऐसे लोगों की देश में अब भी कमी नहीं है। हर भाषा में ऐसे लोग हैं पर वे उपेक्षित हैं। उन की दृढ़ करनी चाहिए। वे चाटुकार नहीं हैं और पद और यशलिप्सा के लिए दौड़ भी नहीं लगाते।

केशव : अकादेमी विशिष्ट कृतियों को जनसाधारण के लिए सुलभ भी कराती है

और साहित्य के मानक मूल्य स्थिर करने लिए पत्रिकाएँ भी निकालती है। उन बारे में आप की क्या धारणा है?

महादेवी : लेकिन देश के विशिष्ट साहित्यकारों की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ आम आदम के लिए सस्ते मूल्यों पर कहीं भी उपलब्ध ही नहीं। अकादमी चाहती तो इस देश अनेकानेक मान्य रचनाकारों की कृति को बहुत सस्ती कीमतों पर अपने अनुबल के बल पर सर्वसाधारण को सुलभ करा दे।

केशव : शायद आप सोचती हैं कि प्रेस पर जैसे 'गीता प्रेस गोरखपुर' रामचरित मानस या संपूर्ण तुलसी ग्रंथों की या संत साहित्य नाम मात्र मूल्य हिंदी भाषी जनता को सुलभ कराया है। ही कुछ साहित्य अकादेमी को भी करना था।

महादेवी : अच्छी याद दिला बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए। कृतिकार कमी पुरस्कार पर नहीं जी रहा। वह अपनी रचना से ही अम प्राप्त करता है। उस की रचना पहुँच जनता तक। यही सच्चा काम है।

केशव : आप का यह निष्कर्ष सही सकता है कि साहित्य अकादेमी न तो अकादमियों के अकादमिक निकष के बल और न अपनी पुरस्कार राशि के ही अपनी मुहर को कोई भी प्रतिष्ठा दे पाएगी और न उसे गरिमा ही दिला पायी। उत्तरोत्तर वह क्षीण ही होती गयी। ऐसी हालत में शासन के इनाम या अकादेमी के इनामों की नीति में क्या कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं?

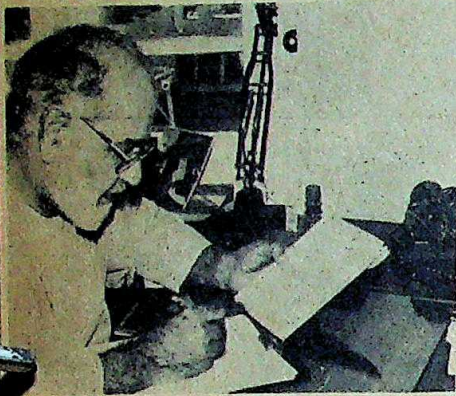
महादेवी : बहुत ही कठिन है परिवर्तन। इस प्रकार के इनाम वांछनीय हैं। केवल एक सामंतवादी प्रकृति या प्रणाली का पोषण करते हैं। उन से ऐसे लेखकों की जमात बढ़ती है जो सत्ता की चाटुकार की ओर क्रमशः उन्मुख होते जाते हैं। उस सूची में आने के लिए ऐसा कुछ लिख पड़ना होता है जो शासन के 'असुविधाजनक' न बने। संक्षेप में वे के लिए उपयोगी बनें—ऐसा ही सिद्धांत जाता है। विरोध करने वाले लेखक पुरस्कृत लेखकों में हों—ऐसा कम ही है। जो ऊपर से विरोध जैसा करते भी पड़ते हैं वे वस्तुतः उसी यथास्थिति बनाये रखने वाले लेखकों का वर्ग ही हैं। फिर एक बात दुहराती हूँ कि यदि रचनाकार का सम्मान करना चाहें (जो कि आज की राजनीतिगत दृष्टि में असंभव ही है) तो उस रचनाकार की कृतियों को सामान्य जन में फैलाने और पढ़े जाने का अवसर दीजिए।



## आवरण कथा

## अकादेमी पर 'अज्ञेय'

प्रयाग शुक्ल के साथ हुई बातचीत में व्यक्त विचार



'अज्ञेय': 'यह सरकारी विभाग बन गयी है'

मैं मानता हूँ कि अकादेमियाँ होनी चाहिए।

लेकिन यह भी मानता हूँ कि उन्हें हर हालत में कुछ ऐसे प्रतिमान बनाने ही होंगे जिन में समाज और साहित्य जगत अपने को कहीं प्रतिबिम्बित होता हुआ भी देखे और उन प्रतिमानों का एक ऐसा स्वरूप भी हो जिसे जरूरत पड़ने पर चुनोती भी दी जा सकती हो। यह मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि अकादेमियाँ 'कंजरबेटिव' (परिमित) भी होती हैं, होनी चाहिए अपने निकषों में, यानी वे ऐसे प्रतिमान बनायेंगी जो सर्वमान्य तो शायद नहीं होंगे पर अपनी जगह कुछ अडिग भी होंगे।

मैं खाली आक्रोश व्यक्त कर के छुट्टी नहीं पा लेना चाहता और न ही आक्रोश और खोश में व्यक्त हुई आलोचनाओं को सही मानता हूँ इस तरह की आलोचनाओं से अकादेमियों का सुधार होने वाला नहीं है। आक्रोश व्यक्त करें तो उस के साथ कुछ रचनात्मक सुझाव भी दें। अकादेमियों के लिए मैं यह एक जरूरी चीज मानता हूँ कि वे साहित्य इतिहास को मूल्यांकन वाली दृष्टि से देखें और साहित्य के प्रामाणिक इतिहास तैयार करावें। पश्चिम का प्रभाव हमारे साहित्य पर रहा है, लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि जब साहित्य इतिहास लिखने बैठें तो गैरजरूरी ढंग से उस प्रभाव का उल्लेख करें, इस सिलसिले में एक उदाहरण देता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुतेरे कवियों ने स्वतः प्रेरित कुछ बहुत अच्छी कवितायें लिखी हैं। अब अगर कोई यह सिद्ध करने चले कि वाल्टर स्कॉट के लेखन से यह निकली है या प्रभावित हुई है, उनकी शुरुआत हुई धारा से—तो वह कितनी भ्रामक चीज होगी। यह उल्लेख इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ साहित्य के इतिहास में, खासतौर से आधुनिक साहित्य के इतिहास

विनमान

में, बराबर पश्चिमी संदर्भों से ही बात को आगे बढ़ाया जाता है। अकादेमी को हर हालत में अपने प्रतिमानों से यह तो बताना ही होगा कि भारतीय राष्ट्र साहित्य को 'इस' ओर 'ऐसी' दृष्टि से देख रहा है। अभी तो ऐसे प्रतिमानों का अभाव बन लगता है। इसी अभाव के कारण जैसी विश्वमनीयता अकादेमी की होनी चाहिए नहीं बन पायी। कहीं यह दृष्टि हमारी अकादेमियों में काम करती रही है कि सरकार पैसा देती है तो नियंत्रण भी रखेगी। इस से निष्कर्ष यही निकला कि सारी शक्ति पैसा है या कि नियंत्रण रखने वाली शक्ति पैसा है। इस तर्क से बहुत तरह की विकृतियाँ पैदा हुईं और बहुत कुछ इन्हीं कारणों से भी साहित्य अकादेमी एक सरकारी विभाग बन गयी है।

उसकी बहुत सारी शक्ति केवल प्रकाशनों की प्रक्रिया में उलझ कर रह जाती है। होना तो यह चाहिए कि स्तरीय और मानक प्रकाशन अकादेमी प्रकाशकों के सहयोग से करें जिस से कि मुद्रण और अन्य प्रक्रियाएँ अकादेमी पर एक बोझ की तरह न पड़ो रहें। और यह तो होना ही चाहिए कि ऐसे बहुत से प्रकाशन जो हमारे परंपरा और साहित्य की परंपरा को समझने के लिए जरूरी हैं, स्वयं साहित्य के रूप में जरूरी हैं, उन का प्रकाशन अकादेमी करे। संस्कृत साहित्य के ही बहुत से ग्रंथों को लें तो वे उपलब्ध नहीं हैं या कि मानक रूप में उपलब्ध नहीं हैं। मसलन वाल्मीकि रामायण नहीं मिलती, कालिदास नहीं मिलता।

जहाँ तक अकादेमी के संगठन का सवाल है इस में हर्ज नहीं कि सदस्य मनोनीत किये जायें। क्योंकि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया तो कई कारणों से दूर तक सफल नहीं होगी। यों भी प्रतिष्ठित लेखकों का या स्तरीय लेखकों का कोई चुनाव तो होता नहीं। वह साहित्य के मूल्यांकन से ही समाजसिद्ध होता है। हाँ, यह जरूर है कि इस को और बराबर दृष्टि रखो जाये कि जो मनोनयन हम कर रहे हैं वह कहीं साहित्य और समाजसिद्ध मनोनयन भी है या नहीं। जो लेखक संगठन हैं लेखकों के अपने संगठन हैं उनमें तो प्रक्रिया चुनाव की रहती है, रहनी चाहिए।

साहित्य अकादेमी को साहित्यिक गोष्ठियों से एक यह शिकायत मुझे रही है कि वह ऐसे विदेशी लेखकों को अपने मंच पर आमंत्रित करती है जो जरूरी नहीं कि अपने अपने देश के प्रतिष्ठित और स्तरीय लेखक हों। यह तो देखना ही चाहिए कि ठीक उन्हीं के स्तर के भारतीय लेखक जब विदेश जाते हैं तो क्या उन का सम्मान या उन के सम्मान में कुछ आयोजन वहाँ की अकादेमियाँ करती हैं!

## तीस लेखक क्या करते हैं?

डॉ. नामवर सिंह से विनोद भारद्वाज की बातचीत

'इंडियन लिटरचर' में प्रकाशित समीक्षा को ले कर हुए विवाद के बारे में आप की अपनी क्या राय है?

समीक्षा तो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है पुरस्कृत पुस्तकों के बारे में साहित्य अकादेमी के प्रथम सचिव कृष्ण कृपलानी ने एक परंपरा कायम की थी। वह यह थी कि पुरस्कृत पुस्तकों के बारे में साहित्य अकादेमी का कार्यालय अपने को विवाद से दूर रखेगा और उन पुरस्कारों के बारे में प्रेस में जो भी चर्चा होगी उस के औचित्य या समर्थन में भी कुछ नहीं कहेगा। न ही वह विवादों का स्पष्टीकरण देगा। अकादेमी के सदस्य स्वतंत्र हैं लेकिन कार्यालय या कर्मचारी नहीं। अकादेमी के कार्यालय को भूमिका तटस्थ है। इस समीक्षा से यह मर्यादा तो भंग हुई ही है।

आपका संबंध 'राजकमल प्रकाशन' से भी रहा है और इस बात की अवसर चर्चा होती है कि राजकमल प्रकाशन की पुस्तकों को हिंदी में कई बार पुरस्कार मिला है। कुछ महाने पहले राधाकृष्ण प्रकाशन के अरविंद कुमार ने एक अंग्रेजी पत्रकार से बातचीत में यहाँ तक कहा था कि 'महामोज' को पुरस्कार इसलिए नहीं मिल पाया है कि वह राजकमल प्रकाशन से नहीं प्रकाशित हुआ है?

महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि पुरस्कार किस प्रकाशक को मिला है। लेखक और उस की कृति का महत्त्व है जिस लेखक को मिला है वह पुरस्कार के योग्य है या नहीं। 1972-77 में मैं कार्यकारी बोर्ड का हिंदी का सदस्य था। मेरे बाद इस पद पर शिवमंगल सिंह सुमन रहे हैं। मेरे कार्यकाल में अमृतराय भी विशेष प्रतिनिधि के रूप में थे। उस समय द्विवेदी जी, शिवमंगल सिंह सुमन, मोष्म साहनी, शमशेर और यशपाल को पुरस्कार मिले हैं। मेरे कार्यकाल के बाद भारत भूषण अग्रवाल, धूमिल (दोनों मरणोपरांत), कृष्णा सोबती और त्रिलोचन को पुरस्कार मिले हैं। दरअसल महत्त्व लेखक का है। द्विवेदी जी के समय में शुरू के 17 पुरस्कार वयोवृद्ध लेखकों





नामवर सिंह : 'मर्यादा भंग हुई है'

को मिले हैं। हालांकि अमृतराय को उन्हीं के समय में पुरस्कार मिला था। वैसे यहाँ मैं एक बात साफ कर दूँ, हिंदी का पुरस्कार अपेक्षाकृत कम विवादास्पद रहा है। यह सही है कि कुछ लोगों को पुरस्कार नहीं मिला। मिसाल के लिए महादेवी वर्मा, नवीन, मैथिलीशरण आदि। वैसे महादेवी 'फेलो' रही हैं। मैथिलीशरण जी तो राज्य-सभा के सदस्य थे लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल, नरेंद्र देव, राहुल जी जैसे सत्ता के विरोधी कहे जा सकने वाले लेखकों को शुरू में पुरस्कार मिला है। शमशेर, यशपाल आदि लेखकों को पुरस्कार दरअसल, 'भूल सुधार' पुरस्कार मिला है।

रेणु जैसे चर्चित लेखक इस पुरस्कार से कैसे वंचित रहे?

रेणु की महत्वपूर्ण पुस्तकों के काल में माखन लाल चतुर्वेदी, दिनकर, पंत, राहुलजी 'दिग्गज' पुरस्कार विजेताओं में थे।

क्या आप को नहीं लगता कि मरणोपरांत पुरस्कार देने की परंपरा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण पुरस्कार इस तरह से नहीं दिया जाता है। और अगर मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाये तो क्यों न उस के साथ एक जीवित लेखक की कृति भी सम्मानित की जाये?

पुरस्कार एक ही हो सकता है। शायद किसी मरणोपरांत की स्मृति की दूसरी तरह से भी सम्मानित किया जा सकता है। पुरस्कार ही उस के सम्मान का एक रूप नहीं है—इस बात को मैं मान सकता हूँ। वैसे अकादेमी पुरस्कार के बारे में एक बात नोट करने लायक है। हिंदी के 30 लोग इस में संलग्न होते हैं। अगर वह सूची भी प्रकाशित की जाये तो उम्मीद में इस पैनल में नये से नये लेखक हैं। पुरस्कार प्रक्रिया में कोई दोष है तो उस की जिम्मेदारी इन तीस लेखकों की है। लेकिन इन 30 में से जवाब पाँच ही देते हैं और अब अक्सर तो वे टिकट लगा लिफाफा भी नहीं लौटाते हैं। दरअसल इन दस वर्षों में अकादेमी ने जो प्रकाशन, साहित्यिक कार्यक्रम आदि किए हैं उन्हें यदि देखा जाये, तो स्थिति बेहतर नज़र आती है। □

## साहित्य अकादेमी के मेरे अनुभव

प्रभाकर माचवे

मैं 1975 की दिसंबर 31 को साहित्य अकादेमी के सचिव पद के कार्यभार से निवृत्त हुआ था फिर उसकी ओर मुड़ कर नहीं देखा। इसके बाद रवींद्र भवन में मैं शायद एक या दो बार ही गया हूँ। गत सात वर्षों से मेरा उस संस्था से कोई संबंध नहीं—किसी भी रूप में। वहाँ एक साहित्य कोश बन रहा है, परंतु मुझसे उसके बारे में कभी भी किसी ने भी एक पत्र नहीं लिखा। यहाँ यह तथ्य बताना आवश्यक है कि मैं विश्व और भारत के बारह साहित्य विश्वकोशों में लिखने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ।

अकादेमी की स्थापना 1954 में हुई। पच्चीस वर्ष पूरे होने पर मुझे एक बार बुलाया था। मैं आइफैक्स हाल में एक दर्शक के नाते, पुरस्कार उत्सव में और एक सेमिनार में श्रोता के नाते उपस्थित था। कहीं भी हमारे लिए (यहाँ मैं अपने से अधिक मूलमंत्री कृष्ण कृपालानी का भी उल्लेख कर रहा हूँ) कोई उल्लेख किसी प्रकाशन या भाषण में नहीं हुआ कि अकादेमी से हमारा कमी कोई संबंध था। इतिहास को इतनी आसानी से झुठलाया नहीं जा सकता।



प्रभाकर माचवे : जब अकादेमी के सचिव थे : 'रेवड़ी बाँटने का सिलसिला शुरू हो गया है'

हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, (जवाहरलाल नेहरू, डा. राधाकृष्णन, डा. जाकिर हुसैन, डा. सुनीतिकुमार चैटर्जी (जिन में से आज एक भी जीवित नहीं) हम पर पूर्ण विश्वास करते थे और सारा कार्य सहयोग की भावना से चलता था। स्व. भारत भूषण अग्रवाल का भी मुझे बहुत सहयोग मिला।

यद्यपि नाम के लिए संस्था स्वायत्त थी परंतु 1954 से 1964 तक नेहरू जब तक जीवित रहे वे इस संस्था के अध्यक्ष थे। उन के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि सरकारी तंत्र ज्यादा हावी नहीं था। शिक्षामंत्री मौलाना आजाद थे, या बाद में हुमायूँ कबीर या कोई अन्य, नेहरू और राधाकृष्णन मिल कर साहित्य अकादेमी के भविष्य निर्माण में अपने विश्वस्तों पर निर्भर करते थे। श्री कृष्ण कृपालानी को नेहरू का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। और पहले बीस वर्षों तक साहित्य अकादेमी के अमला (अधिकारी वर्ग) ने अभी अपने आप को प्रक्षोभित नहीं किया। उस समय के साहित्यकार, विद्वान, समीक्षक, प्राध्यापक सब अपने से बढ़ कर और मूल्यों को महत्ता देते थे।

पुरस्कारों की बात लें। पहली ही हिंदी सलाहकारी समिति के सदस्य जो कार्यकारिणी में थे मैथिलीशरण गुप्त और बनारसी दास चतुर्वेदी स्वतंत्रता के बाद किस का प्रथम सम्मान किया जाये इस पर 1955 में एकमत नहीं हो रहे थे। नेहरू जी ने झल्लाकर कहा—बाहर जाओ और जल्दी से एक नाम तैयार कर के लाओ। बनारसी दास जी, माखनलाल चतुर्वेदी के पक्ष में थे, मैथिलीशरण गुप्त चाहते थे कि पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया जाये। आखिर फैसला माखनलाल जी के पक्ष में हुआ। दिनकर जी को भी बुला लिया गया था, अतिथि सदस्य के नाते।

राहुल जी को पुरस्कार देने की बात उठी तो हुमायूँ कबीर ने नहीं कर दिया—उन के एंटीसीडेंट्स (पूर्व-कार्य) को भी देखना चाहिए। नेहरू जी विगड़ कर बोले, 'वे स्कालर हैं। सारी दुनिया उन को जानती है। कबीर, तुम्हारे क्या एंटीसीडेंट्स हैं?' ऐसा वादविवाद होता था, नेहरू जी के मुँह पर उन का विरोध करने वाले लोग भी थे। सरदार पणिकर, जियालाल कौल। एक बार उमाशंकर जोशी ने कच्छ की संस्कृति पुस्तक पर ऐसी ही बहस की थी। नेहरू शांत भाव से सुनते। बड़े ऊँचे पाये पर सैद्धांतिक बहस होती। लोकतांत्रिक



## आवरण कथा

तरीके से पुस्तकों का चुनाव होता था।

साहित्य अकादेमी के संविधान में ही एक दोष यह था कि प्रत्येक राज्य का शिक्षा मंत्रालय अपने प्रतिनिधि तीन नाम भेजता। पर तब साहित्यिकों के नाम सुझाये जाते थे, अफसरों या मित्रों के ही नहीं। ज्यों ज्यों भाषाओं की संख्या साहित्य अकादेमी में बढ़ती गयी, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर स्तर गिरता चला गया। अंग्रेजी भी अल्पसंख्यक भाषा थी, पर तब उस में हर साल इनाम देने की हिम्मत किसी की नहीं थी। बीस साल में मुश्किल से चार लेखक सम्मिलित हुए। आर. के. नारायण, राजा राव, भवानी मधुचार्म, वेरियर एलविन। बाद में तो तो जैसे रेवड़ी बँटने का सिलसिला शुरू हो गया।

संगोष्ठियों का भी अपना एक स्तर था। रवींद्र नाथ ठाकुर जन्म शताब्दी की अंतर-राष्ट्रीय संगोष्ठी में विदेश से दस लोग आये थे। अबुस हकसले, आइयाँ त्रिफ, सैहाने, इसाया बर्लिन, जाबिताल, सायिन विक्रमसिं, उदरसेमर इत्यादि। तब साहित्य अकादेमी में एहरेतबर्ग आये और देवकोटा आये, नार्मन बाउन आये और नोबकोवा आयीं। बड़ी ही शालीनता और सुरुचिपूर्णता से ये सब समारोह होते।

हिंदी में हजारों प्रस्ताव हिन्दी और राष्ट्रल सांस्कृतिक, नगवतीकरण धर्मा और पक्षपात, बालकृष्ण राव और कक्षा कलिलकर जैसे व्यक्तियों का सहकार्य मिलता था। मैं जानबूझ कर सभी स्वर्गीय व्यक्तियों के नाम ही दे रहा हूँ। परंतु वे सब चीजें डा. सुनीति कुमार चैटर्जी और डा. के. आर. श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनने के बाद बदल गयीं। इस संस्था में अध्यक्ष के भाषाविषयक पूर्वग्रह, उपाध्यक्ष का अंग्रेजी और अरबिद के पक्ष में विशेष पक्षपात बराबर काम करने लगा। फिर तो ऐसी-ऐसी बातें होने लगीं, जिन का पहले कभी स्वप्न नहीं देखा जा सकता था। अध्यक्ष संगोष्ठी में पढ़े अपने निबंध के लिए पारिवर्त्मिक लेने लगा, एक सज्जन ने अपनी बेटी से ही विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा स्वीकृत पुस्तकें लिख-वाले के प्रस्ताव को सान्त्वना दी, एक अमला-चारी ने इस कारण से एक व्यक्ति को पुरस्कार दिलाया कि उस की पत्नी को नोकरी दी थी और पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने उस व्यक्ति से अपने सर्वश्रेष्ठ निबंधों का जयन करवाया। आगे अनेक प्रकार से अपने पूर्वग्रहों को सुनाया गया। □



र. क. केलकर: 'हम सभी को शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं'

## इसका तो जवाब नहीं दे पाऊंगा

अकादेमी के सचिव र. स. केलकर से पंकज शर्मा की बातचीत

पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद भी साहित्य अकादेमी की विभिन्न समितियों में चुने गये व्यक्ति कितने हैं?

यह तो याद नहीं। देखने पर पता चलेगा। लेकिन अकादेमी का एक नियम है कि लगातार दो कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। और लोगों को भी अवसर मिले, इसलिए यह नियम बनाया गया है।

साहित्य अकादेमी जो किताबें प्रकाशित करती है, उनमें से बहुत-सी गोदाम में ही पड़ी रह जाती हैं। इस समय कितने रुपये मूल्य की किताबें गोदाम में पड़ी हैं?

इसका तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, यह तो एक प्रक्रिया है। जब से साहित्य अकादेमी ने प्रकाशन का काम शुरू किया है, तब से 1200 किताबें छपी हैं और वे किताबें ऐसी हैं जो कोई भी व्यावसायिक प्रकाशक नहीं छापता। जो किताबें बच जाती हैं, उनका प्रतिशत 28 से 30 के बीच होता है। निजी प्रकाशकों से तुलना की जाये तो हमारी किताबों की बिक्री की स्थिति बहुत बेहतर है।

अच्छी पुस्तकें छापना अकादेमी का मकसद है। लेकिन स्थिति यह है कि 1981 की सूची में जो 34 उपन्यास हैं, उनमें से दो अनुचित उपन्यासों को छोड़कर बाकी या तो पुनर्मुद्रित हैं या पिछले वर्षों में छप चुके हैं। ऐसा क्यों?

हमें जिन लेखकों से संपर्क करना होता है, वे आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। और यह

तो आप जानते ही हैं कि लेखक 'मंडी' भी होते हैं। कई-कई बार याद दिलाने के लिए हमें चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती हैं तब जाकर पांडुलिपियाँ मिलती हैं। फिर उन्हें देखा जाता है। कई बार सुधार के लिए वापस भी भेजनी पड़ती हैं। इससे मूल पांडुलिपियों के मिलने में देर होती है। रही पुनर्मुद्रण की बात तो हमें पाठकों की रुचि का भी ध्यान रखना होता है।

कहा जाता है कि साहित्य अकादेमी कुछ विशेष प्रकाशक मुद्रकों को लाखों रुपये साल का पुनर्मुद्रण का ठेका देती है। क्या यह सही है?

हमारे पास मुद्रकों की लंबी सूची है और मुद्रण का ठेका देते समय प्रेस की क्षमता वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर किताबों का स्तर भी बनाये रखना होता है।

भारतीय साहित्यकार परिचय 1961 में छपा था। बीस साल हो गये, अब तक उसका दूसरा संस्करण नहीं आया।

दूसरा संस्करण पूरा हो गया है। आज कल में पांडुलिपि प्रेस में जा रही है। इसमें देरी का कारण है। हम जो प्रारूप साहित्यकारों को भेजते हैं, वे समय पर हमारे पास वापस नहीं आते। वैसे अगले तीन महीनों में यह किताब छप जायेगी।

1968 से 79 तक 25 व्यक्तियों को अकादेमी ने अपना महत्तर सदस्य बनाया। लेकिन अनेक को कभी इस लायक नहीं समझा गया, ऐसा क्यों?

इसका उत्तर तो सामान्य सभा ही दे सकती है। यह फैसला वही करती है।

क्या कारण है कि मासिक गोष्ठियाँ अलोकप्रिय हैं और लोग उनमें आते ही नहीं हैं?

हम 200 निमंत्रण पत्र भेजते हैं। दिल्ली में परिवहन की समस्या है। उसी दिन कोई और अपेक्षाकृत ज्यादा आकर्षक कार्यक्रम होने का भी उपस्थिति पर असर पड़ता है।

लेकिन कुछ लेखकों की शिकायत है कि उनके नाम ही निमंत्रण सूची में नहीं हैं और उन्हें निमंत्रण पत्र मिलते ही नहीं।

हम तो सभी को शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे कार्यक्रम सचिव विष्णु खरे प्रसिद्ध कवि हैं और यह काम वह खुद देखते हैं।

1976 में अकादेमी ने यात्रा सहायता की योजना शुरू की। इसके लिए लेखकों को किस आधार पर चुना जाता है?

22 भाषाओं के 22 लेखकों की हर साल यात्रा सहायता दी जाती है। अलग-अलग भाषाओं के सलाहकार मंडल यह तय करते हैं कि किस लेखक को यात्रा सहायता दी जाये। □





पंजाबी लेखकों की सहकारी समिति के वार्षिकोत्सव में पो.बो. नरसिंह राव बोलते हुए बैठे हैं : साधू सिंह हमदद (संपादक अजीत), श्रीमती कुसुम अंसल, डॉ. महीपांसिंह, जोगेंद्र पांडे (सूचना एवं स्वास्थ्य संत्री, पंजाब), प्रवानी प्रसाद मिश्र, खुशवंत सिंह और जानी कुलदीप सिंह

## यह भी देखें कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को किस तरह पुरस्कृत किया जा रहा है

द्रोणवीर फोहली

पिछले दिनों दिल्ली में पंजाबी लेखकों की सहकारी समिति का वार्षिकोत्सव हुआ। पुस्तक-विमोचन का कार्य संपन्न किया हमारे विदेश मंत्री श्री पी. बी. नरसिंह राव ने। श्री राव तेलुगु भाषी हैं। हम लोग सोच रहे थे कि वह अंग्रेजी में भाषण करेंगे। लेकिन धाराप्रवाह हिंदी में बोल कर उन्होंने सभी को चकित कर दिया। अपने संक्षिप्त भाषण के प्रथम वाक्य में ही उन्होंने श्रोताओं के साथ ऐसा तादात्म्य स्थापित किया कि सभी ने एकाग्र हो कर सुना। विदेशमंत्री के पश्चात् भारतीय अंग्रेजी लेखकों के मसौदा श्री खुशवंत सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू किया, लेकिन तत्काल घोषणा की कि पंजाबी में भाषण करने में उन्हें अमुविधा होती है, दलील दी उन्होंने कि हालांकि पंजाबी उन की मातृभाषा है, और 'मैं पंजाबी विच गालां वी कढ़ लैना वा' (मैं पंजाबी में गालियाँ भी दे लेता हूँ) लेकिन पंजाबी में किसी साहित्यिक विषय पर बोलने में वह असमर्थ हैं।

लेकिन इस में भी अफसोस की बात यह थी कि समा में बैठे एक भी लेखक ने खुशवंत की

इस गर्वोक्ति का विरोध नहीं किया—न तो उस समय, और न ही उस के बाद आज तक किसी अखबार में किसी ने कुछ लिखा है। हाँ, सम्मेलन में बैठे एक श्रोता ने अवश्य दबे स्वर में यह कहा था, 'सरदार जी, तुस्सी गालाँ कड़ो'। यानी आप चाहे गाली दे लो, बोलो पंजाबी में ही।

खुशवंत सिंह का प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी भाषा के प्रति गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन यह जो उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी को भी नकारने का बीड़ा उठाया है, यह किस बात का द्योतक है?

मैं समझता हूँ कि इन दिनों खुशवंत एक बड़े तमाशगार यानी 'शोमैन' के रूप में अपनी अलग से पहचान बनाने के फेर में हैं। वह ऐसी बात कहना नहीं चाहते थे, लेकिन या तो उन के मुँह से अन्त्यास यह बात निकल गयी या वह कठोरे में तूफान खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे थे। वह बोले: राज्याश्रय साहित्य में फल फूल नहीं सकता। सरकारी प्रश्रय और सरकारी पुरस्कारों की परंपरा समाप्त कर दी जानी चाहिए। इस के साथ ही उन्होंने साहित्य अकादमी को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। राज्यसभा वाली बात दुहराते हुए उन्होंने कहा कि अकादेमी द्वारा पुरस्कृत दस पंजाबी लेखकों में से सात अकादेमी की कार्यकारिणी से संबद्ध थे।

लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना शर संधौन किया हिंदी वालों पर। अत्यंत विक्षुब्ध लहजे में बोले कि हिंदी पुरस्कारों के मामले में अकादेमी के निर्णय की घोषणा से पहले ही पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नाम निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने इस संबंध में यह कही कि हिंदी लेखकों की एक कतार लगी है जिन्हें बारी-बारी से अकादेमी पुरस्कार दिये जायेंगे।

यहां पर मैं व्यक्तिगत तौर पर खुशवंत जी से सतर्क रहता हूँ। ऐसा हुआ है और हो रहा है। अब नाम लेने में संकोच कैसा। 'साहू लई लई, ते कीह करेगा कोई' यानी लोई उतर गयी, तो कोई क्या कर लेगा। जिस वर्ष स्वर्णीय 'धूमिल' की पुस्तक को अकादेमी ने पुरस्कार दिया, उस से पूर्व ही हम लोग जान गये थे कि एक तो इस लिए 'धूमिल' को पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि उस पुस्तक विशेष के प्रकाशन के तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं उस के बाद यह पुस्तक निर्वाच्य नहीं रहेगी; दूसरे 'धूमिल' के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ही 'धूमिल' को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी तरह, कुष्णा सोबती का नाम भी हम लोगों ने पहले से ही जान लिया था। यह भी बात छिपी नहीं थी कि मनोहर श्याम जो शोका नाम भी बड़ी सर-गर्मी से आगे बढ़ाया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि सोबती और जोशी में 'टाई' पड़ गयी थी।

लेकिन, यह सब सब होते हुए भी ऐसा क्यों है कि खुशवंत जैसे लोग प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के लेखकों पर ही लाल पीले होते हैं? क्या वे यह नहीं जानते कि अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को किस तरह पुरस्कृत किया जा रहा है?

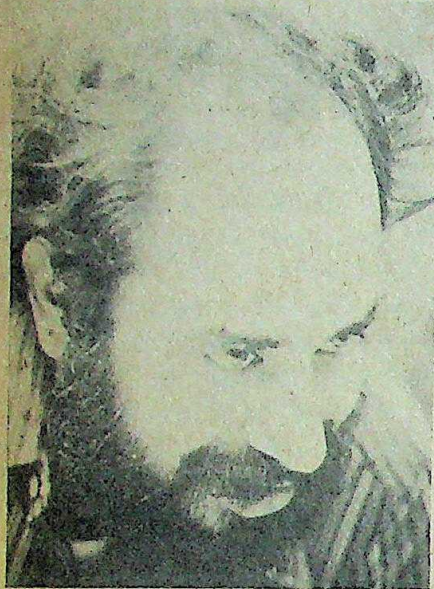
इस संबंध में एक उदाहरण 'आजादी' का है। स्पष्ट है उपन्यास का शीर्षक 'अमीका' को आजादी पर राबर्ट हार्क के उपन्यास 'उद्दर' (शाब्दिक अर्थ आजादी) के अनुकरण पर रखा गया। हम इस पक्ष में नहीं पढ़ेंगे कि चमन नाहल पुरस्कार के अधिकारी थे या नहीं। लेकिन इस के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अवश्य बताना चाहेंगे।

हमें मालूम हुआ था कि 'आजादी' को पुरस्कार दिलवाने में मुत्कराज आनंद का हाथ था। एक दिन हमने मुत्क को घेरा और सफाई देने के लिए कहा। मुत्कराज आनंद ने कोई बात छिपायी नहीं और बताने लगे कि विभाजन की विभीषिका पर वह स्वयं उपन्यास लिखना चाहते थे, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद वह सफल नहीं हुए, इसी दौरान जब 'आजादी' उपन्यास उन्हें पढ़ने को मिला तो उन्हें लगा कि उन के प्रिय विषय पर उपन्यास लिखने वाले को अवश्य पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बस, तत्काल उन्होंने उस की सिफारिश कर दी।

साहित्य अकादेमी किस आधार पर लेखकों को पुरस्कार बाँटती है, इस पर काफ़ी कुछ लिखा बोला जा चुका है। मैं समझता हूँ, जिस संस्था ने 'तमस' को और 'आजादी' को पुरस्कार दिया और 'खुशवंत' को पान नहीं समझा, उस के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहिए।



## लीक से हटने का पुरस्कार



आधारशिला और अशोक आहुजा

मैं घड़ी में समय देखती हूँ. ठीक साढ़े चार बजे हैं. अशोक आहुजा से भेंट का यही समय तय हुआ था. तब ही वह प्रकट होते हैं. सुखद आश्चर्य होता है, अशोक आहुजा अभी फिल्मवालों की लोक से हटकर चल रहे हैं. एक और मियक भी उन्होंने तोड़ा है कि फिल्में फिल्म नगरी में ही रह कर बनायी जा सकती हैं. 1976 में पुणे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से निर्देशन में डिप्लोमा ले कर उन्होंने बंबई की बजाय वापस दिल्ली का रुख किया. भविष्य में भी दिल्ली में ही रह कर फिल्में बनाने का इरादा है. उन के विचार में 'बंबई से दूर रहना ही आज एक फिल्मकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है. वहाँ जिंदगी में कुछ रह नहीं जाता. दूसरे लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रहता. इस का परिणाम यह होता है कि फिल्मकार नकली पात्रों का निर्माण करने लगता है.'

अशोक आहुजा की फिल्म आधारशिला को 1981 का 'निर्देशक की पहली फिल्म' का पुरस्कार मिला है. पुणे फिल्म संस्थान में जाने से पूर्व वह रेडियो, दूरदर्शन और थियेटर से भी जुड़े रहे. लेकिन लोगों से जो कुछ कहना चाहते थे 'फिल्म उस के लिए एक 'बड़ा कैनवास' लगा क्योंकि संगीत, ध्वनि, रंग, टोन, टेक्सचर फिल्म को अधिक प्रभावी माध्यम बना देते हैं.' उन से बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं:

आप दूसरों से कहना क्या चाहते थे?

अगर उसे दो वाक्यों में कहा जा सकता तो 'फिल्म ही क्यों बनाता.

बिनमान

फिर भी?

इस फिल्म में ऐसे युवक की कथा है, जो (स्वयं निर्देशक हैं) अपने जीवन क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है और समझौता नहीं करना चाहता.

क्या अंत में समझौता कर लेता है (फिल्म अभी दिल्ली में प्रदर्शित नहीं हुई)

नहीं, मेरा ख्याल है युवा वर्ग समझौता मुश्किल से ही करता है. प्रौढ़ों के लिए समझौते करना कहीं आसान है.

एक निर्देशक के रूप में आप को किस तरह का संघर्ष-समझौते करने पड़े?

समस्याएँ उस ढंग से आयीं ही नहीं. दर-असल आप को पहले से ही मालूम हो कि किस चीज का सामना करना पड़ेगा तो आप तैयार रहते हैं. 1980 के शुरू में सोचा फिल्म बनानी है उसी वर्ष बना डाली (1976 से 1980 तक वह क्या करते रहे, इस का उन्होंने खास जवाब नहीं दिया). नसीरुद्दीन शाह पुणे

संस्थान में मेरे सहपाठी रहे. बाकी सभी कलाकार नये हैं इसलिए 'डेट्स' की भी कोई समस्या नहीं हुई

आप दूसरी फिल्म कब बना रहे हैं?

फिल्म बना लेना ही अपने आप में काफी नहीं है. कोई भी फिल्म उस समय पूरी होती है, जब वह दर्शक तक पहुँच जाती है.

आप की फिल्म का दर्शक कौन है.

यह बता पाना बहुत कठिन है. व्यक्ति बहुत से कारणों से सिनेमा देखता है. आज भी सिनेमा एक बड़े वर्ग के लिए मनोरंजन का स्रोत से सस्ता साधन है. बहुत से लोग गमियों में एयर कंडिशनर के कारण सिनेमा देखने जाते हैं. एक ही फिल्म को देख कर अमीर आदमी भी खुश निकलता है. गरीब भी. पढ़ी लिखा भी और अनपढ़ भी. (इस प्रश्न पर अशोक आहुजा काफी हद तक अस्पष्ट दिखायी दिये. कही वह उसे ढेर सारे वर्गों में बाँट देते हैं. कहीं कई वर्गों को मिला कर चलते हैं) वैसे मेरी फिल्म



## उनका कहना है

राजनैतिक नेताओं का लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रहने का उपदेश देना ठीक ऐसा है जैसे वैश्या सतीत्व का महात्म्य बता रही हो.

खुशवंत सिंह, अपने साप्ताहिक स्तंभ में.

यदि फिलिस्तीनियों का अलग राज बन भी जाता है तो इस्राइल के पास उसे बरबाद करने के सिवाय कोई और चारा नहीं.

इस्राइली प्रधानमंत्री श्री बेगिन का एक सहायक टाइम पत्रिका में.

चरणसिंह शर्मा से ही अपने विकल्प रखना चाहते हैं. पार्टियों ने विलय के बाद यदि उन्हें अपना नेता नहीं माना तो वह जगजीवन राम और भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब बिठायेगे.

पीलू मोदी एक भेंट वार्ता में आन लुकर से

जिन के मन में भारतीय राष्ट्र की धारणा है, वे हमारे संगठन को ठीक से नहीं समझते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक वाला साहब देवरस दिल्ली की एक सभा में. संडे से.

बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो मेरी बिल्कुल भी मित्र नहीं हैं. पर अमेरिकी कुछ हालात की तरफ से बिल्कुल आँखें बंद किये हुए हैं.

श्रीमती इंदिरा गांधी, एक भेंटवार्ता में, इंडिया टूडे से.

आप प्रकृति को रंगों में देखते हैं ब्लेड एंड व्हाइट में नहीं. यह बात इन कमबख्तों को कैसे समझाऊँ.

रंगीन दूरदर्शन पर एक प्रश्न के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री बसंत साठे, इंडिया टूडे से.

जेल में हालत बहुत खराब है. कैदियों की कोई सुनवाई नहीं है. तिहाड़ जेल में आत्महत्या से पहले अभियुक्त राजसिंह के अंतिम शब्द सत्यजित राय की दूरदर्शन फिल्म सद्गति उतनी ही गलत है जितना इस का विषय—अस्पृश्यता.

इंडियन एक्सप्रेस में फिल्म अभिनेता आई.एस. जोहर.

दूरदर्शन फिल्म सद्गति भले ही सत्यजित राय की बहुत बड़ी उपलब्धि न हो पर जिस ने भी यह फिल्म देखी वह द्रवित हो उठा.

इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय



## चरचे और चरखे

का दर्शक मूलतः भारतीय है—हिंदी भाषी भारतीय.

फिल्म जैसे बड़े माध्यम को भाषा और राष्ट्रीयता में क्यों बाँधते हैं. कैमरे की भी अपनी भाषा होती है. सत्यजित रे की फिल्मों तो हिंदुस्तान से अधिक विदेशों में लोकप्रिय हैं.

यह सही है लेकिन कैमरे की अपनी एक सीमा होती है. भाषा, संस्कृति अलग होने पर उस से कुछ हद तक ग्रहण तो किया जा सकता है. बहुत कुछ छूट भी जाता है.

फिल्म बनाते समय दर्शक की उपस्थिति का अहसास क्या कोई असर डालता है.

हां, कुछ चीजों पर थोड़ा बहुत पड़ता है. आधारशिला में मैंने छह सात गाने दर्शक को ध्यान में रख कर ही रखे हैं. हास्य पक्ष को भी उमारा है. पुणे फिल्म संस्थान में हम जो फिल्में बनाते थे, हमें मालूम होता था उन का कोई दर्शक नहीं है, वहाँ इस तरह का कोई दबाव नहीं होता. जब मैंने आधारशिला बनाने की बात सोची तो लगा दर्शक के लिए फिल्म बनाना उतना आसान नहीं है, जितना संस्थान में बैठ कर फिल्म बना लेना.

पुणे संस्थान में बनी फिल्में प्रदर्शित क्यों नहीं की जाती?

पता नहीं क्यों? किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है. उन में काफी पैसा लगाया जाता है. दर्शक के सामने लायी जानी चाहिए. फिल्म बनाने का तर्क क्या अगर वह दर्शक तक न पहुँचे.

लेकिन दर्शक तक पहुँचने के लिए आज का तथ्याकथित गंभीर युवा फिल्मकार भी लगभग उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर रहा है, जो व्यावसायिक सिनेमा कर रहा है—विशेष रूप से गरीब, हरिजन और स्त्री इस के अस्त्र हैं.

वस्तुतः हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ हम जानते हैं कि दर्शक क्या देखना चाहता है. हम विषय के प्रति कितने गंभीर हैं, ईमानदार हैं. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस से कितने जुड़े हुए हैं.

पिछले एक वर्ष में ही, उदाहरण के लिए 'आक्रोश' 'चक्र' और 'ये नजदीकियाँ', फिल्मों के लिए जिस दंग की विज्ञापनबाजी की गयी, उस से लगता है जैसे फिल्मकार दर्शक से कह रहा हो, मेरी फिल्म में भी वह मसाला मौजूब है, जो व्यावसायिक फिल्म वाले बिखा रहे हैं. ऐसी स्थिति में दर्शक क्या ग्रहण करेगा?

ये फिल्में मेरी नहीं हैं, यह तो वे ही जाने क्या हासिल करना चाहते हैं. मेरे लिए भी दर्शक बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन मैं उस के साथ अपना आशा, अनुभव हर चीज की हिस्सेदारी चाहता हूँ.

—मुषमा पाराशर

## थपकियाँ और चपत

कमी कोयल बोलती है, कमी कुत्ता भौंकता है. फिर कोयल बोलती फिर कुत्ता भौंकता—अजीब प्रतियोगिता सुबह ही सुबह शुरू हो गयी थी. मैं अघट्टी नींद में सुन रहा था. समझ नहीं पा रहा था कि कुत्ते के भौंकने के जवाब में कोयल कुकती है या कोयल के कूकने के जवाब में कुत्ता भौंकता है. या दोनों अलग अलग कूक और भौंक रहे हैं और लग रहा है कि यह सवाल जवाब हो रहा है. दोनों की आवाज़ इस तरह एक साथ तर-ऊपर सुनने का यह पहला मौका था. कहां किन्हीं पेड़ों की डालियों में से छिपी आती मीठी सुरीली आवाज़ और कहां खुले आँगन की यह करलत बेढंगी भौंक! मैं पूरी कोशिश में था कि तय कर सकूँ कि इस समय किस की आवाज़ का खामोश हो जाना मैं पसंद करूँगा. कोयल की या कुत्ते की? कोयल की आवाज़ नींद का नशा बनाये रखने में मदद कर रही थी और कुत्ते की आवाज़ उस नशे को तोड़ रही थी. उठना तो है ही—नींद को सहलाते सहलाते उठना चाहिए या उसे झटके से उखाड़ देना चाहिए. थपकियाँ और चपत दोनों का एक साथ अनुभव आपने किया हो या न किया हो मुझे दोनों का एक साथ अनुभव हो रहा था. इस से पहले कि मैं पूरी तरह जागता और किसी नतीजे पर पहुँचता कि शर्मा जी ने दरवाजा भड़भड़ा कर जगा दिया.

'अभी सो रहे हो?'

'नहीं, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दिया. मैं एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश में था. . .'

'अखबार इधर दीजिए पहले चुनाव किस नतीजे पर पहुँच रहा है यह दिखाइए, अपने नतीजे पर बाद में पहुँच लीजिएगा.' शर्मा जी बोले फिर मेरे सिरहाने से अखबार उठा कर खोलते हुए बोले—

'अपने घर से भागना चाहता था. अभी ये राजनीतिक निठल्ले मेरे घर घमकते ही होंगे और सिर खाने लगेंगे. देखिए कहा था न कि इंका फिर पावर में आयेगी! और चुनाव को ले कर मेरा दिमाग चाटने लगेंगे. इसीलिए तुम्हारे पास भाग आया. अब चाय-वाय पिलवाओ.'

'आप को बहुत दिलचस्पी है चुनाव परिणामों में?' स्तंभकार ने पूछा.

शर्मा जी ने अखबार रख दिया फिर बोले— 'कतई नहीं. किस... को दिलचस्पी है चुनाव के नतीजे में. (स्तंभकार ने गाली उन के मुँह से पहली बार सुनी!) मुझे क्या किसी को भी चुनाव के नतीजों में दिलचस्पी है. दिलचस्पी केवल राजनीतिक दलों के नेताओं,

कार्यकर्ताओं या उन लोगों में है जो सत्ता से अपने पेशे या अपने स्वार्थ के कारण जुड़े या जुड़ते हैं या आप जैसे अखबार वालों को होगी. मुझ जैसे आदमी को इस में कोई दिलचस्पी नहीं है.

'आप गलत कह रहे हैं. दिलचस्पी न होती तो लोग वोट क्यों देते?'

'वोट तो लोग जोर-जबरदस्ती, लालच, देखादेखी और कमी कमी तफरीह में भी दे आते हैं. वह तो दिलचस्पी नहीं हुई. नतीजा भी उसी तफरीह का एक हिस्सा है. दिलचस्पी तो यह हुई कि चुनाव की राजनीति और धंधे के बाहर के लोगों को किसी के जीतने या हारने की खुशी पर तकलीफ हो. कोई जीते या हारे आम आदमी को आज इस में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है. उसे जैसे कोई सरोकार ही नहीं. जैसी हवा देखी, जैसा जोर पड़ा जो खींच खाँच कर ले गया उसे वोट दे आये और फिर आँखें फेर ली—जाय सब जहन्नुम में!'

'यह तो आप बहुत गलत तस्वीर दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र की खींच रहे हैं?'

'यह सही तस्वीर है. हम आप चुनाव के नतीजों पर बहस इसलिए करते हैं कि बहस करने वाले टकराते हैं, आम आदमी नहीं करता. चुनाव धंधे के लोग, बड़ा दूकानदार पुछेगा कि चुनाव का नतीजा क्या रहा? क्योंकि उस को अपना हिसाब किताब उस के आधार पर बैठाना है. पर कोयले की टाल पर काम करने वाला मजदूर, झल्लीवाला, ठेलेवाला, भूमिहीन किसान, गरीब तबका किसी को नतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं. उस से पूछिए तो वह ऐसे देखेगा जैसे पूछ रहा हो 'कैसा चुनाव, कौन सा नतीजा?' क्योंकि वह जानता है कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो उसे ऐसे ही रहना है. यदि गणना हो तो पता चलेगा कि देश के कम से कम सत्तर प्रतिशत लोगों को चुनाव में, चुनाव के नतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं. 'हम तुम तो इसलिए जानकारी रखते हैं कि हमें उन लोगों के बीच घूमना, उन से टकराना पड़ता है जिन के पास बात करने का विषय ही यही है.

'इसीलिए आप के आने के पहले मैं इस नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था कि . . . .'

'समझ गया' कह कर शर्मा जी खुद भी दोनों आवाजों मेरी तरह सुनते रहे फिर बोले—

'कोयल की आवाज़ बंद करना तुम्हारे बस में नहीं. हाँ, खिड़की से गरदन निकाल आँगन में बैठे अपने पालतू पहेरेदार कुत्ते को डाँट सकते हो.'



## दिल्ली के रंग

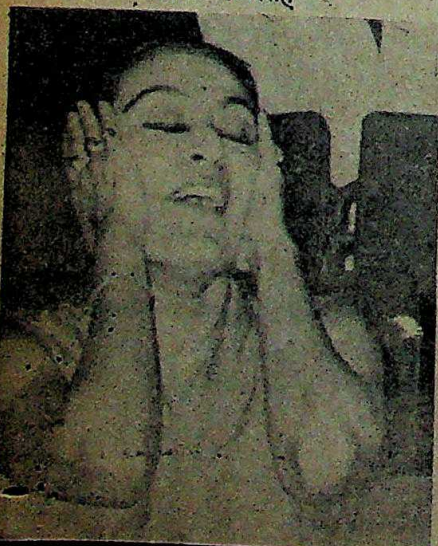
### चोरों की बारात

'असफरशाही ने हर सतह पर सरकारी महकमों में काम करने वाले छोटे बाबुओं से बड़े साहबों तक सैकड़ों नौकरशाहों को मिला कर एक विशाल चोरों की बारात बना दिया है' यह बात पिछले दिनों दिल्ली के काफी हाऊस के एक लोकप्रिय दास्तानगो से सुनी गयी। इस का सबूत भी मिला कुछ दिन पहले समाचार छपा कि तीन पुलिस अफसर इसलिए निलंबित हो गये कि उन्होंने प्रधानमंत्री के घर तक में काम करने वाले एक माली से माल हथियाने का प्रयत्न किया। अपराध उस का यह था कि उस ने एक समारोह में लाऊड स्पीकर लगवा लिया था। माल ले कर ही माली को छोड़ा गया। पुलिस के एक डिप्टी कमिशनर ने मामले की जांच की तो घूस का मामला पाया और अपने तीन कर्मचारियों के निलंबन का आदेश दे दिया। यदि कोई मामूली व्यक्ति होता तो किसी के कान पर जू तक न रेंगती शायद अब उन को सजा होगी या नहीं यह तो महानों की विभागीय और अदालती कार्रवाईयों के बाद पता चलेगा। चालाक आदमी तो प्रायः अदालत में भी विजयी होते हैं। पता नहीं सरकार और समाज इस नयी नौकरशाही जागीरदारी का पूर्ण उन्मूलन कर सकते हैं या नहीं मगर इस मामले में एक प्रशासन विधा विशेषज्ञ की बात जरूर चिंतन मांगती है उन का कहना है सरकारी और प्रशासनिक मामलों में जहाँ देर है, वहीं अंधेरे हैं। देरी के बस दो ही कारण हो सकते हैं : भ्रष्टाचार और अयोग्यता।

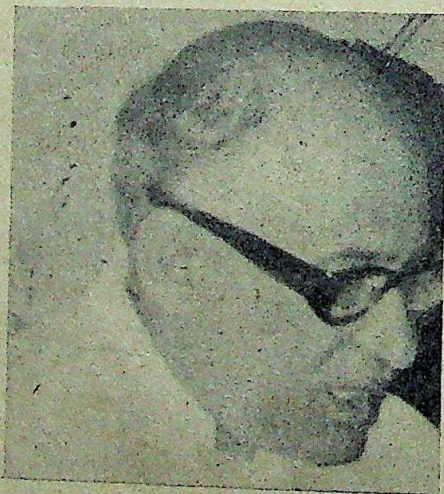
### सोनल की शिकायत

सोनल मानसिंह भारत की विख्यात शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं। अपने देश में ही नहीं, संसार के कोने कोने में जो लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, उन्हें भी जानते हैं, उनके नाम और ख्याति से तो जरूर वाकिफ हैं। हाल ही में मित्रों में

सोनल मानसिंह



बैठे बातचीत करते उन्होंने नृत्य कला के आलोचकों के बारे में शिकायत की। उनका कहना था कि इस देश में सब आलोचक ही आलोचक हैं। प्रायः समीक्षक बहुत कम हैं। अब देखिए जो कुछ ये भले लोग पत्र पत्रिकाओं में नृत्य और अन्य मंच कलाकारों के बारे में लिखते हैं तो किस लक्ष्य से और किस के ज्ञान लाभ के लिए लिखते हैं? यदि विद्वानों के लिए लिखते हैं तो कोई लाभ नहीं। उनमें अपने ज्ञान और विद्वता के बल पर अपनी ही राय कायम करने की शक्ति है, क्षमता है। यदि उन साधारण पाठकों और कलाप्रेमियों के लिए लिखते हैं जो केवल इतना जानना चाहते हैं कि मंच पर किस कलाकार ने क्या पेश किया और उस का क्या महत्व है तो उन्हें कोई लाभ नहीं क्योंकि आलोचक महोदय प्रायः किसी भी कला प्रदर्शन की तकनीकी घुंड़ियों का बखान करने में खोये रहते हैं। चाहिए यह कि जो लोग मंच पर कला प्रदर्शन नहीं देख पाते वे भी इन के लेखन के कारण कुछ कला का ज्ञान तथा स्वादपान कर सकें। जोर कला प्रेम और कला ज्ञान बढ़ाने पर होना चाहिए न कि किसी एक कलाकार की सिर्फ अच्छाइयों और बुराइयों की सूचियाँ छापने पर। यह सोचती है कि मुझे और मेरे जैसे अन्य नृत्य तथा मंच कलाकारों को अब स्वयं अपनी अपनी कला के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर लिखना पड़ेगा।



ख्वाजा अहमद अब्बास

### रोटी, सुंदरी, क्रांति

उपराष्ट्रपति हिदायतउल्ला पुस्तक-विमोचन कर रहे थे अपने ही सरकारी निवास स्थान के एक विशेष कक्ष में। दिल्ली के प्रमुख पत्रकार, प्रकाशक, साहित्यकार, कवि तथा विशिष्ट नागरिक भी पवारे थे जिनमें पत्रकारों के गुरु जे. एन. साहनी, पुस्तक के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास, लंदन से पवारे

'पोयटरी' नामक अंग्रेजी पत्रिका के संपादक तंबी मुत्तू, सूचना प्रसार उपमंत्री आरिफ साहब और जामिया मिलिया इसलामिया के उपकुलपति जमाल किदवई भी तशरीफ रखते थे। पुस्तक का नाम था 'ब्रैड, ब्यूटी एंड रेवोल्यूशन' यानी रोटी, सुंदरी और क्रांति। लाल कागज में लिपटी पुस्तक को उपराष्ट्रपति महोदय ने विमोचन के लिए खोला तो अब्बास साहब ने फरमाया 'मुझे लगता है कि मेरी पुस्तक एक लाल जेल से छूटी है अभी।' उपराष्ट्रपति जी ने कहा मैं इस पुस्तक का शीर्षक समझने का प्रयत्न कर रहा था। यह संकलन है आखिरी पृष्ठों पर लिखे हुए उस कालम का जो 'लास्ट पेज' के नाम से अब्बास साहब कई वर्षों से बंबई के एक अंग्रेजी साप्ताहिक में लिखते हैं क्योंकि पत्रकार पहले पृष्ठ पर लिखे, बीच के पृष्ठ पर या आखिरी पर, उसी से उस की रोटी चलती है। मामला समझ में आ गया। क्रांति की बात सीधे समझ में आती है कि अब्बास सदा क्रांतिकारी लेखक रहे हैं। सुंदरी वाली बात समझने में जरा देर लगी। सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुँचा कि साप्ताहिक के जिस आखिरी पन्ने पर अब्बास साहब का कालम छपता है उस के ऊपर कोने पर एक न एक सुंदरी का चकाचौंध चित्र हर बार जरूर छपता है। देखने लायक होता है, जब हम उस चित्र को देख रहे होते हैं तो हमारा प्रयास यही होता है कि हमारी बेगम साहिबा समझें कि हम केवल अब्बास साहब का लेख ही पढ़ रहे हैं। वैसे हमारी यह राय है कि अब्बास साहब अपने संपादक करंजिया साहब को यह सुझाव दें कि यह चित्र उसी पत्रिका में जिस पृष्ठ पर डाक्टर दस्तूर के लेख छपते हैं वहीं छपा जाये तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा।

साहनी साहब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि अब्बास उन्हें अपना 'गुरु और कामरेड' मानते हैं और साहनी साहब उन्हें शिष्य और 'साहनी स्कूल आफ जर्नलिज्म' का एक झंडा बरदार। साहनी साहब ने बताया कि उन की अपनी नयी पुस्तक का विमोचन भी बस होने ही वाला है उस का नाम रखा है 'ए गैलरी आफ रोज इन इंडियन पोलिटिक्स' यानी भारतीय राजनीति में ऐयारों का एक कक्ष। उन का कहना था कि उन्होंने अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए दो व्यक्तियों को चुना है, ख्वाजा अब्बास या कमलादेवी चट्टोपाध्याय। उन का कहना था कि मैं यह काम रुढ़ि के अनुसार किसी विख्यात व्यक्ति से नहीं कराना चाहता। एक साहब ने पूछा 'क्यों साहनी साहब, क्या अब्बास और कमलादेवी विख्यात व्यक्ति नहीं?'

साहनी साहब हंस पड़े और बोले 'मई मेरा मतलब था विमोचन किसी मंत्री वंत्री से नहीं करवाऊँगा।'

राष्ट्र

राजनैति

इंदिरा

अंग

राजधानी

याणा

मजनलाल

क्या है तो

चुनाव चा

बनाऊँगा।

ठोस बात

बावजूद म

कुछ लं

सुविधा क

सफलता है

मगर इस

ही के लघु

श्रीमती ई

है? तथासे

इंका महाम

ने इंका वि

वे जानते

वापस इंका

कि हमारे

प्रत्याशियों

के हार ग

नहीं, इंदि

प्रत्याशियों

साख अधि

के तूफानी

निकाल दे

है। हाल

हिमाचलप्र

विद्रोह क

कई गुना

कीमत इन

वाले दिनों

के बल के

ही सकती

उपलब्धि म

और साथ

नियंत्रण क

राजस्थ

किया है इ

में इंका प्र

महत्त्वपूर्ण

चुनाव था

सुंदरसिंह

विनयान



राष्ट्र

राजनैतिक बल

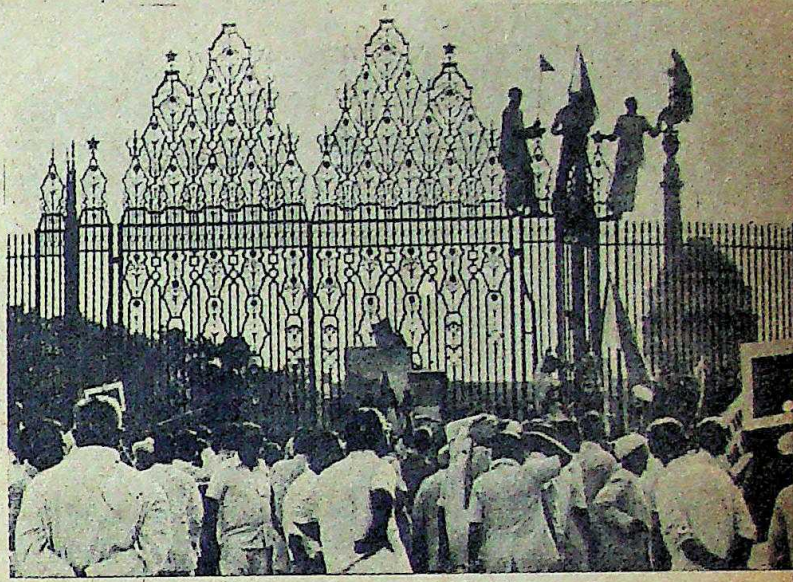
## इंदिरा कांग्रेस का जगला कदम

राजधानी में एक चुटकुला चल पड़ा है. हरयाणा में मतदान से पहले श्रीमती गांधी ने भजनलाल से पूछा कि चुनाव की संभावनाएँ क्या हैं तो तपाक से जवाब मिला : 'मैडम चुनाव चाहे कोई भी जीते सरकार तो मैं ही बनाऊँगा.' चुटकुला तो चुटकुला ठहरा मगर ठोस बात यह है कि इंका के अल्पमत होने के बावजूद भजनलाल ने सरकार बना ही डाली.

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि राजनीति सुविधा की कला ही तो है. महत्त्वपूर्ण तो सफलता है—समर्थ को नहीं दोष गोसाई. मगर इस तर्क में एक बड़ी खामी है. क्या हाल ही के लघु आम चुनावों में इंका, खास कर श्रीमती इंदिरा गांधी की सामर्थ्य में वृद्धि हुई है? तपासे की कार्रवाई को उचित बताते हुए इंका महामंत्री मूपनार ने दलील दी कि लोगों ने इंका विद्रोहियों को इस लिए मत दिया कि वे जानते थे कि आखिरकार वे जायेंगे तो वापस इंका में ही. 'नहीं तो ऐसा कैसे हुआ कि हमारी ही पार्टी के विद्रोही निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में जीते और अन्य पार्टियों के हार गये.' बात सौ पैसे सच है. लोग ही नहीं, इंदिरा कांग्रेस से विद्रोह करने वाले प्रत्याशियों ने यह माँप लिया था कि इंका की साख अधिक नहीं है और न ही श्रीमती गांधी के तूफानी दौरे तथा पार्टी से छह साल के लिए निकाल देने की धमकी में अधिक दम है. हाल के चुनावों में हरयाणा और हिमाचलप्रदेश ने कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह करने का महत्त्व पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया है. इंका विद्रोह की कीमत इन चुनावों में बढ़ गयी है. यह आने वाले दिनों में श्रीमती इंदिरा गांधी और उन के दल के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है. इस लिए मूपनार साहब जिसे उपलब्धि मानते हैं वह उपलब्धि नहीं, मतदाता और साथ ही अपनी पार्टी पर घटते हुए नियंत्रण का प्रमाण है.

राजस्थान में इंका ने काफी कुछ हासिल किया है इस में कोई शक नहीं. तीनों उपचुनावों में इंका प्रत्याशी जीत गये हैं. इस में सब से महत्त्वपूर्ण उदयपुर शहर का संसदीय उपचुनाव था जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुंदरसिंह भंडारी को इंका प्रत्याशी दीनबंधु

विनयान



हरयाणा प्रकरण को लेकर राष्ट्रपति भवन के द्वार पर विपक्ष की दस्तक (ऊपर). बायें के चित्रों में गढ़वाल में पराजित इंका के चंद्रमोहनसिंह नेगी (ऊपर) और ठाणें से निर्वाचित भाजपा के जगन्नाथ पाटील

वर्मा ने 44 हजार से भी अधिक मतों से हराया. उदयपुर में इंका का जीतना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजस्थान में सफलतापूर्वक अपने पाँव नहीं जमा पा रही है. बयाना की लोकसभा सीट भी इंदिरा कांग्रेस के हाथ लगी है और यही हाल सरदार शहर में विधानसभा के उपचुनाव का रहा. यहाँ भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मकुंद शर्मा और इंका के केसरीचंद में था. केसरीचंद को 1,294 मत अधिक मिले. सफलता का संतोष इंदिरा कांग्रेस को बिहार के उपचुनावों से भी मिल सकता है. आदिवासी क्षेत्र लोहारदगा में स्व. कांतिक ओरांव की पत्नी ने भाजपा के ललित ओरांव को पराजित किया. इस राज्य में विधानसभाओं के लिए होने वाले उपचुनावों—साहिबगंज, जलालपुर में भी इंका प्रत्याशी जीत गये. मगर इसके विपरीत मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में सत्तारूढ़ दल की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है. मध्यप्रदेश में जबलपुर लोकसभा उपचुनाव को मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह ने प्रतिष्ठा का चुनाव मान लिया था, क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले इस लोकसभा स्थान को इंदिरा कांग्रेस ने विपक्ष से छीन लिया था और इस की पूरी पूरी कोशिश थी कि इस महत्त्वपूर्ण शहर पर सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व बना रहे. मगर भारतीय जनता पार्टी के बाबूराव परांजपे ने इंका की रत्नकुमारी को पराजित किया.

उत्तरप्रदेश में हेमवतीनंदन बहुगुणा का चुनाव इंका के लिए कुछ ऐसी ही घटना हो गयी है जैसे कि लड़ाकू सांड को किसी ने लाल कपड़ा दिखाया हो. पिछले वर्ष जून के

अनुभव ने इंदिरा कांग्रेस को यह दिखा दिया था कि अत्यधिक शक्ति प्रदर्शन भी कभी कभी उल्टे परिणाम दे सकता है. इस बार उस किस्म का प्रदर्शन तो नहीं किया गया लेकिन साधनों और कार्यकर्ताओं के लिहाज से कोई कोर कसर नहीं रखी गयी. परिणामों ने यह सिद्ध किया कि मतदाता की मर्जी को पहले से माँप लेना इतना आसान नहीं. इंका प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी को उस विधानसभा क्षेत्र में भी कम मत मिले जहाँ से वह विधानसभा के लिए चुने गये थे.

यह पुछा जा सकता है कि एक विपक्षी नेता का लोकसभा के लिए चुना जाना सत्तारूढ़ दल के लिए इतने बड़े आतंक का कारण क्यों है? इसके लिए यह समझना जरूरी होगा कि सत्तारूढ़ दल के पास सही मायने में राजनैतिक दल नाम की कोई चीज नहीं रही है. अति-केंद्रीकृत नेतृत्व को और तथाकथित राजनैतिक संचालन के कारण इसे इसी प्रकार के विरोधी कौशल से काफी खतरा पैदा हो सकता है. और यह राजनैतिक क्षेत्रों में सर्वमान्य बात है कि हेमवतीनंदन बहुगुणा इस राजनैतिक संचालन में किसी से कम नहीं हैं. सच बात तो यह है कि आपात्स्थिति से पहले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री पद से बहुगुणा को हटाने के पीछे यही तथ्य था कि वह श्रीमती गांधी के समानांतर एक शक्तिकेंद्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे. इंदिरा कांग्रेस में असंतोष और विद्रोह की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए बहुगुणा का फिर से जीत कर आना कालांतर में इंदिरा कांग्रेस के लिए सरबदे बन सकता है.



## हरयाणा में महाभारत का खेल

देवीलाल के समर्थकों की हाजिरी 24 मई सोमवार को तय कर दी गयी थी और इस उम्मीद में कि राज्यपाल तपासे के सामने नव-निर्वाचित विधायकों की गिनती करवाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी जायेगी उन्होंने 45 विधायकों को जुटाने की भरपूर कोशिश की थी. मगर सोमवार आने से पहले ही हालात ने नाटकीय पलटो खराया था और राजभवन में लोकदल समर्थक विधायकों की हाजिरी एक प्रदर्शन का रूप ले गयी. एक दिन पहले ही तपासे ने इका विधायक दल के नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी. चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल और देवीलाल की मुठभेड़ से इतनी उत्तेजना पैदा हुई कि बाहर इंतजार कर रही पुलिस को लगा

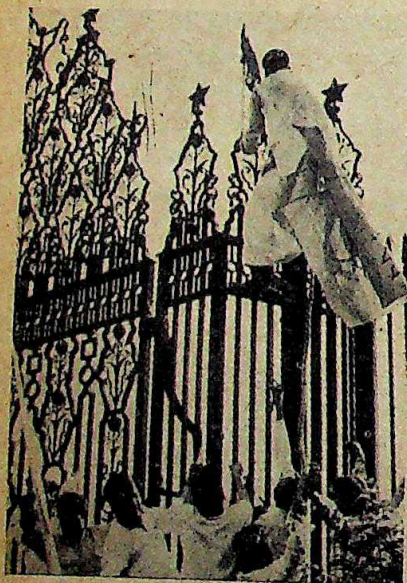
दिया गया था तो भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का नैतिक अधिकार उन्हें कैसे प्राप्त हुआ. इस प्रदर्शन में शिष्टाचार के सभी मापदंड ताक पर रख दिये गये.

भारतीय जनता पार्टी के मंगल सेन का सवाल था कि भजनलाल को एक महीने का समय क्यों दिया गया. क्यों नहीं उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया गया? क्या इसलिए कि एक महीने के अंदर वह विधायकों को फोड़ने में कामयाब हो जायेंगे? श्रीमती चंद्रावती ने ऊँची आवाज में माँग की 'उन्हें अभी इसी समय देवीलाल को शपथ दिलानी चाहिए.' जगजीवन राम कांग्रेस के एक सदस्य का कहना था कि राज्यपाल ने भजनलाल को मुख्यमंत्री बना कर संविधान के विपरीत काम किया है. मगर विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष कर्नल राम सिंह एक कदम आगे गये, 'आपने केवल अपनी रोजीरोटी बचाने के लिए

लोकतंत्र की हत्या की है.' इस कहामुनी सबसे दिलचस्प वाक्य शायद भाजपा के रामविलास शर्मा के मुँह से निकला. उनके अनुसार "याद रखिए यह हरयाणा है जहाँ महाभारत का भीषण संग्राम हुआ था यहाँ खून की नदियाँ बह जायेंगी."

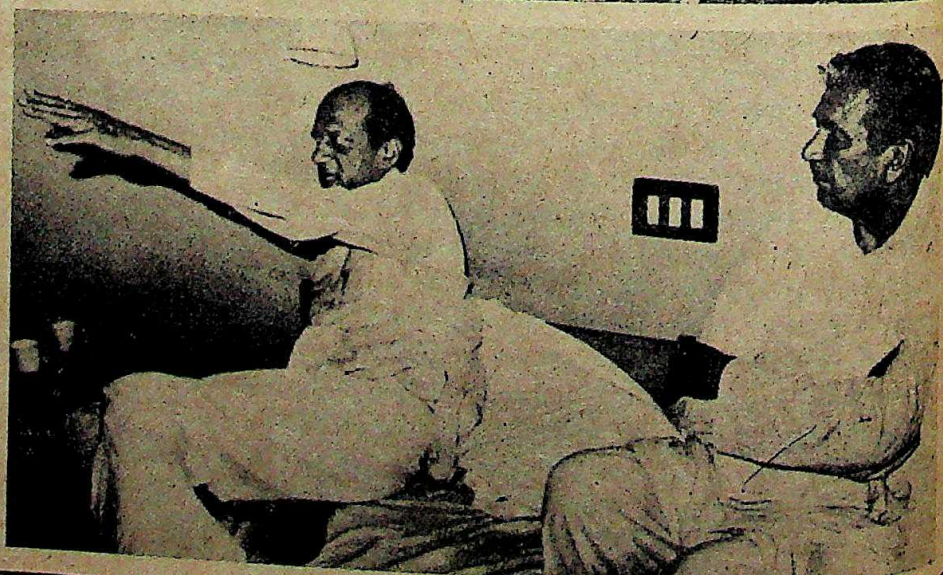
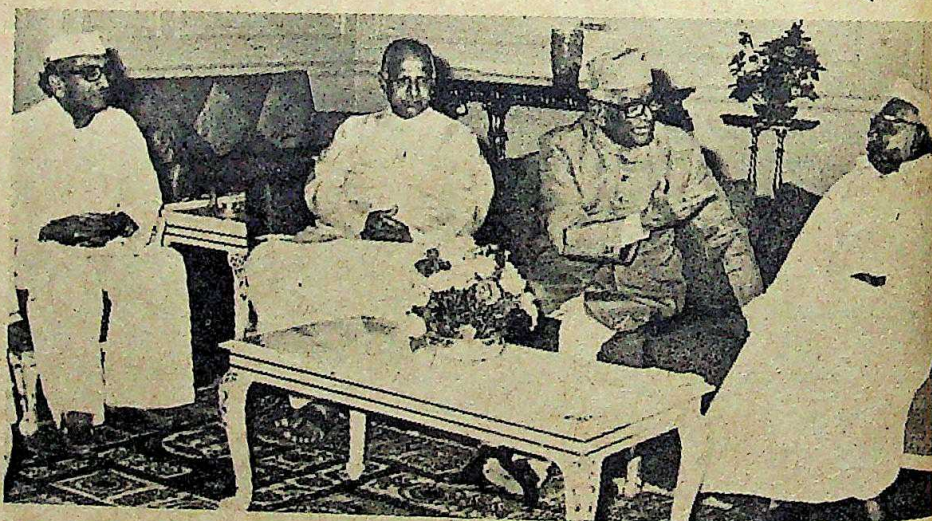
हरयाणा के राज्यपाल के व्यवहार पर विरोध प्रकट करने के लिए प्रमुख विरोधी दलों के नेता राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से भी 24 मई को मिले और उनसे राज्यपाल तपासे को अपने पद से हटाने की माँग की.

राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि वह संवैधानिक मामलों की जाँच करेंगे और जो कुछ भी हो सकता है इस सिलसिले में करेंगे. मगर भारतीय राजनीति के पिछले दशक का इतिहास बताता है कि इस प्रकार की घटनाओं की करीब करीब हू-ब-हू पुनरावृत्ति होती रही है और न तो इनका अभी तक किसी ने गंभीर राजनैतिक हल निकाला है और न संवैधानिक ही. इसी



राज्यपाल के फंसले के विरोध में विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शन किया (ऊपर), और विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से शिकायत की (दायें) हरयाणा भवन में कर्नल रामसिंह ने पुलिस की जबरदस्ती की निंदा की (दायें नीचे) जो कि रामसिंह के कमरे से विधायक लालसिंह को ले जाने आयी थी (अगले पृष्ठ पर ऊपर) इस बीच उत्तेजित मोड़ हरयाणा भवन में इकट्ठी हो गयी थी (अगले पृ. पर नीचे)

कि हाथापाई की नीवत न आ जाये. देवीलाल ने राज्यपाल से पूछा कि जब उन्हें अपने समर्थकों को पेश करने का आदेश





वर्ष जनवरी में असम में करीब करीब इसी प्रकार की मांगें ले कर विपक्षी दल राष्ट्रपति रेड्डी से मिले थे क्योंकि वहाँ भी विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे के स्पष्ट बहुमत के बावजूद अल्पमत वाली इंदिरा कांग्रेस के नेता श्री गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया गया था. यह अलग बात है कि वह एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिक पाये.



### दूसरा दृश्य

हरयाणा के नाटक का पहला दृश्य यदि चंडीगढ़ के राजमवन में खेला गया तो दूसरा अगले ही दिन (25 मई को) देश की राजधानी नयी दिल्ली स्थित हरयाणा भवन में. मंगलवार प्रातः 5 बजे हरयाणा पुलिस के 60-70 जवान हरयाणा भवन पर आ घमके. उनका लक्ष्य था इस सरकारी मेहमानखाने का 14 नंबर का कमरा. इस कमरे के अंदर रह रहे थे हरयाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष कर्नल रामसिंह और उनके साथ थे एक और निर्दलीय विधायक लालसिंह. दरवाजे पर जोरदार थपकियाँ पड़ने लगीं तो रामसिंह ने पूछा कि कौन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है. जवाब मिला 'हरयाणा पुलिस'. पुलिस लाल सिंह को लेने

आयी थी क्योंकि पुलिस के अनुसार किसी अन्य विधायक ने उनके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की थी. ऐसी क्या शिकायत थी कि जिस के लिए तड़के ही विधायक को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ी. यह पुलिस के उपाधीक्षक राम कला ने नहीं बताया. दरवाजा खुल नहीं सका मगर कमरे के भीतर पहुँचने का पुलिस को दूसरा रास्ता मिल गया. पिछवाड़े से वह कमरे के साथ लगे हुए गलियारे में पहुँच गयी. रामसिंह ने लालसिंह को पुलिस के हवाले करने से इन्कार किया. इस उत्तेजना में ऐसा भी क्षण आया जब कि कर्नल रामसिंह ने पुलिस को रोकने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की. मगर उनके एक अन्य दोस्त मित्रसेन ने उन्हें ऐसा करने से रोका.

रामसिंह के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ टेलीफोन पर संपर्क स्थापित किया और कहा : आप हमें इसी प्रकार कल करवाना चाहते हैं तो अलग बात है मगर मैं आप की किसी घमकी के आगे नहीं झुकूंगा. बताया जाता है कि भजनलाल ने रामसिंह को चेतावनी दी कि यदि लालसिंह को पुलिस के हवाले न किया गया तो उनके विरुद्ध एक मामला जो पहले से दर्ज किया गया है सक्रिय हो जायेगा. साथ ही यह भी सलाह दी कि क्यों न आप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिल आयें. रामसिंह को इंदिरा जी से मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी. "मैं पहले भी इंदिरा जी और राजीव जी से मिला हूँ."

10 मिनट बाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव का फोन आया और इंदिराजी से मिलने का समय तय हुआ. इस बीच भजनलाल स्वयं दिल्ली आ पहुँचे. उनके साथ थे हरयाणा के भूतपूर्व गृहमंत्री पोसवाल. जब रामसिंह के कमरे से ये दोनों व्यक्ति बाहर निकल आये तो उनकी मुठभेड़ हुई लोकदल के नेता देवीलाल से. देवीलाल ने कहा कि मैं बंसीलाल को जेल भिजवा चुका हूँ. अब आप की बारी है. भूतपूर्व गृहमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो उनका गिरिबान पकड़ कर देवीलाल ने उन्हें धक्का दे कर अलग कर दिया.

जनता पार्टी के विधायक अजमत खान की हालत भी दयनीय है. वह थे तो देवीलाल के साथ मगर बीच में इका की बैठक में भी शामिल हो गये. मंगलवार को हरयाणा भवन में उन्हें देवीलाल और सुषमा स्वराज अपनी कार में बिठा कर ले गये. हरयाणा की राजनीति के नाटकीय मोड़ उसे कहाँ तक ले जायेंगे इस का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है. शनिवार को लोकदल ने राज्य भर में राज्यपाल के कथित अन्याय का विरोध करने के लिए आंदोलन चलाने की घोषणा की है.

उत्तरप्रदेश में अगर असंतोष और विद्रोह सतह पर नहीं आया है तो केवल इस लिए कि धुबीकरण के लिए कोई स्पष्ट ध्रुव राज्य में उभर कर नहीं आया था. तथ्य है कि आज न सही कुछ समय बाद अपने किले को मजबूत करने के लिए इंदिरा कांग्रेस को काफी कुछ फेरबदल और मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि किसी भी कमजोर स्थल का फायदा विद्रोही उठा सकते हैं. हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में विद्रोही इका सदस्यों और प्रत्याशियों के सामने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व की हार इस स्थिति को और गंभीर बनाती है.

हाल ही के चुनावों में एक और बात महत्वपूर्ण दिखायी देती है. पूरे देश के नक्शे पर नज़र डालने पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा क्षेत्रीय और स्थानीय दल ज्यादा सफल रहे हैं. पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों का जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. डायमंड हारवर लोकसभा उपचुनाव में जीत का अनुमान भी पहले से ही था. केरल क्षेत्रीय दलों का रंगमंच बन गया है और इस में इका स्वयं भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में ही काम कर रही है. उत्तर के दो राज्यों में भी यही प्रवृत्ति दिखायी देती है. हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और हरयाणा में लोकदल का उभर कर आना इस का प्रमाण है. 1985 तक क्या इन में से कोई दल राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए गंभीर चुनौती दे सकता है? मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के थाणे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सफलता इस बात की ओर इशारा करती है कि समय मिलने पर यह दल उत्तर और मध्य-भारत के प्रायः सभी राज्यों में इका के लिए गंभीर चुनौती दे सकता है. थाणे में जगन्नाथ पाटील ने इका प्रत्याशी के साथ ही प्रसिद्ध मजदूर नेता डॉ. दत्ता सामंत को भी हराया. और फिर इस बात का कोई आश्वासन नहीं कि 1985 में एक से अधिक दल मिल कर श्रीमती गांधी के लिए खतरा पंदा न करें. इस लिए राजनैतिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा हो रही है कि श्रीमती गांधी इन क्षेत्रीय रूप से शक्तिशाली दलों को राष्ट्रीय दल बनने का मौका नहीं दे सकतीं. समय उन के पक्ष में नहीं है. विपक्षी दलों के पक्ष में है. यह समय यदि उन्हें मिला तो 1985 में सत्तासंघर्ष बहुत कड़ा होगा. ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर सकती हैं?

पाँच साल की मोहलत के लिए यह नुस्खा आजमाया जा सकता है. मगर इस के लिए ज़रूरी होगा कि श्रीमती गांधी कुछ ऐसा करें कि लोगों का ध्यान किसी ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्रित हो जाये जिस का लाभ उन्हें मिले. □

पिनयान

5 जून '84



# तपासे की कृपा से

इंवरजीत, संपादक, इन्फा

हरयाणा के राज्यपाल तपासे ने सैद्धांतिक निष्ठा का दामन छोड़ कर शांतिपूर्ण लघु आम चुनावों पर पूरे देश में फैले संतोष पर पानी फेर दिया है। उनकी कार्रवाई से लोकतंत्र को और स्वस्थ परंपराओं को एक बार फिर धक्का लगा है। अत्यधिक दोषदर्शियों के जो अंदेश थे वे भी सब मात खा गये हरयाणा की हालत के सामने। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते लिखा था ज्यादातर लोगों का अंदाज यह था कि कई नये विधायक राजनैतिक वेश्यावृत्ति करने लगेंगे और बेशर्मी से खुद को बेचेंगे। कहा जाता है कि इका और लोकदल दोनों की थैलियाँ खुलने को तैयार थीं। कहा जाता है कि भजनलाल ने श्रीमती गांधी से कहा था —“चाहे जो जितनी सीटें जीते, हरयाणा में सरकार हमारी बनेगी।” बहरहाल, यह तो किसी को कल्पना भी नहीं थी कि राज्य के राज्यपाल गनपत दामोदर तपासे ही वस्तुतः ‘दलबदल’ कर डालेंगे।

जनता शासन के दौरान नियुक्त राज्यपाल तपासे से कम से कम यह उम्मीद थी कि वह निष्पक्ष रहेंगे, पर उन्होंने तो ऐसा व्यवहार किया मानों वह स्वयं इका के आदमी हों।

हरयाणा के राज्यपाल के विस्मयकारी व्यवहार को शनिवार के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में देखना होगा। उस दिन लोकदल नेता देवीलाल तपासे से मिले और नयी सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। तपासे ने देवीलाल से कहा कि वह सोमवार, 24 मई को सुबह 10 बजे राजमवन में अपने समर्थकों की ‘परेड’ करा कर अपना बहुमत सिद्ध करें। तब देवीलाल अपने अधिकांश समर्थकों को समीपस्थ परवानू में ले गये, जो कि हिमाचल-प्रदेश में स्थित है, ताकि ‘राजनैतिक डाकेजनी’ से बचाव कर सकें। उन्होंने उन्हें सशस्त्र निहों के पहरे में भी रखा। लेकिन उन्हें उस नाटक का कुछ पता नहीं था जो चंडीगढ़ में खेला जा रहा था। साढ़े चार बजे शाम भजनलाल ने राज्यपाल से मेट की। दो घंटे बाद हड़बडी में संपन्न उस समारोह में उन्हें मुख्यमंत्री ‘द’ की शपथ दिला दी गयी जिस में स्वयं भजनलाल के अनेक रिश्तेदार तक नहीं शामिल हो पाये।

भजनलाल को ‘सबसे बड़े दल के नेता’ के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। तपासे के अनुसार भजनलाल ने उन्हें ‘42 या 44 विधायकों’ की सूची दी। जब पत्रकारों



राज्यपाल श्री तपासे और भजनलाल : आनन फानन में शपथग्रहण

ने पूछा कि क्या विधानसभा में बहुमत होना जरूरी नहीं है तो तपासे ने कहा कि भजनलाल को सब से बड़े दल के नेता होने के नाते, सरकार बनाने का हक है। आगे भजनलाल से कहा गया है कि वह एक महीने के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करें। कुछ पत्रकारों ने तपासे को याद दिलाया कि आपने देवीलाल से सोमवार को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने को कहा है और निश्चय ही एक दिन और इंतजार किया जा सकता था। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या भजनलाल से भी उसी तरह से अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा गया था? लेकिन तपासे सिर्फ यही दुहराते रहे कि भजनलाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे।

स्वभावतः प्रतिपक्ष के लिए ये घटनाएँ आकस्मिक और अनपेक्षित थीं। लोकदल अध्यक्ष चरणसिंह ने कहा, ‘यह एक सर्वाधिक संवैधानिक तोड़ मरोड़ वाला कदम है, जो प्रधानमंत्री के आवेश पर उठाया गया नज़र आता है। यदि प्रधानमंत्री और राज्यपाल क़ानून का पालन नहीं करते तो फिर लोगों द्वारा गैर-संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल अनुचित नहीं होगा।’

भाजपा के महासचिव लालकृष्ण आडवाणी ने हरयाणा के राज्यपाल के इस्तीफ़े की माँग की है, जिन्होंने, उनके अनुसार, ‘अपने आचरण से राज्यपाल के पद और संस्था की गरिमा को लॉछित और लज्जित किया है। यह समझना मुश्किल है कि रातों रात क्या हो गया, जिसमें राज्यपाल ने मन बदला और भजनलाल को शपथ दिला दी। स्वभावतः तपासे ने नयी दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी हो कर

व्यवहार किया है।’

जगजीवनराम ने तपासे के कदम को ‘लोकतंत्र की मौत की घंटी’ कहा है। उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया है कि राज्यपाल ने “केंद्रीय सरकार के दबाव के अधीन निर्लज्जतापूर्ण आचरण किया।” जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि “इका हरयाणा और हिमाचलप्रदेश दोनों जगह हार गयी है और वहाँ प्रतिपक्ष को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए था।” भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने कहा है कि तपासे का निर्णय “कांग्रेस (इं) के प्रति स्पष्ट पक्षपात का मामला है।” मार्क्सवादी नेता पी. राममूर्ति ने कहा है कि राज्यपाल ने “लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हास्यास्पद बना डाला है।” गढ़वाल से जीत कर आये हेमवती-नंदन बहुगुणा ने कहा है कि “यह फँसला संसदीय लोकतंत्र की जड़ों पर ही कुठाराघात है।”

जैसी कि आशा थी। कांग्रेस (इं) आला कमान ने तपासे के कदम का बचाव किया है और इसे दो आधारों पर उचित ठहराया है —संवैधानिक और स्थापित परंपराओं के आधार पर। उनका पहला तर्क है कि संविधान राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 164 में कोई अस्पष्टता या अनेकार्थकता नहीं है। उसमें कहा गया है, “मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा।” आगे, राज्यपाल को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाते वक्त विवेक के प्रयोग की अनुमति है। विवेक परम अधिकार संपन्न है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

कांग्रेस (इं) नेताओं का दूसरा तर्क यह





कदम को है। उन्होंने राज्यपाल ने निर्लेज्जता के अध्यक्ष हरयाणा और यूपी है और का अवसर कम्पुनिष्ठ ने कहा है (इं) के प्रति मार्क्सवादी राज्यपाल ने यास्पद बना पाये हेमवती- 'यह फैसला' पर ही

(इं) आला व किया है ठहराया है रंपराओं के कि संविधान है कि वह र सकता है या अनेक- 'मुख्यमंत्री' आगे, राज्य- न्ममेवारिया अनमति है और उते

तर्क यह 5 जून '84

है कि पहले भी राज्यपालों ने ऐसे कदम उठाये हैं और सबसे बड़े दल के नेता को निर्मंत्रित करने की सुस्थापित परंपरा है। हाल ही में असम में ऐसा किया गया। वे चरणसिंह के मामले को भी उद्धृत करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने 'ऐसी ही परिस्थितियों' में 1979 की वर्षा ऋतु में सरकार बनाने को निर्मंत्रित किया था।

यह तथ्य निर्विवाद है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कुछ संविधान विशेषज्ञ तो यहाँ तक तर्क करते हैं कि सिद्धांततः राज्यपाल अपने किसी 'चहेते' को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसे मर्यादित करने वाले दो तत्त्व हैं: पहला, उस 'चहेते' को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए और उसे वह बहुमत सिद्ध भी करना होगा। दूसरे, ऐसा करते वक्त राज्यपाल को यह ध्यान रखना होगा कि उसे न सिर्फ न्याययुक्त और सही होना चाहिए, बल्कि न्याययुक्त और सही दिखना भी चाहिए। इन स्वस्थ परंपराओं को पिछले वर्षों में स्थापित अनेक अनुचित और अशोभन घटनाओं से अलग होना चाहिए। असम का उदाहरण एक ऐसा ही अशोभन उदाहरण है। दो गलतियाँ मिल कर एक सही नहीं बन जातीं।

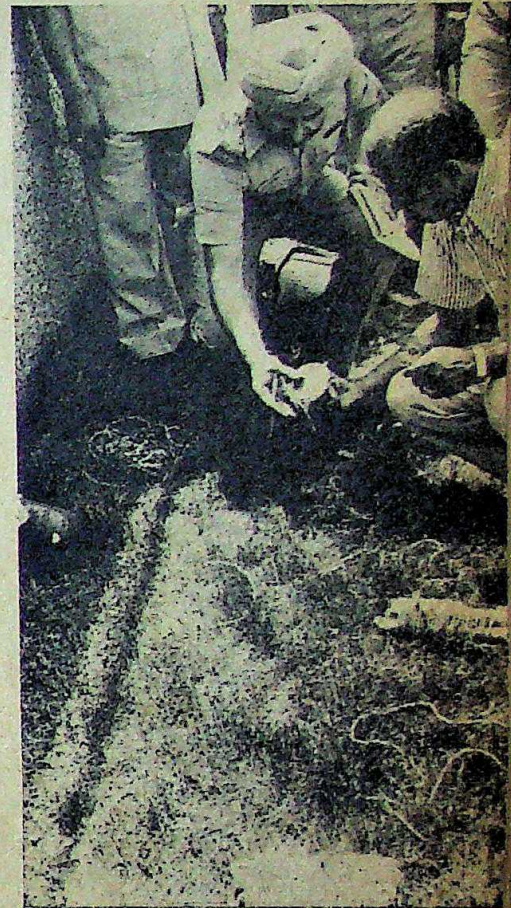
सामान्यतः सब से बड़े अकेले दल के नेता को हक है कि उसे सरकार बनाने बुलाया जाये। लेकिन यह सूत्र उस वक्त नहीं लागू हो सकता जब राज्य में दो या दो से ज्यादा दलों में चुनाव-पूर्व गठबंधन हो और इस संयुक्त मोर्चे को किसी एक अकेले दल से ज्यादा सीटें प्राप्त हो जायें। हरयाणा के चुनाव में लोकदल और भाजपा में स्पष्टतः चुनाव से पहले ऐसा गठबंधन हो गया था। विजय की स्थिति में संयुक्त सरकार बनाने का भी उनका इरादा घोषित था। लोकदल-भाजपा संयुक्त मोर्चे के मान्य नेता के रूप में देवीलाल को स्पष्टतः यह अधिकार था कि उन्हें पहले सरकार बनाने बुलाया जाये। जब देवीलाल स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत करने में अथवा भजन लाल द्वारा प्रस्तुत '42 या 44' से ज्यादा विधायक प्रस्तुत करने में विफल रहते तभी तपासे द्वारा कांग्रेस (इं) को सरकार बनाने का न्योता देना न्यायपूर्ण होता।

तपासे द्वारा दुहरे मानदंड अपनाये जाने से तथा खुले पक्षपातपूर्ण जैसा कदम उठाये जाने से हालत बदतर हो गयी है। तपासे ने देवीलाल के बहुमत के दावे को नामंजूर कर दिया— यहाँ तक कि भाजपा नेता डॉ. मंगलसेन ने और जगजीवनराम कांग्रेस ने पूरी औपचारिकता के साथ उन्हें सूचित किया था कि वे लोकदल को समर्थन देंगे। इस पर भी तपासे ने देवीलाल से कहा कि अपने विधायकों की राजभवन में परेड करायें। इस के बिल्कुल

विपरीत तपासे ने भजनलाल के दावे को सीधे फौरन मंजूर कर लिया— बिना किसी छानबीन के। आगे भजनलाल को अपूर्व जलदबाजी में शपथ दिलायी गयी और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पूरा एक महीना दे दिया गया। अगर तपासे ने सोमवार तक इंतजार किया होता और शीर्षस्थ संवैधानिक अधिकारियों से सलाह कर ली होती तो न तो घस्ती फट जाती न ही आसमान गिर पड़ता।

हमारे संघीय राजतंत्र में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेहरू स्पष्टतः इस मत के थे कि राज्यपाल कोई राजनैतिक नियुक्ति वाला व्यक्ति नहीं है और उस से निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ आचरण की आशा की जानी चाहिए। राज्यपालों को राज्य सरकारों की पूरी सहमति से नियुक्त किया जाता था और उन्हें केंद्र का एजेंट नहीं माना जाता था; यहाँ तक कि जब नेहरू कांग्रेसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाते थे तब भी वह उस से यही अपेक्षा रखते थे कि वह दल से ऊपर उठ कर काम करे। 31 मई, 1949 को उन्होंने संविधान सभा के समक्ष कहा था कि "राज्यपाल प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए और लोगों के सामने दल के दायरे से कुछ ऊपर उठे व्यक्ति की तरह उन्हें पेश आना चाहिए, जिससे कि वे सरकार की उससे कहीं ज्यादा मदद कर सकें जितनी वे पार्टीतंत्र का हिस्सा बन कर कर सकते हैं। ऐसा होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया भली भाँति चल सकेगी।"

क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? संसदीय लोकतंत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जैसा कि नेहरू के आचरण से स्पष्ट है। तो भी, सामान्य छवि के विपरीत, राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथपूर्वक स्वीकृत जिम्मेदारी में कुछ अलिखित शक्तियाँ अंतर्निहित हैं, जिन का तकाजा है कि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ "संविधान को कायम रखने, सुरक्षित रखने तथा बचाने के लिए" काम करें। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार वे हरयाणा घोटाले की जाँच कर सकते हैं और केंद्र को समुचित कार्य-वाई की सलाह दे सकते हैं। इस में कोई रुकावट नहीं है। राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने स्वस्थ परंपराओं की स्थापना के प्रयास के अंग के रूप में ही, उनकी पूर्वानुमति के बगैर, किसी राज्यपाल द्वारा अपनी राजधानी छोड़ने की मुमानियत कर दी है। हरयाणा के दुखद घटना-चक्र में इस से कहीं ज्यादा चीजें शामिल हैं। संसदीय लोकतंत्र जितना संविधान पर आधारित है उतना ही परंपराओं और व्यवहार पर नेहरू, पटेल और अन्य लोगों ने भारत की लोकतांत्रिक इमारत को एक एक ईंट रखते हुए खड़ा किया। हमें उसे अविवेकपूर्ण ढंग से नष्ट नहीं करना चाहिए। □



वैज्ञानिक डॉ. बी. मोइत्रा (दायें) और थानाध्यक्ष खुशवंतसिंह बेदी बम का निरीक्षण करते हुए

दिल्ली

पालिका बाजार में

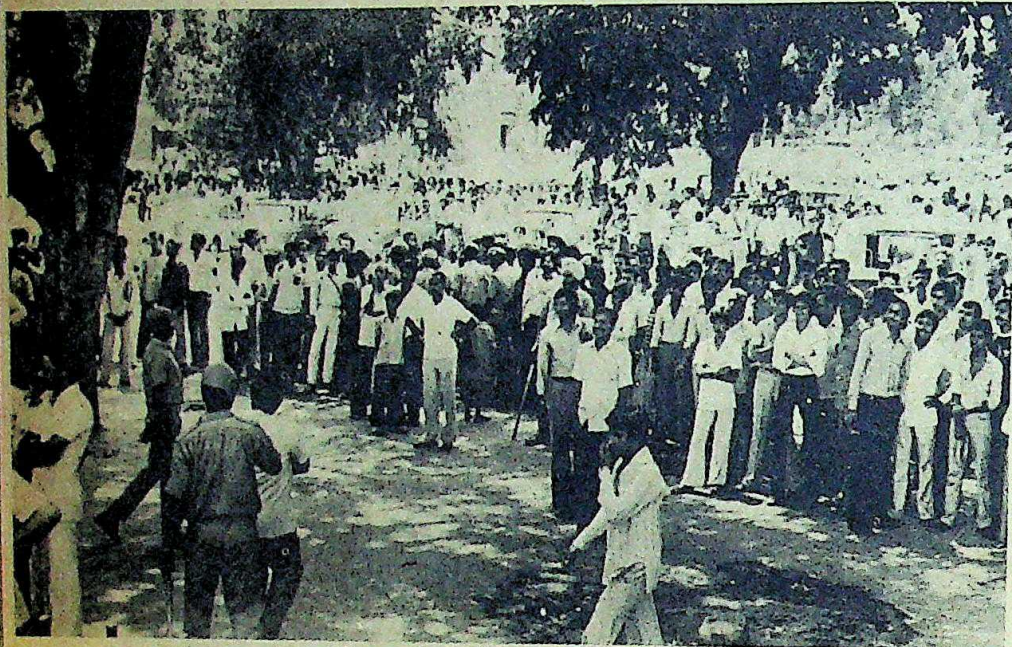
टाइम बम

जितने मुँह उतनी बातें

दिल्ली की तपती दुपहरी में 25 मई को बारह बजे कर 20 मिनट पर जब भूमिगत वातानुकूलित पालिका बाजार में एलान किया गया कि पाँच मिनट में बाजार खाली कर दो क्योंकि ऊपर 'बहुत खतरा' है तो बाजार की खरीद-फरोख्त की गहमागहमी भय और भगदड़ में बदल गयी। दुकानदारों ने तुरंत दुकानों के शटर गिरा दिये। स्त्री-पुरुष-बच्चे निकास द्वारों की ओर भागे। ऐसी भगदड़ कि अगर कहीं उस समय बत्ती न होती तो यह कुतुबमीनार से भी गंभीर हादसा हो सकता था। लगभग 400 दुकानों के लोगों और खरीददारों की भीड़ ही पालिका बाजार के बाहर इकट्ठी नहीं थी बल्कि ऐसा लगा था कि सारा कनाट प्लेस वहाँ जुड़ गया है। इतनी भीड़ को नियंत्रित कर यातायात की व्यवस्था को नियमित रखना आसान काम नहीं था। लेकिन पुलिस आयुक्त

दिनमान





पालिका बाजार के बाहर जमा उत्सुक भीड़

वज्ररंगलाल, अतिरिक्त आयुक्त निखिल कुमार, उपायुक्त (यातायात) किरण वेदी के अलावा अग्नि शमन सेवा के अधिकारियों ने स्थिति को बेकाबू होने से बचा लिया। लगभग डेढ़ बजे जब केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के दल के मुखिया डॉ. बी. मोइत्रा ने बमों से जुड़े तारों और घड़ी को अलग किया, तो खतरा टला। लेकिन वहाँ जमा भीड़ को यकीन नहीं हो पा रहा था। कुछ कड़े दिल के लोगों ने वातानुकूलित संयंत्र को देखने का भी साहस बटोरा, जहाँ से वे टाइम बम प्राप्त हुए थे। इन बमों की 28 छड़ों को ले कर पुलिस अधिकारी तो चले गये, लेकिन लोगों का मजमा वहाँ शाम तक रहा।

हुआ यों कि पालिका बाजार की छत पर एक माली जब काम कर रहा था तो उसे वातानुकूलित संयंत्र से टिक टिक की आवाज सुनायी दी। उसने तुरंत अपने अधिकारी को इस की सूचना दी। यह घटना सुबह साढ़े ग्यारह बजे की है। आननफानन में खबर पुलिस कंट्रोल रूम पहुँची और सवा बारह बजे कनाट प्लेस के थानाध्यक्ष खुशवंतसिंह वेदी अपने दलबल सहित पालिका बाजार पहुँच गये।

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने वातानुकूल संयंत्र के करीब से चार पोटलियों में लिपटे बमों को निकाला। खाकी रंग के कपड़े में बंधे बारह इंच लंबे बम की ये छड़ें तारों से जुड़ी थीं और इन तारों के साथ एक टाइम पीस लगी हुई थी। सब से पहले इन पोटलियों को निकाल कर ध्वस्त किया गया। घड़ी का मुआइना करने पर पता चला कि विस्फोट का समय तीन बजे था। लेकिन पुलिस के अतिरिक्त

आयुक्त निखिलकुमार के अनुसार क्यों कि घड़ी का समय साढ़े तीन घंटे आगे था लिहाजा विस्फोट का समय ग्यारह बजे रात के करीब बैठता है। निखिलकुमार के अनुसार यदि विस्फोट हो जाता तो सारा वातानुकूल संयंत्र नष्ट हो सकता था। वातानुकूल संयंत्र में 25 से 30 हजार लिटर पानी जमा रहता है। उस के ध्वस्त होने से पालिका बाजार के अलावा सारे कनाट प्लेस की मुख्य सड़कें भर जातीं।

श्री वज्ररंगलाल के अनुसार बम की छड़ों से लिपटे जो तीन पुर्जे मिले हैं उन में से एक पर 'पी एल ए' लिखा है; यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, (जनमुक्ति सेना) जो मणिपुर में अपना जेहाद जारी रखे हैं। दूसरे पर लिखा था: 'हम न्याय चाहते हैं,' तो तीसरे पर 'पी एल ए' और 'तारे' का निशान था। यद्यपि इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया तथापि उस के पोस्टर आज भी दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों तथा उन के आसपास के होस्टलों की दीवारों पर चिपके दिखायी देते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में ही इसी गिरौह के एक नेता विजय सिंह को पकड़ा भी गया। अपने साथी की गिरफ्तारी के बाद लगता है इस दल के लोग अधिक सक्रिय हुए हैं। निखिलकुमार के अनुसार ये बम 'गोमिया' निमित्त हैं, जो बिहार में है।

कनाट प्लेस के थानाध्यक्ष वेदी के अनुसार पालिका बाजार तब खलाखच भरा हुआ था। उसे खाली कराना आसान काम नहीं था। लेकिन बम का नाम सुन कर लोगों के होश फाक्ता हो गये। कुछ ने अलबत्ता हँसी में बात उड़ायी। विनमान को कुछ लोगों ने बताया

कि अगर वक्त पर सूचना न मिलती तो कुली मीनार से भी भयानक हादसा हो सकता था। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर आये। लेकिन कुछ दुकानें खुली थीं। बहुत से दुकानदार तो जैसी भी हालत में थे भाग कर बाहर गये। लेकिन चार से पाँच बजे के बीच वे बात से चिंतित थे कि न जाने उनकी दुकान का क्या होगा।

यद्यपि अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है तथापि जनमुक्ति सेना से सहानुभूति रखने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विजयसिंह की गिरफ्तारी के बावजूद जिस प्रकार उनकी गतिविधियों का प्रसार राजधानी में हो रहा है वह अब गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पालिका बाजार के बाहर जमा भीड़ में से ही कुछ लोग कह रहे थे, कहीं यह अफ्रीकी या ईरानी अतिवादी का काम तो नहीं? जिस समय बम फटने का समय निश्चित था लगभग उसी समय नौराट राष्ट्रपति हमीर द राँवर्ट कनाट प्लेस से हो कर राष्ट्रपति भवन पहुँचने वाले थे। बम की खबर पा कर उनका रास्ता बदल दिया गया।

लेकिन अटकलें यहीं खत्म नहीं होतीं। जितने मुँह उतनी बातें। कई लोग यह कह रहे हैं पाये गये कि आखिर डायनामाइट की छड़ों को रखने वाले की मंशा क्या थी। छड़ों के नीचे जिसने पत्र रखे थे क्या वह नहीं जानता था कि यदि विस्फोट होगा तो पत्र सब से पहले नष्ट हो जायेंगे। इस से साफ़ जाहिर होता है कि उद्देश्य विस्फोट नहीं पत्रों को प्रचारित करना था। लोग यह भी सोचते हैं कि यदि पत्रों को प्रचारित करना ही उद्देश्य था तो 28 छड़ें क्यों रखी गयीं? यह उद्देश्य तो चार पाँच छड़ रखने से भी पूरा हो सकता था। इतनी इफरात में छड़ें नष्ट करने के लिए 'पी एल ए' को प्राप्त हो जायें यह भी समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 'पी एल ए' को बदनाम करने वाली ताकतों ने ही बम का नाटक रचा हो, क्यों कि कोई क्रांतिकारी संस्था ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जिस से जनता का और सार्वजनिक ठिकानों का विनाश होता हो। इस से तो जनमत उन के खिलाफ हो जायेगा। जनमत की चिंता तो किसी भी क्रांतिकारी दल को पहले होती है। यदि ध्यान आकर्षण करना ही उनका उद्देश्य था तो वे सरकारी ठिकाने चुनते और वहाँ पर नाटक भी कर सकते थे और उसे वास्तविकता में भी बदल सकते थे। सार्वजनिक जगह पर इस तरह से ऐसा नाटक 'पी एल ए' संगठन ने किया होगा। यह बहुतों की समझ में नहीं आ रहा है। शायद पुलिस की समझ में आये और विध्वंसकारी तत्वों का सही पता चले।



भराफात की आमद

## ‘भारत-पाक संबंधों में सुधार की आशा करता हूँ’

दो दिन की भारत यात्रा के बाद फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासिर अराफात 23 मई को दिल्ली से एक विशेष विमान द्वारा पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। दो दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भारत-फिलिस्तीनी तथा एशिया विशेषकर पश्चिमेशिया के देशों के पारस्परिक संबंधों, समस्याओं के बारे में बातचीत की। अनुमान था कि पाकिस्तान के नेताओं से भी क्षेत्रीय संबंधों और समस्याओं के विषय में उनकी बातचीत होगी। विदाई पूर्व एक संवाददाता सम्मेलन में फिलिस्तीन के महान् नेता ने स्पष्ट किया कि वह इस यात्रा में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ की भूमिका निभाने नहीं आये, मगर उन की इच्छा है और आशा है कि दोनों देशों के संबंधों में शीघ्र और उचित सुधार हो।

जान पड़ा कि प्रधानमंत्री ने भारत की विदेशनीति की आज के दृष्टि चित्रों की व्याख्या उनके सामने रखी और अराफात साहब पाकिस्तान से संबंध सुधार के विषय में भारत के दृष्टिकोण और सद्भावना से बहुत संतुष्ट गये।

दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान जहाँ फिलिस्तीनी नेता ने भारतीय नेताओं से महत्वपूर्ण बातचीत की वहीं दिल्ली में उपस्थित अरब देशों के राजदूतों से भी बातचीत की। उन्होंने **विट्ठलभाई पटेल भवन** तथा **जामिया मिलिया इस्लामिया** में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक समारोहों में फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के बारे में मुक्तकंठ से कहा : “विजय हमारी होगी।”

अपने खुले बयानों और निजी बातचीत के दौरान अराफात साहब ने बहुत से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर निगाह दौड़ाते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया।

**मिस्र-इस्राइल समझौता** : उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हाल ही में जो समझौता मिस्र और इस्राइल के बीच सिनाइ को ले कर हुआ है वह फिलिस्तीनी लोगों को अमान्य है। उनका कहना है कि यह समझौता केवल मिस्र और इस्राइल ने आपस में ही कर लिया है और बस एक ही तीसरा देश उस से संबंधित है—मानी अमेरिका। “हमने यह सब कुछ शुरू से ही स्वीकार नहीं किया और न करेंगे।”

जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका में प्रवल विनयान



यासिर अराफात: ‘पूरा इस्राइल स्वयं अमेरिकी लॉबी है’

इस्राइली लॉबी के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है तो वह हँस कर बोले, “ऐसा नहीं। इस्राइली लॉबी अमेरिका में नहीं, पूरा इस्राइल स्वयं एक अमेरिकी लॉबी है। उनकी रोटी, सब्जी, खाने, पीने, पहनने का सामान, टैंक, तोपें, विमान, सभी तो अमेरिका से आते हैं। वास्तव में इस्राइल अमेरिका का बिगड़ा हुआ और शैतान बच्चा है। अमेरिकी चाहें तो उसे तमोज से व्यवहार करने पर किसी भी समय अवश्य विवश कर सकते हैं।”

ईरान-इराक के जिस युद्ध से अरब तथा एशिया के गुटनिरपेक्ष देश बहुत चिंतित हैं, वह अराफात साहब के विचार में शीघ्र समाप्त होना चाहिए। उन्हें यह भी आशा है कि इस युद्ध को समाप्त करने के जो प्रयास किये जा रहे हैं (जिन में वह स्वयं और भारत के नेता भी जुटे हैं) अवश्य सफल होंगे। शायद सितंबर में बगदाद में होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन से पहले ही कुछ युद्धविराम के रास्ते निकल आयें। फिलिस्तीनी नेता को इस युद्ध में भी अमेरिका की परछाइयाँ दिखायी दीं। उनका कहना था कि इस युद्ध से किस को लाभ है? न ईरान को है न इराक को। दोनों को हानि है और इस क्षेत्र के अन्य देशों को भी। जितनी शीघ्र यह समाप्त हो जाये उसी में सब का भला है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इशारा किया था कि हिंदमहासागर, भूमध्यसागर, लालसागर और अब सिनाइ में भी अमेरिकी उपस्थिति विस्तृत हो गयी है।

**उन्हें पूछिए** : फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए भारतीय जनता, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गहरी सहानुभूति और सहायता के प्रति उन्होंने

फिलिस्तीनी जनता और अपनी ओर से सराहना की। जब एक पत्रकार ने पूछा कि सहायता के रूप में वह हथियार तो नहीं प्राप्त करेंगे तो वह मुस्कुराये, “भई, यह तो उनसे (भारतीय नेताओं से) पूछिए”।

मगर पश्चिमी एशिया में युद्ध तथा तनाव की वृत्तियों को हवा देने के लिए अराफात ने अमेरिका की कड़ी नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपना जाना पहचाना मत दोहराया, “पश्चिम एशिया में स्थिति का सुधार तभी हो सकता है और विवाद पूरी तरह तभी सुलझाये जा सकते हैं जब इस्राइल की सेनाएँ बिना किसी शर्त के अरबों, फिलिस्तीनियों और यरूशलम की वह घरती तुरंत खाली कर दें जिस पर उन्होंने जबर्दस्ती कब्जा किया हुआ है। इस बात का उल्लेख तो भारत और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेताओं द्वारा जारी किये गये संयुक्त घोषणापत्र में भी था। उस में इराक तथा ईरान से अपने मतमेंदों को शीघ्र और शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने का अनुरोध प्रकट किया गया था तथा फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इस्राइल के अनंत आक्रमण, दक्षिणी लेबनान द्वारा बाहर से प्राप्त हुए नये हथियारों के जोर पर इस्राइली हमले के खतरे पर गहरी चिंता प्रकट की गयी थी।

**‘तबन्सुम और तमंचा’** : दिल्ली में निजी रूप से या सार्वजनिक सभाओं में जिस भी नर नारी को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता से नज़दीकी भेंट या दूर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दो बातों से प्रभावित हुए बिना न रहा। जैसे एक साहब ने फरेमाया, “उन का तबन्सुम और उनका तमंचा” वह क्रान्तिकारी जिसके नाम से संसार के बहुत से



नेता धरति हैं, बात पर एक मासूम बच्चे की सी मधु मुस्कान बरसाने लगता है। मगर उस की पिस्तौल भी हर समय उस की कमर से एक पेटो से लटकी रहती है। चाहे वह किसी सरकारी बातचीत में प्रधानमंत्रियों, राष्ट्र-पतियों तथा नरेशों के आमने सामने बैठे हों, चाहे मित्रों के साथ साधारण भोजन खा रहे हों या किसी सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे हों 'तमंचा सदा साथ रहता है'।

दिल्ली में हर जगह मुस्कान और पिस्तौल दोनों ही दिखाई दिये। एक साहब का विचार था कि अराफात गांधी, नेहरू और भगतसिंह तीनों के कुछ कुछ गुण अपने व्यक्तित्व में समोये हैं। शायद ये दोनों बातें उस विचित्र व्यक्तित्व का प्रतीक हैं जो घोर संघर्ष की ज्वालाओं से तप कर क्रांतिकारी से विश्व राजनीति का एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बनता जा रहा है। उसके निजी जीवन पर सदा एक रहस्य का पर्दा पड़ा रहा है। शायद उसका सार्वजनिक जीवन ही उसका निजी जीवन बन गया है। उसके जन्म के बारे में भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। कब हुआ। अनुमान है कि 1930 में हुआ। उनके समेत उनके परिवार में चार भाई और दो बहनें थीं। बचपन से ही वह छापामार युद्ध का प्रशिक्षण ले कर गाजा पट्टी में अपने पिता, भाइयों, बहनों तथा अन्य फिलिस्तीनी मुजाहदीन के साथ कंधे से कंधा मिला कर सशस्त्र संघर्ष में जुटा रहा। 1948 के अरब-इस्राइली युद्ध में उसने सक्रिय भाग लिया। एक सैनिक बन कर अपनी धरती की रक्षा के लिए। उसके पूर्वज हज्र अमीन उल हुसैनी यरुशलम के महा मुफ्ती थे तथा अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत के सालारों में से एक। अराफात ने अपने नाम से अपने बुजुर्गों का नाम शायद इस लिए अटा दिया कि बाद में अल फतह नाम की मुक्तिवाहिनी की स्थापना और फिर सभी फिलिस्तीनी क्रांतिकारियों को एक लड़ी में पिरो कर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की रचना में सहायता मिले। एक पत्रकार ने शायद ठीक ही कहा है कि अब वह एक ऐसा राष्ट्रनायक है जो अपने राष्ट्र की खोज में है। अराफात की विश्वास है कि एक दिन फिलिस्तीनी राष्ट्र अवश्य बनेगा। जब यह हुआ तो राष्ट्रनायक की राष्ट्र की खोज सफल हो जायेगी और पश्चिम के इतिहास का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होगा। जब तक संसार भर में मित्रों और शत्रुओं की निगाहें अराफात पर जमी रहेंगी। पश्चिम एशिया, अरब संसार तथा एशिया और विश्व के अन्य बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के भविष्य की अज्ञाताएँ भी अराफात के भविष्य से कई स्थानों पर जुड़ी हैं। क्या वह एक नये नेहरू, टीटो या नासिर की भूमिका निमायेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य ही देगा।

जिनमान

## तिकोना पुस्तक युद्ध

# किताब जिस पर भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान के प्रकाशकों के बीच खींचतान मची है

प्रसिद्ध लेखक जोड़ी-अमेरिकी लैरी कॉलिस और फ्रांसीसी डोमानी लापियर की भारत में प्रकाशित पुस्तक, 'माउंटबेटन एंड द पारटीशन ऑफ इंडिया' के कारण एक तिकोना पुस्तक युद्ध आरंभ हो गया है, जिस में भारतीय प्रकाशक 'विकास', ब्रितानी प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता 'गारलैंडफोल्ड' और पाकिस्तान के पुस्तक समीक्षक और वितरण अधिकारी उल्लख पड़े हैं।

मामला 4 मई को एक समाचार एजेंसी द्वारा प्रसारित समाचार से शुरू हुआ। इस समाचार में यह कहा गया था कि पाकिस्तानी अधिकारियों को इस पुस्तक में छपे कुछ अंशों पर सख्त आपत्ति है। उन्होंने माँग की है कि संबंधित अधिकारी इस पुस्तक के वितरण पर रोक लगा दें; कारण यह कि इसमें पाकिस्तान के जन्मदाता कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना के बारे में अपमानजनक उल्लेख है। यह उल्लेख पृष्ठ 47 पर पुस्तक के उस भाग में है, जहाँ लेखक जोड़ी ने स्वर्गीय लॉर्ड माउंटबेटन से 1971, 1972 और 1973 में देश के बँटवारे के विषय में 22 मार्च से लेकर 15 अगस्त, 1947 के बीच हुई घटनाओं के बारे में बीस लंबी मुलाकातों की और माउंटबेटन की ही जुबानी उनका जिक्र किया।

एक प्रश्न के उत्तर में लॉर्ड माउंटबेटन ने कॉलिस और लापियर को बताया कि उन्होंने 'इस्मे' को बँटवारे संबंधी प्रबंध की रूपरेखा तैयार करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी। "उन्होंने मुख्य कामकाज का एक नोट बनाया था। भगवान जाने 30, 40 या 50 प्रमुख काम थे। इन कागजात में बँटवारे तथा सत्ता परिवर्तन के परिणाम की झाँकी थी। जिन्ना साहब भी हिल गये थे एक बार। उन्होंने तथा अन्य भारतीय नेताओं ने यह सब कुछ पसंद नहीं किया, क्योंकि वे समझते थे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। सारा मामला एक नाटक की तरह सेमाला गया और यदि मैं नाटक का सूत्रधार स्वयं नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने एक और काम किया, जिसे भारतीय नफरत की दृष्टि से देखते हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जैसी मेरी मित्र भी। मैंने एक कैलेंडर बनवाया, जिस से प्रतिदिन पता चलता था कि अब सत्ता परिवर्तन में कितने दिन शेष रह गये हैं। मैं उन सब पर इस लिए दबाव बनाये हुए था कि ऐसा न करता तो सारा मामला चौपट हो जाता और बँटवारे की योजना मेरे

पाँव तले ही बम की तरह फट जाती।"

इस के बाद आते हैं माउंटबेटन के वे वाक्य जिन पर पाकिस्तानियों को सख्त आपत्ति है। पढ़ें तो समझ आती है कुछ कि आपत्ति क्यों है। माउंटबेटन फरमाते हैं, "मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि जिन्ना जैसा वास्ट (हरामी) था वैसा ही नजर आया। सच मानो वह ऐसा ही था। मेरी उससे इस लिए निग्रज जाती थी कि मेरी किसी से भी पट जाती है। उसने स्वयं रत्ती भर कोशिश नहीं की थी।"

और भी कुछ बातें हैं इस पुस्तक में जिन्ना के बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन के शब्दों में, इन में चाहे ऐतिहासिक सत्य हो मगर जिन्ना के भक्तों को बात चुभेगी तो जरूर; विशेष कर जब वे सब पिछले 34 साल से ऊपर एक ऐसे वातावरण में जिये हैं जहाँ दूसरे की बात को समझने और सहनशीलता की कमी वहाँ की सरकार और वहाँ के समाज दोनों में ही पायी जाती है—केवल दूसरों के प्रति ही नहीं आपस में एक दूसरे के लिए भी।

## किताब की तस्करी

'विकास' प्रकाशन संस्था के निदेशक तथा भारतीय प्रकाशन संघ के अध्यक्ष नरेंद्रकुमार ने पाकिस्तान की इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कहा, "मैं हैरान हूँ कि भारत से इस पुस्तक के विषय में शिकायत करने का क्या तुक है? भारत और पाकिस्तान के बीच तो पिछले 17 साल से पुस्तक व्यापार बंद है। यदि यह पुस्तक यहाँ से पाकिस्तान पहुँची है तो चोरी से पहुँची होगी। हमने नहीं मंजी यहाँ से। अगर वहाँ किसी को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कुछ जिन्ना साहब के बारे में कहा उस से शिकायत है तो वह लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारियों से होनी चाहिए, हम से नहीं। इस देश में प्रकाशक स्वतंत्र है।"

नरेंद्रकुमार का कहना है कि उनकी अपनी संस्था ने, विशेष कर और भारतीय प्रकाशकों ने साधारणतया पुस्तकों के प्रकाशन में सदा स्वतंत्र नीति अपनायी है। उनका कहना है: हमने एयर मार्शल असगर खान की किताब 'द फर्स्ट राउंड' छपी और बेची, जो सरासर पाकिस्तान का दृष्टिकोण प्रसारित करती है जो कि भारत के हक में नहीं। हमने स्वर्गीय मुहंजी की पुस्तक 'इफ आई एम असेसिनेटेड' भी प्रकाशित की थी। और यदि सदर जिया-उल-हक अपनी आत्मकथा लिखना चाहें या किसी

और से अ  
तो हम उ  
के लिए  
बंगलादेश  
बंगलादेश  
और वहाँ  
शिष्टमंडल

भी प्रकाशि  
पुस्तक में  
बंगलादेश  
है। प्रश्न य  
सिद्धांत यह  
लेखक की  
को कितना  
हो, मगर  
राय प्रक  
अधिकार अ

लापियर  
भारतीय प्र  
सरकार ने  
लगायी तो  
सफलता मि  
के प्रकाशन  
भारत और  
प्रकाशन व  
स्वतंत्रता से

नरेंद्रकुमार  
कई देशों में  
ब्रितानी संस  
हैं। पाकिस्त  
का नियमित  
भारतीय प्र  
पाकिस्तान  
सके तो पा  
हो सके तो  
अधिकार क  
तुल्य मामल  
है। ये कोने  
पाकिस्तान में  
कोन जाने।

चोरी के

न तो पा  
और प्रकाशक  
पर ही हस्ता  
पुस्तक व्यव  
मामले में वि  
कारों की प  
इस से बहुत  
पुस्तक 'इ जज  
प्रकाशकों ने  
जिनमान



स्तान

ती."

न के वे वाक्य  
त आपत्ति है  
आपत्ति क्यों  
इस बात को  
जैसा वास्तव  
मा. सच मानो  
स लिए निम  
पट जाती है  
ही की थी."

तक में जिज्ञा  
शब्दों में,  
मगर जिज्ञा  
विशेष कर  
पर एक ऐसे  
की बात को  
भी वहाँ की  
में ही पायी  
नहीं आपस

नदेशक तथा  
नरेन्द्रकुमार  
ना उत्तर देते  
से इस पुस्तक  
क्या तुक है?  
पिछले 17  
इ यह पुस्तक  
तो चोरी से  
हाँ से. अगर  
ने जो कुछ  
से शिकायत  
राधिकारियों  
में प्रकाशक

नकी अपनी  
य प्रकाशकों  
शन में सदा  
कहना है:  
की किताब  
जो सरासर  
त करती है  
वर्गीय भुट्टो  
नेनेटिड' की  
जिया-उल-  
हूँ या किसी  
-5 जून '82

और से अपनी जीवनी लिखवाये  
ता हम उसे भी प्रकाशित करने  
के लिए तैयार होंगे. भारत-  
बंगलादेश जल विवाद पर हम  
बंगलादेश के एक भूतपूर्व मंत्री  
और वहाँ के कई जल संबंधी  
शिष्टमंडलों के नेता की पुस्तक  
भी प्रकाशित कर चुके हैं. उनकी  
पुस्तक में भी भारत का नहीं  
बंगलादेश का ही दृष्टिकोण  
है. प्रश्न यह है कि प्रकाशन का  
सिद्धांत यही होना चाहिए कि  
लेखक की राय से चाहे पाठक  
को कितना ही मतभेद क्यों न  
हो, मगर लेखक को अपनी  
राय प्रकट करने का पुरा  
अधिकार और खुली छूट होनी ही चाहिए.

लापियर और कॉलिस की पुस्तक के  
भारतीय प्रकाशकों का कहना है कि पाकिस्तान  
सरकार ने यदि इस के वितरण पर रोक  
लगायी तो उस का विरोध किया जायेगा.  
सफलता मिले या न मिले मगर सबाल पुस्तकों  
के प्रकाशन और वितरण का है, जो केवल  
भारत और पाक का ही नहीं सारे विश्व के  
प्रकाशन व्यवसाय, लेखन तथा विचार की  
स्वतंत्रता से जुड़ा है.

नरेन्द्रकुमार ने बताया कि यूरोप तथा अन्य  
कई देशों में इस पुस्तक के वितरण के अधिकार  
ब्रितानी संस्था 'गारलैंडफोल्ड' को दिये गये  
हैं. पाकिस्तान को अधिकृत रूप से पुस्तकों  
का निर्यात उसी के द्वारा ब्रिटेन से हो सकता है.  
भारतीय प्रकाशकों ने उनसे कहा है कि यदि  
पाकिस्तान पुस्तक पर रोक लगाता है तो हो  
सके तो पाकिस्तानी न्यायालयों में और न  
हो सके तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी अपने  
अधिकार की रक्षा के लिए तैयारी करें. इस  
तरह मामला एक तिकोने युद्ध का रूप ले रहा  
है. ये कोने हैं भारत में, ब्रिटेन में और  
पाकिस्तान में. अंत में परिणाम क्या निकलता है,  
कोन जाने.

### चोरी के प्रकाशन की समस्या

न तो पाकिस्तान ने कॉपीराइट यानी लेखक  
और प्रकाशक के संबंधों से जुड़े 'बर्न कन्वेंशन'  
पुस्तक व्यवसाय किये हैं और न ही पाकिस्तानी  
मामले में विदेशी लेखकों, प्रकाशकों के अधि-  
कारों की परवाह करते हैं. भारतीय प्रकाशक  
इस से बहुत परेशान हैं. कुलदीप नैयर की  
पुस्तक 'द जजमेंट' को एक नहीं कई पाकिस्तानी  
प्रकाशकों ने एक साथ छापा और घड़ाघड़  
विमर्श



नरेन्द्रकुमार : 'यहाँ प्रकाशक स्वतंत्र हैं'

बिक्री से खूब पैसा कमाने की आशा बाँधी.  
मगर कम से कम दो पाकिस्तानी प्रकाशक  
ऐसे थे जिन्हें इस मामले में मुँह की खानी  
पड़ी : बजाय लाभ के उन्हें भारी हानि उठानी  
पड़ी, ऐसा पुस्तक के मूल भारतीय प्रकाशकों  
का कहना है. स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई  
की, विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकशास्त्र, अर्थशास्त्र  
की भारतीय पुस्तकों को पाकिस्तानी  
प्रकाशक सहज रूप से खुल्लमखुल्ला छापते  
तथा बेचते हैं. अन्य लोकप्रिय भारतीय पुस्तकें  
भी वहाँ चोरी से प्रकाशित होती हैं, लेकिन कोई  
पुछने वाला नहीं.

### नुकसान पाकिस्तान का भी है

चोरी के प्रकाशन व्यवसाय से नुकसान  
पाकिस्तान का भी है. एक तो चोर व्यवसाय  
में कोई हिसाब किताब नहीं होता, उनकी मोटी  
आमदनी से सरकारी खजाने में कोई कर नहीं  
पहुँचते. दूसरे, उस देश में अच्छे स्तर के साहित्य  
का अच्छे मापदंडों के अनुसार विकास  
नहीं हो सका क्योंकि भारत और पाकिस्तान  
के बीच पुस्तक व्यवसाय बंद है इस लिए  
पाकिस्तान की अपनी प्रकाशित पुस्तकों का  
बाजार बहुत छोटा है और माँग भी बहुत  
कम है.

दोनों देशों के अन्य संबंधोंके सुधार के साथ-  
साथ आपस में साहित्य और पुस्तक व्यापार  
संबंधों को सामान्य बनाना जरूरी है, यह  
अधिकतम भारतीय प्रकाशकों की राय है.  
कई पाकिस्तानी पुस्तक व्यापारी और प्रकाशक  
तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब इन दोनों  
देशों के बीच पुस्तक व्यापार के मार्ग में खड़ी  
दीवार टूटेगी.

उन्होंने कुछ प्रमुख भारतीय प्रकाशकों  
से ऐसे वायदे भी करा लेने का प्रयास किया  
है कि 'दीवार टूटेगी, तो व्यापार हम  
से होगा.' □

### प्रक्षेपास्त्र

## फाकलैंड की लड़ाई से भारत क्या सीख सकता है?

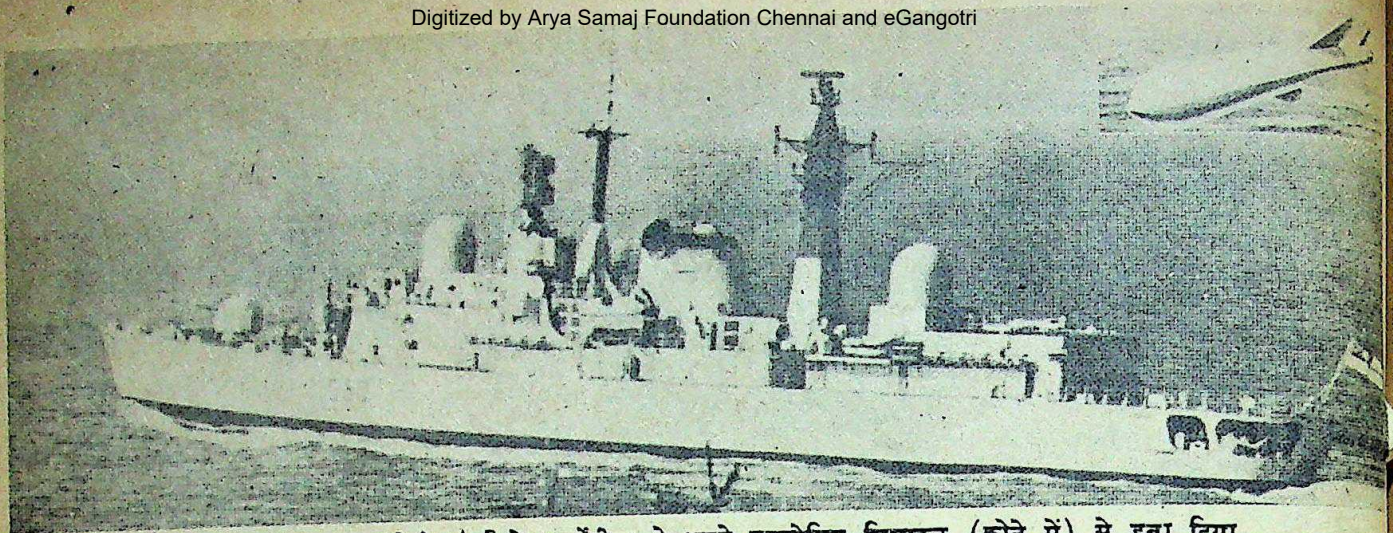
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी

हाल के फाकलैंड युद्ध में आर्जेंटीना ने शक्ति-  
शाली ब्रितानी युद्धपोत 'शेफील्ड' को  
डुबो कर तहलका मचा दिया. इसे डुबाने में  
उसने फ्रांस में बनी जिस एक्जोसिट मिसाइल  
का प्रयोग किया अब पाकिस्तान अपने लिए  
उसे खरीदने जा रहा है और ऐसी संभावना  
है कि यह सौदा शीघ्र ही पट जायेगा. कुछ  
वर्ष पहले फ्रांस ने भारत को यह प्रक्षेपास्त्र  
बेचने की पेशकश की थी किंतु संभवतः अधिक  
महंगा होने के कारण भारत उस प्रस्ताव को  
स्वीकार नहीं कर सका. अब पाकिस्तान द्वारा  
उसके खरीदे जाने की संभावना और फाकलैंड  
में उस के श्रेष्ठ प्रदर्शन ने भारतीय नौसेना की  
प्रतिरक्षात्मक क्षमता के आगे प्रश्नचिह्न लगा  
दिया है.

फाकलैंड का युद्ध भारत के लिए एक सबक  
बन गया है क्यों कि उस में ब्रिटेन और आर्जेंटीना  
दोनों ने ही क्रमशः 'सी वुल्फ' और 'एक्जोसिट'  
घातक नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों का सफल प्रयोग  
कर के कम से कम हमारी नौसेना की जरूरतों  
पर पुनर्विचार करने की जरूरत पैदा कर दी है.

जिस तेवर के साथ ब्रितानी नौसेना ने  
फाकलैंड द्वीपसमूह की घेराबंदी की और  
फिर कब्जा जमाने के लिए हमला किया  
उस से एक बार पुनः सिद्ध होता है कि नौसेना  
की भी निर्णायक भूमिका होती है. जब आर्जेंटीना  
का क्रूजर 'जनरल बेलग्रानो' ब्रितानी पनडुब्बी  
से दागे हुए एक तारपीडो से समुद्र की गोद में  
बैठ गया तो यह भी पता चला कि बड़े बड़े  
जहाज रखना अपने आप में कोई शक्ति का  
परिचायक नहीं है. जनरल बेलग्रानो एक  
पुराना जहाज अवश्य था, जो अमेरिका में  
1935 में 1939 के बीच में बना था, पर उस  
का नवीकरण कर दिया गया था. उसका मार  
10,650 टन था. उसमें दो हेलीकॉप्टर  
थे और दो सी कैंट मिसाइल प्रक्षेपक भी थे. सी  
कैंट मिसाइलें समुद्र से वायु में, घरती से घरती  
पर मार कर सकती हैं यह मिसाइल 1.48  
मीटर लंबी, 68 किलोग्राम मार की होती है  
और यह साढ़े तीन किलोमीटर तक की मार  
कर सकती है. इसके साथ ही साथ इस जंगी  
जहाज में बहुत सी तोपें लगी थीं जो एक पन-  
डुब्बी के एक तारपीडो के सामने समाप्त  
हो गयीं.





ब्रितानी जंगी जहाज 'शेफील्ड' जिसे आर्हेतीना ने अपने एकजोसिट मिसाइल (कोने में) से डूबा दिया

ब्रितानी जंगी जहाजों में जो जहाज डूबा वह एक आधुनिकतम जहाज था, जिस पर ब्रिटेन को सब से अधिक गर्व था। इस जहाज के नाम पर प्रणाली सं. 42 के ऐसे जहाजों को 'शेफील्ड विध्वंसक' कहा जाता है। इसका भार 3,150 टन था। इस पर एक लिक्स हेलीकॉप्टर रहता था, जिसकी तारपीडो किसी भी पनडुब्बी का विनाश कर सकती थी। इस पर एक दुनाली सी डार्ट मिसाइल लांचर भी रखा था। यह मिसाइल सतह से आकाश पर और सतह से सतह पर तो मार कर ही सकती है; अपनी ओर आने वाली मिसाइल को भी नष्ट कर सकती है। शेफील्ड किस्म के सभी विध्वंसकों में 30 मिलीमीटर भार वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इसके बावजूद यह विध्वंसक आकाश से फेंकी हुई एक मिसाइल द्वारा डूबो दिया गया। आर्हेतीना को शेफील्ड किस्म के दो और विध्वंसक बेचे गये थे—हर्कुलिस और सेंटि-सीमा। जिस समय शेफील्ड पर आक्रमण हुआ वह ब्रिटेन के विमानवाहक पोत से 15 किलोमीटर पूर्व में खड़ा हुआ विमानवाहक पोत से रक्षा के लिए जानकारी एकत्र कर रहा था। आर्हेतीना के दो डींगरविमान, जो फ्रांसीसी मिराज-3 विमानों का इस्तेमाल में बना मॉडल है, इस विध्वंसक के बहुत करीब तक समुद्र की सतह से जरा ऊँचे उड़ते हुए आये जिस से कि शेफील्ड के राडार में उनका चित्र नहीं आ सका। इसके बाद वे एकदम आकाश में उड़ चले और वहाँ से उन्होंने फ्रांस निर्मित एकजोसिट मिसाइल दाग दी। फिर भी समझा जाता है कि 300 में से 30 कर्मचारी इस विध्वंसक के साथ समुद्र में डूब गये।

शेफील्ड का डूबोया जाना रणनीति में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जायेगी। इसका वही महत्व है जो अरब-इस्राइल युद्ध में मिराज-3 विमानों द्वारा मिस्र के विमानों और हवाई अड्डों को नष्ट करने के सिलसिले में था, या उस रूसी मिसाइल की करामात थी जिसने इस्राइल की पनडुब्बी को मूमध्यसागर में एक ही बार में डूबो दिया। इसी प्रकार वीएतनाम के तट से दागी हुई एक मिसाइल ने अमेरिकी

विमानवाहक पोत 'फोरिस्टॉल' को, जो अपने किस्म का बहुत बड़ा विमानवाहक पोत था, एक ही मार में लंगड़ा कर दिया और उस के डेक पर जितने विमान थे उन सब को जला दिया। योम किर पर युद्ध में सीरिया और मिस्र के पैदल सैनिकों ने अपने कंधे पर रखी हुई रूसी मिसाइलों के द्वारा इस्राइल के प्रसिद्ध मिराज विमानों को तथा अन्य विमानों को भूमिसात कर दिया था।

एकजोसिट मिसाइल क्या है, यह भी जान लेना जरूरी है। यह इस लिए भी आवश्यक है कि पाकिस्तान फ्रांस से ये मिसाइलें खरीद रहा है और उसके पास वे मिराज-3 विमान भी हैं जो शेफील्ड पर आक्रमण करने के काम में लाये गये थे। इस लिए ब्रिटेन को लगा धक्का भारत के लिए सबक हो सकता है। जो एकजोसिट ए एम-39 मिसाइल विध्वंसक को नष्ट करने के लिए काम में लायी गयी वह एकजोसिट मिसाइल प्रणाली का सुधरा हुआ रूप है। यह मिसाइल फ्रांस के सुपर फ्रैलोन अतलांतिक और सुपर एंताद विमानों में लगायी गयी है। यह मिसाइल 469 सेंटीमीटर लंबी होती है, व्यास 35 सेंटीमीटर होता है और जो मिसाइल आकाश से घरती पर फेंकी जाती है उस के पंख मुड़ सकते हैं, इस लिए वह कम स्थान के लांचर से फेंकी जा सकती है। इसका वजन 650 किलोग्राम और मार 50 किलोमीटर तक की होती है। इस प्रणाली में एम एम-38, एम एम-39, और एम एम-40 मिसाइलें भी हैं। ये तीनों मिसाइलें जहाज से जहाज तक मार कर सकती हैं और यह समझा जाता है कि एम एम-40 की गति ध्वनि की गति से भी दूनी होती है। जर्मनी के सहयोग से एक एकजोसिट एम एम-100 मिसाइल भी बनायी जा रही है, जिस की मार 70 किलोमीटर तक की होगी। क्यों कि भारत के पड़ोसियों दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान ने एकजोसिट मिसाइलें प्राप्त कर ली हैं इस लिए भारत को उनसे सावधान रहना है। हो सकता है जब हम मिराज-2000 विमान खरीदें तो उस के साथ इस मिसाइल प्रणाली की भी कोई मिसाइल

खरीदना उपयोगी हो।

वर्तमान युद्धों में फ्रांस निर्मित हथियार प्रभावी और शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं। पहले मिराज विमान इस्त्राइलियों के हाथ में निर्णायक सिद्ध हुआ और फिर सुपर एंताद विमान। अब एकजोसिट मिसाइलें ब्रितानी नौसेना को आतंकित करने में सफल हुई हैं। उस के संदर्भ में हमें यह सोचना पड़ेगा। कि कौन सी प्रौद्योगिकी ज्यादा उपयोगी है।

हैरियर और सी-हैरियर विमान एक ही प्रकार के हैं: सिवाय इस के हैरियर विमान हवाई अड्डों पर उतरते हैं और सी-हैरियर विमानवाहक पोत पर भी उतर-चढ़ सकते हैं। हैरियर विमान की गति कम ऊँचाई पर 730 मील प्रतिघंटा होती है। उस में साइडवाइंड मिसाइलें लगी होती हैं और उसकी नोक में एक ब्लूफोक्स राडार लगा होता है। सी-हैरियर जर्मनी और अमेरिका की नौसेना में भी हैं। परंतु यह पाया गया है कि साधारण उड़ान में भी हैरियर और सी-हैरियर विमान नष्ट हो गये। युद्ध क्षेत्र में उनकी उपयोगिता पर एक और प्रश्नचिन्ह लग गया है, क्योंकि इन विमानों के बावजूद ब्रितानी नौसेना फॉकलैंड द्वीपसमूह पर अपने थल सैनिक उतार नहीं सकी। इस युद्ध से यह सबक निकलता है कि अनेक विमानों और अच्छी मिसाइलों में बड़े विमानवाहक पोतों और अन्य जहाजों को मार गिराने की क्षमता होती है। शक्ति आकार में नहीं होती।

कच्छ से ले कर बंबई तक का हमारा समुद्री क्षेत्र और उस में विचरण करने वाले हमारे पोत कभी भी शत्रु की चपेट में आ सकते हैं। इस क्षेत्र की निगरानी के लिए हमें उस प्रकार के जल्द सूचना देने वाले विमान चाहिए हैं जैसे साऊदी अरब ने अमी अमेरिका से खरीदे हैं और जिसके कारण इस्त्राइल ब्रितानी इस्त्राइल के विमान इराक में बगदाद तक घुस कर उसके आणविक संयंत्र को नष्ट कर गये और इराक की वायुसेना को पता तक नष्ट लगा। समुद्र तट पर न केवल समुद्र तेल के भंडार बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के ऐसे संयंत्र



## प्रदेश

## चुनाव

## छोटे आम चुनाव के ये नतीजे किस दिशा में संकेत करते हैं

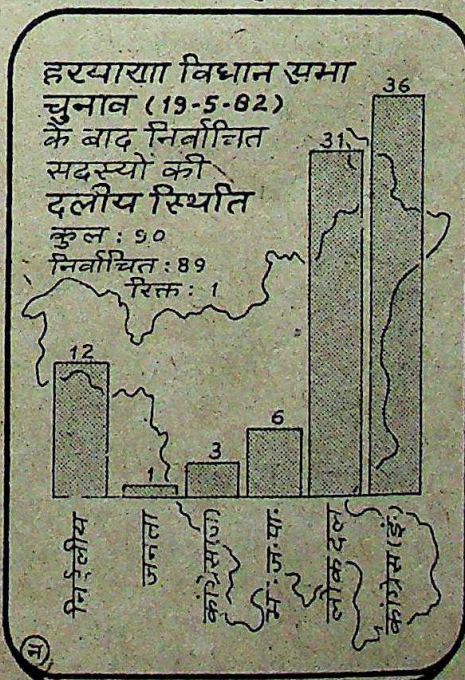
**19** मई के लघु चुनावों की गहमागहमी आम चुनाव से कम नहीं थी। इसके परिणाम भविष्य की राजनैतिक तस्वीर का आभास दे जाते हैं। केवल चार राज्यों—हरयाणा, हिमाचलप्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल की 592 सीटें दांव पर नहीं लगी थीं बल्कि सात लोकसभाई और 15 विधानसभाई उपचुनाव भी हुए जिनके परिणाम भविष्यवाणियों को झुठला गये। ये उपचुनाव महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में हुए। इन उपचुनावों के परिणाम भी स्थानीय सोच को प्रतिबिंबित करते हैं।

केरल में संयुक्त लोकतंत्री मोर्चे की जीत से इंडा का मनोबल ऊँचा हुआ। इस से पूर्व उसे के. कृष्णाकरन के नेतृत्व में दो अवसर अलबत्ता मिले लेकिन दलबदल के कारण इंडा अपनी छाप नहीं छोड़ पायी। लेकिन पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे ने एक बार भारी विजय

प्राप्त कर के अपनी नींव पुख्ता कर ली। वेशक कांग्रेस ने 1977 की अपेक्षा दुगुने से अधिक स्थान प्राप्त किये लेकिन वे वामपंथियों के गढ़ नहीं भेद सके, अधिकतर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ही उनके हाथ लगीं। हरयाणा और हिमाचलप्रदेश में इंडा को कड़ा मुकाबला करना पड़ा। केरल और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक भी स्थान जीतने में भले ही सफल नहीं हुई हो, हिमाचलप्रदेश में उसने इंडा को नाकों चने चववा दिये। वहाँ मतगणना के आरंभ से ही भाजपा ने जो बढ़त हासिल की उस पर विराम मतगणना के अंत में जा कर लगा। इंडा अकेली बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर तो आयी लेकिन सरकार बन जाने पर भी उसके अस्तित्व के लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। हरयाणा में भी इंडा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पायी। देश के सभी प्रमुख पत्रों की मुखियों में छपा



देवीलाल, सुरेंद्रसिंह, लखमनसिंह और मंगलसेन : अपनी अपनी गोटियाँ



कि 'हरयाणा में सत्ता की चाबी निर्दलियों के पास है।' मजनलाल जोड़तोड़ करने वाले राजनीतिकों में रहे हैं, चाहे वे कांग्रेस में रहे हों या जनता पार्टी में। यही कारण रहा कि जहाँ राज्यपाल तपासे के निर्देश पर देवीलाल अपने समर्थक इकट्ठे करने में व्यस्त रहे वहाँ भजनलाल जोड़तोड़ कर के राज्यपाल की मदद से सरकार गठित करने में कामयाब हो गये। हिमाचल में भी कमोबेश ऐसी ही राजनैतिक गोटियाँ बिठायी गयीं। कुछ भी सही, उत्तर भारत से शुरू हुआ यह खतरा इंडा के लिए कभी भी संकट का बायस बन सकता है। 1967 में एक दर्जन विधानसभाओं में कांग्रेस की हार की शुरुआत उत्तर भारत से ही हुई थी। क्या उत्तर भारत में गैरकम्युनिस्ट पार्टियाँ मिल कर इंडा की सत्ता के पाये हिला सकती हैं, यह प्रश्न आम चर्चा का विषय बन गया है। निर्णायक बहुमत का दावा करने वाले

है जिनकी सुरक्षा पर नये सिरे से विचार करना होगा।

भारत को नौसेना और वायुसेना के पारस्परिक सहयोग और उनकी सम्मिलित भूमिका पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। यह सही है ब्रिटेन के दो विमानवाहक पोत 'नर्विसिविल और हरमिज' के विमानों ने फॉकलैंड की राजधानी पोर्ट स्टैनले, डरविन तथा पेबिल द्वीपसमूह पर खड़े आर्हेतीना के विमानों और गोलाबारूद के भंडार को नष्ट किया है। ब्रितानी सूचना के अनुसार 11 विमान नष्ट किये गये, जब कि आर्हेतीना ने केवल तीन माने हैं। पर इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान छाताधारियों का रहा है, जो फॉकलैंड की धरती पर हेलीकॉप्टर से उतर गये और जिन्होंने विमानपट्टी पर खड़े हुए आर्हेतीनी विमानों को नष्ट कर दिया। लेकिन साथ साथ यह ध्यान रखने की भी जरूरत है कि ब्रिटेन में इस बात की बड़ी चिंता है कि कहीं कोई शत्रु की मिसाइल विमान से छोड़ा हुआ बम या पनडुब्बी से दागा हुआ तारपीडो उनके इन दो बड़े विमानवाहक पोतों को नष्ट न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी हानि मानी जायेगी।

हमें स्मरण है कि सन् 1965 के युद्ध में हमारी नौसेना इतनी समृद्ध नहीं समझी गयी थी कि विमानवाहक पोत 'विक्रांत' की रक्षा कर सके और उसे कोचीन के बंदरगाह में खड़ा रखना पड़ा था। यह भी कहा गया था कि उसकी मरम्मत हो रही है। इस के बाद जब उसे 1971 के युद्ध में बंगाल की खाड़ी में भेजा गया और अंडमान द्वीपसमूह के करीब उसने लंगर डाला तब भी सैनिक सूत्रों द्वारा यह कहा जाता था कि 'विक्रांत' लंगड़ा हो गया है। फिर भी लंगड़े ने खूब काम दिखाया। पता यह चला कि 'उसका बायलर बेकार हो गया था और वह पूरी शक्ति के साथ चल नहीं सकता था। कुछ लोगों का तो यह कहना भी था कि एक अन्य जहाज उसे ठेल कर उपयुक्त स्थान पर पहुँचा आया था, जहाँ से उसके विमान चटगाँव तथा पूर्वी पाकिस्तान के अन्य बंदरगाहों पर हमला करते रहे। हमारा विमानवाहक पोत भी उसी जमाने का है जिस जमाने का आर्हेतीना का कूजर था; यानी द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का।

हम अपनी पनडुब्बियों पर ज्यादा भरोसा रखें, मिसाइल युक्त फ्रिगेट या मिसाइल बोट बनायें, या एक नया आधुनिक विमानवाहक पोत तैयार करें या खरीदें, यह विचारणीय प्रश्न है; खास तौर पर उस समय जब कि तेल महंगा है और जितना बड़ा पोत होता है उतना ही खर्च अधिक पड़ता है। विक्रांत पर सी-हैरियर ही लिये जायें या फ्रांसीसी एंताई जैसे विमान, जिसने शेफील्ड को डुबो दिया? □

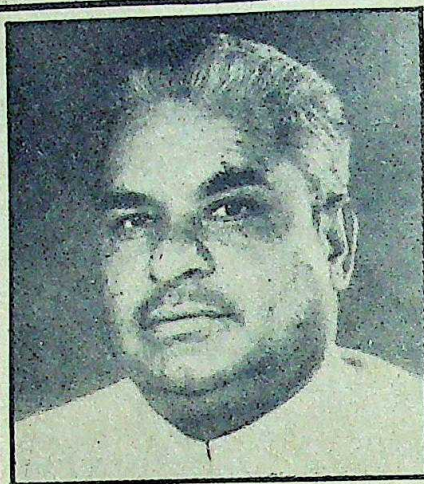


दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केवल 'अकेली बड़ी पार्टी' बनने का ही सुख मिला। उनकी सरकारों का अस्तित्व बेशक दूसरी पार्टियों के सहयोग पर निर्भर है। हरयाणा के मुख्यमंत्री मजनलाल ने निर्दलों के सहयोग की इका के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता करार देते हुए बिना नियमों की परवाह किये अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जब मजनलाल अपने भूतपूर्व सहयोगियों को ही एक साथ ले कर नहीं चल सके तो इन नये समर्थकों को कहाँ तक ले कर चल पाते हैं, इस का फैसला 30 जून के विधानसभा अधिवेशन में या उस से पहले भी हो जाये तो अनहोनी बात नहीं।

हरयाणा में चुनाव परिणामों की जिस प्रकार आँख मिचौली चली अंत तक यह कह पाना मुश्किल था कि किस पार्टी को अधिक स्थान मिलेंगे। कमी लोकदल-भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता तो कमी कांग्रेस (इ) का मतगणना की जब शुरुआत हुई तो खुशी का माहौल लोकदल खेमे में ही था। हरयाणा में जाति विरादरी की हमेशा ही मुख्य भूमिका रही है। जाट और गैरजाट की बात हमेशा उछाली जाती रही है। इस बार जाटों के वोट जाटों को ही मिले। वही गैरजाट सफल हो सका जिसे जाट नेताओं का समर्थन मिला। मुख्यमंत्री मजनलाल ने जाटों के मत पाने की कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हरयाणा की आबादी में जाटों का 25 प्रतिशत है, लिहाजा इका उन की अवहेलना नहीं कर सकती।

इका को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो पाने का एक कारण उम्मीदवारों का चुनाव भी था। जिस प्रकार लगभग डेढ़ दर्जन मंत्रियों को टिकट से महसूस किया गया उस से कांग्रेस (इ) के विभिन्न तबकों में तलखी महसूस की गयी। कुछने विद्रोही उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ा, तो कुछ 'अनुशासन' के नाम पर चुप हो गये। लेकिन उन्होंने अधिकृत उम्मीदवारों का समर्थन भी नहीं किया, बल्कि उन के विरुद्ध चुनाव प्रचार में भाग लिया।

मजनलाल ने 1980 में पूरी काबीना और पार्टी के साथ जिस प्रकार दल बदला था उस से भी आम लोगों में अप्रसन्नता ही रही है। तब वह जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता थे। हिमाचलप्रदेश के रामलाल ने भी यही रास्ता अपनाया। हरयाणा में 1967 में दलबदल की जो शुरुआत हुई थी उससे, पिछले पंद्रह वर्षों में कई पार्टियों और व्यक्तियों के सत्ता में होने के बावजूद, राजनैतिक स्थिरता कमी नहीं आयी। एक दिन में चार बार दल बदलने वाले गया राम इस बार हार गये लेकिन 'आयाराम गया राम' का मुहावरा देने वाले और न जाने कितने इस मुहावरे में जुड़ गये हैं। फिर भी मजन-



## मोजन और मजनलाल : आँखों देखा हाल

मुख्यमंत्री मजनलाल से दो मुलाकातें हुईं :

पहली 22 मई रात आठ बजे और दूसरी 23 मई इतवार को दो बजे। दोनों ही मुलाकातें दिल्ली स्थित हरयाणा भवन में हुईं। दोनों में अलग अलग माहौल था। 22 मई को सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों का नेता चुने जाने से उन का चेहरा दमक रहा था। मुख्यमंत्री का दरवाजा खुला था। हर कोई जा कर मुबारकबाद दे रहा था। बड़ी संख्या में राजनैतिक कार्यकर्त्ता तथा अन्य वर्गों के लोग फूलों के गुलदस्ते, हार, मिठाई के डिब्बे उन्हें देते हुए अपनी 'खुशी' का इजहार कर रहे थे।

मजनलाल जी, क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं?

'बिल्कुल, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमें सब से अधिक स्थान मिले हैं, एक पार्टी के नाते।'

अभी बातचीत चल ही रही थी कि मुबारकबादियों का एक और दल पहुँच गया। मुख्यमंत्री घिर गये : ऐसे घिरे कि कोशिश करने पर भी उन से बातचीत आगे न बढ़ सकी।

इतवार को तीन बजे पुनः हरयाणा भवन गया। पता चला मजनलाल 'लोकल' गये हैं। कुरेदने पर बताया गया कि प्रधानमंत्री निवास स्थान पर हैं। धवन साहब से बातचीत कर रहे हैं। घंटे भर बाद चंडीगढ़ चले जायेंगे, कार से या विमान से। सतर्क आँखों ने घूरा। फिर बोले विमान से। अपने दोनों विमान (राज्य सरकार के) तो खराब हैं। 'स्वामी जी' के विमान से जायेंगे—स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ढाई बजे मजनलाल जी को सफदरजंग हवाई अड्डे पहुँचना था।

लगभग पौने दो बजे अपने दलबल के साथ मजनलाल जी आये। इतने में संसदसदस्य जे. के. जैन आये और भीतर चले गये। पाँच मिनट बाद निकल आये। बाहर आने के बाद जे. के. जैन खुश थे। बोले 'सरकार बनेगी, इस में दो राय नहीं।' आदतन कहते गये 'बहुत अच्छी स्थिति है। मजबूत और स्थायी सरकार बनेगी।' कह कर चल दिये। अंदर के एक जानकार ने बताया कि 'किसी की सिफारिश करने आये थे।'

क्यों कि सभी लोग आ जा रहे थे दिनमान संवाददाता भी भीतर पहुँच गया। मजनलाल जी भोजन कर रहे थे छक कर कल की अधूरी बातचीत की याद दिलायी। बोले, 'दो चार दिन ठहर जाओ, तब जम कर बातचीत होगी।'

क्यों कि बातचीत चल ही पड़ी थी इस लिए सिलसिला जारी रहा।

आप की पार्टी को कम सीटें मिलने का कारण क्या है?

'मित्तरघात (साबोटेज)।' इस का खुलासा नहीं किया।

बहुमत होने पर आप सरकार कैसे बनायेंगे?

'बहुमत हमें मिल गया है। कल ही छह विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो गये हैं।'

इस का मतलब यह कि फिर प्रलोमन की राजनीति शुरू?

'नहीं, यह प्रलोमन की राजनीति नहीं। उन लोगों ने हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है।'

लेकिन चौधरी देवीलाल को भी तो राज्यपाल ने अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया है?

'यह गलत है। संवैधानिक नहीं तकनीकी तौर पर। एक पार्टी के तौर पर हमारी पार्टी को अधिक स्थान मिले हैं। हमारी ही सरकार बनेगी।'

यह सरकार कितने दिन चलेगी? 'क्यों कितने दिन? यह स्थायी सरकार होगी। आप देख लीजिएगा।'

फोन बज रहा था। निजी सचिव हाँक रहा था। खाना चल रहा था। मजनलाल जी बेशक जल्दी में थे। उन की जल्दी का कारण चंडीगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने की तैयारी थी। इस संकेत भी दिनमान संवाददाता को मुख्यमंत्री के चेंबर से बाहर निकलते ही मिल गया था। एक बार फिर देवीलाल टापते रह गये।

—त्रिलोक



दलबल के ये. इतने आये और बाद निकल जैन खुश थे. राय नहीं. स्थिति है. बनेगी. कह जानकार ने रिश करने जा रहे थे पहुँच गया. थे छक कर. पाद दिलायी. ओ, तब जम ही पड़ी थी हा. टें मिलने का इस का सरकार के कल ही छह ल हो गये हैं. फिर प्रलोम जननीति नहीं. श्रीमती इंदिरा अपनी आस्था को भी तो साबित करते नहीं तकनीकी पर हमारे ले हैं. हमारे चलेगी? थायी सरकार के सचिव डॉ. भजनलाल खल्दी का कारण मुख्यमंत्री पद की थी. इस का को मुख्यमंत्री ही मिल गये. टापते रह गये. त्रिलोक

लाल सवा दो वर्ष तक अपनी सरकार को चला ले गये. निर्दलों के सहयोग से बनने वाली वर्तमान सरकार कितनी स्थायी होती है यह तो वक्त ही बतायेगा, क्योंकि इस बार लोकदल-भाजपा की संयुक्त समरनीति अधिक प्रभावी और कारगर साबित हो सकती है.

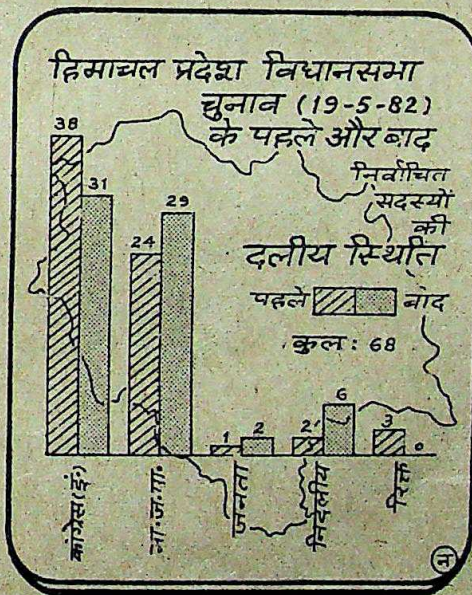
भाजपा ने इस बार पाँच स्थान खोये हैं. पिछली विधानसभा में उस के 11 स्थान थे जो अब घट कर छह रह गये हैं. भाजपा को अधिक स्थान प्राप्त न होने के कई कारण हैं: शहरों के लोग देवीलाल से नाराज थे. वे नहीं चाहते थे कि देवीलाल सत्ता में आये. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर शहरों में है लिहाजा देवीलाल विरोधी मतों के कारण भाजपा के उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिली. उसके वरिष्ठ नेता श्रीमती कमला वर्मा और रामलाल वधवा तक चुनाव हार गये, मंगल सेन ही विजयी हो सके.

वर्तमान विधानसभा में नये चेहरे अधिक होंगे और पुराने कम. प्रतिपक्ष के नेता मूलचंद जैन चुनाव हार गये हैं, हरयाणा भाजपा की अध्यक्ष श्रीमती कमला वर्मा भी इस बार विधानसभा में नहीं होंगी. नये चुन कर आने वाले विधायकों में भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्रसिंह हैं जो तोशम से लोकदल के उम्मीदवार को 25,628 मतों से पराजित कर चुने गये हैं जबकि भजनलाल आदमपुर से 24,412 मतों से ही जीत पाये हैं. जहाँ सुरेंद्रसिंह इतने भारी मतों से जीते वहाँ एक अन्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगवदयाल शर्मा के पुत्र राजेशकुमार केवल 63 मतों से ही यमुनानगर से जीतने में सफल हुए हैं. राव वीरेंद्रसिंह के पुत्र इंद्रजीत, जाट-सामा से 11,000 मतों से विजयी हुए. लेकिन लोकदल के नेता देवीलाल के पुत्र प्रतापसिंह भाग्यशाली साबित नहीं हुए. रौरी में वह कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार से हार गये. मंत्रियों में 14 में से केवल चार ही जीतने में सफल हो सके. सब से अधिक 22,000 मतों से हावले वाले मंत्री गजराज बहादुर नागर हैं. मुख्यमंत्री के अलावा अन्य जो तीन मंत्री जीते हैं वे हैं तारासिंह, श्रीमती शकुंतला भगवरिया और शमशेरसिंह सुरजेवाला. तारासिंह केवल नून को पुनः मतदान होगा. 90 सदस्यीय विधानसभा में अभी तक स्थिति इस प्रकार है: भाजपा 36, लोकदल 31, भाजपा 6, हिमाचल प्रदेश का हाल भी हरयाणा जैसा ही हुआ. यहाँ उस समय कांग्रेस (इं) के खेमे में अलबत्ता खलबली मची जब प्रारंभिक मत-गणना में अधिसंख्य परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गये. एक बार तो ऐसा भी लगा

कि कहीं भाजपा कांग्रेस (इं) का विलकुल सफाया ही न कर दे. लेकिन ज्यों ज्यों मत-गणना का दौर गरमाता गया कांग्रेस (इं) का गिरता हुआ मनोबल भी सँभलता चला गया. अब हालत यह है कि कांग्रेस (इं) को भाजपा से बहुत हासिल हो गयी है. भाजपा के 29 स्थानों के मुकाबले कांग्रेस (इं) के 31 स्थान हैं. 22 लाख मतदाताओं में 50 से 60 प्रतिशत ने मतदान किया. 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ यानी हरयाणा जैसी स्थिति. यहाँ भी कांग्रेस (इं) के नेता रामलाल निर्दलों का सहयोग प्राप्त कर



रामलाल और शांतकुमार : आमने सामने



सरकार बनाने में सफल हो गये. लेकिन उन का यह कदम भजनलाल जैसा विवादास्पद नहीं रहा.

कांग्रेस की निराशाजनक स्थिति का कारण 1980 में रामलाल द्वारा दलबदलों की मदद से सरकार बनाना था. हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ओर से विजयकुमार मलहोत्रा और जनता पार्टी की ओर से डॉ. सुब्रह्मण्यन स्वामी को चुनाव प्रचार अभियान का दायित्व सौंपा गया था. विजयकुमार मलहोत्रा भाजपा की बेहतर स्थिति का कारण शांतकुमार की अपनी छवि और तीस मास का

काम मानते हैं. उन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी पहुँचाया गया, अंत्योदय कार्यक्रम शुरू हुआ, काम के बदले अनाज की शुरुआत हुई, स्वच्छ प्रशासन प्रदान किया आदि. श्री मलहोत्रा के अनुसार हिमाचल के अराजपत्रित कर्मचारी सरकार से क्षुब्ध थे. सरकार ने उन के साथ हुआ समझौता तोड़ा था. अराजपत्रित कर्मचारियों के एक प्रदर्शन पर गोली चलने से दस व्यक्ति मारे गये थे.

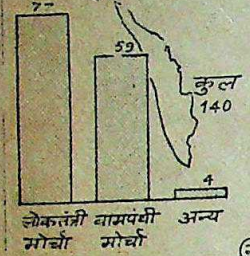
यद्यपि हिमाचल प्रदेश में हरयाणा या बिहार जैसी जाति विरादरी की भूमिका नहीं लेकिन पुराने और नये हिमाचल की भावना मतदान में आज भी अहम भूमिका निभाती है. श्री मलहोत्रा भाजपा की इस जीत का कारण 'कांग्रेस (इं) में भीतरी असंतोष' को पाते हैं. साथ ही भाजपा का 'बेहतर चुनाव प्रचार' भी करार देते हैं. श्री मलहोत्रा ने तीन सप्ताह हिमाचल प्रदेश में बिताये. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस (इं) द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, श्रीमती इंदिरा गांधी की 19 सभाओं तथा राजीव गांधी की 52 सभाओं के बावजूद और बेहिसाब पोस्ट-बाजी के चलते भी जब इंका स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी तो इस से एक ही निचोड़ निकलता है: 'श्रीमती गांधी का जादू अब मतदाताओं पर से काफूर हो गया है. इस से यह भी सिद्ध हो जाता है कि अगर गैरकम्युनिस्ट पार्टियों में एका हो जाये तो वे कांग्रेस (इं) को सत्ता से बेदखल कर सकती हैं.' श्री मलहोत्रा ने कहा कि हम बीस स्थानों की जीत का बीड़ा उठा कर घर से निकले थे, 29 मिल गये अगर 30 का निशाना बना कर चलते तो बहुमत प्राप्त कर सकते थे.

डॉ. सुब्रह्मण्यन स्वामी के अनुसार हवा जनता पार्टी के पक्ष में थी जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया. हमारे साधन सीमित थे, पहाड़ी इलाके के कारण लोगों तक पहुँच पाना मुश्किल था, मौसम भी खराब था, टेलीफोन से संपर्क कर पाना मुश्किल था लिहाजा हम लोगों तक पहुँच नहीं सके. अखबार भी भाजपा की खबरों से भरे रहते थे, जनता पार्टी का कहीं उल्लेख तक नहीं होता था. लहर तो थी जनता पार्टी की लेकिन 'बोगस जनता पार्टी' ने लाम उठाया. बहरहाल, इंदिरा विरोधी चेतना लोगों में जागी है और वह भी उत्तर में, इसलिए फैलाव होगा इस में दो राय नहीं.

केरल में अलबत्ता संयुक्त लोकतंत्री मोर्चे (यू डी एफ) की जीत से इंका की स्थिति मजबूत हुई है. मुख्यमंत्री कुरुणाकरन अपने दोनों चुनाव हलकों से जीते हैं. लेकिन जिस प्रकार लोकतंत्री और वामपंथी मोर्चों में छोटी छोटी पार्टियों का प्रतिनिधित्व है वह कभी भी सरकार के लिए खतरा साबित हो



### केरल विधानसभा चुनाव (19-5-82) के बाद दलीय स्थिति



के. करुणाकरन :  
तीसरी बार

सकती है. दलबदल की यही राजनीति पिछली सरकारों के पतन का कारण बनती रही है. कम्युनिस्ट पार्टी के अच्युत मेनन की जो सरकार कभी इका के समर्थन से सत्ता में रही आज वही कम्युनिस्ट वामपंथी मोर्चे में शामिल हो गये हैं. राजनीति में निरंतर बदलती विचारधाराओं से राजनैतिक सिद्धांतों की बात अटपटी लगने लगी है. मार्क्सवादियों की एक-जुटता बेशक अफवाह है.

केरल के एक करोड़ 30 लाख मतदाताओं में से 75 प्रतिशत ने अपने मतदाधिकार का इस्तेमाल किया. पहली बार मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी इस्तेमाल हुआ. केरल विधानसभा के सभी 140 परिणाम 20 मई को ही प्राप्त हो गये. केरल के कुछ भागों में जाली मतदान भी हुआ लेकिन मोटे तौर पर स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य ही रही. चार में से तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री—करुणाकरन, नायनार और मुहम्मद कोया तो जीत गये लेकिन एक मुख्यमंत्री पी. के. वासुदेवन नायर चुनाव हार गये. 140 सदस्यीय विधानसभा में संयुक्त लोकतंत्री मोर्चे को 77 और वामपंथी मोर्चे को 63 स्थान मिले. करुणाकरन सरकार को अपने निर्णायक मतों से बचाने वाले विधानसभा अध्यक्ष ए. सी. जोस पेरुर से 78 मतों से हार गये.

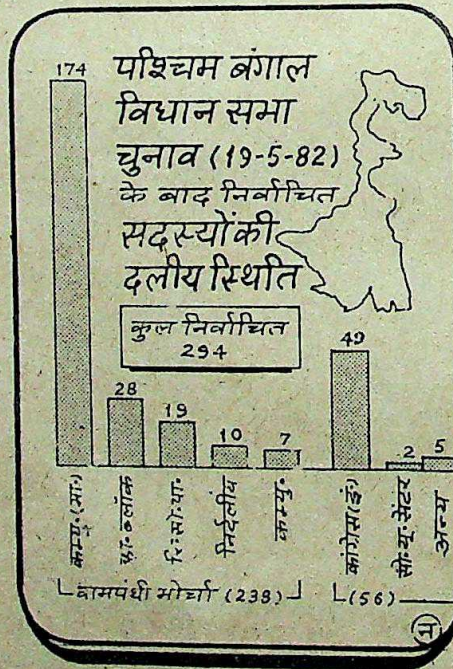
पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों का वर्चस्व बरकरार रहा. उन को बेदखल करने के प्रयास में इका आपसी मतभेदों और मार्क्सवादियों की एकजुटता के कारण सफल नहीं हो पायी और इस की संभावना भी नहीं थी. जहाँ इका के 249 उम्मीदवारों में से केवल 49 ही सफल हुए वहाँ मार्क्सवादियों के 209 में से 174 उम्मीदवार चुनाव जीते. ऐसी स्थिति उन की सहयोगी पार्टियों की भी रही. आर.एस.पी. 23 में से 19, फारवर्ड ब्लाक 34 में से 28, कम्युनिस्ट 12 में से सात, फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सवादी) तीन में से दो सीटों पर जीता. 294 सदस्यीय विधानसभा में वामपंथी मोर्चे

को 238 और इका और उस के समर्थकों को 54 स्थान मिले हैं. पश्चिम बंगाल में पहली बार मार्क्सवादी पूरे पाँच वर्ष सत्ता में रहे. कलकत्ता से दिनमान संवाददाता ने लिखा है:

बहुत दिनों पहले नक्सलवादियों ने नारा लगाया था—“ग्राम धेके शहर घेरो” अर्थात् गाँव से शहर घेरो. बाद में नक्सलवादी आंदोलन इस तरह टूट और बिखर गया कि वे गाँव से शहर को नहीं घेर सके. लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने साथियों के साथ गाँवों में अपने पाँव जमा कर शहरों पर शासन करने और उन्हें अपने रास्ते पर



ज्योति बसु और प्रफुल्ल कांति घोष



लाने का निर्णय किया है. पिछले शासनकाल में उन्होंने गाँवों के विकास पर अधिक जोर दिया और अपने राजनीतिक संगठन को भी गाँवों में मजबूत किया जिस से इस बार इन्हें गाँवों में पहले से अधिक सीटें मिली हैं. वस्तुतः वे गाँव से शहर घेरने की स्थिति में पहुँच गये हैं.

दूसरी तरफ कांग्रेस (इं) ने कलकत्ता महानगर और आसपास में अपने उखड़े पाँव फिर जमा लिए हैं. 1977 में कांग्रेस (इं) को कुल 294 सीटों में से मात्र 20 सीटें मिली थी

जिन में से एक भी सीट कलकत्ता और हावड़ा से नहीं मिली थी. इस बार कलकत्ता की 20 सीटों में से 11 कांग्रेस (इं) को, 9 माकपा को और एक एक सीट कां. स. दल तथा फारवर्ड ब्लाक को मिली है. हावड़ा में भी कांग्रेस (इं) को 3 सीटें मिली हैं. हावड़ा से लाल जिले हुगली में भी कांग्रेस (इं) को 4 सीटें मिली हैं जब कि पिछले निर्वाचन में एक भी सीट नहीं मिली थी.

हिंदी भाषी क्षेत्र : कांग्रेस (इं) का जोरदार समर्थन हिंदी भाषी क्षेत्रों से हुआ है. सच तो यह है कि कलकत्ता, हावड़ा और हुगली के जिन इलाकों से कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार जीते हैं उन में हिंदीभाषियों की संख्या काफी अधिक है. केंद्रीय मंत्रियों ने इन क्षेत्रों में धूम-धार प्रचार किया था जिस का प्रभाव निर्वाचन पर पड़ा. सब से पहले केंद्रीय सिंचाईमंत्री केदार पांडेय अपनी विधायक पत्नी कमला पांडेय के साथ कलकत्ता आये और प्रचार अभियान शुरू किया. इस के बाद हवा में कुछ गर्मी आयी और स्थानीय लोग जागे फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सांसद राजीव गांधी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं से शहरी इलाकों में कांग्रेस (इं) के पक्ष में एक हवा सी तैयार हो गयी.

कलकत्ता में बड़ा बाजार क्षेत्र से राजेश खेतान, (कोषाध्यक्ष कांग्रेस इं), जो सांकू से देवकीनंदन पोद्दार और जोड़ा बाजार से सुब्रत मुखर्जी निर्वाचित हुए. ये सभी कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार थे और सब को अच्छे से बहुमत प्राप्त हुआ. अन्य हिंदी-उर्दू भाषी क्षेत्रों में वहाँ बाजार, अलीपुर, सियाल्दह और बड़तल्ला भी शामिल हैं जहाँ से कांग्रेस के अब्दुल रऊफ अंसारी, अनूप कुमार सोमेन मित्र और अजित पांजा विजयी हुगली और हावड़ा के इलाकों में, जहाँ कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार विजयी हुगली हिंदीभाषियों की संख्या काफी अधिक वामपंथी मोर्चा ने खासकर माकपा ने हिंदी-उर्दू भाषी इलाकों में हिंदी-उर्दू भाषी उम्मीदवारों को ही खड़ा किया था. लेकिन उम्मीदवार मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके. कांग्रेस (इं) के हिंदी-उर्दू उम्मीदवार बहुत कम थे. जो थे, वे सब के सब जीत गये.

इस बार निर्वाचन की एक दिलचस्प बात यह है कि मतदाताओं ने केवल वामपंथी और कांग्रेस (इं) गठबंधन के दलों को वोट दिया है. अन्य दल विलकुल साफ हो गए हैं. केवल समाजवादी एकता केंद्र को तरह विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला है. भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और दल आदि का सफाया हो गया है.



## नारी जगत

## वर ढूँढो और जबरन पकड़ लाओ

लड़कियों की शादी करवाने का एक नया धंधा

पटना से अरुण रंजन चित्र : राजीव

बिहार में अपराधी तत्त्व अब पैसे वालों की सुहागरात मनवाने लगे हैं। विवाह मंडपों के वास्तविक पुरोहित इधर बाजू के बली हो गये हैं।

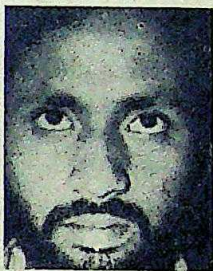
मुंगेर जिला में इस बार लगन के दिनों में वरों का अपहरण करा, उन से अपनी कन्या का जबरन विवाह कराने की धूम मची है। अपराधी गिरोह निश्चित फीस के एवज में शुभ विवाह करा रहे हैं। दहेज की समस्या का ऐसा तथाकथित विकृत निदान किस की जरूरत की उपज है? पहले दहेज की माँग से कन्यापक्ष तस्त रहता था। अब अपहरण विवाह से वर पक्ष आतंकित है।

विपिन (20) मुंगेर के परिवहन निगम के अधीक्षक रामजीसिंह का पुत्र है। स्थानीय कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र। उसे मई के शुरू में सिनेमा दिखाने के बहाने कुछ लोग जमालपुर ले गये। सिनेमा हॉल के बाहर पिस्तौल की नोक पर उसका अपहरण कर इंदरल पंचायत के एक गाँव में उसे कैद रखा गया। दूसरे दिन अपहरणकर्ताओं ने उसे एक कन्या से शादी करने को बाध्य किया। फिर वर के पिता को सादर सूचित किया गया कि आकर पुत्र तथा पुत्रवधू को ले जायें। पिता ने पुलिस में रपट दर्ज की। अभी वह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि पुत्रवधू को रखेंगे या नहीं?

बी. काम का स्थानीय छात्र जयनंदन एक मित्र के विवाह में खड़गपुर थाने के लाहेची गाँव गया था। विवाहोपरांत जब बाराती पक्ष आराम फरमा रहा था तो जयनंदन को कुछ लोग बाहर बुला कर पड़ोस के मकान में ले गये तथा कैद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने कड़े अहरे में अन्यत्र ले जा कर उससे अपनी कन्या का जयनंदन के इनकार करने तथा भागने की चेष्टा पर उसे गोली मार देने की धमकी मिली। विवाह के बाद वह पत्नी के साथ खुशाल मुंगेर लौटा है। उसकी माँ उर्मिला देवी का कहना है कि अब तो पुत्रवधू स्वीकार करनी पड़ेगी। मुंगेर तवाकू कारखाने के दो युवा कर्म-चारी मुरझकुमार तथा गिरीश कुमार के साथ जमालपुर घटनाएँ घटी हैं। मुंगेर के अलावा बेग-नालंदा के इंडा का विधायक रामनरेश सिंह के अनुसार—“कन्यापक्ष किसी अपराधी गिरोह को लगभग 1000 रु. में वर उठाने का ठेका

देता है। उसे इच्छित वर दिखा दिया जाता है। कन्यापक्ष वर के दैनिक कामकाज, संगी-साथ, शौक से भी अपराधी गिरोह को बखूबी परिचित करा देता है। नियत दिन अपराधी गिरोह वर को उठा लाता है। इधर कन्या के यहाँ विवाह का अर्धगुप्त इंतजाम रहता है। वर के बाराती बनते हैं वही मुस्टंडे। पंडित-पुरोहित, आसपड़ोस इस तमाशे में सहर्ष शामिल रहते हैं।

क्या कहते हैं, तीन कुंवारी कन्याओं के एक शिक्षक पिता—“दहेज की माँग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण कन्यापक्ष वाले ऐसा आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। मध्यम वर्ग अपहरण विवाहों में सब से आगे है। अपनी चढ़ती उम्र



शकील उज्जमाँ और रामनरेश सिंह



की कुंवारी बेटि को निरंतर देखने की हुताशा में बाप फौरी कार्रवाई कर बैठता है।” मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में तस्करों एवं ठेकेदारों ने वरों का दाम आसमान चढ़ा दिया है। इस सारे इलाका में ठेके का निविदा बंदूक से ही तय होता है। इधर अपराधी गिरोह भरे हैं। उन्हें वर-अपहरण से नया कार्यक्षेत्र मिला है।

ऊँचे वर्ग में एक लाख दहेज सामान्य बात है। आई. ए. एस. इस से ऊपर में ही बिकता है। बैंक तथा डाक्टरी पेशा के युवक की कीमत 40 से 60 हजार रु. है। गहने, टी. वी., सोफा ऊपर से है। पाँच गहनों का सेट (15 हजार रु. का) देना इधर नियम है। ईमानदार तथा सामान्य नौकरी पेशा, कृषक इतना जमा धन कहाँ से लायें?

अपहरण विवाहों की सामाजिक मर्त्सना का स्वर अत्यंत क्षीण है। मुंगेर युवा इंडा के नेता जिया उर रहमान, कमल कुमार, मंटू शर्मा आदि युवकों ने एक प्रेस वक्तव्य में ऐसे सामाजिक अपराध के प्रति रोष तो व्यक्त किया है। लेकिन कैसे? रहमान साहब ने लड़कों के पिता से, जनता के आर्थिक संकट की इस घड़ी में दहेज की दर घटाने की अपील की है। उन्होंने लड़कों के अभिभावकों से विद्रोह कर बिना पैसे की शादी की सलाह दी है।

प्रेम विवाह रचाने का माहौल बिहार में है कहाँ? जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता जनार्दन शर्मा दाढ़क ढंग से कटु तस्वीर रखते हैं—“यह बिहार है, सामंती बिहार। यहाँ लड़के और लड़की के बीच की न्यूनतम दूरी आठ फुट



बिहार का एक दूल्हा : जुल्मी शहनार्द

रखी जाती है। लड़की का छत पर घूमना शुबहा-बदनामी माना जाता है। लड़की माँई के दोस्त को आता देख कर यों घर में घुसती है मानो वह कोई बलात्कारी हो।”

एन. एस. यू. आई. युवा संगठन के अखिल भारतीय महासचिव शकील उज्जमाँ का मानना है कि “अपहरण विवाहों को खुली सामाजिक मान्यता मिल रही है। यह रोग प्रसार पर है। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया में दो दर्जन से ऊपर जबरन विवाह हो चुके हैं। सामाजिक मान्यता—वासदी—का प्रभाव पुलिस पर पड़ा है। वह बस खानापूर्ति करती है ऐसे मामलों में।” शकील का आगे कहना था कि “पहले दो बदमाशों की लड़ाई में कोई शरीफ पंचायती करा देता था। अब दो पैसे वाले परिवारों के बीच अपराधी वैवाहिक गठबंधन बंधवा रहे हैं। यह सुनियोजित कार्रवाई पैसे वाले तथा अपराधी दोनों मिल कर कर रहे हैं। अपराधी इसमें समाजसेवा की शह डाल रहे हैं मानो यह कोई मिशनरी काम हो।” यहाँ शकील यह संगीत सवाल उठाते हैं कि “क्या अब समाजसेवा में भी अपराधी अनिवार्य तत्त्व होंगे?”

रामनरेश सिंह (विधायक) ने इस नका-रात्मकता में एक सकारात्मक बिंदु ढूँढ निकाला है। दहेज की सर्वस्वीकृत ठंडी समस्या पर फिर गर्मागर्म सार्वजनिक बहस उठा दी है। अपहरण विवाहों में मज्जे की बात यह है कि पहले कन्या पक्ष दहेज को कोसता था, अब की वर पक्ष दहेज पर रो रहे हैं।



पटना के एक अविवाहित युवा राजाराम पांडे अंतर्मन के कुछ सवाल उठाते हैं— जबदस्ती व्याहे गये लड़के की मन-स्थिति क्या होगी? वह अगर किसी को चाहता हो तो? अपहरण विवाह की विडंबना है कि इसमें वर के अलावा कन्या का भी जबरन उपयोग होता है. इस घुसपैठी वृह को समुराल में क्या स्वीकृति मिलेगी? गिरोह क्या उसे जिदगी भर उस

घर में टिकने की गारंटी दे सकेगा?" राजाराम उस सुहागरात की कल्पना करते हैं जिसमें पलंग पर फूल की जगह कारतूस तथा खिड़की पर लड़ी की जगह मूछलों की छाया हो.

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष नरेंद्रसिंह मुंगेर तरफ के हैं. उनका स्पष्ट कहना था कि दहेज के विरुद्ध कोई व्यापक

जनांदोलन नहीं होने से, प्रतिक्रियास्वरूप एक लहसिक अभियान ने जन्म लिया है. नरेंद्र जी ने पटलचस्प जानकारी दी कि अपहरण विवाह जाने पर अगर वर पक्ष थोपी गयी वृह फोरनस कार करने पर तैयार हो, तो कई मामलों कन्या पक्ष उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दहेज देने तैयार मिला. यहाँ दहेज विरोधी इस प्रति का वाई की असलियत और नंगी हो जाती है.

## जलते प्रश्न

### एक पिता की व्यथा कथा

ऐसे संबंधखसोट परिवारों में बेटी देने से उसे कुंवारी रखना ज्यादा अच्छा है

सिक्के का दूसरा पहलू भी है? बल्कि कहा जाये तो आज के विवाहों का सीधा पहलू यही है जहाँ संबंध-कन्यापक्ष को लूटने खाने के लिए जोड़े जाते हैं. यह संबंधखसोटी तभी समाप्त होती है जब रिश्ता खत्म कर दिया जाये. और रिश्ता खत्म का मलतव जिदगी का खात्मा होता है. दहेज और लूट का नतीजा अंततः लड़कियों की मौत में ही बदलता है. दिनमान को लिखा यह पत्र जिसे 78 फलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद से शुक्रदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपनी बेटी प्राची बाला की संदिग्ध स्थितियों में मौत के बारे में भेजा है उसी तकलीफ को प्रकट करता है पत्र इस प्रकार है :

"मेरी पुत्री प्राची बाला एम. ए. (संस्कृत) का विवाह देवराज स्वामी एम. एससी. सुपुत्र परमानंद स्वामी, कस्बा खमरिया, थाना औराई (वाराणसी) के साथ 12 मार्च 1980 को हुआ था. शादी के समय ही दहेज में पाँच हजार रुपये और एक स्कूटर की माँग की गयी थी. इस पर मैंने अपनी विवशता व्यक्त करते हुए कहा: 'मैं एक अवकाशप्राप्त कर्मचारी हूँ. आप की इच्छाओं की पूर्ति करने की मेरी सामर्थ्य नहीं.' शादी तो हो गयी और प्राची बाला अपने पति देवराज के साथ समुराल रहने लगी लेकिन उसके लोभी समुर और पति उसे सदैव प्रताड़ित करते रहते. प्राची मुझसे शिकायती लहजे में कहती कि कितने लालचियों के साथ मेरा

संबंध जोड़ दिया है. लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी गिरती आर्थिक स्थिति से अवगत करा कर समझा देता.

"नवंबर 1980 में देवराज स्वामी की नियुक्ति एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हो गयी. एक बार फिर उसने स्कूटर की माँग बलंद की. प्राची बाला के यहाँ अप्रैल 1981 को एक पुत्र ने जन्म लिया. इस अवसर पर भी स्कूटर का तकाजा हुआ.

"इस बीच एक नयी स्थिति पैदा हो गयी. देवराज स्वामी अपने कार्यालय से दो-तीन मास की छुट्टी लेकर दारागंज आ गया. उस का छोटा भाई महाराज स्वामी बी. ए. की पढ़ाई भी हमारे यहाँ रह कर करते लगा. ये लोग पूरा समय हमारे घर रहते और तरह-तरह की छानबीन करते रहते. कभी हम लोगों की नजर पड़ती तो बहाने गड़ देते. जब हम उनकी जरूरत के बारे में पूछते तो वे झर झर की हाँकने लगते और अवसर मिलते ही घर भर की तलाशी लेते. इस से मुझे और मेरे बच्चों को परेशानी होती. कभी कभी हमारे पैसे भी गायब होते. लेकिन मेहमानों पर संदेह करने से हम हिचकिचाते. देवराज और महाराज अक्सर नये नये पकवानों की फरमाइश करते रहते जिसे मैं और मेरी रुग्ण पत्नी पुरा करते थे. अक्सर उनके दूरदराज के संबंधी भी परीक्षा देने के बहाने मेरे यहाँ महीना पंद्रह दिन रुकते और अपनी फरमाइशें पूरी कराते.

"9 अप्रैल, 1982 को देवराज स्वामी अचानक दमोह से दारागंज आये. उन के आने के कुछ देर बाद उनका एक छोटा भाई लोकराज स्वामी भी आया. देवराज ने कहा कि मैंने आई. ए. एस. की लिखित परीक्षा पास कर ली है, अब तो स्कूटर दे ही दोजिए. मैंने अपनी मजबूरी बताते हुए उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश की लेकिन वह नाराज हो अपने भाइयों और अपने सारे सामान के साथ खमरिया चले गये. 19 अप्रैल 1982 को सूचना मिली कि श्रीमती प्राची बाला का

18 अप्रैल को देहांत हो गया. हम लोगों पर तो वज्रपात हुआ. किसी प्रकार खमरिया पहुँचे. वहाँ कुछ भी न था. पता चला कि बिना पोस्टमार्टम किये ही शव का दाह संस्कार कर दिया गया है. देवराज और परमानंद स्वामी के दुराचरण से पूरा खमरिया क्षुब्ध था. यह पता चला कि प्राची बाला का शव लावारिस चार-पाँच घंटे रेल पट्टी पर पड़ा रहा हालाँकि प्राची के पति, समुर, देवर सभी मौजूद थे. विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह दुघटना देवराज और महाराज के समक्ष घटी. सूचना पा कर समुर परमानंद घटनास्थल से प्राची बाला के कान की सोने की बाली, नाक की कील तथा पैरों की चप्पल उतार कर ले गये. बिना पोस्टमार्टम के तथा मायके वालों को देर से सूचना दे लाश को रातोंरात जला कर सभी प्रमाण नष्ट कर दिये गये, ऐसा क्यों?

"देवराज और उसके भाइयों में अध-राधवृत्ति का समावेश है. दूसरो का माल हुड़पना उनका स्वभाव है. पूरे गाँव में उन के किसी से मधुर संबंध नहीं. समुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अवकाश-प्राप्त प्रधानाचार्य हैं जिनकी पेंशन इस-लिए रुकी हुई है, क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने सरकारी धन में हेराफेरी की थी. परमानंद, देवराज, लोकराज, महाराज और योगिराज के व्यवहार के ही कारण उन का बड़ा पुत्र धर्मराज सपत्नीक अपने परिवार से 50 किलोमीटर दूर रहता है और छट्टियों में भी अपने घर आने के बजाय अपने समुराल जाना पसंद करता है.

"प्राची बाला को समुराल में निरंतर दहेज के लिए सभी छोटे बड़े प्रताड़ित करते थे. परमानंद स्वामी अपने लड़के को उकसाता था कि दारागंज जा कर शुक्रदेव के यहाँ रहो, वहीं खाओ और मीठ करो. मैं समाज के ऐसे कोढ़ों से दूर रहने के लिए सचेत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे कुत्सिक, घृणित परिवारों ने अपनी बेटीयों का रिश्ता जोड़ने के बजाय उनका कुंवारी रखना श्रेयस्कर है."



विश्व

फाकलैंड

## ब्रिटेन क्यों लड़ रहा है ?

ब्रिटेन है कि ब्रितानी प्रधानमंत्री मारग्रेट टैचर-की मंत्रिपरिषद ने फाकलैंड की मुहिम में सैनिकों को हुक्म दिया है कि वे इस द्वीप की राजधानी पोर्ट स्टेनले पर तुरंत हमला कर लें, जब कि आर्जेंटीना ने यह दावा किया है कि द्वीप के एक हिस्से पर काबिज ब्रितानी सैनिक अलग थलग पड़ गये हैं और उन, कपड़ों और गोला बारूद के अभाव में वे कभी भी आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। ब्रितानी सैनिक पोर्ट स्टेनले पर कब्जा कर रहे हैं या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होते हैं यह तो समय ही बतयेगा परंतु एक बात यह है कि जीत कर भी ब्रिटेन के हाथ कुछ होने वाला नहीं है। लगता है कि 1956 के क्राइमियन की तरह फाकलैंड द्वीपसमूह में वह अपनी किरकिरी ही करायेगा।

संयुक्तराष्ट्र महासचिव जेवियर पेर्रेज द द्वीप के शांतिप्रयासों की विफलता ने फाकलैंड द्वीप को गरमा दिया है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और नम में करारी झड़पें हुई हैं और घन-जन की भारी हानि उठानी पड़ी है। लड़ाई के लंबे अनुभव के बावजूद आर्जेंटीना की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यह नहीं कि वतन से 1000 मील दूर लगभग 80 युद्धपोतों के दक्षिणी अतलांतिक में पहुँचें ब्रितानी लड़ना नहीं जानते, बल्कि यह है कि द्वीप की हकूमत युद्ध के दूरगामी आर्थिक-राजनीतिक परिणामों से आतंकित है और उसने उसने ओखली में जो सिर दिया है उस किसी न किसी प्रकार साबुत वचा लेना चाहती है और इसका एक ही रास्ता है—द्वीपों के बीच समझौता। बड़े पैमाने पर द्वीपों पर समझौते की संभावना क्षीण है, यह जिही श्रीमती टैचर जानती हैं। छिट-छिट की नीति अपनाकर वह आर्जेंटीना को समझौते के लिए मजबूर करना चाहती हैं किन अभी तक उनके हाथ निराशा ही आयी है और उसके हवाबाज नौसेना की नाक बम किये हुए हैं और तब तक किये रहेंगे जब तक कि उसके हवाई अड्डों पर बमबारी न की जाय। ब्रिटेन उनको उड़ान भरने के नाकाबिल बना देता। ब्रिटेन यह कर सकता है लेकिन द्वीपों के बाद से टैचर सरकार देश-

विदेश में जिस तेजी से अपने समर्थकों को खोज रही है, उसे देखते हुए व्यापक युद्ध का जोखिम वह नहीं उठायेगा।

2 अप्रैल को जब आर्जेंटीना ने फाकलैंड (जिसे वह मालविनस द्वीपसमूह कहता है) में सेना उतारी तो विश्व के अधिसंख्य देशों ने गालतियरे की सैनिक सरकार की कार्रवाई को पसंद नहीं किया था और इसी कारण फाकलैंड विवाद संबंधी 3 अप्रैल का सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव बिना विरोध के पारित हो सका था। यहाँ तक कि जो सोवियत संघ और चीन आज खुलेआम आर्जेंटीना का पक्ष ले रहे हैं उन्होंने तब मतदान में भाग न ले कर भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। अब हवा ब्रिटेन के विरुद्ध चल निकली है। लगता है कि उद्धत राष्ट्रवाद से प्रेरित श्रीमती टैचर समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किये बिना पिछी से आर्जेंटीना को सबक सिखाने का फैसला कर बैठीं और उनका वही फैसला अब उनके गले की हड्डी बन गया है।

अब श्रीमती टैचर पर समझौते के लिए विदेशी दबाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया और इसके साथ ही देश के भीतर भी जनमानस

युद्ध विरोधी बनता जा रहा है। इसकी बानसी 'गार्डियन' में छपे पाठकों के पत्रों से मिलती है। ब्रितानी जंगी जहाज 'शेफील्ड' के डूबाये जाने पर बेकंशायर के जॉन आर. शॉर्ट ने, जिनके भाई शेफील्ड पर तैनात थे और मौत का शिकार बने, लिखा है : "इस देश में चंद लोगों को छोड़ कर किसी को भी फाकलैंड की परवाह नहीं है। हमें द्वीपवासियों की चिंता हो सकती है लेकिन विवाद छिड़ने के पहले तो हमारी नीति इस द्वीपसमूह को आर्जेंटीना को सौंपने की ही थी। कब सौंपा जाये बस इतना तय होना था। इस में देर की जिम्मेवारी विदेशमंत्रालय पर है।

"जंगी वेड़ा नहीं भेजा जाना चाहिए था... जंगी वेड़ा भेज कर हमने न केवल अपनी व्यूहरचना का लचीलापन खोया बल्कि विश्व जनमत भी गँवाया। इसकी जिम्मेवारी कुछ ब्रितानी लोगों पर भी है। हाउस आफ कॉमंस में तो अनेक उन्मादित सांसदों ने खून की नदी बहाने की माँग तक कर डाली। मेरा भाई रोमांच सुख तथा भ्रमण के अवसर से प्रेरित हो कर और काम न मिलने की मजबूरी के कारण सेना में भरती हुआ था। वह श्रीमती टैचर की घरेलू आर्थिक नीतियों और विदेश

## यह विरोध दर्ज करना चाहता था

फाकलैंड समस्या पर लंदनवासी मार्गरेट टैचर की गार्डियन में प्रकाशित निम्नांकित टिप्पणी ब्रितानी सरकार की मानसिकता का पर्दाफाश करती है:

ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती टैचर को देश के अधिसंख्य लोगों का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले कि मामला रफा-दफा हो मैंने सोचा उनकी फाकलैंड नीति का विरोधी होने के नाते मैं भी कुछ कहूँ, भले ही वह बेअसर रहे। मैंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट का नंबर घूमाया दूसरी ओर सचिव महोदय फोन पर आये। बातचीत इस प्रकार हुई :

मैं : मैं सरकार की फाकलैंड नीति के प्रति अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूँ।

सचिव : क्षमा करें, मैं ऐसा कोई संदेश नहीं ले सकता हूँ। कृपया प्रधानमंत्री को लिखिए।

मैं : मैं लिख चुका हूँ फिर भी समर्थन देने वाले संदेशों के विरुद्ध मैं तुरंत अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूँ, बस।

सचिव : खेद है कि मैं आप का संदेश नहीं ले सकता। कृपया अपना विरोध लिख भेजें।

मैं : यदि मैं श्रीमती टैचर का समर्थन

करता तो क्या आप मेरा संदेश ले लेंगे?

सचिव : हमारे पास संदेशों का अंवार है। आप भी लिख भेजें।

मैं : तो आप श्रीमती टैचर को यह जानकारी नहीं मिलने देंगे कि जनता में कम से कम एक व्यक्ति तो इस लड़ाई के विरुद्ध है? आपको मालूम है कि वह मेरी ओर से युद्ध का निर्णय ले रहा है, और इसलिए मैं अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूँ।

सचिव : आप को लिख कर ही भेजना होगा।

दस मिनट बाद मैंने फिर फोन किया। मैं आवाज बदल कर बोला : मैं फाकलैंड विवाद को ले कर प्रधानमंत्री टैचर को बधाई देना चाहता हूँ।

सचिव : क्यों नहीं, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री इस प्रकार के संदेश को पा कर बहुत प्रसन्न होंगे।

सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी। मुझे एक वर्ष पूर्व देखे मोन्टी पायथोन के प्रदर्शन की याद आयी जिस में 'चतुर राजा ओट्टो' के साम्राज्य का चित्रण था। ओट्टो राजा के साम्राज्य में सभी लोग खुश थे क्योंकि 'सभी नाखुश लोगों को गोली से उड़ा दिया गया था'। फाकलैंड के मामले में भी जो लोग नाखुश हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है।



नीति का धिकार बना—आर्हेतीना और ब्रितानी परिवारों की पीड़ा वैयक्तिक पीड़ा से कहीं अधिक है—वह यह बताती है कि समस्या के सैनिक समाधान नहीं होते, अंततः मानवीय सत्य ही जीवन है।”

इसी तरह आर्हेतीनी ओस्वाल्डो लुई लेरिन ने इसी समाचारपत्र में लिखा है : “मैं आर्हेतीनी हूँ और ब्रिटेन में रह चुका हूँ और मेरे ब्रितानी मित्र हैं, मेरे विचार में दोनों देशों में वहाँ के लोगों के बीच युद्ध ही सबसे बुरी बात हो सकती है, अपने किसी प्रिय को गैरानि से हुई क्षति को पूरना बहुत कठिन काम होता है।” सचमुच हर लड़ाई का परिणाम दुःखद होता है।

फाकलैंड की लड़ाई ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, आर्हेतीना में उन्हें इसलिए सताया गया कि वहाँ की सरकार और लोगों को उनकी नीति पर शक था और ब्रिटेन में इसलिए कि उन्होंने सच कहने की जुर्रत की, उदाहरणार्थ, अमेरिकी दूरदर्शन संवाददाता क्रिस्टोफर जॉस को आर्हेतीनी विदेशमंत्रालय के बाहर से कार में उठा लिया गया और तीन घंटे तक जलील करने के बाद उनकी नकदी और कपड़े छीन कर कार से धकेल दिया गया, दिनदहाड़े यही गति ब्रितानी दूरदर्शन दल की बनायी गयी, इस दल के तीन सदस्यों को भी विदेशमंत्रालय के कार्यालय के सामने से उठा लिया गया और शहर से 30 मील दूर धूल भरी सड़क पर नंगा छोड़ दिया गया, तीन ब्रितानी पत्रकारों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया।

इधर ब्रिटेन में पत्रकारों को दूसरे तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, उन पर आरोप है कि वे तटस्थ रह कर और कभी कभी घटनाओं के बारे में आर्हेतीना द्वारा दिया गया विवरण प्रस्तुत करके सरकार को नीचा दिखाते हैं, ब्रितानी सांसद जॉन पेग का आरोप है कि बी. बी. सी. ‘यदि हम ब्रितानी अधिकारियों पर विश्वास करें—’ जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करता है, स्वयं श्रीमती टैचर का कहना है : ‘मझे अनेक बार ऐसा लगा कि हमें और आर्हेतीना को लगभग समान माना जाता है,’ यानी आर्हेतीना को घमकाने के लिए ब्रिटेन ने जो कदम उठाया उसने अंततः युद्ध-कालीन स्थिति पैदा कर दी है और जैसा कि युद्ध में होता है, फाकलैंड विवाद से संबद्ध सभी पक्ष सहज मानवीयता छोड़कर, राष्ट्रवाद के उन्माद में डूब गये जान पड़ते हैं, स्थिति इतनी अधिक उलझ गयी है कि शीघ्र ही इस विवाद का अंत होता दिखाई नहीं पड़ता, सं. रा. सुरक्षा परिषद छह दिन विचार-विमर्श करके महज इस नतीजे पर पहुँची कि महासचिव समझौता कराने का एक प्रयास और करें।

चिनमोन

चीन-अमेरिका

## पुराने मित्र को मँझधार में नहीं छोड़ेंगे

ताइवान को हथियार देने के प्रश्न पर अमेरिका और चीन के बीच पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा है जिसे तय करने के सिलसिले में अभी पिछले दिनों अमेरिकी उपराष्ट्रपति जार्ज बुश पीकिङ्ग में थे, दो दिन की अपनी इस संक्षिप्त यात्रा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने चीनी नेताओं से ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न पर लंबा विचार विमर्श किया, लेकिन प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच इस प्रश्न पर मतभेद दूर नहीं हुए हैं, चीन के अनुरोध पर पिछले काफी समय से रीगन प्रशासन ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई तथा हथियारों के पुर्जें आदि देना स्थगित कर रखा है लेकिन रीगन प्रशासन ने चीन की यह बात बिल्कुल भी नहीं मानी है कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक देने की अंतिम तारीख निश्चित कर दे, राष्ट्रपति रीगन ने अपने पद का कार्यभार संभालते ही ताइवान को अमेरिकी समर्थन मिलते रहने का वायदा कर दिया था, संभवतः चीन का यह अनुरोध अमेरिकी वायदे के खिलाफ है इसलिए अमेरिका इसको मानेगा भी नहीं।

ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न को लेकर चीन और अमेरिका के मतभेद भले ही कम न हुए हों लेकिन चीनी नेताओं ने राष्ट्रपति रीगन के इस अनुरोध पर तो सहमति दिखायी ही है कि सोवियत सहयोग होना चाहिए, इस आशय का अनुरोध राष्ट्रपति रीगन ने चीनी नेताओं के नाम अपने तीन पत्रों में किया जो उपराष्ट्रपति जार्ज बुश अपने साथ पीकिङ्ग ले गये थे, राष्ट्रपति रीगन ने यह पत्र चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष श्री देङ्ग और प्रधानमंत्री श्री जियाङ्ग और पार्टी अध्यक्ष श्री हुआ के नाम लिखे थे, श्री हुआ का चीनी नेताओं से कहना है कि सोवियत संघ दोनों देशों और समूचे विश्व के लिए खतरा है इसलिए अमेरिका और चीन में सहमति होनी चाहिए और दोनों के बीच सहयोग और बढ़ना चाहिए, श्री रीगन ने अपने इन पत्रों में विश्वास व्यक्त किया है कि इस प्रश्न पर सहमति को रखते हुए दोनों



जार्ज बुश

देशों के बीच मतभेद वाले अन्य सवाल सकते हैं, जहाँ तक ताइवान को हथियारों की सप्लाई का संबंध है, रीगन ने बड़ी चतुराई से इस प्रश्न को उनका कहना था कि अगर दोनों देशों एक दूसरे के प्रति विश्वास हो तो मतभेदों को दूर किया जा सकता है, समस्या का समाधान भी ढूँढ़ा जा सकता है, लेकिन श्री रीगन ने अपने पत्र में अमेरिका चीन संबंधी नीति को तो स्पष्ट कर ही है, उन्होंने साफ कह दिया है कि एक ही है और हम चीन की इस बात को हैं कि शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान मुख्यभूमि के साथ मिल जाये तो अमेरिका दोनों पक्षों की बातचीत के प्राप्त समाचारों से यही पता चलता है, दोनों देशों के बीच मतभेद का मुद्दा तहाँ है, दो दिन की अपनी चीन यात्रा समाप्ति पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति इतना ही कहा कि हमें आशा है कि के प्रश्न पर दोनों देशों के बीच समस्या समाधान हो सकता है, श्री जार्ज बुश में आतिथ्य सत्कार की चीन की संतुष्ट थे, अपनी यात्रा को एक बड़ी मान कर जार्ज बुश ने इतना ही कहा कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है, अमेरिकी राष्ट्रपति की इस महत्वपूर्ण यात्रा अमेरिका की चीन संबंधी नीति के इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं जाहिर है कि यह सब तो राष्ट्रपति रीगन की जानकारी मिलने के बाद ही स्पष्ट उनका कहना था कि ताइवान को सप्लाई के प्रश्न पर चीन से आगे बातचीत होगी।

बातचीत आगे चाहे जितनी भी हो ताइवान के बारे में श्री रोनाल्ड रीगन घोषणा पर तो जमा ही रहेगा कि पुराने मित्र को मँझधार में नहीं छोड़ेंगे, चीन भी ताइवान के बारे में अपनी नीति को छोड़ने वाला नहीं है, स्पष्ट है और चीन अपने मतभेदों को दूर करने के लिए प्रतिष्ठा बचाने जैसा कोई निकालने की कोशिश में ही रहेंगे।

बंगलादेश

## जनरल इरशाद के इरादे क्या हैं?

जनरल इरशाद ने 24 मार्च को सैनिकों के द्वारा सत्ता हथियाने के साथ देशवासियों को आश्वासन दिया था कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद



धर्मयुद्ध तो नहीं छिड़ा, आतंक पैदा करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई अलवत्ता की गयी और इस समय नौ मंत्री भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ करने के आरोप में तजरबंद हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने में अपनी विफलता को यह कह कर अलवत्ता नहीं छिपाया कि भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है, क्यों कि यह कह कर वह भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहन ही दे रहे होते। सत्तारूढ़ होने के लगभग दो महीने बाद सत्ता पर उन्हें अपने वायदे की याद आयी और उनकी सरकार ने देश के सभी राजनैतिक दलों और उनसे संबद्ध संगठनों के बैंक खातों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही जिन भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध मुकद्दमे चल रहे हैं या जो भूमिगत हैं उनके बैंक खाते जब्त करने का आदेश भी दिया गया है। इस सिलसिले में गठित पाँच सदस्यीय सैनिक अदालत ने ढाका के भू.पू. महापीर और लोकनिर्माणमंत्री अबुल हसनत को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख टका जुर्माना भरने की सजा भी सुना दी है। सरकार को इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार तो क्या मिटेगा, वह कुछ करती हुई अलवत्ता जान पड़ेगी।

गले तक भ्रष्टाचार में डूबे राष्ट्र को उबारने में जनरल इरशाद की दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन उससे अधिक उनकी दिलचस्पी अपनी छवि निखारने में है। सत्ता सँभालने के बाद उनकी जो छवि सामने आयी है वह प्रायः पाकिस्तान समर्थक और पश्चिमी गुट से प्रभावित शासक की है। उनके सलाहकारों में जो प्रमुख नाम हैं उनमें अधिसंख्य वे हैं जो बंगलादेश के मुक्ति संग्राम के विरोधी थे। उदाहरणार्थ, जन. इरशाद ने जित मेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) एम. ए. करीम को अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त किया था और जिन्होंने कुछ दिन बाद ही पदत्याग कर दिया वह बंगलादेश (तब पूर्वी पाकिस्तान) में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बावजूद पश्चिमी मोर्चे पर पाक सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अन्य सलाहकार मेजर जनरल अमीनूल इस्लाम, सैफुल आजम, वाइस एयर मार्शल (अवकाशप्राप्त) ए. जी. महमूद और अबू बकर भी इसी श्रेणी में आते हैं। जनरल इरशाद ने बंगलादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े ए. एम. ए. सलाहकार परिषद् में शामिल कर के एक संतुलन बनाने की कोशिश अवश्य की है। लेकिन कुल मिला कर उनकी सरकार का जो स्वरूप सामने आया है वह उनकी इस कोशिश को झुल्लाता ही है।

इसी तरह परिषद् का संविधान भले ही यह संकेत देता हो कि जनरल इरशाद का प्रशासन किसी बस या उस अंतरराष्ट्रीय शक्ति से नहीं चलाया है वह उन्हें पाकिस्तान के भूत-पू.पू. की

पूर्व राष्ट्रपति अय्यूब ख़ाँ के समकक्ष खड़ा कर देने हैं।

जनरल इरशाद ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का आश्वासन दिया है और उसके कुछ कदम उठाने की घोषणा की है। इस समय देश में लागू मंडल-उपमंडल की प्रशासनिक व्यवस्था को थाने के स्तर तक विकेंद्रित करने का उनका इरादा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संसत्सदस्य को थाना मुख्यालय पर अपना कार्यालय खोलना होगा और उस पर अपने क्षेत्र के समग्र विकास और आयोजन की जिम्मेवारी होगी। जनरल इरशाद यह मानते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से नियोजित विकास का लाभ ग्राम स्तर तक पहुँचाया जा सकेगा। वह एक कदम यह भी उठाना चाहते हैं कि किसी डॉक्टर को पंजीकृत तभी किया जाये जब वह पाँच वर्ष तक गाँवों में चिकित्सा कार्य कर चुका हो। उन्होंने सह-कारी खेती का प्रस्ताव भी किया है, लेकिन इसे लागू करने से पहले वह संभवतः इस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे। वह यह भी चाहते हैं कि हर थाने में एक औषधालय, एक परिवार नियोजन केंद्र और एक न्यायिक व्यवस्था हो। जनरल इरशाद का यह प्रस्तावित कार्यक्रम अय्यूब ख़ाँ के बेसिक लोकतंत्र या जियाउर्रहमान के ग्राम सरकार के सपने से भिन्न नहीं है।

संभवतः जनरल इरशाद यह जानते हैं कि सेना के बल पर अधिक समय तक शासन नहीं किया जा सकता। उसके लिए राजनैतिक आधार की जरूरत होगी और उनका प्रस्तावित कार्यक्रम उसी दिशा में किया जाने वाला एक प्रयास है। उनकी एक कोशिश यह भी है कि विभिन्न राजनैतिक दलों में उनकी ही तरह सोचने वाले जो लोग हैं उन्हें एक मंच पर इकट्ठा किया जाये। इस सिलसिले में उन्होंने अवांसी लीग के उन लोगों से संपर्क किया है जो पश्चिम के समर्थक हैं। फिर भी, अभी यह कहना संभव नहीं है कि जनरल इरशाद देश में किस तरह की राजनैतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, सिवाय इस के कि फिलवक्त उनका रुझान पश्चिमी गुट और पाकिस्तान के समर्थन का है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा और भारत के लिए एक दिन वह स्थिति भी आ सकती है जो 16 दिसंबर, 1971 से पूर्व थी।



जनरल इरशाद

## सोवियत संघ-पाकिस्तान

### बातचीत का दरवाजा आखिर खुला

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को लेकर रूस और पाकिस्तान में पिछले काफी समय से जो तनाव चला आ रहा था वह अब समाप्त होता नज़र आता है। पाकिस्तान से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि सोवियत संघ ने बातचीत के लिए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को मस्क्वा आने का निमंत्रण दिया है। यह खबर समाचार एजेंसियों ने इस्लामाबाद स्थित सोवियत संघ के राजदूत के हवाले से ही दी है। इधर रेडियो पाकिस्तान ने भी इस खबर की पुष्टि की है। लेकिन पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचारपत्र 'नवाये वक्त' का कहना है कि सोवियत संघ ने विदेशमंत्री साहबजादा याकूब ख़ाँ को ही मस्क्वा आमंत्रित किया है।

मस्क्वा में रूस और पाकिस्तान के बीच मुख्यतः अफगानिस्तान संकट पर ही बातचीत होगी। लेकिन अन्य क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद स्थित सोवियत राजदूत के हवाले से ही ये खबरें भी मिली हैं कि सोवियत संघ पाकिस्तान और उस के पड़ोसी देशों के बीच विवाद को बातचीत द्वारा तय करने के ही पक्ष में है। पर सोवियत संघ का जोर इस बात पर भी है कि राजनैतिक समाधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। अभी पिछले दिनों सोवियत विदेशनीति पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान स्थित सोवियत राजदूत ने कहा था कि सोवियत संघ से लगने वाली पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों का सामान्य रहना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान की भी इस में पूरी दिलचस्पी है। पर सोवियत राजदूत ने अफगानिस्तान के मामले को लेकर यही बात दोहरायी कि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएँ वहाँ की बबरक करमाल सरकार के निमंत्रण पर ही मौजूद हैं। अगर अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप खत्म हो जाता है तो सोवियत सेनाएँ वहाँ से हटायी भी जा सकती हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ियाउलहक अफगानिस्तान से बिना शर्त सोवियत सेनाओं के हटने की माँग शुरू से ही करते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में लाखों अफगानियों के शरणार्थी हो कर पाकिस्तान चले आने की चर्चा भी कई बार की है। पर उन्होंने यह भी कहा है कि संयुक्तराष्ट्र और गुटनिरपेक्ष देशों के सुझावों के अनुसार ही समस्या का राजनैतिक समाधान निकल सकता है। इस के लिए सोवियत सेनाओं का हटना बहुत जरूरी है। उधर सोवियत संघ पाकिस्तान को अमेरिकी



हथियारों के मिलने का विरोध करता रहा है। और बराबर कहता रहा है कि अमेरिकी सहायता से इस क्षेत्र में विल्कुल नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। दोनों देशों के इस रवैये को देखते हुए पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच बातचीत की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना है।

**अफगानिस्तान के आरोप:** अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी पिछले दिनों पाकिस्तान स्थित सोवियत राजदूत को उनकी काबुल यात्रा के दौरान पाकिस्तान में कुछ विद्रोही छापामारों के कोई 80 प्रशिक्षण केंद्र होने के बारे में प्रमाण पेश किये थे। अफगानी प्रधानमंत्री

का कहना था कि इन केंद्रों से अफगानिस्तानी प्रदेश पर बराबर हमले होते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र होने की बात से इनकार किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा सोवियत संघ से बराबर अपनी इस समस्या का जिक्र करता रहा है कि जब से अफगानिस्तान में बबरक करमान की सरकार आयी है अफगान शरणार्थियों के रूप में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्हें वापिस बुलाने के लिए बराबर करमाल से कहा जा रहा है। पर उन्होंने एक नहीं सुनी। पता चला है पाकिस्तान स्थित सोवियत राजदूत ने पाकिस्तान की इस समस्या

को ध्यान में रख कर ही पाकिस्तान सोवियत संघ के बीच प्रस्तावित बातचीत व्यवस्था की है। फिर भी रूस का यही कहना कि समस्या पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि विकासशील देशों के सहयोग से ही ठीक सकती है। पाकिस्तान के सीटों और सैनिक संघियों से अलग होने और गुटनि आंदोलन में शामिल होने को भी सोवियत बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है और संभवतः लिए सोवियत संघ ने पाकिस्तान को बातचीत का निमंत्रण दिया है। सीधे बातचीत का प्रस्ताव अफगानिस्तान संकट के समाधान दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## अफगानिस्तान

### उन्हें सशस्त्र क्रांति की आदत हो गयी है

**ढाई** वर्ष पहले सोवियत कब्जे के बाद से अफगानिस्तान लगातार चर्चा का विषय रहा है। उस के भौगोलिक और सामरिक महत्व को ले कर इस बीच व्यापक चर्चा हुई है लेकिन जनजीवन के बारे में जानकारी की प्रायः उपेक्षा ही की गयी है। नागपुर के विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग में वास्तुशास्त्र के प्राध्यापक अशोक छत्रे तीन साल में अफगानिस्तान की तीन सशस्त्र क्रांतियां देख कर लौटे हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं उनके अनुभव जो अफगानिस्तान के आम आदमी की जिंदगी पर प्रकाश डालते हैं:

अफगानिस्तान की प्रत्येक क्रांति रक्त-रंजित होती है तथा नया शासक अपने पूर्ववर्ती शासक का नामोनिशान तक मिटा देने की कोशिश करता है। अफगानों को सशस्त्र क्रांति की आदत उसी तरह हो गयी है जैसे कि भारतीयों को आये दिन मोर्चों की क्रांतिकाल में चारों ओर फौजी हलचल अवश्य होती है किंतु वहाँ के आवागमन तथा जनजीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता।

अशोक छत्रे ने बताया कि अफगानों को मास्त स्वर्ग के समान दिखायी देता है, उन्हें भारतीय फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी संगीत की महफिलें भारतीय महफिलों जैसी होती हैं तथा अनेक गीतों की लय तथा बोल तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन की यात्री 'गोवर्ध' और 'पोवाड़े' के समान होते हैं।

अफगानिस्तान का क्षेत्रफल महाराष्ट्र से सवा दो गुना है किंतु आबादी एक करोड़



क्रांति का शिकार एक अफगान परिवार

75 लाख ही है। कारखाने नहीं के बराबर हैं। देश इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि उसे दियासलाई तथा गोंद तक का आयात करना पड़ता है। वहाँ अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं को कोई नहीं समझता। वे पशतों और फारसी जानते हैं। इस लिए परदेशी को कुछ दिनों तक काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अफगानिस्तान में दायीं ओर चलने का नियम है तथा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था अपर्याप्त होने से वहाँ गंदगी बहुत फैली रहती है। वहाँ छह महीने कड़ी ठंड पड़ती है। इस लिए अधिसंख्य लोग उन दिनों नहाते नहीं हैं। गरीबों के घरों में स्नानगृह नहीं हैं, लेकिन सावजनिक हमामघर काफी हैं। वे रोटियां जेब में रख लेते हैं तथा चार-चार दिनों तक उन्हें खाया करते हैं। अफगान हर जानवर का मांस

खाते हैं। बगैर मांस के भोजन को कल्पना भी नहीं कर सकते। मांस से जो चर्बी बड़ जाती है उसे बगैर दूध चीनी की चाय दिन में कई बार पी कर खाने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान के अनेक व्यक्ति भारतीयों के समान दिखायी पड़ते हैं। किंवदंती है कि वे औरतों से उत्पन्न संतान हैं जिन्हें अश्व ग्राह अन्धाली पानीपत के युद्ध के बाद देश ले गया था।

श्री छत्रे के अनुसार अफगानिस्तान अमीरी और गरीबी का भेद बहुत कम तथा व्याज लेना उनके धर्म के अनुनिषिद्ध है। वहाँ के पठानों की तुलना में वैसे उन पठानों से नहीं की जा सकती जो व्याज बसूल करने के लिए कर्जदा छाती पर चढ़ बैठते हैं। व्याज निषिद्ध के कारण बैंक व्यवसाय दूसरों के हाथ में है। अफगानिस्तान में चोरी और लूट के साथ छेड़खानी नहीं होती। युवतियाँ बिना किसी डर के बिरात बेधड़क बाहर आती जाती स्त्रियाँ नखशिख परिधान पहनती अंग प्रदर्शन विल्कुल नहीं करतीं। नया में भी पश्चिमी वेशभूषा तथा पूर्वी अंग संगम है। बेटी के जन्म पर खुशी जाती है क्योंकि विवाह के अवसर लड़कियों की कीमत डेढ़ से दो लाख तक होती है। एक पुरुष अधिकतर औरतों के साथ शादियाँ कर सका अत्र यह प्रथा कम होती जा रही है।

अफगानिस्तान के शासकीय काम सुबह आठ बजे से दोपहर साढ़े चार तक खुले रहते हैं। कर्मचारियों को काम की ओर से ही भोजन मिलता है। आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था की है। किंतु उन्हें वेतन कम ही मिलता है। निजी व्यवसाय नहीं है तथा उसे प्रोत्साहित भी नहीं करती।



## निया भर की



जोन क्रोहन पुलिस की गिरफ्त में

### पर हमला

एक वर्ष पहले वैटिकन के सेंट पीटर की चौक पर कैथोलिक धर्मगुरु पोप जॉन पॉल दूसरे का एक हत्यारे के हाथों से बाल बाल बचने की उसी समय उन्होंने मन में ठान ली थी कि इस घटना के एक वर्ष बाद वह मध्य पुर्तगाल के धर्मस्थल आवर लेडी ऑफ फ्रातिमा यात्रा करेंगे, अपना वचन पूरा करने के लिए 13 मई को पोप पॉल पुर्तगाल आये, जहाँ इस वार भी 32 वर्षीय स्पेनवासी जोन क्रोहन ने उन की जान लेने की कोशिश की। स्पेनी पादरी के लिबास में सज्जित होने पर पोप को खड़ा करने के लिए आगे बढ़ा, जोन क्रोहन ने स्वीकार किया कि पोप को छुरा कर मारने के लिए ही वह पेरिस से, जहाँ वह रहता है, पुर्तगाल आया था। पोप को छुरा मारने के बाद ही वह भाग निकला। पोप को छुरा मारने के बाद ही वह भाग निकला। पोप को छुरा मारने के बाद ही वह भाग निकला।

### हीरा नहीं चाहिए

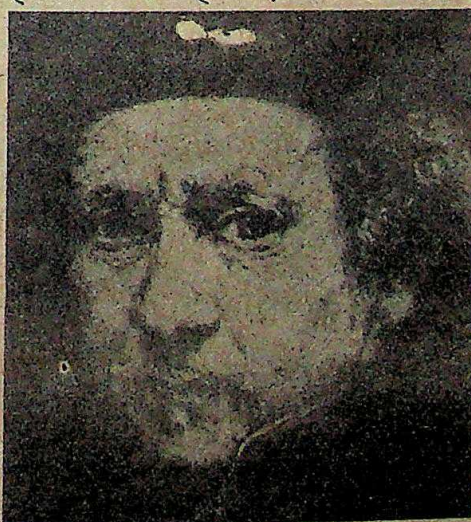
निया के हीरों में पाँचवाँ स्थान रखने वाले हीरा 'डी बीअर्स' को जब नौलामी के लिए रखा गया तो उस नामालिक को यह देख कर निराशा हुआ कि इस हीरे के खरीददार उसे आशा के अनुसार नहीं देना चाहते। 32 लाख 50 हजार रुपए की अधिकतम बोली लगने के बाद इस हीरे को नौलामी पर से हटा लिया गया और हीरे को खरीदने वालों के लिए अब व्याज की दर 1888 में दक्षिण अफ्रीका के हीरे की कीमत से प्राप्त हुआ था और साल भर बाद हीरे की एक नमूनायश में प्रदर्शित किया गया। अनुमान है कि उस के बाद वह किसी परिवार की संपत्ति में शामिल कर लिया गया था और 10 वर्ष तक एक तिजोरी में बंद रहा। नौलामी की असफल चेष्टा के बाद अब 'डी बीअर्स' को पुनः उसी तिजोरी में वापिस रख दिया जायेगा।

### आसमानी जासूस

अप्रैल 2 को आर्जेंटीना द्वारा फॉकलैंड पर कब्जा किये जाने के समय महाशक्तियों ने उस इलाके में होने वाली सामरिक गतिविधियों की टोह लेने के लिए कई उपग्रह छोड़े। इस घटना के ठीक दो दिन पहले दो रूसी उपग्रह काँसमास 1345 और 1346 अंतरिक्ष में पहुँचे। उस के बाद से इस देश के छह और उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा चुके हैं। अमेरिकी उपग्रहों की तुलना में रूसी उपग्रहों की मियाद कम होने की वजह से रूस को अधिक संख्या में अपने उपग्रह भेजने पड़ते हैं। इस के विपरीत अमेरिका के उपग्रह ऐसे बनाये जाते हैं कि वे महीनों और कभी कभी सालों तक अंतरिक्ष में टिक सकते हैं। इस समय रूस के छह उपग्रहों के मुकाबले अमेरिका के केवल दो उपग्रह दक्षिण अतलांतिक पर चक्कर काट रहे हैं।

### रेंब्राँ की असली/नकली कलाकृति

अमेरिका में होने वाले विश्व मेले के अवसर पर 17 वीं शताब्दी के डच चित्रकार रेंब्राँ के जिस चित्र का अनावरण किया जाएगा उस के असली होने के बारे में कला विद्वानों को, ऐन मौके पर, शक होने लगा है। इस चित्र में, जिस की कीमत 90 लाख डॉलर आँकी गयी है, दोबारा जीवित होने वाले ईसा मसीह पर उन के शिष्य थॉमस के संदेह की कहानी चित्रित है। इसी तरह का एक चित्र मस्क्वा के पुश्किन संग्रहालय में भी है, जिसे रूसी अधिकारी असली मानते हैं। लेकिन विवादास्पद चित्र को विश्व मेले में भेजने वाले कला एजेंट विलियम-मैन हार्ट का विश्वास है कि एक विषय पर बनाये



रेंब्राँ : अपनी नज़र में

गये ये दोनों ही चित्र असली हैं। इस चित्र को 1978 में पोलस्का के रहने वाले फ्लोरियन ब्रजोस्की अमेरिका लाये थे, जिन्होंने मरने से पहले दावा किया था कि उन्होंने उसे एक यूरोपीय गैरराज में विक्री के लिए प्रदर्शित वस्तुओं में से चुना था।

चित्र के रंगों और चौखटे को देख कर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यह रेंब्राँ के जमाने में, 1630 के आसपास, बनाया हुआ चित्र है।

### बूढ़े प्रेम न करे

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने उन सभी पतियों को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है जो भारत और पाकिस्तान जैसे गरीब देशों के माता पिताओं को मोटी रकम देकर उन की बेटियों से शादी करने के लिए उन्हें खरीद लेते हैं। गत तीन वर्षों में यहाँ की सरकार के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आयी हैं कि 60 वर्ष के बूढ़े ने 15 वर्ष की किशोरी से ब्याह रचाया है। पति पत्नी की उम्र में फर्क को देखते हुए सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि ऐसे दंपतियों के विवाहित जीवन कभी स्वाभाविक नहीं हो सकते, इस लिए उन से सामाजिक बुराईयाँ पैदा होती हैं। फिर 'नयी' पत्नी को उस से भी 'नयी' पत्नी के लिए तलाक़ दे देने के मामले भी सामने आये और बहुत से पति छोड़ी हुई विदेशी स्त्रियों को उन के देश वापिस भी नहीं भेज पाये। इस लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार इस प्रस्ताव पर गौर कर रही है कि विदेशी पत्नी रखने का जोखिम उठाने वाले को, निकाह से पहले ही, नयी पत्नी के हाथ में ढाई लाख रुपये थमा देने पड़ेंगे।

### तूतनखामन की मौत का कारण

प्राचीन मिस्र के किशोर राजा तूतनखामन की मृत्यु के कारण के बारे में मिस्र के पुरा-तत्त्वविदों ने एक नया सिद्धांत पेश किया है। यहाँ के समाचारपत्र 'अल जम्हूरिया' के अनुसार जाने माने पुराविद अहमद अब्दुल हमीद युसुफ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तूतनखामन स्वाभाविक मौत नहीं मरे, बल्कि सिर पर आघात किये जाने से उनकी मृत्यु हुई।

### खून का विकल्प

अमेरिकी सेना के चिकित्सकों ने संशोधित रासायनिक हेमोग्लोबिन (रक्त को रंग देने वाला तत्व) से खून का एक ऐसा विकल्प तैयार किया है जिस के रहते अस्पतालों को रक्त जमा कर के रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तरल पदार्थ के रूप में यह बहुत ठंड के बिना भी 10 दिन तक ठीक रहता है और ठंडक से सुखाये जाने पर इसे, कमरे के तापमान में, छह महीने रख जा सकता है। □



**भारतीय** हॉकी की इतनी खस्ता हालत शायद ही पहले कभी देखी गयी हो। अमी क्रिकेट टीम के चयन को ले कर उठे विवाद शांत भी नहीं हुए थे कि हॉलैंड में चैंपियंस कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भेजी जाने वाली भारतीय टीम के चयन को ले कर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। यह हंगामा अचानक नहीं हुआ था क्योंकि पिछले कई महीनों से भारतीय हॉकी संघ के तथाकथित घोटालों की जाँच की माँगें सामने आती रही हैं। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष इंदर मोहन महाजन को लगता है इस बात की फिक्र कम है कि हॉकी की हालत बेहतर कैसे बनायी जाये और वह इस बात को ले कर अधिक परेशान नजर आते हैं कि विदेशी टीमों का मनोरंजन कैसे हो और विदेश यात्रा के मोके कैसे निकाले जायें।

भारतीय हॉकी के सचमुच बुरे दिन हैं। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि भारतीय टीम इधर कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में इस लिए नहीं अच्छा खेल पायी कि उसे एस्ट्रो टर्फ ('कृत्रिम घास') पर खेलने का अभ्यास नहीं है। एशियाई खेलों को ध्यान में रख कर नयी दिल्ली में एस्ट्रो टर्फ बिल्डवाने की व्यवस्था किसी तरह से हुई भी तो भारतीय हॉकी का दुर्भाग्य है कि



सुरिंदरसिंह मोदी : नये कप्तान

चैंपियंस कप के लिए जाने वाली टीम को अभ्यास करने के लिए जो थोड़ा समय मिला था वह और भी थोड़ा हो गया। एस्ट्रो टर्फ विछवाने का ठेका एक अमेरिकी कंपनी मोसांटों को दिया गया था। प्रगति मैदान के हाल नं. 1 में बैठे एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अधिकारी चारों तरफ अभी एस्ट्रो टर्फ के गुणगान ही कर रहे थे कि अचानक पता चला कि विदेशी कंपनी के कर्मचारी अधुरा सा काम छोड़ कर बिना किसी को

बताया सुबह तीन बजे ही भाग  
 किसी तरह से इस कंपनी को  
 भिजवा कर काम चलाऊ व्यवस्था  
 और इस तरह से एस्ट्रो टर्फ भी अ  
 मौजूद है। देखना है कि आरोपों  
 का बुरी तरह से शिकार भारतीय  
 वाले दिनों में कितने कम गोलों से  
 यह सही है कि मुरजीत सिंह की क  
 सामने आयी जब वह लगभग एक  
 खिलाड़ी साबित हो चुके थे। भा  
 संघ की गड़बड़ियों पर उत खिल  
 बराबर नजर रखनी चाहिए जो  
 चुके हुए खिलाड़ी न हो कर चुने  
 हों। फिलहाल तो बड़े बड़े नामी पुरा  
 भारतीय हॉकी की मौत और उस  
 वीमारियों की चर्चा कर रहे हैं। क  
 तीय कप्तान और फुल बैक खिला  
 सिंह ने सरकार की खामोशी प  
 व्यक्त करते हुए कहा है : अगर कोई  
 अप्पेशन नहीं किया गया तो यह बी  
 में बदल कर देश में हॉकी की मृत्यु  
 सवाल यह है कि खिलाड़ी क  
 अधिकारी, शायद इन दोनों के  
 रचनात्मक संबंध स्थापित किए बि  
 हॉकी को स्वस्थ हालत में लाना अस

चैंपियंस कप की समिति के उपाध्यक्ष कमांडर नंदी सिंह का कहना है "जो माल उपलब्ध था उस में से इस से बढ़िया और कोई चुनाव हो ही नहीं सकता था."

65 करोड़ की आबादी वाले देश में साल की कमी वाली बात कुछ खटकती है?

जनसंख्या से ही सभी कुछ नहीं आँका जा सकता। चीन दुनिया की सब से ज्यादा आबादी वाला देश है लेकिन पदकों की सूची में उस का नाम ऊपर नहीं रहता। इस क्षेत्र में यूरोप के छोटे छोटे देश जैसे पूर्व जर्मनी ही सूची तालिका में ऊपर होते हैं। सवाल यह है कि आबादी का खेलकूद के प्रति किस प्रकार का झुकाव है।

हस का आप क्या कारण मानते हैं?  
आर्थिक पिछड़ापन. आप यूरोप की  
तरफ से अति हल्के स्वेज नहर पार कर  
जाइए पदकों की संख्या घटती चली  
जायेगी.

जब हाँकी में हम शिखर पर थे तब हमारी  
गिनती अमीर देशों में तो नहीं थी?

तब खेल के प्रति झुकाव था, आस्था थी। तब उत्तर के लोगों में जो जज्बा था वह इधर कम हुआ है। एंग्लो इंडियन की भी उन दिनों हाँकी में बहुत रुचि थी। अब काफी बड़ी संख्या में एंग्लो-इंडियन भारत छोड़ गये हैं। बेशक उन का स्थान बिहार और मध्यप्रदेश के आदिवासी खिलाड़ियों ने लिया है लेकिन उनमें खेल के प्रति एंग्लो इंडियन जैसी आस्था अभी पैदा नहीं हो पायी है। हो जायेगी।

क्या यह सही नहीं कि चयन समिति के रवये के कारण ही प्रेवाल और मुरजीत सिंह ने हाँकी से संन्यास लिया?

देखिए, ग्रेवाल को सोढी की कीमत पर एशिया कप में शामिल किया गया था। लेकिन कराची में महमूस किया गया कि उसे पुनः मौलिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। खेल के कमजोर हिस्सों को दृढ़ करने के लिए उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया उस पर उन्हें आपत्ति थी। सुरजीत सिंह बेशक बेहतर खिलाड़ी है, फुल बैक में उस का

जबाब नहीं. उसे कहीं से सुराग  
था कि इस बार शायद ही उसे  
सौंपी जाये, लिहाजा कम भते  
बना खेल से संन्यास ले लिया.

एस्ट्रो टर्फ तो बिछा दिया गया।  
उस पर अभ्यास की क्यों वक्तव्य  
रही है:

जहाँ तक भारत में एस्ट्रो टर्फ के निर्माण संबंध है जब भारत में परमाणु वनस्पति क्षमता है तो एस्ट्रो टर्फ वह क्यों नहीं बना सकता?

खेलों में और खास तौर पर बढ़ती राजनीति के बारे में आप वास्तव में जब हम हासते राजनीति की बात की जाती है

लेकिन भारतीय ओलंपिक  
अध्यक्ष राजा मालिंदर सिंह  
राय है: "राजनीति कहाँ नहीं  
पाकिस्तान में नहीं जहाँ सैनिक  
आज हाँकी और क्रिकेट में  
पाकिस्तान में राजनीति है जहाँ  
भारत में भी नहीं।"



मुका

वजे ही भाग  
कंपनी को  
बलाऊ व्यवस्था  
स्टो टर्फ भी अ  
कि आरोपों  
गकार भारतीय  
कम गोलों से  
नीत सिंह की  
वह लगभग ए  
चुके थे. भा  
पर उन खि  
नी चाहिए  
हो कर चुने  
बड़े नामी पु  
मौत और उस  
कर रहे हैं  
ल बैंक खिला  
नी खामोशी  
हैं: अगर कोई  
गया तो यह बी  
हाँकी की मु  
के खिलाड़ी  
इन दोनों के  
पिपित किए कि  
त में लाना अ  
हीं से सुराग  
पायद ही उसे  
ना कम भते  
ले लिया.  
छा दिया गया  
क्यों दिक्का  
भ्यास शुरू हो  
स्टो टर्फ के नि  
परमाणु बम  
टर्फ वह क्यों  
बास तोर पर  
बारे में आप  
हम हाते  
की जाती है  
ओलिंपिक  
लंदर सिंह  
ति कहाँ नहीं  
जहाँ सैनिक  
क्रिकेट में  
नीति है उत



सुरजीत सिंह: नाटक कितनी बार?

## अधिकारी एक जैसे हैं

राज थानी

भारत संहिता बनाने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि यह सिर्फ दूसरों के लिए उन के अपने लिए भी है. यही कारण है आज खिलाड़ी अधिकारियों को कोस रहे और अधिकारी खिलाड़ियों को. भारतीय इस समय इतनी बीमार हो चुकी है कि के स्वस्थ होने की दूर दूर तक कोई चिन्ता नहीं दिखाई पड़ती है. एक दिन सुनने कि सिंह (प्रशिक्षक) को इसलिए निकाल दिया है कि बंबई में हुई विश्व कप और ची में हुई एशियन कप प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक साबित हुआ है. कि क्या इस के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार थे. हार गये तो प्रशिक्षक की हाय हाय. जीत गये तो प्रशिक्षक की जय जयकार. लीजिये हम बात प्रशिक्षण पक्ष से ही शुरू करते हैं. हाँकी के गिरते स्तर को सुधारने का यही उपाय है कि हर दूसरे महीने प्रशिक्षक प्रशिक्षक के अपने मंत्र और गुरुमंत्र उसकी एक शिक्षण पद्धति और तकनीक है और सब से पहले वह यही पाठ पढ़ाता है कि अब तक जो तुमने सीखा है वह गलत है. गलत को सही करो फिर पाठ पढ़ाओ. अचानक एक किस्सा याद आ गया. एक भारतीय संगीत के एक गुरु के पास जाता है कि 'आप की शरण में आया

हूँ इस कला और विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा.'

गुरु पूछते हैं, 'क्या इस से पहले कहीं दीक्षा पायी है.' जवाब मिलता है 'अमुक गुरु से आठ साल सीखा है.' गुरु ने कहा तुम्हें 16 बरस लगेगे. पास ही एक दूसरा शिष्य बैठा था वह भी शास्त्रीय संगीत सीखने आया था. उस से भी यही पूछा गया. उस का जवाब था, 'पहली बार आया हूँ और आप ही की शरण में आया हूँ.' गुरु बोले, तुम्हें 8 वर्ष लगेगे. पहले वाला शिष्य कैसे चुप रहता. पूछने लगा मुझे आप का ज्ञान, विद्या, तर्क समझ से बाहर हैं. गुरु ने झट से कहा: 'समझ भी कैसे सकते हो. आठ बरस तो मुझे वह सब भुलाने में लग जायेंगे जो तुमने आज तक सीखा है.'

लीजिए, प्रशिक्षक फिर बदल दिया गया है और इस बार यह भार बलबीर सिंह को सौंपा गया है. जी हाँ, वही बलबीर सिंह जो 1975 में विश्व कप में प्रशिक्षक और मैनेजर थे. जी हाँ, वही बलबीर सिंह जो 1948, 52 और 56 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. तो क्या इस परिवर्तन से यह मान लिया जाये कि सब ठीक हो जायेगा. इस समय भारतीय टीम का बल और मनोबल दोनों ही इतने गिर चुके हैं, कि छः महीने तो मनोबल उठाने में लगेगे. बल की बारी तो बाद में आयेगी. यहाँ एक बात और जान लेनी जरूरी है कि झम्मन लाल शर्मा निकाले जाने पर इतने दुखी नहीं थे और बलबीर सिंह नया पद ग्रहण करते समय इतने सुखी नहीं थे. वजह जो भी हो, सब से बड़ी वजह तो यही है कि दूसरे दर्जे की टीम सौंप दी जाती है. बीच बीच में हस्तक्षेप भी किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि दो चार महीने में ही यह पहले दर्जे की टीम बन जाये. हर कोई जानता है कि इस समय हमारी मुख्य कमजोरियाँ क्या क्या हैं? गोली, हाफबैक और सेंटर हाफ हमारी कमजोरियाँ हैं जो जाते जाते ही तो जायेंगी.

टीम का मनोबल कितना गिर चुका है उस का इस से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि सुरजीत सिंह जैसा खिलाड़ी त्यागपत्र दे दे. एक एक कर के कितने खिलाड़ियों ने त्यागपत्र दे दिये. सुखबीर सिंह, ग्रेवाल, महाराज कौशिक, इस तरह 10 खिलाड़ी बाहर हो गये. हरेक ने अपने त्यागपत्र में केवल एक ही बात कही है कि हम भारतीय हाँकी संघ के अनुचित व्यवहार और उन के मनमाने रवैये से दुखी होकर त्यागपत्र दे रहे हैं. ग्रेवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि खिलाड़ियों को तो दैनिक भत्ता भी नहीं मिल सकता और भारतीय हाँकी संघ के अध्यक्ष इंदर मोहन महाजन को अपनी और अधिकारियों की मौज मस्ती के लिए 45

हजार रुपये खर्च करने की छूट. 'हम आह भी करें तो बदनाम वो कल भी करें तो कुछ नहीं.' और जब ग्रेवाल साहब से यह पूछा गया यदि अधिकारियों को बदल दिया जाये तो क्या आप अपना निर्णय बदल देंगे. इस पर उन्होंने झट से जवाब दिया अधिकारी बदलने से कुछ नहीं होगा, 'सिस्टम' को बदलो. अधिकारी तो सब एक जैसे ही हैं. एक फौजी फरमान जारी करता है तो दूसरा पुलिस कमिश्नर की तरह है. हम खिलाड़ी हैं, खेल के सिपाही हैं. पुलिस कमिश्नर या फौजी जनरल तो नहीं.

अब आइये सुरजीत सिंह के बयान पर. इन महाशय का दुख या दर्द समझ से बाहर है. दुनिया जानती है कि इन को कप्तान बनाने में सब से बड़ा हाथ महाजन का ही था. मस्क्वा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय हाँकी टीम के कप्तान मास्करन को जब दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया उस समय तो सुरजीत ने मौनव्रत धारण कर लिया. (कप्तान पद जो प्राप्त करना था) उस समय तो महाजन उन के लिए देवता थे. आज अचानक दानव कैसे हो गये? कल तक तो वह हाँकी के बादशाह थे अब तानाशाह कैसे हो गये? कहीं सुरजीत को यह तो नहीं आभास हो गया था कि इस समय यहाँ वहाँ उन्हीं के खेल की सब से ज्यादा आलोचना की जा रही है. बार बार कहा जा रहा है कि सुरजीत अपने फार्म में नहीं हैं. इससे पहले कि चयन समिति के सदस्यों की कसौटी पर वह खरे न उतरें, स्वयं त्याग पत्र देने में मलाई है. कहीं सुरजीत का सारा ध्यान खेल से हटकर बयान पर तो नहीं आ गया. कहीं किसी ने उन के कान में यह मंत्र तो नहीं फूँक दिया था कि 'बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा'. सुरजीत सिंह ने ऐसा पहली बार नहीं किया. पहले भी चार बार यह नाटक कर चुके हैं.

अब हम हाँकी संघ के अधिकारियों की थोड़ी खबर ले लें. क्या आप इतने व्यस्त रहते हैं कि चयन प्रशिक्षण के समय उपस्थित भी नहीं हो सकते. क्या आप नहीं जानते कि आप लोकतंत्र में भी राजतंत्र की तरह काम करते हैं. शायद इसलिए कि आप जो कुछ भी करते हैं, सही करते हैं, गलती तो दूसरे करते हैं. बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है. जितने वकील उतनी दलील. सब एक दूसरे को कोस रहे हैं. सब एक दूसरे के लिए आचार संहिता बना रहे हैं. काश कोई अपने आचार संहिता तैयार कर ले.

जहाँ तक भारतीय हाँकी प्रेमियों का सवाल है वे खिलाड़ियों और अधिकारियों दोनों बयान वाजियों से इतने परेशान हैं कि हर बयानवाजी में उन्हें सौदेबाजी की ब्वनि सुनाई पड़ती है.



## हाँकी का बुरा हाल

भूषण सरहिवा

भारतीय हाँकी इन दिनों एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती है। 6 जून से एम-स्टैंड में चैंपियंस कप हाँकी प्रतियोगिता के लिए भारतीय दल का चयन पिछले दिनों नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेलकुद संस्थान पटियाला में हुआ। चयन स्पर्धाएँ तीन दिन तक चलती रहीं और तीनों दिन निराशा का वातावरण छाया रहा।

इस बात पर दो मत नहीं कि एमस्टैंड के लिए जो दल चुना गया है वह एक कमजोर दल है जिससे विजय की आशा कम है परंतु एक आश्चर्यजनक बात यह देखने में आई कि बलबीर सिंह ने, जिन्हें हाँकी महासंघ ने दल का नया प्रबंधक, मुख्य प्रशिक्षक व निर्देशक प्रशिक्षण नियुक्त किया है, समाचार पत्रों को यह बयान दे दिया कि उनका दल कई पहलुओं से कमजोर है और शायद यह चैंपियंस कप प्रतियोगिता में अच्छा खेल न दिखा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इनके पास कोई "जादू की छड़ी" नहीं है जिससे वे थोड़े समय में दल को सुदृढ़ बना सकें। बलबीर सिंह के वक्तव्य से हाँकी प्रेमियों में निराशा बढ़ी है और सच्ची बात तो यह है कि उनका कथन समय के अनुकूल नहीं है। हाँकी महासंघ ने प्रबंधक झमन लाल शर्मा व प्रशिक्षक हरमीक सिंह की छुट्टी करके बलबीर सिंह को भारतीय दल की नैया का कर्णधार बनाया। यदि वही ऐसी बातें करने लगे जिससे दल के सदस्यों का मनोबल कमजोर हो, तो हाँकी का बस "बोलो राम" ही है। यह उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने दल का चयन किया उनमें बलबीर सिंह भी शामिल थे। अब वे स्वयं ही दल को कमजोर बता रहे हैं।

गत् दो वर्षों से भारतीय हाँकी महासंघ की गाड़ी जिस गति से चल रही है उसकी चारों ओर से बड़ी आलोचना हुई है परंतु जिस ढंग से महासंघ अपने घोड़े बदलता जा रहा है इससे भारतीय हाँकी दिशा विहीन होकर रह गई है और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भारत सरकार ने एशियाई खेलों की तैयारी हेतु जो बोधक समिति (मॉनिटिंग कमेटी) राम निवास मिर्धा के नेतृत्व में बना रखी है, वह भी हाँकी महासंघ के चौधरियों के सामने बेबस मालूम होती है!

1980 में भारत सरकार के सुझाव पर नेता जी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेलकुद संस्थान ने मित्र मित्र खेलों में तैयारी हेतु एक तीन वर्षीय योजना बनाई थी जिसके अधीन प्रशिक्षण शिविर आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया

था। हाँकी महासंघ ने उत्तर प्रदेश के झमन लाल शर्मा को भारतीय हाँकी दल का प्रबंधक और नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेलकुद संस्थान के हाँकी प्रशिक्षक हरमीक सिंह को मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त किया था। यह भी निर्णय किया गया था कि ये दोनों, एशियाई खेलों तक बदले नहीं जायेंगे। शर्मा व हरमीक सिंह भारतीय हाँकी दल के यूरोप भ्रमण के समय, पाकिस्तान के साथ चार टेस्ट मैचों में, बंबई में हुई विश्व कप हाँकी प्रतियोगिता में और कराची में आयोजित एशियाई कप प्रतियोगिता के साथ रहे। विश्व कप में भारत पाँचवें स्थान पर आया। और एशियाई कप में द्वितीय स्थान पर रहा।

कहा जाता है कि झमन लाल शर्मा व हरमीक सिंह की छुट्टी इस लिए की गई कि हाँकी महासंघ के मालिकों को यह पता चल गया था कि ये दोनों खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाने व उनका मनोबल बनाए रखने में असफल रहे—लेकिन अब जिस ढंग से बलबीर सिंह खिलाड़ियों का 'मनोबल' बढ़ा रहे हैं इससे तो खिलाड़ी और भी हतोत्साहित हो जायेंगे।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि तीन वर्षीय प्रशिक्षण योजना का क्या बना। गत् वर्ष महासंघ ने सरकार की ओर से स्वीकृत दो प्रशिक्षण शिविर लगाने से इस लिए इंकार कर दिया था कि वे इसकी 'आवश्यकता' नहीं समझते थे। वे यह समय खेल अभ्यास पर लगाना चाहते थे। सरकार की बोधक समिति ने इस पर नाराजगी जाहिर की और प्रशिक्षण शिविर लगाने पर बल दिया। परंतु महासंघ के सर्वेसर्वा इंद्र मोहन महाजन ने यह सुझाव स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अब जबकि एशियाई खेल नजदीक हैं—महासंघ ने अपने घोड़े बदल दिए हैं और सरकार की बोधक समिति मूँह देखती रह गई है।

पिछले छह महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय दल का काम कैसा रहा और क्या क्या कमियाँ सामने आयीं इस पर झमनलाल शर्मा व हरमीक सिंह ने महासंघ के नाम पर अपनी रिपोर्ट में विचार किया है। पाकिस्तान के साथ हुए टेस्ट मैचों के बारे में झमनलाल शर्मा ने लिखा है कि केवल पाकिस्तान के मुकाबले में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हॉलैंड के मुकाबले में भी भारतीय दल में अनुभव की कमी है। इन देशों के खिलाड़ी सात आठ वर्ष से लगातार अंतरराष्ट्रीय हाँकी खेल रहे हैं जिससे उनका अनुभव बहुत बढ़ा है। दूसरी ओर भारतीय दल केवल आठ माह पूर्व गठित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैचों में भारत की अग्रिम पंक्ति श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन न कर सकी। लैफ्ट बैक व लैफ्ट हाफ खिला-

ड़ियों में नालमेल की कमी थी। से- गेद का ठीक पास देने में भी असफल

कराची में गत् 12 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित प्रथम एशियाई कप हाँकी प्रतियोगिता के बारे में झमन लाल शर्मा की मंच में (जो भारत व बंगलादेश के बीच 12 पैनल्टी कानर भारत को मिले व्यर्थ गए। हमारे मैच (जो सिगापुर के हुआ) भारत को 14 पैनल्टी कानर जिन में से 12 व्यर्थ गए, तीसरे मैच मलेशिया के साथ हुआ) भारत को चार कानर मिले जिनमें तीन व्यर्थ गए। मैच श्रीलंका के साथ था जो इस प्रति- में सबसे कमजोर टीम थी। इस मैच में को कुल 32 पैनल्टी कानर मिले परंतु से 28 व्यर्थ गए। पाँचवाँ मैच चीन के- इसमें भारत को 7-0 से विजय प्राप्त पाकिस्तान के साथ भारत का अंतिम शर्मा का कथन है कि पाकिस्तानी खिला- ने खेल के हर विभाग में श्रेष्ठ खेल का किया। भारत को 4-0 से हार हुई। कप प्रतियोगिता के बारे में श्री शर्मा ने रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन किया भारतीय खिलाड़ियों का खेल उल- था। एक और बात उन्होंने यह कही कि ङियों पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया अब मुख्य प्रशिक्षक हरमीक सिंह सुनि- कराची की प्रतियोगिता के- इनका दृष्टिकोण, यह है कि अंतर- स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों को- पर खेलना पड़ा जबकि उन्हें इस अनुभव नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय हाँकी में एस्ट्रो टर्फ का ओलंपिक 1976 से आरंभ हुआ। समय भारत ऑस्ट्रेलिया से 6-0 से ह- दूसरी बार 1979 में कराची में पा- पाकिस्तान के समक्ष 7-1 से पराजि- पड़ा। तीसरी बार 1982 की टेस्ट मै- कराची में पाकिस्तान से 4-2 से ह-

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार भारत को 12 अप्रैल से दिल्ली में एस्ट्रो टर्फ प्रशिक्षण दिया जाना था। परंतु ऐसा सका क्योंकि टर्फ समय पर तैयार न- इस संबंध में हाँकी महासंघ के प्रधान महाजन ने एक वक्तव्य में कहा है कि टर्फ के लिए गोल के भारी खंभे और गेंदों का प्रबंध नहीं किया गया। खंभों का संबंध था इसके लिए कोई नहीं। सीमलैस गेंदें आयात करनी प- पता चला है कि महासंघ के अधिकारियों गेंदें मंगवाने के लिए अपनी माँग ए- को बहुत देरी से भेजी!

जान  
सम वि  
समत शर्मा  
माम नदी खो  
विजली, न  
धौशरी के  
तुलर भी क  
हो गयी।  
और हर  
पुत्रों का अनु  
टन गेहूँ पैदा  
ही कटाई  
गोदामों तक  
राज कुपित ह  
वर्षा से खराब  
की 'लैंडसेट'  
न जाने कितने  
अपनी जामूसी  
की बावजूद कि  
ही अथवा ह  
तार मसलाधा  
न दिया कि  
के लिए गहा  
नकार लोगो  
माने जाने  
म उत्तरप्रदेश  
पसल बरबा  
ज भी 25 से  
इसी बीच रव  
करने के  
के किसानों  
शाल अल्पक  
किसान उर्व  
वोहर खरीर  
यक्रम के लि  
3 करोड़ रुप  
सारे मौसम वै  
में मई के इ  
साल में इतनी  
निक साधनों  
वरसात के व  
फो कुल नुक  
क दूरदर्शन प  
3-4 दिन म  
दिनों में सब  
मौसम विज्ञा  
नहीं कर पा र  
या कुपि विज्ञा  
कने है? इस  
न से बात-  
में गेहूँ की  
में नहीं सोचा

दिनमान



ज्ञान

## सम विज्ञानी भी किसानों का जोखिम कम नहीं कर पा रहे

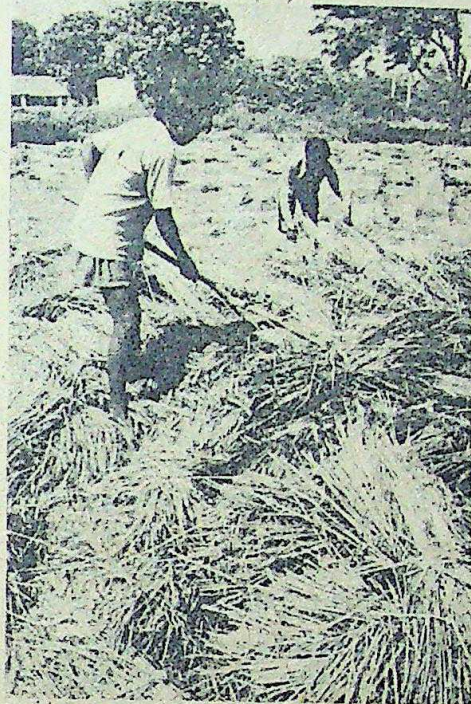
शिव शर्मा

सम नयी खोजों, नये कृषि यंत्रों, उर्वरक, विजली, नलकूपों, डीजल पंपों, ट्रैक्टरों और धातुओं के बावजूद किसानों का जोखिम और भी कम नहीं हुआ है, इस बार तो जो सिगापुर के पैनल्टी कानून और हरयाणा में, कृषि भवन के पंजों का अनुमान था कि इस साल 117 टन गेहूँ पैदा होगा लेकिन इस का चौथाई भी कटाई और गहाई के बाद मंडियों में गोदामों तक पहुँच पाया था कि इंदौर में राज कुपित हो गये। लगभग दस लाख टन वर्षा से खराब हो गया। अंतरिक्ष में घूमते की 'लैंडसेट' से ले कर भारतीय इनसेट न जाने कितने देशी विदेशी उपग्रह मौसम अपनी जामूसी आँख गड़ाये रहते हैं लेकिन बावजूद किसानों की पकी फसल, खेतों की अथवा खलिहानों में पड़ी रही और मूसलाधार बारिश ने उन को इतना न दिया कि वे अपनी मेहनत का फल लिए गहाई कर दाने निकाल पाते।

किसानों का कहना है कि गेहूँ का माने जाने वाले हरयाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 प्रतिशत फसल बरबाद हो चुकी है, सरकारी जमीन भी 25 से 30 प्रतिशत तक तो मानते हैं। इसी बीच रबी के इस नुकसान को खरीफ करने के लिए कृषि मंत्रालय ने 20 करोड़ के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये अल्पकालिक ऋण जारी किया है, किसान उर्वरक, बीज और कीटनाशी वगैरह खरीद सकें। पिछले साल खरीफ ऋण के लिए इस तरह का ऋण केवल 3 करोड़ रुपये दिया गया था।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि उत्तर भारत में मई के इस पखवाड़े की वर्षा पिछले साल में इतनी कमी नहीं हुई। अगर तमाम साधनों से लैस मौसम विज्ञानी सही बरसात के बारे में ठीक ठीक बता पाते, तो कुछ नुकसान बच सकता था। यहाँ की दूरदर्शन पर यह बताया गया था कि 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा और उन दिनों में सबसे भारी वर्षा हुई। मतलब मौसम विज्ञानी भी किसानों का जोखिम नहीं कर पा रहे हैं।

कृषि विज्ञानी इस बारे में कुछ मदद कैसे कर सकते हैं? इस बारे में अनेक भारतीय कृषि विभागों से बातचीत हुई। अभी किसी भी मौसम विज्ञानी को ऐसी किस्मों तैयार करने के लिए कोई भी साधन नहीं मिला है जो दाने पकने के समय



खराब गेहूँ : बेमौसम बरसात की मार

होने वाली बेमौसम वर्षा को सह सकें। हिसार के हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय में आनुवंशिकी विभाग के अध्यक्ष प्रो. डा. रामकठिन सिंह ने बताया कि अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। इस साल बहुत नुकसान हुआ है। हम इस दिशा में कार्य शुरू करेंगे। (वैसे हरयाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सी-306 किस्म इस दृष्टि से काफी हद तक वर्षारोधी है) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उपमहानिदेशक डा. महाराज सिंह का कहना है कि पूर्वी भारत के लिए गेहूँ की कुछ ऐसी किस्में विकसित की गयी हैं, जिन का दाना पकी वाली में अगर ऊपर से झाँके तो दिखाई देता है। यानी भीगने के बावजूद गहाई करने पर उनके दाने आसानी से अलग हो सकते हैं। लेकिन इन किस्मों को उत्तर भारत के किसान अपनायेंगे। इस बारे में संदेह है।

सबसे आशाजनक समाचार आया है आस्ट्रेलिया से, जहाँ के गेहूँ उत्पादक किसानों को भी कटाई से पहले की बे मौसम बरसात का सामना करना पड़ता है। वहाँ के 'न्यू साउथ वेल्स' इलाके के उत्पादकों को हर साल बे मौसम बरसात की वजह से लगभग 180 करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर की फसल की बरबादी बरदाश्त करनी पड़ती है। इसीलिए सिडनी विश्वविद्यालय के नैरोबी प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक गेहूँ की ऐसी किस्में तैयार करने में लगे हुए हैं, जो पकने के बाद कटाई से पहले कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक आकस्मिक वर्षा को सह सकें। इस के लिए

उन्होंने आस्ट्रेलियाई गेहूँ की किस्मों के अपने विशाल संग्रह के अतिरिक्त भारत जैसे मानसूनी वर्षा क्षेत्रों से भी गेहूँ की किस्में इकट्ठी की हैं। वे खासतौर से गेहूँ की जंगली किस्मों की जाँच कर रहे हैं, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि कुछ ऐसे आनुवंशिक गुण हो सकते हैं, जिनसे वर्षारोधी क्षमता आ जाये। गेहूँ के गुण सूत्रों का अध्ययन करके वे इन जंगली गेहूँओं के वर्षारोधी जीन को गेहूँ की अधिक उपज देने वाली प्रचलित किस्मों में डालने की कोशिश करेंगे। इस तरह उन किस्मों को खासतौर से खेती में से हटा दिया जायेगा, जो जरा सी वर्षा होते ही पकने के बाद अंकुर छोड़ देती है।

इस प्रयोजना में अनुसंधान के लिए आस्ट्रेलियाई वनस्पति वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला के अंदर ही कृत्रिम वर्षा करने वाला एक विशेष कक्षा स्वीडी डिजाइन के आधार पर बनाया है। जिन किस्मों की वे जाँच कर रहे हैं, उन्हें बालियाँ पकने के बाद काट लिया जाता है और फिर 5, 15 और 25 दिन तक उन पर वर्षा का असर देखा जाता है। इसके लिए लगभग 2 इंच वर्षा 2 घंटे तक की जाती है और उस के बाद लगभग 20 सें. ग्रे. तापमान पर 58 घंटे तक उच्च नमी का वातावरण रखा जाता है। इस वर्षा-यंत्रणा के बाद गेहूँ की बालियाँ 5 से 40 सें. ग्रे. तापमान पर गरम हवा दे कर सुखायी जाती हैं और फिर उनमें से दाने अलग कर के आटा तैयार किया जाता है।

कितना नुकसान हुआ है, इसका पता लगाने के लिए रंग रूप और वजन के अलावा यह भी देखा जाता है कि बेमौसम बरसात दानों के अंदर मौजूद एंजाइमों में क्या परिवर्तन किया और उससे दानों की और आटे की क्वालिटी पर क्या असर पड़ा। लेकिन यह प्रयोग शायद हमारे यहाँ इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि आस्ट्रेलिया में गेहूँ को आमतौर पर ब्रेड और बिस्कुट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए उनका ध्यान एंजाइमों वगैरह पर ज्यादा है। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि भीगने के बाद भी आटा आदमी के खाने के काबिल रहे। अब तक किये गये परीक्षणों के आधार पर नैराश्री योजना के जीव रसायनविद टेरिल मारिस का कहना है कि आस्ट्रेलिया में प्रचलित गेहूँ की किस्मों में से 'काइट' नाम की किस्म ही ऐसी है, जो कि पकने के समय होने वाली वर्षा को बरदाश्त कर पाती है। एक और किस्म जिस का नाम 'कुर्क' है, उसमें भी दूसरी किस्मों की तुलना में भीगने के बाद गेहूँ के दानों में अंकुरण बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आशा बंधती है 'सन 44-ई' किस्म से, जो कि इस



पोष प्रजनन के संस्थान में अनेक परीक्षणों के बाद विकसित की गयी है। पिछले 3 सालों में इस पर परीक्षण चल रहा है। लेकिन अभी किसानों को खेती के लिए शायद इसे 1983 तक ही जारी किया जा सकेगा। लेकिन इस किस्म में भी केवल वर्षा सहने की क्षमता है। अगर पकते समय या पकने के बाद वर्षा के साथ साथ तापमान भी कम हो जाये तो फिर यह किस्म भीतर कुलबुलाने कुल्लों को रोक नहीं पाती और फिर वे फट पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों में इन किस्मों के गुण भारतीय किस्मों में लाये जा सकें तो काफी कामयाब साबित हो सकती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ पकने के समय और पकने के बाद जो वर्षा होती है उससे तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता।

भारत में गेहूँ की नयी किस्मों के विकास में सब से नामी वैज्ञानिक श्री बी. एस. माथुर

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

**कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें। अपने विषय की विवरणी मंगाइये। कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.**

**अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। विवरणी हेतु लिखें। इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), पोस्ट बॉक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.**

**हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विवरणी मंगाइये। पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.**

### एजेंट चाहिए

**फिल्म, साहित्य व संगीत के हिन्दी मासिक राग बहार को मंगाने हेतु न्यूजपेपर एजेंट संपर्क करें। व्यवस्थापक, राग बहार, 946, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली-6.**

### व्यापार आमंत्रण

**घोड़ी पूंजी से बेरोजगारों को बड़ा रोजगार। 101 स्वनिर्मित व्यापार आवश्यकतानुसार संपूर्ण जानकारी। पुस्तक उचित मूल्य में मंगाएँ। इंडस्ट्रियल कोर्स बुक सेंटर, अलीगढ़-25.**

भारतीय कृषि अनुसंधान, नयी दिल्ली में काम करने हैं। उन्हें बोलॉन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वह भी अब वर्षा-विरोधी किस्मों के प्रजनन की ओर अधिक ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 'मी-306' पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 'डब्ल्यू एल-2265' और स्वयं श्री माथुर द्वारा विकसित 'आई डब्ल्यू पी-72' गेहूँ की प्रचलित किस्मों वर्षारोधिता की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं। अगली बार गेहूँ की बुआई करने समय उन इलाकों के किसान इन किस्मों का बीज बो सकते हैं, जहाँ वे मौसम बरसात ने उनकी इस बार की मेहनत पर पानी फेर दिया।

लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले साल गेहूँ की फसल पकने के बाद वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में होगी, जिनमें इस साल हुई थी। सच तो यह है कि खेती-बाड़ी के इन बेशुमार जोखिमों को देखते हुए दूसरे उद्योग धंधों की तरह और पशु बीमे की तरह फसल बीमा भी पूरे देश में लागू करना चाहिए। किसान की मेहनत को कोई प्राकृतिक आपदा आकर मिट्टी में मिला दे और वह हाथ मलने के सिवा कुछ न कर सके, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। अभी फसल बीमा के लिए कुल 20 करोड़ रुपये की राशि रख कर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही इसे आजमाया जा रहा है। इसको पूरे देश में फैलाने के साथ ही खलिहान में पड़ी फसल के लिए आग बीमे की तरह मौसम बीमा भी किया जा सकता है। कम से कम किसान ने जो खर्चा किया है, वह तो उसे वापस मिलने की गारंटी रहे। सवाल यह है कि करेगा कौन? सुझावों और प्रस्तावों की भाषा यहाँ समझता ही कौन है?

## चिकित्सा

### बंधुआ वैद्य

दुर्ग जिले के कुछ वैद्यों ने सन् 1974 में उजबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस का फैसला '79 में वैद्यों के पक्ष में हुआ। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी आज तक शासन वैद्यों को उस फैसले के आधार पर बिना भेदभाव के वेतनमान देने में अनाकानी कर रहा है।

शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त अन्य सुविधाओं की बात तो अलग रही। महीनों वैद्यों को वेतन नहीं मिलता। ऐसे भी वैद्य हैं, जिन्हें सन् 1956 में लागू स्वीकृत वेतन ही आज भी दिया जा रहा है। सन् 1960 में लागू

नाराचंद वेतनमान, वह भी मूल रूप से भी 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दे रहा है। इसी बीच शासकीय कर्मचारियों के लिए पांडेय वेतन आयोग और चौधरी आयोग द्वारा अनुशासित वेतनमान बढ़ाया गया है।

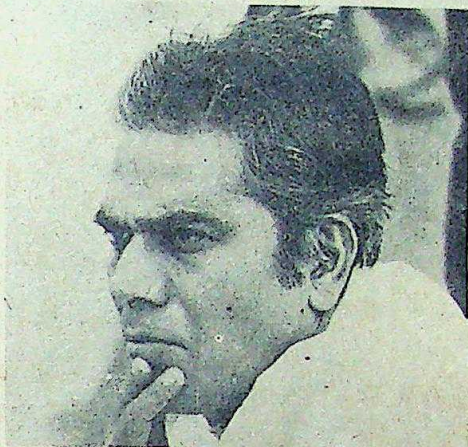
वस्तुतः समस्या की नींव मध्यप्रदेश पुनर्गठन के समय ही रखी गयी थी तब निर्यात के लिए आयुर्वेद औषधालय सभाओं के अधीन ही रखे गये जबकि शामिल क्षेत्रों में सभी आयुर्वेद औषधालय शासन द्वारा संचालित हैं। प्रयोजन के अनुसार कि शासनाधीन होने पर ये औषधालय जनपद सभाओं के स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप और नियंत्रण से बाहर हो और नेता इन वैद्यों को बंधुआ मजदूरों के प्रयोग करने से बंचित रह जाते, जो भी हो रहा था। जो वैद्य स्थानीय नेता चुनाव प्रचार से ले कर निजी काम में भी करने से इनकार करते थे, उन्हें अक्सर बहुत की है स्थानांतर, वेतनवृद्धि में रोक, कुछ स्थानीय जीवन की वेतन न दे कर परेशान किया जाता है। वेतन के अलावा स्वायत्तता के नाम पर वेतन के सुविधा और स्वेच्छा से अलग नियम बनाती रहीं, एक ओर जहाँ सभाओं के नियमों में 'हठधर' वर्गीय कर्मचारियों को नियमित रूप से देय राशियों का भुगतान किया जाता है, वैद्यों को पुनरीक्षित वेतनमान, बंधुआ मजदूरों को भी नहीं दिया गया। और आज मंहगाई भत्ता कभी नहीं दिया गया। और तो ऐसा गया तो बाद की तारीखों से लागू तो ऐसा

समस्या तब और बढ़ गयी जब पंचायतों का गठन किया गया। जनपद के दायित्व तो इन्हें दिये गये, सभाओं के कुछ स्रोत शासन ने ले लिये। पंचायत की सीधी मार वैद्यों पर पड़ी। विकास सहायक को पंचायत का कर्मचारी माना गया किंतु वैद्यों को पंचायत पर भार माना गया। अब इन के दायित्व तो सरकार वहन करना चाहती है। जनपद पंचायत, शासन कहता है कि पंचायत सक्षम हो तो इन्हें नियमानुसार तान करे। जनपद पंचायतें भी अपने साधनों से एकत्रित आय तथा शासकीय विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त को इन वैद्यों के स्वत्वों के भुगतान खर्च करना चाहतीं। क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल ने वैद्यों दशा के लिए रायपुर में वैद्यों के लिए आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना —प्र. प्र. आयुर्वेद अधिकारी संघ के डॉ. आर. एन. शुक्ल से प्राप्त आधार पर.



## शिवर राजनीति के शिकार : मधु लिमये

राजनीति का नया मोड़' शीर्षक से श्री मधु लिमये की एक पुस्तक प्रकाशित है, जिस में उन के चार भाषण संग्रहीत हैं, जो राजनीति को नया मोड़ देने की नीति का परिणाम यह आया है कि देश फिर आपात्काल पूर्व स्थिति में, जिस के भी कहीं पीछे जा पहुँचा है। इस का यह परिणाम आश्चर्यजनक ही होगा। मधु लिमये के ये नये मोड़ फिर लगते, इतना ही नहीं, लगता है कि इज्जत पाने के लिए कहीं वह कुशल की तरह झूठी पैरवी तो नहीं कर रहे? पहले पर मधु लिमये की वाद कुशलता ही जाव दीवता है। लेकिन यह हारे हुए की वादकुशलता है।



मधु लिमये : कुशल वकील की झूठी पैरवी

मधुलिमये की बुद्धिमानी की तारीफ दीये, उन्हें अत्यंत बहुत की है। मुहम्मद करीम छागला रोक, कुछ भी जीवनी में (रोजेस इन दिसंबर) किया जाता है। मधुलिमये भी एक है। भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री मोरारजी देसाई को मधु लिमये ने ही सभाओं के बीच में 'हठधर्मी' कहा है। उन्होंने भी नियमित रूप से प्रतिभाशाली (जीनियस) न किया जाता है। लेकिन उन की प्रतिभा वेतनमान, बर्तमान है, ऐसा ही बताया है। मधु लिमये दिया गया। और आज की देश की वास्तविकता से लापता तो ऐसा लगता है कि मोरारजी में कुछ तथ्य है।

वर्तन के लिए उतावलापन हो और गये, सभाओं में आगे बढ़ने में जो तालमेल बैठाना ले लिये। पण उस में सफलता न मिले तो परिवर्तन पड़ी। लिमये का वाद केंद्र में चरण सिंह, चव्हाण का जुली सरकार बनी। मध्यम हाथ में सत्ता आने का साक्षात्कार मधु लिमये ने संजय-इंदिरा के सहयोग से सत्ता हासिल की थी, यह बात की थी—ऐसा नहीं माना जा सकता। मोरारजी ने उन दिनों जो षडयंत्र किये की चर्चा करते हुए दोष दूसरे के शक्ल ने वैद्यों के प्रति की स्थापना का पता नहीं चलता। लोकसभा, इन लोगों को अपने घर क्यों वापस का विस्लेषण भी मधु लिमये नहीं

गुंजित करने वाले जाज फर्नांडिस एक ही रात में जनता पार्टी से अलग कैसे हुए, ऐसे कतिपय उदाहरण यत्रतत्र पुस्तक में देखने को मिलते हैं। लोकदल को सत्तापक्ष का विकल्प बनना है या अन्य छोटे मोटे गुटों के मुकाबले में खड़ा करना है, इस के बारे में भी मधु-लिमये कुछ कहना नहीं चाहते। संसद में लोकदल के चालीस सदस्य हैं, ऐसा बताते समय इंदिरा कांग्रेस की सदस्य संख्या के मुकाबले में अपने दल की संख्या कितनी कम है, इस का मान ही उन को नहीं होता। अन्य विपक्षी दलों को नीचा बताने के लिए वह अपने दल के 40 सदस्यों की डींग मारते हैं तो अजूबा लगता है। वास्तव में इस पर तो उन को दुखी होना चाहिए।

जनता पार्टी के मुख्य सचिव बनने के बाद मधु लिमये शिवर राजनीति में फँसे रहे, आज भी उन की यही स्थिति है। जनता पार्टी का कार्यक्रम लोगों को समझाने के बदले नेताओं को मनाने में उन्होंने समय बर्बाद किया। 'जनता पार्टी के कार्यकाल में हम दिल्ली के गुलाम बने थे' ऐसा वह स्वयं कहते हैं। मधु लिमये के दिल्ली के गुलाम बनने पर बाहर कोई काम न हो तो वह एक तरह का अवतारवाद ही हो गया। इस तरह की व्यक्ति-परक राजनीति लोकतांत्रिक मानस का निर्माण करने में बाधा बनती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा की हार तथा राजनारायण की जीत हुई। उस एक घटना के लिए देश ने कितने दाम चुकाए? कुछ समय बाद चौधरी तथा राजनारायण में अनबन हो गयी। गुंडागर्दी कर के लोकदल के दफ्तर पर राजनारायण ने कब्जा करना चाहा और बरसों तक सरकार को वहाँ पुलिस तैनात करनी पड़ी।

आज भारतीय राजनैतिक दलों की (खास कर सत्ताकांक्षी दलों की) स्थिति बकरी की पूंछ जैसी हो गयी है : न वह मच्छर को हटा सकती है, न ही अपनी इज्जत भी वह बचा पाती है। आज के राजनैतिक दल जन शक्ति का इतना भरोसा नहीं करते जितना कि उन को शासन में है। चाहे जिस रास्ते से लोगों के वोट पा कर सत्ता हथिया लेना और उस के मार्फत सब तरह के परिवर्तन हो जायेंगे ऐसी अंधश्रद्धा लोगों में जगाना वे पर्याप्त मानते हैं। मधु लिमये तथा जिन दलों के वह सदस्य रहे हैं वे सभी दल इसी चक्कर में फँसे हैं।

कानून लोकमत की मुहर बने ऐसी स्थिति पैदा करना कष्टप्रद है। उस के बदले कानून की जंजीरों से वे लोग सब को बांधना चाहते हैं। लोकमत की मुहर बने ऐसी स्थिति पैदा करना कष्टप्रद है। उस के बदले कानून की जंजीरों से वे लोग सब को बांधना चाहते हैं। लोकमत की मुहर बने ऐसी स्थिति पैदा करना कष्टप्रद है। उस के बदले कानून की जंजीरों से वे लोग सब को बांधना चाहते हैं।



## कला

के सिद्धांत आत्मा की तरह होते हैं। प्रकट होने के लिए उन का संगठनात्मक शरीर आवश्यक होता है। लेकिन साठ वर्ष के करीब पहुँचे नेताओं को इतना धीरज कहाँ है! झट धोया फट पहना वाली नायलोन नीति द्वारा वे काम करना चाहते हैं। पक्षांतर्गत लोकतंत्र को एक न एक बहाना बना कर सभी राजनैतिक दल ठुकरा रहे हैं। गठजोड़ के लिए किसी सैद्धांतिक आधार को वे जरूरी नहीं मानते। जनता के विश्वास के वे पात्र नहीं हैं। “आज की पक्ष पद्धति कारावास तो नहीं बनी है।” ऐसा आरंभ में एक अवतरण मधु लिमये ने दिया है, भारत के संदर्भ में वह सही है।

लोकतंत्र में संपूर्ण प्रभुता नागरिक की ही होती है, होनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने वाले नेताओं के बारे में सामान्य नागरिक क्या सोचता है, यह देखना चाहिए। आपात्काल से भी कठिन समय आया है और तिस पर भी विकल्प बनने के इच्छुक दिलों को नागरिक नकारता है, यह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन महँगाई विरोधी आंदोलनों को नागरिक का साथ नहीं मिल रहा है। वह इतना बुजदिल आज बन गया है, यह अधिक चिंता का विषय है। आज की बढ़ती महँगाई और जनता पार्टी के कार्यकाल के सुस्थिर भावों के बारे में चर्चा निकलने पर एक सामान्य जन ने तपाक से कहा, “हम ने सत्ता तुम्हारे सुपुर्द की थी। हम ने थोड़े ही आप को अपदस्थ किया। आप ही लोगों ने आपसी अनबन के कारण अपने को अपदस्थ किया है। अब आप का भरोसा कैसे मानें? अब तो जो हो उसी में गनीमत मान कर चलना होगा।” जिन लोगों ने जनता का विश्वास खोया है और राजनैतिक सटोरियों के हाथ सभी सूत्र जिन्होंने सौंपे हैं उन को अब निवृत्त होना चाहिए और नये नेताओं को अवसर देना चाहिए।

आज सारी दुनिया संभ्रमित अवस्था में चौराहे पर खड़ी है। सूझ नहीं रहा है। “जायें तो जायें कहाँ” ऐसा प्रश्न सब के सामने खड़ा है। नवनिर्माण की वेदनाओं से दुनिया संव्रस्त है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उन की उन वेदनाओं को महसूस कर रहे थे। लेकिन सत्ता के सटोरियों ने उन को निराश तथा अपमानित कर दिया है और उस के फल वे आज भोग रहे हैं। आज की मुर्दनी हटानी है, तो लोकशक्ति का निर्माण ही उस का कारगर इलाज हो सकता है। प्रबोधन-रचना तथा संघर्ष ही उस का एकमात्र रास्ता हो सकता है।

—यदुनाथ थले

भारतीय राजनीति का नया मोड़ : मधु लिमये, समता पुस्तक माला, नयी दिल्ली।

विनमान

## गढ़ी : यह जगह और अच्छी हो सकती है

ललित कला अकादमी की गढ़ी कार्यशालाएँ देश में अपने ढंग की अभी तक अकेली कार्यशालाएँ हैं। गढ़ी झड़िया मड़िया नाम के गाँव के पास ये कार्यशालाएँ हैं। यह गाँव स्वयं दिल्ली में लाजपत नगर इलाके के पास है। गाँव के, जो अब दरअसल शहर का ही रूप ले चुका है, शुरू होने से पहले ही ये कार्यशालाएँ एक काफी बड़े उद्यान के चारों ओर बनी हुई हैं। कार्यशालाओं का लकड़ी का काफी बड़ा मुख्य दरवाजा पुराने दिनों का ही है जो याद दिलाता है कि कभी यहाँ सचमुच की गढ़ी यानी एक छोटा गढ़ रहा होगा। कार्यशालाएँ स्वयं नयी हैं—पत्थरों की बनी हुई। इन में से एक कार्यशाला सिरैमिक के लिए है, एक मूर्तिशिल्प के लिये, एक ग्राफिक्स के लिए, एक चित्र के लिए। इन के अतिरिक्त कुछ स्टूडियो हैं जिन में यह व्यवस्था है कि कोई एक ही कलाकार काम कर सके। उद्यान में अशोक, मौलश्री और नीम के पेड़ हैं। स्वयं उद्यान का रखरखाव बहुत अच्छा है। इस तरह यह कलाकारों के लिए एक अनुकूल वातावरण में काम करने की अच्छी जगह है।

लेकिन गढ़ी के अब तक के इतिहास में कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। कभी वह बहुत सक्रिय दिखी है, कभी शिथिल और यह अब तक वे अपेक्षाएँ पूरी नहीं कर सकी जो कि इस की परिकल्पना में थीं। आजकल यहाँ जो कलाकार काम कर रहे हैं उन में प्रमुख हैं : कृष्ण खन्ना, हिम्मतशाह, मनजीत बाबा, मृणालिनी मुखर्जी, अमिताभ दास, गोगी, मनोहर आत्रे, गौरी खोसला, दरोज, संतोष, नरीन नाथ आदि। यहीं कुछ वर्षों तक सुप्रसिद्ध कलाकार ज. स्वामीनाथन भी काम करते रहे हैं। हर कार्यशाला के साथ एक प्रशिक्षक-प्रबंधक भी जुड़ा हुआ है। ग्राफिक कार्यशाला के प्रशिक्षक-प्रबंधक देवराज हैं। सिरैमिक के श्री शर्मा हैं, मूर्तिशिल्प की कार्यशाला में इन दिनों कोई प्रशिक्षक-प्रबंधक नहीं है। चित्र कार्यशाला में यों उस की जरूरत भी नहीं है और उस का प्रावधान भी शुरू से रखा भी नहीं गया था। इस कार्यशाला में चित्रकारों को ईजल मर उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

गढ़ी की परिकल्पना के समय सोचा यही गया था कि यह रचनाशील कलाकारों के काम करने की जगह होगी और उस का उद्देश्य प्रशिक्षण का नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है दिल्ली में और देश में कई कला महाविद्यालय मौजूद हैं ही। गढ़ी के वर्तमान निदेशक सुधी रंजन भूषण



गढ़ी ग्राफिक्स कार्यशाला में युवा कलाकार

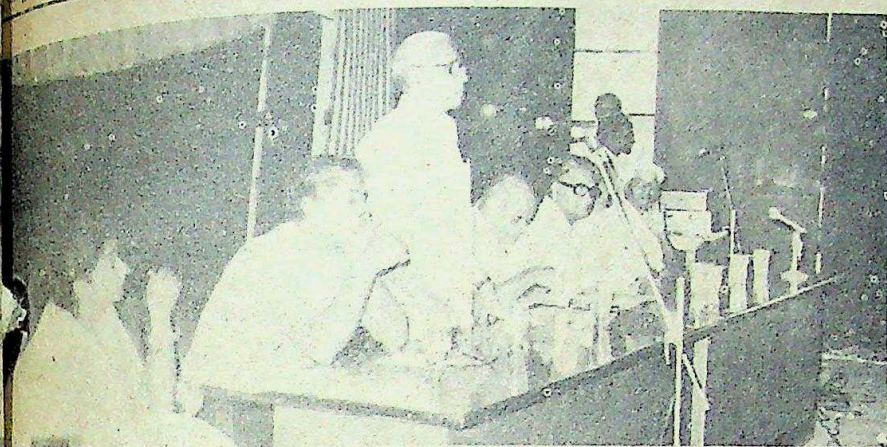
स्वयं कलाकार हैं और दिल्ली में दो दशकों से रह रहे हैं। अपने कार्य उन्होंने गतिविधियाँ बढ़ाने के कुछ प्रयास हैं जिन में से कार्यशिविरों का आयोजन व्याख्यान, स्वयं गढ़ी में कार्यशिविरों में गये कामों का प्रदर्शन आदि हैं। लेकिन कुछ अर्से से गढ़ी में एक शिथिलता पड़ती है। यहाँ यह उल्लेख कर देना होगा कि ललित कला अकादमी की पिछले दो वर्षों में गढ़ी के लिए कुछ को शोध वृत्तियाँ देने की शुरुआत गयी है। इस के लिए देश के विभिन्न हिस्से से कलाकार आवेदन कर रहे हैं। लेकिन गढ़ी को और रचनात्मक के लिए, अब ऐसा लगता है कि कोई उपाय भी किये जाने चाहिए। अक्सर कार यह महसूस करते हैं कि कला और अकादेमी की राजनीति कई बार पर भी हावी हो जाती है जब कि उसे से एक स्वतंत्र रचनात्मक संस्था के क्षेत्रों से देखा जाना चाहिए। कुछ बढ़ाते की जरूरत भी निश्चय ही दीख मसलन चित्र स्टूडियो में एक साथ कलाकार काम करते हैं और सब को काम करने की जगह नहीं मिलती। व्यक्तिगत रूप से किसी कलाकार को काम करने के लिए स्टूडियो देने के हैं—और कुछ कलाकारों को निश्चय की पर्याप्त जरूरत भी होती है। हिम्मत शाह ने जो पिछले कई वर्षों शिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करते इधर सिरैमिक माध्यम में भी किया है, और बड़े आकार में भी करते हैं। लेकिन जरूरत इसी बात की करने की सुविधाएँ और बढ़ें। और गढ़ी प्ठित और युवा प्रतिभाएँ समान रूप

गढ़ी में (बाएँ) आंदोलन विविध

आका उद्देश्य किये बिना पु का संगीत, नृ का की जा स मान के साथ स्कार बनान सक गतिविधि नये जीवन का सही उ की को समन्व मंच में है। हिंदी भाषी विभाग न की और अ विद्यालयों औ मंच विभाग और रचना म माना न प्रकारों से पर उन्होंने मंचंद्र जैन, विद्यालय के स प्रेक्षागृह लय संगोष्ठी का के मुख्य और शिक्षा के वृत्त में भा इसी प्रेक्षागृह द्विवेदी के कला के नाट उपन्यास अ शिक्षा औ निदेशक गिरी



रंगमंच



गोष्ठी में (बाएँ से) गिरीश रस्तोगी, मोहन महर्षि, नेमिचंद्र जैन (बोलते हुए), गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एस.पी. नागेंद्र तथा अन्य

## रंगमंच और विश्वविद्यालय

आका उद्देश्य सर्जनात्मक शक्ति को सक्रिय करने का आयोजन किया बिना पुरा नहीं होता और न नाट्य कार्यशिविरो में भाग लेना ही जा सकती है। विश्वविद्यालय का काम के साथ कला का रिश्ता जोड़ना, स्कार बनाना और सांस्कृतिक बौद्धिक-गतिविधियों द्वारा अपने खुले क्षेत्र में नये जीवन की चेतना और रचनात्मकता का मही उपयोग करना है। व्यक्ति को समन्वित करने की शक्ति निश्चित रचनात्मकता में है। इन शब्दों के साथ नेमिचंद्र हिंदी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में विभाग न होने की स्थिति पर चिंता की और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के अनेक विश्वविद्यालयों और विदेशों में विश्वविद्यालयों मंच विभाग की उपस्थिति को उत्साह-पूर्ण रचनात्मक कलात्मक दृष्टि का माना। सर्जनात्मक अभिव्यक्ति के प्रकारों से शिक्षा के संबंध की आवश्यकता ही दोष पर उन्होंने बल दिया।

नेमिचंद्र जैन, हिंदी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय संगोष्ठी में रंग आंदोलन और विश्वविद्यालय के माध्यम से उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में साहित्य, और शिक्षा के संबंधों और मूल्यों पर एक वृत्त में भाग ले रहे थे। इस संगोष्ठी से इसी प्रेक्षागृह में स्वर्गीय आचार्य हजारी द्विवेदी के उपन्यास 'बाणभट्ट' की प्रस्तुति, उपन्यास और नाटक, साहित्य और शिक्षा और कला के संबंधों के विषय में वार्तावर्णन बन चुका था। रूपांतरकार निदेशक गिरीश रस्तोगी की इस प्रस्तुति

ने प्रस्तुतीकरण में अपनायी गयी भरतमुनि की शास्त्रीय पद्धति और आधुनिक नाटक में उस की उपयोगिता पर भी प्रश्न उठाये थे।

गोष्ठी में स्थानीय साहित्यकारों बुद्धि-जीवियों, शिक्षाविदों के अतिरिक्त मोहन महर्षि (अध्यक्ष रंगमंच विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़), डा. केदार नाथ सिंह, श्रीराम वर्मा ने भाग लिया। मोहन महर्षि ने विश्वविद्यालय में नाटक विभाग को एक आवश्यकता मानते हुए नाटक और रंगमंच के प्रति उपेक्षाभाव को पिछड़ी हुई मानसिकता का परिणाम बताया। उन्होंने उस शिक्षा को निष्प्राण और निरर्थक बताया जो युवावर्ग की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाती। युवा शक्ति और स्फूर्ति उमंग को आत्मसंतोष और संतुलन नहीं दे पाती बल्कि भाषा के बारे में प्रयोग में, बनावटी बुरे शब्दों में भाषणों को लपटती है और भाषा की जीवंत शक्ति, उस की ध्वन्यात्मकता विवात्मकता से और रंगमंच की भाषा की जीवंतता से परिचय ही नहीं होने देती। कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यमों और अपनी संस्कृति को समझने के लिए अभ्यास और संस्कार की अपेक्षा को रोचक शब्दों में समझाते हुए उन्होंने आंतरिक अनुशासन के लिए रंगमंच के महत्त्व को स्वीकार किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में गिरीशचंद्र चतुर्वेदी, कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक और बुनियादी प्रश्नों को विचारणीय बताया। उदाहरणार्थ उन्होंने कहा कि थियेटर के वे मूल तत्व कौन से होंगे जिन का संबंध शिक्षा के लक्ष्य से जुड़ा है? क्या रंगमंच शिक्षा में परिवर्तन ला सकता है? विश्वविद्यालय में उसके कोई सांस्कृतिक मूल्य हैं? शिक्षा तथा जीवन के लिए उस की सार्थकता क्या होगी? प्रतिकुलपति डा. एस.पी. नागेंद्र और अधिष्ठाता कला संकाय, डा. ए.सी. बनर्जी ने भी रंगमंच की सार्थकता और कलात्मकता को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक

गठन में विश्वविद्यालयों को मुक्त आधार कहा। अंत में हिंदी विभाग के प्रो. एवं अध्यक्ष डा. रामचंद्र तिवारी ने शिक्षा और रंगमंच के संबंध, रंगमंच की विशिष्टता और सर्जनात्मकता को रेखांकित किया।

अगली गोष्ठी, रंग आंदोलन और विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर हुई। डा. केदारनाथ सिंह ने रंगमंच को सही जमीन से उठाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्त्व को स्थापित किया और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ पर बोलते हुए सामाजिक राजनीतिक और रचनात्मक दबाव के कारण नाटक को गति और उत्तेजना देने वाला माध्यम कहा और युवा वर्ग की अस्मिता के विकास में रंगमंच को व्यापक अर्थ में लेने पर बल दिया, उसे केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं माना। सामूहिक चरित्र, मानवीय गुण की शक्ति, मुक्तछंद जैसी वार्तालाप की लय होने के कारण उन्होंने रंगमंच को एक सशक्त लेकिन खतरनाक माध्यम कहा। श्रीराम वर्मा ने रंगमंच का संबंध रंगमंच से जोड़ा तो रूपांतर के कलाकार प्रमोदकुमार पांडे ने अभिभावकों की मानसिकता और सामाजिक दृष्टि बदलने में रंगमंच की अहं भूमिका मानी। डा. परमानंद श्रीवास्तव, डा. शिवाजी सिंह ने इस गोष्ठी में कवि और समीक्षक डा. विश्वनाथ प्रसाद, हरीश माथुर और रामनरेश श्रीवास्तव ने गोष्ठी में भाग लिया।

रंगमंच की सृजनशीलता पर मोहन महर्षि ने अभिनेता की जागरूकता, चितनशीलता को अनिवार्य मानते हुए विभिन्न धाराओं से सीख कर अखबार से ले कर हर विषय, ज्ञान विज्ञान दर्शन आदि से जुड़ कर रंगदृष्टि तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा युवा वर्ग के मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास में रंगमंच और विश्वविद्यालय का संबंध सहायक ही सकता है। दूरदर्शन और फिल्म रिकार्डेंड सत्य है जबकि रंगमंच जीवंत अनुभव है और वह अभिनेता का माध्यम है। गोष्ठी में रंगकर्मियों और साहित्यकारों में सरनबली श्रीवास्तव, ए. आर. मौमिक, राजेश वर्मा, दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव, आनंद राय, संत कुमार श्रीवास्तव, नवनीत मिश्र ए. बी. लाल आदि ने कई प्रश्न उठाये। अंत में अध्यक्ष डा. एस. पी. नागेंद्र ने तीसरी दुनिया को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने, उन मूल्यों को खोजने, कला और जीवन के सार्थक संबंध को विकसित करने और शाश्वत मनीषा को सुरक्षित रखने के लिए रंगमंच को विशिष्ट माध्यम कहा। डा. रामचंद्र तिवारी ने अपने समापन भाषण में सांस्कृतिक गठन और कला एवं जीवन के सार्थक संबंध की प्रतिष्ठा में विश्वविद्यालय को उपयुक्त स्थल माना और भविष्य में भी ऐसी गोष्ठी को कामना की। □



## फिल्म



'अंगूर' में मौसमी चटर्जी और संजीव कुमार

## तमाशा गलतफहमियों का

फिल्म निर्माता निर्देशक गुलजार अपनी अनेक फिल्मों में विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन आमतौर पर उन्होंने इन स्रोतों के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं किया।

अपनी नयी फिल्म अंगूर में उन्होंने कृपापूर्वक विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के प्रति शुरू में ही आभार प्रकट कर दिया है। फिल्म के अंत में हम शेक्सपियर को दर्शकों को आँख मारते हुए भी देखते हैं।

इन दिनों हिंदी फिल्मों में मारघाड़ की फिल्मों का बोलबाला है। अच्छी और सुसज्जित पूर्ण कॉमेडी फिल्में दुर्लभ होती जा रही हैं। इस हालत को ध्यान में रखते हुए गुलजार ने थोड़ा अलग तरह का काम किया है। 'अंगूर' एक याद रहने वाली कॉमेडी भले ही न हो लेकिन वह एक कामचलाऊ कॉमेडी तो है ही। हिंदी फिल्मों की डिशुम डिशुम और तस्करी की भयावह दुनिया से घबड़ाया हुआ दर्शक 'अंगूर' से थोड़ी बहुत राहत पायेगा और फिर इस में ताराचंद्र बड़जात्या शैली की 'नकली नैतिकता' भी नहीं है।

वैसे 'अंगूर' के बारे में यह बात जरूर कहने की इच्छा होती है कि इस फिल्म को सेंसर ने 'ए' प्रमाणपत्र क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं कि इस में कोई खास आपत्तिजनक प्रसंग है बल्कि इसलिए कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसे अवयस्क दर्शकों के लायक समझा जाये। कहानी की बनावट, संवादों और स्थितियों में जो बातें सामने आती हैं वे दरअसल वयस्क दर्शकों के हँसने और समझने के लायक ही हैं। आखिर अगर किसी सुंदर

युवती के गयन कक्ष में पति के धोखे में कोई हमशक्ल आदमी आ जाये, तो जो स्थितियाँ सामने आयेंगी उन का मजा वयस्क दर्शक ही ले पायेंगे।

लेकिन हमारे यहाँ सेंसर ने हमेशा सतही कारणों से किसी फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र देने या न देने लायक समझा है। बल्कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि फिल्म निर्माता खूब पैसे वगैरह खर्च कर के कोशिश करते रहते हैं कि उन की फिल्म को कहीं 'ए' प्रमाणपत्र न मिल जाये। इस के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि आम घरों में 'ए' फिल्मों के नाम से ही आतंक सा छा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ घरों की लड़कियों को इन फिल्मों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। खैर।

'अंगूर' फिल्म की शुरुआत में एक जहाज दुर्घटना में जुड़वा बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता है। सेठ के जुड़वा बच्चे तो अलग हो ही जाते हैं— गरीब जुड़वा बच्चे भी अलग अलग हो जाते हैं। यानी साहब और गुलाम अलग अलग पलते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो एक शहर में अचानक तमाम गलतफहमियों के बीच में बुरी तरह से फँस जाते हैं। इन गलतफहमियों का अंत जाहिर है

कि मुखद होता है।

इस फिल्म के साहब हैं संजीव कुमार गुलाम हैं देवेन वर्मा। एक रोल में संजीव कुमार शादीशुदा है और अपनी बीवी (मौसमी चटर्जी) की हार पहनने की जिद में पड़े हैं। दूसरे रोल में संजीव कुमार अमीर हैं और जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते जोर-जोर से काफ़ी दूर जा चुका है। और नौकर तो नौकर है। फर्क सिर्फ इतना है कि शादीशुदा साहब का नौकर भी शादीशुदा है। उस की भरी पूरी देह वाली पत्नी (अमिताभ बच्चन की ईरानी) उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। शादीशुदा साहब की साली (दीप्ति नवल) भी है।

गुलजार फिल्म कला की अपनी विशेषता का अधिक इस्तेमाल न कर के एक नाटक को जैसे फिल्माते से नजर आता है। कहीं कहीं हास्य हमें दिलचस्प जगहों पर ले जाता है। लेकिन अक्सर वह फिल्म चाल से ही चलता नजर आता है। गाने इस फिल्म में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन गुलजार ने किसी तरह से दो गाने दे ही दिए हैं। अभिनय की दृष्टि से जरूर इस फिल्म का अंदाज पेशेवर आता है।

## अधूरी फिल्मों की दास्तान

28 साल पहले एक फिल्म बनना शुरू हुई। पहले तो इस फिल्म के निर्माता का निधन हो गया। बाद में निर्देशक का भी निधन हो गया। इस फिल्म की लगभग 85 प्रतिशत शूटिंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह फिल्म आज भी डिब्बों में बंद है। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि इस के नायक हैं दिलीप कुमार और नायिका हैं नूतन। यह जोड़ी पहली बार सिनेमा के पर्दे पर आने जा रही थी। लेकिन इस फिल्म का दुर्भाग्य था कि वह कभी पूरी न हो पायी। दिलीप कुमार, नूतन बाद में किसी फिल्म में एक साथ काम भी न कर सके।

यह जानकारी एक सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आयी है। शबाब अहमद ने कुछ साल पहले अमेरिका में रह रहे भारतीय फिल्मकार कृष्ण शाह के निदेशन में सिनेमा सिनेमा नाम से एक फिल्म बनायी थी। अब शबाब अहमद फिल्म ही फिल्म नाम से एक और फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म का विषय भी भारतीय सिनेमा है।

'फिल्म ही फिल्म' के निर्माण के दौरान

बंबई में एक सर्वेक्षण कराया गया। से यह पता चला कि पचास से भी अधिक बरसों से अधूरी पड़ी हुई हैं। इन में से प्रतिशत फिल्में इस लिए नहीं पूरी हो पाईं। अभिनेताओं और निर्देशकों के बीच अहंता लड़ाई चल रही थी। इन में से दस प्रतिशत फिल्में इस लिए अधूरी हैं कि नायिका शादी करा ली और घर बसाने के लिए सिनेमा की दुनिया में वापस आना नहीं समझा।

नीतू सिंह, मुमताज और राजेश्वरी फिल्मों के साथ यही हुआ। अमिताभ बच्चन की अधूरी फिल्मों की सूची सब से लंबी है। कई फिल्में तो तब से अधूरी पड़ी हैं जब एक नामी कलाकार भी नहीं बने।

समस्या सिर्फ फिल्मों की ही नहीं है। की भी है। दो हजार से अधिक फिल्में रिकार्ड करने के बाद फिल्माये भी गये हैं वे आज भी डिब्बों में बंद हैं।

जाहिर है कि इन अधूरी फिल्मों और गानों की मदद से एक पूरी फिल्म तो कम बनायी ही जा सकती है।



# कृति समाचार

## आधुनिकता और

### साहित्य

मार्च में चार अप्रैल को रामनारायण रुइया के हिंदी विभाग तथा साहित्य और से 'आधुनिकता और आज का साहित्य' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन प्रा. वलसंगकर, प्रा. रामदत्त, प्रा. वि. निवसरकर की देखरेख तथा प्रा. वि. रामसकल शर्मा ने की। अध्यक्षता डॉ. रामसकल शर्मा ने की। डॉ. रामसकल शर्मा ने अपने आलेख 'आधुनिकता के सवाल पर, में केवल आधुनिकता की परिभाषा को ले कर अपनी बात रखी। उसमें उन्होंने कहा कि विदेशों में सम-संबंधों को क्रांति कहा जाता है, इसे आधुनिकता मानते हैं जबकि हम इस आधुनिकता से स्वयं को जोड़ नहीं पा रहे हैं। आधुनिकता की नहीं, सुख की बात है। व्यक्तिवादी अराजकतावादी 'आधुनिक' इस स्थिति को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। अराजकतावादी के कारण ही आदमी को फेंक दिया जा रहा है। जहाँ वह अपने और अकेलेपन को अनुभव करता है, स्थिति ठोस आर्थिक भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जबकि होता यह भी है कि एक जगह से कट कर यदि अकेला हो तो दूसरी जगह इस तरह कटे हुए अकेले पड़े लोग एक दूसरे से जुड़ भी नहीं पाते। डॉ. त्रिभुवन राय ने आधुनिकता के हिंदी नाटक पर आलेख पढ़ा। उन्होंने अपने आलेख में कहा 'समय और अंतर' से उपजा अंतर जब चेतना और अंतर पर महसूस किया और भोगा तो उस के साथ साथ एक दर्शन और संवर्तता है, एक दृष्टि जनमती और पैदा होती है, फिर यह दृष्टि एक चुनौती होती है, उन सब के लिए जो समय के अंतर को नहीं, समय को रास्ता दिखाने का दावा भी करते हैं। प्रा. देवेश ठाकुर का आलेख 'आधुनिकता और आज की हिंदी कहानी' को उन्होंने गतिशील और रचनात्मक प्रक्रिया है और समकालीन परिस्थितियों और अंतर को जोड़ती हुई होती है और दूसरी ओर से संपूर्ण होने के साथ साथ उस से अंतर को देखने की कोशिश है।

—प्रा. जे. राजपूत

## बनारस में 'स्पार्टाकस'

वाराणसी में मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में हावर्ड फास्ट की विश्वविख्यात कृति पर आधारित बादल सरकार के नाटक आदि विद्रोही स्पार्टाकस (अनु. रति बाथेलोम्पु) वीरेंद्र सबसेना, निर्देशक डॉ. प्रमोद अग्रवाल का प्रदर्शन वाराणसी के रंगप्रेमियों के लिए एक उत्तेजक अनुभव रहा।

आदिकाल से बिल्कुल आज तक होने वाले मानव द्वारा मानव के शोषण और उस पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की शास्वत गाथा का नाम है 'स्पार्टाकस'। नाटककार ने अपने आलेख में इस 'तथ्य' को भी रेखांकित करने की कोशिश की है कि



'स्पार्टाकस' का एक दृश्य

समर्थ और संपन्न व्यक्तियों द्वारा सर्वहारा के शोषण की स्थिति किसी भी देश काल और समुदाय में बिल्कुल एक जैसी होती है—चाहे वह रोम हो या भारत। बादल बाबू के इस नाटक का कथ्य तो विचारोत्तेजक और रोचक है ही, इस आलेख की दूसरी विशेषता है शिल्पगत बुनावट की सघनता और नवीनता जिस के चलते वे हावर्ड फास्ट के बृहद कैनवास को दो घंटों के संक्षिप्त आलेख में समेट सके हैं। निर्देशक, अभिनय, संयोजन, मंच उपयोग, गति विधानों में एक संतुलन बनाये रख सका और यह प्रस्तुति यहाँ हो रही आम प्रस्तुतियों से अलग हट कर संतोषजनक प्रभाव डाल सकी। अभिनेताओं में अशोक सेठ (बटियाट्स) अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उमरे, शेष अभिनेताओं में राजेंद्र कपूर (स्पार्टाकस), निमी सिन्हा (वारीनिया) नंदिनी मेहता (हेलेना),

अनूप अरोणा (क्रासुस) एवं दीपक (सूत्र-धार) ने भी अच्छी संभावनाएँ प्रदर्शित कीं।  
—कुमार विजय

## पटना में 'सगीना महतो'

पटना की नाट्य संस्था अंतरंग की ओर से पिछले दिनों वार्षिकोत्सव के अवसर-पर सगीना महतो का मंचन स्थानीय भारतीय नृत्यकला मंदिर में किया गया। इस नाटक के मूल कथाकार गौर किशोर घोष, नाट्य रूपांतर बादल सरकार तथा अनुवादक यामा सराफ हैं।

नाटक में अरविंद रंजन दास का निर्देशन सशक्त रहा और साथ ही साथ गौरा की भूमिका में अपने अच्छे अभिनय के कारण दर्शकों को लुभाने में समर्थ रही। अभिनय के दृष्टिकोण से सगीना, ललिता, विशाखा, सुखन सिंह एवं महादेव की भूमिका में क्रमशः बी. मंडल, नूतन सिन्हा, सुस्मिता बोस,



'सगीना महतो' में मंडल और नूतन

संजय कुमार उपाध्याय एवं शशि कुमार वर्मा का अभिनय उत्तम कोटि का रहा। बाकी और सभी कलाकारों का अभिनय प्रभावशाली नहीं रहा।

नाटक अपनी विषयवस्तु और कथ्य में बेहद पका हुआ और मजबूत है। इस नाटक में इस बात को दर्शाया गया है कि जिस समय श्रमिक वर्गों के संगठन का प्रचलन नहीं हुआ था उस समय मालिक लोग किस तरह से भूखे, गरीब तथा कमजोर मजदूरों का खून चूसते थे। इन्हीं अत्याचारों के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग संगठन की योजना बनी परंतु वह भी गंदे राजनैतिक दलों के जाल में फँस कर रह गयी जिस के कारण न तो अच्छा औद्योगिक वातावरण बना और न ही मजदूरों की रक्षा हो सकी।

—मिथिलेश कुमार सिन्हा



## चरित चर्चा



### श्यामलाल शकधर

ऐसा कभी कभी ही होता है किसी का नाम जीवन में उस के वास्तविक काम का सही सही परिचायक हो। चुनाव आयुक्त लोकतांत्रिक शासन पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव की निर्भीक निगरानी करता है। और संयोग यह है कि शकधर-चौकीदार नाम का व्यक्ति ही आज भारत का चुनाव आयुक्त है।

लोकसभा में विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त श्यामलाल शकधर लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इस पद पर पहुँचे। और हर सीढ़ी पर उन्होंने अपनी योग्यता और साहस का परिचय दिया। नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के कुछ महीने पहले सत्तारूढ़ दल और सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध कदम उठाकर, सार्वजनिक रूप से आलोचना करके और फैसले दे कर चुनाव आयुक्त ने लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश का यह पहला चुनाव आयुक्त है जिन के जीवन में नाटकीय घटनाएँ एक के बाद एक आती रही हैं।

बिनमान

1977 का आम चुनाव जिस मे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आपात्स्थिति के अमृतपूर्व शक्तिशाली अस्त्रों से लैस थी विपक्ष के लिए भयहीन वातावरण में चुनाव की व्यवस्था करना शायद इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण घटना होगी।

आरोप लगाया गया था कि शकधर की सहायुक्ति विपक्षी दलों के साथ है। मगर 1980 के आम चुनाव में जनता पार्टी के उखड़ते हुए पाँव को सँभालने में शकधर ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया। हाल ही में गढ़वाल चुनाव के सिलसिले में चुनाव आयुक्त ने सभी सत्तारूढ़ शक्तियों के विरोध के बावजूद एक ऐसा फैसला लिया जिस के कारण यह उपचुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया पिछले वर्ष जून में गढ़वाल के कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की कठिनाई हुई। तुरंत जाँच करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान तो निरस्त कर दिया। और नये मतदान का आदेश जारी किया।

नयी तिथि की घोषणा करते समय भी उत्तरप्रदेश सरकार ने उन के फैसले का डट कर विरोध किया था। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया। उन के अनुसार निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। उस के सिलसिले में सत्ताहीन या सत्तारूढ़ के बीच भेदभाव नहीं बरता जा सकता।

—ज. कौ.

### स्वामी अग्निवेश

स्वामी अग्निवेश हरियाणा में अंबाला कैट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गये हैं। जनता पार्टी के उम्मीदवार गैरिकवसन धारी स्वामी अग्निवेश चुनाव अभियान के लिए मुश्किल से 15 दिन पहले निकलते समय बोले—'नये ढंग से चुनाव लड़ना है, जातिवाद, संप्रदायवाद सब से मतदाताओं को ऊपर उठा कर उन्हें हरियाणा की राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में बताना है। मतदाता को

जागरूक कर के उस का मत पाना मेरा उद्देश्य है।' सो वह अंबाला की गली गली नुक्कड़ सभायें करते रहे, पहले चार-छह फिर दस-बीस फिर सौ-पचास की भीड़ के सामने सिद्धांत की बात करते रहे—न झूठे वायदे करते रहे, न प्रलोभन देते रहे, न जाति दल के नाम पर उकसाते रहे—राजनीति और राजनीतिज्ञों की बात करते रहे। और इस तरह मतदाताओं से बातचीत और संवाद की स्थिति बनाते रहे, वहस करते रहे और फिर अपनी झोली फैला कर पैसा भी उन्हीं से लेते रहे। राज्य में बंधुआ मजदूर



मुक्ति आंदोलन के अकेले योद्धा के रूप में संघर्षरत स्वामी अग्निवेश सत्ता और पैसे वाले वर्ग की आँखों के काँटे रहे हैं। उन से हमदर्दी उन्हीं की रही और है जो साधनहीन हैं।

उन की हार से यह सिद्ध है कि साधनहीन की हमदर्दी से, सच्चाई के बल पर, सही सार्थक संवाद स्थापित कर आज चुनाव नहीं जीता जा सकता। आंध्र में पैदा हुआ, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में वचपन बिताया हुआ। यह व्यक्ति कलकत्ते से अपना कार्यक्षेत्र हरियाणा ले आया और इस क्षेत्र में आर्यसमाज के नेता के रूप में धर्म की अंधी गलियों से ऊपर उठ, अपने कार्य को शोषितों से जोड़ता रहा और नक्सलवादी होने का आरोप भी सहता रहा। जनता शासन में शिक्षामंत्री रहे स्वामी अग्निवेश 'अपनी हार को 'जनता को और जागरूक करने के अभियान की शिक्षा' के रूप में ग्रहण करते हैं। —स. द. स.



### ना. ग. गोरे

जून 15, 1982 को जीवन के 75 कर रहे महाराष्ट्र के नेता, साहित्यकार तथा नारायण गणेश गोरे को मरवा दिया जा रहा है।

यूथ लीग के प्रवर्तक समाजवादी दल के संसद में लोक सभा तथा के सदस्य, ब्रिटेन में भूतपूर्व राजदूत। ऐसी जिम्मेदारियों का वहन आज तक किया है। स्वतंत्रता संग्राम के उन का समावेश होता है बाद रियासत के विद्रोह तथा गोवा विमोचन तक संघर्ष में वे रहे। मराठी तथा वैचारिक साहित्य अपना एक विशेष स्थान वे मराठी के शैलीकार माने जाते हैं। पत्रकारिता में अपना स्थान रहा है।

उन का कहना है—'पूजक हूँ। सौंदर्य पूजा राजनीति में खींचा है। देखता हूँ कि सौंदर्य की प्रति के लिए समाज व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। राजनीति में परिवर्तन शक्ति है।' जनता पार्टी भारतीय नेताओं में से प्रमुख नेता तो हैं ही, उनके निर्माण में भी उन का हिस्सा रहा है।







# Say it...



## with PNB Gift Cheques

How often did you receive or give as a gift something that was not needed.

Yet it is so easy nowadays to give just what would be liked... with PNB's Gift Cheques of Rs. 11, Rs. 21, Rs. 31, Rs. 51 or Rs. 101.

Give a Gift Cheque and a choice too (at no extra cost) to buy what is wanted....

...and show that you care.

# punjab national bank

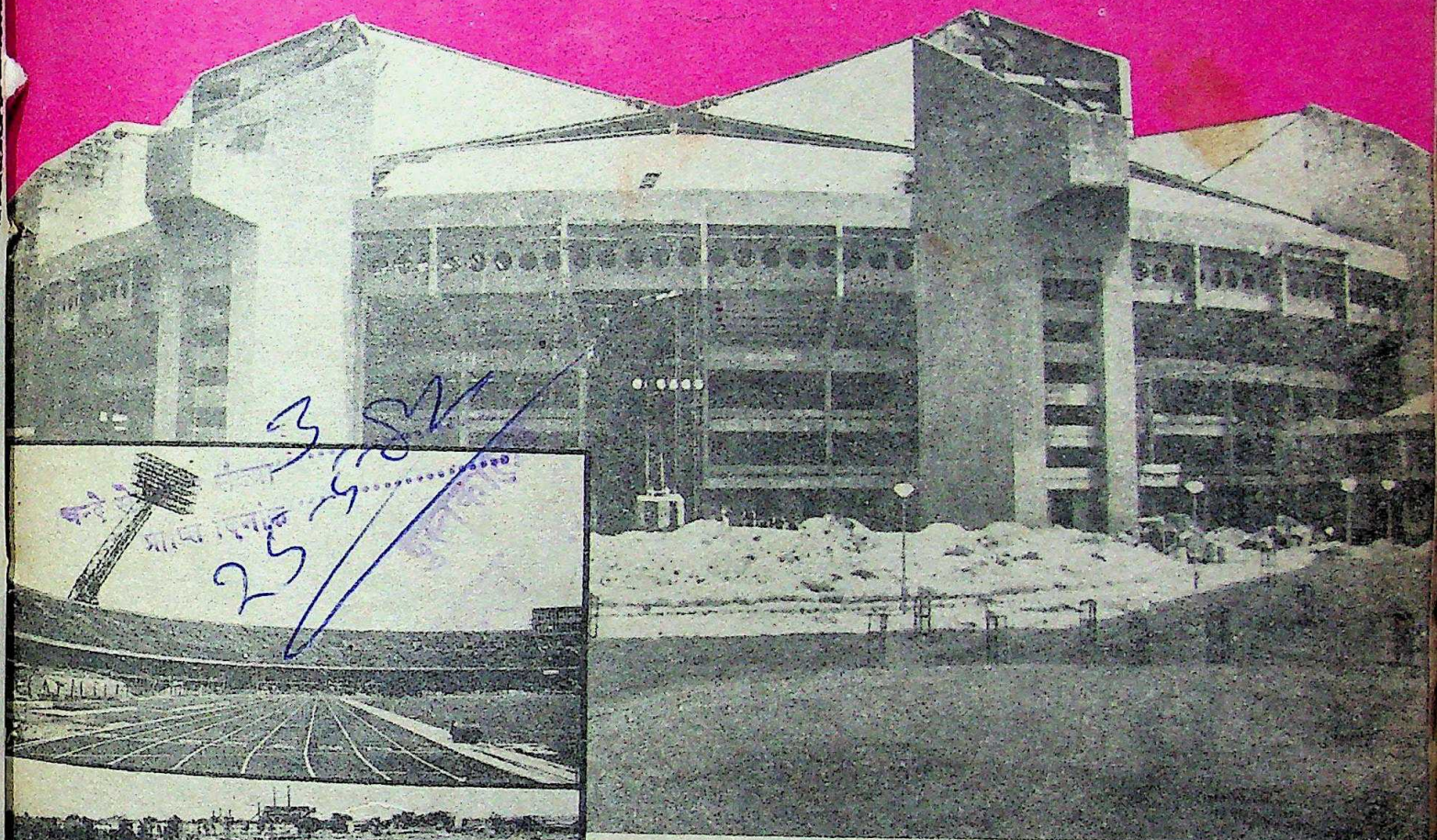
(A Government of India Undertaking)

...the name you can BANK upon



# दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन



## एशियाई खेल

क्या हमारी तैयारियाँ छठवें  
नंबर पर आने के लिए ही हैं?

## भारतीय कार उद्योग

मारुति के गमले में  
सुजूकी की पौध  
किन शर्तों पर लगी



29 मई, 1982

2-8 ज्यूलै, 1904

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

रु. 2.00



# साफ़, ताज़ा सांस मज़बूत, स्वस्थ दांत



## कोलगेट डेन्टल क्रीम से

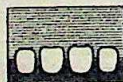
हर भोजन के बाद अपने दांत कोलगेट से साफ़ कीजिए। यह ठीक उसी तरह दांतों की रक्षा करता है, जैसे दुनिया भर के दांतों के डाक्टर कहते हैं।

दांतों में छुपे हुए अन्नकणों में कीटाणु बढ़ते हैं। इनसे सांस में बदबू पैदा होती है, और दांतों में सड़न भी।

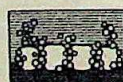
इसीलिए, हमेशा भोजन के फ़ौरन बाद कोलगेट डेन्टल क्रीम से दांत साफ़ कीजिए। यह सांस को ताज़ा, दांतों को सफ़ेद और दांतों की सड़न रोकने में असरदार साबित हो चुका है।

कोलगेट का ताज़ा पेपरमिंट जैसा स्वाद मन में बस जाता है।

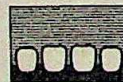
देखिए, कोलगेट के भरोसेमंद फ़ार्मूले का काम :



दांतों में छिपे हुए अन्नकणों में, सांस में बदबू और दांत में सड़न पैदा करनेवाले कीटाणु बढ़ते हैं।



कोलगेट का अनोखा, असरदार झाग दांतों के कोने में छिपे हुए अन्नकणों को और कीटाणुओं को निकाल देता है।



नतीजा : आपके दांत आकर्षक सफ़ेद, आपकी सांस तरोताज़ा और दंतक्षय की रोकथाम।

**कोलगेट डेन्टल क्रीम से  
सांस की बदबू रोकिए-  
दंतक्षय का प्रतिकार  
कीजिए...**



दांतों की पूरी देखभाल के लिए कोलगेट ट्राइफ़ाई टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। तीन गुना बेहतर है।

- 1 दांतों के रंग में रक्षा करता है।
- 2 दांतों पर बनी परत को हटाता है।
- 3 मयूषों की रक्षा करता है।



## संपादक कन्हैयालाल नंदन

सहायक संपादक  
जितेंद्र गुप्त

मुख्य उपसंपादक  
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

संपादकीय सहकर्मी

श्यामलाल शर्मा

जवाहरलाल कौल

शुक्ला रुद्र

त्रिलोक दीप

महेश्वरदयालु गंगवार,

प्रयाग शुक्ल

बनवारी

विनोद भारद्वाज

सुषमा पाराशर

विशेष संवाददाता

रामसेवक श्रीवास्तव

सज्जा

रवि शर्मा

संपादकीय कार्यालय

10, दरियागंज,

नई दिल्ली 110002.

व्यवस्थापन तथा प्रसार

विभाग

7, बहादुरशाह जफर मार्ग,

नयी दिल्ली-110002.

बंबई

डा. दादामाई नौरोजी रोड

अहमदाबाद

139, आश्रम रोड

कलकत्ता

13/1, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट

मद्रास

63, मोंटियस रोड,

एगमोर

पुणे

407-1, तीर्थ भवन,

स्वार्डर गेट

लंदन

26, स्टेशन एग्रीच, सडबरी

बंबई, मिडिलसेक्स, लंदन

यू. के.

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट दिल्ली के पास जमुनापल पर खड़े हैं। इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम की और मजूर दौड़ाई तो दिल्ली का नक्शा खेल-खेल में बदल जाने का विश्वास होने लगता है। एशिया का सब से बड़ा और दुनिया का तीसरे नंबर का यह इन्डोर स्टेडियम चौबीसों घंटे काम की गहमागहमी से मरा रहता है। एशियाई खेलों की तैयारी के बहाने दिल्ली की कायापलट होती जा रही है लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसी बहाने कितने ही लोगों की आर्थिक कायाकल्प भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के प्रख्यात खेल प्रेमी विजयकुमार मलहोत्रा आजकल अक्सर कहते हैं कि 'हालत यह है कि एशियाड के नाम पर लूट मची है। पता नहीं रातोंरात सरकार के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गये!'

लेकिन एशियाई खेलों के अधिकारी ऐसी आलोचनाओं को अनगल प्रलाप समझ कर पूरी तैयारी में हैं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुए हैं। रोज मीटिंगें होती हैं, काम की निगरानी की निगरानी होती है और ढिलाई करने वालों की खिचाई होती है। कुछ सरकारी अधिकारी तो इतने घबराए हुए रहते हैं कि 'एशियाड' के नाम से कान पकड़ कर कहते हैं: "राम राम कर के यह बवाल टले। नौकरी बचे बस इतना बहुत है।" यानी इधर लोगों की नौकरियाँ दाँव पर हैं और उधर राजा मालिंदर सिंह ने एशियाई खेलों में भारत की स्थिति के बारे में 'दिनमान' को बताया कि "मैं मानता हूँ कि हमारी स्थिति बँकाक जैसी हो होगी अर्थात् छठी।" (देखिए पृष्ठ 7) तो क्या ये सारी तैयारियाँ सिर्फ भारत को छठवें स्थान पर लाने के लिए हो रही हैं। 'दिनमान' ने अपने संवाददाता त्रिलोक दीप को इस दिशा में खोजबीन के लिए लगाया। आवरण कथा में एशियाई खेलों की तैयारियों की जानकारीयाँ और इन जानकारीयों के पीछे की जानकारीयाँ प्रस्तुत हैं।

लेकिन अपने स्तंभ में इंदरजीत जी ने इस बार (पृष्ठ 20) पर ऐसे सवाल पर कलम चलायी है जिस का बाजार इस 'लघु आम चुनाव' के परिणामों के बाद सब से ज्यादा गरम होने वाला है: "दुख है कि इस तरह रंग बदलने वाले गिरगिटों की तिजारत को बंद करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। वेश्यावृत्ति तो देश में बहुत पहले कानूनन बंद कर दी गयी लेकिन राजनैतिक रंडीबाजी का बाजार लगातार गर्म होता गया है। ताज्जुब इस बात का कि बेशर्मी में इसे एक शानदार जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर के चला जा रहा है।" इंदरजीत जी के इस विश्लेषण के तथ्य और इस समस्या के तमाम पहलुओं पर प्रस्तुत है: "विधायकों को एक और जबर्दस्त नीलामी।"

इसी के साथ इस बार भारतीय कार निर्माताओं की कुरूप कथा। यह मारुति लि. के साथ जापानी फर्म सुजूकी का सहयोग किन शर्तों पर होने जा रहा है इस की जानकारी के लिए भारतीय और चंद विदेशी कार निर्माता अपने जासूसी घोंड़े दौड़ाते रहे लेकिन मारुति के गमले में सुजूकी की पीठ को लगने से काट न सके। यह जरूर हुआ कि उन की नींद टूटी और अपनी अपनी कारों के भाग्य बदलने की तरकीबें सोचने लगे। आइए देखें कि भारतीय कार उद्योग की अंदरूनी तस्वीर है क्या और जितने में उपभोक्ता को कार मिलती है उस में उपभोक्ता कितने पैसों का माल पाता है और कितना पैसा कहाँ जाता है।

कन्हैयालाल नंदन

इस सप्ताह



पृष्ठ 29



पृष्ठ 21

आवरण कथा : एशियाड के नाम पर कितनी लूट 8.

एशियाड के निर्माणकार्य का

मविष्य क्या है 8.

मजदूरों के शोषण की नींव पर 7.

चीनी प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली

में 15. डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी से

मैं 17.

भारतीय मोटर कार उद्योग

की कुरूप कथा :

मारुति और सुजूकी का समझौता

21-25.

साहस यात्रा : लीजिंग से करा-

कोरम तक 29.

ऊर्जा : बिजली हम भी बनायेंगे

28.

समयचक्र : विधायकों का एक

और बड़ा नीलाम 20.

बिहार : अपने ही घर पर धरना;

मध्यप्रदेश : उज्जैन में हरिजनों पर

अत्याचार, आधुनिक विश्वामित्र 31.

प्रखेपास्त्र : रूस और अमेरिका,

फाकलैंड, ईरान-इराक युद्ध,

नामीबिया, पाकिस्तान 27.

मत सम्मत 4. पिछले सप्ताह 5-6.

पत्रकार संसद् 6. युवाजगत 11.

उन का कहना है 12. चरचे

और चरखे 13. चुनाव चौपदा

13. दिल्ली के रंग 14. दुनिया

भर की 39. विज्ञान 40. शिक्षा

42. वित्त 43. साहित्य 44.

रंगमंच 45. संगीत 46. कला 47.

फिल्म 48. संस्कृति समाचार 49.

चरित चर्चा 50.

आवरण: एशियाई खेल (पृ. 7)

फोटो: विमल सक्सेना



## अश्लील विज्ञापनों पर कालिख पोतिये

25 अप्रैल-1 मई : 8 मार्च को अंतर-राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना ने जो अभियान चलाया वह बेशक सराहनीय है। युवतियों ने अश्लील विज्ञापन एवं पोस्टरों पर कालिख पोत कर अपने अदम्य तथा साहसी कार्य का ही परिचय नहीं दिया बल्कि उन्होंने नारी वर्ग को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने तथा भारतीय संस्कृति को उजागर करने में योगदान दिया है। अश्लील विज्ञापन निश्चित नारी के शोषण का परिचायक है।

विज्ञापनों पर कालिख पोतने का अभियान जहाँ कुछ मायने में उचित है वहीं दूसरी ओर यह सिर्फ औपचारिक, हास्यास्पद तथा कोई ठोस कारगर कदम नहीं है। आखिर कितने विज्ञापनों और पोस्टरों पर कालिख पोतना संभव है? फिर कल तब पोस्टर लगेंगे। यदि इस अभियान को युवतियाँ सफल बनाना चाहती हैं तो सब से पहले उन के मुँह में कालिख पोतनी होगी जो इन्हीं अश्लील विज्ञापनों में मॉडल बनने की होड़ में खड़ी हैं।—लालबहादुर सिंह, हॉलैंड हॉल छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

ऐसे अभियान देशव्यापी चलने चाहिए, न कि किसी क्षेत्र विशेष में। दुख इस बात का है कि ऐसे अभियान किसी विशेष अवसर या उत्सव पर ही किये जाते हैं, जैसे कि पटना की युवतियों का अभियान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही किया गया। जब तक ऐसे अभियानों का सामान्यीकरण नहीं किया जाता तब तक किसी विशिष्ट उपलब्धि की आशा नहीं करनी चाहिए।—कृष्णचंद्र उपाध्याय, 2/21 डॉ. तारा चंद छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

पटना में चलाये गये इस अभियान को एक ऐसी शुरुआत माननी चाहिए जो हमारी संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण है। यह शुरुआत पटना से हुई है और यदि धीरे धीरे अन्य नगरों तक पहुँचती है तो विभिन्न नगरों में मुख्य चौराहों, गली मोहल्लों में लगे अश्लील पोस्टर काफ़ी हद तक कम हो जायेंगे; साथ ही भविष्य में विज्ञापनों को अश्लील होने से बचाया भी जा सकेगा। आज आवश्यकता है इस अभियान को सफल बनाने की: तब ही इस शुरुआत की सार्थकता है।—एस. डी. चूरा, 36, नाडी मोहल्ला, पाली मारवाड़ (राज.)।

आधुनिक समाज की विडंबना है कि जहाँ औरतों को अपेक्षाकृत अधिक आज़ादी मिली है वहीं वे सजावट की भी वस्तु बनती जा रही हैं। ट्रक के टायर से लेकर स्नो तक के विनयान

## न्याय चाहिए

मैं मीरजापुर जिले (उ. प्र.) के चुनार तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का इंटर प्रथम वर्ष का छात्र है, जितने लड़कों ने प्रवेश लिये हैं उन में उस का अधिकतम अंक है। इस आधार पर दी जाने वाली स्कालरशिप दो वर्ष के लिए मिली है मात्र 16 रु. प्रतिमास, जब कि उसी कक्षा में पिछड़ी जातियों (कुर्मी) के लगभग सभी बच्चों को 62 रु. प्रतिमास. स्मरण रहे कि इस तहसीर की 70 प्रतिशत जनसंख्या कुर्मियों की है, उन लोगों के पास ट्रेक्टर, जीपें, कारें हैं। स्कूटर उन लोगों के लिए साइकिल के समान है, संपूर्ण सैकड़ों की संख्या में ईंटों की चिमनियाँ कोल्ड स्टोरेज उन्हीं लोगों के पास है, प्रत्येक गाँव में ट्रकें हैं वह भी उन्हीं की हैं। एक साधन संपन्न कुर्मी से मैंने पूछा कि आप इस तरह की छात्रवृत्ति अपने लड़के के लिए क्यों लेते हैं उन्होंने कहा कि सरकार अंधी है देती है तो क्या फेंक दूँ। मैं दोनों समय बच्चों को भोजन जुटा नहीं पा रहा हूँ। पुत्र मेधावी है तो 16 रु. छात्रवृत्ति और पिछड़ी जाति के नाम पर लखपति कुर्मियों के बच्चों को 62 रु. प्रतिमास मदद दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि पिछड़ा आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय गरीबी में जी रहे लोगों पर भी विचार किया जाये।—रामानंद दूबे, चुनार (मीरजापुर)

विज्ञापनों में उन के शरीर का खुलेआम प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इन प्रदर्शनों में औरतों ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम मदद नहीं की है। आधुनिकता मात्र वस्त्रों की नहीं विचारों की होनी चाहिए।—आलोक यादव, षष्ठ वर्ष, समाजशास्त्र, क्रमांक-9, पटना विश्वविद्यालय।

## पूर्वांचल की समस्या

25 अप्रैल-1 मई : 'लड़ाई दो गैर-बराबर ताकतों के बीच है' शीर्षक लेख के संदर्भ में सर्वप्रथम यह कहना पड़ेगा कि लड़ाई दो ताकतों के बीच नहीं है, वरन् तीन ताकतों के बीच है : चर्च, विश्वहिंदू संगठन एवं आदिवासी धर्म। दूसरी बात कि लेखक महोदय ने निष्पक्षता का कवच मात्र ओढ़ा है। यह रपट एकतरफ़ा और अपूर्ण है। उसने मुख्यमंत्री का समर्थन ही किया है। उस के वक्तव्यों का मूल्यांकन तथ्य के आधार पर नहीं किया है। इस का मूल कारण है लेखक का एक पक्ष की ओर झुकाव।

अरुणाचल प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता एक मखौल है क्योंकि, लेखक के अनुसार ही, अरुणाचल प्रशासन आदिवासियों को ईसाई बनाने से रोकने हेतु और हिंदू बनने के लिए

सभी सुविधाएँ और लालच प्रदान कर रहा है, जिस की पुष्टि लेखक ने स्वयं की है।  
—वि. टोप्यो, पत्थलकुदवा, राँचे

पूर्वांचल की समस्या को बहुत ही वास्तविक अर्थों में व्यक्त करने के लिए जिले गुप्त को बघाई. वस्तुतः इस समस्या के लिए जिम्मेदार पक्ष, यानी कि सरकार द्वारा की गयी इन राज्यों की उपेक्षा ही एक प्रमुख कारण है कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ घर्मांतरण करवाने, पृथक्तावाद का विषम करने में सफल रही हैं।

आवश्यकता है देश के अन्य भागों में उपर्युक्त राज्यों जैसी समस्याओं को प्रचारित कर के ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र का भंडा फोड़ करने की, ताकि देश के अन्य आदिवासी पिछड़े तथा संवेदनशील क्षेत्रों में लालच घोखा दे कर घर्मांतरण को रोका जा

देश के राजनीतिकों के स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण ही आज सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था अशक्त होती जा रही हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी विश्वहिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार छुआछूत विरोध साहित्य का प्रचार गाँव गाँव में कर के एक चेतना उत्पन्न की है वह अभी नहीं तो कुछ समय बाद सुखद परिणाम अवश्य लायेगी।

विधा भारती क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर क्या है? आर. एस. एस. ही तो है। ये वास्तव पूर्वग्रह से प्रेरित लगते हैं।—अशोक शर्मा, द्वारा इलाहाबाद बैंक, जालौन. (उ.प्र.)

## सांप्रदायिकता का जहर देश की अखंडता के लिए घातक

25 अप्रैल-1 मई : कन्याकुमारी जिले में सांप्रदायिक दंगे में ईसाई मछुआरों और हिंदू दंगाइयों को तितरबितर करने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। इस घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस की लपटें तमिषनाडु के दूसरे जिलों में तक बढ़ते बढ़ते दूसरे राज्यों से लेकर पूरे देश में फैल सकती है, जिस से पूरे देश की अखंडता को भी खतरा पैदा हो सकता है। इस सांप्रदायिकता रूपी जहर को फैलने से रोकने तथा दोनों संप्रदायों के बीच भाईचारा कायम करने के लिए सामाजिक, राजनैतिक और सरकारी तानों स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए।  
—प्रो. सुरेशप्रसाद सिंह, राजनैतिक विभाग, रामाधीन महाविद्यालय, शेखपुरा (मुंगेर) भागलपुर विश्वविद्यालय।



8-14 मई, 1982

देश

8 मई : अमृतसर पटियाला में रात्रि कर्फ्यू में ढील. दिल्ली के कई मंदिरों में गोमांस फेंका गया. असम रेल दुर्घटना में तीन की मृत्यु. शेख अब्दुल्ला द्वारा गिलगित, हुंजा और स्काई को पाक अधीनस्थ मानने की जिया की टिप्पणी पर आपत्ति.

9 मई : झारखंड आंदोलन का विस्तार. चुनाव आयुक्त शकधर को चुनावों के शांतिपूर्व होने की आशा. प्रधानमंत्री द्वारा विरोधी दलों पर केंद्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप. गृहमंत्री जैलसिंह द्वारा धर्म विरोधी कार्यवाइयों को रोकने के लिए कानून में संशोधन का संकेत.

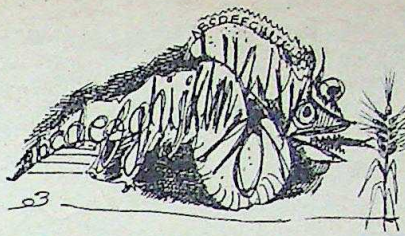
10 मई : प्रधानमंत्री द्वारा शराबारी तत्वों से सावधान रहने की सलाह. दिल्ली में बाल्मीकि-जाटव संघर्ष में कई जख्मी. अमृतसर में रात्रि कर्फ्यू बढ़ाया गया. उ. प्र. में बच्चों के लिए घटिया खाना. मराठवाड़ा में सूखा.

11 मई : प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों की स्वायत्तता को कम कर के न आंकते का आश्वासन. सेना के दल द्वारा 475 दिन में पूर्ण हिमालय की परिक्रमा. चुनाव आयुक्त शकधर द्वारा चुनाव के समय प. बंगाल में सैनिकों की मांग. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समरेन्द्रचंद्रदेव आनंदमार्ग हत्याकांड की एक सदस्यीय जांच समिति के अध्यक्ष.

12 मई : प्रधानमंत्री द्वारा प. बंगाल में माकपा पर आक्रमण से चुनाव प्रचार प्रारंभ. मुख्य चुनाव आयुक्त संतुष्ट. झंडवालान देवी मंदिर पर स्वामित्व के झगड़े में ईका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता घायल. महा-राष्ट्र राज्य विद्युत ब्रोड द्वारा स्विस फर्म को प्रोजेक्ट. दूरदर्शन कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह की धमकी.

13 मई : दिल्ली में तेज वर्षा और ठंड. दिल्ली के 35 वर्षीय पेशे से बलक कवलजीत द्वारा देवी को बायीं भुजा में ट. फूलन देवी को आश्रय देने के आरोप में 50 गिरफ्तार. इस वर्ष तेल आयात के लिए रूस भारत में समझौता शीघ्र.

14 मई : राज्यों को फसल क्षति के लिए अधिक नृण. प्रधानमंत्री की सितंबर के अंत में रूस यात्रा की संभावना.



## वैधानिकता के पीछे की मानसिकता

कुछ दिन पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कनिष्ठ शोध छात्र वृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा में कोई उल्लेख नहीं था, किंतु उत्तर पुस्तिका में निर्देशित था कि अंग्रेजी में ही उत्तर लिखना वैधानिक होगा. इस वैधानिकता के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, इस पर अधिक विवाद नहीं करना चाहूंगा, किंतु अंग्रेजी की कलम से पैदा हुए कृषि विभाग के विशेषज्ञों से पूछना चाहूंगा कृषि के लिए किस भाषा की जरूरत है. भारत में, जहाँ कि 80 प्रतिशत ग्रामीणों में से 70 प्रतिशत जनता जो आज भी बहुसंख्य परंपरागत तरीके से खेती कर रही है, अधिकांश अंगूठा छाप ही हैं. (आंकड़े छोड़िये, क्यों कि वे दिल्ली में ही तैयार होते हैं) उन को अनुसंधानों, कृषि प्राविधियों, योजनाओं को बताने के लिए किस भाषा की जरूरत है, अंग्रेजी, या हिंदी की? यहाँ सवाल हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित करना नहीं रहा, बल्कि अब हिंदी बोलना और लिखना भी अवैधानिक (गैर-कानूनी) माना जायेगा.—आनंदकुमार त्रिपाठी, 15, गौतम बुद्ध होस्टल, गोरखपुर विश्वविद्यालय.

## सच्चे क्रांतिकारी अब कहाँ हैं?

आपने दिनमान, 25 अप्रैल-1 मई के अंक में पंडित परमानंद जी के विषय में सामयिक सूचना प्रकाशित की है. इसे पढ़ते समय मुझे एक अन्य सेनानी का ध्यान आ गया, जिन के साथ सौभाग्य से मैं स्वयं भी कुछ दिन, सन् 1942 के आंदोलन में 'अंडर ग्राउंड' रहा था. उन को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब राज्यसभा के लिए आमंत्रण दिया तो उन्होंने पंडित जी से कुछ रुखे स्वर में ही कहा था, 'जिस कुर्सी पर अंग्रेज बैठते हैं क्या तुम मुझ को वहीं पर बैठाना चाहते हो' और ऐसा कह कर उन्होंने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था. उन का नाम है पंडित काशीनाथ पांडेय. ऐसे क्रांतिकारी अब कहाँ हैं और आज काशीनाथ जी अपनी नैतिकता का मूल्य गरीबी में चुका रहे हैं.—मुरेंद्र अप्पवाल, सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र, 35 फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली.

दुर्भाग्य इतना ही है कि अधिकांश हिंदू वर्ग निर्धन है. धन, लालच, धोखा, फरेब से कोई जंचा नहीं बन जाता. धर्म प्रचारकों का गंदा रूप है यह जो कुछ ईसाईबहुल क्षेत्रों में हो रहा है उस का उत्तर न तो बोट प्रेरित राजनीतिज्ञों के पास है व न ही कर्तव्य-विमुख बुद्धिजीवी वर्ग के पास.—कमल कान्त, द्वारा कालड़ा विक्लिस्तालय, जगदीश कलौनी, शोहतक.

कन्याकुमारी की रपट में आपके संवाददाता ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष प्रमाणित करने के चक्कर में लीपा पोंती करने की कोशिश की है. हमारे गृह राज्यमंत्री तथा तमिषनाडु के मंत्री ने संसद और विधानसभा में जो वक्तव्य दिये हैं वे स्पष्ट साबित करते हैं कि ईसाई मछुआरों ने समुद्र में स्नान करती स्त्रियों पर आक्रमण किया, उन के कपड़े फाड़ डाले और उन का शील मंग किया. पुलिस ने स्त्रियों के नंगे बदन ढकने के लिए वहाँ लगे शामियाने आदि फाड़ कर उन के शरीर को ढका. हिंदू अब जागना चाहता है तो उसे को अपने पूजा करने के अधिकार से अपने ही देश में वंचित किया जा रहा है. कन्याकुमारी केंद्र बनते समय डाली गयी लावट तो जग जाहिर है. आज ईसाई कन्याकुमारी जिले में बहुमत में हो गये हैं तो वह 'क्रेमेर' जिला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब शोर मचा रहे हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है.—राख बिहारी, संगठनमंत्री, विश्वहिंदू परिषद, हरयाणा.

प्राप फरमाते हैं  
व्यंग्य चित्र : लक्ष्मण



मुझे अपनी कुर्सी से कोई टस से मस नहीं कर सकता. जब तक केंद्र का साया मुझ पर है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते.

दिनमान

3-29 मई



8-14 मई, 1982

विदेश

8 मई : ब्रिटेन ने फाकलैंड को अधिक लड़ाकू विमान भेजे, भारत में ब्रितानी उच्चायुक्त सर जान धामसन की विदेश सचिव एम. के. रसगोवा से भेंट, भारत और यूगोस्लाविया के बीच कई मुद्दों पर समझौता, 1982 का कलिंग पुरस्कार वेनेजुएला के विज्ञान पत्रकार को, बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पक्ष के उपाध्यक्ष देंग बियाओपिंग और अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की भेंट.

9 मई : ब्रिटेन द्वारा फाकलैंड पर पुनः हमला, इसादली विमानों द्वारा लिबाना में फिफिस्तीनी गुरिल्ला मोर्चों पर हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा इस के विरुद्ध चीन से एकता की अपील, पोलैंड में पुनः अव्यवस्था की आशंका.

10 मई : ब्रिटेन द्वारा फाकलैंड पर आक्रमण जारी, संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा फाकलैंड समस्या पर समझौता वास्ता, ईरानी फौजों द्वारा खुर्मनशहर की घेराबंदी, उ. लिबाना में संघर्ष में 20 की मृत्यु, 136 घायल, बारासाड (पोलैंड) में संघर्षों को रोकने के लिए सन्धि नियुक्त.

11 मई : ब्रिटेन द्वारा आर्जेंटीना के जहाज पर हमला, संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा परमाणु सस्त्र वातां अगले महीने, अफगान समस्या पर जिम्मा में 15 जून को वातां: जिवा.

12 मई : भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए उनके सप्ताह वास्ता की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय सचिव रुमा मल्हात्राजी की हत्या, बारासाड में ब्रितानी जहाजों ने दो आर्जेंटीनी लड़ाकू विमानों को गिराया.

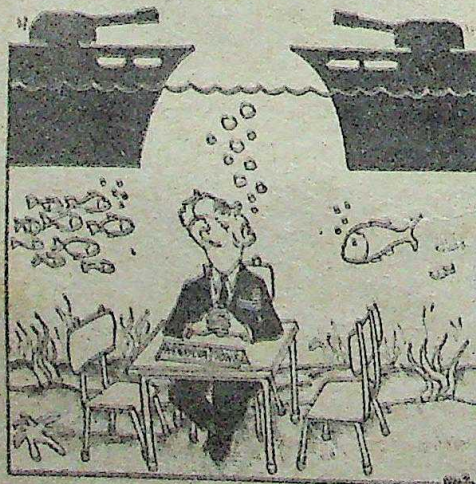
13 मई : ब्रिटेन का लड़ाकू जहाज आर्जेंटीना से मुक्तबले में अतिप्रसन्न, पीपू पर हमले के आरोप में एक विमानों, भारत चीन के बीच सीमा रेखा और अन्य मुद्दों पर वास्ता में चीन आशाविस्त.

14 मई : ब्रिटेन-आर्जेंटीना कई मुद्दों पर समझौता, रक्षा व्यय पर रोगन की जीत, चित्रबैक द्वारा पाकिस्तान को एक करोड़ 40 लाख डॉलर

# खुमैनी का मविष्य : आर्हेंतीना और बम

ईरान इराक युद्ध भड़क उठने से पश्चिम-शिया की स्थिति पर विश्व के समाचार पत्रों में पिछले सप्ताह व्यापक चर्चा हुई है. एक ओर तो दोनों देशों की लड़ाई के समाचार पत्रों का मुख्य समाचार बना दूसरी ओर संपादकीय लेखों में ईरान की आंतरिक स्थिति का विश्लेषण देखने को मिला. प्रसिद्ध ब्रितानी साप्ताहिक इकानामिस्ट ने अपने ईरान स्थित संवाददाता के हवाले से प्रमुख धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी की हत्या के षड्यंत्र का विवरण प्रकाशित किया है. इस प्रसंग में पत्र ने लिखा है :

'अयातुल्ला खुमैनी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में भू. पु. विदेशमंत्री श्री कुतुबजादे और अयातुल्ला खुमैनी के प्रतिस्पर्धी धार्मिक नेता श्री अयातुल्ला खरियत मदारी को गिरफ्तार किया जा चुका है. श्री कुतुबजादे ने अभी पिछले सप्ताह अयातुल्ला खुमैनी की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप को स्वीकार किया है. जिस के कारण उन्हें मृत्यु दंड मिलना प्रायः निश्चित है. निस्संदेह अयातुल्ला खुमैनी को मार कर सत्ता हस्तगत करने का षड्यंत्र ईरान में काफी समय से है और अब यह जोर पकड़ रहा है. अयातुल्ला खरियत मदारी के सभी पक्ष तो छिप ही लिए गए हैं इस के अलावा उन के घर और आसपास के उन के अन्य लोगों की तलाशियां भी ली गयी हैं. लगता है ईरान की सरकार का निशाना केवल ये दो नेता ही नहीं हैं, अयातुल्ला खुमैनी का विरोध करते वाले युवा वर्ग के और बहुत से लोग भी हैं. दरअसल बात यह है कि ईरान के मुल्ला भी अयातुल्ला खुमैनी का उत्तराधिकारी ढूँढ रहे हैं.



फाकलैंड संकट वातां 'गाडियन' साप्ताहिक के ध्वजकार की दृष्टि में

रहे हैं. इस्लामी देश बनने के बाद ईरान ने आर्थिक सुधारों का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ है. और अधिक स्थिति दिनोदिन खराब होती जा रही है. ईरान के मुल्ला और धार्मिक नेता शाह के जमाने से ही भूमि सुधार जैसे आर्थिक कार्यक्रमों के खिलाफ रहे हैं. उन का ध्यान तो मस्जिदों और धार्मिक स्थानों की तरफ रहा है. इन सब कामों में इन धार्मिक नेताओं को बड़े बड़े जमींदारों और सरमापेदारों से मदद मिलती है. उधर धार्मिक प्रभुत्व पाने के लिए ईरान के मुल्लाओं में प्रतिस्पर्धा भी रहती है. अब यह प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गयी है. धार्मिक नेताओं में अयातुल्ला खुमैनी का सीधे विरोध करने का साहस नहीं है. इन मुल्लाओं ने अयातुल्ला खुमैनी का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर रखा है. तेहरान रेडियो ने एक प्रसारण में श्री खुमैनी ने कहा भी था कि जो लोग मेरी हत्या करने और इस्लामी क्रांति को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हें शायद इस्लाम की ताकत का पता नहीं है.

## आर्हेंतीना और बम

फाकलैंड पर ब्रिटेन और आर्हेंतीना के बीच मौजूदा लड़ाई के संदर्भ में ब्रितानी साप्ताहिक गाडियन की यह टिप्पणी शायद बहुत आश्चर्यजनक है कि आर्हेंतीना परमाणु बम बना रहा है. हाल ही की अपनी एक संपादकीय टिप्पणी में पत्र ने इस प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डाला है. केवल आर्हेंतीना के पास परमाणु बम होने की अटकल ही लगायी है. पत्र का विचार है :

'आर्हेंतीना ने परमाणु बम निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस का मतलब है वह या तो परमाणु बम बनाने की सोच रहा है या उस के पास है. जिस संधि के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका को परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र घोषित किया गया है उस पर भी आर्हेंतीना ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस का मतलब है कि वह परमाणु बम बनाने के लिए बिल्कोप करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता है. अगर आर्हेंतीना ने परमाणु बम बनाया भी तो वह अन्य परमाणु बमों के बिल्कुल भिन्न होगा. इस समय आर्हेंतीना एक दृढ़ संघर्ष की स्थापना कर रहा है. इस के बाद वह प्लेटोनम बनाने का कारखाना स्थापित कर लेगा. आर्हेंतीना अपने आपकी बहुत जल्दी परमाणु शक्ति संपन्न कर लेना चाहता है. पर ब्रिटेन महसूस कर रहा है कि आर्हेंतीना को आक्रमण से रोक रहे के लिए उसे के पास परमाणु अस्त्र होना बहुत आवश्यक है.



# एशियाड : कितनी लूट, कितना शोषण

अलेख : त्रिलोक दीप चित्र : विमल सक्सेना

हाँ, न और फिर हाँ की जिरह और ऊहापोह से निकल नवें एशियाई खेलों का वर्ष आ ही नहीं गया बल्कि एक तिहाई बीत भी चुका है। आसपास के निर्माणकार्यों की प्रगति को देख कर अब एशियाड के आयोजन पर तो यकीन होने लगा है लेकिन उसकी सफलता असफलता पर अटकलें अभी भी जारी हैं। स्टेडियम, फ्लाईओवर और होटलों के ढँचे तो दीखते हैं लेकिन समय पर उन के तैयार होने पर अभी भी कयास लगाये जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेहमान तो आ कर द्वार पर दस्तक दे दें और मेजबान सामसजी में ही उलझा हो।

ऐसी छीछालेदर न हो इस लिए निर्माण कार्य की गति में तेजी आ गयी है। इन्द्रप्रस्थ जैसे स्टेडियम में चौबीस घंटे दो पारियों में काम हो रहा है तो मुख्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंजीनियरों और श्रमिकों की आँखों में रात की खूमारी साफ दीखती है। वे दावा भी करते हैं कि यह सरकारी कामकाज थोड़े ही है, चुनौती है। मिशन के तौर पर पूरी बतिया के साथ काम कर रहे हैं।

लेकिन दुबले, पतले, मरियल और कुछ तगड़े भी राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार के मजदूरों के सामने मिशन नहीं शुद्ध रोटी का सवाल है। इन सारे निर्माण-कार्यों से जुड़े लगभग सवा लाख मजदूरों के सामने इस समय एक ही सवाल है : 'इस के बाद क्या होगा?' कुछ तो जवाब स्वयं ही दे देते हैं : 'गांव लौट जायेंगे, दो-चार महीने बैठ कर खा लेंगे।' तो कुछ तगड़े किस्म के लोग कहते हैं : 'दिल्ली में काम की कउन कमीयो है, बूढ़े लेव।' यद्यपि दिल्ली प्रशासन के नियमों के अनुसार एक अकुशल मजदूर रु. 11.60 प्रतिदिन का हकदार है तो कहीं उसे दस सवा मिलता है तो कहीं इस से भी कम। बोलते वे हैं नहीं। सवाल रोटी का है। मजदूरों के ठेकेदारों का हौवा भी है। हालाँकि आज कल से तो कटाई के कारण मजदूरों की कमी है लेकिन जिस प्रकार बेमौसम की वर्षा से खेतों का बनाव खराब हो गया है उसी प्रकार यो सवालिया निशान लगा गया है। लिहाजा ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण बरकरार है। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे देखें

कि एशियाड परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिले और 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूर के तौर पर भर्ती न किया जाये। इस निर्देश का विरोध करने वालों के विरुद्ध उचित दंड का भी आदेश दिया गया है।

लेकिन कुछ लोगों के तो एशियाड ने वारे न्यारे कर दिये हैं। प्रतिपक्ष तो इसे 'एशियाड के नाम पर लूट' करार देता है। उस के अनुसार आज हर व्यक्ति चाहे सरकारी अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी अपना तबादला एशियाड से संबंधित किसी न किसी दफ्तर में कराने की जुगाड़ में रहता है। यह सोच कर शायद गर्दिश के सितारे गलती से मुस्करा दें। बहरहाल, जिन पर मुस्कराये



राजीव गांधी : खेल दृष्टि

हैं खूब मुस्कराये हैं। इसे वे बेशक कबूलें या न कबूलें उन के चेहरे और सेहत 'सितारों के मुस्कराने' की बात अलबत्ता कह देती है।

ऐसे लोगों में ठेकेदार, मजदूरों के नेता, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वर्ग ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोग हैं जिन का कमी खेल से वास्ता नहीं रहा और वे किसी न किसी खेल समिति के सदस्य बन गये हैं। इसे खेल अधिकारी भी स्वीकारते हैं और प्रतिपक्ष को तो मानो उछालने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। बेशक लगभग 65 करोड़ की आबादी वाले भारत में हम चमत्कार करने का दावा कर सकते हैं लेकिन तभी जब हम क्षेत्रवाद, संकुचित विचारधारा, राजनैतिक झमेलों और आपाधापी से ऊपर उठें। यदि हम खेल को खेल की भावना से ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते तो लाख कोशिश करने पर भी हम



श्रमिकों के तफ़रीह के क्षण

शायद ही किसी नतीजे पर पहुँच सकें। लेकिन हम कहीं पहुँच सकें इस की कोशिश कुछ लोग पार्श्व में रह कर रहे हैं जिनमें संसद सदस्य राजीव गांधी का नाम आता है। वह किसी भी समिति के सदस्य या अध्यक्ष नहीं लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब वह दिल्ली में हों और किसी न किसी स्टेडियम, खेल कार्यालय में न पहुँच जायें, क्योंकि खेलों में रूचि है, समझ है, आधुनिक दृष्टिकोण है। वह सलाह तो देते हैं लेकिन एक खेलप्रेमी की हैसियत से। लेकिन यह हैसियत कमी विशेषज्ञों के भी कान खड़े कर देती है। अभी हाल ही में एशियाई खेलों के सूचना-प्रसारण सुविधाओं का आकलन करने के लिए जो बैठक हुई उस में दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा दी जा रही जानकारियों की जम कर खिचाई हुई और विशेषज्ञ दंग रह गये कि खेल प्रेमी राजीव गांधी खेल सूचनाओं की तकनीक के इतने गहरे जानकार कैसे निकल आये!

एक और खेलप्रेमी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजयकुमार मलहोत्रा निर्माण-कार्य से तो संतुष्ट हैं लेकिन उद्घाटन और समापन समारोह का दाखियव सेना के सुपुर्द करने के तर्क से कुछ सकते में आ गये : 'बेशक यह अच्छा शो होगा, लेकिन इसे खेलकूद कतई नहीं कहा जायेगा और इसे वांछनीय भी करार नहीं दिया जा सकता।' श्री मलहोत्रा अक्सर कहते हैं, 'आजकल हालत यह है कि एशियाड के नाम पर लूट मची है। पता नहीं रातों रात सरकार के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गये।

इन पैसों की वसूली मात्र टिकटों या प्रसारण के कुछ व्यावसायिक अधिकार दे देने से तो हो नहीं जायेगी। बेहतर यही था कि

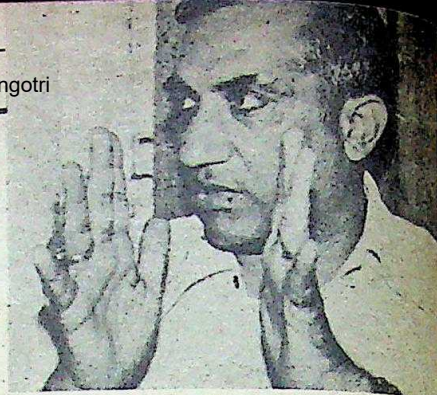


## आवरण कथा

लाटरी शुरू की जाती. इस से सरकार को खासा पैसा मिल सकता था. यही अंतराष्ट्रीय परंपरा भी है.

श्री मलहोत्रा को सब से अधिक परेशानी खिलाड़ियों के नाकाफी प्रशिक्षण से है. हमारे खिलाड़ियों को घरेलू मैदानों की पहल का सुख नहीं मिल पा रहा है. यह प्रशिक्षण तो कम से कम छह मास पहले शुरू हो जाना चाहिए. श्री मलहोत्रा वर्तमान प्रशिक्षण शिविरों के

पक्ष में नहीं. इसे वह बेवक्त की पुरानी प्रणाली मानते हैं. आज का युग तो विशिष्टता का युग है, व्यक्तिगत तौर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है. हमें यह तय कर लेना चाहिए कि 25-30 स्वर्ण पदक हमें किस खेल से मिल सकते हैं. उस खेल के खिलाड़ियों को ऐसा गहन प्रशिक्षण देना चाहिए कि कहीं हमारी पीठ न लगे. हम जानते हैं कि हमें एथलेटिक्स, कुस्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, चक्का फेंक



विजयकुमार मलहोत्रा: एशियाड के नाम पर...

आदि में स्वर्णपदक मिल सकते हैं. फुटबाल, बालीबाल में भी हमारा स्थान ठीक ही रहा है. हाँकी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. यह तभी संभव है कि जब ठीक लोगों को ठीक काम दिया जाये. आज सभी लोग विदेश भागने की सोचते हैं, चाहे उन्हें कुछ आता हो या नहीं. आज तो हालत यह है कि मैदान पर निशान लगाने वाला व्यक्ति भी विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाता है. राजनीतिकों और खेल अधिकारियों की तो बात ही और है.

श्री मलहोत्रा के अनुसार एशियाड के आयोजन पर 700 करोड़ रु. खर्च होंगे. इतना खर्च होने के बावजूद यदि हम कहीं नहीं पहुँचे तो इस से बड़ी निराशा और क्या होगी. अभी तक एशियाई खेलों में मेजबान देश का पहला या दूसरा स्थान रहा है. जापान पहले स्थान पर रहा, शेष सभी मेजबान देश दूसरे स्थान पर

बेशक निर्माणकार्य बड़ी तेजी से चल रहा है. स्टेडियम, फ्लाईओवरों, चौराहों के काम जल्दी से समाप्त करने के प्रयास किए जा



वेदप्रकाश चेतल और एन.सी. जयराम

रहे हैं. सब से बड़े स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य इंजीनियर एन. सी. जयराम के अनुसार 26 अक्टूबर 1980 को शुरू हुआ निर्माणकार्य जुलाई 1981 तक पूरा हो जायेगा. बेशक 100 एकड़ में बनने वाली उस इतनी बड़ी परियोजना में का काम आसान नहीं. इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने के लिए जगह होगी—57,000 ऊपर क्रिकेट स्थलों और 18,000 के लिए कुर्सियाँ होंगी. ऊपर हिस्सा सतह से 23 मीटर की ऊँचाई पर



## खेलने का सामान विदेशों से आयेगा विशेष संचालन समिति के अध्यक्ष बूटासिंह

एशियाड के निर्माणकार्य की प्रगति की गति कैसी है? आप के अनुसार कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा?

एशियाई खेलों के लिए सभी नये स्टेडियमों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है. कुछ स्टेडियमों के नवीकरण आदि का काम भी 30 जून, 1982 तक पूरा हो जायेगा.

अभी तक कितने देशों ने निमंत्रण स्वीकार किया है? आप के अनुसार कुल कितने खिलाड़ी तथा अधिकारी आ सकते हैं?

अभी तक 17 देशों ने एशियाई खेलों में शामिल होने की अनौपचारिक सहमति सूचित कर दी है. खेलों में लगभग 5,000 खिलाड़ियों और 2,600 अधिकारियों के शामिल होने की आशा है.

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की कैसी गति है?

खिलाड़ियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक चल रहा है. अब तक 131 प्रशिक्षण शिविर

लगाये जा चुके हैं. अधिकांश शिविर पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में लगाये गये हैं. एशियाई खेल आरंभ होने से पहले तक प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते रहेंगे ताकि खिलाड़ियों का अभ्यास बना रहे.

ऐसा भी सुना जाता है कि प्रतियोगिता के लिए खेलने का सामान विदेशों से मंगाया जा रहा है? ऐसा क्यों?

यह सही है कि प्रतियोगिताओं के लिए खेलों का सामान विदेशों से मंगाया जा रहा है. एशियाई खेलों की प्रतियोगिताओं में केवल वही सामान इस्तेमाल किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय संघों द्वारा अनुमोदित हो. भारत में बनने वाले सामान को अभी तक इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है.

हाल ही में कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं जैसे विश्व कप हाँकी, बालीबाल, नेहरू फुटबाल, टेबल टेनिस, और कराची में एशिया हाँकी कप. भारतीय खिलाड़ियों का खेल अधिक उत्साहजनक नहीं रहा. आप की क्या राय है?

यह सच है कि हाल ही में आयोजित विश्व कप हाँकी, बालीबाल, नेहरू फुटबाल, टेबल टेनिस और एशियाई हाँकी कप की प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों को अधिक सफलता नहीं मिली मगर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के मिलने और अभ्यास करने के फलस्वरूप एशियाई खेलों में अधिक सफलता की आशा की जा सकती है.

एशियाड के लिए जिस प्रकार व्यापक निर्माणकार्य हो रहा है, इस प्रतियोगिता के बाद आप उन का कैसा उपयोग करेंगे?

अब तक जो सुविधाएँ बन कर तैयार हो गयी हैं उन में अभ्यास के फलस्वरूप भारतीय खिलाड़ियों का स्तर उन्नत हो जायेगा और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए ये स्टेडियम बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे.



होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एथलेटिक्स के लिए ब्रिटेन की एनटाउटकेस ने कृत्रिम दौड़ मैदान तैयार किया है जिसे ब्रितानी कारीगरों ने ही बिछाया है। समय संबंधी सभी उपकरणों का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होगा। यह काम जापान की सीको कंपनी कर रही है। मैट्रीक्स किस्म के दो स्कोर बोर्ड होंगे—एक छोटा, दूसरा बड़ा और प्रमुख दोनों में हिंदी और अंग्रेजी में परिणाम दिखाये जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होने से अन्य स्थलों के परिणाम भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। बिजली का काम फिलिप्स के कंपनी हाथ में है। स्टेडियम के भीतर इस प्रकार के स्पीकर लगाये गये हैं कि बाहर शोरगुल ज्यादा होने पर भी स्वतः इन स्पीकरों की आवाज बढ़ जायेगी। दर्शकों और खिलाड़ियों के आने जाने के अलग अलग आठ द्वार होंगे। श्री जयराम के अनुसार इतने बड़े स्टेडियम को खाली होने में दस मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। एथलेटिक्स के अलावा रात को फुटबाल भी खेला जा सकता है। इस के लिए तेज प्रकाश की व्यवस्था है। इस तरह की भी व्यवस्था है ताकि रंगीन टेलीविजन कार्यक्रम तुरंत प्रस्तुत किये जा सकें। केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस स्टेडियम पर 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अवरोधों और अड़चनों के बारे में श्री जयराम और उन के सहायक इंजीनियर रामबिहारीलाल अग्रवाल के अनुसार केवल कम समय के और कोई कठिनाई हमारे सामने नहीं आयी।

इंडिया गेट के पास स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण हुआ है। 1951 में पहले एशियाई खेल इसी स्टेडियम में आयोजित हुए थे। इस के नवीकरण पर 2.47 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। यहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए 25,000 स्थान हैं। नकली घास वाला मैदान भी इसी स्टेडियम में बनाया गया है।

इंद्रप्रस्थ स्थित इनडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कम चुनौती भरा नहीं था। यमुना के किनारे स्थित इस स्थान पर निर्माण कार्य से पूर्व लगभग दो मीटर गहरे गड्ढों को पाटना पड़ा। कहा गया है कि बाढ़ के दिनों में यह स्थान जलमग्न हो जायेगा लेकिन इस स्टेडियम के प्रमुख परियोजना इंजीनियर के प्रकाश चेतल इंद्रप्रस्थ इनडोर स्टेडियम को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरे नंबर का मानते हैं। पहले दो स्टेडियम न्यू यॉर्क (अमेरिका) में हैं। यहाँ पर चौबीस घंटे काम होता है। नवंबर, 1980 में काम शुरू हुआ और जुलाई 1982 में समाप्त हो जायेगा। सभी काम भारतीय इंजीनियरों ने किया है।



## ‘मैं पहले स्थान की कल्पना नहीं करता’ भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष राजा भालिदरसिंह

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अभी तक के प्रदर्शनों में भारत की स्थिति अच्छी नहीं रही है, इस का आप क्या कारण मानते हैं?

‘हाँ काफी हद तक यह सही है। लेकिन मेरा विचार है कि इन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की वजह से राष्ट्रकुल और एशियाई खेलों के आयोजन तक भारतीय खिलाड़ियों के खेल में खासा सुधार होगा।’

कुछ खिलाड़ियों को बुनियादी प्रशिक्षण पर एतराज है?

‘इस में एतराज होने का कारण नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण की तो हरेक को जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज लगभग सभी महत्वपूर्ण खेलों में विदेशी प्रशिक्षक आमंत्रित किये

गये हैं। जिन खेलों को विदेशी घरती पर माँजने की जरूरत है उन्हें विदेश भेजा जा रहा है जैसे एथलेटिक्स, कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी और हॉकी की टीमों।’

एशियाई खेलों में भारत की कंसी स्थिति की आप उम्मीद करते हैं?

‘मेरा ख्याल है कि हमारी एथलेटिक्स, कुश्ती और निशानेबाजी में बेहतर स्थिति होगी। मैं यह मानता हूँ कि हमारी स्थिति बैंकॉक जैसी ही रहेगी अर्थात् छठी। इस समय के खेल को देखते हुए मैं पहले या दूसरे स्थान की कल्पना नहीं कर सकता।’

1992 की ओलंपिक के बारे में आप की क्या राय है?

‘उस के लिए आवेदन हमने सितंबर 1981 में ही दे दिया था। हालाँकि 1985 तक अर्थात् ओलंपिक शुरू होने से सात वर्ष पहले देना चाहिए लेकिन हम ने यह काम 11 वर्ष पहले ही कर दिया।’

वर्तमान ढाँचे क्या नाकाफी नहीं होंगे?

‘बेशक। लेकिन बुनियाद होने पर ही तो इमारत खड़ी हो सकती है। वर्तमान स्टेडियमों में एशियाई और अगर संभव हुआ तो अफ्रो-एशियाई खेल आयोजित हो सकते हैं। ओलंपिक के लिए हमें कुछ और इनडोर स्टेडियम बनाने होंगे और कुछ मामूली फेरबदल की जरूरत होगी।’

खेल अधिकारियों के विदेशी दौरों को लेकर बहुत आलोचना हो रही है। इस पर क्या राय है?

‘यह वक्तव्य और आलोचना गलत है। हमारे अधिकारी तो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम विदेश जाते हैं। आप ही सोचिए अगर हमारी विदेश में आवाज नहीं होगी तो हमारे खेलों का विकास कैसे हो सकता है। हमारे पिछड़ने का एक कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद की कमी है।’

इस में 12,000 लोग काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े स्टेडियम के निर्माण के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इसी स्टेडियम के साथ ही साइकिल दौड़ के लिए यमुना वेलोड्रोम बनाया गया है जो दुनिया में अपने किस्म का तीसरा है। श्री चेतल के अनुसार इस स्टेडियम की उपयोगिता सदैव रहेगी। खेल के न होने के समय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैठकें आयोजित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने, सर्कस आदि के लिए यह स्टेडियम मौजूद होगा। खिलाड़ियों के रहने के लिए भी यहाँ व्यवस्था है। एशियाई के बाद वह स्थान एक बड़े पाँच सितारा होटल में बदल दिया जायेगा।

लिहाजा इस स्थान की गहसागहमी हमेशा बनी रहेगी। इस स्टेडियम के साथ एक प्राकृतिक नहर भी है जिस में वर्षा का या अन्य तरह का पानी स्वतः चला जायेगा। अतः बाढ़ के पानी की फिक्र नहीं रहेगी। इस स्टेडियम की छत का प्रत्येक पाया प्रबलित सीमेंट की बनी 15 मंजिला इमारत के बराबर है। यह स्टेडियम 110 एकड़ में फैला है। स्टेडियम की डिजाइन की सबसे बड़ी विशेषता है इस का 150 मीटर व्यास और कटोरे जैसी संरचना। अगर कल्पना के अनुकूल इन स्टेडियमों की उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा यह सोचने और जाँचने का शायद अभी किसी की फुर्सत नहीं।



## आवरण कथा

एशियाड पर होने वाले खर्च को ले कर तरह तरह की अटकलें हैं। इस का कारण भी है : कई अभिकरण इस से जुड़े हैं और सभी के खर्च में अभी तक तालमेल नहीं; सभी कुछ तदर्थ हैं केंद्रीय निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नयी दिल्ली नगरपालिका, संचार-मंत्रालय, शिक्षामंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और अन्य अनेक विभाग इस परियोजना से संबद्ध हैं। इसलिए न तो श्री मलहोत्रा का 700 करोड़ रु. का खर्च ही इस समय सच लगता है और न ही महासचिव एस.एस. गिल का 90 करोड़

रु. का अंदाज़ ही सही दीखता है। 1977-78 का 26 करोड़ रु. का अनुमान तो अब अतीत की कहानी बन कर रह गयी है। इसी प्रकार एशियाड से होने वाले राजस्व की स्थिति भी है। टिकट की बिक्री से डेढ़ करोड़ रुपए की आमदनी की संभावना है। टिकटों के सामने के भाग पर चार राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन से पाँच लाख रुपए प्रति बैंक से प्राप्त होंगे जब कि पिछले भाग पर जापान के पिकासालि. से सात लाख रुपए की वसूली होगी। विदेशी टेलीविजन के अधिकार एशिया



किरण बेदी और परमजीतसिंह बाबा

पैसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन को लगभग 20 लाख रुपए में दिये गये हैं। मैदानों के भीतर विज्ञापनों का अधिकार दुबई के मीट्रोने 60 लाख डॉलर में प्राप्त किए हैं जब कि लॉस एंजेलस के मैसर्स विपिन सहमल ने टेलीविजन प्रायोजित अधिकार 50 लाख रुपए में प्राप्त किये हैं।

इतने बड़े आयोजन की देखरेख, कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा का दायित्व कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह दायित्व पुलिस के अधिकारित आयुक्त परमजीतसिंह बाबा को सौंपा गया है। उन की सहायता के लिए श्रीमती किरण बेदी सहित चार और पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। एशियाड के लिए पाँच बटालियन मंजूर की गयी हैं। एक बटालियन में 700-800 जवान होते हैं। इन के अलावा राज्यों के भी पुलिस सहायता प्राप्त होगी। खेल द्वारों को सम्भालने का दायित्व सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल को सौंपा गया है। लेकिन सभी तरह के समन्वय की जिम्मेदारी श्री बाबा की ही है। 'क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हादसे हो चुके हैं लिहाजा हमें सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। श्रीमती किरण बेदी के अनुसार एशियाड की यातायात व्यवस्था के लिए 2400 जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यातायात की व्यवस्था दो प्रकार से होगी— एक में खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों अधिकारियों और प्रेस आता और दूसरे में दर्शक। लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, बसों, रिंग रेलवे, तिपाहिया स्कूटर, टैक्सियों की समुचित व्यवस्था होगी। 'हम यह चाहेंगे कि खेलों के बाद दर्शकों को घर जाने की वाहन मिलने में पंद्रह मिनट से अधिक इंतजार न करना पड़े। दर्शकों के अलावा बड़े पैमाने पर अतिथि भी तो घुसपैठ कर सकते हैं। पर श्री बाबा का उत्तर था : 'हमें अपनी निगरानी चौकस और दिमाग एशियाड, अनुकूल बनाए रखेंगे। वावजूद इन दावों के दिल्ली को यातायात की दृष्टि से जानलेवा शहर माना जाता है।

### नवें एशियाई खेल 1982 : एक नज़र में

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम एशियाई खेल                                               | : नयी दिल्ली, मार्च 1951                                                                                                                                                                                                                   |
| 1951 में भाग लेने वाले देशों की संख्या                         | : 11                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रथम एशियाड में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या          | : 489                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1951 में खेलों की संख्या                                       | : 6 (छह)                                                                                                                                                                                                                                   |
| खेलों का विवरण                                                 | : एथलेटिक्स, बास्केटबाल, साइकिल दौड़, फुटबाल, तैराकी और भारोत्तोलन                                                                                                                                                                         |
| अब तक हुए एशियाई खेलों का विवरण                                | : 8 (आठ)                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | दिल्ली 1951                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | मनीला 1954                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | तोक्यो 1958                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | जकार्ता 1962                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                | बैंकॉक 1966                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | बैंकॉक 1970                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | तेहरान 1974                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | बैंकॉक 1978                                                                                                                                                                                                                                |
| नवें एशियाई खेलों की अवधि                                      | : 19 नवंबर से 4 दिसंबर, 1982                                                                                                                                                                                                               |
| खेलों की संख्या                                                | : 21: तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, साइकिल दौड़, घुड़सवारी, फुटबाल, जिम्नास्टिक, गोल्फ, हैंडबाल, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती, नौकायन, (रामगढ़ झील, जयपुर) पाल नौकायन (बंबई) |
| इस बार शामिल किये गये नये खेल                                  | : गोल्फ, हैंडबाल, नौकायन और घुड़सवारी                                                                                                                                                                                                      |
| प्रदर्शन खेल                                                   | : कबड्डी और सपक तकुरा (मलयेसिया)                                                                                                                                                                                                           |
| भाग लेने वाले देशों की संभावित संख्या                          | : 31                                                                                                                                                                                                                                       |
| कुल शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या                       | : 5,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| तकनीकी अधिकारियों की संख्या                                    | : 2,700                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्टेडियमों की संख्या                                           | : 17                                                                                                                                                                                                                                       |
| नये बनाये गये स्टेडियम                                         | : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा तरणताल, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, यमुना वेलोड्रोम, तुगलकाबाद शूटिंग रेंज                                                                                                                                   |
| एशियाई खेल ग्राम में आवास निर्माण यातायात के लिए अन्य सुविधाएँ | : होजखास (दक्षिण दिल्ली में) 853 फ्लैट दिल्ली में बड़ी सड़कों के निम्नलिखित चौराहों पर फलाई ओवरों का निर्माण;<br>1. मूलचंद्र अस्पताल 2. जाकिर हुसेन मार्ग<br>3. लोधी रोड 4. आई. टी. ओ. चौराहा<br>5. सेवा नगर 6. जेल रोड और 7. स्कूल लेन    |



## युवा जगत

### राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय में नशे की राजनीति

गत दो मई को राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय के दूसरे वर्ष के छह छात्रों के शराब पी कर रिहर्सल पर आने और अतिथि निदेशक भानुभारती से दुर्व्यवहार की घटना की भूमिका राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय के ही वरिष्ठ छात्रों के अनुसार, काफी पहले लिखी गयी थी। यह उस नाटक का पहला दृश्य है जिसे कुछ बाहरी लोग विद्यालय रंगमंच पर खेलना चाहते हैं। इसी लिए इन छह छात्रों के निलंबन से कक्षा के भी ज्यादातर छात्रों को कोई सहानुभूति नहीं है।

उस दिन द्वितीय वर्ष के छात्र 'चंद्रमोह' नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। अक्षरकुमार के. बी., अतुल तिवारी-दो छात्र और मधुभी बत्ता, एस. मालती, सुषमिता मुखर्जी और रहमत जमाल-ये चार छात्रों ने संवाद नहीं बोल पा रही थीं। उन के कवम लड़खड़ा रहे थे। इन में दो को उल्टी भी हो गयी थी। सात दिन बाद ही नौ मई को नाटक का प्रदर्शन होना था। यह हालत देख कर छात्र भुग्ध हो गये। भानुभारती कक्षा में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए चुप रहे। रिहर्सल के बाद स्टेज मैनेजर राजेश सिंह से कहा कि सूचना पट्ट पर सूचना लगा दें कि रिहर्सल के समय कोई छात्र शराब पी कर नहीं आयेगा। लेकिन राजेश सिंह ने कारवाई करने के बजाय स्तीफा दे दिया। मुझे उन्होंने बताया कि जब स्तीफा दे देना ही ठीक है। भानुभारती ने तब विद्यालय के निदेशक बृजमोहन शाह को घटना का ब्योरा दिया। श्री शाह ने उन से कहा कि 12 मई को नाटक का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद इन छात्रों से बातचीत करेंगे।

किंतु ये छात्रों छात्र दो दिन रिहर्सल पर ही नहीं आये। पांच मई को आये तो रिहर्सल करने से इनकार कर दिया। इस पर छात्रों में तनाव बढ़ गया। इन लोगों ने कहा 'हम रिहर्सल तब करेंगे, जब यह विवाद सुलझ जायेगा।'

एस. मालती के अनुसार 'सुषमिता मुखर्जी को उस दिन रक्तचाप कम था। उन की भूमिका नुकल गयी थी। उस स्थिति में नाचना कर दी।' 'किस बात पर?' 'इस का जवाब तो नहीं देंगे। लेकिन दो मई को हम लोगों ने शराब पी थी। यह बात गलत है।' एस. मालती ने कहा।

एस. मालती ने जो ब्योरा दिया, उस के



राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तीन निदेशक, (बायें से) ड. अलकाजी, बा. व. कारंत और बृजमोहन शाह : योग्यता, जबरता और संतुलन

अनुसार; 'एक मई को मेरा जन्मदिन था। मुझे तो याद ही नहीं था। अतुल तिवारी ने अचानक मुझे अंगूठा दिखा कर कहा, 'हैप्पी मे डे'। (यह प्रचार है कि ये सभी छह छात्र माकपा समर्थित हैं। एस. मालती के पति रा. ना. वि. के दूसरे अतिथि निदेशक प्रसन्ना भी माकपा समर्थित हैं। मालती और इन सभी छात्रों ने इस से इंकार किया। लेकिन जन्मदिवस की शुभकामनाओं का भी हैप्पी मे डे (मजदूर दिवस की शुभकामना) के रूप में आदान प्रदान क्या इंगित करता है) 'तब मुझे याद आया कि मेरा जन्मदिन है। हम लोग, जो उस समय उपस्थित थे, जन्मदिन मनाने चले गये। पर उस समय इस बात का तनिक भी अहसास नहीं था कि मेरा जन्मदिन अचानक राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा। वहाँ हम ने थोड़ी सी शराब पी थी। लेकिन रात को लौट कर हम ने बारह बजे तक रिहर्सल की। तब किसी को महसूस नहीं हुआ। पांच मई को अचानक तानाकशी शुरू कर दी। उस स्थिति में हम लोग किस तरह काम कर सकते थे। अतः हम ने भानुभारती से कहा कि पहले यह तनाव खत्म करें, तब ही काम हो पायेगा। अगले रोज हमें निलंबित कर दिया गया। हम पर शराबी होने का आरोप लगा दिया गया। अगर हम रिहर्सल के समय लड़खड़ा रहे थे तो भानुभारती ने हमें उसी समय क्यों नहीं टोका? हमें उसी समय थपड़ मार कर रिहर्सल से निकाल देते तो बुरा नहीं लगता। किंतु यह धुनि प्रचार क्यों?'

भानुभारती ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं बिना किसी व्यवधान के अपने नाटक का प्रदर्शन करना चाहता था। ऐसे भी मैं अतिथि निदेशक हूँ। विद्यालय का कोई अधिकारी ही अनुशासनात्मक कारवाई कर सकता था। राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय के काफी वरिष्ठ छात्रों को इन छात्रों के व्यवहार पर आश्चर्य है। 'अपने इस कार्य पर शर्मिंदगी भी ये छात्र महसूस नहीं कर रहे हैं। इस के विपरीत इसी बीच अपनी कक्षा के छात्रों के विरुद्ध लिखित रूप से छेड़खानी का आरोप भी इन

छात्रों ने लगाया है। जो गलत है। गत वर्ष इन्हीं की कक्षा के छात्र मंजुलकिशोर वर्मा और वरिष्ठ छात्र केशवानंद स्वामी (इन्होंने गत गत वर्ष आत्महत्या कर ली) ने, इन्हीं में से दो छात्रों से छेड़खानी कर रहे कुछ दुबकों से लड़ाई मोल ली थी। भला वही लोग ऐसा कर सकते हैं!'

वरिष्ठ छात्रों के अनुसार इन छात्र छात्रों का निलंबन छात्रों में कुछ तो अनुशासन पैदा करेगा ही। और यह आदेश वापस ले लिया गया तो न केवल दूसरे छात्र भी उड़ड़ हो जायेंगे बल्कि स्वयं श्री शाह की छवि धूमिल हो जायेगी। इस घटना के पीछे विद्यालय के छात्रों में बढ़ गयी अनुशासनहीनता को भी एक कारण माना जा रहा है। छात्रों ने बताया; बा. व. कारंत ने 1981 में जब रा. ना. विद्यालय छोड़ कर भोपाल रंगमंडल जाने का निश्चय किया तो राजेंद्रनाथ का नाम नये निदेशक के रूप में सुझाया। लेकिन अधिकतर अध्यापकों छात्रों को यह कतई स्वीकार नहीं था। मोहन महर्षि को भी कुछ दूसरे लोगों ने पसंद नहीं किया। बृजमोहन शाह को समझौते के तौर पर स्वीकार किया गया। लेकिन निहित स्वार्थों के कारण यह कोशिश जारी है कि बृजमोहन शाह प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत न कर पायें।

कुछ वरिष्ठ छात्रों की राय में बा. व. कारंत ने दिसंबर 1977 में रा. ना. विद्यालय का कार्यभार संभालने के बाद जो कई परिवर्तन किये, उस से विरुद्धविद्यालय का पतन तो हुआ ही छात्र भी अनुशासनहीन और विवाहीन हो गये। उन्होंने भू. पू. निदेशक इब्राहिम अलकाजी द्वारा लागू पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया। विशेषज्ञता खत्म कर दी गयी। विशेषज्ञता के लिए अलग से चौथा वर्ष रखा गया। किंतु किसी नये पाठ्यक्रम में पढ़ाई ठप्प रही। काफी अध्यापक भी बदले गये। पहली बार प्राध्यापकों को स्थायी किया गया। कुछ छात्र पढ़ाई का स्तर गिरने के लिए स्थायी हो जाने पर प्राध्यापकों की निश्चितता को भी उत्तर-





मानुभारती : 'चमकू' की चमक

दायी मानते हैं। 'प्रारंभ से ही लड़के लड़कियाँ एक होस्टल में रहते थे। अचानक होस्टल अलग कर दिये गये। पहले विद्यालय के छात्रों में केवल वर्ग विभाजन था, इस बार वे लड़के लड़कियों में भी बँट गये। पहली बार छात्र संघ बनाया गया जिस के कारण गुटबंदी की राजनीति शुरू हो गयी। यह सब परिवर्तन करने के बाद बा. व. कारंत स्वयं वर्ष में नौ महीने विदेशी रंगमंच का अध्ययन करने में व्यस्त रहे। पक्षपात की परंपरा ने भी जन्म लिया।

'कुछ छात्र श्रीराम कला केंद्र में स्वतंत्र रूप से नाटक करते रहे। लेकिन सजा केवल उन्हें मिली जिन का कोई सरपरस्त नहीं था। रिचर्ड एटनबरो की गांधी पर बन रही फिल्म के लिए दो छात्रों ने विद्यालय की अनुमति से स्वीकृति दी लेकिन बाद में विद्यालय रंगमंडल के नाटकों की तारीखें फिल्म की शूटिंग के दिनों में रखी गयीं। मजबूरन उन्हें विद्यालय रंगमंडल छोड़ना पड़ा।' बांग्ला देश के एक छात्र गुलाम सरवर को अकारण दो बार फेल किया गया। छात्र संघ के दबाव पर पास किया गया? रंजीत कपूर जैसे कुशल निर्देशक को भी विद्यालय छोड़ना पड़ा। 'छात्रों में ये प्रश्न आम हैं। उत्तर भी उन्हीं के पास है। 'क्यों कि कुछ लोगों को आगे लाने के लिए ऐसा जरूरी था।'

छात्रों को इस घटना के पीछे भी मुख्य कारण यही राजनीति दिखायी देती है। 'बा. व. कारंत के समय में कर्नाटक के छात्रों को काफी बढ़ाया गया। एक नियम सा बन गया है कि एक निर्देशक एक वर्ष में एक ही नाटक का निर्देशन करेगा। लेकिन प्रसन्ना (एस. मालती के पति) को बा. व. कारंत की कृपा से एक ही वर्ष में तीन अवसर दिये गये हैं। उन्होंने रांची में एक वर्कशॉप किया। मायाबाजार नाटक का निर्देशन किया। पाठ्यक्रम में गोदान नाटक था। उस की जगह उन्होंने स्वयं इस का चुनाव किया। अधिकतर छात्रों और रंगमंच समीक्षकों की राय में वह नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं, सप्रू हाउस के स्तर का नाटक था। 'इस के

बावजूद तुगलक के निर्देशन का भार उन्हें सौंपा गया। पहले इस नाटक का निर्देशन स्वयं बा. व. कारंत करने वाले थे लेकिन भोपाल रंगमंडल जाते समय पंडारा रोड स्थित अपने सरकारी निवास में रहने का अधिकार देने के साथ साथ तुगलक के निर्देशन का भार भी प्रसन्ना को सौंप दिया।' इस नाटक का प्रदर्शन इस वर्ष सितंबर में लंदन में भारत महोत्सव में किया जायेगा। किंतु समस्या की जड़ इस समय राष्ट्रीय विद्यालय में खाली 'एक्सटेंशन प्रोफेसर' का पद बताया गया है। मानुभारती और प्रसन्ना दोनों ही इस समय अतिथि निर्देशक हैं। मानुभारती दो वर्ष की वरिष्ठ योग्यता तो रखते ही हैं। अब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए उन्होंने जिन

दो अन्य नाटकों हानूश और द एलीफेंट का निर्देशन किया था, वे काफी सराहे गये थे निर्देशक के रूप में उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आयी थी। मायाबाजार प्रभावित करने में असफल रहा। कुछ छात्रों ने कहा 'प्रसन्ना को भय था कहीं चंद्रमासिंह उर्फ चमकू भी अच्छा न बन जाये। केवल 'माया बाजार' के बल पर कैसे टिका रहा जा सकता है।' अब छात्रसंघ के कोषाध्यक्ष अवतारसिंह पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इन छह छात्रों का साथ दें। सचिव अतुल तिवारी तो निलंबित छह छात्रों में ही हैं। छात्रसंघ के अध्यक्ष प्रताप सामल उसी दिन से गायब हैं। मानुभारती को भी जे. ने. वि. के. कुछ छात्रों का नाम लेकर धमकी दी गयी है।

—सुषमा पाराशर

## उन का कहना है

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर सेना को विश्वास में लेना आवश्यक है क्योंकि देश की रक्षा में सेना का सब से ज्यादा महत्व है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-मुल्तान के संवाददाता सम्मेलन में कोई समाज उतनी पुलिस नहीं रख सकता जितनी उसे चाहिए क्यों कि वह उस का खर्च नहीं उठा सकता।

श्री ए. सिंहल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली की एक विचार गोष्ठी में मेरे मन में अब भी श्रीमती गांधी के प्रति अपार सम्मान और प्रेम है।

श्रीमती मेनका, गांधी सिडनी, मॉनिंग, हेराल्ड और रेडियो न्यूज़ीलैंड के साथ एक मेटवार्ता में श्रीमती गांधी में हमला करने और निर्णय लेने की पहले जितनी शक्ति अब नहीं रह गयी है।

श्री मोरारजी देसाई शिमला में श्रीमती गांधी के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए

हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि दूरदर्शन फिल्म 'सदगति' से जातियों में घृणा उत्पन्न होगी जैसा कि श्रीमती गांधी ने फिल्म देखने के बाद विचार व्यक्त किया।

इंडियन एक्सप्रेस में एक पाठक

हरियाणा विधानसभा के चुनावों में अगर इंका, कांग्रेस हार गयी तो केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार छह महीने बाद गिर जायेगी।

लोकदल अध्यक्ष चरणसिंह—कुरुक्षेत्र में

हम शांति से विवाद तय करना चाहते हैं। चुपचाप अपने को बेच देना नहीं चाहते।

ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टैचर फाकलैंड विवाद पर हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना पड़ता है। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु

कलकत्ता के संवाददाता सम्मेलन में

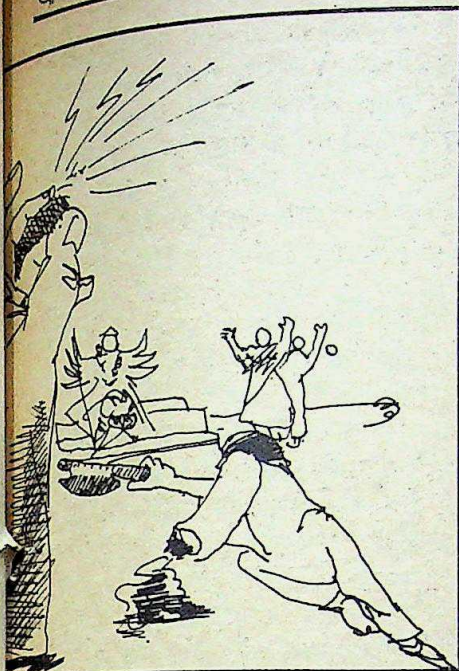
विरोधी दल कभी एक नहीं होंगे। इसलिए जनता से किये गये अपने वायदे भी पूरे न कर सकेंगे।

संसद सदस्य राजीव गांधी यमुना नगर की एक सार्वजनिक सभा में





## चरचे और चरखे



## कटे हाथ की पुकार

राजधानी में पटेल नगर के दुर्गा मंदिर में 35 वर्षीय एक आदमी ने दुर्गा की मूर्ति के सामने अपना हाथ काट कर चढ़ा दिया। यह आदमी दिल्ली मिल्क स्कीम में क्लर्क है। दस्तर का काम खत्म कर के वह मंदिर आया। उस समय पुजारी आरती कर रहा था। औरतें कीर्तन कर रही थीं। वह बहुत देर तक मूर्ति के सामने लंबवत पड़ा रहा फिर उस ने झोले से कुल्हाड़ी निकाली और अपना बायाँ हाथ काट लिया। आगे का किस्सा व्यवस्था से ताल्लुक रखता है, भक्ति से नहीं। पुजारी पुलिस को सूचना देता है। पुलिस उस पर आत्महत्या का केस बनाती है और आदमी को लोहिया अस्पताल में भरती करा दिया जाता है। जहाँ वह बार बार यही दोहराता रहता है 'मैं अपने दोनों हाथ दुर्गा माता को चढ़ा देना चाहता था' सवाल उठता है क्या यह भक्ति है? या आत्महत्या का प्रयत्न है?

यदि भक्ति है तो इस का जिम्मेदार कौन है? क्या बेसिर पेर की पौराणिक कथाएँ नहीं हैं जहाँ इष्टदेव के सामने अपने शरीर के अंगों और कभी कभी तो स्वयं को चढ़ा देने की महिमा को मंडित किया गया है? रावण तो अपने सिर ही काट कर शिव को चढ़ा देता है। तब कहीं जा कर उसे वांछित वरदान मिलता है... इन सब का असर तो पड़ता ही है। हो सकता है यह क्लर्क भी कोई वरदान चाहता हो। जिस के लिए वह अपनी दोनों भुजाएँ दुर्गा माता को अर्पित कर देना चाहता था। यह तो आगे जांच से पता चलेगा। जरूरी है कि ऐसी कहा-नियों का पोच समझाया जाये और ऐसे अंध-विश्वासों के खिलाफ वातावरण तैयार किया जाये। इन पर निषेध होना चाहिए। आज भी नरबलि होती है! पिछड़े इलाके, पिछड़ी जातियाँ और पिछड़े दिमाग इस देश में क्यों हैं? कब तक रहेंगे?

यदि यह भक्ति नहीं है आत्महत्या का प्रयत्न है तब भी इस की गंभीरता कम नहीं होती और बढ़ती ही है। पिछले दिनों 3 अप्रैल की एक खबर पढ़ी थी कि दो बच्चों के एक बेरोजगार बाप ने पंखे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। अखबारों में रोज ही ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जहाँ बच्चे परीक्षा में फेल होने पर या फेल होने के डर से, औरतें घर में बुरे व्यवहार और अत्याचार से तंग आ कर, आदमी निराश हो कर आत्महत्या कर लेते हैं। इस सब का दोष इन व्यक्तियों पर ही नहीं आता, इस व्यवस्था पर भी आता है जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यदि मनोभाव संग्रह का कोई राष्ट्रव्यापी ऐसा विधान संभव हो जिस से पता चले कि आदमी आज जीना चाहता है या मरना, तो शायद मरना चाहने वालों की संख्या अधिक होगी। यह दूसरी बात है कि आत्महत्या का साहस जुटा पाना कठिन होता है और ऐन मौके पर जीवन का मोह उमड़ आता है। यदि यह आदमी आत्महत्या करना चाहता था तो क्यों? क्या नौकरी होने पर भी नौकरी उस की आज की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, न होने जैसी थी? क्या वह खाने-पीने, पेट भरने के बाद भी चारों ओर के सामाजिक तनावों से मुक्ति पाना चाहता था? क्यों उस के लिए यह दुनिया न रहने लायक रह गयी थी? किसी का भी इस नतीजे पर पहुँचना कि यह दुनिया रहने लायक नहीं है एकदम उस का निजी मामला नहीं है, इस में उन लोगों की भी जिम्मेदारी है—बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो इस दुनिया को चला रहे हैं। हो सकता है कल जाँच के बाद इस नतीजे पर पहुँचा जाये कि यह आदमी मानसिक रूप से विकृत था—पागल था। इसे यूँ ही नहीं मान लेना होगा। क्योंकि कोई अपने आप पागल नहीं हो जाता। उसे पागल किया जाता है—जाने अनजाने समाज उसे पागल करता है। सोचना होगा यह क्यों पागल हुआ? उस कटे हाथ की पुकार सुननी होगी, जो काम करने के लिए बना था, काम कर रहा था लेकिन अपने ही स्वत्व के लिए बेकार होता जा रहा था, बेकार हो गया था। क्यों?

शरीर से अलग हुए उस कटे हाथ की पुकार सुननी होगी क्योंकि वह उन करोड़ों हाथों में से ही एक है, जो आज अपनी शिकायत पेश करने के लिए उठे हुए हैं लेकिन जिन्हें व्यवस्था अपने समर्थन में उठा हुआ मान रही है। □

## चुनाव चौपदा



समूची अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। किसान का बेटा जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा देश का सुधार... —चौ. चरणसिंह



एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, अगर यह भी धंस गया तो... —चंद्रशेखर



चुनाव नहीं होगा, यह झूठ है, सरासर झूठ. इसका सबूत है मेरे पास... चलिए अदालत में दिखाऊँगा... —राजनारायण



सुकुमल फूलों के मुरझाने का नहीं, डूबने का डर है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक... —अटलबिहारी वाजपेयी



## दिल्ली के रंग

### प्रायी बरसात तो

पिछले सौ वर्षों में मई के महीने में न तो दिल्ली में इतनी वर्षा हुई और न इतनी ठंडक। पहले कुछ दिनों की फुहार में लोगों को गुलाबी जाड़े का सा मजा आया। फिर कंबल निकल आये और कुछ दिन पहले तो कई लोग घर में रजाइयाँ ओढ़े और दफ्तरों में कोट पहने दिखायी देने लगे। महानगर के निवासी ठिठुर रहे थे तो ग्रामवासी सिसक रहे थे। कटी फसलें काली पड़ गयीं। गेहूँ गोबर हो गया। अन्न बस चारे में बदल गया। मनुष्यों के खाने योग्य बहुत सा अनाज नहीं रहा। पता नहीं पशु भी इसे खाना पसंद करे या नहीं। किसानों के दाने काले पड़ गये पर काले बाजार वालों की चाँदी होने वाली है। यही हाल रहा तो भाव तो कुछ बढ़ते दिखायी दे रहे हैं। फिर से फिर कहना पड़ता है हमें 'आयी बरसात तो बरसात पे रोना आया।'

### 'सचमुच, जाने मन !'

बंगाली मार्केट में हलवाई की दुकान के बाहर वह गुलदस्ता लिये खड़ा था। पत्ते तो गहरे हरे रंग के जामुन के पेड़ से उखाड़े लगते थे। इतने पत्तों में घिरा बस एक ही ठोस लाल रंग का फूल दीख रहा था तर-ओ-ताजा। हैरान रह गये बस देखने वाले। एक ने साहस कर आगे बढ़ पुछा, 'क्यों मई यह असली फूल है या नकली। अब आजकाल के बेतुके मौसम में क्या गुल खिलेंगे दिल्ली में?' गुलदस्ते वाला मुहावरे में बोला 'हुजूर मैं दिल्ली वाला हूँ मगर कली कश्मीर की है। बिलकुल कच्ची और यह साथ है गुल वादिये जन्नत का। सचमुच! जाने मन.'

सवाल पुछने वाले संमझे जवाब देने वाला गुल फरोश मजाक कर रहा है। फिर कास रहा है। तुनक कर बोले 'जाने मन? जाने मन? क्या मतलब है तुम्हारा? यह कोई बात करने का ढंग है?'

गुल फरोश साहब के माथे पर जूँ नहीं रेंगी। यूँ हँसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़े ठहरावों से बोले 'जनाब यह कश्मीर का मशहूर तोहफा है, इसी मौसम में खिलता है। कदरदान इस के कश्मीर से कानपुर तक है। उस से आगे का हमें पता नहीं क्योंकि हम ने यह कलियाँ और फूल इतनी दूर तक कभी भेजे ही नहीं। हाँ, इस गुल का नाम ही जाने मन है। देखिये ना कैसे महबूबा के होंठों की तरह तीखी लाली है, इस में जोड़ा खरीदिये तो अच्छा है। बस सिर्फ दो रुपये में। पानी बहुत पीता है यह फूल। दिन में दो चार लोटे डालने जरूरी हैं। एक बार ले जाइये साल भर बहार लूटिये। पानी सखावत से डालते रहिये तो

दिनमान

कभी यह मुरझायेगा ही नहीं। बेहतर यह होगा कि कलियों का जोड़ा ले जाइये। आपके अपने डाइंग रूम में खिलेंगी तो कैसा रहेगा? बड़े बड़े फारेन साहब, एम. पी., मिनिस्टर, कलक्टर पसंद करते हैं इसे।'

हम पास खड़े सुन रहे थे। बस झट से एक कलियों का जोड़ा हासिल कर लिया। घर ले आये। दस दिन हो गये। कई लोटे पानी उँडले गुल फरोश साहब की हिदायत के मुताबिक पर कलियाँ नहीं खिलीं अभी तक।

### बचाओ! बचाओ!

फैशन के मतवालों से बेजुबान पशु पक्षियों को बचाओ। सौंदर्य साधना के लिये संहार बंद करो। इस लक्ष्य को सामने रख एक अभियान दिल्ली में उठा है। उस का नेतृत्व कर रहे हैं लोक सभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। लगभग 1,50,000 स्त्री-पुरुषों के हस्ताक्षरों के साथ एक विनय पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी



उर्दू की शायिराएँ : नज़्मों की खुशबू

को भेजा है। इन हस्ताक्षरों में 100 तो संसद सदस्यों के हैं। अन्य हस्ताक्षर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से देश के प्रमुख नागरिकों के हैं। एक संस्था है जिस का नाम है 'सौंदर्य मगर, निर्दयता नहीं।' उसी के तत्वाधान में यह सब कुछ हो रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है।

संस्था को डर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक प्रस्तावित योजना से हजारों रीछों, लोमड़ियों, गिलहरियों, साँपों आदि की खालें खींच ली जायेंगी। उन की फर और खालें खींचने के लिये ही इन वन्य प्राणियों को पाला पोसा जायेगा—इस प्रस्तावित योजना में। गर्ज यह है कि विदेशी सुंदरियों के सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन के लिये इन बजुबानों को मृत्यु दंड दे कर उन की चमड़ियों का निर्यात किया जायेगा। विदेशी मुद्रा कमाने के इस अभियान को डेढ़ लाख भारतीय शर्मनाक मानते हैं। 'खालों से माल' कमाने के खिलाफ हैं।

खालों के व्यापारियों के पंजे से भेड़िये और मगरमच्छ तक नहीं बचे जिन का शिकार यह खाल के लालची मछलियों और तीतर बटेरों की तरह करते हैं। कहा जाता है कि भेड़ियों का वंश तो देश से मिटता ही जाता है। हाथियों

को जहर खिला कर उन के हाथीदांत के लिए मारते हैं ये और और कस्तूरी मृग की कस्तूरों के लिये उसे लोहे की कीलों के बने फंदों पर घसीटते हैं। उस के पाँव में कील गाड़े जाते हैं और छुरियों से उसे खराशा जाता है ताकि इस नीच ढंग से उच्च कोटि की कस्तूरी प्राप्त हो।

### कोकिला गोष्ठी

संस्था का नाम 'तरंगिनी'। मुख्य संचालिका जमीला बानो। काम उर्दू साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक धाराओं को अग्रसर करने का है। हाल ही में कमानी हाल उन्होंने राजवाड़ा में एक अखिल भारतीय 'महिला मुशायरे' आयोजन किया। मीरे मुशायरा तथा शायर सन्ध्या स्त्रियाँ थीं। शायिराओं के अतिरिक्त उपराजपाल सुंदरलाल खुराना तथा शायर महेंद्रसिंह वेदी सदर मंच पर थे। जोश मलीहाबाद और फिराक गोरखपुरी की याद में जो

की शायिरायें तशरीफ लायीं उन में दिल्ली की ही नहीं बंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़ की कविता कोकिलें हैं, दिल्ली वालियाँ प्रमुख और अधिक थीं।

### पुलिस चौकी में चोरी?

अजीब सी बात है मगर शिकायत करने वाले साहब कहते हैं ठीक है। उन्होंने एक पहियों वाला आटोरिक्षा लिया किराये रेलवे स्टेशन जाने के लिये। एक छोट से बूट में कुछ पुराने और कुछ नये कपड़े रखे, तब लगा साथ ले लिया। सफर के लिये स्टेशन उतर गये। बैंग आटो रिक्शा में भूल प्लेटफार्म पर पहुँचे तो याद आया बैंग। प्रस्थ की पुलिस चौकी पर जमा करा दिया। वहाँ पहुँचे बैंग था चौकी पर मगर तब टूटा हुआ था। कपड़े उस में थे मगर पुराने गायब थे। रिक्शा वाले का कहना था चुराना होता तो बैंग चौकी पर लाने तकलीफ क्यों करता? नये कपड़े कहाँ कौन जाने?



राष्ट्र

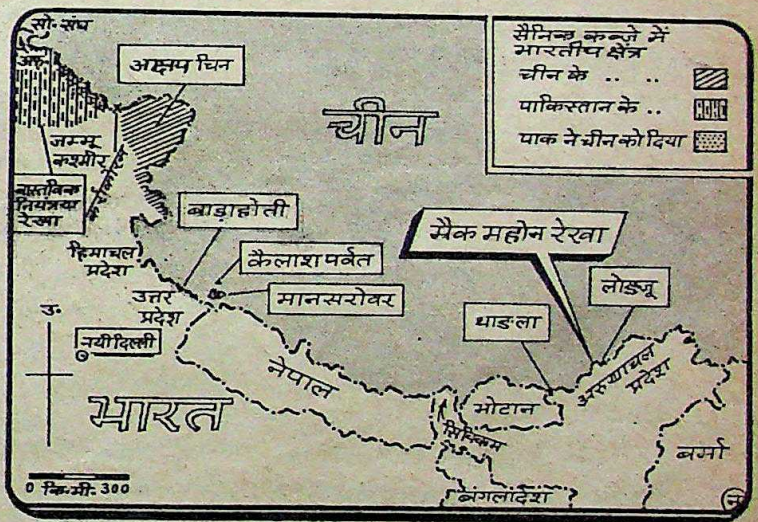
भारत-चीन

## पहला कदम कौन उठाये?

चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता विदेश मंत्रालय के सचिव एरिक गोंसलवेज ने जब यह कहा कि इस बातचीत के दौर से 'कोई नाटकीय परिणाम' निकलने की उम्मीद नहीं है तो उन्होंने कोई अप्रत्याशित बात नहीं कही, क्योंकि दो दशक के बाद अचानक भारत और चीन सीमा संबंधी गंभीर विवादों को अधिकतर स्तर पर बातचीत द्वारा सुलझा लेंगे यह अव्यावहारिक अनुमान होगा। इतनी गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों की जरूरत है जो दोनों देशों के आर्थिक और राजनैतिक हितों के लिए अत्यंत

शुरू हुई और अगले दिन प्रतिनिधिमंडलों को चार छोटे छोटे गुटों में बांटा गया। उद्देश्य यह था कि राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सीमा संबंधी विषयों पर अलग अलग बातचीत हो। चीन और भारत के बीच सीमित पैमाने पर व्यापार हो रहा है। दोनों देशों के बीच औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कम सहयोग है। क्योंकि उस का मुख्य कारण यह है कि औद्योगिक सहयोग के लिए व्यापक पैमाने पर आर्थिक तालमेल और एक दूसरे की आवश्यकताओं का विश्लेषण जरूरी होता है। सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत और चीन के बीच पिछले दो दशकों में बहुत कम आदान प्रदान हुआ। इन क्षेत्रों में निस्संदेह अधिक

अभी चीन के लिए मित्रता और पूर्णसहयोग की स्थिति पैदा करना प्राथमिकता का विषय नहीं। इस लिए किसी ठोस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं। मगर इन वास्तविकताओं के बावजूद यह बात सही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने के लिए किसी न किसी दिशा में कुछ कदम आगे तो बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। बातचीत में एक दूसरे के उद्देश्यों की गहरी लेने की कोशिश तो जरूर होगी। कौन कहा तक जा सकता है और कहाँ तक जाने में देश का हित है वर्तमान बातचीत इसी की आँखों का एक माध्यम है। चीन के दूसरे देशों के साथ विवादों को सुलझाने के क्रम को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल किसी ठोस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक बातचीत करने से पहले कई बार मिलें। इस की प्रगति के बारे में दो टूक बात कहने का खतरा कोई नहीं लेना चाहता। अलग अलग



चीन और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री फू हाउ और एरिक गोंसलवेज : जान पहचान से आगे

सहयोग स्थापित किया जा सकता है मगर इस के लिए जरूरी है कि केंद्रीय मुद्दे को सुलझाने के सिलसिले में ठोस प्रगति हो। यह केंद्रीय मुद्दा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का है। पिछली बार यह बताया गया था कि चीन ने परोक्ष रूप से एक मिलेजुले समझौते का सुझाव दिया था जिस का आधार यह था कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में वर्तमान नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा मान लिया जाये। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के सुझाव को भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। मगर यह भी सही है कि भारत की ओर से अभी तक कोई वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

गुटों में हुई बातचीत का मूल्यांकन बृहस्पतिवार को एक सामूहिक बैठक में किया गया। क्योंकि सीमा संबंधी बातचीत की प्रगति का असर अन्य सभी गुटों की बातचीत पर पड़ना स्वाभाविक है इस लिए अन्य क्षेत्रों में घौमी प्रगति अस्वाभाविक नहीं है। सीमा विवाद के सिलसिले में दोनों देशों को व्यावहारिकता का सहारा लेना होगा। यदि चीन कोई मिला-जुला प्रस्ताव सरकारी तौर पर रखता भी है तब भी उसे यह स्वीकार करना होगा कि पश्चिमी क्षेत्र में अक्षय चिन के बारे में या शेष मैकमहोन रेखा पर वह अपने अधिकार को निर्विवाद नहीं मान सकता।

(पत्रकार शिष्टमंडल से मेट अगले पृष्ठ पर)



## चीन पत्रकारों की नजर में

दिल्ली के मौर्य होटल के कमरा नंबर 106 में चीन से आये पत्रकार शिष्टमंडल के नेता जियांग युआव चुन अपना सामान बाँध वापस पीकिङ लौटने के लिए तैयार बैठे थे। तारीख थी मई 14, शुक्रवार तभी उन्होंने भारत में अपनी आखिरी बातचीत 'दिनमान' से की।

प्रश्न: आप यहाँ पधारे, भारत में घूमे और पत्रकारों तथा अन्य मुख्य नागरिकों से आपकी बातचीत हुई। आपके बाद आप के देश के उच्चाधिकारियों का प्रतिनिधि-मंडल भी बातचीत के लिए यहाँ आ रहा है। क्या आशाएँ हैं आप को इस मेलजोल और बातचीत के दौर से?

उत्तर: मतभेद दोनों देशों में हैं। मगर मुझे आशा है कि दोनों ओर के प्रतिनिधि-मंडल एक दूसरे का नुक़्तानजर समझने का प्रयत्न करेंगे। हम चीनी पत्रकार आशा करते हैं कि दोनों ओर से आपसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा। एक दूसरे में विश्वास रख सार्थक, युक्तिसंगत, मित्रतापूर्वक और न्यायसंगत राहें अपनायी जायेंगी।

प्रश्न: कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से सहयोग की शुरुआत हो सकती है?

उत्तर: मैंने अपनी भारत यात्रा में ऐसे कई क्षेत्र देखे हैं जहाँ सहयोग की बड़ी संभावनाएँ हैं। कृषि, जनसंख्या नियंत्रण, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में दोनों देश बहुत कुछ कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या आप का पहले कभी भारत आना हुआ है? आज के भारत के बारे में आप के क्या अनुभव हैं?

उत्तर: मुझे भारत में पहली ही बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत के विषय में आम जानकारी तो मुझे और मेरे अन्य पत्रकार साथियों को पहले से थी। आँखों देखने और सीधी समझबूझ का यह पहला ही अनुभव है। हमने देखा कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद ठोस प्रगति की है। भारत की आर्थिक संस्कृति में विशेष सफलताएँ हमें देखने को मिलीं। ये अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, खास तौर पर इस नाते कि भारत तीसरी दुनिया, विकासशील देशों के परिवार और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण सदस्य है। हमें भारतीय प्रेस से विस्तृत संपर्क का अवसर मिला। हम ने देखा कि भारतीय प्रेस ने तकनीकी रूप से

काफी उन्नति की है और काफी प्रगतिशील है। हमारा अनुभव तो यह है कि चीन और चीनी जनता के प्रति भी अधिकतर सद-भावना ही दिखाई दी हमें।

प्रश्न: अपने देश लौटेंगे तो आज के भारत के विषय में अपने पाठकों के सामने चित्र पेश करेंगे?

उत्तर: मैं समझता हूँ कि अपने अनुभवों के आधार पर हम आज के भारत और भारतीय स्थिति के बारे में अधिक सहानु-भूति और अधिक सूझ के आधार पर सच्चाई पेश कर सकेंगे। मेरे विचार में चीन के पत्रकारों को यही राह अपनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत और चीन दोनों ही विकासशील देश हैं। दोनों ने ही वर्षों साम्राज्यशाही शक्तियों की घाँस सही है। दोनों की बहुत सी समस्याएँ एक सी हैं। दोनों के बीच वर्षों तक मित्रतापूर्वक आमना सामना और आदान-प्रदान रहा है। आपसी सूझ बूझ, मित्रता और सहयोग से दोनों देश इस क्षेत्र में और शेष संसार में क्रांति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या भारतीय और चीनी पत्रकार मंडलों के आदान-प्रदान से इस सहयोग के मार्ग में कुछ योगदान हो सकता है?

उत्तर: हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। हम लोग यहाँ अखिल भारतीय समाचार संपादक सम्मेलन के निमंत्रण पर आये। जहाँ जहाँ हम इस देश में गये हमारा बड़ी शिष्टता और मित्रता से स्वागत हुआ। हमें बहुत कुछ देखने समझने का अवसर मिला। अच्छी यादें ले कर हम घर लौट रहे हैं। इस साल के उत्तरार्द्ध में भारतीय संपादकों के एक प्रतिनिधि-मंडल के चीन पधारने की संभावना है। मुझे आशा है कि भारतीय और चीनी पत्रकारों के इस आदान-प्रदान से दोनों देशों को एक दूसरे को अधिक समझने और आपसी मित्रता बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। मैं समझता हूँ कि दोनों देशों की जनता में एक दूसरे को अधिक समझने और मित्रता बढ़ाने की इच्छा है।

प्रश्न: कुछ लोगों का विचार है कि भारत और चीन जैसे संसार के अन्य बहुत से देश विश्व प्रसारण साधनों की आज की स्थिति के कारण एक दूसरे को समझने के लिए पश्चिमी प्रसार साधनों से देखने पर विवश हैं जिस से एक दूसरे को सचमुच में समझना कठिन हो जाता है। विश्व प्रसारण व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता समझते हैं ये लोग। इस संबंध में आप के क्या

विचार हैं?

उत्तर: जब हम भारत और भारतीय सरकार के इस देश में परिवर्तन और विकास लाने के प्रयासों के बारे में लिखेंगे, मेरे विचार में विकासशील देशों के पत्रकारों और प्रचार साधनों को पश्चिम से भिन्न आपदंड और राहें अपनानी चाहिए। बहुत से पश्चिमी पत्रकार हमारे देशों में बस पिछड़ेपन के पहलू खोजने और उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए ही आते हैं। उन्हें पिछड़ेपन पर विजय पाने के लिए हमारे सक्रिय प्रयास दिखाई नहीं देते। वह हमारा चित्र खींचते हैं तो हमें मूर्ख, पिछड़े और अफरातफरी प्रेमी लोगों का देश कहते हैं। वे यह बात बड़े आराम से भूल जाते हैं कि हमारा पिछड़ापन उन्हीं पश्चिमी देशों द्वारा एक लंबे दमन और शोषण की उपज है। भारत और चीन के सहयोग से इस दिशा में तथा शांति स्थापना के क्षेत्र में न केवल एशिया पर ही बल्कि सारे संसार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

प्रश्न: कुछ आप आज की चीनी प्रेस के बारे में बतायेंगे। उस का जनता, चीन की सरकार और वहाँ की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से क्या संबंध है?

उत्तर: चीन का प्रेस अपने आपको चीनी जनता और समाज के एक अटूट अंग के रूप में देखता है। हम अपनी भूमिका सरकार के प्रतिद्वंद्वी मात्र की नहीं समझते। देश की रक्षा, उसकी एकता और देशव्यापी अमन बनाये रखना हम चीनी प्रेस और पत्रकारों का भी उतना ही कर्तव्य समझते हैं जितना किसी भी अन्य देशभक्त चीनी नागरिक का। हम जनता, पार्टी, सरकार और प्रेस को एक दूसरे से अलग अलग, परस्पर टकराने वाले तत्व नहीं मानते। हम अपने देश की जनता की आकांक्षाओं और सामूहिक संकल्पशक्ति को प्रतिबिंबित करने में जुटे रहते हैं। मगर जहाँ सरकार या पार्टी में कमी देखते हैं, वहाँ नीतियाँ बनाने में या नीतियों पर ठीक अमल करने में, वहाँ की आलोचना द्वारा जनता का मत व्यक्त किया जाता है। भूल सुधारने का अनुरोध किया जाता है।

प्रश्न: कोई मिसाल देंगे आप?

उत्तर: जरूर। एक मिसाल देता हूँ। पिछले वर्ष एक मंत्री पीकिङ के एक बड़े रेस्तराँ में अपने कुछ मित्रों के साथ खाना खाते थे। भोजन के बाद उन्होंने पूरा बिल नहीं चुकाया। समाचारपत्रों ने कड़ी आलोचना इस बात की। मंत्री और उनके मित्रों अपनी भूल का सुधार करना पड़ा।



भेंटवार्ता

## भारत को बड़ी ताकत बनना चाहिए-

क्षितींद्र मोहन श्रीवास्तव से

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी की बातचीत

भारतीय राजनीति के सब से विवादास्पद और चर्चित व्यक्तियों में एक हैं जनता पार्टी के संसद सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यन स्वामी. चीन और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों के सब से बड़े वकीलों में उनकी गिनती होती है. दिनमान के लिए इस विशेष भेंट में उन्होंने बताया है कि इस के पीछे कारण क्या हैं?

डॉ. स्वामी के अनुसार, 'पिछले दस सालों में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है. परंतु इस परिवर्तन को पहचानने के लिए हमारे देश के अधिसंख्य लोग तैयार नहीं हैं. बंगलादेश के निर्माण के बाद अब पाकिस्तान हम से बराबरी का दावा नहीं कर सकता. उस युद्ध में दो टुकड़ों में बंटने के बाद पाकिस्तान से हमें जो खतरा था वह समाप्त हो गया. दूसरी बड़ी घटना पोखरन में हमारा सकल परमाणु विस्फोट है जिसने हमारी हैसियत बदल दी है.'

वीएनएम में पराजय के बाद अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि इस क्षेत्र में कहीं और फौज भेजे. कम से कम पचास साल तक अमेरिका कहीं अपनी फौज भेज कर हस्तक्षेप नहीं करेगा.

यदि ईरान में सोवियत संघ घुस गया तो परमाणु युद्ध होगा लेकिन अमेरिका वहाँ फौज नहीं भेजेगा.

इस तरह अमेरिका द्वारा खाली की गयी जगह को एशिया में भारत को भरना चाहिए.

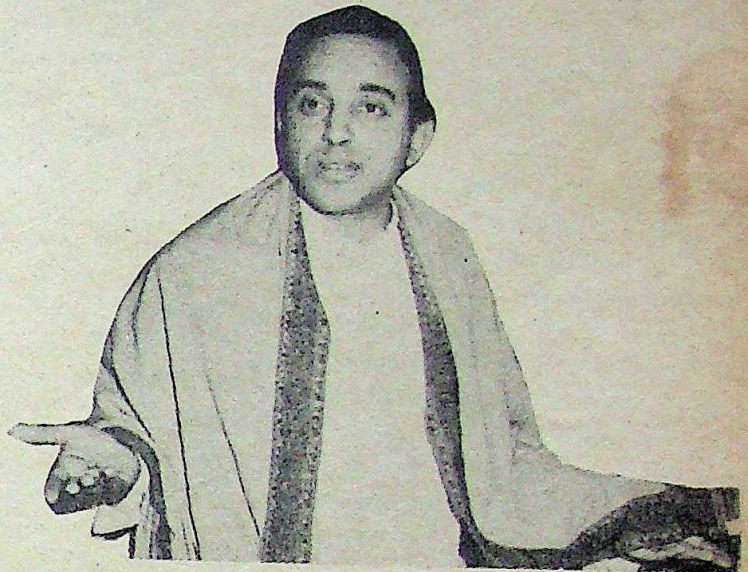
यदि हम इस जगह को नहीं भरेंगे तो रूस भरगा या चीन भरगा. भारत को बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनना है.

यह कैसे संभव होगा?

यह तभी संभव है जब हम पाकिस्तान, नेपाल, भोटान, बंगलादेश आदि की रक्षा की जिम्मेदारी लें. यह जिम्मेदारी लेने को वर्तमान सरकार तैयार नहीं है. ऐसा नहीं करने से हम फँसने वाले हैं. ईरान में अस्थिरता है.

यह और वे सोवियत के समर्थक हैं. पाकिस्तान जनरल जिया जायेगा तो श्रीमती मट्टो जायेगी. वह भी रूस के साथ होंगी. इस तरह खाली जगह रूस भर देगा जो बहुत खतरा बन जायेगा. हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ कर उस की रक्षा की जिम्मेदारी लें. यह बात श्रीमती गांधी

'हमें चाहिये कि हम पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ कर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लें.'



नहीं समझ रही हैं. उन्हें 'नौ बार पैकट' के वातावरण का लाभ उठाना चाहिए था.

पर आगा हिलाली के वक्तव्य के बावजूद?

पहले तो आगा हिलाली ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो नवंबर 1981 में संयुक्तराष्ट्र महासभा में आगा शाही ने न कही हो. पर बाद में जब हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता अनावश्यक रूप से मड़के तो आगा हिलाली ने भी कुछ ऐसा कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था. पर कश्मीर का विषय उठा कर पाकिस्तान क्या कर लेगा? क्या वह हमारे पास जो हिस्सा है वह ले सकता है? कभी नहीं. यदि पाकिस्तान इस बार लड़ा तो यह उस का आखिरी युद्ध होगा. बंगलादेश की लड़ाई के बाद जो पाकिस्तान बचा है उसे मैं 'बाकिस्तान' कहता हूँ और अब फिर लड़ाई हुई तो हम उसे 'चटनिस्तान' बना देंगे. कश्मीर का मामला कहीं भी उठाए उस से क्या होता है?

क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की रक्षा का जिम्मा लें और हथियार बना कर पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों को बेचें?

विल्कुल! पाकिस्तान को हथियार बेचने से कितना मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा इस की कल्पना कीजिए. फिर इस में हर्ज ही क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन सदा के लिए नहीं होता. द्वितीय विश्वयुद्ध इस का उदाहरण है.

फिर खतरा समुद्र से भी आ सकता है. हमें अपनी नौसेना का विस्तार करना चाहिए. इस से बड़ी ताकत हमारे हाथ में आयेगी. निकोबार द्वीपसमूह के आखिरी द्वीप और सुमात्रा के बीच सिर्फ 90 मील का अंतर है. इस 'मलक्का स्ट्रेट' से यूरोप और अमेरिका का

10 प्रतिशत व्यापार गुजरता है. स्वेज का जो लाभ मित्र ने उठाया है वही लाभ इस स्थिति का हम उठा सकते हैं.

फिर समुद्र में हमें तेल मिला है और मिल रहा है. इस की सुरक्षा भी जरूरी है. नौसेना को यह स्तर प्रदान करने के लिए हमें उत्तरी सीमा को शांत रखना होगा. इस के लिए चीन के साथ बेहतर संबंध जरूरी हैं. चीन इस के लिए तैयार भी है. यदि हम यह स्पष्ट दिखा दें कि हम रूस से जुड़े हुए नहीं हैं.

पर हाल ही में सोवियत राष्ट्रपति ब्रेज्नेव ने चीन से बातचीत का प्रस्ताव किया है और बी.बी.सी. के पीकिङ संवाददाता का कहना है कि चीनी नेताओं का रूस से बातचीत के लिए जितना अनुकूल रुख अभी है उतना पहले कभी नहीं था?

इस का कारण रीगन की ताइवान नीति है. पर वास्तव में चीन और रूस में कभी दोस्ती हो नहीं सकती. वे एक बार घोखा खा चुके हैं.

बंगलादेश में हाल के सत्ता परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं?

यह हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ. सत्ता जिनके हाथ में है वे लोग पाकिस्तान समर्थक हैं और मेरा अनुमान है कि अमेरिकी सहानुभूति भी उनके साथ है. इस के अलावा अमेरिका श्रीलंका में त्रिकोमाली में अपनी सेना के लिए 'रेस्ट एंड रिसेप्शन सेंटर' खोल रहा है. वहाँ भी थाईदेश जैसी हालत हो जायेगी और बाद में वहाँ पर जमाये रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है.

माल्टा में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्तालिन के बीच हुई संधि में दोनों महाशक्तियों ने प्रभाव क्षेत्र बाँट लिये थे. वह संधि अभी भी कायम है. तीसरी दुनिया उस संधि के दायरे में नहीं है इसलिए इसके देशों को अपने प्रभावक्षेत्र



में लेने की होड़ लगी हुई है। अफगानिस्तान में रूस का घुस जाना खतरे की घंटी है। समुद्र की ओर से हमें अमेरिका घेर रहा है।

**क्या आप समझते हैं कि भारत को परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए?**

यदि भारत अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाना चाहता है तो परमाणु अस्त्र बनाना जरूरी है। परमाणु अस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते। सिर्फ धमकी दे कर लाभ उठाया जा सकता है। हिरोशिमा के बाद अभी तक कहीं परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन उनके उपयोग की धमकी ग्यारह बार दी जा चुकी है। अमेरिका ने बंगलादेश युद्ध के दौरान हमें भी परमाणु बम की धमकी दी थी। उसने हमें संदेश भेजा था कि सातवें बड़े के जो जहाज बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहे हैं उन में परमाणु अस्त्र हैं।

**रीगन और उनकी नीतियों के बारे में आप का विश्लेषण क्या है?**

वह निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ग की विचारधारा यह है कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए और बाहर अपने दोस्तों को मजबूत करना चाहिए, दोस्त कोई भी हो। लोकतंत्र में दोनों तरह के लोग होते हैं — बुराई करने वाले भी और तारीफ करने वाले भी। अमेरिका को डिक्टेटर ज्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ एक ही आदमी से बात करनी पड़ती है। भारत में लोकतंत्र है लेकिन अमेरिका को जिया उल हक ज्यादा पसंद है। यह 'काउन्टरवाय एप्रोच' कहलाती है।

**चलिए अब भारत लौट आये। देश की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं?**

हमारे पास सब कुछ है। पढ़े लिखे लोग हैं, बारह महीने धूप है, समुद्र है, खनिज है, हर तरह की प्रतिभा है। कमी है तो सही चरित्रवान नेतृत्व की।

**आपको भी तो सत्ता में रहने का अवसर मिला था, वह नेतृत्व आपने क्यों नहीं दिया?**

हमारे पास 'क्वालिटी' थी पर 'टीम वर्क' नहीं था।

**'क्वालिटी' में भी सभी ठीक थे क्या?**

नहीं, सब तो अच्छे नहीं थे।

**भी अटलबिहारी वाजपेयी से आपकी अनबन के पीछे सत्य क्या है?**

इन्होंने मुझे बहुत रलाया है। इमरजेंसी के दौरान यह माफी माँग पर पेट्रोल पर छूटे। जब मैंने राज्यसभा में 'प्वाइंट आफ आर्डर' उठाया था तो यह कहते थे कि इस से मुँह काला

हो गया। ओम मेहता से बात कर के इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि आत्मसमर्पण कर दो। आर. एस. एस. के माधवराव मुले ने कहा कि यह ठीक नहीं है। स्वामी को जेल में टाँच कर रहे, तो इन्होंने कहा कि मैंने ओम मेहता से बात कर ली है। जेल अच्छी होगी। अटेन्ड बाथ होगा, टी. वी. होगा। इन्होंने मेरा हौसला तोड़ने की बड़ी कोशिश की।

जब सरकार बनी तब भी यह तंग करते रहे। इन्होंने कहा कि स्वामी इसलिए नाराज है कि मैंने इसे मंत्री नहीं बनने दिया। मंत्री नहीं बनाने वाले यह कौन थे। मंत्री नहीं बनाने वाले तो मोरारजी थे और उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे और अभी भी हैं। यह रोज मेरी शिकायत करते थे। एक बार अक्टूबर 1977 में इन्होंने चंद्रशेखर, मधु लिमये वगैरह को राजी कर लिया था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाये, पर मोरारजी ने ऐसा नहीं होने दिया। जनता पार्टी के शासन के दौरान विदेशमंत्री के रूप में इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया मोरारजी ने किया। यह तो बस सँभलते थे। जून 1979 में मस्क्वा में जब मोरारजी ब्रेजनेव से बात कर रहे थे यह तब ऐश कर रहे थे। यह बात मुझे खुद मोरारजी ने बतायी।

चीन जाने के पहले पता था कि वीएतनाम के साथ क्या होने वाला है। तेड्. सियाओ पिङ्. ने कहा था कि हम वीएतनाम को सबक सिखायेंगे। मैंने तेड्. सियाओ पिङ्. से कहा था कि वीएतनाम को क्यों तंग करते हैं, बेकार में। पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्हें बातचीत कर के सीधे वापस आ जाना चाहिए था। पर चले गये सँभलते थे।

**विपक्षी दलों के एकता प्रयासों के विषय में आप क्या सोचते हैं?**

यह तो सही है कि देश में दो या तीन पार्टियाँ होनी चाहिए। पर दूसरे विरोधी दलों के लोग हमारे साथ कितनी देर तक साथ रहेंगे इस में संदेह है। जो लोग इंदिरा गांधी को जेल भेजना चाहते हैं उन्हीं लोगों ने उसी इंदिरा गांधी का साथ ले कर पार्टी तोड़ कर सरकार बना ली। जुलाई 1979 में जब से यह हुआ है शंका बनी हुई है। जिन्हें आता है जनता पार्टी में आये और सेवक की तरह काम करे, बिना शर्त, बिना पद. फिर शरद पवार और जगजीवनराम जैसे लोग हैं जो कांग्रेस (इं) में जाना चाहते हैं पर श्रीमती गांधी उन्हें ले नहीं रही इसलिए विपक्ष में हैं। ये लोग आगे क्या करेंगे कौन जानता है? एकता के बाद भी जीतना कठिन है परंतु जीत के बाद दोबारा टूटना हम पसंद नहीं करेंगे।

## लोकहित में आप भी याचिका दायर कर सकते हैं

साधनहीन खास कर कार्यपालिका मुकाबले में कमजोर या अपने कानूनी अधिकारों से अनजान लोगों को जो अवांस्त दरवाजे नहीं खटखटा सकते, क्या न्याय मिल सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित मामले में अन्य व्यक्ति की ओर से अवांस्त न्याय माँग सकता है। इस कानूनी मुद्दे को उठा बहस का विश्लेषण कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत पांडे।

**यों** तो भारतीय संविधान में प्रतिपादित उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अन्य किसी भी देश के न्यायालय की तुलना अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली है, कि लोकहित के मुकद्दमों के संबंध में याचिका दायर करने एवं सुने जाने के अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर जो आयाम एवं तजीर की है उसे लेकर एक दिलचस्प बहस जारी अधिकांश लोगों की राय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित दिशाबोध एक सराहनीय फैसला है जिसके दूरगामी प्रभाव भारतीय परिस्थिति में अवश्यभावी हैं। कुछ अन्य समीक्षकों की राय में न्यायालय की यह उदारता गतिविधि लोक-हित के नये मुकद्दमों की बाढ़ लाती है जब कि वर्तमान में भारतीय न्याय प्रणाली निर्णयाधीन मुकद्दमों की समस्या से लुप्त चरमरा-सी रही है।

याचिका दायर करने एवं सुने जाने के अधिकार के बारे में न्यायालय अपनी परंपरावादी अनुदार दृष्टिकोण अपनाती है जिसके अनुसार केवल उसी व्यक्ति को ही विशेष को न्यायालय में सुना जाये जिसे प्रत्यक्ष रूप में पर्याप्त वैयक्तिक हानि अथवा हानि हुई हो। इस विचारधारा के तहत सार 'विधि जागरूक की सहायता करने न कि सुपुर्त की।' 'विधि कुछ बातों पर ध्यान नहीं देती', 'विधि की अनमिशन प्रतिहेतु नहीं है'।

कालांतर में समाज के बदलते चेहरे के साथ-साथ समस्याओं का स्वरूप बदलता है, इनका समाधान भी बदलता है, कि शास्त्र इस परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं रह सकता है।

सात न्यायाधीशों की पीठ : उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ : 23-29



प भी  
कर

वर्षपालिका

कानूनी अधि

नो अवाला

क्या न्याय

में सर्वो

कसी भी व्यक्ति

जनिक हित

र से अवाला

कानूनी मुद्दे

रहे हैं सर्व

मीकोत पा

में प्रतिपा

की अधिकारि

लय की तुलना

शाली है, नि

बंध में याचिका

के अधिका

ने अपने नि

एवं नजीर का

प बहस जा

नवोच्च न्याया

सराहनीय

भारतीय परि

न्य समीक्षकों

उदारता भवि

नी बाढ़ ला

तीय न्याय प्र

मस्या से खु

एवं सुने जा

यालय अभी

कोण अपना

उसी व्यक्ति

में सुना जा

वैयक्तिक

व्यवहार के

सहायता कर

तुच्छ बात

नी अनभिज्ञता

के बदलते

का स्वतन्त्र

ता है, फिर

प्रक्रिया से

एक विशिष्ट न्यायापीठ ने 30 दिसंबर, 1981 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी मुकद्दमे में जो निर्णय दिया वह पिछले दिनों सारे देश में चर्चा का विषय रहा है। इस महत्वपूर्ण मुकद्दमे की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि न्यायालय ने एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि न्यायालय ने लोकहित में याचिका दायर करने एवं सुने जाने के अधिकार के बारे में स्पष्ट एवं सर्व-सम्मत निर्णय दिया, जिसके दूरगामी प्रभाव शीघ्र ही परिलक्षित होने लगे हैं।

इस निर्णय से पहले भी उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के मुकद्दमों में सुने जाने के अधिकार की व्याख्या की है, जैसे के. आर. शेनॉय, बनाम उडिपी नगरपालिका (1974), एम. देसाई बनाम रोशन कुमार (1976), आर. काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.बी. दमोकर, (1975), रतलाम नगरपालिका बनाम वर्षी चंद (1970), सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980), डा. ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1981) फटिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन, सिदरी बनाम भारत सरकार (1981), आर.के. गर्ग बनाम भारत सरकार (1981), आदि; परंतु सात न्यायाधीशों की न्यायापीठ के इस निर्णय के बाद इस विषय को लेकर जो थोड़ा मतभेद एवं संदेह था, वह समाप्त हो गया है।

उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की इस न्यायापीठ के समक्ष लोकहित में याचिका दायर करने एवं सुने जाने के अधिकार का विशेष एवं स्पष्ट रूप से सामने था। अकालीन केंद्रीय विधिमंत्री द्वारा जारी किये गये विवादग्रस्त परिपत्र की संवैधानिक वैधता को कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायालय में चुनौती दी। सरकार यानी बचाव पक्ष ने आरोप में इन अधिवक्ताओं के याचिका दायर करने एवं न्यायालय में सुने जाने के अधिकार पर संदेह व्यक्त कर यह दलील दी कि इन अधिवक्ताओं को विवादग्रस्त परिपत्र से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष वैयक्तिक हानि नहीं होती, अतः उन्हें न्यायालय में याचिका दायर करने एवं सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत का तर्क : न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती (जिन्होंने इस मुद्दे पर न्यायापीठ का बहुमत निर्णय लिखा) के अनुसार लोकहित के मुकद्दमों में किसी तीसरे पक्ष द्वारा याचिका दायर करने एवं सुने जाने के अधिकार का आधार न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए न्यायालयों द्वारा उपलब्ध अनेक कारणों से संभव है एवं भारतीय जनमानस का एक भाग अपने अधिकारों से या तो अनभिज्ञ

है अथवा उनके लिए ये अधिकार मात्र थोथी आशाएँ बनकर रह गये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पक्ष की दलीलों को न मानते हुए यह निर्धारित किया कि अब यह प्रायः निश्चित है कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के विधिक अथवा संवैधानिक अधिकार के हनन से कोई क्षति अथवा हानि होती है और वह व्यक्ति या वर्ग विशेष गरीबी अथवा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण न्यायालय में प्रतितोष के लिए आने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में तीसरा पक्ष (व्यक्ति अथवा संगठन विशेष) भारतीय संविधान के 226 वें अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर उचित अनुतोष की प्रार्थना कर सकता है। यदि किसी मामले में संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो तो ऐसी स्थिति में संविधान के 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार अब कोई भी नागरिक सार्वजनिक कर्तव्यभंग होने, संविधान अथवा कानून के किसी विशेष उपबंध के हनन होने से प्रत्युत्पन्न सार्वजनिक हानि होने की स्थिति में न्यायालय में याचिका दायर कर न्यायायिक प्रतितोष की मांग कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक हित के मुकद्दमों

में याचिका दायर कर सकने के अधिकार की उदार व्याख्या कर पिछड़े एवं संतप्त वर्ग में एक नयी आशा को जन्म दिया है। उपयुक्त मामले में उच्चतम न्यायालय को लिखे गये पत्र मात्र को ही याचिका रूप में स्वीकार कर न्यायालय उस पर उचित निर्देश दे सकता है, इस प्रकार न्याय उपलब्ध में पूर्व की पारंपरिक औपचारिकता (जिन्हें अधिकतर बाधाएँ माना जाता है) कम हुई हैं, साथ ही अब न्याय यथाशीघ्र एवं सुलभ तरीके से प्राप्त हो सकेगा, ऐसी लोगों को आशा बँधी है। बिहार के विचारार्थ अभियुक्तों का मुकद्दमा, भागलपुर जेल में अभियुक्तों को अंधा किये जाने पर दायर मुकद्दमा, आगरा के स्त्री अपराधियों के संरक्षण गृह के संबंध में दायर किया गया मुकद्दमा, मंदसौर में स्लेट की खानों में काम करने वाले बंधुवा मजदूरों का मुकद्दमा, कमला को लेकर पत्र-कारों द्वारा दायर मुकद्दमा आदि कुछ ऐसे ही



न्यायमूर्ति भगवती

उदाहरण हैं। ये मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन हैं।

पहले उच्चतम न्यायालय ने रतलाम नगर पालिका वाले मुकद्दमे में यह निर्धारित किया कि नगरपालिका एवं उसके अधिकारियों को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों के परिपालन हेतु न्यायालय से मांग की जा सकती है। सुनील बत्रा के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जेल में सजा मोग रहा एक अपराधी दूसरे अन्य अपराधियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

तत्पश्चात् का दूसरा पहलू : न्यायालय का यह प्रयास आलोचना से मुक्त नहीं रह सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। विधि आयोग द्वारा जारी किये गये विवादग्रस्त प्रश्न संग्रह में भी इस समस्या का उल्लेख है जो कि विचार एवं सुझाव हेतु राष्ट्र के सामने है।

समीक्षकों के एक वर्ग के विचारानुसार :

(1) लोकहित के मुकद्दमों में सुनवाई के बढ़ते अधिकार से नये मुकद्दमों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे निर्णयाधीन मुकद्दमों की समस्या और भी जटिल हो जायेगी, (2) न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच तनाव और बढ़ेगा, (3) यह न्यायपालिका प्रशासन के क्षेत्र में अवांछनीय हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा, (4) न्यायाधीशों पर प्रशासन संबंधी समस्याओं एवं समाधान हेतु इस प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार करना खतरे से खाली नहीं है, (5) इस प्रकार के मुकद्दमों द्वारा कोई भी व्यक्ति या वर्ग विशेष लोकहित की आड़ में अपना या वर्ग विशेष का स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। इस प्रकार यह न्यायालय एवं न्यायप्रणाली का दुरुपयोग होगा।

उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की न्यायापीठ के समक्ष विपक्ष यानी सरकारी पक्ष की तरफ से ये सारी दलीलें दी गयीं। इस तर्क के आधार पर न्यायालय से अनुरोध किया गया कि याचिका दायर करने एवं सुनवाई के अधिकार को यथासंभव सीमित रखा जाये। न्यायाधीश श्री पी. एन. भगवती ने अपने निर्णय में इन सभी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। माननीय न्यायाधीश के अनुसार 'इस स्थिति में न्यायालयों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। न्यायालयों को अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए एवं संविधान द्वारा विधानमंडल एवं कार्यपालिका के निर्धारित कार्य क्षेत्र में न्यायालयों का अतिचार नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक कानून के विधिशास्त्र के बढ़ते एवं बदलते सिद्धांतों एवं मान्यताओं के संदर्भ में यह मर्यादा और भी आवश्यक है। □



## विधायकों की एक जबर्दस्त नीलामी!

इंदरजीत, संपादक : इन्फा

जल्दी ही एक ऐसी अवस्था आ सकती है जब विधायकों की एक और बड़ी नीलामी होगी। दो बदनाम राज्यों, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में यदि किसी एक दल या संयुक्त दलों को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता तो दलबदल होना अवश्यमावी है। विशेष रूप से यदि कांग्रेस (इं) को मामूली बहुमत मिले या बहुमत मिलने में थोड़ीसी कमी रह जाये तो ऐसा होना संभव है। जो लोकतंत्र प्रिय लोग भारत में स्वस्थ लोकतंत्र को पतनता हुआ देखना चाहते हैं वे अभी से वातावरण में दलबदल की चर्चा सुन कर बड़े दुखी हैं। काश! पिछले वर्षों में दलबदल का इस परंपरा को खत्म करने के लिए जरा भी कुछ किया गया होता। भारत में वेश्यावृत्ति पर कई वर्षों से रोक लगी हुई है। पर यहां राजनैतिक वेश्यावृत्ति निर्लज्जता से पतन रही है। इस से भी बुरी बात यह है कि इसे चतुराई का काम माना जा रहा है।

श्रीमती गांधी ने एक बार फिर दलबदल के बारे में अपने विचारों पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहने दी है। रविवार को हरयाणा में मिवाजी की एक सभा में जब राज्य के मुख्यमंत्री मजनलाल श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वागत में बोल रहे थे तो उपस्थित भीड़ ने बहुत हल्ला-गुल्ला मचाया। याद रहे, मजनलाल श्रीमती गांधी के सत्ता में लौटते ही जनता पार्टी के बहुमत को साथ लेकर दलबदल कर कांग्रेस (इं) में आ गये थे और इस तरह उन्होंने दलबदल का एक नया कालिमान स्थापित किया था। ऊपर से क्रोध दिखाते हुए श्रीमती गांधी ने दलबदलों की, और व्यक्तिगत रूप से श्री मजनलाल की प्रशंसा कर दी। बताया जाता है कि श्रीमती गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने पश्चाताप किया तथा बाद में कांग्रेस (इं) में लौट आये हैं उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण मूल प्रश्न है श्रीमती गांधी का दलबदलों के पक्ष में आश्चर्यजनक रूप से खुले आम सफाई देना। प्रभुसत्ता संपन्न कौन है, जनता या उनके प्रतिनिधि? लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। दूसरे शब्दों में जनता प्रभुसत्ता संपन्न है और हमारी शासन प्रणाली के अंतर्गत विधिवत चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार शासन करती है। परस्पर विरोधी उम्मीदवार अपने आप को चुनाव के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिन में से अधिकतर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। जनता किसी भी एक दल के प्रति अपनी अंमिरुचि प्रकट करती है। जब कोई चुनाव हुआ प्रतिनिधि अपनी इच्छा से दल बदलता है तो वह जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है और किसी सीमा तक स्वयं को 'प्रभुसत्ता संपन्न' मान बैठता है।

यह निर्विवाद है कि प्रत्येक विधायक को अपनी राय बदलने तथा दल और सिद्धांत छोड़ने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में किसी भी सांसद या विधायक को त्यागपत्र देने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए, वह लोकदल छोड़ कर कांग्रेस (इं) में शामिल हो सकता है। पर अपने मतदाताओं और चुनाव क्षेत्र के प्रति ईमानदारी बरतते हुए उसे सांसद या विधायक के रूप में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तो वह अपने मतदाताओं को ही दलबदल के लिए बाध्य कर रहा होता है। उसके लिए सम्मानित तरीका तो यही होगा कि वह अपने स्थान से त्यागपत्र दे और प्रभुसत्ता संपन्न जनता से फिर से आदेश प्राप्त करे। पचासवें दशक के आरंभ में आचार्य नरेंद्र देव ने इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी गढ़वाल से कांग्रेस (इं) सांसद के रूप में त्यागपत्र दिया और वह अब नया चुनाव लड़ रहे हैं।

भारत पर दलबदल का चाबुक सब से पहले 1967 के आरंभ में पड़ा जब वह लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा में खरा उतर चुका। चौथे आम चुनावों के स्वतंत्र और निर्विघ्न समाप्त हो जाने का सेहारा के सिर पर बंध चुका था। फिर भी, हमारे लोकतंत्र को कुछ ही महिनो भीतर अवसरवाद के परिणामस्वरूप दलबदल के रूप में आजादी बाद पहली बार एक जबर्दस्त चुनौती का सामना करना पड़ा। 'सेवा' का स्थान स्वार्थ ने बड़ी बेलगामी और बेशर्मी के साथ लिया और दलबदल का व्यवसाय आजकल आम बात हो गयी।

देश यह देख कर अवाक रह गया कि सांसद तथा विधायक अयंत्रित हो कर 'जन सेवा' और 'देश' की अपेक्षा 'स्वार्थ' को अधिक महत्त्व दे रहे हैं। 8 दिसंबर 1981 को वर्तमान गृह राज्यमंत्री वेंकट सुबेय्या के एक प्रस्ताव को लोकसभा ने निर्विरोध स्वीकार कर दिया कि दलबदल की समस्या से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय। 21 मार्च, 1968 को तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यशवंत राव चव्हाण ने दलबदल की समस्या को लेकर एक समिति गठित करने की घोषणा की थी और दलबदल को एक ऐसा 'राष्ट्रीय रोग' बताया 'जो लोकतंत्र के मूलाधार को ही खाये जा रहा है'। समिति के अध्यक्ष स्वयं चव्हाण थे और समिति के सदस्यों में थे—सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, एम. सी. सोतलवाड़ तथा मोहनकुमार मंगलम्। इनके अतिरिक्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और तीन निदलोय गुटों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे।

समिति ने कई नैतिक, राजनैतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक सिफारिशें कीं। कुछ मामलों में मत वैमिष्य भी था। फिर भी महत्त्व यह है कि समिति दलबदल की परिभाषा देने में एकमत हो गयी थी। विधायिका का एक चुनाव हुआ सदस्य, जिसे किसी भी राजनैतिक दल का सुरक्षित चुनाव बिना दिया गया हो तथा वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का विधान परिषद विधानसभा का सदस्य चुना गया हो और फिर वह स्वेच्छा से उस राजनैतिक दल से संबंध या सहभागिता तोड़ता है और ऐसा वह संबंध के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप नहीं करता तो उसे 'दलबदल' माना जा सकता है।

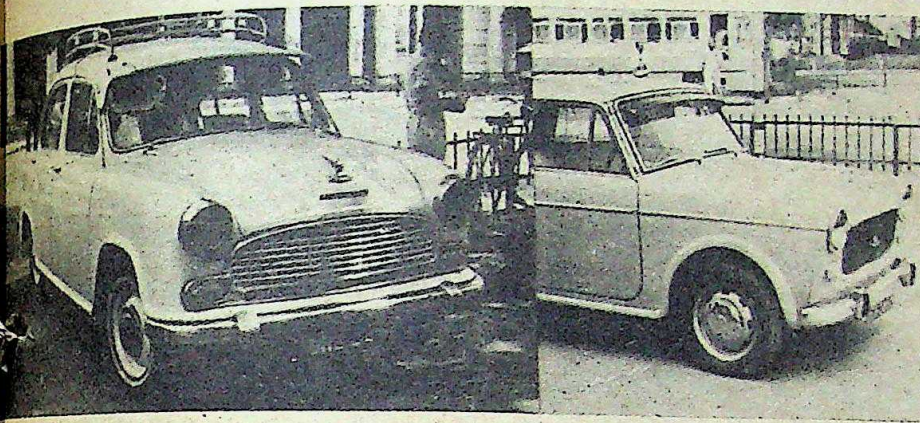
सभी इस बात पर सहमत थे कि 'दलबदल' को एक वर्ष की अवधि के लिए या उस स्थान से त्यागपत्र दे कर फिर से चुनाव जीतने तक के किसी मंत्री या सभापति या उपसभापति या किसी भी ऐसे पद के अयोग्य करार दिया जाये, जिस के लिए भारत के समेकित कोष वेतन अथवा भत्ते दिये जाते हों। चव्हाण समिति ने दृढ़ता से कहा कि इस समस्या का स्थायी हल तभी मिल सकता है, यदि राजनैतिक पार्टियाँ किसी आचार संहिता या परंपराओं का पालन करें जिससे 'किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के काम को चलाने के लिए आधार गुणों और शालीनता का ध्यान रखा गया हो'।

क्या इस महामारी के शुरू होने के पहले, भी कुछ किया जा चुका है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके दलबदल पर रोक लगाने हेतु एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है—पर यह संभव है जब श्रीमती गांधी कम से कम संवैधानिक समिति की सिफारिश को लागू करने की इच्छा रखती हों। बताया जाता है कि राष्ट्रपति संजीव रेड्डी अपने कार्यकाल के शेष समय में भारत तथा हमारे जनतंत्र के लिए बहुत कुछ करने को उत्सुक हैं, वह जहाँ प्रभुसत्ता संपन्न वही सरकार को बनाये रखने का परामर्श दे सकते हैं। धुवीकरण जाने की अनुमति दिये जाने का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं न कभी न कभी तो लक्ष्मण रेखा खींचनी ही होगी क्योंकि लोकतंत्र ही अनिवार्यतः सरकार का एक सभ्य स्वरूप है। यदि 'जन कानून' चलेगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता।



भारतीय कार निर्माताओं की करुण कहानी

## इनके खातों में लाभ के आँकड़े कैसे आने लगे



उपयोग न करने की तथा यह एक संभावना पूर्ण बाजार के दुरुपयोग की कहानी है।

देश के तीसरे यात्री कार के निर्माता की स्थिति इस का सही उदाहरण है, मद्रास की स्टैंडर्ड कार कंपनी की घटती माँग तथा लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए उसे गत वर्ष कार का उत्पादन बंद कर देना पड़ा। 1981 में कंपनी का कुल कार उत्पादन गिर कर केवल चार कार ही रह गया और अंत में कंपनी ने हलके किस्म के व्यावसायिक वाहनों का



नारायणदत्त तिवारी

निर्माण शुरू कर दिया। इन वाहनों को आम तौर से 'स्टैंडर्ड पिक-अप वैन' कहा जाता है।

प्रत्यक्ष रूप से स्थिति अब उलट गयी है, क्योंकि कारों के मूल्य सर्वोच्च बिंदु

पर पहुँच चुके हैं तथा अब लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वे कार खरीद सकें। इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगले दो वर्षों के बाद इन दो कार उत्पादकों को भी भारत के चलते अपना उत्पादन बंद कर देने के लिए मजबूर होना पड़े।

हिंदुस्तान मोटर्स व प्रीमियर आटोमोबाइल पहले देश में चार पहिए वाले ट्रक क्रमशः 'हिंदुस्तान' व 'ब्रैडफोर्ड' बनाती थीं, लेकिन गत दशक में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इन ट्रकों का उत्पादन बंद सा कर दिया है। सब से पहले इन्हीं लोगों ने ट्रक बनाने आरंभ की थी।

**मुनाफाखोरी:** यह स्पष्ट है कि इन उत्पादकों का एकमात्र लक्ष्य तात्कालिक लाभ कमाना ही है। ग्राहक की संतुष्टि उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। इस संदर्भ में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान डीलक्स मॉडल कारों के लिए भी ये उत्पादक पंजीकरण हेतु अग्रिम राशि के रूप में काफी राशि एकत्र कर चुके हैं। यह बात वैसे प्रीमियर आटोमोबाइल, डीजल एंबेसडर कार के बारे में नियमित रूप से हो रही है। ये कारें अधिकांशतः संसद सदस्यों तथा उनके सहयोगियों को ही बेची जाती हैं।

खुले बाजार में प्रीमियर कार की माँग बहुत है, लेकिन कंपनी ने कभी भी अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। इस से यह स्पष्ट होता है कि बाजार की स्थिति को देखते हुए ही निर्माता जानबूझ

भारतीय यात्री कार उद्योग की देश में कोई खास साख नहीं है, फिर भी अनेक वर्षों से वह बेचारे ग्राहकों को लूट खसोट कर फलता फूलता रहा है। कारों के खरीददार अधिकांशतः उच्च और मध्य आय वर्ग के लोग हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभाग व संस्थान हैं। अब लग रहा है कि इस उद्योग को राजनैतिक संमेलना पड़ेगा क्योंकि वह संकट की घड़ी पर पहुँच चुका है।

सीधी सच्ची बात तो यह है कि भारत सरकार ने कार उद्योग की शोषण प्रवृत्ति निराकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को निर्माण के क्षेत्र में उतारने का निर्णय किया है। सरकार ने यह निर्णय देर से किया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत देरी एवं उपयुक्त है। इस समय देश में केवल ही कार निर्माता हैं—हिंदुस्तान मोटर्स प्रीमियर आटोमोबाइल। दोनों ही निर्माता प्रतिवर्ष अपनी कारों के मूल्यों को बढ़ाते रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत भारत उद्योग लिमिटेड विसंयुक्त की मूमिका निभायेगा। 'जनता' का स्वप्न प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी ने सन् सत्तर दशक में साकार करने की सोची थी और उद्योग की शुरुआत की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली।

अब सार्वजनिक क्षेत्र के भारत उद्योग ने प्राचीन कंपनी 'सुजुकी' के साथ वित्तीय एवं प्रमुखता सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर छोटी यात्री कारों के साथ ही कम मूल्य उत्पादन अगले वर्ष के मध्य में आरंभ करने के लिए जोर शोर से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। निर्माताओं को लूट : कितने लोगों की लाइसेंस एंबेसडर कार' के निर्माता

तथा हिंदुस्तान मोटर्स के मालिक बिड़ला व इटली की सुप्रसिद्ध फियेट कार का भारतीय मॉडल बनाने वाली प्रीमियर आटोमोबाइल के मालिक हीराचंद लालचंद के साथ हो सकती है? शायद कोई भी व्यक्ति इन की खातिर एक भी आँसू न बहायेगा और न ही शायद इस से किसी के दिल को घक्का लगेगा। यह भी सत्य है कि संजय गांधी ने भी यह कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उन के सपनों की कार 'भारति' भी कभी देश के इन दो पुराने कार निर्माताओं को हिला कर रख देगी।

अनेक दशकों में इन दो उत्पादकों ने बेचारे भारतीय ग्राहकों को बहुत लूटा है। और ग्राहक वास्तव में तकनीकी रूप से इस बात से अनभिज्ञ है कि इस ऊँचे मूल्य पर जो कार उसे दी जा रही है उस में पुरानी प्रौद्योगिकी से तैयार किया गया इंजन लगाया गया है तथा इस इंजन की कार्यक्षमता भी कम है।

बदलती परिस्थितियों में सरकार की उत्सुकता का उल्लेख केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी के ताजा वक्तव्य में मिलता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि कारों के मूल्यों में अयुक्तिसंगत वृद्धि हो रही थी तथा यह उद्योग अन्य देशों में हो रही प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ कदम मिल कर चलने में असफल रहा है। यही नहीं, ये निर्माता विदेशी तकनीकों को भी पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाये हैं जिस के लिए उन्होंने विदेशी सहयोग के समझौते किये थे।

गत कुछ वर्षों में जो कुछ भी हुआ वह भारतीय यात्री कार उद्योग की एक करुण कहानी है। यह गाथा है प्रारंभिक ऊँचे खर्चों के बावजूद अपरिमित लाभ की, कम उत्पादन की तथा दो या तीन दशक पुरानी प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए आंतरिक स्रोतों का



कार कम कारों का निर्माण कर रहे हैं। प्रीमियर कार एंबेसडर कार से कुछ हजार रुपये सस्ती है, इसीलिए उसे पाने के लिए कम से कम पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

दोनों निर्माताओं की कार उत्पादन क्षमता 51 हजार कार प्रति वर्ष है। 1973 में तब तक सब से अधिक 39,937 कारों का निर्माण हुआ था। इस के बाद 1975 में यह संख्या घट कर 23,075 रह गयी। इस में फिर से सुधार आया, 1980 में, जब कि देश में 30,538 कारों का निर्माण हुआ। 1981 में कारों के निर्माण में अमृतपूर्व वृद्धि हुई और उन की संख्या 42,106 तक पहुँच गयी। हिंदुस्तान मोटर्स ने 23,197 कारों तथा प्रीमियर आटो-मोबाइल ने 18,874 कारों का निर्माण किया।

**नयी प्रौद्योगिकी का आयात :** वैसे मारुति के सक्रिय होने से हिंदुस्तान मोटर्स व प्रीमियर आटोमोबाइल की कुमकरणी नींद अब खुल गयी है तथा उन्होंने सरकार से अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम करने की अनुमति मांगी है। हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटेन की 'लीलैंड' कंपनी से नये इंजन के लिए तथा अमेरिका की 'वाक्सहॉल' कंपनी से नयी कार के ढाँचे के लिए सहयोग का प्रस्ताव किया है।

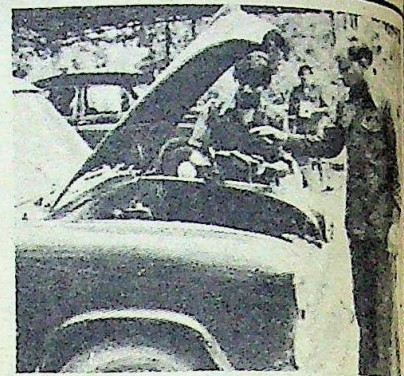
इसी प्रकार प्रीमियर ने भी स्पेन की 'सीट' कंपनी से नये ढाँचे तथा इटली की फियेट से नये इंजन के बनाने में सहयोग का प्रस्ताव किया है तथा नयी कार का नया नामकरण कर के इसे फियेट 124-डी कहा जायेगा। आशा है कि दोनों कंपनियों को मिला कर नये मॉडलों के विकास पर लगभग 80 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे, जबकि मारुति अगले पाँच वर्षों में कुल 230 करोड़ रुपये कार निर्माण पर खर्च करेगी। अब से ले कर 1983 तक 70 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान मारुति ने लगाया है।

दूसरी ओर मारुति छोटी कारों की शृंखला में विश्व की सबसे अधिक कार्यक्षम कार का निर्माण करेगी, जबकि हिंदुस्तान मोटर्स की नयी कार में मात्र कुछ रंग रूप का ही परिवर्तन किया जायेगा तथा प्रीमियर आटो-मोबाइल की नयी कार में भी कुछ ही नयी विशिष्टताएँ होंगी। प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों कार निर्माता वर्तमान कार से कुछ अधिक सुवरी हुई कार का ही निर्माण करेंगे।

ये दोनों ही निर्माता 'विक्रेता' प्रधान बाजार में अपनी कारें बेच रहे हैं, लेकिन वे बाजार में मारुति के दबाव को कम कर के आँक रहे हैं। मारुति के इंजन में ईंधन की खपत 'हिंदुस्तान' और 'प्रीमियर' की कारों से आधी है। संभवतः भारतीय बाजार में मारुति एक बार तो पूरी छा जायेगी और इन दोनों कारों पर एक प्रकार से झाड़ू सी फेर देगी।



बी. के. मेहता



अली मंजर

## ‘घूँसा मारो तो बाड़ी पिचक जाये’

पिछले तीन वर्ष में देश में बनने वाली प्रीमियर पद्मिनी और एंबेसडर कारों की कीमतों में 60 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई, जब कि यह आम शिकायत है कि इन कारों की गुणवत्ता में भारी कमी आयी है। इस बीच कीमतें और चीजों की भी बढ़ी हैं और इस तर्क में दम हो संकता है कि कच्चे माल की कीमतें और मजदूरी बढ़ने के कारण कारों के मूल्य में वृद्धि हुई है। परंतु वृद्धि इतनी अधिक है कि वह चौंकाने वाली हो गयी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार उद्योग के लिए संभावित संकट की आशंका ने कार निर्माताओं को समय रहते अधिकाधिक कमायी कर लेने के लिए प्रेरित किया हो?

प्रेमनाथ मोटर्स प्रा. लि. के, जो दिल्ली में पद्मिनी कार के विक्रेता हैं, विक्रय प्रबंधक बी. के. मेहता का कहना है कि कारों के मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण करनी पड़ी है। किंतु उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कार की गुणवत्ता में कमी आयी है। अगर क्वालिटी गिरी होती तो खरीददारों की लाइन न होती। फियेट के बारे में हमें ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली है, उनका तर्क था। फिर उन्होंने सगर्व बताया कि 'अब पद्मिनी के लिए 18-20 वर्ष की बुकिंग चल रही है।' वह यह नहीं मानते कि मारुति और जापान की सुजूकी कार निर्माता कंपनी के बीच हुए समझौते का भारत के कार उद्योग पर कोई असर पड़ेगा। 'हम अपनी कार की बाड़ी आदि में सुधार कर रहे हैं।'

लेकिन अलायड मोटर्स प्रा. लि. के, जो एंबेसडर कार के विक्रेता हैं, प्रबंध निदेशक ओ.एन. तलवार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि 'फर्क जरूर पड़ेगा

और मौजूदा कारों में सुधार लाना होगा। विदेशी कारों के मुकाबले टिकने के लिए बहुत सुधार की जरूरत है।' मूल्यवृद्धि का कारण उन्होंने भी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को बताया। श्री तलवार ने यह स्वीकार किया कि 'इस वर्ष एंबेसडर कार की विक्री में भी भारी कमी आयी है जिस का कारण 'टाइट मनी' पोजीशन है, क्योंकि 90 प्रतिशत एंबेसडर कारों की खरीद कार्यालय स्तर पर होती है।' श्री तलवार ने इस बात से इनकार किया कि नयी कारों की गुणवत्ता में कोई कमी आयी है, लेकिन एक अन्य ऑटोमोबाइल व्यापारी ने अनाम रहते हुए यह बात कही कि स्थिति स्पष्ट की कि 'जब पूर्णतः से कम होती है तो माल की 'क्वालिटी' गिरावट आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ग्राहक उपलब्ध माल को ही खरीदने के लिए विवश होता है। उस के सामने विकल्प नहीं होता।'

इस बात की पुष्टि एक ऑटो गैरेज के फोरमैन अली मंजर ने भी की। उनका कहना है, 'नयी और पुरानी कारों में जमीन आसमान का अंतर है—मशीनरी में नयी और 'बाँडी' में इस्तेमाल होने वाली चीजों में भी नयी कार की चादर इतनी कम होती है कि घूँसा मारो तो पिचक जाये। पुरानी कारों की चादर अब भी नयी कारों की कहीं अधिक मजबूत है। पुरानी कारों का कार्बोरेटर भी नयी के मुकाबले बुरा अच्छा था। कीमतें अलबत्ता बढ़ रही हैं।'

जाहिर है कि कोई अपने माल को बुरा बताने के लिए तैयार नहीं है। बेचना जो है। लेकिन असलियत जगह पर है—कीमतें लगातार बढ़ी और गुणवत्ता में कमी आयी है।

—म.द. गंगोत्री



प्रोमियर आटोमोबाइल अपनी 'प्रोमियर पदमिनी' को 71 हजार रुपये में तथा हिंदुस्तान मोटर्स अपनी 'एंबेसडर' कार को 74 हजार रुपये में बेच रही है। उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऐंड प्राइस) के अनुमान के अनुसार निर्माता प्रत्येक कार पर पाँच हजार से सात हजार रुपये का लाभ कमा रहे हैं।

'जनता कार': अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंपनियाँ अपनी कारों के नये मॉडलों को 1984 में बाजार में भेजेंगी तथा उनका मूल्य एक लाख रुपये प्रति कार से अधिक होगा। वास्तव में चार पहियों पर सैर करने का यह राजसी मूल्य है। इस की प्रतिस्पर्धा के लिए मारुति का मूल्य 59 हजार रुपये से अधिक होना होगा तथा यह कार 1983 के अंत तक बाजार में बिक्री के लिए आ जायेगी। शायद मूल्य इस से भी कम रखा जाये क्योंकि सरकार ने जनता को 'जनता कार' उपलब्ध कराने का वायदा किया है।

इसीलिए मारुति के लिए मैदान साफ है। मारुति औसतन एक लिटर पेट्रोल में 22

किलोमीटर दौड़ेगी जबकि प्रोमियर और एंबेसडर अधिक से अधिक एक लिटर पेट्रोल में दस किलोमीटर ही चल पाती है। साथ में मारुति में खरीदारी का सामान रखने के लिए काफी स्थान भी उपलब्ध होगा।

कार उत्पादन के क्षेत्र में मारुति के प्रवेश से ये दोनों निर्माता चेत रहे हैं। अब तो दोनों ही निर्माता ग्राहकों की बदलती माँगों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो उठे हैं तथा जल्दी से जल्दी तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव सरकार के पास भेज रहे हैं।

आश्चर्य होता है ये दोनों ही निर्माता उत्पादन लागत में वृद्धि के नाम पर कारों के मूल्यों में हर साल लगातार वृद्धि करते जा रहे थे। फिर भी उनके खातों में घाटा हो घाटा था। लेकिन आज स्थिति पलट गयी है और रातों-रात ये निर्माता लाभ दर्शाने लगे हैं।

इस प्रवृत्ति का जाहिरा कारण वे सरकारी नियम हैं जिनके अनुसार 'विदेशी सहयोग' की अनुमति पाने के लिए आंतरिक साधन उपलब्ध होना अनिवार्य है।

## मारुति के गमलों में सुजुकी की पौध

### किन शर्तों पर लगी है?

मध्य वर्ग के लिए छोटी कार उपलब्ध कराने का एक दशक पुराना स्वप्न अब साकार होना दोख रहा है। हाल ही में राष्ट्रीयकृत मारुति उद्योग लिमिटेड के निदेशकमंडल ने 'क्वालिटी' सुविद्ध जापानी कार कंपनी 'सुजुकी' के साथ दस वर्ष के वित्तीय तथा प्रौद्योगिक समझौते का अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी ने इस वर्ष तक छोटी कार बनाने की ठानी थी, लेकिन यह वर्ष तक छोटी कार एक स्वप्न ही बनी रही। पर अब मारुति कंपनी 'सुजुकी' कंपनी के सहयोग से छोटी कार का उत्पादन शुरू करेगी। (देखिए आवरण पर प्रस्तावित सुजुकी कार)।

आशा है कि यह कार 1983 के अंत तक भारतीय सड़कों पर दौड़ने लगेगी। सभी परिवारों को देखा जाये तो वास्तव में यह एक अत्यंत कार है। 800 घन सेंटीमीटर अश्व-शक्ति वाले वाहनों में यही एक कार विश्व में 22 किलोमीटर तक की दौड़ लगा सकती है। सुजुकी मोटर कंपनी की सफलता का मुद्रा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जनरल मोटर कंपनी ने भी जापानी कंपनी सुजुकी के पाँच प्रतिशत शेयर खरीद लिये

थे। जनरल मोटर कंपनी एक समय विश्व की नंबर एक मोटर कार निर्माता कंपनी थी।

सुजुकी जनरल मोटर कंपनी के इस समझौते ने संपूर्ण विश्व के मोटर कार उद्योग के समक्ष एक अच्छी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। अमेरिकी बाजार के लिए सुजुकी एक हजार घन सेंटीमीटर अश्वशक्ति के इंजन वाले वाहनों की एक नयी श्रृंखला का विकास कर रहा है। आशा है कि जनरल मोटर कंपनी इस श्रृंखला के वाहनों को 1984-85 तक बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत कर पायेगा।

आज विश्व में छोटी कार की प्रौद्योगिकी और उत्पादन में सुजुकी अग्रणी है। सुजुकी प्रति वर्ष लगभग छह लाख कार बनाती है तथा उस में से चार लाख कारें दूसरे देशों को भेजती है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि यह कहा जाये कि छोटी कार के निर्माण के लिए किया गया यह समझौता सर्वोत्तम है तो गलत न होगा। यह समझौता मारुति लि. के राष्ट्रीयकरण के दो वर्ष बाद किया

गया है, लेकिन यह भी सच है कि विश्व में सुजुकी से उत्तम कोई अन्य कार उत्पादक नहीं है।

यह कहना भी गलत होगा कि सुजुकी के जापानी प्रतियोगी 'मिस्बिशि' और 'निसान' किन्हीं अर्थों में सुजुकी से घटकर हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस सहयोग समझौते को अंतिम रूप देते समय 'सुजुकी' ने वित्तीय और प्रौद्योगिक सहायता देने की जो शर्तें रखीं उन्हीं के कारण यह मारुति-सुजुकी समझौता हो सका।

आसान शर्तें: मारुति को एक ओर छोड़ कर यदि एक गैरजानकार व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाये तो भी यह तर्कसंगत हो लगता है कि इतने बड़े सहयोग के साथ साथ मिली वित्तीय सहायता वास्तव में किसी को भी प्रलोभन में डाल सकती है। ऊपर से स्वत्व शुल्क (रॉयल्टी) की दर 2.5 प्रतिशत से भी कम रखी गयी है और पूर्ण देय राशि के रूप में यदि देखा जाये तो लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि ही 'सुजुकी' को देनी होगी। तकनीकी सहयोग के दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य में तकनीकी विकास के लिए सारी तकनीक निःशुल्क सुलभ होगी। तकनीकी सहयोग के लिए शुल्क के रूप में एक करोड़ से कुछ कम ही राशि देनी होगी।

विश्व के अन्य प्रतिस्पर्धियों से तुलना की गयी तो सुजुकी का चुनाव और आसान हो गया। विश्व के अन्य मोटरकार निर्माताओं द्वारा आठ प्रतिशत की दर से रॉयल्टी वसूली जाती है। यदि संपूर्ण देय राशि के रूप में रॉयल्टी आंकी जाये तो यूरोप की कंपनियों को 25 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये के बीच रॉयल्टी मिलती है। अन्य जापानी मोटरकार कंपनियों 15 से 19 करोड़ रुपये की राशि रॉयल्टी के रूप में माँगती है।

उद्योगमंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सुजुकी कार का वर्तमान मॉडल डेढ़ वर्ष पुराना है तथा वह अगले चार पाँच वर्ष तक



सुजुकी माइको बस



प्रचलित रहेगा. इस बीच मारुति के पास पर्याप्त समय होगा कि वह अपनी कार निर्माण तकनीक में प्रवीणता का विस्तार कर ले.

यही नहीं, वर्तमान समझौते में एक विशेष शर्त में यह भी कहा गया है कि सुजुकी अमेरिकी बाजार के लिए जिस एक हजार घन सेंटीमीटर वाले इंजन का विकास कर रहा है वह उस की प्रौद्योगिकी भी मारुति को देगा. मारुति इन इंजनों को अपने चार पहियों वाले वाहनों, माइक्रो बसों तथा पिक अप वैन में प्रयोग कर सकेगी.

वैसे दोनों कंपनियाँ अंतिम समझौते पर इस वर्ष जून में किसी समय हस्ताक्षर करेंगी. इस बीच इस समझौते पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस पर सहमति प्राप्त कर ली जायेगी, तथा विदेश निवेश बोर्ड (फॉरन इन्वेस्टमेंट बोर्ड) से आवश्यक सहमति तथा औद्योगिक लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया जायेगा.

इस समझौते के अंतर्गत मारुति दो सौ करोड़ रुपये की इस परियोजना में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी 'सुजुकी' की होगी. इस योजना के अंतर्गत मारुति यात्री कारें, माइक्रो बसें, पिकअप वैन तथा चार पहियों वाली जीपों का निर्माण करेगी.

वर्तमान अनुमानों के अनुसार मारुति में व्यावसायिक रूप से उत्पादन 1983 के अंत तक आरंभ होने की आशा है. 1984 के बारह महीनों में लगभग बीस हजार वाहनों के बनने की आशा है. योजना के अनुसार 1988 तक सभी प्रकार के निमित्त वाहनों का निर्माण एक लाख तक पहुँच जायेगा.

कंपनी आरंभ में एक चार द्वार वाली, चार सीटों वाली यात्री कार, पाँच से आठ यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाली छोटी बस तथा छह सौ किलोग्राम तक भार वहन करने वाली 'पिक अप' ट्रक का निर्माण करेगी.

**एक लिटर में 22 किलोमीटर :** मारुति लिमिटेड के अनुसार इन सभी वाहनों में तीन सिलेंडर वाले आठ सौ घन सेंटीमीटर क्षमता वाला पेट्रोल इंजन लगा होगा तथा यह यात्री कार शहर के भीतर एक लिटर पेट्रोल में 22 किलोमीटर तक जा सकेगी तथा लंबी दूरी की यात्रा में और भी कम पेट्रोल खायेगी. इस के विपरीत भारत की प्रतिष्ठित एंबेसेडर कार लंबी यात्रा में भी एक लीटर पेट्रोल में दस किलोमीटर से अधिक नहीं चल पाती.

कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार सहयोग के लिए सुजुकी का चुनाव अनेक यूरोप तथा व जापानी कंपनियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. दूसरी ओर उन के वाहन वहाँ की घरेलू जरूरतों के लिए ही उपयुक्त हैं तथा सुजुकी का प्रस्ताव भारत के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था.

मारुति को अभी यह तय करना है कि विभिन्न गाड़ियों का अनुपात क्या हो? वैसे यह अनुपात घरेलू आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करता है. आशा है कि व्यावसायिक वाहनों का निर्माण अन्य वाहनों से अधिक होगा.

यह कंपनी पाँच हजार लोगों को सीधा रोजगार देगी. इस के अतिरिक्त लगभग इस से दुगने लोग संबद्ध उद्योगों में काम करेंगे.

घरेलू मोटर कार उद्योग में पर्याप्त आधुनिकीकरण की आवश्यकता है. माँग की नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस सहयोग समझौते से घरेलू

सहायक उद्योगों को धक्का लगेगा.

इस बात का स्पष्टीकरण इस तथ्य से जाता है कि मोटर कार उद्योग में 50 से प्रतिशत कल पुर्जें सहायक उत्पादकों से बन जाते हैं तथा शेष 50 से 45 प्रतिशत उत्पादक अपने कारखानों में बनाते हैं.

किसी भी प्रकार मारुति को अपनी कार मूल्य कम रखना होगा, क्योंकि कि इस का निर्माण का कार्य 'जनता कार' के नारे पर किया जा रहा है और दूसरी ओर व्यक्तिगत वाहन की माँग को ध्यान में रखना होगा. घरेलू बाजार में कई वर्षों बाद एक नयी कार जनता उपयोग के लिए उपलब्ध होगी.

## छोटी कारें दौड़ में आगे निकल रही हैं

जमाना छोटी कारों का है. इस में जापान सब से आगे है. अक्सर पूछा जाता है कि जापानी कारें विदेशों में क्यों सफल और लोकप्रिय हैं? जापानी कार निर्माताओं का अपनी स्वामाविक विनयशीलता से युक्त उत्तर होता है: 'ईंधन की किफायत, सभी तरह की सड़कों के योग्य और पश्चिमी देशों की कारों की अपेक्षा सस्ती. कुछ अन्य लोग इस लोकप्रियता का कारण 'ओपेक, जी. एम. फोर्ड और जिम्मी कार्टर' भी मानते हैं. दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं.

1973 में अरब देशों ने तेल में तीन, चार और पाँच गुना जो बढ़ोतरी की उससे पश्चिमी देश हिल गये. खास तौर पर जापान और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों, जिन के पास तेल नहीं है, अपनी अर्थव्यवस्था पर इस का सीधा प्रहार देखने लगे. मंहंगे तेल का मतलब कार उद्योग का पहिया जाम होना था. लोग कार चलाने की आदत छोड़ने लगे तो जापान में ऐसी छोटी कारों के निर्माण पर विचार होने लगा ताकि ईंधन की किफायत हो सके. जापान की कारों का बाजार यूरोप और अमेरिका है. अमेरिकी कार निर्माता छोटी कारें नहीं बनाते. यह नहीं कि अमेरिका ने छोटी कारों के निर्माण का प्रयास नहीं किया: जी. एम. फोर्ड ने तीन बार छोटी कार बनाने की कोशिश की लेकिन आयातित जापानी कार की तुलना में वह टिक नहीं सकी. अतः वह बड़ी कारों पर ही नये प्रयोग करने लगे.

जापान में भी छोटी कारों की ही माँग है, इस की वजह संकरी सड़कें, भीड़ मड़का और तेल का आयात है. छोटी कारों के निर्माण से ईंधन में किफायत होती है बल्कि अमेरिका के साथ मुठभेड़ से भी वह बचा रह सकता है. आज भी जापान की सबसे

अधिक कारें अमेरिका में ही खपती हैं. जापानी व्यापारी दूरदर्शी हैं. जहाँ अमेरिका और यूरोप तेल संकट से होने वाले प्रभाव का इंतजार करने लगे वहाँ जापानी कार निर्माताओं ने तुरंत छोटी कार का फैसला लिया. इस में सरकार भी खासा योगदान था. सरकार ने जापान के मोटर उद्योग से साफ सुथरे इंजनों की शर्त रख दी. इस का प्रभाव पड़ा. कार निर्माताओं के स्तर पर नियंत्रण रहा. वह नियंत्रण इतना सख्त है जितना कि अमेरिका में संभव नहीं. कड़ नियंत्रण के कारण जापान ने साफ सुथरे इंजन की जो प्रणाली ईजाद की वह शायद यूरोप या अमेरिका में भी नहीं है.

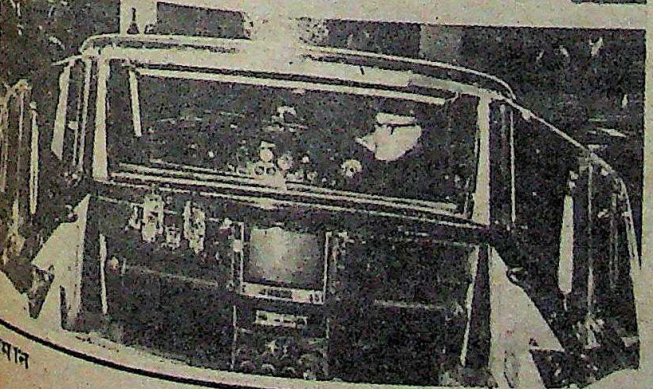
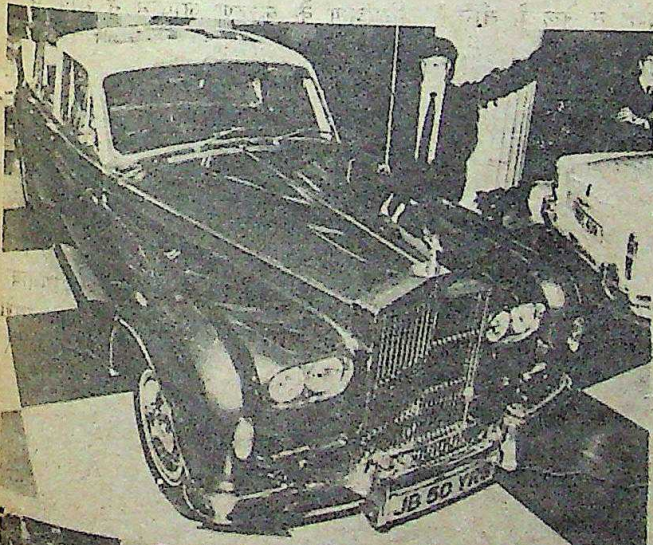
जिस तेल बचाओ अभियान को 1973 में कार्टर ने शुरू किया उस का उत्तर छोटे इंजन वाली जापानी कारें पहले ही प्रस्तुत कर चुकी थीं. अमेरिकी कार निर्माताओं ने एक बार फिर छोटी कार बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी. इस बीच विश्व को दूसरे तेल संकट से गुजरना पड़ा. डॉलर के अनुपात में जापानी येन की कीमत बढ़ गयी. इस का भी जापानियों ने लाभ उठाया और उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण प्रविधि विकसित की. इंजन में और सुधार किया और वैकल्पिक ईंधन का भी जगाह दिया. जापानी प्रविधि के समक्ष अमेरिकी विशेषज्ञ नहीं टिक सके. आज हालत यह है कि विश्व के कार निर्माता अब संयुक्त उद्यमों की बात सोचने लगे हैं, मसलन, सुजुकी और जी. एम. टोयो कोमगो और फोर्ड, मित्रसूविशी और क्रिस्लेर, होंडा और बी. एल. वॉक्सवैगन और बी. एल. वॉक्सवैगन और रेना, फिएट और वॉक्सवैगन आदि.



## महंगाई की मार : हल्की कार

तेल संकट ने विश्व के वाहन उद्योग पर भी कड़ा प्रहार किया है। कारें बनाने वाले जिन विराट संगठनों पर कई देशों की अर्थ व्यवस्था टिकी थी वे भी लड़खड़ाने लगे हैं। अमेरिका के जनरल मोटर कारपोरेशन और फोर्ड के लिए न केवल पिछला वर्ष बल्कि इस वर्ष की शुरुआत भी बड़ी निराशाजनक रही। कारों के दाम लगातार बढ़ते चले गये और खरीदार लगातार घटते गये। और इस पर तुरी यह कि जापान की हल्की और सस्ती कारें अमेरिकी बाजार पर छा गयीं। अमेरिका का तीसरी महत्वपूर्ण कार कंपनी क्रिस्लर कारपोरेशन के बाजार पर भी जापानी हावी होने लगे। क्योंकि जापान करीब करीब वेंसी ही मोटर कार अमेरिकी बाजार में एक हजार सात सौ डालर कम मूल्य पर बेच सकता है।

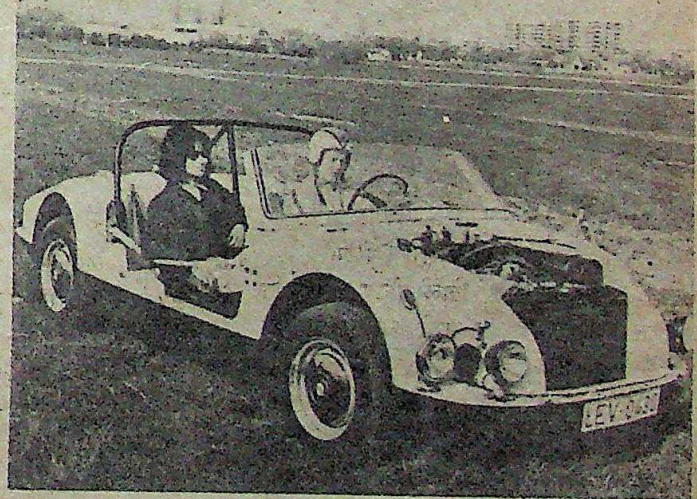
विश्वविख्यात जगुआर में तो मंदी का आतंक इतना छाया हुआ था कि उसे पूरी तरह से बाजार से खदेड़े जाने का खतरा पैदा हो गया। मगर अपने इंजनों में सुधार, पुर्जों की कार्यकुशलता तथा अन्य नयी सुविधाओं के कारण अब इस कंपनी को उम्मीद हो गयी है कि वह यूरोप और अमेरिकी बाजार में टिक जायेगी। जगुआर का नाम अब अकुशल और अविश्वसनीय मोटर कार के साथ न जुड़ जाये इस बात की चिंता कंपनी के मालिकों को हीं गयी है। ऊर्जा संकट ने इटली के विराट मोटर संस्थान को भी चक्कर में डाल दिया। बरसों तक फ़ियट काफी लोकप्रिय गाड़ी थी। अचानक इस की बिक्री कम होने लगी और हानि बढ़ने लगी। अब खानदानियत के शिकंजे से मुक्त हो कर यह कंपनी नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए मैदान में उतर आयी है। पहले दो वर्ष में भी एक नया नमूना नहीं बनता था अब हर दो मास में नये प्रकार की गाड़ी बाजार में आने लगीं।



कारों के उद्योग में कम खर्चीली और हल्की गाड़ियों के निर्माण की होड़ शुरू हो गयी है। खर्च का सबसे बड़ा मुद्दा है तेल। मेथनोल के बारे में दुनिया बहुत पहले जानती थी मगर पेट्रोल के सामने मूल्य के लिहाज से यह ईंधन टिक नहीं पाता था। मगर अब कार निर्माता यह महसूस करने लगे हैं कि मेथनोल या अलकोहल पेट्रोल के साथ मिला कर आसानी से वैकल्पिक ईंधन दे सकता है। इस सिलसिले में शुरुआत की है संघीय जर्मन गणराज्य की प्रसिद्ध मोटर कार कंपनी वोक्सवैगन ने। इस कंपनी द्वारा तैयार नये प्रकार के कारों में तीन प्रतिशत कम ऊर्जा खर्च होती है। कार्बन मोनो-ऑक्साइड की मात्रा 50 प्रतिशत कम होती है और अन्य हाइड्रो-कार्बनों का उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम ही होता है। केवल पश्चिम जर्मनी में इस से 1994 तक 14 करोड़ 20 लाख मार्क प्रतिवर्ष बचाने की उम्मीद की जाती है।

दूसरा मुद्दा है वजन। इस के लिए फाइबर ग्लास और प्लास्टिक का सहारा लिया जा रहा है। पेंथर लिमा-2300 कार का पूरा ढाँचा फाइबर ग्लास से ढला हुआ है। मगर हानोवर में अब एक ऐसी मोटर कार का निर्माण हो गया है जिस का पूरा ढाँचा विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बना हुआ है। न केवल बैठने का स्थान, बल्कि इंजन का चैसिस भी।

इस का मतलब यह नहीं कि मारी और महंगी कारें अब नहीं बन रही हैं। अभी भी ऐसी गाड़ियों के नमूने सामने आ रहे हैं जिन की कीमत एक हवाईजहाज से कम नहीं होती। हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी रोलस रायस मोटर गाड़ी दुबई के एक व्यापारी श्री करानी ने खरीदी है। जिस में हर संभव सुविधा रखी गयी है। टी.वी. सेट, दो तरफा रेडियो, टेलीफोन आदि तो हैं ही जगह जगह इस में सोना



दुनिया की सबसे महंगी कार जिसमें हर संभव सुविधा है। प्लास्टिक की कारें (ऊपर) अब हल्की कारों की दौड़ में आगे निकल रही हैं

मुड़ा हुआ है। इसी प्रकार का एक नमूना इस कंपनी ने अरब शेखों के लिए तैयार किया है जिस के शीशे इतने मजबूत हैं कि उन पर राकेट का भी असर न हो। □



पंजाबी भाषा को दिल्ली में, हिंदी के बाद, दूसरा दर्जा दिलवाने के लिए केंद्रीय पंजाबी बोर्ड ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी इस मांग को मनवाने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास के सामने धरना दिया। (दायाँ)

केंद्रीय पंजाबी बोर्ड की शिकायत है कि दिल्ली प्रशासन ने कुछ वर्ष पहले, एक विज्ञप्ति जारी कर के, स्कूलों में पंजाबी भाषा सिखाने की सुविधाएँ खत्म कर दी थीं।



कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में बेवक्त की बारिश से अब तक 10 लाख टन गेहूँ बर्बाद हो चुका है। मेहरौली (दिल्ली) के लाडो सराय इलाके में वर्षा से क्षतिग्रस्त फसल और राजधानी में अस्तव्यस्त जनजीवन (अपर) 10 मई को बिहार राज्य छात्र युवा मोर्चे के स्वयंसेवकों ने, अपनी पाँच सूत्रीय मांगों की ओर सरकार और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पटना में एक जन निकाला (बायाँ) इन मांगों में प्रमुख मांगें मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र अपने पद से इस्तीफा



खोड में एक  
नगरियों के लिए  
निराश्रितों का  
को शक्ति नगरी  
नहीं रहते. यह  
दिशा में है. नि  
एक बड़ी दुर्घ  
ति और





भारतीय उपग्रह इनसैट ने, आरंभिक निष्क्रियता के बाद, 3 मई को अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी का चित्र अपने अतिप्रभावशाली उपकरण रेडियोमीटर के माध्यम से खींचा (ऊपर बायें) यह उपकरण दृश्य और इंफ्रा रेड पट्टियों के चित्र खींचने में सक्षम है. पृथ्वी के पहले असंशोधित चित्र को हासन में तत्क्षण देखे जा सकने वाले साधनों से प्राप्त किया गया. नयी दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग में उपलब्ध सुविधाओं से संशोधित करने के बाद इस चित्र में पृथ्वी का रूप और भी स्पष्ट दिखायी पड़ेगा. इनसैट को अंतरिक्ष में इस वर्ष 10 अप्रैल को छोड़ा गया था.

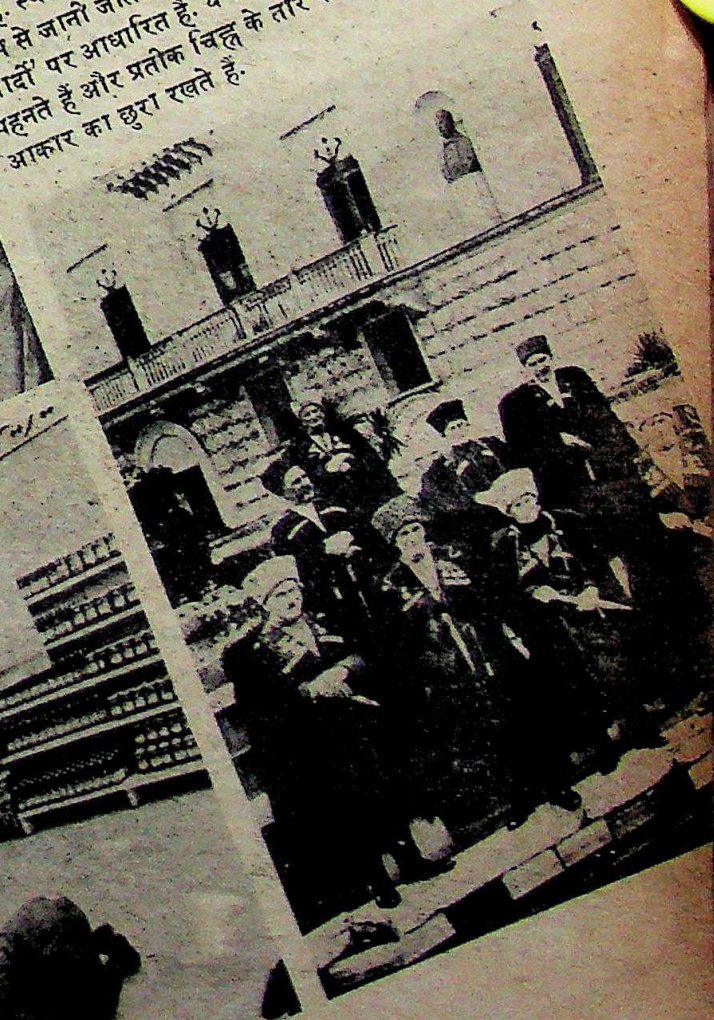
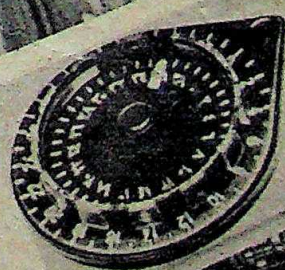
तोब्यो के पास अमेरिकी नौसैनिक अड्डे योकोसुका से अमेरिकी विमानवाहक जहाज 'मिडवे' को, युद्ध के साजसामान से दोबारा लेंस करने के लिए, जापान के ही दूसरे नौसैनिक अड्डे सासेबा में ले जाया गया. उस के बाद अपने मूल अड्डे पर लौटते हुए 'मिडवे' को जापान-अमेरिकी प्रतिरक्षा समझौते के विरोधियों का सामना करना पड़ा. 'मिडवे' के योकोसुका पहुँचने से पहले ही वहाँ लगभग 10,000 विरोधी पहुँच चुके थे. उन का एक नेता, माइक्रोफोन से भाषण देते हुए, आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ाता रहा. (बीच में बायें)

बुढ़ापा कोई बाधा नहीं—इस बात को चरितार्थ किया है इन बूढ़ों ने, (नीचे) जिन में हरेक 100 वर्ष से अधिक उम्र का है. स्थानीय लोकसंगीत के इन गायकों की टोली 'नार्ता' नाम से जानी जाती है. नार्ता अबलज लोगों के प्राचीन नाम 'नार्दों' पर आधारित है. वे अपने क्षेत्र की परंपरागत वेशभूषा पहनते हैं और प्रतीक चिह्न के तौर पर हाथ में एक विशेष आकार का छुरा रखते हैं.

भारत में  
व टन गेहूँ  
) के लाडो  
कसल और  
(ऊपर).  
छात्र युवा  
सूत्रीय मॉडल  
सयों का ध्यान  
ना में एक जुड़  
में प्रमुख मॉडल  
अपने पद से इतर



खोडन में एक घड़ी बनाने वाली संस्था ने उन  
मनमानों के लिए एक विशाल कुतुबनुमा (दिशा  
निर्देशक घंटा) का निर्माण किया है जो इस्लाम  
की पवित्र नगरी मक्का की दिशा के बारे में आश्वस्त  
नहीं रहते. यह घंटा बता देता है कि मक्का किस  
दिशा में है. त्रिपोली (लीबिया) की परचून की  
एक बड़ी दुकान में पैगंबर की इबादत में झुका हुआ  
पिर और कुतुबनुमा. (दायें).





## हजार बिजलीघरों का आंदोलन

**12** अक्टूबर 1977 को चमोली जिले के एक छोटे से गांव टंगसा पलसारी में कुछ लोगों की एक अमृतपूर्व बैठक हुई। अमृतपूर्व इस मायने में कि एक ऐसे सत्याग्रह का जन्म होने वाला था जिस की कल्पना कुछ दिन पहले तक देश में किसी ने नहीं की थी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के पश्चात पहली बार लोगों ने जीवन के लिए महत्वपूर्ण किसी काम को स्वयं करने के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आग्रह किया था। यह था बिजली सत्याग्रह। क्यों न नागरिक अपनी खपत के लिए स्वयं बिजली बनायें? खास कर जबकि सरकार महत्वपूर्ण कामों, रोजी रोटी के लिए जहरी घरेलू उद्योग के लिए सामान्य-जन को बिजली मुहैया नहीं करती। वह दिन यहाँ के लोगों के लिए एक उत्तेजना का दिन था जब कि पानी के इस बहाव से जेनेरेटर चल पड़ा और उस के ऊपर लगा हुआ बिजली का बल्ब जगमगा उठा।

चंडी प्रसाद भट्ट, पीतांबर तिवारी, आनंद सिंह बिष्ट और ऐसे ही कुछ समाजसेवियों की एक बैठक में यह तय हुआ कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गिरने वाले जल प्रपातों से बिना सरकारी सहायता के काम चलाऊ जनरेटरों से बिजली पैदा की जाये, जिस का उपयोग स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ दिन प्रतिदिन के काम के अतिरिक्त लघु उद्योग स्थापित करने के लिए करें। आज तक सरकारी कानून के अनुसार बड़े बड़े कारखाने ही अपनी बिजली स्वयं पैदा कर सकते थे, और वह भी डीजल जेनरेटरों से। किसी किसी कारखाने या संयंत्र में ताप बिजली उत्पादन का भी काम चल रहा है, मगर न तो औद्योगिक संस्थानों ने और न ही सरकार ने यह कल्पना की थी कि कोई पनबिजली का संयंत्र भी निजी प्रयासों से लगा सकता है। कुछ ही मास में किलोस्कर के एक पुराने जनरेटर को संशोधित कर के टंगसा में स्थापित किया गया। एक छोटी सी नहर खोद दी गयी जिस से 80 फुट के गिराव की शक्ति से इस जनरेटर को चालू करने का प्रयास किया गया।

गोपेश्वर से 10 किलोमीटर के दायरे में टंगसा और दोगड़ी काण्डई के 14 गाँवों के लोग लगातार इस बात की माँग करते रहे हैं कि उन्हें छोटे छोटे उद्योग चलाने के लिए बिजली उपलब्ध करायी जाये। कुछ ही दूरी पर राज्य सरकार ने 15 वर्ष पहले 600 किलो-वाट का एक बिजलीघर बनाया था। जिस से इस क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। दूर दराज के कस्बाई क्षेत्रों में इस बिजली का उपयोग घरेलू प्रकाश के लिए किया जाता

था। काफी कोशिश के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं मिल पायी। स्वामाविक था कि सरकार के विरुद्ध एक विरोध भावना ग्रामीणों में जागृत हो गयी। एक आंदोलन ने जन्म लिया। मगर इस आंदोलन की दिशा रचनात्मक नहीं थी। कुछ लोगों ने यह सुझाव भी दिया कि बिजली घर के लिए पानी पहुँचाने वाली नहर को बीच में काट दिया जाये, न जायेगा पानी और न पैदा होगी बिजली। यदि हमें बिजली नहीं मिल रही तो किसी को नहीं मिलेगी। मगर दशोली ग्राम स्वराज्य संघ और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया और आंदोलन को एक ठोस रचनात्मक रूप प्रदान किया गया। सरकारी बिजली घर बच गया। मगर उस के समानांतर स्थानीय प्रयासों से एक गैर सरकारी बिजली घर का जन्म हुआ। टंगसा के बाद कुछ किलोमीटर दूर दोगड़ी काण्डई में



आनंदसिंह बिष्ट

की प्रक्रिया शुरू की। आठ सौ फुट की लंबी नहर को चट्टान काट कर बनाया गया और 220 फुट लम्बे पाइप द्वारा 150 फुट से पानी गिरा कर टरबाइन द्वारा विद्युत प्रवाह प्रवाहित किया गया। इस अमृतपूर्व कार्यक्रम में शिक्षित अशिक्षित सभी युवकों ने बिना किसी पारिश्रमिक के काम किया। चट्टानें काटीं, पानी को दिशा दी, मोटर चालू की, खंभों पर तारें खींची और विद्युत उत्पादन का एक नया इतिहास चालू कर दिया। टंगसा और दोगड़ी काण्डई दोनों स्थानों पर यह काम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया। इस लिए बिजली का उपयोग छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है।

टंगसा सेवा समिति के संचालक पीतांबर तिवारी के अनुसार 'मैं कोई इंजीनियर या अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ मगर मुझे विश्वास था कि स्थानीय नौजवानों की सहायता से हम इस सत्याग्रह में सफल हो जायेंगे क्योंकि मैं इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना

चाहता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर से गिरने वाले जल प्रपातों का उपयोग स्थानीय लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए तभी किया जा सकता है जब कि उस का यांत्रिक और विद्युत दोनों प्रकारों से प्रयोग किया जा सके। वर्षों से जगह जगह इस की यांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल पनचक्कियों के रूप में किया जाता रहा है। मगर कोई कारण नहीं था कि बहुत छोटे पैमाने पर इन प्रपातों से हम बिजली घर न बना पायें। इस समय टंगसा के जल प्रपात से न केवल संस्था के कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध होती है बल्कि इस से एक लकड़ी चिराई मशीन भी चल रही है। चिराई मशीन से नीचे पानी की शक्ति से एक पनचक्की भी चालू कर दी गयी। जाखेश्वर शिक्षण संस्थान ने सरसों चिराई मशीन चालू की है। इस क्षेत्र में सरसों उत्पादन केवल इस लिए कम हुआ था कि तेल निकालने के यंत्र बहुत दूर स्थानों में थे। महँगाई के कारण ग्रामीणों ने सरसों का तेल खरीदना बंद कर दिया था। इस स्थानीय विद्युत घर के कारण अब वे सरसों बोना शुरू किया है।

टंगसा के 80 फुट के गिराव से 10 किलोवाट बिजली बहुत आसानी से निकाली जा सकती है जबकि जाखेश्वर शिक्षण संस्थान गिराव की ऊँचाई 150 फुट है, जिस से 100 से भी अधिक ऐसे जलप्रपात हैं जिनसे पनबिजली निकाली जा सकती है। इस प्रकार पनबिजली के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से बहुत कम व्यय आता है। वैकल्पिक ऊर्जा के इस जमाने में लघु बिजलीघरों की शुरुआत का निर्माण देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जाखेश्वर शिक्षण संस्थान के संचालक आनंद सिंह बिष्ट के शब्दों में 'भारी भरकम खर्चीली योजनाओं की बजाय चोंच ने अब तक उपेक्षित इस सरल व्यावहारिक योजना का रास्ता दो छोटी संस्थाओं ने खोला है। यह प्रयोग न केवल शक्ति के ग्रामीण उपयोग का उदाहरण बल्कि ग्रामीण इच्छा शक्ति का भी प्रमाण है। औद्योगीकरण के लिए बिजली जलाने से बिजली का उत्पादन कोयला जलाने से होता है और अब परमाणु विखंडन से भी



# 475 दिन का युग

संवाददाताओं से खचाखच भरे अकबर होटल (दिल्ली) के सभाकक्ष में बात शुरू करते हुए कैप्टन कोहली ने कहा, 'यह मोड़ देख कर मुझे डर लग रहा है। पिछले 475 दिनों में हम चारों को बहुत कम अवसरों पर कुछ गिने चुने लोगों को ही देखने का मौका मिला था.'

28 वर्षीय कैप्टन एच. सी. कोहली, उस ट्रांस हिमालयन अभियान, दल के नेता थे जिस ने अरुणाचल प्रदेश के जेलिंग से लेकर काराकोरम दर्रे के बीच की लगभग आठ हजार किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा 475 दिनों में पूरी कर के विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। यात्रा में उन के साथ थे कैप्टन एच. चौहान (30) नायक एन. डी. शेरपा (32) और नायक सूबेदार नरबहादुर गुरुंग (35)। दुर्गम, बीहड़, पहाड़ी रास्ता, बर्फ से ढकी चोटियाँ रास्ते में चुनौती देते हुए घने जंगल, अरुणाचल की बदन को झुलस देने वाली गर्मी और लड़ाख का शून्य से 31 डिग्री नीचे का जमा देने वाला तापमान। इस साहसिक यात्रा में 8 जोड़े जूते फट गये। सभी का भार 20 प्रतिशत कम हो गया। साल भर के इस चुनौती भरे अभियान में शरीर तप और ठिठुर कर पहाड़ी लाली में बदल गया था। बाल बढ़ गये थे। पूरा व्यक्तित्व बेतरतीबी और उलझाव का एक प्रतीक बन गया था। लेकिन सभी के चेहरे पर विजय का एक ऐसा संतोष भाव था, जो चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद ही आ पाता है।

परिचय कराते हुए आर्मी एडवेंचर फाउंडेशन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल ए. एम. सेठाने कहा, 'यह हमारा पहला अभियान था। अभी आरंभ है लेकिन इस से यह भी स्पष्ट है कि सागर, धरती और आकाश में ऐसी यात्राओं के लिए बहुत संभावनाएँ हैं। अल्पाइन शैली के इस अभियान में सारे साज सामान का बोझ पीठ पर था। सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था एक खूखरी के अलावा। इस टीम ने अपनी लंबी यात्रा के दौरान अरुणाचल और लड़ाख के बीच की अनजानी, अनछुई जगहों से संबद्ध अनेक सूचनाएँ और जानकारीयाँ प्राप्त की हैं जो पुस्तक रूप में शीघ्र ही सामने आयेगी।

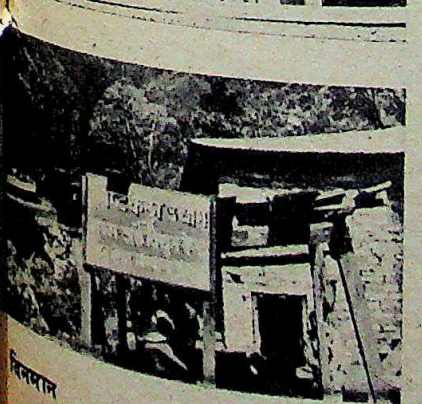
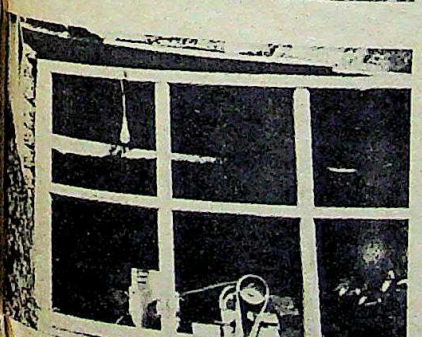
पूरे अभियान में टीम ने 48 बड़े दर्रे और 24 गैलेशियर पार किये। सिक्किम में वे 21 हजार 4 सौ फुट ऊँची कैंपु डोम चोटी पर भी चढ़े जहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ा था। एवरेस्ट और मकालू के बीच की यात्रा सब से कठिन थी। वहाँ 18 हजार फुट की ऊँचाई पर 18 दिनों तक रहते हुए उन्हें तीन बड़े दर्रे से

अभी भी पानी के प्रवाह से विजली का उत्पादन सब से सस्ता और सब से उपयोगी है, क्योंकि इस में प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल होता है और इस से प्रदूषण नहीं होता। मैदानी इलाकों में विजली पहुँचाने के लिए अपेक्षाकृत बड़े बिजलीघरों को जरूरत रहती है। बड़े पन-बिजलीघरों के लिए काफी ऊँचाई से काफी बड़ी मात्रा में पानी का गिराव जरूरी है। इसी लिए बहुउद्देश्यीय योजनाओं के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह नदियों पर बांध बनाये जाते हैं, जिनका पानी सिंचाई के भी काम आता है और बिजली पैदा करने के भी। मगर प्रायः यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में बिजली पैदा होती है उन क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में इसका उपयोग नगण्य है। और 'चिराग तले अंधेरे' के कारण औद्योगीकरण और आर्थिक लाभ भी स्थानीय लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। इस के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष कर हिमालय की विस्तृत तराइयों में विशाल बांध बनाने से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का भारी खतरा पैदा होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादित बिजली काफी महँगी भी होती है और काफी समय के बाद उपयोग में लायी जा सकती है। इस के विपरीत कश्मीर से लेकर नगालैंड तक हिमालय की तराइयों में हजारों जलप्रपातों पर छोटे छोटे बिजलीघर स्थापित किये जा सकते हैं, जिन से बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय तौर पर बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। बिजली उत्पादन के विकेंद्रीकरण के आंदोलनों की शुरुआत देश में हो गयी है। इस का अंत कहाँ होता है यह देखना बाकी है क्योंकि अभी तक हमारे देश में बिजली पैदा करने पर कानूनी रूप से भले ही कोई प्रतिबंध न हो परंतु उस के विक्रय पर प्रतिबंध है। इस लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएँ स्वयं बिजली का उत्पादन कर भी लेती हैं, इस बिजली का उपयोग केवल अपनी संस्थाओं के लिए कर पाती हैं। इस सिलसिले में एक बड़े सर्वेक्षण की आवश्यकता है जो इस बात का अनुमान दे सके कि छोटे बिजली घरों की कितनी संभावनाएँ हमारे देश में हैं और पिछड़े इलाकों के विद्युतीकरण में उनका कितना योगदान हो सकता है। हिमालय क्षेत्रों में विद्युत क्रांति की शुरुआत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान तथा तकनीकी विभाग को रुचि लेनी चाहिए अन्यथा यह रचनात्मक आंदोलन एक सार्थक अखिल भारतीय कार्यक्रम का रूप नहीं ले पायेगा। सरकारी पहल नहीं हुई तो इस बात का खतरा है कि निजी उद्योगपति शुद्ध अपने लाभ के लिए उन गतिज ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जा करें जो सामाजिक लाभ के लिए विद्युत ऊर्जा में बदले जा सकते हैं। □



जाखेवर में तार खींचते हुए युवक

मोटे क्रमशः पानी गिरने वाली पाइप, बिजली का जनरेटर और बल्ब, काष्ठ कला उद्योग









प्रदेश

बिहार

## अपने ही घर पर धरना

घटनास्थल से अरुण रंजन की विशेष रपट. छाया : राजीव

राँची शहर के इंद्रपुरी मुहल्ले के उस दोतल्ले मकान पर हर गुजरने वाले की तरस, उत्सुकता, आक्रोश मिश्रित नजर अवश्य पड़ती है. मकान की दीवार पर मोटे अक्षरों में ये नारे लिखे हैं :

‘दहेज के लोभी घर से फरार

बहु माँग रही इंसाफ.’

‘यशोदा ताड़कों (शायद सास) बहु कोपमाजन का शिकार.’

इन नारों के नीचे स्कूटर का चित्र बना है. बरामदे पर एक चटाई पर दुवली साँवली एक लड़की बैठी है. यह मंजू सहाय है. इस घर की बहु. मंजू के अगल बगल दो स्त्री बिपाही हैं. बरामदे का एक दरवाजा भीतर खुला है. वहाँ से कुछ जोड़ी उत्सुक आँखें आंगतुक को झाँकती हैं. यह किरायेदार का परिवार है. बहु बाहर है, किरायेदार अंदर, मकान मालिक फरार. कोई गंभीर बात है. मंजू धीमे धीमे बताती है—24 अप्रैल 1980 को उसकी शादी दस हजार नगद, सोना, फर्नीचर दे कर इस घर के स्वामी के पुत्र अमयशंकर सहाय, जो ग्रामीण अमि-युवक संगठन में लेखा लिपिक है, से हुई. दो सप्ताह बाद मंजू को बाप से एक स्कूटर दिलाने को कहा गया. मंजू के पिता सरजूप्रसाद सिन्हा ‘टेलको’, जमशेदपुर में चार्जमैन हैं. उन्होंने स्कूटर, जो कालाबाजार में दस हजार रुपये से ऊपर मिलता है, देने में मंजूबूरी प्रगट की.

तब ससुराल में सास के नेतृत्व में ससुर, देवर आदि ने लड़की के स्नातक प्रमाणपत्र के जाली होने एवं उम्र में लड़के से ज्यादा होने का शङ्का छोड़ा. मंजू को पिपा की जेल से पिता के घर जाना पड़ गया. वह दो साल में मात्र चार माह पति के घर रह सकी. उसे घर प्रवेश निषिद्ध होने की स्थिति में चचेरे ससुर के राँची स्थित मकान में तीन महीने गुजरने पड़े. इन के ससुर तथा चचेरे ससुर में इतना मनमुटाव बढ़ा कि आपस में लड़कें लड़कर हुई. चचेरे ससुर के लड़कों ने थाने में मामला किया. फलस्वरूप ससुर-पति दोनों दहेज के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई बस गत 22 अप्रैल को मंजू ससुराल लौटी तो घर वालों पर ताला मार कर ‘फरार’ हो गये.

जाते समय मंजू को कहा कि गुंडा ले कर आयी हो. तब से मंजू ससुराल के बरामदे पर धरना दे रही है. ससुराल में रहने का हक पाने के लिए.

ससुराल वाले रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हैं. उपायुक्त को उन पर कार्रवाई करने को कहा गया तो उत्तर मिला—‘सामाजिक दबाव डालिए.’ अप्रैल से दाखिल तलाकनामा विचाराधीन है, दहेज निरोध कोषांग में केस भी है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे



मंजू सहाय : घर वापसी

गये पत्रों का कोई उत्तर नहीं मिला है.

धीरे धीरे अगल बगल की औरतें सहानु-भूति में अकेली लड़की के पास आने लगीं. फिर युवक जुटे. अब समां एक लघु आंदोलन का है. मई के प्रथम सप्ताह में ‘जागरण’ नामक संस्था ने सामने के मैदान में आम समा की. पति के रिश्तेदार, स्त्रियाँ, युवक अच्छी संख्या में मंजू की तरफ से आये. उसी दिन हाँटिया के युवा जपा विधायक सुबोधकांत आये. वह राँची एक्सप्रेस में विचित्र साहसी लड़की की बाबत पढ़ कर उत्तेजित थे. सुबोध मध्यम वर्ग के छद्म इज्जत के नकाब को फाड़ कर शुरू हुए इस चिनगारी युद्ध को छात्र युवा संघर्ष वाहिनी एवं नारी संगठनों की मदद से आंदोलन एवं संगठन का रूप देने को कहा. उन्होंने मंजू को न जल भरने या फाँसी न लगा कर दहेज के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का साहस बँधाते हुए पूछा—‘हम क्या करें, बताइए.’ मंजू का दृढ़ जवाब था—‘यहाँ रहने के लिए एक कमरा खुलवा दें.’ (अब समझौता हो जाने पर मंजू के लिए घर खुल गया है.)



सरस्वती : वापसी की प्रतीक्षा



सुबोधकांत : अन्याय का विरोध

घटनास्थल पर मिली स्त्री सिपाही, किरायेदारनी स्त्री, दो जमादारियों, एक प्रध्या-पक रामेश्वर मिश्र ने मंजू के हक पाने के तरीके को सही बताया.

आम समा में उपा सक्सेना प्राध्यापिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने घोषणा की कि दो दिन में अगर कुछ न हुआ तो ताला तुड़वा कर मंजू को घर में प्रवेश करा दिया जायेगा.

उसी समा में मुनेश्वर साहू की विवाहिता पुत्री सरस्वती देवी ने छह वर्षीया पुत्री नीतू के साथ मंच पर आ कर आप बीती बतायी : ‘22 मई 1974 को मेरी शादी विदेश्वरी वर्मा से हुई. कोई विश्वास नहीं करेगा कि किसी विवाहिता हिंदू नारी को ससुराल में सिद्दूर तक न मिले. भूखे पेट, टाट पर सोती, तौक-रानी की तरह काम करती.’ सरस्वती को 1976 में एक बार 22 दिन तक खाना न



मिला तो उन्होंने पति के कमरे तक घिसट कर जा कर पावरोटी खानी चाही. फिर मार पड़ी. बेहोश हुई. गत छह वर्षों से वह पिता के घर में है. तब पुलिस केस भी हुआ. अदालत ने 1981 में खर्चा देने का फैसला भी किया. इस पर फिर उसे समुराल ले जा कर मारा गया. केस जारी है, तारीख पर तारीख पड़ रही है. बच्ची नीतू बड़ी हो रही है.

बेकसूर सरस्वती देवी को यह सब जुल्म कम दहेज के कारण सहना पड़ रहा है. सवाल है—उनके शेष जीवन का क्या होगा? नीतू का क्या होगा? अपराधियों का क्या होगा? समा में पचास भीगी आँखों में यह कौध थी.

इन त्रासदियों—लड़ाइयों का सामाजिक प्रत्युत्तर इतना 'फार्मल' क्यों है. विधायक सुबोधकांत के अनुसार जो संप्रति अविवाहित हैं, इस वर्ष जब सरकारी कर्मचारियों खास कर क्लर्कों का वेतन बढ़ा तो उसी अनुपात में रातोंरात दहेज के बाजार में उन का पुन-मूल्यांकन हुआ. क्लर्कों का वेतन बढ़वाने के लिए संघर्ष किया गया, किसी ने दहेज घटाने मिटाने के लिए चूँ तक न की. बिहार युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक मेहता ने प्रांत, जाति से बाहर बिना दहेज प्रेम विवाह किया है. उन्होंने बताया—जेपी के मुहल्ले कदमकुआँ में एक लड़का आई.ए.एस. बना तो तुरंत तीन लाख दहेज ले कर व्याहा गया. इस लड़के को 'खरीदा' एक नवधनाढ्य काले पैसे वाले ने. अशोक के मुताबिक, खास खतरा है: वह लड़का कहीं घूम फिर कर दहेज निरोध कोषांग का प्रभारी बन बैठा तो? □

मध्यप्रदेश

## एक और हरिजन अत्याचार

डॉ. शिव शर्मा

उज्जैन के पास एक छोटा सा गाँव है "वाड़कुम्मेद", जो 31 मार्च की घटना के बाद हरिजन अत्याचार के लिए पहचाना जाने लगा है. सवर्ण समाज के पाटीदारों का यहाँ बहुमत है तथा कुल 40 घर हरिजनों के हैं, जिन में 200 हरिजन रहते हैं. इन में से 4-5 के पास ही अपनी भूमि है, शेष पाटीदारों के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं.

31 मार्च को सवर्ण समाज के लोग हथियारबंद हो कर उन हरिजन मजदूरों को तलाश रहे थे, जो कई दिनों से खेतों पर काम करने नहीं आये थे और अधिक वेतन की माँग कर रहे थे. बंदूकधारी, फरसे, लकड़ियों से लैस सवर्ण पार्टी को गाँव में जब ये मजदूर नहीं मिले तो जंगल में इन्हें तलाश गया. अंततः गिरधारी, बलदेव, हरि, रमेश तथा एक स्त्री सजनबाई को इन्होंने पकड़ा तथा रस्सियों से हाथ बाँध कर इन की खूब पिटाई की गयी. पिटने वाले हरिजन जिन में एक बालक और एक स्त्री थी, दो परिवारों के ही लोग थे और पीटने वाले एक दर्जन सवर्ण समाज के लोग. बिजली के तारों, बंदूक के कुंदों और अन्य हथियारों से इन्हें तब तक पीटा जाता रहा



पीड़ित हरिजनों के बीच सांसद जटिया

जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गये. यही तो इन को बाँध कर हरिजन मोहल्ले में बुरा निकाला गया और कहा गया कि जो भी हरिजन काम पर नहीं आयेगे, उन का यही हाल किया जायेगा. यह सिलसिला शाम तक चलता रहा.

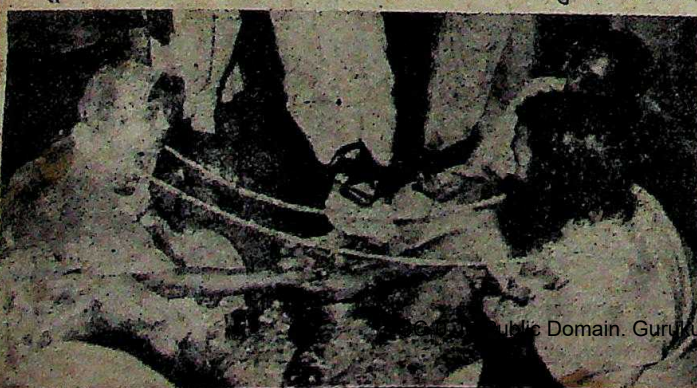
हरिजन बस्ती के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वह पुलिस थाने जा कर शिकायत कर सके. जो शिकायत करने जायेगा गोली से उड़ा देने की मुनादी पहले ही कर गयी थी. मायाराम नामक एक हरिजन साहस कर पास के थाने 'नरवल' पर शिकायत की किंतु पुलिस दरोगा ने रिपोर्ट लिखी

## आधुनिक विश्वामित्र

इंदौर से 80 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ अमरदेव बाबा रहते थे. उन्हें लगा कि योग साधना से उन्हें शायद अमरत्व न मिल पाये, तो फिर सांसारिक सुखों से ही, क्यों वंचित रहें. इस 58 वर्षीय "महात्मा" ने बाकायदा एक कन्या से शादी कर ली—चोरी छिपे नहीं, अभिभावकों और अपने भक्तों की उपस्थिति में, वैसे ही जैसे पौराणिक कथाओं के ऋषि राजकन्याओं से विवाह किया करते थे.

यह घटना इसी अप्रैल की है, जिस का सचित्र विवरण हमें ओंकारेश्वर में आयोजित बालचर शिविर में शामिल कुछ युवकों ने भेजा है.

बाबा अमरदेव का विवाह ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे बालू रेत पर 16-4-82 को सायं लगभग 6 बजे संपन्न हुआ. बाबा के



भक्तगण बंबई, कलकत्ता, मद्रास, सूरत से आये हुए थे. ये सभी प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं.

बाबा ने विवाह के पूर्व अपनी जटा और दाढ़ी काली करवाई. मंगवे वस्त्रों में विवाह वेदी पर विराजमान हुए. बाबा की गिनती ईश्वर के विद्वान संतों में होती है. वह इंदौर के प्रसिद्ध गीताभवन से भी संबन्धित रहे हैं. जो कन्या अमरदेव की वधू बनी वह सुशिक्षित (दर्शनशास्त्र एम.ए.) है और इंदौर के एक करोड़पति व्यवसायी की पुत्री है. माँ आनंदमयी से दीक्षा ले चुकी थी और बाबा अमरदेव की शिक्षा बनना चाहती थी, किंतु गुरु महाराज ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि उसे पत्नी धर्म स्वीकार करना पड़ा—पता नहीं क्यों? "लोकमान्य" के नाम पर या किसी अन्य मजबूरी के कारण.

विवाह के पूर्व महात्मा जी ने अपने भक्तों से गीताभवन में हनुमान चालीसा चढ़ाई की. रुपया चंदा यज्ञ के नाम पर एकत्र किया और उस से वधू के लिए नवरात्रि बनवाए जिस में हीरे की एक कीमती अँगूठी भी शामिल है. वैदिक रीति से पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ. 12 किलो शुद्ध धूप हवन किया गया.

विवाह के उपरांत महात्मा जी काशी रवाना हो गये. इंदौर में अधिक खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि इन महात्मा का पहले विवाह हो चुका था और जबलपुर से फरार होकर इंदौर आये थे.

इस घटना से इंदौर के प्रसिद्ध गीताभवन के साधुओं एवं विद्वानों अमरदेव के इस कृत्य पर रोष है.



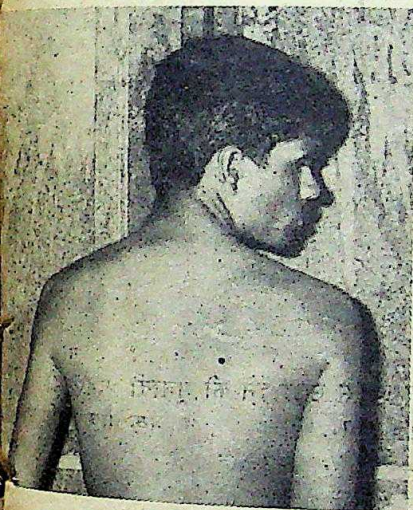


सांसद जटिया

हो गये. यही क  
मोहल्ले में क  
कि जो भी हिं  
का यही ह  
सला शाम  
यक्ति की हिं  
जा कर शिका  
रने जायेगा  
पहले ही का  
एक हरिजन  
वल' पर शिका  
रिपोर्ट लिखे

थे. ये सभी प्र

मना कर दिया. शाम सात बजे पुलिस घटना-  
स्थल पर पहुँची भी तो उस ने सवर्णों का साथ  
दिया तथा पुलिस के कुछ जवानों ने शराब  
पी कर रस्सियों से बँधे हरिजनों की पिटाई  
की शुरुआत कर दी. एक मंदिर में रात भर  
हरिजनों को बाँध कर रखा गया और  
उन की पिटाई चलती रही. पुलिस और सवर्ण  
सममिलित हो कर यह खेल तमाशा  
कर रहे. बाद में पुलिस ने बहाना बनाया कि  
हरिजन किसी चोरी में सम्मिलित थे, जब कि  
तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि वे  
चोरी में सम्मिलित थे.  
बंदी हरिजनों को एक अप्रैल की प्रातः  
को 'नखर' लाया गया तथा बाद में इन्हें  
उन का मामूली इलाज भी करवा दिया गया.  
उज्जैन के जिला अस्पताल में जब ये लोग  
पहुँचे तो वहाँ भी इन्हें भरती नहीं  
किया गया, क्योंकि पुलिस ने इन्हें भरती न  
करने को कहा था.



जुलम का शिकार एक हरिजन

इस कांड में एक युवा रमेश की आँख फूट  
गयी थी और हाथ की हड्डी भी टूट गयी थी.  
बाद में उसे भरती कर लिया गया.

उज्जैन से जिला कलेक्टर अजीत रायजादा  
वाइकुम्मेद पहुँचे और उन्होंने राज्य शासन  
की ओर से घायल परिवारों को आर्थिक  
सहायता प्रदान की. एक शांति समिति का  
गठन किया गया तथा प्रशासकीय जाँच  
समिति भी बना दी गयी.

राज्य के लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री  
दुर्गादास सूर्यवंशी जो उज्जैन जिले का विधान  
सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ने दिनमान को  
बताया कि वाइकुम्मेद के हरिजन मजदूरों  
को सवर्णों ने काम पर से हटा दिया है और  
40 परिवार मूखे मर रहे हैं. अभी भी गाँव  
में आतंक और अत्याचार का साम्राज्य छाया  
हुआ है. उन्होंने बताया कि हरिजन चूँकि  
कांग्रेस (इ) के समर्थक हैं अतः उन पर  
अत्याचार किये गये. उधर भारतीय जनता  
पार्टी के सांसद श्री जटिया भी वाइकुम्मेद  
पहुँचे. तथा उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों  
से जानकारी प्राप्त की तथा राज्य शासन को  
लिखा कि हरिजनों पर काफी अत्याचार  
हुए हैं.

गाँव के हरिजनों ने शासन से माँग  
की है कि उन्हें सवर्णों के खेतों पर पुनः मजदूरी  
दिलायी जाये, जो झोपड़े उजाड़ गये हैं वे  
बसाये जायें तथा तत्काल आर्थिक सहायता  
दिलायी जाये.

## पंजाब

## क्या राष्ट्रपति शासन लागू किया जायेगा?

राज्यव्यापी सांप्रदायिक तनावों के बाद  
इधर अब शांति है लेकिन राजनैतिक  
स्तर पर ऊहापोह बराबर बनी हुई है. राज्य में  
राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने तथा गृहमंत्री  
जैलसिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाये जाने  
की चर्चा इधर काफी तेजी से चल रही है. इसमें  
सचाई कितनी है यह बताना तो मुश्किल है  
लेकिन जैलसिंह और मुख्यमंत्री दरबारासिंह  
के घड़ों द्वारा जिस नियोजित ढंग से परस्पर  
विरोधी अफवाहें उड़ायी जा रही हैं उससे  
लोगों को यह मानने के लिए विवश होना पड़  
रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो है.

यदि राज्य सरकार प्रदेश में घमाँव तत्वों  
पर, जिन्होंने धार्मिक स्थलों की पवित्रता मंग  
कर के प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को मँडकाया

है, नियंत्रण कर पाने में विफल रहती है तो  
फिर प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के लिए पंजाब  
में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और  
कोई विकल्प नहीं होगा. इस के अतिरिक्त  
अकालियों से वार्ता के बाद श्रीमती गांधी कुछ  
समय के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू  
करने के बारे में सोच सकती हैं.

गत वर्ष पंजाब के धार्मिक उग्रवादियों  
द्वारा फैलाये गये आतंक तथा राजनैतिक  
हत्याओं के कारण कांग्रेसजन में प्रदेश के नेतृत्व  
के प्रति जो व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया था  
उस की वजह से उस समय भी राज्य में राष्ट्र-  
पति शासन लागू की बात सोची गयी थी. लेकिन  
उस समय जैलसिंह गुट ने अपने प्रतिद्वंद्वी  
दरबारासिंह घड़े को नीचा दिखाने के प्रयास में  
जो अनावश्यक उत्साह दिखाया उसने पंजाब में  
राष्ट्रपति शासन लागू करने के अभियान को  
समाप्त कर दिया. उस समय राज्य सरकार  
द्वारा कुछ उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लेने  
तथा अन्य को तितरबितर कर देने से प्रदेश में  
स्थिरता का वातावरण उत्पन्न हुआ था. उधर  
मंत्रिमंडल विस्तार से पार्टी का भीतरी असंतोष  
काफी हद तक कम हुआ.

लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों के घटनाक्रम ने  
पंजाब की स्थिति में परिवर्तन ला दिया है.  
जहाँ इका कार्यकर्ताओं में प्रदेश नेतृत्व  
के प्रति असंतोष कुछ कम हुआ वहाँ प्रदेश में  
सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी.  
1981 में भी धार्मिक उग्रवादियों द्वारा  
हत्याओं द्वारा आतंक फैलाने का प्रयास किया  
गया था. लेकिन इस वर्ष उनकी रणनीति  
लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को सामूहिक  
रूप से भड़काने की प्रतीत होती है.

पंजाब में इस समय जो कुछ भी हो रहा है  
उस के परिणाम गंभीर और दूरगामी हो सकते  
हैं तथा यहाँ जल रही सांप्रदायिकता की आग  
देश के अन्य भागों को भी प्रभावित कर  
सकती है.

राष्ट्रपति शासन लागू कर दिये जाने से  
क्या पंजाब की समस्याएँ हल हो जायेंगी?  
यह प्रश्न भी यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है.  
कुछ क्षेत्रों का कहना है कि इस कदम से यहाँ  
के लोगों में विश्वास लौटेगा और स्थिति शांत  
होने में सहायता मिलेगी. असल में पंजाब  
की समस्या प्रशासकीय कम राजनैतिक  
अधिक है.

अपनी कमजोरियों के बावजूद राज्य सरकार  
ने सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित कर पाने में  
सफलता पायी है. लेकिन इस को बनाये रखने  
के लिए उग्रवादियों पर नियंत्रण के लिए  
तुरंत एवं दीर्घकालीन प्रसावी कदम उठाये जाने  
की आवश्यकता है.

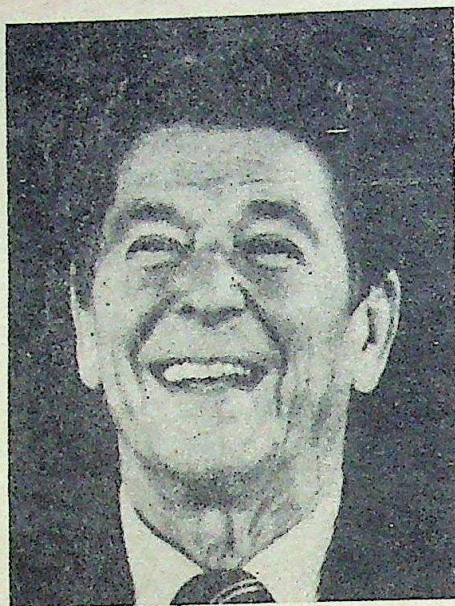


## सोवियत संघ-अमेरिका

## हथियार तो हम रखेंगे ही

अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रीगन ने अभी पिछले सप्ताह अंतरमहाद्वीपीय परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को सीमित करने के लिए सोवियत संघ के सामने जो सुझाव रखे थे उन्हें सोवियत संघ ने प्रचार की संज्ञा दे कर अस्वीकार कर दिया। सोवियत समाचार एजेंसी तास ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी यूरोप यात्रा से पहले श्री रीगन ने अपनी छवि उमारने के लिए इस प्रकार के सुझाव दिये हैं। श्री रीगन के सुझाव के अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ही अपने अपने यहाँ परमाणु प्रक्षेपास्त्र कम कर देने चाहिए और साथ ही भूमि से भूमि तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में भी कमी की जानी चाहिए। परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के लिए श्री रीगन का सुझाव है कि दोनों देश कम से कम एक तिहाई की कमी तो कर ही दें। अस्त्रों और सेनाओं में कटौती संबंधी 'साल्ट' वार्ता की पुष्टि भी अमेरिकी संसद ने अभी नहीं की है। इस वार्ता के बाद दोनों देशों में जो संधि होने वाली थी उस की संभावना भी कम हो गयी है। शायद श्री रीगन का विचार है कि इस प्रकार की संधि से सैनिक शक्ति में अमेरिका सोवियत संघ से हल्का पड़ जायेगा।

रीगन के प्रस्ताव पर सोवियत संघ की पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि उसने अमेरिका पर आक्रमण का ताना बाना बुनने का आरोप लगाया है। अभी पिछले दिनों हालाँकि राष्ट्रपति रीगन ने विदेश नीति संबंधी एक वक्तव्य में कहा था कि आशा है दो बड़ी शक्तियाँ परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को धीरे धीरे कम करने के प्रश्न पर शायद जून में बातचीत करें। लेकिन सोवियत संघ की प्रतिक्रिया से ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती कि विश्व की ये दो शक्तियाँ अपने अपने यहाँ के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्य घातक हथियारों को कम करने या सीमित करने के बारे में कोई बातचीत कर सकती हैं। उल्टे सोवियत संघ बराबर कह रहा है कि अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस से वह विश्व के समाजवादी देशों पर हावी हो सके। जहाँ तक साल्ट वार्ता-2 का संबंध है अमेरिकी विदेशमंत्री श्री हेग अपने एक बयान में कह चुके हैं कि सामरिक महत्व के अस्त्रों को सीमित करने के बारे में 1979 की अमेरिका-सोवियत वार्ता अर्थात् साल्ट-2 का अव प्रश्न ही नहीं उठता। श्री हेग ने सीनेट की विदेश-नीति संबंधी समिति में यहाँ तक कह दिया कि साल्ट वार्ता को अब दफन कर दिया गया है। श्री हेग का कहना है कि हमने यह बात सोवियत



रीगन : कटौती को तैयार

संघ को बता दी है और उसने मान भी लिया है। श्री रीगन की तरह श्री हेग ने भी कहा था कि सामरिक महत्व के अस्त्रों को सीमित करने तथा परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को कम करने के बारे में सोवियत संघ और अमेरिका की बातचीत जून में किसी भी समय हो सकती है।

रीगन प्रशासन के एक उच्च अधिकारी का कहना है कि अमेरिका और सोवियत संघ में परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को सीमित करने के बारे में अगर कोई बातचीत होती भी है तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि दोनों देश फिर अस्त्रों की होड़ में पड़ जायेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के श्री रॉबर्ट मैकफाल्ड का तो यहाँ तक कहना है कि अगर दोनों बड़ी शक्तियाँ अपने अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को कम करने के प्रथम चरण की बातचीत में सहमत हो भी जाती हैं तो भी इन प्रक्षेपास्त्रों में सोवियत संघ का पलड़ा ही भारी रहेगा।

वाशिंगटन के सूत्रों ने खबर दी है कि अमेरिका और सोवियत संघ की शिखर वार्ता इस वर्ष किसी समय हो सकती है। इन सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति रीगन अस्त्रों की होड़ समाप्त करने और विश्व में तनाव को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के अनुसार ब्रेजनेव-रीगन वार्ता के बारे में अभी कोई सहमति नहीं हुई है। अमेरिका तो वार्ता जून में न्यूयार्क में करना चाहता है लेकिन सोवियत संघ अक्टूबर में किसी तीसरे देश में इस शिखर वार्ता का इच्छुक है। फिर भी दोनों बड़े देशों के राष्ट्रपति इस प्रश्न पर शिखर वार्ता के लिए तो उत्सुक हैं ही।

सोवियत समाचार एजेंसी तास के अनुसार सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी यूरोप की ओर अधिक प्रक्षेपास्त्र न लगाने



ब्रेजनेव : वृद्धि न करने का फंसला

की घोषणा कर दी है। श्री ब्रेजनेव ने इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र छोड़ने के और ठिकानों के निर्धारण के रोक देने का आदेश भी दिया है। लेकिन सोवियत संघ ने देश के पूर्वी भाग में स्थापित इस तरह के प्रक्षेपास्त्र हटाने का अमेरिकी सुझाव एक दम अस्वीकार कर दिया है। अमेरिका पर रूस की इकतरफा घोषणा को अमेरिकी कूल प्रतिक्रिया नहीं हुई है। अमेरिकी विदेशमंत्री श्री हेग अभी भी यही कह रहे हैं अगर सोवियत संघ की इस घोषणा को अमेरिका स्वीकार कर ले तो सोवियत संघ अस्त्रों में कमी करने पर सहमत नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रीगन का कहना है कि ब्रेजनेव के भाषण से संकेत मिलता है सोवियत संघ परमाणु अस्त्रों में कमी करने के लिए संधि पर बातचीत करने की इच्छा रखता है।

परमाणु अस्त्रों की दोनों देशों की वर्तमान क्षमता : विश्वास किया जाता है कि सोवियत संघ के पास अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 2,300 है। इन में से कोई 2,300 जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं जबकि अमेरिका के पास ऐसे प्रक्षेपास्त्रों की संख्या 1700 है। इन में से अधिक पनडुब्बियों से मार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के मामले में अमेरिका आगे है। बताया जाता है कि अमेरिका के पास इन की संख्या 7,200 है जबकि सोवियत संघ के पास 6,300 है। लेकिन बताया जाता है कि सोवियत संघ प्रक्षेपास्त्र आकार में तो बड़े हैं लेकिन उनका संहारक शक्ति अमेरिका के मुकाबले कम है। राष्ट्रपति रीगन के परमाणु अस्त्रों में कमी या सीमित करने के सुझावों को लेकर दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन की संभावना



के बारे में तरह तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। उधर अमेरिकी सीनेट ने रासायनिक अस्त्र तैयार करने के श्री रीगन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

दोनों देशों की सहमति से अगर यह शिखर बार्ता होती भी है तो अमेरिकी मुझाव और उस पर सोवियत प्रतिक्रिया को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि दोनों में से कोई भी अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में साल्ट वार्ता का अगला चरण शुरू होने की संभावना भी नहीं है। □

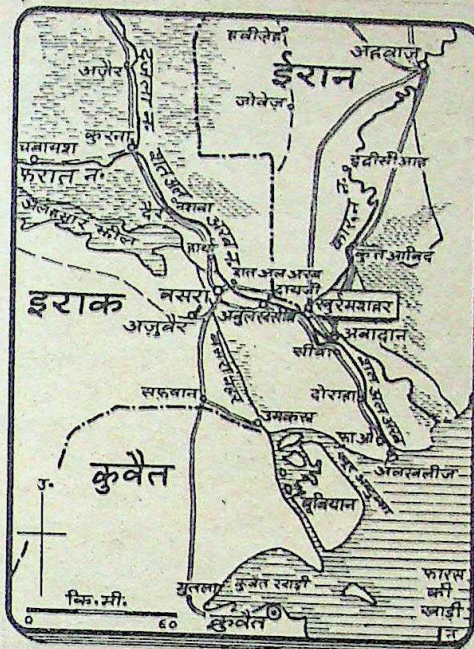
इरान-इराक

## हम लड़ाई बंद करने को तैयार हैं

इराक ने ईरान से पिछले डेढ़ वर्ष से भी ऊपर चले आ रहे युद्ध के इस वर्ष सितंबर में समाप्त हो जाने की आशा व्यक्त की है। इराकी शिक्षामंत्री और इराकी राष्ट्रपति के विशेष दूत अब्दुल कादर हमाली ने कहा है कि इराक की अपने इलाके का विस्तार करने की जरा भी इच्छा नहीं है इस लिए हम तो युद्ध रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि सीमाओं को गारंटी हो जाये तो हम ईरान के प्रदेश हट जाने को भी तैयार हैं। लेकिन ईरान, ईरान की सुरक्षा की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है उल्टे इराक में सरकार बदलने की बात कर रहा है। इराक के शिक्षामंत्री श्री अब्दुल कादर हमाली इस समय राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर निकले हुए हैं। पाकिस्तान से काठमांडू आते हुए उन्होंने एक जगह अपने ये विचार व्यक्त किये।

शात-अल अरब जलमार्ग पर प्रभुसत्ता को ले कर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था उस के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए इराकी शिक्षामंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम इस जलमार्ग पर से अपनी प्रभुसत्ता छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उनका कहना है कि युद्ध पर बातचीत के लिए युद्धविराम तो होना चाहिए। इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा कि युद्धनिरोधक देशों और संयुक्तराष्ट्र प्रधान के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकला है।

युद्ध में तेजी : ईरान-इराक युद्ध में काफी समय तक ठहराव आने के बाद अभी पिछले



सप्ताह से युद्ध के तेज होने की खबर आने लगी थी। ईरानी सैनिक कमान की ओर से अभी हाल ही में ऐलान किया गया था कि उस की सेनाओं ने खुर्रमशहर के इराकी अधिकृत बंदरगाह में पाँच मील तक प्रवेश कर लिया है। इराक का कहना था कि ईरानी सेनाओं को शहर से बाहर खदेड़ दिया गया है। खुर्रम-शहर ही ऐसी जगह है जिस पर 19 महीने से चले आ रहे ईरान युद्ध का फैसला होगा। तेहरान के एक सैनिक कमान ने यह भी दावा किया था कि ईरानी सेनाएँ खुर्रमशहर की उत्तरी और पूर्वी वस्तियों की ओर बढ़ रही हैं। और तेल प्रांत ख़ुजिस्तान को इराक के कब्जे से छुड़ाने के लिए जल्दी ही हमला होने वाला है। इस से पहले ईरानी सेनाओं के खुर्रम-शहर को पूरी तरह घेर लेने की खबरें आयी थीं। ईरान-इराक युद्ध शुरू होते ही इराकी सेनाओं ने खुर्रमशहर पर कब्जा कर लिया था जिसे वापस लेने के लिए अभी पिछले दिनों ईरानियों ने लड़ाई और भी तेज कर दी। खुर्रमशहर को ले कर दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध दावे करते रहे हैं। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इराक की ओर से बराबर कहा जा रहा है कि ईरान में इराक के किसी भी शहर पर कब्जा करने की ताकत नहीं है।

पिछले दिनों दोनों देशों के बीच लड़ाई और तेज होने से इस युद्ध के जल्दी समाप्त होने की आशा की जा रही है पर दोनों देशों के बीच शात अल अरब जल मार्ग का विवाद तय होने के अभी कोई असार नज़र नहीं आ रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक खुर्रमशहर के लिए दोनों देशों के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी। □

नामीबिया

## इंतजार और कब तक

एक अरसे से चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद नामीबिया की स्वाधीनता का प्रश्न अंधर में लटका हुआ है और दक्षिण अफ्रीका के तेवर देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह भसला शीघ्र सुलझ सकेगा। इस से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जन संगठन (स्वापो) में उत्तेजना पैदा होना स्वाभाविक ही है। वह एक लंबे अरसे से समझौते की आस लगाये बैठा है। अब और अधिक प्रतीक्षा करने का उसका धैर्य चुकता जा रहा है। पिछले महीने उत्तरी नामीबिया में उसके आठ जवानों की पुलिस द्वारा हत्या ने उसकी बेचैनी को और बढ़ाया है।

इस बीच नामीबिया समस्या के समाधान के लिए पश्चिमी 'संपर्क समूह' के देशों ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और कनाडा ने एक और फार्मूला उछाला है जिसमें असेंबली के चुनाव में एक व्यक्ति के वोट को दो बार गिनने का प्रावधान है जिस के परिणामस्वरूप आधे प्रतिनिधि तो मतों के अनुपात के आधार पर चुने जायेंगे और आधे चुनाव क्षेत्र के आधार पर। इस से पहले उन्होंने इसी से मिलते जुलते 'एक व्यक्ति, दो वोट' का प्रस्ताव किया था जिसे 'स्वापो' ने अस्वीकार कर दिया था। नया प्रस्ताव भी उसे स्वीकार नहीं है क्योंकि वह पूरी आजादी से कम और कुछ लेने को तैयार नहीं।

अग्रिम मोर्चे के अफ्रीकी देशों ने भी स्वापो के इस रुख का समर्थन किया है। इस महीने की चार तारीख को दारेसलाम में तान-जानिया, जांबिया, मोजांबीक बोत्स्वाना, जिबाब्वे और केन्या के विदेशमंत्रियों और



पीटर बोथा (ऊपर)  
और कैनेथ काउंडा  
(दाएँ) : समाधान  
की तलाश





अंगोला के उपविदेशमंत्री की एक बैठक के बाद जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में 'स्वापो' के हक को सही बताते हुए समस्या के समाधान के लिए एक नये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की उस की मांग का समर्थन किया है। इस समर्थन में 'स्वापो' को निश्चय ही बल मिलेगा।

उधर इस समस्या को ले कर जांबिया के राष्ट्रपति केनेथ काउंडा और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री पीटर वोथा के बीच भी इस महीने के शुरू में लगभग चार घंटे बातचीत हुई। 1975 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन वोस्टर से श्री काउंडा की मुलाकात के बाद दोनों देशों के नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। यद्यपि बातचीत का व्योरा नहीं बताया गया लेकिन दोनों नेता जिस आश्वस्त भाव से दक्षिण अफ्रीका-वोत्स्वाना सीमा पर स्थित वात्सस्थल से लौटे उस से यह अनुमान लगाया गया है कि अब भी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की संभावना है।

यह संभावना बनी भी रहनी चाहिए। लेकिन यदि दक्षिण अफ्रीका और उस की पीठ ठोकने वाले पश्चिमी देशों ने समस्या को उलझाये रखने की कोशिश की तो शांतिपूर्ण समाधान की यह संभावना शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति अफ्रीकी लोगों का पहले ही बहुत अधिक अहित कर चुकी है। उस के रहते काले अफ्रीका के सपने पूरे होने की आशा क्षीण ही बनी रहेगी। संभावना तो यह भी है कि 'स्वापो' शांति का रास्ता छोड़कर एक बार फिर मरते मारने पर उतारू हो जाये और शेष अफ्रीकी देश उस का साथ दें। इस प्रकार यदि नामीबिया में फिर हिंसा भड़की तो उस का उत्तरदायित्व दक्षिण अफ्रीका के साथ ही उन पश्चिमी देशों पर भी होगा जिनकी दुरंगी चाल भी समस्या के समाधान में एक बाधा बनी हुई है। □

### फाकलैंड

## आहत अहं पर प्रतिदिन नौ करोड़ रु. का खर्च

ब्रिटेन फाकलैंड की घेराबंदी पर प्रतिदिन अनुमानतः 9 करोड़ रु. खर्च कर रहा है और अब तक वह लगभग 5 अरब रु. के खर्च की लपेट में आ चुका है। परिणाम सिर्फ इतना ही निकला है कि फाकलैंड विवाद अब उस मोड़ पर पहुँच गया है, जहाँ दोनों पक्षों के बीच किसी भी समय युद्ध हो सकता है। शांतिपूर्ण समझौता सभी को रास आयेगा क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता—न ब्रिटेन, न



ब्रितानी पत्रिका 'इकोनामिस्ट' के आवरण पर प्रकाशित व्यंग्यचित्र

आर्हेतीना और न उनका कोई पक्षधर। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसका क्षेत्र व्यापक हो सकता है। उस में किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की भी संभावना है, यह नौबत न आये, ऐसा भी सभी चाहते हैं।

पिछले दस दिन से संयुक्तराष्ट्र महासचिव जेवियार पेरैज द कूलर समझौते के लिए जी जान से जो प्रयास करते रहे हैं वे अब सफल होते नहीं जान पड़ते हैं। आर्हेतीना ने अपना यह आग्रह संभवतः त्याग दिया है कि समझौता वार्ता तभी हो सकती है जब कि ब्रिटेन फाकलैंड पर आर्हेतीना की प्रभुसत्ता स्वीकार करे। ब्रिटेन शुरू से ही इस का विरोधी रहा है और हाल ही में ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट टैचर ने यह स्पष्ट कहा था कि 'हम शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं, शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं।' उधर आर्हेतीना के राष्ट्रपति लिओपोलोदो गालतियारी ने भी यह आशा व्यक्त की थी कि 'फाकलैंड विवाद का कुछ दिनों में कोई न कोई हल निकल आयेगा। लेकिन अब जब तक कोई नया प्रयास शुरू न हो शांतिपूर्ण समाधान की संभावना क्षीण ही बनी रहेगी। श्रीमती टैचर ने ब्रितानी संसद में यह कह कर आर्हेतीना पर दबाव डालने की कोशिश अलवत्ता की है कि आर्हेतीना की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है और यह कि 'हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं'।

फाकलैंड विवाद से सीधे जुड़े ब्रिटेन और आर्हेतीना के बाद सब से अधिक परेशानी अमेरिका को हुई है क्योंकि संघर्षरत दोनों ही देश उसके मित्र हैं। इसी लिए 2 अप्रैल को

पर हमला कर के उसे काफी हानि पहुँचायी समझौता न होने की स्थिति में उसने फाकलैंड द्वीपसमूह पर बलपूर्वक अधिकार करने तैयारी भी पूरी कर ली है। युद्ध के लिए तैयारी भी सन्नद्ध है। लेकिन युद्ध हुआ तो यह गैर बराबरी की लड़ाई होगी।

लेकिन क्या इसीलिए आर्हेतीना को फाकलैंड पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा छोड़ देना चाहिए? ब्रितानी साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त होता था लेकिन आज वह यूरोप के एक कोने में सिमट कर रह गया है। फाकलैंड पर आर्हेतीना के कब्जे से ब्रिटेन का आहत अहं क्या बार फिर अपने साम्राज्य के विस्तार की कोशिश करेगा?

फाकलैंड का विवाद नया नहीं है। 15 वर्ष की लंबी इंतजार के बाद आर्हेतीना से आर्हेतीना उस पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा कर रहा है। अगर ब्रिटेन की नीयत सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए है तो यह मसला कमी का सुलझ गया है। 15 वर्ष की लंबी इंतजार के बाद आर्हेतीना ने फाकलैंड द्वीपसमूह पर कब्जा किया है उसकी इस कार्रवाई से ब्रिटेन का अहं आहत हो तो इसकी जिम्मेवारी किस पर है? इस दिशा में पहले ही पहल करनी चाहिए जितनी दौड़धूप वह अब कर रहा है। दशमांश भी पहले की होती तो यह पैदा होने की नौबत ही नहीं आती। उसने छोटे मित्र पर बड़े की नीति अपनाकर मुद्दे को खड़ा रखा।

फाकलैंड पर आर्हेतीना के कब्जे से इस विवाद में वह भी ही मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है। सं. रा. महासचिव ने जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा कर अलवत्ता उसका बोझ हल्का किया।

शांति प्रयासों की बीच युद्ध का मोर्चा यदाकदा गरमाता है और 15 मई ब्रितानी सेना ने 'फाकलैंड द्वीप' पर हमला कर एक 'सीमित युद्ध' आर्हेतीना के 10 कि. मी. नष्ट कर दिये थे। उस दिन से एक दिन ब्रितानी बमबर्फी पोर्ट स्टेनले हवाई

पाकिस्तान 'चुनाव' में चा...

पाकिस्तान के संयुक्त...

अध्यक्षता में...

कुमारी बेनज...

बंदियों को रि...

और राष्ट्रपति...

स्तान को ज...

पुली देने...

शाहवाही या...

की पाँचवीं व...

में सेनाध्यक्षों...

बायदा किया...

मविध्य में देश...

नाओं से भी...

कहा कि 19...

सिद्धांतों का...

बताया जायेगा...

प्रशासन में...

अपने पिछले...

और आलोचन...

इस संबंध में इ...

सुझाव है उर्दू...

इस प्रसंग में ज...

स्थापित है...

देश की सा...

होगी, जिस से...

काल समाधा...

इस से पहले...

निक प्रणाली...

व्यक्त...

है कि देश...

मूमिका हो...

की रक्षा...

किस्तान के ए...

नरल जिया के...

की है। पा...

नैतिक पाठ...

पगारों ने क...

सेना की स्था...

मान सकते...

करना होत...

का कोई...

कार समर्थक...

जमरल जिया...

स्वीकार किय...

पान



पाकिस्तान

## ‘चुनाव तभी होंगे जब मैं चाहूँगा’

पाकिस्तान में लगभग 9 विरोधी पार्टियों के संयुक्त मोर्चे ने श्रीमती नसरत भुट्टो की अध्यक्षता में एक ओर तो जनरल ज़िया से भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष असगर खाँ और कुमारी बेनजीर भुट्टो सहित सभी राजनैतिक बंदियों को रिहा करने की माँग की है। दूसरी ओर राष्ट्रपति जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान को जल्दी ही एक नयी इस्लामी शासन प्रणाली देने का वायदा किया है। सैनिकी तानाशाही या अपने को सत्ता में स्थापित करने की पाँचवीं वर्षगांठ के अवसर पर रावलपिंडी में सेनाध्यक्षों के सामने जनरल ज़िया ने यह वायदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने निकट भविष्य में देश में आम चुनाव कराने की संभावनाओं से भी इंकार किया। बस इतना ही कहा कि 1973 के संविधान में इस्लामी सिद्धांतों का समावेश कर उसे व्यावहारिक बनाया जायेगा।

प्रशासन में सेना की स्थायी भूमिका के अपने पिछले सुझाव का देशव्यापी विरोध और आलोचना को देखते हुए जनरल ज़िया ने इस संबंध में इतना ही कहा कि अभी यह मात्र सुझाव है उर्दू दैनिक नवा ए वक्त के अनुसार इस प्रसंग में जनरल ज़िया ने देशवासियों को सूचित किया है कि उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में स्थापित एक उच्चस्तरीय कमान सेनाओं को देश की सारी घटनाओं से अवगत कराती होगी, जिस से कि देश में किसी भी संकट का तत्काल समाधान किया जा सके।

इस से पहले राष्ट्रपति ज़ियाउल हक राजनैतिक प्रणाली में सेना की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं जिन में उन्होंने कहा है कि देश में प्रशासन के कार्य में सेना की भूमिका होना आवश्यक है क्योंकि अंततः प्रशासन को ही करनी पड़ती है। जनरल ज़िया के इस विचार की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पगारों ने कहा है कि हम देश के प्रशासन की स्थायी भूमिका का सुझाव कभी नहीं कर सकते। सेना का काम केवल देश की रक्षा करना होता है और प्रशासन में उस की भूमिका कोई मतलब नहीं है। श्री पगारों ने जनरल ज़िया के मंत्रिमंडल में मंत्रिपद स्वीकार किया था।

चुनावों के बारे में और प्रशासन में सेना की भूमिका के बारे में जनरल ज़िया के सुझावों का पूरे पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। गैर कानूनी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गैर पार्टी आधार पर पाकिस्तान में चुनाव कराने के जनरल ज़िया के सुझाव का जवर्दस्त विरोध किया है और कहा है कि इस तरह के चुनावों से देश एक और बड़े संकट में पड़ जायेगा, क्योंकि पार्टी से अलग जो लोग भी चुने जायेंगे उन के अपने निहित स्वार्थ बन जायेंगे और समूचा पाकिस्तान कुछ लोगों की मुठठी में बंद होकर रह जायेगा। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 1973 के संविधान के अंतर्गत प्रांतों को दी गयी स्वायत्तता से भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए इस पार्टी का विचार है कि देश में ऐसा संविधान आये जिस में प्रांतों को अधिकाधिक स्वायत्तता हो।

चुनावों को ले कर पूरे पाकिस्तान में इस



नसरत भुट्टो : चुनाव कराने का संकल्प

समय काफी बेचैनी पायी जाती है और जनरल ज़िया चुनावों को टालने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। इस के पहले के एक वक्तव्य में उन्होंने चुनावों के संदर्भ में यह भी कहा है कि जब तक वह समझते हैं देश में स्थिरता नहीं आयी है तब तक वे चुनाव नहीं करायेंगे। इस से भी स्पष्ट है कि जनरल ज़िया वास्तव में सत्ता में बने रहना चाहते हैं और चुनावों की अपनी एक अलग ही परिभाषा बता कर अनिश्चित समय के लिए उन्हें टालते रहना चाहते हैं।

प्राप्त खबरों के अनुसार पाकिस्तान की सभी पार्टियाँ इस समय चुनावों की माँग कर रही हैं और किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को सैनिकी तानाशाही से मुक्त देखना चाहती हैं। □

पूर्व जर्मनी

## ‘शांति को हथियारबंद होना चाहिए’

बर्लिन से रामनारायण यादव

‘नैटो’ के सदस्य पश्चिमी देशों में विशेषकर पश्चिम जर्मनी में पिछले दिनों परमाणु बम विरोधी शांतिवादी आंदोलनों की बाढ़ से पूर्व जर्मन नेता बड़े खुश थे। मन ही मन लड़्डू फोड़ने लगे थे कि ‘आक्रमणवादी नैटो’ अब अपने ‘अंतर्विरोधों’ के कारण खुद ही चरमरा जायेगा। उन्हें गुमान था कि ‘हमारे यहाँ किसी की शांति के लिए आंदोलन’ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ‘हम एक समाजवादी देश हैं’ और ‘शांति तथा समाजवाद एक दूसरे के पर्याय हैं’।

दुनिया पर रंग जमाने के लिए, पिछले वर्ष दिसंबर में, उन्होंने पूर्व बर्लिन में यूरोप के जर्मन भाषी लेखकों और साहित्यकारों की एक गोष्ठी भी रचा डाली। उन्हीं दिनों पश्चिम जर्मन चांसलर हेल्मुट श्मिट पूर्व जर्मनी के नेता श्री होनेकर से बातचीत कर रहे थे। इस गोष्ठी में पहली बार कुछ ऐसे भूतपूर्व पूर्व जर्मन साहित्यकारों को भी भाग लेने दिया गया, जिन्हें राजनैतिक कारणों से स्वदेश छोड़ कर पश्चिम जर्मनी में बसना पड़ा है। लेकिन सिर मुँडते ही ओले पड़ें। पश्चिम जर्मन और भूतपूर्व पूर्व जर्मन साहित्यकारों ने ही नहीं, बहुत से वर्तमान पूर्व जर्मन साहित्यकारों ने भी अपने नेताओं के दिखावटी शांति प्रेम को खूब आड़े हाथों लिया। उन्हीं में से एक रॉल्फ शनाइडर ने कहा—‘जर्मन जनवादी गणतंत्र के अखबारों में लिखा रहता है, स्कूलों में पढ़ना पड़ता है कि शांति को हथियारबंद होना चाहिए। मेरे विचार में यह मन के शस्त्रीकरण का एक नमूना है’।

पूर्व जर्मनी के ही एक और साहित्यकार ग्युंटर दे ब्रोयेन ने अपने देशवासियों की चिंता के बारे में इस गोष्ठी में कहा—‘अगले युद्ध में मरने वाले बिना विरोध के नहीं मरना चाहते... ज.ज.ग. की जनता को भी पता है कि राकेटों के बीच रहने वाले हम एक करोड़ सत्तर लाख लोगों की मौत पूर्वनियोजित है... अखबारों को पलटने पर यह देख कर अच्छा नहीं लगता कि ज.ज.ग. की सरकार सीमापार के ईसाइयों, शांतिवादियों और अनिवार्य सैनिक सेवा ठुकराने वालों के युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का तो स्वागत करती है, पर अपनी ही सीमा के भीतर के ईसाइयों, शांतिवादियों और अनिवार्य सैनिक सेवा विरोधियों के युद्ध विरोधी



प्रदर्शनों को रोकना पड़ता है।

इस गोष्ठी में इस बात पर सरकार के चमत्चों और आलोचकों में गरमागरमी तक हो गयी कि पूर्व जर्मनी में गैरसरकारी शांति प्रदर्शन क्यों नहीं होते? इस समय पश्चिम बर्लिन में रह रहे पूर्व जर्मन लेखक ग्रेक बेकर ने कहा—“क्योंकि उन पर प्रतिबंध है, क्योंकि उन में भाग लेने वालों से बदला लिया जा सकता है—”

‘झूठ है, सरासर झूठ है,’ सरकार भक्त लेखक चिल्लाने लगे। पूर्व जर्मनी के इस सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार विजेता को चुप हो जाना पड़ा। किंतु अब भी पूर्व बर्लिन में रह रहे स्तेफान हाइम से चुप नहीं रहा गया। ‘मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ,’ पूर्व जर्मनी के इस प्रसिद्ध वयोवृद्ध लेखक ने कहा, ‘मैं स्तेफान हेमेलोन, क्रिस्टा वोल्फ, ग्युटर दे ब्रोयेन के साथ ज.ज.ग. की राजधानी के मुख्य केंद्र अलेक्सान्द्र चौक पर दोनों जर्मन राज्यों—संघीय जर्मनी और ज.ज.ग. से आणविक अस्त्रों की समाप्ति के लिए प्रदर्शन करने को तैयार हूँ और क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि वह भी शांति की समर्थक है, इसलिए मैं पहली कतार में कामरेड होनेकर जैसे सरकारी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने को तैयार हूँ। अगर यह प्रदर्शन होने दिया गया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस देश का वह मोन बहुमत हमारे साथ हो लेगा जो हमेशा अपना मुंह बंद रखता है क्योंकि उसका समझना है कि हम मला क्या कर सकते हैं।”

कहना न होगा कि यह शांतिवादी प्रदर्शन आज तक नहीं हो सका। हाँ, पूर्व बर्लिन के इस अलेक्सान्द्र चौक पर, 19 अप्रैल के दिन तीन स्पानी युवकों ने शांति और निरस्त्रीकरण के लिए जब प्रदर्शन करना चाहा, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन के बैनर को, जिस पर ‘फ्रीडेन शाफ्त, ओने वाफ्त’ (विना हथियारों के शांति स्थापना) लिखा हुआ था, ‘शांतिवादी’ पूर्व जर्मनी की पुलिस ने दो मिनट के भीतर छीन लिया।

पूर्व जर्मन के नेता कैसे विचित्र शांतिप्रेमी हैं, इसका सब से बड़ा उदाहरण यही है कि पश्चिम जर्मन शांतिवादियों के मुख्य नारे ‘शांति लाओ, हथियार हटाओ’ पर उन्होंने अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि ‘शांति को हथियारबंद होना चाहिए।’

इधर कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे स्वदेश और विदेश में अमेरिकी ही नही, सोवियत हथियारों को भी हत्या का साधन बताया जा रहा है, पूर्व जर्मन नेताओं की हड़बड़ी बढ़ रही है। पूर्व बर्लिन में नियुक्त एक पश्चिम जर्मन संवाददाता को एक दिन तब तक पूर्व बर्लिन में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जब

तक उसने अपनी कार पर लगे शांतिवादी नारे के सारे लेबल हटा नहीं दिये। यह हड़बड़ी उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी प्रतीत हुई, जब गुड फ्रायडे के दिन एक सब से प्रमुख सरकार आलोचक और शांतिवादी प्रो. रॉबर्ट हावेमान की लंबी बीमारी के बाद पूर्व बर्लिन में मृत्यु हो गयी। मृत्यु से पूर्व 72 वर्षीय हावेमान ने इच्छा प्रकट की थी कि उनकी अंत्येष्टि में पश्चिम जर्मनी में रह रहे उनके मित्रों और संबंधियों को भी बुलाया जाये। किंतु पूर्व जर्मन सरकार ने 17 अप्रैल को अंत्येष्टि के दिन न केवल सभी आमंत्रितों को प्रवेश वीसा देने से इनकार कर दिया, बल्कि बहुमत ने ऐसे लोगों को भी उस दिन अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया, जिनके पास प्रवेश वीसा था और जिन्हें हावेमान की अंत्येष्टि से कोई सरोकार नहीं था।



एरिख होनेकर : शांति उस पार

मृत्यु शय्या पर पड़े हावेमान के प्रति सरकार ने केवल इतनी ही दया दिखायी कि मृत्यु से पहले इस समय पेरिस में रह रहे उन के एक शिष्य, गीतकार वोल्फ वीयरमान और पश्चिम जर्मनी में रह रही उनकी पुत्री को उनसे मिलने दिया। पर मृत्यु के बाद वीयरमान और हावेमान की पुत्री, दोनों को ही दुबारा पूर्व बर्लिन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी। वीयरमान के माध्यम से बाहरी दुनिया को दिये गये अपने अंतिम संदेश में मार्क्सवादी हावेमान ने कहा—“हमारा शांति आंदोलन न तो प्रतिक्रांति चाहता है और न पूंजीवाद की पुनर्स्थापना। हम इस पुराने अर्थ में शांतिवादी नहीं हैं। हम युद्ध की जड़ खोदना चाहते हैं।”

युद्ध की जड़ खोदने और पश्चिम के शांति-प्रेमियों का अंधानुकरण करने के आरोप से बचने के लिए पूर्व जर्मनी के शांतिप्रेमियों ने अपना एक अलग ही नारा बनाया है। नारा है

बाइबल में लिखा एक आदर्शवाक्य: ‘तलवारों को हलों में बदल दो।’ किंतु सरकार ने तलवारों को हलों में बदलने की माँग पर भी ध्यान लगा दी है। कल कारखानों और सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया गया है कि इसका को अपनी कमीजों पर टाँक कर चलने वाले विरुद्ध तुरंत अनुशासन की कार्रवाई की जाये। कई गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। ईसाई चर्च अधिकारी आये दिन अपने समा सम्मेलनों सरकारी प्रतिशोध पर चिंता और असमर्थता पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस इस समय उन कोई दो हजार ऐसे लोगों के पीछे पड़ी हुई है, जिन्होंने पूर्व बर्लिन के पादरी एपलमान की ‘शांति लाओ हथियार हटाओ’ नाम की अपील पर हस्ताक्षर किये हैं।

जब से जनता में निरस्त्रीकरण की लहर पकड़ने लगी है, नेताओं में अस्त्रीकरण लिए उतावली और भी बढ़ चली है। बंबई के कलकत्ता की सम्मिलित आवादी विचारक जनसंख्या वाले इस छोटे से देश के लिए लाख सैनिकों की नियमित सेना शांति के अलमवरदारों को अब कम लगने लगी है। 18 वर्ष की आयु के हर युवक के लिए कम से कम 18 महीने की सैनिक सेवा पहले से अनिवार्य है। स्कूली बच्चों के लिए भी 4 वर्षों से सैनिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय है। लड़कियों के लिए भी।

नये कानून में कहा गया है कि सैनिकों की तैयारी सभी स्कूलों, कालेजों और रोज प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का अंग है। सभी शासकीय और सामाजिक कारखाने, संगठन एवं संस्थान नागरिकों के सैनिक सेवा के लिए तैयार करने को बाध्य अनिवार्य सैनिक के रूप में हर पुरुष के अभ्यासकाल 21 से बढ़ा कर 24 महीने दिया गया है।

कुछ मामलों में यह समय कम से कम महीने भी हो सकता है। आम तौर पर और आक्रमण की हालतों में 18 से 50 आयु की सभी औरतों को भी सामान्य सैनिक सेवा में शामिल किया जा सकता है। तोप और बंदूक चलानी होगी। अब तक कानून के अनुसार औरतों को संकटकाल केवल घायलों की परिचर्या, तकनीकी कामों अन्य असैनिक कामों के लिए ही सेना में शामिल किया जा सकता था।

कैसी विचित्र स्थिति है कि जनता ‘तलवारों को हलों में बदलने’ की माँग कर रही है, जबकि सरकार औरतों को भी सक्रिय सैनिक शामिल करने का कानून बना कर हलों को तलवारों में बदलने पर उतारू है।



## दुनिया भर की



हेल्मुट श्मिड्ट

### खानाबदोशों का कर्ज चुकाओ

युद्ध समाप्त होने के 37 वर्ष बाद पश्चिम जर्मनी की सरकार का ध्यान उन खानाबदोशों की ओर गया है जिन्होंने नात्सियों के हाथों बहुत यातनाएँ सही. अनुमान है कि रोमानी नाम से जानी जाने वाली इस जाति के लगभग 5 लाख लोगों को 1940 और 1945 के दौरान, हिटलर के शासन काल में, जाति विद्वेष के कारण, यातना शिविरों में फाँसी पर लटका कर, गैस द्वारा या भूख से तड़पा कर मार दिया गया था.

स्वयं को रोमानी नहीं बल्कि शूटी कहने वाली यह जाति केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही सारे यूरोप में भी सतायी जाती रही. इन्हें 'खानाबदोश, घोखेबाज और आवारा' करार दे कर इन की हमेशा प्रताड़ना की जाती रही और कई देशों में इन की घर पकड़ कर के उन्हें मार डालने का भी समयन किया गया. पश्चिम जर्मनी के प्रधानमंत्री हेल्मुट श्मिड्ट ने रोमानियों की दशा सुधारने में पहल करने की घोषणा की है और इसके लिए यथासंभव प्रयास करने का वचन दिया है.

### विरोध के बावजूद

जापान के 1500 स्वयंसेवक, परमाणु प्रसार के विरोध में, तीन महीने की शांति यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिस का अंत सर्वप्रथम परमाणु युद्ध की विमोक्षका से जुड़े वाले नगर हिरोशिमा में होना था.

परमाणु प्रसार के विश्वव्यापी विरोध के बावजूद कई देश परमाणु शस्त्र जमा करने में लगे हुए हैं. इस्राइल के पास इस समय युद्ध के लिए ऐसे 200 परमाणु उपकरण हैं जिन का इस्तेमाल दूर दूर तक किया जा सकता है. दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और इस्राइल ने दूर तक मार करने वाले शस्त्रों के निर्माण से संबद्ध एक समझौता किया है, जिस के अंतर्गत एक ऐसे प्रक्षेपक बनाने की भी योजना है जो रूस तक मार कर सकेगा. आर्जेंटीना भी परमाणु के दौड़ में शामिल होने जा रहा है, जब इस दशक के मध्य में वह परमाणु परीक्षणों के लिए सक्षम हो जायेगा और 1990 तक उस के पास परमाणु अस्त्र शस्त्र हो जायेंगे.

### जहाजों की कब्रगाह

विशेषज्ञों की राय है कि सिसली और उत्तर अफ्रीका के बीच का भूमध्यसागर 264-146 ईसा पूर्व के बीच लड़ी गयी तीन लड़ाइयों में ध्वस्त जहाजों का कब्रिस्तान है. लेकिन अभी तक इस विशाल खजाने की खोज करने के लिए इटली की सरकार धन नहीं जुटा पायी है. उस समय पश्चिम भूमध्यसागर पर प्रभुत्व का फैसला करने के लिए दो बड़ी शक्तियों में कई लड़ाइयाँ लड़ी गयीं, जिन का अंत उत्तरी अफ्रीका को रोमन साम्राज्य में मिला लेने के बाद हुआ.

ब्रितानी वैज्ञानिक श्रीमती फ्रांस्ट को सब से पहले जहाजों की कब्रगाह का पता 1969 में चला, जब उन्हें ऐसा ही एक प्राचीन जहाज सिसली के मार्साला बंदरगाह के तट से हट कर प्राप्त हुआ. विशेषज्ञों के लिए यह एक सनसनीखेज आविष्कार था, जिस से उन्हें यह पता लगाना था कि जहाज निर्माण की तकनीक उस समय कितनी प्रगति कर चुकी थी. मार्साला के जहाज के कुछ हिस्से पूर्व निर्मित उपकरणों से बने हैं और समय को देखते हुए इन की तकनीक बहुत विकसित जान पड़ती है.



### पति पत्नी का संयुक्त छाप

ब्रितानी गद्दी के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और उन की पत्नी लेडी डाएना अब उन सभी चीजों पर एक नया मुहर लगा सकेंगे जो उन दोनों की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है. इस मुहर के नमूने में दोनों के परिवारों के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है—सिंह और यूनिकॉर्न (घोड़े से मिलताजुलता जंतु) शाही और स्पेंसर (डाएना के पिता का परिवार) परिवारों के कवचों के दो ओर दिखाये गये हैं. शाही कवच में ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के चिन्हों के साथ वेल्स के चार ड्रैगन (परदार साँप) भी हैं. डाएना के कवच के बाहरी छोर पर बांज के पत्तों की माला अंकित है. इस के अलावा दो गाँठों के बीच एक पट्टी पर तीन शंख डाएना के परिवार का परिचय देने के लिए इस कवच पर मौजूद हैं. प्रिंस चार्ल्स के अनुरोध पर, सब से नीचे, शतुरमुग के तीन परों वाले उन के प्रतीक चिन्ह के साथ उन का आदर्श वाक्य 'आई सर्व' (मैं सेवा करता हूँ) भी दिया गया है.

### गुण नहीं, रूप चाहिए

ब्रिटेन में बसा हुआ औसत एशियाई युवा पढ़ाई समाप्त करने के बाद एक वर्ष तक बेरोजगार रहता है, ऐसी सूचना ब्रैडफोर्ड में किये गये एक सर्वेक्षण से मिली. 1980 में जिन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी उन में से केवल 28 प्रतिशत को रोजगार मिला, जब कि उस

वर्ष इसी उम्र के 64 प्रतिशत गोरे नौकरी पर लगे.

बेरोजगारों के बारे में आम तर्क यह दिया जाता है कि कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा बेरोजगार रहते हैं. लेकिन ब्रैडफोर्ड के शिक्षा और विज्ञान विभाग के सर्वेक्षण से पता चला कि यहाँ के अश्वेत और एशियाई विद्यार्थी श्वेतों की तुलना में ज्यादा पढ़ाई करते हैं और इन में स्कूली पढ़ाई खत्म करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या श्वेतों से कम होती है.

### तलाकी आँकड़े

कुवैत के न्यायालय से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार गत वर्ष इस देश में तलाकों की संख्या पहले से 13.5 प्रतिवर्ष बढ़ गयी थी और बीस से तीस वर्ष की आयु के कम पढ़े लिखे दंपति अपना वैवाहिक जीवन का अंत करने में सब से आगे रहे. विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी स्त्रियाँ तलाक में रुचि नहीं रखती. 33.8 प्रतिशत तलाक चाहने वाले ऐसे पुरुष थे जिन की एक से अधिक पत्नियाँ हैं. 1981 में कुल मिला कर 2304 तलाक के मुकद्दमे पेश किये गये. इन में 936 ऐसे दंपति थे जो दोनों ही कुवैतवासी हैं. कुवैती पुरुषों की विदेशी पत्नियों के 469 और विदेशी दंपतियों के 735 मामले अदालत में ले जाये गये. इसी दौरान 164 कुवैती पत्नियों का उन के विदेशी पतियों से विवाह भंग हुआ.

### एकाधिकार क्यों चाहिए?

कैनाडा के दो प्रमुख समाचारपत्रों के प्रकाशक थॉमसन न्यूज-पेपर्स और साउथाम को आदेश मिला है कि वे अदालत में पहुँच कर उन पर लगाये गये सात आरोपों का जवाब दें. इन आरोपों में सब से गंभीर आरोप है. प्रति-योषिता को खत्म करने के लिए रची गयी साजिश, गैरकानूनी, तौर पर विलय और अखबार निकालने और बेचने में एकाधिकार स्थापित करना. □



## विज्ञान

### रुकावट के लिए खेद है

रमेशचन्द्र शर्मा

अमेरिका के फोर्ड एयरोस्पेस कम्प्यूनिक्शन कारपोरेशन द्वारा भारतीय डिजाइन के आधार पर निर्मित 1159.8 किलोग्राम भारवाला उपग्रह इनसेट-1-ए शुरू से ही जिद्दी साबित हुआ। एक बार पुर्जों में खराबी और दूसरी बार मौसम की खराबी के कारण। इस तरह दो बार उड़ान स्थगित करने के बाद 8 अप्रैल के बजाय 10 अप्रैल को भारतीय समय रात के 12 बज कर 17 मिनट (अमेरिकी समय दिन के 1 बज कर 17 मिनट) पर, इसे 12 करोड़ डालर (लगभग 96 करोड़ रुपए) खर्च कर के अमेरिका के 3910-डेल्टा राकेट से उन के ही अंतरिक्ष अड्डे केप केनेवरल से इसे उड़ाया गया। कुल खर्चा तो 200 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। लगभग 600 करोड़ रुपए का बीमा अलग है। पहली किशत ही 6 करोड़ रुपए दी गयी। बीमों में भारतीय कंपनी के अतिरिक्त एक ब्रिटिश बीमा कंपनी का भी साझा है। उड़ने के 18 मिनट बाद ही घोषणा की गयी कि इनसेट अपनी कक्षा में आ गया है। लेकिन बाद में असलियत भी बतानी पड़ी। क्योंकि भारतीय केंद्र के अतिरिक्त अमेरिकी केंद्र भी तो इस की निगरानी कर रहे थे। पता यह चला कि पहली बार पाठशाला भेजे गये वच्चे की तरह 'इनसेट' अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं कर रहा। आखिर क्यों?

हुआ यह कि उपग्रह का 'सी-बैंड एंटीना' नहीं खुला। इसी कारण यह गुंगा भी हो गया और बहरा भी। यह एंटीना कोई 1.2 मीटर लंबा है और उपग्रह के पूर्वी किनारे पर लगा है। इसी को रेडियो, दूरदर्शन और दूरसंचार के पृथ्वी से भेजे गये संकेत ग्रहण कर के उन्हें कई गुना बढ़ा कर पुनः पृथ्वी की ओर प्रसारित करना था। जब 'इनसेट' बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने पहली बार बताया (भारतीय वैज्ञानिक तब तक चुप्पी साधे थे) कि उपग्रह का 'सी-बैंड एंटीना' नहीं खुल रहा, तो उन तमाम आशाओं पर तुल्यप्राप्त हो गया, जो इस प्रयोजना पर भारी खर्चों की एवज में जगायी गयी थीं। वस यों समझिए कि कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था कि 'रुकावट के लिए खेद है' की घुन छिड़ गयी।

यही नहीं, बल्कि इस एंटीना के न खुलने से 'इनसेट' को निर्धारित भूमसकालिक कक्षा में 74 डिग्री अंश पूर्व देशांतर पर दिल्ली के ठीक 35890 किलोमीटर ऊपर लाने के



उपग्रह की आंख से धरती

प्रयास भी असफल रहे। एक ओर तो वैज्ञानिक 'एंटीना' को धरती से 'खुल जा सिम-सिम' के रेडियो संकेत भेजने में लगे और दूसरी ओर उसी से अटकी प्रथम एपोजी मोटर को चालू करने में जिस का धक्का उपग्रह को सही 'सही' कक्षा में पहुँचा दे। अंत में 11 अप्रैल रविवार को रात 2 बज कर 11 मिनट पर कोई आधा घंटा तक यह 'मोटर' दागी गयी और इनसेट उचक कर माध्यमिक कक्षा में आ गया, यानी पृथ्वी से निकटतम कक्षा 11,305 किलोमीटर पर और दूरतम कक्षा 35,139 किलोमीटर पर थी। लेकिन इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमा पथ 14 घंटे में ही पूरा हो जाता था। असल में इसे बढ़ा कर 24 घंटे का करना था ताकि पृथ्वी की ओर उपग्रह की गति समान हो जाये और वह धरती में ऐसा लगे जैसे कंदील की तरह एक जगह टंगा है।

इस बारे में भी सूचनाओं की आँख मिचौनी चलती रही। अभी खबर मिलती कि पहुँचा दिया जी, सही कक्षा में पहुँचा दिया। हम तालियाँ बजाने को हाथ उठाते कि तब तक खंडन आ जाता कि अभी सही कक्षा की ओर अग्रसर है, पहुँचा नहीं। उधर 'खुल जा सिमसिम' के निवेदन भी जारी रहे। उड़ने के 41 मिनट बाद ही 'इनसेट' बंगलौर से कोई 185 किलोमीटर दूर स्थित मास्टर कंट्रोल केंद्र से टोही क्षेत्र में आ गया था। यहाँ से रेडियो संकेत भेज कर उपग्रह को ऊपरी खंड करने के आदेश दिये गये, उपग्रह की अपनी घुरी पर घूमने की गति ठीक की गयी, निकटतम कक्षा को और ऊँचा किया गया। ये सब आदेश तो उपग्रह मानता रहा, पर न तो कान खोलने को तैयार हुआ और न होठ। यानी 'सी-बैंड एंटीना' लाख मिन्नतों के बाद भी खुल कर न दिया। मंगलवार 13 अप्रैल को उपग्रह का पूर्वी भाग सूर्य की ओर मोड़ा

गया ताकि उधर लगे 'सोलर सेल' सूर्य की धूप की ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल कर उपग्रह का तापमान इतना बढ़ा है कि एंटीना खुल जाये। एंटीना तो फिर भी नहीं खुला। पर इसी बीच उपग्रह को घकिया कर 24 घंटे 20 मिनट के परिक्रमा समय में ले आया गया—यानी अभी उस कक्षा में पहुँचना चाँहा था, जहाँ ये 40 मिनट और ज्यादा ले अर्थात् भूमसकालीन कक्षा में आ जाये। इस कक्षा में बेचारा किसी तरह लड़खड़ाता हुआ भूमसकालीन कक्षा में आ जाये। ठीक 11 दिन बाद 21 अप्रैल को पहुँचा।

निर्धारित स्थान पर पहुँचने के बाद उपग्रह ने 'खुल जा सिमसिम' को प्रार्थना भी मारी और 22 अप्रैल की सुबह साढ़े दस बजे (भारतीय समय) अंततोगत्वा 'सी बैंड एंटीना' खुल गया। इस के बाद 23 अप्रैल को इस स्थित मुख्य नियंत्रण केंद्र से रंगीन दूरदर्शन कार्यक्रम उपग्रह के माध्यम से प्रसारित कर देखा गया और यह परीक्षण सफल रहा। एंटीना खुलने के बाद उपग्रह में लगे

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्यापकों को सीखने का अवसर मिलेगा। अपने विषय की विवरणी मंगाई। कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। विवरणी लिखें। इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), वाक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विवरणी मंगाइये। पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

### एजेंट चाहिए

फिल्म, साहित्य व संगीत के हिन्दी भाषी राग बहार को मँगाने हेतु न्यूजपेपर संपर्क करें। व्यवस्थापक, राग बहार, छोटा छीपीवाड़ा, चावडी बाजार, दिल्ली-110024.



## अपना राकेट कब तक ?

**भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अभी तक अपने राकेट से केवल 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह भेजने में ही सफलता मिल पायी है। इसी लिए हर बार भारतीय उपग्रह विदेशी आसरे पर अंतरिक्ष में भेजे गये हैं। आर्यभट्ट (1975), भास्कर-1 (1979) तथा भास्कर-2 (1981) रूसी अंतरिक्ष अड्डे से उन के राकेट से छोड़े गये। 'एपल' को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था की ओर से फ्रांस के अंतरिक्ष अड्डे ने भेजा। अब 'इनसेट-1' की तरह इस शृंखला के बाकी दो उपग्रह भी अमेरिकी मदद से अंतरिक्ष में स्थापित किये जायेंगे। क्या हम इस मामले में कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पायेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे अंतरिक्ष विभाग के एक प्रवक्ता का कहना है कि सन् 1990 तक यानी अभी आठ वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस के लिए दो किस्म के राकेटों पर काम चल रहा है—एक तो 'ए एस एल वी' और दूसरा 'पोलर सटेलाइट लांच व्हीकल' (पी. एस. एल. वी.)।**

इरादा यह है कि 'पी एस एल वी' की क्षमता इतनी कर दी जाये कि कम से कम 800 किलोग्राम वजन का वर संवेदी भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा सके। यह उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में घूमते हुए उस के नीचे पड़ने वाले घरेलू के सभी हिस्सों की तस्वीरें ले कर

हमारे भू-केंद्रों को भेज सकेगा। अंतरिक्ष विभाग ने इस प्रयोजना की जो रपट तैयार की है, उस के हिसाब से तो सन् 1986-87 तक ही अपने राकेट से अपना उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर लेंगे।

'एल एल वी-3' श्रेणी के राकेटों का वजन केवल 17 टन था। जब कि नये 'पी एस एल वी' राकेट का वजन 30 टन होगा। इस का घेरा 2.8 मीटर होगा और इस की ऊंचाई 12 मंजिल के मकान जितनी होगी। इस में ठोस और द्रव दोनों तरह के ईंधन इस्तेमाल किये जायेंगे। एक और किस्म के 'क्रायोजेनिक इंजन' पर भी काम चल रहा है। इस इंजन में द्रव-आक्सीजन का पहली बार इस्तेमाल होगा। अकेले इंजन निर्माण की प्रयोजना का खर्चा 50 करोड़ रुपये का होगा। अंतरिक्ष में करोड़ों से कम में कोई बात नहीं होती।

'ए एस एल वी' की किस्म के जिस राकेट पर काम चल रहा है वह 'एस एल वी-3' का ही परिवर्द्धित संस्करण कहा जा सकता है। यह 150 किलोग्राम वजन के उपग्रह को 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रक्षेपित कर सकेगा। उम्मीद की जाती है कि अगले चार साल में यह राकेट तैयार हो जायेगा। डर यही है कि जिस तरह 'रोहिणी' का नाम 'रोगिणी' पड़ गया था, वैसे ही नाम हमें अपने इन राकेटों के न रखने पड़ें।

'ईसिल' को दिया गया है। उपग्रह से सीधे कार्यक्रम ग्रहण करने लिए विशेष एंटीना वाले एक टी.वी. सेट की कीमत 15 हजार रुपये बैठती है। दो हजार सेट बनाने में 'ईसिल' राम जाने कितनी देर लगाये। इसी लिए अभी आंध्रप्रदेश, ओडिसा और महाराष्ट्र के कुल नौ जिले चुने गये हैं। अभी तो उन गांवों की भी सूची नहीं बनी है, जिन में कार्यक्रम दिखाये जाने हैं।

**सारे कदम हबड़ा तबड़ी में उठाये जायें तो कायदों को ताक पर रख कर अच्छा धंधा किया जा सकता है। टेंडर फेंडर के झंझट में कौन पड़े जी, कल तक काम हो जाना चाहिए। जहाँ तक कार्यक्रम तैयार करने का प्रश्न है, सो 'साइट' के दौरान के कार्यक्रम बने पड़े हैं, तब तक वहीं दिखाये जायेंगे। स्वयं अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों ने चिंता प्रकट की है कि बजाय शिक्षा के इस महंगी उपग्रह प्रणाली को भी बाजारू शहरी मनोरंजनों पर बरबाद किया जायेगा। यह आशंका**

बेबुनियाद नहीं है। जल्दी ही रात 9 बजे से 10-10 बजे तक सभी दूरदर्शन केंद्रों से एक ही राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित होने लगेगा।

1 जून से दिल्ली, मसूरी, बंबई, बंगलौर, और मद्रास केंद्र उपग्रह शुरू कर देंगे। बिहार, उत्तरप्रदेश और गुजरात को छठी योजना के अंत तक इंतजार करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। 'साइट' कार्यक्रम की योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी वह रपट कहीं धूल खा रही होगी, जिस में खामियां गिनायी गयी थीं। और बताया गया था कि किस नेता या उभरते नेता को कितनी देर दूरदर्शन के चौखटे में रखा गया। गलतियों से सबक सीखने की अभी क्या जल्दी पड़ी है। तब तक तालियां हो जायें कि भारतीय वैज्ञानिकों की देखरेख में अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाये गये और अमेरिकी राकेट द्वारा उड़ाये गये हमारे 'उपग्रह' ने पृथ्वी के पूरे गोल का सफलतापूर्वक चित्र लिया और पृथ्वी पर भेजा। □



# शिक्षा

## पढ़ाई का लाभ खाते पीते घरों को ही क्यों ?

ऊपर से देखने पर सामाजिक गतिशीलता की धारणा काफी भारीभरकम और जटिल लगती है लेकिन आज की दुनिया में सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न रूपों की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उस के अध्ययन के दिलचस्प नतीजे सामने आते हैं। इस स्थिति का शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का नजदीकी रिश्ता है। लेकिन यह सामाजिक गतिशीलता आखिर है क्या चीज? गतिशीलता का सीधा सादा अर्थ होता है—एक स्थान या स्थिति से चल कर या गतिशील हो कर दूसरे स्थान या स्थिति पर पहुँच जाना। मिसाल के लिए गाँवों के लोग शहरों और औद्योगिक केंद्रों में जा कर बसते हैं। इसी प्रकार भारत आदि देशों से कई लोग धनी पश्चिम की दुनिया में जा कर बस जाते हैं। यही परिवर्तन गतिशीलता है। लेकिन सामाजिक गतिशीलता की धारणा का भाव यही अर्थ नहीं होता है।

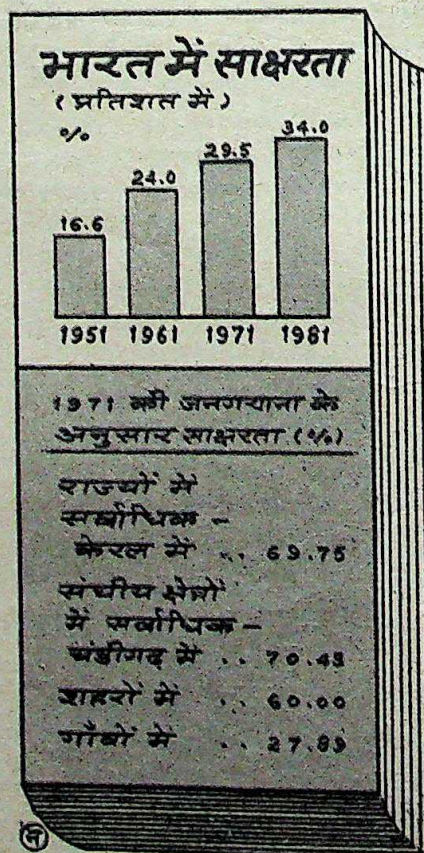
समाजशास्त्र के एक शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह की ओर व्यक्तियों की गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता के दो मुख्य रूप गिनाये हैं—प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता। पहले प्रकार के अंतर्गत उच्च वर्ग या धनी या प्रतिष्ठित वर्ग के माता पिता अपनी कन्याओं के लिए जब अपनी जाति या समान परिस्थिति समूह में योग्य घर नहीं पाते हैं तो होनहार दिखने वाले निर्धन परिवारों के लड़कों को चुन लेते हैं तथा अपनी ओर से रुपया पैसा देकर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। यानी अपनी राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर वे उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करा देते हैं। यह प्रदत्त गतिशीलता का एक स्पष्ट उदाहरण है।

दूसरी ओर संघर्ष गतिशीलता के अंतर्गत एक व्यक्ति परिश्रम और परिस्थितियों से अपनी लड़ाई के बल पर ऊँची जगह पर पहुँचने की कोशिश करता है। आज की दुनिया में व्यक्तियों के सामने सीमित अवसर, लाभ, पुरस्कार अथवा इच्छित वस्तुएँ होती हैं। उन्हें पाने के लिए वे जी तोड़ कोशिश करते हैं। जो अधिक परिश्रम, प्रयास और चतुराई से संघर्ष करता है वह अपनी इच्छित वस्तु या पद को प्राप्त कर लेता है। बुली सामाजिक व्यवस्था में (जहाँ सामाजिक वर्ग व्यवस्था और प्रजातंत्र है) इस प्रकार की गतिशीलता को अपनाने पर विशेष बल दिया जाता है।

इसी तरह से भारतीय समाज में संस्कृति-करण की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इस प्रक्रिया में एक हिंदू जाति या जनजातीय या कोई अन्य समूह एक उच्च (प्रायः द्विज) जाति की दिशा में संस्कारों, रिवाजों तथा जीवनविधि आदि को बदलने का प्रयास करते हैं।

प्रत्येक जाति या समूह या समुदाय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वृद्धि और उन्नति चाहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसके सदस्यों में अधिक से अधिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हों। ऐसी सुविधाएँ सीमित होती हैं इसलिए उस समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों को उन का लाभ नहीं मिलता। यह स्पष्ट है कि पिछले 25-30 वर्षों में भारत में सामाजिक गतिशीलता में तेजी आने से शिक्षा सुविधाएँ बढ़ी हैं। गाँवों से लोग शहरों में आ कर बसने लगे हैं। ऐसे मेहनती लोग भी सामने आये हैं जो अपने साधनों और हाँसलों से निजी शिक्षा संस्थाएँ खोलते रहे हैं।

पश्चिमी समाजों के अध्ययन से एक विद्वान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ



अधिकांश धनी व्यक्ति इसलिए धनी क्यों हैं क्योंकि उन के माता पिता के पास धन था। उन्होंने ऊँची शिक्षा पा कर अपने धनी नहीं बनाया है। भारत में भी अनेक धनी समुदाय हैं जो शिक्षा के द्वारा ही जगहों पर नहीं पहुँचते हैं।

लेकिन अक्सर मध्यम या निम्न वर्ग पिछड़े वर्ग के लिए इस तरह से ऊँची शिक्षा पर पहुँचना संभव नहीं होता। उन के शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है।

दुनिया के विकसित देशों में अक्सर यह देखा जाता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति और नागरिकता का विकास करना ही नहीं है। भविष्य के जीवन के व्यवसाय के लिए तैयार करने पर अधिक बल नहीं दिया जाता। भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में इन्हीं धनी देशों का अनुकरण कर के भारी भूल की है। देश में गरीबी, बेकारी, अनुपयुक्त रोजगार, बढ़ती जनसंख्या और गिरती हुई सामाजिक स्थिति आदि तब तक दुष्परिणाम सामने हैं। भारत जैसे देशों तथाकथित सफल जीवन के लिए व्यक्ति मूल्यों, दृष्टिकोणों आदि को सर्वोपरि देना व समुचित व्यवसायिक प्रशिक्षण निम्न या हेय समझना बुद्धिमानी का नहीं है। इधर कुछ वर्षों में भारतीय राजनेता और समाजशास्त्रियों ने इस कड़वी सच्चाई को महसूस किया है। 1971 में प्रो. सुरेश ने भारतीय शिक्षा में प्राथमिकताओं पर लिखा कि यह मुझाब दिया था कि बी.ए. के पाठ्यक्रम को पूर्णतया व्यावसायिक रूप पर रूख दिया जाना चाहिए।

हालाँकि आज देश के कोने कोने में शालाएँ व कॉलेज दिखते हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग 105 हो गई है लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को महत्वपूर्ण शिक्षा गतिशीलता प्राप्त करना मुश्किल गया है। 1970-71 में संघीय लोक आयोग द्वारा संचालित भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में मुसलमानों के दाय में से केवल एक ही व्यक्ति चुना गया। दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी संस्थान नयी दिल्ली के विद्यार्थियों में से 95 प्रतिशत विद्यार्थी तनरीय मध्यम वर्ग और उच्चवर्ग के प्रतिनिधि हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातों के छात्रों की हालत इस से साफ साफ जाती है। यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा का लाभ आमतौर पर धनवान या पीते घरों के विद्यार्थी ही जुटा पाते हैं। प्रकार शिक्षा सामाजिक वर्गभेद को बजाय और अधिक बढ़ा रही है।

—डॉ. महेंद्र नारायण



वित्त

## पूँजी की तंगी से उत्पादन नहीं बढ़ता

सरकार की ऋण देने की कठोर नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव होगा। मंदी की ओर झुकाव शुरू दिसंबर में दिखने लगा था। इसने 31 मार्च, 1982 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में उच्च औद्योगिक विकास की संभावना को निरुत्साहित ही किया है।

न केवल औद्योगिक उत्पादन में कमी आयी है, वरन् निमित्त उत्पादनों की माँग भी घटी है जिसकी वजह है कठोर ऋण नीति के परिणामस्वरूप क्रयशक्ति में कमी।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ विकास जरूरी है, ऋण में कमी के कारण उत्पादन में कमी होने से स्फीतिकारी दबाव बन सकते हैं। इस प्रकार यह एक विरोधाभास पैदा हो गया है कि सरकार तो मुद्रा स्फीति को रोकने की कोशिश में ऋण निर्धारण के दबाव को रोक रही है और फलस्वरूप मुद्रा स्फीति को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है।

एक ताजा सरकारी आकलन के अनुसार 1981-82 के 12 महीनों की अवधि में इस वर्ष औद्योगिक विकास की दर निर्धारित दस प्रतिशत के लक्ष्य से कम होगी। अब यह अनुमान किया जा रहा है कि यह नौ प्रतिशत के लगभग होगी, हालाँकि अंतिम आकलन में विकास की दर का स्तर नौ प्रतिशत से भी कम हो सकता है क्योंकि कपड़ा उद्योग में पिछले 100 दिनों से चली आ रही हड़ताल का प्रभाव तथा इससे संबद्ध अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में असाधारण प्रभाव पड़ा है।

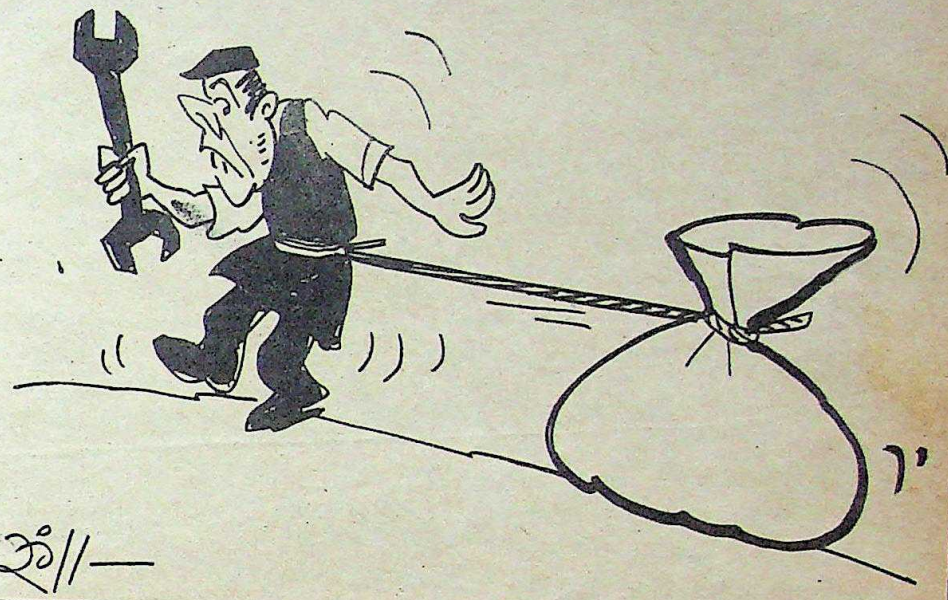
कपड़ा उद्योग के महत्व को हम इसी तथ्य से जाँच सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकों में इस का अकेला सब से बड़ा अंश दिसंबर 1981 के बाद की औद्योगिक विकास दर इस प्रकार है: एक ओर जब कि कपड़ा उद्योग में हड़ताल के कारण चार प्रमुख क्षेत्रों—कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, रसायनों और रंजकों ने अपने दरवाजे बंद ही कर दिये हैं, कर्जों की कठोर नीति के कारण बैंक ऋण के अभाव में व्यावसायिक वाहनों (ट्रकों) और ट्रैक्टरों के आयातों के सामने उन के भंडार भरे पड़े हैं।

यद्यपि 1981-82 के लिए अपेक्षित 9 प्रतिशत की विकास दर एक प्रशंसनीय उपलब्धि है, विशेष रूप से इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि एक वर्ष पहले की इसी अवधि में मात्र चार प्रतिशत विकास दर पंजीकृत की

गयी थी। इस समय जरूरी हो गया है कि औद्योगिक गतिविधियों में तत्काल नयी शक्ति डालने के लिए लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि यहाँ लगायी जाये।

दिसंबर के बाद की उत्पादन की गिरावट का संबद्ध उद्योगों पर भी एक क्रमिक प्रभाव पड़ा है। ट्रैक्टरों तथा व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में कमी ने उन सहायक उद्योगों को भी प्रभावित किया जो लगभग 600 करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य के मूल उपकरणों की आपूर्ति करते थे।

अधिकांश उद्योगों को ऋण न मिलने के कारण अभियांत्रिक उद्योगों पर इसका सब से बुरा प्रभाव पड़ा है। बताया जाता है कि वे चालू पूँजी के अभाव में लड़खड़ा रहे हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण उन के निर्यात पर और बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन में से काफी अनुबंध के बावजूद आपूर्ति करने की हालत में नहीं हैं।



और कार्क उद्योगों में यह गिरावट 16.5 प्रतिशत है। चमड़ा उद्योग की क्या कहें जिस की उत्पादन दर दिसंबर से मार्च के अभाव में 5.9 प्रतिशत तक गिर गयी है। कागज और सोडा ऐश दो ऐसी वस्तुएँ हैं जो कि माल लागत से कम मूल्य पर मिल सकती हैं।

साथ ही तीन उद्योग समूहों ने, जो उद्योग उत्पादन के सूचकांक में 2.51 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, अप्रैल से जनवरी, 81-82 के दौरान ऋणात्मक विकास दर दिखायी है।

इन के अतिरिक्त 409 बड़े उद्योग और 23,255 लघु उद्योग रुग्ण हुए बताये जाते हैं। बहुत से कारणों में से कुछ कारण हैं बाजार में मंदी, बिजली की कटौती, कच्चे माल की कमी।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति अचानक पिछली जनवरी से शुरू हुई जब मुद्रा-स्फीति विरोधी नीतियों का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। यह संश्लेषी समग्र औद्योगिक विकास दर से आसानी से दर्शाया जा सकता है। यह दर अप्रैल-दिसंबर 1981 के दौरान 9.4 प्रतिशत थी जो अप्रैल-जनवरी 1981-82 के दौरान अचानक गिर कर 9.1 प्रतिशत रह गयी।

प्रौद्योगिक विकास महानिदेशालय के अंतर्गत 132 चुने हुए उद्योगों में भी यही स्थिति थी जहाँ इसी दौरान विकास दर 12 प्रतिशत से घट कर 11 प्रतिशत रह गयी है।

यद्यपि 1981-82 के लिए अपेक्षित 9 प्रतिशत की विकास दर एक प्रशंसनीय उपलब्धि है, विशेष रूप से इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि एक वर्ष पहले की इसी अवधि में मात्र चार प्रतिशत विकास दर पंजीकृत की

गयी थी। इस समय जरूरी हो गया है कि औद्योगिक गतिविधियों में तत्काल नयी शक्ति डालने के लिए लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि यहाँ लगायी जाये।

दिसंबर के बाद की उत्पादन की गिरावट का संबद्ध उद्योगों पर भी एक क्रमिक प्रभाव पड़ा है। ट्रैक्टरों तथा व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में कमी ने उन सहायक उद्योगों को भी प्रभावित किया जो लगभग 600 करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य के मूल उपकरणों की आपूर्ति करते थे।

अधिकांश उद्योगों को ऋण न मिलने के कारण अभियांत्रिक उद्योगों पर इसका सब से बुरा प्रभाव पड़ा है। बताया जाता है कि वे चालू पूँजी के अभाव में लड़खड़ा रहे हैं। उत्पादन में गिरावट के कारण उन के निर्यात पर और बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन में से काफी अनुबंध के बावजूद आपूर्ति करने की हालत में नहीं हैं।

चालू पूँजी की कमी बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले नकद ऋणों की सीमा में कमी का सीधा परिणाम है और धीरे-धीरे उसका प्रभाव कई उद्योगों के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। यद्यपि सरकार ने हाल ही में बैंकों के माध्यम से नकदी-संचित (कैश रिजर्व) अनुपात को घटा कर 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋणों की गुंजाइश पैदा कर दी है।

इस का अभी तक कोई प्रभाव नजर नहीं आता क्योंकि यह कुल अतिरिक्त ऋण जरूरतों का एक छोटा सा अंश मात्र है। फिर भी कुछ संकेत मिलते हैं कि सरकार कुछ विशेष तौर पर चुने हुए उद्योगों के समूह की चालू पूँजी की जरूरतों



## शिष्टाचार

व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के क्षेत्रों पर बातचीत करने व नीति निर्धारण के लिए हाल ही में जापान से एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल भारत दौरे पर आया।

जापानी दल के 40 वर्षीय युवा नेता ने बातचीत की शुरुआत इस प्रकार की: "भारत में अभिनंदन का तरीका क्या है?"

उच्च पदासीन भारतीय अधिकारी ने प्रचलित नमस्कार की मुद्रा में उन्हें अनुप्रहित किया।

इससे भारत-जापानी संयुक्त नीति के लिए उच्चस्तरीय बातचीत का रास्ता खुल गया।

और इस प्रकार दोनों नेताओं ने इस अत्यधिक भाव प्रवण जगत में प्रचलित अभिनंदन के विभिन्न तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए शांतिपूर्वक एक घंटा बिता दिया।

बैठक में दिलचस्प मोड़ तब आया जब जापानी प्रतिनिधि ने भारतीय अधिकारी

से पूछा कि क्या वह ब्रितानी तरीके से—यानी गालों पर चुंबन अंकित करके—अभिनंदन करवाना पसंद करेंगे?

अधिकारी के मुँह पर पहले तो चुंबन के विचार से ही लाली छा गयी, फिर अपने पर काबू करते हुए उसने कहा: "यदि स्वागत करने वाले ब्रेजनेव हों तो नहीं, पर यदि कोई युवती हो तो जरूर पसंद करूँगा।"

उच्च स्तरीय भारतीय-जापानी बैठक काँफी के दो दौरों के बाद समाप्त हो गयी।

एक कनिष्ठ अधिकारी, जो पूरी बैठक के दौरान वहाँ बैठा रहा था, अपने वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लेने की दृष्टि से पूछ बैठा, "श्रीमान, इस उच्चस्तरीय भारतीय-जापानी विचार विमर्श के औपचारिक विवरण के लिए मुझे क्या लिखना है?"

वरिष्ठ अधिकारी का जवाब था, "मूल जाओ कि कभी कोई जापानी शिष्ट-मंडल बातचीत करने के लिए आया भी था।"

की आपूर्ति के लिए अगले दो या तीन महीनों में कुछ और राशि उपलब्ध करा सकती है।

27 नवंबर 1981 को औद्योगिक क्षेत्रों पर, जिन में मध्यम, बड़े व लघु उद्योग शामिल हैं, कुल बैंक ऋण के रूप में 14081 करोड़ रुपये वकाया थे, इससे पहले 27 मार्च, 1981 को यह राशि 13214 करोड़ रुपये मात्र थी।

आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त धन को ऋणों के रूप में उद्योगों को देने की व्यवस्था नहीं की गई तो संभव है कि औद्योगिक उत्पादन वर्तमान वित्त वर्ष 1982-83 में 1980-81 के वर्ष से भी नीचे गिर जाये।

अप्रैल से दिसंबर 1981 के दौरान उद्योगों को परिवहन आदि सहायक उद्योगों से जितना सहयोग मिला उतना इससे पहले कभी नहीं मिला, उन में 13.7 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गयी। विद्युत उत्पादन में 10.1 प्रतिशत, कोयला उत्पादन में 9.6 प्रतिशत, कच्चे तेल में 54.5 प्रतिशत, पेट्रोलियम शोधन उत्पादनों में 16.7 प्रतिशत, ब्रिक्री योग्य इस्पात में 14 प्रतिशत और सीमेंट में 12.6 प्रतिशत वृद्धि हुई।

अन्य उद्योगों के मामले में विकास दर इस प्रकार रही: नाइट्रोजन उर्वरक में 48.2 प्रतिशत, फास्फेट उर्वरक में 13.1 प्रतिशत, यात्री कारों में 39 प्रतिशत, व्यावसायिक वाहनों में 28.9 प्रतिशत तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोगी ट्रैक्टरों में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि अप्रैल से दिसंबर 1981 के 9 महीनों

की अवधि में हुई। औद्योगिक मशीनों, कागज और पेपर बोर्ड में उत्पादन की विकास दर में वृद्धि का प्रतिशत अप्रैल से जनवरी 1981-82 के 10 महीनों की अवधि में क्रमशः 14.4 प्रतिशत तथा 7.8 प्रतिशत रहा।

सरकार ने हाल ही में एक अति उदार नीति अपनायी है जिस के अंतर्गत सीमेंट को आंशिक रूप से विनियंत्रित कर दिया गया तथा लिखने और मुद्रण के सफेद कागज पर से लेवी कम करने के लिए कार्यवाही की गयी है। साथ ही इस उद्योग का 1981-82 से पहले के प्रांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में जितना सर्वाधिक उत्पादन रहा है उस से 33 $\frac{1}{3}$  प्रतिशत तक अपनी क्षमता अधिक बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है।

इस के अतिरिक्त सरकार ने उद्योगों की परिशिष्ट-1 की वर्तमान सूची में पाँच और क्षेत्र जोड़ दिये हैं। यह उन क्षेत्रों की सूची है जो बड़े औद्योगिक गृहों तथा 'एफ. ई. आर. ए.' कंपनियों के लिए खुले हैं। सरकार ने 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' भी घोषित किया है।

ये सारे प्रयोग उद्योग के लिए निरर्थक सिद्ध तो होंगे ही और न ही व्यापार को इस उदार नीति से लाभ उठा लेने के लिए समुचित वित्तीय प्रोत्साहन ही मिल रहा है। एक हिसाब से सरकार धारक बांडों के अध्ययन से अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा कर चुकी है और थोड़ा-सा जो बच गया है वह माल तथा भंडार के रूप में है, जिसके परिणामस्वरूप ही ऋणों की कमी महसूस हो रही है।

## एक अनूठा उपन्यास

हम सब मंसाराम मुद्राराक्षस का प्रकाशित हुआ है लेकिन इस की जितनी चर्चा और जितना स्वागत होना चाहिए या उक्त क्यों नहीं हुआ इस पर उन्हें आश्चर्य नहीं होना जो लोग हिंदी आलोचना जगत की मिराब से परिचित हैं। इस उपन्यास का समसामयिक हिंदी उपन्यास जगत में एक विशिष्ट उपन्यास के रूप में स्वागत किया जाना चाहिए।

अपनी भाषा शैली, विषय वस्तु की सफाई और सादगी में यह उपन्यास बेजोड़ है। लेखक ने बहुत छोटी परिधि में आज के चुनाव राजनीति का व्यापक कुरूप चेहरा किसी लाग लपेट और भावुकता के साथ कर रख दिया है। आज अब कि सारे राजनीतिक उपन्यास किसी राजनीतिक पार्टी के नया नजरिए के तहत लिखे जाते हैं यह उपन्यास केवल मानवीय संवेदना को आधार बना लिखा गया है—एक अतिसाधारण गाँव का एक अतिसाधारण हरिजन के भीतर होने वाला परिवर्तन को यह उपन्यास टटोलता है।

कुछ बदल रहा है इस उत्साह में बिना सोचे समझे लगभग एक बेवकूफ की इस का नायक राजनीतिक हलचल के कूड़े की ढेर के इर्द गिर्द सक्रिय रूप से कुछ पाने की इच्छा से मंडराता है, अपनी भी भूमिका को अपने तर्द जरूरी मानता और राजनीतिक आदमियों के स्वार्थ और को चालों को सही संवेदना मान उन के पूरे जी जान से समर्पित हो जाता है।

पल पल बदलते दल बदल और संबंधों को न समझ पाने के कारण अंत में उन से पिटता और उन की अमानवीयता का शिकार होता रहता है। एक अतिसाधारण आदमी की इस त्रासदी का बहुत ही कुशल मार्मिक चित्रण मुद्राराक्षस ने किया है।

सूक्ष्म दृष्टि के साथ उन्होंने गाँव में होने वाली आज के राजनीतिक प्रपंच से जुड़े मानसिक स्तर के लोगों, जातियों और के यथार्थ रूप को खोलने का प्रयत्न किया है। वह उन की जानकारी पर अचल करता है। यह एक विशद यथार्थ चित्रण है। वह अपेक्षाकृत आसान होता है। यह वास्तविक, संकेतगर्मी आहटों का है जो अपने प्रतीकों में समर्थ काव्य अर्थ खोलती है।

इस उपन्यास को पढ़ कर लू थू 'आक्षू की सच्ची कहानी' की याद आती है। इस का नायक भी जाहिल, बुद्धिहीन, लू थू का नायक आक्षू की भाँति है, क्रान्तिकारी होने का अर्थ और मारा जाता है। इस का नायक



यास

भ्रम का 130  
यह पिछले  
की जितनी  
हिए था उत  
अचय नहीं हो  
गत की गिरा  
का समसामयि  
विशिष्ट उपन्या  
ना चाहिए।  
वस्तु की सपना  
बेजोड़ है। लेख  
ज के चुनाव  
प्य चेहरा सि  
ता के साथ  
कि सारे राज  
तेक पार्टी के  
ते हैं यह उपन्या

आधार बना  
साधारण गाँव  
भीतर होने का  
टटोलता है।  
साह में बिना  
बेवकूफ की  
हलचल के  
रूप से कुछ  
है, अपनी नि  
जहूरी मान  
के स्वायं और  
मान उन के  
हो जाता है।  
दल और अ  
के कारण अंत  
अमातवीरता  
एक अतिसा  
बहुत ही कुशल  
ने किया है।  
गाँव में होने  
च से जुड़े नि  
जातियों और  
का प्रयत्न नि  
पर अचर

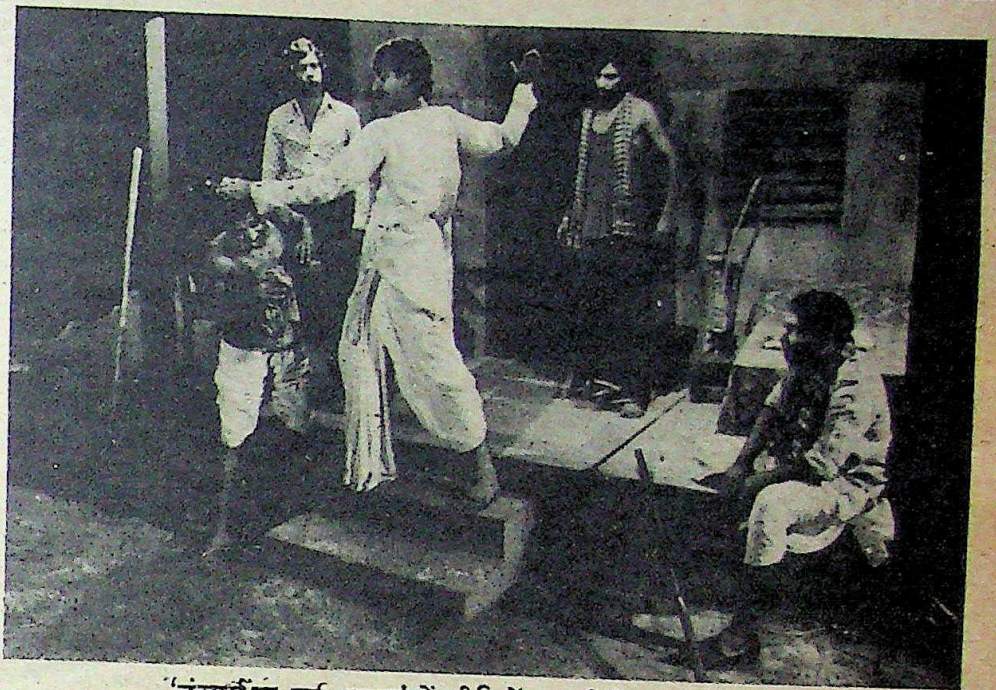
हम सब संसारामः मुद्राराक्षस, लिपि प्रका-  
शन, अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली.  
110002. मूल्य-18 रु.

गामंच

## चंद्रमासिंह उर्फ चमकू

खुले में पेड़ों के नीचे तीन चार खपरैल के  
जहूरी मानते हैं, उन के ओसारे हैं, सामने खुला सहन है,  
यह इस देश के एक गाँव का छोटा  
हिस्सा है—'चंद्रमासिंह उर्फ चमकू'  
का दृश्यबंध. राजधानी के राष्ट्रीय  
विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने  
पिछले दिनों विद्यालय के अहाते में खेला  
आमतौर पर छात्रों की प्रस्तुतियों की चर्चा  
होती जाती क्यों कि वह उन के पाठ्यक्रम  
का हिस्सा होता है लेकिन इस नाटक का  
लेख इसलिए जहूरी है कि यह पाठ्यक्रम  
का हिस्सा होते हुए भी एक ऐसी प्रस्तुति है  
—विद्यालय में बहुत कम हुई होगी.  
प्रस्तुति और कथ्य में यह नाटक विद्या-  
लय ही नहीं, राजधानी के रंग जगत की एक

'चंद्रमासिंह उर्फ चमकू' लू शुन की  
कहानी—'आक्यू की सच्ची कहानी'  
मानु भारती द्वारा किया गया खूबसूरत  
रूपान्तर है. रूपान्तरण अवधी में है,  
मानु भारती ने ही इस नाट्य रूप का निर्देशन  
किया है. विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्रों  
अच्छा काम करा ले जाना जहाँ  
मानु भारती के निर्देशन कौशल  
परिचायक है. वहीं इस बात  
परिचायक है कि ऐसे कलाकार जो  
मंच व्यक्तित्व का निर्माण



'चंद्रमासिंह उर्फ चमकू' में सीढ़ियों पर विपिन शर्मा (चमकू)

नहीं हुआ है, ताजगी से भरा जैसा अभिनय  
कर सकते हैं वैसा मंच व्यक्तित्व छाप कला-  
कार नहीं कर सकते. छात्रों का विद्यालय के  
ही राष्ट्रीय रंगमंडल के कलाकारों की तरह  
अपना कोई रूढ़िग्रस्त अभिनय व्यक्तित्व न  
होने के कारण प्रस्तुति में उन के अभिनय का  
सहज निखार देखता था. आक्यू का चरित्र  
परिचित है. चमकू सिंह उस का भारतीय  
प्रतिरूप है. रूपान्तरण में समसामयिक भारतीय  
राजनैतिक परिवेश को बना गया है और  
भोजपुर क्षेत्र के नक्सलवादी आंदोलन की  
पृष्ठभूमि में गाँव को और उस के चरित्रों को  
समाहित करने का प्रयत्न किया गया है. लू  
शुन के समय के चीन का जितना सटीक पर्याय  
आज का भारत नहीं है उतना ही सटीक रूपां-  
तरण भी नहीं है. लेकिन चीन के गाँवों की  
जो समस्याएँ, ग्रामीण चरित्रों का जो वर्गरूप  
और आक्यू की जो मनःस्थिति थी, वैसी ही  
समस्याएँ वैसेही वर्ग चरित्र हमारे गाँवों के और  
वैसी ही मनःस्थिति आक्यू के पर्याय चमकू की  
तो है ही. बाहरी लड़ाई की सघनता में जहाँ  
थोड़ा अंतर है वहाँ रूपान्तरण प्रतीक के स्तर पर  
अर्थ ध्वनित करता है. इस तरह रूपान्तरण  
यथार्थ के स्तर पर जीवंत, धड़कता हुआ है और  
मविष्य की आहटों को भी प्रतीक रूप में स्पर्श  
करता है.

प्रस्तुति में मंच रूप और अभिनय ही श्रेष्ठ  
नहीं थे, गाँव का पूरा वातावरण, चरित्रों  
का अवधी में ही बोलने का अपना अलग अलग  
लहजा, उन के वस्त्र, उन की चाल, सब अलग  
प्रतिमान बनाते थे. पहली दफा ऐसा हुआ कि  
अलग अलग भाषा क्षेत्रों से आये छात्र अपने  
उच्चारण में बेदंगी नहीं दीखे—बोली में सब की

भाषिक कमजोरियों खप गयीं.

सब से जानदार अभिनय चमकू की भूमिका  
में छात्र विपिन शर्मा का था. अपने चरित्र  
के क्रमशः विकास का—अपने भोलेपन, अपनी  
मूर्खता, अपनी मुराही, अपने भ्रम और  
अनेक सतहों पर अपनी भीतरी बेचैनी का  
चित्रण वह बखूबी कर सका. निर्देशक ने गाँव  
के माहौल के चित्रण में न कहीं अतिरंजना  
आने दी, न ही शहरी भोंडापन. यथार्थ की  
खूबसूरत तस्वीर सामने थी, चाहे वह गाँव  
में होने वाली गवाँरू नौटंकी हो, उस के गाने  
नाचने वालों की बेसुरे झटके हों, चाहे दर्शकों  
की भौजमस्ती भरी आवाजें और फवतियाँ  
हों ! निर्देशक अंत तक आते आते उस त्रासदी  
को गहरा कर सका जहाँ निरीह, अपने भ्रम  
में जीता चमकू इस नतीजे पर पहुँचता है—  
कि विद्रोह भी बड़े लोगों के लिए है उस के  
लिए नहीं और क्रांति की कीमत फांसी पर  
चढ़ कर चुकानी पड़ती है—व्यवस्था की  
गोली से निहत्था बिना क्रांतिकारी हुए भी  
मार दिया जाता है. फिर सैनिक उसे उठा  
कर दर्शकों के पीछे से एक जुलूस की शकल में  
ले जाते हैं. दर्शकों को घूम कर उस के शव प्रद-  
र्शन को देखना पड़ता है, निर्देशक ने जैसे संपूर्ण  
समसामयिक हिंसात्मक स्थिति पर घूम कर  
देखने की अनिवार्यता को इस तरह खामोशी  
से रेखांकित कर दिया हो ! यह नाटक विद्यालय  
के इन छात्रों द्वारा मले ही अब विद्यालय में  
न खेला जा सके लेकिन आशा की जानी चाहिए  
कि मानु भारती इस सार्थक सुंदर नाटक का  
मंचन करते रहने का एक लंबा सिलसिला  
बनायेंगे और यह आगे भी खेला और देखा  
जा सकेगा.

—स.द.स.





सुशी कंकणा बनर्जी :  
गायन सुख (दाएँ)  
पुरुषोत्तम पांडेय : संयो-  
जन का दायित्व (दाएँ)

## श्रोता की एकनिष्ठ साझेदारी

इस बार वाराणसी के संकट मोचन संगीत मेले (12 अप्रैल से 15 अप्रैल) में सितार वादकों और कथक नर्तकों की घूम रही। युवा सितार वादक—गोपाल शंकर मिश्र और कृष्णा चक्रवर्ती ने अपने वादन से श्रोताओं को जहाँ आकर्षित किया वहीं अनुभवसिद्ध मान्य सितार वादकों—बुधादित्य मुखर्जी, मणिलाल नाग और इंद्रनील भट्टाचार्य ने अपनी छाप अलग-अलग संगीत समाजों में छोड़ी। कथक नर्तकों में लखनऊ घराने के विजय शंकर की भावगत एवं तालगत पारंगतता श्रोताओं को रस्तोद्रेक की चरम सीमा तक ले गयी। जयपुर घराने के प्रतिनिधि दुर्गालाल का नृत्य कथक के विविध प्रकरणों को उभारता हुआ विशिष्ट वाहवाही प्राप्त कर सका। वादन में शंभुलाल कंडारा और रोबीन घोष का वायोलिन—गुरुदेव सिंह का तथा अमित भट्टाचार्य का सरोद वादन बंदिशों और राग की समझ के लिए प्रशंसित हुए। ताल एवं लयकारी के काम में काशी के रसिक-समाज के प्राण बसते हैं। किंतु इस बार का समग्र गायन कार्यक्रम फीका ही रहा। यद्यपि ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, चैती, भजन सभी अंग प्रस्तुत हुए किंतु उनमें न तो उतनी ताजगी ही मिली और न ही प्रतिमान-निर्मित करने वाली कला ही प्रदर्शित हो सकी। गायिकाओं में सुनंदा पटनायक, कंकणा बनर्जी, अलकादेव, शोभा मोदगल्य के सामान्य रोचक कार्यक्रम हुए। पं. महादेव प्रसाद मिश्र, छत्रलाल रंगीले ठाकुर, राजन-साजन मिश्र, पशुपतिनाथ एवं अमरनाथ, पं. प्रताप नारायण और अनेक गायक भी इस उत्सव में शामिल हुए। संगीत उत्सव का प्रारंभ पहले दिन पं. त्रिभुवन उपाध्याय के पखावज वादन से हुआ था—और अंतिम दिन भी पखावज के ही सम्पुट से बाबूलाल पखावजी ने समापन किया।

इस संगीत-मेले की एक अनुठी परिकल्पना बरसों से चली आयी है। इसमें कलाकारों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। वे स्वतः आते हैं और गाते बजाते हैं। उनकी इस कला साधना में सबसे बड़ा योगदान रहता है उन दस बारह हजार श्रोताओं की उपस्थिति का जो प्रतिदिन एक आसन पर सांयकाल सात बजे से प्रातः तक बैठ कर अमृतपूर्व एकाग्रता के साथ संगीत का रसास्वादन करते हैं। संगीत में श्रोता की यह एकनिष्ठ साझेदारी अन्यत्र दुर्लभ है। इस साझेदारी से ही उस ऊर्जा का जन्म होता है जो संगीत के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नए या दौयम दर्जे के माने जाने वाले कलाकारों की भी प्रस्तुतियों को सहसा एक चमत्कारिक शिखर दे देता है।

इस आयोजन में विदेश से आये हुए पर्यटक श्रोताओं की भी अच्छी संख्या रहती है। टॉटन हेफर स्मिगर (30) छः साल से बनारस में गाना सीख रहे हैं। उनके लिए यह आयोजन 'कई वर्षों से देखा और सुना है जो वर्णनातीत है। यहाँ यह आनंद सबके लिए उपलब्ध है। कोई टिकट नहीं। रिक्शा वाला भी गाना सुन रहा है। यह एक आनंद का अनुभव है। जो आनंद गायक को मिलता है वही वह हमें भी दे रहा है। यह आध्यात्मिक अनुभव है या नहीं—कह नहीं सकता किंतु यहाँ संगीत की गुणात्मकता से सीधे साक्षात्कार होता है।' अमेरिका से आयी चिकित्सक डाक्टर मेरीलीन मांटगोमरी (33) को भारतीय संगीत की जिस उदात्तता से यहाँ परिचय हुआ वह उनके भीतर इस देश के प्रति एक अतिरिक्त गहरा आकर्षण पैदा करता है। 'कलाकारों के भीतर से मैं परमात्मा की आवाज सुन रही हूँ। संगीत का हर आंदोलन मुझसे अपना पाखंड और झूठा अहं त्यागने की मांग करता हुआ लगता है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे साथ पूरी प्रकृति गा रही है—ये वृक्ष, ये आसमान, ये घरती सब कुछ एक तरंग में है। पच्छिम के संगीत का श्रोता अनासक्त होता है। यहाँ का श्रोता संगीत को

जीवन का अंश बना देता है।' वयोवृद्ध गायक पं. प्रताप नारायण (बंबई) का अनुभव 'संकट मोचन का संगीत उत्सव बड़ा विविध है। यहाँ का श्रोता गाना बजाना समझता है। पूरे देश में संगीत रसिकों में बनारस एक नाम पर है दूसरे पर पुणे है। यह क्षेत्र ही बड़ा सुविधा है।' गायिका कंकणा बनर्जी (बंबई) का कहना है 'कि 'मैंने तो इस मंदिर में गायिकाओं को प्रभु के सामने गाने का अधिकार दिलाया। यहाँ का श्रोता बड़ा 'कठिन श्रोता' है। इसके सामने गाने में आता है। श्रोताओं और इतने अधिक कलाकारों को संभालते हुए इसका संयोजन करते पुरुषोत्तम पांडे जो बचपन से इसी उत्सव में हुए हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को याद दिलाया है। देश के अनेक मूर्ख गायकों-वादकों की स्मरण किया जो अब तक इस उत्सव में बस बीस बरसों से आते रहे हैं। उनका कहना है कि श्रोताओं का मनोयोग और अनुशासन होकर इस तरह सारी रात संगीत का रसास्वादन करना कलाकारों के लिए एक अनुभव होता है। उन्हें आज तक कभी गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ा और प्रशासन को कोई दखलंदाजी भी कभी करनी पड़ी। सब श्रोता इस आयोजन में सम्मान के अधिकारी हैं। कलाकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो आते रहे हैं उन्हें रोका जा सकता। श्रोता नयों को भी सुनना चाहते हैं। समय कम है। चार दिन में अब पूरा नहीं पारित किया जा सकता। किंतु कार्यकर्ताओं, 'सेवकों' को इतना परिश्रम करना पड़ता है कि उनसे लगातार सात दिन जागने और निरंतर काम के लिए कहा जाये? कलाकारों का व्यवहार सौजन्य पूर्ण और आत्मीय रहता है कि और कलाकार में उत्तरोत्तर दूरी कम गयी है। उनके अनुसार स्त्रियों का नृत्य के प्रांगण में अभी तक इस उत्सव में नहीं है यद्यपि अत्यंत प्रतिष्ठित श्रीमती संयुक्ता पार्मण्यही प्रभृति ने इस प्रतिबंध को उठा लेने की जोरदार को है।

आयोजकों की निष्ठा, शील और सौजन्य के नाते कलाकारों की एक भारी इस उत्सव में एकत्र होने लगी है। उनके रचनात्मक रसास्वादन की प्रक्रिया में जाये, किस प्रकार उनके कार्यक्रमों को रखा जाय, कैसे नए बहुश्रुत एवं प्रशस्त किया जाये—यह सोचना और योजना बनाना बहुत जरूरी है ताकि श्रोता का संगीत के नए घरातलों में भी होता रहे।



## दुनिया को मत मारो

पोस्टर विधा के बारे में सब से अधिक उल्लेखनीय बात यही है कि एक पोस्टर के माध्यम से किसी संदेश, सूचना या विचार को कलात्मक ढंग से रखा जा सकता है। हमारे यहाँ दरअसल अभी कलात्मक पोस्टरों की विधा पूरी तरह विकसित ही नहीं हुई—पिछले कुछ ही वर्षों में यह हुआ है कि किसी कला क्लब, नृत्य, संगीत आयोजनों, प्रदर्शनियों आदि के अच्छे पोस्टर बनने शुरू हुए हैं। लेकिन किसी विचार या संदेश को ले कर कलात्मक पोस्टर तो हमारे यहाँ अभी भी न के बराबर बनते हैं। इसीलिए पिछले दिनों 'दक्षिण एशिया' द्वारा लिए अंतरराष्ट्रीय 'क्वैकर कार्यक्रम' द्वारा भारत में आयोजित निःशस्त्रीकरण एवं विकास पोस्टर प्रदर्शनी में कोई भारतीय पोस्टर न देख कर कोई विशेष अचरज नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर लगा कि संस्थाएँ

भी इस बात के लिए कम ही प्रयत्न करती हैं कि विभिन्न विषयों को ले कर भारतीय कलाकार पोस्टर बनाएँ। उनके पहल करने पर अब निश्चय ही यह संभव है कि कई कलाकार ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आगे आएँ।

बहरहाल निःशस्त्रीकरण विषय पर यह पोस्टर प्रदर्शनी एक अच्छी प्रदर्शनी थी। और इस प्रदर्शनी का एक संदर्भ भी है : जून-जुलाई 1982 में ही दूसरा विशेष निःशस्त्रीकरण सम्मेलन होने जा रहा है। 'क्वैकर' शांति और समाज विकास के लिए कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसे 1946 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध भी है। इस प्रदर्शनी के

(बायें) एक पोल्स्की पोस्टर,

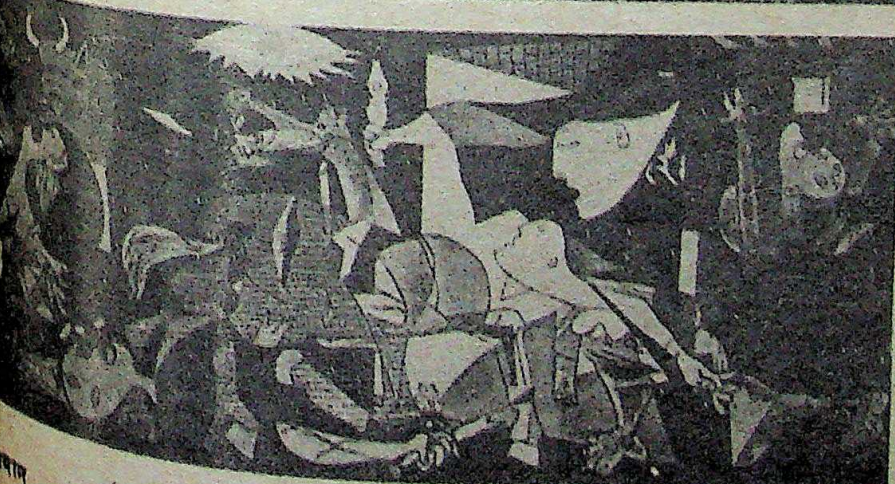
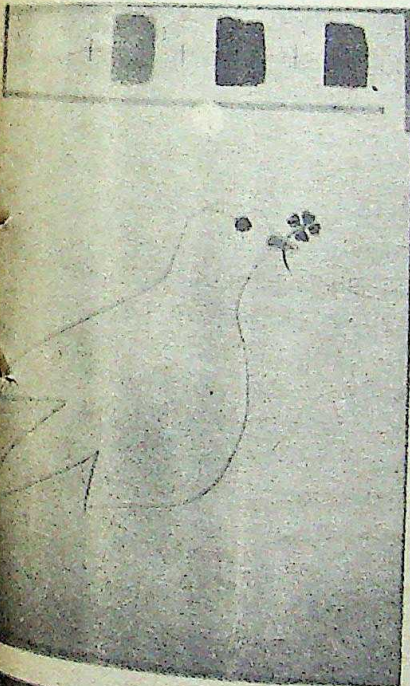
(दायें) शांति का फूल

(नीचे) पिकासो की सुप्रसिद्ध कृति 'ग्वेनिका' का एक पोस्टर के रूप में इस्तेमाल : संहार नहीं चाहिए।

लिए पोस्टर विभिन्न देशों से संकलित किये गये हैं जिन में सबसे प्रभावशाली पोस्टर पोल्स्का के हैं—यह स्वाभाविक ही है अब तक विभिन्न विषयों पर पोल्स्की पोस्टर दुनिया भर में सब से अच्छे पोस्टर माने जाते हैं। इस प्रदर्शनी में भी निःशस्त्रीकरण संबंधी पोल्स्की पोस्टर बहुत कम रंगों, आकारों, रेखाओं में शांति के असरकारी संदेश को साथ लेकर चलते हैं। शांति के प्रतीक कपोत को आधार बना कर रचे गये इन पोस्टरों के विवरण इतने सशक्त हैं कि उन में लिखे हुए शब्दों को न पढ़-समझ पाने वाले भी इन के संदेश को समझ जाएँगे। देखें तो पोस्टर विधा के वही पोस्टर सशक्त होते भी हैं जो चित्र और शब्द को साथ साथ ले कर चलते हुए भी निरा शब्द निर्भर नहीं रह जाते और लिखित शब्द के अर्थ की रक्षा करते हुए, उसे पोस्टर विधा का एक हिस्सा बना लेते हैं। पोल्स्की पोस्टर लिखित शब्दों का प्रयोग मुक्त मुल्लेख के रूप में भी करते हैं और छपे हुए अक्षरों जैसे आकारों के रूप में भी। कुछ देशों के पोस्टरों में एक चित्र रूप रखने के बाद अपनी अपनी भाषा में केवल यही लिखा है 'नहीं' यानी 'यह नहीं'। इन पोस्टरों का 'नहीं' भी बहुत कुछ कहता है—यही कि नहीं चाहिए शस्त्रास्त्रों से संहार।

प्रदर्शनी में पिकासो के सुप्रसिद्ध चित्र 'ग्वेनिका' की एक प्रतिकृति भी रखी गयी है। पिकासो का यह चित्र कला-इतिहास में युद्ध के विरुद्ध रचे गये सशक्ततम चित्रों में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से विशेष रूप से बनवाये गये निःशस्त्रीकरण संबंधी कुछ पोस्टर भी बहुत अच्छे हैं। जिन में से एक में अफ्रीकी स्त्रियों-बच्चों के पुष्ट, मुडौल और अत्यंत मानवीय चेहरे हैं—कुछ कुछ प्रभाव-वादी शैली में। पोस्टर के रंग अत्यंत संवेदन-शील हैं और विवरण और रंग मिला कर इस बात को बहुत अच्छी तरह प्रतिष्ठित करते हैं कि इन रूपों और रंगों का संहार दरअसल कितना अमानवीय होगा। कुछ पोस्टरों में हिरोशिमा के संहार की स्याह, 'निर्जन' रेखाएँ बहुत गहरे में विचलित करती हैं।

पोस्टर विधा की एक शर्त यह भी है कि वह कलात्मकता छोड़े बिना विचार को सटीक ढंग से पहुँचाये। इस दृष्टि से भी इस प्रदर्शनी के कुछ पोस्टर देखने लायक थे। यही प्रदर्शनी बंबई (सितंबर 1981) सूरत (सितंबर 81) अहमदाबाद (अक्टूबर 1981) बंगलूर (नवंबर 1981) मद्रास, मदुरै (फरवरी 1982) में आयोजित हो चुकी है। क्वैकर के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि एस. के. दे. के अनुसार इस तरह की प्रदर्शनियाँ भविष्य में भी आयोजित की जायेंगी जिन में अब भारतीय कलाकारों के पोस्टर भी प्रदर्शित करने की योजना है। □





## पाँच सितारा होटल और एक बेचारी स्मिता पाटिल



स्मिता पाटिल

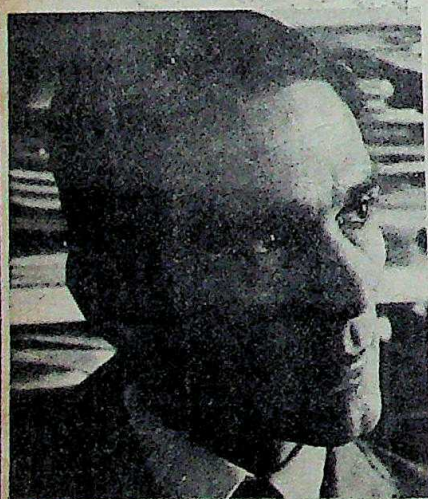
लगभग 10 वर्ष पहले अमिताभ बच्चन ने 'जंजीर' फिल्म से अपनी जो छवि बनायी थी वह अब बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। अपनी नयी फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा का साथ दिया है। अमिताभ बच्चन की छवि में अब नया मले ही कुछ नहीं रह गया हो लेकिन यह तो है ही कि आज-कल मनोरंजन की जिस शैली को बंबइया

सिनेमा में विकसित कर लिया गया है उस में अमिताभ का फार्मूला काफी सफल सिद्ध होता है। 'नमक हलाल' में अमिताभ बच्चन ने कृपा-पूर्वक हिंसा की शैली का कम इस्तेमाल किया है। और उन की भूमिका मुख्य रूप से नायक और कॉमेडियन का घालमेल है।

लगता है अमिताभ बच्चन ने निर्माताओं की कई समस्याओं का हल निकाल लिया है। मिसाल के लिए उन के साथ एक कॉमेडियन को चिपके रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही एक सुपर कॉमेडियन हैं।

'नमक हलाल' के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उस में भव्य सेटों से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं समझी गयी है। लगभग सारी फिल्म एक पाँच सितारा होटल के आलीशान वातावरण में चलती रहती है। सड़क या आसमान दिखाने की तो लगभग कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है।

'नमक हलाल' में वह सब कुछ है जो एक बड़े बजट की फिल्म में होना चाहिए। इन फिल्मों की सफलता का एक मुख्य फार्मूला यह होता है कि समय समय पर दर्शक की आँखों में आँसू आ जायें। और इस मामले में हमारे पटकथा लेखक सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। सीधे हृदय पर आक्रमण करते हैं।



स्व. पासोलीनी

### पनीर के लिए मौत

राजधानी में पिछले दिनों प्रसिद्ध इतालवी फिल्मकार पीयेर पासोलीनी की चार फिल्मों का एक लघु सिंह प्रदर्शन आयोजित हुआ। ये फिल्में इतालवी सूचना केंद्र में मूल इतालवी में ही दिखाई गयीं जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण

बात है। पासोलीनी जैसे विश्वविख्यात फिल्म निर्देशकों की फिल्में भारतीय फिल्म प्रेमियों को बहुत कम देखने को मिल पायी हैं। पिछले फिल्म महोत्सव से पहले एक बातचीत में फिल्म महोत्सव निदेशालय के निदेशक को दिनमान ने सुझाव दिया था कि वह पासोलीनी की फिल्मों का कलकत्ता में सिंह प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश करें। लेकिन पता चला कि उन की फिल्मों के उपशीर्षकों वाले प्रिंट उपलब्ध नहीं हैं।

पासोलीनी की प्रतिष्ठा फिल्मकार के अलावा कवि, उपन्यासकार और निबंध-कार के रूप में भी रही है। उन की प्रकाशित पुस्तकों और फिल्मों की संख्या को देख कर सचमुच आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि 1975 में केवल 53 वर्ष की उम्र में उन की हत्या कर दी गयी थी।

पासोलीनी की फिल्में फिल्मकला के सिद्धांत पक्ष को तो समृद्ध करती ही रहीं अक्सर उन्हें विवाद का सामना भी करना पड़ा। 1963 में उन्होंने ला रिक्कोत्ता नाम से एक 40 मिनट की फिल्म बनायी थी

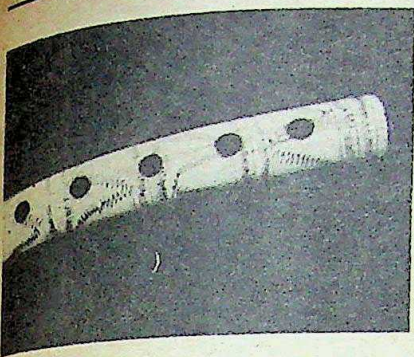
'नमक हलाल' की एक खासियत अमिताभ बच्चन का इस तरह की बॉक्स ऑफ़ीस प्रधान फिल्म में होना है। स्मिता पाटिल नसिरुद्दीनशाह की जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि वे कला फिल्मों के कलाकार हैं। स्मिता पाटिल को 'नमक हलाल' में अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई खास मौका नहीं मिला है। बारिश में अमिताभ बच्चन के साथ गाते वक्त जरूर निर्देशक ने उन की फिल्म वाली अंग प्रदर्शन की 'क्षमता' का इस्तेमाल किया है। फिल्म प्रेमियों को जाहिर है स्मिता पाटिल की यह 'नयी भूमिका' नहीं आयेगी। वैसे इस में दोष स्मिता पाटिल का नहीं है।

पाँच सितारा होटल में जो कुछ रहा है उस में एक बेचारी स्मिता पाटिल कर सकती है! लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि स्मिता पाटिल को इस फिल्म में अभिनय के पारिश्रमिक मिला हो वह अब तक की सभी पुरानी फिल्मों के पारिश्रमिक से ज्यादा हो।

यह दिलचस्प किस्म की आवाजाही है श्याम बेनेगल अपनी फिल्मों में स्मिता पाटिल की जगह पर रेखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक रेखा जैसी अभिनेत्रियों का इस्तेमाल करने वाले निर्देशक बेनेगल की फिल्मों की स्मिता पाटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जो अच्छे खासे विवाद का विषय बन गयी। इस फिल्म में एक विदेशी फिल्म निर्देशक इटली में आ कर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने के प्रसंग पर एक फिल्म बना रहा है। पासोलीनी ने इस फिल्म में निर्देशक पर बहुत अधिक ध्यान न दे कर एक 'एक्स्ट्रा' कलाकार की भूमिका को समझ पर ध्यान दिया है। किसी तरह से वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और बाजार में कर खूब सारा पनीर खरीद लाता है। बदहवास हालत में वह पनीर को खा लेता है। आमंत्रित सम्मानित व्यक्तियों के साथ फिल्म की जब शूटिंग चल रही होती है तो सूली पर इस 'एक्स्ट्रा' कलाकार को मृत हालत में पाया जाता है। पासोलीनी पर यह आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म में उन्होंने धर्म का मखौल उड़ाया है और उस के प्रति अपनी नफरत को दिखाई है। आज शायद इस फिल्म को देख कर कोई विवाद न हो लेकिन अपने समय में इस फिल्म ने काफी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। दरअसल पासोलीनी की फिल्म में हमें एक प्रतिबद्ध कवि की जिम्मेदारी मिलती है।





गीतांजलि की एक कविता की छाया

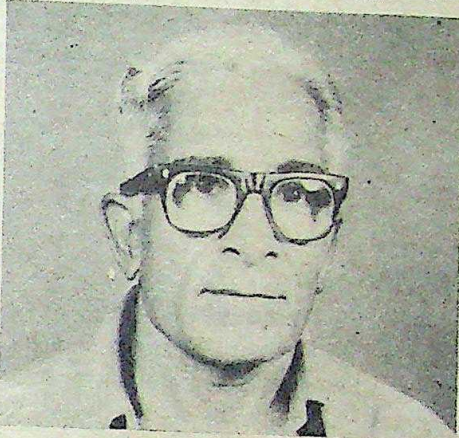
## छायाचित्रों में गीतांजलि

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि पर आधारित छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी पिछले दिनों गांधी संग्रहालय (नयी दिल्ली) में आयोजित हुई। छायाकार फूलचंद मिश्र रायपुर में एक बैंक अधिकारी हैं और छायांकन को अपने लिए 'पेशा नहीं जीने की शर्त' मानते हैं। अक्टूबर '81 में यही प्रदर्शनी रायपुर में आयोजित हुई थी जिस का उद्घाटन पंडित रवि शंकर ने किया था। इसी अप्रैल महीने में यही प्रदर्शनी विश्वभारती, शांतिनिकेतन में भी आयोजित हुई थी। श्री मिश्र इस प्रदर्शनी के लिए गीतांजलि की 34 कविताएँ चुनी हैं। उन का कहना है : गीतांजलि में बार बार डूबा हूँ और उस के कविता आलोक से प्रेरित हो कर कुछ कविताओं के अनुरूप छायाचित्रों की खोज की है—कश्मीर में कथाकुमारी तक फैले प्रकृति के वैभव को धरे में पकड़ने का प्रयास किया है। मानव प्रकृति का उपयोग उन्होंने वहीं किया है, जहाँ प्रकृति लगा है। बादल, बिजली, समुद्र, नदी, पर्वत आदि के बिना कविता प्रसंगों के कहीं अनुरूप नहीं हो सकता है। एक प्रयोग, और काव्यकृति को प्रति गहरा लगाव व्यक्त करने के रूप में—प्रदर्शनी संवेदनशील लगती है। —प्र.शु.

## गुरु रामदास त्रिशताब्दी समारोह

गुरुपति शिवाजी के गुरु तथा राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले मराठी भाषी संत, आदर्श एवं समर्थ गुरु रामदास स्वामी के 300 वें जन्मदिन के अवसर पर हाल ही में मराठी भाषी क्षेत्र में सक्रिय मराठी-भाषियों की संस्था सत्कार कला समारोह का सुंदर, सुव्यवस्थित, आयोजन किया। इस "त्रिशताब्दी समारोह" का कार्यक्रम हिंदी में अवसर पर आयोजक संस्था ने

समर्थ रामदास लिखित मराठी साहित्य के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक काव्य ग्रंथ श्री दासबोध का सरल हिंदी रूपांतर हिंदी दासबोध जो चार खंडों में केंद्र प्रकाशित कर रहा है के पहले खंड का विमोचन करवाया। समारोह के प्रमुख अतिथि केंद्रीय रेल मंत्री श्री प्रकाशचंद्र सेठी थे। हिंदी दासबोध के रूपांतरकार हैं इंदौर के श्रमिक क्षेत्र के निवासी लगभग



पांडुरंग लोहकरे : कर्मठ

पचास वर्षीय मराठी भाषी समाज सेवी विद्वान साहित्यकार पांडुरंग लोहकरे। निर्धन फटेहाल जिंदगी जीते हुए भी अपने स्वामि-मानी, कर्मठ व्यक्तित्व के कारण उन्हें सबका आदर प्राप्त है। —अनिल कुमार घड़वईवाले

## नाट्य प्रतियोगिता

अल्मोड़ा में अप्रैल के अंतिम सप्ताह संघटक महाविद्यालय में त्रिदिवसीय नाट्य प्रतियोगिता हुई। शिक्षा संकाय में सृष्टि का आखिरी आदमी (आलेख-धर्मवीर भारती, निदेशन-योगेश साह) विज्ञान संकाय ने सिंहासन खाली है (आलेख-सुशील सिंह, निदेशन-डी. के. शर्मा श्यामू रोतेला) वाणिज्य संकाय ने आक्रोश (आलेख-विप्लव, निदेशन-देवेंद्र कांडवाला) कला संकाय ने जागृति (आलेख-प्रदीप गुरुरानी, निदेशन-अरविंद साह) और विधि संकाय ने कथा एक कंस की (आलेख-दया प्रकाश सिन्हा, निदेशन-नरेंद्र मोहन सिंह) प्रस्तुत किया।

अपने सहज और लयबद्ध चरित्रों में 'सृष्टि का आखिरी आदमी' में अनिल साह (वैज्ञानिक) एवं कु. हेमलता तिवारी (औरत बीज), 'सिंहासन खाली है' में श्यामू रोतेला (शासक) एवं सत्येंद्र पंडित (सूत्रधार), 'कथा एक कंस की' में नरेंद्र मोहन (कंस) 'जागृति' में संजु लारेंस (शासक) एवं अरविंद साह (हिमालय) और 'आक्रोश' में देवेंद्र कांडपाल (सेनानी) आशीष सिन्हा (गरीब) और रवि एंथोनी (धर्मदास) आदि ने अपने संतुलित संवाद और सशक्त भावा-



'सिंहासन खाली है' का दृश्य

भिनय से सभी प्रस्तुतियों की प्रासंगिकता को बल दिया। —सुधीर शाह

## राजधानी में दो नयी संस्थाएँ

रागरंजनी : इस नयी सांस्कृतिक संस्था ने मावलंकर प्रेक्षागृह में 22 अप्रैल, को अपने प्रथम समारोह में सुगम संगीत की एक नयी गायिका कृष्णा कुमारी को प्रस्तुत किया। इस से पहले वह कलकत्ता में थी। कृष्णा ने अपने कार्यक्रम में पहले भजन प्रस्तुत किए



## 'रागरंजनी' कार्यक्रम में श्रीमती कृष्णा कुमारी

फिर गजलें, जिन्हें श्रोताओं ने पसंद किया। उन के स्वर में मिठास है गाने का ढंग मनोहर है।

इस संगीत कार्यक्रम के पश्चात गुरु जयराम राव तथा उनकी पत्नी बनश्री ने कुंचीपूड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। इस उमरती जोड़ी ने गति, अंग-संचालन और अभिनय सभी दृष्टियों से सराहनीय नृत्य प्रस्तुत किया। —पी.

चंद्रिका कल्चरल सोसाइटी : एक और नयी सांस्कृतिक संस्था चंद्रिका कल्चरल सोसाइटी ने 8 मई को श्रीराम कला संस्कृति केंद्र में अपने पहले कार्यक्रम के रूप में उषा गुप्ता का ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। उषा गुप्ता नयी ओडिसी नृत्यांगनाओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रही हैं। अपने नृत्य-अभिनय पक्ष और कला पक्ष दोनों से अपनी साधना की छाप छोड़ती हैं। संस्था की आगे चल कर विभिन्न कला रूपों के बीच सार्थक संबंध बनाने और उन के विकास की योजना है। —स.





## जनरल गालतियारी

**फॉकलैंड द्वीपसमूह का विवाद** सम्मानजनक ढंग से तय होने की आशा है पर आर्हेतीना ब्रितानी हमले का मुंहतोड़ जवाब के लिए भी प्रस्तुत है। अपने को एक दम फौजी मानने वाले आर्हेतीना के राष्ट्रपति जनरल गालतियारी का आज यही संकट है। अप्रैल में जब उन्होंने फॉकलैंड द्वीपसमूह पर आर्हेतीना के आधिपत्य का एलान किया तो उन्होंने अपना ही नहीं, आर्हेतीना का भविष्य भी दाँव पर लगा दिया।

जनरल गालतियारी का जन्म 15 जुलाई 1926 को एक मजदूर परिवार में हुआ। सन् 1953 में उन्होंने अपने देश के सैनिक कालेज में प्रवेश लिया। फौजी इंजीनियरिंग में विशेष प्रशिक्षण ग्रहण कर सेना में आ गये और लगातार उन्नति करते गये। 1979 में वह सेनापति के पद पर पहुँच गये।

उस समय देश में फौजी प्रशासन था। मार्च 1981 में फोल्ड मार्शल रावर्टो वायोला उस के सर्वेसर्वा हो गये। लेकिन उन्हें आठ महीने भी नहीं हुए थे कि नवंबर 1981 को गृहविभाग के कर्ताधर्ता जनरल होरासियो टामस लियेंडो राष्ट्रपति बन गये। बीस दिन बाद फिर तख्तापलट गया और 11 दिसंबर 1981 को जनरल गालतियारी ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। तब से वह आर्हेतीना के फौजी प्रशासक और

राष्ट्रपति हैं।

ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर ने जनरल गालतियारी को 'जल्लाद' की संज्ञा दी है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन उन्हें एक प्रबल कम्युनिस्ट विरोधी और अमेरिका का मित्र मानते हैं।

जनरल गालतियारी छः फुट एक इंच लंबे हैं। डीलडौल के भरकम, स्वस्थ और मुद्रा के गंभीर। वह सैनिकों के सैनिक कहे जाते हैं। वह बड़े मेहनती हैं लेकिन साथ ही भव्युक भी।

आर्हेतीना की आवादी तीन करोड़ है। 6 बरस के सैनिक शासन से लोक त्रस्त हैं। नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया है। आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति बहुत चिंताजनक है। महँगाई हर महीने 10 प्रतिशत बढ़ जाती है। क्या इन सब चीजों से अपने देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए ही जनरल गालतियारी ने फॉकलैंड का विवाद रचा है। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रकार का कहना है कि फॉकलैंड का संकट उन्हें आर्हेतीना का बेताज का वादशाह बना सकता है बशर्ते कि सैनिक की अपनी देह में, राजनीतिक कुशलता के कुछ इंच भी वह दिखा पाते। —सु.

## फ्रांसिस पिम

**फॉकलैंड** को लेकर अर्हेतीना-ब्रिटेन विवाद के संदर्भ में पिछले दिनों लगातार चर्चा में रहने वाले ब्रिटेन के विदेशमंत्री फ्रांसिस पिम एक ऐसे संपन्न और



तेजस्वी परिवार की संतान हैं जिस के लोग सत्रहवीं सदी से ब्रितानी संसद के सक्रिय सदस्य रहे हैं। फ्रांसिस लेसली पिम का जन्म 13 फरवरी 1922 को आयरिश वानी काउंटी में हुआ। जब 1970 को जून में एडवर्ड हीथ के नेतृत्व में कंजरवेटिव सरकार की स्थापना हुई तो पिम मुख्य विपक्ष और कोषागार के मंत्री बनाये गये। सन् 1973 में वह उत्तरी आयरलैंड के मंत्री मनोनीत किए गए। मार्च 1974 में लेबर सरकार फिर से आ गयी और अप्रैल 1979 के अंत तक रही। इस अवधि में पिम विरोधी दल के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में चमके—श्रीमती मारग्रेट थैचर ने ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में नयी सरकार बनायी। उन्होंने उस में फ्रांसिस पिम को रक्षामंत्रालय सौंपा।

पिम स्वभाव के मधुर और बातचीत में बड़े कुशल हैं। विपक्षी पर रोज मीठी चोट करते हैं। इस कारण से वह अज्ञात शत्रु माने जाते हैं और लगातार यशस्वी होते जाते हैं। अभी उन की उम्र साठ साल की है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन के मित्रों और प्रशंसकों का मानना है कि एक दिन वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। पिम के हाल के कुछ वक्तव्यों से यह भी लगता है कि वह फॉकलैंड के मामले में हठधर्मी नहीं हैं और अपनी सरकार को शांति समझौते की सलाह अनुकूल परिस्थितियों में जरूर ही दे सकते हैं। —सु.

## चंडीप्रसाद भट्ट

**चमोली** के मुख्यालय गोपेश्वर में लोग उसे सर्वोदय नाम से जानते हैं—नाम कितने ही भ्रामक हों चिपक जाते हैं मगर दशौली ग्राम स्वराज्य संघ एक अनोखा आश्रम है जहाँ न साधु-संन्यासी रहते हैं न मठा-वीश। यह एक रचना केंद्र है जहाँ से पर्वतीय जन और वन में एक मूक क्रांति लाने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है।

और इस क्रांति की शुरुआत श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जाये तो उस का नाम चंडीप्रसाद भट्ट होगा। भट्ट जी आयु है 'राजनीति के जूते उतार कर आइए तो यहाँ स्वागत है' कुछ वर्ष पहले ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हिमालय के वनों को बचाने के लिए रेंगी के जंगलों में लोग पेड़ों से चिपके थे तो चंडीप्रसाद भट्ट ने उस 'चिपका आंदोलन' को जन्म दिया था।



की अनुगूँज देश के बाहर पर्यावरण में आज तक सुना दे रही है। सड़क मजदूरों के और मुंशी की नौकरी से कर के इस दुबले पतले पहाड़ी हिमालय की संवेदनशीलता एहसास दिलाने के लिए जो अपित किया है। हिमालय की 'भावुक बच्चे' की संज्ञा देते जरा भर भी छेड़ने से वह रोते हैं। अलकनंदा की भयंकर बाढ़ के बाद तो पर्यावरण वैज्ञानिक और आयोजक भी उन के को स्वीकार करने लगे हैं।

आज भट्टजी की संस्था एक संकट दिखायी देती है जिस के जनक भी वह स्वयं हैं। काष्ट का लघु उद्योग लीसा उन के कार्यकर्ताओं को उद्यम था मगर 'जब जंगल की प्रवृत्ति का ही विरोध है तो शुरुआत हमें अपने जंगल करनी चाहिए।' न आयोजक न चलेगा लघु उद्योग। भट्टजी साथी पहाड़ी आंचल को स्वयं बनाने के अनेक कामों में मगर स्वयं भट्टजी मुफलिशी को ही बरसा आये हैं।



# राजकमल प्रकाशन को एक और ज्ञानपीठ पुरस्कार



अमृता प्रीतम  
की काव्यकृति

कावाज और कैनक्स

ज्ञानपीठ पुरस्कार  
से सम्मानित

नागरी लिप्यन्तरण में  
अमृताजी की मूल पंजाबी कविताएँ  
और उनका  
उतना ही सुरुचिपूर्ण हिन्दी रूपान्तर

1973 में प्रकाशित प्रथम संस्करण के बाद  
अब एक अपूर्व डोलक्स संस्करण  
मूल्य : तीस रुपये मात्र



राज्य सरकारों के 40 पुरस्कार,  
2 सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार,  
9 साहित्य अकादमी पुरस्कार और  
2 ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बाद

राजकमल प्रकाशनों को  
मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्  
के तीन और पुरस्कार

‘कामताप्रसाद गुरु पुरस्कार’ से सम्मानित

भारत के प्राचीन भाषा-परिवार और हिन्दी :

डा० रामविलास शर्मा

मूल्य : प्रथम खण्ड : रु० 50.00;

द्वितीय खण्ड : रु० 60.00; तृतीय खण्ड : रु० 75.00

‘तुलसी पुरस्कार’ से सम्मानित

अपने सामने : कुँवरनारायण

मूल्य रु० 18.00

‘पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी’ पुरस्कार से सम्मानित

विकलांग श्रद्धा का दौर : हरिशंकर परसाई

मूल्य : रु० 16.00

## राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

8, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002 / शाखा : साइंस कालेज के सामने, पटना-800006

मोहम्मद एंड कंपनी लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स. 10 बरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
कार्यालय : डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएँ : 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9;  
7 ए.एस. एन. वनजी रोड, कलकत्ता-700014. कामाख्या रोड, गुवाहाटी-781005. कलकत्ता-700069; 63, मोटियम रोड, इगमोर, मद्रास-8;  
1, वीरपुत्र भवन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन एप्रोच, सडबरी, बंबई, मिडिलसेक्स, लंदन, यू.के., लंदन टेलीफोन : 01-903-9696.





स्मशियों की सुहानी घड़ी...

रीजेन्ट किंग  
 अपना की घड़ी



रीजेन्ट  
 किंग

स्वाद और ताज़गी का खुशनुमा मे

वैधानिक चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है  
 STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

SAA/SM/52A 8 H



# दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन

18-5-82

## चुनाव की लहर

निर्वाचन  
क्षेत्रों से विशेष  
समाचार



बहुगुणा



संजयसिंह

बहुगुणा गढ़वाल  
को असम बनाना  
चाहते हैं और  
हम स्वर्ग."

— संजयसिंह से विशेष भेंट



दलाई लामा को चीन  
क्यों बुला रहा है?



# टाइम्स हाउस द्वारा खेल पत्रकारिता के मैदान में एक बंपर उछाल

हिंदी में सम्पूर्ण खेल पत्रिका

# खेल भारती

जिसका लाखों पाठक न जाने कब से  
इंतजार कर रहे थे. अब हर महीने की  
पहली और १६ वीं तारीख को प्रकाशित



पहले ही अंक में आप इसमें पायेंगे : • भारत के ही नहीं  
विश्व भर के प्रमुख खेल आयोजनों का आखों देखा हाल.  
• मशहूर खेल सितारों और खिलाड़ियों के जीवंत इंटरव्यू  
• विभिन्न खेलों के नये-से-नये कीर्तिमानों की जानकारी.  
• भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दयावहारिक सूचनाएं.  
• खेलों के रोमांचक क्षणों के अनूठे अचूक छायाचित्र.  
इतना ही नहीं, और बहुत-सी ऐसी सामग्री जिसकी  
आपने कल्पना भी न की होगी.

हर खेल प्रेमी के लिए जरूरी है

# खेल भारती

A GREAT NEW AD. MEDIUM

मैनेट, कोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वतंत्राधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग प्रसेस. 10 बरियानगंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
पंजी. कार्यालय: डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएँ : 7, बहादुरशाह जकर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001; 105/7 ए, एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700014; 13/1, नर्मदेमंदिर रोड, इस्ट, कलकत्ता-700069; 63, मॉडियस रोड, इमरान, मुंबई-400001; 407-1, तीर्थ भवन, स्मार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन एग्रोच, सडबरी, बैंगलूर, मिडिलसेक्स, लंदन, यू. के., लंदन टेलीफोन : 01-903-1000



### इस सप्ताह

क्या अब भी चुनाव टलने का अंदेश है : इंदरजीत सिंह; पेनाल्टी किक के भरोसे : गढ़वाल से जवाहरलाल कौल; युवा इंडका नेता संजयसिंह से बातचीत; चुनाव के भेंवर में प्रतिष्ठा की नावें : हरयाणा से महेश्वरदयालु गंगवार; पश्चिम बंगाल, हिमाचलप्रदेश, केरल राज्यों से और उदयपुर, बयाना तथा जबलपुर संसदीय क्षेत्रों से विशेष रपटें. पृ. 15 से 25 और पृ. 28 से 31. दलाई लामा को चीन क्यों बुला रहा है पृ. 7, चीन में प्रशासनिक परिवर्तन 35.



पृ. 17



पृ. 18



पृ. 7

मत और सम्मत 4, पिछले सप्ताह 5-6. पत्रकार संसद 6. उनका कहना है 9. शिक्षा 10. भूमि संघर्ष 11. चरचे और चरखे 12. विल्ली के रंग 13. युवा जगत 14. दुनिया भर की 39. खेल और खिलाड़ी 40. विज्ञान 42. साहित्य 43. नृत्य नाट्य 44. कला 46. फिल्म 48, संस्कृति समाचार 49. चरित चर्चा 50.

### संपादक : कन्हैयालाल नंदन

संपादकीय सहकर्मी : जितेंद्र गुप्त (सहायक संपादक), सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (मुख्य उपसंपादक), श्यामलाल शर्मा, जवाहरलाल कौल, शुक्ला वद, त्रिलोक दीप, महेश्वरदयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, बनवारी, विनोद भारद्वाज और सुषमा पाराशर.

विशेष संवाददाता : रामसेवक श्रीवास्तव  
सज्जा : रवि शर्मा

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन  
10, बरियागंज, नयी दिल्ली-110002

### पाठकों से

महेश्वरदयालु गंगवार

जवाहरलाल कौल

देश के चार प्रदेशों—पश्चिम बंगाल, केरल, हरयाणा और हिमाचल की विधानसभाओं के आमचुनावों के साथ 15 विधानसभाई और 7 लोकसभाई सीटों के उपचुनावों में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के अपने मताधिकार का उपयोग करने की तैयारियां पूरी हैं. पिछली बार श्रीमती गांधी की पार्टी इन चारों प्रदेशों में बहुमत प्राप्त कर सकने में असफल रही थी लेकिन बाद में हरयाणा के थोक 'आयाराम-गयाराम' प्रकरण तथा हिमाचल में जनता दलबदल ने इंदिरा कांग्रेस को सत्ता में प्रतिष्ठापित कर दिया था. इस बार के चुनावों में मतदान के एक सप्ताह पहले तक भी पश्चिम बंगाल को छोड़कर तस्वीर इतनी साफ नजर नहीं आ रही कि कुर्सी किस दल का वरण करेगी. पश्चिम बंगाल से हमारे प्रतिनिधि ने स्पष्ट लिखा है कि "चुनाव-प्रचार और आम सभाओं को देखने से साफ लगता है कि राज्य में वामपंथी दलों की पकड़ काफी मजबूत है और कांग्रेस (इं) के लिए उन्हें उखाड़ फेंकना सहज नहीं है." ऐसा नहीं कि वहाँ के इंडका उम्मीदवारों को इस बारे में कोई गलतफहमी है. एक उम्मीदवार के मुताबिक : "अगर मैं न जीत सका तो भी 'फाँका माढ़े गोल होते देवोना'.

इधर गोल न करने देने या कर ले जाने की होड़ में हर उम्मीदवार अपना जोर लगाये है तभी बीच बीच में ये आवाजें भी उठने लग जाती हैं कि अंततः चुनाव स्थगित भी हो सकता है. इंदरजीत जी ने इस बार अपने 'समयचक्र' स्तंभ में इसी बात को गहराई से वितुनकर देखने की कोशिश की है कि इन शंकाओं के आधार क्या हैं और उनके निवारण के लिए किया क्या गया है : "तब भी किसी एक आघ चुनाव क्षेत्र में चुनाव को निरस्त कर देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता."

असाधारण परिस्थितियों वाले ऐसे अपवादों को छोड़ कर बाकी कहाँ किसका अँट किस करवट बैठने वाला है इसकी सीधी और सच्ची रपट पेश करने के लिए 'दिनमान' ने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को जागरूक रखने के साथ-साथ अपने दो युवा संवाददाताओं जवाहर लाल कौल और महेश्वरदयालु गंगवार को दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया. कौल ने गढ़वाल की पहाड़ी घड़कों को पढ़ने के लिए देहरादून से लेकर गोपेश्वर तक की खाक छानी : "गोपेश्वर से तीस किलोमीटर दूर नंद प्रयाग में एक किसान ने कहा कि प्रलोमनों से लोग बदल तो जाते हैं मगर अशिक्षित सही, पहाड़ी ग्रामीण इतना बेवकूफ नहीं है कि वह एकदम रातों रात पलट जाये."

वकौल जवाहरलाल कौल पहाड़ी इलाकों में बहुगुणा का पलड़ा मारी हो सकता है लेकिन तराई में युवा इंडका नेता संजयसिंह की चुनाव रणनीति ने जरूर तस्वीर पलटी हुई है. इस पर अपने अपने दावे हैं लेकिन गढ़वाल में इंदिरा कांग्रेस के चुनाव नियामक संजयसिंह का कहना है कि "बहुगुणा गढ़वाल को असम बनाना चाहते हैं और हम स्वर्ग." (देखिए दिनमान से उनकी दोटूक बातचीत पृ. 18-19 पर)

लेकिन संजयसिंह की सर्वशक्तिमंत नेता श्रीमती गांधी का चुनाव अभियान इस तरह के प्रलोमनपूर्ण दावे करने से कोसों दूर है. जिन दिनों गंगवार हरयाणा में गाँव गाँव चक्कर काट रहे थे, श्रीमती गांधी हरयाणा का चुनाव दौरा पूरा कर रही थीं. गंगवार ने अपनी रपट के लिए तीन दिनों में लगभग सात सौ किलोमीटर सफर पूरा किया. "लोगों तक पहुँचने के लिए मैंने हेलीकॉप्टर छोड़ कर अपने वश में जो भी साधन संभव थे, सभी अपनाये. जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पैदल भी चला."

आइए देखें 'लघु आम चुनाव' की संज्ञा वाली इस लोकतंत्रीय प्रक्रिया पर विभिन्न क्षेत्रों की घड़कनें क्या कहती हैं और किस उम्मीदवार का अँट किस करवट बैठती है.

*Handwritten signature and text at the bottom right of the page.*



## दुआ कीजिए नफरत न हो

18 अप्रैल : 'दुआ कीजिए कि हम में फिर जंग न हो' पढ़ा. इस तरह का लेख कितने उन लोगों को अब तक पढ़ने को नहीं मिला होगा जो पाकिस्तानियों से नफरत करते आये हैं. खुद मुझे पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के बाशिन्दे हिंदुस्तानियों के प्रति इतनी हमदर्दी रखते हैं. वैसे, अपवाद कहाँ नहीं होते. हम हिंदुस्तानियों को भी चाहिए कि पाकिस्तानी भाई वहाँ के प्रति सद्व्यवहार करें एवं अच्छी निगाहों से देखें. मुझे उम्मीद है कि इस तरह के लेख आपसी सद्भावना बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर सोची जा रही मैत्री संबंधों का आधार होंगे. —विनोद कुमार, द्वारा—श्री नंदकुमार प्रसाद सिन्हा, (इंजीनियर) उत्तरी मंदिरी (द्वारका स्कूल के पीछे) पटना

## बाल्टी बाबा क्यों ?

उत्तरप्रदेश आवश्यक वस्तु निगम के नये अध्यक्ष बहुचर्चित तांत्रिक बाल्टी-बाबा, जो मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों में हैं, बनाये गये हैं. बाल्टी बाबा कई राजनैतिक नेताओं को विश्वास में ले चुके हैं, उस में प्रमुख समाजवादी नेता राजनारायण भी हैं, जो डा. लोहिया के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं. (ज्ञातव्य हो, डा. लोहिया ने कभी तांत्रिकों के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया). नेतागण राजनैतिक बुद्धि लगा कर थक गये. अब तंत्र-मंत्र से शासन चलेगा. बाल्टी बाबा विधान परिषद के लिए इका के प्रत्याशी बनते बनते रुक गये. प्रधानमंत्री का कहना है—एक तांत्रिक को एकाएक ज्यादा अधिकार देना ठीक नहीं. जनता बुरा मानेगी. मेरा कहना है—जनता बुरा नहीं मानेगी क्योंकि वर्षों से तांत्रिकों एवं धार्मिक ठेकेदारों से आशीर्वाद प्राप्त का

मुहिम तो वरिष्ठ राजनेता चला ही रहे हैं और जनता इन सब चीजों को देखने सुनने की आदी हो गयी है.

बाल्टी बाबा अनेक अपराधिक मुकद्दमों में अभियुक्त रह चुके हैं लेकिन तंत्र-मंत्र के बल पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने तथा जटिल से जटिल समस्याओं को मुलझाने का आश्वासन दे चुके हैं. —बच्चानंद सिंह, शोध छात्र, 29, अधर छात्रावास, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

## युवकों की हताशा

2 मई : चरचे और चरखे पड़ा. मात्र 'नौ घंटे के नाटक' के नेपथ्य में प्रच्छन्न एक ज्वलंत समस्या को रेखांकित करने का आकर्षक प्रयास निःसंदेह प्रशंसनीय है. आज जब समस्त राजनैतिक दल येन केन प्रकारेण विद्या मंदिर के पुजारियों को उन के मुख्य उद्देश्य से दिग्भ्रमित करने में व्यस्त हैं और उन का प्रयोग निहित स्वार्थवश भावी निजी दलीय पृष्ठभूमि बनाने में कर के देश के सुखमय भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं तो उन से एक स्वस्थ दिशा निर्देशन की अपेक्षा भला कैसे की जा सकती है. फलतः अब ऐसी स्थिति में अनियंत्रित संवेदनशील (और शायद हताश भी) युवावर्ग उचित अनुचित सभी निर्णय स्वयं लेने पर विवश न हो तो क्या हो.—राजीवकुमार शुक्ल, 46, सर सुंदरलाल छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

## विकास कर का अर्थ क्या है ?

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने घोषणा की है कि वह अगले सत्र से हर पांच माह के अंतराल पर प्रति छात्र 5 रु. वसूल करेंगे जिसे विश्वविद्यालय के विकास में लगाया जायेगा. वकौल कुलपति के विकास का अर्थ है : इमारत, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि आदि. वे सब सामग्री जिन में छात्र नहीं आते. साठ हजार छात्र वाले विश्वविद्यालय को कुल तीस



'जो हाँ! कल ही इन्हें खरीबा था. तब तब विकास की परिभाषा थी किताब पढ़ना. अब विकास के लिए रुपया चाहिए.'

लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी जिस का लेखा जोखा देखने के लिए एक अलग विभाग बनाया जायेगा. मजे की बात तो यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता श्रीमती माधुरी शाह ने अपनी सहमति दे दी है. एक छात्र होने के नाते हम व्यक्तिगत रूप से कुलपति श्री गुरुवर्षा सिंह और श्रीमती माधुरी शाह से विकास का अर्थ जानना चाहेंगे जिस के एवज में इस महँगी शिक्षा नीति में 5 रु. अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है. इस कठिन विकास में क्या छात्रों को हुनर और दिमाग की शिक्षा दी जा सकेगी? क्या उन्हें रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी? यदि नहीं तो मेहनत बानी कर के स्वतंत्र भारत का संविधान का कष्ट करें जिस में शिक्षा सामग्री जुटाने का जिम्मेदारी राज्यसत्ता पर होने का उल्लेख है.—शिवकुमार, अध्यक्ष, छात्र संघ, का. वि. वाराणसी; रामकृष्ण चौबे, अध्यक्ष, छात्रसभा, उ. प्र. वाराणसी

## पुलिस जुल्म की कथा

गत 15 अप्रैल को सिंहभूम के शौर्यपदक अशोकचक्र विजेता श्री गंगाराम को वहाँ की दुलारुआ पुलिस ने बड़ी बेरहमी तथा बेहयाई के साथ राइफल के कुंदे से मार डाला. ऐसा जघन्य अपराध कर पुलिस ने अपने जुल्म पर एक और मुहर लगाते हुए एक प्रश्नचिह्न भी खड़ा कर दिया है. शहीद गंगाराम का जुर्म सिर्फ इतना ही था कि वह अपने कार्यक्षेत्र में विस्थापितों को बसाने की माँग को ले कर संघर्ष कर रहे थे. आश्चर्य एवं खेद है कि जिसने तपते रेगिस्तान, ठिठुरती ठंडक, उमड़ते सैलाव में देश पर आँच नहीं आने दी, दुश्मनों का मुँहतोड़ जवाब देते हुए राष्ट्रीय सम्मान (अशोक चक्र) प्राप्त किया उस के साथ इतनी बड़ी घटना पत्र पत्रिकाओं में अपनी कोई जगह न ले सकी. जब कि मंत्री महोदय के खासी होने के समाचार समाचारपत्रों में अच्छी खासी जगह ले लेते हैं. हाँ, कुछ ईमानदार समाचारपत्रों ने इसे प्रकाशित किया, जिस से कुछ लोगों को इस की जानकारी मिली. इस शर्मनाक घटना के बाद भी न तो किसी नेता ने, न पुलिस अफसरों, न ही पुलिस यूनिटन के नेताओं ने उस वीर सपूत के खो जाने की देश से क्षमा माँगी और न ही सेवानिवृत्त सैनिक संघ ने इस की निंदा की.—शंभू प्रताप सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, मंगतराम, लक्ष्मीनारायण रस्तोगी, अजयकुमार आजाद, सदस्य गण युवा समाज कल्याण समिति, पटना

## शिक्षक हड़ताल क्यों न करें?

12 अप्रैल से बिहार के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पठन पाठन ठप्प है कि शिक्षकगण अनिश्चित काल के लिए अपने माँगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं. माँगें उचित हैं या अनुचित यह कोई भी ईमानदार नौकर करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने वेतन की पड़ताल में रह कर जान सकता है. महँगाई के इस दौर में रुपये की बाजार कीमत कितनी रह गयी है यह सर्वविदित है. इस आर्थिक परिस्थिति में शिक्षक या कोई ईमानदार वेतनभोगी नौकर करे? लेकिन छात्रों का भविष्य हड़ताल की सफलता या असफलता से बुरी तरह से जुड़ा हुआ है. यदि किसी कपड़ा मिल या कारखाने की हड़ताल होती है तो सरकार चिंतित हो उठती है



# पिछले सप्ताह

1-7 मई, 1982

देश

- 1 मई : केंद्र सरकार द्वारा दल खासला पर प्रतिबंध, अमृतसर के गुरुद्वारों के आसपास तंबाकू, मांस और शराब की विक्री पर रोक, कास्बा में आतंजमागियों की हत्या के बारे में केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भैरवदत्त पांडे से रपट की मांग।
- 2 मई : कांग्रेस (इं) द्वारा चुनाव घोषणापत्र जारी। अमृतसर और पटियाला में हिंसा की छिटपुट घटनाएं, उद्योगपति मोहनलाल जालान का कलकत्ता में देहांत, भारत के विदेशमंत्री नरसिंह राव और ईरान के विदेशमंत्री अली अकबर विलायती द्वारा नयी दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अफगान संकट समाप्त करने का आह्वान।
- 3 मई : कांग्रेस (एस) नेता और विख्यात वकील रजनी पटेल का बंबई में देहांत, प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा नवें एशियाई खेलों संबंधी निर्माणकार्य का निरीक्षण, पटियाला और अमृतसर में कर्फ्यू की अवधि में बढ़ोतरी, श्रीलंका के 73,900 परिवारों का पुनर्वास।
- 4 मई : श्रीमती गांधी का चुनाव दौरा शिमला से शुरू और प्रतिपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर प्रहार, 17 मई से भारतीय और चीनी प्रतिनिधिमंडलों में नयी दिल्ली में बातचीत करने का निश्चय।
- 5 मई : लोकदल द्वारा जारी अपने चुनाव घोषणापत्र में कृषि को प्राथमिकता, असम बंद की पूर्वसंध्या पर 60 व्यक्ति गिरफ्तार, राज्यसभा द्वारा वित्त विधेयक का अनुमोदन।
- 6 मई : असम बंद के कारण राज्य में जनजीवन अस्तव्यस्त, श्रीमती गांधी द्वारा केरलवासियों को स्थिर सरकार का आश्वासन, राज्यसभा में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर तीखी बहस।
- 7 मई : कलकत्ता में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा पश्चिम बंगाल में मतदान की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त, असम के नेताओं द्वारा आंदोलन जारी रखने का निश्चय, पंजाब में सामान्य वातावरण का सरकार का दावा, भविष्य निधि की व्याप्ति दर में बढ़ोतरी।

हैं क्योंकि इस से उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। सरकार वार्ता एवं समझौता के लिए पहल करती है। लेकिन क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि बिहार सरकार वार्ता करने से साफ इंकार कर रही है। इस से साफ होता है कि हमारी जन प्रतिनिधि सरकार छात्रों तथा शिक्षकों के प्रति कितनी संवेदनशील है।

22 अप्रैल से शिक्षकगण अपनी गिरफ्तारी रहे हैं बिहार के सभी पुरुष तथा स्त्री शिक्षकों को क्रमशः विशेष कारा एवं केंद्रीय कारा में रखा जा रहा है। लेकिन दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि सरकार की हठधर्मिता के कारण उन्हें साधारण कैदियों की श्रेणी में रखा जा रहा है। उन की जायज मांगों के समान ही जेल के भीतर भी शिक्षकों को उन के हक से इंकार किया जा रहा है। —परमानंद राय, राष्ट्रीय अंग्रेजी विभाग, संस्था महाविद्यालय, भागलपुर

## नेपाल में चुनाव का मतलब क्या

नेपाल में ग्राम एवं जिला पंचायत के चुनाव इसी मई महीने में संपन्न होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। नेपाल में राजनैतिक पार्टियाँ प्रतिष्ठित हैं। तब भी जिला से ले कर केंद्र तक विभिन्न नेताओं, सब का अपना गुट अलग अलग हैं। केंद्र में वर्तमान प्रधानमंत्री थापा का गुट मू. पू. प्रधानमंत्री मातृकाप्रसाद कोइराला का गुट मुख्य है। थापा सरकार के कार्यकाल में नेपाल में बढ़ती हुई महंगाई, तस्करी, भ्रष्टाचार एवं जंगल विनाश के प्रश्न को ले कर एक वर्ष से तीव्र विरोध होता जा रहा है।

आप फरमाते हैं

व्यंग्य चित्र : लक्ष्मण



में कितने ही राष्ट्रीय पंचायत सदस्यों ने खुला विरोध किया लेकिन आश्चर्य है उन के मंत्रिमंडल में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिला चुनाव में थापा जिले में अपना पक्षीय उम्मीदवार जिताने की प्रयत्नशील हैं। तराई में गत आम निर्वाचन जैसे ही भारतीय क्षेत्र में गुंडे, लठैत, तीरकमान वालों का मगवाया जा रहा है। कितने ही मतदान केंद्र लूटे जायेंगे कितने लोग घायल होंगे? शक्ति के आधार पर चुनाव जीते जायेंगे? जैसे गत आम निर्वाचन में हारे हुए उम्मीदवार की याचिका की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, वैसे ही इस बार भी नहीं होगी इस में कोई संदेह नहीं है। —राम नारायण देव, संपादक, चंद्रोदय, बिसहरिया, राजबिराज (नेपाल)

## उन्होंने अपना जीवन दिया, आपके पास शब्द भी नहीं

25 अप्रैल : जिसने अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 40 वर्ष अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में काटे, उस की मृत्यु पर ज्यादातर पत्रिकाएं खामोश रहीं। मैं तो समझ रहा था कि दिनमान में पंडित परमानंद की जीवनी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का विस्तृत वर्णन होगा। लेकिन आपने इतना ही छापा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। विख्यात क्रांतिकारी और साहित्यकार मन्मथनाथ गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि आज शुरू से ही, जब वृद्धा क ख ग सीखना शुरू करता है, तो उस के दिमाग में यह भरना शुरू कर दिया जाता है कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलायी और दूसरे पहलू का कोई जिक्र नहीं होता जो कहीं अधिक उज्ज्वल और गौरवमय है। —विजय कैंसर, 25-बी, नार्थ कालानी, साहिबगंज, संथाल परगना (बिहार)

## कोयले की दलाली में मुंह काला

देश में बढ़ रही महंगाई, व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कानून की बिगड़ती हुई रूपरेखा के लिए इका सरकार को जिम्मेदार बताने वाले कांग्रेस (श) और जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के आगामी 19 मई को होने वाली विधानसभा चुनाव में इका का ही सहारा लेने जा रहे हैं। जनसाधारण यह समझ नहीं पा रहा है कि स्वयं को इका का विकल्प कहने का दावा करने वाले ये विपक्षी नेता किस भाषा में बात कर रहे हैं। यदि इका कालिख की कोठरी है तो इस की दीवारों से सटने वाले ये नेता बेदाग कैसे रह पायेंगे। —सतीश मापतपुरी 'निर्मल' पत्रकार, सिविल लाइन, नहर क्षेत्र, बक्सर, जिला भोजपुर (बिहार)

मिल मालिकों से सहानुभूति इसलिए है कि मैं ही इस मिल का मालिक हूँ।



विदेश

- 1 मई: ब्रितानी विमानों द्वारा फॉकलैंड की हवाई पट्टी पर हमला. भारतीय क्रिकेट टीम का लंदन आगमन. मई दिवस के अवसर पर सोवियत राष्ट्रपति कियोमिच जेजनेव द्वारा लोगों का अभिवादन. अल् सात्वाडोर में विद्रोहियों द्वारा बमबारी.
- 2 मई: संयुक्तराष्ट्र महासचिव जेवियार पेरैज दे कूलार द्वारा फॉकलैंड समस्या का परस्पर चर्चा से समाधान करने का प्रस्ताव. सोवियत संघ द्वारा परमाणु युद्ध के विरुद्ध प्रभावकारी कदम उठाने पर सहमति.
- 3 मई: ब्रिटेन द्वारा आर्जेंटीना के एक युद्धपोत का डूबोया जाना. वरशावा में सॉलिदारनोरेब के समर्थकों पर अभूतिस. राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का इब्रिज (आयरलैंड) पहुँचने पर अभ्य स्वागत. अमेरिका द्वारा एफ-5 जी विमान युद्धन को बेचने का निर्णय. विश्व विख्यात धावलनबादक विलियम फ्राइमरोज का प्रोबो (अमेरिका) में देहांत.
- 4 मई: ब्रिटेन द्वारा आर्जेंटीना के डूबोये गये पोत से 680 नौसैनिक सुरक्षित. ईरान के प्रहार का इराक द्वारा कड़ा प्रतिरोध. ब्राजील द्वारा आर्जेंटीना को विमान बेचने की पुष्टि. अल्जीरिया के विदेशमंत्री बिन याह्या की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु. चीन के 11 उपप्रधान-मंत्री बर्खास्त.
- 5 मई: चीन में छह नये उपप्रधानमंत्री नियुक्त. ईरान में 11 व्यक्तियों को फाँसी पर लटकवाया जाना. अमेरिका का शिखर चार्जी के लिए सोवियत संघ के साथ नियमित संपर्क. आर्जेंटीना द्वारा अपनी मुद्रा पेसो का 16.8 प्रतिशत अवमूल्यन.
- 6 मई: ब्रिटेन और आर्जेंटीना द्वारा फॉकलैंड पर संयुक्तराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार. इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुहर्तो की गोप्यकर पार्टी की भारी विजय. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पीकिङ में चीनी नेताओं से ताइवान को अस्व बेचने संबंधी मुद्दे पर चर्चा.
- 7 मई: ब्रिटेन द्वारा फॉकलैंड में युद्ध क्षेत्र का विस्तार. पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्नह हक द्वारा देश की भविष्य की शासन प्रणाली के लिए सक्रिय सैनिक भूमिका का उल्लेख.

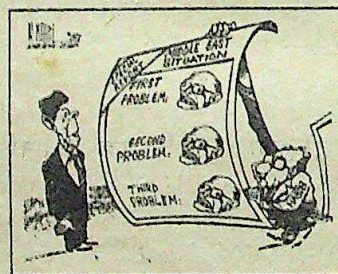
# "हम ठीक हैं : वे गलत हैं"

भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हाल ही की साऊदी अरब यात्रा को ले कर पाकिस्तान के समाचारपत्रों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. अफगानिस्तान में सोवियत सेना की मौजूदगी को ले कर भारत की विदेश नीति को कड़ी आलोचना प्रायः सभी पाकिस्तानी पत्रों ने की है. कराची के मानिंग न्यूज का विचार है:

"साऊदी अरब के नेताओं के साथ दो मुद्दों पर जरूर बातचीत हुई है. अमेरिका से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के प्रति भारत का अवास्तविक रवैया और अफगानिस्तान के भीतर मामलों में सोवियत हस्तक्षेप के कारण कोई 26 लाख अफगानियों का बेघर हो जाना. दोनों प्रश्नों पर साऊदी अरब का रवैया तो बिल्कुल स्पष्ट है. यह तो सब को याद ही होगा कि कुछ समय पहले साऊदी अरब सरकार ने गुटनिरपेक्ष देशों के विदेशमंत्रियों के नयी दिल्ली सम्मेलन में भाग नहीं लिया था. कारण इस का अफगानिस्तान के प्रति भारत का अवास्तविक रवैया इस्लामी देश अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने खुल्लम-खुल्ला आक्रमण किया और भारत उस का समर्थन कर रहा है. इस से साऊदी अरब नेताओं में उत्तेजना होना स्वाभाविक ही है. फिर भारत के इसाइल से निकट के संबंध हैं जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन है. अगर साऊदी अरब नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी है तो यह अस्वाभाविक नहीं है.

कराची के उर्दू समाचारपत्र जसरत ने रियाद के संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भाषा और विचारों पर आपत्ति की है. पत्र का कहना है

"अपनी चार दिन की साऊदी अरब यात्रा के बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी है वह आपत्तिजनक तो है ही साथ ही वास्तविकता से भी दूर है. कहना चाहिए इतिहास के तथ्यों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयत्न किया. पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है अगर हम पाकिस्तान को न मानते तो यह समूचा उपमहाद्वीप विभाजित न होता. श्रीमती इंदिरा गांधी



पाश्चिमेशिया की समस्याओं पर अरबन्यूज के एम काहिल का व्यंग्य.

को बल प्रयोग द्वारा अलग कराने सहित बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता. फिर यह कहना बहुत हास्यास्पद लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं. यह सारा अत्याचारों के शिकार है. वास्तव में भारत में अधिक शिकार है. आंकड़ों के अनुसार हर बीघे में भारत में एक सांप्रदायिक दंगा होता है.

उधर पाकिस्तान में प्रांतों को स्वायत्तता देने के प्रश्न पर काफी विवाद हो रहा है. प्रांत का समय से और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं पर पाकिस्तान सरकार ने अभी तक प्रश्न पर अपनी नीति स्पष्ट की है. कराची के मशरिफ ने इसे अव्यवहारिक बताया है. पत्र का कहना है

"राष्ट्रपति जिन्ना उल हक ने एक अमेरिकी पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था कि 1973 के संविधान के अंतर्गत प्रांतों को और अधिक स्वायत्तता देने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ. संविधान चूंकि सर्वसम्मति से बना है इसलिए उस में संशोधन की गुंजाइश नहीं है.

इस प्रकार राष्ट्रपति ने दो बुनियादी बातें स्पष्ट कर दी हैं. पहली तो यह कि ऐसा संविधान ही गलत है कि पाकिस्तान में चार जातियां हैं दूसरे यह दलील बेमानी है कि केंद्र को प्रांतों के मामलों में दखल देने का हक नहीं है. 1973 के संविधान में केंद्र और प्रांतों के अधिकारों को स्पष्ट से तय किया गया है. प्रांत स्वयं इस से संतुष्ट है पर यह मांग करना कि रक्षा, वैदेशिक मामलों और मुद्रा प्रणाली छोड़ कर सभी कुछ प्रांतों को दे दिया जाये व्यवहारिक नहीं है. इस के खतरनाक नतीजे भी निकल सकते हैं. □

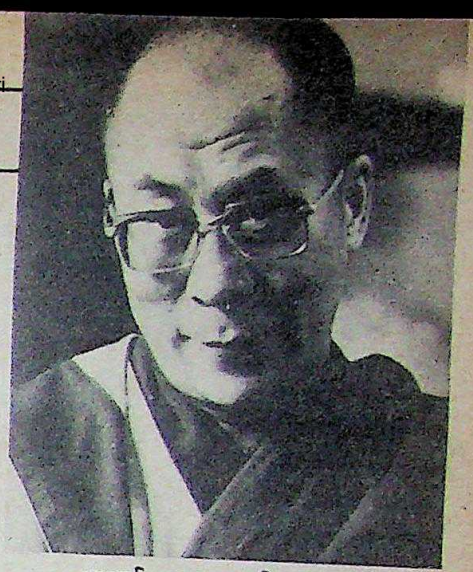
चीन-ति  
द  
अप्रैल के  
द्वारा अ  
बेचे जाने  
बातचीत का  
गया है, जो  
उस समय द  
हालत का  
प्रतिनिधिमंड  
उन में से ए  
चीन ने सम  
कर दिया था  
किया गया  
की एक जन  
के विरुद्ध मड़  
ने इस कार्य  
विसिपाहट व  
कहना था कि  
ज से मिलने  
निवृत्तियों ने  
बागादी के स  
शासन के विर  
या. उन का य  
में से एक था,  
यात्रा के दौर  
मंडल के अनु  
नीति प्रतिनि  
प्रकारों के उ  
जिसे चीन सर  
निवृत्त यात्रा  
निवृत्त पर ची  
हली बार ए  
प्रकारों ने अ  
इस घटना  
रु गयी थी. ज  
प्रांतों सदस्यों ने  
के अव्यक्ष लो  
पीकिङ पहुंचने  
हो की मुख ह  
नारा आयोजित  
श एकदम बा  
नी समय तिब  
र रहे तीसरे  
पीकिङ शासकों  
शयक्रम पूरा क  
बातचीत का नि  
पहले से निर्वा  
शासकों ने चौथे  
रु कह कर प्रवे  
विमान



चीन-तिब्बत

# दलाई लामा को चीन क्यों बुला रहा है

विजय क्रांति



दलाई लामा : नयी साख

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दलाई लामा द्वारा अपना चौथा प्रतिनिधिमंडल चीन भेजे जाने से घर्मशाला—पीकिङ के बीच बातचीत का वह सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जो 1980 में अचानक टूट गया था। उस समय दलाई लामा ने तिब्बत की भीतरी हालत का जायजा लेने के लिए जो तीन प्रतिनिधिमंडल तिब्बत यात्रा पर भेजे थे, उन में से एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को चीन ने समय से एक सप्ताह पहले ही मंग कर दिया था। चीन के अनुसार यह इसलिए किया गया क्योंकि प्रतिनिधियों ने ल्हासा की एक जनसभा में लोगों को चीनी शासन के विरुद्ध भड़काया था। दूसरी ओर प्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई को महज चीनी शासकों की तिसियाहट का नतीजा बताया था। उन का कहना था कि उन के गेस्ट हाऊस के बाहर उन से मिलने के लिए आये लगभग दो हजार तिब्बतियों ने दलाई लामा और तिब्बती राजादी के समर्थन में तथा तिब्बत पर चीनी शासन के विरोध में अपने आप प्रदर्शन किया था। उन का यह प्रदर्शन उन दर्जनों प्रदर्शनों में से एक था, जो उन्हें अपनी तीन महीने की यात्रा के दौरान देखने को मिले। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इस प्रदर्शन पर तोखी चीनी प्रतिक्रिया का असली कारण विदेशी सरकारों के उस दल की वहाँ मौजूदगी था, जिसे चीन सरकार ने अपने प्रचार के लिए तिब्बत यात्रा पर विशेष रूप से बुलाया था। तिब्बत पर चीनी शासन के तीस वर्षों में पहली बार ऐसे किसी प्रदर्शन को विदेशी सरकारों ने अपनी आँखों से देखा था। इस घटना की कड़वाहट तब और भी बढ़ गयी थी। जब तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के अग्रणी सदस्यों ने, जिन में तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष लोसांग जिपा भी शामिल थे, पीकिङ पहुँचने पर चीन फैसले के विरुद्ध 36 घंटे की भूख हड़ताल की और चीन सरकार द्वारा आयोजित उन के चीन यात्रा कार्यक्रम का एकदम बहिष्कार कर दिया। हालांकि उसी समय तिब्बत के अन्य भागों में यात्रा कर रहे तीसरे तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को पीकिङ शासकों ने अक्टूबर तक अपना यात्रा कार्यक्रम पूरा करने दिया लेकिन उसके बाद बातचीत का सिलसिला लगभग टूट गया। पहले से निर्धारित शर्तों के बावजूद चीनी शासकों ने चौथे तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को यह कह कर प्रवेश की अनुमति नहीं दी कि

जो कुछ तीन प्रतिनिधिमंडलों ने देख लिया वह फिलहाल काफी है। यह भी कहा गया कि क्योंकि तिब्बत में चीन की नयी नरम नीति के फल दिखाई देने में अभी कुछ और समय लगेगा इसलिए अगले प्रतिनिधिमंडल को अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। ज्ञातव्य है कि बातचीत और यात्राओं का यह सिलसिला निर्वाचित तिब्बती शासक दलाई लामा को तिब्बत वापस लौटने के चीनी निमंत्रणों की ही परिणति है।

पिछले कई वर्षों से आ रहे चीनी बुलावों पर दलाई लामा की प्रतिक्रिया यह रही है कि जब तक वह इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते कि तिब्बती जनता चीनी शासन में सुखी है, तब तक वह चीन अधिकृत तिब्बत में वापस जाने की बात सोच भी नहीं सकते। शायद इसी कारण से चीन ने दलाई लामा की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों को तिब्बत यात्रा की छूट देना मान लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त तीनों शरणार्थी प्रतिनिधिमंडलों को पीकिङ सरकार की ओर से तिब्बत में घूमने की व्यापक छूट दी गयी। हालांकि कुछ प्रतिनिधियों ने समय समय पर चीनी अधिकारियों द्वारा उन के कार्यक्रमों में फेरबदल करने और उन की गतिविधियों की जासूसी करने आदि के आरोप लगाये हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्हें उन विदेशी

पत्रकारों और मेहमानों के मुकाबले कहीं अधिक नजदीक से तिब्बत की असली हालत देखने को मिली। जिन्हें चीनी शासकों ने चीनी दुमाधियों और अफसरों की देखरेख में तिब्बत के कुछ चुने हुए क्षेत्रों का दौरा कराया है। पहले प्रतिनिधिमंडल को छह मास, दूसरे को तीन मास और तीसरे को चार मास तक तिब्बत के केंद्रीय, उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों का व्यापक दौरा करने का अवसर मिल पाये।

लेकिन इस का अर्थ यह भी नहीं कि चीनी शासक इस सब तमाशे को आँख मूंद कर देखते रहे हैं। चीनी प्रचार तंत्र और आज कल चीन को प्रसन्न करने की होड़ में लगे पश्चिमी प्रेस के माध्यम से उन्होंने सारे मामले को दुनिया के सामने इस तरह पेश किया है मानो दलाई लामा और उन के नेतृत्व में देश निकाले में रह रहे एक लाख तिब्बती शरणार्थी अब हताश हो कर तिब्बत लौट आने को उत्सुक हैं और इस उत्सुकता में वे तिब्बत को चीनी मातृभूमि का अभिन्न अंग मान



आम्दो प्रांत के कुंभुम मठ के बाहर स्थानीय तिब्बती जनता द्वारा प्रतिनिधियों का स्वागत



लेने के लिए तैयार हैं। कुछ प्रेक्षकों का तो यह भी विचार है कि प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा के दौरान हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों आदि से चीनी शासकों को राष्ट्रवादी तिब्बती तत्त्वों को पहचानने और बाद में उन से निबटने का भी अवसर मिला है।

इस लेखे जोखे में दलाई लामा पक्ष को मिले लाभ का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पीकिङ्ग के साथ इस आदान प्रदान में दलाई लामा को सब से बड़ा लाभ हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्रों में एक नयी राजनैतिक साख का। इस से पहले चीनी नेता दलाई लामा को 'महज मुट्ठी भर डाकुओं के गिरोह का सरगना और अमेरिकी प्रतिक्रियावादी कुत्ता' जैसे विशेषणों से पुकारते रहे हैं और यह दावा करते रहे हैं कि तिब्बती जनता पर उन का प्रभाव नहीं है। अब अचानक ही पहल करके दलाई लामा को 'महान मातृ-भूमि' की बाहों में लौटने और 'विशाल चीनी राष्ट्र' की प्रगति में बराबर के भागीदार होने के निमंत्रण दे कर और समझौता वार्ता की मेज पर उतर कर चीन ने कम से कम यह तो स्वीकार कर ही लिया है कि तिब्बती समस्या के संदर्भ में दलाई लामा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हैं। चीन के सामने अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि देश निकाले में बीस वर्षों से अधिक समय तक रहने के बावजूद दलाई लामा के लिए तिब्बती जनता के



चीनी प्रचार के चीचड़े

दिलों में आज भी गहरा आदर है। शायद यही कारण है कि चीनी शासक दलाई लामा को वापस तिब्बत ला कर अपनी वे समस्याएँ हल करने के लिए उतावले हैं, जिन्हें वे तीस वर्ष तक अपनी फौजी दखलदाजी के बावजूद हल नहीं कर पाये। इन में सब से बड़ी समस्या है तिब्बतवासियों के मन में चीनी सैनिक शासन के विरुद्ध घृणा और उन के साथ विदेशी आक्रांता जैसा व्यवहार।

तिब्बती प्रतिनिधिमंडलों की तिब्बत यात्रा का एक अन्य विशेष लाभ हुआ है तिब्बत की भीतरी हालत की सही जानकारी के रूप में। दलाई लामा की निर्वासित सरकार के मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य, जो पहले प्रतिनिधि मंडल में थे, के शब्दों में—'हमने जिस हालत की कल्पना की थी, तिब्बती जनता की असली हालत उस से भी कहीं खराब है। इस यात्रा ने चीन के असली इरादों के बारे में हमारी आंखें खोल दी हैं।

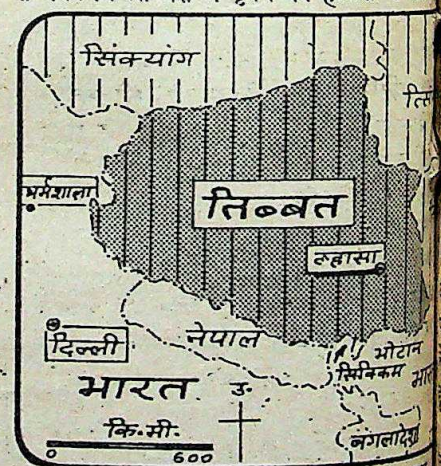
प्रतिनिधिमंडलों ने यात्राओं से वापसी के बाद जो विवरण प्रकाशित किये हैं, उन के आधार पर आज के तिब्बत की जो तस्वीर उभरती है, वह उस तस्वीर से ठीक उल्टी है जिसे चीनी प्रचार तंत्र और उस की हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ पश्चिमी समाचार माध्यमों ने हाल ही के वर्षों में पेश किया है।

तिब्बती प्रतिनिधियों ने अपनी यात्राओं के दौरान पाया कि कुछ गिने चुने इलाकों में सड़कों, बिजली और पक्के मकानों के रूप में हुई प्रगति साफ साफ दिखती है। लेकिन यह प्रगति केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है, जहाँ चीनी सैनिक और प्रशासक लोग रहते हैं। तीस वर्षों में सड़कों का व्यापक जाल अवश्य बिछा है लेकिन उस का एकमात्र उपयोग चीनी सेना के आने जाने और भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा जैसे देशों के साथ लगने वाले सीमा क्षेत्रों को चीन से जोड़ने के लिए होता है। आम तिब्बती जनता के लिए नाम मात्र के लिए भी जन यातायात व्यवस्था तक स्थापित नहीं की गयी है। उन के एक स्थान से दूसरे

स्थान पर जाने पर आज भी कड़ा सरकारी नियंत्रण है और आवश्यकता पड़ने पर कोई तिब्बती केवल सैनिक और माल ढोने वाले ट्रकों पर ही कहीं जा सकता है।

यह भी ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में दो तीन स्थानों पर दियासलाई, सीमेंट, ऊन, दूध और चमड़े आदि के कारखाने लगाये गये हैं लेकिन इन का वास्तविक उद्देश्य या तो सैनिक निर्माणों के लिए सीमेंट तैयार करने और इस तरह हजारों मील का भाड़ा बचाना है या फिर तिब्बत में मौजूद चीनियों की दूध, चमड़े आदि की जरूरतों को पूरा करना और शेष बचे माल का चीन को निर्यात करना है। आम तिब्बतियों के जीवन पर इन उद्योगों के लाभ का असर लगभग न के बराबर है। दूकानों पर बिकने वाले जूतों, टोपियों और बर्तनों आदि को देख कर साफ पता लगता है कि दैनिक प्रयोग की लगभग सभी चीजें आज भी चीन से आयात की जाती हैं।

मारी पैमाने पर वनों के कटाई को देखते हुए कुछ प्रतिनिधियों का अनुमान है कि अकेले इमारती लकड़ी के निःशुल्क निर्यात से ही तिब्बत को इतना नुकसान हो चुका है जितना चीन ने अब तक तिब्बत में कृषि विकास के नाम पर खर्च किया है। नये कृषि तरीकों को अपनाने और कृषि भूमि के विस्तार से यकीनन तिब्बत में कृषि की हालत में भारी



परिवर्तन आया है। लेकिन इसका लाभ किसे हुआ? चीनी शासकों ने वहाँ न केवल जौ के स्थान पर गेहूँ का उत्पादन आरंभ कर के स्थानीय जनता की मोजन आदतों को खलल डाला है बल्कि कम्प्यूनों द्वारा की जाने वाली फसल का अधिकांश हिस्सा स्थानीय कुरों और 'युद्ध तैयारी' और 'भूमि-से प्यार' जैसे कुरों के नाम पर बर्बाद कर के उसे चीन भेज दिया जाता है। परिणामस्वरूप आम तिब्बती कृषि मजदूरों को वर्ष में तीन चार महीने फाकाकशी में गुजारते पड़ते हैं। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में फसल काटने के समय आग लग कर फसल नष्ट कर देने जैसी भूमिगत बर्बादियों की संख्या काफी बढ़ गयी है।

## चौथा शिष्टमंडल दो वर्ष बाद

**पहला 5 सदस्यीय शिष्टमंडल जनवरी 1980 में तीन महीने की सद्भाव यात्रा पर तिब्बत गया था। इस दल का नेतृत्व दलाई लामा के बड़े भाई लोबसांग सामदेन ने किया।**

**दूसरा शिष्टमंडल मई 1980 में तीन महीने की तिब्बत यात्रा पर गया था। पाँच सदस्यीय इस शिष्टमंडल में दलाई लामा के टोक्यो, न्यूयार्क और यूरोप के तीन प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे।**

**तीसरे पाँच सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व दलाई लामा की छोटी बहन श्रीमती पेमा ग्यालपो ने किया था। यह शिष्टमंडल जुलाई '80 में चार महीने की यात्रा पर गया था। लेकिन 103 दिन बाद ही यह दौरा स्थगित कर दिया गया था।**

**चौथा शिष्टमंडल दो वर्ष के अंतराल के बाद इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भेजा गया। इस तीन सदस्यीय शिष्टमंडल के सदस्य दलाई लामा की निर्वासित सरकार के शिक्षामंत्री श्री जुबेन तुप्ता, सुरक्षा मंत्री श्री पी. टी. ताकला और तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री लोदिग्यारी है।**



कड़ा सरकार  
इने पर कोई  
ल दोने वाले  
है।  
कुछ वर्षों में  
सीमेंट, ऊ,  
रखाने लगाये  
क उद्देश्य था  
सीमेंट तैयार  
गोल का भाड़ा  
जुद्ध चीनियों  
रतों को पूरा  
न को नियमित  
जीवन पर  
र लगभग न  
विकने वाले  
को देख कर  
क प्रयोग की  
न से आयात  
आई को देखते  
नुमान है कि  
रुक नियत से  
हो चुका है।  
वत में कृषि  
है। नये कृषि  
मि के विस्तार  
हालत में भारी  
ति  
तासा  
ओटान  
सिमेंट  
(बंगलादेश)  
इसका लाभ  
वहाँ न केवल  
न आरंभ कर  
न आदतों को  
न द्वारा  
धकांश हिस्सा  
'और 'माम'  
म पर बल  
ता है। परि  
मजदूरों को  
नी में गुजारे  
है कि पिछले  
य आग लगे  
मूमित पर  
है।  
-22 मई '82

शिक्षा के नाम पर जो थोड़े बहुत स्कूल  
बनाये गये हैं, उन का प्रयोग मुख्य रूप से  
चीनी अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई के  
लिए किया जाता है। इन में पढ़ने वाले तिब्बती  
बच्चों को चीनी राजनैतिक घुट्टी पिलाने के  
साथ साथ उन्हें स्थानीय संस्कृति से धृणा  
करती सिखायी जाती है। दलाई लामा ने हाल  
ही में आरोप लगाया था कि कई स्थानों पर  
स्कूलों को बच्चों को बंधुआ मजदूरों की तरह  
उपयोग करने के काम में लाया जाता है।  
दो वर्ष के दौरान तिब्बत गये तीनों प्रतिनिधि-  
मंडलों ने जब भी किसी सार्वजनिक स्थान पर  
बच्चों को देखा, उन्हें फटे चीथड़ों में लिपटे  
पाया। लेकिन उन्हें जहाँ जहाँ स्कूल दिखाये  
गये, वहाँ उन्हें तिब्बती बच्चे लकड़क पोशाकों  
में मिले।  
जहाँ तक धर्म और संस्कृति की बात है,  
लासा से लौटे श्री तेनजिग टी थोंग, जो कि  
दलाई लामा के न्यूयार्क प्रतिनिधि हैं, ने मुझे  
बताया कि वहाँ नब्बे प्रतिशत से अधिक  
मंदिर नष्ट किये जा चुके हैं। जो कुछ बचे खुबे  
मंदिर रह गये हैं, उन्हें पर्यटकों को दिखाने  
के लिए सजा कर रखा गया है। धर्म की  
जागीर के नाम पर अब केवल घरों के अंदर  
इश की छूट है लेकिन बच्चों को धार्मिक  
शिक्षा देने पर अभी भी पाबंदी है।  
हालांकि चीनी प्रचारतंत्र ने तिब्बत में  
स्थानीय प्रशासन में तिब्बतियों को बड़ा हिस्सा  
देने जाने की बातें खूब दोहरायी हैं। लेकिन  
चिने की तिब्बत समिति के अध्यक्ष और  
दूरे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य श्री फुंत्सोक  
सांगपाल ने कुछ मास पूर्व लंदन में हुई मुला-  
कात में मुझे बताया कि तिब्बती प्रशासन में  
तिब्बतियों की बराबरी की बात निहायत  
गिर पर की है। उनके शब्दों में : 'नगर और  
ग्राम स्तर के सभी प्रमुख स्थानों पर चीनी  
अधिकारी नियुक्त हैं। कुछ गिने चुने स्थानों  
पर कुछ तिब्बती अवश्य सजा कर रखे गये हैं।  
लेकिन उन में से अधिकांश पुराने पहचाने  
की चीनी दलाल हैं।'  
प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब दलाई  
लामा और उनके प्रतिनिधि यह जान गये हैं  
कि तिब्बत की असली हालत क्या है तो  
आत्मनिर्देशित वातचीत का सिलसिला  
कैसे चलेंगे? चीनी पक्ष के लिए इस वातचीत  
का आगे चलाये रखने के एक से अधिक  
कारण हैं। एक ओर वातचीत जारी रख कर  
विश्व को यह दिखाने की कोशिश कर  
रहा है कि तिब्बत की समस्या उन की घरेलू  
समस्या है और इसे वे वातचीत से ही हल  
कर लेंगे हुए हैं। दूसरी ओर दलाई लामा  
की तरफ यह शरणार्थी समाज में आपसी आशंकाएँ  
विरोध पैदा कर सकने की भी उम्मीद  
है।  
तीनी उत्सुकता का एक प्रमुख कारण

## उनका कहना है

हम विरोध पक्ष के लोगों को अंतिम रूप से तय कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के शत्रु हैं या इका कांग्रेस हम सब की शत्रु है। इतना तय कर लेने भर से हम चुनाव में अपनी साख बना सकते हैं फिर उम्मीद-वारों का चयन कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटलबिहारी वाजपेयी चार राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रतिपक्ष एकता की संभावनाओं पर

इस में जरा भी शक नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका तथा अन्य देशों से जो आधुनिकतम हथियार ले रहा है उन का इस्तेमाल रूस, चीन या ईरान के विरुद्ध नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध ही होगा।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हिमाचलप्रदेश की एक चुनाव सभा में



वह दूरदर्शन पर सेक्स शिक्षा का सूत्रपात करना चाहते हैं। सब को इस की निंदा करनी चाहिए। समझ नहीं आता इस स्वामी को क्यों चढ़ाया जा रहा है। हमारी प्रधानमंत्री समझदार हैं। उन्हें सब मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। इस स्वामी को सफदरजंग रोड में घुसने किसने दिया। प्रधान मंत्री क्यों इसे आने देती हैं यह बह्यचार कहता है, दस लाख रुपया मेरे लिए, दस पैसे जितना भी नहीं। यह इका कांग्रेस का मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है। कोई जमाना था जब साधु संत पैसे को मिट्टी माना करते थे।

कांग्रेस एस के श्री ए. जी. कुलकर्णी राज्यसभा में एक न्यूट्रान बम से किसी भी शहर के दस लाख लोगों में से तीन लाख तो मर ही जायेंगे। कोई चार लाख आदमी झुलस जायेंगे और उन पर रेडियो विकिरण का घातक प्रभाव पड़ेगा। परमाणु युद्ध छिड़ने पर चूंकि इस तरह के हजारों बमों का विस्फोट होगा इसलिए मानव जाति के भविष्य का तो सवाल ही नहीं उठता।

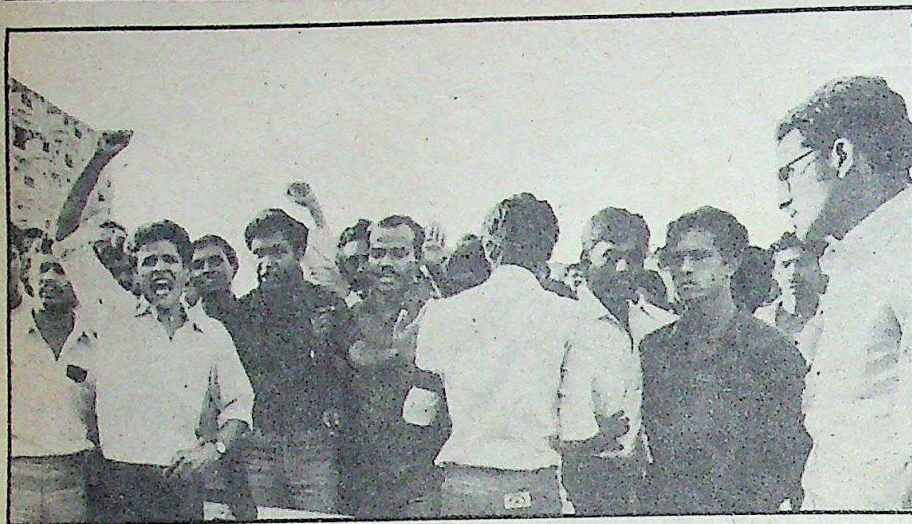
परमाणु युद्ध विरोधी चिकित्सकों की विश्व संस्था के उपाध्यक्ष और सोवियत विद्वान श्री योव गेनी शेजोव

यह भी है कि हाल ही के वर्षों में रूस ने तिब्बती प्रश्न पर न केवल अपने तटस्थ रवैये को ताक पर रख कर दलाई लामा की अस्थायी सरकार के साथ गुपचुप संबंध स्थापित कर लिये हैं, बल्कि रूसी प्रचार तंत्र में तिब्बत समर्थक प्रचार सामग्री की मात्रा भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। उधर तिब्बती पक्ष को इस प्रेमालाप से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बार फिर से पुनर्स्थापित होने का मौका मिला है। यात्राओं में जहाँ उन्हें तिब्बती जनता के हौसलों की जानकारी और उन के चीनी शासकों के साथ वास्तविक संबंधों की सही झलक मिली है, वहाँ जगह जगह हुई समाओं में दलाई लामा की राजनैतिक गतिविधियों और इरादों की जानकारी दे कर उन्होंने देश के भीतर रह रही जनता को भविष्य के लिए रास्ता सुझाने के भी व्यापक प्रयास किये हैं। हाल ही में एक मेट के दौरान दलाई लामा ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था—'इस वातचीत और यात्राओं का मेरे देश की जनता को एक सीधा फायदा यह हुआ है कि दिखावे के लिए ही सही, चीनी शासकों ने उन्हें कुछ

खुल कर साँस लेने की छूट दी है। मेरे ब्याल में अगर हम उनकी इस राहत को कुछ देर और बनाये रख सकें तो उन्हें भविष्य के लिए एक नया आत्मविश्वास और शक्ति जरूर मिलेगी। फिलहाल इतनी उपलब्धि भी थोड़ी नहीं है।

चौथे प्रतिनिधिमंडल की यात्रा आरंभ होने के समय एक प्रवक्ता द्वारा दलाई लामा को पीकिङ में अपना कार्यालय खोलने की पेशकश किये जाने का समाचार छपा है। इस पेशकश के बारे में दलाई लामा पक्ष की प्रतिक्रिया अभी समाने नहीं आयी है। लेकिन लगता है कि नये प्रतिनिधिमंडल की पीकिङ यात्रा से वातचीत का क्रम आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कुछ प्रेक्षकों को यह भी आशा है कि अब एक अन्य तिब्बती प्रतिनिधि मंडल को तिब्बत के उन भागों की यात्रा का मौका मिल सकता है, जो अब तक उन की पहुंच से परे रहे हैं। यह भी आशा कयी जा रही है कि इस बार की वातचीत में तिब्बती भाषा और संस्कृति की शिक्षा देने के लिए कुछ शरणार्थी तिब्बती अध्यापकों को कुछ चुनींदा तिब्बती क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्ति पर चीन सहमत हो जायेगा। □





जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाराज नवयुवक

## जनेवि की प्रवेशनीति का इंद्रजाल

नयी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने जन्मकाल 1969 से ही गहरे विवाद का विषय रहा है। इस की स्थापना के लक्ष्यों और आज तक की उपलब्धियों के बारे में विचारधारात्मक रूढ़ान के अनुसार विभिन्न, परस्पर विरोधी मत बनता स्वामा-विक है। दरअसल इस के मूल्यांकन का प्रश्न पर्याप्त जानकारी की मांग करता है।

एक ओर छोटे छोटे गुट और व्यक्ति हैं जिन के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से शासक वर्ग की राजनीतिक रणनीति के अंतर्गत हुई थी और इस का मुख्य लक्ष्य भारतीय सामाजिक विकास की वर्तमान मंजिल पर, जब अनेक व्यवस्था विरोधी विचारधाराएँ जनचेतना में जगह ले रही हैं और इस प्रकार एक भीतिक शक्ति में तबदील हो रही है, एक नये किस्म का जनबल तैयार करना है। यह जनबल न केवल शासक वर्ग की प्रशासकीय आवश्यकताओं को पूरा करने और जनांदोलनों के नौकरशाही दमन में सक्षम होगा, बल्कि मानविकी, कला एवं विविध विज्ञानों की विशेष जानकारी से लैस हो कर जनचेतना को कुंठित और लक्ष्यच्युत करने के शासकीय विचारधारात्मक प्रयासों को सूक्ष्म, सटीक और प्रभावशाली रूप देगा।

दूसरी ओर वह प्रवृत्ति है जो विश्वविद्यालय की स्थापना को एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखती है और इस धारणा को पुष्ट करना चाहती है कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग इस शिक्षा संस्थान में एक जनवादी परंपरा का अस्तित्व है। इस परंपरा के उदाहरण के रूप में वे शिक्षक समुदाय के एक अंश के वामपंथी रूढ़ान, पाठ्यक्रम में एक सीमा तक

आज की प्रभुत्वशाली विचारधाराओं के समा-वेश, और विभिन्न अकादमिक निकायों (स्टूडेंट फेकल्टी कमिटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडेमिक कौंसिल) में छात्रों को एक स्तर पर मिले प्रतिनिधित्व को पेश करना चाहेंगे।

इसी जनवादी परंपरा के अभिन्न अंग के रूप में विश्वविद्यालय की प्रवेशनीति का भी हवाला मुख्य रूप से दिया जाता है। इस प्रवेश-नीति का सूत्रीकरण विश्वविद्यालय अधिका-रियों ने 1973 में छात्रसंघ के सहयोग से किया था। (इस सहयोग शब्द पर अनेक वाम-पंथी उछल पड़ेंगे क्योंकि उन की व्याख्या के अनुसार यह नीति छात्र संघर्ष की उपलब्धि है न कि अधिकारियों की ओर से तोहफा!) इस नीति में बदलाव के लिए पहली पेशकश अधिकारियों की ओर से 1976 में हुई थी, लेकिन छात्र समुदाय के बहुमत के रूढ़ान को देखते हुए वे इसे अमली रूप देने की ओर प्रवृत्त नहीं हुए। इस दिशा में एक निश्चयात्मक कदम उन्होंने नवंबर 1981 में ही उठाया और उपकुलपति ने प्रवेशनीति संबंधी प्रस्तावों की एक सूची पेश की।

प्रवेशनीति पर हुए विवाद में शिक्षक समु-दाय ने, इस के अनेक सदस्यों के प्रगतिशील दावों के बावजूद नहीं के बराबर रुचि ली है। छात्रों में विवाद मुख्य रूप से उप कुलपति के प्रस्तावों के फीरी प्रभावों को लेकर ही रहा है।

जनेवि प्रवेशनीति के जिस विशेष पहलू को सब से अधिक प्रचारित किया और उलझाया गया है, वह है क्षेत्रीय, सामाजिक, एवं आर्थिक पिछड़ेपन के लिए प्रवेशार्थियों को मिलने वाले 'विशेष' अंक। कुल सी अंकों

की प्रवेश योग्यता 'इंडेक्स' में इन का योग 20 होता है। इन के बारे में विचार करते हुए हम एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं। इस 'इंडेक्स' को बिना शर्त समर्थन देने वालों और विभिन्न कारणों से इस का विरोध करने वालों, दोनों के ही विचारों में हम दो सामान्य बातें पाते हैं: (क) यह विचार कि ये 'विशेष' अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का योग्यता स्तर ही कुछ बुनियादी दृष्टियों में कम होता है, और (ख) अकादमिक योग्यता के बारे में एक संदिग्ध धारणा का।

बहरहाल पिछड़ेपन के अंकों को योग्यता 'इंडेक्स' में शामिल किये जाने में शासकवर्ग की यह स्वीकृति निहित है कि सामाजिक-संदर्भ व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं के विकास में निश्चयात्मक भूमिका निभाता है और आज के सामाजिक संदर्भ में असमानता एक तथ्य है लेकिन सामाजिक असमानता की यह स्वीकृति आंशिक और छद्मपूर्ण है क्योंकि यह इन तथ्यों पर बड़ी चतुराई से पर्दा डालती है: (क) सामाजिक संदर्भ न केवल ज्ञान के स्तर को प्रभावित करता है बल्कि मूलभूत रूप से ज्ञान की प्रकृति और अंतर्वस्तु को निश्चित कर देता है, (ख) उपरोक्त कारणों से ही सामाजिक असमानता की स्वीकृति यह भी आवश्यक बना देती है कि अकादमिक क्रिया-कलाप की प्रकृति और तदनुरूप मूल्यांकन प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन किया जा

लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ही प्रसंग में स्थापित अकादमिक मानदंड और पद्धतियों को कोई बुनियादी चुनौती नहीं दी जा सकी है। छात्रों के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक श्रेणियों से आने के बावजूद उन का चयन वास्तव में योग्यता की स्थापना कसौटी के आधार पर ही होता है, वह भी एक आदर्श स्थिति में अगर शिक्षक समुदाय के विभिन्न पूर्वग्रहों पर विचार न किया जाये। मूल्यांकन के शिक्षकों के बेरोकटोक अधिकार पर जनेवि के जनवादी परिप्रेक्ष्य में भी कोई आघात नहीं किया गया है। किसी भी 'अवांछित' तत्व को वे आसानी से प्रवेश सूची से बाहर ठेल सकते हैं। मौखिक एवं लिखित प्रवेश परीक्षा अंकों के जरिए पिछड़ेपन के अंकों को होने वाले तथ्याकथित लाभ को आसानी से खाल किया जा सकता है!

सामाजिक विज्ञान की थोड़ी सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति आसानी से इस इंडेक्स को समझ जायेगा। इस प्रवेशनीति को लागू कर के प्रगतिशीलता के छद्म के माध्यम से शिक्षा की विशिष्टतावादी शैली को ही जनेवि स्वरूप प्रदान किया गया है।



भूमिसंघर्ष

## बलुआहा गाँव में पुलिस ने गोली वर्याँ चलाई

नव वर्षा

ग्राम के करीब चार बजे भुतहा बाजार के एक साधु मानस का पाठ कर रहे थे। प्रसंग राम रावण युद्ध और तदंतर रावण संहार का लगभग उसी समय पास के गाँव बलुआहा में निहत्थे भूमिहीन खेत मजदूरों और हथियारों से पुलिस के बीच संघर्ष चल रहा था। इस में कुछ लोगों की जानें गयीं। अखबारों ने इसे भूमिहीनों का संघर्ष कहा।

मधुवनी से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर बलुआहा गाँव 3 अप्रैल को खून की गोली का चरमदीय गवाह बना। पूरे गाँव में घण्टा का सन्नाटा था। हर नया आनेवाला वहाँ की निगाहों से देखा जाता था।

मिथिला का मधुवनी जिला एक अरसे से शोषण का केंद्र रहा है। तब के अविभाजित भारत का एक अंग मधुवनी विगत सात-आठ सौ से जिला है। राजनगर थाने के मठसिमरी क्षेत्र में कभी चार भूपतियों का दबदबा था। अधिकधिक जमीन और संपत्ति के मामले में सभी बड़ी मछली छोटी मछली का खेलते रहे। बची बड़ी मछली रामेश्वर ठाकुर इधर कई वर्षों से बेताज बादशाह बने हैं। वही मुखिया और उपप्रधान भी हैं। बाजार, रतिकर, कोइमख, मौआही जैसे कई गाँवों में इनकी मिल्कियत फैली है। पूरे क्षेत्र के गरीब, भूमिहीन किसान छोटी-छोटी जमीन के लोग इनकी दया पर जी रहे हैं।

कई वर्ष पूर्व छोटे किसानों और भूमिहीनों का जुट हो कर जयनगर निवासी जमींदार रामकुमार गुप्ता की 6 बीघा जमीन पर बटाई-बंटाई का दावा कर भूमि सीमा अधिनियम के तहत उसे सस्ते भाव बेचने पर बाध्य कर दिया था। ठाकुर परिवार ने हस्तक्षेप कर जमीन को जमीन का कागज दिलवा दिया। इस बाद में घोखे से कागज वापस ले लिया। एक भूमिहीन के पास अभी भी जमीन का हिस्से की जमीन की रसीद है। किंतु जमीन का मालिक ठाकुर परिवार ही बना है। इसी तरह एक बार सरकार की ओर से जमीन मजदूरों को लगभग 10-10 घर की मो साम, दाम दंड और भेद से हड़प लिया गया। साधनहीन गरीब किसान मजदूरों को तो कलकत्ता या पंजाब जाते, नहीं तो सरकारी मिट्टी में उम्र और रोटी का अक्स खाती थी। देह तोड़ काम लिया जाता



(ऊपर) मृत ब्याबेबो के पति अर्जुन पासवान, (ऊपर दाएँ) मृत कारी साहू, (नीचे) बलुआहा के बाबू लाल खतबे की बीरान झोंपड़ी : पिता पुत्र दोनों मारे गये।

था, वहाँ बेटीयों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी।

बार बार न्यायोचित माँगों को ठुकराने के कारण इन लोगों ने पिछले धान की फसल को काटने से इनकार कर दिया तो ठाकुर परिवार ने बाहर से मजदूर मँगवा लिये। अपने पेट पर पड़ी इस लात से शोषित जनता तिलमिला उठी। ठाकुरों की इस हरकत ने स्वयं को असुरक्षित होने का एहसास दिलाया। पुलिस के उच्चाधिकारियों (प्राप्त जानकारी के अनुसार आई जी तक) से ले कर प्रशासनिक उच्चाधिकारियों तक ने सुरक्षा का बंदोबस्त करने के नाम पर पुलिस कैप बिठा दिया।

एक बार पंचायत भवन की जमीन और निर्माण के लिए रामेश्वर ठाकुर को सरकार की ओर से मुखिया और उपप्रधान होने के नाते रुपया भी मिला लेकिन उन्होंने जई पासवान की झोंपड़ी गिरा कर पंचायत भवन बनवा दिया। तब जई पासवान रोजी रोटी की तलाश में सपरिवार पंजाब में था। इस वर्ष 31 जनवरी को जई पासवान वापस आया तो जमीन का मालिक होने के नाते पंचायत भवन पर कब्जा कर लिया। भूमिहीनों और ठाकुर परिवार के बीच मुख्य विरोध की स्थिति यहीं से बनी। शोषण के बहु आयामी हथकंडों से मुक्ति पाने के लिए भूमिहीनों और गरीब लोगों ने अपने ही बीच से उभरे जटाधर झा को नेता मान लिया जिसे मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में स्वीकारा है।

जिस खेत पर मेहनत और दावा इस तबके के लोगों का होता था, उस की फसल ठाकुर



परिवार काट लेते थे। जब उन्होंने फसल काटी तो ठाकुर परिवार और उनके समर्थकों ने उसे लूट और डकैती की संज्ञा दी। 2 फरवरी को एक गरीब खतबे परिवार की बारह वर्षीया लड़की गीता मर गयी। उस के दाह संस्कार के लिए लोग ठाकुर परिवार से बाँस माँगने आये। इनकार किये जाने पर रोष में इन लोगों ने जबरन बाँस काट लिया। इस से बीखला कर ठाकुर ने उसका घर जला डाला।

3 अप्रैल की घटना की पृष्ठभूमि 2 अप्रैल बनी। सिधेश्वर खतबे की लड़की रुक्मिणी भैंस चरा रही थी। ठाकुर परिवार के घर से सटा एक मंदिर है। उस के चारों ओर सात बीघा जमीन में गोहूँ की फसल खड़ी थी। यह खेत मंदिर के नाम है। परीक्षितः उस पर ठाकुर परिवार का कब्जा है। चरते चरते भैंस जब उस खेत में जाने लगी तो भगाने के लिए रुक्मिणी बोड़ी। तब तक मंदिर के पुजारी सूर्यदेव भारती गालियाँ देते पहुँचे। एफ आई आर संख्या 494/82 के अनुसार भारती ने उसे मर्दा गाली दी। रोती हुई वह अपने टोले गयी। वहाँ से रुक्मिणी की माँ और अन्य औरतें पुजारी को भला बुरा कहने आयीं। औरतों के आगे बढ़ने पर मर्द भी आ जुटे। मीड को भगाने के लिए ठाकुर पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी की। पुजारी ने रुक्मिणी की माँ पर लाठी चलायी। सुखदेव शर्मा नामक बड़ई जब आगे बढ़ा तो उसे भी जस कर पीटा गया। फिर उसे पुलिस कैप ले जाया गया और गिरफ्तार किया गया। इस पथराव और लाठी प्रहार में तीन औरतें और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुईं।

पूरे क्षेत्र में इस घटना से आक्रोश छा गया। अगले दिन 4 अप्रैल को आसपास के गाँवों के लगभग साढ़े तीन सौ लोगों ने ठाकुर के



दालान पर प्रदर्शन किया। उन को मुख्य भागें थीं—मुखदेव शर्मा को रिहा करो, रामगार दो, आतंक दूर करने के लिए पुलिस को हटाओ, सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दो, इज्जत की गारंटी दो, अपमानित करना बंद करो आदि। निहत्थे प्रदर्शनकारियों में औरतें और बच्चे भी थे। रामेश्वर ठाकुर के बड़े भाई भुवनेश्वर ठाकुर ने उन सबों की स्थिति में सुधार का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारी जब वापस लौटने लगे तो भुतहा बाजार के राम मंडल के अनुसार ठाकुर परिवार के नौकरों ने पथराव किया। जवाब में प्रदर्शनकारी लोगों में से भी कुछ ने पथर फेंके। इस पर पुलिस ने गोली चलायी जिस से तीन औरतें और दो मर्द मरे। भागती भौड़ पर मौआही गांव की ओर से आ रहे हथियार-बंद दल ने गोली चलायी और दो लोगों को मार गिराया। यह तो सरकारी आँकड़ा है जिस के अनुसार कुमुम लाल पासवान, उपेंद्र साह, बाबूलाल खतवे, खुशीलाल मंडल, कारी साह, दया देवी मरी। घायलों की संख्या भय से गाँव छोड़ देने के कारण उपलब्ध न हो सकी। एफ आइ आर के मुताबिक 13 गोलियाँ चलीं। लग-भग 26 लोगों के मरने की बात लोग करते हैं।

रामेश्वर ठाकुर ने मिलने पर बताया कि वे लोग दो हजार की संख्या में हथियारों से लैस थे। उन का नेता जटाधर झा है जो किसान सभा का आदमी है। जटाधर झा आपके ही दुश्मन क्यों हैं? पूछने पर बताया कि मेरे पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्वी ठक्कन झा से उनकी घनिष्ठता है। वे ही मुझसे बदला लेने के लिए उनको सहयोग देते हैं। लेकिन पसीने से सिंची जिस जमीन को पीड़ितों ने अपने ही रक्त से लाल किया, उस का मुआयना करने पर उन की बात की असत्यता का पता चला। आसपास के खेतों की फसल सुरक्षित थी। तो क्या प्रदर्शनकारियों की इतनी अधिक संख्या फसल बचाते हुए भागी थी? मधुबनी के आरक्षी अधीक्षक रंजीत सिन्हा के अनुसार पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलायी। लेकिन ठाकुर परिवार और पुलिस के कितने लोग घायल हुए इसकी कोई सूची नहीं थी। आत्म-रक्षार्थ गोली चलाने से पहले क्या लाठी चार्ज, अश्रुगैस, हवाई फायर नहीं किये जा सकते थे? प्रशासनिक अकर्मण्यता और ठाकुर परिवार से साँठगाँठ का ही नतीजा था यह सब नहीं तो क्या कारण था कि पंचायत सुपरवाइजर गौरीशंकर दास को मजिस्ट्रेट का अधिकार दे कर पुलिस का नेतृत्व दिया गया और जमादार रामराज राम ने दबाव डाल कर सीधे गोली चलाने का आदेश प्राप्त कर लिया।

इस आग में बहुतांश को हाथ सँकने का अवसर मिला। मृतकों के परिवार को भी जनसंख्या कम करने के एवज में पाँच पाँच सौ रुपये, दस दिनों का राशन, कपड़ा वगैरह दिया गया। जान की कीमत बस इतनी ही। □

## चरचे और चरखे

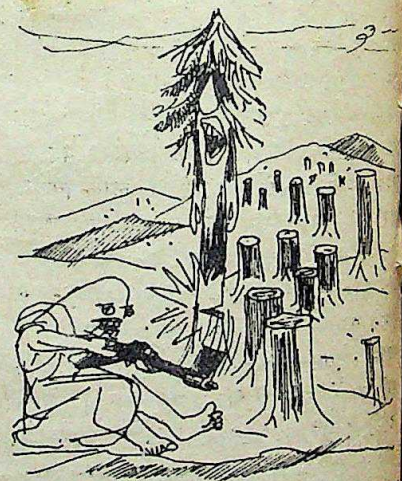
### पेड़ों का कत्ल

“राम राम हरा पेड़ काटसी, नरक में पड़सी।” वचन में ‘चाँद’ के मारवाड़ी अंक में छपे एक व्यंग्य चित्र का शीर्षक पिछले दिनों अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय दैनिक में छपी एक कोने में एक छोटी सी खबर पढ़ कर याद आ गया। खबर के अनुसार पालमपुर में पाँच मई को श्रीमती इंदिरा गांधी को सार्वजनिक सभा के मैदान को घेरने के लिए स्थानीय लोक निर्माण विभाग ने बांदला जंगल के पाँच सौ से अधिक देवदार के नये वृक्ष काट डाले और उन हरी शहतीरों से बाड़े बनाये गये। ऐसा करने में किसी भी नियम की परवाह नहीं की गयी। कानून-नियम सब ताक पर उठा कर रख दिए गये। कहा जाता है कि इस अवैध कटाई से एक लाख रुपये की लागत का नुकसान हुआ है। बस खबर इतनी ही है। लेकिन एक चिनगारी जैसे फूस में आग लगा देती है वैसे यह छोटी सी खबर जागरूक आदमी के मन में आग लगाने की काफी है।

सभा मैदान में बाड़े बनाना क्यों जरूरी था? क्या बिना बाड़े के सभा नहीं हो सकती—लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्रीय नेता की सभा? मान लीजिए सुरक्षा के कारणों से या समाज के विभिन्न स्तर और वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जगह बनाने के उद्देश्य से बाड़े बनाना जरूरी था तो फिर उस के लिए इतने सारे हरे पेड़ काटने की क्या जरूरत थी? ये बाड़े रस्सी, पाइप आदि से नहीं बनाये जा सकते थे? लेकिन लोक निर्माण विभाग को पेड़ों की चिंता नहीं थी। ऊँचे अधिकारियों को खुश करने की चिंता थी और ऊँचे अधिकारियों को प्रधानमंत्री को। वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री देखें कि कितने साफ सुथरे बाड़े बने हैं और उन के प्रबंध कौशल को सराहें। इस से दो बातें पता चलती हैं कि देश में सत्ता को खुश करने के खयाल से कोई कुछ भी कर सकता है—यह दूसरी बात है कि सत्ता उस से खुश हो या न हो—इंदिरा गांधी को इन हरे पेड़ों का काटा जाना अच्छा लगा हो या न लगा हो—लेकिन नीचे का आदमी ऊपर के आदमी को खुश करने के खयाल से कुछ भी गलत, अनियमित, गैर-कानूनी, जब्य कर सकता है! दूसरा यह कि लोक निर्माण विभाग इस देश में लोक ध्वंस विभाग है—वह निर्माण के नाम पर ध्वंस की दूरगामी योजनाएँ बनाता रहता है। जंगल का एक पेड़ काटने पर जंगल अधिकारी गरीब मजदूर-किसान को सजा देने, जुर्माना करने का हक रखता है लेकिन एक बड़े के नाम की खातिर बड़े लोगों द्वारा सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर दुम हिलाता है और

खीस निपोरता रहता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। लोक निर्माण विभाग को यदि पेड़ से मोह होता तो वह यह हरकत नहीं करता। लेकिन उसे पेड़ों से मोह नहीं है। हुकूम मिलने पर पेड़ लगवाने का नाटक कर सकता है (भले पेड़ ही क्यों न जायें) और बिना जरूरत के जरूरत पर निर्भर हो काट सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए—पेड़ काट रहे हों, देश उजड़ रहा हो और उस का असर मौसम पर पड़ रहा हो, भूमिशरण रहा हो, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हों, जब प्रशासनिक अधिकारी अपना बिकेला खो बैठे हों, अपना स्वार्थ ही देख रहे हों, और खतबा और पैसा कमा और कमवा रहे हों, क्योंकि ये शहतीरें बाढ़ा बनने के दोषी हैं। वाद विकेंगी और इस इंतजाम के पीछे का धंधे का साँप फन उठाये होगा। कोई रास्ता नहीं है सिवा विरोध के। स्थानीय जनता को ऐसी स्थिति में तुरत विरोध करना चाहिए और इस गलत काम को रोकना चाहिए। पेड़ों को बेमतलब बेहिसाब काटना अपराध है—यह समझना और समझाना जरूरी है। इस



गलत असर पर्यावरण पर पड़ता है जिस से इनसमन की जिंदगी से सोधा रिश्ता है। नरक तरह पेड़ों को काटने की इस हरकत को नबूद दाज किया जा सकता है न इस खबर को लेने खबरों पर समाज की व्यापक प्रतिक्रिया जरूर है। लड़ाई का यह भी एक जरूरी मोर्चा है। जनता को और सरकार को भी इस काटने का जवाब माँगना चाहिए और यदि इस उस का खुद का कहीं हाथ है तो उसे शर्म से बच चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती से बचना का अहद करना चाहिए। नहीं तो जनता को पेड़ काटने के विरोध में अपने आंदोलन को व्यापक करना होगा क्योंकि हरा पेड़ काटने वालों को शायद अन्न नरक का भय नहीं है उन्हें किसी और भय की जरूरत है। उन मन में यह आतंक घर कर लेना चाहिए ‘हरा पेड़ काटसी जन कोप में पड़सी।’



## दिल्ली के रंग

### राजधानी बूढ़ी हो रही है

सवाल था : क्या दिल्ली बूढ़ी हो रही है? इंडिया गेट के पास फव्वारों वाले पार्क शाम को बैठे हुए बूढ़ों के दल में एक ने दूसरे से पूछा था। दूसरे बूढ़े महाशय ने जो शायद निवृत्त स्वास्थ्य संस्थान की कोई रिपोर्ट पढ़ कर जवाब दे, कहा 'जी हाँ, देश की राजधानी बूढ़ी हो रही है। कुछ स्थानीय कारणों से और कुछ इसलिए कि सारी दुनिया ही बूढ़ी हो रही है।' तब उन्होंने आँकड़े पेश किये कुछ ऐसा कहा जाता है कि सन् 2000 ई. के शुरू होने तक एशिया की जनसंख्या में 52 प्रतिशत बढ़ि हो जायेगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बूढ़ों की जनसंख्या में 102 प्रतिशत बढ़ि होगी। अब दिल्ली कोई एशिया के बाहर नहीं बूढ़ी है। यह तो महाद्वीप की प्रमुख राजधानियों में से है। 'अवश्य बूढ़ी हो रही है।' बूढ़े महाशय ने फरमाया। काफी वजन था इस बात में उन की। दिल्ली बूढ़ी हो रही है और वहाँ कहीं तो कुछ मर भी रही है। शाहजहानाबाद, जो मुगल शाहनशाहों के समय वजीरों, अमीरों, रईसों, मुलतानों, घन्नासेठों और राजदारों की नगरी दिल्ली थी, अब अंधेरी और तंग गलियों, सड़ंध और बदबू के फुंकारे वाली नालियों, फोड़ों की तरह बढ़ते, फैलते बड़े करकट और गंदगी के अंबारों की एक बालू वस्ती बनती जा रही है। लाल किले के चारों ओर भी पुरानी शाही इमारतों की दीवारों की अक्सर सिसक सिसक कर मरम्मत की आवश्यकता सी दिखायी देती हैं। नयी दिल्ली में सब कुछ नया है और दिन व दिन नये नये स्कूल, दुकानें, सड़कें, पार्क, बाग, बगीचे सभी बनते रहे हैं और बन रहे हैं। पुरानी दिल्ली में पुरानी ही इमारतों का अपने पाँव लटका रहना दुस्वार हो गया है। बहुत पुरानी हो जाती हैं तो कमेटी वाले इन्हें खतरनाक करार दे देते हैं और फिर ये ढाहू दी जाती हैं ऐसे भी कटेर हैं जहाँ कई कई दिन सफाई नहीं होती और महीनों मरम्मत नहीं। काश कि इस वादशाओं की दिल्ली को इतनी तेजी से बूढ़ा होने से रोके और पल पल टूटने, फूटने, गिरने और मरने से बचाये। जहाँ विकास और प्रगति का अतिक्रमण होना चाहिए।

### साबरी बोले सब कीजिये

पिछले दिनों पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता गुलाम फरीद साबरी और उन के छोटे भाई मकबूल राजधानी में पधारे थे। साबरी तो थे वह अजमेर में ख्वाजा चिश्ती के दरबार पर साथी झुकाने मगर अपने प्रशंसकों और प्रेमियों के अनुरोध पर कुछ दिन दिल्ली

भी रुके। दो कव्वालियों के कार्यक्रम उन्होंने राजधानी में पेश किये। एक रंजीत होटल के पास 'नेहरू पहाड़ी' के प्रांगण में और दूसरा एक केंद्रीय मंत्री के घर के विशाल लान में जहाँ मंत्री जी के मित्र, अतिथि, जिन में गृह-मंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी थे, पधारे। रात का समय था, कुछ ठंडक भी हो रही थी। अब दिल्ली वालों को चाय और सिगरेट की लत है ही। जब मेहमानों ने कुर्सियों पर जम सिगरेट निकाल फूँकने शुरू किये तो संगीत बंद हो गया। गुलाम फरीद साबरी की आवाज माइक पर गूँजी 'जनाब सिगरेट और कव्वाली साथ नहीं चलते। यहाँ इबादत की बात है। माफ कीजिए या तो सिगरेट बाहर जा कर पी लीजिए या थोड़ी देर के लिए कव्वाली बंद कर देते हैं। पी लीजिए मगर मेरी अर्ज तो यह है कि सिगरेट तो आप रोज पीते हैं। आज सब कीजिए। संगीत सुन लीजिए। जब हम गज़ल सुनायेंगे तब बेशक सिगरेटनोशी फरमाइए।' बात शायद ज्ञानीजी को भी पसंद आयी। सिगरेट सब फेंक दिये गये। कव्वाली फिर शुरू हुई। बहुत जमी और सुनने वालों को बहुत मजा आया। बाद में साबरी साहब ने बताया कि संगीत में कव्वाली का स्थान मीरा और सूरदास के भजनों से कम नहीं। यह वास्तव में स्तुति संगीत है और इसे आदर और श्रद्धा से मेंट करना चाहिए और उसी भक्ति भाव से स्वीकार करना चाहिए। बुरा हो आज के चालू गवैयों का जिन्होंने कव्वाली को बाजार की आवाजों में बदल दिया है। असली कव्वाली तो वही है जो भक्ति भाव में बसी है।

### जीत का तर्क

केंद्रीय मंत्री सीताराम केसरी एक विवाह समारोह में पधारे तो मित्रों, प्रशंसकों ने घेर लिया। पूछा 'क्यों केसरी जी, विधानसभा चुनाव में आप की इंका का क्या भविष्य है?'

केसरी बोले, 'मई जीतेगी हमारी पार्टी हरयाणा, हिमाचल आदि में और मेरा तर्क यह है कि हमारे विरोधी दलों में वह बात नहीं जो बाबू जयप्रकाश नारायण ने पैदा की थी, इन दलों का डमेज उन्होंने बनाया था। वह इन दलों को जोड़ जाड़ कर शक्ति दे सकते थे, इन्हें बना सकते थे। इसी लिए हम लोग हारे थे। मगर तब में और अब में बड़ा अंतर है। जे. पी. नहीं हैं और इन विरोधी दलों और नेताओं पर कोई ऐतबार नहीं करता। जे. पी. इन्हें पैदा कर सकते थे। ये नया जे. पी. पैदा नहीं कर सकते। लाम हमी को होगा। क्यों ठीक है ना?' शायद केसरी जी ठीक ही कह रहे थे कम से कम राजनैतिक दलों पर जनता के टूटने हुए विश्वास के बारे में।



साबरी भाई कहते हैं : जरा सब कीजिए

### परिश्रम तो कर रहे हैं

चुनाव का फल क्या होगा। इस विषय में एक मित्र राजधानी के एक अन्य धरलू समारोह में भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी से भी बात करते सुने गये। आडवाणी जी उसी दिन चुनाव प्रचार के एक दौरे से दिल्ली लौटे थे और अगले दिन अपने दल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए केरल जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कई जगह जाना है उन्हें प्रचार के लिए, अंत में भागलपुर पहुँचेंगे। प्रश्न उन से भी किया गया। 'आप इतना कड़ा परिश्रम कर रहे हैं? क्या विचार है आपके दल की सफलता मिलेगी चुनाव में?' आडवाणी जी हँस कर बोले इतना 'परिश्रम कर रहे हैं कुछ तो फल निकलेगा।'

### तुम भूत हो

जाने पहचाने चित्रकार सतीश गुजराल एक पुराने मित्र से बड़े दिनों के बाद एक पार्टी में मिले तो बोले 'क्यों तुम भूत हो? तुम वह तो हो नहीं सकते जो मेरे मित्र थे।' शिकायत का अंदाज था एक अपना कि दो पुराने दोस्त इस महानगरी में रहें, दुख मुख की सैकड़ों घड़ियाँ गुजर जायें और आमना सामना तक न हो। मगर सतीश के मित्र भी कुछ कम न थे। भर्राई आवाज बना कर बोले 'हाँ, मैं भूत हूँ तुम्हारे दोस्त का।'

कलाकार कहाँ पीछे रहने वाला था। झूठ मूठ अकड़ दिखते हुए सतीश गुजराल बोले 'मैं नहीं डरता। दोस्त के ही तो भूत हो।' और दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े।



## युवा जगत

### राजनीति, मेरा व्यवसाय

पिछले दिनों एक युवा राजनेता से मेट हुई. अपने 'व्यवसाय' को ले कर उन्होंने ने बेबाक बातचीत की. यह बातचीत किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि आज के युवा राजनीतिक समाज की मनःस्थिति को स्पष्ट करती है. एक बात स्पष्ट हुई कि युवा राजनेता आज स्वयं को जिस 'मजबूर और आदर्शहीन' स्थिति में पा रहा है, उस के लिए वह अपने आप से अधिक अपनी पुरानी पीढ़ी और उस से भी अधिक इस देश की जनता को इस के लिए उत्तरदायी मानता है. उसी युवक राजनीतिक के शब्दों में 'जब तक हमारी जनता भावनाओं, आस्थाओं और अंधविश्वासों में जीती रहेगी और आँख मूंद कर भक्तिभाव से राजनीतिक निर्णय करती रहेगी, तब तक युवा राजनेता भी आज की झट्ट होती राजनीति का हिस्सा बनते जायेंगे.' अलबत्ता यह उन्होंने नहीं बताया कि जनता को यथास्थितिवादी बनाये रखने के लिए कौन जिम्मेदार है. उन से हुई बातचीत के कुछ अंश यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं. उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, आज की संपूर्ण युवा राजनीतिक पीढ़ी के सोच को स्पष्ट करना है, इसीलिए यहाँ उस युवा राजनीतिक का नाम नहीं दिया जा रहा है.

आप राजनीति में क्यों आये?

जिस लिए लोग दूसरे व्यवसायों में जाते हैं. क्या दूसरे व्यवसायों और राजनीति में कोई अंतर नहीं?

मैं कोई साधू संन्यासी तो हूँ नहीं. मुझे भी जीवित रहना है. जीवित नहीं रहूँगा तो राजनीति-सेवा ही सही, कहेगा कैसे और जीवित रहने के लिए पैसा चाहिए. सुविधाएँ चाहिए. आप का राजनीतिक आधार क्या है?

जातिवाद की राजनीति.

लेकिन इस के बल पर कब तक जीवित रह सकेंगे आप?

जब तक जातिवाद के नाम पर जनता मुझे वोट देती रहेगी. जनता भी यह जानती है.

जनता को समझाने का काम किस का है?

मेरा नहीं.

राजनीतिक के साथ सेवा और बलिदान शब्द प्रारंभ से जुड़े हुए हैं?

हाँ, लेकिन अब जब जनता बिना बलिदान और सेवा के वोट देती है, बलिदान की जरूरत क्या है.

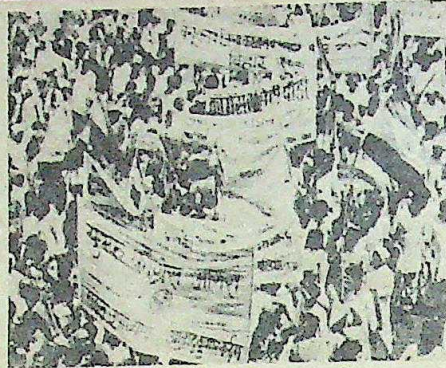
क्या किसी योग्यता को बिल्कुल जरूरत नहीं?

कुछ योग्यताएँ होना भी जरूरी है.

मसलन?

मैं आप को समझाता हूँ. मैं जब पढ़ाई पूरी कर के विश्वविद्यालय से निकला तो केवल

दिनमान



युवा राजनीति : भोड़ का चरित्र

500 रुपये मेरी जेब में थे (युवा राजनेता विश्वविद्यालय में छात्र नेता रह चुके हैं. एक बार छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा किंतु जमानत जन्त हो गयी थी) हवाई जहाज से उस शहर में पहुँचा था. हवाई जहाज का किराया भी किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया था. शहर में मुझे कोई नहीं जानता था. मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न था. विधानसभा चुनाव भी निकट ही थे. जरूरी था कि लोगों को तेजी से प्रभावित करूँ. मैं ने सौ डेढ़ सौ गुंडे बदमाश किराये पर लिये और शहर में घड़ाघड़ समाएँ करनी शुरू कर दीं. मैं डेढ़ दो घंटे के घुंआधार भाषण की तैयारी कर के जाता था, लच्छेदार बातें करता ही था. प्रारंभ में मेरे खरीदे हुए लोग ताली बजाने का काम करते थे. डेढ़ दो घंटे में दो तीन हजार लोग हो ही जाते थे. मैं ने दस पंद्रह दिन में करीबन पचास समाएँ कर डालीं. तब तक पार्टी में और लोगों में भी मेरी चर्चा होने लगी थी कि लड़का अच्छा बोलता है.

हमारे दल की संयुक्त सार्वजनिक सभा भी हुई. दल के सभी वरिष्ठ नेता उस में शामिल हुए. आजकल जनता भी तेज हो गयी है. तरह तरह के सवाल पूछते हैं. उस सभा में लोगों ने एक लिखित प्रश्नावली भेज दी. 'आप राजनीति में क्यों आये, आप हमारे लिए क्या करेंगे? इसी चुनाव क्षेत्र से क्यों खड़े हैं?' इत्यादि-इत्यादि. 'सभी वरिष्ठ नेताओं ने बारी बारी इन सवालों का सैद्धांतिक विश्लेषण करना शुरू किया.' मेरी भी बारी आयी. मैं ने कहा, 'देखिए मैं केवल 500 रुपये ले कर इस शहर में आया था, राजनीति करने. निश्चित रूप से आप के शहर में भीख माँगने की मेरी कोई योजना नहीं है. राजनीति करने आया हूँ तो पैसा भी चाहिए. राजनीति कहेगा तो पैसा भी तो राजनीति से ही कमाऊँगा. ये जो वरिष्ठ नेता अभी आप के सामने लंबी चौड़ी सैद्धांतिक बहस कर रहे थे, सब राजनीति से ही पैसा कमाते हैं. लेकिन ये आप से छोटे छोटे काम करने का भी पैसा लेते हैं. मैं ऐसी राजनीति नहीं कहूँगा. गरीब जनता से कोई पैसा नहीं लूँगा. हाँ, कोई बड़ा तस्कर, काले घंघे वाला

सेठ आया तो उस से कहूँगा मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को इतने पैसे की जरूरत है, उन में बंट दो. इस तरह आप का भला होगा और अगर उस में से दो चार टुकड़े भी भी खा लें तो कोई एतराज है आप को.' सभी लोग मौचके रह गये. लेकिन मैं चुनाव जीत गया. आदर्शवादी राजनीति का आप कोई महत्त्व नहीं मानते?

आप ही बताइए! आज गांधीवादी राजनीति कर के क्या मैं चुनावों की राजनीति में रह सकता हूँ. मैं अगर गांधीजी की तरह लोगों को बाँध कर अपने चुनाव क्षेत्र में जाऊँ और गरीब लोगों को आदर्शवाद का उपदेश देने लूँ और उसी समय कोई तस्कर आ कर उन 50 हजार रुपये वांट जाये तो बोलिए क्या होगा. लोग उस तस्कर की जय जयकार करेंगे और मुझे जूतियों से मारेंगे और जब तक स्थिति चलती रहेगी, मैं भी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हूँ.

यह दशा क्या इसलिए नहीं है कि पिछले लंबे समय से राजनीतिक इस देश के लोगों को आर्थिक आधार देने में असफल रहे हैं?

बताइए, कहाँ असफल रहे. (इस पर मैं बहस उचित नहीं समझी).

आप राजनीति में 500 रुपये ले कर आये थे, अब कितना पैसा है?

लाखों रुपये कमाये हैं.

मंत्री पद से हटने के बाद कहाँ रहते हैं?

उसी बंगले में जहाँ पहले रहता था. बार बार कहीं रहने लगे तो अपने आप उस जगह को छोड़ सकते हैं. जब तक हटाना न जाये.

किराया देते हैं?

अरे, किराया दे कर मरना है. लोग कहेंगे मैंने बहुत पैसा कमाया है और नहीं दिया. कहेंगे बेचारा गरीब है, छोड़ो किराया.

जब आप विद्यार्थी थे, तब अपने एक दूकानदार से सामान उधार लिया था. उस का पैसा नहीं लौटाया था. ऐसा सुना गया है?

हाँ, सही था.

उस ने माँगा तो आप ने धमकी दी थी. के मारे उस ने दूकान छोड़ दी.

मैं दूकानदार के पैसे न दूँ और वह मुझे पैसे माँगे और उस की दूकान भी चलती रहे. फिर तो कर ली मैंने राजनीति. यहीं तो आप की राजनीति में टिकने का मूल मंत्र है.

आगे आपका इरादा क्या है?

फिलहाल अभी तो मंत्री हूँ नहीं. विधानसभा में. भविष्य में मंत्री बनने की संभावना भी है. अगले चुनाव में फिर मैदान में रहूँगा. और मंत्री बनने की पूरी कोशिश करूँगा.

मैं आप का साक्षात्कार छापूँ?

अरे! मेरा कबाड़ा हो जायेगा.

—सुपमा पारंगत



# क्या अब भी चुनाव टलने का अंदेश है?

वरजीत, संपादक : इन्फा



**‘कहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव स्थगित कराना जरूरी हो. लोगों को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि चुनाव स्थगित कर दिये जायेंगे या होंगे नहीं।’**

—मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर

किसी को उपकृत नहीं करने जा रहे हैं. पिछले सप्ताह ही उन्होंने नामा और फरीदकोट की दो विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों को टालने के लिए पंजाब सरकार के आवेदन को अमृतसर में हुई दुखद घटनाओं के बावजूद दृढ़ता से ठुकरा दिया है.

दरअसल, यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साहसपूर्वक आयोग की स्वतंत्रता न बनाये रखी होती और इस पर बल देने के लिए प्रभावी कदम न उठाये होते तो मुझे जरा भी शंका न रहती कि ये लघु आम चुनाव नहीं होंगे. यदि कोई कमजोर मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो अपने कार्यकाल के बाद की स्थितियों को नजर में रखते हुए केंद्र में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस (इं) को उपकृत करने के लालच में पड़ जाता और जब पार्टी की पश्चिम बंगाल शाखा ने आठ लाख शिकायतें दाखिल कीं तो वहाँ के चुनाव रोक देता; पर उन्होंने यह देखने पर कि ये शिकायतें झूठी और जाली हैं न केवल उन्हें ठुकरा दिया बल्कि इस मामले को ले कर उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई की. श्री शकधर की उम्र 63 वर्ष है और यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनका पाँच वर्षीय कार्यकाल आगामी 17 जून को समाप्त होने जा रहा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल में यह कठोर रवैया इस लिए अपनायी क्योंकि वहाँ एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो रही थी जिस

से लोकतंत्र के आधार को ही क्षति पहुँच रही थी. लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता पर जनता के लिए शासन. इस को समयबद्ध और स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनावों के द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है. फिर भी आज सत्ता पार्टी में कष्टकर चुनावों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. गढ़वाल इस मामले में एक उदाहरण है. इस के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस (इं) पिछले दो सालों से दिल्ली में चुनाव करवाने से इनकार करती आ रही है. यद्यपि लैफ्टिनेंट गवर्नर श्री एम. एल. खुराना ने चुनावों की सिफारिश की थी और मुख्य चुनाव आयुक्त से बार बार कहते रहे हैं कि वह थोड़े समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं.

यद्यपि लघु आम चुनाव के टलने की संभावना पूरी तरह से दरकिनार की जा सकती है पर किन्हीं एक दो चुनाव क्षेत्रों में चुनाव को निरस्त कर देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. चुनाव तब भी निरस्त हो सकता है जब, उदाहरण के लिए, मतदान के पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाये. गढ़वाल के प्रतिष्ठा वाले चुनाव के बारे में एक दिलचस्प बात सामने आयी है. एक वयोवृद्ध उम्मीदवार, बताया जाता है कि, अपनी माँगों को पूरा न किये जाने तक के लिए आमरण अनशन पर बैठ गये हैं. बहुगुणा के कुछ समर्थकों को इस में चुनाव को फिर से टाल देने की एक और कोशिश की वृत्ति आने लगी. कैसे? संकेत यह है कि उस उम्मीदवार ने यह स्वीकार किया है कि उसने यह कदम, बताया जाता है कि, कांग्रेस (इं) के कहने पर उठाया है. इस पर चुनाव आयोग से शिकायत की गयी. वहाँ से निर्देश मिले कि उम्मीदवार को किसी अस्पताल में ले जाया जाये और उसे बलपूर्वक खाना खिलाया जाये.

## स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

चुनावों के लिए चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करने में लगा है जिस से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ साथ निर्भय भी हों. यह बात गत सप्ताह श्री शकधर से हुई मेरी बातचीत में उन्होंने कही. उन्होंने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिरीक्षकों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से बातचीत की. इस के अतिरिक्त वह खुद भी दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर गये (संयोग से यह यात्रा गत माह उसी दिन तय हुई जिस दिन श्री शकधर ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. इस का, कुछ अनभिज्ञ रिपोर्टों के विपरीत श्रीमती गांधी के कलकत्ता में दिये गये बयान से कोई संबंध नहीं है). उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि कानून और व्यवस्था

आगामी लघु आम चुनावों को ले कर नयी दिल्ली में अनुमानों का बाजार गर्म है. कई लोग पूछ रहे हैं: 'चुनाव होंगे भी या टाल दिये जायेंगे?' इस अटकलबाजी पर आश्चर्य नहीं होता क्योंकि पिछले गुरुवार को प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कलकत्ता की एक जनसभा में साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के आसार नहीं हैं. उन्होंने फिर एक सवाल किया: "यह क्या चुनाव होगा जिसमें लोगों को अपने मताधिकार का ही प्रयोग न करने दिया जाये और कई लोगों को डर हो कि वे मताधिकार का प्रयोग कर ही नहीं पायेंगे?" दो दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने भी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अपनी भारी पराजय की संभावना से घबरा कर कांग्रेस (इं) 19 मई को होने वाले लघु आम चुनावों को टाल भी सकती है.

## साधनों की शुद्धता

साधनों की शुद्धता की जिस बात पर गांधी जी हमेशा से ही जोर देते रहे हैं उसकी शिविरता आज खत्म हो गयी है और केवल लक्ष्य सामने रह गया है, इसलिए आज कुछ भी हो सकता है. फिर भी व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि चुनाव टलेंगे. यह बात मैं दो कारणों से कहता हूँ. पहला तो यह है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और चुनाव केवल एक ही हालत में टल सकता है जब आपात्-स्थिति घोषित हो जाये—बाहरी या भीतरी. साफ साफ कहूँ तो चुनाव तभी टल सकते हैं जब पूरे पश्चिम बंगाल, केरल, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे. यदि पाकिस्तान या कोई और पड़ोसी देश अचानक भारत पर हमला कर दे, तब भी चुनाव टल सकते हैं.

दूसरा कारण भी इतना ही महत्वपूर्ण है. इस अवस्था में आ कर चुनाव को एक ही संवैधानिक अधिकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस. एल. शकधर ही टाल सकते हैं. राष्ट्र-पति और प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ नहीं कर सकते—यह बात 1977 में सामने आयी थी जब जनता पार्टी के पक्ष में हवा जाती देख कर कुछ कांग्रेस (इं) नेता चुनावों को टालना चाहते थे. वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में वह



## आवरण कथा

बनाये रखने के लिए भरसाक प्रयास करने और केंद्र से सी. आर. पी. की टुकड़ियों के रूप में हर सहायता के लिए कहें।

### पुलिस का विकल्प

दरअसल यह अविवशनीय लग सकता है कि केंद्र के पास चार राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, हरयाणा और हिमाचलप्रदेश में चुनावों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल का ही मामला लें। श्रीमती गांधी के अनुसार कांग्रेस (इं) के कार्यकर्त्ताओं पर हमले किये जा रहे हैं और उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। मुझे पता चला है कि राज्य सरकार ने सी. आर. पी. की 17 बटालियनों की माँग की है। पर केंद्र सरकार अभी केवल दस बटालियनें ही भेजने की स्थिति में है। केंद्र की अपनी कठिनाइयाँ हैं। सी. आर. पी. की कई बटालियनें असम में विदेशी नागरिकों को लेकर पैदा हुई विस्फोटक स्थिति का मुकाबला करने के लिए भेजी गयी हैं। सी. आर. पी. की कई बटालियनें पंजाब भेजी गयी हैं।

चुनाव आयोग ने चारों राज्यों को सलाह दी है कि पड़ोसी राज्यों से पुलिस की टुकड़ियाँ मंगवायें। पर जब सभी जगह कानून और व्यवस्था बिगड़ रही हो तो यह बात कहने में जितनी सरल लगती है करने में उतनी सरल नहीं सिद्ध होती। उदाहरण के लिए, बिहार ने पश्चिम बंगाल से पुलिस टुकड़ियाँ भेजने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। इन हालात में चुनाव आयोग ने एक अच्छा काम किया है, उसने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि 19 मई को मतदान के काम पर होमगार्डों, फॉरेस्ट गार्डों और फायर गार्डों जैसे संगठनों का सहयोग प्राप्त करें और उस दिन के लिए उन्हें पुलिस की पोशाक और अधिकार से भी युक्त करें। आप पूछ सकते हैं कि सेना की टुकड़ियों की बात क्यों नहीं की जा रही है, पर किसी भी लोकतंत्रीय चुनाव में सिद्धांतरूप से सेना की बात नहीं की जानी चाहिए।

### संवैधानिक जिम्मेदारियाँ

बहुत से लोग नहीं जानते कि चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग पर कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। ज्यादा क्या कहें, इसे 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' की असीम शक्तियाँ दे दी गयी हैं। यह सच है कि कानून और व्यवस्था राज्य की जिम्मेवारी है। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को इस उद्देश्य से, यदि जरूरत हो तो, बाहर से पुलिस बल बुलाने का अधिकार है। पर चुनाव आयोग को भी यह जानने का अधिकार है कि ऐसा कहाँ और क्यों किया जा रहा है। स्वतंत्र और

निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी भी है। पुलिसबल चोरी छिपे बुलाना बदनीयता माना जाता है। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसी आधार पर गढ़वाल में दोबारा चुनाव की तजवीज की थी।

कई लोग नहीं जानते कि मुख्य चुनाव आयुक्त की राय पुलिसबल की संख्या के मामले में भी महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि 1978 में चिकमगलूर की लोकसभा सीट के लिए हुए ऐतिहासिक उपचुनाव के समय हुआ था। उस चुनाव में जनता सरकार के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुई थीं। जब यह शिकायत मिली कि अधिक पुलिस बल चुनाव को दूषित कर सकता है तो श्री शकधर ने कर्नाटक की कांग्रेस (इं) सरकार को चुनाव क्षेत्र से कुछ पुलिस दल हटाने के आदेश दिये थे। इसके बाद जब राज्य के विरोधी दलों ने शिकायत की कि कांग्रेस (इं) सरकार के अधीन स्थानीय पुलिसबल श्रीमती गांधी के प्रति पक्षपात कर रहा है तो सी. आर. पी. और बी. एस. एफ. की टुकड़ियों को लाने की सलाह भी दी गयी। श्री शकधर ने व्यवस्था दी कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में पुलिस बल उतना ही होना चाहिए कि चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके—न इस से कम न ज्यादा।

इतना ही नहीं, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हों, यह बात सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में विशेष पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर के एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कुछ पर्यवेक्षक चुनाव आयोग से ही नियुक्त किये जायेंगे। सभी पर्यवेक्षक वरिष्ठ अधिकारी होंगे। उदाहरण के लिए, गढ़वाल में आयोग ने पाँच न्यायिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी अधिकारी विभागाध्यक्ष के दर्जे के होंगे और चुनाव अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे। सिर्फ पश्चिम बंगाल में हर चुनाव क्षेत्र में एक के हिसाब से 294 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की संभावना है।

मतदाताओं और उम्मीदवारों के अधिकारों तथा चुनाव विधियों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी न होने के कारण चुनावों की निष्पक्षता को ले कर कई शंकाएँ पैदा हो रही हैं। इस साल चुनाव आयोग ने जो प्रणाली लागू की है उसका अध्ययन करने का कष्ट कुछ ही लोगों ने उठाया है। वर्तमान प्रणाली में न केवल चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना सुनिश्चित हुआ है बल्कि यह ऐसा भी है कि मतदाता बिना डरे अपने मतधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतपत्र की गोपनीयता के संबंध में आशंका निर्मूल है।

मतदान खत्म होने के बाद, कमसंख्या लगे

सब प्रतिपणों (काउंटरफाइल) को एक लिफाफे में डाल दिया जाता है और उस पर सील लगा दी जाती है। मतपेटियों और चुनाव के कागजों को लिफाफे में रख कर उन पर भी सील लगा दी जाती है। चुनाव एजेंटों को भी मतपेटियों पर अपनी-अपनी सील लगाने की अनुमति दी जाती है। इसी तरह गिनती खत्म हो जाने के बाद मतपत्रों को उम्मीदवार या उसके गणना एजेंट की उपस्थिति में सील कर दिया जाता है। ये सभी तथा चुनाव के अन्य कागजात पेटियों में बंद कर के सील किये जाते हैं और उन्हें सरकारी खजाने में दोहरे तालों के भीतर रख दिया जाता है। उन पेटियों को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले अदालत की आज्ञा से ही खोला जा सकता है। यदि चुनाव याचिका नहीं आती तो एक साल के बाद ये मतपत्र नष्ट कर दिये जाते हैं।

### निष्पक्षता का आश्वासन

1971 के चुनाव के दौरान मतदाताओं से मतपत्र के प्रतिपण पर हस्ताक्षर करवाने की परंपरा पर कुछ विरोधी दलों ने आपत्ति की थी। तर्क दिया गया था कि इस से मतदाताओं के दिमाग में एक तरह का डर पैदा हो सकता है। अंततः आयोग के साथ विधिवत विचार विमर्श कर के सरकार ने विरोधी दलों की इच्छा के आगे झुकते हुए इस परंपरा को छोड़ दिया। उम्मीदवारों को भी अपने को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ दी जाती हैं कि मतपेटियों को मतदान केंद्रों से बिना किसी रोक टोक के सुरक्षित रूप से मतगणना केंद्रों पर ले जाया गया है और गणना शुरू होने से पहले मतपेटियों को जिस सुरक्षित स्थान पर रखा गया वहाँ भी किसी तरह दखल नहीं होगा। इस के अतिरिक्त जब तक मतपेटियाँ गणना के लिए नहीं ले जायी जाती, उम्मीदवार को तैनात करने की सुविधाएँ भी दी जाती हैं।

कुल मिला कर चुनाव पद्धति इस तरह तैयार की गयी है कि किसी तरह की गड़बड़ी और छेड़छाड़ संभव न हो सके। यहाँ तक कि अमिट स्याही पर भी फिर से परीक्षण हो रहा है ताकि जाली मतदान को रोकने के लिए सच्चे अर्थों में वह अमिट स्याही सिद्ध हो सके। पर राजनैतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के लिए यह पद्धति पूरी तरह से समझना तथा उसे प्रभावकारी ढंग से इसे लागू करवाना जरूरी है। किसी व्यक्ति की तरह किसी व्यवस्था में भी विकृतियाँ आना स्वाभाविक है। फिर भी राजनैतिक दूरदर्शिता इसी में है कि सभी पार्टियाँ मिल कर विकृतियों को होने से रोकें ताकि लोगों को अपनी स्वतंत्रता का मुक्त रूप से निर्भय हो कर प्रतिज्ञान हो सके।



पुलिस

# पेनाल्टी किक के भरोसे

गढ़वाल

बार बार रामलाल, भजनलाल आदि तो पहाड़ नहीं गये हैं। हाँ विश्वनाथप्रताप सिंह हेलीकाप्टर जरूर घाटियों में उतरता-उतरता नज़र आता है। मगर उनकी बात और वह तो राज्य के मुख्यमंत्री ठहरे और फिर उनके राज्य में यही तो एक कांटे की लड़ाई बिस की हार-जीत पर बहुतां की पगड़ी की हुई है। हरयाणा की पुलिस भी गढ़वाल काजकल दिखायी नहीं दे रही है। पुलिस है मगर मुख्य रूप से केंद्रीय आरक्षित ब्रिग और उत्तरप्रदेश की अपनी। और जैसा कि बहुगुणा को उम्मीद है—कम से कम सार्वजनिक रूप से उन्होंने यही कहा कि “मैं अपनी पुलिस को जानता हूँ (मुख्यमंत्री रहते हैं) वह रफ़री का काम करेगी। सत्ता



मुख्यमंत्री का भ्रमण

को कहने पर खुद ही मैदान में उतर कर गोल नहीं दागेगी।” खेल और चर्चा अन्यत्र भी हुई जबकि केदार के विधायक ने गोपेश्वर को जन-मंडल में कहा कि यह खेल तो हम जीत चुके पिछली बार तो उन्होंने (सत्तापक्ष ने) नियम तोड़ कर खेल रुकवा दिया था। बार तो केवल ‘पेनाल्टी किक’ भर जरूरत है बहुगुणा जी को। “पेनाल्टी किक’ सिद्ध हों सके तो खेबाज चीज होती है इसी पर जीत करना किसी भी अच्छे खिलाड़ी को पड़ सकता है। यह बात बहुगुणा को समझते हैं। मुख्यमंत्रियों का काफिला और राज्य के पुलिस दस्ते न भी आये हों तो कौन से लेकर आजमगढ़ और अमेठी के हजारों इंका कार्यकर्ता तो पहाड़ पर उतरा दून युवा कांग्रेस के महामंत्री स्थानीय हिरासिंह विष्ट का दावा है कि इस

बार किसी दूसरे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं। क्योंकि अब के युवा कांग्रेस ने सारा अभियान अपने हाथों में ले लिया है। संजयसिंह, जिन्हें अपने समर्थक राजकुमार जी कहना नहीं भूलते—अमेठी के भूतपूर्व नरेश रणजयसिंह के पुत्र होने के नाते शायद यह ‘हक’ उन्हें हासिल है—गढ़वाल चुनाव अभियान के संचालक बनाये गये हैं। और इसी लिए उनके साथ राज्य भर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा काफिला भी आ पहुँचा है। यों हीरासिंह विष्ट के अनुसार “हम ने इस बार स्थानीय लोगों के नेतृत्व में ही प्रचार का संचालन करने का फैसला किया है।” पिछली बार गढ़वाल चुनाव की गूँज अनुगूँज ज़बर्दस्त थी मगर इस वर्ष माहौल कुछ ठंडा क्यों है? “क्योंकि



बहुगुणा : पथ की लड़ाई

को अलग कर के देहात (पहाड़ी क्षेत्र) के कुछ भाग को शामिल करने की चाल तो बहुगुणा जी की थी ताकि उनका कुछ प्रभाव भी इस में शामिल रहे।” इस तक से परोक्ष रूप में वह यह मानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुगुणा का प्रभाव है। देहरादून गढ़वाल चुनाव क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अहसास सभी नेताओं को है। जहाँ इंका नेता चुनाव स्थगित करवाने और चुनाव आयोग के प्रतिकूल फैसले से विगड़ी हुई अपनी प्रतिमा को सुधारने में लगातार लगे हुए हैं, वहीं बहुगुणा की ओर से विपक्ष के नेता लगातार जनसभाएँ संबोधित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी की बड़ी चर्चा है। कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक खासी जनसभा में बहुगुणा का समर्थन यह कह कर किया था कि ‘मले ही बहुगुणा से उनके गंभीर मतभेद रहे हों मगर इस उपचुनाव में उनका उद्देश्य इंका को हराना है। और क्योंकि बहुगुणा के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है, इस लिए उनको मत दिया जाना चाहिए। कमला बहुगुणा, जो देहरादून में प्रचार का काम संभाले हुए हैं, के अनुसार “अटल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। जब लोगों ने तालियाँ बजायीं तो उन्होंने कहा कि तालियाँ उस दिन के लिए सुरक्षित रखिए जब इंका प्रत्याशी हार जाये।”

श्रीमती बहुगुणा को आशंका है कि इस बार भी गढ़वाल के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से होने नहीं दिया जायेगा। यह तो शहर है यहाँ वही बात दुबारा नहीं कर सकते जो पिछले वर्ष जून में की थी। मगर पहाड़ के गरीब गाँव में अभी से आतंक का वातावरण पैदा

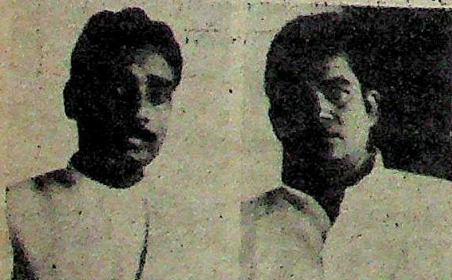


कर दिया गया है। अगर इस समय यह आतंक वास्तविक हिंसा का रूप नहीं ले रहा है तो केवल इस लिए कि हिंसा में सत्तापक्ष को अपनी हार नजर आ रही है। उन्हें अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने हैं। यहाँ हिंसा होगी, चुनाव स्थगित होंगे तो हरयाणा और हिमाचल उस से अछूता नहीं रहेगा। इसी लिए, एक तो हरयाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को फुसंत नहीं, अपने घर में आग लगी है; दूसरे इस वक्त वे ऐसा आभास देना चाहते हैं कि जैसे भलेमानसों की तरह वह इसे दो खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानते हैं। "मुझे तो यह आशंका है कि यह वातावरण केवल 18 मई तक रहेगा। 18 और 19 मई को इका के कार्यकर्ता अपने नग्न रूप में सामने आ जायेंगे। अन्यथा क्या जरूरत है कि सारे राज्य के हजारों नौजवानों को युवा कांग्रेस के नाम पर पहाड़ों में इकट्ठा कर दिया जाये। क्या हम नहीं जानते कि यह कथित कार्यकर्ता वास्तव में कौन है और कैसे हैं।"

श्रीमती कमला बहुगुणा को शिकायत है कि कोई क्यों संजय सिंह से यह नहीं पूछता कि वह आये दिन अपढ़ और गरीब पहाड़ियों के बीच नयी नयी योजनाओं की घोषणा किस बूते पर कर रहे हैं। कहीं वह रेलवे लाइन दिला रहे हैं, कहीं सड़कें बनवा रहे हैं, कहीं कोई और आश्वासन दे रहे हैं। क्या वह कोई मंत्री है, क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारों को उन के हवाले कर दिया है? इस से तो संजय गांधी की याद आती है जिन्होंने अधिकार न होते हुए भी सभी अधिकारियों के हक अपनी मुट्ठी में बंद कर रखे थे।

### किस्सा परेड भंडान का

चुनाव में गड़बड़ी की आशंका तो जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को भी है। देहरादून



संतोषकुमार सिंह

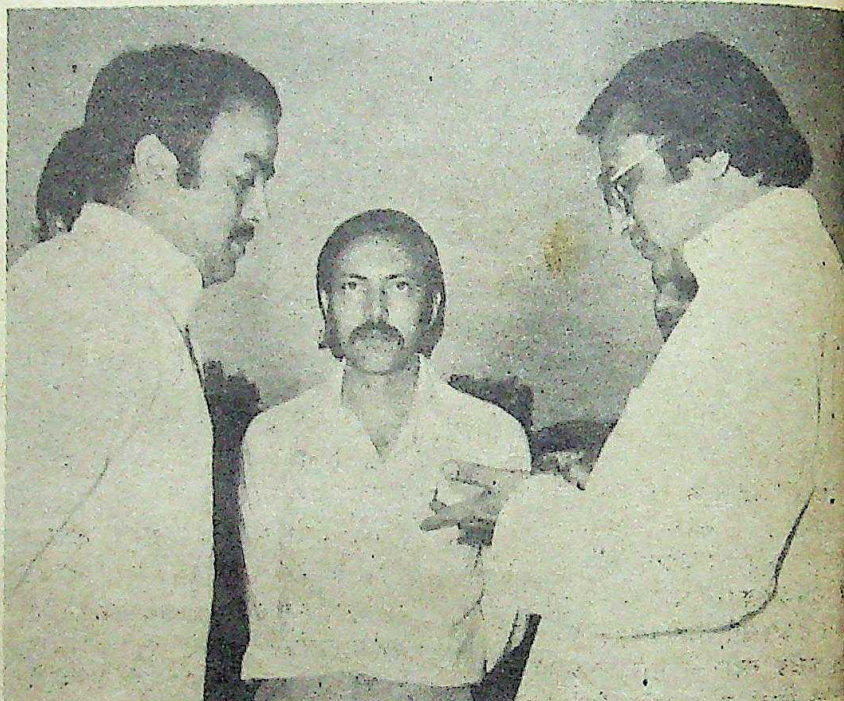
बिनेश पांडेय

नगरपालिका के मैदान में बरसात के बावजूद अच्छी खासी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सत्ता पक्ष पुलिस और जिला अधिकारियों का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। असल में उन को व्यक्तिगत शिकायत भी थी। जब वह देहरादून

बिनामान

## ‘बहुगुणा गढ़वाल को असम बनाना चाहते हैं और हम स्वर्ग’

गढ़वाल की राजनीतिक किञ्चा के कुछ पर्यवेक्षक कहते हैं हेमवतीनंदन बहुगुणा को गढ़वाल में कोई दैवी शक्ति ही पराजित कर सकती है, और कोई नहीं। इंदिरा कांग्रेस ने यह अपने युवा नेता संजय सिंह को सौंपा है। संजयसिंह गढ़वाल को परंपरागत कांग्रेसी सीट मानते हैं। गढ़वाल में कांग्रेस (इ) की चुनाव रणनीति का नियमन पूर्णतया उनके हाथों में है। बहुगुणा पक्षधर इस सीट को हाथ आये सीट मानते हैं और इसीलिए अभी तक उनके अनेक विचार साथी चुनाव के इतने नजदीक आ जाने पर भी लखनऊ में ही चक्कर काट रहे हैं। सारे देश और गढ़वाल पर हैं। यहाँ प्रस्तुत है संजय सिंह से ‘दिनमान’ की दो टूक बातचीत।



गढ़वाल का बोट गणित : संजयसिंह (बायें) अपने साथियों के साथ

कांग्रेस (इ) ने गढ़वाल चुनाव अभियान का मुख्य संयोजक आप को बनाया है। “वेष्ट के अनेक पत्रों व राजनीतिज्ञों का विचार है कि चूंकि यह सीट कांग्रेस के हाथ से जा रही थी, इसलिए आपको सौंप दी गयी।

‘मैं आप से मतभेद रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस यह सीट जीत रही है। यह कांग्रेस (इ) की परंपरागत सीट है। दूसरे आप यह क्यों नहीं सोचते कि मुझे यह जिम्मेदारी इसीलिए दी गयी है कि इंदिरा जी व राजीव जी ने मुझे इस के योग्य पाया है। पिछले वर्षों से मैं चुनाव अभियानों से लगातार संबद्ध रहा हूँ। अमेठी में मैंने स्वर्गीय संजय गांधी व श्री राजीव गांधी के चुनावों में सक्रिय भाग लिया था। फिर अमेठी विधानसभा सीट के लिए खुद चुनाव जीता। रायबरेली में श्री अरुण नेहरू के चुनाव को नजदीक से देखा।

मुझे पार्टी द्वारा जो भी काम दिया जायेगा, उसे मैं मनोयोग से करूँगा। पार्टी के काम में मुझे अधिक संतोष मिलता है। शायद यही कारण था कि जब मेरे पास मंत्री पद का प्रस्ताव आया तो मैंने विनम्रतापूर्वक पार्टी का कार्य करने की ही इच्छा प्रकट की। कदाचित मेरे अनुभव व दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कार्य सौंपा गया है। अपनी पार्टी के लिए चुनाव का संचालन करने में मुझे पर्वतीय विकास संबंधी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का अवसर भी अनायास ही मिल गया है। मैं और मेरे साथी गढ़वाल के घर-घर में इंदिराजी की विकास योजनाओं को पहुँचायेंगे।

बहुगुणा के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपने बहुत से अराजक तत्वों को गढ़वाल में एकत्र कर लिया है? युवा कांग्रेस (इ) एक अनुशासित संगठन है। युवा कांग्रेस (इ) पर इस प्रकार







आने वाले थे तो उन के समर्थकों ने जिलाधीश से किसी निरीक्षण भवन में चंद्रशेखर जी के लिए एक कमरे का इंतजाम करने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधीश ने यह प्रश्न पूछा था कि 'आखिर यह चंद्रशेखर कौन है मैं तो नहीं जानता।' जनसभा में सामान्यतः शांत रहने वाले चंद्रशेखर भी उबल पड़े: "यदि ऐसे ही व्यक्ति चुनाव अधिकारी बनाये जाते हैं तो फिर वह इका प्रत्याशी को छोड़ कर किसी को नहीं पहचानेंगे।"

वैसे देहरादून में रहने लायक सभी स्थानों पर किसी न किसी बहाने कब्जा कर लिया गया है। कई छोटे बड़े होटलों में चक्कर काटने पर भी इस संवाददाता को कोई स्थान नहीं मिल पाया। एक होटल वाले के अनुसार 'दो घंटे बाद आइए आप के नसीब में होगा तो एक कमरा मिल जायेगा।' मगर सब से दिलचस्प बात तो परेड मैदान की है। चुनाव की घोषणा के बाद यह तो स्पष्ट था कि देहरादून के एकमात्र बड़े मैदान का इस्तेमाल चुनाव समाजों के लिए किया जायेगा, मगर जिलाधिकारी ने इस को एक सर्कस कंपनी के हवाले कर दिया। सर्कस कंपनी ने एक किनारे अपने तंबू गाड़ दिये। तब तक यह अनुरोध आया कि 16 तारीख को बहुगुणा जी देहरादून आ रहे हैं, उन के लिए परेड मैदान में समा की इजाजत दी जाये। मगर इजाजत देने के बदले अधिकारियों ने सर्कस कंपनी को किनारे से उठाकर ठीक स्थायी मंच के सामने कर दिया। बची हुई जगह के लिए पहले तो इजाजत दे दी गयी, बाद में एक और आदेश दिया कि बहुगुणा जी को समा करने के लिए परेड मैदान नहीं दिया जा सकता क्योंकि 16 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं।

चंद्रमोहन सिंह नेगी इका के प्रभावशाली प्रत्याशी हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र के लैस डाउन इलाके से विधायक भी हैं और पर्वतीय विकास-मंत्री भी। पर्वतीय विकास मंत्री वास्तव में चार जिलों का छोटा मोटा मुख्यमंत्री होता है जिन के लिए अलग बजट और अलग योजनाएँ सुरक्षित रखी जाती हैं। इस लिए आवासनों की भरमार है। वह अपने इलाके लैस डाउन-दुगड्डा क्षेत्र में पिछले चुनावों में भी वह अच्छे मतों से आगे रहे थे और अब भी कोई कारण नहीं कि तराई के इस क्षेत्र में वह अपने प्रतिद्वंदी से आगे न रह जायें। सच तो यह है कि गढ़वाल चुनाव क्षेत्र का पूरा तराई का इलाका जिस में देहरादून, लैस डाउन दो विधानसभाई क्षेत्र हैं, बहुगुणा को रास नहीं आ रहे हैं। यों भी तराई का इलाका आर्थिक और भौगोलिक रूप से ठेठ पहाड़ से बहुत बातों में भिन्न है। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह आर्थिक और व्या-

विनमान

पारिक रूप से संपन्न है और गैर पहाड़ी लोगों के प्रभाव में है। देहरादून के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि पर करीब करीब पूरा कब्जा गैर पहाड़ियों का है। और उन के यह आर्थिक हित उपनिवेशवादियों की तरह सत्ता के साथ रहने में सुरक्षित रहते हैं। इसी लिए देहरादून में इका से आगे पहुँचने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा को जी तोड़ कोशिश करनी होगी। इका नेताओं का कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में उन का प्रतिनिधित्व 20 हजार मतों से जीता था। इतना भारी बहुमत केवल गैर पहाड़ियों के बल पर तो नहीं हो सकता था न। मगर कमला बहुगुणा का कहना है कि अगर जून के लोकसभा चुनाव में उन्हें 20 हजार मत अधिक मिले होते तो देहरादून में ही मत केंद्रों पर अधिकार करने की जरूरत ही क्या थी। कुछ भी हो इस उपचुनाव में पहाड़ और तराई क्षेत्रों के रवैये अलग अलग हैं।

पहाड़ यों भी इका कार्यकर्ताओं के लिए पहाड़ ही है। देहरादून से 265 कि. मी. दूर गोपेश्वर जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है और बदरी केदार विधानसभा क्षेत्र के राजनैतिक गतिविधि का केंद्र इका कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। बदरी केदार में इका के चुनाव का संचालन करने वाले उत्तरप्रदेश युवा कांग्रेस के सह सचिव संतोष कुमार सिंह और दिनेश पांडेय का जो कि पूर्वी उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले से आये हैं, कहना है कि युवकों को इस लिए चुना गया है ताकि पहाड़ की चढ़ाईयों और कठिन मार्गों पर आसानी से चल सकें। चढ़ना उतरना मैदान के उम्र रसीदा नेताओं के लिए बहुत कठिन है। इस के बावजूद दिनेश पांडेय का दावा है कि घुर देहात इका प्रत्याशी के साथ हैं क्योंकि जो गरीब है वह विपक्ष के साथ हो ही नहीं सकता। यद्यपि दिनेश पांडेय और संतोष कुमार सिंह यह दावा करते हैं कि सारा काम स्थानीय कार्यकर्ता ही करते हैं, फिर भी कुछ लोग इस बात की याद दिलाते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद स्थानीय इका कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर के केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया था कि बाहर के लोगों को चमोली न भेजा जाये। स्थानीय कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में इका के साथ हैं यह तो नहीं मालूम हो सका, मगर आठ मई को जब मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर पुलिस मैदान में उतरा तो कई सौ इका कार्यकर्ताओं की बैठक में गढ़वाल से बाहर के चेहरे बहुतायत में दिखायी दे रहे थे।

### पहाड़ का कर्ज

एक दिन पहले गोपेश्वर के बाजार में बहुगुणा की समा हुई थी। यह तिराहा ही गोपे-

श्वर का एकमात्र ही समास्थल है जहाँ सब के अतिरिक्त पहाड़ी ढलान ही श्रोताओं को बैठने का काम देती है। खड़ी बोली तथा गढ़वाली के मिश्रित भाषण में उन्होंने फिर वही मुद्दे दोहराये जो गत जून में और बाद में नवंबर में चर्चा का विषय थे। उन का कहना था कि हमारी लड़ाई पद की नहीं है, पथ की लड़ाई है। श्रीमती गांधी कहती हैं कि पहले ताकत हासिल करो, सेवा का काम बाद में होगा। मैं कहता हूँ कि सेवा पहले होनी चाहिए ताकत आये न आये। मैं वंश पर देश को तरजीह देता हूँ। उन के लिए वंश सब से पहले है। बहुगुणा जी के अनुसार श्रीमती गांधी आर्थिक कठिनाइयों की तह में कमी भी नहीं जातीं। कभी उन्होंने कोयला खदानों में यह देखने की कोशिश की है कि कोयला पर्याप्त आये दिन मात्रा में क्यों नहीं निकाला जाता। कभी उन्होंने यह सोचा कि इस कोयले के अभाव में और अभाव अपने आप पनपते हैं। हाँ कोयले देने की बात उन्होंने सोची। गरीब आदिमियों को प्रलोभन दिये जा रहे हैं। तरह तरह के कर्जों, मगर ऐसे कामों के लिए जो अनुत्पादक हैं। अगर बिड़ला का कारखाना ठीक तरीके से नहीं चलता तो उसे बीमार घोषित कर के सरकार ले लेती है और अगर गरीब आदिमों द्वारा कर्जों से ली हुई भैंस दूध नहीं देती तो गरीब आदमी को जेल भेज दिया जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने एक नया प्रलोभन जारी कर दिया है। "हाडा"—हिल एलिफेन्ट डेवलपमेंट एजेंसी। यह हाडा गरीब आदिमों के लिए एक हड़डी की तरह है, जो कि वह मूखा कुत्ता हो। इस प्रकार का प्रलोभन सरकार को वापस लेने का कोई हक नहीं है जिस के लिए उसने स्वयं कर्जदार को प्रोत्साहन नहीं दिया। यदि सरकार चाहे तो गाँव के गाँव को जेलखाने में डाल दे। मगर लोको चाहिए कि वह इस नीति का डट कर मुकाबला करें। 'हाडा' की चर्चा छिड़ने पर एक दर्शक ने धीरे से मेरे कान में कहा 'इन पोलिफ कि यह हाडा वाली योजना किस शुरु की। इंदिरा गांधी ने या कि बहुगुणा की जनता पार्टी ने।' हेमवती नंदन बहुगुणा की बातों का असर गोपेश्वर के बाजार के निवासी ही सीमित है या कि ठेठ देहात के निवासी अनपढ़ और गरीब पहाड़ियों को भी यह समझ में आ जाता है? गोपेश्वर से 30 कि. मीटर दूर नंद प्रयाग में एक किसान ने कहा कि प्रलोभनों से कुछ लोग बदल तो जाते मगर अशिक्षित ही सही, पहाड़ी ग्रामीण इलाके बेवकूफ नहीं है कि वह एकदम रातोंरात पहाड़ जाये। हाँ, उसे इस बात का दुख जरूर है कि आये दिन उसे बलि का बकरा बना कर चुनाव के दंगल में घसीटा जा रहा है। □



# हरयाणा कथा

हरयाणा

## चुनाव के भंवर में प्रतिष्ठा की नावे

महेश्वरदयालु गंगवार

महेश्वरदयालु गंगवार (19 मई) ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार समाता जा रहा है। लेकिन जिसे लुभाने के लिए उम्मीदवार एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं वह मतदाता प्रायः चुनाव निरपेक्ष बना हुआ है और हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मतदान के दिन भी अपने प्रतिनिधि को चुनने में वह सोत्साह भाग ले खदानों में यह होगा। इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि कोयला पपकियाये दिन के चुनावों से आज्ञिज आ चुका जाता। बल्कि यह भी है कि इस बार प्रकृति उसके ले के अभाव में तसाह पर पानी फेरे हुए है। उसकी एक आँख ते हैं। हाँ ऊपर आकाश में सतत घिरे बादलों पर गरीब आदिमजदूर की फसल पर। अब वह चुनाव पर जो अनुत्साह रखने के लिए तीसरी आँख कहाँ से लाये? ना ठीक तरीके संभवतः यही कारण रहा कि 9 मई को घोषित कर पानीपत में हुई प्रधानमंत्री की सभा में किसान गरीब आदिमजदूर कम आये, शहरी श्रोता (या दर्शक) हीं देती तो अधिक थे। 1978 में करनाल में लोकसभा दिया जाता जो उपचुनाव हुआ था उस के दौरान नया प्रलोभन श्रीमती गांधी के सत्ता में न होने पर भी उन्हें—हिल एरिक्सेन दूर दूर के गाँवों से लोग करनाल गरीब आदिमजदूर पानीपत की सभाओं में जुड़े थे। देखना तरह है, कि इस्तेमाल करने के पीछे कारण है। लोग श्रीमती गांधी की एक झलक पाने के बाद कोई हक तलाश से फूटने लगते थे और आज भी जंदार को कोशिश स्थिति है। 9 मई को दिन में पानीपत में रकार चाहे जनसभा में न आने का फैसला कर के रुड़े मगर लोकमान नफे में ही रहा। दिन भर गहवाई कर ते का डट कर वह कुछ अनाज तो अपने कोठे में ले ही नर्चा छिड़ने लगा होगा। रात को आयी आंधी और बुआं-में कहा 'इन वरसात ने अगले दिन की गहवाई चौपट होनी थी। उम्मीदवारों के बैनरों की स्याही वरसात में धुल गयी। शहरी मतदाता में चुनाव के प्रति अलवत्ता उत्साह देखने को मिला। उसे फसल की हात के निवासी नहीं है। अनाज देश में न हुआ तो विदेश को भी यह लगेगा सरकार उसका पेट भरेगी। से 30 किताबों को भी किसान की साँसत से कुछ लेना नहीं, उसे तो बादलों ने गर्मी से निजात दी है और वह सारे दिन धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर सकता है, कर भी रहा है। नहीं तो मई की दोपहरी में घर से बाहर निकलता? चुनाव स्थिति किये जाने की भाजपा नेता

श्री वाजपेयी की आशंका के बावजूद चुनाव होंगे। (शकधर ने इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया है) और अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद मतदाता वोट देगा। हरयाणा विधान-सभा का चुनाव इस बार असाधारण चुनाव बन गया है। मतपेटी में पड़े वोट उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेंगे ही, भावी मुख्य-मंत्री का चुनाव भी करेंगे। अगर श्रीमती गांधी ने पैतरा नहीं बदला तो इका को बहुमत मिलने पर भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे और लोकदल-भाजपा के जीतने पर देवीलाल।

यह चुनाव असाधारण इस लिए भी है कि इसमें एक साथ बहुत से लोगों की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी है, यह कि इसमें न केवल हर-याणा की बल्कि देश की भावी राजनीति की दिशा निर्धारित होगी। सब से पहले इस चुनाव में श्रीमती गांधी की प्रतिष्ठा दाँव पर है



सतरामदास बतरा (इंका) और हरिमोहन (इंका विरोधी): रोहतक

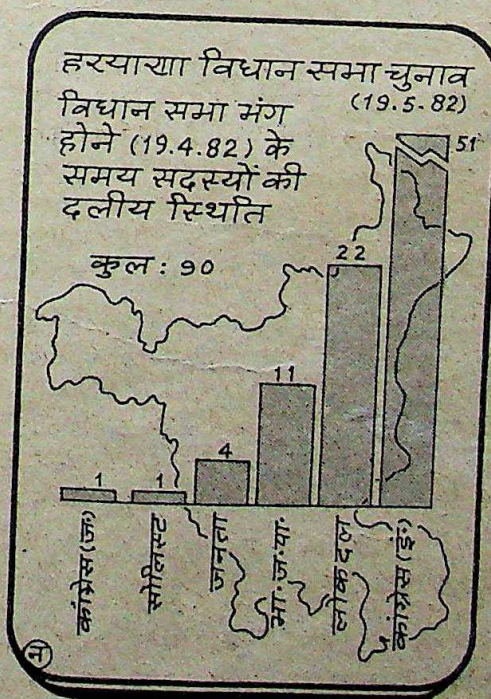
जिन्होंने चौ. बंसीलाल के नेतृत्व के दावे को ठुकराकर चौ. भजनलाल को चुनाव की बाग-डोर सौंपी है। रोहतक में एक असंतुष्ट कार्य-कर्ता ने तो यहाँ तक कहा कि 'भजनलाल ने श्रीमती गांधी को खरीद लिया है।' यह भी सुनने को मिला कि भजनलाल ने टिकट के बदले घन लिया है। आरोप झूठा हो सकता है लेकिन यह सच्चाई तो है ही कि श्रीमती गांधी ने बंसीलाल के मुकाबले भजनलाल को तर-जीह दी और अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए उन्होंने और उनके प्रभावशाली पुत्र राजीव गांधी ने राज्यव्यापी चुनाव दौरे किये और करने वाले हैं। फिर भी, रोहतक के इका कार्यकर्ता डॉ. राममेहर सिंह के अनु-सार 'कांग्रेस की हवा खराब है।' उन्होंने इसका कारण भी बताया : 'पहले कार्यकर्ता ऊपर के सही या गलत सभी फैसलों को मान लेते थे, अब वे निर्णय सही न होने पर उसे मानने को तैयार नहीं।' उनके अनुसार 'अगर चुनाव की बागडोर चौ. बंसीलाल के हाथ में होती तो नतीजा कुछ और होता। अब तो कांग्रेस को राज्य भर से 25 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी—रोहतक जिले की नौ में से 2



ओमप्रकाश गार्ग (इंका) कुरुक्षेत्र और बेवीदास (भाजपा) सोनीपत

सीटों पर ही उसके जीतने की उम्मीद है।' हसनगढ़ चुनाव क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता चौ. माडू सिंह की राय में हरयाणा में 'इंका और लोकदल-भाजपा गठजोड़ की जीत के अवसर लगभग बराबर हैं। उन्होंने यह अलवत्ता कहा कि राज्य में भजनलाल विरोधी हवा है। स्वतंत्रता सेनानी 81 वर्षीय राम-बख्श सैनी ने यह तो माना कि 'मतदाताओं के मिजाज का पता नहीं चलता।' लेकिन उनका कहना है कि पंजाब की घटनाओं का हरयाणा के चुनाव पर असर पड़ेगा। 'लोकल वोटर इंका को वोट देंगे। फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा।'

टिकटों के बँटवारे को ले कर हुई खींचतान ने इंका के आम कार्यकर्ता को निराश किया है और धर्मपाल सैनी के अनुसार 'मामला बड़ा कड़ा (टेढ़ा) है। कांग्रेस की आपसी फूट उसके लिए मझंगी पड़ सकती है। फिर भी कार्यकर्ता तो काम करेंगे ही। हम जायें कहाँ?'



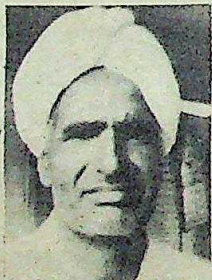


इंका के टिकटों के बँटवारे की शिकायत श्रीचंद ने भी की और कहा कि 'चुनाव में जात-पात का बोलवाला है।' एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी स्थिति यह कह कर स्पष्ट की : '1952 से ले कर पिछले चुनाव तक मैंने और मेरे पूरे परिवार ने कांग्रेस को ही वोट दिया लेकिन इस बार मन डोल रहा है। अब मतदाता को बरगलाया नहीं जा सकता।'

डॉ. राममेहरसिंह के अनुसार 'राजीव गांधी का चुनाव दौरा सफल नहीं रहा। टूकों में ला कर मोड़ जुटायी गयी।' साँपला में श्री गांधी की जनसभा के दौरान फकीर से लगने वाले एक श्रोता ने यह भविष्यवाणी की कि 'यह लड़का अपनी माँ को ले कर देश से भागेगा।' श्री सिंह को यह कथन भविष्य की हकीकत लगता है। यह हकीकत भले ही न हो लेकिन यह हकीकत तो है ही कि श्रीमती गांधी की प्रतिष्ठा इस बार दाँव पर है। भिवानी और हिसार में यह हकीकत और भी उजागर हुई। भिवानी चौ. बंसीलाल का कार्यक्षेत्र है और हिसार भजनलाल का। इन दोनों जिलों में भी इंका को बहुमत नहीं मिला तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बंसीलाल और भजनलाल दोनों ही अपनी आँखें भविष्य पर टिकाये हुए एक दूसरे की काट कर रहे हैं और यह काट सब जगह चल रही है—हिसार हो या हांसी, कुरुक्षेत्र हो या करनाल, पानीपत हो या सोनीपत। यही कारण है कि भिवानी के तोशाम क्षेत्र में बंसीलाल के सुपुत्र सुरेंद्रसिंह की जीत प्रायः निश्चित मानी जा रही है (लोकदल इस चुनाव क्षेत्र में प्रतीकात्मक मुकाबला ही कर रहा है) जबकि बंसीलाल का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी मुंडाल खुर्द में भजनलाल के साथ दल बदल कर इंका में आये राज्यमंत्री ठा. बीरसिंह का भाग्य अघर में लटका है। चरखी दादरी में राजीव गांधी की सभा के दौरान श्रोताओं ने भजनलाल को नहीं सुना जो इन दो जाट नेताओं के आपसी बैर का परिणाम ही बताया गया।

यों चुनाव के बारे में एक राय आम आदमी की भी है। भिवानी के रिक्षाचालक सूरजमान का कहना है कि 'वोट उसे देंगे जो काम करायें और मन बदला नहीं तो वह भाजपा उम्मीदवार रमेश जोशी को वोट देंगे। काम कराने वाले को वोट देने का इरादा रेहड़ी वाले मनोहरलाल का भी है और वह इस 'भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए कांग्रेस के सागरराम गुप्त को वोट देंगे।' यानी हरयाणा के आम आदमी की नजर में भजनलाल की सरकार इंका की सरकार न हो कर जनता पार्टी की सरकार है। शायद उसे ऐसा बताया

गया हो। जपा और भाजपा को ले कर भी कई क्षेत्रों में विभ्रम देखने को मिला, अनेक लोग भाजपा को जपा ही मानते हैं। रामभरोसे मैनपुरी के हैं और पिछले 35 वर्ष से करनाल में किराये का रिक्षा चलाते हैं। जब उनसे चुनाव संभावना के बारे में पूछा तो बोले: 'जनता पार्टी जीतेगी।' कौन सी जनता पार्टी—हलधर वाली या कमल के फूल वाली? उनका उत्तर था 'कमल के फूल वाली।' वैसे वह भी नेताओं से बहुत निराश हैं: 'गरीबों की कोई नहीं सुनता। वोट दे कर चुनते तो हम हैं लेकिन चुने जाने पर वे पैसे वालों का साथ देते हैं।' रामभरोसे के इन शब्दों में मौजूदा राजनीति पर पैसे के वर्चस्व की झलक मिलती है, लेकिन गाँव का मतदाता यह सब सोचता नहीं जान पड़ा। वह या तो दलीय निष्ठा से बँधा है या जातीय निष्ठा से। सिरसा के शब्बूसिंह और हर्वासिंह ठाकुर होने के नाते ठा. बीरसिंह के साथ हैं तो घनाना के चौ. भरतसिंह जाट होने के बावजूद दलीय निष्ठा के कारण उनका साथ दे रहे हैं।



सागरराम गुप्त (इंका) भिवानी और कस्तूरीलाल आहुजा (इंका) पानीपत

यों हरयाणा की राजनीति में जाति का ही अधिक बोलवाला है। सभी राजनैतिक दलों ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही टिकट बाँटे और अब चुनाव प्रचार में भी इस समीकरण को तरजीह दे रहे हैं। यही कारण है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के अधिक वोट हैं, उस जाति के उम्मीदवार जीतने की ही अधिक संभावना है। रोहतक की चौबीसी का फैसला तो पहले से ही सर्व-विदित है, (मेहम चौ. देवीलाल का चुनाव क्षेत्र है, चौबीसी इसी के अंतर्गत है। यहाँ की पंचायत जो फैसला करती है वह पत्थर की लकीर होता है) कुरुक्षेत्र के सैनियों ने भी इस वर्ष बाकायदा आमसभा कर के थह फैसला किया कि वे अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। यह फैसला ही वहाँ लोकदल उम्मीदवार साहबसिंह सैनी की सब से बड़ी पूँजी है जबकि इंका के ओमप्रकाश गंग और जपा के फूलचंद गोयल वैश्य वोटों पर आस लगाये बैठे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार को उम्मीदवारों और दलों के लिए न पड़ का भावी मुख्यमंत्री के लिए पड़ेंगे, संभावना इसकी ही अधिक है। भजनलाल और देवीलाल के चुनाव प्रचार का अंदाज इस बात का सूचक है कि वे यह माने बैठे हैं कि उनके अपने दल को बहुमत मिलने पर वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इस दृष्टि से इन दोनों जाट नेताओं की प्रतिष्ठा दाँव पर है। दो और जाट नेता हैं, जिनके लिए यह प्रतिष्ठा का चुनाव वे हैं लोकदल अध्यक्ष चौ. चरणसिंह और इंका नेता चौ. बंसीलाल। भजनलाल पर अवरोध वरीयता सिद्ध करने के लिए बंसीलाल को कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और यही



भरतसिंह और मनोहरलाल

चरणसिंह तथा देवीलाल पर भी लागू है। लोकदल उम्मीदवारों में आये दिन बदलाव इसके प्रमाण हैं कि भीतर ही भीतर चरणसिंह और देवीलाल के बीच टकराव चल रहा है जिसका खामियाजा कुछ उम्मीदवारों को भुगतना पड़ सकता है।

जहाँ तक लोकदल और भाजपा के गठजोड़ का प्रश्न है वह सारे राज्य में प्रचलित है। दोनों दलों के कार्यक्षेत्रों में कंधे से कंधा मिला कर चुनाव अभियान चला रहे हैं। शाहबाद के एक लोकदल नेता हनुमंतसिंह ने बताया, 'शुरू में लोकदल के बंदराने के स्थानों पर गठजोड़ के बीच टिकटों के बँटवारे को ले कर कार्यकर्त्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया हो लेकिन अब किसी तरह का टकराव नहीं रहा।' इंका की तरह लोकदल में कुछ बागी उम्मीदवार अवश्य बने हुए हैं। किंतु दोनों दलों के ऐसे उम्मीदवारों को इन दोनों दलों के ऐसे उम्मीदवारों के साथ मिलकर प्रभावित करने की स्थिति में हैं, जैसे रोहतक में ला. हरीमोह नीलोखेड़ी में मू. पू. विद्याधर सिंह इत्यादि। गठजोड़ का अधिकतम फायदा भाजपा को मिलेगा। उस के पास अधिकतर शहरी सीटें हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि गठजोड़ के सहारे भाजपा



## आवरण कथा

इस बार भी...  
लेन पड़...  
इंगे, संभाव...  
ल और देवी...  
स बात का...  
उनके अपने...  
मुख्यमंत्री...  
जाट नेताओं...  
जाट नेता...  
ठा का चुनाव...  
चरणसिंह...  
नलाल पर अ...  
वंसीलाल...  
और यही...

अनता पार्टी के प्रभाव को देखते हुए ऐसा  
ली लगता है कि नयी विधानसभा में वह चार  
विधायक भी भेज सकेगी. भू. पू. प्रधानमंत्री  
राजीव देसाई और जपा अध्यक्ष चंद्रशेखर  
राजाजी दोनों से भी स्थिति में कोई उल्लेख-  
नीय परिवर्तन नहीं आया है. करनाल जिले  
की स्थिति अन्य जिलों से बेहतर  
पड़ी जिसका श्रेय जिला जपा अध्यक्ष

कमल सिंह और युवा जनता अध्यक्ष कमल  
सिंह जैसे कुछ उत्साही युवा कार्यकर्ताओं  
को दिया जा सकता है. लेकिन उनका उत्साह  
सीट निकाल सकेगा इसकी संभावना  
ही है. कांग्रेस (ज) की स्थिति भी जपा  
से बेहतर नहीं है. किंतु दोनों में एक अंतर है—  
जपा उम्मीदवार जहाँ लोकदल-भाजपा

उम्मीदवारों को हानि पहुँचायेंगे वहाँ कांग्रेस  
इंका के वोट काटेगी. इस चुनाव की एक  
वस्तु यह भी है कि जयगुरुदेव के

भी कई स्थानों पर दूरदर्शी पार्टी के  
से चुनाव लड़ रहे हैं. इस पार्टी ने 50  
उम्मीदवार खड़े किये हैं. करनाल,  
सोनीपत में सर्वाधिक दूरदर्शी  
उम्मीदवार हैं. लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस  
का कोई भी उम्मीदवार अपने

क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा  
सकेगा.

राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में

राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में

राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में

राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में

राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में  
राज्य में

## हिमाचलप्रदेश

### साधनों और उपलब्धियों का संघर्ष

हिमाचल के पर्वतीय प्रदेश में विधानसभा  
के चुनावों में सत्ता का संघर्ष इतना तीव्र  
तथा भयंकर कभी नहीं था, जितना इस बार  
दिखायी दे रहा है, क्यों कि सत्ताधारी इंका  
को पहली बार (1977 की विशेष स्थिति के  
अतिरिक्त) सीधे तौर पर एक ही पार्टी  
कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है जिसके अधि-  
संख्य नेता तथा सहयोगी लगभग 30 महीने  
तक सत्ता का स्वाद चख चुके हैं.

भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इंका  
के किले पर संगठित आक्रमण किया है, और  
यह कहना अनुचित न होगा कि परिणाम  
अथवा फल पाने की साधकता से परे, भाजपा  
के समर्थक सत्ताधारी पार्टी को जबर्दस्त ढंग  
से झकझोरने में सफल होते हैं और यदि 19  
मई के मतदान में सत्ता उनके हाथ आ गयी  
तो उनकी मेहनत को एक निश्चित अर्थ  
मिल सकेगा.

मले ही इस चुनाव में भाजपा ने 'न नारे  
को न नाम को, वोट हमारे काम को' को अपने  
चुनाव अभियान के मुख्य नारे के रूप में चुना  
है, किंतु वास्तव में इंका के साधनों के सामने  
भाजपा अपने काम को ही कसौटी के रूप में  
प्रस्तुत कर सकती है तथा उन तीस महीनों  
के लिए गर्व से सिर ऊँचा कर सकती है, जब  
1977-80 तक के समय में शांताकुमार  
के नेतृत्व में उसने जनता सरकार को  
चलाया था.

हिमाचल विधानसभा के 68 चुनाव क्षेत्रों  
में कुल 441 प्रत्याशी मैदान में हैं और केवल  
सोलन की एक सीट को छोड़ कर, जहाँ श्रीपाव  
अमृत डांगे की आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी  
के लिए इंका ने सीट छोड़ दी है, शेष सभी सीटों  
पर इंका के प्रत्याशी हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ठाकुरसेन नेगी, जो  
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कुछ  
वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे, किन्नोर क्षेत्र से पुनः  
चुनाव लड़ रहे हैं, किंतु स्वस्थ परंपरा हेतु  
उनके विरुद्ध भाजपा ने कोई प्रत्याशी खड़ा  
नहीं किया, जब कि इंका ने एक अवकाशप्राप्त  
बनाधिकारी को टिकट दिया है.

मुख्य चुनाव संघर्ष इंका तथा भाजपा के बीच  
है, इसलिए यह चर्चा करना भी उचित होगा  
कि भाजपा तथा लोकदल में चुनाव समझौता  
हो जाने के बावजूद उनमें परस्पर टकराव की  
स्थिति अनेक स्थानों पर बनी हुई है, जब कि  
सत्ताधारी पार्टी को एक अन्य खतरा अपने उन  
विरोधी सदस्यों से बना हुआ है, जो टिकट न

मिल पाने के कारण अधिकृत प्रत्याशियों के  
विरुद्ध खड़े हो गये हैं.

इन चुनावों में वास्तविक मुद्दे स्थिरता, जिसे  
इंका ने अपने चुनाव घोषणापत्र का आधार  
बनाया है तथा बेहतर प्रशासन तथा सुनि-  
योजित विकास, जिसे भाजपा ने अपनाया है,  
सम्मिलित हैं.

दलबदल के दलदल में ग्रस्त होने के कारण  
हिमाचल प्रदेश में भाजपा इस नारे को न्यायो-  
चित्त मानती है जब कि इंका नेताओं ने  
सिर्फ यह कहना काफी समझा है कि केवल  
इंका ही एक स्थिर और पूरी अवधि तक चलने  
वाली सरकार दे सकती है तथा 1977 के  
बाद जनता पार्टी का जो हथ महत्वाकांक्षी  
नेताओं के हाथों हुआ उसे अपनी दलील के  
समर्थन में पेश करती है. इंका की ओर से प्रधान-  
मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी लग-  
भग दो दर्जन स्थानों पर चुनाव समाएँ संबोधित



शांताकुमार



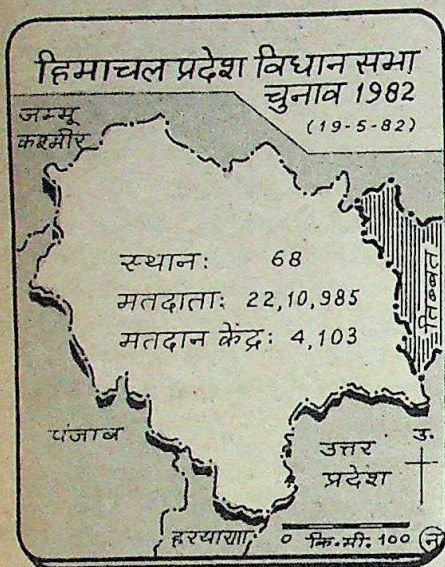
रामलाल

कर के इस बात पर बल देते दिखायी दिये कि  
केंद्र तथा राज्यों में आपसी सद्भाव के लिए  
भी यह आवश्यक है कि प्रदेशों में भी इंका  
की सरकार बने, जब कि भाजपा के वरिष्ठ  
नेता लालकृष्ण आडवाणी, श्रीमती विजया  
राजे सिंधिया तथा भाजपा अध्यक्ष अटल-  
बिहारी वाजपेयी ने इसे लोकतांत्रिक ढाँचे पर  
प्रहार तथा इंका की उस मनःस्थिति का  
परिचायक बताया है जिसका एकमात्र उद्देश्य  
देश भर में केवल एक पार्टी राज्य की स्थापना  
के सपने को साकार करना है.

वास्तविक स्थिति क्या है? कुछ प्रमुख  
चुनाव क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा हिमाचलप्रदेश  
के अनेक क्षेत्रों के दौरे से बिमलान के प्रतिनिधि  
ने यह पाया कि निस्संदेह भाजपा सत्ताधारी  
दल के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर रही है  
और संभव है कि उस में कुछ सीमा तक उसे  
सफलता भी मिल जाये, किंतु इंका अपने को  
सत्ता में बनाये रखने के लिए पूरी तरह सजग



## आवरण कथा



प्रतीत होती है तथा इस के लिए कार्यरत है। विपक्षी दलों में किसी ठीक किस्म के समझौते का अभाव, भाजपा, लोकदल, जनता पार्टी, भाकपा, माकपा के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों में विद्रोही इका प्रत्याशियों के खड़े रहने से यह संभावना बनी हुई है कि मतदाताओं में व्याप्त इस बँटवारे से लाभ उठा सकने में इका शायद सफल हो जाये, भले ही उसे 68 स्थानों में सिर्फ उतने ही स्थान मिल सकें जिस से उसे सरकार बना पाने में सफलता मिल जाये।

दूसरी ओर भाजपा इस संबंध में पूरी तरह आश्वस्त दिखाई देती है कि सरकार बनाने का अवसर उसे ही मिलेगा, क्योंकि दल बदलुओं के सहारे 1980 में सरकार बना लेने का इका का काम आम लोगों को पसंद नहीं आया और दलबदल के विरुद्ध जन साधारण में भावनाएँ बराबर बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री रामलाल का अपने पुराने चुनाव क्षेत्र जुबल कोठी में भाजपा प्रतिद्वंद्वी श्यामलाल से कड़ा मुकाबला है। दो निर्दलीय भी मैदान में हैं। श्री रामलाल, जो कि 1977 की जनता लहर में भी उखाड़े नहीं जा सके थे, इस बार भी मजबूत स्थिति में हैं।

मुलेह क्षेत्र में भाजपा नेता तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री शांतकुमार भी रामलाल की भाँति काफी अच्छी स्थिति में हैं, हालाँकि इका ने उन्हें उखाड़ने के लिए यहाँ काफी जोर लगा रखा है। हिमाचल प्रदेश इका अध्यक्ष श्रीमती सरला शर्मा को जो अपने स्वर्गीय वामपंथी पति कामरेड परसराम के चुनाव क्षेत्र जसवन, जिला कांगड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, पति की पार्टी भाकपा के प्रत्याशी के अलावा मुख्य रूप से भाजपा उम्मीदवार ठाकुर आजाराम, लोकदल के डा. जगरूप सिंह से जूझना पड़ रहा है और वोटों का बँटवारा शायद उनके

पक्ष में रहे।

कांगड़ा जिले के थुरल चुनावक्षेत्र से हिमाचल लोकदल अध्यक्ष कुंवर दुर्गाचंद को, जो राजनीतिक जीवन के एक लंबे समय तक जनसंघ में रह चुके हैं, श्रीमती चंद्रेश कुमारी (इका) के हाथों काफी जूझना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गंगासिंह, जो जोगिंदर नगर (मंडी जिला) से लड़ रहे हैं, लगभग सुरक्षित दिखाई देते हैं। इका के रतनलाल के अतिरिक्त माकपा के तारा चंद, लोकदल के कृषिराज और अनेक निर्दल प्रत्याशी मैदान में हैं। मंडी जिले में गंगासिंह का काफी दबदबा है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य रह चुके हैं।

रमणीय चंबा जिले के भाटियात क्षेत्र से शिक्षामंत्री शिवकुमार उपमन्यु इका के प्रत्याशी हैं। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी टिकट पर चुनाव जीता था, किंतु वास्तव में उनका, उनके परिवार का निजी और राजनीतिक प्रभाव सारे चंबा जिले में महसूस किया जा सकता है। उनके स्वर्गीय पिता पंडित जयवंत राम शर्मा, जिन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी टक्कर भाजपा के कप्तान अमरसिंह से है।

चंबा चुनाव क्षेत्र से भाजपा के किशोरी लाल बंध अपने इका प्रतिद्वंद्वी सागर चंद तथा जनता पार्टी के उम्मीदवार से काफी आगे दिखाई देते हैं, जबकि इका के विद्याधर को राजनगर सुरक्षित क्षेत्र से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा इसको अपना काफी पक्का क्षेत्र मानती है।

देहरादून (उ. प्र.) से लगने वाले चुनाव क्षेत्र पीता साहिब (जिला सिरमौर) से इका के प्रत्याशी कुश परमार, अपने समुर मुख्यमंत्री रामलाल के कारण न भी प्रभावी हों, किंतु अपने पिता डॉ. परमार के प्रभाव का लाभ उठाने में सफल रहे हैं, जब कि विरोधी इका प्रत्याशी रतनसिंह, जिन्होंने 1977 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, उनके लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं।

कांगड़ा जिले के बमसान क्षेत्र से उद्योग-मंत्री रणजीतसिंह वर्मा की हालत काफी पेचीदा दिखाई देती है।

मोटे तौर पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भाजपा के चुनाव प्रचार में अनेक कार्यकर्ता दिल्ली से आये हैं जिन में विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना आदि शामिल हैं। ये सत्ताचारी दल को उखाड़ने के लिए सक्रिय दिखाई देते हैं। और सत्ता की इस दौड़ में भाजपा इका के बीच काफी कम फासला इस समय दिखाई देता है।

## पश्चिम बंगाल

### उपलब्धियों का लेखाजोखा

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 29 सीटों के लिए कुल 1,206 उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं। आगामी 19 मई राज्य में मतदान होगा, जिस के दौरान लगभग तीन करोड़ लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। चुनाव पर कुल 4 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की यात्रा पर हुआ 10 लाख रुपए का खर्च शामिल नहीं है।

इस बार चुनाव की एक बड़ी विशेषता यह है कि मतदान का दिन बहुत निकट होने के बावजूद राजनैतिक दलों द्वारा धुंधला प्रचार नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में अभी तक यह प्रचार किया जा रहा है कि अंत में चुनाव स्थगित भी हो सकता है।

चुनाव के लिए वामपंथी मोर्चा पहले से पूर्ण तैयार था और उसने अपनी योजना अनुसार समय से सीटों का बँटवारा किया। चुनाव घोषणापत्र जारी किया और विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग बहुत बाद में प्रचार करने मैदान उतरे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बंगाल के बाद इका के प्रचार में तेजी आयी।

मजबूत पकड़ : चुनाव प्रचार और मतदाताओं को देखने से लगता है कि राज्य में वामपंथी दलों की पकड़ काफी मजबूत है और इका के लिए उन्हें उखाड़ फेंकना नहीं है। 1977 में कुल 229 सीटें मोर्चा जीत मिली थीं, जिस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सीटें 177 थीं। दूसरे शब्दों में भाजपा वादी अकेले सरकार बना सकने की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी घटकों को पिछली मोर्चा सरकार से समान ही और लगभग उसी अनुपात में मंत्रिपद प्रदान किया। इस से चुनाव के बाद मोर्चा की एकता बनी रही।



ज्योति बसु



अजित घोष



इस बार चुनाव के पहले राज्य के एक प्रमुख वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी मोर्चा में शामिल कर लिया गया है। इसी तरह जनता पार्टी से टूट कर निकले समाजवादियों ने भी मोर्चा का साथ दिया है और वे प. बंगाल समाजवादी पार्टी के रूप में मोर्चा के घटक हो गये हैं। गणतान्त्रिक समाजवादी दल भी मोर्चा के साथ है, जिस के नेता हेमवतीनंदन बहुगुणा ने डायमंड हार्बर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह सीट किसी और को देना स्वीकार नहीं किया। अब मुख्यमंत्री ज्योति बसु के भांजे अमल दत्त डायमंड हार्बर से मार्क्सवादी उम्मीदवार हैं। उनके विरुद्ध कांग्रेस (इं) ने एक वकील जैनुल आबदीन को खड़ा किया है।

यहाँ दोनों दलों के बीच कांटे की कुश्ती होने का अनुमान है, हालाँकि राज्य विधानसभा की लगभग सब सीटें पिछली बार मोर्चा को प्राप्त हो गयी थीं।

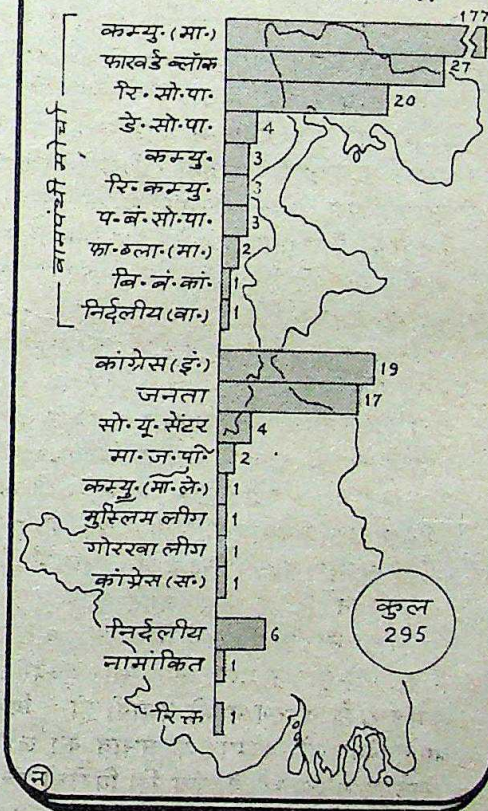
मार्क्सवादी मोर्चा के नेता अपने शासन काल का हिसाब पेश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। पहला हिसाब यह है कि आते समय ही उन्होंने जेलों में बंद तीन हजार से कुछ अधिक नक्सलवादियों को बिना शर्त रिहा कर दिया और उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया। नक्सलवादियों के साथ कुछ समाज विरोधी तत्व भी मुक्त हो गये, लेकिन सरकार ने यह खतरा मोल लेने का साहस किया। सरकार ने घोषणा की कि बिना मुकदमा चलाये वह किसी को गिरफ्तार कर नजरबंद नहीं रखेगी और इस तरह के किसी भी कानून का विरोध करेगी। सब से अच्छा काम मोर्चा सरकार ने राज्य में बंगला को बुनियादी शिक्षा का माध्यम बना कर किया, जिसका अंग्रेजी के गुलाम लोगों द्वारा तीव्र विरोध भी किया गया। अब राज्य में कक्षा पाँच तक शिक्षा का माध्यम केवल बंगला है। इस के ऊपर की कक्षाओं में अंग्रेजी शुरू होगी। मोर्चा सरकार के 36 सूत्री कार्यक्रम में वर्ग आपरेशन और काम के लिए अनाज कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी। लेकिन इस दिशा में उसे कितनी सफलता मिली है और ग्रामीण बंगाल का मानचित्र कितना बदला है, इसका पता मतदान के समय लगेगा। मुख्यमंत्री श्री बसु और वामपंथी मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोददास गुप्त ने एक से अधिक बार कहा है कि कोई ऐसा कारण नहीं कि संगठित मोर्चा असंगठित कांग्रेस (इं) के सामने पराजित हो जाये।

**अंतिम स्थिति :** चुनाव पूर्व अंतिम स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि मार्क्सवादी मोर्चा कुछ सीटों के हेरफेर से पुनः

सत्ता में आ सकता है। इस का कारण यह है कि उसने जीतने के लिए संगठित रूप से कार्य किया है और निर्वाचन तंत्र द्वारा जनता का वोट लेने की स्थिति में है। राज्य की आबादी में लगभग 25 प्रतिशत मतदाता मुसलमान हैं, जो पहले कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। लेकिन पिछले निर्वाचन में उन्होंने मोर्चा का साथ दिया था। मार्क्सवादियों के सत्ता में आने के बाद से राज्य में सांप्रदायिक उपद्रव नहीं हुए।

इंका की स्थिति अंतिम क्षणों में कुछ सुधरी, लेकिन लगता है काफी देर हो चुकी है। सारे एकता प्रयासों के बावजूद अनेक क्षेत्रों में कांग्रेस (इं) के लोग अपने ही उम्मीद-

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (19.5.92)  
से पहले वि. स. सदस्यों की  
वर्तमान दलीय स्थिति



वारों की जड़ें खोद रहे हैं। इंका के 50 प्रतिशत उम्मीदवार नये हैं। इस दल के अनेक प्रतिष्ठित नेताओं को टिकट नहीं मिला है, जिस से वे नाराज हैं। दरअसल इस बार टिकट का बँटवारा केंद्रीय संसदीय परिषद द्वारा किया गया और टिकट उन्हें ही मिले जो बंगाल के दो केंद्रीय मंत्रियों, गनी खान चौधरी और प्रणव मुखर्जी के गुटों में थे।

राज्य में अन्य दलों की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस (स) कांग्रेस (इं) के साथ मिल कर चुनाव लड़ रही है, इस लिए दो चार सीट की उम्मीद कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी को किसी तरह विधान-

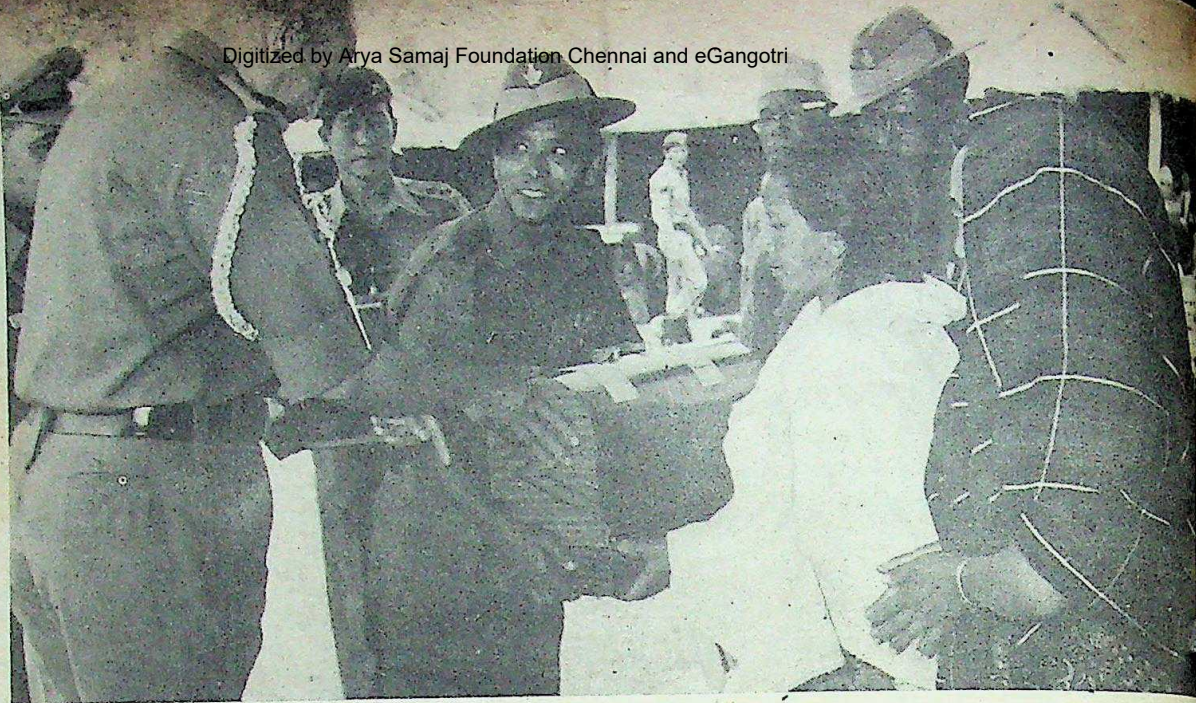
सभा में एक दो प्रतिनिधि भेजने का मौका मिल जाये तो बहुत होगा।

**बिजली, चीनी, गेहूँ :** ठीक चुनाव के पहले राशनशुदा इलाकों में गेहूँ और चीनी की आपूर्ति में बाधा पड़ी है। वामपंथी मोर्चा के नेता प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र ने चुनाव को नजर में रखते हुए अनाज और चीनी की आपूर्ति कम कर दी है। राज्य में बिजली की आपूर्ति में भी भारी कटौती चल रही है। दामोदर घाटी निगम ने अधिकृत तौर पर घोषणा कर राज्य के लिए, खास कर कलकत्ता महानगर के लिए बिजली की आपूर्ति में और कटौती कर दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझ कर विद्युत संकट गहरा करने के लिए ऐसा किया है।

**32 सीधी टक्करें :** अंतिम आँकड़ों के अनुसार 14 जिलों में कुल 32 स्थानों पर सीधी टक्करें होंगी। इन टक्करों में 23 स्थानों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सीधी टक्करों में कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार 26 स्थानों पर हैं। दो स्थानों पर कांग्रेस (स) के उम्मीदवार मोर्चा के उम्मीदवारों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। सीधी टक्करों में मुख्यमंत्री की सीट सतगाछिया भी शामिल है। यह 24 परगना जिले में कलकत्ता महानगर से थोड़ी दूर पर है। श्री बसु को पिछली बार यहाँ से 45 हजार से भी अधिक मत मिले थे, जब कि कांग्रेस (इं) के उम्मीदवार को 7 हजार मत ही मिल पाये थे। इस बार भी इंका के उम्मीदवार कोई बड़े नेता नहीं, एक साधारण (प्राइमरी) स्कूल अध्यापक दीनबंधु वैरागी हैं।

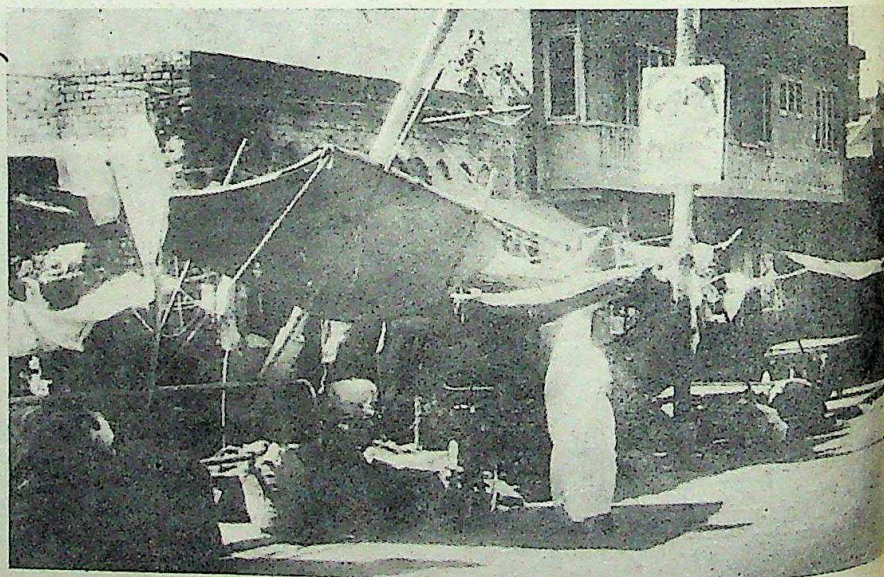
चौबीस परगना कलकत्ता महानगर को तीन तरफ से घेरे हुए है। देश के सब से बड़े इस जिले में विधानसभा की पचास सीटें हैं। अनेक दृष्टियों से यह विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र है। श्रमिक मतदाता और सुंदरवन के मतदाता इस क्षेत्र में पड़ते हैं। समाजवादी एकता केंद्र और मुस्लिम लीग भी इसे अपना गढ़ मानते हैं। पहले यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस जिले के आम डांगा क्षेत्र में न्यायमंत्री हाशिक अब्दुल हलीम (मार्क्सवादी) का मुकाबला जनता पार्टी के अशोककृष्ण दत्त और मुस्लिम लीग के मोहिदुल इस्लाम से हो रहा है। पिछले चुनाव में हलीम साहब भारी बहुमत से विजयी हुए थे। देगंगा सीट से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ए. के. एम. हसनुज्जमा खड़े हैं, जिनका मुकाबला दो निर्दलीय और एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार से होगा। पिछली बार हसनुज्जमा यहाँ से जीते (शेख पृष्ठ 28 पर)





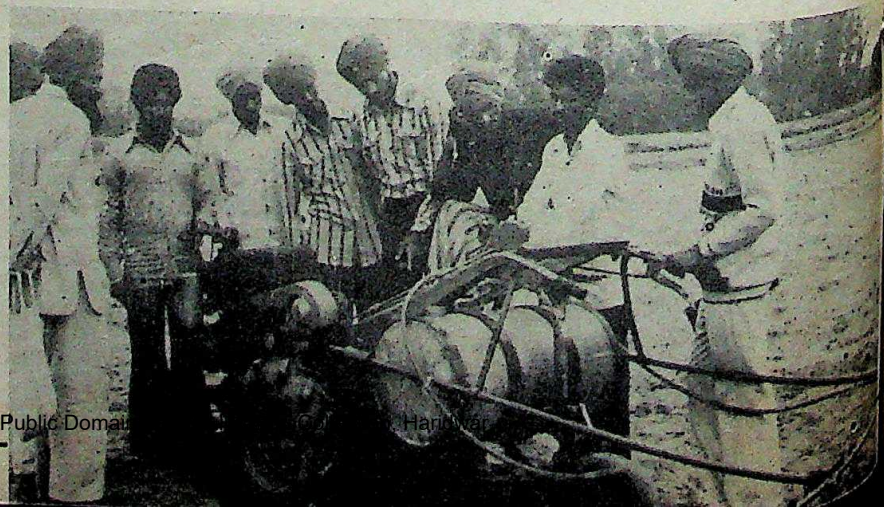
भारत के थलसेनाध्यक्ष जनरल के. बी. कृष्णराव ने हाल ही में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान पोखरा में मृतपूर्व सैनिकों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट (नेपाली सैनिकों की टुकड़ी) की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले गोरखाओं की विधवाओं-वीर नारियों को सिलाई मशीनें भेंट की। (ऊपर)

(नीचे) एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के दौरान अमृतसर की सब्जीमंडी में लोहगढ़ फाटक के अंदर की बंद दुकानें।



मणिपुर के भूमिगत उपवादी अब हर जगह फैल गये हैं। इन्हीं के 28 वर्षीय नेता चोइ थाम विजय सिंह को नयी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। (ऊपर) अपने को 'मेजर' कहने वाले विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और मणिपुर के एक अवकाशप्राप्त पुलिस अधिकारी के पुत्र हैं। मणिपुर और नगालैंड में कई डकैतियों और चोरियों के सिलसिले में पुलिस को इन की तलाश थी।

कृषि में मशीनीकरण के साथ साथ गाँव के किसान अब सिंचाई के लिए अधिक से अधिक तेल के इंजनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। (दाएँ)



(ऊपर) मणिपुर के चोइ थाम, जो फ्रांसीसी सेना में था, को भारत में भेजते हुए भारत सरकार ने उसे स्वागत किया।  
दक्षिण कोशिस वाले ने, र अधाधुन गो निचिया में वह शिकार व्यक्ति

छोटा भारत  
बार फिर जारी  
राधिकारी चा  
एक बच्ची से ब  
1984 में लॉ  
को लंबी बी  
पर हो रही हैं।  
को बीड डारि  
गोपत किया है। य  
तो है और 197  
के फोटोकारी 3







ये. वादुरिया सीट से इका के भूतपूर्व महा-सचिव काजी अब्दुल गफ्फार खां खड़े हैं, जहाँ उन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी उम्मीदवार मोस्तफ़ुर बिन कासिम से होगा। गार्डन रीच से मार्क्सवादी उम्मीदवार छेदी-लाल गुप्त खड़े हैं, जिन का मुख्य मुकाबला मोहम्मद शमसुज्जोहा से होगा। टीटागढ़ से परिवहनमंत्री मुहम्मद अमीन (मार्क्सवादी) खड़े हैं, जिन को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस (इ) के गंगा प्रसाद शाह और जनता पार्टी के अंबिका प्रसाद. मेदिनीपुर में 37 सीटें हैं. यहाँ मार्क्सवादियों के साथ कुछ कम्युनिस्ट (गैरमार्क्सवादी) और जनता पार्टी के टूटे हुए लोग भी हैं. कांग्रेस (इ) को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. चौबीस परगना के समान ही हावड़ा और हुगली श्रमिक प्रधान क्षेत्र हैं, जहाँ मार्क्सवादी प्रभाव अधिक रहा है. अनेक कारखानों के बंद हो जाने से कहीं कहीं स्थिति बदली हुई है जिस का प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है. दार्जिलिंग में मार्क्सवादी उम्मीदवारों को, जिन की संख्या 4 है, लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं. कांग्रेस (इ) ने यहाँ से तीन उम्मीदवार खड़े किए हैं. नदिया और पश्चिम दिनापुर में नक्सलवादी चुनाव की राजनीति के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं. लेकिन इस का मतदान पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है. केंद्रीय ऊर्जामंत्री गनीखान चौधरी अपने जिले की सभी ग्यारह सीटों पर एडी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं. एक उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक का है.

**कलकत्ता में कांटों की कुश्तियाँ :** कलकत्ता महानगर में अनेक स्थानों पर कांटों की कुश्तियाँ हो रही हैं. 19 आनंदमार्गियों की बालीगंज में हुई निमंत्रण हत्या से वहाँ वातावरण बदला हुआ बताया जाता है. कांग्रेस (इ) के धुन्न चक्रवर्ती ने दावा किया कि बालीगंज से कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार रथीन तालुकदार अब आसानी से निकल जायेंगे, क्यों कि मार्क्सवादी उम्मीदवार सचिन सेन इस बार इस घटना के कारण कमजोर पड़ गये हैं.

जोड़ा बगान में कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार सुब्रत मुखर्जी की स्थिति कमजोर नजर आती है, क्योंकि भूतपूर्व कांग्रेसी स्व. नेपाल राय की पत्नी इला राय कांग्रेस (इ) से निकल कर जनता पार्टी में चली गयी हैं और उन का विरोध कर रही हैं. लेकिन श्री मुखर्जी का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के युगलकिशोर जैयलिया और मार्क्सवादी उम्मीदवार श्रीमती सरला महेश्वरी से है. जोड़ा सांकू में कुल 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन

दिनमान



अशोक मित्र (माकपा), विष्णुकान्त शास्त्री और सुब्रत मुखर्जी (इंका)

मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रो. विष्णुकान्त शास्त्री, मोर्चा के उम्मीदवार श्यामसुंदर गुप्त (फॉरवर्ड ब्लॉक) और कांग्रेस (इ) के भूतपूर्व विधायक देवकीनंदन पोद्दार के बीच होगा. बड़ा बाजार क्षेत्र से भी 12 उम्मीदवार खड़े हैं, जिन में इंका के कोषाध्यक्ष राजेश खेतान, वर्तमान विधायक रविशंकर पांडेय (गणतान्त्रिक समाजवादी दल-मोर्चा द्वारा समर्थित) और भारतीय जनता पार्टी के श्याम कन्हैया सिंह प्रमुख हैं.

बहु बाजार से इंका नेता और भूतपूर्व मंत्री अब्दुल रऊफ अंसारी खड़े हैं, जिन का मुकाबला वर्तमान मार्क्सवादी विधायक अबुल हसन से हो रहा है. श्री अंसारी की स्थिति इस वर्ष सुधरी नजर आती है. लेकिन मार्क्सवादियों के कुछ गढ़ इस क्षेत्र में हैं, जिस से उन्हें चिंता हो रही है. चौरंगी से पिछले चुनाव में जनता पार्टी के संदीप दास चुने गये थे, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबला नेता जी सुभाषचंद्र बोस के भतीजे डॉ. शिशिर बोस और मार्क्सवादी डॉ. जहूरल हक के बीच हो रहा है. इस क्षेत्र में अमीरों के मत अधिक हैं, इस लिए श्री हक को परेशानी उठानी पड़ रही है. कवित्तीथ क्षेत्र से उपाध्यक्ष कलीमुद्दीन शमा के फिर जीतने के आसार बढ़ गये हैं, क्यों कि यहाँ कांग्रेस (श) के उम्मीदवार सौगात राय बाहर के उम्मीदवार समझे जा रहे हैं और कांग्रेस (इ) के रामप्यारे राय उन का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला. लोकदल के नूर अहमद और जनता पार्टी के केशव अग्रवाल विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं. एक निर्दलीय सलीम खान मैदान में है.

अलीपुर में मोर्चा विधायक मंडल के मुख्य सचेतक अशोककुमार बोस का मुकाबला इंका के उम्मीदवार अनूपकुमार चंद्र से है. रासबिहारी क्षेत्र से राज्य के वित्तमंत्री डॉ. अशोक मित्र खड़े हैं, जहाँ से वह पहले जीते थे. लेकिन इस बार हजारों लोग उन का इस

लिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने 500 रु. से अधिक आय वाले हर व्यक्ति पर 'व्यवसाय कर' (प्रोफेशनल टैक्स) लगा दिया है.

टालीगंज में मार्क्सवादी उम्मीदवार प्रशांत सूर (नगर विकासमंत्री) को भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाल में उन के एक निर्वाचन कार्यालय में कुछ विरोधियों ने आग लगा दी थी, जिस से पास के कई मकान जल गये और एक युवक की भी जल जाने से मृत्यु हो गयी. श्री सूर का मुकाबला कांग्रेस (इ) के असीम दत्त से है, जिन्होंने पुलिस की सहायता से अपना नामांकन दर्ज किया था. धाकुरिया से जनकार्यमंत्री जतीन चक्रवर्ती फिर खड़े हैं. इस बार उन के विरुद्ध इंका के उम्मीदवार तुषारकांत दासगुप्ता हैं.

केरल

## क्या भाजपा निर्णायक भूमिका निभायेगी?

1956 में केरल राज्य के जन्म से लेकर अब तक इस प्रदेश के जागरूक मतदाता एक स्थायी सरकार चुनने की उम्मीद में, सात बार मतदान कर चुके हैं. 19 मई को आठवीं बार केरल में विधानसभा के 140 स्थानों के लिए चुनाव होंगे, जहाँ 699 उम्मीदवार चुनाव के अखाड़े में मौजूद हैं. वैसे तो अधिक कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्रों में संयुक्त गणतान्त्रिक मोर्चा और वामपंथी गणतान्त्रिक मोर्चे के बीच सीधी टक्कर होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी मैदान में उतरने से स्थिति कुछ जटिल दिखायी पड़ती है. वैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आधे से कुछ ही अधिक चुनाव क्षेत्रों में खड़े हैं, जिस से यह साबित होता है कि यह दल इस प्रदेश में सत्ता की आकांक्षा नहीं रखता; केवल परीक्षण के लिए ही उसने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. वैसे भारतीय जनता पार्टी समझती है कि

वह केरल  
— दर्जन  
यहाँ तो रि  
राजनीति  
राजनैतिक  
वामपंथी  
नेतृत्व मा  
कम्युनिस्ट  
कांग्रेस (स  
मुस्लिम ली  
केरल कांग  
समाजवादी  
हैं. इन के  
मोर्चा के उ  
में कांग्रेस  
कांग्रेस (उ  
नेशनल डेमो  
कन पार्टी,  
आर. एस. प  
मछेरों व  
असली मुक  
उम्मीदवारों  
उम्मीदवारों  
में है, जिन में  
किसी एक  
मार्क्सवादी  
51 क्षेत्रों में  
उम्मीदवारों  
माकपा का च  
इनमें अधिसं  
से टूट कर अ  
दिये गये थे.  
हंसा भी शा  
क्षेत्रों में हैं औ  
कम्युनिस्ट पा  
के 18, मुस्लि  
(म) के 17  
भारतीय मुस्लि  
(ज) के 12  
(कांतिकारी)  
एस. आर. पी  
(समाजवादी)  
हैं. इन दलों के  
पाटियों के केव  
उम्मीदवारों क  
तों में मोर्चा  
भूमिका निभायें  
संयुक्त गणत  
कर पनपने वा  
शामजूद उस के  
से संयुक्त गुट  
समर्थन और उन  
भी प्राप्त है, जि  
निष्पत्ति



वह केरल में अधिक स्थान प्राप्त नहीं कर सकती—दर्जन भर स्थान मिल जायें तो काफी हैं। यहाँ तो सिर्फ यह दिखाना है कि इस देश की राजनीति में उसका भी स्थान है, जिसे अन्य राजनैतिक दल नजरंदाज नहीं कर सकते।

वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे में, जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी कर रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस (स), जनता पार्टी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, केरल कांग्रेस (समाजवादी), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (बहुगुणा) और लोकदल हैं। इन के मुकाबले में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार हैं, जो इका के नेतृत्व में कांग्रेस (एंथनी) मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (जोसेफ), जनता (क्रांतिकारी), नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, आर. एस. पी. (श्रीकांतन), आर. एस. पी. (राष्ट्रीय) और डी. एल. पी. (मछेरों का दल) से मिल कर बना है। असली मुकाबला इन दोनों मोर्चों के 280 उम्मीदवारों में ही है। इन के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों की भी एक बड़ी संख्या मैदान में है, जिन में से कुछ को दो प्रमुख दलों में से किसी एक का समर्थन प्राप्त है, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी 51 क्षेत्रों में हैं और 9 क्षेत्रों में वह निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, जिन्होंने माकपा का चुनाव चिन्ह भी अपना लिया है। इनमें अधिसंख्य संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे से टूट कर आये हैं, क्यों कि उन्हें टिकट नहीं दिये गये थे। इनमें इका के प्रादेशिक अध्यक्ष हंसा भी शामिल हैं। इका के प्रत्याशी 35 क्षेत्रों में हैं और एंथनी कांग्रेस के 28, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 26, कांग्रेस (समाजवादी) के 18, मुस्लिम लीग के भी 18, केरल कांग्रेस (स) के 17, जनता पार्टी के 13, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 12, केरल कांग्रेस (ज) के 12, आर. एस. पी. के 8, जनता (क्रांतिकारी) के 8, एन. डी. पी. के 8, एस. आर. पी. के 6 और आर. एस. पी. (समाजवादी) के 4 उम्मीदवार भी डटे हुए हैं। इन दलों के अलावा दोनों मोर्चों की अन्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 356 है, जो कि मुकामा निमायेंगे।

संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चे में स्थानों को ले कर पनपने वाली फूट सर्वविदित है, लेकिन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए यह सब संयुक्त गुट है। इस मोर्चे को इसाइयों का भी प्राप्त है, जिन का मतदाताओं की एक बड़ी



संख्या पर बहुत प्रभाव है। संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा के कुछ नेता स्वीकार करते हैं कि उन की आपस में एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति या स्नेह नहीं है। मिल कर चुनाव लड़ने का एकमात्र मकसद है सत्ता का बँटवारा। इस के विपरीत वामपंथीय मोर्चे में मार्क्सवादी पार्टी अन्य दलों के मुकाबले सशक्त होने के कारण इस में शामिल छोटे दलों को सीटों के बँटवारे को ले कर अपना असंतोष व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। जो कुछ मिला वही उन्होंने स्वीकार किया। इस लिये केरल के मतदाता इस बारे में सचेत हैं कि संयुक्त मोर्चा के दल जब सीटों को ले कर जूझ रहे थे तो सत्ता में आने पर एकजुट हो कर वे शासन कैसे चला पायेंगे और इस बात का असर संयुक्त मोर्चे पर निश्चित रूप से पड़ेगा।

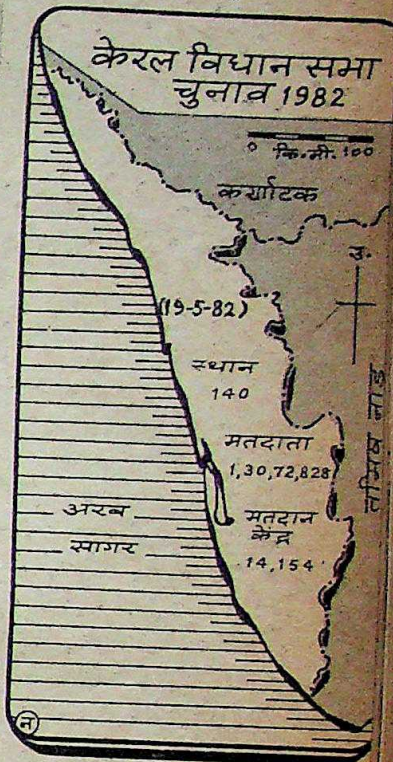
केरल में मतदान की स्थिति हमेशा कमो-बेश एक ही जैसी रही। जिस मोर्चे को मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त है वह 19 प्रतिशत मत तो निश्चित ही प्राप्त करने की उम्मीद रख सकता है। फिर केरल कांग्रेस के दोनों घटक जिन के साथ होंगे उन्हें इसाइयों के मत भी मिलने चाहिएँ, जो कि कुल मतदाताओं का 21 प्रतिशत है। इका अब पहली बार अपनी छत्रछाया में ऐसे तीन दलों को एकत्रित करने में सफल हुई है जिन के साथ 40 प्रतिशत मतदाता हैं। 1980 में जब संयुक्त मोर्चा के साथ कांग्रेस (एंथनी) और केरल कांग्रेस (मणि) नहीं थे तो उस ने 44,26,669 मत प्राप्त किये थे। वामपंथी मोर्चे को तब 48,32,481 मत प्राप्त हुए थे और 93 स्थान मिले थे। यदि गत वर्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के सत्ताच्युत होने के तत्काल बाद चुनाव हो जाते तो संयुक्त मोर्चा शायद इस बार कुछ और अधिक मत प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री करुणाकरन के 80 दिन के शासन के दौरान होने वाली परेशानियाँ केरल के मतदाता अभी मूले नहीं

इका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन (दायें) और मुस्लिम लीग के मोहम्मद कोया

हैं, जो कि संयुक्त मोर्चे के आड़े आ सकती हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े में आ जाने से कुछ और मत भी वह खो बैठेगा, ऐसा सोचा जा रहा है।

चुनाव के मैदान में कुछ जाने-माने नाम हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों, माला और नेमोम से चुनाव लड़ेंगे। अन्य प्रत्याशी हैं—मुस्लिम लीग के मोहम्मद कोया, मा.क.पा. के नयनार, केरल कांग्रेस मणि गुट के नेता क.म. मणि और चाको, केरल कांग्रेस (जोसेफ) के संस्थापक प.ज. जोसेफ, माकपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वासुदेवन नायर, भूतपूर्व मंत्री बेबी जॉन, माकपा के भूतपूर्व गृहमंत्री रामाकृष्णन और भारतीय जनता पार्टी के राजा गोपाल, जो वरिष्ठ राजनीतिक इस बार चुनाव के अखाड़े में नहीं उतरे उन में अच्युत मेनन, एंथनी, बलराम (माकपा के राज्य-सचिव), माकपा के राज्य सचिव, अच्युतानंदन तथा भारतीय जनता पार्टी के नंबूदिरिपाद और मरार शामिल हैं।

इस बार केरल में मतदाताओं की संख्या 1980 के मतदाताओं से कम है। अधिकारिक सूत्रों ने इस का कोई कारण नहीं बताया है। इस लिए विपक्षियों को यह कहने का मौका मिला है कि उस समय नयनार सरकार से घबरा कर हर पंचायत ने मतदाताओं की सूची गलत भेजी होगी। वैसे यह भी संभव है कि केरलवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या खाड़ी के देशों में जा कर बस जाने से मतदाताओं की सूची में फर्क पड़ गया है।





## संसदीय क्षेत्र

## उदयपुर और बयाना :

## ऊँट की करवट

राजस्थान के दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, उदयपुर तथा बयाना (सुरक्षित) क्षेत्र तथा एक विधानसभा क्षेत्र सरदारशहर के लिए भी आगामी 19 मई को मतदान होने जा रहा है। राजस्थान में भी विपक्ष में कोई सम-सौता न होने के कारण इका क्षेत्रों में प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। फिर भी इका के किसी भी प्रकार के मजबूत संगठनात्मक ढाँचे के अभाव और उदयपुर क्षेत्र में इका की अंदरूनी दलबंदी के कारण देखना यह है कि ऊँट आखिर किस करवट बैठता है।

तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में से, सब से अधिक शक्तिपरीक्षण वाला संघर्ष उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए होने की बात है। इस स्थान से अपने जीवनकाल में आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले दिवंगत नेता मोहनलाल सुखाड़िया चुनाव लड़ते रहे थे। सुखाड़िया ने अपने सत्रह वर्षीय मुख्यमंत्रित्वकाल में उदयपुर क्षेत्र का भरपूर विकास किया और इस का प्रभाव इस क्षेत्र के जनमानस पर अभी तक है। उनकी मृत्यु के बाद इस बात की काफी चर्चा सुनायी देती रही कि उनका परिवार राजनीति में प्रवेश करेगा। पर शायद सुखाड़िया परिवार इस बात को कहीं गहराई से समझ गया था कि दल के उच्च स्तरीय क्षेत्रों में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पायेगा और इसीलिए बाद में इस तरह की चर्चाएँ दब गयीं। सुखाड़िया जी की पत्नी श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया को लोग इस क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे पर उन्हें अंततः टिकट मिला ही नहीं।

इका ने राजस्थान की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दिवंगत नेता माणिक-लाल वर्मा के पुत्र दीनबंधु वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दीनबंधु वर्मा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के साले हैं। भाजपा ने इस के जवाब में दल के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुंदरसिंह भंडारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भंडारी पिछले दिनों राजस्थान में ही होने वाले राज्यसभा चुनावों में, विपक्षी मतों के भी इका उम्मीदवारों को मिलने के कारण पराजित हो चुके हैं। जनता (जेपी) के राज्य अध्यक्ष कल्याणसिंह बालवी भी इसी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। लोकदल की ओर से मुनवर 'राही' चुनाव लड़ रहे हैं। लोकदल का इस क्षेत्र में प्रभाव लगभग नगण्य है। इका

विनमान

और भाजपा के लिए यह संघर्ष प्रतिष्ठा का संघर्ष है। सुखाड़िया जी की मृत्यु के बाद उन के क्षेत्र में होने वाले प्रथम चुनाव में—सुखाड़िया के नाम पर कृतज्ञता महसूस करने वालों के मत इका को प्राप्त होंगे। श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया द्वारा जारी किये गये एक छोटे से वक्तव्य में लोगों से सुखाड़िया जी के सपनों को पूरा करने के लिए दीनबंधु वर्मा को जिताने की बात कही गयी है। शिवचरण माथुर अपनी पूरी शक्ति से यह चुनाव लड़वा रहे हैं और चुनाव संचालन की बागडोर बांसवाड़ा क्षेत्र के प्रभावशाली विधायक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को सौंप दी गयी है। स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा के प्रति भी लोगों में सम्मान है और उन्होंने अपने जीवनकाल में आदि-वासियों के लिए महत्वपूर्ण काम किये थे। इस लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके पुत्र दीनबंधु वर्मा को समर्थन मिलने की आशा है। क्षेत्र के प्रभावशाली इका नेता जैसे हीरालाल देवपुरा और गुलाबसिंह शक्तावत भी पूरे जोश से दल के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के



सुंदरसिंह भंडारी

प्रतिष्ठित कवि और अब राजस्थान साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष और इका नेता प्रकाश आतुर दीन-बंधु वर्मा के निकट-तम सहयोगियों में से रहे हैं और बुद्धिजीवी क्षेत्रों से उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हैं। पर इसी क्षेत्र में इका के भीतर का एक और गुट सक्रिय है जिस का नेतृत्व पहाड़िया मंत्रि-मंडल के एक भूतपूर्व मंत्री हनुमान प्रभाकर करते हैं। खुले तौर पर प्रभाकर इका प्रत्याशी के साथ हैं। पर राजनैतिक क्षेत्रों में कहा यही जा रहा है कि यदि इका के मत टूटे तो उस का कारण इका के अपने ही लोगों द्वारा विश्वास-घात होगा। भाजपा नेता भानुकुमार शास्त्री इस क्षेत्र में हमेशा सुखाड़िया के विरुद्ध चुनाव लड़ते रहे और जनता पार्टी के दौर में संसद में भी गये, पर दल का टिकट उनके बजाय सुंदरसिंह भंडारी को दिया गया। जनता (जेपी) के कल्याणसिंह कालवी भी विपक्षी मतों को विभाजित करेंगे। इस क्षेत्र में भाजपा की स्थिति भी कामी मजबूत रही है और पिछले संसदीय चुनाव में सुखाड़िया भी 52 हजार मतों से ही विजयी हुए थे। इस के पहले भी राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुखाड़िया जी को जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। आठ विधानसभा क्षेत्रों वाले उदयपुर

संसदीय क्षेत्र में इस समय मतदाताओं की कुल संख्या 7 लाख 52 हजार 719 है। चुनाव क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कमजोर वर्गों और आदिवासियों का भी इस संख्या में एक बड़ा प्रतिशत है।

बयाना सुरक्षित संसदीय क्षेत्र में जनवरी 1980 के आम चुनावों में जगन्नाथ पहाड़िया विजयी हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र को त्यागपत्र दे कर खाली कर दिया था। राज्य में इका का पहाड़िया समर्थक समूह इस बात के लिए फिर प्रयत्न करता रहा कि यहाँ से दल का टिकट पहाड़िया को पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया को मिले, पर इका उच्च कमान ने यह स्वीकार नहीं किया। इका ने यहाँ से अपना प्रत्याशी नानाराम केन को बनाया है। भाजपा ने रामजीलाल महामना को खड़ा किया है तो जनता दल ने रामजीलाल सुमन को। जगजीवनराम कांग्रेस के बुद्धिराम लहरी भी प्रत्याशी है। लोकदल के चेताराम भारतीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। माथुर सरकार द्वारा धौलपुर को जिला घोषित कर दिये जाने का लाभ भी इस बार यहाँ के इका प्रत्याशी को मिलेगा। शांति पहाड़िया को टिकट न मिलने के कारण पहाड़िया समर्थक असंतुष्ट जरूर हैं पर वे कोशिश करने पर भी अपने दल के प्रत्याशी को किसी रूप में नुकसान पहुँचाने की स्थिति में संभवतः नहीं रह गये हैं। इस क्षेत्र में विपक्षी मत भी काफी विभाजित होंगे। □

## जबलपुर : तीन हवेलियों में बंद कांग्रेसी राजनीति

जबलपुर का लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जो प्रदेश इका अध्यक्ष सुंदर शर्मा की मृत्यु के कारण रिक्त हुआ है, 1952 से लेकर 1974 के पहले तक कांग्रेस का अजेय गढ़ माना जाता था। स्व. सेठ गोविंददास ने 22 वर्षों तक संसद में जबलपुर का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मृत्यु के कारण 1975 में उपचुनाव हुआ। वे दिन स्व. जयप्रकाश के बिहार आंदोलन वाले दिन थे। बिहार का प्रभाव हालाँकि जबलपुर में अखबारों के माध्यम से ही पहुँचा था, परंतु जबलपुर उन दिनों खुद छात्र राजनीति की लपटों में था।

कांग्रेस ने परंपरा का निर्वाह करते हुए गोविंददास के पोते, युवा रविमोहन को प्रत्याशी बनाया था जब कि हताशा से भरे प्रतिपक्ष ने जबलपुर विश्वविद्यालय के भू.पू. अध्यक्ष शरद



ओं की कुल है। चुनाव वगैरे और में एक बड़ा

में जनवरी पहाड़िया की वनने के खाली कर गया समयक यल करता हाड़िया की मिले, पर नहीं किया। ना राम केन ल महामना मजी लाल बुद्धिराम के चेताराम हैं। माथुर घोषित कर हाँ के इंका को टिकट क असंतुष्ट भी अपने में नुकसान ही रह गये भी काफी □

हवे-सी

क्षेत्र, जो की मूल्य कर 1974 गढ़ माना 22 वर्षों त्व किया। उपचुनाव आंदोलन कि जबल-पहुँचा था। राजनीति

करते हुए प्रत्याशी प्रतिपक्ष ने यस्य शरद 2 मई '82

यादव को सर्वदलीय प्रत्याशी मान लेने में बानाकानी नहीं की।

उन दिनों जनसंघ ही मजबूत दल था। उस ने पूरी निष्ठा से कांग्रेस को पराजित करने में अपने को लगा दिया। शरद यादव ने कांग्रेस के दुर्ग को ढहा कर संपूर्ण प्रतिपक्ष की एकजुटता का रास्ता बनाया। 5,85,908 मतदाताओं वाले जबलपुर चुनाव क्षेत्र से शरद यादव को 1,73,029 और कांग्रेस को सिर्फ 85,667 मत ही मिले थे। 1977 की जनता लहर का सामना करने कांग्रेस के पूर्व शिक्षामंत्री जगदीश नारायण अवस्थी आये थे। अवस्थी जी को लोहपुरुष द्वारकाप्रसाद मिश्र को पराजित करने का श्रेय मिला था। परंतु शरद यादव दोबारा लोकसभा के लिए 75,109 मतों के अंतर से चुन लिये गये।

1980 का मध्यावधि आम चुनाव इंदिरा लहर के रूप में आया। अब तक प्रतिपक्षी दलों का पुनः विखंडन हो चुका था। शरद यादव इस बार लोकदल के प्रत्याशी थे जबकि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जनसंघ ने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया था। इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार बन कर पत्रकार मुंदर शर्मा अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने उतरे थे।



रत्नकुमारी देवी

इस वक्त जबलपुर दूसरे उपचुनाव में डूबा हुआ है। कुछ ही पहले सागर लोकसभा उप-चुनाव में भाजपा की जीत से इंका में हल्की सी दहशत है। भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं—जबलपुर केंद्र, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम और जबलपुर छावनी। चार विधानसभा क्षेत्र जबलपुर नगर में ही हैं, जबकि पनागर सिहोरा, बहोरीबंद और कटनी बंद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं। इन आठों सीटों पर इंका विधायक हैं। एक विधायक हाजी बनायत राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। 1980 की अपेक्षा इस बार मतदाता घट गये हैं। 1982 के चुनाव में लोकसभा के लिए 6,66,846 मतदाता मतदान करेंगे। मतदाता क्यों पड़े यह एक विचारणीय प्रश्न है।

इंका ने सेठ गोविंददास की पुत्री श्रीमती रत्नकुमारी देवी को प्रत्याशी बनाया है। रत्नकुमारी देवी दो बार राज्यसभा के लिए चुनी गयी हैं। अभी भी वह राज्यसभा की सदस्य हैं। जबलपुर में कांग्रेसी राजनीति तीन हवेलियों

में बंद है। गोविंददास की बखरी, मू. पू. राज्यमंत्री परमानंद भाई पटेल का महल और नवकुबेर अनंत का बंगला। इस बार जब लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम चले तो तीनों महलों के नाम शामिल थे। दिल्ली में बैठे लोगों को महलों का सम्मोहन अब भी आकर्षित करता है। रत्नकुमारी देवी का जबलपुर की राजनीति से गहरा जुड़ाव नहीं है। वह वक्तव्यों और समारोहों के माध्यम से ही जनता से मेलजोल रखती रही हैं। बखरी के सलाहकार और राजनैतिक विचौलिये पुराने युग के ही हैं, जिन से राजनीति की नयी पीढ़ी रिश्ते स्थापित नहीं कर पायी।

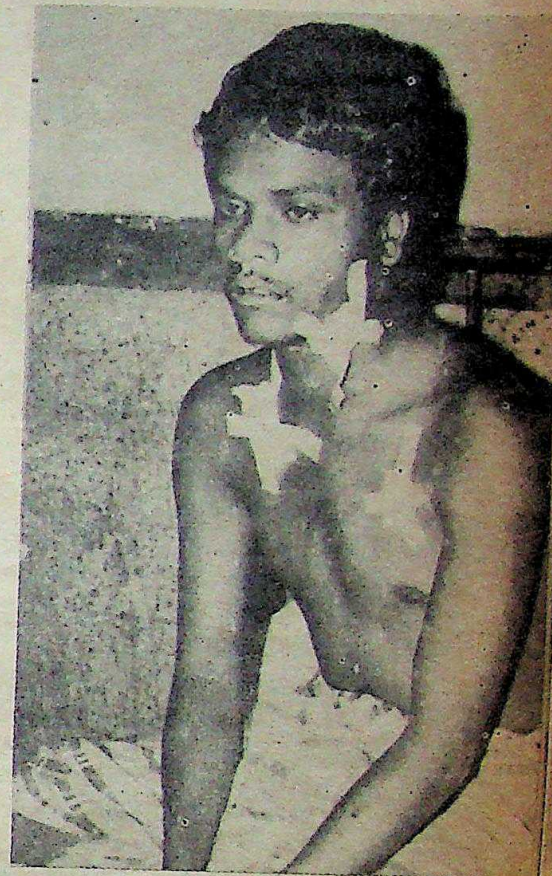
भाजपा ने इस बार बाबूराव परांजपे को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1972 में जनसंघी उम्मीदवार के रूप में श्री परांजपे हार चुके हैं। 1977 में जपा का टिकट न मिलने पर विद्रोही उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में डॉ. के. एल. दुबे से पराजित हो चुके हैं। डॉ. दुबे जबलपुर नगरनिगम महापौर के चुनाव में भी परांजपे को पराजित कर चुके हैं। डॉ. दुबे इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं।

तीसरे प्रत्याशी मू. पू. महापौर एवं विधायक डॉ. के. एल. दुबे हैं। वह समाजवादी रहे हैं तथा 1973 में जबलपुर के महापौर चुने गये थे। 1977 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता था। डॉ. दुबे को जनता (जे.पी.), कांग्रेस (स), लोकदल तथा माकपा एवं माकपा के अतिरिक्त मुस्लिम युवा मोर्चे का समर्थन प्राप्त है।

डॉ. दुबे का गरीब तबकों में अच्छा प्रभाव है। जब वह महापौर थे तब नज़ूल पर बसा कर पट्टे वितरित किये थे।

शरद यादव इस बार मैदान से बाहर रहने में अपना हित समझ रहे हैं। सदैव प्रत्याशी रहने वाले मनीषी जी इस बार नहीं हैं, पिछले दिनों वह नहीं रहे।

इंदिरा कांग्रेस के लिए अनेक कमियों के बावजूद चुनाव जीत लेना कठिन नहीं है। विद्याचरण शुक्ल, प्रकाशचंद्र सेठी और मुख्य-मंत्री अर्जुनसिंह इस चुनाव में साथ-साथ हैं। श्री शुक्ल इस चुनाव में इंका के कर्ता धर्ता हैं। सागर संसदीय क्षेत्र में इंका की पराजय ने यह समझौता करने को मजबूर किया है। पिछली बार प्रधानमंत्री जब भोपाल गयी थीं तभी श्री शुक्ल को जबलपुर चुनाव की बाग-डोर सौंपने का फैसला कर लिया था और इस प्रकार राज्य की राजनीति में श्री शुक्ल के प्रभाव को मान्यता दी गयी। श्री अर्जुनसिंह और श्री सेठी को समर की पराजय ने इस स्थिति में ला दिया है कि श्री शुक्ल का साथ देने के अलावा उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं है। □



गौशा उरांव : निरपराध शिकार

## आदिवासी संस्कृति में कारतूस का छेद

रांची से अरुणरंजन

गत 29 अप्रैल को रांची जिला के मांडर थाना में अभूतपूर्व घटना घटी। बिहार सरकार के एक आदिवासी मंत्री ने मीड पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की वर्दी सार्वजनिक तौर पर उतरवा दी। पुलिस संघ ने पहली बार किसी गोलीकांड की जांच के लिए अपनी समिति बनाने की घोषणा की। झारखंड में इस घटना को आदिवासी संस्कृति पर बाहरी हमले के रूप में लिया जा रहा है। छोटानागपुर के उरांव आदिवासी रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी से झारखंड में बसने आये थे। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सेना रोहतास में घुसी तो सरहुल पर्व के कारण मर्द शराब के नशे में धुत थे। तब उरांव औरतों ने मर्द वेष में परंपरागत हथियार ले मुगल सेना का मुकाबला किया था। तबसे बारह वर्ष में एक बार उरांव औरतें मर्द वेष में परंपरागत हथियार लेकर जनी शिकार पर निकलती हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जनी शिकारी औरतें गाय-बैल छोड़ छोटे खाने योग्य जानवरों का शिकार करती हैं।



इस वर्ष 22 अप्रैल से जनी शिकार शुरू हुआ। रांची से कोई 25 किलोमीटर दूर मांडर थाना के लोयो गाँव की जनी शिकारी औरतें मूरमा गाँव में शिकार खेलने गयीं। इन जनी शिकारियों ने रात्रि विश्राम मूरमा तथा बगलगीर सूरसा बस्ती में किया। वहीं एक जनी शिकारिन को एक मेजवान आदिवासी मई ने जबरन अपनी वासना का शिकार बना डाला। अगले दिन उसकी सूचना मिलने पर जनी शिकारियों ने बलात्कारी का फूस का घर ध्वस्त कर डाला।

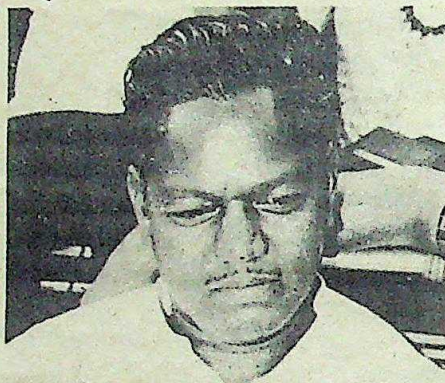
फिर मूरमा तथा सूरसा के बाशिंदे लोयो माफी मांगने गये। वहाँ आम की डाली घुमा कर परहा बैठा। परहा कई गाँवों की आपसी आदिवासी पंचायत है जो हथ्या छोड़ अन्य सभी अपराधों का दंड निर्धारित करती है। परहा ने बलात्कारी पुरुष को आर्थिक एवं भोज दंड देकर मामला निपटाना चाहा। तब तक स्थानीय पुलिस के एक दलाल ने मांडर थाना में सूचना दे डाली। थाना प्रभारी तथा सहायक आरक्षी निरीक्षक ने घूस कमाने का अच्छा अवसर पाकर परहा में हस्तक्षेप किया। परहा में सम्मिलित छह प्रमुख व्यक्तियों को मामले में साना गया। पुलिस अफसरों ने दो व्यक्तियों से जबरन 500 रु. छीन लिया तथा प्रति व्यक्ति एक हजार रु. केस हटाने की फीस माँगी।

हटिया के जपा विधायक सुबोधकांत के अनुसार—संबंधित गाँवों में तिवारियों के दो गुटों में राजनीति चलती है। ये तिवारी स्थानीय जमींदार तथा कांग्रेसी राजनीति करने वाले लोग हैं। एक तिवारी की रिश्तेदारी रांची जिला इंका के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से है जो मांडर के विधायक एवं शिक्षामंत्री करमचंद भगत के समर्थक हैं। मुकद्दमे से परेशान तिवारियों ने आम ग्रामीणों को चढ़ाया कि 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे मांडर थाना चलना है क्योंकि वहाँ करमचंद भगत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आने वाले हैं। दर्जनों गाँव के 5000-7000 आदिवासी तथा गैर आदिवासी जिसमें ढेरों जनी शिकारिनें भी थीं, थाने के सामने जा डटीं। भीड़ ने घूसखोरी विरोधी नारे लगाये तथा प्रथम सूचना रपट छीननी चाही। काफी गर्मी के कारण स्त्रियाँ थाना के बरामदे में चढ़ गयी थीं। इधर मंत्रीजी को खबर कर दी गयी कि कार्यक्रम में न आयें, भीड़ उग्र है। पुलिस को भी खबर दी गयी कि एक अन्य उग्र भीड़ थाने की ओर आ रही है। ज्योंही एक उच्च पुलिस अधिकारी की जीप थाने के पास आयी कि डेढ़ बजे दिन में थाने के भीतर से गोली चलने लगी। नवीं कक्षा का छात्र जगदीश उरांव तथा शेख सरफूल (21) मारे गये। 13 घायलों में 7 स्त्रियाँ भी थीं। रांची अस्पताल में इस संवाददाता ने कई घायलों के शरीर में छरों के जलम देखे जो इस बात का

बिनाम

प्रमाण है कि थाने के भीतर से भीड़ पर निजी बंदूकों से भी गोली चली। पुलिस वालों का कहना है कि राइफल छीने जाने के बाद वे गोली चालन को भजबूर हुए।

गोली चालन के बाद भी भीड़ थाने पर डटी रही। शाम 4 बजे शिक्षामंत्री करमचंद भगत वहाँ आये तो उन्हें भीड़ के उग्र आक्रोश का सामना करना पड़ा अंततः शाम 6.30 बजे मंत्री महोदय ने भीड़ की माँग पर पुलिस की बर्दी, पेटी, व टोपी उतरवा दी तथा उनके हथियार घरवा दिये। उच्च प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को विरोध करने पर डाँट खानी पड़ी। शाम 7.30 बजे मंत्री रांची सर्किट हाउस लौट आये तो वहाँ कमरा नंबर एक में घुस कर उग्र आदिवासी छात्रों ने काफी तोड़फोड़ की। फिर वे कमरचंद भगत को पैदल आदिवासी छात्रावास ले गये जहाँ उन्हें जमीन पर बैठकर मशाल लेकर पुलिस



करमचंद भगत : अप्रहर्षशी

को दंडित कराने की शपथ खिलायी गयी। उस वक्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी छात्रावास परिसर से बाहर मूक दर्शक बने थे। आक्रामक आदिवासी छात्र करमचंद भगत से दो कारण से नाराज थे। उनका कहना था कि अगर भगत 10 बजे सुबह मांडर आ जाते तो गोली चालन टल जाता। फिर उनका मानना था कि बर्दी उतरवाना मंत्री महोदय का नाटक था।

रांची की सड़क पर जनी शिकारी औरतें



लेकिन यह नाटक सरकार की महंगा पड़ा। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस-कर्मियों पर चल रहे भागलपुर आँखफोड़ कांड के मुकद्दमे के भावी फैसले को लेकर पुलिसकर्मियों के भीतर आंदोलित होने की मंशा है। बर्दी उतरवाने की घटना ने इस आम में घी डाला। जब एक मई को आदि संस्कृति रक्षा समिति ने उग्रतम रांची बंद किया तो पुलिसकर्मी तटस्थ रहे। मांडर क्षेत्र लोहार दग्गा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है जहाँ 19 मई को उपचुनाव है। पुलिसकर्मी चुनाव में झूठी देने का फैसला ले चुके हैं।

मांडर गोलीकांड से झारखंड में इंका की अंदरूनी गृहकलह सड़क पर आ गयी। अभी चुनाव में भूतपूर्व केंद्रीयमंत्री (स्वर्गीय) कांतिक उरांव की पत्नी सुमति उरांव इंका उम्मीदवार हैं। इंका के एक गुट का कहना है कि एकछत्र नेतृत्व के लिए भगत सुमति का तहेदिल से समर्थन नहीं करेंगे। वैसे एक तटस्थ गुट का खयाल है कि खूटी उपचुनाव हारने के बाद अगर लोहरदग्गा इंका के हाथ से गया तो अरबन कोआपरेटिव बैंक के मामले में फंसे मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र का पता और जल्द कटेगा। अतः मंत्री करमचंद भगत भी सुमति को जितवाने के लिए पूरा जोर लगायेंगे।



सुमती अन्याय विरोध की सच्चा

इंका के मुख्य चुनावी प्रतिद्वंद्वी भाजपा के उम्मीदवार ललित उरांव ने गोलीकांड को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया है।

प्रतिक्रियाएँ : विभिन्न दलों तथा मानसिकता के लोगों की ये प्रतिक्रियाएँ मांडर गोलीकांड के अनेक छुपे आयामों को प्रकट करती हैं। अधिकांश विपक्षी दलों ने शिक्षामंत्री करमचंद भगत के इस्तीफे की माँग की है। करमचंद भगत ने 30 अप्रैल को प्रेस सम्मेलन बुला कर स्पष्ट किया कि जनी शिकार की घटना तथा उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में कोई अंतर्संबंध नहीं था। मंत्री ने पुलिस की घूसखोर प्रवृत्ति पर खुली चोट की। थाना प्रभारी तथा सहायक



# मंत्री और संतरी कहाँ आकर बराबर होते हैं

(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा)

रांची बंद : सुनसान सड़क

आरक्षी निरीक्षक निलंबित घोषित हुए, मृतकों-घायलों को मुआवजे की घोषणा हुई। श्री भगत ने घटना को पूरी जाँच कराने की माँग स्वयं उठाकर विपक्ष का मुँह बंद करना चाहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक लड़ाकू राजनैतिक दल के मुख्य सचेतक सूरज मंडल का मानना है कि आदिवासी क्षेत्र में गिरि-जनों की संस्कृति से अनभिज्ञ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भरे जाने से ऐसी घटनाएँ खूब हो रही हैं। अगर थाना प्रभारी जनी शिकार तथा परहा की मर्यादा से परिचित होता तो घटनाक्रम आगे नहीं बढ़ता। इसी पार्टी के विधान परिषद सदस्य भाई हेलेन कुजूर इस घटना को अस्तित्व के लिए लड़ती आदिवासी संस्कृति पर सरकारी हमला मानते हैं। जब पूछा गया कि क्या यह सच है जनी शिकारी टोलियाँ सड़कों पर जबरन बंदा माँगती हैं तो सूरज मंडल एवं हेलेन कुजूर ने तीव्र आपत्ति दर्शाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शोबू सोरेन का अनुभव सुनाया। उनसे दो रुपया माँगने पर जब उन्होंने जनी शिकारियों को पाँच रुपया दिया तो उन्हें तीन रुपया वापस किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी हिंदू मुसलमान भी जनी शिकार में भाग लेते हैं। शोबू सोरेन के अनुसार शिकार में आदमी के बराबर शिकारी कुत्ते को भी माँस का समान हिस्सा दिया जाता है। हटिया के जपा विधायक शोषकांत जनी शिकार को शौर्य, सामुहिकता तथा स्वरक्षा के अभ्यास के रूप में देखने के बावजूद इन परंपराओं में आम आदिवासी शोषण के कारण पैदा हो रहे आक्रोश तथा आक्रामकता को नजरअंदाज नहीं कर पाते। रांची के इका विधायक ज्ञान रंजन उन लोकसंघ काँग्रेसियों में से हैं जो मांडर गोलिकों को विपक्ष का चुनावी खेल मानते हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंदन बागची ने शिकायत बयान दिया कि भाजपा तत्वों ने गोलियों तथा पुलिस को दो तरफा मड़का कर गोली चलवाने का षडयंत्र किया। इस कांड में चौतरफा न्यायिक जाँच की माँग उठी है। एक अहम बात पर किसी का ध्यान नहीं आया जनी शिकार में बलात्कार कब से होने लगे? क्या आदिवासी संस्कृति में दिक्कत है? क्या आदिवासी संस्कृति की तरह क्षय के कीटाणु फैल रहे हैं? □

यह भारतीय गणराज्य का पटना शहर है। पुराने जमाने का पाटलिपुत्र और आज के बिहार की राजधानी।

इस शहर में एक रेलवे स्टेशन है। बड़ा रेलवे स्टेशन जिसे रेलवे की समय सारिणी में पटना जंक्शन नाम दिया गया है। यहीं पर एक गांधी मैदान भी है। नुमाइश से ले कर सार्वजनिक सभा तक के लिए इस का इस्तेमाल होता है। जंक्शन और मैदान दोनों सरकारी संपत्ति हैं।

इसी शहर में आजादी के 23 वर्ष बाद यानी 1970 में छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गयी थी। कहा जाता है कि इस बैंक से कर्ज लेने के लिए एक उद्यमी ने रेलवे प्लेटफार्म और गांधी मैदान दोनों को अपनी संपत्ति के रूप में जमानत में दे दिया था। सहज विश्वास के धनी बैंक अधिकारियों ने किसी तरह की जाँच की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन जब मेद खुला तो पता चला कि फर्जी संपत्ति दिखा कर कर्ज लेने वालों की संख्या एक नहीं अनेक थी। क्योंकि कुल मिला कर बैंक में लगभग 45 लाख रुपए का घोटाला हुआ था।

1970 में विधान परिषद का सदस्य होने के बाद पटना पहुंचने पर जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने बैंक स्थापना की योजना आगे बढ़ायी तो स्वतः यह विश्वास हो गया कि अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर मिश्र बैंकिंग व्यवसाय की बारीकियों और संभावनाओं से परिचित होने के कारण बैंक और उद्यमी दोनों को तरक्की की राह पर ले जायेंगे।

दरअसल प्रदेश की तरक्की के लिए किए गए डॉक्टर मिश्र के इस प्रयत्न की सराहना की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र के कुछ निवासी पोटलीपुत्र बन जाने का मोह संवरण नहीं कर पाये और नेकनीयती की दीवार बदनीयती की लतों से ढक गयी।

बैंक के कारनामे धीरे धीरे आम चर्चा का विषय बने—विधानसभा की बहुसं—प्राक्कलन समिति की बैंक के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की सिफारिश—तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फूर द्वारा मुकद्दमा चलाने का आदेश—मुख्यमंत्री हो जाने पर डॉक्टर मिश्र द्वारा शुरू शुरू में मुकद्दमा चलाने का विरोध और बाद में

मंत्रिमंडल की एक उपसमिति द्वारा मुकद्दमा वापस लेने का फैसला—उस के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश और पटना उच्च न्यायालय में विधायक शिवनंदन पासवान की याचिका की अस्वीकृत और उच्चतम न्यायालय (दिनमान 21-27 मार्च 82) में पुनः निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध याचिका।

श्री पासवान की दलील यह है कि मुकद्दमे का कारण किसी तरह का राजनैतिक द्वेषभाव नहीं है। उस का संबंध सार्वजनिक हित से है और आरोप धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार विश्वासभंग आदि के हैं, इसलिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों में से किसी ने सार्थक तत्त्वों को महत्व नहीं दिया। “दस्तावेजों के निरीक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि मुकद्दमा वापस लेने के प्रश्न पर विचार करते समय विद्वान न्यायाधीश के सामने केस डायरी और दूसरे दस्तावेज नहीं थे : मुख्य आरोप यह है कि 1975 में श्री मिश्र, नवल किशोर सिन्हा, के.पी. गुप्ता, एम.ए. हैदरी, आदि ने ऐसा आपराधिक षडयंत्र किया जो जाबता फौजदारी की धारा 120 बी, और 109 तथा भ्रष्टाचार कानून 1947 के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डॉक्टर मिश्र ने भ्रष्ट और गैरकानूनी तरीके से ऐसा कार्य किया जिस से उन्हें एक लाख रुपए का और श्री सिन्हा और अन्य पदाधिकारियों को कई लाख रुपए का आर्थिक लाभ हुआ। डॉक्टर मिश्र ने सहकारिता विभाग की फाइल संख्या 9/लीगल/9/75 पर 14.5.75 को दिए गए अपने ही एक लिखित आदेश पर 16.5.75 का एक आदेश चिपका दिया। यह जालसाजी है। डॉक्टर मिश्र ने लिखा : “फाइल देखने से लगता है कि अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ गबन का कोई आरोप नहीं है। कर्जदारों से वसूली के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।” उन्होंने 30-6-75 को लिखा : “बातचीत हो चुकी है। फौजदारी का मुकद्दमा चलाने की कोई जरूरत नहीं है।” सहकारिता विभाग के सचिव, पंजीयक सहकारी समितियाँ और सहकारिता आयुक्त ने जाँच अधिकारी के समक्ष कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उन से कोई बातचीत नहीं की। खुद डॉक्टर मिश्र पूछताछ के दौरान स्पष्ट ढंग से यह नहीं बता सके कि उन्होंने किन अधिकारियों से बातचीत की थी।”

फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने मुकद्दमे



की वापसी के विरुद्ध दाखिल की गयी थी। पासवान की याचिका को पूरी सुनवायी के लिए स्वीकृत कर लिया है। न्यायालय की राय में विशेष न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने वापसी के विरुद्ध दिए गए तर्कों पर विचार नहीं किया। न्यायमूर्ति श्री देसाई के अनुसार "उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि वह मजिस्ट्रेट के निर्णय से सहमत है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने प्रश्नों की पूरी जाँच-परख नहीं की। क्या उन्होंने दूसरे पक्ष की दलीलों के बारे में सोचा? निचली अदालत ने इस मामले में शिवनंदन पासवान के अदालत का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया।"

बिहार सरकार की ओर से भारत के महान्यायाधीश लाल नारायण सिन्हा ने कहा कि अभियोजन राजनैतिक प्रतिशोध में तब किया गया जब डाक्टर मिश्र जनता शासन काल में इका विधायक दल के नेता थे। यह जिम्मेदारी लोक अभियोजक की है कि वह मुकद्दमें को आगे बढ़ाये। चूंकि फैसला कार्यकारी था अतः सरकार अभियोजक से मुकद्दमा वापस लेने को कह सकती है। न्यायालयों के कार्य इस मामले में सीमित होते हैं।

श्री पासवान की ओर से बोलते हुए अधिवक्ता श्री बेणुगोपाल ने श्री सिन्हा के तर्क को काटा और कहा, 'यदि अभियोजक फौजदारी के एक आम मुकद्दमें में ऐसा एकपक्षीय फैसला ले सकते हैं तो उस के परिणाम भयंकर होंगे। यदि अपराध राजनैतिक हो तो सार्वजनिक नीति के नाम पर मुकद्दमा वापस लिया जा सकता है। लेकिन यह मुकद्दमा भ्रष्टाचार का है, राजनीतिक नहीं। घूस लेने के मामले में सार्वजनिक नीति नहीं आती। ऐसे मामलों में एक मंत्री और चपरासी दोनों बराबर हैं।' न्यायालय को यह जरूर बताना होगा कि वह किस आधार पर मुकद्दमें की वापसी मंजूर कर रही है। इस मुकद्दमें में डाक्टर मिश्र के विरुद्ध जालसाजी के स्पष्ट प्रमाण हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जाँच से स्पष्ट है कि एक आदेश के ऊपर पहले की तारीख में दूसरा आदेश चिपका दिया गया।"

ध्यान देने की बात है कि पिछले दिनों न्यायाधीशों के तबादले वाले मुकद्दमें में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक हित के मामले में किसी भी नागरिक के अदालत का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को मान्यता दी थी।

श्री पासवान ने अपनी याचिका में 14 मई 1975 के आदेश पर 16 मई 1975 का आदेश चिपकाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 'जाँच अधिकारी ने अल्ट्रा किरणों के जरिए उस का चित्र लिया और उसमें जालसाजी मिली। उद्देश्य स्पष्ट था। एम.ए. हैबरी की

याचिका के अनुसार डाक्टर मिश्र ने नलवकिशोर सिन्हा तथा अन्य पदाधिकारियों को बचाने के बदले में अर्थलाम किया। नवंबर 75 में डा. मिश्र ने बैंक की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय कोष से 15 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया, लेकिन सहकारिता समितियों के पंजीयक के.बी. सक्सेना (आई.ए.एस.) ने विभागीय फाइल संख्या 2/पी.यू.सी.वी.-020/75-76 में उस का विरोध किया। उन्होंने राज्य सरकार के उद्देश्य को चुनौती दी।

अगस्त 1976 के पहले हफ्ते में डॉक्टर मिश्र ने आधी रात को अपने निवास पर एक बैठक की जिस में सहकारिता मंत्री मुहम्मद हुसैन आजाद, सचिव आर.के. श्रीवास्तव संयुक्त पंजीयक सीताराम गोप और गुप्तचर विभाग (सहकारिता रक्षा) के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा मौजूद थे। डा. मिश्र ने जबानी कहा



कि कर्जदारों के खिलाफ मुकद्दमा कायम किया जा सकता है बशर्ते कि नवल किशोर सिन्हा को अभियुक्त न बनाया जाये। इन अधिकारियों के बयान जाँच अधिकारी ने लिए हैं। श्री शर्मा ने फाइल संख्या 11 पी.सी. 21/76 पर 8 अक्टूबर 76 को लिखा कि सभी मामलों में देखने से लगता है कि नवल किशोर सिन्हा के विरुद्ध सबल साक्ष्य हैं। इसे देखते हुए उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। गुप्तचर विभाग के उपपुलिस महानिरीक्षक शशिमणि सहाय ने 12 जून 76 को श्री शर्मा के सुझाव पर सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि नवल किशोर सिन्हा को सभी मामलों में अनिवार्यतः अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक श्री मिश्र ने भी सहमति दी थी और तब फाइल सहकारिता विभाग को भेज दी गयी थी। बैंक के

निस्तारक (लिक्विडेटर) श्री नवल कुमार ने सहकारिता सचिव को एक पत्र अलग से लिखा जिस में श्री सिन्हा के विरुद्ध मुकद्दमा कायम करने की अनुमति मांगी गयी थी। सहकारिता अयुक्त विनोद कुमार ने सहकारिता मंत्री के पास फाइल भेजी। उन्होंने श्री सिन्हा के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की सहमति देते हुए फाइल (आर.सी.ए.-एल-19/76) 21 जुलाई 77 को मुख्यमंत्री के पास भेज दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मिश्र ने सहमति देने के बजाय लिखा कि सभी 23 मुकद्दमे उठा लिए जायेंगे।"

याचिका के अनुसार (पृष्ठ 8) आरोपों की पुष्टि करने वाले सबूत संक्षेप में ये हैं कि रिजर्व बैंक ने 1972-73 और 73-74 के लेखा परीक्षण में अनेक अनियमितताएँ पायीं और अध्यक्ष नवल किशोर सिन्हा तथा बैंक के अन्य पदाधिकारियों को 10 लाख रुपए की वसूल न हो सकने वाली राशि (बैंड डेट) और 25 लाख रुपए के गबन और घोटाले का जिम्मेदार ठहराया। सहकारिता विभाग ने रिजर्व बैंक की लेखा परीक्षा की रपट में दिए गए तथ्यों के आधार पर पुनः परीक्षा करायी और पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की सिफारिश की। विधि विभाग ने उसे मंजूर किया। 2 जनवरी 75 को मुख्यमंत्री ने उस के लिए आदेश जारी किया।

इस मुकद्दमे को चलाने के लिए गिरीश नंदन सिन्हा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। सहकारिता विभाग ने मसौदा तैयार कराया। उसे विधि विभाग ने स्वीकृत किया। जिला सहकारिता अधिकारी जगदीश नारायण वर्मा ने शिकायत पत्र पर दस्तखत किया और उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना की अदालत में दाखिल करने के लिए 27 जनवरी 75 को गिरीश नंदन सिन्हा के पास भेजा गया। उस शिकायत में नवल किशोर सिन्हा मुख्य अभियुक्त थे। वह दस्तावेज जाँच अधिकारी ने अपने कब्जे में ले रखा है और वह साक्ष्य के रूप में अब कागजात के साथ नत्थी है।"

अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने श्री पासवान की याचिका पूरी सुनवायी के लिए स्वीकार कर ली है देखना यह होगा कि वह मुकद्दमे वापस ले लेने के राज्य सरकार के अधिकार और उस पर स्वीकृति की मुहर लगाने वाले जिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के फैसले को सही मानता है या नहीं। यह भी कि मामला राजनैतिक द्वेषभाव से दाखिल किया गया था या सार्वजनिक हित में? यदि सार्वजनिक हित में था तो क्या शिवनंदन पासवान को राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है या नहीं?



विश्व

चीन

## साम्यवादी बदल रहे हैं

चीन में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं जिन्हें जनराज्य की स्थापना के बाद से बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संविधान के संशोधित मसौदे में मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं जिन के आधार पर अब चीन का प्रशासन चलाया जायेगा। मार्क्स, लेनिन और माओ के सिद्धांत चीन के मार्गदर्शक होंगे। विभिन्न जातियों द्वारा स्थापित चीन को एक बहुजातीय राष्ट्र कहा गया है।

संविधान के संशोधित मसौदे के बाद चीन की सर्वोच्च संस्था राज परिषद की स्थायी समिति ने विदेशमंत्रालय में 6 सहमंत्रियों की नियुक्ति की। विदेशमंत्रालय से दो प्रमुख उपमंत्रियों को हटा दिया गया है। इन में से एक श्री हान नियांन लाङ्ग हैं जिन्होंने पिछले दिसंबर में भारत और चीन की सरकारी स्तर की वार्ता में चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। विदेशमंत्रालय के ही एक और उपमंत्री श्री फूहो को भी उन के पद से हटाने की खबर है लेकिन पता चला है नयी दिल्ली में भारत चीन वार्ता के दूसरे दौर में वह चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पर यह नहीं बताया जा रहा है कि वह किस हैसियत से यह नेतृत्व करने वाले हैं। मंत्रिमंडल में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन अंतर-राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के उपमंत्री श्री पूशाङ्ग चिन्ह का हटाया जाना है। वह भी पिछले वर्ष फरवरी में भारत चीन आर्थिक वार्ता में चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।

संशोधित मसौदे में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि चीन ने समाजवाद का रास्ता नहीं छोड़ा है और न वह तेज़ सिआओ पिङ्ग के उस समाधनवाद से पीछे हटा है जो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित है। कोई 10 वर्ष की प्रशासनिक ऊहापोह के बाद इस संशोधित मसौदे को चीन में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

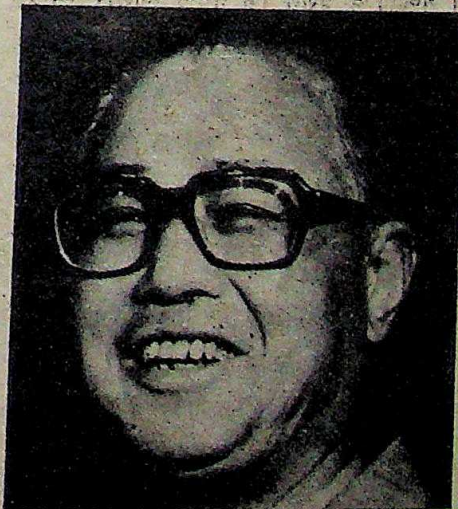
**प्रशासनिक परिवर्तन :** चीन की सरकारी समाचार एजेंसी की पिछले सप्ताह की घोषणा के अनुसार उपप्रधानमंत्रियों की संख्या 13 से घटा कर 2 कर दी गयी है। मंत्रियों की संख्या 52 से घटा कर 41 कर दी गयी है। घोषणा में यह भी बताया गया है कि 10 शरिष्ट अधिकारियों को सर्वोच्च संस्था में नये पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री चाओ ब्याङ्ग की सिफारिशों पर विनयान



तेङ्ग : जड़ें गहरी हैं

यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। स्थायी समिति ने पहले इन सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में दो उपप्रधानमंत्री अपने अपने स्थानों पर कायम रहे हैं। एक हैं 66 वर्षीय वान ली और दूसरे 64 वर्षीय याद्रो यिलिन। बताया जाता है ये दोनों पार्टी उपाध्यक्ष श्री तेङ्ग के सबसे निकट के लोगों में से हैं। सर्वोच्च परिषद में विदेशमंत्री श्री हुआङ्ग हुआ और अर्थशास्त्री श्री ग्युम्यू को भी लिया गया है। बताया जाता है कि आर्थिक विकास की जिन योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका उनकी जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को सौंपी गयी है। मंत्रिमंडल में परिवर्तन के साथ साथ अनेक मंत्रालयों का पुनर्गठन भी किया गया है। इन के अलावा 23 नये मंत्री नियुक्त किये गये हैं।

चीन में इस व्यापक परिवर्तन का अनुमान



चाओ ब्याङ्ग : प्रशासनिक सुधार जरूरी था

बहुत पहले से लगाया जा रहा था। चीन के प्रशासन में बुनियादी परिवर्तन की योजना काफी पहले से तैयार कर ली गयी थी। इस से पहले मार्च के महीने में 12 मंत्रालयों और आयोगों को मिला कर 6 विभाग बना दिये गये थे और इन 6 विभागों की देखभाल के लिए एक एक सहमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। वास्तव में चीन में नौकरशाही का प्रभाव समाप्त कर समूचे प्रशासन को एक नया रूप देने के लिए पार्टी के भीतर बहुत समय से आंदोलन चल रहा था। चीनी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी चीन में सत्ता संघर्ष जारी है। प्रशासन को कुशल बनाने के नाम पर सत्ता संघर्ष की इस राजनीति ने नया मोड़ लिया है। एक ओर तो घरेलू और विदेशी मामलों में श्री तेङ्ग की नीतियों के समर्थक हैं जो नये परिवर्तनों को स्थायी बना देना चाहते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सारी नीतियों को श्री तेङ्ग के राजनैतिक क्षेत्र से हटते ही बिल्कुल ही उलट देना चाहते हैं।

रक्षामंत्रालय में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। देश की सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए एक केंद्रीय रक्षा परिषद बनायी जा रही है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस देश की सब से बड़ी विधायी संस्था होगी। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए चार उपप्रधानमंत्री होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन प्रशासन में यह है कि गांवों में फिर से प्रशासनिक परिषद बना दी जायेगी। सामूहिक अर्थव्यवस्था के लिए कम्यून गांवों की बुनियादी संस्था होगी। अब होगा यह कि कम्यून के प्रबंध और संचालन का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहेगा। यह संभवतः सांस्कृतिक क्रांति जैसे आंदोलनों को हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चीन के समाचारपत्रों में पार्टी को ले कर जो आलोचनाएँ देखने को मिली हैं उनसे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी के दो गुटों में अंदर ही अंदर सत्ता संघर्ष अब भी चल रहा है। बताया जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन बढ़ाने, आयोजन का विकेंद्रीकरण करने और हाट अर्थव्यवस्था पर और अधिक निर्भर रहने जैसे परिवर्तन किये जाने वाले हैं जिनका निश्चय ही उग्रवादी लोग विरोध करेंगे। हाल ही के महत्वपूर्ण परिवर्तनों द्वारा चीन के प्रशासन और नीतियों को नया रूप निश्चय ही दिया है लेकिन इस से पार्टी के दो गुटों के बीच संघर्ष और भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन चीन की राजनीति में श्री तेङ्ग की जड़ें गहरी हैं। घरेलू नीतियों में परिवर्तन के साथ साथ वैदेशिक मामलों में पश्चिम देशों की ओर चीन का झुकाव जारी है। □





वीएना में डॉ. ब्रूनो क्राइस्की (बायें) के साथ रजत अरोड़ा : दूना सिटी का दर्जा

ऑस्ट्रिया

## यूरोप में 'संयुक्तराष्ट्र नगर'

बॉन से रजत अरोड़ा

दुनिया के किसी भाग में राजनैतिक उथल-पुथल हो, और संयुक्तराष्ट्र संघ सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने से बच जाये—ऐसा कम ही देखने में आता है। किंतु इस आलोकना का निशाना इन दिनों संयुक्तराष्ट्र संघ न हो कर उस के नये महासचिव पेरु निवासी जावियेर पेरेज दे कूलार हैं। न्यूयॉर्क स्थित संघ का मुख्य कार्यालय छोड़ कर जब से उन्होंने यूरोप की ओर प्रस्थान किया है तब से उन की यह यात्रा ही टीकाटिप्पणी का विषय बनी हुई है। अनेक प्रश्न इस संबंध में उठये जा रहे हैं। क्या इस नाजुक समय में जब कि दुनिया फिर एक बार युद्ध के कगार पर आ खड़ी हुई है, दे कूलार का स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकलना ठीक है? क्या महासचिव का कर्तव्य इस समय संघ के मुख्य कार्यालय में रह कर फॉकलैंड के मामले में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच समझौता कराने में मदद करना नहीं है? क्या अर्जेंटीना के आक्रमण के समय ही महासचिव का न्यूयॉर्क से प्रस्थान केवल एक संयोग है? क्या उन की यह यात्रा टालमटोल एवं इस समस्या से मुंह चुराने की एक कोशिश नहीं है?

महासचिव की यूरोप यात्रा पर आपत्ति उन्हीं क्षेत्रों में की जा रही है जो इस यात्रा के

महत्व को नहीं समझना चाहते। महासचिव के पद पर निर्वाचित होने के बाद, यह दे कूलार की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य यूरोप स्थित संघ के कार्यालयों की समस्याओं से परिचित होना और उन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना है। इस का पता उन के यात्रा कार्यक्रम से भी लग जाता है। उन्होंने केवल उन्हीं स्थानों को अपना गंतव्य बनाया है जहाँ कि संघ की बड़ी शाखाएँ स्थित हैं और जहाँ उनकी उपस्थिति प्रशासन के लिए उपयोगी हो सकती है। वह स्विट्जरलैंड के बाद इटली गये, विश्व खाद्य और कृषि संगठन का निरीक्षण किया और वेनिस में तीन दिन विश्राम। इसे महत्वपूर्ण न मानें तो भी उन की ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की यात्राओं को महत्वहीन नहीं ठहराया जा सकता।

दे कूलार की स्विट्जरलैंड की यात्रा, जहाँ उन्होंने अनेक कार्यालयों का निरीक्षण किया, उस समय हुई है जब संयुक्तराष्ट्र संघ की सदस्यता का मुद्दा फिर वहाँ सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है और उसे ले कर शीघ्र ही वहाँ एक जनमतसंग्रह भी होने वाला है। यह ठीक है कि ऐसे जनमतसंग्रह गत चालीस वर्षों में वहाँ कई बार हुए हैं और पूर्वी स्विट्जरलैंड एवं ज्यूरिख के घनी किंतु कंजूस जर्मनों के कारण—जिन्होंने आठ करोड़ डॉलर का वार्षिक खर्चा सामने आते देख हमेशा इस का विरोध किया है। सदस्यता के इच्छुक ज़िनेवा के प्रोटेस्टेंट फ्रांसीसियों को हर बार इस संबंध में निराशा ही हाथ लगी है। किंतु इसी आधार पर संघ के महासचिव को टालमटोल करने वाला कहना गलत होगा।

किसी राष्ट्र के सिर पर हमेशा अर्थशास्त्र ही रहे और वह हमेशा कीमत और फायदे के सवाल ही उठाये, यह जरूरी नहीं है। राजनीति और उस से संबंधित प्रश्न भी कभी वहाँ प्रधान हो सकते हैं। देश में हुए हाल के ही एक अभिमत संग्रह से पता चलता है कि 39 प्रतिशत नागरिक आज इस सदस्यता के पक्ष में हैं, जबकि दूसरे लगभग इतने ही प्रतिशत नागरिक अभी भी निन्यान्त्रवे के चक्कर में पड़े हैं और ऐसी स्थिति में महासचिव की स्विट्जरलैंड की उपस्थिति पल्ले को संघ की ओर झुकाने में मददगार हो सकती है।

ऑस्ट्रिया की राजधानी वीएना स्थित संघ की शाखाओं की स्थिति इस के विपरीत है। अपनी 'तटस्थता' को सुदृढ़ बनाने तथा उसे एक 'ठोस' रूप देने के उद्देश्य से—जो कि ऑस्ट्रियाई सरकार के अनुसार स्वीडेन और स्विट्जरलैंड की तटस्थता से भिन्न है—यहाँ की समाजवादी सरकार ने 1979 में डोनाओ नदी के किनारे एक नगर—यू.एन.ओ. सिटी (जिसे वहाँ दूना सिटी कहते हैं) का निर्माण कर उसे संयुक्तराष्ट्र संघ को समर्पित किया था जहाँ कि आज अंतरराष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्थान के अलावा संघ की कई एक दूसरी छोटी एजेंसियाँ मौजूद हैं। वीएना स्थित संयुक्तराष्ट्र संघ नगर की वर्तमान समस्या यह है कि यद्यपि यहाँ तीन हजार से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। फिर भी उसे संघ की नौकरशाही और सोपान में वह दर्जा नहीं है जो कि यूरोप स्थित संघ की दूसरी शाखाओं को है जिस के कारण यहाँ के संघ कर्मचारियों को वह भत्ता और सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जो कि संघ के दूसरे यूरोपीय कर्मचारियों को मिलती हैं।

ऑस्ट्रिया स्थित संघ कर्मचारियों की इस असुविधा के प्रति यद्यपि कई बार संघ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है किंतु जैसा कि मुझे ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री ब्रूनो क्राइस्की ने, एक भेंटवार्ता में बताया था—कई एक कारणों से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व विदेशमंत्री कुर्ट वाल्डाहाइम उस समय संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिव थे और वे नहीं चाहते थे कि वीएना को यह सुविधा दिलाने की बजाय वे अपने देश के साथ पक्षपात करने का आरोप उन पर आये। अतः उन्होंने अपनी इस माँग को हमेशा दबी आवाज में ही संघ के समक्ष रखा था। इस के अलावा एक समस्या स्विट्जरलैंड को ले कर भी थी। संघ की शाखाओं से प्रतिष्ठा और अर्थ दोनों का प्रचुर लाभ उठाने वाला, यह व्यापारिक एवं घनी राष्ट्र वीएना के संयुक्तराष्ट्र नगर (यू.एन.ओ.सिटी) को आरंभ से ही प्रतिस्पर्धा की नजर से देखता रहा है। किंतु इस बीच इन दोनों देशों की संघीय शाखाओं के

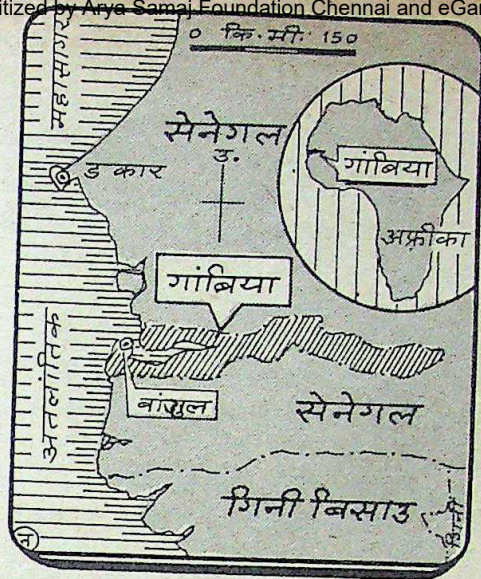


# सुहर्त की जीत अप्रत्याशित नहीं थी

एक बार फिर राष्ट्रपति सुहर्त की सत्ता-रुद्ध गोलकर पार्टी विजयी रही. 1977 की अपेक्षा उसे तीन प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए. सेना समर्थित गोलकर पार्टी को चार करोड़ 60 लाख मत प्राप्त हुए जब कि मुस्लिम युनाइटेड डेवलपमेंट (पी. पी. पी.) पार्टी को दो करोड़ छोटी इंदोनेसियाई लोकतंत्री पार्टी (पी. डी. आई) केवल पचास लाख मत ही बटोर पायी. सत्तारुद्ध पार्टी लोगों के इस विश्वास को राष्ट्रपति सुहर्त की नीतियों और उन के महत्वाकांक्षी विकासकार्यों के प्रति समर्थन पाती है.

इंदोनेसिया के ये चुनाव परिणाम अप्रत्या-शित नहीं थे. इन्हें इसलिए भी आश्चर्यजनक नहीं माना जाता, क्योंकि इंदोनेसिया का लोक-तंत्र सेना की 'कृपा' पर निर्भर है. इसीलिए उसे 'नियंत्रित' लोकतंत्र ही करार दिया जाता है. समाचारपत्रों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, मजदूर संघ गठित करने की स्वाधीनता नहीं, इसलिए किसानों और श्रमिकों के दंगों की खबरें कभी कभी सुनने को मिलती हैं. इन बढ़ते हुए दंगों की घटनाओं के कारण ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख एडमिरल सुडोमो ने सुहर्त से राजनैतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की अवधि घटाने का सुझाव दिया था. लेकिन सुहर्त क्योंकि देश के संविधान के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, लिहाजा उन्होंने प्रतिपक्ष पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगायी.

दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों छोटी पार्टियाँ भी सरकार की देन हैं. 1973 में मुसलमानों के हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए पी पी पी का गठन किया जब कि अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए पी. डी. आई. अस्तित्व में आयी. सरकार द्वारा गठित इन पार्टियों से खास तौर पर पी.पी.पी. पार्टी से गोलकर को अधिक खतरा था, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमानों का दबदबा हाल में बढ़ा है. ये कट्टरपंथी पश्चिमेशिया से प्रेरणा लेते हैं. बेशक इंदोनेसिया में 90 प्रतिशत मुसलमान हैं तथापि वे कट्टरपंथी नहीं. साउदी अरब, ईरान और कुछ हद तक पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के प्रभाव के बावजूद सुहर्त की पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफल हो गयी. अपने इस कट्टरपंथी चरित्र के कारण ही पी पी पी उदारपंथी मुसलमानों के मत बटोरने में सफल नहीं हो सकी. सुहर्त की विजय का एक अन्य कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार है. गरीबी की रेखा तले रहने वाले चालीस प्रतिशत लोगों को अधिक



सहयोग से एक बार फिर सत्तारुद्ध होने में सफल हुए. एक हफ्ते की मशक्कत उन्हें हिला गयी. वे सतर्क हो गये. लोगों में अपनी स्थिति जानने के लिए 4 मई, 1982 को देश की संसद के लिए चुनाव कराये. एक बार फिर सर डावडा जवारा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया. इस जीत के लिए राष्ट्रपति जवारा ने जान की बाजी लगा दी. उन्होंने स्वयं चुनाव प्रचार किया. एक बार तो राजधानी वांजुल से 200 किलोमीटर पूर्व में 57 वर्षीय राष्ट्र-पति जवारा का हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वह बच तो गये लेकिन एक बार फिर हिल गये. क्या उन्हें यह दूसरा जीवनदान था : कभी वह अपने आप से पूछते, कभी डाक्टरों से जिन्होंने राष्ट्रपति को एक हफ्ते के विश्राम की सलाह दी थी.

बहरहाल, इस व्यापक चुनाव प्रचार और हेलिकॉप्टर के हादसे से राष्ट्रपति जवारा ने लोगों की सहानुभूति अर्जित की. उन की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी (पी. पी. पी.) ने 35 सदस्यीय सदन में एक बार पुनः स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया. प्रतिपक्षी नेशनल कंवेन्शन पार्टी (एन पी सी) के नेता शेरिफ मुस्तफा दिब्बा जो जुलाई 1981 की क्रांति में भाग लेने के कारण जेल में हैं, एक भी स्थान जीतने में सफल नहीं हुए. 1977 के चुनाव में पी पी पी पार्टी ने 28 स्थान जीते थे जब कि यूनाइटेड पार्टी ने दो और एन सी पी ने पाँच स्थान. 1979 के नगरपालिका चुनावों में भी पी पी पी का दबदबा रहा. इन चुनावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति जवारा की गाम्बिया की राजनीति पर खासी पकड़ है.

गाम्बिया गुटनिरपेक्ष देश है. गाम्बिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध तो हैं ही, कभी उस के ताइवान और इस्राइल से भी संबंध हुआ करते थे. ताइवानी विशेषज्ञों की सहायता से गाम्बिया में सिचाई परियोज-नाएँ पूरी की गयी थीं.

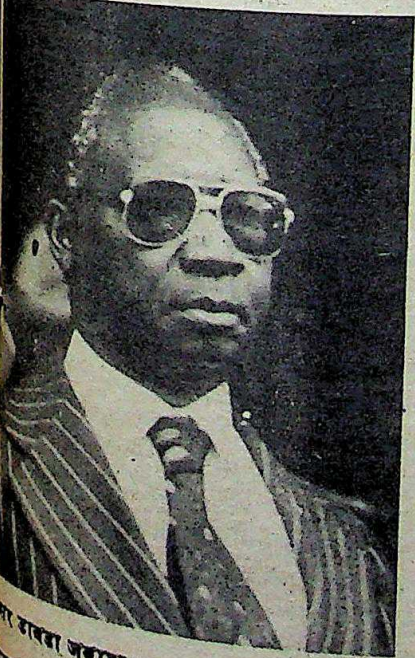
वर्ष एवं कार्यक्षेत्र स्पष्ट हो जाने तय  
वांजुल हाइम के महासचिव के पद से मुक्त  
हो जाने के कारण स्थिति बदल गयी है और  
हो जाने के कारण स्थिति बदल गयी है और  
हो जाने के कारण स्थिति बदल गयी है और

ऑस्ट्रिया सरकार की नीति तीसरी दुनिया  
की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के प्रति  
सचेत है, केवल इसी लिए उस की इस माँग  
केवल नहीं है बल्कि इस लिए भी है कि यूरोप का  
यह अपेक्षाकृत कम धनी राष्ट्र मानवजाति  
को दी गयी इस विशाल एवं स्थायी भेंट के  
तले में संयुक्तराष्ट्र संघ से प्रतिवर्ष केवल 1  
बिलियन का सांकेतिक किराया ही वसूल  
जाता है.

गाम्बिया

## दूसरे हादसे की जीत

राज से दस महीने पहले 29 जुलाई 1981  
को लंदन में शाही दावत उड़ाते समय  
गाम्बिया के राष्ट्रपति सर डावडा जवारा को  
सरा पलट का संदेश मिला तो उन के हाथ  
के काँटा और चाकू चलते चलते रुक से गये.  
उसे खायी नहीं गया. वह शाही दावत की  
समाप्ति का बेसब्री से इंतजार करने लगे.  
उन्होंने शाही नवदंपति राजकुमार चार्ल्स  
और राजकुमारी डियाना का अभिवादन कर  
उन से कूच किया. क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी  
और बच्चों के बंधक बनाये जाने का समाचार  
मिल चुका था, लिहाजा वे सेनेगल की राज-  
धानी डाकार पहुँचे और वहाँ के राष्ट्रपति के



सर डावडा जवारा : चुनाव के झूए में जीत



लाम नहीं हो सका लेकिन आसपास के देशों को देखते हुए या राष्ट्रपति सुकर्णो को सरकार से तुलना करने पर सुहर्तो की सरकार को बेहतर माना जाता है। 1979 में जहाँ देश में 21.9 प्रतिशत मुद्रास्फीति थी 1981 में वह घट कर 6.8 प्रतिशत रह गयी। इस के अलावा देश की तेल संपदा से विदेशी ऋण की भी अदायगी संभव हो सकी। लिहाजा राष्ट्रपति सुहर्तो द्वारा देश को दी गयी राजनैतिक स्थिरता भी निस्संदेह उन की जीत का कारण बनी।

बावजूद इस के अभी भी सुहर्तो को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंदोनेसिया में तीन हजार के करीब द्वीप छिरे पड़े हैं। उन में संचार व्यवस्था और उन का प्रशासन अपने आप में खासा मुश्किल काम है। इन्हीं द्वीपों में ऐसे लोग भी बसते हैं जिन्हें पाषाण युग का माना जाता है और इन्हीं द्वीपों में आधुनिक युग के लोग भी बसते हैं। हरेक की ज़रूरतें अलग अलग हैं। लिहाजा राजधानी जकार्ता में रह कर दूरदराज फैले द्वीपवासियों की समस्याओं का आकलन कर पाना मुश्किल होता है। इस के लिए सुहर्तो की यदाकदा आलोचना भी होती रहती है। इस के अलावा सुहर्तो का शासन कम्युनिस्ट विरोधी है। आज भी जब सुकर्णो के बच्चे कम्युनिस्ट पुराने स्वर्णिम युग की याद करते हैं तो उन्हें तुरंत दबा दिया जाता है। इन तत्त्वों से अलबत्ता सुहर्तो कभी कभी परेशान से हो जाते हैं लेकिन अपने लचीले व्यक्तित्व के कारण स्थिति संभाल ले जाते हैं। □

फॉकलैंड

## यह किन सिद्धांतों की लड़ाई है

फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन और आर्जेन्टीना के जिस संघर्ष को मामूली समझा जा रहा था उस ने अब गंभीर रूप ग्रहण कर लिया

सभी तरह के सामान से भरे मोलों के साथ आर्जेन्टीना के सैनिकों का फॉकलैंड आगमन : ताजा प्रहार का संकेत



है। आर्जेन्टीना ने सोचा था कि वह फॉकलैंड पर कब्जा कर लेगा और कहीं कोई हरकत नहीं होगी तो ब्रिटेन के मन के किसी कोने में शायद यह टंका था कि फॉकलैंड से आर्जेन्टीना के सैनिकों की निकासी में कठिनाई नहीं आयेगी। दोनों की समर और रणनीतियाँ गलत साबित हुईं। कल की समझी जाने वाली चिनगारी अब शोला बन चुकी है और उस की गिरफ्त में सिर्फ ब्रिटेन और आर्जेन्टीना ही नहीं संयुक्तराष्ट्र भी आ चुका है।

पिछले दिनों संयुक्तराष्ट्र के महासचिव जेवियर पेरैज दे कूलार ने दोनों देशों को वार्ता पटल पर आमने सामने बिठा समस्या का समाधान ढूँढना चाहा। डॉ. कुर्ट वाल्डाहाइम के बाद महासचिव का पद संभालने वाले कूलार के समक्ष यह पहला जटिल मसला था। निस्संदेह ऐसे जटिल मुद्दों पर ही किसी व्यक्ति और विशेष तौर पर संयुक्तराष्ट्र महासचिव की परीक्षा होती है। श्री कूलार का छह नुक्तों का प्रस्ताव इस प्रकार था : 1) सभी तरह के संघर्ष को तुरंत समाप्त किया जाये, 2) आर्जेन्टीना के सैनिकों की फॉकलैंड से वापसी हो, 3) ब्रितानी नौसैनिक बेड़े की ब्रिटेन वापसी हो, 4) बातचीत की शुरुआत की जाये, 5) आर्जेन्टीना के विरुद्ध लगे आर्थिक प्रतिबंधों का निलंबन हो और 6) संयुक्तराष्ट्र द्वारा संक्रमणकालीन उपाय किए जायें। संक्रमणकालीन उपायों में दक्षिण अतलांतिक द्वीपों के प्रशासन के लिए संयुक्तराष्ट्र प्रशासक की नियुक्ति है। यह प्रशासक वहाँ तब तक रहेगा जब तक दोनों पक्ष चाहेंगे।

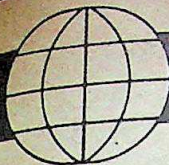
शुरु में आर्जेन्टीना और ब्रिटेन दोनों का ही संयुक्तराष्ट्र महासचिव के इस प्रस्ताव के प्रति अनुकूल रवैया था। बाद में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट टैचर ने घोषणा की कि जब तक आर्जेन्टीना अपने सभी सैनिकों को वापस नहीं बुला लेता तब तक ब्रिटेन युद्धविराम के लिए तैयार नहीं है (श्रीमती टैचर की माँग है कि 2 अप्रैल से फॉकलैंड में तैनात 900 सैनिक तुरंत हटें) जब कि आर्जे-

न्टीना पहले बिना शर्त युद्धविराम की माँग कर रहा है। क्योंकि दोनों के ही अपने अपने हठ हैं लिहाजा यह मसला निरंतर खिंचता जला जा रहा है। इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र महासचिव दे कूलार का 8 मई, 1982 का पूरे दिन का प्रयास अधिक फलदायी सिद्ध नहीं हुआ। उन की केवल इतनी ही प्रतिक्रिया थी 'कुछ मुद्दों पर ही प्रगति हो सकी है'।

फिलहाल पेरैज दे कूलार की मध्यस्थता भी अमेरिकी विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग की कई दौरा मध्यस्थता की तरह विफल ही करार दी जा सकती है। दो दिन की शांति के बाद ब्रितानी सैनिक पुनः सक्रिय हो गये हैं और आर्जेन्टीना के सैनिक भी अभी तक डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ब्रितानी सैनिक और शासक वर्तमान प्रहार को निर्णायक प्रहार करार दे रहे हैं। प्रेक्षकों का मानना है कि यदि इस बार फॉकलैंड पर अधिकार करने में वे सफल नहीं हुए तो श्रीमती टैचर की सत्ता के पाये हिल सकते हैं। पिछले दिनों हाउस ऑफ कामंस में प्रतिपक्षी नेता माइकेल फू ने इस आशय की माँग तक कर डाली। वास्तव में कंजरवेटिव पार्टी की कुछ ऐसी ही निर्णय भी रही है। एडवर्ड हीथ भी जब कोयला खनिकों को संतुष्ट न कर सके तो उन्हें सत्ता से हटाना पड़ा और मध्यावधि चुनाव में हार विल्सन की लेबर पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली। लेकिन इस बार मामला आंतरिक नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आम तौर पर सभी पक्ष सरकार की नीति का समर्थन ही करते हैं।

बहरहाल, ब्रितानी, सैनिक पुनः सक्रिय हो गये हैं। ब्रितानी युद्धपोतों ने फॉकलैंड के मुख्य नगर पोर्ट स्टेनली के बाहर मुख्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। ब्रितानी सैनिकों ने अपने प्रहार के क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया है। ब्रिटेन ने मछली पकड़ने की एक नौका को डुबो दिया है। ब्रितानी वायु सैनिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है ताकि आर्जेन्टीना को संभलने का अवसर न दिया जाये। क्या ब्रिटेन फॉकलैंड में लड़ने की सिद्धांतों को लेकर लड़ रहा है? यदि हाँ तो इस के लिए उसे खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस समय दक्षिण अतलांतिक के ब्रितानी जंगी बेड़े में दो हजार नौसैनिक हैं, तीन हजार और शीघ्र जुड़ सकते हैं। यद्यपि ब्रिटेन ने तीन हेरियर खोये हैं लेकिन आर्जेन्टीना की खबर स्वीकार की है लेकिन आर्जेन्टीना के अनुसार ब्रिटेन ने एक दर्जन से अधिक हेरियर गँवाये हैं। 66,000 टन असला भी भेज चुका है। यद्यपि आर्जेन्टीना के नेता ब्रितानी सैनिकों के जमाव और पोर्ट स्टेनली पर प्रहार को आर्जेन्टीना के सैनिकों में घबड़ाहट फैलाने वाला काम मानते हैं लेकिन श्रीमती टैचर लगता है अपनी राजनैतिक जीवित रखने की आखिरी वाजी लगाना तय कर चुकी है।





## रूस में नात्सी

फासीवादियों जैसी काली कमीज पहने और नात्सी प्रतीक बिह लगाये हुए कई रूसी युवक आज कल रूस की सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास करते हैं। पश्चिम के इसी तरह के अन्य दलों के समान वे लड़के भी बाल छोटे छोटे रखते हैं और जरा सा बहाना मिलने पर अन्य दलों से लड़ाई खोल ले लेते हैं। 20 अप्रैल को रूसका के पुश्किन चौक में जमा हो कर जब ये लड़के हिटलर की वर्णगठ मना रहे थे तो पुलिस और अन्य युवा दलों ने इन्हें दबोच लिया। वैसे कई शहरों में इन की फासी धाक है, विशेष कर बाल्टिक क्षेत्र में, जहाँ रूसी शासकों के चंगुल से निकलने को उत्सुक लोगों ने नात्सियों का स्वागत किया था।

## शेखों के बुरे दिन

कुवैत उन राष्ट्रों में से एक जो 1973 से लगातार तेल के दाम बढ़ाते रहे हैं—लेकिन केवल बाहर वालों के लिए। कुवैत के नागरिकों को तो अब तक तेल की भाव मिलता रहा। इस देश के 500,000 गाड़ियों के मालिक सब से बढ़िया पेट्रोल 90 ऑक्टेन से अपनी गाड़ियों में तेल टंकियाँ भरवाने के लिए केवल 19 सेंट खर्च करते थे, जब कि 7.5 सेंट डीजल से गाड़ी की टंकी भर जाती थी। कुवैत की सरकारी तेल संस्था कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी अपने खर्चों से भी कम भाव में अब तक पेट्रोल बेचती रही। लेकिन हाल में यहाँ के मोटर चालकों ने माया कि अचानक ही पेट्रोल के भाव तिगुने हो गये हैं। इस के कारण विश्वबाजार में तेल का दाम तेजी से गिरना है, जिस से 5 साल कुवैत की आमदनी 5 अरब डॉलर कम हो जायेगी। इस घाटे को घर के खरीददारों से ही पूरा किया जा सकता है, ऐसा कुवैत की सरकार का विचार है।

## दक्षिण अफ्रीका पर आरोप

गत नवंबर में सेशेल्स में क्रांति की असफल कोशिश के पीछे दक्षिण अफ्रीका का हाथ था, इस बात का पता वरिष्ठ उग्रवादी नेता कर्नल मार्ईक होर ने दक्षिण अफ्रीका के न्यायालय में दिया। कर्नल होर कठघरे में खड़े किये गये उन 43 उग्रवादियों के मुकद्दमें में बोल रहे थे जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि असफल क्रांति के बाद उन्होंने एक भारतीय विमान का हवाहरण किया था। होर ने आगे बताया कि सेशेल्स सरकार को अपदस्थ करने की साजिश के बारे में दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर विभाग को मालूम था और क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र भी दक्षिण अफ्रीका के सैनिकों से प्राप्त हुए थे।



## ‘ईसा फिर आ रहे हैं’

स्कॉटलैंड के 59 वर्षीय चित्रकार बेंजमिन क्रीम ने दुनिया भर के प्रमुख समाचारपत्रों में पूरे पृष्ठों के विज्ञापन दे कर विश्व को संदेश दिया है कि ‘जल्द ही ईसा मसीह अपना परिचय दुनिया के सामने रखेंगे और अगले दो महीनों में वह किसी भी समय मानवता से वात्सलाप करेंगे’। लेकिन क्रीम ने ईसा मसीह का नाम बदल कर मैत्रेय स्वामी कर दिया है, क्योंकि उन का कहना है कि आज के ईसा मसीह भारतीय हैं और 19 जुलाई, 1977, से अपने देश से बाहर, छद्म नाम ले कर, किसी शहर में रह रहे हैं। क्रीम को इस का पता कैसे चला?

टेलीपथी (दूरसंवेदन) से, क्यों कि वह स्वामी जी के पाँच शिष्यों में से एक हैं।

क्रीम जल्द ही लॉस एंजेलस में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करेंगे कि ईसा मसीह इस समय कहाँ हैं। उसके 60 दिन के अंदर भगवान ईसा स्वयं दूरदर्शन के पर्दे पर प्रकट होंगे। वह बोलेंगे कुछ नहीं, क्यों कि हर व्यक्ति से, टेलीपथी के जरिये, वह हरेक की अपनी अपनी भाषा में बातचीत करेंगे। इस के साथ एक नये युग का आरंभ होगा, जिस का आधार साझेदारी, न्याय और शांति होगा। यह क्रीम की सनक मात्र है, या उस के पीछे कोई तथ्य है, यह जानने के लिए उत्सुक लोगों को अभी दो महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

## ‘न्यायालय सचाई से घबराता है’

इटली के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एल्डो मोरो की हत्या के सिलसिले में ‘रेड ब्रिगेड’ के जिन सदस्यों को अदालत में पेश किया गया था वे अदालत पर ही यह आरोप लगाते हुए एक जुट हो कर निकल गये कि अदालत सचाई से डरता है। 63 अभियुक्तों में से 31 उपस्थित अभियुक्तों को यह भी शिकायत थी कि उन्हें नामों

के प्रथम स्वरों के अनुसार कठघरे में नंबरवार खड़ा किया गया था, जब कि किस कठघरे में किस के साथ खड़ा होना है, यह उन की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए था। ‘रेड ब्रिगेड’ के नेता ल्यूका निकोलैत्ती ने यह मांग अध्यक्ष के सामने रखी, जो कि स्वीकृत नहीं हुई। फिर कचहरी में केवल एक ही अभियुक्त खड़ा रह गया, जो ‘पश्चाताप’ करने के लिए तैयार था।

## गणित में बेहतर कौन

अमेरिका में कंप्यूटर विज्ञान, प्रायोगिक शोध और वाणिज्य व्यवस्था पढ़ने वाले अधिकांश छात्र पुरुष हैं, जब कि वेनेजुएला जैसे कुछ देशों के विश्वविद्यालयों में इन विषयों को पढ़ने वालों में अधिकांश लड़कियाँ हैं। इस का कारण यह बताया है कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलता है और बहुसंख्य लड़कियाँ बड़े जैव अंक प्राप्त करती हैं, जब कि अमेरिकी लड़कियाँ गणित से घबराती हैं। फिर राजनीति को छोड़ कर यहाँ हर क्षेत्र में स्त्रियाँ आगे हैं, जिस के कई सबूत मौजूद हैं। जैसे वेनेजुएला की एक बड़ी इंजीनियरी कंपनी में दो सब से बड़े ओहदों पर इंजीनियर स्त्रियाँ हैं।

## जासूसी का ‘इनाम’

देश के विभाजन के बाद से पूर्व और पश्चिम जर्मनी एक दूसरे को शक की नजरों से देखते रहे हैं और दोनों देशों के जासूसों की घर पकड़ जारी रही है। इसी सिलसिले में भारीएत्ता और यर्गेन रीशवॉल्ड पर इस समय पूर्व जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है। पश्चिम जर्मनी की सरकार का कहना है कि पति

पत्नी दोनों ही 1973 से जासूसी के काम में लगे हुए हैं और इंजन तथा विमान के कारखानों में काम करते हुए उन्होंने कुछ गोपनीय सूचनाएँ पूर्व जर्मनी को पहुँचायी हैं।

इन के साथ हॉस्ट हेक को भी 1980 में गिरफ्तार किया गया था। अब इस वर्ष के आरंभ से, म्यूनिख में, इन तीनों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है।

## हॉस्ट हेक और रीशवॉल्ड वंपति





## खेल और खिलाड़ी

### विबलडन

## विजय अमृतराज के लिए यह स्वर्ण अवसर हो सकता है

**वि**श्व की सब की प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता विबलडन (21 जून से 4 जुलाई 1982) में इस वर्ष स्वीडन के ब्योन बॉर्ग नहीं होंगे। पांच बार विबलडन चैंपियन बॉर्ग न तो मुख्य प्रतियोगिता में खेलने के लिए 'योग्यता प्राप्त' करने वाले टूर्नामेंट से गुजरने को तैयार हैं और न ही दस प्रमुख प्रतियोगिताओं में खेलने की शर्त ही उन्हें मंजूर है। बॉर्ग की इस इनकारी पर टेनिस परिषद ने एक समझौता प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगर बॉर्ग 1983 के पहले तीन महीनों में तीन अतिरिक्त प्रतियोगिताएँ खेलने पर सहमत हों तो उन्हें सीधे प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन बॉर्ग इसे उचित और सम्मानजनक प्रस्ताव नहीं मानते: 'आप इस बात की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अगले वर्ष आप के साथ क्या होगा।'

बॉर्ग के अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया के इवान लेंडल और आर्जेन्टीना के क्लेक के भी विबलडन में खेलने की कम संभावना है। लेंडल को घास का मैदान रास नहीं आता। वह सीमेंट के मैदान पर खेलने का आदी है। यही कारण है कि पिछले विबलडन के पहले चक्र में लेंडल को 195 नंबर के खिलाड़ी ने हरा दिया था। पिछले दिनों डलेस (अमेरिका) में टेनिस विश्व चैंपियनशिप में जॉन मेक्नरो को पराजित कर डेढ़ लाख डॉलर का इनाम जीता। लेंडल की मेक्नरो पर यह चौथी लगातार विजय थी। मेक्नरो स्वयं मानते हैं कि लेंडल बेहतर खिलाड़ी है। लेंडल मेक्नरो को भी अच्छा खिलाड़ी मानते हुए कहते हैं कि हर बार मेक्नरो को पराजित करना महत्वपूर्ण होता है। पिछले दिनों लेंडल ने 80 मैच खेले जिस में से 78 उस ने जीते।

क्लेक के विबलडन में न खेलने का कारण फांक्लैंड द्वीपसमूह के स्वामित्व को लेकर आर्जेन्टीना और ब्रिटेन में युद्ध है। आर्जेन्टीना के जोस लुई क्लेक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर फांक्लैंड द्वीप पर ब्रिटेन और आर्जेन्टीना में युद्ध जारी रहता है तो 'मैं विबलडन नहीं खेलूंगा' क्लेक का इस समय विश्व टेनिस में पाँचवाँ स्थान है।

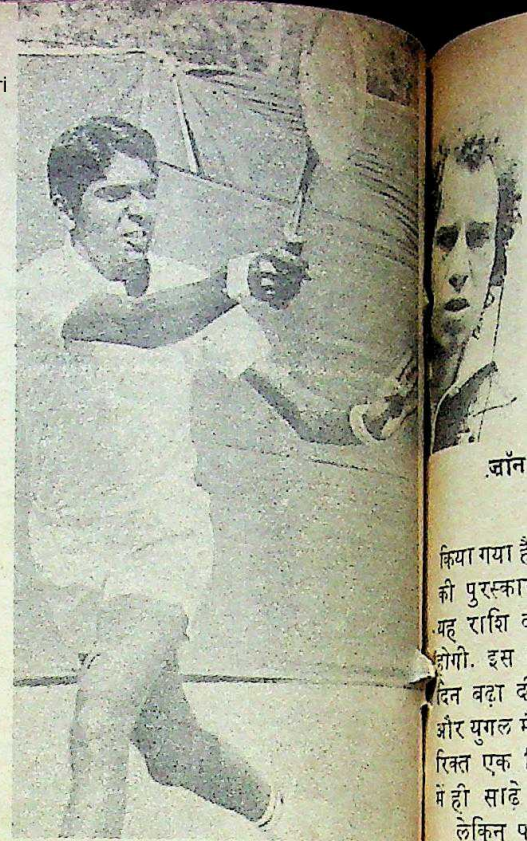
इन तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के विबलडन बहिष्कार से दर्शक वेशक बेहतरीन खेल से महलूम रहेंगे लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो कभी

क्वार्टर फाइनल और सेमिफाइनल तक पहुँचते रहे हैं वे अपना भाग्य आजमाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे खिलाड़ियों में भारत के विजय अमृतराज से कुछ उम्मीद बँधती है। वह एक बार विबलडन के सेमिफाइनल तक पहुँच चुके हैं। जिस प्रकार का उन का खेल और खेलने का ढंग है नामुमकिन नहीं कि वह फाइनल तक पहुँचने में सफल हो जायें। यह जो महत्वपूर्ण अवसर विजय को प्राप्त होगा उस का लाभ उठा कर वह पहले भारतीय विबलडन चैंपियन बनने की अपनी हसरत पूरी कर सकते हैं। वैसे रमेश कृष्णन् के खेल में भी खासा सुधार हुआ है लेकिन उम्र और अनुभव में उसे अभी विजय अमृतराज जैसा स्थान प्राप्त करने में समय लगेगा। शिखर पर पहुँचने के लिए अभी भी विजय को दो प्रमुख खिलाड़ियों से भिड़ना होगा: पिछले चैंपियन मेक्नरो और कोनर्स से। इन दोनों ही खिलाड़ियों को विजय कई प्रतियोगिताओं में पराजित कर चुका है।

बॉर्ग और लेंडल के न खेलने से विबलडन के दर्शकों को निराशा अवश्य होगी लेकिन आयोजक ऑल इंग्लैंड क्लब इस तरह के हादसे का आदी हो चुका है। 1973 में युगोस्लाविया के निक्की पिलिच के मुद्दे को लेकर सभी पेशेवर खिलाड़ियों ने विबलडन में खेलने से इनकार कर दिया था। इस का कारण पिलिच को डेविस कप के लिए खेलने से इनकार करने पर निलंबित किया जाना था। इसी प्रकार 1968 में जब सभी पेशेवर खिलाड़ियों ने विबलडन में खेलने से इनकार कर दिया तो ऐसा लगा कि विबलडन लड़खड़ा जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विबलडन में तब दर्शकों की बेमिसाल भीड़ एक नयी मिसाल कायम कर गयी।

विबलडन विबलडन है। उस की अपनी परंपराएँ हैं। ब्रितानी वैसे भी परंपरा और परिपाटी प्रिय हैं। इस प्रकार के बहिष्कारों की वे चिंता कम ही करते हैं। यही कारण है कि 1877 से अभी तक विबलडन विश्व की प्रथम श्रेणी की टेनिस प्रतियोगिताओं में से है। इस बीच वेशक अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता, फ्रांसीसी प्रतियोगिता, जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ अस्तित्व में आयीं लेकिन विबलडन का आकर्षण बरकरार है।

समय सरकने के साथ साथ विश्व टेनिस में परिवर्तन हुए हैं लेकिन विबलडन ने बदलाव का विरोध ही किया है। आज भी विबलडन में घास के कोर्ट पर टेनिस खेला जाता है जब कि अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता तथा यूरोप की अन्य प्रतियोगिताएँ सीमेंट के कोर्ट पर खेली जाती हैं। विबलडन ही एक मात्र ऐसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जो व्यापारिक तौर पर प्रायोजित नहीं होती।



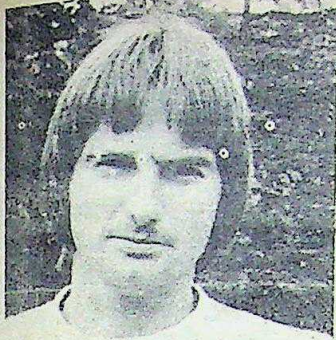
विजय अमृतराज : चुनौती

हालाँकि इस आशय के प्रस्ताव कई बार आ चुके हैं। विबलडन अधिकारी अभी तक इस आशय के प्रस्तावों को ठुकराते आये हैं। इस का कारण यह है कि आर्थिक तौर पर विबलडन ठोस धरातल पर है और घोटालों की संभावनाएँ कम हैं। पिछले वर्ष विबलडन में उस ने इतना धन कमाया कि लगभग 20 लाख डॉलर (दो करोड़ रुपये) ब्रितानी लॉन टेनिस संघ को खेल के विकास में सहायता के लिए दे दिये। इस वर्ष पुरस्कार राशि में 84 प्रतिशत की वृद्धि का एलान



ब्योन बॉर्ग : बहिष्कार





जॉन मेक्नरो और जिम्मी कोनर्स  
मूलपूर्व चैंपियन

किया गया है। पिछले वर्ष की 757,020 डॉलर की पुरस्कार राशि की तुलना में इस साल यह राशि दस लाख, साठ हजार डॉलर की होगी। इस वर्ष प्रतियोगिता की अवधि एक दिन बढ़ा दी गयी है ताकि पुरुषों का एकल और युगल मैच रविवार को हो सके। इस अतिरिक्त एक दिन से केवल टेलिविजन राजस्व में ही साढ़े सात लाख डॉलर की वृद्धि होगी।

लेकिन पटरी पर रात भर सो कर टिकट देने वाले दर्शकों को अलबत्ता इस वर्ष एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। ब्रितानी कानून के अनुसार किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए इतवार को गेट पर टिकट बेचने की मनाही है। लिहाजा ऐसे दर्शकों को फाइनल देखने वाले अन्य ढाई लाख लोगों की तरह अग्रिम टिकट डाक से प्राप्त करने होंगे। डाक से प्राप्त टिकट से प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। वैसे खड़े होकर मैच देखना भी एक परंपरा है। पटरी पर सोने वाले लोगों के विरुद्ध लंदन के स्थानीय लोगों की भी शिकायत है। पटरी पर सोने वालों के विस्तार तो लगे होते हैं लेकिन वे रात भर गिटार बजा बजा कर गाते रहते हैं। इससे लोगों के सोने में बाधा उत्पन्न होती है जो ब्रितानी कानून और परंपराओं दोनों के अनुकूल नहीं।

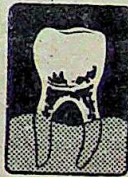
यद्यपि बोर्ग ने योग्यता परीक्षण प्रतियोगिता में खेलने से इनकार कर दिया है लेकिन बॉल इंग्लैंड क्लब के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल सर ब्रियेन बर्नेट ने इस की पूरी तैयारी कर ली है; न जाने बोर्ग का मन कब बदल जाये। योग्यता परीक्षण की प्रतियोगिता में खेल खेलने और खिलाड़ियों की सुरक्षा की सुविधाएँ नहीं। अगर बोर्ग ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो दर्शकों के प्रवेश पर मनाही होगी। लेकिन पाँच बार विवडलन चैंपियन बोर्ग ने योग्यता परीक्षण को 'अपमानजनक' करार दिया है और कहा है कि वे अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। क्या एक साल में चार मास विश्राम करना गुनाह है। इतना खिलौने के बाद यह विश्राम खेल और खिलाड़ियों के ही हित में है। बेशक नियमों को जकड़न भी ब्रितानी परंपरा है।

## फोरहॅन्स दाँतों के डॉक्टर का बनाया हुआ दूधपेस्ट



**दाँतों को साफ करने के साथ-साथ  
मसूड़ों की मजबूत बनाने में मदद करता है**

मसूड़ों की तकलीफ से स्वस्थ दाँत भी गिर सकते हैं



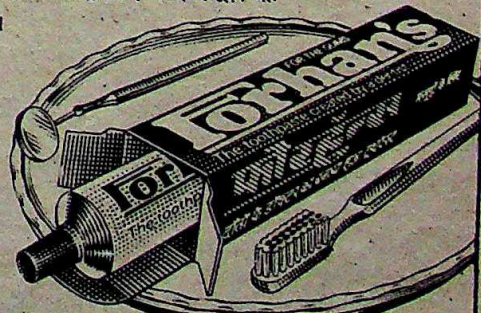
दाँतों के डॉक्टर कहते हैं कि दाँतों को ठीक से साफ न किया जाय तो कीटाणुओं की अदृश्य परत, जिसे प्लाक कहते हैं, दाँतों और मसूड़ों पर जमा होने लगती है। आगे चलकर यह टारटर बन जाती है जो मसूड़ों को कमजोर बनाकर उन्हें सिकोड़ती है जिससे स्वस्थ दाँत भी गिर सकते हैं। मसूड़ों की तकलीफ से तन्दुरुस्ती भी खराब हो सकती है।

**फोरहॅन्स- मसूड़ों की रक्षा के लिए**



डॉक्टर फोरहॅन्स का विशेष फ़ॉर्मूला अपने असरकारक एस्ट्रिजेंट के कारण मसूड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें तकलीफ से दूर रखने में आपकी मदद करता है।

इसलिये फोरहॅन्स दूधपेस्ट और फोरहॅन्स डबल एक्शन दूधब्रश से अपने दाँतों की सफ़ाई और मसूड़ों की मालिश कीजिये।



**फोरहॅन्स  
मसूड़ों के लिए**

Regd. T.M. Geoffrey Manners & Co. Ltd.

267F-222 HIN



**डाक्टर** हालाँकि कवि नहीं है, पर महोश चांदनी मला किसे नहीं खींचती। तभी फोन की घंटी खनखना उठती है। अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में डाक्टर को बुलाया गया है। डाक्टर जाता है और देख कर दंग रह जाता है। सब के सब मरीज वे थे, जो जहर खा कर मरना चाहते थे। डाक्टर उल्टियाँ कराने की दवा पिलाने की हिदायत करता है और खुद खिड़की से झाँकने लगता है। बाहर पूर्णिमा की सफेद दूधिया चांदनी बिखरी होती है। अचानक डाक्टर के मन में एक विचार कौंधता है। कहीं पूर्णिमा और विषपान में कोई पारस्परिक संबंध तो नहीं।

इस तरह जन्म होता है एक अनुसंधान योजना का। पटना मेडिकल कालेज से जुड़े अस्पताल में डा. चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर ने अपने साथ युवा डा. राम नारायण शर्मा और सांख्यिकीविद अक्षर साहव को भी लिया और जनवरी 1976 से दिसंबर 1979 तक अस्पताल में जहर खाने के जितने भी मरीज दाखिल हुए, सब के आँकड़े इकट्ठे किये। जब तक खुद रिश्तेदारों ने ही जहर न दिया हो, लोग घोखे से या आत्महत्या के इरादे से विषपान करने वाले को तुरंत अस्पताल ही ले जाते हैं। चार वर्ष के इस अनुसंधान काल में 49 पूर्णिमाएँ पड़ीं और इन में जहर खाने की 45 घटनाएँ दर्ज की गयीं। यों ऐसा नहीं था कि सारे लोग जहर की पुड़िया लिए हुए पूनम की रात की ही प्रतीक्षा करते रहे हों। बिना पूनम वाले 1412 दिनों में भी जहर खाने की घटनाएँ हुईं। लेकिन आँकड़ाशास्त्री अक्षर साहव के हिसाब से ये कम थीं। तुलना करने पर यही तय पाया गया कि कुछ लोगों के लिए कमबलत चांदनी सचमुच जान लेना सिद्ध होती है।

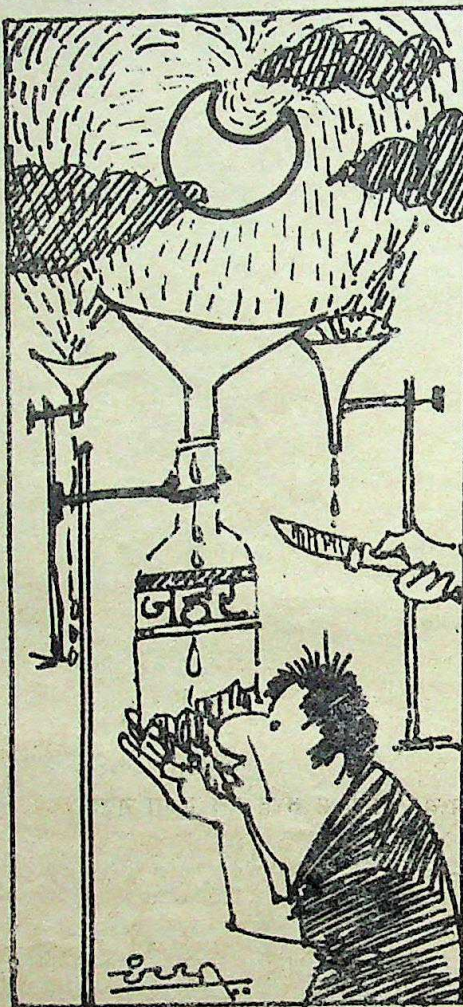
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के 281 वें खंड के पृष्ठ 1684 पर प्रकाशित अपने शोध-पत्र में डा. ठाकुर और उन के सहयोगी शर्मा और अक्षर का यही कहना है कि जिस तरह पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार की लहरें सब से ऊँची उठती हैं, कुछ-कुछ वैसा ही प्रभाव मानव देह पर पड़ता होगा। डाक्टर टोली ने इस प्रभाव को 'मानवीय ज्वार तरंग' (ह्यूमन टाइडल वेव) कहा है। इसीलिए पटना मेडिकल कालेज के इन डाक्टरों का कहना है कि देह जल पर पूर्णिमा के चंद्रमा का खिंचाव न जाने शरीर के भीतर कितनी तरह के रासायनिक परिवर्तनों की शृंखला पैदा करता होगा। इन का असर अंत में मस्तिष्क पर पड़ता होगा, जिस के कारण कुछ लोगों का मानसिक संतुष्ट सारी सीमाएँ तोड़ कर उन्हें विषपान के लिए विवश कर देता होगा।

हालाँकि इस तरह की 'गान्धी-ने' वाली संशयात्मक भाषा भारतीय राजनीति और आकाशवाणी की ही शोभा देती है, विज्ञान में नहीं चलती। लेकिन बिहार के इन विशेषज्ञों ने

विज्ञान

## हर समस्या की जड़ चांदनी ही है

रमेशबन्त शर्मा



अपनी अभिव्यक्ति के लिए यही स्तर चुना है। पूर्णिमा की रात मानव शरीर में क्या कोई खास जीव-रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस बारे में डा. ठाकुर की संझली ने कोई प्रयोग नहीं किये, नहीं तो वे अपनी बात अधिक तथ्य-परक भाषा में रख पाते। उन्होंने शिकागो की इलीनॉइस यूनिवर्सिटी के फार्माकोलोजी (भेषज विज्ञान) के प्रोफेसर राल्फ डब्ल्यू मोरिस का भी जिक्र नहीं किया, जो मानव देह पर चांद सितारों के असर के बारे में की गयी वैज्ञानिक खोजों के लिए मशहूर हैं। डा. मोरिस ने पता लगाया है कि देह की कोशिकाओं में सतत चलने वाली निर्माण और विनाश की चयापचय क्रियाएँ पूर्णिमा की रात ज्यादा तेज हो जाती हैं। रक्तचाप भी प्रामाणिक रूप से बढ़ता है और दिल धड़कने की रफ्तार भी कुछ ज्यादा हो जाती है। यही नहीं, देह में विविध ग्रंथियों से स्रवित होने वाले हार्मोनों और एंजाइमों की क्रिया में भी पूर्ण चंद्र के प्रभाव से अधिक तीव्रता आ जाती है।

इतना तो लोक मानस भी जानता है कि पूर्णिमा को खून बहा तो फिर बहता ही जाता है। इसीलिए देहातों में बैलों को बधिया करने का काम पूर्णिमा के दिन नहीं करते। अब तो अस्पतालों में भी जहाँ तक हो सज्जन लोग बड़े आपरेशन तो प्रायः पूर्णिमा को नहीं करते डा. मोरिस ने भी अपने अध्ययनों में पाया कि पूर्णिमा और अतिरिक्त स्त्राव का भी परस्पर संबंध है। इसी तरह मिर्गी के दौरे और दिल के दौरे भी पूनम के कारण ज्यादा पड़ते हैं। दुनियाभर के पागलखानों में पूर्णिमा को 'लूनेटिक' यों ही तो नहीं कहा गया। खुशी की बात यही है कि डा. मोरिस का कहना है कि वे अपनी खोजों के आधार पर शायद ऐसे रास्ते सुझा सकें, जिन के द्वारा कुछ विशेष रोगों और लोगों की गुत्थी सुलझ सके। कुछ दवाएँ तो सचमुच ही पूर्णिमा को दी जायें तो बेहतर असर करती हैं। इस का उल्लेख आयुर्वेद में भी है।

चूँहों पर किये गये एक प्रयोग से पता चला कि दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए मौफॉन दवा अगर पूर्णिमा के रोज दी जाये, तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा गहरा असर करती है। इसी तरह दिल के दौरे के मरीजों को एक दवा दी जाती है 'डाइजोक्सिन'। इस को भी प्रयोगशाला के प्राणियों को खिला कर परखा गया तो दिल को दुरुस्त करने में पूर्णिमा के रोज इस दवा ने ज्यादा चुस्ती दिखायी।

डा. मोरिस की प्रयोगशाला से इस तरह के अन्य शुभ समाचारों का हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें बेचैन किये रहती है यह खबर, जो न्यूयार्क से आयी है। यहाँ पर एक शोध योजना की रफ्तार छपी है जिस में बताया गया है कि पूनम की रात में लूटपाट, चोरी और संधमारी की घटनाएँ शतप्रतिशत वृद्धि पायी गयी। बलात्कार और हत्याओं के आँकड़े भी इसी खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। एक भयंकर अपराधी हुषा है डेविड बकोविज उर्फ 'सन ऑफ साम' उस ने आठ हत्याएँ की थीं, जिन में से पाँच के लिए उस ने चांदनी रात ही चुनी।

अब आप कुछ कुछ समझ गये होंगे कि आखिर सारा हिंदुस्तान छोड़ कर बिहार के ही डाक्टरों को यह क्यों सूझा कि चांदनी और जहर की जड़ चांदनी ही है; वहाँ की सरकार को तो ये अखबार वाले नाहक बदनाम करते हैं। फिजल ही शोर मचाया जा रहा है कि बिहार में बेहद गरीब को बेहद अमीर सता रहा है जो जहर खा सकता है, वह मला किस से गरीब हुआ। जहर कोई भी हो। रोटी से तो महंगा ही होगा। जो भी हो, डा. सी. पी. ठाकुर को बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्हें इस वर्ष 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है।



गोष्ठी

## ‘सर्वहारा अधिनायकवाद की जगह सर्वहारा जन-तंत्र’

मार्क्सवाद पर डॉ. रामविलास शर्मा



देते हुए कहा कि क्रांति जब भी होगी और सर्वहारा राज्य बनेगा तो सत्ता में और क्रांति में किसानों की हिस्सेदारी अवश्य होगी. आप किसानों की उपेक्षा क्यों करते हैं जब कि रूस में

किसानों की सोवियतों के कारण ही सर्वहारा क्रांति सफल हुई. लेनिन ने क्रांति के दिनों में और बाद में किसानों और सर्वहारा के संयुक्त मोर्चे पर जोर दिया, बुखारिन और त्रात्स्की से अहसमति व्यक्त की तथा सत्ता में सर्वहारा अधिनायकवाद जैसी चीज को मानने से इनकार किया.

लेनिन ने सर्वहारा जनतंत्र को विस्तृत करने पर जोर दिया. डा. शर्मा ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आप लोगों को सर्वहारा अधिनायकवाद, शब्द से इतना प्रेम क्यों है. इस संदर्भ में उन्होंने सी. पी. आई, सी. पी. एम. की रणनीति की आलोचना की और सुझाया कि सर्वहारा क्रांति में किसानों की हिस्सेदारी और मोर्चे को स्वीकार करना चाहिए. और किसानों को समझा-बुझा कर अपने साथ लाना चाहिए. कम्युनिस्ट पार्टियों को किसानों से भी सीखना चाहिए. 1857 के गदर से सीखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जैसी सांप्रदायिक समस्या को किस तरह हल किया गया था. कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवाद पढ़ने के बावजूद 1946-47 में सांप्रदायिक समस्या को क्यों नहीं हल किया?

प्रगतिशील लेखकों पर उठे प्रश्न पर परिहास करते हुए डा. शर्मा ने टिप्पणी की कि पहले प्रगतिशील लेखक मेरी जेब में रहते थे अब डॉ. नामवर सिंह की जेब में हैं.

फासिज्म पर किये गये सवाल के बारे में डा. शर्मा ने कहा कि फासिज्म का आधार पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद ने आतंकवाद, नस्लवाद, अंध राष्ट्रवाद और युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा की हैं. पूंजीवाद के साथ साथ अमेरिका में नस्लवाद समाप्त नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया.

राष्ट्रवाद का आधार भी ‘मोनो-पोली कैपिटलिज्म’ है. जैसा कि जर्मनी में और भारत में. पूंजीवाद जहाँ भी विकसित हुआ वहाँ सामंती अवशेषों को बरकरार रखते हुए. इसलिए भारत में सामंतवाद और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए किसानों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाना जरूरी है. मार्क्स और एंगेल्स ने किसानों की हिस्सेदारी पर बराबर जोर दिया था. बातचीत की समाप्ति तक कुछ लोगों की असहमतियाँ बनी रहीं.

—नगेंद्र सिंह

साहित्य

## घोषणापत्र

इब्बार रब्बी ‘एक फुनगी पर बैठ कर दूसरी फुनगी पर’ लिखते हैं और अपने को ‘वक्त से आगे दौड़ते’ पाते हैं. एक फुनगी पर बैठे होने का जो उद्वेलन वह झेलते हैं दूसरी फुनगी पर लिखने का भी वही उद्वेलन उन की कविता में दिखायी देता है—निम्न मध्यवर्गीय जीवन का संघर्षमय पारिवारिक यथार्थ उन की पीठिका है जिस पर वह बैठे हैं जो रचते समय उन के मर्म में हिलती रहती है और सामाजिक राजनैतिक यथार्थ व्यासपीठ है जो लिखते समय उन की कलम को हिलाता रहता है और इन दोनों—भीतर का आहत मर्म और बाहर का वैचारिक यथार्थ—के साथ एक आकाश भी है, दृष्टि का आकाश—क्रांति का कल्पना लोक. एक हिलती फुनगी और दूसरी हिलती फुनगी के बीच यह स्थिर आकाश उन की रचना भूमि है जहाँ वह सीधे, सच्चे मन से खड़े हैं. यह बात केवल उन के संग्रह की प्रारंभिक कविताओं के आधार पर कही जा रही है—वाद की पिछली कविताओं के आधार पर उतनी नहीं—जहाँ वह कोई एक चीज उठा लेते हैं; मेज़, घड़ी, घर, झुग्गी और वे तीनों लोक नापने की कोशिश करते दीखते हैं. एक ओर माँ, बहन, पिता, माई, पत्नी, बच्चे तो दूसरी ओर शोषण और अन्याय तथा तीसरी ओर एक व्यापक मुक्ति और क्रांति का सपना. कठिन जमीन इस तरह इब्बार रब्बी ने चुनी है और उसे जोड़ रखा है अपनी रचनाधर्मिता से. तीनों को एक साथ साध पाना कठिन है. कहीं एक साफ दीखता है तो दूसरा हिल जाता है कहीं दूसरा साफ दीखता है तो एक हिल जाता और तीसरा जबर्दस्ती टाँका हुआ लगता है. लेकिन यह रचना संघर्ष है. कवि को करना ही है और ऐसा नहीं है कि यह वह कर नहीं सकता क्योंकि पिछली कविताएँ जो इस संग्रह में हैं उन से आज तक की यात्रा यह आश्वस्त भी करती है. इब्बार रब्बी चाहें तो जिस फुनगी पर बैठे हैं उसी फुनगी पर लिखें. अभी अपने को फैलाएँ नहीं, ‘दौड़े’ नहीं, क्यों कि कविता पारिवारिक यथार्थ से टकराते मर्म से भी लिखे जाने पर बड़ी हो सकती है और भावक को दूसरी फुनगी और आकाश का अहसास करा सकती है—‘घर’ जैसी उन की कविता इस का उदाहरण है. अभी तो उन का कैमरा हिल जाता है. पहचान में सब आते हैं लेकिन जान नहीं पड़ पाती. ‘घोषणापत्र’ की इबारत शुरू से आखिर तक साफ पढ़ नहीं मिलती. इतना तो पता चल जाता है कि कुछ दर्द है, कुछ आग है, कुछ आह्वान है: इतने के लिए यह संग्रह पढ़ा जा सकता है.—स.द.स.

घोषणापत्र : इब्बार रब्बी, असय प्रकाशन 7/7 दरियागंज, नयी दिल्ली-2. मूल्य तीस रु.





चार मायुर और सिंहजीत सिंह

## कल्पनाशील मणिपुरी नृत्यनाटिका

राजधानी में अक्सर नृत्य नाट्य होते रहते हैं लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नृत्यनाटिका अपने विशुद्ध नृत्यरूप, उद्दीप्त संगीत, सादे सार्थक परिधान, बिना खर्चीले तामशाम के कल्पनाशील दृश्यबंधों, अतिरंजना रहित न्यूनतम संकेतों-मुद्राओं से संपन्न कुशल अभिनय और साफ सुथरे निर्देशन के साथ सारगर्भित रस प्रवाह में आप को समाहित कर ले. 6 मई को श्रीरामकला संस्कृति केंद्र में त्रिवेणी कला संगम द्वारा प्रस्तुत कच देवयानी नृत्य नाटिका ऐसी ही थी. इस का निर्देशन किया था गुरु सिंहजीत ने. कहा जा सकता है कि यह मणिपुरी नृत्य नाटिका पिछले कई वर्षों में दिल्ली के मंच पर प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ नृत्य नाटिकाओं में है. किसी निर्देशक की कल्पनाशीलता का मुग्धकारी नमूना इसे कहा जा सकता है.

कच देवयानी की पौराणिक कथा शायद शत्रु पक्ष में जा कर जासूसी की पहली कथा है. देव और असुर संग्राम में देवता निरंतर हार रहे थे क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी का रहस्य जान लिया था जिस से वह मारे गये असुरों को जिला देते थे. देवताओं ने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को उस संजीवनी विद्या का रहस्य जानने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा. शत्रु शिविर में आ कर कच शुक्राचार्य के शिष्य बनने में समर्थ हो गये. असुर कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कच की प्रगाढ़ मैत्री हो गयी थी. असुरों ने आश्रम से बाहर मौका पा कर कच को मार डाला और उस का शरीर नष्ट कर दिया. देवयानी के शोक से द्रवित हो कर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से कच की हत्या को जान

लिया और संजीवनी विद्या से उसे जिला लिया. असुरों ने फिर कच की हत्या कर दी और उस की मृत देह को शुक्राचार्य के पेट में छिपा दिया — कच को मारे कर, जला कर उस की राख शराब में मिला कर उन्होंने शुक्राचार्य को पिला दिया. अब कच के पुनर्जीवन का अर्थ शुक्राचार्य की मृत्यु हो गया. एक ही चारा रह गया कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या पेट में ही कच को सिखा दें. जिस से कि कच बाहर आ कर फिर उन्हें जीवित कर सके. ऐसा ही हुआ. अति प्रसन्न, कच के प्रेम में डूबी देवयानी ने कच से उस की पत्नी हो कर उस के साथ चलने का प्रस्ताव किया. लेकिन कच ने यह कह कर इनकार कर दिया कि उस के पिता के पेट से जन्म लेने के कारण यह भाई बहन का रिश्ता हो गया. देवयानी ने दुखी हो कर उसे शाप दिया कि वह इस विद्या का इस्तेमाल अपने हाथों से नहीं कर सकेंगे. लेकिन कच यह विद्या दूसरों को सिखा तो सकता था. कच असुरलोक से देवलोक चला गया. इस तरह जासूस की नैतिकता का पहला पौराणिक प्रमाण बना.

कथा बताने का अर्थ यह है कि दृश्य रूप में इतनी जटिल और वैविध्य-हीन कथा पर जीवंत नृत्य नाटिका तैयार कर ले जाना कठिन काम था. दो बार वही हत्या प्रसंग, दो बार वही मृत को जीवित करना उबाऊ हो सकता था और कथा प्रस्तुति की गति घिसट सकती थी पर सिंहजीत जी ने अपनी अद्वितीय कल्पनाशीलता द्वारा विविध रंगपट्टियों, ढालों, वृक्षों, नृत्य गतियों तथा संगीत के द्वारा विविधता बनाये रखा और कहीं भी नाटिका की गति को शिथिल नहीं होने दिया, उसे दोहराव के दोष से मुक्त रखा. मणिपुरी नृत्य रूप इतना समर्थ है इस का अनुमान यह नृत्य नाटिका देख कर ही हो सकता है—वीर, कर्ण, शृंगार सभी रस, विशद गतियों और संगीत से पूर्ण अभिव्यक्ति पाते हैं. युद्ध दृश्यों में भाले, तलवार, ढाल के साथ विविध नृत्य गतियाँ, कलावाजियाँ, वीर भाव को जिस तरह उभारती हैं वह किसी और शास्त्रीय नृत्य रूप में संभव नहीं! फिर अभिनय के अतिरेक की इस में गुंजाइश नहीं. संक्षिप्त संतुलित गतियों और मुद्राओं में ही हर भाव निष्पन्न करना होता है. देवयानी के रूप में इस दृष्टि से चार मायुर को देखना उन के प्रति सराहना के भाव से भरना ही है. चार अपने सौंदर्य और अपनी नृत्य की तराशी गतियों से मंच पर आकर्षण का बिंदु बनी रहती हैं. शुक्राचार्य का नृत्याभिनय भी प्रभावपूर्ण और सराहनीय था. युद्धों के दृश्य में सहयोगी सैनिक चरित्र जीवंत और आकर्षक थे. उन के गति नियोजन, समूहन, विभिन्न रूपाकारों का संपुजन, सुखद चाक्षुष विषों में परिवर्तित हो कर नाटिका को गरिमामय बनाता था. इस सुंदर

श्रेष्ठ नृत्य नाटिका के लिए सिंहजीत को पात्र हैं. इस की और प्रस्तुतियों की जरूरत चाहिए. यह नृत्यनाटिका नृत्यनाटकों की वर्तमान दुनिया को एक नया और सुंदर आयाम देती है.

## पुस्तकें

“शेष” निष्पक्ष विचारधारा की कथा त्रैमासिक यदि आप सृजनशील रचनाकार हैं? प्रश्न पाठक हैं? तो “शेष” को आपका सहयोगी दरकरार है. संपर्क: संपादक, शेष, पन्ना निवास, लोहारपुरा, जोधपुर (राज.). वार्षिक शुल्क 15 रुपये. एक प्रति 3 रुपये.

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें. अपने विषय की विवरणी मंगाई. कहानी-लेखन महाविद्यालय, राज. (द) अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें. विवरणी मंगाई. लिखें. इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), पॉस्ट बॉक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. विवरणी मंगाईये. पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

### रिक्त स्थान

आकाशवाणी, रंगमंच, सांस्कृतिक के पाक्षिक को संपूर्ण भारत वर्ष में अवैतनिक संवाददाता चाहिए. आवेदन पत्र हेतु लिखें. अंतर्राष्ट्रीय श्रोता समाचार, 27 जवाहर स्ववायर, इलाहाबाद.

### एजेंट चाहिए

फिल्म, साहित्य व संगीत के हिन्दी मासिक राग बहार को मंगाने हेतु न्यूजपेपर एजेंटों से संपर्क करें. व्यवस्थापक, राग बहार, छोटा छीपीवाड़ा, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110024.



निधन

# रमई काका की 'अरधान'

केशवचंद्र वर्मा

रमई काका का पूरा नाम पं. चंद्र भूषण त्रिवेदी- (67) उन विरले व्यक्तियों में एक हैं जिन्होंने अपने जीवनकाल में आकाशवाणी और अपने रुढ़पात्रगत उपनाम रमई काका को एक दूसरे का पर्याय बना दिया था। लाखों की संख्या में नित्य प्रति तब उत्तरप्रदेश के एक मात्र आल इंडिया रेडियो केंद्र लखनऊ में ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुनने वाले रमई काका को ही वह अचल धुरी मानते थे जिस पर अनेकानेक विविधवर्णी कार्यक्रम घूमते रहते थे, चाहे वह सामान्य ढंग पंचायत घर का कार्यक्रम से संचालन हो, चाहे कविता पाठ हो, चाहे बहरेबाबा नाटक हो, चाहे संगीत के अन्यान्य प्रोग्राम हों, —वे अपने रमई काका को उस मीड में अलग पहचान देते थे रेडियो में फिल्मी दुनिया के विपरीत-लोकप्रिय चरित्र या व्यक्तित्व निर्माण की अपरा कमी थी ही नहीं बल्कि ऐसे वनते व्यक्तित्वों के 'खतरों' से आगाह विदेशी हुकूमत उन्हें उस प्रोग्राम से ही अलग कर देती थी। उस जमाने में उस परंपरा को चुनौती देते हुए 'रमई काका' ने अपने उस लोकप्रिय रूप की जय पताका गाड़ दी। उन का निधन 18 अप्रैल 1982) गोस्वामी तुलसीदास के उन वारिसों का क्षरण है जिन्होंने अवधी भाषा के लालित्य, समृद्धि व्यंजना और रसमय प्रवाह की अनूठी वानगी की हिंदी क्षेत्र की भाषाओं को तोड़ कर पूरे देश में मान्यता प्रदान कर दी थी—इनमें थे स्व. पं. बलमंदर प्रसाद पंडित, स्व. पं. वंशीधर शुक्ल और स्व. पं. चंद्रभूषण त्रिवेदी—'रमई काका'।

'रमई काका' को रेडियो स्टेशन में काम करने वाले और बाहर से आने वाले कलाकार को 'काका' कह कर प्यार से बुलाते थे। अपने सहज प्रीति व्यवहार में उस सम्मान और आदर से परिचय पहली बार आकाशवाणी लखनऊ केंद्र पर 1944 में हुआ कालांतर में ही आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र के प्रसारण घर में नौकरी कर ली। तब लखनऊ के कार्यक्रम मिले जुले होते थे। उस दौरान 'काका' से बहुत निकट का रिश्ता हुआ। वे सचमुच बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कुछ ही घंटों में नया नाटक लिख कर प्रसारण कर देना, स्वयं उसे निर्देशित कर के प्रसारण से लहालोट कर देना उन की अद्भुत क्षमता थी। फरमाइशी विषयों से लेकर सामान्य जीवन की क्षमता दर्शाने वाली कवि-

ताओं को तो वे आश्चर्य चकित करने वाली अवधि में लिख डालते थे। वह रेडियो में कई तरह के कार्यक्रमों में जान डाला करते थे। बाद में वह दूरदर्शन से भी लोकप्रिय चरित्र के रूप में जनमानस के और निकट आये। कम लोगों को यह पता होगा कि पं. चंद्र भूषण त्रिवेदी मूलतः गायक थे और ध्रुपद धमार की स्वयं रचना करके गाया करते थे।

'रमई काका' उत्तरी भारत के अनेक कवि सम्मेलनों में आदर के साथ बुलाये जाते रहे। दक्षिण भारत में भी उन्होंने अवधी कविता का जादू सिद्ध कर के दिखाया। रेडियो पर ही नहीं अपितु जन परिपदों और सामान्य सामाजिक संस्थाओं के कवि सम्मेलनों में वे पहुँचे।



रमई काका

रमई काका के पास ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली अवधी (विशेषतः बैसवारी) की अपार शब्द संपदा थी जिस का वह बेखटके उपयोग अपनी रचनाओं में करते थे। ग्रामीण शब्दों की एक विशेष व्यंजना को 'रमई काका' अक्सर साहित्यिक-गारिभा दे पाने में सक्षम थे। ध्वनि विशेष के आधार पर बने हुए ग्रामीण शब्द रमई काका की रचनाओं में एक ऐसा ताजापन देते हैं जो आज की कविता में दुर्लभ है। उदाहरण के लिए, चुर-मुर चुरमुर, 'उमकारना', 'चुमकना' या घर की सुंदरता को 'घर दहर दहर होई रहा' कहना—या इसी प्रकार 'महर महर लहलही, डहडही, गच्चापिच, अहलक' आदि तमाम ऐसे शब्द हैं जो कविता की बुनावट में आकर नयी छवि देते हैं। अत्यधिक सुगंधि को 'अरधान' कहने में जो व्यक्त हुआ है वह अभिव्यक्ति को कितनी ताजगी और गहराई देता है। 'करौदन गमकि उठी अरधान!' रमई काका सामान्य किसान की विपत्तियों को कविता के क्षेत्र में पड़ी सफलता से लाते हैं। वह चाहे 'कंचेहरी' की मुकदमेबाजी हो,

चाहे नौकरी का चक्कर, हो, चाहे 'तलब' की मुसीबत हो। अन्योक्ति के सहारे विदेशी हुकूमत के जुलम और गांधी के आंदोलन के प्रति निष्ठा रमई काका की कितनी ही रचनाओं में व्यक्त है। 'पिजरा मा सोचि रहा पंछी पूरी अब कब धौ साधि मोरि'—उन की एक अत्यंत प्राणवान रचना हुई है। रमई काका ने हास्य और व्यंग्य को आधार बना कर भी बहुत सी कविताएँ लिखी हैं उन्होंने कई रचनाएँ खड़ी बोली में भी की हैं। काका के लिखे हुए और उन्हीं की मुख्य भूमिका में खेले हुए बहरे बाबा का धारावाहिक हास्य नाटक जितना रेडियो पर लोकप्रिय हुआ उतना ही मंच पर भी सफलता के साथ खेला गया। 'हम कहा हमें घोखा है गा' उनकी हर जवान चढ़ी कविता थी। रमई काका ने अपनी कविताओं को मुना मुना कर उन्हें लोकप्रिय किया और अपनी ही रचनाओं को छाप कर (ग्राम साहित्य मंदिर, मन्वदल गंज, लखनऊ) उन्हें फुटपाथों पर अत्यंत सस्ते दामों पर बेचा। काका बताते थे कि उन्हें इस रोजगार में कमी घाटा नहीं हुआ। उन की किताबें प्रकाशकों की 'मेहरबानी' से केवल 'सरकारी खरीद' के 'अनुग्रह' पर निर्भर रह कर सिर्फ पुस्तकालयों में बंद नहीं पड़ी रह गयी। वे किताबें पढ़ी गयीं, याद की गयीं और रचनाएँ सम्मानित हुईं। रमई काका की रचनाओं में बौद्धार (प्रथम काव्य संग्रह), भिनसार, फुहारा, हरबाती तरवार आदि प्रमुख हैं। उन के नाटक संग्रह भी प्रकाशित हैं। उन की सशक्त रचना धरती हमारि के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं।

धरती हमारि-धरती हमारि!

हैं चरती परती गउवन कै-औ ह्यातन कै धरती हमारि

धरती हमारि धरती हमारि!

हम अपनी छाती के बल तें धरती मा फार चलाइत है

माटी के नान्हे कनकन मा हमहीं सोना उपजाइत है

अपने लोनखरे पसीना ते रेतो मा ह्यात बनावा हम

मुरदा माटी जिदा होइगे जहँ लोहखर अपन छुवावा है

ऊंकरील उसर बीजर परती धरती मुड़गारि नीवर जरजरि

बसि हमरे पौरख के बल तें, होइगे हरयारि दनगरि बलगरि

हम तरक सहित स्यावा सिरजा, सो धरती है हमका पियारि

धरती हमारि धरती हमारि! □



**पिछले दिनों 7 युवा कलाकारों—जोगेन चौधरी, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख, विवान सुंदरम, मनु पारेख, सुधीर पटवर्धन डी. एल. एन. रेड्डी—के चित्रों की एक समूह प्रदर्शनी रवींद्र भवन दीर्घाओं में आयोजित हुई। यही प्रदर्शनी इन गमियों में हांबुर्ग (पश्चिम जर्मनी) में भी दिखायी जायेगी। इन में से तीन कलाकारों, मनु पारेख, नलिनी मलानी और डी. एल. एन. रेड्डी को छोड़ कर शेष कलाकारों का काम कुछ अरसा पहले ग्लेस फार पीगुल (लोगों की जगह) नाम की प्रदर्शनी में रवींद्र भवन दीर्घाओं में ही दिखाया गया था। लेकिन इस प्रदर्शनी में उन कलाकारों का भी नया काम है और इस में कुछ कलाकारों के रेखांकन भी शामिल हैं। इन कलाकारों में जो एक समानता दिखायी पड़ती है वह यही कि ये सभी आकृतिमूलक कलाकार हैं। और अगर उन की विषय वस्तुओं पर गौर करें तो कहीं यह भी दिख पड़ता है कि वे सामाजिक यथार्थ के आग्रह को ले कर भी काम करने वाले कलाकार हैं। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं कि चित्रकला के प्रति वह कोई समान 'कार्यक्रम' सामने रख कर काम करने वाले कलाकार हैं। जहाँ तक चित्ररूपों का सवाल है उनमें एक वैमिष्य भी है। और वे आकृति को किसी एक ही शैली में नहीं बरतते। हाँ, यह जरूर है कि कुछ कलाकारों के काम में एक दूसरे के काम के कुछ तत्व भी कहीं झलक जाते हैं। और एक प्रकट यथार्थवादी आग्रह भी उन में है ही।**

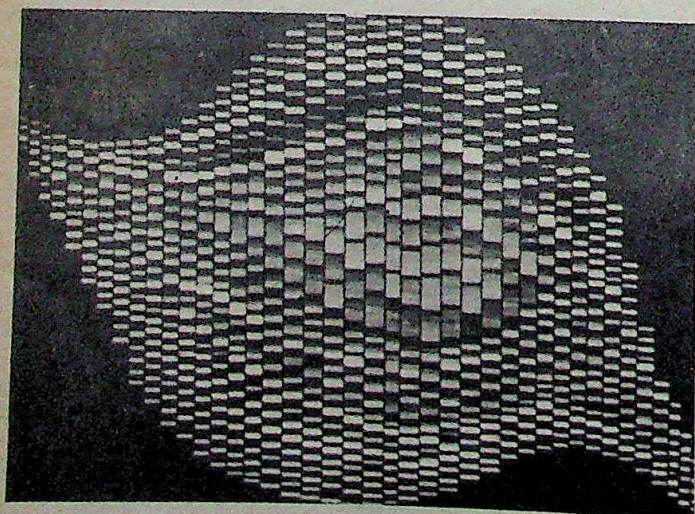
यथार्थवादी अंकन वाले चित्रों का जहाँ तक सवाल है यह बात कही जाती है कि आज की कई समयगत सच्चाइयाँ आकृतिमूलक काम के

## आकृति क्या कह रही है?

जरिये ही कही या बतायी जा सकती हैं। इस से एक जगह पर विरोध नहीं भी हो सकता। हालाँकि यह भी उतना ही सही है कि कला में आकृति-मूलकता बनाम अमूर्तता की वहस अब कुछ मोली हो लगती है। क्योंकि कला के भिन्न आकारों को जाँचने के मापदंड अलग-अलग नहीं होते। जरूरी नहीं कि आकृति हमसे कुछ अधिक कहती हो और अन्य आकार कुछ कम। और इस से भी आगे यह कि आकृति और अन्य आकारों का रखरखाव ही कला में अपने आप में कभी अंतिम नहीं होता। क्योंकि वहाँ रंगरूप भी एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। और फिर यह सवाल तो बचा ही रहता है कि आकृति या अन्य



(ऊपर) नलिनी मलानी का रेखाचित्र (नीचे—बाएँ) डॉन क्रीगर का एक्रिलिक चित्र (बीच में) जोगेन चौधरी की चित्रकृति (दायें) सुधीर पटवर्धन का एक तैलरंगी चित्र

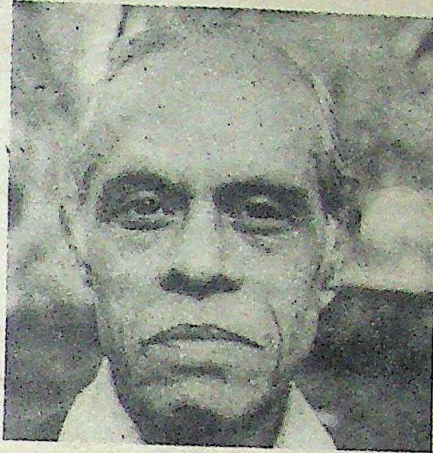


आकारों को ले कर दरअसल किसी कलाकृति में किया क्या जा रहा है?

बहरहाल चूँकि यहाँ आकृतिरूप प्रमुख हैं इसलिए यह जाँचने की एक वाध्यता हो लगती है कि इन कृतियों में आकृति दरअसल किस हद तक टिकाऊ हैं। टिकाऊ हमारा तात्पर्य यही है कि क्या वे एक बार देख लिये जाने पर हमारे लिए निःशेष हो जाते हैं या कि उन के वहाने अर्थों की एक निरंतरता बनी रहती है। इस सिलसिले में जोगेन चौधरी और सुधीर पटवर्धन ही इस प्रदर्शनी में एक अपवाद लगते हैं जिन के काम में हम देखें हैं कि आकृति रूपों की आकार रेखाएँ केवल शरीरगत स्थितियाँ ही हम तक न पहुँच कर अन्य कई मानवीय मर्मों को भी रेखांकित करती हैं। नीलिमा शेख के काम में भी हम देखते हैं कि आकृति रूपों के बीच कहीं एक ऐंद्रिक रंग व्याप्ति है जो अपने मर्मों के साथ टिकती है। अन्य कलाकारों के बारे में हम उसी यही बात नहीं कह सकते। उन के चित्रों में यथार्थवादी ढंग से कुछ चित्रित हुआ जस देखते हैं। लेकिन यह चित्रण जैसे गहरे पल नहीं। विवान सुंदरम के काम उन के पिछले वर्षों के काम की तुलना में निश्चय ही अधिक संवेदनशील हुए हैं। लेकिन तब उनके बिल्कुल हाल के काम को देख कर कहीं यह भी लगता है कि वह अपने बनाये रास्ते को कुछ ज्यादा आसान किये दे रहे हैं। मनु पारेख की रेखांकन क्षमता तो दीख पड़ती है लेकिन यहाँ भी हम केवल रेखाओं की एक ऊर्जा थोड़ा सा चमत्कृत हो कर रह जाते हैं। नलिनी मलानी के रेखा और रंग कुछ निश्चित सीमा से घिरे मालूम देते हैं। डी. एल. एन. रेड्डी



## कला जगत ही उनका परिवार था



एस. ए. कृष्णन (1926-1982)

नयी दिल्ली में 2 मई की सुबह सुप्रसिद्ध कला समीक्षक एस. ए. कृष्णन का देहांत हो गया। वह 56 वर्ष के थे। एक स्कूटर दुर्घटना में कृष्णन के निधन से कला जगत को गहरा धक्का लगा है। 3 मई की दोपहर को ललित कला अकादमी में उन को शोक सभा में और 3 मई को ही शाम 4 बजे विद्युत शवदाह गृह में उनको अंत्येष्टि के समय, दिल्ली के कलाकार, लेखक, पत्रकार, कला प्रेमी, राजदूतावासों के प्रतिनिधि एक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शोक सभा में ललित कला अकादमी के म. पू. अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा और सचिव रिचर्ड बार्थोलोम्यु ने भरी हुई, शोकाकुल आवाज में कृष्णन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और दो मिनट के मौन ने कृष्णन के न रहने को और गहरा किया।

एक मई की रात कोई साढ़े 10 बजे जब कृष्णन एक विवाह में शरीक हो कर स्कूटर पर लौट रहे थे तो नयी दिल्ली के करोलबाग इलाके में रास्ते में अचानक सड़क पर आ गयी एक गाय से होने वाली टक्कर को बचाने में उन का संतुलन बिगड़ गया और वह स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गये। दोपहिया स्कूटर में उन के पीछे ललित कला अकादमी के सचिव रिचर्ड बार्थोलोम्यु भी बैठे हुए थे, वह भी गिर पड़े। किंतु उन्हें मामूली चोट आयी। उन्होंने कुछ अन्य व्यक्तियों की मदद से कृष्णन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन कृष्णन को बचाया नहीं जा सका। और 2 मई की सुबह लगभग 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कृष्णन का निधन दुःख और आकस्मिक तो है ही, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और वह एक सावधान चालक थे—वह कई वर्षों से दोपहिया स्कूटर की सवारी कर रहे थे।

1926 में मैसूर में जन्मे कृष्णन 1954

के सितंबर महीने में ललित कला अकादमी से संबद्ध हुए थे और कई वर्षों तक सहायक संपादक के पद पर काम करने के बाद वह पिछले कुछ वर्षों से ललित कला अकादमी के संपादक थे। ललित कला के अंग्रेजी कला पत्र 'ललित कला कंटेपरेरी' का संपादन तो उन्होंने किया ही, एक असें से वह ललित कला अकादमी के प्रकाशनों से जुड़े रहे थे और कलाकारों पर पुस्तक-पुस्तिकाओं से लेकर प्रतिकृतियों के प्रकाशन आदि का काम देखते रहे थे। विगत दो दशकों में ललित कला अकादमी के प्रायः सभी प्रकाशन उन की ही देखरेख में प्रकाशित हुए थे, जिनमें से कुछ उन्होंने लिखे भी थे। इस के अतिरिक्त वह दिल्ली के अंग्रेजी दैनिक 'स्टेट्समैन' के पिछले 20 वर्षों से कला समीक्षक भी थे। और नियमित रूप से दिल्ली में होने वाली प्रदर्शनियों की समीक्षा लिखा करते थे। यह कार्य उन्होंने स्टेट्समैन के लिए सुप्रसिद्ध कला समीक्षक चार्ल्स फाबरी के निधन के बाद संभाला था। कृष्णन दिल्ली में, और अन्य प्रदेशों में आयोजित होने वाली कई समूह प्रदर्शनियों के निर्णायक मंडल में रहे थे और विदेशों में भी कई बार प्रदर्शनियों के निर्णायक के बतौर गये थे। वह 1975 में तोक्यो में आयोजित दसवीं छपा (ग्राफिक्स) द्विवाषिकी के अंतरराष्ट्रीय निर्णायक मंडल में रहे और 1980 में तीसरी दुनिया कला द्विवाषिकी लंदन/बगदाद के निर्णायक मंडल के सदस्य थे। एक बहुत लंबे अरसे से समकालीन भारतीय कला जगत से निकट से जुड़े रहने के कारण कृष्णन देश के विभिन्न भागों के कलाकारों को व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे। और कई उनके निकट मित्रों में भी थे। और कह सकते हैं कि कला जगत ही उन का परिवार था। लगभग 10 वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तब से वह अकेले ही रहते थे। उन की कोई संतान नहीं थी।

श्री कृष्णन चित्र-रचना भी करते रहे हैं। 1947 में उन्होंने लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। अनंतर बंबई चले गये जहाँ 'प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप' के कलाकारों से भी जुड़े। 1951 में दिल्ली चले आये। कुछ अरसे तक टाइम्स आफ इंडिया के कला-नृत्य समीक्षक भी रहे। उन्होंने देश विदेश में समकालीन भारतीय कला पर कई व्याख्यान भी दिये। जिनमें प्रमुख है 1972 में नौ महीनों के लिए इसी उद्देश्य से की गयी उनकी यूरोप यात्रा।

कृष्णन के निधन से राजधानी के कलाजगत को तो आघात लगा ही है, देश के अन्य कलाकेंद्रों में भी उन के अभाव को महसूस किया जायेगा। □

की विशालकाय, एक लंबान में तनी आकृतियाँ जैसे अभी पूरा रचाव प्राप्त नहीं कर सकी। उनकी इस चित्रभाषा में संभावनाएँ जरूर दीख पड़ती हैं। अभी कह दो स्थितियों के एक तरल विरोधाभास से जो टिप्पणियाँ करते हैं वे हमें कुल बात की तह तक नहीं ले जाती।

इनमें से कुछ कलाकारों पर कुछ सुप्रसिद्ध पश्चिमी कलाकारों के काम की छाप का उल्लेख हम करेंगे। यह बताना तो कुछ व्यर्थ ही लगता है कि वे पश्चिमी कलाकार कौन से हैं। छाप का उल्लेख हम केवल यही बताने के लिए कर रहे हैं कि कला में पड़ने वाले कई बार अनिवार्य प्रभावों को भी यहाँ अपनी रचनात्मक शक्तों के लिए अच्छी तरह सुलझाया नहीं गया। एक कलाकार ने टिप्पणी की कि इन में से कुछ कलाकारों के ये काम देख कर कई बार यह भी लगता है कि कलाविद्यालयों के अंतिम वर्षों के छात्रों से ये काम थोड़ा बेहतर भर हैं। यह टिप्पणी कुछ अतिरंजित हो सकती है और उसे किन्हीं कलाकारों के काम पर लागू करना कुछ ज्यादाती भी। लेकिन इस टिप्पणी में, अपेक्षाएँ पूरी न होने से जो खीझ छिपी है, वह जरूर गौर तलब है। इन में लगभग सभी कलाकारों को कलाजगत में गंभीरतापूर्वक ही लिया जाता है। इसलिए इतना अफसोस तो स्वाभाविक ही है कि वे इन कामों में अपने भाग्यों के कहीं बंदी ही अधिक लगते हैं।

अमेरिकी कलाकार डोनाल्ड क्रौगर के चित्रों की प्रदर्शनी श्रीधरणी गैलरी में हुई। क्रौगर लक्की के पटों को छील और तराश कर कुछ रूपभ्रम बनाते हैं फिर उन्हें एक्रिलिक रंगों से रंग देते हैं। पहली नजर में उन का काम आप कला का एक हिस्सा लगता है। पर असल है नहीं। क्योंकि आप कला की तरह वे किन्हीं वाक्षुष भ्रमों की रचना नहीं करते। रंग-रंग एक रंगशीलता की ओर इशारा करते हैं। क्रौगर के रंग बहुधा चटक हैं लेकिन अपने अंतिम प्रभाव में वे किसी चकाचौंध की रचना न कर के एक शांत वातावरण ही बनाते हैं (जो भीतर से कहीं अशांत भी लगता है)। क्रौगर भारत में अपने देश के एक सांस्कृतिक अधिकारी हैं। और यों तो उन्होंने कला की विविध शिक्षा भी ग्रहण की है लेकिन कह सकते हैं कि आज कल वह केवल शौकिया काम करते हैं।

उन्हीं के अनुसार 'अब अधिक काम करने का अवकाश ही नहीं मिलता।' कुछ वर्ष पहले क्रौगर अफ्रीका के एक छोटे से देश बेनिन में रहे थे। और यह मानने के कारण हैं कि उनकी कला के पटों के प्रति उन का रुझान अफ्रीका का ही होगा। उन की कला किसी बड़े दावे से रहित कला है और अपनी सादगी में वह एक रंग संवेदनशीलता को तो रेखांकित करती ही





'उंबरठा' में स्मिता पाटिल तथा गिरिश कर्नाड

## सुबह हो चुकी है

जब्बार पटेल की मराठी फिल्म उंबरठा की संक्षिप्त चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं। इस फिल्म को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार मिला है। मराठी में 'उंबरठा' का अर्थ होता है देहलीज। लेकिन यह फिल्म हिंदी में सुबह नाम से प्रदर्शित की जायेगी। जब्बार पटेल पेशे से एक डॉक्टर हैं और मुख्य क्षेत्र उन का रंगमंच रहा है। 'घासीराम कोतवाल' के कारण रंगमंच के क्षेत्र में उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिल चुकी है। लेकिन कुछ वर्षों से वह सिनेमा भी बना रहे हैं। पहली कथा फिल्म 'सामना' थी और 1979 में 'सिंहासन' से उन्होंने एक अलग तरह का राजनीतिक सिनेमा बनाया।

'उंबरठा' की पटकथा प्रसिद्ध नाटककार और सिने लेखक विजय तेंडुलकर ने लिखी है। यह फिल्म एक स्त्री के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है और अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने सुलमा के रूप में प्रभावशाली अभिनय किया है।

'उंबरठा' की मुख्य विशेषता यही है कि उस में स्त्रियों के जीवन की समस्याओं को बहुत बारीकी और संवेदनशीलता के साथ देखा गया है। भारतीय सिनेमा में आधुनिक स्त्री की समस्याओं को अच्छी समझ के साथ बहुत अधिक नहीं देखा गया है। 'उंबरठा' की नायिका सुलमा अच्छा खासा उच्च मध्यवर्गीय जीवन जी रही है। घर में सुख सुविधाएँ हैं, पति वकील है और जेठ एक डॉक्टर है। सास भी पढ़ी लिखी है और समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है। स.स. ने सुलमा की 'प्रतिभा को पहचान कर' उसे टाटा समाज विज्ञान संस्थान से समाज कार्य में एक वर्ष का 'कोर्स' भी करवाया है।

फिल्म के शुरू के 15-20 मिनट सुलमा के घर के हैं। दरअसल फिल्म शुरू तो तब होती है जब अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ सुलमा बहुत दूर एक छोटी सी जगह के महिला आश्रम की अधीक्षिका का काम सँभाल लेती है। इस नियुक्ति की खबर से घर में हलचल सी मच जाती है। घर के सदस्यों का आधुनिक नजर आने वाला दृष्टिकोण अब अपने असली चेहरे को दिखाना शुरू कर देता है। सास सुलमा के इस फैसले से प्रसन्न नहीं है। वकील पति (गिरिश कर्नाड) भी मुनमुनाता नजर आता है। लेकिन सुलमा अपने आलीशान लगने वाले घर की निरर्थकता को पहचान चुकी है। उस की बच्ची स्कूल जाती है लेकिन उस की जेठानी के यहाँ कोई संतान न होने के कारण उस का पालन पोषण वही लोग कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र पा कर सुलमा अकेले ही एक दूर के छोटे से शहर में पहुँच जाती है।

घर में सुलमा का जीवन कुछ ऐसा था कि कैंसेट पर भीमसेन जोशी के गायन के साथ में हजामत बनाते हुए वकील पति के चाय नाश्ते का प्रबंध कर देना, आदि आदि। टाटा संस्थान में अपनी बहू को प्रशिक्षित कराने के पीछे सास की शायद यही इच्छा थी कि वह बंबई के किसी ऊँचे किस्म के समाज कार्य में अपने को व्यस्त कर ले। लेकिन सुलमा ने अपने फैसले के बाद अपने आप को एक ऐसे महिला आश्रम में पाया जहाँ तरह तरह की अपराधी और समाज द्वारा बहिष्कृत स्त्रियाँ रह रही थीं। कोई पति द्वारा सतायी हुई है, तो कोई वेश्या है और कोई पागल है। जाहिर है कि यह बहुत मुश्किल किस्म की दुनिया है।

सुलमा का व्यक्तित्व ऐसा रोबीला भी नहीं है कि महिला आश्रम के भ्रष्ट और सुस्त कर्मचारी उस से आसानी से डर जायें और फिर

आश्रम में रहने वाली स्त्रियों की तो अनपि स थाएँ हैं। छोटे छोटे समूहों में बैठ कर सुलमा इन औरों की जिदगी को जानने की कोशिश करती है। कोई औरत आश्रम से भाग जाना चाहती है, तो कोई औरत आश्रम ही अपनी जिदगी बिता देना चाहती है कि बाहर उस के साथ अधिक अत्याचार होगा।

आश्रम की भ्रष्ट (और अमागी) जिदगी को पहचानने में सुलमा को देर नहीं लगती साथ ही वह यह भी समझ जाती है कि जिस तरह की अत्याधुनिक और फैशनप्रिय अव्यक्षा के निर्देशों के अनुसार उसे काम करना है उस स्थिति में अपने ढंग से काम करना आसान नहीं होगा। फिर भी वह आश्रम के नियमों को बेहतर बनाने की कोशिश करती है।

सुलमा के लिए यह भी एक कठु अनुभव है कि आश्रम के बोर्ड की बैठकों में अमागी औरतों की समस्याओं को जिस उदासीनता और क्रूरता के साथ निपटाया जाता है उस में अपनी बात को मनवाना भी आसान नहीं है।

सुलमा का वकील पति एक बार आश्रम में उससे मिलने भी आता है लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन सुलमा को एक गर्भवती स्त्री की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अपने पति से वह अच्छी तरह से मिल नहीं पाती।

आश्रम के जीवन में अचानक एक दुर्घटना हो जाती है। दो औरतें आश्रम से भाग जाती हैं और फिर उन्हें पकड़ कर आश्रम जेलनुमा कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ये औरतें अपने कपड़ों पर आग लगा कर आत्महत्या कर लेती हैं। इस दुर्घटना की खबर सुलमा को दोपी तो नहीं सिद्ध किया जाता। पता पर अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। सुलमा वापस अपने घर आती है तो उसे यह भी पता चलता है कि पति ने अपनी 'शारीरिक जहर' को ध्यान में रख कर एक दूसरी स्त्री से मित्रता कर ली है। सुलमा अपने घर के वरुण से बहुत कुंठित होती है। उस का यह तो नहीं चाहता कि सुलमा घर छोड़ने पर सुलमा घर छोड़ने का फैसला कर ले है और अंत में हम उसे रेलगाड़ी की डिब्बे के पास बैठे बाहर के भागते हुए दृश्यों को देना हुआ पाते हैं।

जब्बार पटेल के निर्देशन में एक आश्रम सादगी है। छायांकन, पटकथा आदि भी निर्देशन में रंगाया है। 'उंबरठा' के मूड को बनाने में मदद देते हैं। निःसंदेह एक अपने ढंग की अच्छी फिल्म और आधुनिक समाज में औरत को बचाने की जगह दिलाने की कोशिश करती है।





## साहित्य कला परिषद पुरस्कार

दिल्ली की सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण और उत्थान से संबंधित संस्था साहित्य कला परिषद ने मई दिवस पर 1981 के 11 पुरस्कार एक भव्य समारोह में दिये। परिषद अनेक वर्षों से ये पुरस्कार ही नहीं दे रही है, नये पुराने कलाकारों को प्रोत्साहन तथा शिक्षा और विभिन्न जनक्षेत्रों को कला और कलाकारों के अनेक कार्यक्रमों द्वारा परिचित भी करा रही है। पुरस्कार इस प्रकार हैं: सतीश शर्मा (चित्रकला), महेश्वर दयाल (इतिहास), नैमिचंद्र जैन (रंगमंच), रामनाथ शर्मा (संगीत), मोहनलाल (नृत्य), श्रीकांत वर्मा तथा सत्यवती मलिक (हिंदी साहित्य), नरेंद्र पाल सिंह तथा तारा सिंह (उर्दू), उर्दू लेखक राजेंद्र मनचंदा 'बानी' को यह पुरस्कार मरणोपरान्त दिया गया। ये पुरस्कार दिल्ली के उपराज्यपाल सुंदरलाल खुराना ने दिये। प्रशस्ति पाठ परिषद के सचिव दयाल सिंह ने हिंदी में किया। परिषद के अध्यक्ष सुरतदास ने जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, पुरस्कृत कलाकारों और साहित्यकारों को स्वागत किया। श्रीराम संस्कृति कला केंद्र आयोजित इस पुरस्कार समारोह के बाद पाल सानासिंह का नृत्य कार्यक्रम आयोजित है। उस का उद्घाटन भी हुआ।

## जादू जंगल

लासपुर में पिछले दिनों राजेश जोशी लिखित लोक नाटक 'जादू जंगल' का मंचन हुआ। नाटक में राजकमल नायक के नायकत्व में रंगमंच द्वारा प्रगति कला के तत्वा-युक्त प्रगति नगर, कोरवा के सामुदायिक मंच में किया गया। नाटक की कथावस्तु प्रतीकों के माध्यम से आज की व्यवस्था में व्याप्त अंधाधुंध प्रगति को प्रस्तुत करता है जो आज की समाज की शोषण और पुरानी पीढ़ी की

(ऊपर दाएं) श्रीकांत वर्मा खुराना जी से पुरस्कार प्राप्त करते (ऊपर बाएं) जादू जंगल का एक दृशक (बगल में) प्रोधागिरी गोष्ठी में बोलते हुए जनेंद्र जी, उनके बाएं नरेंद्र मोहन दाएं देवेन्द्र इस्सर

हताशा का कारण है। लेखक ने इस से बचने की एक मात्र संभावना सामूहिक जागरण और क्रांति में बतलाई है।

नाटक में सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया। विशेषतः अम्मा की भूमिका में श्रीमती कुमुद चौधरी, किस्सा पटेल की भूमिका में रविंद्र चौधरी और नागन की भूमिका में श्रीमती आशा वरठे का अभिनय अविस्मरणीय रहा। मंच सज्जा सादी और ग्रामीण परिवेश को उभारने वाली थी।

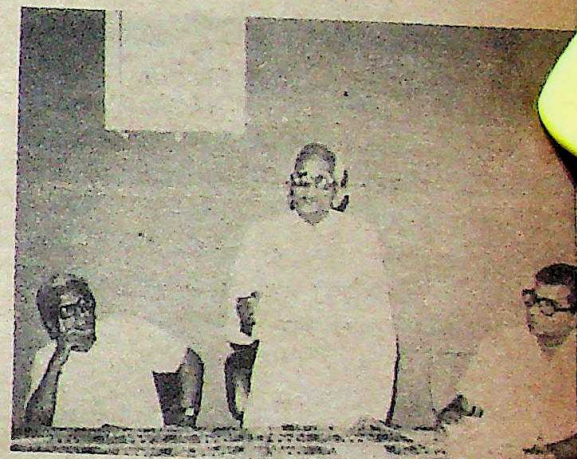
—बालकृष्ण काबरा 'एतेश'

## साहित्य और प्रौद्योगिकी

'साहित्य और विज्ञान का विकास स्थल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ता रहा है। इसलिए हमारा दिमाग प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के विकास से भी आगे जायेगा।' उक्त विचार प्रमुख साहित्यकार विचारक जनेंद्र कुमार ने 'साहित्य और टेक्नोलॉजी' विषय पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रकट किये। इस का आयोजन भारतीय लेखक संगठन की ओर से दिल्ली में किया गया।

डा. नरेंद्र मोहन ने कहा कि प्रौद्योगिकी से समाज का हित हुआ है। पर वह अमानवीयकरण की प्रक्रिया से भी गुजर रही है। इस के प्रभाव से साहित्य में संवेदना का रोमानी ढर्रा टूट गया है। देवेन्द्र इस्सर ने आलेख में प्रौद्योगिकी के विकास की जानकारी दी और उगमगाने भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की।

डा. यश गुलाटी की राय थी कि प्रौद्योगिकी से लाभ है और हानि भी। अतः साहित्यकार



का दायित्व है कि उस का उपयोग मनुष्य के हित में हो। डा. भरीप सिंह के अनुसार पश्चिम की चिंता है कि मनुष्य सोचना बंद कर देगा और भारत की चिंता है कि हमारे यहाँ का मनुष्य सोचना शुरू ही न कर सकेगा।

अन्य वक्ता थे डा. विनय, डा. हरदयाल, जगदीश चतुर्वेदी, डा. रत्नलाल शर्मा, डा. सुखबीर सिंह, डा. बलदेव बंशी, अजित कुमार, सुधीश पचौरी डा. शंलेश जैदी और डा. बुद्धसेन नौहार।

—डा. रत्नलाल शर्मा

## जिजीविषा-1 : विमोचन

मेरठ में इस 25 अप्रैल को 'जिजीविषा-1' (मेरठ के चार कवियों मुधा गुप्ता, विष्णु शरण 'इंदु', रुक्मा शर्मा एवं मानसिंह वर्मा का सहयोगी कविता संकलन) का विमोचन केदारनाथ सिंह द्वारा किया गया। मुधा गुप्ता द्वारा स्वागत और 'जिजीविषा' संस्था के संक्षिप्त परिचय के बाद केदार नाथ सिंह ने अपने विमोचन भाषण में बतलाया कि अब कविता दुनिया के महानगरों से नहीं, छोटे नगरों कस्बों से आ रही है। प्रस्तुत संकलन को मैं इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हूँ। समारोह के अध्यक्ष प्रो. विजयेंद्र स्नातक ने की।

—र. श.





## कुंवर नारायण

हिंदी में इस वर्ष का कुमारन आशान पुरस्कार सुपरिचित कवि कुंवर नारायण को उनके तीसरे संग्रह 'अपने सामने' (राजकमल प्रकाशन, 1979) के लिए दिया गया है। हाल में इसी संग्रह को मध्यप्रदेश का तुलसी पुरस्कार भी मिला है। आशान (1873-1924) मलयालम भाषा के प्रमुख कवियों में से रहे हैं। उन की स्मृति में यह पुरस्कार हर वर्ष दक्षिणी भाषाओं के कवियों के अलावा बंगला और हिंदी के कवियों को भी दिया जाता है। एक पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय भी है जो पिछले वर्ष प्रसिद्ध अफ्रीकी कवि लेओपोल्ड सेंधोर को दिया गया था। इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध कुवाई कवि निकोलस खुएन को मिला है।

हिंदी में यह पुरस्कार पिछले वर्ष से ही दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार एक अन्य सुपरिचित हिंदी कवि केदारनाथ सिंह को उन के कविता संग्रह 'जमीन पक रही है' (1980) के लिए दिया गया था।

हिंदी क्षेत्रों में दक्षिणी भाषाओं की आधुनिक कविता की अच्छी जानकारी नहीं है और न ही दक्षिण में हिंदी के अच्छे रचनाकार बराबर जा पाते हैं। इस संदर्भ में कुमारन आशान पुरस्कार का विशेष महत्व हो जाता है। यह पुरस्कार कवि के गांव कायिकर में एक भव्य समारोह में दिया जाता है। कुमारन आशान की कविताएँ और उन के विचार केरल में बहुत जाने पहचाने हैं। उन के

अनेक प्रसिद्ध कथनों में से एक यह भी है: "कानून को बदलो, नहीं तो कानून तुम्हें बदल देगा।"

कवि, कहानीकार के अलावा कुंवर नारायण की प्रतिष्ठा एक प्रमुख आलोचक के रूप में भी रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने अपना निबंध संग्रह प्रकाशित नहीं कराया है। इतनी चीजें विखरी हुई हैं कि खूब समय चाहिए। 'अपने सामने' संग्रह 'आत्मजयो' (1965) के छपने के लगभग पंद्रह वर्ष बाद प्रकाशित हुआ था। वैसे भी प्रकाशन और पुरस्कारों से किसी रचनाकार का महत्व नहीं सिद्ध होता है। असली बात लेखन कर्म को गंभीरता और चुनौती के रूप में लेने की है और साहित्यिक प्रशंसा से बचने की भी। इसी संदर्भ में कुंवर नारायण सरीखे रचनाकारों का महत्व समझा जा सकता है।

कुंवर नारायण दैनिक यथार्थ से नजदीकी और दूरी-दोनों ही तरह का रिश्ता बनाते हैं। इधर पिछले कुछ वर्षों की कविताओं में उन्होंने इतिहास का एक चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना किया है। एक युवा समीक्षक ने 'अपने सामने' की कविताओं के बारे में ठीक ही कहा है कि वे इतिहास में एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह नहीं जाते। मामूली आदमी की तरह जाते हैं।

'अपने सामने' की कविताओं की दुनिया में 'इन्नेवतूता मावर के जंगलों में सोच रहा है कि पैसे बाँसों की सूलियों में बिधे कौन है ये जिन के शरीर से रक्त चूता है! दिन में इतना अँधेरा है या सुल्तान अंधा है?' 'अपने सामने' के कवि का मूल्यांकन इसी दुनिया और भाषा में किया जा सकता है।—वि.

## रामसिंह

31 वर्षीय रामसिंह गुजरात से चुन कर आये राज्य सभा के नये सदस्य हैं। वह संभवतः राज्य सभा के युवतम सदस्य भी हैं। और ऐसे पहले सदस्य तो हैं ही जो मूलतः चित्रकार हैं। 72 से 80 तक वह बड़ौदा विश्व-

विद्यालय के ललित कला विभाग के छात्र रहे हैं, जहाँ उन्होंने पहले चित्रकला में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, बाद में ग्राफिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 80 में जहाँगीर आर्ट गैलरी, बंबई में और 81 में अहमदाबाद की कंटेपेरी आर्ट गैलरी में वह अपनी एकल प्रदर्शियाँ भी आयोजित कर चुके हैं। रामसिंह प्रमुखतः अम्लोक्त और मिला-लेखी पद्धति से छापों की रचना करते हैं।

गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके के राठवा आदिवासी परिवार में जन्मे रामसिंह को वचन से ही राजनीति और समाजसेवा का माहौल मिला। उन के पिता पातलिया माई जेहला माई छोटा उदयपुर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं और आदिवासियों के बीच उन्होंने काफी काम किया है। पिता शुरू से कांग्रेस में रहे हैं। रामसिंह कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। राजनीति में आने के बाद उन का इरादा कला को छोड़ने का कतई नहीं है। दिल्ली आने के बाद उन्होंने दिल्ली में रह रहे बड़ौदा के उन कलाकारों की खोजबीन तो की ही जो उन के साथ बड़ौदा में पढ़ रहे थे, वह अन्य कलाकारों से भी मिले। और कई शामों को ललित कला अकादमी के बहावलपुर स्थित अतिथि गृह के बाहर की घास पर बैठ कर कलाकार मित्रों से आत्मीय चर्चा करते हुए देखे गये। अपने छापों की दुनिया में वह प्रमुखतः आदिवासी जीवन और आदिवासी अभिप्रायों को ही कल्पनाशील ढंग से रखते हैं।—प्र.



## दिनेश गोस्वामी

राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में विजयी श्यामल यादव को बधाई देने वाले से पहले नेता दिनेश गोस्वामी खुद उस पद के निर्दलीय लेफ्ट प्रतियक्ष संयुक्त उम्मीदवार थे। पेशे से वकील श्री गोस्वामी राजनीति में संयोगवश आ गये। इसी लिए ग्यारह वर्षों से संसद में रहते हुए आज राजनैतिक वातावरण और उनकी संस्कृति से सही अर्थों में नहीं बिठा पाये हैं। उन्होंने कहा, "छात्र जीवन में ही विवाद में दिलचस्पी गहरी गयी और प्रादेशिक तथा भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में विजयी हुआ। गुआहाटी कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व किया।"

71 से 77 तक लोकसभा में और 78 में राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों ही भूमिकाओं में अंतर्दृष्टि, विषयगत सूत्र जानकारी के कारण सदन ध्यान खींचने में सफल रहे। दिलचस्प तथ्य यह है श्री गोस्वामी की काफी दिलचस्पी खेलकूद में है। असमिया में फुटबाल और असमिया में फुटबाल क्रिकेट का आँखों देखा हाल के कारण खेल प्रेमियों में प्रशंसकों की संख्या राजनीति प्रशंसकों से कहीं ज्यादा है।

श्री गोस्वामी ने नाटक लिखे हैं। तीन नाटकों का प्रसारण गुआहाटी रेडियो केंद्र से हो चुका है। दो महीना पहले जो प्रसारित हुआ उस की वस्तु राजनीति की कल्पना है।



पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस प्रशासन और प्रशिक्षण तथा  
व्यापिक विज्ञान की मौलिक और अनूदित  
हिन्दी पुस्तकों के लिए पुरस्कार

भारत सरकार ने पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों अथवा अनूदित पुस्तकों के लिए, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार शुरू करने का निश्चय किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन विषयों पर हिन्दी के प्रकाशनों को प्रोत्साहन देना है।

पुरस्कार : उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मूल पुस्तकों के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

1. पहला पुरस्कार—10,000/- रु. (दुर्लभ पुस्तकों के अनुवाद अथवा उपरोक्त विषयों पर ख्याति प्राप्त लेखकों से अनुरोध करके मूल पुस्तकों लिखाने पर.)

2. दूसरा पुरस्कार—7,000/- रु. (उपरोक्त विषयों पर उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकों के लिए प्रत्येक पंचांग वर्ष में 5 पुरस्कार)

3. तीसरा पुरस्कार—3,000/- रु. (इन विषयों पर अन्य भाषाओं से मूल रूप से लिखी प्रामाणिक पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों के लिए प्रत्येक दो पुरस्कार.)

प्रस्ता : भारत के सभी नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं। यह वर्ष पुरस्कारों का पहला वर्ष है, अतः 31 मार्च 1982 तक प्रकाशित सभी मूल पुस्तकों, पांडुलिपियों और प्रामाणिक अनुवादों के हिन्दी अनुवादों पर पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा। इस योजना के लिए भेजी जाने वाली पुस्तकें पहले ही प्रकाशित नहीं होनी चाहिए।

चयन : पुरस्कार पाने योग्य पुस्तकों का चयन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। पुरस्कारों के संबंध में इस समिति का निर्णय अंतिम होगा। यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं पाया जाता तो सभी पुरस्कार प्राप्त करने की एक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 1982 है।

प्रकाशक का नाम, विषय, लेखक और प्रकाशक का पूरा नाम और प्रकाशन तिथि, कापीराइट रखने वाले का नाम व पता, यदि कोई हो, पुस्तक की कीमत, पृष्ठ संख्या आदि के पूर्ण विवरण के साथ प्रकाशकों की चार प्रतियां इस पते पर भेजी जायें :—

निदेशक,  
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,  
बी-1688 कस्तूरबा गांधी मार्ग बैरेक्स,  
नई दिल्ली-110001.

ए.पी.पी. 82/15

# पराणा

## बच्चों की

## सम्पूर्ण मासिक

## पत्रिका

विज्ञापन दरें :

पूरा पृष्ठ रु. 1510.00

आधा पृष्ठ रु. 760.00

पैनल रु. 118.00 प्रति पैनल

(5.50 सें.मी. × 5.50 सें.मी.)

विज्ञापन व्यवस्थापक

# पराणा

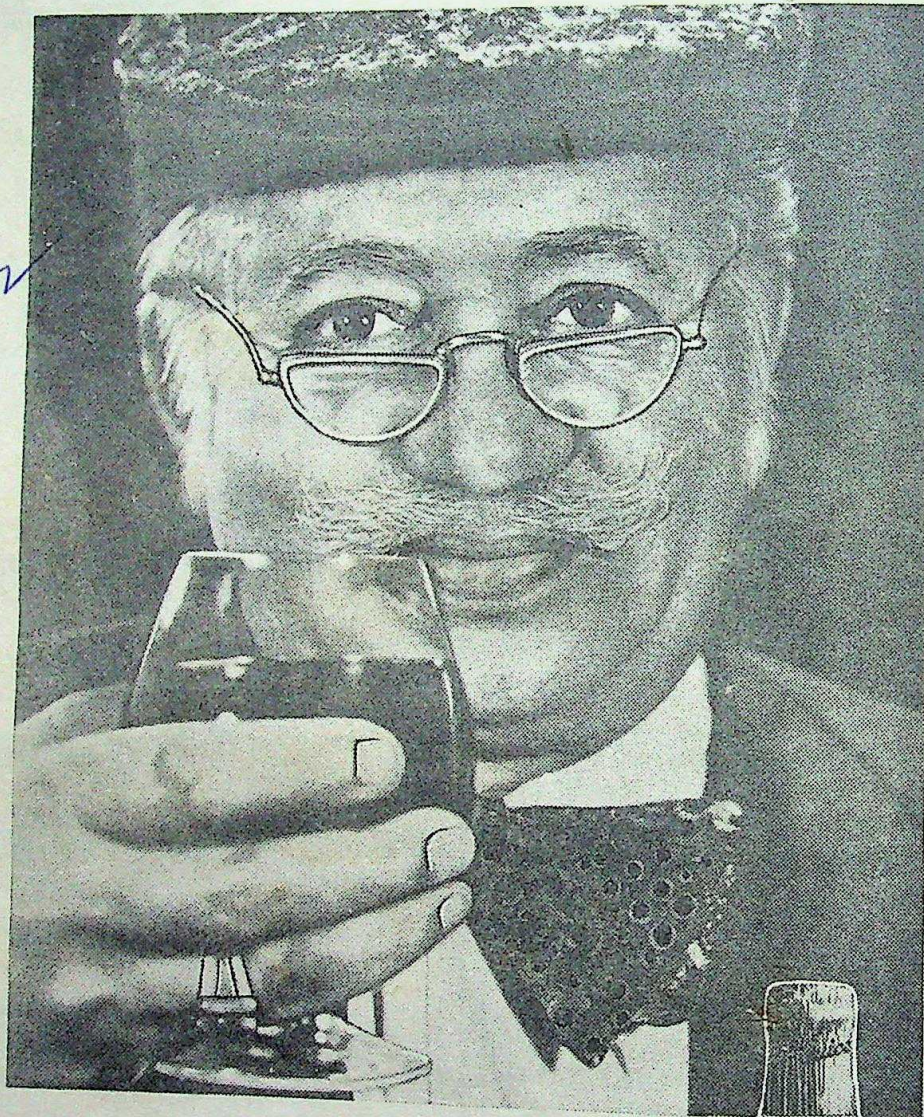
7, बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली-110002

फोन : 270161



# मद्यत्यागी !



पीजिए  
मोहनज़  
**गोल्ड कॉयन**  
एप्पल जूस

६५० मि.ली. व २०० मि.ली. की बोतलों में प्राप्य.

मोहन मीकिन लिमिटेड (स्थापित १८५५)

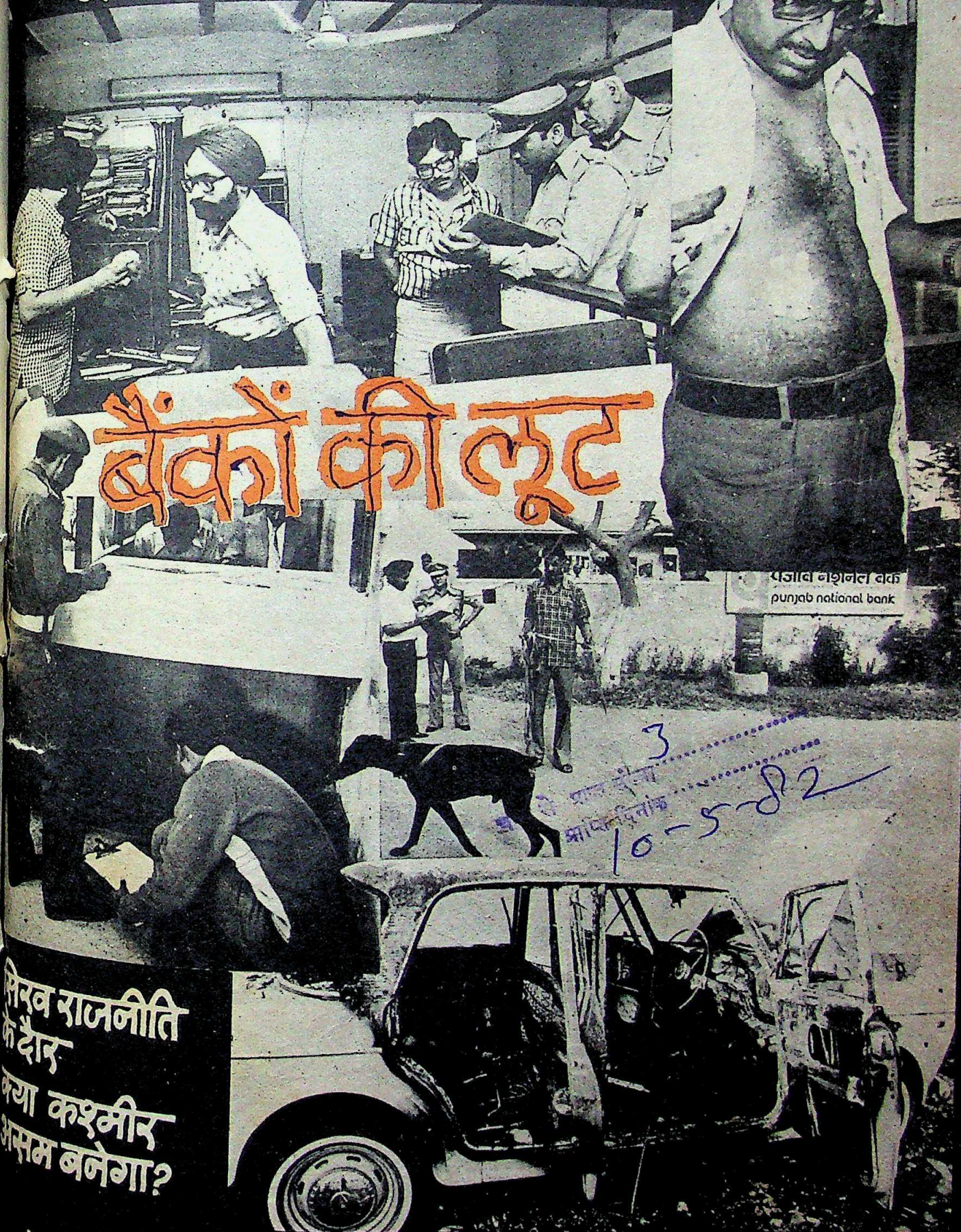
वितरक : ट्रेड लिक्स लिमिटेड, 'प्रभात किरन', १७ राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-११०००८





# दिनमाना

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन



सिरव राजनीति  
के दौर  
क्या कश्मीर  
असम बनेगा?

9-15 मई, 1982 • 19-25 बैसाख, 1904

रु. 2.00





# क्या आपको अपनी अगली पीढ़ियों का ख्याल है ?

- इतिहास गवाह है इंसान वक्त के साथ बदलता रहा है। उसके रीति-रिवाज, जीने का अंदाज कितना बदल चुका है। आज छोटे परिवार का रिवाज जोर पकड़ रहा है।
- छोटे परिवार के साथ ही हम दुनिया की दौड़ का मुकाबला कर सकते हैं।
- क्या आपको और आपके पड़ोसियों को इस बात का अहसास है कि आजादी के बाद हमारी आबादी दुगुनी हो चुकी है।
- सोचिए आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा ?

**आइये वक्त के साथ कदम बढ़ाइये**

**नया 20 सूत्री कार्यक्रम**

विस्तृत जानकारी के लिए निम्न कूपन का प्रयोग करें।

उप निदेशक,  
मास मेलिंग यूनिट,  
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय,  
बी ब्लॉक, कस्तूरबा गांधी मार्ग,  
नई दिल्ली - 110001

नाम \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_  
पिन \_\_\_\_\_

नये 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया मुझे हिंदी/अंग्रेजी की पुस्तिका भेजें।



## इस सप्ताह

बैंकों की लूट : उजले समाज का  
हाला चेहरा : आवरण कथा 7.  
मुस्लिम स्त्री का हक 10.  
लघु आम चुनाव की हलचल :  
अमय चक्र 18. पंजाब में सिख  
राजनीति के दौर 15. हरयाणा के  
विधानसभा चुनाव नये बदलाव  
की कहानी कहेंगे : चौ. देवीलाल  
से भेंटवार्ता 25. आंध्रप्रदेश और  
हार्नटक में आम चुनाव क्यों नहीं  
कराये गये 26. फाकलैंड में ब्रिटेन  
द्वारा सैनिक कार्रवाई 27.  
सोनी में भारतीय 30. कवि  
मलयज का निधन 37.



पृ. 7-9



पृ. 10



पृ. 37

मत और सम्मत 4. पिछले सप्ताह  
5-6. पत्रकार संसद 6. दिल्ली  
के रंग 11. चरचे और चरखे 12.  
विज्ञान 12. उनका कहना है 13.  
युवा जगत 14. दुनिया भर की  
31. खेल और खिलाड़ी 32.  
सामंच 35. साहित्य 36.  
फिल्म 38. कला 40. संस्कृति  
समाचार 41. चरित चर्चा 42.

आवरण : दिल्ली में बैंक डकैतियाँ पृ. 7-9  
फोटो : टाइम्स आफ इंडिया फोटो विभाग

## संपादक : कन्हैयालाल नंदन

संपादकीय सहकर्मी : जितेंद्र गुप्त (सहायक  
संपादक), सर्वेश्वरदयाल सबसेना (मुख्य  
उपसंपादक), श्यामलाल शर्मा, जवाहरलाल  
कौल, शुक्ला कदम, त्रिलोक दीप, महेश्वरदयाल  
गंगवार, प्रयाग शुक्ल, बनवारी, विनोद  
मारडवाज और सुषमा पाराशर.

विशेष संवाददाता : रामसेवक श्रीवास्तव

संस्था : रवि शर्मा

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन  
10, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002

## पाठकों से

देश में और देश की राजधानी में भी सनसनीखेज अपराधों की सूची  
निरंकुश महंगाई की तरह इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि  
वे नये जमाने के 'स्वाभाविक अंग' लगने लगे हैं—अब वे उतनी सनसनी  
भी नहीं पैदा कर पाते जितनी पहले हुआ करती थी. आम आदमी न केवल  
असहाय और असुरक्षित महसूस करता है, वरन् यह भी समझता है कि  
सरकारीतंत्र इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है. यह अकारण नहीं है  
क्योंकि वह देख रहा है कि ये अपराध कर्म समाज के उन वर्गों के लोगों  
द्वारा किये जा रहे हैं जो संपन्न भी हैं और जो कहीं न कहीं राजनीति से  
भी जुड़े हैं. दिल्ली में बैंकों की लूट के संबंध में राजधानी की पुलिस ने  
जिन चार नौजवानों को गिरफ्तार किया है उन में लखपतियों के बेटे भी  
हैं और डिप्रीयाप्ता नौजवान भी. इस तबके के लोग जाहिर है कि पेट  
की 'भूख' या किसी 'वाद' के कारण डाके नहीं डालते, बल्कि मुफ्त के माल  
पर, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट पर गुलछरें उड़ाना चाहते हैं. धन और सत्ता  
की लोलुपता के कारण होने वाले अपराध खास कर बैंकों की लूट हमारे  
समाज के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक भी है और सरकार के लिए कहीं  
बड़ी चुनौती भी है. 1980 में 21 सार्वजनिक बैंक लुटे और 1981 में  
ऐसी 32 वारदातें हुई. यही हमारी आवरण कथा का विषय है—देखिए  
पृष्ठ 7-8-9.

सिखों में से कुछ अमृतसर को मक्का की तरह पवित्र नगर का स्तर  
दिलवाने की माँग करते हैं, कुछ पंजाब में कश्मीर की तरह  
केंद्रीय सरकार की शक्ति चंद विषयों तक सीमित करना चाहते हैं, तो  
कुछ अलग खालिस्तान की आवाज उठा रहे हैं. उग्रपंथी सिख राजनीतिकों  
के विभिन्न वर्ग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की धुन में सिख राजनीति को  
एक नये मगर खतरनाक दौर में प्रविष्ट करा चुके हैं, जिसकी लगाम  
न मुख्यमंत्री दरबारासिंह के हाथ में है न गृहमंत्री जैलसिंह के जो एक  
दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुहाते. पंजाब की वर्तमान राजनीति को  
विदेशी ताकतों का कितना या कैसा समर्थन मिल रहा है, इसे निरूपित  
न करके उसके पीछे 'विदेशी हाथ' होने का हौआ खड़ा कर के केंद्र सरकार  
अपनी गफलत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, देखिए पृष्ठ  
15-16.

कश्मीर विधानसभा ने कश्मीर घाटी छोड़ कर गये शरणार्थियों  
की वापसी और पुनर्वास के नियमन का जो विधेयक पास किया  
है उस से जनमानस के सांप्रदायिक आधार पर विभाजित हो जाने की  
आशंका पैदा हो गयी है. एक तरफ 35 साल से कश्मीर में रह रहे लोगों  
को आज भी नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये हैं, दूसरी तरफ 35  
साल पहले कश्मीर छोड़ कर पाकिस्तान चले गये लोगों को वापस  
बुलाने के लिए कानूनी कवच तैयार किया जा रहा है. प्रतिपक्षी सदस्यों  
का ख्याल है कि अगर यह विधेयक राज्यपाल की संपुष्टि के बाद अमल  
में आता है तो कश्मीर की हालत असम जैसी हो जायेगी. मामले की पूरी  
जाँच के लिए हमारे विशेष संवाददाता ने जनता पार्टी के महासचिव  
सैयद शहाबुद्दीन से भेंट की और संवैधानिक विधि के विशेषज्ञ डी. पी.  
सिंह से भी मुलाकात की. विधि विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर सरकार  
ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह विधेयक बनाया है, क्योंकि  
नागरिकता का अधिकार केंद्रीय विषय है. देखिए पृष्ठ 20-21.

*Handwritten signature/initials*



## थोड़ी कृपादृष्टि आकाशवाणी भागलपुर पर भी

11 अप्रैल 'आकाशवाणी : बेचेहरणी का राना' लेख महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक था. आकाशवाणी भागलपुर के केंद्र निदेशक मनमाने ढंग से कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. चार या पाँच महीने में कार्यक्रम में कुछ न कुछ तब्दीली करते रहते हैं. उस पर सोने में सुहागा आकाशवाणी की बिजली प्रायः गायब रहती है. जब भी कोई कार्यक्रम सुनने के लिए बैठता है, मालूम हुआ आकाशवाणी भागलपुर से लाइन कट गयी. जेनरेटर सिर्फ नाम के लिए है. जब लाइन कट जाती है तो 20-25 मिनट के बाद कार्यक्रम शुरू किया जाता है. भागलपुर कमिश्नरी का क्षेत्र बहुत बड़ा है परंतु आकाशवाणी की प्रसारण क्षमता 100 किलोमीटर 10 किलोवाट है. यहाँ के बहुत से लोग भागलपुर रेडियो के लाम से वंचित रह जाते हैं. इसलिए इस की प्रसारण क्षमता बढ़ा कर 300 किलोमीटर 20 किलोवाट कर देना चाहिए. आकाशवाणी भागलपुर निजी मकान में कार्यरत है. और हाल साउंडप्रूफ नहीं है इसलिए कार्यक्रम बाहरी हल्ले गुल्ले से भरे रहते हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि आकाशवाणी भागलपुर पर भी थोड़ी कृपादृष्टि रखने की कोशिश करें. —रूपक कुमार 'मुंगेरी', अध्यक्ष, कुमार गौरव रत्ना, सचिव, मुंगेर रेडियो श्रोता संघ, 57, नया टोला माधोपुर, मुंगेर (बिहार)

## बेसुरे गायकों का मेला

किसी ने एक बेसुरे गायक को सलाह दी कि आप रेडियो पर क्यों नहीं गाते—कम से कम लोग रेडियो बंद तो कर सकेंगे. आज लगता है कि यह कोई लतीफा नहीं, वरन सच्चाई है. इतना ही नहीं बल्कि बेसुरे गायकों ने सलाह पर पूरी तरह अमल भी किया. अगर भरोसा नहीं हो रहा हो तो आकाशवाणी इंदौर के युववाणी कार्यक्रम में अपनी गलेबाजी दिखाने वाले उमरते कलाकारों से मिलिये. एक से बढ़ कर एक बेसुरा—उच्चारण की गलती, गलत नुक्ते यानी सब कुछ एक साथ. ऐसा नहीं है कि इन नये कलाकारों को रेडियो पर नहीं आने दिया जाना चाहिए लेकिन थोड़े से रियाज से इन कमियों को दूर किया जा सकता है. लगता है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारियों के पास इस सब के लिए समझ नहीं है और उन की इस लापरवाही की सजा श्रोताओं को भुगतनी पड़ती है.

यही हालत इस केंद्र के नाटक की भी है. पिछले बीस बाइस सालों की प्रतिष्ठा, जो

आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रमों के बंद होने की वजह से, उसे बिगड़े बेटे की तरह नये निदेशक मिट्टी में मिला देने पर तुले हैं.—अतुल शर्मा, 19, मोरसली गली, इंदौर

## बी. बी. सी. सुनो

आज भी भारत के लाखों लोग आकाशवाणी के समाचारों के साथ साथ (सच्चाई जानने के लिए) बी. बी. सी. लंदन या वाइस आफ अमेरिका अवश्य सुनते हैं और कहते हैं कि सही खबर सुननी है तो बी. बी. सी. लगाओ. क्या इस से सिद्ध नहीं होता कि आकाशवाणी की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है.

—सुभाष छाबड़ा, 49-50, आर. आर. क्वार्टर्स, रुद्रपुर

## सब को अपनी पड़ी है

आकाशवाणी से संबंधित सवाल बड़े तीखे हैं परंतु विल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जब प्रशासन ही लोकनमुख नहीं हो तो आकाशवाणी से क्या अपेक्षा की जाये. आकाशवाणी के वर्तमान चरित्र के लिए नेतावर्ग सबसे ज्यादा उत्तरदायी है. विरोधी दल के नेता भी अपना नाम ही सुनने के लिए हल्ला गुस्ला मचाते हैं तो लोग क्या करें. दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है.—संजय कुमार, अनिल कुमार, अर्जुन प्रसाद, स्नातकोत्तर, राजनीति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

## विज्ञापन भारती

सरकार की स्तुति हेतु प्रयुक्त समाचारों के प्रस्तुतीकरण में आकाशवाणी निस्संदेह अपना सानी नहीं रखती. कार्यक्षमता या कुशलता यही रही तो तथाकथित भारतीय जन प्रतिनिधियों का इसे व्यापक सहयोग मिलेगा.

आकाशवाणी द्वारा सरकार के मात्र एक उपग्रह की भूमिका निभाये जाने से उस के द्वारा प्रसारित समाचारों के प्रति बढ़ती अविश्वसनीयता के कारण बी. बी. सी. की बढ़ती लोकप्रियता ने आज आकाशवाणी को जन जागरण नहीं बल्कि मात्र विज्ञापन संस्था बना दिया है.—राजीव कुमार शुक्ल, 46, सरसुंदर लाल छात्रावास प्रयाग, विश्वविद्यालय

## पड़ोसी देशों के झंडे

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया ने गिलगित, हुंजा और स्कार्दू को उस देश की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व दे कर भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने में एक और रुकावट पैदा की है. भारत सरकार और भारत की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं ने इस की भर्त्सना की है. लेकिन क्या भारत सरकार की नीति इस ओर स्पष्ट है. कुछ सप्ताह हुए, दिल्ली दूरदर्शन केंद्र के बच्चों के

एक कार्यक्रम में 'पड़ोसी देशों के झंडे' नामक वार्ता प्रसारित हुई थी. इस के अफगानिस्तान देश का झंडा शामिल नहीं किया गया था. यदि भारत सरकार गिलगित, हुंजा और स्कार्दू को भारत का अंग मानती है तो अफगानिस्तान निश्चित रूप से भारत का पड़ोसी देश है.—विद्यासागर, ई 13, सकेत नयी बिल्ली

## सुरक्षार्थी सोते हैं या जागते हैं

11 अप्रैल: 'एक पत्र उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम' शीर्षक से अपने पत्र में लेखक ने अपने जिन अनुभवों को व्यक्त किया है, वे मात्र लेखक के ही अनुभव एवं पीड़ा नहीं हैं बल्कि हजारों हजारों व्यक्ति इस से पीड़ित हैं. मुझे स्वयं लखनऊ से देवरिया आने जते में इन्हीं सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एक ओर जहाँ आम जनता तो गाड़ी में जगह न मिल पाने के कारण दर दर की ठोकरें खाती है तथा गाड़ी में आदमी पर आदमी कसे जाने के बावजूद अधिकांश यात्री रेल की छत पर अपनी जान जोखिम में डाल कर यात्रा करने को मजबूर होते हैं, वहीं दो चार पुलिस वालों को जनता की सुरक्षा के नाम पर कई वर्ष एवं सीटों वाला डिब्बा देना कहाँ तक उचित है, यदि इस सुरक्षा दल का कार्य वाकई सुरक्षा करना ही है तो क्या सो कर सुरक्षा की जाती है? यदि नहीं तो फिर दो चार पुलिसकर्मियों हेतु इतनी बड़ी व्यवस्था की क्या जरूरत? स्पष्ट है कि सुरक्षा के

## आप फरमाते हैं

व्यंग्यचित्र : लक्ष्मण



'ये दुनिया जा किधर रही है! बैंक डकैती भी भ्रष्टाचार की तरह विश्वव्यापी होती जा रही है.'



## देश

- 24 अप्रैल : हरयाणा के असंतुष्ट मंत्रियों द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल. पंजाब में 'नहर रोको' आंदोलन विफल. वीएनएम के विदेशमंत्री नयूनेन को थाच की दिल्ली में भारतीय नेताओं से वार्ता.
- 25 अप्रैल : अल्जीरिया के राष्ट्रपति चादली बेंदजेद की भारत यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी. हिमाचलप्रदेश में कांग्रेस (इ) में क्रांति के संकेत.
- 26 अप्रैल : बिहार के राज्यपाल डॉ. ए.आर. किदवाई द्वारा चार उपकुलपति वरिष्ठ, पश्चिम बंगाल कांग्रेस (इ) के दो असंतुष्ट नेता मृत्यु. यमुना पार (दिल्ली) की एक बस्ती में डकैती के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु और तीन घायल. राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण.
- 27 अप्रैल : राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान. अमृतसर में सांप्रदायिक दंगों के कारण कर्फ्यू और देखते ही गोली मार देने के आदेश.
- 28 अप्रैल : प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ की अपनी यात्रा स्थगित. ईरान के विदेशमंत्री डॉ. अली अकबर विलायती की दिल्ली में भारतीय नेताओं से परस्पर संबंधों पर वार्ता. श्यामलाल यादव राज्यसभा के उप-सभापति पुनः निर्वाचित.
- 29 अप्रैल : हरयाणा के सात मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र. डॉ. विलायती की प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से वार्ता. मणिपुर के एक विद्रोही नेता चांगथाम विजयसिंह दिल्ली में गिरफ्तार. अमृतसर में तनावपूर्ण स्थिति के कारण चौबीस घंटे का कर्फ्यू पुनः लागू.
- 30 अप्रैल : हिंसक भीड़ द्वारा कलकत्ता में 17 आनंदमार्गियों की मार मार कर हत्या. लोकसभा का बजट अधिवेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित. पिछड़े वर्गों के बारे में मंडल आयोग की राय संसद में प्रस्तुत. पटियाला में पुलिस की गोलीबारी में 24 व्यक्ति घायल.

उद्देश्य खालिस्तान के निर्माण के पक्ष में तथा श्री जर्नेल सिंह भिंडरावाला की गिरफ्तारी के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करना है.' जेल से रिहा होने के बाद श्री भिंडरावाला का वक्तव्य था, 'उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया.'

14 अप्रैल 1982 को इंडा के संसद सदस्य दलवीर सिंह के निवास में आंध्रप्रदेश के दो नवयुवक रामनारायण कुमार एवं कुमार स्वामी ने प्रातः 7.30 बजे 5 व्यक्तियों को बंधक बना लिया. 9 घंटे के पश्चात लगभग सायं 4.30 बजे पुलिस के समक्ष समर्पण करते हुए उन्होंने वक्तव्य दिया, 'हमारा उद्देश्य शडहोल जिले में कोयला खानों के मजदूरों की मांगों के पक्ष में जनमत तैयार करना था.' उन की जमानत भी नहीं हुई तथा गृहमंत्री ने लोकसभा में वक्तव्य दिया, 'सरकार हिंसा से दृढ़ता से निपटेगी.'

सरकार को निपटना भी चाहिए. महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहाँ उक्त दोनों घटनाओं के पात्रों की राजनीतिक मांगों को पूर्ण किया गया (खालिस्तान की नहीं) वहाँ कोयला खानों की मांगों के विषय में क्या हुआ? क्या यह मांग राजनैतिक नहीं? —विपिन प्रताप गौतम, डी. ए. वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलंदशहर

## महंगा मनोरंजन

11 अप्रैल : दिल्ली में महंगे सिनेमाघरों पर लेख पड़ा. दिल्ली ने ही नहीं महाराष्ट्र और म. प्र. ने फिल्म की मनोरंजन दरों में भारी वृद्धि की है. म. प्र. में तो भारी मूल्यवृद्धि हुई. केरल सरकार ने 1,122 छविगृहों पर मनोरंजक प्राप्त करती है—बारह करोड़, इतना ही कर म. प्र. सरकार मात्र 461 छविगृहों से वसूलती है. इन में से भी इंदौर में 22 और भोपाल में 17 छविगृह हैं. दर वृद्धि से फिल्म उद्योग किस संकटपूर्ण स्थिति में है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत 2 माह में इंदौर में मात्र 22 छविगृहों में करीब 150 फिल्में बदलीं, जो एक कीर्तिमान भी है. इन में अधिकतर पुरानी ही थीं. दरवृद्धि के कारण नयी प्रदर्शित फिल्में कोई वितरक नहीं ले रहे. ले रहे हैं तो सिसक सिसक कर. कई छविगृह विवश हो मूल्यवृद्धि न कर घाटा उठा रहे हैं क्योंकि अच्छी से अच्छी फिल्में भी खाली जा रही हैं, इस दौरान दर्शकों की संख्या भी काफी घटी है सरकार ने 'दुधारू गाय का लाभ नाजायज जन विरोधी तरीके से उठाने का प्रयास किया है. शासन को फिल्म मनोरंजन सस्ता मुलभ करना चाहिए पर यहाँ उस के विपरीत निर्णय लिया गया. —धर्मश यशलहा 'प्रिय' पत्रकार, 256, जवाहरलाल मार्ग, राजमोहल्ला, इंदौर (म. प्र.).

नाम पर इस के पीछे भ्रष्टाचार है. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रेलमंत्री महोदय—इन सुरक्षा के मुल्यमंत्री हेतु मात्र बैठने का स्थान दिलाने के लिये कमियों हेतु मात्र बैठने का स्थान दिलाने की व्यवस्था करें न कि गद्दा बिछा कर सोने की जिस से मजबूर यात्रियों से जबरन पैसा वसूलने एवं उन्हें बेइज्जत करने तथा भ्रष्टाचार फैलाने की कार्यवाही पर रोक लग सके. पांडेय, उत्तरप्रदेश जलनिगम, रामआधार

## अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों

11 अप्रैल : चरचे और चरखे स्तंभ में प्रेषित नाटक अकादेमी के पुरस्कार वितरण समारोह में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे तथ्यपूर्ण हैं, आज जबकि देश में केंद्रीय सरकार द्वारा दुरावाद में अंग्रेजी इंस्टीट्यूट खोलने के विवेक अंग्रेजी का स्तर तेजी से गिर रहा है, इस के सुदूर भागों में जहाँ पहले हिंदी का खल विरोध था, अब हिंदी के पक्ष में आवाजें उठने लगी हैं.

आज जब कि देश में नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा दक्षिण के कुछ राज्यों में जहाँ कि कभी या अभी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम था है, पृथक्तावादी भावनाएँ जोर पकड़ रही हैं, सरकार के लिए उचित होगा कि वह देश में अंग्रेजी की पढ़ाई को समाप्त कर दे तथा वहाँ उस के स्थान पर प्रथम भाषा के रूप में राज्य की राजभाषा तथा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहन दे. —शकुनचंद गुप्त विशारद, विशारद मेडिकल स्टोर, स्थान पो. लालगंज, जि. रायबरेली (उ. प्र.)

## अपहरणकर्ता और सरकारी नीति

20 दिसंबर 1978 को भोला पांडे एवं लैंग पांडे (वर्तमान उ. प्र. विधानसभा सदस्य) ने संयुक्त रूप से इंडियन एयरलाइंस के विमान बोइंग 37 का अपहरण किया था. तथा 132 विमान यात्रियों को बंधक बनाया था. 14 घंटे के बाद उन्होंने समर्पण करते हुए कहा था 'हमारा उद्देश्य श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करना है. (स्टेट्समैन 22 दिस. 1978) इन के कृत्य पर तत्कालीन विरोध पक्ष की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का वक्तव्य था, 'अपहरण-कर्ताओं को कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए.' विमान : 31 दिस. 1978 पृ. 21)

30 सितंबर 1981 को उग्रवादी खालसा लाल के सदस्य गजेंद्रसिंह अपने साथियों की सहायता से इंडियन एयरलाइंस के विमान बोइंग 37 का अपहरण करके लाहौर ले गये. तथा 121 विमान यात्रियों को बंधक बना लिया. पाकिस्तान अधिकारियों के समक्ष समर्पण करते हुए उन का वक्तव्य था, 'हमारा



विदेश

- 24 अप्रैल : ब्रितानी विदेशमंत्री फ्रांसिस पेयस द्वारा फॉकलैंड समस्या पर होने वाली बातचीत में प्रगति का दावा उगांडा के राष्ट्रपति डॉ. मिल्टन ओबोटे द्वारा ईदी अमीन के समय निष्कासित एशियाइयों से वापसी का आग्रह.
- 25 अप्रैल : ब्रितानी जंगी जहाजों द्वारा दक्षिण जॉर्जिया पर अधिकार. इस्राइल द्वारा सिनाइ का बचा हुआ एक तिहाई भाग खाली कर मित्र को सौंपना.
- 26 अप्रैल : फॉकलैंड के मुख्य द्वीप पर ब्रितानी हमला आसन्न. विवादास्पद पट्टी पर इस्राइल और मित्र में समझौता. सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेज्नेव अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से अबतक में वार्ता पर दृढ़.
- 27 अप्रैल : एक चीनी विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 100 व्यक्तियों की मृत्यु. ब्रितानी प्रधानमंत्री मारग्रेट टैचर और अमेरिकी विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग द्वारा आर्जेंटीना को चेतावनी. अमेरिका द्वारा इस्राइल और मित्र को अधिक अस्त्र बेचने की घोषणा.
- 28 अप्रैल : अमेरिकी राज्य संघ द्वारा फॉकलैंड पर आर्जेंटीना की प्रभुसत्ता का समर्थन. चीन द्वारा सैनिक परिवर्द्ध गठित करने का निश्चय. पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेल्मुट श्मिड द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल. पाकिस्तान में 17 और उग्रपंथी गिरफ्तार. ईरान द्वारा अमेरिका को खनिज तेल बेचने की खबर का खंडन.
- 29 अप्रैल : ब्रिटेन और आर्जेंटीना में युद्ध की संभावना प्रबल. सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापसी. डॉ. आलवारो मेगना अल साल्वाडोर के अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त.
- 30 अप्रैल : अमेरिका के सहयोग से ब्रितानी सैनिकों द्वारा फॉकलैंड की नाकेबंदी शुरू. इराकी सैनिकों द्वारा ईरानी प्रहार का कड़ा जवाब. पीकिङ में पहला गैरसरकारी विश्वविद्यालय चीन सामाजिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन. बंगलादेश के भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री जमालुद्दीन अहमद को सात वर्ष का कठोर कारावास. श्रीमती मिल्का प्लानिच युगोस्लाविया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त.

विमान

# आर्जेंटीना अब पछता रहा होगा !

फॉकलैंड पर आर्जेंटीना और ब्रिटेन का विवाद आज विश्व के प्रमुख समाचारपत्रों के संपादकीय लेखों का विषय है. पश्चिमी यूरोप के समाचारपत्र स्पष्टतः ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं. पश्चिम जर्मनी के प्रमुख पत्र फ्रैंकफुर्त्त अल्मोनाइने त्साइटुंग का विचार है :

'व्यूनस आयर्स की सैनिक सरकार को इस बात से दुखद आश्चर्य होगा कि अधिकांश यूरोपीय देश इस प्रश्न पर तटस्थ रहने के बजाए ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं. इस प्रश्न पर पश्चिमी देशों के रवैये के बारे में आर्जेंटीना को गलतफहमी रही होगी. आर्जेंटीना को समर्थन न देने का हमारा पहला कारण यह है कि आज की इस संघर्षरत दुनिया में हम किसी भी हालत में इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि क्षेत्र संबंधी दावे लोग बलप्रयोग से तय करें, भले ही वे दावे सही हों.

दूसरी बात यह है कि फॉकलैंड में ब्रिटेन अपनी पुरानी औपनिवेशिकता की रक्षा नहीं कर रहा है न वह अपने व्यापार और सैनिक अड्डों को बनाये रखने की कोशिश कर रहा है. यह तो ब्रितानी मूल के कुछ लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रश्न है. इन की आर्जेंटीना में मिलने की जरा सी भी इच्छा नहीं है. वे आर्जेंटीना को छलांग लगा कर अपने यहाँ क्यों आने दें ? अगर इन सब को आर्जेंटीना के सिपुर्द कर दिया जाये तो वे अपनी स्वतंत्रता, गरिमा और संवैधानिक गारंटी खो बैठेंगे. फॉकलैंड पर आर्जेंटीना का दावा स्वीकार कर लेने से फॉकलैंड के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुँचता. पश्चिम जर्मनी से आर्जेंटीना को समर्थन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. पश्चिम जर्मनी अपने ही मित्रों के प्रति वफादार रहेगा.

ब्रितानी साप्ताहिक गार्डियन ने फॉकलैंड के विवाद पर ब्रिटेन को पश्चिम यूरोपीय देशों के समर्थन को ही यूरोपीय एकता का प्रतीक माना है. पत्र का विचार है :

"आर्जेंटीना से हर प्रकार के आयात पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रतिबंध लगाना बहुत उचित और स्वागत योग्य कदम है. इस से आर्थिक समुदाय के देशों को कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी नहीं होने वाला है. यूरोपीय देशों और रीगन प्रशासन के रवैये में बहुत फर्क नहीं होना चाहिए. व्यापार के मामले में आर्थिक समुदाय के देशों का रवैया उनकी विदेशनीति से भी परिलक्षित होना चाहिए जिस से सब को पता लग जाये कि किसी भी प्रश्न पर यूरोपीय समुदाय के देश समान रवैया अपना सकते हैं या एक हो सकते हैं.

आर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है. वहाँ इस समय मुद्राप्रसार दस प्र. श. है और बेरोजगारी बहुत फैली हुई है. अमेरिका का करोड़ों डॉलर का कर्ज है. आर्थिक दृष्टि से आर्जेंटीना बहुत कमजोर देश है. आर्जेंटीना पर तरह तरह के दबाव हैं और ये दबाव बढ़ ही रहे हैं. आर्जेंटीना का एक तिहाई निर्यात समुदाय के देशों को ही होता है. अब वह सब बंद हो जायेगा. इसी वर्ष व्यापार घाटे को पूरा करने और कर्जों से राहत पाने में सहायता के लिए आर्जेंटीना की अमेरिका से बातचीत होने वाली थी. अगर ब्रिटेन से विवाद जल्दी ही तय नहीं होता है तो विदेशी मुद्रा में कमी होने से और व्यापार में कमी होने से आर्जेंटीना में लोगों का जीवनस्तर और गिरता चला जायेगा.

प्रसिद्ध फ्रांसीसी पत्र ल मांड के विचार में आर्जेंटीना ने स्थिति की गंभीरता को अब समझ लिया होगा. पत्र का कहना है.

'आर्जेंटीना ने सोचा था कि सीमित सैनिक कार्रवाई से वह अपना सीमित उद्देश्य प्राप्त कर लेगा. उसे यह अनुमान नहीं होगा कि मामला इतना तूल पकड़ जायेगा. इतना तो निश्चित है कि आर्जेंटीना में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो राजनयिक स्तर पर प्रयत्न किये वगैर सैनिक कार्रवाई द्वारा अपने देश का झंडा फॉकलैंड द्वीपसमूह पर फहराते देखना चाहते हैं.

आर्जेंटीना फॉकलैंड द्वीपसमूह पर अपना अधिकार अनिवार्य मानता है. इस लिए फिलहाल फॉकलैंड द्वीपसमूह से आर्जेंटीना के अपने सैनिक हटाने का सवाल ही नहीं है. आर्जेंटीना में इस संकट के कारण सैनिक सरकार और राजनैतिक दलों के बीच निकटता बढ़ गयी है. अब आर्जेंटीना में



फॉकलैंड पर गार्डियन के गेबरेल का व्यंग्य

राष्ट्रीय असैनिक सरकार बनने की भी चर्चा होने लगी है. पर जब तक लोकतंत्र को वापस लाने का वायदा न हो तब तक तो यह संभव नहीं है. फिर भी आर्जेंटीना में लोग यही समझ रहे हैं कि राजनयिक उपायों द्वारा फॉकलैंड द्वीपसमूह पर आर्जेंटीना की प्रभुसत्ता एक न एक दिन ली जायेगी.



# बैंकों की लूट : उजले समाज का काला चेहरा

माचारपत्रों के न का समय है : कि अधिकांश न पर पश्चिमी र्जन न देने का त में इस बात दावे सही हो की रक्षा नहीं र रहा है. यह ना में मिलने ने दें ? अगर र संवैधानिक के लोगों की खनी चाहिए. यूरोपीय देशों तबंघ लगाना ई बहुत बड़ा में बहुत फर्क वेदेशनीति में यूपीय समुदाय य मुद्राप्रसार है. अधिक ये दबाव बढ़ ह सब बंद हो ए आर्हेतीना होता है तो ननस्तर और अब समस्य ह्य प्राप्त कर शिचत है कि रवाई द्वारा ए फिलहाल तीना में इस आर्हेतीन में परकार बनने लगी है. पर वापस लाने तक तो यह नी आर्हेतीना रहे हैं कि एरा फॉकलैंड हतीना की दिन मत 5 मई '82

अपराध जगत ने दक्षिणी दिल्ली को बैंक लुटेरों की राजधानी सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठा रखी. पिछले कुछ महीनों में सनसनीखेज डाके पड़े दक्षिणी दिल्ली के बैंकों में और लुटेरे लाखों रुपये ले उड़े. सभी डाके प्रायः दिनदहाड़े पड़े. डाक युवा पीढ़ी के थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, आधुनिक हथियारों और स्कूटर तथा कार आदि चलाने में दक्ष और उनका लूटपाट अभियान सुनियोजित रहा. झट से लूट, पट से गाथब हो गये हर अपराध के बाद वे. अपराध तो पुराना है, मगर लुटेरों के दल नये हैं. पुलिस के अपराध रजिस्ट्रारों में उनका कोई रिकार्ड नहीं. पुलिस के जाने पहचाने, अपराध जगत के भेदियों और पिटठुओं से उनके बारे में कोई सूचना आसानी से नहीं मिलती, इस लिए तहकीकात का काम भी बहुत मुश्किल हो रहा है पुलिस अधिकारियों के लिए. अपराधी अपने धंधे का आधुनिकीकरण कर चुके हैं. पुलिस की कार्यप्रणाली भी पुरानी ही है. लुटेरों और पुलिस के काम करने के बीच भ्रमता और गति की खाई है, जिस कर बैंकों की लूट के संबंध में. अपराधियों के हथकंडों में तीव्र परिवर्तन आ रहा है. आज युग की वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं का वे पूरा प्रयोग कर रहे हैं.

स्पष्ट है कि पुलिस वालों को भी अपने पुराने रीति-रिवाज बदलने होंगे, वरना लुटेरों द्वारा शहर पर दिये जाने पर वे मात ही खाते रहेंगे. ये हैं कुछ तथ्य जो हाल ही की बैंक डकैती लहर की तहकीकात के दौरान सामने आये हैं. कोई भी तथ्यों से आँखें नहीं मूंद सकता. पुलिस को खबर लाना होगा और शीघ्र गति से. बैंकों को भी सुरक्षा के नये कदम उठाने होंगे, वरना संगठित लुटेरों के गिरोहों की मार से न तो बैंक बचेंगे और न ही बैंकों के कर्मचारी. देखा गया है कि लुटेरे घावा बोलते हैं बैंकों पर पैसे की लूट के लिए मगर बैंक कर्मचारी यदि उनका सामना करते हैं तो मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार हो जाते हैं.

बस महीनों में चार बैंक लुटे: वे दिन गये कि बैंक में डाका पड़ता था तो लोग दांत से उंगली दबा कर रह जाते थे. अब तो शास्त्रचर्य तब होगा जब किसी बैंक या सरकारी कमाने, डाकघर आदि के लुटेने का समाचार सूचना दो महीना देश के समाचारपत्रों में छपे. दक्षिणी दिल्ली ने तो देश में बैंक लुटेरों का राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित कर दिया है. जून 1981 से ले कर इस वर्ष के मध्य तक के दस महीनों में ही इस क्षेत्र में चार बैंक लुटे. इसी वर्ष 12 अप्रैल को दिन-रात गीतांजलि कालोनी में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा लुटी. डाकू युवजन थे, जीन और जैकेट पहने और चेहरों को फिल्मी अंदाज में कालों से छुपाये हुए. एक ने तो 'शोले' फिल्म के नायक की तरह बैंक कर्मचारियों की सिट्टी-सीट पर का आशय यह था कि वह तो बड़ा जालिम लुटेरा है और उस से बड़ों बड़ों के औसान खता है. डाकू ढाई लाख रुपये से ऊपर नगदी लूट कर चपत हो गये.

इस से पहले केनरा बैंक की महारानी बाग और साउथ एक्सटेंशन शाखाओं में डाके पड़े

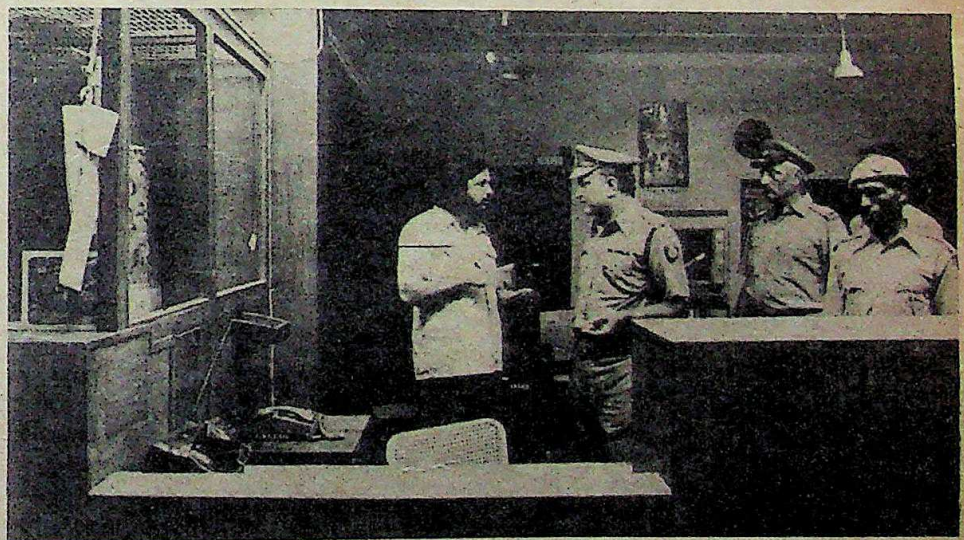
जिन में क्रमशः 10 लाख और साढ़े छह लाख रुपये ले उड़े लुटेरे. जून 1981 में डाका पड़ा था बैंक आफ इंडिया की ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 शाखा पर जिस में लुटेरों ने लगभग पौने दो लाख रुपये उड़ाये. प्रत्येक डकैती में लूट की रकम बढ़ती ही जा रही है. पौने दो लाख से बढ़ कर लूट 10 लाख तक जा पहुँची. गीतांजलि के डाके में केवल ढाई लाख रुपया डाकुओं के हाथ इसलिए लगा कि उस समय शायद उतनी ही नकदी बैंक में थी.

मगर इस का अर्थ यह नहीं कि राजधानी

स्ट्रीट की ओर जाती हुई एक बैंक वैन पर घावा बोल कर 6 लाख रुपया लूटा था. बाद में इस कांड के अपराधी पकड़े गये और अब जेल में अपने किये की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि इस लूट में उन्होंने हत्या भी की थी. शुरु है कि राजधानी के शेष बैंक डाकों में हत्या कोई नहीं हुई, केवल नकदी लूटी गयी, लूट हुई, यदि इस बात पर शुरु किया जा सकता है तो!

ऊँचे घरों के सपूत: नये लुटेरों ने पुलिस के लिए नयी समस्याएँ भी खड़ी कर दी हैं. लूट और डकैतियों की नयी लहर के सरदार हैं ऊँचे घरों के कपूत. पिछले दो वर्षों में दिल्ली और अन्य महानगरों में बड़े बड़े अपराध कांडों की पुलिस तहकीकात से इस तथ्य की स्पष्टतया पुष्टि होती है.

पुलिस की समस्या है कि बड़े घरानों के लोग अपने बिगड़े पुत्रों के गुनाह छुपाने और जब वे पकड़े जायें तो उन्हें कानून की पकड़ से बचाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार के प्रभाव का पूरा और सशक्त प्रयोग करते हैं और अधिकतर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने में सफल हो जाते हैं.



दक्षिण दिल्ली के एक बैंक में डकैती के बाद पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल

के अन्य भागों में स्थित बैंक लुटेरों के हमले से सर्वथा सुरक्षित रहे. अप्रैल 1978 में करीलबाग में सिंडीकेट बैंक की शाखा पर डाका पड़ा था. इस बैंक डकैती लहर की शुरुआत राजधानी में 1973 में हुई थी. यह डाका अब 'सुनील बतरा कांड' के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऊँचे घर के एक सुशिक्षित युवक सुनील बतरा के नेतृत्व में युवा लुटेरों के एक गिरोह ने चाँदनी चौक से पार्लियामेंट

इसी नयी सुशिक्षित (यदि उन्हें सुशिक्षित कहना उचित है), अंग्रेजी बोलने और जीन जैकेट पहनने वाली पीढ़ी की मनोवृत्ति की ओर इशारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्याय-मूर्ति सैयद फ़ज़ल मुरतजा अली ने हाल में गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारियों की एक शैक्षणिक गोष्ठी को संबोधित करते हुए आधुनिक अपराधों और आधुनिक अपराधियों की मनोवृत्तियों का अध्ययन विश्लेषण करने के



## यह कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है

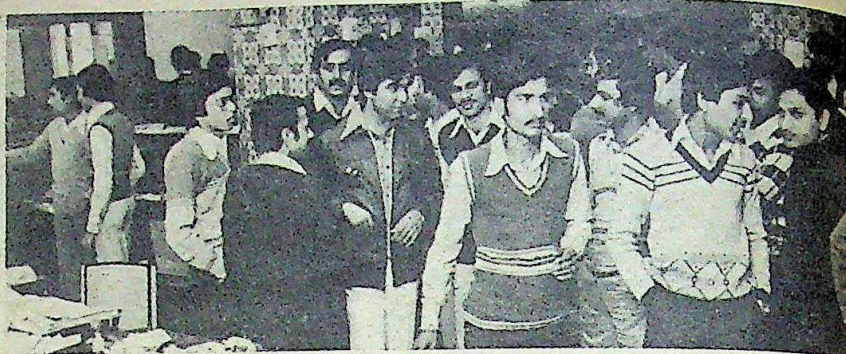
**पि**छले दो वर्ष में बैंक डकैतियों की जो बाढ़ आयी है वह शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों के विकास पर प्रश्न चिह्न लगाती है। देश के आर्थिक विकास में बैंक अहम भूमिका निभाते हैं लेकिन यह भूमिका कारगर तभी बन सकती है जब लोगों के मन में यह विश्वास बना रहे कि बैंक में उनका धन सुरक्षित रहेगा। बढ़ती बैंक डकैतियाँ अंततः बचत को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा मान कर नहीं चला जा सकता है कि खातेदारों की रकम हर हाल में बरकरार रहेगी, लुटी रकम का बोझ राजकोष उठायेगा, जरूरत तो ऐसी व्यवस्था की है जिस में बैंक लुटे नहीं और खातेदार निर्भय हो कर बैंक से लेनदेन कर सकें।

गत दस माह में दिल्ली में पड़ी चार बैंक डकैतियाँ संभवतः बहुचर्चित इसलिए हुई कि उन में मोटी रकम लुटी गयी और यह कि वे राजधानी में पड़ीं। अन्यथा पिछले दो वर्ष में 47 बैंक डकैतियाँ देश के अन्य भागों में भी पड़ीं जिन में 10 हजार रु. (स्टेट बैंक, लुधियाना) से ले कर 12 लाख रु. (स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, पश्चिम बंगाल) तक की रकम लुटी गयी। सब तो यह है कि 12-13 मामले ही ऐसे हैं जिन में लुटेरों के हाथ एक लाख रु. से कम की रकम लगी, इन में भी 50 हजार रु. से कम की डकैतियाँ चार ही हुई हैं।

मोटी रकमों की लूट के अलावा एक चिंताजनक पक्ष यह है कि ये बैंक डकैतियाँ देशव्यापी हुई हैं। अधिसंख्य बैंक डकैतियाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और पंजाब में पड़ीं। ग्रामीण बैंक उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक लुटे।

इस व्यापक लूट के बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि इसे रोकने के लिए सरकार पर्याप्त तत्परता दिखा रही हो। संभवतः बैंक डकैतियों को देश में व्याप्त कानून और व्यवस्था की आम स्थिति से जोड़ कर देखा जा रहा है। एक हद तक ऐसा हो भी सकता है परंतु इस से इस प्रश्न की अहमियत कम नहीं हो जाती है कि बैंक डकैतियों के अचानक बढ़ जाने का कारण क्या है और उसका निदान क्या है?

एक कारण तो सर्वविदित है कि लुटेरों को बैंक में मोटी रकम मिल जाती है और वह भी प्रायः बिना किसी तरह के प्रतिरोध के। इसका भी कारण है। बैंक कर्मचारी जानते हैं कि जो धन लूटा जा रहा है वह



बैंक डकैती के बाद : डकैती होने का आतंक कहां?

उनका नहीं है। फिर वे जान पर खेल कर उसकी हिफाजत क्यों करें। जहाँ कहीं प्रतिरोध किया भी गया तो वह एक या दो व्यक्तियों का प्रतिरोध ही रहा, संगठित प्रतिरोध नहीं। इस कारण लुटेरे प्रतिरोध करने वालों को ठिकाने लगा कर अपना काम करने में सब जगह सफल हुए। अतः जरूरत यह है कि बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि उनकी नजरें न केवल अपराधी को पकड़ सकें बल्कि वे संगठित प्रतिरोध भी कर सकें। इस मामले में मात्र पुलिस के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठा नहीं रहा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंक से कोसों दूर पुलिस चौकी होती है। आने वाले दिनों में और भी सुदूर गाँवों में भी बैंक खुलेंगे। वहाँ पुलिस कैसे पहुँचेगी? हर बैंक के साथ पुलिस चौकी बिठाना क्या संभव होगा? बहतर तो यही होगा कि बैंकों के कर्मचारियों की मानसिकता को सुरक्षा अभिमुखी बनाने का प्रयास हो। सभी बैंकों के लिए सतर्क, दक्ष और हथियारबंद संतरियों की व्यवस्था की जाये। इस समय बैंकों में जो संतरी हैं उनकी या तो बैंक की सुरक्षा में दिलचस्पी कम है या वे इतने दक्ष नहीं हैं कि दूर से ही खतरे को भाँप सकें। वे प्रायः गाफिल पाये जाते हैं और अपराधकर्मी बड़ी आसानी से उन पर काबू पा लेते हैं।

बैंकों में ऐसे आधुनिक यंत्र लगाने की बात भी फिर्जा में है जिनका संबंध निकटवर्ती पुलिस केंद्र से हो ताकि डाका पड़ने पर खतरे की घंटी थाने में बजने लगे। फिलवक्त तो दूरभाष से ही बाहर संपर्क किया जा सकता है जिसे अपराधी आते ही काट देते हैं। शहरों में यह उपाय कारगर हो सकता है।

इतनी बैंक डकैतियाँ पड़ जाने के बावजूद बैंक के उच्चाधिकारियों के पास सुरक्षात्मक व्यवस्था पर विचार करने के लिए शायद समय नहीं है। अन्यथा अब तक कोई न कोई

हल निकल ही आता। वे यह मान कर चल रहे हैं कि यह काम तो पुलिस का है। यह मूल जाते हैं कि खातेदारों की अमानत की सुरक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। पुलिस तो मांगे जाने पर ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है, वह भी अपनी सीमाओं के भीतर ही। कानून और व्यवस्था बनाये रखने में उलझी पुलिस के इस तर्क में वजन है कि उसके पास न तो इतने लोग हैं और न साधन कि वह बैंक डकैतियों को रोक सके। यों पुलिस के विशेष दस्ते बना कर इस दिशा में एक कारगर प्रयास किया जा सकता है।

एक कारगर उपाय यह भी हो सकता है कि सामाजिक और राजनैतिक माहौल ने आम आदमी में कानून और व्यवस्था के प्रति जो उदासीनता पैदा की उसे तोड़ा जाये। यह हो सका तो समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है लेकिन इसके लिए राजनैतिक दलों और उनके नेताओं को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। 'आप हमें वोट दें, हम आपका हर बोझ उठावेंगे', इस तरह का आश्वासन जनचेतना को कुंठित करता है। इसी का परिणाम आज यह दिखाई दे रहा है कि बैंक तो क्या, पड़ोसी भी लुटता रहे तो दूसरे तमाशा देखते रहते हैं। आम आदमी की इस उदासीनता को हर मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप ने भी बहुत बढ़ाया है। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'अपराधी को छुड़ाने के लिए कोई न कोई नेता थाने में आ घमकता है और हमें उसका कहना मानना पड़ता है। फिर खोजबीन करने और अपराधी को पकड़ने से क्या फायदा।'

बैंकों की लूट की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या ही नहीं है वह देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकास के लिए भी चुनौती बन गयी है। अतः हर स्तर पर उस का सामना किया जाना चाहिए।

—महेश्वरदयालु गंगवार

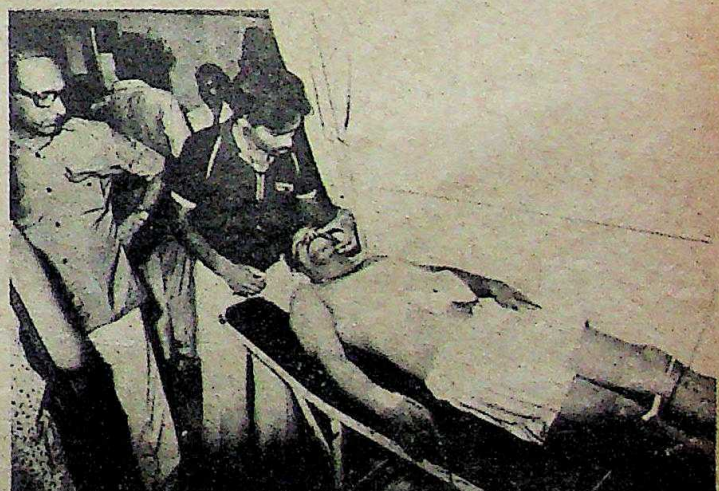


कर चल  
यह मूल  
गानत की  
हीं पर है  
हैं सुरक्षा  
सीमाओं  
या बनाये  
में वजन  
हैं और न  
रोक सके  
कर इस  
केया जा  
सकता है  
माहोल ने  
वस्था के  
मड़ा जाये  
हल हो  
तक दलों  
र तरीके  
आपका  
माशवासन  
इसी का  
है कि  
रहे तो  
दमी की  
जनैतिक  
बार एक  
अपराधी  
नेता थाने  
कहना  
रने और  
ता.  
त्र कानून  
मस्या ही  
जक तथा  
नीति बत  
सामना  
गंगवार  
15 मई '82

एक विशेष संस्थान की स्थापना का  
दिया।  
जो लुटेरे पकड़े गये : जो लुटेरे बैंक डकैतियों  
अन्य घिनौने अपराध के संबंध में पकड़े  
की गयी पुलिस पृच्छताछ से आज  
उन्से समाज का काला चेहरा साफ  
है, ये नये अपराधी पाँच सितारा  
होते हैं, बड़े लोगों से इनका मेलजोल रहता  
है और ये जानते हैं कि आज के बीमार  
समाज में पैसा बोलता है, सत्ता ही सती सावित्री  
पैसे और सत्ता की तुरंत साधना के लिए  
बहुत कारगर मंत्र हैं। उसे ही सिद्ध  
रहे हैं ये जुटे रहते हैं। हाल में दिल्ली के बैंक  
लुटेरों के एक गिरोह के कुछ युवा सदस्य पकड़े  
गये। ये सभी बड़े घरों के कुल दीपक हैं। एक तो  
व्यक्ति का पुत्र बताया जाता है कहते हैं  
उन्से पैमाने के जुआरी भी हैं। घुड़दौड़ में और  
में सिर चकरा देने वाली मोटी रकमों की  
जीत होती है तो शामत आती है बैंकों की।  
महानगरी के इन महालुटेरों का एक प्रतीक  
मध्यप्रदेश का बी. एस.सी. का विद्यार्थी  
गुज्जर भटनागर। उसने अपने कई नाम रख छोड़े  
इसी लिए कुछ पुलिस कर्मचारियों ने  
उसे 'दस चेहरे वाला दस्यु' का खिताब दिया।  
गुज्जर दक्षिणी दिल्ली में ईस्ट आफ कैलास में  
आनंदार बंगले में रहता था। जिमखाना क्लब  
वाकायदा मित्रों से मिलता जुलता था  
मजे के लिए। रातें रंगीन करने के लिए

रोज मिलती है दससुल वह सब अपराधी  
अपराधी है। तहकीकात करने वाले अफसरों  
के अनुसार राजू भी आधुनिक बैंक लुटेरों की  
तरह सुनहरे समाज के काले चेहरे का प्रतीक  
था। हाँ, उसका धंधा अधिकतर ब्लैकमेल और  
फिरोती का था, बैंक डकैती नहीं। तहकीकात  
से यह भी बात सामने आयी कि मध्यप्रदेश,  
दिल्ली और देश के अन्य भागों में बहुत से बड़े  
बड़े लोगों से उसका अच्छा संपर्क था, क्योंकि  
वे भी उसे अपनी तरह बड़ा आदमी समझते  
थे। उसके पास वह सब कुछ था जो बड़े लोगों  
के पास होता है। किसी ने यह जानने का कष्ट  
कभी नहीं किया कि यह सब कैसे और कहाँ  
से आया। पुलिस जान गयी तो लुटेरा पकड़ा गया।  
बैंक डकैतियाँ संसद में : पिछले महीने  
गीतांजलि कालोनी में पंजाब नेशनल बैंक  
के डाके के बाद बैंक डकैतियों की गूँज संसद  
में उठी। जो आँकड़े सामने आये उनसे सभी  
को चिंता होनी चाहिए। बात सामने आयी कि  
दिल्ली में ही नहीं दिल्ली के बाहर भी नगरों,  
महानगरों में बैंक लुटेरों का निशाना बन रहे हैं।  
सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में ही लूट और डाके  
की वारदातें 1980 में 21 हुई और 1981  
में बढ़ कर 32। इन दो वर्षों में बैंक लुटेरों ने  
कुल मिला कर 1 करोड़ 16 लाख रुपये की  
रकम लूटी। पुलिस अब तक इस लूट में से  
लगभग साढ़े ग्यारह लाख रुपये नकद और  
कुछ जेवर ही बरामद करने में सफल हुई है।  
क्यों रहती है पुलिस असफल? डकैतियों की

गिरफ्तार पुलिस के पास केवल सजा का हथियार  
है जो समाज परिवर्तन के लिए काफी नहीं।  
हम पुलिस में सुधार अवश्य कर सकते हैं और  
कर रहे हैं मगर उस से बड़ी बात है समाज  
सुधार की जो समाज के नेता कर सकते हैं।  
एक अन्य सूत्र ने बताया कि दिल्ली में  
पुलिस दक्षिणी दिल्ली से शुरू हो कर घर घर  
में एक सर्वेक्षण करेगी यह खोजने के लिए कि  
ऊँचे घरों की संतान का कितना संबंध है  
आधुनिक अपराधों से और कितने नयी पीढ़ी  
के युवा अपराधी दूसरे प्रदेशों से आ कर  
गुमनामी के पर्दे में छुप कर अपराध के धंधे में  
व्यस्त हैं? दिल्ली पुलिस में बंदोबस्ती काम  
से तहकीकात यानी अपराधी खोजने पकड़ने  
के काम को अलग करने के लिए भी कार्रवाई  
हो रही है। इस दिशा में जो कुछ कदम उठाये  
गये हैं उन में अपराधियों की खोज पकड़ में  
कुछ सफलताएँ भी मिली हैं पुलिस को।  
कुछ नागरिक और बैंक कर्मचारी भी इस  
बात पर सहमत हैं कि बैंकों में सुरक्षा प्रबंध  
ढीला और नकारा है। प्रायः बैंक इस ओर  
अधिक ध्यान इस लिए नहीं देते कि इन बड़े-  
बड़े वित्तीय संस्थानों की घनराशि का बीमा  
करा लिया जाता है। अगर पैसा लुटता है तो  
हानि तो देश को ही होती है, बैंक की न सही,  
बीमा करने वाले संस्थान की सही। बैंकों को  
भी सुरक्षा के सार्थक उपाय करने चाहिए  
और करने होंगे। वरना डकैतियाँ बढ़ेंगी।  
कुछ लोग आज के अनैतिक सामाजिक



पुलिस द्वारा बैंक में घटनास्थल का निरीक्षण (बायें) और लुटेरों द्वारा घायल किया गया एक बैंक कर्मचारी (दायें)

इस अक्सर दिल्ली के पाँच सितारा होटलों में  
रखा जाता था। गत वर्ष जब पुलिस ने बड़ी  
लुटेरों के बाद उसे निशाने पर घर लिया और  
ईस्ट आफ कैलास में उसके किराये के बंगले पर  
गिराफ्तार कर उसे हिरासत में ले लिया तो  
जो भी अफसर की बेटी से रोमांस भी चल रहा  
था, पुलिस सूत्रों के अनुसार शायद वह बेचारी  
नहीं जानती थी कि जिस ऊँचे घर के मीठा  
शौकने वाले, सुदर्शन सुसज्जित युवक से वह

इस भरमार में बार बार यही प्रश्न पूछा जा  
रहा है कि क्यों असफल रहती है पुलिस बैंक  
डकैतियों को रोकने में और बैंक लुटेरों को  
हथकड़ियाँ पहनाने में।  
इस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत से लोगों ने  
अपने ढंग से दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधि-  
कारी ने कहा, 'पुलिस तहकीकात कर सकती  
है, अपराधी को पकड़ सकती है, मगर समाज  
को नहीं बदल सकती, जीवन के हर क्षेत्र में  
बढ़ती अनैतिकता और अनुशासनहीनता के

और राजनैतिक वातावरण को अपराधों की  
जड़ मानते हैं। उनका विचार है कि शीघ्र  
सत्ता साधना के लिए राजनैतिक नेता और  
दल जो छलांग लगाने की नीति, अवसरवाद,  
हिंसात्मक आंदोलन तथा अनैतिकता के  
रास्ते पर चलते हैं उसी का दूसरा स्वरूप है शीघ्र  
घनशक्ति संग्रह के ये अनैतिक, हिंसात्मक  
द्रुतगामी ढंग, नये अपराध जगत के, विशेषकर  
पढ़े लिखे, ऊँचे समाज के आदर्श हैं 'सुलताना'  
और 'सुंदर', 'मानसिंह' और 'फूलन देवी'। □



# मुस्लिम स्त्री के हक कुरान की आयतों में बंद हैं

इंदौर विश्वविद्यालय की एक अध्यापिका कृष्णा राजवाड़े ने जब अपने शोध प्रबंध के लिए 'स्टेटस आफ मुस्लिम वुमेन इन इंदौर सिटी' विषय चुना तो सब को बड़ी हैरत हुई. 1979 में शोध प्रबंध प्रस्तुत हुआ और इंदौर विश्वविद्यालय ने उस को स्वीकृत कर डॉक्टर की उपाधि उन को दी, तब तो लोगों की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा. एक हिंदू स्त्री का यह विषय चुनना और सफलता से अपना संकल्प पूरा करना लोगों की कल्पना के बाहर की बात थी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में एक दुर्लभ्य खाई बनी हुई है, ऐसा लोगों को लगता है.

विश्व महिला वर्ष के संदर्भ में शोधकार्य के कुछ उद्देश्य निश्चित किये गये थे (1) स्त्री पुरुष समता का अधिकार, (2) स्त्रियों को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर देना तथा (3) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उन की भूमिका क्या हो, इस को निश्चित करना था. भारतीय स्त्री समूह की एक महत्वपूर्ण इकाई मुस्लिम औरतें हैं. अतः उन के बारे में भी कुछ किया जाये, ऐसा कृष्णा राजवाड़े को लगा और डा. के. पी. पोथन तथा अन्य विश्वविद्यालयीन अध्यापकों का समर्थन प्राप्त कर कृष्णा राजवाड़े इस काम में जुट गयीं.

इंदौर नगर की 400 आम औरतों तथा 50 पढ़ी लिखी औरतों का सर्वेक्षण करना एक पेचीदा मामला था, लेकिन वास्तव में कृष्णा राजवाड़े को जो अनुभव हुआ, वह हौसला बढ़ाने वाला था. महाविद्यालयीन शिक्षा का जिन को अवसर मिला था, वे मुस्लिम स्त्रियाँ सहयोग करने के लिये तैयार हो गयीं. नजमा मुनशी, नजमा अख्तर, अलिया आरा, रहमत कुरेशी, शकीला बानू, मसूदा बेगम, सलिमा जहाँ आदि स्त्रियों तथा हमीद खान, इसरार खान, मुहम्मद अनवर, प्रो. शमीम, नसीर खान आदि पुरुषों ने पूरा सहयोग दिया.

अपने शोधकार्य द्वारा जिस नतीजे पर श्रीमती कृष्णा राजवाड़े पहुँचीं वे इस तरह हैं : (1) भारत की अन्य किसी भी तबके की स्त्री दुर्बलता में शायद ही मुस्लिम औरत के मुकाबले में खड़ी हो सके. (2) तलाक और सौत की दो तलवारें उसके सिर पर हर समय लटकती रहती हैं, जिसकी वजह से उन के खौफ के दबाव के नीचे जिदगी काटनी पड़ती है. (3) अपने पैरों पर खड़ी हो सके ऐसी शायद ही कोई क्षमता उस को प्राप्त हो सकती है. उस की दुर्बलता का यह भी एक कारण हो सकता है. (4) शिक्षा की जो सुविधाएँ उस को प्राप्त हैं उन का भी लाभ वह उठा



नहीं पाती. हमीद दलवाई साहेब ने मुस्लिम सत्य-शोधक मंडल स्थापित कर मुस्लिम स्त्रियों के लिए जो काम किया उसका उल्लेख अपने शोध प्रबंध में कृष्णा राजवाड़े ने किया है. उन का कहना है कि इस तरह की संस्थाएँ स्थान स्थान पर स्थापित हो जायें तो मुस्लिम स्त्रियाँ आगे बढ़ सकेंगी, गरीबी तथा अज्ञान की वजह से इस हालत में जीना पड़ता है, इसका ध्यान बहुत सारी स्त्रियों को है, लेकिन इस में से रास्ता निकले तो कैसे नकले, बहुत स्त्रियों को इस की चिंता है.

उन्होंने अपने शोध प्रबंध में बताया है कि अनेक बेबुनियादी बातें लोगों के दिलों में जड़ें जमा कर बठी हैं. मुसलमान अपने को एक दूसरे के बराबर मानते हैं, यह एक झूठा वहम है. मुसलमानों में भी एक तरह की जातिप्रथा तथा ऊँच नीच देखने को मिलता है. रोटी एक दूसरे के साथ खाने में किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन शादियाँ खुल कर आपस में अभी भी नहीं होतीं. शेख, सैयद, लुहार, तेली, भिस्ती आदि का भेद इंदौर के मुसलमानों में मौजूद है. सैयद अपने को मुहम्मद पैगंबर के परिवार का मानते हैं और अपने को ऊँचा बताते हैं. मीर या शाह शब्द को अपने नामों से वे इसीलिए जोड़ते हैं. स्त्रियाँ आमतौर से अपने को ऊँचा बताने के लिए बेगम बताती हैं. सैयद की लड़की आमतौर पर सैयद से ही व्याही जाती है. मुगलों से रिश्ता जोड़ने वाले अपने को मिर्जा या बेग बताते हैं. अफगानों से अपने को जोड़ने वाले अपने को खान बताते हैं. अनुवंश विज्ञान की कसौटियों पर यह सही उतरने की कोई संभावना नहीं है.

60 फीसदी स्त्रियाँ दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकतीं क्यों कि ऐसा करना बुरा माना जाता है. निरक्षरता के कारण मनबहलाव का एक ही रास्ता बचता है और वह है दूसरों की नुक्ताचीनी करना. 400 औरतों में से 386 औरतों से शादी के बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था. शादी की उम्र औसतन 15 साल थी लेकिन शिक्षित

स्त्रियों में औसतन उम्र 21 साल की थी. 90 फीसदी स्त्रियाँ सौत को अपने घरों में हजिज बरदाश्त नहीं करना चाहती थी. 58 फीसदी स्त्रियों की तीन से ज्यादा संतान थी. 24 फीसदी स्त्रियों ने संतान संख्या को रोकने के लिए नसबंदी करवा ली थी. अपने बच्चों की ठीक देखभाल करना हो तो संतान की संख्या मर्यादित करना आवश्यक है. इस की चिंता बहुतेरी औरतों में देखने को मिली. तलाकों की संख्या तथा अनेक औरतों वाले मर्दों के बारे में चर्चा बहुत चलती है. लेकिन इन की तादाद अपेक्षा से बहुत कम है.

इस्लाम में औरतों को ज्यादा हक दिये जायें. ऐसा हमेशा प्रचार किया जाता है. लेकिन वास्तविकता दूसरी ही है. कुरान की आयतों के आधार पर दावा किया जाता है इस्लाम औरत की जितनी इज्जत करता है शायद दूसरा कोई करता हो! श्रीमती राजवाड़े का कहना है कि मुहम्मद पैगंबर साहेब का कानून अनेक हक दिये लेकिन फतवा के द्वारा और मुसलमान औरत को बुर्के के पीछे खदेड़ कर प्रत्यक्ष व्यवहार में ये हक लिये गये हैं! कानून में जो भूमिका है वह हादसों में नहीं मिलती और कुरान की आयतों को ताक पर रख कर हदीसों को ले कर औरतों को दबाया जाता है. मर्द से औरत की कीमती आधी है, ऐसा खुद मुहम्मद पैगंबर मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि काजी के सामने कोई मामला पेश हो तो दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही जितनी महत्वपूर्ण माना जाये! इतना ही नहीं एक बयान के अनुसार दोजख में मर्दों से औरतों की तादाद ज्यादा थी. ऐसा मुहम्मद पैगंबर साहेब ने देखा, औरत बराबरी इस्लाम में भी नहीं है. एक भ्रम फैलाया गया है, जिस के कारण मुस्लिम औरतें दबी दबी सी रहती हैं. श्रीमती राजवाड़े का कहना है कि अधिकृत जानकारों के अभाव के कारण सुधारों के लिए कोई ठोस बुनियाद ही नहीं बत पाती.

डॉ. कृष्णा राजवाड़े का यह शोध प्रबंध अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है. लेकिन प्रकाशित होने पर अनेक स्थानों पर इस का शोध कार्य प्रारंभ हो सकता है. सामाजिक विज्ञान शोधपरिषद् का सहयोग कृष्णा राजवाड़े को प्राप्त था. अन्य संशोधकों को भी इस तरह की मदद प्राप्त हो सकती है. इस तरह के शोध कार्य के द्वारा जो वास्तविकता सामने आ जाये उस को हिम्मत से देखना चाहिए. वास्तविकता को नजर अंदाज करने का आप ही आप समस्याएँ हल नहीं होंगी. —यदुनाथ



दिल्ली के रंग

## बेताल बदलियाँ

अप्रैल भर दिल्ली में पारा चढ़ता रहा, उतरता रहा. बेताल बदलियाँ घिर आयीं जब भी जरा सी धूप निकली तापमान बहुधा साधारण से कई डिग्री कम हो रहा. मौसम वालों का कहना था 'कोई खास बात नहीं.' महानगरवासी प्रसन्न रहे कि गरमी ने अभी दौट नहीं दिखाये. और काटना नहीं शुरू किया. मगर किसान फिक्रमंद हैं, क्यों? फसलें कटी नहीं हैं. बेताल बदलियाँ उन्हें दागी बना रही हैं. गलने सड़ने का डर है. न जाने विधाता के मन में क्या है, कुछ लोगों को भय है कि दिल्ली और भारत के मौसम में किन्हीं कारणों से मौलिक परिवर्तन आ रहा है. कुछ को भय है कि चिनचिनोला ज्वालामुखी के 29 मार्च को भड़कने और विस्फोट से जो भयानक बादल उमरा है मैक्सिको से, और पहुँच गया है

## सूर्य का रहस्य

सूर्य क्यों चमकता है? वैज्ञानिकों को शायद इस प्रश्न के उत्तर की खोज शतियों से रही है. देव मालाओं में सूर्य को देवता और भगवान का पद भी उस के इस रहस्यमयी और चका-चौंध प्रकाश के कारण ही प्राप्त हुआ शायद. लगभग 50 वर्ष पूर्व तक इस प्रश्न का कोई ठीक उत्तर नहीं था वैज्ञानिकों के पास. प्रश्न एक बार फिर उठाया प्रोफेसर बसंत नारलेकर ने जो गणित और तारक ज्ञान के क्षेत्रों में विज्ञान-विश्व में विशेष स्थान रखते हैं. श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के संस्थापक की स्मृति में दिल्ली में स्मारकीय भाषण देते हुए उन्होंने भारतवासियों के लिये विज्ञान और तकनीकी को अपने जीवन में ढालने के फायदों पर बल दिया और उसी प्रसंग में उल्लेख हुआ सूर्य के रहस्य का.

सिद्ध की 1930 में. और तब से अब तक अणु युग हमारी धरती पर साक्षात है.

प्रोफेसर नारलेकर ने कहा, इस विज्ञान कथा का महात्म यह है कि 'जो कुछ उधर हो रहा है उस की ओर आँखें मत बंद रखिये.' धरती पर एक नये सौर युग की संभावना के बारे में उन्होंने एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक डा. प. क. आईंगर के विचार दोहराते हुए कहा कि विज्ञान के नवयुग में महान और विचित्र संभावनाएँ उभर सकती हैं. 'यदि हम सूर्य की नकल करने में सफल होते हैं तो आज के तकनीकी युग की सब से जटिल चुनौती, ऊर्जा समस्या का समाधान तो सरल ही हो जायेगा.'

## कवियों का मौसम

बेताल मौसम में एक स्पष्ट ताल भी उभरी और अभी तक उभर रही है. और उसे नाम दिया है एक मित्र ने कवियों का मौसम. विख्यात पंजाबी कवियत्री अमृता प्रीतम भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार-भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता घोषित हुई. हिंदी के कवि बाल स्वर्ण राही भारतीय ज्ञानपीठ में नियुक्त हुए तथा रियाद (सऊदी अरब) से हिंदी और उर्दू के बीच की दीवार को तोड़ने में जुटे 'नम्रता' उपन्यास के लेखक और उर्दू के युवा कवि सलाहूद्दीन परवेज राजधानी में पधारें. कुछ पाकिस्तानी कवि भी राजधानी में पधारें और उन्हें निजामुद्दीन में गालिब एकेडमी में सम्मानित किया गया. सुना गया है कि एक हिंदी कवि शायद राजदूत नियुक्त होने जा रहे हैं.

परवेज साहिब ने बताया कि अब वह लोरियों को साहित्य में उचित स्थान प्रदान करने के प्रयास में लगे हैं. उन का कहना है कि वह लगभग 50 के करीब आधुनिक लोरियाँ लिख चुके हैं और उन की लोरियों का संग्रह इसी वर्ष छपेगा. उन्होंने एक 'लोरी हिंदुस्तान की' भी लिखी थी जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्पित की और जिस में भारत के बच्चों को अपने देश के चित्र महात्मा गांधी, नेहरू और गांधी के चित्रों में दिखाने का प्रयास किया.

## पुछल्ला

दिल्ली की स्त्रियाँ ताव में हैं. उन का कहना है कि युगों तक तो साहित्यकार और राज-नीतिज्ञ उन्हें 'अबला' बना कर पेश करते रहे अब दिल्ली परिवहन ने उन्हें 'अपंगों' की बिरादरी में मिला दिया. ताव का कारण है परिवहन की बसों में शिष्टाचार आंदोलन के अंतर्गत अंकित यह संदेश 'माई चारा किस के संग? नारी, बच्चे और अपंग.' □



सलाहूद्दीन परवेज दिल्ली से अलीगढ़ भी गये : प्रशंसकों ने फूल बरसा कर स्वागत किया

सऊदी अरब तक प्रशांत महासागर पार कर के. उस का संबंध तो कहीं इस मौसम परिवर्तन से नहीं है? बादल धरती से 15 मील की ऊँचाई पर उड़ रहा था और उस की मोटाई दो मील की थी. जब एक थू-2 विमान लालक ने, जो अमेरिका के अंतरिक्ष तथा अड्डयन संस्थान (नासा) के लिए मौसम निरीक्षण उड़ान पर था उसे देखा. पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ पता नहीं यह ज्वालामुखी का मेघदूत कहाँ जा कर दम लेगा और इस का प्रभाव मौसम और वातावरण पर क्या होगा. अभी तक तो जहाँ तक यह ज्वालामुखी का तापमान में कमी हुई और आकाश में रंग बदल लिया. हवाई द्वीप पर नीला आकाश गंदला पड़ गया. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं. अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे. कुछ मो परिणाम निकलें अंत में इन बेताल बदलियों पर अभी तो उर्दू के एक शायर के शब्द ही याद आते हैं. 'आयी बरसात तो पानी से रोना आया.'



## आँधी आँधी की टक्कर

दिल्ली के राजनैतिक सम्मेलनों के इतिहास में पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिस का ऐतिहासिक महत्त्व आगे चल कर आँका जायेगा, यद्यपि राष्ट्रीय अखबारों ने उस की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। यह था रोटी, जनवाद और आजादी के नाम पर निरंकुशता विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन जिस में सारे देश के 200 जनसंगठनों के 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन 24-25-26 अप्रैल को हुआ—दो दिन प्रतिनिधियों की सभा और आखिरी दिन, 26 को खुला अधिवेशन। 26 को ही सारे देश के काफी शहरों और कस्बों में दिल्ली के इस सम्मेलन के समर्थन में स्थानीय जनसंगठनों—किसान मजदूर सभाओं—की ओर से रैलियाँ की गयीं और आगे हर 26 अप्रैल को तानाशाही विरोधी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में एक मसविदे पर प्रतिनिधियों की बातचीत हुई और उस बातचीत के फलस्वरूप एक मोर्चे की स्थापना हुई जिस का नाम भारतीय जन मोर्चा (इंडियन पीपुल्स फ्रंट) रखा गया जिस के अध्यक्ष बिहार के कवि किसान कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी रमताजी चुने गये और उपाध्यक्ष तमिपनाडु के मजदूर कार्यकर्ता एस. नटराजन तथा मुख्य सचिव बिहार के राजाराम और जिस का उद्देश्य सामंतवाद, साम्राज्यवाद और निरंकुश ताकतों के खिलाफ सतत संघर्ष घोषित किया गया। मोर्चा किसी राजनीतिक दल के प्रत्यक्ष प्रभाव में नहीं है और न ही यह मानता है कि केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टियाँ ही राष्ट्रीय विकल्प हो सकती हैं—इस से कुछ आशा बंधती है कि मोर्चा एक व्यापक और साथक राष्ट्रीय जन समर्थन प्राप्त कर सकेगा। एक सही लोकतंत्री समाज की स्थापना के लिए मोर्चा किसान और मजदूर संघर्ष के ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार करता है और यह भी मानता है कि जिन राजनीतिक दलों ने सामंतशाही के खिलाफ संघर्ष नहीं किया है आगे चल कर उन का निरंकुश दलों का रूप ले लेना निश्चित ही है। मोर्चे के गठन के समय प्रतिनिधियों के समवेत स्वर में भारत के सभी प्रांतों के अलावा, मेघालय, मिजोरम, असम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे सुदूर प्रांतों के स्वर भी थे।

यह स्तंभकार पहले और दूसरे दिन की उन की बैठकों की कार्यवाही को एकाध घंटे देख सका और इस ने पाया कि प्रतिनिधियों की चिंता लड़ाई के आकार को छोटा कर के देखने की नहीं है, चाहे वह रूसी और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हो, चाहे भारतीय सामंतवाद के, चाहे वर्तमान निरंकुशता और

के. उस का मानना है कि यह लड़ाई व्यापक है और पूरे जन के साथ लचीली और खुले रूप में ही लड़ी जा सकती है जिस में किसान मजदूर ही नहीं देश का बुद्धिजीवी भी शामिल होगा।

लेकिन यह स्तंभकार फिरोजशाह कोटला ग्राउंड के विशाल शामियाने में जहाँ ये डेढ़ हजार प्रतिनिधि ठहरे थे मय औरतों और बच्चों के, उन का सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा बहुत देख सका जिस में बिहार, बंगाल तथा अन्य प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने जनवादी गीत और जनवादी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किये। उन को संभ्रांत कला से जोड़ कर देखना उन के साथ अन्याय है लेकिन ये लोक कला के, बिना समय के लंबे प्रवाह में कटे छटे, खूबसूरत कच्चे नमूने थे जिन में आज के जनमानस के आग की आँच देखी जा सकती थी। क्या होगा इन मोर्चों से, राजनीतिक दलों की आज की हालत देख कर यह सवाल मन में उठना स्वाभाविक था और उठ भी रहा था। मन कुछ थमा था, पर कुछ निराशा से भी भरा था कि अचानक आँधी आ गयी। यह 24 अप्रैल की शाम थी। इतनी जबरदस्त आँधी की शामियाना जोर जोर से हिलने और उड़ने लगा। क्या देखते हैं कि सैकड़ों बाँस जिन से शामियाना बँधा हुआ टिका है प्रतिनिधियों ने पकड़ लिए हैं। एक एक बाँस आठ-आठ दस-दस प्रतिनिधियों ने पकड़ रखे हैं। जमीन पर टिके उन बाँसों को कोई टस से मस नहीं होने दे रहा है। आँधी शामियाना उपर खींच रही है, वह फूल रहा है पर जनप्रतिनिधि उन्हें नीचे रोके हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम गाना बजाना चल रहा है—‘समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आयी।’ आँधी के साथ फिर जोरदार बारिश भी—चारों ओर से बौछारें, बिजली मकभकाने लगी, फिर अँधेरा, आग लगने के डर से बिजली के तार काट दिये गये—डेढ़ घंटे अँधेरे में उस मुसलाधार वर्षा और आँधी से ये लड़ते रहे। अँधेरे में केवल ‘इंकलाव जिंदावाद’ की आवाजें आती रहीं। जब आँधी-पानी रुका तो सब भौग गये थे। पर शामियाना उन्होंने उड़ने नहीं दिया था। केवल एक कोने में वह कुछ लटक कर सहम गया था। अँधेरे में ये आवाजें सब कुछ बचाए रहने के संगठित संकल्प के साथ अब जब भी तेज आँधी तूफान आता है इस स्तंभकार को सुनायी देने लगती हैं और ऐसे समाचारों के बीच जैसे—चंडीगढ़ में विरोधी राजनीतिक दलों की एकता-वार्त्ता-सम्मेलन का पंडाल उड़ गया—कुछ आशा जगाती हैं कि जो पेशेवर राजनीतिक दलों के लोग नहीं हैं, आम किसानों और मजदूरों के बीच से आए लोग हैं, अपने संकल्प और एकता से किसी भी आँधी को टक्कर दे सकेंगे उस की निरंकुशता नहीं चलने देंगे। यह स्तंभकार आँधी से आँधी की ऐसी टक्कर का स्वागत करता है।

## वह मर कर भी अपनी हँसी दे गयी

रमेशदत्त शर्मा

‘सटर्डे रिव्यू’ के संपादक नार्मन कजिस को सन् 1964 में डाक्टरों ने रीढ़ की बीमारी बतायी और सलाह दी कि लिखा पढ़ना छोड़ कर आराम फरमाइए। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि बचने की उम्मीद बहुत कम थी। 500 में से एक रोगी ही बच पाता है। लेकिन शायद कजिस को अहसास था कि उनकी बीमारी की जड़ क्या है। लिहाजा उन्होंने संपादकीय आपाधापी से छुट्टी ली। होटल में कमरा बुक कराया और हास्य व्यंग्य का साहित्य और चुटकले पढ़ना और हँसी मजाक वाले फिल्मों देखना शुरू किया। बस फिर क्या था, सात दिन संपादक जी पेट भर हँसते और रात को कम से कम दो घंटे की गहरी नींद लेते। इससे पहले उन्हें नींद की गोलियाँ भी मुश्किल से आधा पौन घंटा सुला पाती थीं। हँसी की वजह खुराक संपादक जी ने नियमित रूप से ली। कुछ साल में उन का रीढ़ रोग गायब हो गया।

हँसने के इस स्वास्थ्यदायक प्रभाव पर काफी गंभीर अनुसंधान हुए हैं और होते रहते हैं। जब आप हँसते हैं तो जबड़े की मांसपेशियों का ही नहीं, आप की पसलियों, छाती, आमाशक, दिल, फेफड़े और जिगर का भी खासा व्यायाम



हो जाता है। हृदय की मांसपेशियाँ हँसने से इतनी चुस्त दुरुस्त हो जाती हैं कि उस का धड़कना अपनी सही रफ्तार पकड़ लेता है—एक मिनट में कोई 72 बार। हँसते हँसते आप ने देखा होगा कि चेहरा लाल हो जाता है। यानी आप की धमनियों में खून तेजी से दौड़ता है। यहाँ तक कि आपकी साँस की नली में कुछ अटका है तो वह भी हँसते हँसते बाहर निकल जायेगा। अगर हँसी इतने जोर की उठी है कि आप हँसते हँसते दुहरे हो जायें तो चेहरे की हड्डी नहीं, पूरे शरीर की अच्छी कसरत हो



जाती है. तनाव, कुंठा, उदासी, घुटन, संत्रास, जब 'लाफिंग गैस' तक उन्हें खिलखिलाने पर मजबूर नहीं कर सकी. जब भी बेचारा हँसना चाहता तो उस का चेहरा ऐंठ कर रह जाता. पर मुस्कान नहीं उभरती. ऊपर से रक्तचाप भी गिर जाती और नब्ब बहुत धीमी हो जाती. लेकिन अब जाक हँस सकता है. म्यूनिख के ग्रससेडन क्लिनिक के डाक्टर वॉलेंटिन कार्ल ने

38 वर्षीय स्त्री एंटनी के जबड़े की हास्य पेशी निकाल कर जाक के जबड़े में रोप दी. यूरोप में इस तरह का यह पहला आपरेशन था. जिस स्त्री की हास्य पेशी निकाली गयी, उसे वचपन से ही बेहद हँसने की बीमारी थी. अंत में टी. वी. पर एक मनोरंजक कार्यक्रम ने उसे हँसाते हँसाते मार डाला. पर मरने के बाद भी वह अपनी हँसी जाक को दे गयी.

## उनका कहना है



इस्लाम में हजामत बनाना हराम है : जनरल जिया उल हक को मार्शल लॉ के तहत आवेश जारी कर देना चाहिए कि सभी सैनिक नागरिक और अवाम बाढ़ी रखें. बाढ़ी रखने से पाकिस्तानियों की इस्लाम में आस्था तो जाहिर होगी ही, साथ ही जो समय और ताकत बाढ़ी बनाने में खर्च होती है वह मुल्क की तामीर में काम आयेगी.

'पाकिस्तान टाइम्स' में एक पाठक का खत.

रेलगाड़ियाँ अपराधियों का अड्डा बन कर रह गयी हैं.

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के श्री आर. एस. शास्त्री रेलों में अपराध पर लोकसभा की बहस में.

में समझता हूँ सहज प्रवृत्तियों पर सेंसर से कुछ सुधार हो सकता है पर अंततः सब कुछ जनता की रुचि पर ही निर्भर है. सस्ती और फूहड़ फिल्मों के विरुद्ध जनता को ही अपना निर्णय देना है.

राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 29 वें फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में.

यदि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता, अमेरिकी विदेशमंत्री श्री हेग ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका—ब्रिटेन का साथ देगा.

ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टेंचर फाकलैंड संकट पर ब्रितानी लोकसभा में.

हम भारत सरकार पर फिर से बातचीत करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं. जो वक्त और तारीख भारत को अनुकूल पड़े वह तय कर ले. हमने तो यह सब उसी पर छोड़ दिया है, हमें कोई जल्दी नहीं है.

पाकिस्तान के विदेशमंत्री श्री याकूब खां इस्लामाबाद हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए.

भारतीय विमान सेवा के कर्मचारी जनता की सेवा के बजाय अपनी सेवा में अधिक विश्वास करते हैं.

भारतीय विमान सेवाओं के 1976 से 81 तक के कार्य पर सार्वजनिक लेखा समिति की रपट.

भारतीय संगीत आत्माहीन हो गया है. अब उस के नाम पर शोर शराबा है.

संगीत निर्देशक नौशाद—दादा साहब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के बाद दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए.

पंजाब में पृथक्तावाद प्रवृत्तियाँ फैलाने वाले कुछ मुठ्ठी भर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है. इन का इलाज भारतीय परंपरा के अनुसार यही है—मुंह काला करो, गधे पर बिठा कर घुमाओ और चौराहों पर कोड़े लगाओ.

खुशवंत सिंह पंजाब की स्थिति पर राज्यसभा की बहस में.

सरकार इस सुझाव पर विचार कर इसे लागू करने की कोशिश करेगी. गृहमंत्री श्री जैल सिंह का जवाब.

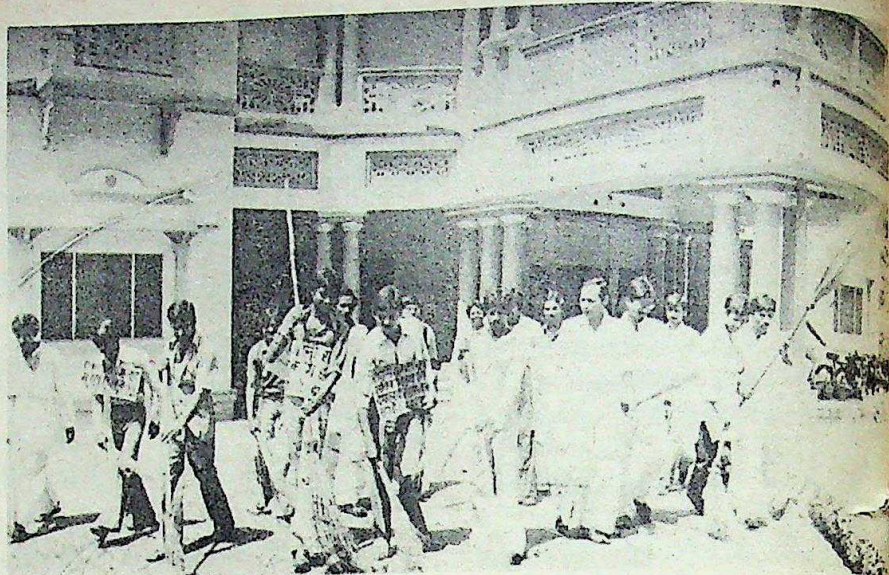


## बीमार कारखाने की बैचैनी

पिछले दिनों काशी विश्वविद्यालय में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी और लोग अनिश्चित कालीन बंदी का अनुमान लगाने लगे। छात्रसंघ के अध्यक्ष शिवकुमार, गैरशिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र त्रिपाठी ने अपनी अपनी जमात की माँग को मनवाने के लिए 16 अप्रैल से आमरण अनशन पर जाने की घोषणा कर दी और निश्चित तिथि पर अनशन पर बैठ भी गये। छात्र संघ अध्यक्ष की माँग थी कि विश्व-विद्यालय स्थित अस्पताल में छात्रों के लिए 'स्टूडेंट वाड' पुनः स्थापित किया जाये, सत्र को नियमित किया जाये और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जाँच करायी जाये। छात्रसंघ अध्यक्ष की इस माँग का सभी छात्रसंगठनों ने समर्थन किया। छात्रसभा के रामकृष्ण चौबे ने छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ अनशन पर बैठने के पूर्व छात्रसभा की आपात बैठक बुला कर संगठन की तरफ से संपूर्ण समर्थन की घोषणा जारी कर दी। इसी तरह जनता विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, समाजवादी युवजन सभा, युवा जनता, छात्रजनता, छात्र संगठन (आई) ने भी सक्रिय समर्थन के साथ अपने दो दो प्रतिनिधियों को अनशन पर बैठाया। सभी संगठनों का जुलूस छात्रसंघ से उठ कर मुख्य द्वार पर बढ़ा जहाँ मालवीय जी की प्रतिमा के पास आम सभा में बदल गया। छात्र-सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्रसंघ के भू. पू. अध्यक्ष चंचल ने अनशनकारियों को माला पहना कर अनशन पर जाने की घोषणा की। इसी मंच से सभी संगठनों के कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया और साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का संकल्प दुहराया। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र त्रिपाठी, समान कार्य के समान वेतनमान का निर्धारण, वखास्त कर्मचारियों की वापसी और अन्य तैतालिस माँगों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गये। पूरा विश्वविद्यालय नारों से गुँजता रहा। अध्यापक संघ को छोड़ कर बाकी पूरा विश्वविद्यालय आंदोलित हो उठा।

विश्वविद्यालय प्रशासन अभी इन समस्याओं की खोजबीन कर हल निकालने में व्यस्त ही था कि छात्रसभा ने एक नये आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस संगठन के लगभग 35 छात्र हाथ में झाड़ू टोकरी लिए पीठ पर अलग अलग नारों की तख्तियाँ लटकाये सड़क पर उतर आये और प्रशासन से माँग करने लगे कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हम उन की माँग का समर्थन करते हैं। उन की माँग

दिनमान



विश्वविद्यालय में सफाई कर रहे छात्र सभा के सदस्य



तीन अध्यक्ष : मोहन प्रकाश, शिवकुमार, चंचल

जायज हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को गंदा नहीं होने देंगे। हमारे दो हाथ हैं हम अपनी सफाई खुद करेंगे लेकिन जिन जगहों से गंदगी निकल कर पूरे विश्वविद्यालय में फैलती है, पहले हम उसे साफ करेंगे, कुलपति निवास और केंद्रीय कार्यालय को इस गंदगी का प्रतीक माना गया और छात्रों ने यहाँ सफाई का कार्य शुरू किया। कुलपति डाक्टर इकबाल नारायण और कुल-सचिव रमेश चंद्र प्रताप सिन्हा के हस्तक्षेप से सफाई में लगे इन छात्रों के बीच वार्ता शुरू हुई जिस में छात्र पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि हमारी पढ़ाई मात्र अक्षरज्ञान की है, इसे रोज-गार से जोड़ा जाये और हमें केंद्रीय श्रमबोर्ड नियम के तहत 11 रु. 65 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से दिये जायें और उन तमाम छात्रों को रोजगार दिया जाये जो पढ़ाई के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए काम करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन सहमत हो गया और उस ने पंजीकरण के प्रथम चरण में पैंतीस छात्रों को पंजीकृत किया। इस की जिम्मेदारी छात्र अधिष्ठाता डा. गलगली को देकर कहा गया कि इन्हें रोजगार देने और मुद्रा व्यवस्था

का इंतजाम करने की जिम्मेवारी केंद्रीय कार्यालय की होगी।

विश्वविद्यालय सफाई कर्मचारी जिन का कुल तादाद 800 के लगभग है, के बारे में छात्रसभा के चंद्रशेखर, रामकृष्ण चौबे, अशोक अरुण मालवीय, प्रमोद मिश्र ने संयुक्त माँग-पत्र जारी कर कहा कि 'परिसर में गंदगी का कारण कर्मचारी नहीं हैं बल्कि टाउन कमेटी के सचिव के.के. शुक्ला हैं, जिन के अग्र दवाइयों को बाहर बेचने, पान वाले, ग्वाला गुमटी के दुकानदारों से खिखत ले कर गंदगी फैलाने की जिम्मेदारी है। इस की जाँच हो जाये और उन्हें तत्काल किसी और विभाग में भेजा जाये।' माँग में कहा गया कि विश्वविद्यालय में कुल 15038 छात्र-छात्राओं 2600 कर्मचारियों, 1700 अध्यापक, अधिका-रियों के स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालय का कुल एक लाख सतहत्तर रुपया व्यय होता है जिस में से 5000 रु. केवल आवांरा कुतों के पकड़ने पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। इन लोगों की माँग थी कि '77 से इस घोटाले की जाँच करायी जाये। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक जाँच समिति की घोषणा भी कर दी।

रपट लिखने तक स्थिति सामान्य होने के समाचार मिले हैं, अध्यक्ष माँगें मान ली जाने से अनशन समाप्त कर चुके हैं छात्रों को आंशिक रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। 9 वर्गमील के अहाते में फैले 24 करोड़ सालाना बजट के इस विश्व-विद्यालय में जहाँ 16000 छात्रों, 2600 कर्मचारियों एवं 1700 अध्यापकों को मिला कर कुल एक लाख की आवादी है, समस्याओं का उठना स्वाभाविक है, लेकिन शिक्षा की सार्थकता से जुड़ा सवाल कब उठेगा? कौन उठायेगा?



राष्ट्र

सांप्रदायिकता

## सिख राजनीति का नया दौर

पिछले वर्ष 9 सितंबर को लाला जगत-नारायण की हत्या के पश्चात पंजाब में हत्याओं का एक दौर शुरू हुआ था, जो इस वर्ष के शुरू में कुछ कमजोर पड़ता दिखायी दिया। मगर पिछले माह की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा की यह राजनीति काफी गहराई में जड़ें पकड़ चुकी है। 26 अप्रैल को कटरा अहलूवालिया और बाजार काठियाँ के मंदिरों के सामने गायों के कटे हुए सिर टंगे हुए पाये गये और यह अनुमान लगाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई कि इस जघन्य अपराध के पीछे भी वही तत्त्व काम कर रहे हैं जो पंजाब में सांप्रदायिक राजनीति को राजनैतिक सत्ता हासिल करने का हथियार बना रहे हैं। यह स्वामाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया शहर में और शहर से बाहर पंजाब और पड़ोस के कई राज्यों में होती। असल में इसी प्रतिक्रिया के लिए यह अपराध किया गया था। यह घटना अन्य घटनाओं से अलग थलग तो थी नहीं। इसका प्रमाण पंजाब के दो संपादकों को मिले हुए पार्सल हैं जिनमें इन्हीं गायों के कान काट कर भेजे गये थे। पंजाब के संपादक रमेशचंद्र को यह भी याद दिलाया गया था कि उनके पिता लाला जगत नारायण की हत्या भी इसी उद्देश्य से की गयी थी।

प्रदर्शनों और विरोधी प्रदर्शनों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियों और गोलीचालन का सहारा लेना पड़ा है जिस से शोध दर्जन से भी अधिक लोग मारे गये और पांच सौ से अधिक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए हैं। केंद्रीयमंत्री जैलसिंह और नारायणदत्त ने बारी, गृहसचिव चतुर्वेदी और विधानसभा के अध्यक्ष वृजमूषण मेहरा तथा मुख्यमंत्री सरवासिंह द्वारा अमृतसर में शांति जुलूस निकालने के बावजूद पंजाब के शहरों में तनाव कायम हुआ है, क्योंकि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि अपराधियों को सख्त सजा दी जायेगी लोगों को विश्वास नहीं है कि वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में पंजाब सरकार और केंद्रीय सरकारों की स्थिति को काबू में कर पायेंगे। इस विश्वास का सब से बड़ा उदाहरण यह है कि पंजाब के प्रमुख शहरों में व्यापार में काफी रुकावट आ गयी है और उद्योगपति पूंजी लगाने से रुक रहे हैं। इस बात के समाचार भी मिले हैं कि कई उद्योगपति अपने व्यापार को पड़ोस



अमृतसर का स्वर्ण मंदिर : सिख राजनीति का केंद्र?

के राज्यों हरयाणा और हिमाचलप्रदेश ले जाने की योजनाएँ बना रहे हैं।

यह विचित्र बात है कि अपने राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ उग्र-वादियों ने ऐसे दो संप्रदायों के बीच नफरत पैदा कर दी जिनका सांस्कृतिक आधार एक ही है। सब से विचित्र बात तो यह है कि सिख संप्रदाय उसी प्रकार गाय को पवित्र मानता रहा है जिस प्रकार गैर सिख हिंदू, यद्यपि गुरुग्रंथ साहब में इस सिलसिले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है—और वह इस लिए नहीं है कि ग्रंथ साहब संतवाणियों का एक वृहत् संकलन है। जिस में सामाजिक आचार संहिताएँ शामिल नहीं की गयी हैं। मगर विभिन्न गुरुओं द्वारा मौखिक और लिखित रूप में इस सिलसिले में जो उपदेश दिये गये हैं उन से इस बात में कोई भी संदेह नहीं रहता कि गाय के प्रति आदर की भावना सिख संप्रदाय के लिए अनिवार्य घोषित की गयी है। इस सिलसिले में दसवें गुरु गोविंदसिंह जी के आदेश सब से स्पष्ट हैं। इस लिए यह प्रश्न अनायास ही पैदा होता है कि अपने आप को कट्टर सिख कहने वाले कुछ उग्रपंथियों ने एक ऐसा काम कैसे कर डाला जो मूलतः उनकी अपनी धार्मिक मान्यताओं के भी विरुद्ध है। इसके लिए पिछले कई वर्षों में पंजाब में हुए सांप्रदायिक राजनीतिकरण को समझना होगा।

पंजाब में सिख राजनीति के कई दौर आये और गुजर गये। प्रतापसिंह कैरों के जमाने में मास्टर तारासिंह और बाद में संत फतेहसिंह ने भाषायी मसला उठा कर पंजाब की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था। उस समय यद्यपि राजनीति का सांप्रदायिकीकरण शुरू हो गया

था फिर भी प्रमुख हथियार उस समय पंजाबी भाषा को बनाया गया। पंजाब के बंटवारे के पश्चात यह दौर समाप्त हुआ मगर जिस सांप्रदायिकता ने राजनीति का स्वाद चखा था वह नये मुद्दे खोजने की कोशिश करने लगी। ये नये मुद्दे हाल ही में दल खालसा के नारों के रूप में प्रकट हो गये। अकाली दल के कई गुटों में बंट जाने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। जत्येदार जगदेवसिंह तलवंडी द्वारा विश्व सिख सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाना उसी प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा है जो अकाली गुटों के बीच एक दूसरे को पोछे खदेड़ने के लिए शुरू हो गयी थी। इस कार्रवाई से प्रेरित हो कर एक कदम और आगे बढ़ने के लिए संत हरचरण लोंगोवाल ने सतलुज-यमुना नहर को ही रोकने की घोषणा की, हालाँकि यह कार्रवाई वह कर नहीं सके। फिर भी इस से यह तो स्पष्ट हो गया है ये अलग अलग गुट किस हद तक कृत्रिम मुद्दे उठा कर उत्तेजना फैलाने की कोशिश कर सकते हैं।

इसी संदर्भ में अमृतसर में सिगरेट और पान की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का सवाल भी उठाया गया है। इस सिलसिले में यह बात महत्वपूर्ण है कि सत्तारूढ़ इंदिरा कांग्रेस के विभिन्न पक्षों ने भी इस आग में घी डालने का ही काम किया। उदाहरण के लिए संत जरनैल सिंह मिडरावाला और गंगासिंह ढिल्लों के प्रति जो नरमी सत्तापक्ष ने दिखायी उस का कोई कारण दिखायी नहीं देता। श्री तलवंडी ने अपनी राजनैतिक अवसरवादिता की मिसाल इस बात से भी दिखायी है कि पंजाब के मामले में जामा मस्जिद के इमाम को भी खींच लिया है यद्यपि इमाम का अमृतसर के मामले



में न तो प्रत्यक्षतः कोई स्वार्थ होना चाहिए और न वहाँ उनका कोई योगदान हो सकता है।

पंजाब सरकार कुछ तो केंद्रीय गृहमंत्रालय की नरमी के कारण और कुछ व्यावहारिक कारणों से समय पर शरारती तत्वों को काबू करने में सफल नहीं रही। सब से बड़ा कारण तो यह है कि यह शरारती तत्व प्रायः गुहद्वारों में शरण लेते रहे हैं। हालाँकि गुहद्वारा प्रबंधक समिति के नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर में किसी अपराधी को शरण नहीं दी जाती। पंजाब मुख्यमंत्री और शिरोमणि गुहद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहड़ा के बीच यह विवाद काफी दिनों से चलता आ रहा है। मगर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह राजनैतिक आंदोलन चलाने वाले लोग गुहद्वारों में शरण प्राप्त करते हैं। भारतीय विमान के अपहरण का उत्तरदायित्व दल खालसा ने लिया था। इस दल के मुख्य पंच हरसिमरन सिंह ने स्वर्ण मंदिर के अहाते में ही संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर टोहरा दावा कर चुके थे कि दल खालसा का कोई व्यक्ति स्वर्ण मंदिर में नहीं है। स्वर्ण मंदिर के अहाते में गुरनानक निवास नाम की सराय है जिस में तीर्थयात्रियों के रहने के लिए एक सप्ताह तक कमरे दिये जाते हैं। निरंकारी बाबा की हत्या के पश्चात् जर्नेलसिंह भिडरावाला इसी सराय की ऊपर वाली मंजिल में ठहरे हुए थे। इसी प्रकार खालिस्तान की राष्ट्रीय परिषद की घोषणा भी इसी निवास के एक कमरे से की गयी। एक छोटा ट्रांसमीटर सेट भी इस में ही स्थापित किया गया था।

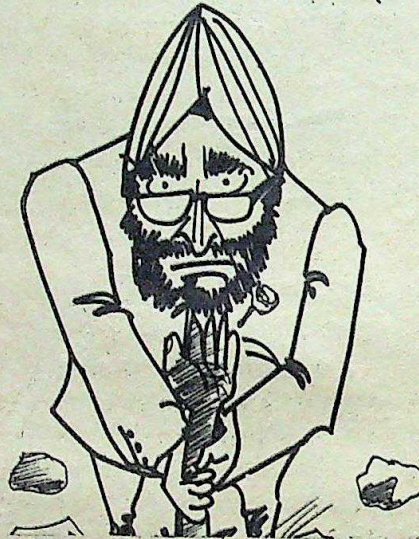
दल खालसा के सदस्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इस का संकेत उन्होंने काफी पहले दिया था। मार्च में ही इस दल के कुछ सदस्यों ने यह चेतावनी दी थी कि अगर अमृतसर में सिगरेट बीड़ी की बिक्री बंद नहीं की गयी तो वह अमृतसर में ही गौहत्या करेंगे।

यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार दल खालसा की गतिविधियों के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखती थी, फिर भी इनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। केंद्रीय गृहमंत्री जैलसिंह किसी भी रूप में दल खालसा पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं। यद्यपि दरबारासिंह का तर्क था कि बिना कानूनी प्रतिबंध लगाये प्रभावशाली प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। सब से पहले प्रतिबंध की माँग भारतीय विमान के अपहरण के बाद उठायी गयी। उस समय जैलसिंह ने इस माँग को रद्द कर दिया। 26 अप्रैल की घटना के बाद फिर से यह माँग मुख्यमंत्री की ओर उठायी गयी फिर भी गृहमंत्री ने प्रतिबंध लगाने में अनाकानी की। गृहमंत्री का दावा था कि दल खालसा के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं है। इस लिए उन

बिनमान

के विरुद्ध किसी असाधारण कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। मगर पिछले दो-तीन की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही दल खालसा के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने में बहुत ही खतरनाक भूमिका निभा सकते हैं, इस लिए केंद्रीय सरकार ने दल खालसा और नेशनल काउंसिल पर प्रतिबंध लगा दिया।

मंदिरों को अपवित्र करने की घटना की निंदा दोनों अकाली दलों और गैर अकाली सिखों ने की है। मगर इस निंदा से भी काम नहीं बन सकता। अपराधियों को गिरफ्तार तो किया ही जाना चाहिए। उसके साथ ही पंजाब में दोनों संप्रदायों के उदारवादी लोगों को खुल कर सामने आना चाहिए, क्योंकि पिछले माह जैसी



घटनाएँ यदि दुबारा हुईं और दूसरे संप्रदाय की ओर से इस की जवाबी कार्रवाई की गयी तो न केवल पंजाब बल्कि आसपास के सभी राज्यों में घृणा की यह आग फैल जायेगी। यह जरूरी है कि पंजाब का उदारवादी सिख और गैरसिख तमाशाही बन कर पीछे न रहे क्योंकि इस प्रदेश की शांति में सब से ज्यादा स्वार्थ उन्हीं का है। इस सिलसिले में यह बात महत्वपूर्ण है कि अपराधियों को धार्मिक नेताओं और गुहद्वारों का सहारा प्राप्त नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार इस सिलसिले में यदि सख्ती से काम नहीं लेती तो प्रतिबंध का कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं हो सकता। पिछले कुछ माह में पंजाब की सांप्रदायिक शांति जिस तेजी के साथ बिगड़ी है उस के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है और इसी लिए कई क्षेत्रों में यह माँग बड़े जोरों से उठायी जा रही है कि दरबारासिंह सरकार को बर्खास्त किया जाये। पंजाब के राष्ट्रीय राजनैतिक दल वर्तमान संकट की घड़ी निष्क्रिय से हो गये हैं, सच तो यह है कि इन राष्ट्रीय दलों की राजनैतिक गतिविधियों में उत्तरोत्तर ह्रास और आम जनता के साथ संपर्क का अभाव भी वर्तमान संकट का एक बड़ा कारण है। पिछले सात माह में हत्याओं

का जो सिलसिला चला है उस में अपराधियों को सजा न दे पाने के कारण राज्य सरकार की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है। केंद्रीय सरकार का बार बार यह कहना कि इन घटनाओं के पीछे विदेशी हाथ हैं बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। इस भायने में तो विदेशी हाथ है कि दल खालसा के जो समर्थक भारत से बाहर खालिस्तान का प्रचार कर रहे हैं उन्हें कुछ विदेशी ताकतें आर्थिक और राजनैतिक सहायता प्रदान कर रही हैं। मगर 'विदेशी हाथ' पर ही सारा उत्तरदायित्व डाल कर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने से समस्या का हल नहीं निकल सकता। प्रमुख रूप से कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार और केंद्रीय गृहमंत्रालय का काम है। और यदि गृहमंत्री ज्ञानी जैलसिंह और मुख्यमंत्री दरबारासिंह एक दूसरे को नीचा दिखाते के लिए स्थिति को बिगड़ने दें तो विदेशी हाथ इन घटनाओं के पीछे हो न हो गैर जिम्मेदार राजनैतिक आचरण का योगदान तो साफ दिखायी देता है।

## आनंदमार्ग

### क्रुद्ध भीड़ की हिंसा

चुनावों से केवल 19 दिन पहले कलकत्ता के कस्बा वालीगंज क्षेत्र में क्रुद्ध भीड़ द्वारा 26 (सरकारी आँकड़ा 17) आनंदमार्गियों की हत्या को ले कर राजनैतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की प्रक्रिया तो जोर शोर से जारी है ही, स्वयं आनंदमार्गियों द्वारा घटना की गहराई से जाँच और दोषी व्यक्तियों को दंडित किये जाने के मूल विषय से हट कर पश्चिम बंगाल की माकपा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहरा कर सरकार को हटाये जाने की माँग पूरी घटना को एक अलग ही ढंग से देखने को विवश कर देती है।

प. बंगाल में आनंदमार्ग का विरोध कोई नया नहीं है। इस से पूर्व 1965 में भी पुरुलिया जिले में पाँच आनंदमार्गियों की हत्या की गयी थी। पिछले दिनों कलकत्ता स्थित आनंदमार्गियों के मुख्यालय जागृति केंद्र में सप्ताह भर के लिए जो सम्मेलन हुआ, उस में दिल्ली के निर्देश पर कई विदेशी प्रतिनिधियों को कलकत्ता में ही नहीं घुसने दिया गया। लेकिन इस घटना में बिना किसी आधार के राज्य सरकार को दोषी मान कर सरकार की बरखास्तगी और तिलजला क्षेत्र में माकपा विधायक की गिरफ्तारी की माँग घटना की जाँच के महत्व को ही खत्म कर देती है। चाहे वह आनंदमार्गियों की माँग पर केंद्र द्वारा गठित कोई स्वतंत्र जाँच आयोग ही क्यों न हो। राज्य द्वारा गठित किये गये जाँच आयोग को तो किसी भी प्रकार



## “हमारा कोई दुश्मन नहीं”

आनंदमार्ग के प्रवर्तक आनंद मूर्ति (वास्तविक नाम प्रभात रंजन सरकार) ने कलकत्ता में आनंदमार्गियों पर हुए बर्बर हमलों पर, जिन में गत 30 अप्रैल को लगभग 26 आनंदमार्गी मारे गये (सरकारी आँकड़े 17 मृतकों के हैं) अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा : ‘मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस (इं) किसी भी दल को अपना दुश्मन नहीं समझता।’ आनंदमूर्ति को एक संवाददाता ने उन के दक्षिण कलकत्ता में लेक गार्डन स्थित निवास पर एक लिखित प्रश्नावली दी जिस के लिखित उत्तर में उन्होंने यह बात कही।

आनंदमूर्ति से यह पूछा गया था कि आनंदमार्गी इस हत्याकांड के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इस से पहले भी मार्क्सवादियों पर ये आरोप लगाये गये हैं। आप लोगों ने

इंका पर भी आरोप लगाये हैं कि आनंदमार्गियों के विरुद्ध हैं। लेकिन यह हमला क्यों हुआ और ये हमलावर कौन थे? आखिर में विरोध क्यों कर रहे हैं?

उत्तर में आनंदमूर्ति ने कहा : पिछले एक वर्ष से मैं तिलजिला (जहाँ आनंदमार्गी शिविर है और जिस के आसपास हत्याकांड हुआ) नहीं गया और पिछले 4 अगस्त से अस्वस्थ हूँ। इसलिए वहाँ की घटनाओं के बारे में ठीक उत्तर प्रतिष्ठान के स्थानीय कार्यकर्ता ही दे सकते हैं।

प्रश्न : लेकिन यह हमला और विरोध क्यों?

उत्तर : आनंदमार्गी का अपना धर्म, दर्शन, साधना, मनुष्यता, समाजचेतना निष्ठा और दृढ़ता से उन्नति की ओर है। इस से ईर्ष्यावश कोई क्षमता लोभी व्यक्ति या दल आनंदमार्ग को शत्रु समझ रहे हों तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंदमार्ग किसी को दुश्मन नहीं समझता। बहुत सारी बाधाओं के बाद भी वह अविचलित भाव से संपूर्ण विश्व में अपनी मानव सेवा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।

कलकत्ता से दिनमान प्रतिनिधि ने लिखा केंद्रीय सरकार ने आनंदमार्गियों पर हुए है : हमले और उनकी सामूहिक हत्या के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल भैरवदत्त पांडेय ने भी पुलिस महानिरीक्षक और कलकत्ता पुलिस आयुक्त को बुला कर घटना की जानकारी प्राप्त की।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इस घटना को एक अलग थलग घटना—वर्ल्ड आकस्मिक घटना बताया। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार, इस का राजनीति या चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आनंदमार्गियों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है जिस से इस तरह की कोई घटना न घटने पाये।

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद गोपाल मुखर्जी ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि यह हत्याकांड बाहर से लाये गये तत्त्वों द्वारा एक संगठित योजना के अंतर्गत किया गया है। जनता पार्टी के नेता प्रफुल्लचंद्र सेन ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है। अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की निंदा की है।

आनंदमार्गियों ने इस हत्याकांड के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया है और उन की सरकार से इस्तीफे की मांग की है।

### कानून

## न्यायप्रणाली में परिवर्तन सहमति से ही हो

लक्ष्मीकांत पांडेय, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय।

उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार आर. सुब्बाराव ने 19 अप्रैल, 1979 को उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव के नाम एक पत्र लिखा, जिसे ले कर एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। कुछ लोगों की राय में यह विवाद ‘चाय के कप में तूफान’ की तरह था।

इस विवादग्रस्त पत्र का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार की याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के बारे में अधिवक्ता संघ के सदस्यों के विचार एवं सुझाव जानना था। न्यायाधीशों की ओर से यह प्रस्ताव था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद संविधान के 136 वें अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की गयी याचिकाओं एवं अन्य विविध प्रकार की याचिकाओं पर न्यायालय में सुनवाई करने के बदले न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ मात्र याचिकाओं के लिखित परिचलन के आधार पर उनका निपटारा करेगी।

का सहयोग देने से आनंदमार्गियों ने इनकार कर हो दिया है, केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रति अब तक अपनाये गये ‘लोकतांत्रिक रवैये’ में उन्होंने आस्था ज़रूर प्रकट की है।

इस दर्दनाक कांड में जिन सत्रह आनंदमार्गियों की जान गयी, उन में दो स्त्रियाँ भी थीं। भीड़ ने पहले सामने पड़ने वाले आनंदमार्गियों को बुरी तरह पीटा और बाद में, कुछ के संह पर कपड़ा लपेट कर भी उनके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना के पीछे मुख्य कारण पिछले कुछ समय से आनंदमार्गियों द्वारा शहर के बच्चों का अपहरण बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आनंदमार्गियों ने काफी नागरिकों को अपने बच्चे

आनंदमार्ग संप्रदाय के लिए दान देने हेतु पत्र भी भेजे थे। इस से कलकत्ता के नागरिकों में भय व्याप्त था। आनंदमार्ग ने पूरे देश में लगभग एक हजार अनाथाश्रम बनाये हैं। इन में 120 केवल पश्चिम बंगाल में हैं, जिन में अनाथ बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। कहीं कहीं तो पाँच से भी कम। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय से उन्होंने बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया था। दो दिन पूर्व भी कुछ लोगों ने आनंदमार्गियों को बच्चे चुराते पकड़ा। कुछ माकपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच बचाव से उस दिन मामला पुलिस स्टेशन पर सुलझ गया था।

बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना वाले दिन, 30 अप्रैल को भी सवेरे 7 आनंदमार्गी दो बच्चों को पकड़ कर ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने देखा, फौरन शोर मच गया। लोग सैकड़ों की संख्या में आनन फानन में इकट्ठे हो गये और उन की पिटाई शुरू कर दी। इस के बाद उस स्थल पर जो भी आनंदमार्गी दिखायी दिया भीड़ ने उसे बुरी तरह पीटा, क्षतविक्षत किया और फिर पेट्रोल छिड़क कर उन के शरीर को आग लगा दी। लेकिन भीड़ ने जिस संगठित ढंग से लाठियों और पेट्रोल आदि जलाने की सामग्री के साथ आनंदमार्गियों के मुख्यालय के दोनों रास्तों पर एक ही समय में इकट्ठे हो कर आक्रमण किया, वह अचानक हुआ नहीं लगता। इस को स्वयं माकपा के राज्य सचिव ने भी स्वीकार किया है। इस पूरे कांड में पुलिस की निराशाजनक भूमिका भी आलोचना और जांच का विषय है।



आनंदमार्गियों के कुछ क्षत विक्षत शव



# चुनाव के असली मुद्दे

इंदरजीत, संपादक : इन्फा

चुनाव युद्ध गरमाना शुरू हो गया है। दोनों ओर से शुरुआती गोले छोड़े जा चुके हैं। श्रीमती गांधी ने अभियान शुरू कर दिया है और विरोधी नेताओं ने भी—चौधरी चरणसिंह और अटलबिहारी वाजपेयी ने हरयाणा एवं हिमाचल में तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल और पश्चिमी बंगाल में। चंद्रशेखर और शरद पवार चंडीगढ़ सम्मेलन में गरजे हैं। जगजीवनराम भी मैदान में उतर आये हैं। लगता है मतदाता कुछ उलझन में है क्योंकि सभी पार्टियाँ एक ही राजनैतिक मुहावरे और तर्ज में बोल रही हैं और एक जैसे वायदे कर रही हैं।

कांग्रेस (इं) का घोषणापत्र आ गया है—संक्षिप्त और तेजतर्रार। अखबारों में विज्ञापन भी आये हैं। घोषणापत्र के आरंभ में लिखा है : “संगत तथ्य इस प्रकार हैं। अमी थोड़े ही समय पहले हमारे लोगों ने केंद्र और कई राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकार का अनुभव किया है। पर हुआ क्या? जाँची और परखी नीतियों का परित्याग हो गया। अर्थव्यवस्था बुरी तरह खराब हो गयी। उत्पादन घटा और मुद्रास्फीति की रफ्तार इस कदर थी जैसे आज तक न रही होगी। असामाजिक तत्त्वों पर से नियंत्रण हट गया और अतिवादी संगठनों को प्रतिष्ठित होने का मौका दिया गया।

“हर कहीं सामाजिक तनाव मुखर हो गये, जातियाँ और संगठन एक दूसरे से खुलेआम लड़ने लगे। इस दिशाहीनता ने असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया और देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो गया। इन परिस्थितियों में लोग एक ऐसी सरकार के लिए, जिस के पास लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता समाजवाद आत्मनिर्भर विकास को प्रोत्साहित करने वाली स्पष्ट प्रगतिशील नीतियाँ हों और जो लगातार बढ़ती हुई अनिश्चितताओं वाली इस दुनिया में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा प्रदान कर सके, कांग्रेस (इं) और श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर उन्मुख हुए।”

विरोधियों द्वारा इस के जवाब की तलाश एक दिन मुझे चौधरी

चौधरी साहब के पास उनके बंगले 12-तुंगलक रोड ले गयी। हवा में उत्तेजना व्याप्त थी। चौधरी साहब और उनके निकट के साथी सर्वश्री देवीलाल, बीजू पटनायक तथा कुंभाराम आर्य पिछले दिनों वहाँ इकट्ठे हुए थे। सैकड़ों लोग घर के बाहर विस्तृत मैदान में जमा थे। चौधरी साहब को मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ। वह काफी स्वस्थ और प्रसन्न लग रहे थे। उनसे मेरी आधा घंटे बातचीत होनी थी, पर हमारी बात दो घंटे चली।

चौधरी साहब के अनुसार, चुनाव में जो मुद्दे दाँव पर हैं वे न तो स्थानीय हैं और न प्रांतीय। वे राष्ट्रीय महत्त्व के हैं और उनका संबंध देश की समृद्धि और प्रगति से है। वास्तव में वे ‘भारत के एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व बनाये रखने’ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये मुद्दे आम तौर पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हैं। साथ ही उनका संबंध एकसूत्रता तथा भ्रष्टाचार के मामले तथा कानून और व्यवस्था से भी है जो हर नागरिक के लिए सब से महत्वपूर्ण विषय हैं। चौधरी साहब के अनुसार बिना कानून की व्यवस्था का मतलब है अधिनायकवाद। और बिना व्यवस्था के कानून का मतलब अराजकता है। जो भी व्यवस्था लोकतंत्री होने का दावा करती है, उस में इन दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।

चौधरी साहब ने जो मुद्दे उठाये, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :

**सामाजिक :** हमने जातिप्रथा की बुराई को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। जातिप्रथा ही मूल रूप से भारत की सदियों से चली आयी गुलामी के लिए ज़िम्मेदार है। भारत के विभाजन की जड़ भी यही प्रथा रही है। जाति पर आधारित सामाजिक विविधताओं का सत्ता में आने के लिए निर्बाध रूप से इस्तेमाल हो रहा है तथा इन्हें कायम रखा जा रहा है। इसे दूर करना चाहिए। जब तक जातिप्रथा समाप्त नहीं हो जाती भारत प्रगति नहीं कर सकता।

**बेरोजगारी :** 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आयी बेरोजगार दफ्तरों में एक करोड़ दो लाख लोगों के नाम दर्ज थे। पाँच वर्षों के भीतर ही यह संख्या 80 प्रतिशत बढ़ गयी। लोकदल के अतिरिक्त और कोई पार्टी बेरोजगारी की समस्या पर बात ही नहीं करती।

**गरीबी :** अमीर लोग अधिक अमीर हो गये हैं और गरीब अधिक गरीब। योजना आयोग के अनुसार 1960 में भारत में 45 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार अब यह संख्या बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गयी है। 1950 में गाँव के आदमी और शहर के

संयोग से जब यह पत्र प्राप्त हुआ तब उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ में पदाधिकारियों के वार्षिक चुनावों की सरगमी थी। समीक्षकों की राय में अधिवक्ता संघ की तीखी और उत्पन्न प्रतिक्रिया आंशिक रूप से इस सरगमी के कारण रही।

उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रेषित विवादग्रस्त पत्र न्यायाधीशों की ओर से निर्णयाधीन वादों की जटिल समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव मात्र था न कि परिपत्र। उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ की 20 अप्रैल को हुई आपत्कालीन बैठक में इस प्रस्ताव को एक परिपत्र और अंतिम निर्णय मानकर निंदा की गयी। साथ ही यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि यदि यह परिपत्र 21 अप्रैल तक वापस न लिया गया तो संघ के सदस्य 23 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। समीक्षकों की राय में संघ के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता एवं क्षमता को ले कर व्यक्त किये गये विचार आपत्तिजनक रहे।

विषय

अधिवक्ता संघ के इस प्रस्ताव के उत्तर में रजिस्ट्रार श्री सुब्बाराव ने न्यायाधीशों की ओर से 21 अप्रैल को एक पत्र अधिवक्ता संघ के सचिव के नाम लिखा, जिस में अधिवक्ता संघ के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा व्यक्त आपत्तिजनक विचारों एवं संघ द्वारा पारित प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही 19 अप्रैल को लिखे पत्र का आशय भी स्पष्ट किया।

मुख्य न्यायाधीश के सुझाव पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी इस विवाद पर विचार-विमर्श हेतु उनसे मिले। मुख्य न्यायाधीश ने पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि विचाराधीन नयी प्रणाली को लागू करने से पहले अधिवक्ता संघ के सदस्यों के विचार, सुझाव एवं राय को ध्यान में रखा जायेगा और इस संबंध में न्यायालय एकतरफा कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

मुख्य न्यायाधीश एवं संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई बातचीत एवं 21 अप्रैल के पत्र पर विचार के लिए अधिवक्ता संघ की आपत्कालीन बैठक हुई जिस में एक प्रस्ताव पारित कर याचिकाओं पर सुनवाई के अधिकार के

विवाद को ले कर 20 अप्रैल को पारित प्रस्ताव को दुहराते हुए उसे संघ का स्पष्ट एवं दृढ़ निश्चय बताया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 19 अप्रैल के पत्र द्वारा जारी की गयी किसी भी सिफारिश को यदि भविष्य में लागू किया गया तो अधिवक्ता संघ के सदस्य अनिश्चितकाल की हड़ताल करेंगे। संघ के पदाधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर संघ ने 23 अप्रैल से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का अपना निर्णय वापस ले लिया। इस प्रकार एक गंभीर संकट कुछ समय के लिए टल गया।

पिछले दिनों देश के लगभग सभी प्रमुख समाचारपत्रों में इस घटना की विशेष चर्चा रही। संपादकीय लेखों द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता संघ पर नाना प्रकार की टीका टिप्पणियाँ की गयीं। एक प्रमुख समाचारपत्र के अनुसार अधिवक्ता गण शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के विचार से ही नफरत करते हैं क्योंकि इस का सीधा संबंध उनकी फीस से है। एक अन्य संपादकीय लेखानुसार ‘जैसे ही आप (न्यायाधीश) तेज गति के लिए कोई भी



आदमी की आय का अनुपात 1:2 था. 1977 में यह 1:4.1 हो गया और आज यह 1:4.5 है

**संपत्ति :** भारतीय गाँवों के नीचे के बीस प्रतिशत यानी लगभग 10 करोड़ लोगों के पास जितनी कुल संपत्ति है वह टाटाओं या बिड़लाओं की अकेली संपत्तियों से कम होगी यह बात एक सरकारी स्वायत्तशासी संस्था, नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने कही है. इन 20 प्रतिशत लोगों की कुल पूँजी 1,050 करोड़ रुपये होगी. इसके विपरीत बिड़लाओं के पास 1,170 करोड़ तथा टाटाओं के पास 1,180 करोड़ की संपत्ति है.

चौधरी साहब ने जोर दे कर कहा कि श्रीमती गांधी 'चारों संस्थाओं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तथा समाचार जगत को बदनाम करने पर तुली हैं और सच तो यह है कि लोकतंत्र को ही नष्ट कर रही हैं.' अपने इन मुद्दों के विस्तार में उन्होंने बताया:

**न्यायपालिका :** नियुक्ति, पुष्टि और तबादले के संबंध में हर प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं. भारत के कुछ मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश इस दबाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं. पर कुछ ने इसके सामने हार मान ली है. जिस मजिस्ट्रेट ने 1977 में श्रीमती गांधी को बिना जमानत रिहा कर दिया था उसे पुरस्कृत किया गया है. जिस न्यायाधीश ने संजय गांधी को दो साल के कारावास सजा दी थी उस की छीछालेदर की जा रही है.

**कार्यपालिका :** इसे लगातार धोखा दिया जा रहा है तथा भ्रष्ट किया जा रहा है. कोई भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है. यदि आप किसी गुंडे के आदेशों का पालन नहीं करते तो आप को अपना बोरिया-विस्तर बाँधना पड़ सकता है. और यदि आप ईमानदार और अच्छे जिलाधीश हैं तब भी अगले दिन सड़क पर हो सकते हैं. अधिकारियों को निष्पक्षता से काम नहीं करने दिया जाता.

**विधायिका :** सरकार लोकतंत्र में जो चाहती है, कर लेती है. पर इसके साथ ही विरोधियों की भी सुनी जानी चाहिए. कोई भी असुविधाजनक कार्य नहीं होने दिया जाता. संसद सदस्यों तथा विधायकों दोनों की योग्यताओं में कमी आ गयी है. संसद में भेद खुलते ही अंतुले को निकाल दिया जाना चाहिए था, पर वह तभी बाहर निकला जब बंबई उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया.

कदम लोगे हम (अधिवक्ता संघ) ब्रेक लगाने को तैयार हैं.

निर्णयाधीनवादों की समस्या अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जटिल प्रश्न बन कर राष्ट्र के सामने है जिस का शीघ्र उचित समाधान न होने पर स्वयं न्याय व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरा है. विधि आयोग द्वारा जारी किये गये विवादग्रस्त प्रश्नसंग्रह में भी इस समस्या का उल्लेख है एवं विचार और सुझाव के लिए राष्ट्र के सामने है. परंतु रोग के इलाज के लिए रोगी का ही अंत सर्वथा अनुचित एवं अनुपयुक्त होगा. शीघ्र न्याय वितरण के वास्ते न्याय के सही स्वरूप को भी दफनाया नहीं जा सकता. भारतीय संविधान में प्रतिपादित न्यायालय में सुनवाई का मूल अधिकार भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार एवं अमिन्न अंग है.

समीक्षकों की राय में न्यायालय में सुनवाई के आधार पर व्यवस्थित वर्तमान न्यायप्रणाली के स्थान पर याचिकाओं के लिखित परिचालन के द्वारा प्रस्तावित न्याय प्रणाली भारतीय परिस्थिति में अनुपयुक्त एवं अव्यावहारिक है. प्रस्ता-

वित न्यायप्रणाली संयुक्तराज्य अमेरिका की न्यायव्यवस्था का अंग है, जिसे हम सोचे समझे बिना भारतीय न्याय व्यवस्था पर नहीं थोप सकते. अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रणाली हेतु आवश्यक सभी साधनों से संपन्न हैं और एक लंबे अनुभव के बाद यह प्रणाली न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है. भारतीय न्यायाधीशों के लिए न तो ये साधन उपलब्ध हैं और न ही उन्हें इस प्रणाली की कोई अनुमति है. अतः इस नयी प्रणाली को लागू करने से पहले न्यायाधीशों एवं अधिवक्ता संघ के बीच पूर्ण विचारविमर्श एवं सहमति आवश्यक है. साथ ही इस नयी प्रणाली के हर पहलू पर अपेक्षित अध्ययन भी किया जाना चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मुकद्दमों की समस्या के लिए केंद्र सरकार भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है. लंबे समय तक रिक्त स्थानों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न होना मुकद्दमों की दिन प्रति दिन बढ़ रही संख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न होने से यह समस्या सुरसा के समान बढ़ रही

**भ्रष्टाचार :** ईमानदारी और विश्वसनीयता का आज पुलिस वालों में पूरी तरह अभाव है. भ्रष्टाचार तो जैसे कानून ही बन गया है और इस से तबाही हो रही है. वह ऊपर से नीचे की ओर आता है. यदि हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में 25 ईमानदार और सक्षम व्यक्ति उच्चतम पदों पर हों तो पाँच साल के अंदर हम अपने जन जीवन और प्रशासन को शुद्ध कर सकते हैं.

दो सवाल फिर भी बाकी रह गये. पहला मैंने चौधरी साहब से पूछा : आप के जातिप्रथा के विरुद्ध लड़ने की बात कहने के बावजूद यह कैसे हो गया कि आप की छवि भी एक जातिवादी जाट नेता के रूप में बन गयी है. दूसरा, आप की पार्टी के पास लोगों को देने के लिए क्या है? वे लोकदल को वोट क्यों दें?

उनके उत्तर स्पष्ट थे. "मैं जातिवादी नहीं हूँ. जानबूझ कर मेरी निंदा की जाती है. मुझे गालियाँ दी जाती हैं और मुझे गलत समझा जाता है. मेरी एक लड़की का विवाह एक कायस्थ के साथ हुआ है. मेरी दो पोतियों का विवाह खत्रियों में और एक पोती का यादवों में हुआ है. मेरे निकटतम मित्रों में एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक खत्री (अरोड़ा) है और एक बनिया है. मेरा कोई जाट मित्र नहीं है. वे मेरे प्रशंसक और अनुयायी अवश्य हैं."

अंत में उन्होंने जोर दे कर कहा कि लोकदल एक ऐसी सरकार का प्रस्ताव रखता है जो देश की आज की महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझा सकती है. यह सच है कि विरोधियों की विश्वसनीयता को पिछले कुछ सालों में गहरा आघात लगा है. पर उन्हें विश्वास है कि वे कांग्रेस (इं) के मुकाबले लोगों में बहुत कुछ दे सकते हैं—"एक अच्छी सरकार जो साफ सुथरी हो और सब से बड़ी बात यह है कि अपने रूपाकार और प्रतिबद्धताओं से गांधीवादी हो."

कई लोग चौधरी साहब की राजनीति और शैली से सहमत नहीं हैं. वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी संसद का सामना नहीं कर पाये. कई लोग उनके हाल ही के संन्यास और फिर राजनीति में लौटने का मजाक उड़ा रहे हैं. इस के बावजूद ठोस तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि चौधरी साहब ने भारत तथा गरीबी में फँसे करोड़ों लोगों के भविष्य से संबंधित मुद्दे उठाये हैं.

है. इस समय उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ पर आसीन चौदह न्यायाधीशों की संख्या किसी भी मापदंड से निर्णयाधीन एवं नये मुकद्दमों के शीघ्र निपटारे के लिए अपर्याप्त है.

सन् 1957 में लगभग एक हजार नये मुकद्दमे उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिए दाखिल हुए जब कि न्यायाधीशों की संख्या ग्यारह थी. यह संख्या 1976 में बढ़ कर 14,000, सन् 1977 में 26,000, सन् 1978 में 35,000, सन् 1979 में 41,000, सन् 1980 में 53,000 और सन् 1981 में लगभग 60,000 हो गयी. इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में ही नये मुकद्दमों की संख्या लगभग पाँच गुनी हो गयी है, जब कि वर्तमान में न्यायपीठ पर मात्र चौदह न्यायाधीश आसीन हैं. अतः निर्णयाधीन एवं नये मुकद्दमों के शीघ्र निपटारे की समस्या के निराकरण के लिए न्यायव्यवस्था के तीनों अंग—न्यायपीठ, अधिवक्ता संघ एवं केंद्र सरकार—मिल कर शीघ्र कोई उचित समाधान निकालें. इस प्रयोजन हेतु एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो शीघ्र ही अपने सुझाव दे. □



## संविधान

# क्या कश्मीर भी असम बनेगा ?

(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा)

**असम** को बहिरागतों की समस्या ने उलझा दिया. कश्मीर शरणार्थियों के शिकंजे में फँसने जा रहा है.

बहिरागत बंगलादेश (पूर्व पाकिस्तान) की जिदगी से तंग आ कर चुपचाप असम में आये. वे असमी नहीं थे. शरणार्थी कश्मीर में पाकिस्तान से आये. उन्हें चुपचाप आने की मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि वे कश्मीरी मूल के होंगे.

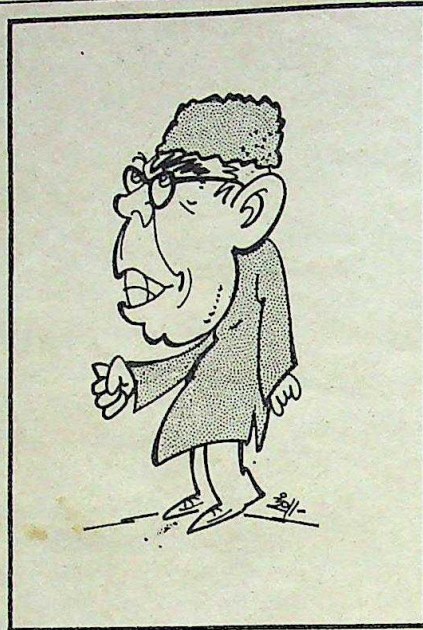
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने हाल ही में शरणार्थियों की स्थायी वापसी और पुनर्वास (1982) का जो विधेयक पास किया है उस के अनुसार 1 मार्च, 1947 के बाद स्वेच्छा से या अन्यथा राज्य के जो लोग पाकिस्तान चले गये वे खुद या राज्य में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार द्वारा अर्जी मंजूर करा कर वापस आ आ सकते हैं. बस सकते हैं.

विधेयक राज्यपाल के पास संपुष्टि का इंतजार कर रहा है. लेकिन इस के पहले कि राज्यपाल उस पर विचार करें प्रतिपक्षी दलों ने विरोध की आवाज तेज कर दी है. डॉक्टर कर्णोसिंह ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह राज्यपाल को विधेयक की संपुष्टि न करने की सलाह दें क्योंकि उस कानून की अमलदारी बेर-सबेर जम्मू-कश्मीर में भी असम जैसी समस्या पैदा कर सकती है. पोपुलर कांफ्रेंस और जमायते इस्लामी ने विधेयक का खुला समर्थन नहीं किया है. लोकदल और पेंथर पार्टी ने मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाह की नीयत पर शक किया है. डेमोक्रेटिक नेशनल कांफ्रेंस ने उस का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है, क्योंकि उसे डर है कि उक्त कानून की अमलदारी राज्य में अव्यवस्था और अशांति पैदा करेगी. भारतीय जनता पार्टी ने देश व्यापी आंदोलन चलाने की धमकी दी है.

विधेयक के विरोध की वजह यह है कि उस से दो राज्यों के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोगों के लिए न केवल राज्य के दरवाजे खुल जायेंगे बल्कि धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को भी धक्का लगेगा. यह संदेह निराधार नहीं है कि उस के बाद पूरे राज्य का जनमानस सांप्रदायिक चिंतन के आधार पर विभाजित हो जायेगा. यह स्थिति स्वयं शेख साहब के अब तक के प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने वाले उनके अमूल्य अवदान का मखौल बन सकती है.

विधेयक का समर्थन करते हुए शेख साहब ने

दिनमान



इंसानियत का सवाल उठाया था. उन्होंने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर (कारगिल) के मेहर-अली पाकिस्तानी पारपत्र पर हज करने गये. 1971 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने वह गाँव भारत को दे दिया. मेहरअली को उस गाँव में घुसने नहीं दिया गया. पाकिस्तान उन्हें लेने को इच्छुक नहीं था. क्या उन्हें अपने गाँव में परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं था. नहीं था, तो क्या वह अपना गाँव पाकिस्तान को लौटाने की माँग नहीं कर सकते थे."

मेहरअली को ले कर शेख साहब के दिल में उठे इंसानी जज्बे ने उन सब की याद बहुत मुहब्बत से की जो 35 साल पहले पाकिस्तान चले गये थे. वह उन्हें बुलाने और बसाने यानी उन्हें नागरिकता का पूरा अधिकार देने की मजबूरी महसूस करने लगे. मुहब्बत का यह जज्बा शेख साहब के दिल में उन लाखों हिंदुओं और सिखों को ले कर नहीं उठा जो कश्मीर में 35 साल से रह रहे हैं लेकिन अभी भी उन्हें राज्य की नागरिकता नहीं मिली है. शेख साहब उन्हें आज भी शरणार्थी ही मानते हैं. खयाल है कि उस विधेयक का असर उन दो तीन लाख हरिजन शरणार्थियों पर पड़ेगा जो

डॉ. पी. सिंह : अवैध विधेयक



पाकिस्तान से आये थे और जिन्हें पाकिस्तान चले गये लोगों की जमीन इस आधार पर मिली थी कि वे अपनी जमीन विभाजन के वक्त पाकिस्तान छोड़ आये थे. अब अगर पाकिस्तान से लोग आते हैं तो इन शरणार्थियों को जमीन छोड़नी पड़ सकती है. यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की दिन-ब-दिन बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी वापस आना चाहेंगे.

यह मानने के बाद कि शेख साहब सांप्रदायिक संकीर्णताओं से मुक्त एक उदार चेता व्यक्ति हैं, सवाल उठता है कि 'पाकिस्तान में फँसे हुए लोगों' को कश्मीर वापस बुलाने का औचित्य क्या है? प्रतिपक्षी दलों का कहना है कि शेख साहब को घाटी के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों के समर्थन की उम्मीद नहीं है. वे अन्य दलों के साथ हैं. जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता कम होते देख कर वह घाटी क्षेत्र पर विशेष जोर दे रहे हैं. अपने पुत्र डॉक्टर फारुख अब्दुल्लाह को उत्तराधिकार का ताज पहनाने के बाद उनकी कोशिश यह है कि अपने जीवनकाल में ही वह उन के राजनैतिक आधार को मजबूत कर जायें. पाकिस्तान से आने वाले लोग उन के समर्थक होंगे.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो मार्च 47 के बाद पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया, सक्षम अधिकारी से पुनर्वास का परमिट ले कर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है. यह प्रावधान शुरू में कश्मीर पर लागू नहीं था लेकिन 1952 में दिल्ली समझौता होने, और 1954 में कश्मीर संविधान आदेश लागू होने पर एक संशोधन के जरिये अनुच्छेद 7 वाली सुविधा कश्मीर के लोगों को भी मिल गयी. दिल्ली समझौते की अमलदारी के सिलसिले में राज्य संविधानसभा ने कश्मीर के संविधान में 1956 में धारा 6 (2) में कहा कि 'जो व्यक्ति 14 मई 1954 के पहले तक राज्य का पहली या दूसरी श्रेणी का नागरिक था और 1 मार्च 1947 के बाद उस क्षेत्र में चला गया जो अब पाकिस्तान में शामिल है तो यदि एक परमिट के अंतर्गत वापस आता है तो वह राज्य का स्थायी निवासी माना जायेगा. इसी के साथ 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता का कानून पास किया और उसे 1 मई 1965 तक संशोधित कर दिया. उस में ऐसे व्यक्तियों को पुनः नागरिकता का अधिकार देने का अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया जो पाकिस्तान चले जाने के बाद पुनः लौटने के इच्छुक हों. इस रूप में अनुच्छेद 7 का प्रावधान खत्म हो गया. नागरिकता प्रदान करने का एक सामान्य प्रावधान कानून में है जिस के

अंतर्गत एक नहीं है पंज पाकिस्तान क्योंकि वहाँ बाद वे भार

कानूनी द

निकता का

कि नागरिक

है. विधेयक

के निवासिय

तथा पाकिस्त

ये सभी के

भारतीय ना

यो कर पा

लेने वालों में

उस में यह स

अपने के इच्छ

में दिया जाये

क्षेत्र में प्रवे

अनुसार पाक

व्यक्ति, पाकि

वास से बीसा

नहीं कर सकत

जनता पा

गाहबुद्दीन का

को बीसा कानू

है. वैसे भी

(देखें बॉक्स

बुद्ध नेशनल क

सदस्य ने उस

सोली. शेख स

रूकान का पता

कश्मीर के जन्म

के ताते वह हि

यकते थे, लेकि

नोमित रखा.

रतकलाब लान

संवैधानिक

न्यायालय के

का स्पष्ट मत

कानून बनाने

नागरिकता का

एक मात्र अधि

पूरी की 17वीं

श्री सिंह ने

के संविधान क

एक कहा कि

200 के अंतर्

के आने के बाद

अधिकारों का

ये स्वीकृत क

वित्त संबंधी न

पैदा सकते हैं.

विचार के लिए

विषय



अंतर्गत एक व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं है पंजीकरण कराना होता है। इस में पाकिस्तान चले गये लोग भी आ जाते हैं क्योंकि वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेने के बाद वे भारत के नागरिक नहीं रहे।

पाकिस्तान आधार पर विभाजन के अव अव शरणार्थियों ह भी माना दिन-ब-दिन ज्यादा से जाहेंगे।

साहब सांप्र-उदार चेता पाकिस्तान में बुलाने का का कहना लावा राज्य समर्थन की पाथ हैं। जम्मू प्रियता कम शेष जोर दे अबुल्लाहाने के बाद जीवनकाल को मजबूत ले लोग उन

च्छेद 7 के आर्च 47 के चला गया, परमिट ले सकता है। र लागू नहीं श्रौता होने, आदेश लागू अनुच्छेद 7 को भी मिली के सिल-कश्मीर के (2) में कहा के पहले तक का नागरिक उस क्षेत्र में शामिल है। आता है तो ना जायेगा। न्य संसद ने आ और उसे दिया। उस में का अधिकार में किया गया पुनः लौटने छेद 7 का प्रदान करने में है जिस के

15 मई '82



## केंद्रीय अनुमति अनिवार्य है

### पाँच खामियाँ

सैयद शहाबुद्दीन ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस विधेयक ने ऐसा राजनैतिक विवाद पैदा किया है जो जनभावना को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकता है। इस में पाँच खामियाँ हैं: (1) तिथि निर्धारण का अभाव—यानी अगर एक व्यक्ति शांति कायम हो जाने के बाद भी गया तो लौटने पर उसे पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। ऐसे लोग अपने हित में सामान्य परिस्थिति में सीमा पार कर के चले गये—संकटकाल की किसी मजबूरी में नहीं। (2) पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से इशारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से नहीं, मूल पाकिस्तान से है। जो लोग पाकिस्तान चले गये, वहाँ के नागरिक हो गये, वे केवल विदेशी नागरिक के रूप में सिर्फ सार्थक प्रावधानों के अंतर्गत इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य, पाक अधिकृत क्षेत्र समेत भारत का अभिन्न अंग है अतः विलय के दिन पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में चले जाने से उस की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस

श्रेणी के व्यक्ति को देश के भीतर कहीं भी बसने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए कश्मीर सरकार ने कुछ खास नियम पहले से ही बना रखे हैं—इसलिए यह नया कानून उन पर लागू ही नहीं होता। (3) विधेयक में वापसी या पुनर्वास के दावेदार व्यक्तियों के लिए तिथि सीमा नहीं है। उस की एक निश्चित तिथि होनी चाहिए और उसी के भीतर उन्हें वापसी का आवेदन अनिवार्यतः देना चाहिए। (4) विधेयक भारत सरकार के नागरिकता प्रदान करने के अधिकार को खत्म करता है। जम्मू कश्मीर संविधान आदेश 1954 की जिस धारा 2(3) व के अंतर्गत लोग पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में गये वह संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता कानून (1955) के प्रभावी हो जाने के बाद सार्थक नहीं रह जाती। वह कानून अनुच्छेद 7 द्वारा कश्मीर सरकार को उपलब्ध विशेषाधिकारों को निष्क्रिय कर देता है। इसी लिए जम्मू कश्मीर मूल के विदेशी नागरिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति अनिवार्य है। इस का कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है। (5) विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता कि वापसी के बाद ऐसे व्यक्तियों को अपनी वह जमीन जायदाद वापस माँगने का अधिकार होगा या नहीं जो उन्होंने जाते वक्त कश्मीर में छोड़ दी थी और जिसे बाद में अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया और जिस पर अभी भी उन का ही कब्जा है।

न्यायालय ने पुरुषोत्तम बनाम केरल सरकार (1962-उ. त. 964-701-2) के मामले में यह फैसला दिया था कि यदि राष्ट्रपति को उस की संपुष्टि में कठिनाई हो तो मामला परामर्श और विचार के लिए उसी के पास (उच्चतम न्यायालय) भेजा जाये। कश्मीर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ राज्यपाल (1) संपुष्टि कर सकते हैं। (2) या संपुष्टि करने से इनकार कर सकते हैं। विधेयक वित्त संबंधी न हो तो इस अनुरोध के साथ लौटा भी सकते हैं कि विधानसभा पूरे विधेयक या उसके किसी अंश पर पुनर्विचार करे। पुनर्विचार के बाद उन्हें संपुष्टि करनी होगी। सवाल यह उठता है कि अगर वह पहली ही बार संपुष्टि देने से इनकार कर दें तब क्या होगा? निश्चय ही वह एक गतिरोध की स्थिति होगी।

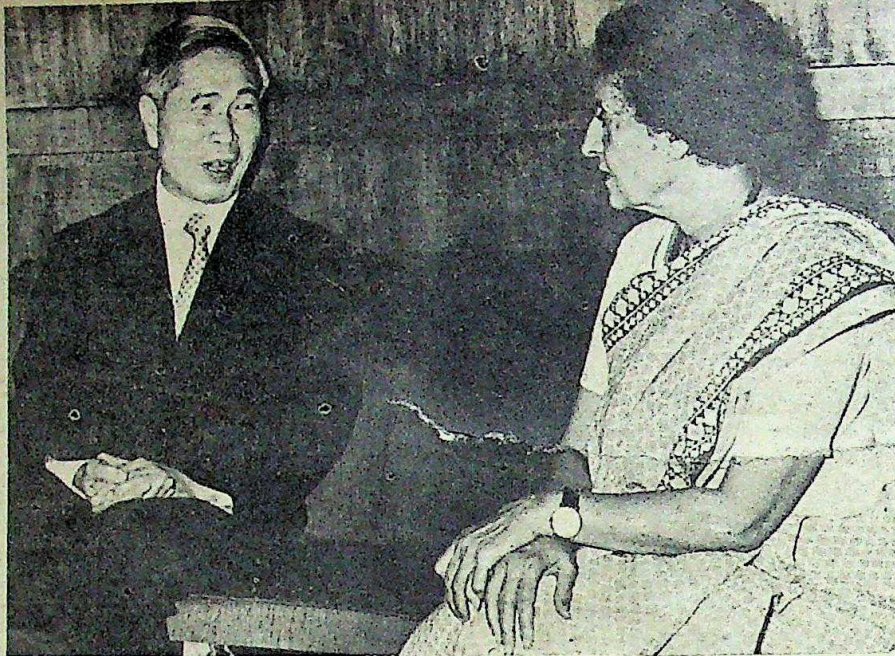
उसी तरह सूची में देश की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा की तैयारी, युद्ध काल में युद्ध चलाने और उस की समाप्ति के पश्चात सैन्य बियोजन

संबंधी सारे नियम-अधिनियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विधेयक में प्रस्तावित स्थिति में परिवर्तन की योजना सूची संख्या 1 में नहीं आती। उसे पास करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति का अधिकार उस से संबंधित अनुच्छेद 9 से 10 तक में उपलब्ध प्रावधानों से खत्म नहीं हो जाता। सूची नं. 17 में जो कुछ स्पष्ट किया गया है उसकी पुष्टि अनुच्छेद 11 से हो जाती है और इसी से सिद्ध हो जाता है कि वह विधेयक पूर्णतः अवैध है। सूची संख्या 1 के अनुसार तो वह असंवैधानिक है ही। इसीलिए यह कहना कि उस विधेयक के लिए केंद्र की अनुमति अनिवार्य है, समस्या को बहुत छोटा करके रखता है।

वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार को वैसा विधेयक बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। □

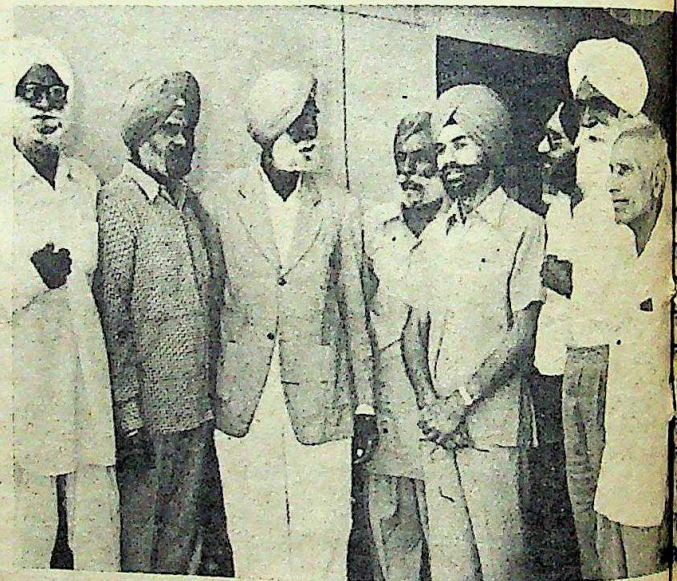
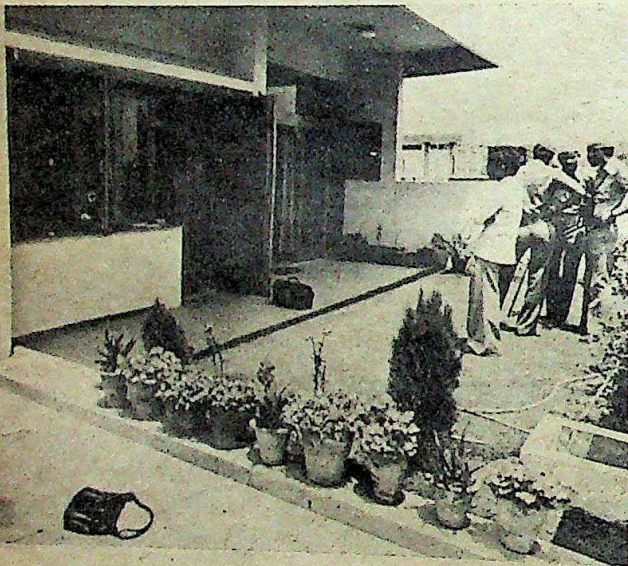


# विमानों के आइने में



वीएनएम के विदेशमंत्री नारयण को थाच, भारत सरकार के निमंत्रण पर, पाँच दिवसीय यात्रा पर भारत आये. दोनों देशों के नेताओं ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना के बारे में फ़ैसला किया. नारयण को थाच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उन के संसद भवन के कार्यालय में मिले. (बायें)

एशियाई खेल संयोजन समिति के निमंत्रण पर पंजाब के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने आसन्न एशियाई खेलों लिए चल रहे निर्माणों का निरीक्षण किया. ये खिलाड़ी हैं (बायें से) गुरनार्णसिंह, परदुमनसिंह, अमर सिंह, निवर्कासिंह, बलबीरसिंह, जगदेवसिंह, मखनसिंह, खुशी राम तथा रौनकसिंह. (नीचे)



हाल में डाकुओं के एक दल ने दिल्ली की संपन्न बस्तियों, निर्माण विहार और स्वास्थ्य विहार के तीन मकानों को तड़के लूटने की कोशिश की, जिसे चुनौती देने वाले एक मकान मालिक की जान चली गयी और 10 व्यक्ति घायल हो गये. पुलिस के पहुँचने से पहले हमलावर भाग खड़े हुए. (ऊपर) निर्माण विहार के मकान की जाँच करते हुए पुलिस अधिकारी और दो हेंड बग तथा कुछ अन्य सामान, जो डाकू जाते जाते एक घर के बाहर छोड़ गये.



नयी दिल्ली के बोट बल्ल का मैदान अब लंदन के हाइड पार्क का मुक़ाबला करने लगा है, जहाँ विभिन्न विचारों, राजनैतिक दलों के लोग अपनी शिकायतों और भावनाओं को सप्ताधारियों तक पहुँचाने के लिए एकत्र होते हैं. (बायें) राजपथ के तरफ़, विशेष कर संसदीय सत्र के दौरान, विभिन्न भाषाओं में विरोध प्रदर्शन करने वाले तमाम पोस्टर टेंगे रहते हैं.



वदेशमंत्री नुयें  
कार के निर्माण  
यात्रा पर भारत  
नेताओं ने  
की सहयोग के  
योग की स्थापना  
किया. नुयें को  
द्वारा गांधी से  
के कार्यालय में

योजन समिति  
व के कुछ वरिष्ठ  
न एशियाई खेलों  
गों का निरीक्षण  
हूँ (बायें से)  
नसिह, अमर  
लबीरसिंह,  
सिंह,  
वकसिह. (नीचे)



निजी विमान 'बीच बोनांजा' के  
यात्रा मोत के मुंह से बाल  
बचे, जब इस विमान को  
परजंग हवाई अड्डे से उड़ान  
ने के बाद कुछ ही मिनटों में  
नोपुर (दिल्ली) के पास एक  
में जबरन उतारना पड़ा. विमान  
पालिक और चालक अरविंदर  
(संसद सदस्य) ने अपने अन्य  
साथियों के साथ जैसे ही विमान  
बाहर कदम रखा उस में आग  
गयी. खेत में पड़े विमान के  
क्षेत्र दुर्घटना के साक्षी हैं. (ऊपर)

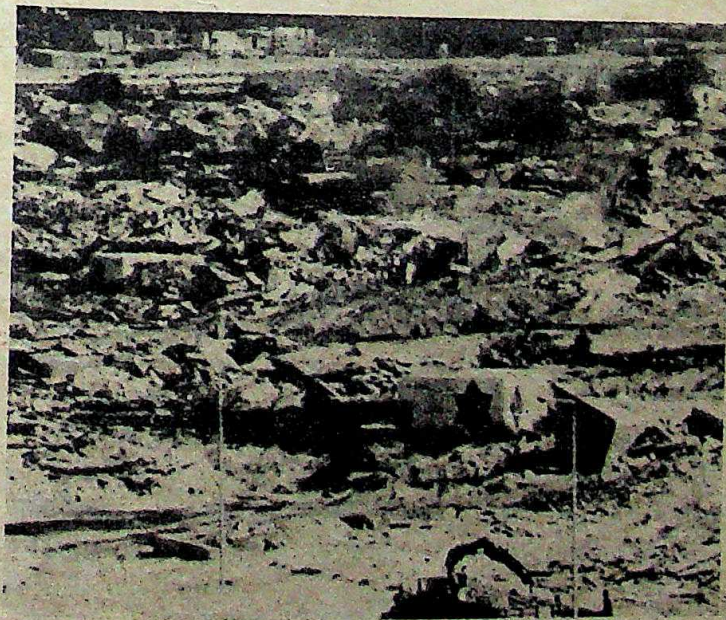
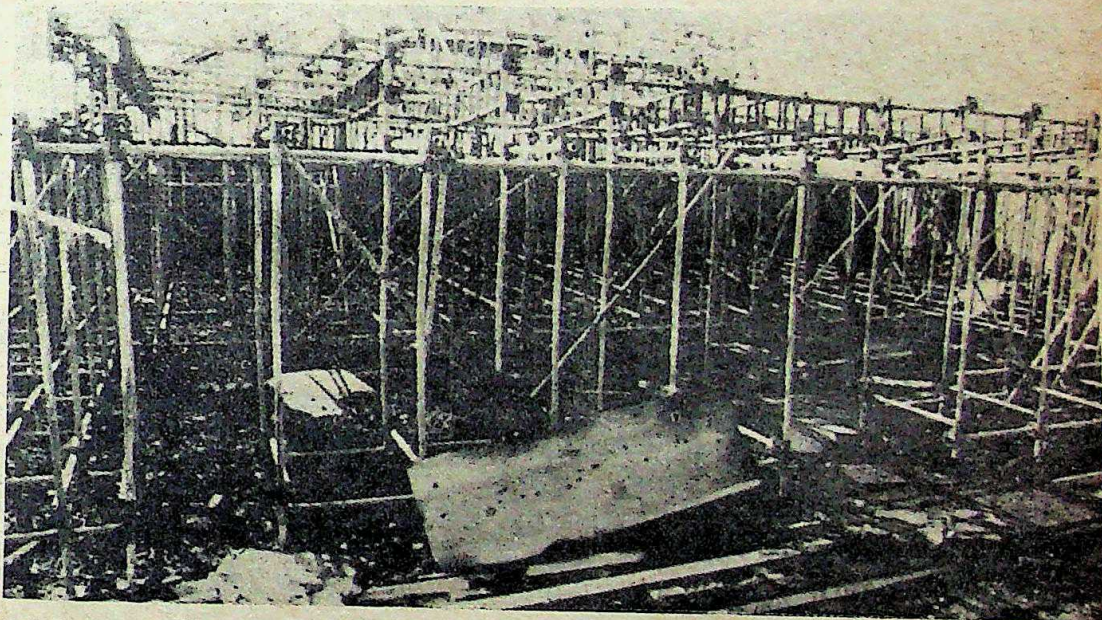
मरे विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) के  
नॉर्थम उस विशाल गुंबद के  
का निरीक्षण कर रहे हैं जो  
1982 के एशियाई खेलों के लिए  
मैदानों में निर्माणाधीन एक बड़े खेल  
मैदान का प्रमुख हिस्सा होगा.  
(बायें)

मोट बलब का  
हाइड पार्क का  
है, जहाँ विभिन्न  
दलों के लोग  
र मावनाओं  
पहुँचने के लिए  
राजपथ के किनारे  
सद्वीय सत्र के  
गाओं में विभिन्न  
माम पोस्टर

निजी विमान 'बीच बोनांजा' के  
यात्रा मोत के मुंह से बाल  
बचे, जब इस विमान को  
परजंग हवाई अड्डे से उड़ान  
ने के बाद कुछ ही मिनटों में  
नोपुर (दिल्ली) के पास एक  
में जबरन उतारना पड़ा. विमान  
पालिक और चालक अरविंदर  
(संसद सदस्य) ने अपने अन्य  
साथियों के साथ जैसे ही विमान  
बाहर कदम रखा उस में आग  
गयी. खेत में पड़े विमान के  
क्षेत्र दुर्घटना के साक्षी हैं. (ऊपर)

मरे विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) के  
नॉर्थम उस विशाल गुंबद के  
का निरीक्षण कर रहे हैं जो  
1982 के एशियाई खेलों के लिए  
मैदानों में निर्माणाधीन एक बड़े खेल  
मैदान का प्रमुख हिस्सा होगा.  
(बायें)

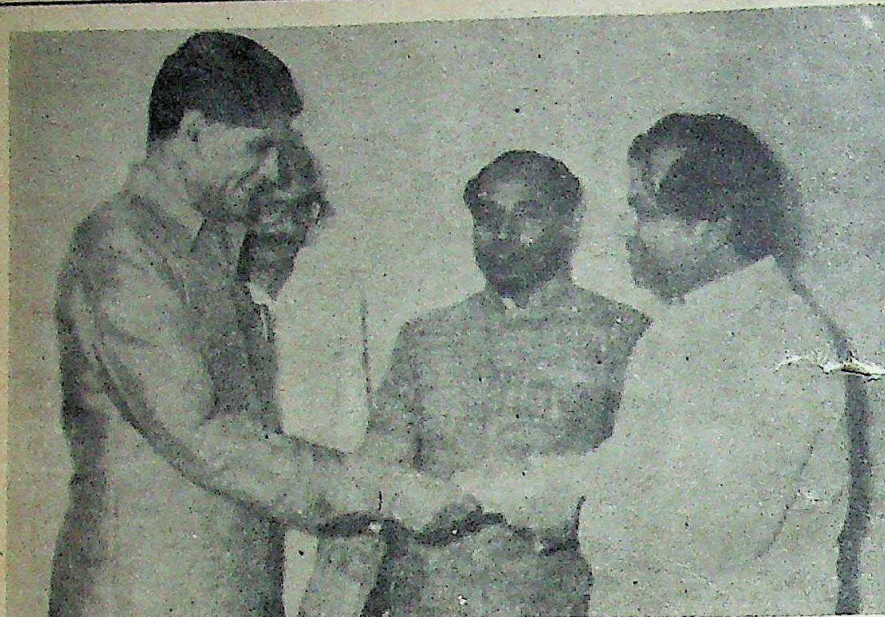
मोट बलब का  
हाइड पार्क का  
है, जहाँ विभिन्न  
दलों के लोग  
र मावनाओं  
पहुँचने के लिए  
राजपथ के किनारे  
सद्वीय सत्र के  
गाओं में विभिन्न  
माम पोस्टर



पोप जॉन पॉल की ब्रिटेन यात्रा  
के दौरान उन का संदेश सुनने के  
के लिए कार्डिफ में जो खुला मंच  
तैयार किया जा रहा था वह पूरा  
होने से पहले ही आग से क्षतिग्रस्त  
हो गया. (ऊपर) इसे आगजनी माना  
जा रहा है और पुलिस उन तीन  
युवकों की ताक में है जिन्हें इस  
घटना के बाद भागते हुए देखा गया.

(बायें) सिनाइ क्षेत्र का वह  
इलाका जहाँ पहले यमित बसा हुआ  
था. अब इस ध्वस्त रेगिस्तानी शहर  
में मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता  
है. पहले बुलडोजर द्वारा इस शहर  
को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की  
गयी; जो बचा रहा उसे भी  
इस्त्राहली सैनिकों ने उड़ा दिया.





गांधीगलेज जिला सहकारी चीनी कारखानों के अध्यक्ष पी.आर. नालबडे श्री अंतुले को 3 लाख 63 हजार रुपये का चेक सेंट करते हुए. बीच में हैं महाराष्ट्र इंका के अध्यक्ष गुलाबराव पाटील

महाराष्ट्र

## अंतुले पर एक और मुकदमा

भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले को अब राज्य की सहकारी चीनी मिलों के प्रत्यक्ष विरोध का भी सामना करना पड़ेगा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ ने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए उन्हें 'भ्रम' में रख कर दान दिये जाने को बाध्य किये जाने के लिए श्री अंतुले पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया है. यह मुकदमा 15 जिला न्यायालयों में दायर किया जायेगा. चीनी मिलों के निदेशकों के अनुसार प्रतिष्ठान के लिए दान मांगते समय उन्हें इस भ्रम में रखा गया कि इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान एक सरकारी ट्रस्ट है. इसी दबाव के कारण उन्होंने ट्रस्ट को दान दिया था.

प्रतिष्ठान को दान दिये जाने के कारण मिल के निदेशकों को न केवल कटु आलोचना का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अब तो सभी 48 चीनी मिलों के हिस्सेदारों ने दान दी गयी अपने हिस्से की राशि वापस किये जाने के लिए निदेशकों पर मुकदमा दायर कर दिया है. ट्रस्ट को लगभग तीन करोड़ रुपये की जो धनराशि दान की गयी थी, उस के लिए बेचे गये गन्ने में से प्रति टन दो रुपये की कटौती की गयी थी. अगर हिस्सेदार मुकदमा जीत जाते हैं तो प्रत्येक हिस्सेदार को 75000 से ले कर दो लाख रुपये तक वापस करना पड़ेगा.

विमर्श

प्रतिष्ठान के विवादास्पद होने के बाद से ही हिस्सेदार ट्रस्ट को दान दी गयी राशि को ले कर सवाल उठा रहे थे लेकिन बंबई उच्च न्यायालय द्वारा इसके विरोध में निर्णय दिये जाने के बाद दानराशि वापस किये जाने के लिए सहकारी न्यायालय में मुकदमा ही ठोक दिया.

इस वर्तमान संकटावस्था से बचने के लिए मिल निदेशकों ने भूतपूर्व और वर्तमान दोनों ही मुख्यमंत्रियों से सहयोग मांगा था लेकिन दोनों ने ही इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. बाबासाहेब भोंसले से आग्रह किया गया था कि वह प्रतिष्ठान को दी गयी दानराशि को 'वैध' करार दिलवा दें. बाबासाहेब भोंसले, जो श्रीमती गांधी की कृपा के बल पर किसी तरह अपनी सत्ता बचाये हुए हैं, इस समय शायद किसी और आलोचना को जन्म नहीं देना चाहते थे. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चीनी मिलों के निदेशकों को सलाह दी कि 1979-80 में एक विशेष कोष के अंतर्गत, जो धनराशि एकत्र की गयी थी, उससे वे हिस्सेदारों की मांग को पूरा कर दें.

एक अनुमान के अनुसार 1979 के अंतिम तीन महीनों में इस कोष के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ रुपया एकत्र किया गया था लेकिन निदेशकों के अनुसार अधिकतर धनराशि स्थानीय विद्यालयों की सहायता इत्यादि कई सार्वजनिक कार्यों पर खर्च कर दी गयी है. अपने बचाव का उनके पास अब यही अंतिम उपाय बचा है.

हरयाणा

## दलबदलुओं का फिर बोलबाला

'आ'थाराम, गयाराम की राजनीति के लिए ख्यातनाम यह राज्य चुनाव के बाद फिर उसी ढर्रे पर चले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि राजनैतिक क्षेत्रों में यह आम चर्चा है कि टिकटों के बंटवारे में इंका और लोकदल दोनों ने ही इस संभावना को ध्यान में रखा है. लोकदल अध्यक्ष चौधरी चरणसिंह और भूपू. मुख्यमंत्री देवीलाल के बीच युद्धविराम हो जाने से सब कुछ ठीक हो गया हो ऐसा नहीं लगता हालांकि चौधरी चरणसिंह ने उम्मीदवारों के चयन में चौ. देवीलाल के दावे को मान्यता देने का अपना वायदा निभाया है. चंद नामों को छोड़ कर प्रायः उन सभी लोगों को टिकट मिले हैं जिन के नामों की सिफारिश चौ. देवीलाल और डॉ. स्वरूपसिंह की दो सदस्यीय समिति ने की थी.

भावी स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चौ. देवीलाल के समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि भूपू. प्रतिरक्षामंत्री और इंका सांसद चौ. बंसीलाल के कम से कम नौ समर्थक लोकदल की सूची में हैं. यह भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल के 12 समर्थकों को भी लोकदल की सूची में स्थान मिला है और इतने ही चौ. चरणसिंह के समर्थक इंका की उम्मीदवारी पाने में कामयाब हुए हैं. यद्यपि चौ. देवीलाल ने इस बात से साफ़ इनकार किया है कि उन की पार्टी दलबदलुओं को स्वीकार करेगी (देखें बॉक्स). अन्य दलों के टिकट पर चुने गये वे विधायक दलबदल नहीं करेंगे यह उम्मीद भला कैसे की जा सकती है. जो दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा ये उधर भाग लेंगे, संभावना तो यही है.

इंका की आंतरिक कलह चुनाव के दौरान और उसके बाद भी अपना रंग दिखाये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. इंका ने जपा से दलबदल कर आये अनेक लोगों को टिकट नहीं दिया और उनमें से अधिसंख्य निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. इस सिलसिले में गृहमंत्री कन्हैयालाल पोतवाल समेत 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी देना पड़ा है. इंका की अनुशासन समिति 'विद्रोहियों' के विरुद्ध कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है.

फिलहाल हालत यह है कि विधानसभा की 90 सीटों के लिए विभिन्न दलों के और निर्दल कुल मिला कर 1095 उम्मीदवार मैदान में हैं. इंका और उस का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी लोकदल



फिर

नीति के लिए  
नाव के बाह  
आश्चर्य की  
तक क्षेत्रों में  
टबारे में इका  
संभावना को  
यक्ष चौधरी  
देवीलाल के  
ब कुछ ठीक  
ठाँकि चौधरी  
ययन में चौ  
ने का अपना  
तो छोड़ कर  
मिले हैं जिन  
गल और डॉ  
ते ने की थी  
त से लगाया  
समर्थक यह  
क्षामंत्री और  
न से कम तो  
यह भी कहा  
गल के 12  
ची में स्थान  
ह के समर्थक  
कामयाब हुए  
बात से साफ़  
दलबदलुओं  
अन्य दलों  
क दलबदल  
कैसे की जा  
की स्थिति  
ता यही है  
व के दौरान  
दिखाये तो  
इंका ने जपा  
ने को टिकट  
संख्य निर्दल  
रहे हैं इस  
ल पोसवाल  
त्यागपत्र भी  
सन समिति  
करने पर भी  
धानसभा की  
और निर्दल  
र मंदान में  
ही लोकदल

हरयाणा लोकदल के एक प्रमुख नेता चौ.  
देवीलाल से कुमार पुष्प की बातचीत :  
इस बार के चुनाव में इंका पिछली सरकार  
के कार्यों को जनता के सामने मुद्दों के रूप  
में रख रही है। क्या लोकदल भी इस के  
समानांतर कुछ मुद्दे उठा रहा है?

इंका कहने को कुछ भी कहती रहे लेकिन  
यह सच्चाई है कि रावी-व्यास समझौता,  
सतलुज-यमुना लिंक नहर, हरिजनों की बस्ती  
में रोशनी, गाँव गाँव में चौपाल और गाँवों  
को जोड़ने वाली सड़कें आदि काम हमारे समय  
में हुए थे।

सतलुज-यमुना लिंक नहर का उद्घाटन  
प्रकाशसिंह बादल (पंजाब के तत्कालीन  
मुख्यमंत्री) को करना था। इस समारोह की  
व्यवस्था मुझे करनी थी लेकिन दिल्ली में  
किसान रैली आयोजित हुई थी जिस पर  
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हमसे नाराज  
हैं। नतीजा यह हुआ कि यह काम कुछ समय  
के लिए रुक गया।

रावी-व्यास समझौते के बारे में भी काम  
श्री ने शुरू किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने  
इसला सुना दिया होता, अगर बार बार इस  
अव्ययन न करवाया गया होता, इंका सरकार  
करा किये गये इस समझौते के तहत आज हमें  
पानी मिला है, पहले की अपेक्षा बहुत  
अच्छा है। हमें पचास प्रतिशत पानी मिलना  
चाहिए था। इस पूरे समझौते का लाभ हरयाणा  
को कम पंजाब को कहीं अधिक हुआ है।

गाँव गाँव में हरिजन चौपाल, हरिजन  
समितियों में रोशनी, काम के बदले अनाज की  
जोना, फसल नष्ट होने पर मुआवजा, व्याज  
में कमी, शिक्षा में सुधार आदि बहुत से  
काम हमारी सरकार ने ही आरंभ किये थे। मैंने  
जबने शासन के दौरान जन साधारण के  
हरयाणा की जितनी योजनाएँ लागू की थीं,  
मजनलाल ने उन सभी को खूँटी पर टाँग दिया।

इंका ने इस बार अपने उम्मीदवार तय  
करते हुए कुछ ऐसे लोगों को टिकट नहीं  
दिये हैं जिन पर अष्टाचार के आरोप हैं।  
शायद पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करने  
का यह एक नया करिश्मा है। आप की  
क्या राय है?

इंका ने सारे अष्ट आदमियों को टिकट  
दिये हैं। देखिए न, उन्होंने 41 दल बदलुओं में  
से 22 को टिकट दिया है। कांग्रेस शासन के दो  
वर्षों के इतिहास में राजनैतिक, सामाजिक,  
व्ययि और नैतिक गिरावट का सब से दुःखद  
उदाहरण रहा है। मजनलाल ने अपनी कुर्सी बर-  
करार रखने के लिए हर बुराई अपनायी,  
जन के और उनके साथियों के काले कारनामों  
को जता अच्ची तरह वाकिफ है।

क्या इंका के भीतर फैले असंतोष का लाभ  
विपक्ष को होगा?

जल्द, लोक-

दल और भा-  
जपा के बीच  
हुए समझौते  
से इंका के  
खेमों में खल-  
बली मच गयी  
है। हरयाणा  
और हिमाचल  
में होने जा  
रहा चुनाव एक  
नये बदलाव  
की कहानी कहेगा।



जिन्हें इंका का टिकट नहीं मिला है, क्या  
वे लोकदल में शामिल हो सकते हैं?  
कतई नहीं। हम दलबदलुओं को नहीं लेते।  
लोकदल के घोषणापत्र में ग्रामीण विकास  
और बेरोजगारी आदि के संबंध में ठोस  
बात कहीं गयी है, लेकिन क्या कारण  
है कि लोकदल एक बड़ी जन समर्थित पार्टी  
के रूप में विकसित नहीं हो पा रही है?

## अगला चुनाव नये बदलाव की कहानी कहेगा

बेरोजगारी, लघु ग्रामीण उद्योग आदि  
मसलों को हल करने में लोकदल गांधीजी के  
सुझाये गये कार्यक्रमों को लागू करना चाहता  
है। हमारे देश में इंजन, हवाई जहाज, ट्रैक्टर  
जैसी चीजों को बनाने के लिए बड़े उद्योग धंधे  
तो होने ही चाहिए लेकिन इन के साथ ही बड़े  
परिणाम में छोटे छोटे उद्योग धंधे भी लगाये  
जाने चाहिए, जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों  
को रोजगार मिल सके। जिन दिनों मैं मुख्य-  
मंत्री था मैंने ग्राम उद्योग योजना शुरू की थी।  
इस में 90 प्रतिशत लागत धन की व्यवस्था  
नाममात्र के व्याज पर और 15 प्रतिशत धन  
के अनुदान (सबसिडी) की व्यवस्था की गयी। इस  
योजना के तहत करीब 1200 छोटे कारखाने  
लगाये गये, लेकिन मेरे बाद की सरकार ने  
इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखायी।

लोकदल में सब से बड़ी कमी यह है कि वह  
पूरी तौर पर संगठित नहीं है। पार्टी के पास  
जनाधार तो है लेकिन इसमें प्रतिबद्ध कार्य-  
कर्ता नहीं हैं।

क्या आपने अपने चुनाव घोषणापत्र में  
प्रदेश के किसानों के विकास के लिए कुछ  
नये मुद्दे उठाये हैं?

अपने घोषणापत्र में हमने एक बात कही  
है कि किसानों के कर्जें माफ हों—हमारे प्रदेश

में गरीब किसान मजदूर पर पचास करोड़ के  
लगभग कर्जें हैं। ये माफ हो जाने चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि सरकारी कर्मचारी  
की तरह 65 साल से ऊपर की आयु के किसान  
मजदूर को भी पेंशन दी जानी चाहिए।

तीसरा यह है कि नहरों एवं खालों का  
खर्च किसानों से न लिया जाये, आखिर जब  
उद्योगपति उद्योग लगाता है तो सरकार उसे  
कम कीमत पर जमीन देती है, पानी देती है,  
बिजली देती है तो आखिर किसान से खालों  
के निर्माण का खर्चा क्यों वसूला जाना चाहिए।  
नहरों और खालों को पक्का करने से पानी की  
बचत होगी, सिंचाई अधिक होगी और सरकार  
को भी कर के रूप में काफी फायदा होगा।  
इसलिए यह जरूरी है कि पक्की खालों का  
खर्चा माफ कर दिया जाये।

ऐसा लगता है कि हरयाणा की बहुसंख्यक  
ग्रामीण जनता लोकदल के साथ है फिर  
भी आपको निगाह में वे क्या कारण हैं  
जो चुनाव में पार्टी को कहीं कमजोर  
बनाते हैं?

दरअसल, लोकदल के शासन का मतलब  
है किसान मजदूर का शासन। प्रदेश की जनता  
यह बात अच्छी तरह समझती है। यही कारण  
है कि आप यहाँ लोकदल के प्रति उत्साह  
देख रहे हैं।

मैंने 'एक वोट और एक नोट' का नारा  
दिया है। इसका असर यह हुआ कि रोज हमें  
चार-पाँच हजार रुपये मनीआर्डर से आ रहे  
हैं अन्यथा रिवाज यह रहा है कि जब उम्मीद-  
वार आते हैं तो पैसा भी साथ लाते हैं लेकिन  
जनता का उत्साह देखिए अब तक कुल डेढ़  
लाख रु. आ चुके हैं। गाँव गाँव में फैले हुए लोक-  
दल के कार्यकर्ता जनसंपर्क कर के घन इकट्ठा  
कर रहे हैं और हमें भेज रहे हैं।

हमारा संगठन अब तक ठीक से विकसित  
नहीं हो पाया, उस का कारण आंतरिक चुनावों  
का न होना है। चरणसिंह और मुझ में कुछ  
मतभेद भी हुआ लेकिन अब मसला काफी  
हल हो चुका है। अब चुनाव प्रचार हेतु  
समिति बनी है जो काम कर रही है और धीरे  
धीरे हम लोकदल के संगठन को भी मजबूत  
करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस समय भी  
समिति अपने 4000 कार्यकर्ताओं को पत्रों  
के जरिये संगठित कर रही है जो जनता को  
पार्टी की विजय के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

यदि चुनाव में लोकदल को सरकार बनाने  
हेतु बहुमत मिल जाता है तो क्या प्रदेश  
की अपनी नयी राजधानी बसाने के बारे  
में सोचा जायेगा?

राजधानी के विषय में हम बाद में सोचेंगे,  
लोकदल की सरकार बनने पर क्या आप  
मुख्यमंत्री बनेंगे?

यह तय करना चुने हुए जनप्रतिनिधियों  
का काम है।



भाजपा गठजोड़ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने पर तैयार है। अन्त्य दलों में जनता पार्टी और जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस के नाम उल्लेखनीय हैं।

लोकदल (67 स्थान) और भाजपा (23 स्थान) ने 2 मई को रोहतक में एक विशाल आम सभा कर के अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। इस सभा को चौ. चरणसिंह और अटलबिहारी वाजपेयी के अलावा कर्नाटक में नये दल का गठन करने वाले देवराज अर्स ने भी संबोधित किया। श्री अर्स की इस उपस्थिति को राजनैतिक क्षेत्रों में काफी महत्व दिया जा रहा है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि देर सवेर लोकदल और भाजपा का विलय होने पर श्री अर्स भी उस में शामिल हो जायेंगे। □

आंध्र-कर्नाटक

## विधान सभाओं को आठ महीने का जीवनदान

काफी ऊहापोह के बाद इंडा आला कमान ने आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में फिलहाल चुनाव न कराने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे अन्य कारणों के अलावा एक प्रमुख कारण संभवतः आंध्र में नयी पार्टी का गठन और कर्नाटक में इंडा की घटती प्रतिष्ठा रही है। पिछले दो तीन महीनों में इन दोनों राज्यों में राजनैतिक घटनाचक्र इतनी तेजी से चला कि इंडा अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं रह पायी। कर्नाटक के भाषा विवाद ने भी इस फैसले में भूमिका निभायी होगी। अतः बेहतर होगा कि अभी चुनाव न कराये जायें। सारी स्थिति का विश्लेषण करते हुए हैदराबाद से दिनमान प्रतिनिधि श्रीराम शर्मा ने लिखा है :

निर्धारित समय से पहले दक्षिण के दोनों राज्यों में चुनाव की आवश्यकता क्यों हुई? यह बात स्पष्ट है कि विधानसभाओं को समय से पहले मंग करने या निर्लंबित रखने और किसी प्रदेश का शासन राज्यपाल को सौंपने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जनहित को ध्यान में रख कर नहीं किये जाते। सत्ताधारी राजनैतिक दलों के लाभ-हानि को ध्यान में रख कर सारे निर्णय किये जाते हैं। यह बात बार बार दोहराई गयी कि बंगाल और केरल में यदि इंडा की पराजय होती है तो उस से जो क्षति होगी उस की पूर्ति आंध्र और कर्नाटक की विजय से कर ली जायेगी। इस मनोवैज्ञानिक सूझ के अतिरिक्त भी कुछ कारण थे। दोनों राज्यों में इंडा विधायक दल बहुत से अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। आंध्र में इंडा का भारी बहुमत होतें हुए भी डॉ. चेन्ना रेड्डी ने बहुत से गैर इंडा विधायकों को अपने दल की सदस्यता प्रदान की थी। यह

भाजपा उद्योग परमाध्यम से नहीं किया था। डॉ. चेन्ना रेड्डी को विधानसभा के चुनावों के बाद शीघ्र ही पता चल गया था कि इंडा कोई सुगठित दल नहीं रह गया है। इंडा के कई प्रभावशाली विधायक चेन्ना रेड्डी के विरोध में संगठित होने लगे थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने विपक्ष के विधायकों को अपने दल की सदस्यता ही नहीं दी, तीन को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग भी दिये। डॉ. रेड्डी ने दलबदल को प्रोत्साहन दे कर इंडा के विरोधी गुट को कुछ समय के लिए खामोश कर दिया किंतु दो वर्ष बाद ही उन्हें अपने साथियों के विद्रोह के कारण पद छोड़ना पड़ा।

श्री अंजैया ने अपने दल के आघे से अधिक विधायकों को मंत्री पद पर या सरकार द्वारा संचालित निगमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निदेशक-संचालक के पदों पर नियुक्त कर के कुछ दिनों तक शासन का दायित्व संभाला था। नये मुख्यमंत्री भी निगमों और प्रतिष्ठानों से संलग्न विधायकों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। प्रत्येक इंडा विधायक अधिक से अधिक महत्व का पद पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कर्नाटक की स्थिति और खराब है। वहाँ विधानसभा का इंडा दल विपक्ष में बैठता था। उसके हाथ में सत्ता का सुयोग इसलिए आया कि कांग्रेस के विधायक देवराज अर्स का साथ छोड़ कर गुंडुराव के समर्थक बन गये। वहाँ इंडा ने मंत्रिमंडल अवश्य बना लिया, किंतु स्वामिमक्तों और कृतघ्नों का संघर्ष पहले दिन से ही चला आ रहा है।

इन स्थितियों में यह सोचा गया कि आंध्र और कर्नाटक दोनों जगह मध्यावधि चुनाव कराये जायें। जो लोग चुने जायेंगे, वे कम से कम दो-तीन साल तक खामोशी से काम करेंगे। इस तरह के विचार से यह संभावना जुड़ी थी कि दोनों राज्यों में श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभाव उसी तरह बना हुआ है, जैसे 1979-80 में था। वास्तविकता यह है कि इस बीच आंध्र की कृष्णा गोदावरी और कर्नाटक की कावेरी में बहुत सा पानी बह चुका है।

पहली बात तो यह है कि दोनों राज्यों में विपक्ष ही नहीं इंडा के विधायक भी दिल्ली के हस्तक्षेप की प्रत्यक्ष या छिपे छिपे निंदा करने लगे हैं। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अंजैया को जिस तरह राजीव गांधी ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर अपमानित किया और चलती विधानसभा को रुकवा कर उनसे जिस तरह त्यागपत्र दिलाया गया उसे प्रदेश की जनता पचा नहीं पायी है।

इस बीच एन. टी. रामाराव के नेतृत्व में गठित तेलुगू देशम नामक नये राजनैतिक संगठन ने आंध्रप्रदेश की मनस्विता को उद्बलित किया है। श्री रामाराव और उन के साथी मुख्य रूप से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंडा के मंत्रियों ने प्रदेश के आत्मसम्मान को अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया है।

## अर्स की नयी पार्टी

जैसी कि संभावना थी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अर्स ने 29 अप्रैल को कांग्रेस (स) से नाता तोड़ कर राज्य में एक क्षेत्रीय दल के गठन की घोषणा की है। उनका कहना है कि 'एक राजनैतिक दल के रूप में कांग्रेस (स) दिशाहीन हो गयी है।' श्री अर्स के साथ कई विधायकों और दल के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस (स) से नाता तोड़ लिया है। लेकिन इस बीच श्री अर्स के दो कट्टर समर्थक के. एच. श्रीनिवास और अजोब सेठ इंडा में शामिल हो गये हैं।

इंडा से अलग होने के बाद श्री अर्स को शीघ्र ही यह अहसास हो गया कि वह जिस कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उसका कोई भविष्य नहीं है। शायद इसी लिए वह अध्यक्ष के रूप में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाये और शीघ्र ही उन्हें महाराष्ट्र के युवा नेता शारद पवार के लिए गद्दी खाली करनी पड़ी। उस के बाद श्री अर्स ने विपक्ष के एकता प्रयासों में दिलचस्पी लेनी शुरू की।

एकता प्रयासों को ले कर कांग्रेस (स) की पैतरेबाजी श्री अर्स को नहीं भायी और उन्होंने कुछ दिन पहले दल के नेतृत्व को यह चेतावनी दे दी थी कि यदि एकता नहीं हुई तो वह क्षेत्रीय दल बना लेंगे। देखा यह है कि श्री अर्स का अब तक अनाम क्षेत्रीय दल सिरें चढ़ता है या कि नहीं।

कर्नाटक में भी क्षेत्रीय राजनैतिक दल के निर्माण की तैयारियाँ पूरी हो गयीं और देवराज अर्स ने कांग्रेस (स) से अलग होकर एक क्षेत्रीय दल का गठन कर लिया है। (बक्स देखें)

क्षेत्रीय संगठनों के कारण इंडा के नेता अपनी विजय के प्रति आश्वस्त नहीं रह पाये। वस्तुतः भाजपा, माकपा आदि संगठनों अब तक इंडा को दक्षिण के दोनों राज्यों इतना खतरा दिखाई नहीं दिया जितना क्षेत्रीय संगठन से दिखाई देता रहा है। आंध्रप्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में स्थापित तेलंगाना समिति ने निर्वाचनों में उस समय सफलता प्राप्त की थी। जब पूरे देश में इंदिरा जी की आँधी चल रही थी। दोनों राज्यों के क्षेत्रीय संगठन मुख्य रूप से उस वर्ग का सहयोग पाने के लिए प्रयास करेंगे जो अब तक इंडा की सहायता करता रहा है।

इस परिवर्तित स्थिति में यह उचित समझा गया कि आगामी आठ मास तक आंध्र और कर्नाटक में निर्वाचन न कराये जायें। तब तक क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जोश शांत हो जायेगा उस समय तक इंडा अपने भावी नेताओं की खोज भी पूरी कर लेगी।

दिनमान



पार्टी

विषय

नोटिक के मत-  
असं ने 29  
नाता तोड़ कर  
के गठन की  
था है कि एक  
कांग्रेस (स)  
सं के साथ कई  
अधिकारियों ने  
तोड़ लिया है  
के दो कट्टर  
और अजीब  
हैं।द श्री असं को  
कि वह जिस  
उसका कोई  
एलए वह अच्युत  
हो पाये और  
हुवा नेता शरद  
रनी पड़ी। उस  
एकता प्रयासोंकांग्रेस (स)  
ही भायी और  
के नेतृत्व को  
दि एकता नहीं  
लेंगे, देखना  
व तक अनाम  
कि नहीं।राजनैतिक दल  
यीं और देवरा  
कर एक क्षेत्री  
(बकस देवों)  
इंका के नेतृ  
नहीं रह गये  
दि संगठनों के  
दोनों राज्यों  
जितना क्षेत्रीय  
आंध्रप्रदेश के  
गाना समिति ने  
ता प्राप्त की है  
आंधी चल रही  
गठन मुख्य रूप  
के लिए प्रयत्न  
सहायता कर रहेह उचित समय  
तक आंध्र और  
जायें, तब तक  
जोश हाथ में  
ने भावी नेताओंह उचित समय  
तक आंध्र और  
जायें, तब तक  
जोश हाथ में  
ने भावी नेताओंह उचित समय  
तक आंध्र और  
जायें, तब तक  
जोश हाथ में  
ने भावी नेताओंह उचित समय  
तक आंध्र और  
जायें, तब तक  
जोश हाथ में  
ने भावी नेताओं

फॉकलैंड

## यह युद्ध बिल्कुल नहीं है!

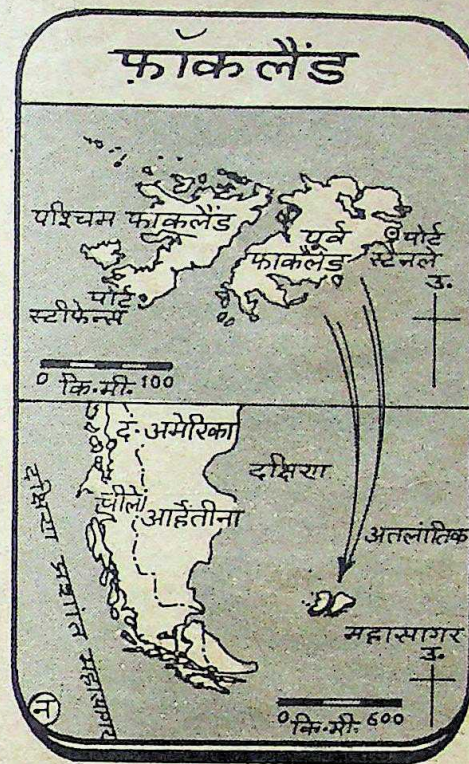
समस्या का राजनैतिक समाधान ढूँढ़ते ढूँढ़ते आज फॉकलैंड के प्रश्न पर आर्जेंटीना और ब्रिटेन लड़ाई के मैदान में हैं। समुद्री और वायु लड़ाई दोनों के बीच हो रही है। आर्जेंटीना की ओर से कहा गया है कि ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपसमूह में अपनी सेनाएँ उतारने की कोशिश की लेकिन आर्जेंटीना के तोपखाने ने उन की इस कोशिश को बेकार कर दिया। अंतिम समाचार मिलने तक ब्रितानी सेनाओं फॉकलैंड में उतरने की कोई खबर नहीं आई। कार्रवाई वे आत्मरक्षा के लिए ही कर रहे ब्रितानी रक्षा विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि यह युद्ध बिल्कुल नहीं है। संयुक्तराष्ट्र संघ के अनुसार यह केवल आत्मरक्षा की कार्रवाई है।

फॉकलैंड द्वीपसमूह से कुछ दूर ब्रितानी सैनिक बेड़े की पनडुब्बियों द्वारा आर्जेंटीना के युद्धपोत क्रूजर नष्ट करने के बाद आर्जेंटीना ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर देना आभाषित ही था। पर अब ब्रिटेन और आर्जेंटीना की लड़ाई भयंकर रूप धारण कर गयी है। इस आयसं की सैनिक सरकार का कहना है कि अमेरिकी शांति योजना संतोषजनक नहीं और अब तो ब्रिटेन के आर्जेंटीना का क्रूजर नष्ट करने से स्थिति और भी खराब हो गयी है।

ब्रितानी विदेशमंत्री ने, जो अमेरिका और संयुक्तराष्ट्र के नेताओं से बातचीत के लिए अमेरिका गये थे स्पष्ट कहा है कि बातचीत अगर शुरू नहीं होती तो ब्रिटेन का जीतना निश्चित है। ब्रिटेन ने यह भी घोषणा की है कि आर्जेंटीना एलिजाबेथ द्वितीय बड़ा युद्धपोत कोई भी तीन हजार सैनिकों को ले कर फॉकलैंड द्वीपसमूह पर डबोया गया। ब्रिटेन का कहना है कि यह ब्रितानी नौसेना के लिए एक खतरा था।

अमेरिका लड़ाई रोकवाने के लिए पेरू के राष्ट्रपति का कहना है कि आर्जेंटीना को बराबर शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। आर्जेंटीना के राष्ट्रपति का कहना है कि हमें बराबर अस्वीकार किया जा रहा है। अंतिम प्रस्तावों में फॉकलैंड से आर्जेंटीना के दस हजार सैनिक वापिस बुलाने की बात कह रहा है। ब्रिटेन अपना नौसैनिक समूह वापिस बुला सकता है।

संयुक्तराष्ट्र की मूमिका: ब्रितानी विदेश-सचिव श्री पेयम ने फॉकलैंड के झगड़े में संयुक्तराष्ट्र की कोई मूमिका होने की संभावना से



इनकार किया है। उन का कहना है कि आर्जेंटीना जब तक फॉकलैंड से अपनी सेना नहीं हटाता झगड़ा तय नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ बातचीत में भी ब्रितानी विदेशमंत्री ने यही बात दोहरायी है। उन का कहना है सैनिक कार्रवाई के सिवाय ब्रिटेन के पास कोई चारा ही नहीं रह गया था। ब्रितानी विदेशमंत्री कहते हैं कि हम ब्रितानी मूमि और ब्रितानी लोगों की रक्षा के लिए ही वहाँ गये हैं। पूरी सैनिक कार्रवाई से पहले हम बातचीत के लिए तैयार थे और अब भी हैं। हम तो फॉकलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं।

उधर समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए प्रयत्न जारी है। लेकिन ब्रितानी विदेशमंत्री फ्रांसिस पेयम ने फॉकलैंडवासियों के नाम एक प्रसारण में कहा है, युद्ध बढ़ भी सकता है। श्री पेयम अमेरिकी विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग से बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन रवाना हो चुके थे। फिर उनका संयुक्तराष्ट्र महासचिव कूलर से मिलने न्यूयॉर्क जाने का विचार है। बताया जाता है कि युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर नये सिरे से बातचीत करने के लिए भी यह सब कुछ हो रहा है। आर्जेंटीना के विदेशमंत्री कोस्टा मेंडेज ने संयुक्तराष्ट्र मुख्य कार्यालय में संकेत दिया है कि आर्जेंटीना संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमल करने के लिए तैयार है और संकट के समाधान के लिए संयुक्तराष्ट्र की मध्यस्थता आर्जेंटीना को स्वीकार है। साथ ही आर्जेंटीना के विदेशमंत्री ने यह भी कह दिया है कि फॉकलैंड द्वीपसमूह

पर आर्जेंटीना की प्रभुसत्ता के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती। ब्रिटेन और आर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड द्वीपसमूह पर युद्ध शुरू होते ही सोवियत संघ अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद के साथ जुड़ रहा है।

अमेरिका हालाँकि ब्रिटेन और आर्जेंटीना के बीच लड़ाई शुरू होने से कुछ पहले तक समस्या के समाधान की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा विदेशमंत्री श्री हेग ने ब्रिटेन के फॉकलैंड पर आक्रमण के समाचार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह तो होना ही था। स्पष्ट है कि ब्रिटेन ने सैनिक कार्रवाई से पहले अमेरिका से पूरी तरह विचारविमर्श कर लिया होगा। आर्जेंटीना सरकार ने ब्रिटेन पर संयुक्तराष्ट्र प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

**संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् फॉकलैंड द्वीपसमूह पर पहले ही एक प्रस्ताव पास कर चुकी है** जिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युद्ध तुरंत समाप्त किया जाये और आर्जेंटीना फॉकलैंड द्वीपसमूह से अपनी सेनाएँ हटा ले। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कुछ सूत्रों के अनुसार अपनी एक और बैठक में संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद् फॉकलैंड द्वीपसमूह से आर्जेंटीना की सेनाएँ हटाने की एक तारीख भी तय करने वाली है। अमेरिका के इस प्रस्ताव का भी समर्थन करने की पूरी संभावना है।

आर्जेंटीना के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा ब्रिटेन ने इस विवाद के शुरू होते ही कर दी थी। ब्रिटेन के साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने भी आर्जेंटीना से आयात बंद कर दिया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टैचर ने इसे यूरोपीय एकता का प्रतीक बताया था। ताज़ा समाचारों के अनुसार जापान भी आर्जेंटीना की आर्थिक नाकेबंदी में शामिल हो रहा है।

आर्जेंटीना के फॉकलैंड द्वीपसमूह पर कब्जा करते ही सोवियत संघ ने आर्जेंटीना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था। फ्रांस ने आर्जेंटीना के हाथ हथियार बेचने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन का विश्वास था कि आर्जेंटीना के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से आर्थिक दृष्टि से आर्जेंटीना को काफी नुकसान पहुँचेगा और फॉकलैंड द्वीपसमूह का मामला ब्रिटेन से तय करने के लिए वह मजबूर हो जायेगा। लेकिन आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक नाकेबंदी के बावजूद आर्जेंटीना फॉकलैंड द्वीपसमूह पर अपनी प्रभुसत्ता मनवाने के लिए युद्ध कर रहा है। □



# जहाँ 102 वर्ष पूर्व भारतीय पहुंचे थे

ब्रह्मवत् स्नातक

प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में असंख्य छोटे और बड़े द्वीप हैं। इन में फीजी द्वीपसमूह है जिसे छोटा भारत कहा जाता है। उस देश में भारतवासियों की जनसंख्या कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक है। 44 प्रतिशत लोग आदिवासी या मूल निवासी हैं जिन को वहाँ कार्डीबीती कहा जाता है। चार प्रतिशत में चीनी मूल के तथा मिश्रित नस्ल के लोग, जिन्हें वहाँ पार्ट (यूरोपीय) कहा जाता है तथा पास के रोटुमन आदि द्वीपों के निवासी हैं।

अब से 102 वर्ष पूर्व भारतवंशियों का पहला दल वहाँ पहुँचा था। इन जाने वालों में से लगभग सभी लोग मुख्यतः पूर्वी उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद आदि के अलावा बनारस, जौनपुर आदि के थे। इस के अतिरिक्त ब्रज प्रदेश के मथुरा, आगरा आदि से भी वहाँ लोग गये। बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र छपरा, पटना आदि से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। इस के अतिरिक्त राजस्थान के शेखावाटी तथा अजमेर आदि स्थानों से एवं वर्तमान मध्यप्रदेश के बुंदेलखंडी क्षेत्रों से भी कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे। चूँकि इन सब की भर्ती कलकत्ता के मटियाबुज भर्ती केंद्र से हुई थी, इनको बोलचाल की भाषा तथा सरकारी कागजों में कलकत्तिया कहा गया।

कालांतर में मद्रास में एक भर्ती केंद्र खोला गया। इस से दक्षिण के राज्यों से तमिष, तेलुगु, कुछ मलयालम भाषी तथा मराठी भाषी भी फीजी में पहुँचे। सरकारी आँकड़ों के अनुसार

विभिन्न खेपों में, जिस की शुरुआत 1879 में हुई थी और जो 1920 तक अवधि तक चली रही, भारत से पहुँचने वालों की कुल संख्या 60 हजार के लगभग थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रितानी साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी, और उस के बाद राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक विपन्नता के फलस्वरूप तथा अकाल की छाया पड़ने एवं भारतीय घरेलू उद्योगों के ह्रास के कारण भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को शर्तबंद कुली प्रथा के अंतर्गत मॉरिशस, त्रिनिदाद, सुरीनाम तथा फीजी आदि देशों में ले जाया गया था। ये मजदूर जहाँ अत्यंत परिश्रमी पाये गये वहाँ इन को वहाँ की दृष्टि से न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी और एक करार के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए उन देशों में जाना पड़ता था।

फीजी में पाँच वर्ष तक काम करने के बाद वे लोग वापस स्वदेश लौट पड़े। स्वदेश अपने खर्च पर जाने को स्वतंत्र थे और अगले पाँच वर्ष तक और काम करने पर वे मालिकों के खर्च पर भारत लौट सकते थे। चूँकि ये लोग एक करार के अंतर्गत फीजी गये थे, इन को वहाँ 'एग्मीमेंट' शब्द से बने अपभ्रंश यानी 'एग्मीमेंट-गिरमिट' से निकला शब्द गिरमिटिया कहा जाता था। यह हिंदी भाषा के लचीलेपन का सबूत है कि मजदूरों ने एक अंग्रेजी शब्द एग्मीमेंट को गिरमिट और गिरमिटिया से गढ़ लिया। इसी प्रकार इन मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए लगे अफसर को (जो सदा शुरू में गोरे ही होते थे) 'काल नंबर' कहा जाता है। वह मजदूरों को नाम से नहीं, अपितु नंबरों से पुकारा करता था। भारतवंशियों ने अपनी भाषा में उस का नाम कालनंबर से बदल कर "कोलंबर" कर लिया था।

भारत से करार के अंतर्गत गये इन गिर-

मिटियों में से बहुत से लोग मार्ग में होने वाले कठिनाइयों, फिर वहाँ पर अपने गोरे मालिकों के अत्याचारों के कारण, सामाजिक जीवन के बिखराव परिवार से विलगता, आत्म-पातक संख्या में स्त्रियों की कमी आदि कारणों से या तो अवधि के पश्चात् भारत लौट आये। इन में से कुछ लोग जातिबहिष्कार, समुदाय यात्रा के बाद प्रायश्चित्त तथा धार्मिक अवशिष्टों के शिकार हो कर पुनः फीजी लौट गये। कुछ ने फीजी जाते हुए या वहाँ पहुँच कर आत्महत्याएँ कर लीं। इन में बड़ी संख्या मालिकों द्वारा की गयी विषयवासना का शिकार स्त्रियों की भी थी। वैसे फीजी की समृद्धि की कहानी सुन कर त्रिनिदाद, मॉरिशस आदि देशों में पहले गये कुछ भारतवंशी मजदूर भी अपनी करार की शर्त पूरी करने के बाद वहाँ पहुँचे थे। गिरमिट प्रथा के समाप्त होने के बाद पंजाब एवं गुजरात के लोग जमीन एवं व्यापार की खोज में फीजी पहुँचे। आज यह वर्ग अपेक्षाकृत समृद्ध है।

फीजी में रह रहे इन भारतवंशियों की दुर्दशा को देख कर कुछ गोरे ईसाई मिशनरियों ने सब से पहले अपनी रपटों से ब्रितानी सरकार का तथा समाचारपत्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा। भारत में यहाँ की सरकार और जनता का ध्यान सब से प्रथम गिरमिट प्रथा के अंतर्गत भारत से फीजी जा कर पुनः वहाँ से लौटे स्वर्गीय पंडित तोता राम सनाढ्य ने किया। "फीजी में मेरे 21 वर्षों का नामक इस ऐतिहासिक पुस्तक को 1914 में श्री पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने उस समय लिपिवद्ध एवं संपादित किया था। इस के प्रकाशित होने के बाद इस के संस्करण अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं में भी निकले। जनता एवं समाचारपत्रों में एक आक्रोश जागा स्वामी सी. एफ. एड्जुज वहाँ पर गये। राइट आनरेबल श्री निवास शास्त्री एवं स्वामी भवानीदास जी ने इस संबंध में आंदोलन किया। लेख लिखे इस के परिणामस्वरूप यह शर्तबद्ध कुलीप्रथा समाप्त हो गयी। आज इन गिरमिटियों की तीसरी और चौथी पीढ़ी फीजी के नवनिर्माण में जुटी हुई है।

गत वर्ष मेलबार्न राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के भाग लेने से पूर्व भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी फीजी सरकार के निमंत्रण पर वहाँ पहुँची थीं। भारत के विभिन्न प्रांतों के इन गिरमिटियों ने स्वदेश छोड़ते ही अपनी जातिगत, प्रांतगत और भाषागत संकीर्णता को तिलांजलि दे दी। आज समूचे फीजी में विदेशी कर बीतीलैवु और वनुआलैवु नामक दो भाषा द्वीपों में—जहाँ कि फीजी की कुल 6 लाख जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग रहता है—वहाँ हिंदुस्तान के फीजी रेडियो के समाचार गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बातचीत तथा साइनबोर्ड के द्वारा आज भी अच्छी प्रकार समझी जाती है।

फीजी की एक सामूहिक नृत्यमंडली : मिश्रित संस्कृति का प्रतीक





में होने वाली गोरे मालिकों माजिक जीवन लगता, आन-कमी आदि का तात् भारत लोह विष्कार, समु-धमिक अंध-नः फीजी लोह वहाँ पहुँच का बड़ी संख्या धयवासना का वैसे फीजी को सदाद, मॉरिशस छ भारतवर्षी तें पूरी करने के प्रथा के समा-के लोग जमी-पहुँचे. आज का रतवशियों का आई मिशनरियों ब्रतानी सरकार आमाजिक कार्य-रत में यहाँ का सब से प्रथ-त से फीजी का डित तोता रा-मेरे 21 वर्ष का 1914 में ने उस समय-त. इस के प्रक-रण अंग्रेजी ए-ले. जनता ए-जागा स्वर्गी-राइट आनरेब-ने भवानीदया-न्या. लेख लि-तबद्ध कुलीप्र-गरमितियों के ने के नवनिर्मा-तीय सम्मेलन-तमन्त्री श्रीम-निमंत्रण पर व-प्रांतों के इ-नी अपनी जाति-संकीर्णता के-नीजी में विवे-नामक दो ब-कुल 6 लाख-भाग रहता है-ने के समा-को के बातचीत-अच्छी प्रक-

## सुहर्त सकता है

## दुनिया भर की

Digitized by eGangotri Foundation

एशिया के एक और देश तूदी के दूसरे महत्वपूर्ण देश इंदोनेसिया का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है 1966 में जनरल सुहर्त के सत्ता में आने के बाद यह तीसरा चुनाव था लेकिन परिणाम लोक से हट कर नहीं थे. जैसे मलयेसिया के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भविष्यवाणी की थी वैसे ही इंदोनेसिया में भविष्यवाणियों ने अनुकूल सत्तारूढ़ गोलकर को ही 460 सदस्यीय संसद में बहुमत प्राप्त होने की भविष्यवाणी की है. अन्य दो प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टियों इंदोनेसियाई डेमोक्रेटिक पार्टी (पी. डी. आई.) और मुस्लिम पार्टी जो पी पी पी के नाम से अधिक लोकप्रिय है की न तो गोलकर से जीत लेने की हैसियत है और न ही दमखम. लोक राष्ट्रपति सुहर्त ने इंदोनेसिया में लोकतंत्र को बहाली की है. लेकिन वह उस तरह का लोकतंत्र नहीं जैसा ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों में है. इन देशों में 160 सदस्यों का पाँचवाँ हिस्सा अर्थात् तीसरा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं. इन देशों में लोक के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है. सुहर्त आज भी सेना का दबदबा पहले जैसा है. यद्यपि इंदोनेसिया की चुनाव सभाओं में लोगों को दिलचस्पी और उपस्थिति विख्यात लोकतंत्री देशों से किसी मायने में कम नहीं है. यहाँ के लोग अपने आप पर बंदिश नहीं करते हैं. चुनाव पूर्व जितनी भी सत्ता हुई उन में बड़ी संख्या में भीतें हुई. लोगों का कारण भगदड़ बताया गया. भगदड़ का कारण इंदोनेसिया में नतेंकों और लोकतंत्र के कारण भगदड़ का कारण बने. इंदोनेसिया में चुनाव प्रचार के लिए 45 दिन का समय था. उस के बाद चुनाव सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और चुनाव सभाओं पर भी अर्थात् मतदान से चार दिन का समय था. कारण यह बताया गया कि मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने में 'ठंडे दिलोदिमाग' की जरूरत होती है. यदि समाचारपत्र और चुनाव सभाओं के मतदान के समय तक सक्रिय रहेंगी तो मतदान के दिन मतदाताओं का प्रयोग निष्पक्ष होगा. इंदोनेसिया की 148,085,000 जनसंख्या (1979 का आँकड़ा) में आठ करोड़ लोग हैं. 1966 में सत्ता में आने के बाद 4 मई 1982 को जनरल सुहर्त ने संसद का यह

पश्चिमी पाप संस्कृति और उस के किशोर हसी हिमायतियों की भर्त्सना करते हुए अपने पत्र में रोज गूँथ होने वाली ऐसी चिट्ठियाँ लिखीं जिन में पाप संगीत को 'गंभीर और अर्थहीन' और 'अंधा' के रूप में फरवरी 1978 में रॉक बैंड के एक सदस्य को



सुहर्त : तीसरी विजय

तीसरा चुनाव कराया. पहले दो चुनाव 1971 और 1977 में हुए थे. पहले के दोनों चुनावों में गोलकर पार्टी ने सिरतोड़ बहुमत प्राप्त किया था. गंभीर इंदोनेसियाईयों और चुनाव विश्लेषणकर्ताओं के अनुसार देश में परिवर्तन आसान नहीं. इस समय देश में सत्ता पर सेना का पूर्ण नियंत्रण है और इसे स्वीकृत और सहज मान लिया गया है. एक तो 460 सदस्यीय संसद में पाँचवाँ हिस्सा सदस्य सत्ता द्वारा नामजद किये जाते हैं और दूसरे यहाँ की राष्ट्रपतीय प्रणाली में सत्ता संसद में निहित नहीं बल्कि एक कार्यापालिका में है जिसे संसद नहीं चुनती बल्कि 920 सदस्यीय जन सलाहकार सभा चुनती है. इन में आधे सदस्य संसद के होते हैं और शेष आधे विभिन्न क्षेत्रों, संगठनों और राजनैतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस प्रकार नामजद सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक होती है.

1965-66 में छात्रों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी वह अब इतिहास की घटना बन गयी है. छात्रों का दायरा अब विश्वविद्यालयों तक सिमट कर रह गया है. और तो और 1978 में उन्हीं कल के छात्रों ने आज के छात्रों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की माँग की थी. यही कारण है कि पिछले दिनों कुछ विदेशी राजनयिकों ने कहा भी कि 'इंदोनेसिया में राजनीति लगभग मर चुकी है'. अब तो नाम मात्र की राजनैतिक संस्थाएँ रह गयी हैं. इसी के फलस्वरूप इंदोनेसिया में पार्टियाँ सिमटी हैं. 1971 में अधिसंख्य पार्टियों का सत्तारूढ़ गोलकर में विलय हो गया. गोलकर के अलावा दो अन्य पार्टियाँ हैं: पी डी आई और पी पी पी. पी डी आई में इंदोनेसिया के संस्थापक और भूतपूर्व मरहूम राष्ट्रपति डॉ. सुकर्ण के समर्थक हैं. इन में कम्युनिस्ट और ईसाई भी शामिल हैं. मुसलमानों के बाद अल्पसंख्यक ईसाईयों का महत्वपूर्ण स्थान

अमेरिकी दायरा के 39 वर्षीय अधिकारी गुओन ब्लूफोर्ड अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे. अब तक अंतरिक्ष में भेजे गये यात्रियों में सैली सब से कम उम्र की हैं और इस यात्रा के दौरान उन के जिम्मे उन तीन उपग्रहों की निगरानी का काम होगा जिन में से एक को पश्चिम जर्मनी के वैज्ञानिक गोर्गों के लिए और अन्य दो को कनाडा और इंदोनेसिया की संचार व्यवस्था के लिए 'चैलेंजर' ने छोड़ा है.



पिछल चुनाव में पा पा पा का 29 प्रतिशत मत मिले थे. बावजूद इस के गोलकर पार्टी की स्थिति दृढ़ है. गोलकर की मजबूती सुहर्त की मजबूती है और जब तक सुहर्त हैं इंदोनेसिया में उनके नेतृत्व को चुनौती देने का फिलहाल किसी में भी दमखम नहीं दीखता. इस का कारण यह है कि जो सुकर्ण को सत्ता से बेदखल करने की जुर्रत कर सकता है क्या उसे बेदखल करना आसान है, अवश्य विचारणीय प्रश्न है. □

अल साल्वाडोर

## नये राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा

आल्वारो मैगना ने 2 मई को अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति का पद सौमालते ही अशांति से पीड़ित देशवासियों को आश्वासन दिया कि अब से उन का हर दिन देश में पनपने वाली उस हिंसा को रोकने की कोशिश में बीतेगा जिससे तीन वर्ष से भी कम समय में 30,000 जानें चली गयी हैं. इस राजनैतिक हिंसा को रोक कर देश में शांति स्थापित करना ही उन का प्रमुख लक्ष्य होगा.

अल साल्वाडोर की संसद ने भूतपूर्व बैंक अधिकारी और स्वतंत्र राजनीतिक मैगना को देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना. संसद द्वारा सीधे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नया संविधान बनाये जाने तक वह इस पद का कार्यभार सौमाले रहेंगे. 28 मार्च को अल साल्वाडोर में आम चुनाव संपन्न होने के बाद से राष्ट्रपति के चयन के बारे में विभिन्न दल एकमत नहीं हो पाये थे. एक महीने के मतभेदों के बाद मैगना को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के पद पर बिठाया गया.

आल्वारो मैगना यद्यपि देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं लेकिन साथ यह बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस शांति की खातिर वह वामपक्षीय छापामारों से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं. 'हमारे पास बातचीत के लिए कोई मुद्दा नहीं है.' उन्होंने अपने सहायकों को बताया. इसलिए दो वर्ष का गृहयुद्ध समाप्त करने के लिए कोई अन्य तरीका अपनाना होगा.



# जहाँ 102 वर्ष पूर्व भारतीय पहुंचे थे

राष्ट्रवास्तु स्नातक

प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में असंख्य छोटे और बड़े द्वीप हैं। इन में फीजी द्वीपसमूह है जिसे छोटा भारत कहा जाता है। उस देश में भारतवासियों की जनसंख्या कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक है। 44 प्रतिशत लोग आदिवासी या मूल निवासी हैं वह दश में युद्ध के कारण अस्तव्यस्त जीवन को सजग और सामान्य बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे एकजुट हो कर देश की समस्याओं को मिटाने की कोशिश करें। असंतोष, बदले की भावना और जातिगत राजनीति से ऊपर उठ कर वे युद्ध के थपेड़ों से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने में सरकार का हाथ बँटाये। नये राष्ट्रपति का देशवासियों के नाम यह संदेश टेलीविजन के माध्यम से देश भर में प्रसारित किया गया। □

कुवैत

## पुरखे हमारे सेतु बने

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान (10-11 मई, 1981) जब कहा कि खाड़ी के देशों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए तो इस का माकूल असर हुआ था। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा (जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी) से बेशक दोनों देशों की करीबी और करीब आयी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा कुवैत के अमीर शेख जबर अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह की तीन दिवसीय भारत यात्रा (9-11 सितंबर, 1980) के जवाब में की गयी (कुवैत के किसी अमीर की पहली भारत यात्रा थी)। श्रीमती गांधी की भावनाओं के अनुरूप ही पिछले दिनों कुवैत की संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेता जासिम अल सऊ ने अपनी नयी दिल्ली यात्रा के दौरान (23 अप्रैल, 1982) कहा कि 'कुवैत के भारत से विशेष संबंध हैं। हमारे पुरखे अरब सागर और हिंदमहासागर पार कर भारत पहुंचे थे। तभी से हम दोनों मुल्कों के बीच व्यापार के घनिष्ठ संबंध बने और बढ़े हैं।'

कुवैत का इस समय विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। वह दुनिया का सब से अमीर मुल्क है (1976 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सवा लाख रुपये है) भारत से वह मसाले, फल, काँफी, चाय, मांस, मशीनें, लोहा और इस्पात का आयात करता है। पिछले वर्ष

दिनमान

जिसमें खेपों में, जिस की शुरुआत 1879 में हुई थी और जो 1920 तक अर्धव्यवस्थित रही, भारत से पहुंचने वालों की कुल संख्या 60 हजार के लगभग थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रितानी साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी, और उस के बाद राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक विपन्नता के फलस्वरूप तथा अकाल की छाया पड़ने एवं भारतीय घरेलू उद्योगों के ह्रास के कारण भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को शर्तबंद कुली प्रथा के अंतर्गत मॉरिशस, त्रिनिदाद की सुरीनाम तथा फीजी आदि देशों में कुवैत की गया था। ये मजदूर जहाँ अल में 52 प्रतिशत विदेशी हैं। विदेशियों में फिलिस्तीनी, मिस्री, इराकी, ईरानी, भारतीय और पाकिस्तानी हैं (भारतीयों की संख्या 1,15,00 कूती जाती है)। कुवैत का क्षेत्रफल सात हजार वर्गमील



शेख जबर अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह और युवराज शेख साद अल-अब्दुल्ला अल-सलीम अल-सबाह : लोककल्याण पहले

है। तेल से प्राप्त होने वाले धन का प्रयोग सामाजिक लाभों के तौर पर 1951 से किया जा रहा है। कुवैत सरकार कल्याणकारी कार्यों पर खासा धन खर्च करती है। सब से अधिक व्यय शिक्षा और चिकित्सा पर होता है। कुवैत में प्रति दस हजार व्यक्तियों के पीछे 20 डॉक्टर हैं। शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। बजट का 14 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है जब कि इटली में 4.3 प्रतिशत और पश्चिम जर्मनी में 4 प्रतिशत होता है।

कुवैत में कभी पानी नहीं था। 25 वर्ष पहले तक पीने का पानी इराक से आयात किया जाता था। आज कुवैत में 5620 लाख गैलन पानी प्रतिदिन निकाला जाता है। इस के लिए कुवैत ने अपनी एक परियोजना विकसित की है। पानी लोगों को मुफ्त दिया जाता है। पानी से जुड़ी बिजली भी है जिस के लिए नाममात्र शुल्क लिया जाता है। कुवैत में आयकर नहीं,

मिटियों में से बहुत से लोग मार्ग में होकर के कठिनाइयों, फिर वहाँ पर अपने गेहों पदार्थों के अत्याचारों के कारण, सा पाउडर आदि के बिखराव परिवार से दूद होने से बहुत पातिक संख्या में स्त्रियों की कीमत नहीं के कारणों से या तो के भीतर टेलीफोन करने को आये। इन में है। वास्तव में कुवैत जैसी कल्याण-यात्रा केवघाए तो पश्चिमी देशों में भी नहीं। विष्कुवैत में केवल तेल ही नहीं होता बल्कि पिछले दिनों औद्योगिक विकास भी संभव हुआ है। कुवैत के कारखानों में धातु की पाइप, कृषि उत्पाद, बिजली के प्लग और निर्माण-कार्य के लिए सामग्री तैयार की जाती है। अल्युमिनियम, इस्पात और सीमेंट स्थानीय बाजार में ही उपलब्ध है। लेकिन औद्योगिकीकरण यहाँ पर सफल नहीं। एक तो बाजार छोटा है और दूसरा ज्यादातर जमीन रेतीली है। लिहाजा



शेख जबर अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह और युवराज शेख साद अल-अब्दुल्ला अल-सलीम अल-सबाह : लोककल्याण पहले

कुवैत सरकार अपने यहाँ औद्योगीकरण से बेहतर वस्तुओं का आयात करना समझती है। यही कारण है कि कुवैत शासक अपनी पूँजी दूसरे देशों में लगा रहे हैं ताकि लगातार आय के स्रोत बने रहें। एक दिन ऐसा आयेगा कि विदेशों में लगी पूँजी से कुवैत इतना धन अर्जित कर ले जितना वह तेल की बिक्री से कमाता है।

पश्चिमेशिया में तेल पैदा करने वाले देशों में कुवैत का तीसरा स्थान है और दुनिया में सातवाँ। लेकिन वास्तव में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पश्चिमेशियाई देशों में केवल कुवैत में ही है। 19 जून 1961 को स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद कुवैत में जो संविधान बना उस में शेख जबर अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह कुवैत के अमीर हैं तथा शेख साद अल-अब्दुल्ला अल-सलीम अल-सबाह युवराज और प्रधानमंत्री। लेकिन संसद सदस्यों की शिकायतों और मुआवों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है।

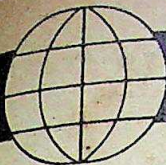


में होयिक के  
गोवाच पदाको  
पाउडर और  
होने से बहुत  
नीमत नहीं के  
फोन करने की  
जैसी कल्याण-  
में भी नहीं  
होता बल्कि  
स भी संभव  
पाउ की पाइ,  
और निर्माण-  
की जाती है  
नेमेट स्थानीय  
औद्योगिकीकरण  
वाज़ार छोटा है  
ली है, लिहाज़ा

अल-सलीम

औद्योगिकीकरण  
ना समझती है  
क अपनी पूँजी  
लगातार आ  
आयेगा कि  
नना धन अर्जित  
से कमता है  
करने वाले देशों  
और दुनिया में  
कतवीय शासन  
में केवल कुछ  
वाधीनता प्राप्त  
न बना उस देश  
कि वह आर्थिक नाकाबंदी और  
शमभण तक की बात सोच  
रिस्को का अंधेरा पक्ष  
सूय की युवा पीढ़ी के समाचार-  
स को मोनोल्सकाया प्राब्दा ने

15 मई '82



# दुनिया भर की

## जमीन की चोरी

इसाइल अधिकृत युर्दान नदी के पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में, ज़ाली अधिकारपत्रों की सहायता से, बड़े पैमाने पर ज़मीन की चोरी की खबरें मिल रही हैं। बरादाद ऑब्ज़र्वर के अनुसार 1967 से ही इसाइली सरकार, ज़मीन खरीदने के नाम पर, फ़िलिस्तीनियों को उन की ज़मीन से बेदखल करती रही है और 1967-68 के दौरान उसने लगभग 700000 हेक्टेयर ज़मीन के मालिकों से उन की ज़मीन हड़प ली थी। अब इसाइली सरकार कुछ विशेष संस्थाओं को पश्चिमी तट की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की छूट दे रही है, जो कि शीघ्र जिनेवा सम्मेलन के खिलाफ़ है। अब लोगों की ज़मीन का इस्तेमाल नयी वस्तियाँ बसाने, बेती करने और पानी के नये स्रोत प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

## उत्तर का 'फ़ॉकलैंड'

दक्षिण अतलांतिक में फ़ॉकलैंड ग्रेप को ले कर ब्रिटेन और आर्जेन्टीना में विवाद छिड़ा हुआ है और इसी से मिलती-जुलती स्थिति उत्तर अतलांतिक के सेंट पीएरे में बनती जा रही है। न्यूफ़ाउंडलैंड के तट से हट कर दो नन्हें द्वीपों के दूने वाले आतंकित हैं कि उन पर अधिकार को ले कर फ़्रांस और कॅनाडा में युद्ध की नींवत न आ जाये। इस समय यहाँ फ़्रांस का शासन है और ओटावा को भय है कि साम्रा वाज़ार की मछली पकड़ने वाली नौकाएँ इन दोनों द्वीपों को पार कर के कॅनाडा के समुद्री क्षेत्र में आसानी से आ सकती हैं। फ़्रांसीसी सिनेट में 8000 जनसंख्या वाले इस उप-विभाग के प्रतिनिधि मार्क प्लांता-मैन्स ने दावा किया कि कॅनाडा को मुद्दे को ले कर इतना चिंतित हो कि वह आर्थिक नाकाबंदी और शमभण तक की बात सोच

पश्चिमी पाँप संस्कृति और उस के किशोर रूसी हिमायतियों की भर्त्सना करते हुए अपने पत्र में रोज़ प्राप्त होने वाली ऐसी चिट्ठियाँ छापी हैं जिन में पाँप संगीत को सस्ता, विदेशी और अर्थहीन कहा गया है। इस वर्ष फ़रवरी में इस पत्र में स्वीडन के रॉक संगीत दल ऐब्बा पर वार करते हुए एक लेख छपा था, जिस पर बनायी गयी फ़िल्म को कुरुचि-पूर्ण और अश्लील बताया गया। रूस में 1981 में दिखायी गयी यह फ़िल्म तब दर्शकों में बहुत लोक-प्रिय हुई थी, लेकिन अब उस का प्रदर्शन रोक दिया गया है।



गत वर्षों से रूस में डिस्कोथेकों (पाँप संगीत और नृत्यशालाएँ) की भरमार हो गयी है और यहाँ पर बजायी जाने वाली 'अमेरिकी धुनों' को कलाविहीन बताया गया है। 'डिस्को का अंधेरा पक्ष' शीर्षक वाले लेख में डिस्कोथेक जाने का शौक रखने वाले युवक-युवतियों पर भी जोरदार प्रहार किया गया है—'इन के दिमाग़ बिल्कुल खाली हैं और वे इधर उधर नाचते रहने के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहते। यही इन का जीवन दर्शन है'।

## अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी स्त्री

30 वर्षीया खगोल भौतिक-विद सैली राइड अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी स्त्री होगी, जो 20 अप्रैल, 1988 को, अन्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, अंतरिक्ष यान चैलेंजर में छह दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होगी। उन के साथ उड़ान भरने वाले

अमेरिकी धातुसैनी के 39 वर्षीय अधिकारी गुओन ब्लूफ़ोर्ड अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। अब तक अंतरिक्ष में भेजे गये यात्रियों में सैली सब से कम उम्र की हैं और इस यात्रा के दौरान उन के जिम्मे उन तीन उपग्रहों की निगरानी का काम होगा जिन में से एक को पश्चिम जर्मनी के वैज्ञानिक शोधों के लिए और अन्य दो को कॅनाडा और इंदोनेसिया की संचार व्यवस्था के लिए 'चैलेंजर' ने छोड़ा है।

## जर्मन कैसे हैं ?

जर्मनी की वीभत्स घटनाओं के बारे में टेलीविज़न और पदों पर दिखायी जाने वाली फ़िल्मों और कार्टूनों को निरंतर देखते और पढ़ते रहने से 15 और 20 वर्ष के बीच के ब्रितानी बच्चों की एक ऐसे देश के बारे में जो इस शताब्दी के दौरान दो युद्धों में उन का शत्रु रहा क्या धारणा है, यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जिस के नतीजे, ब्रिटेन स्थित पश्चिम जर्मनी के दूतावास के लिए काफ़ी संतोषजनक रहे। अब तक यही सोचा जाता था कि ब्रिटेन विगत दिनों को मुला नहीं पाया है। लेकिन वास्तव में ब्रिटेन की युवा पीढ़ी जर्मनी के लोगों को कार्य-कुशल, अभिमानी, प्रतिस्पर्धी सुशिक्षित, परिश्रमी, लेकिन मज़ाक न समझने वाले मानते हैं। फिर यहाँ पश्चिम जर्मनी को पश्चिमी यूरोप का सबसे संपन्न और प्रभावशाली देश और उस के उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

## सीथियाई सभ्यता के अवशेष

रूस के विभिन्न भागों में खुदाई करते समय सीथियत पुरातत्त्वविदों को हाल के वर्षों में अनेक चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। उदाहरण के लिए कज़ाख़स्तान की राजधानी अल्माअता के बाहर इस्सक समाधि स्तूप में अमीर वीर सैनिक की कब्र मिली है। ऐसा अनुमान है कि उसे ईसा पूर्व तीसरी या चौथी सदी में दफनाया गया था।

इसी तरह मोल्दावियाई विज्ञान अकादेमी के इतिहास



सीथियाई सभ्यता की खोज करने वाले रूसी पुरातत्त्ववेत्ता एन. संमाह और एन. सरोवा

विज्ञान के सदस्य एन. सेत्रारू के नेतृत्व में पुरातत्त्वविदों की टोली ने अभी हाल में ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के सीथियाई कब्रिस्तान का पता लगाया है। यह स्थान दुबोस्सरी नगर के कब्रगाह स्थल की खुदाई करने के समय मिला। यहाँ पर कान के छल्ले, हाथ के कंगन तथा स्त्रियों के अन्य आभूषण मिले हैं। इस से पूर्व पुरातत्त्वविदों को 800 ग्राम वजन का गले का हार मिला था, जिस पर शेरों और पक्षियों के चित्र खुदे हैं।

नोवोरोद प्रदेश में प्राचीन मूर्ति चित्रकार के स्टूडियो की खोज का भी विशेष महत्व है।

## शब्दों की शक्ति से लैस मशीन

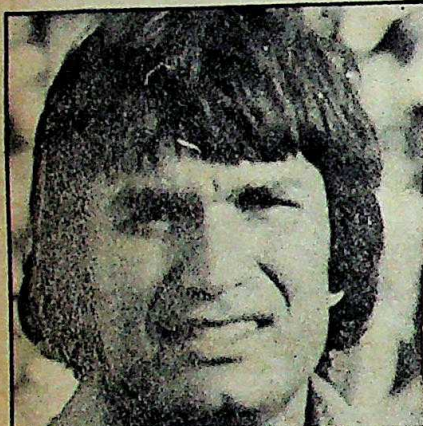
ब्रिटेन में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनी के विशेषज्ञ टोनी फ्रीस और प्रकाशन परामर्शदाता पॉल प्रॉक्टर एक ऐसी मशीन को विकसित करने में लगे हुए हैं जिसे वे एक 'क्रांतिकारी नया यंत्र' बता रहे हैं। इस से न केवल अनुक्रमणिका और पाद टिप्पणियाँ तैयार करने के नीरस काम किये जा सकेंगे बल्कि लेखक को कोई शब्द न सूझने पर बटन दबा कर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द भी मिल सकेगा। यह मशीन आवश्यकता पड़ने पर अनावश्यक दोहराये गये शब्दों को निकाल देगी और इस की सहायता से शब्दावली पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। फ़िलहाल यह यंत्र एक छोटे से कंप्यूटर से शक्ति प्राप्त करता है। बाद के नमूने शायद विषयवस्तु भी सुझा सकेंगे। □



## खेल और खिलाड़ी

# हॉकी ये आरोप-प्रत्यारोप हमें कहाँ ले जायेंगे?

भारतीय हॉकी के इतिहास में अप्रैल 1982 को अविस्मरणीय मास माना जायेगा। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जिस दिन हॉकी के अधिकारियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रबंधकों को ले कर खबरों ने सुखियां न पायी हों : मिसाल के तौर पर जमनलाल शर्मा



## ‘हॉकी इस वक्त आखिरी साँस ले रही है’

खोज कर हॉकी से संन्यास लेने वाले लोगों में अब सुखबीरसिंह ग्रेवाल भी शामिल हो गये हैं। पहले चर्चित नामों में पूथीपाल सिंह और असलम शेरखान का नाम लिया जाता है। असलम ने 1 सितंबर 1978 को जब दिल्ली दूरदर्शन पर भारतीय हॉकी संघ की बखिया उबेड़ी तब वह उस के परिणाम से परिचित थे। लेकिन अपने मन की बातें कम ही लोग कहने का दम-खम रखते हैं।

दिनमान से एक बातचीत में असलम शेरखान ने बताया कि टीम में एक भावना होती है, एक जजबा होता है, सभी का मेलमिलाप और योगदान होता है। लेकिन इस समय लगता है कि हॉकी संघ के अधिकारियों को खेल की भावना से कोई मतलब नहीं रहा। इस समय हॉकी मरा हुआ गिद्ध है जिसे सभी नोचे जा रहे हैं, जिसके हाथ जो कुछ भी लग रहा है नोचे जा रहा है। आज हॉकी की जो दुर्गति है, उतनी कभी नहीं रही—मेरा तो ख्याल है कि हॉकी इस वक्त आखिरी साँस ले

और हरमीकसिंह को क्रमशः प्रबंधक और प्रशिक्षक के पद से बर्खास्त किया जाना, भारतीय हॉकी संघ के कोषाध्यक्ष फाल्गुनी मतीलाल का अपने पद से इस्तीफा देना, भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष इंदरमोहन महाजन द्वारा किये गये ‘वित्तीय घोटाले’ का मतीलाल द्वारा पर्दाफाश करना; भारत के सेंटर फारवर्ड सुखबीरसिंह ग्रेवाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास आदि।

ये कुछ ऐसे मुद्दे और मिसालें हैं जो भारतीय हॉकी संघ की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती हैं। अब जब नवें एशियाई खेलों की

रही है, इस वक्त हॉकी संघ में लूटखसोट का जो दौर चल रहा है यदि उस को बंद नहीं किया गया तो यह खेल खत्म हो जायेगा। मिसाल के तौर पर रामास्वामी के पास पैसा था, खेल की समझ नहीं थी; महाजन कुछ खेल के बारे में जानते हैं लेकिन और तरह की लूट में लगे हुए हैं।

‘हॉकी को नुकसान पहुँचाने की एक और संस्था पटियाला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान है। मेरा ख्याल है कि हॉकी को पटियाला की चहारदीवारी से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहिए। वहाँ सभी खिलाड़ियों को बेशक घुटन महसूस हो रही है।’

अधिकारियों और खिलाड़ियों की मनो-वृत्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असलम ने कहा: ‘लगता है कि सभी लोग विदेश यात्रा के मोह में फँसे हुए हैं। असुरक्षा की भावना इतनी है कि खिलाड़ियों को पता नहीं कि कल खेल पायेंगे कि नहीं। हॉकी खिलाड़ियों की खेल की उम्र औसतन दस वर्ष होती है। लिहाजा जोड़तोड़ कर खिलाड़ी विदेश जाते हैं, थोड़ी बहुत खरीददारी करते हैं, विदेशी फर्में से तोहफे मिल जाते हैं। बस इसी में वह खुश हैं, क्रिकेट और टेनिस जैसे वे व्यावसायिक खिलाड़ी तो हैं नहीं।’

कोषाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर असलम का मत: ‘मतीलाल जैसे ही कुछ लोग ईमानदार बचे रह गये थे। उन के त्यागपत्र से संघ ने बेशक एक दयानतदार इन्सान खोया है। वैसे तो चोरों की बारात में सभी शामिल हैं।’

‘अलवत्ता हरमीक के हटाये जाने पर मुझे कोई रंज नहीं। न तो वह अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और न बेहतर इन्सान। इस के उलट बलबीरसिंह (सीनियर) का कोई मुकाबला नहीं। उन के प्रशिक्षण में बेशक यूरोप का दौरा सफल हो सकता है।’

तयारी शिखर पर है इस तरह की घटनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल ऊँचा कैसे हो सकता है। हरमीक और जमनलाल शर्मा को एशियाई खेलों की समाप्ति तक नियुक्त किया गया था। उन के स्थानापन्न के तौर पर प्रमुख प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी बल्कि अलग अलग स्थानों के लिए अलग प्रशिक्षक फिलहाल नियुक्त किये जाने का फैसला किया गया है। जैसे गोली के लिए भूतपूर्व ओलिंपिक खिलाड़ी, देशमुख, हाफ लाइन के लिए सर्विस के बलबीरसिंह (जूनियर) तथा फुलबैक के लिए माइकल किडो। भूतपूर्व कप्तान अजितपाल सिंह की सेवाएँ भी प्राप्त की गयी हैं। साथ ही यूरोप के दौरे पर जाने वाली टीम के साथ तीन ओलिंपिक में खेलने वाले बलबीरसिंह (सीनियर) को प्रबंधक नियुक्त किया गया है।

जिन मुद्दों से भारतीय हॉकी संघ की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार हुआ उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। पी. मतीलाल का खुला पत्र और संसद में श्री महाजन की एक साल में सात विदेश यात्राओं के उल्लेख से भारतीय हॉकी का रहासहा होसला पस्त होता दीखता है। मतीलाल ने जो आरोप लगाये हैं उन में श्री महाजन द्वारा वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं का बरता जाना, विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन तथा हॉकी संघ के अन्य सदस्यों को बिना विश्वास में लिए मनमाने फैसले करना। मतीलाल ने कहा है कि भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष ने कई स्रोतों से नकद धन इकट्ठा कर हॉकी संघ के संविधान का खूला उल्लंघन किया है। श्री महाजन ने इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

अधिकारियों की आपसी लड़ाई और तोक-झोंक जारी थी कि भारत के सेंटर फारवर्ड सुखबीरसिंह ग्रेवाल ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस की सूचना उन्होंने पटियाला स्थित नेताजी सुभाषचंद्र राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान को भी दे दी है। अलवत्ता वह इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलते रहेंगे। ग्रेवाल की खोज का कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण था। ग्रेवाल के अनुसार हम लोग इतने मैचों में खेल चुके हैं फिर भी हमें बुनियादी सीख ही अभी तक दी जाती है। वास्तव में न तो उससे हम कुछ सीख पाते हैं और न ही हमें कोई प्रशिक्षक सिखा ही पाता है। हमें विशिष्टता की आवश्यकता है। ग्रेवाल उन खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने विश्व की लगभग सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। 1974 में मोपाल में उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुक़ाबला जीता था। उस के बाद वह सभी प्रदान टीमों में रहे सिवाय 1977 में जब डेढ़ बरस तक वे की वजह से वह खेल नहीं सके।



# उत्तर रेलवे

## समय सारणी सूचना

1 मई 1982 से लागू होने वाली उत्तर रेलवे समय सारणी की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:—

नई गाड़ियाँ

(i) शामली और सहारनपुर के बीच गाड़ी नं. 1 एस एस एम/ 2 एस एस एम जिनमें द्वितीय श्रेणी के स्थान होंगे, निम्न समयानुसार चलाई जायेंगी:—

| 1 एस एस एम        | 2 एस एस एम |
|-------------------|------------|
| 18.10 छू. शामली   | प. 17.30   |
| 20.50 प. सहारनपुर | छू. 14.50  |

(ii) दिल्ली और पालम के बीच चल रही गाड़ी नं. 1 पीडी/ 2 पीडी जिनमें द्वितीय श्रेणी स्थान हैं, अब इनमें सामान्य यात्री भी यात्रा कर सकेंगे:—

| 1 पी डी<br>(रविवार को छोड़कर) | 2 पी डी<br>(शनिवार) | 2 पी डी<br>(रविवार और<br>शनिवार छोड़कर) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 7.45 छू दिल्ली प.             | 15.00               | 17.30                                   |
| 8.40 प. पालम छू.              | 14.05               | 16.40                                   |

गाड़ियों का विस्तार

(i) 1 डी एस एस/8 डी एस एस दिल्ली-शामली/यात्री गाड़ियाँ सहारनपुर तक बढ़ाई जाएंगी. अब इनके नए नम्बर 3 एस एस डी/4 एस एस डी होंगे और निम्न समय अनुसार चलेंगी:—

| 3 एस एस डी           | 4 एस एस डी |
|----------------------|------------|
| 10.05 छू. दिल्ली जं. | प. 18.30   |
| 14.12 प. शामली       | छू. 14.17  |
| 14.22 छू.            | प. 14.07   |
| 17.00 प. सहारनपुर    | छू. 11.30  |

अतः 3 डी एस एस, 5 डी एस एस, 7 डी एस एस, 9 डी एस एस तथा 10 डी एस एस गाड़ियों के नए नंबर क्रमशः 1 डी एस एस, 3 डी एस एस, 5 डी एस एस, 7 डी एस एस और 8 डी एस एस होंगे.

(ii) 1 ए टी डी आगरा-टूंडला-दिल्ली यात्री गाड़ी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच बढ़ाई जाएंगी. इसका नया नं. 1 ए टी एन होगा और निम्न समयानुसार चलेगी:—

| 1 ए टी एन |
|-----------|
| दिल्ली    |
| प. 18.40  |
| छू. 19.42 |
| नई दिल्ली |
| प. 19.55  |

(iii) 46 डाउन/45 अप अमृतसर-दिल्ली जनता एक्सप्रेस दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन के बीच बढ़ाई जाएंगी. इनके नए नाम हजरत निजामुद्दीन-अमृतसर एक्सप्रेस होंगे. अब इनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्थान होंगे और दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन के बीच निम्न समयानुसार चलेंगी:—

| 46 डाउन                  | 45 अप     |
|--------------------------|-----------|
| 5.23 प. दिल्ली जं.       | छू. 22.15 |
| 5.45 छू.                 | प. 21.45  |
| 5.58 प. नई दिल्ली        | छू. 21.35 |
| 6.20 छू.                 | प. 21.15  |
| 6.35 प. हजरत निजामुद्दीन | छू. 21.00 |

(iv) 379 डाउन/366 अप पलवल-नई दिल्ली यात्री गाड़ियाँ नई दिल्ली और दिल्ली के बीच निम्न समयानुसार बढ़ाई जाएंगी:—

| 379 डाउन          | 366 अप    |
|-------------------|-----------|
| 9.53 प. नई दिल्ली | छू. 17.10 |
| 10.07 छू.         | प. 17.05  |
| 10.20 प. दिल्ली   | छू. 16.50 |

गाड़ियों के चालन क्षेत्र में कटौती

गाड़ी नं.

के बीच

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 डी एन एम/2 डी एन एम शटल (नया नंबर 1 एन. एम./2 एन एम) | दिल्ली और नई दिल्ली |
| 331 अप यात्री गाड़ी                                    | सहारनपुर-अमृतसर     |
| 332 डाउन यात्री गाड़ी                                  | अमृतसर-सहारनपुर     |
| 353 अप यात्री गाड़ी                                    | अंबाला छावनी-अमृतसर |
| 354 डाउन यात्री गाड़ी                                  | अमृतसर-अंबाला छावनी |
|                                                        | बरास्ता धुरी        |

गाड़ियों के समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 अप मुगलसराय 7.00/7.35 की बजाए 6.08/6.38 पहुंचे/चलेगी                                                                            |
| 3 अप मुगलसराय 6.07/6.25 की बजाए 7.33/7.53 बजे पहुंचे/चलेगी और इलाहाबाद 9.15/10.10 की बजाए 10.45/11.15 बजे पहुंचे/चलेगी            |
| 155 अप मुगलसराय 17.41/18.00 की बजाए 16.46/17.06 बजे पहुंचे/चलेगी और नई दिल्ली 5.25 की बजाए 6.10 बजे पहुंचेगी (अगले पृष्ठ पर जारी) |



- 153/167/191 अप दिल्ली 11.35 की बजाए 12.25 बजे पहुंचेगी  
 175 अप मुगलसराय 8.30/8.50 की बजाए 6.55/7.15 बजे पहुंचे/चलेगी और नई दिल्ली 21.35 की बजाए 21.05 बजे पहुंचेगी.  
 28 अप वाराणसी से 11.00 की बजाए 11.30 बजे चलेगी  
 116 अप कानपुर 11.30/11.50 की बजाए 12.00/12.30 बजे पहुंचे/चलेगी और लखनऊ से 10.00 की बजाए 10.35 बजे चलेगी  
 119 अप नई दिल्ली 12.15 की बजाए 13.15 बजे पहुंचेगी  
 2 डाउन मुगलसराय 19.35/20.05 की बजाए 20.55/21.25 बजे पहुंचे/चलेगी  
 156 डाउन मुगलसराय 9.48/10.03 की बजाए 11.03/11.23 बजे पहुंचे/चलेगी और नई दिल्ली से 22.10 की बजाए 22.00 बजे चलेगी  
 192 डाउन मुगलसराय 6.50/7.10 की बजाए 7.30/7.50 बजे पहुंचे/चलेगी  
 176 डाउन नई दिल्ली से 7.00 की बजाए 6.00 बजे चलेगी  
 120 डाउन नई दिल्ली से 15.15 की बजाए 14.25 बजे चलेगी  
 139 डाउन और 159 डाउन इलाहाबाद 15.30/15.55 की बजाए 18.20/18.50 बजे पहुंचे/चलेगी और वाराणसी 19.00 की बजाए 22.00 बजे पहुंचेगी  
 13 अप मुगलसराय 17.25/17.50 की बजाए 17.45/18.10 बजे पहुंचे/चलेगी  
 21 डाउन नई दिल्ली 5.35 की बजाए 6.10 बजे पहुंचेगी  
 121/123/125 डाउन नई दिल्ली 13.40 की बजाए 16.00 बजे पहुंचेगी  
 143 डाउन हजरत निजामुद्दीन 10.35 की बजाए 14.35 बजे पहुंचेगी  
 16 अप नई दिल्ली से 19.30 की बजाए 19.10 बजे चलेगी  
 122/124/126 अप नई दिल्ली से 6.50 की बजाए 6.15 बजे चलेगी  
 144 अप हजरत निजामुद्दीन से 9.20 की बजाए 6.40 बजे चलेगी  
 38 डाउन फिरोजपुर छावनी से 21.35 की बजाए 21.10 बजे चलेगी  
 60 डाउन श्रीगंगानगर से 19.45 की बजाए 19.20 बजे चलेगी और मटिडा 23.00 की बजाए 22.35 बजे पहुंचेगी  
 37 अप फिरोजपुर छावनी 6.20 की बजाए 6.45 बजे पहुंचेगी  
 18 डाउन जम्मू तवी से 22.40 की बजाए 22.05 बजे चलेगी  
 88 डाउन मटिडा 21.40 की बजाए 21.05 बजे पहुंचेगी  
 2 सी सी एम मिर्जापुर से 17.35 की बजाए 18.15 बजे चलेगी  
 357 अप मुगलसराय से 16.50 की बजाए 17.20 बजे चलेगी  
 355 अप आगरा छावनी से 18.30 की बजाए 19.15 बजे चलेगी और टूंडला 20/5 की बजाए 20/45 बजे पहुंचेगी और 20.50 की बजाए 21/30 बजे चलेगी.  
 536 अप कानपुर से 4.30 की बजाए 5.00 बजे चलेगी.  
 542 डाउन लखनऊ से 6.00 की बजाए 7.30 बजे चलेगी  
 540 डाउन लखनऊ से 22.30 की बजाए 23.30 बजे चलेगी  
 2 के ए कानपुर से 14.45 की बजाए 15.25 बजे चलेगी और इलाहाबाद 20.50 की बजाए 21.20 बजे पहुंचेगी  
 2 ए एच एच अलीगढ़ से 8.00 की बजाए 8.15 बजे चलेगी और हाथरस किला 9.40 की बजाए 9.55 बजे पहुंचेगी  
 6 जे एफ फिरोजपुर छावनी से 12.55 की बजाए 13.10 बजे चलेगी  
 6 एल एफ जाखल 22.15 की बजाए 22.40 बजे पहुंचेगी  
 4 एल एफ लुधियाना 15.27 की बजाए 15.10 बजे पहुंचेगी  
 8 एल एफ फिरोजपुर छावनी से 18.55 की बजाए 17.20 बजे चलेगी और लुधियाना 22.45 की बजाए 12.15 बजे पहुंचेगी  
 381 डाउन तुगलकाबाद 15.24/15.26 की बजाए 14.54/14.58 बजे पहुंचे/चलेगी और नई दिल्ली 16.20 की बजाए 15.45 बजे पहुंचेगी  
 336 डाउन श्रीगंगानगर से 8.35 की बजाए 7.00 बजे चलेगी और मटिडा 13.15 की बजाए 12.25 बजे पहुंचेगी  
 3 ए बी क्यू अमृतसर से 14.50 की बजाए 14.00 बजे चलेगी और कादियां 17.00 की बजाए 16.00 बजे पहुंचेगी  
 4 ए बी क्यू कादियां से 20.50 की बजाए 16.40 बजे चलेगी और अमृतसर 22.55 की बजाए 18.45 बजे पहुंचेगी  
 343 अप श्रीगंगानगर 1.05 की बजाए 1.30 बजे पहुंचेगी  
 335 अप श्री गंगानगर 19.10 की बजाए 18.40 बजे पहुंचेगी  
 4 एस एच बी श्रीगंगानगर से 17.45 की बजाए 17.20 बजे चलेगी और मटिडा 22.05 की बजाए 21.30 बजे पहुंचेगी  
 1 बी ए अबोहर 20.03 की बजाए 20.20 बजे पहुंचेगी  
 2 ए पी जे जम्मू तवी से 22.00 की बजाए 22.40 बजे चलेगी  
 2 डी एस दिल्ली 11.00 बजे की बजाए 11.15 बजे पहुंचेगी  
 367 डाउन तुगलकाबाद 8.40/8.42 की बजाए 8.16/8.18 बजे पहुंचेगी/चलेगी और नई दिल्ली 9.28 की बजाए 9.01 बजे पहुंचेगी  
 1 एन जी एन गजियाबाद से 10.50 की बजाए 10.35 बजे चलेगी  
 5 डी एस एस (पुराना 7 डी एस एस) दिल्ली से 20.00 बजे की बजाए 19.20 बजे चलेगी और शामली 24.00 की बजाए 23.30 बजे पहुंचेगी  
 (अगले पृष्ठ पर जारी)



## संवेदनार्थों की सूक्ष्म बुनावट

बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नाटक अपने आलेख, अपनी प्रस्तुति, अपनी दृष्टि-चिन्ता, अपनी सादगी—सभी स्तरों पर अचानक अच्छा लग जाये। पिछले दिनों राजधानी के श्रीराम कला संस्कृति केंद्र में तमाशा संस्था द्वारा प्रस्तुत नाटक टुट्टू ऐसा ही था जिस के लेखक और निर्देशक थे **विनोद वर्मा**। विनोद वर्मा पेशेवर लेखक या पेशेवर निर्देशक दोनों होने का दावा नहीं करते, न ऐसा कोई मुगलता रखते हैं। शायद इसी लिए सार्थक और सुंदर काम करते हैं। उन का पिछला नाटक 'अनामघर' पंजाब के एक गांव के एक रुढ़िप्रस्त परिवार के मूल्यों के विघटन की यथार्थवादी तस्वीर पेश करता था तो यह नाटक 'टुट्टू' हिमाचल प्रदेश के एक गांव में हो रही एक अतिमानवीय, संवेदनशील स्थिति की परतें उघाड़ता है जहाँ परिवार और दूसरों की चिन्ता, ममता और प्यार के बीच एक अविकसित दिमाग का युवक ज़िदगी का रास्ता खोज रहा है। लेखक अपने अविकसित दिमाग वाले इस नायक के चित्रण के लिए कालसेन मक्कलू के उपन्यास 'टिम' का आभार मानता है। टुट्टू का शरीर सुंदर स्वस्थ युवा का शरीर है पर दिमाग बच्चों सा है। विरोध सह नहीं पाता, प्यार से बंध जाता है। वह एक विधवा सुंदर ईसाई औरत के यहाँ काम करता है, प्यार पाता है, आकर्षित होता है। वह औरत



टुट्टू में स्वस्ति श्रीमाली (बिन्नु) विनोद वर्मा (बापूजी) और सुरेंद्र दुगल (शील मसीह)

उस से शादी कर लेती है। नाटक की बुनावट का कमाल है कि यह सीधा कथानक इतना संकेतगर्भी और मानवीय चिन्ताओं से पूर्ण बनाया गया है कि एक अविकसित दिमाग वाले व्यक्ति को इस समाज में जीवंत रिश्ते बना कर जीने के हक को बड़ी गहराई से मन पर, विवेक पर उकेर देता है। नाटक का अंत यदि और साफ हो और ठीक उस समय जब विवाह के बाद नायिका टुट्टू के साथ स्त्रियोचित सपने देखना शुरू करती है तो वह कहीं और खो जाता है, इस स्थिति को नायिका स्वीकार कर ले तो नाटक दुख के बिंदु पर न खतम हो। इस स्वीकृति पर खतम हों कि यह संबंध समआवेग की जगह दूसरे की प्रतीक्षा माँगता है। नाटककार ने इसे रहस्यमय रहने दिया है जिस की ज़रूरत नहीं थी और जिस से उस की मूल्य स्थापना का आधार डगमगा जाता है।

अपेक्षाकृत सादे मंच पर यह प्रस्तुति काफी कुछ प्रभावशाली थी। टुट्टू की भूमिका में रवि झाकल और नायिका शील मसीह की भूमिका में सुरेंद्र दुगल ने उस यथार्थ की विश्वसनीयता को बड़ी खूबसूरती से बनाये रखा और कहीं संवेदना के सूत्र को बिखरने नहीं दिया। **विनोद वर्मा** (बापू) निरूपमा वर्मा (अम्मा जी) स्वस्ति श्रीमाली (बिन्नु) ने टुट्टू के बाप, मां और बहिन की भूमिका का सुखद निर्वाह किया। कुल मिला कर यह नाटक इधर खेले जाने वाले नाटकों में एक अलग सार्थक, स्वाद की सृष्टि करता है। इसे और खेला जाना चाहिए।

—स.व.स.

मुख्य परिचालन अधीक्षक

5 बजे चलेगी  
और 20.50

8 डी एस एस शामली से 6.40 की बजाए 7.20 बजे चलेगी और दिल्ली  
11.10 की बजाए 11.25 बजे पहुंचेगी

8 डी एस एस (पुराना 10 डी एस एस) दिल्ली 22.25 की बजाए  
22.00 बजे पहुंचेगी

12 के एस कालका 17 की बजाए 16.45 बजे पहुंचेगी

2 जी एन नजीबाबाद से 8.40 की बजाए 8.10 बजे चलेगी और  
गजरोला 12.35 की बजाए 12.10 बजे पहुंचेगी

2 के एन कोट्टुद्वार से 7.30 की बजाए 6.55 बजे चलेगी और नजीबाबाद  
8.20 की बजाए 7.50 बजे पहुंचेगी

4 एफ के फाजिल्का 22.45 की बजाए 22.25 बजे पहुंचेगी

3 बी एच भटिंडा से 21.00 की बजाए 21.15 बजे चलेगी

339 अप भटिंडा से 18.15 की बजाए 18.00 बजे चलेगी

सीधे होकर जाने वाले और खंडीय सवारी डिब्बों के चलने में परिवर्तन

(i) 37 अप/38 डाउन पंजाब मेल गाड़ियों के साथ दिल्ली और  
फिरोजपुर के बीच एक प्रथम श्रेणी डिब्बा (एफ सी) लगाया  
जायेगा।

(ii) देहरादून मम्बई सेन्ट्रल टी/एस मिश्रित डिब्बे के स्थान पर  
20/87-88/19 गाड़ियों के साथ देहरादून और इन्दौर के बीच  
एक मिश्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (एफ सी एस) डिब्बा  
लगाया जायेगा।

(iii) 454/137-138/451 गाड़ियों के साथ परसिया और हजरत  
निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में एक दिन की बजाए सप्ताह में  
दो दिन एक मिश्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (एफ सी एस)  
डिब्बा लगाया जायेगा।

(iv) 7/15-16/8 गाड़ियों के साथ लगने वाला वालटेयर—नई  
दिल्ली डिब्बा सप्ताह में दो दिन अब 3/51/21-22/52/46  
गाड़ियों के साथ लगाया जायेगा।

(v) वाडसेर-अहमदाबाद 2 टियर शयनयान 2 जे. बी/1एस बी/  
/66-ए 65/ए 2 एस बी/1 जे बी गाड़ियों की बजाए 2 जे बी/  
/266/66 ए 65/ए/265/1 जे बी गाड़ियों द्वारा वहन किया  
जायेगा।

(vi) विलासपुर और अमृतसर के बीच 137/45-46/138 गाड़ियों  
के साथ एक प्रथम श्रेणी (एफ सी) और एक 3 टियर शयनयान  
(जी एस सी एन) लगाया जायेगा।

गाड़ियों के समय, सीधे जाने वाले और खंडीय डिब्बों आदि के  
जाने के संबंध में विस्तृत व्योरे के लिए कृपया उत्तर रेलवे समय सारणी  
1 मई 1982 को देखें जो रेलवे बुकिंग-आरक्षण/पूछताछ कार्यालयों  
या महत्वपूर्ण स्टेशनों के बुक स्टालों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

15 मई '82



## क्या जाने

दिव्य और दलहर की मिश्रित का एक चमत्कार 'कुरु कुरु स्वाहा' में उपस्थित करने के बाद जोशी जी प्रस्तुत करते हैं दूसरा शाहकार कसप. किशोर प्रेम की यह वयस्क कहानी 'प्रेमी युगल' के विषय में नहीं, प्रेम के विषय में है. उसे उस की यह विशिष्टता अपने प्रेमी पात्रों को करतूतों से नहीं, कथावाचक की व्याख्या और टिप्पणी से प्राप्त होती है. व्याख्या और टिप्पणी का नमूना देखने के लिए सीधे पुस्तक ही देखनी पड़गी बरना उद्धरणों की भरमार इस थोड़े से स्थान में समा नहीं पायेगी. इन व्याख्याओं और टिप्पणियों से निकलने वाले निष्कर्ष जरूर बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नये सिरे से न केवल प्रेम के बारे में सोचने समझने की जरूरत को बल्कि 1910 की काशी से ले कर 1980 तक के हालीवुड के देशकाल के फैलाव के बीच प्रेम के नये रूपरंग और ढंग को उजागर करते हैं.

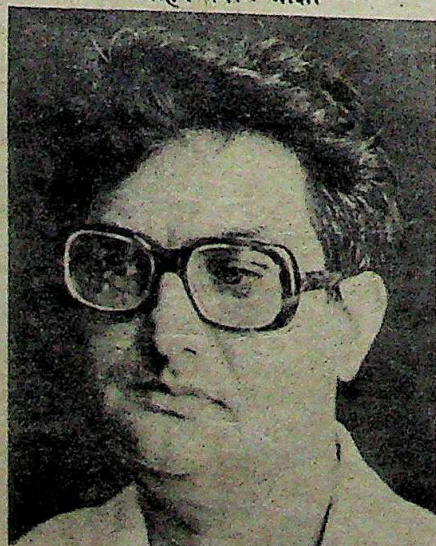
यों, बात सीधे यहाँ से शुरू कर के रफा दफा की जा सकती है कि लूट शोषण, हाहाकार, गरीबी, मुखमरी इत्यादि विषयों के रहते हुए इन्हें प्रेम का राग अलापने की सुझी है तो हाजिर है तुरुष का इक्का. प्रेमी नायक सदा का भूखा, नंगा सताया हुआ बेचारा, गरीबी का मारा है जिस के लिए प्रेम करने का अर्थ 'किसी के लायक' बन कर दिखाना है और 'किसी के लायक' बनने का अर्थ 'लाखों वाला' बन जाना है—'किसी के योग्य बनते बनते इस योग्य बन जाये कि भारतीय रुपया बहुत सस्ता मालूम होने लगे. जिस भारतीय अमीरी ने उसे हिकारत से देखा है उस भारतीय अमीरी को वह हिकारत से देख सके.' और इस का आसान रास्ता है पश्चिम क्योंकि जो उस के मन में खड़ा है न आज भी पुस्तैनी घर का खंडहर, उस के क्रेता वहीं हैं, और जो स्वप्न में खड़ा है एक भव्य भवन, उस के विक्रेता वहीं हैं. खुद को वगंच्युत (डी क्लास) करते हुए आदमी की आकांक्षा, उद्योग और अनुभव को परतों को इतना सँभाल सँभाल कर ऐसी शारीकी से कथावाचक उतारता है कि हर परत सावित छिल जाती है. 'कुरु कुरु स्वाहा' में स्थितियों की हास्यास्पदता को उस चरम बिंदु तक पहुँचाया गया था जहाँ पहुँच कर स्थूल यथार्थ की कसोटियाँ अपने आप बेकार हो जाती थीं और लेखक के अमिप्राय की तलाश करने को मजबूर होना पड़ता था. हास्यास्पदता की काफी कुछ वही भूमिका 'कसप' में भी है किन्तु उस से भी वह कर कुशल प्रयोग आलोचनात्मकता का हुआ है. परिहास और आलोचना के स्वयंपाक से कथावाचक पंडित महोदय आलोचक को पहले ही पटकनी दे बैठते हैं.

आपत्तियों की कल्पना करते हुए वे कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ही पूर्व पक्ष की छुट्टी कर देते हैं कि लीजिए साहब, और कीजिए आलोचना. प्रेमी नायक के सिलसिले में यह कौशल कुछ निमग्न भाव से आजमाया गया है और नायिका के सिलसिले में कुछ मुग्ध भाव के साथ.

नायिका को 'किसी के योग्य कुछ बन कर' दिखाने की बात बेवकूफी लगती है. 'अपने योग्य' बनना उसे कुछ बनने का पर्याप्त कारण लगता है. उस के लिए 'प्यार किसी और की चुनौती से नहीं, अपनी ही अस्मिता की चुनौती से उपजता है.' इन दो छोरों के बीच का विस्तार अपने अपने बिंदु से आगे बढ़ कर दूसरे को छू लेने की, पा लेने की आकांक्षा से तय किया जाता है और अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग निष्कर्षों की सीढ़ियाँ पार करता है. पूरे आनंद के लिए तो इन्हें जोशी जी की विलक्षण शब्दावली में ही पढ़ना जरूरी है, बानगी के तौर पर एक नमूना पेश है—भक्षण प्रेम का अंतिम चरण है.

लेकिन जिस बिंदु पर अंतराल तय होता है वह न लय का बिंदु है न विलय का. वह टक्कर और मुकाबले का बिंदु है. कथावाचक के शब्दों में 'बड़े के घड़ा के का 'परम प्रतिद्वंद्विता का जो भाव शब्दों में बंध नहीं सकता.' जिसे प्रेम की तरह यहाँ पहचाना गया है वह केवल स्त्री पुरुष का नहीं, अमीर गरीब का नहीं, आत्म और वस्तु की उन मूलभूत दृष्टियों का भी है जिन्हें कथावाचक अपने पंडिताऊ परिहास की अनगिनत परतों में लपेट कर हाड़मास का जामा पहना कर मनुष्य बना देता है और जामा भी ऐसा कि दर्शन के दर्शन भी परिहास-पूर्ण हों. 'एकाकी वह रमा नहीं, इसी लिए एकाकी रमता नहीं. उसने दूसरे की इच्छा की' को इस प्रेमी युगल के आचरण और व्यवहार में ढला हुआ देखिए और क्या कीजिए दांतों तले उंगली दबाने के सिवा कि इस प्रेमी युगल

मनोहर श्याम जोशी



की धीगा मुस्ती, धमाचौकड़ी, मारघाड़ में कैरे वह चरितायें हो रहा है.

भाषा के साथ जोशी जी का रिश्ता बहुत अंतरंग है. अदाकारी का हिस्सा कसप के बिल्कुल निर्दोष बन पड़ा है, 'कुरु कुरु स्वाहा' के कहीं कहीं कुछ अधिक और अतिरिक्त होने के दोष से मुक्त. कुमाऊनी पंडित समाज के मध्यवर्गीय घरेलू जीवन के संस्कारों, रीतियों, विधि विधानों के दृश्यों की शृंखला को बीच बीच में रोक कर कथावाचक की रनिंग कमेंटरी कुमाऊनी हिंदी की बहुत प्यारी घरेलू बोली को इस तरह पांडित्यपूर्ण संस्कृत प्रधान भाषा में घुला देती है कि प्रेमकथा बेध बदल कर सृष्टिकथा का रूप धारण कर लेती है. इस रनिंग कमेंटरी में न केवल कथा के प्रेमी-पात्र बल्कि एक पूरी जीवन शैली, जीवन दृष्टि, संस्कार पद्धति और उस के साथ आधुनिक जीवन की मिश्रित समा जाती है. इस संदर्भ में अपनी संक्षिप्त उपस्थिति के बावजूद जबरदस्त प्रभाव डालने वाली गुलनार का नाम लेना जरूरी है जिसे इस प्रेमकथा का तीसरा कोण कहा जा सकता है. इस अर्थ में नहीं कि वह प्रेमी युगल के बीच तीसरी है बल्कि इस अर्थ में कि वह प्रेम की दो दृष्टियों के बीच तीसरी है जो भावनाओं को शोषण का साधन मान कर चलती है. प्रेम के इस त्रिकोण ने अपनी परिधि के भीतर एक पूरे युग के परिवेश को इस तरह समेटा है कि एक अतिरिक्त आयाम की तरह प्रेमी नायक के चरित्र में एक रचनाकार मानस का क्रमशः विकास दिखायी देता है. कथा में कमी प्रसंगवश और कमी अधिकारवश जितने विषयों को समेटा गया है और जितना प्रेम कभी परिहास तो कभी गांभीर्य के साथ न केवल दृष्टिपात बल्कि अधिकारपूर्वक टीका टिप्पणी भी की गयी है, उनकी केवल सूची भर बना सकना भी टेढ़ी खीर है. विशेषतः कौशल तो इन विषयों को शामिल करने के ढंग में है कि हर बात खिंची चली आती है पर खींच कर लायी जाती हुई नहीं दिखती. बात बेबात के इस क्रम में कब मोड़ ले कर कथा मुस्ती से मुस्ती और परिहास से उदास मनोभाव को छूने लगती है, पता भी नहीं चलता और पर्यवसान एक विश्वदृष्टि में होता हुआ दिखायी देता है. सृष्टि के जिन मूलभूत रहस्यों के संधान से विश्वदृष्टि जन्म लेती है वे अक्सर प्रश्न बन कर खड़े होते हैं, उत्तर वही है जो पुस्तक देती है—क्या जाने. किन्तु न जानने की इस भोली मंगिमा में पता नहीं कितना कुछ जानने का भाव छिपा है जबकि पता नहीं कितना कुछ जानने का दावा अक्सर इस क्या जाने के समक्ष निहत्था हो जाता है.

—अर्चना वर्मा

कसप—उपन्यास; लेखक : मनोहर श्याम जोशी, राजकमल प्रकाशन, 8, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002. मूल्य रु. चालीस



निघन

## मलयज नहीं रहे

मलयज नहीं रहे. यह लिखते कलम थरथरा रही है. अभी 28 मार्च को सीढ़ियाँ चढ़ कर वह मेरे घर आये थे. थोड़ी देर साँस सँभालने के बाद बोले—'अब थकान आ जाती है.' औसत कद का यह कमजोर दुबल शरीर देखने के हम आदी थे और अक्सर बातचीत करते समय उन के फेफड़ों में कफ की खड़खड़ाहट सुनने के भी. इस हालत में मैं उन्हें 17 साल से देख रहा था. जब फेफड़ों की तकलीफ बढ़ती तो अपने हाथ से इंजेक्शन लगा लेते थे.

लेकिन जिंदगी की लड़ाई तो लड़नी ही थी. इस भागमभाग दिल्ली शहर में नौकरी, बच्चे, बूढ़े पिता, माई सब को सँभालने के लिए वसों के पीछे दौड़ना और धक्के खाना ही था. उन के चौड़े माथे पर चिपके कम वालों की ही चिंता की रेखाएँ आप भले ही मान लें पर वह वहाँ शायद टिकती नहीं थीं, वह टिकने नहीं देते थे. एक हल्की फीकी मुस्कराहट दो क्षण की मुलाकात में भी वह परोस लेते थे और छोटी से छोटी बात में भी एक नयी चितनशील मस्तिष्क की चमक फैला लेते थे.

आज मलयज की अनुपस्थिति में हिंदी समीक्षा जगत के एक कोने में पड़ी वह अकेली खाली हो गयी है जिधर सारी निगाहें उस समय टिकती थीं. जब किसी कृति पर लिख रहे, स्वायं रहित, वाद रहित, दुराग्रहों से मुक्त एक विवेकशील, संवेदनशील, सही, तार्किक, खरी दृष्टि की जरूरत महसूस होती थी. मलयज ने कम लिखा है. लेकिन जितना लिखा है वह समसामयिक समीक्षा की दुनिया में अग्रिम पंक्ति में है और अपने समय की कृतियों की पहचान बनाता अग्रिम पंक्ति में है. कभी भी किसी तात्कालिक जरूरत के तहत उन्होंने नहीं लिखा. वह रचना के साथ अरसे तक रहते थे, उस की एक एक पंक्ति पहचानने में लगे रहते थे और फिर लिखते थे. आज यह कहना जरूरी लगता है—'अब इसका कोई मतलब नहीं है'—वह समसामयिक हिंदी कविता के सबसे पारखी थे और एक मात्र ऐसे समीक्षक थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था. उन का निघन इस अर्थ में एक अपूरणीय संपदा है.

मलयज ने कविताएँ भी लिखी हैं, सर्जनिक गद्य भी लिखा है. जिस का संकलन अभी से जाने के लिए तैयार है. वह रामचंद्र शुक्ल पर भी इधर काम कर रहे थे. लेकिन हिंदी आलोचना की दुनिया में कच्चा रास्ता और अपनी एक कच्ची छपी छोड़ कर वह चले गये. दोनों को उन



की सख्त जरूरत थी. अभी उन्हें और रहना चाहिए था. इतनी जल्दी और इतनी खामोसी से नहीं जाना चाहिए था.

26 अप्रैल को 5 बजे माडल टाउन के अपने निवास से हिंदूराव अस्पताल ले जाते समय हृदय गति रुक जाने से टैक्सी में ही उन का देहांत हो गया. उसी दिन उन्होंने आफिस टेलीफोन किया था कि तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन की छुट्टी चाहते हैं. कहते हैं आवाज टेलीफोन पर ही डूब रही थी फिर धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ने लगा. अस्पताल जब शरीर पहुँचा तब वह पार्थिव था. पुलिस ने रख लिया. किन्हीं नियमों के अनुसार जाँच पड़ताल में पूरी रात और दूसरे दिन के डेढ़ बजे तक का समय पुलिस ने बिता दिया. फिर कहीं परिवार वालों को शव दिया गया. इस तरह 27 अप्रैल को दो बजे दिन में उनका शरीर, सकते में खड़े उन के दफ्तर के तमाम लोगों, बीस पच्चीस उदास साहित्यकारों, बिलखती पत्नी, कांपते बूढ़े पिता और सहमे दो भोले बच्चों के सामने विद्युत शवदाह गृह को सौंप दिया गया.

एक खामोश, आत्म विज्ञापन से दूर, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ वह व्यक्ति इस तरह हमेशा के लिए अनुपस्थित हो गया जिसे हम राजधानी की साहित्यिक भीड़ में खोजते रहते थे और कभी कभी किसी भीड़ में अचानक कहीं अलग चुपचाप खड़े देख लेते तो खुशी से भर जाते थे. मलयज जी भावुक नहीं थे. तन से भले ही रहें हों पर भीतर से कमजोर नहीं थे. संघर्ष की अपार क्षमता उन में थी. सहृदयता और संवेदना से भरपूर थे. पर किसी का भी वह प्रदर्शन नहीं करते थे. बच्चे, पत्नी, पिता, माई—सबके होकर जी रहे थे. इन का क्या होगा?

बच्चा बिटुर बिटुर ताकता है  
बीबी उधेड़ उधेड़ कर सीती है  
रोती हुई आँख.

घुआँ है छप्पर को उठाए हुए दीवार

## मलयज

जन्म: 1935 महुई, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में.

शिक्षा: एम. ए. (अंग्रेजी) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1963 में.

प्रकाशन: जह्म पर धूल (कविता संग्रह): 1971. शमशेर (सर्वश्वर दयाल सक्सेना के साथ संपादित): 1971. कविता से साक्षात्कार (आलोचनात्मक निबंध): 1979. अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ (कविता संग्रह): 1980. सर्जनात्मक गद्य का एक संकलन हँसते हुए अकेलापन शीघ्र प्रकाश्य. घर का पता: सी-12, माडल टाउन, दिल्ली-110009

एक हाथ सँकता है दूसरा मुलगाता है  
एक बहुत बड़े पड़ोस के अहाते में  
धिरा हुआ यह मकान  
वस यूँ ही खड़ा है—  
(अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ)

माडल टाउन में उन का किराये का मकान याद आता है जहाँ वह 17 साल से रह रहे थे—और यह भी कि उसके साथ हम सब भी वस यूँ ही खड़े हैं—उन की पत्नी, बच्चों, तथा परिवार जनों के दुख में दुखी...

—स. द. स.

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंगलिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें. अपने विषय की विवरणी मंगाइये. कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें. विवरणी हेतु लिखें. इंस्टीट्यूट आफ जर्नेलिज्म (द), पोस्ट बाक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. विवरणी मंगाइये. पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.



## राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह



विज्ञान भवन में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से पुरस्कार प्राप्त करत हुए (बायें से) गौतम घोष, अपर्णा सेन, आशा जोसले और खय्याम

## चूहेदानी में फँसा आदमी

29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की चमक और उस का 'ग्लैमर' इस बार भी कम नहीं था। पुरस्कारों से जब कुछ लोकप्रिय नाम जड़ जाते हैं, तो इन समारोहों का ग्लैमर अपने आप ही बढ़ जाता है। लोगों का ध्यान सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्देशक से अधिक फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों पर रहता है। इस बार के पुरस्कृत अभिनेता ओम पुरी वर्षों दिल्ली में मंडी हाउस के इर्दगिर्द की सांस्कृतिक दुनिया में देखे जाते रहे हैं। तथाकथित कला फिल्मों में काम करके भी उन्होंने अपनी विशेष पहचान बना ली है। लेकिन अभी वह फिल्मी सितारों के नखरों से दूर हैं और इस का एक कारण यह भी है कि उन के प्रशंसक अभी उन्हें बुरी तरह से घेर नहीं लेते हैं। इसलिए वह पुरस्कार समारोह में वक्त से कुछ पहले ही अपनी सीट पर बैठ गये। श्याम बेनेगल तो उनसे भी पहले बड़ी ईमानदारी से अपनी सीट पर जमे हुए थे। लेकिन लोगों को जाहिर है कि इतजार अभिनेत्री रेखा का था।

यह तो बहस का विषय है ही कि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेनिफर कपूर को क्यों नहीं दिया गया। '36, चौरंगी लेन' कि बहुचर्चित निर्देशिका अपर्णा सेन इस फिल्म से जुड़ कर इतना अधिक प्रचार पा चकी हैं कि पुरस्कार समारोह के बाद टी. वी. द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने अलग से और काफी ध्यान दे कर इस फिल्म की सफलता में जेनिफर के योगदान की चर्चा की। यहाँ यह भी बता देना उचित होगा कि सत्यजित राय के अलावा लगभग सभी बड़ी हस्तियाँ अपना पुरस्कार पाने के लिए मौजूद थीं। इस

तर्क से '36, चौरंगी लेन' के निर्माता शशि कपूर को अपना रजत कमल और 15 हजार रुपए का पुरस्कार लेने के लिए आना चाहिए था। लेकिन उन का पुरस्कार भी अपर्णा सेन ने लिया। वैसे विज्ञान भवन में बैठे दर्शक अगर रेखा और नौशाद अली और खय्याम आदि लोकप्रिय फिल्मी नामों का जोरशोर से स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने अपेक्षाकृत कुछ कम ग्लैमर रखने वाले नामों का भी उत्साह से स्वागत किया। यह अलग बात है कि समारोह का पुरस्कार वाला हिस्सा खत्म होने के तुरंत बाद काफी लोग घर जाने के लिए दौड़े। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 'दखल' को देखने की हिम्मत शायद सब में नहीं थी। 'दखल' के निर्देशक गौतम घोष इस वर्ष कलकत्ता फिल्म महोत्सव में अपनी प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से फिल्म पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पत्रकारों ने फिल्म को देखा नहीं था।

अभिनेत्री रेखा सजी घड़ी पुरस्कार समारोह के ठीक वक्त पर पहुँची। पत्रकार और फिल्म प्रेमी रेखा के 'मूडी' होने की खूब चर्चा कर रहे थे। लेकिन यह भी सब को पता था कि रेखा आयेंगी जरूर। आखिर राष्ट्रीय स्तर के समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने का सपना एक बॉक्स ऑफिस की लोकप्रिय अभिनेत्री भी देखती है। रेखा की बगल में इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता लेखेंद्र सिंह अपने प्रदेश (मणिपुर) की वेशभूषा में मुस्तेदी से डटे हुए थे। 9 वर्ष के इस बाल कलाकार ने अपनी पहली ही फिल्म में यह पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। पतंगबाजी के शोकीन इस बाल कलाकार का रेखा ने बराबर ध्यान रखा।

समारोह के अंत में जब अपने पाँच हजार रुपए के चेक को अपने कागजों में लेखेंद्र सिंह ने बहुत सँभाल कर नहीं रखा, तो रेखा ने फौरन उस पर ध्यान दिया।

कथा फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने अपने भाषण की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर की। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने जो भी पहला काम किया था उस में कोई दुर्घटना जरूर हुई थी। और इस दुर्घटना का संबंध खुद उन से नहीं दूसरों से रहा है। इस प्रकार की अनेक दुर्घटनाओं की चर्चा करते हुए अशोक कुमार ने कुछ मुस्करा कर कहा कि लगता है 'पहली बार के इस अपशकुन' से मुक्त हो गया हूँ क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कोई दुर्घटना नहीं जुड़ी है।

अशोक कुमार ने 'शो बिजनेस' की आलोचना भी की और उसे बचाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा—फिल्म उद्योग के लिए सरकार की मदद से एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

बैसे तो जूरी के फैसलों से आम सहमत मुश्किल होती है लेकिन इस बार भी फिल्म प्रेमियों और समीक्षकों की आम राय है कि फिल्म में पहला और दूसरा पुरस्कार पाने वाली फिल्मों से बेहतर फिल्में मौजूद थीं। 'दखल' में संवेदनशील ढंग से अपनी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रही औरत की कहानी को फिल्माया गया है। सिर्फ 72 मिनट की इस फिल्म में निर्देशक ने फिल्म भाषा को अपनी अच्छी समझ दिखायी है। लेकिन लयांग है बंगाल के अधिकांश फिल्मकार सत्यजित राय की फिल्मों के असर से मुक्त नहीं हो पाए हैं। 'दखल' का अंदाज हालाँकि 'प्येर पंजाबी' से



बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनेक स्थलों पर उस को याद आ जाती है। किसी बड़े फिल्मकार से प्रभावित होना स्वाभाविक है लेकिन एक नये फिल्मकार को अपनी भाषा के बड़े फिल्मकार को एक चुनौती के रूप में अधिक लेना चाहिए।

इस वर्ष की दूसरी सर्वश्रेष्ठ कथा फिल्म 'पोक्कूवेईल' के निर्देशक सुपरिचित मलयालम फिल्मकार जी अरविंदन हैं। फिल्मों की अपनी काव्यात्मक समझ को वह अपनी अनेक फिल्मों के माध्यम से उजागर कर चुके हैं। 'पोक्कूवेईल' एक संवेदनशील कॉलेज के छात्र की कहानी है जो पागलपन की दुनिया में पहुँच गया है। एक खिलाड़ी और एक क्रांतिकारी लड़के के साथ के अलावा इस युवक के काव्यात्मक विराज से एक लड़की भी प्रभावित है। लेकिन धीरे धीरे उस के सब साथी उस से दूर चले

पहुँच कर अडूर ने यह साबित कर दिया है कि वह दक्षिणी सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार हैं। उन की पहली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ कथा फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि उन की नयी फिल्म को इस प्रकार के सम्मान से वंचित रखा जाये।

'एलीपथम' में उन्नी नामक एक विचित्र व्यक्ति के जीवन का बारीक अध्ययन किया गया है। सामंती परिवार व्यवस्था की उपज उन्नी किसी मेहनत के काम के लायक नहीं है। उस की तीन बहनें हैं जिन में से एक विवाह के बाद अलग अपने परिवार के साथ रह रही है। लेकिन वह अपना हिस्सा चाहती है। उन्नी की अन्य दो बहनें उस के साथ ही रह रही हैं। इन में से एक राजम्मा (शारदा) विवाह की उम्र पार कर चुकी है और बीमार

रह रही है। चूहे को चूहेदानी में फँसा कर बाहर तालाब में डुबो दिया जाता है लेकिन चूहे तो निकलते ही रहेंगे। खुद उन्नी का जीवन एक चूहे की तरह है जिसे कुछ लोग एक दिन तालाब में डाल आयेगे। उन्नी वैसे तो डरपोक है लेकिन अपने हितों को लेकर बहुत सजग भी है। काम वह नहीं करना चाहता है लेकिन अपनी जमीन जायदाद और घर में बैठ कर आराम कुर्सी में पड़े-पड़े खूब ध्यान से अखबार पढ़ने की आदत में वह बहुत चीकन्ना है। लेकिन क्या किया जाये—वक्त ही ऐसा आ गया है कि उन्नी चूहेदानी में फँस कर चीजों को देखने के लिए मजबूर है।

अडूर गोपालकृष्णन की सिनेमा की समझ बहुत साफ है लेकिन उन की पटकथा थोड़ी उलझी हुई है। अभिनय, कैमरे के काम, संगीत, ध्वनि, संवाद आदि अनेक स्तरों पर निर्देशक

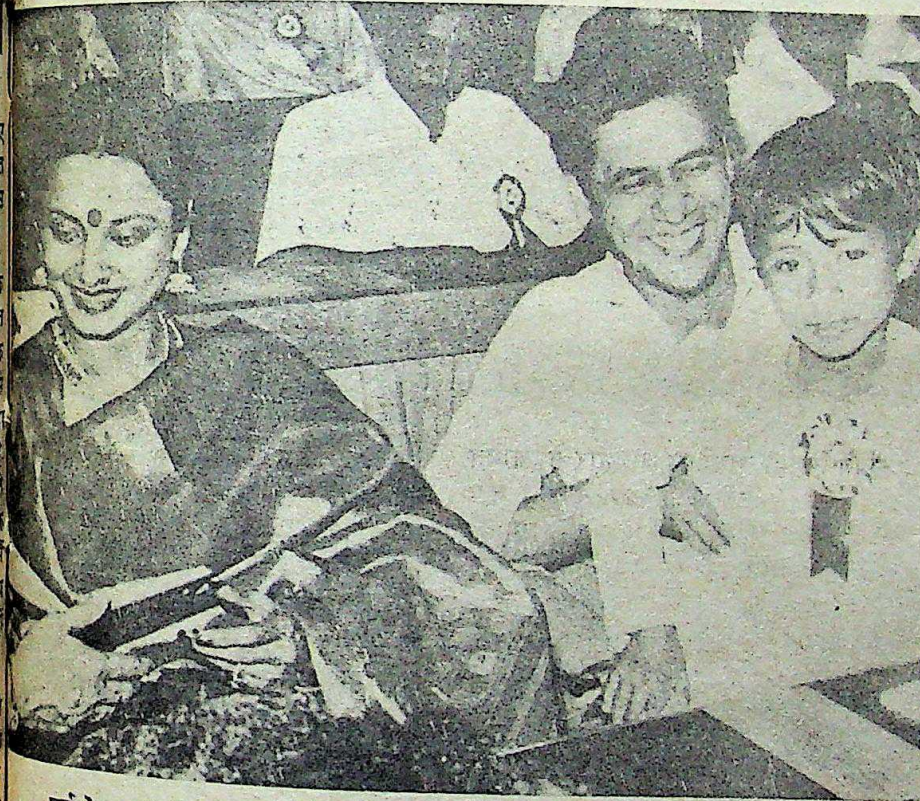
और लक्ष्य

चौं हजार रूप  
द्र सिंह ने बहु  
ने फौरन उ

अध्यक्ष अशोक  
आत व्यक्तिप  
कि अब तब  
क्या था उस  
और इस दुर्घटना  
संसारों से रहा है  
की चर्चा कर  
करा कर कहा कि  
अपशकुन' से मैं  
ने तक राष्ट्रीय  
ई दुर्घटना नहीं

विजनेस' को  
बचाने की भी  
फिल्म उद्योग के  
अच्छी वित्तीय

आम सहज  
बार भी फिल्  
राय है कि क  
पुरस्कार प  
लमें मौजूद  
अपनी अमी  
रत की कहानी  
72 मिनट की  
फिल्म भाषा को  
लेकिन लया  
मकार सत्य  
स्त नहीं हो पा  
'प्येर पंजाब  
9-15 मई '82



सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेखा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओमपुरी और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार लेखेंद्र सिंह



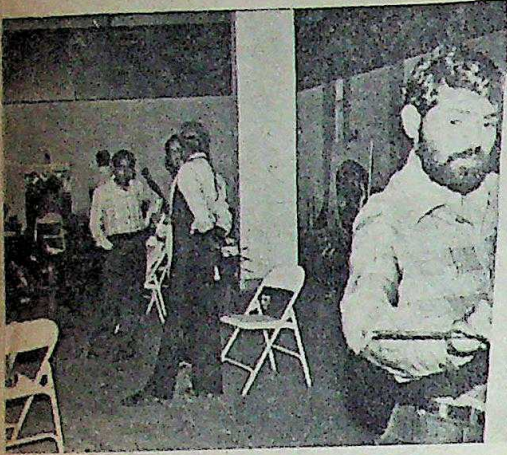
जी. अरविंदन और अशोक आहूजा

ने पर्याप्त कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए अपने विचित्र पात्र से हमारा परिचय कराया है। बुनियादी रूप में यह फिल्म त्रासदीपूर्ण है लेकिन इस में जगह-जगह पर व्यंग्य भी बहुत तीखा है।

इस वर्ष की अनेक पुरस्कृत फिल्मों की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 'आधारशिला' और 'उंबरठा' (मराठी) दो अन्य पुरस्कृत फिल्मों का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। नये निर्देशक अशोक आहूजा ने 'आधारशिला' में एक रचनात्मक फिल्मकार के संकटों को उभारा जरूर है पर फिल्म अपनी समग्रता में कोई प्रभाव नहीं डालती है। अंत तक आते आते तो वह उखड़ ही जाती है। इस फिल्म में देवकीनंदन पांडे ने जरूर एक लेखक की रोचक भूमिका निभायी है। जम्भार पटेल की 'उंबरठा' हिंदी में 'सुबह' नाम से भी प्रदर्शित होगी। इस में सुलभा (स्मिता पाटिल) नामक एक उच्च मध्य-वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी बहू का जीवन संघर्ष है। वह कुछ करना चाहती है और लगता है कि उस की समाजसेवा में लगी सास और उस का बकील पति भी उस को कुछ करने देना चाहता है। लेकिन वह जब कुछ करने लगती है तो परिवार के सदस्यों की पोल धीरे धीरे खुलती है। एक महिला आश्रम की अधीक्षिका के रूप में अनेक तरह की औरतों के संपर्क में आ कर सुलभा जीवन को एक नये ढंग से देखती और समझती है। □

रहती है। उन्नी उस पर इतना अधिक निर्भर है कि दरअसल वह चाहता ही नहीं है कि उस का विवाह हो। सब से छोटी बहन श्रीदेवी कॉलेज जाती है और प्रेम के स्वाभाविक सपने देखती है। उन्नी का जीवन बराबर अँधेरे की तरफ जा रहा है। राजम्मा की बीमारी एक दिन उसे खा जायेगी। और श्रीदेवी घर की घुटन से घबरा कर एक दिन भाग जायेगी। उन्नी अपने दुःस्वप्नों की दुनिया में खत्म हो जायेगा। निर्देशक ने उन्नी के जीवन के संकट को उस के कई प्रकार के डरों से जोड़ कर देखा है। वह ठंडे पानी में नहाने से और चूहे से बहुत डरता है। फिल्म की शुरुआत चूहे के उस के





कलाकार कार्यशिविर : अच्छी शुरुआत

## तीसरी मंजिल में कलाकार

पिछले दिनों साहित्य कला परिषद, दिल्ली ने दिल्ली ललित कला महाविद्यालय में एक कलाकार कार्यशिविर का आयोजन किया। साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित यह पहला ही कार्यशिविर था। भाग लेने वाले दिल्ली के 10 चित्रकार थे—देवसी, अनिल करंजी, मोना राय, निर्मल कपूर, उमेश वर्मा, सूरज घई, रवींद्र वर्मा, बी. पी. पालीवाल, आर. पी. निगम और सुमानव. तिलक मार्ग स्थित दिल्ली ललितकला महाविद्यालय की तीसरी मंजिल में यह कार्यशिविर 12 दिनों तक चला। साहित्य कला परिषद ने कलाकारों को अपेक्षित रचना सामग्री की व्यवस्था की। शिविर के दौरान बनने वाले चित्रों का स्वामित्व कलाकारों का ही रहा। अनंतर परिषद ने रवींद्र भवन दीर्घाओं में इस शिविर में तैयार कृतियों की एक प्रदर्शनी भी लगायी (प्रत्येक कलाकार का एक चित्र) इसी समय राजस्थान ललित कला अकादेमी ने भी परिषद के सहयोग से अपनी 23 वीं राज्य प्रदर्शनी की कृतियाँ रवींद्र भवन दीर्घाओं में प्रदर्शित कीं। यह प्रदर्शनी अंतर-राज्यीय आदान-प्रदान योजना के अंतर्गत लगी।

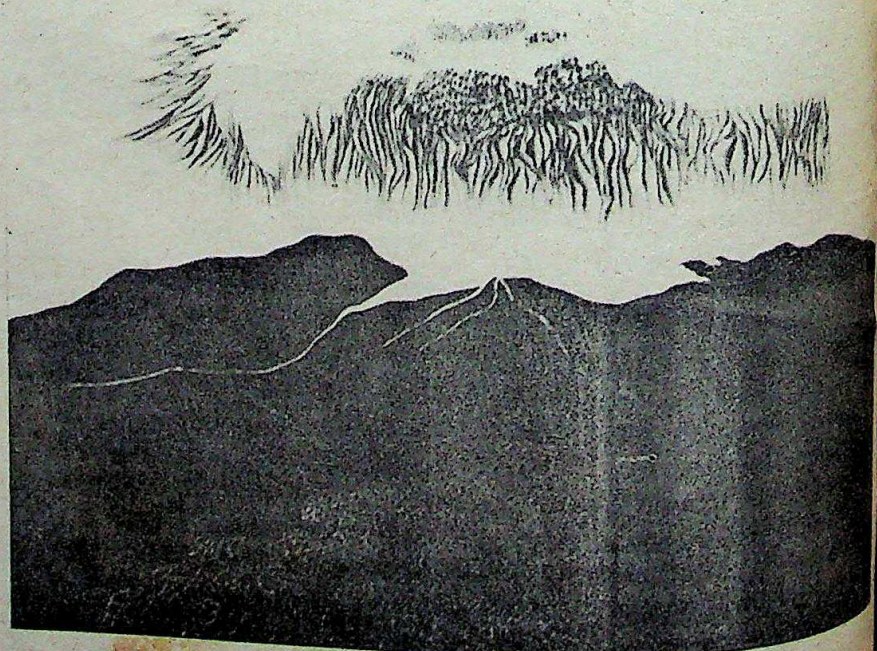
परिषद द्वारा शिविर की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। कलाकार देवसी के अनुसार 'शिविरों में काम करना एक अलग तरह का अनुभव है। कृति की शुरुआत अपेक्षाकृत सोची विचारी (जोर देकर?) होती है। लेकिन फिर कृति अपनी ही रचनात्मक शक्त अख्तियार कर लेती है।' हम समझते हैं कि शिविरों का आयोजन दो तरह से हो सकता है: एक तो उसी तरह जैसे यह शिविर आयोजित हुआ: कलाकार लगभग एक तरह के एकांत में काम करते रहे। दूसरे इस तरह कि कलाकार शिविर के साथ ही कलाकारों के साथ औपचारिक-अनौपचारिक

बातचीत के आयोजन, स्लाइड शो, कला फिल्मों के प्रदर्शन भी हों—जिस से कि शिविर स्थल पर तत्काल एक 'वातावरण' भी बने और दर्शकों की एक दूसरी तरह की साझीदारी भी हो। दर्शकों और कला प्रेमियों के पक्ष से सोचें तो दूसरी तरह के कार्य शिविर ही अधिक उपयुक्त लगते हैं। बहरहाल परिषद ने इस तरह के आयोजन से अपनी कला संबंधी गतिविधियाँ कुछ और बढ़ायी हैं। इस से पहले तो वह एक वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन भर करती रही है। यहीं यह जोड़ सकते हैं कि जिस तरह उसने अंतराज्यीय आदान-प्रदान के अंतर्गत राजस्थान के कलाकारों की प्रदर्शनी लगायी है, उसी तरह वह कलाकार-कार्यशिविरों में अन्य राज्यों के कुछ कलाकारों को भी आमंत्रित कर सकती है। शिविर की अवधि के लिहाज से चित्रों का स्तर सामान्यतः अच्छा था। सूरज घई, देवसी आदि के चित्रों की रंग-संगति और रंग व्याप्ति संवेदनशील थी।

## लेकिन एक सवाल

राजस्थान ललित कला अकादेमी की 23 वीं वार्षिक प्रदर्शनी में कुल 76 कृतियाँ थीं : 48 चित्र, 21 छापे और 8 मूर्तिसिल्प। पुरस्कृत चित्रकारों—मोहन शर्मा, राधा वल्लभ गौतम, कन्हैया लाल वर्मा, विद्यासागर उपाध्याय, दलीप सिंह चौहान और मीनाक्षी शर्मा की कृतियाँ साधारणतः अच्छी थीं। सम-कालीन राजस्थानी कलाकार अपनी कला परंपरा और परिवेश से एक आत्मीय रिश्ता बनाये रहे हैं और समय समय पर इस के कुछ अच्छे नतीजे भी देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन

एक सवाल जो इन प्रदर्शनियों को भी देख कर उठता है (कई अन्य प्रदर्शनियों की तरह) वह ईजल/कैनवास चित्रों से जुड़ा हुआ है। कैनवास चित्र भले ही पश्चिम की देन हो, लेकिन अब तक हमारे यहाँ भी उस की एक परंपरा बन चुकी है। ऐसी स्थिति में उस की हालत जाँचने लायक है—या कहें वह समय समय पर जाँचने लायक बन जाती है। हर माध्यम की अपनी कुछ शक्तें, चुनौतियाँ और संभावनाएँ होती हैं। कभी कभी यह लगने लगता है कि हम ईजल या कैनवास चित्र की चुनौतियों और संभावनाओं, दोनों से कुछ बचने लगे हैं। तथाकथित आधुनिक मुहावरों की किन्हीं रूढ़ियों के आरोपण से ही बहुतेरे चित्र संपन्न होते हैं या फिर कागज पर बनने वाले रेखांकनों-चित्रणों का एक रूपान्तर भर कैनवास धरातल पर देखने में आता है। अचरज नहीं कि ऐसे बहुत से चित्र हमें अच्छा ही छोड़ जाते हैं। कई बार तो कैनवास धरातल पर रंगों को जैसे तैसे रख देने से ही एक चित्र की इतिश्री मान ली जाती है। चित्रण और चित्रांकन में जो मूल भेद है, उसे ही अनुपस्थित पा कर हम एक चित्र को पूरा होता हुआ देखते हैं तो एक बासीपन जैसे उसमें दूर से ही दिखने लगता है। जब कि किसी चित्र की सब से बड़ी ओर पहली या एक अत्यंत जहरी माँग तो यही है कि वह स्पेस संबंधी एक सम्यक बरताव को चौखटे के भीतर जितना क्षेत्र है, वही चित्र क्षेत्र भी लगे—शुरू से आखिर तक तो जाहिर है कि चित्र, कथ्य को हमारे लिए निरंतर खोजने को बाध नही बना रह सकता। इन समूह प्रदर्शनियों में भी कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो बहुतेरे चित्र, चित्र बनाने की एक औपचारिकता लगते हैं।



विद्यासागर उपाध्याय की एक चित्रकृति



को भी देख का  
की तरह) वह  
आ है. कैनवास  
हो, लेकिन अब  
एक परंपरा का  
हालत जांचने  
समय पर जांचने  
की अपनी कुछ  
होती हैं. कभी  
हम ईजल या  
पर संभावनाओं,  
कथित आधुनिक  
आरोपण से ही  
फिर कागज पर



सम्मेलन का उद्घाटन करते  
भगवत झा आजाद

## हिंदी साहित्य सम्मेलन

पिछले दिनों भागलपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का छठा अधिवेशन स्थानीय गवान पुस्तकालय में संपन्न हुआ अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय श्रम मंत्री भगवत झा आजाद ने किया. अपने उद्घाटन भाषण में आजाद जी ने कहा कि—'देश को एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी ही है. लोगों को अपने राष्ट्र-प्रेम के समान ही राष्ट्रभाषा का भी सम्मान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'जिस तरह माँ को दुध की जरूरत है उसी तरह हम हिंदी को हिंदी की जरूरत है.' उद्घाटन से पहले जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के महा-पंचायत के डॉ. विष्णु किशोर झा 'बेचन' ने आमंत्रित साहित्यकारों का स्वागत किया.

इस अधिवेशन में विहार के मुख्य साहित्य-कारों ने भाग लिया. जिस में हिंदी विद्या-पीठ, देवघर के कुलपति नवल किशोर गौड़, गुरुदास लाल सेवा आयोग के अध्यक्ष डा. कुमार राम, विहार राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक डा. राम कयाल पांडेय प्रमुख थे. मंच का उद्घाटन भागलपुर विश्वविद्यालय के भू. पू. विभाग के सत्येंद्र नारायण अग्रवाल ने किया. इस में कवि सम्मेलन हुआ. जिस में पं. राम कयाल पांडेय, दामोदर शास्त्री, डा. बेचन, गणत, रविकांत नीरज, लखन 'अकेला' आदि कवियों ने भाग लिया.

—प्रमोद नारायण मिश्र

## चित्र प्रदर्शनी

हाल ही में कोटा (राजस्थान) सूचना केंद्र पर चित्र प्रदर्शनी 82 के नाम से संपन्न प्रदर्शनी में लगभग एक दर्जन उभरते एवं परंपरागत कलाकारों के लगभग चार दर्जन

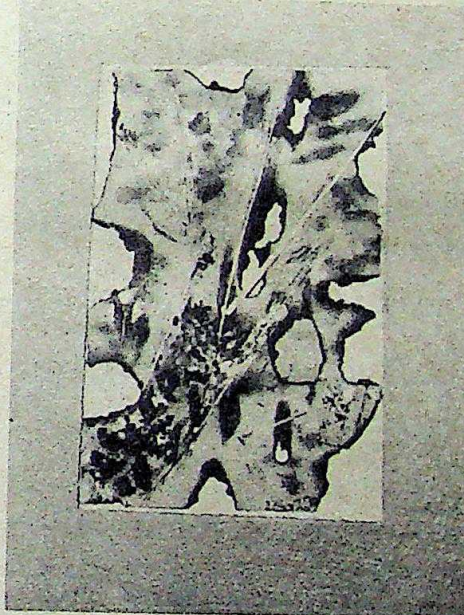
चित्र परंपरागत एवं आधुनिक शैली के प्रदर्शित किये गये.

साहित्य कला मंदिर के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में परंपरागत शैली के वयोवृद्ध चित्रकार प्रेमचंद शर्मा, डा. कुमारी अचना कुलश्रेष्ठ आधुनिक शैली तथा विदेशों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि रंगकर्मी सुभाष केकरे तथा श्रीमती उषा जोशी के दृश्य में सैरों की चर्चा रही.

डा. कुमारी कुलश्रेष्ठ व श्रीमती उषा जोशी ने अपने चित्रों को नया मोड़ दे कर कला जगत में सराहनीय कार्य किया. कु. कुलश्रेष्ठ ने कागज को जला कर रंग संयोजन का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया. श्रीमती जोशी ने ब्लेड व चाकू की सहायता से रंगों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया.

—प्रभात कुमार सिंघल

कु. अर्चन कुलश्रेष्ठ द्वारा जला कर प्राकृतिक रंग संयोजन से बनी आधुनिक शैली की एक कृति



## जनजातीय संगीत नृत्य समारोह

मीरजापुर में ओबरा के खुले स्टेडियम में जो चारों ओर पहाड़ियों और नदियों, नालों, झरनों से घिरा है, उ. प्र. संगीत नाटक अकादेमी के तत्वाधान में केंद्रीय संगीत नाटक अकादेमी के सहयोग से आयोजित आदिवासी संगीत नृत्य समारोह हुआ. इस आदिवासी क्षेत्र में लगभग 150 आदिवासी कला-कार पहली बार एक मंच पर देखे गये. कोल, खरवार, बैगा, बैसवार, घसिया, घांगर, भुईहार, घरकार आदि जनजातियों द्वारा करमा, झूमर, कोलदहकी, घरकहरी, अगरिया, (देवी नृत्य) नटुआ आदि नृत्य परंपरागत वाद्य

यंत्रों के साथ सादे वेशभूषा में प्रस्तुत हुए जिन को देखने के लिए लगभग 10,000 की भीड़ एकत्र थी.

करमा के बाद आदिवासी स्त्री पुरुषों ने झूमर नृत्य प्रस्तुत किये. झूमर यानी जिमे झूम झूम कर गाया जाता है. नटुआ नर्तकों की टोली ढोल, मजीरा, सारंगी, सितार, थाली, छड़ की सम्मिलित आवाज में 'कहवाँ जनम मइन इसरी महादेव, कहवाँ जन्ममइ हो कन्हइया' पंक्तियाँ गूँजने लगती हैं. पीले रंग का घंघरा, साड़ी, चिथड़े लपेटे जोकर. चुटकुले छोड़ता है, नाटक करता है, पुराने किस्म के नाटक जो कहीं लिखे नहीं मिलते. घरकारों की टोली नंग वड़ंग केवल बिहटी लपेटे, काले कलुटे,



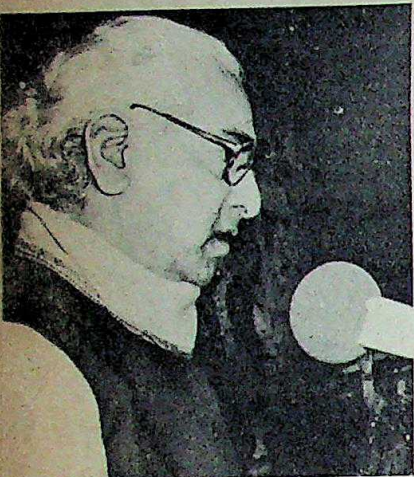
करमा नृत्य का एक दृश्य

डफला और निशान बाजे बजाते गाती नाचती है. कोल कोलदहकी नृत्य प्रस्तुत करते हैं. ढोल की आवाज, नृत्य ऐसा कि जमीन से धूल उड़ने लगी. इन के इस गीत का नाम कोलदादर है. यह नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिल कर भी प्रस्तुत करते हैं. घांगरी, करमा और अंत में बैगाओं, बैसवारों, खरवारों और अगरियाओं द्वारा देवी भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया—झंडा, जलती अंगीठी, बाना, गुरदम, ढोल के साथ. देवी की चढ़ाई हुई. जीम में लोहे का छड़ पहना दिया गया. गुरदम भाँजते भाँजते पीठ पर रक्त के छींटे दिखाई पड़ने लगे.

इसी अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिस में डा. जगदीश गुप्त, डा. अर्जुनदास केसरी, एस. अतिबल, राकेश तिवारी और नरेंद्र नीरव ने जनजातीय संस्कृति, संगीत नृत्य एवं जनजीवन पर अपने सार्थक और सुझावात्मक विचार प्रस्तुत किये. प्रेमनाथ चौबे तथा राजदेव शुक्ल ने आदिवासियों के लिए रोटी की आवाज भी उठायी. आदिवासी बालकों ने भी तीरंदाजी का प्रदर्शन किया. लोकवार्ता शोध संस्थान द्वारा वाद्ययंत्र, शस्त्रास्त्र, वस्त्राभूषण संगीत नृत्य से संबंधित वस्तुएँ भी इस अवसर पर प्रदर्शित की गयी थीं.

—अर्जुनदास केसरी





## फहीमुद्दीन डागर

“ध्रुपद फहीमुद्दीन डागर नहीं है, वह भारतीय संस्कृति है। इस की साधना भारतीय संस्कृति की साधना है—योग की साधना”—प्रसिद्ध ध्रुपद गायक रहीम फहीमुद्दीन डागर (56 वर्ष) ने यह उद्गार एक सच्चे आवेग के साथ पिछले दिनों राजधानी में एक सलोनी शाम अपने विमुधकारी गायन के बाद व्यक्त किये। ‘डागर वाणी’ नादयोग है, स्वर-तत्व ज्ञान है। यह उन की मान्यता है। इस समय वह डागरवाणी के वरिष्ठ प्रमुख गायक हैं। वह रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी में हैं और इंडियन टुबैको कंपनी की संगीत शोध अकादेमी में कार्यरत हैं। कलकत्ते में रह रहे हैं। देशी विदेशी अनेक छात्र उन के हैं। स्त्रियाँ भी ध्रुपद सीख रही हैं जो स्वागत योग्य बात है क्योंकि आम तौर पर स्त्रियाँ ह्याल गायिकी से जुड़ी रही हैं। ध्रुपद गायिकी से नहीं। ‘ध्रुपद कठिन योग-गायन है। स्त्रियों के लिए पूरी तरह से इसे साध पाना कठिन है’ फहीमुद्दीन डागर कहते हैं। अपने पिता स्व. रहीमुद्दीन डागर से उन्होंने शिक्षा ली है और अपनी विनयशीलता में उन के सामने अपने को उन के पैरों की धूल भी नहीं मानते पर जब गाते हैं तो स्वरों के सहारे ही लगता है कि सैकड़ों मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं और मंत्रोच्चार हो रहा है। —स.

विनयान

## नौशाद अली

नौशाद को इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। भारतीय फिल्म संगीत को भारतीय बना रहने देने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी वह चुप नहीं हो गये हैं। ‘बैजू बावरा’, ‘अंदाज’, ‘मेरे महबूब’, ‘मदर इंडिया’ सरीखी फिल्मों के संगीतकार नौशाद आज भी ‘चाणक्य चंद्र-गुप्त’ फिल्म में भारतीय संगीत को रचाने बसाने की अपने ढंग की और महत्वपूर्ण कोशिशें कर रहे हैं। नौशाद शुरू से ही कम फिल्मों का काम अपने हाथ में लेते रहे हैं—मन से काम करने की सुविधा के लिए (उन्होंने बताया मेरी बीवी हमेशा इस बात से दुखी रही है कि छह लड़कियों की जिम्मेवारी के बावजूद आप अपने मन का काम करना चाहते हैं और ‘आर्ट’ की दुनिया में खोये रहते हैं!) फिर भी नौशाद सक्रिय हैं।

शोर और संगीत के घालमेल से नौशाद पराजित नहीं हुए हैं। दुखी जरूर हैं। हालाँकि उन्हें लगता है कि भारतीय संगीत की पहचान फिर से जरूर होगी। शायरी के अंदाज में वह कहते हैं, ‘अपने ही घर में खजाने बहुत हैं।’ वैसे नौशाद संगीतकार के अलावा शायर भी हैं। नयी दिल्ली में पुरस्कार पाने के अगले दिन पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कहना मुश्किल है कि मुझे अपनी किस फिल्म का संगीत खास तौर से पसंद है। अपनी कविता के



रंग में उन्होंने जोड़ा : ‘प्यास मेरी जो बुझ गयी होती, जिदगी फिर न जिदगी होती’।

अंग्रेजी के रंग में डूबी पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस कॉफ़ेंसों को ध्यान में रख कर नौशाद ने शुरू में ही कह दिया कि हिंदुस्तानी जवान में आप संवाल करेंगे तो मैं खुल कर अपने ख्यालात का बयान कर पाऊँगा और फिर जब नौशाद खुले और यादों में वह गये, तो बाहर आना मुश्किल था।

जनता की पसंद क्या है इसे दूषित करने के लिए नौशाद मुख्य रूप से फिल्म निर्माताओं को दोषी मानते हैं। आजकल के फिल्म निर्माताओं ने संगीत के संबंध में एक नयी भाषा ही बना ली है। भिसाल के लिए ‘म्यूजिक पर सिटिंग’ होती है जिस में ‘ट्यून’ पसंद वे लोग करते हैं जो संगीत को पहचानते ही नहीं। संगीत को वे लोग इस तरह की भाषा में पसंद करते हैं : ‘पेट तक लगा, पेटो के नीचे तक नहीं पहुँचा’।

जहाँ तक जनता की पसंद का सवाल है ‘आप इस बात को नोट कर लीजिए—ग्रामोफोन कंपनी आज भी साल में एक करोड़ रुपये का मेरा संगीत बेचती है’। नौशाद ने बताया कि “मेरे महबूब” के मुख्य गीत में जब उन्होंने कुल 6 साजों की व्यवस्था की, तो सब लोग हैरान थे कि दस भिन्न का गाना और इतने कम लोग! लेकिन नौशाद ने ‘आन’ के एक स्वप्न गीत के लिए सौ से ज्यादा साजों का इस्तेमाल भी किया था। सवाल भारतीय संगीत की समझ का और पश्चिम के आतंक से मुक्त होने का है। —वि.

## श्यामलाल यादव

राज्य सभा के उपसभापति पद पर पुनर्निर्वाचित श्यामलाल यादव की विशेष रुचि खेती और कानून में है। जन्म 1927 में वाराणसी के एक गाँव में, प्रारंभिक शिक्षा डी. ए. बी. कालेज वाराणसी और उच्च शिक्षा (एम. ए. एल. एल. बी.) इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई।

‘हमारी डिग्री पर उपकुलपति की हैसियत से आचार्य नरेश के हस्ताक्षर हैं। वह दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास सभी के पंडित थे। उन के उपदेश का इतना असर पड़ा था कि मैं भी विचारों से समाजवादी हो गया था’।

खेती का कानून और कानून की खेती करने (वकालत) की प्रक्रिया में, राजनीति में 1952 से ही सक्रिय हैं।



व्यक्तित्व का एक दिलचस्प पहलू यह है कि 30 वर्षों से निरंतर नगर और महानगर में रहने के बावजूद वह आज भी सपना गाँव का ही देखते हैं।

“गाँव की तरक्की देखना चाहता हूँ। बहुत कुछ बदला है। शिक्षा बढ़ी है, स्कूल कालेज बढ़े हैं। लेकिन उसी के साथ बेकारी भी बढ़ी है। यह बेकारी गाँव के लोगों को कसकने लगी है”।

राज्य सभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में सभी सदस्यों की बातें बहुत गौर से सुनते हैं। कहते हैं कि यदि सदस्य नियम अनुसार चले और अनावश्यक बातों में समय न गवायें तो अधिक विषयों पर ज्यादा उपयोगी बातें हो सकती हैं। संसद का कार्य ठीक तरह से होना चाहिए। विषयों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। संसद गलियारों में अक्सर यह सुना जाता है।

गवर्नमेंट मस्ट हैब इट्स वे अपोजीशन मस्ट हैब इट्स वे “मैं हमेशा ही इसे चरित्र करने की कोशिश करता हूँ”।

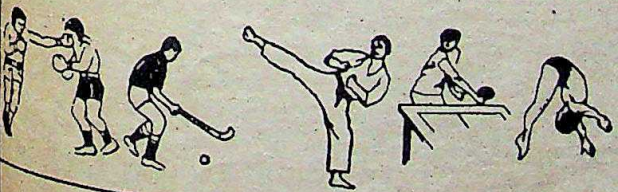


# टाइम्स हाउस द्वारा खेल पत्रकारिता के मैदान में एक बंपर उछाल

हिंदी में सम्पूर्ण खेल पत्रिका

# खेल भारती

जिसका लाखों पाठक न जाने कब से  
इंतजार कर रहे थे. अब हर महीने की  
पहली और १६ वीं तारीख को प्रकाशित



पहले ही अंक में आप इसमें पायेंगे : • भारत के ही नहीं  
विश्व भर के प्रमुख खेल आयोजनों का आखों देखा हाल.

- मशहूर खेल सितारों और खिलाड़ियों के जीवंत इंटरव्यू
- विभिन्न खेलों के नये-से-नये कीर्तिमानों की जानकारी.
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की व्यावहारिक सूचनाएं.
- खेलों के रोमांचक क्षणों के अनूठे अचूक छायाचित्र.

इतना ही नहीं, और बहुत-सी ऐसी सामग्री जिसकी  
आपने कल्पना भी न की होगी.

हर खेल प्रेमी के लिए जरूरी है

# खेल भारती

A GREAT NEW AD. MEDIUM.

बोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, 10 बरियानगंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
कार्यालय : डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएं : 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9;  
17 ए.एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700010; काशी-221001; कोलकाता-700069; 63, मोटियथ रोड, इगमोर, मद्रास-8;  
1, तीर्थ मयन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन एप्रोच, सडबरी, बेंगले, मिडिलसेक्स, लंदन, यू. के., लंदन टेलीफोन : 01-903-9696.







सामाहिक

# दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन

25 अप्रैल-1 मई, 1982 ★ 5-11 बंसाख, 1904

3  
28-4-82  
e

होटल जम्मू अशोक

मनमोहक घाटी का प्रवेश द्वार

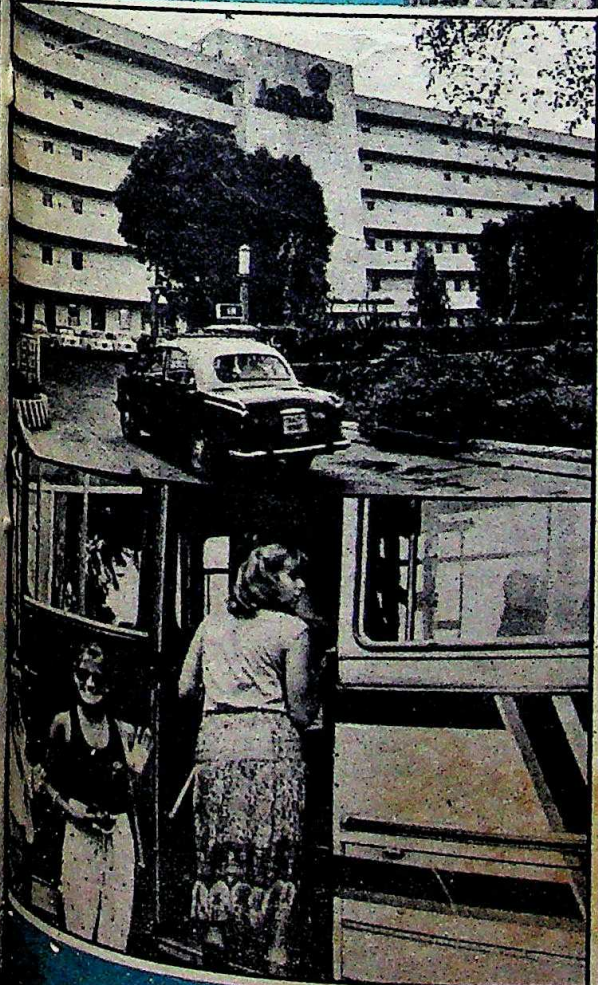
मालियर घराने  
की राजमहल  
राजनीति

धुर दक्षिणा  
में सांप्रदायिकता  
बार-बार क्यों  
मड़क रही है?

अरुणाचल  
के खोखले कवच

चंद्रशेखर,  
चौधरी और  
चंडीगढ़

12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त रहने की सुविधा



रु. 2.00

एशियाई के बाद  
सात हजार करोड़  
का क्या होगा?



# १९८२ को खेल वर्ष का नाम दीजिए!

क्योंकि इसकी  
शुरुआत भारत में  
विश्व कप के  
आयोजन से हुई

क्योंकि इसी वर्ष  
भारत में  
एशियाई खेल  
होने जा रहे हैं

और



क्योंकि इसी वर्ष खेलों की दुनिया में  
एक और घटना होने जा रही है  
जानते हैं क्या है वह ?

हिन्दी में एक सम्पूर्ण खेल पत्रिका का शुभारंभ ॥  
एक ऐसी पत्रिका जिस की कमी  
बहुत समय से महसूस की जा रही थी ॥  
एक ऐसी पत्रिका

जिसका लाखों पाठक अब तक इंतजार  
कर रहे थे. प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त.

टाइम्स आफ इंडिया की  
नयी सहयोगी पत्रिका

## खेलभारती

खेलों की दुनिया में नया कीर्तिमान

१६ अप्रैल से  
प्रकाशित

नेट, कोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, 10 बरियामंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित  
पंजी. कार्यालय: डॉ. दादामाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएँ: 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380015/7 ए. एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700014. कार्यालय: 13/1, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता-700069; 63, मोंटियथ रोड, इमोरी, मद्रास-600007-1, तीर्थ भवन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002; 26, स्टेशन रोड, सिकंदर, पंजाब-132001. कार्यालय: 10, मिडिलसेक्स, लंदन, यू. के., लंदन टेलीफोन: 01-963-9634



## इस सप्ताह

भारतीय पर्यटन विकास निगम :  
एशियाड के बाद होटलों के  
सात हजार कमरों का क्या  
होगा 13. ग्वालियर की  
राजमहल राजनीति 20. धर्म-  
निरपेक्षता : लड़ाई दो गैर  
बराबर ताकतों के बीच है 7.  
तमिषनाडु : धुर दक्षिण में  
सांप्रदायिक दंगे बार बार क्यों  
भड़क उठते हैं 24.  
बूढ़ों का नया संविधान 30.

मत और सम्मत 4. पिछले  
सप्ताह 5-6. पत्रकार संसद 6.  
उनका कहना है 10. दिल्ली  
के रंग 11. चरचे और  
चरखे 12. चित्रों के आईने  
में 22-23. दुनिया भर की 31.  
खेल और खिलाड़ी 32. युवा  
जगत 33. साहित्य 34.  
कला 37. संगीत 38. रंगमंच  
39. फिल्म 40. संस्कृति  
समाचार 41. चरित चर्चा 42.



शशिकांत मिश्र



तेगांग अपांग



पियरे बूढ़ो

आवरण : अशोक यात्री निवास, दिल्ली  
फोटो : श्रीकृष्ण शर्मा.

## संपादक : कन्हैयालाल नंदन

संपादकीय सहकर्मी : जितेंद्र गुप्त (सहायक  
संपादक), सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (मुख्य  
उपसंपादक), श्यामलाल शर्मा, जवाहरलाल  
कौल, शुक्ला दत्त, त्रिलोक दीप, महेश्वरदयाल  
गंगवार, प्रयाग शुक्ल, बनवारी, विनोद  
भारद्वाज और सुषमा पाराशर.  
विशेष संपादकता : रामसेवक श्रीवास्तव  
संस्था : रवि शर्मा

टोइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन  
10, वरियागंज, नयी दिल्ली-110002

## पाठकों से

दिल्ली में होटलों का निर्माण इन दिनों जोरों पर है। ये निर्माण कार्य 9वें एशियाई खेलों की तैयारी का हिस्सा है। हजारों विदेशी खिलाड़ी और दर्शक इस वर्ष के आखिर में हमारे मेहमान होंगे। उन सब के ठहरने के लिए जगह चाहिए और इस सिलसिले में होटलों के लगभग 7000 कमरों के अलावा भी हजारों और कमरों को सजाया जा रहा है। लेकिन इस से एक सवाल यह उठा है कि आखिर एशियाड बीत जाने पर इस अतिरिक्त आवासीय सुविधा का क्या होगा? आखिर भारतीय पर्यटन विकास निगम की योजनाएँ क्या हैं और क्या कहते हैं इस के अध्यक्ष श्री एस. के. मिश्र, 'दिनमान' प्रस्तुत कर रहा है। इन आसमान छूती बिल्डिंगों के आरामदायक पहलू के पीछे की समस्याएँ आवरणकथा के रूप में (पृ. 13 से 16).

ग्वालियर राजघराने के जिस राजनैतिक वर्चस्व को बनाये रखने के लिए श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1972 में इंदिरा कांग्रेस छोड़ कर जनसंघ में शामिल हो गयी थीं उस पर 1975 में संकट के बादल घिर आये। वह नजरबंद कर ली गयीं। ऐसे समय में राजमाता के पुत्र माधवराव सिंधिया ने संजय गांधी की दोस्ती के सहारे सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया। इस के बाद माँ-बेटे में मतभेद बढ़े जो अब संघर्ष में बदल गये हैं। जयविलास महल, जिसकी जमीन और इमारत का ही मूल्य 25 करोड़ रुपया आँका जाता है, माँ-बेटे में मुकद्देबाजी का मुद्दा बन गया है। इस बार दिनमान के लिए श्री क्षितींद्रमोहन श्रीवास्तव ने ग्वालियर जा कर इस मामले की छानबीन की, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों से भी मिले जो गुमनामी जीते हैं और राजमहल की किचकिच को रोज आँखों देखते हैं। प्रस्तुत है ग्वालियर से लौटने के बाद उनकी रपट. (पृ. 20-21).

'इनर लाइन' की लक्ष्मण रेखा और 'देशी धर्म स्वाधीनता विधेयक' के रक्षा कवच के बावजूद सीमा प्रदेश अरुणाचल के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह खतरा अरुणाचल के बाहर मसीही धर्मकेद्रों से है जिनके प्रेरणा और धन के स्रोत विदेशों में हैं। 1951 में अरुणाचल में एक भी ईसाई नहीं था लेकिन अब उनकी संख्या 15 से 20 हजार के बीच आँकी जा रही है। अरुणाचल का जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना लेता है वह सांस्कृतिक बागी हो उठता है। दिनमान के सहायक संपादक जितेंद्र गुप्त ने हाल में अरुणाचल का दौरा किया और पाया कि मसीही संगठन साम, दाम और भेद द्वारा अरुणाचल को मसीही रंग में रंगने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। (पृ. 7-8).

कन्याकुमारी की घरती हमारे देश के घुर दक्षिण में न केवल तीन समंदरों के मिलन का दृश्य प्रस्तुत करती रही है वरन हिंदू और ईसाई एकता का उदाहरण भी रही है। अचानक एक दिन उस एकता में दरार का घमाका सुनायी पड़ा। एकता प्रयासों ने स्थिति को शांत किया लेकिन चंद हफ्तों की खामोशी के बाद स्थिति फिर भड़क उठी। यह स्थिति देश में हिंदू-ईसाई सद्भाव के लिए गंभीर चुनौती बने इस से पहले हमें सोचना है कि आखिर घुर दक्षिण में यह आग बार-बार क्यों भड़क उठती है? क्या यह राष्ट्रीय एकता के आगे सवालिया चिह्न लगाती? आखिर इस क्षेत्र की एकता समिति के अध्यक्ष और संसद सदस्य क्या कहते हैं? (पृ. 24)

*Handwritten signature*



## जीवन भर 'अछूत'

4 अप्रैल : पद्मभूषण सीताराम सेकसरिया के बारे में पढ़ा। क्या यह कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि हम अपने समाज की महान विभूतियों के बारे में उन के निधन के बाद ही जान पाते हैं। हिंदी पत्रकारिता की यह परंपरा बन गयी है कि किसी की मृत्यु के बाद ही उस पर कोई लेख छप सकेगा। पेशावर कांड के वीर चंद्र-सिंह गढ़वाली, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक कर्मवीर पं. सुंदरलाल, इलाहाबाद के पं. पद्मकांत मालवीय जी, आचार्य किशोरीदास वाजपेई, बैरिस्टर मुकंदलाल आदि के बारे में पाठकों को उन के निधन पर ही जानकारी मिल सकी। हिंदी पत्रकारिता इन्हें जीवन भर 'अछूत' बना कर इन की उपेक्षा करती रही। मुझे दुखपूर्वक लिखना पड़ रहा है कि काकोरी कांड तथा लाहौर पड़्यंत्र केस के सुविख्यात क्रांतिकारी स्वर्गीय कुंदनलाल गुप्त की मृत्यु का समाचार तक अखबारों में नहीं छपा, जबकि वह एक 'जिंदा शहीद' की मौत थी। वे अपने जीवन के शेष दिन नागपुर में एक टीन के बने मोटर गैरेज में घोर अमावों और कष्टों में बिताते रहे, पर किसी पत्रकार ने उन्हें पूछा तक नहीं।—मुधिर विद्यार्थी, 43, सदर बाजार, शाहजहांपुर (उ. प्र.)

## भगतसिंह की खंडित प्रतिमा

इस वर्ष जबकि भगतसिंह और उन के क्रांतिकारी साथियों का 51 वां शहादत दिवस व्यापक रूप से मनाया जा रहा है, पिलानी में भगतसिंह की प्रतिमा खंडित की गयी। इस से पिलानी और पास पड़ोस की जनता में जबर्दस्त रोष फैला। श्री मनीराम वागड़ी ने गत सप्ताह लोकसभा में सवाल उठाया और मांग की कि सी. बी. आई. द्वारा अपराधियों का पता लगाया जाये और उन्हें उचित दंड दिया जाये। लेकिन सरकार ने गोल मटोल उत्तर दे कर मामले को रफा दफा कर दिया। यह घटना क्या है और इस घृणित कार्य के पीछे किन तत्त्वों का हाथ है मैं इस संबंध में 'दिनमान' के माध्यम से कुछ तथ्य प्रकाश में लाना चाहता हूँ।

भगतसिंह की यह प्रतिमा पिलानी की जनता द्वारा 23 मार्च 1980 को स्थापित की गयी थी। इसे एक स्थानीय कलाकार ने बनाया था। इस समारोह की अध्यक्षता मैंने की थी और प्रतिमा का अनावरण मन्मथनाथ गुप्त ने किया था। मेरठ के क्रांतिकारी साथी जोगेंद्र सिंह वारियर भी हमारे साथ थे। लोगों में बड़ा उत्साह था और वे बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे।

पिलानी घनश्यामदास बिड़ला का जन्म-स्थान है। बिड़ला ने वहाँ इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय कायम किया है, जहाँ दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। बिड़ला बंधुओं ने पिलानी को पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह दो भागों में विभाजित कर रखा है। दोनों भागों की म्युनिसिपैलिटी अलग अलग है। जिस भाग में बिड़ले का विश्व-विद्यालय है उस की म्युनिसिपैलिटी के सदस्य बिड़लों द्वारा नामजद होते हैं। जिस भाग में पिलानी की जनता बसती है, उस की म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों का चुनाव होता है। लोगों की मांग है कि एक नगर की दो म्युनिसिपैलिटी क्यों हों? दोनों को मिला कर एक किया जाये। इस के लिए उन्होंने अर्जी आदि भी दी और संघर्ष भी छेड़े, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस से पानी के निकास और सड़कों के निर्माण आदि में आम जनता को बड़ी कठिनाई है।

बिड़ला भाग के पिलानी चौक में गांधी की प्रतिमा है। जनता भाग के पिलानी चौक में भगतसिंह की प्रतिमा स्थापित की गयी। इसी चौक में चुंगी का दफ्तर है जो चौबीस घंटे खुला रहता है। यह प्रतिमा 18 फरवरी 1982 को रात को खंडित की गयी। चौकी के सामने जो चारपाई बिछी रहती है उस की दमेन निकाल कर प्रतिमा के गले में फंदा डाला गया और उसे गिराने का प्रयास किया गया। इस फंदे के निशान गले में मौजूद हैं। लेकिन लोहे

## आप फरमाते हैं

व्यंग्यचित्र : लक्ष्मण



“गैर जिम्मेवार प्रेस ने जो हम पर झूठे आरोप लगाये थे वे सब सही निकले हैं।”

के सरिये डाल कर प्रतिमा को मजबूती से लगाया गया है, इसलिए अपराधी उसे गिराने में तो असफल रहे लेकिन उसे जगह जगह से खंडित कर दिया।

ज़ाहिर है कि इस काम में काफी समय लगा और चुंगी के दफ्तर में एक न एक मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहता है। इस लिए अगर पुलिस चाहे तो अपराधियों का पता लगाना कठिन नहीं है। लेकिन आज तक अपराधियों का पता नहीं चल सका। कारण यह कि अपराधी चाहे कोई भी हैं उन के पीछे बड़ी शक्ति का हाथ है।—हंस राज रहबर, एस-16, नवीन शाहदरा, दिल्ली

## कुर्सी की भूख?

कांग्रेस (ज) के अध्यक्ष श्री जगजीवनराम ने भोपाल में बताया कि विपक्षी दलों को एकता के बजाय मिली जुली सरकार की पहल करनी चाहिए। शायद वे बगैर नींव के मकान बनाना चाहते हैं जो कभी भी आंधी के झोंके से गिर जायें।

बाबू जगजीवनराम ने वाराणसी में कहा था कि एकता की बात करने वाले 'कुर्सी की भूख' जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक एकता नहीं हो सकती। अब बाबू जी के बयान से लगता है कि उन को कुर्सी की भूख लग गयी है।—महेशगर्ग, 1514 उषागंज, इंदौर (म. प्र.)

## किसकी महानता?

इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम की घोषणा कर दी गयी है। टीम में कई संभावित खिलाड़ी नहीं हैं। चयनकर्ता वैसे तो कहते हैं कि खिलाड़ी का चयन उस का खेल देख कर किया जाता है परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो टीम रणजी प्रतियोगिता के फाइनल में 705 रन बना कर जीत जाये उस के सिर्फ एक खिलाड़ी (मदनलाल) का खेल पसंद आया और जो टीम सेमीफाइनल में ही हार जाती है उस के 6 खिलाड़ियों का खेल पसंद आ गया!

इस से साफ पता चलता है कि या तो भारतीय चयनकर्ताओं पर गावस्कर की महानता का इतना प्रभाव है कि गावस्कर के आगे उन की एक नहीं चलती या फिर चयनकर्ताओं में क्षेत्रतावाद की भावना नजर आती है। चौहान, मोहिंदर अमरनाथ, राकेश शुक्ला की उपेक्षा नहीं की जा सकती। टीम में दिलीप वेंगसरकर का चयन चकित करने वाला है। टीम में कोई नियमित विकेट कीपर नहीं है क्या यह इसलिए नहीं किया गया कि गुलाम



# पिछले सप्ताह

8-16 अप्रैल, 1982

## देश

8 अप्रैल : मोजावीक के राष्ट्रपति समीरा मोसेस मासोक का दिल्ली पहुँचने पर मध्य स्वागत, वीजू पटनायक, देवीलाल और कुमराम आर्य लोकदल से मुअनल. चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस (एस) को मान्यता प्रदान. ट्रारिका के शंकराचार्य श्री अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ का राजकोट में देहांत.

9 अप्रैल : प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मोजावीक के राष्ट्रपति को सभी तरह की सहायता का आश्वासन. डकैत जगतपाल पासी की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत्यु. राजस्थान के कर्मचारियों की 23 दिवसीय हड़ताल समाप्त.

10 अप्रैल : भारत के बहुउद्देश्यीय उपग्रह 'इनसट' का अंतरिक्ष में छोड़ा जाना. खालिस्तान के समर्थक गंगासिंह दिल्ली को दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेजा जाना. पवनार आश्रम में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आचार्य विनोबा भावे से भेंट.

11 अप्रैल : पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम को 1981 का डेढ़ लाख रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार.

12 अप्रैल : गीताजलि एन्क्लेव (दक्षिण दिल्ली) स्थित एक बैंक में 2.27 लाख रुपये की डकैती. डॉ. चेन्ना रेड्डी पंजाब के राज्यपाल नियुक्त. भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकदल और कांग्रेस (ज) से चुनाव समझौता करने का फैसला.

13 अप्रैल : भारत द्वारा फ्रांस से 40 मिराज विमान खरीदने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर. बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विदेश्वरीप्रसाद मंडल का पटना में देहांत. स्वाधीनता सेनानी पंडित परमानंद का दिल्ली में निधन.

14 अप्रैल : दिल्ली के साउथ एवेन्यू में संसद सदस्य दलवीर सिंह के घर दो सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा पाँच लोग बंधक बनाना लेकिन नौ घंटे बाद आत्मसमर्पण.

15 अप्रैल : पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल हक द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर दांव पर विदेशमंत्री नरसिंह राव का विरोध.

16 अप्रैल : चंडीगढ़ में प्रतिपक्षी सम्मेलन द्वारा संयुक्त चुनाव प्रचार का फैसला.

## मंत्री जी का रेल सफर

हमारे इलाके के संसद सदस्य जो कांग्रेस (ड) के हैं और जनता शासन के बाद श्रीमती गांधी की तूफानी जीत के साथ—आवास-निर्माण मंत्री बने तो ऐसा लगता था (उन के भाषणों व आवासीय योजनाओं से) कि अब देश के अन्य लोग चाहे आवासहीन हों पर इंदौर व उनके मतदाता जरूर अपना एक बंगला बने न्यारा का स्वप्न पूरा कर लेंगे. पर बदनसीबी कि वे कर्मचारियों की तरह तबादला लेकर पेट्रोल व रसायन के वजीर हो गए. फिर जब भी वे इस सर जमीन पर आये लाखों गैस के कनेक्शन का सज्ज बाग दिखाते रहे. पता नहीं कितने घरों को चूल्हे मिले और कितने घर आज भी धुआँ देख रहे हैं. अब वे रेल मंत्री हैं. अभी रेलमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी वह आए थे. इस के पहले शायद ही कोई रेलमंत्री इस शहर में और रेल से आया हो. उनके रेल वजीर बनते ही रेल विभाग ने ताबड़तोड़ एक डब्बा हावड़ा के लिए शुरू कर दिया और स्टेशन का नवीनीकरण. जो दरवाजे कभी नहीं खुले थे जिन पर रंग रोगन नहीं था वह भी चमक गए. बड़ा शानदार स्वागत हुआ बरसों की माँग पूरी करने का (दोहद इन्दौर लाईन). वादा हो गया. जो भी हो, अगर अपने अपने क्षेत्र का विकास का काम हर संसद सदस्य व वजीर तय कर ले तो देश चमन हो जाये, साथ ही मुल्क के वजीर आसमान के बजाए जमीन पर आ जायें तो भी मुल्क गुलजार हो जाये. मैं अपने 'दिनमान' के जरिये इस देश के सभी मंत्रियों से गुजारिश करूँगा कि वे मुल्क के हर शहर में जायें ताकि वहाँ के तमाम सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों का रख-रखाव सही हो सके. न्यायालय, थाना, अस्पताल, शिक्षालय जनसेवा व इमानदारी से काम कर सकें—रेल आरक्षण में जो कायदे के बजाए फायदे में काम होता है और मुसाफिरों की जो जेब कटी होनी है उससे रेलमंत्री राहत दिलायें. लंबे मुसाफिरों की जो तकलीफ मधु दंडवते ने सुनी थी वह रेलमंत्री ने छीन ली (5 रु. में प्रति बर्थ चाहे उस सफर में जितनी रातें लगे).

श्रीमती गांधी अपने तमाम वजीरों को रेल व कार से सफर करने को कहें. इस से सड़कें सुधर जायेंगी, बस स्टैंड सुधर जायेंगे वरना बोइंग व उनके अड्डों का ही विकास होगा. हमारे मुख्यमंत्री ने शायद ही इस महानगर का बस स्टैंड देखा होगा. —रईस लखनऊ-वाला, ई-2, रेसकोर्स रोड, इंदौर



पारकर को इंग्लैंड की सैर करायी जा सके. वयनकर्ताओं के इस प्रकार के आचरण से उमरती प्रतिभाओं और अच्छे खिलाड़ियों के उत्साह को ठेस पहुँचती है.—संजीव यादव, विधि प्रथम वर्ष, सर गंगा नाथ छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## हत्या या धोखा?

4 अप्रैल : उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई चंद्रशेखर प्रताप सिंह की हत्या जहाँ एक ओर सभी पत्र-पत्रिकाओं के लिए ज्वलंत समस्या है वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि देश के सारे राजनीतिक नेता भी शायद परिवार सहित अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

यह तो सभी समझ ही रहे हैं कि इस हत्या के पीछे गहरी राजनीति है. फिर भी प्रश्न है कि इसे हत्या की संज्ञा दी जाये या इसे धोखा माना जाये क्योंकि जहाँ दिनमान (4-10 अप्रैल) लिखता है कि श्री सिंह के मारे जाने के बाद जब श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा "हम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम शंकरगढ़ के युवराज हैं, यहाँ शिकार खेलने आये थे. गोलियाँ क्यों चलायीं?" फिर बाहर आने के बाद एक हमलावर का यह कहना, "ये तो दूसरे लोग हैं, उस साले ने बताया था कि पुलिस वाले हैं", साबित करता है कि उन की हत्या धोखे में ही हो गयी.

किंतु प्रश्न है कि जब रीवा (म. प्र.) पुलिस उस रात जगतपाल पासी की तलाश में उस जंगल में थी और आमना सामना होने पर गोली नहीं चलने का सवाल ही नहीं था, तो क्या पुलिस जंगल के मुख्य द्वार पर अन्य लोगों के प्रवेश का निषेध नहीं कर सकती थी? जब कि मुता है कि जंगल के चारों तरफ दीवार की घेरावदी भी है.

दूसरी ओर रविवार (4 अप्रैल) में संतोष भारतीय लिखते हैं कि श्री सिंह की मृत्यु के बाद जब हमलावर बाहर आये तो एक ने कहा "यही साला सी. एस. पी. सिंह है."

ये दोनों तथ्य अपने आप में विरोधाभास दर्शाते हैं.

—संजीव कुमार मिश्र, शारदा औषधालय, चतुर्भुज स्थान, मुजफ्फरपुर-842001

## भूल सुधार

11 अप्रैल : पृ. 14 तीसरे कालम पर छपे गुरजितसिंह और विजयनारायण सेठ के चित्रों के तीर्थक उलट कर छप गये हैं. कृपया पाठक सुधार कर पढ़ें—सं.



- 8 अप्रैल : ब्रिटेन द्वारा फॉकलैंड की नाकाबंदी का निश्चय.
- 9 अप्रैल : ईरान के भूतपूर्व विदेशमंत्री सादिक कुतुबजादे देशद्रोही गति-विधियों के आरोप में गिरफ्तार. बंगलादेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल. यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा आर्जेंटीना को अस्त्र देने पर प्रतिबंध.
- 10 अप्रैल : ईरान के क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला खुमेनी की हत्या का विफल प्रयास. यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा आर्जेंटीना से आयात पर प्रतिबंध. पाकिस्तान के अल्प भागों के अध्यापकों के समर्थन में सिंध में एक लाख अध्यापकों की हड़ताल.
- 11 अप्रैल : अमेरिकी विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग द्वारा फॉकलैंड से आर्जेंटीना के युद्धपोतों के हटाय जाने का दावा. दो ब्रितानी उत्तरी ध्रुव पहुँचने में सफल.
- 12 अप्रैल : भारतीय विदेश सचिव राम साठे की काठमांडौ में नेपाली नेताओं से परस्पर संबंधों पर बार्ता. जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद द्वारा सरकारी तौर पर मुख्य फौजी कानून प्रशासक का पद ग्रहण. इस्लामाबाद द्वारा फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अड़्डों पर हमला करने की योजना का बेबुनियाद बताना. सियेरा लियोन के राष्ट्रपति सियाका स्टीवंस द्वारा 20 अप्रैल को संसद का चुनाव कराने का एलान.
- 13 अप्रैल : पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक द्वारा भिलगित और हुंजा पर दावा. अलेक्जेंडर हेग द्वारा फॉकलैंड पर नया प्रस्ताव प्रस्तुत. इराक द्वारा ईरान से अपनी सेनाएँ हटाने का सुझाव.
- 14 अप्रैल : अमेरिका द्वारा तद्धान्त को अतिरिक्त कलपुर्जे देने पर चीन का विरोध. पाकिस्तान द्वारा चाशमा में 937 मेगावाट का परमाणु संयंत्र स्थापित करने का फैसला.
- 15 अप्रैल : मिश्री राष्ट्रपति अनवर सादत के हत्यारों को फाँसी पर लटकवाया जाना. बंगलादेश में भ्रष्टाचार के आरोप में छह हजार लोग गिरफ्तार. अमेरिका द्वारा इराक को परिवहन विमान बेचने का निश्चय.
- 16 अप्रैल : ईरान में कुर्दों के साथ संघर्ष में सौ से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु.

## तानाशाही आकर नहीं जाती

बंगलादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर विश्व के समाचारपत्रों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है. निकटतम पड़ोसी के नाते बंगलादेश की किसी भी राजनैतिक घटना के संदर्भ में भारत का उल्लेख स्वामाविक है. इसीलिए ब्रितानी साप्ताहिक 'गार्डियन' ने बंगलादेश पर अपनी टिप्पणी भारत से ही शुरू की. पत्र का विचार है:

"भारतीय राजनैतिक प्रणाली की कुछ भी वृष्टियाँ हों उपमहाद्वीप के देशों में उस की एक विशेषता तो है. यहाँ का निर्वाचित नेता किसी भी पश्चिमी देश की राजधानी के समारोह में बिना इस आशंका के कुछ दिन के लिए शामिल हो सकता है कि लौटने पर उस की जगह कोई सैनिक नेता उसकी जगह नहीं बैठा होगा. यह बात न तो पाकिस्तान के बारे में कही जा सकती है और न 1977 में स्थापना के बाद बंगलादेश के बारे में कोई कह सकता है. अभी पिछले दिनों ठीक उस समय जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टैचर की मौजूदगी में लंदन के भारत महोत्सव के सिलसिले में उद्घाटन की घंटियाँ बजा रही थीं, तो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल जिया उल हक ने दमनकारी, इस्लामी शासन के खिलाफ अपने यहाँ हड़तालों और प्रदर्शनों को बंद करने के लिए गिरफ्तारियों की एक नयी मुहिम शुरू कर रखी थी और उधर ढाका में सात वर्ष में पाँचवीं सैनिक क्रांति हो गयी. असैनिक राष्ट्रपति श्री अब्दुल सत्तार ने चुपचाप लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद के लिए जगह खाली कर दी और अब 200 से अधिक राजनैतिक लोग सैनिक अदालतों में अपने ऊपर मुकदमे चलने का इंतजार कर रहे हैं.

जनरल इरशाद कहते हैं कि मैंने तानाशाही कायम करने के लिए सत्ता नहीं संभाली है. संविधान सिर्फ स्थापित किया गया है रह नहीं किया गया. जैसे ही मैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दूँगा नागरिक अधिकार फिर से लोगों को सौंप दिये जायेंगे. इधर जनरल इरशाद असैनिक सलाहकारों की एक समिति बना रहे हैं और उन्होंने एक असैनिक राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कर दी है. पाँच वर्ष पहले पाकिस्तान में राष्ट्रपति जिया उल हक ने सत्ता संभालते ही घोषणा की थी कि मुल्क के हालात ठीक करने में उन्हें

90 दिन लगेंगे और फिर चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन बंगलादेश में जनरल इरशाद ने ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की है. जनरल इरशाद की नीयत पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं है. क्योंकि राष्ट्रपति जियाउर-रहमान की जब रहस्यमय ढंग से हत्या हुई थी तब जनरल इरशाद सेनाध्यक्ष थे. चाहते तो उसी समय सत्ता संभाल लेते लेकिन उन्होंने बागडोर तभी संभाली जब देश में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था काबू से बाहर हो गयी. इसलिए जनरल इरशाद की नीयत पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है. पर इस बात में संदेह जरूर है कि सब कुछ ठीक ठाक कर के, और बंगलादेश को लोकतांत्रिक सरकार सौंप कर वह खुद ही सेनाओं के साथ बैरकों को लौट जायेंगे. क्योंकि उपमहाद्वीपों में सैनिक तानाशाही इतनी आसानी से जाती नहीं है.

## खतरनाक खेल

आर्जेंटीना और फॉकलैंड का झगड़ा नाजुक दौर में पहुँच गया है. बातचीत द्वारा झगड़ा तय कराने के प्रयत्नों के समाचार बराबर आ रहे हैं. पर फ्रांसीसी पत्र लं मांद के विचार में फॉकलैंड में सेना भेजते समय आर्जेंटीना की राजधानी ब्युनिसआयर्स में जो जोश था वह अब नश्वर नहीं आ रहा है. आर्जेंटीना के नेताओं में इस समय निराशा और चिंता फैली हुई है और नेताओं और लोगों को यह चिंता सता रही है कि इस के नतीजे क्या होंगे. आर्जेंटीना के राष्ट्रपति गालतियेरी ने जिन्होंने कि समूची कार्रवाई का संचालन किया था फॉकलैंड में सेना भेजने से पहले राष्ट्रपति श्री रीगन की चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं दिया. अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बाद वह कह रहे हैं मैं ब्रिटेन से बात करने को तैयार हूँ. दूसरी तरफ आर्जेंटीना के नेता यह भी कह रहे हैं जरूरी हुआ तो हम निहत्थे लड़ेंगे. आर्जेंटीना के लोग राष्ट्रवादी भी हैं और परिवर्तनशील भी. अगर आर्जेंटीना को फॉकलैंड में मुंह की खानी पड़ती है तो लोग सैनिक सरकार पर जल्दबाजी में खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगायेंगे.

बंदूकें लोगों को नहीं मारती लोग ही लोगों को मारते हैं  
ईस्टर्न इकॉनामिस्ट रिव्यू से सामार



25 अप्रैल - 1 मई



# लड़ाई दो गैरबराबर ताकतों के बीच है

अरुणाचल प्रदेश के दौरे से हाल में लौटे जितेंद्र गुप्त की रपट

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम और मेघालय की समस्याएँ रिसते घावों की तरह बराबर समाचारों में उभरती रहती हैं। इन प्रदेशों के उत्तर में उद्वेलित पूर्वोत्तर भारत का एक टुकड़ा ऐसा भी है जो अभी तक देश के लिए सिरदर्द नहीं बना है। शांति के इस द्वीप का नाम है अरुणाचल, जिस के भीतर परिवर्तन की हलचल है, कुछ उथल पुथल भी है, लेकिन उस का स्वरूप नवोढ़ा की ऊहापोह जैसा है। ऊँचे नीचे पर्वतों की गोद में बसे अरुणाचल का क्षेत्रफल 84,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी केवल सवा छह लाख है।

हाल में केवल दो बार अरुणाचल का नाम अखबारों में उभर कर आया है। एक दफे तब जब पीकिंडू जाने वाले एक शिष्टमंडल के अरुणाचली सदस्य टी. एल. राजकुमार को, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चीन ने बीसा देने से इनकार कर दिया था। दूसरा मौका मार्च में आया जब राज्यसभा में कुछ प्रतिपक्षी सदस्यों ने अरुणाचल प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता को जबरन कटघरे में घसीटने का प्रयास किया। उन की मुख्य शिकायत थी कि अरुणाचल में ईसाई धर्मगुरुओं को जाने की अनुमति नहीं मिलती, स्थानीय ईसाइयों के प्रति अन्याय हो रहा है और वहाँ हिंदू धर्म प्रचारित किया जा रहा है।

संयोग की बात है कि दूसरे हफ्ते के शुरू में संसद में अरुणाचल का मामला उठाया गया और इसी के 4-5 दिन बाद अरुणाचल जाने का और प्रतिपक्षी नेताओं के आरोपों की जाँच खुद करने का सुयोग मिल गया। छानबीन से जो असलियत हाथ लगी उस से एक दूसरी ही तस्वीर उभरती है, जिस में चर्च की मूमिका रहस्य और षड्यंत्र से मुक्त नहीं दिखायी देती। अरुणाचल के लोग चर्च को आक्रामक गतिविधियों से आतंकित हैं। कितने? यह इस वाक्य में पूरी तरह मुखरित होता है: "यह संघर्ष दो गैरबराबर ताकतों में है और इस लड़ाई में हम हारते जा रहे हैं।" पूछा, 'क्यों?' तो बेवाक उत्तर मिला: "हमारे पास इतने साधन नहीं हैं जितने प्रतिपक्षियों के (चर्च के) पास हैं।" यह बात कड़ी और कड़वी लग सकती है, इस में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन है सही। आम आदमी की सरल मानसिकता और पारंपरिक प्रभाव में इतनी जीवनशक्ति नहीं है कि वे हमला बर्दाश्त कर सकें। पते की बात यह है



मुख्यमंत्री अपांग और उनकी बच्ची

शक्तिशाली चर्च प्रतिष्ठान अरुणाचल की सीमा के बाहर हैं जहाँ वे दशकों से जनसेवा के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी काम करते रहे हैं।

अरुणाचल के चितनशील राजनीतिकों में, प्रशासकों में ललक है कि अरुणाचल मुख्य राष्ट्रीय धारा का हिस्सा बने—नगालैंड और मिजोरम का साया उस पर न पड़े। समय के साथ परिवर्तन वे भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह धीरे धीरे कि स्थानीय निवासियों के सामाजिक मूल्यों का अस्तित्व पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में वह न जाये। उन्हें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मसीही धर्म उनके सामाजिक-राजनैतिक लोकाचार के विरुद्ध पड़ता है।

अरुणाचलियों को गिला है कि केंद्र सरकार हमारी समस्या समझ कर भी नहीं समझती



अपातानी कबीले का पुजारी (ऊपर बायें) और एक अपातानी युवती अपनी बच्ची के साथ

—मदद तो वह करती है, लेकिन औपचारिक ढंग से। युवा कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की पीड़ा है: "धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सब धर्मों का समानता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ईसाई मिशनरी हमारे धार्मिक विद्वांसों को नष्ट कर देने पर तुले हुए हैं।"

9 मार्च को राज्यसभा में धर्मनिरपेक्षता का वास्ता देते हुए निर्दलीय सांसद अलेक्जेंडर वार्जरी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये अरुणाचल को प्राप्त वैधानिक संरक्षणों पर सीधी चोट की। नगालैंड के टी. अलिबा इस्ती, कर्नाटक की श्रीमती मारग्रेट अल्वा और जनता पार्टी के संयद शहाबुद्दीन ने उन का साथ दिया।

● वार्जरी की शिकायत थी कि अरुणाचल में 20 हजार ईसाई हैं, जिन में से अधिकतर को अपने त्योहार मनाने के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि ईसाई धर्मोपदेशकों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी जाती—यहाँ तक कि (नोबेल पुरस्कार विजेता) मदर टेरेसा को भी अनुमति नहीं दी गयी। दूसरा आरोप था कि अरुणाचल में कई ईसाइयों के घर जला दिये गये हैं।

● श्रीमती अल्वा का कहना था कि एक ओर अरुणाचल में "देसी धर्म स्वाधीनता अधिनियम" में बौद्ध, वैष्णव और स्थानीय धर्मों को मान्यता दी गयी है तो दूसरी ईसाई, मुस्लिम या सिख धर्म के लोगों को ठेके भी नहीं दिये जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की संस्थाओं को



स्थानीय प्रशासन द्वारा 79 लाख रुपये की सहायता दी गयी है—आखिर हम लोगों में क्या कमी है? “क्या हम (ईसाई) धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं?”

● सैयद शहाबुद्दीन ने एक अधिक पैना तीर फेंका : अरुणाचल के आदिवासियों पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है—राज्य की सारी शक्ति इसी पर खर्च हो रही है.

● नगालैंड के अलिबा इस्ती ने कहा कि देसी धर्म विधेयक सीने में कांटे की तरह घुसा हुआ है, क्यों कि इस की वजह से अरुणाचल में आदिवासियों को हिंदू धर्म से खतरा पैदा हो गया है.

गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री एन.आर. लस्कर ने प्रस्ताव पर अपने बयान में सभी आरोपों के जवाब न देते हुए वैधानिक स्थिति का ही निरूपण किया. उन्होंने बताया कि 1873 के सीमांत नियम के तहत कोई भी गैरअरुणाचली प्रवेशपत्र लिये बिना वहाँ नहीं जा सकता. धार्मिक प्रचार करने वालों को बहुत सोच-विचार के बाद ही अनुमति दी जाती है जिस से सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष की नौबत न आये. प्रतिबंध ऐसे लोगों पर अवश्य है जो धर्मपरिवर्तन के लिए संदेहास्पद विधि अपनाते हैं. ऐसे प्रतिबंध नगालैंड और मिजोरम में भी हैं. मंत्री जी के अनुसार 1980 में 30 मिशनरियों को अरुणाचल जाने की अनुमति दी गयी; अरुणाचल के देसी धर्म स्वाधीनता अधिनियम, 1978 को सर्वोच्च न्यायालय भी वैध मान चुका है और ऐसे अधिनियम ओडिसा और मध्यप्रदेश ने भी तो बनाये हैं.

तिरप जिले के दौरे के बाद अरुणाचल की

मुख्यमंत्री नेगांग अपांग से मुलाकात हुई तब तक वस्तुस्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी थी. पासीघाट महाविद्यालय (अरुणाचल) में शिक्षित, आदि कबीले के सदस्य और नौजवान मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ “ईसाइयों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाता—सरकारी अधिकारियों द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं. हमारे यहाँ बहुत से अधिकारी ईसाई हैं, लेकिन उन्हें बराबर पदोन्नति और पुरस्कार मिलते हैं. हाँ, इतना जरूर है कि गांवों के लोगों की अपनी पंचायतें हैं जो परंपरागत कबाइली समाज की स्वामाविक अंग हैं. ये ग्राम पंचायतें लोगों में नैतिक और सामाजिक अनुशासन लागू करती हैं. जो अपराध करते हैं या कबीले के रीतिरिवाजों का विरोध करते हैं उन्हें पंचायत समझाती बुझाती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दंडित भी करती हैं. जब चर्च द्वारा दीक्षित युवक विद्रोहस्वरूप पूजा के दिन खेत पर जाते हैं, और रविवार को खेत पर नहीं जाते तो गाँव बूझा (गाँव का मुखिया) कभी कभी उन के खिलाफ कार्रवाई करता है. मैंने भी सुना है कि ऐसे विद्रोही युवकों की झोंपड़ी एक दो जगह नष्ट कर दी गयी है.” (कबाइली पंचायतें काफी मामले खुद निपटा लेती है. अदालत में जाने की नौबत बहुत कम आती है).

रामकृष्ण मिशन के बारे में उन का कहना था कि “यह पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संगठन है, जिसे हम विद्यालय और औषधालय चलाने के लिए अनुदान देते हैं. रामकृष्ण मिशन को चर्च या किसी अन्य धार्मिक संगठन के समकक्ष रखना भ्रामक प्रचार का हिस्सा है.” मुख्यमंत्री के

अनुसार अरुणाचल में मुस्लिम या सिख धर्म अनुयायी नहीं हैं, इसलिए उन के प्रति भेदभाव का सवाल ही नहीं है. हमारे विरोधियों का यह कहना बेमानी है कि पेड़ काटने या अन्य कामों के ठेके देने में धार्मिक भेदभाव बरता जाता है. अरुणाचल में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार तथा उद्योग के लाइसेंस और ठेके केवल स्थानीय लोगों को ही दिये जाते हैं.”

मदर टेरेसा ने मुख्यमंत्री की जानकारी में अरुणाचल आने की अनुमति कमी नहीं मंगी. उन का कहना है कि यदि कोई मिशनरी यहाँ धर्म प्रचार के लिए या अपने सहर्षमियों से मिलने आना चाहता है तो हम उसके आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं.

कामेंग, उत्तर सियांग और लोहित में बौद्ध आदिवासी हैं और कुछ कबीलों पर वैष्णव धर्म का प्रभाव है. इसलिए विधेयक में उन्हें भी देसी माना गया है.

अरुणाचल से बाहर स्थित चर्चों और मसीही प्रचारकों से ये लोग क्यों भयभीत हैं? इस के ऐतिहासिक, व्यावहारिक और मनो-वैज्ञानिक कारण हैं. 1947 के पहले पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में गोरे मिशनरी ही पहुँचते थे—वही आदिवासियों की चिकित्सा और शिक्षा का प्रबंध करते थे. इसलिए आज भी इस क्षेत्र में गोरे मिशनरियों की बहुत इज्जत है.

अनेक दशकों में मेहनत से बनायी गयी इस साख का फायदा ईसाई मिशनरियों ने भरपूर उठाया. इस भूभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में आज 100 लोगों के पीछे 51 ईसाई बन चुके हैं. असम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और केंद्रशासित प्रदेश—मिजोरम तथा अरुणाचल में 1961 और 1971 के बीच ईसाइयों की आबादी में 67.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जब कि उन का सार्वदेशिक औसत 32.6 रहा.

1947 के बाद अरुणाचल को धर्म परिवर्तन अभियान का लक्ष्य बनाया गया और ब्रह्मपुत्र के उत्तर में, जहाँ असमि चाय बागानों के गरीब मजदूर रहते हैं, चर्चें बनायीं गयीं और विद्यालय खोले गये. डिब्रूगढ़, हरमुती, लिखाबली और घिमाजी उन के प्रमुख केंद्र हैं. 1951 में अरुणाचल में एक भी ईसाई नहीं था, लेकिन अरुणाचली अधिकारियों के अनुसार आज उस की संख्या 10-15 हजार के आसपास है. चर्च की घुसपैठ से चिंतित हो कर 1969 में केंद्र तत्कालीन नेफा की एजेंसी काउंसिल ने केंद्र से विधिवत अनुरोध किया था कि आदिवासियों के धार्मिक विश्वासों और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाये जायें. 1976 में अंचल समितियों के 2000 सदस्यों ने भी जिस में पूरे प्रदेश से विभिन्न कबीलों के लोग थे, केंद्र से यही अनुरोध किया. प्रथम निर्वाचित विधानसभा ने पहले अधिवेशन में ही इसी

## अरुणाचल प्रदेश





या सिख धर्म उन के प्रति हमारे विरोधियों ने पेड़ काटने, धार्मिक मेदभाव आदिवासियों और तथा उद्योग स्थानीय लोगों को जानकारी में भी नहीं मानी। मिशनरी यहां सहर्षमियों से उसके आवेदन करते हैं। ओहित में वेद्यों पर वैष्णव धेयक में उन्हें

चर्चों और क्यों भयभीत रिक और मनो-पहले पूर्वोत्तर रे मिशनरी ही की चिकित्सा इसलिए आर्यों की बहुत

नायी गयी इस रियों ने भरपूर क्षेत्रों में आज ई बन चुके हैं। पुरा, मेघालय म तथा अरुणा-बीच ईसाइयों की वृद्धि हुई है, तो 32.6 रहा। धर्म परिवर्तन और ब्रह्मपुत्र गानों के गरीबों और विद्या-नी, लिखाबनी हैं। 1951 में ही था, लेकिन सार आज उन सपास है। चर्च 1969 में ही उंसिल ने केंद्र ग कि आदि र संस्कृति की जायें। 1978 सदस्यों ने भी बीलों के लोग धर्म निर्वाचन में ही इसी

आशय का संकल्प किया। अंततः 'अरुणाचल प्रदेश देसी धर्म स्वाधीनता विधेयक' 1978 में पारित हुआ जिस के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत के मिशनरियों ने जबर्दस्त आंदोलन चलाया कि राष्ट्रपति इसे मंजूरी न दें। बावेल मचाने वालों में चर्च समर्थक सांसद, नगालैंड की रानो शैजा और मेघालय के विधानसभाई थे। नगालैंड विधानसभा ने तो विधेयक के विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित कर डाला।

अरुणाचल देसी धर्म स्वाधीनता विधेयक में 'बल, धोखे, लालच और दबाव से धर्म परिवर्तन' के निषेध का विरोध अकारण नहीं था। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुगूज थी।

असम की चर्चों के अधिकारी अरुणाचल में धर्म परिवर्तन के लिए स्थानीय ईसाइयों को



शारदा मिशन स्कूल की बालिकाएँ

अपने प्रचार का माध्यम बनाते हैं। ऐसे प्रचारकों को 300 से लेकर 1500 रुपया प्रति-मास वेतन मिलता है और अन्य खर्च अलग से। ये लोग गरीब आदिवासियों से मिलते हैं, उन्हें अमेरिकी चावल, ट्रांजिस्टर और नकदी देते हैं और प्रचारित करते हैं कि ईसा की शरण में जाने पर भौतिक उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। तर्क होता है कि चांद पर आदमी भेजने वाले ईसा के अनुयायी हैं। ईसा की कृपा से इन लोगों के पास अकूत धन, विद्या और विज्ञान, सभी कुछ है। कबाइली विश्वास और रीति-रिवाज गुजरे जमाने की चीजें हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अच्छी नौकरी का लालच और तात्कालिक लाभ—नकद रकम, फैशनबुल कपड़े, आधुनिक उपकरण—का मोह गरीब लोगों के लिए प्रबल आकर्षण सिद्ध होते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे असम और मेघालय के मिशनरी स्कूलों में भर्ती करा दिये जाते हैं। जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते या जो स्कूल छोड़ बैठे हैं वे ईसाई बन कर आदिवासी समाज में विद्रोही की भूमिका निभाते हैं। गुहरे घमजाल का तानाबाना बुनने वाली लोगों की आर्थिक शक्ति के सामने अरुणाचली समाज साधनहीन ही माना जायेगा। एक बार

पूर्वोत्तर भारत के ईसाई मिशनरियों को विदेशों से 1976-77 में 24 करोड़ रु. नकद प्राप्त हुए थे, और 1978-79 में 17 करोड़ रु.।

धर्मपरिवर्तन का लक्ष्य क्या केवल सांस्कृतिक विजय के लिए है? 'नहीं'— एक अरुणाचली का कहना है—“वे दक्षिण से ले कर अंतरराष्ट्रीय सीमांत तक मसीही पट्टी तैयार करना चाहते हैं, जिस से कि पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को बर्मा और तिब्बत जाने के नये रास्ते मिलें। एक दो बार नगा तिरप हो कर बर्मा आये-गये हैं। इस क्षेत्र के वांचू और नोकटे कबीले नगा जाति के ही हैं। धर्मपरिवर्तन से यह नातेदारी और गहरी हो जायेगी। चर्च की निगाह लोअर सुबनसिरी जिले पर भी है।”

अरुणाचल सरकार ने चर्च की चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यतः शिक्षा का रास्ता अपनाया है। अधिक से अधिक विद्यालय खोले जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। अनेक स्कूलों के साथ छात्रावास भी हैं जहाँ रहने, खाने, कपड़े लत्ते और किताबों का खर्च छात्र के माता पिता को नहीं देना पड़ता। यदि विद्यालय रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद केंद्र का है तो सरकार प्रति छात्र एक निश्चित रकम अनुदान के रूप में देती है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद केंद्र को आमंत्रित और प्रोत्साहित करने का कारण है कि ये धर्म-निरपेक्ष संगठन हैं जो बच्चों को सिखाते हैं कि 'मैं भारतीय हूँ। भारत मेरा देश है।' इन में सभी धर्मों की जानकारी दी जाती है।

अरुणाचल में दो कालेज और 1091 विद्यालय हैं। इन में रामकृष्ण मिशन के दो बाल माध्यमिक विद्यालय हैं—आलोंग और देवमाली में। खोंसा में बालिकाओं के लिए शारदा मिशन का एक माध्यमिक विद्यालय है। विवेकानंद केंद्र के 13 विद्यालय हैं। कुल 19,000 छात्रों में से लगभग 7000 छात्रावासों में रहते हैं जिन का पूरा खर्चा सरकार और संचालक उठाते हैं। अरुणाचलियों के धार्मिक विश्वास अलग अलग हैं, किंतु वे सभी डोनी (सूर्य) को माँ और पोली (चंद्रमा) को पिता मानते हैं। 'डोनी पोली मिशन' नाम से एक नयी संस्था बनी है, जिसने प्रदेश की राजधानी इटानगर में इसी वर्ष एक विद्यालय खोला है। मुख्यमंत्री के संरक्षकत्व में यह विद्यालय 'विद्याभवन' भी यही लक्ष्य ले कर चल रहा है कि यहाँ के छात्र भारत देश के जिम्मेदार नागरिक बनें।

नगालैंड और मिजोरम में, जहाँ लगभग सभी लोग ईसाई धर्म के अनुयायी बन चुके हैं, पृथकतावादी प्रवृत्तियों से सभी परिचित हैं। लेकिन मणिपुर भी जहाँ वैष्णव मेइती बहु-संख्यक हैं, उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। इसलिए केंद्र को अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर की समस्याओं की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। □

निधन

## ‘मैं कोई बेवकूफ नहीं जो चुनाव लड़ूँ’

पंडित परमानंद ने पंडित जवाहर लाल नेहरू से कहा था

भारत की आजादी के लिए पंडित परमानंद अपनी जान दाव पर लगा कर सदा लड़े मगर देश आजाद हो गया तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आदि के लिए चुनाव लड़ने के लिए वह कभी तैयार नहीं हुए। एक समय फांसी की रस्सी के उम्मीदवार, काले पानी के निवासी थे पंडित परमानंद झांसी। अंग्रेज के शासन के विरुद्ध शस्त्र-अस्त्र सहित देश और विदेश की घरती पर भी सदा लड़ने मरने को तैयार थे। देश आजाद हुआ तो उन्होंने सत्ता के लोभ के सामने कभी हथियार नहीं डाले। मगर 13 अप्रैल को 93 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हस्पताल में मौत के सामने हथियार डालने पड़े। गदर पार्टी के जन्मदाताओं में से एक थे पंडित जी। बैशाखी के दिन, जो उत्तर भारत में शहीदों का दिन माना जाता है, उन का देहांत हुआ। यह भी एक विचित्र संयोग है कि 1914 में बैशाखी के दिन ही ब्रितानी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनायी थी लेकिन सिद्ध यही हुआ कि वर्ष तय करना उसके हाथ में न था। वैसे क्रांतिकारी की यात्रा के अंत का तो यह ठीक ही दिन था।

## उन की कहानी उन की जुबानी

याद आ गयी एक और दिन की बात जो साल भर भी पुरानी नहीं। तारीख थी 26 मई 1981। जवाहरलाल नेहरू की बरसी से संबंधित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आये थे 'पंडित झांसी'। साथ उन के थे एक और बूढ़े शेर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी श्री रामचंद्र। पंजाब के भूत-पूर्व मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन और बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ अन्य क्रांतिकारी भी उपस्थित थे। स्थान था तीनमूर्ति भवन और प्रदर्शनी का शीर्षक था 'क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 1931 तक'। सादे मगर उज्ज्वल सफेद वस्त्रों में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर जैसी लंबी दूधिया दाढ़ी वाले पंडित परमानंद झांसी कवि अधिक क्रांतिकारी कम दिखायी दे रहे थे—जब तक मौन थे। बोलने लगे तो शब्दों की ललकार में शरीर के बुढ़ापे की झलक मात्र न थी। बानवे वर्ष के ब्रह्मचारी ने कुछ अपनी, कुछ नेहरू की और कुछ उस क्रांति की कहानी सुनायी जिस में 'लाहौर षडयंत्र' के उन के 40 साथियों से से 7 को फांसी हुई और शेष उन के साथ 'कालेपानी' पहुँचे।



उन्होंने कहा 'जो जवाहरलाल ने इस देश के लिए 25 वर्षों में किया उस की मिसाल सारे संसार के इतिहास में नहीं मिलती। यह तीन-मूर्ति भवन तो भारतीय क्रांति का मंदिर है और नेहरू की स्मृतियों ने इस की पवित्रता को और बढ़ा दिया है.'

फिर उन्होंने ही लोकसभा के पहले ही चुनाव के बाद नेहरू से अपनी एक भेंट की बात सुनायी। उन का कहना था कि नेहरू के जीवन-काल में उन के लिये तीनमूर्ति भवन के द्वार सदा खुले रहते थे जब मन चाहता था पंडित झांसी नेहरू से मिलने चले आते थे। उस भेंट में दोनों के बीच वार्तालाप यों हुआ :



दलाई लामा

**पंडित परमानंद :**

पिता : गया प्रसाद,  
माता : शकुनाबाई.  
जन्म 1887 सिकरोधा,  
हमीरपुर (उ. प्र.).  
काशी, प्रयाग, झांसी,  
कानपुर, गया, पटना,  
कलकत्ता, मद्रास,

बंबई, गुजरात, लाहौर और विदेशों में  
में—पेशावर, सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका  
में क्रांति का बिगुल बजाते रहे। अपने क्रांति-  
कारी जीवन में पंडित परमानंद को स्वामी  
श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा  
गांधी, लाल लाजपत राय, गोपालकृष्ण  
गोखले, पं. सुंदरलाल, गणेश शंकर  
विद्यार्थी, वीर सावरकर, मानवेंद्रनाथराय,  
लाला हरदयाल, भाई परमानंद,  
सरदार पटेल के साथ रहने और कार्य  
करने का अवसर मिला। साहित्यमंडली  
से बाबू श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद,  
निराला, मुंशी प्रेमचंद, जगन्नाथ दास  
रत्नाकर, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी  
वर्मा आदि से संपर्क रहा। रायदेवी प्रसाद  
'पूर्ण' के व्यक्तित्व और कृतित्व से भी  
प्रभावित हुए।

अपने जीवन काल में लगभग 45 हजार  
पुस्तकों का अध्ययन किया था। इन के  
पांडित्य को देख कर ही मित्रमंडली इन्हें  
पंडित कहने लगी थी। वैज्ञानिक विषयों  
का भी अच्छा ज्ञान था।

विद्वता का सम्मान करते हुए ही  
कानपुर विश्वविद्यालय ने डी. लिट एवं  
गोरखपुर विश्वविद्यालय ने राजपि की  
उपाधि से सम्मानित किया।

पंडित नेहरू : 'भाई, आप लोकसभा के लिए  
चुनाव क्यों नहीं लड़ते? पंडित झांसी : मैं कोई  
बेवकूफ नहीं कि चुनाव लड़ूँ। पंडित नेहरू :  
'आप समझते हैं हम जो इतने लोग चुनाव लड़  
कर संसद में आ गये हैं सब बेवकूफ हैं?'  
पंडित झांसी : 'अच्छा आप ही बताइये यदि  
कोई सैकड़ों मूढ़ अज्ञानियों के वोट ले कर चुना  
जाये तो क्या खुद बहुत बड़ा मूख नहीं होगा?'

दिनमान

□ लड़ाई न करने की संधि का पाकिस्तान का प्रस्ताव न मान कर  
भारत वहीं गलती कर रहा है जो पाकिस्तान ने अब से 29 वर्ष पहले  
की थी।

—राष्ट्रपति जियाउल हक नवाए वक्त के हवाले से।

□ भारत और तिब्बत की मित्रता वास्तव में आधुनिक, आर्थिक  
अथवा राजनैतिक नहीं है। यह प्राचीन और आध्यात्मिक है। भारत  
तिब्बत को देवस्थान मानता है जिस के लिए हम भारत के आभारी हैं।

—चंडीगढ़ में दलाई लामा।

□ मैं समझता हूँ प्रथम श्रेणी बराए नाम है, कुछ अधिक पैसा दे कर  
थोड़ी सी ज्यादा जगह मिल जाती है। मैंने जीवन में कभी इतनी गंदी रेल  
यात्रा नहीं की। कलकत्ता से बंबई तक की 44 घंटे की यात्रा में कहीं कुछ  
ओढ़ने बिछाने को नहीं, न किचन कार. बंबई पहुँच कर जब हम ने  
लांडरी को अपने कपड़े दिये तो उस से माफ़ी माँगनी पड़ी कि इतने गंदे  
कपड़े हम धुलने दे रहे हैं।

—साक्ससेसे पी एडवर्ड हंटर जो भारत पर्यटन के लिए आये थे।

□ विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। मेरे प्रधानमंत्री बनने के  
बाद से ही ब्रितानी प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री का स्वागत करने  
के लिए लंदन हवाई अड्डे पर आना शुरू किया। भारत को आज  
सोवियत संघ से जो कुछ मिल रहा है उस का प्रस्ताव सोवियत संघ ने  
मेरे प्रधानमंत्री काल में ही किया था।

—भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई, विरोधी दलों के  
चंडीगढ़ सम्मेलन के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा में

□ भारत ही एक ऐसा देश है जिस के नेता शासन में रहने का अधिकार  
खो चुके हैं पर साथ ही लोगों में बगावत करने की हिम्मत भी नहीं रह  
गयी है। आज यहाँ क्रांति की सब से अधिक जरूरत है। हमारा मकसद  
सरकार को उलटना नहीं है। अगर हम सरकार बदल भी देते हैं तो  
विरासत में हमें यह सड़ा गला ढाँचा ही मिलेगा और हमें अपने आप को  
उस के मुताबिक ही ढालना होगा।

—नयी दिल्ली के एक संसद सदस्य के घर पर कुछ लोगों को  
बंधक बनाने वाले रामनारायण कुमार और कुमार स्वामी  
का इशतहार जो उन्होंने खिड़की से फेंका था। शीर्षक था  
'हिंसा एक ऐतिहासिक आवश्यकता'।

□ यह कंसी विडंबना है कि पिछले तीस वर्षों में भारतीय टेलीफोन  
उद्योग ऐसा टेलीफोन उपकरण भी विकसित नहीं कर सका जिसे पूर्ण  
कहा जा सके।

—सार्वजनिक उद्योग लेखा समिति की टेलीफोन सेवाओं  
पर रपट।

□ चंडीगढ़ सम्मेलन (तीन विरोधी दलों का एकता प्रयास) ने इका  
कांग्रेस को और संगठित तथा सुदृढ़ बना दिया है। उम्मीद है कि मई के  
राज्य विधानसभा चुनावों में इका को 90 में से 70 जगहें मिल जायेंगी।

—श्री भजनलाल, मुख्यमंत्री, हरयाणा, नयी दिल्ली के  
संवाददाता सम्मेलन में।

□ अमेरिका में हिंसा और अपराध रोकने के लिए बंदूक रखने संबंधी  
कानूनों को सख्त बनाने के बजाय अपराधों को लंबी सजा देने का कानून  
बनाना ज्यादा कारगर होगा।

—राष्ट्रपति रीगन, इलियोनोस में स्कूली बच्चों के समारोह  
में भाषण करते हुए।



## यह सवाल कौन सी अदालत तय करेगी?

एक खबर

‘संथाल परगना जो आदिवासी जिला है उस के माधोपुर खंड के 523 गांवों में एक लाख निवासियों में से कोई 80 प्रतिशत लोग आधी भुखमरी की स्थिति में हैं। यह बात सभी अधिकारियों को मालूम है जिन्हें इस से निपटने के लिए अधिकार और साधन दोनों ही उपलब्ध हैं। अपनी मुसीबतों से घबराकर इन में से कुछ मर्द और औरतें इस भुखमरी की हालत और फटेहाली में पिछले दिनों शहर पटना में इस आशा में चले आये कि उन मंत्रियों द्वारा उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा जो रात दिन इस की शपथ खाते रहते हैं। उन्होंने ईस्टर्न न्यूज सर्विस के संवाददाता को बताया कि उन्हें 25 मार्च को मुख्यमंत्री के निवास से भगा दिया गया। इस क्षेत्र में बरसात कम होने से कम जमीन वाले या नाम भर को जमीन वाले या भूमिहीन खेतिहर सभी पिछले नवंबर से सहायता की फरियाद लिए घूम रहे हैं।’

दूसरी खबर

‘पौष्टिक कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजनों और आदिवासियों में मुफ्त बांटने के लिए तीन साल पहले खरीदी गयी अरहर की दाल पटना के राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में सड़ रही है। सूत्रों का कहना है कि निगम के गोदामों में 1137 मीट्रिक टन दाल सड़ रही है। जिसे 1979 में कल्याण विभाग ने खरीदा था। इस समय बाजार भाव में यह दाल 55 लाख रुपये के आसपास पड़ती है। सूत्रों का कहना है कि निगम का काम खाली दाल को सेंभालने का था, कल्याण विभाग को ही उसे वहाँ से उठाना और हरिजन और आदिवासियों में उसे खिचड़ी के रूप में वितरण करना था। बार बार कहने पर भी कल्याण विभाग ने दाल नहीं उठायी... दाल अब आदमी के खाने लायक नहीं रह गयी है।’

ये दोनों खबरें राजधानी से प्रकाशित होने वाले एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक पत्र में एक ही पृष्ठ पर ऊपर नीचे मोटी मोटी सुखियों में काफी विस्तार से छपी हैं। इन्हें पढ़ कर यदि सत्ताधारियों का विवेक नहीं जागता, बिहार सरकार के कान पर जूँ नहीं रेंगती और आम नागरिक को गुस्सा नहीं आता तो समझ लेना चाहिए कि हम सड़ांध के उस मुकाम पर पहुँच गये हैं जहाँ इस समाज के नष्ट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस हद तक उदासीनता कि एक ओर आदमी भूख मर रहे हों और दूसरी ओर अनाज सड़ रहा हो किस तरह की व्यवस्था का चरित्र सामने लाता है? यदि यह वर्तमान की कथा न हो



और आपने इसे इतिहास के पन्नों में पढ़ा होता तो उस काल को आप क्या कहते? यही न कि वह ‘सत्तामदांध मुख, जनशत्रु राजा का कॉल था जिस के कर्मचारी निकम्मे, आलसी और कामचोर थे। राजा और उस के अधिकारी सब अपने ऐश्वर्य और विलास में डूबे रहते थे जब कि जनता त्राहि त्राहि कर रही थी।’ लेकिन यह इतिहास की घटना नहीं है। यह वर्तमान की स्थिति है। यह राजतंत्र भी नहीं है लोकतंत्र है जिसे जनता की सरकार कहते हैं। और सत्ता में वे लोग हैं जो इस दावे से आये हैं कि वे ‘सरकार चला सकते हैं’ इस तरह चलती हैं सरकारें? यदि कोई जीवित समाज जीवित व्यवस्था होती तो प्रदेश सरकार को इसी बात पर इस्तीफा देने को मजबूर कर देती—सरकार का तब्ला उलट जाता। लेकिन यह मिलावटी दवाओं, सड़े हुए अनाज, भूसा और लोड खिलाने वालों की सरकार है और हम उन मरियल भूखे चौपायों की तरह सड़कों पर घूमते हैं और मंत्रियों के उद्यान में हरी खास देख घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ से मार कर निकाल दिया जाना हमारी नियति है।

कौन पूछेगा, किस से पूछेगा, कब पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ओर आदमी भूखों मर रहा है दूसरी ओर अनाज सड़ रहा है, यदि यह सड़ रहा अनाज भूखा मरता आदमी लूट कर खा ले तो यह गैरकानूनी क्यों है? वह राजद्रोही क्यों कहलाया जाये? भूखा मारने, अनाज सड़ाने वाले लोग राजद्रोही क्यों नहीं हैं, गैरकानूनी आचरण करने वाले क्यों नहीं कहे जाते? यह सवाल कौन पूछेगा? क्या अनाज लूटना ही गैरकानूनी है? अनाज सड़ाना गैरकानूनी नहीं है? यह सवाल कौन सी अदालत तय करेगी? कब तय करेगी? □

फिर दोनों खिलखिला कर हँस दिये।

पंडित परमानंद और रामचंद्र दोनों ने ही कहा ‘जिस क्रांति के लिए हम लोगों ने जान की बाजी लगायी और जिस में हमारे कई बहादुर साथी खेत रहे, अभी अधूरी है। हम चाहते थे आजादी और समाजवाद। अंग्रेज की गुलामी से तो छुटकारा मिल गया मगर देश की जनता को अभी भूख, प्यास और बेकारी से छुटकारा पाना है।’

फिर पंडित झांसी ने कुछ अपनी कहानी सुनायी : ‘मैं 1905 में इलाहाबाद में था। जवाहरलाल नेहरू और मैं सहपाठी थे। मुझे ‘रस्तीकेट’ कर निकाल दिया गया। फिर मैं पंडित मदनमोहन मालवीय के पास गया। उन्होंने ही अपने यहाँ मेरे रहने-सहने का प्रबंध किया। तब मैं उस समय के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री शिवप्रसाद गुप्त के साथ जापान चला गया और वहाँ से अमेरिका, जहाँ मैं गदर पार्टी में भरती हुआ। सन् 1914 में हम लगभग 6000 क्रांतिकारी थे जो भारत की 26

सैनिक छावनियों में फैल गये। बगावत का झंडा उठाये। हमारा आंदोलन दबा दिया गया। हम पर विशेष अदालतों में मुकद्दमे चलाये गये जहाँ सच्चा मिनटों में दी जाती थी। इन्हें ‘समरी कोर्ट’ कहते थे। हमें 27 लोग जिन्हें फाँसी की सजा हुई सात सूली पर चढ़े। बाकी कालेपानी के कारागार में अंदमान द्वीप भेज दिये गये। कालेपानी में हमारे साथ भाई परमानंद और वीर सावरकर भी थे। मैंने अगले 34 साल कालेपानी के कारागार में कटे।

पंडित परमानंद ने कहा ‘हमारी भारतीय क्रांति एक महान क्रांति थी। कम से कम खून बहा और सब ने अपना अपना योगदान किया इस क्रांति में। जो लोग किसी एक या अन्य व्यक्ति की कुर्बानियों को बहुत महान सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं वे सच्चे क्रांतिकारी नहीं।’

पंडित परमानंद झांसी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि दी तो कहा ‘साहस और देशप्रेम में वह अद्वितीय थे।’ गृहमंत्री जैल सिंह, प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल के नेता और कई अन्य नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें आदर से मस्तक नवाया। कुछ राजनीतिकों ने मांग की कि उस महान क्रांतिकारी के लिए जिस ने कभी सत्ता और सरकार से संबंध स्वीकार नहीं किया था ‘सरकारी सम्मान सहित शवयात्रा का प्रबंध किया जाये’ घोषित हुआ कि 5000 रुपये उन का स्मारक बनाने के लिए दिया जायेगा और उन की एक गोद ली पुत्री को पेंशन मिलेगी। मगर पंडित परमानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के अधिकारी तो शायद वही लोग हैं जो क्रांतिकारी के अंधरे स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लें, उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करें। यानी लड़ाई भूख, प्यास और बेकारी के खिलाफ, पूरी मानवता के साथ। □



## ‘बेगन बेलिया’ का मेला

पिछले दिनों सैकड़ों दिल्ली निवासियों ने देखा एक अनुपम फूल के फूलों का मेला। निजा-मुद्दीन में हुमायूँ के मकबरे के सामने राष्ट्रीय बेगन बेलिया समिति ने यह दो दिन का मेला सरकारी सुंदर नरसरी में संयोजित किया था। उस में कम से कम 100 विभिन्न आकारों, प्रकारों और रंगों के बेलों की बहार थी। लाल, गुलाबी, पीली, उन्नाबी, सुनहली, रूप-हली, दूधिया और सीपिया—लगभग प्रत्येक प्रकार की बेगन बेलियों ने अपना सौंदर्य प्रदर्शन किया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बेल ऐसी है कि सुखे में भी फलती और फूलती है और इसी लिए देशभर में लोकप्रिय होती जा रही है। जोधपुर, उदयपुर आदि रेत और पथरीली पहाड़ियों से घिरे राजस्थानी नगरों के प्रवेश मार्गों पर भी बेगन बेलियों के फूल खिलते हैं आजकल। यह बात अलग है कि इस लोकप्रिय लता को हम खालिस स्वदेशी सुमन सुंदरी नहीं कह सकते। इस का जन्म हुआ था दक्षिणी अमेरिका में अठारहवीं शताब्दी में। एक फ्रांसीसी नाविक कप्तान लुई ब्रुगेनवील साहिब इस लता को वहाँ से ले आये और ला जमाया। रुम सागर के क्षेत्रीय देशों में तभी से उस का नाम ब्रुगेनवीलिया और भारत में आने पर बेगन बेलिया पड़ गया।

भारत में कौन और कब लाया इस विचित्र लता को इस के बारे में ठीक ठीक तो विशेषज्ञ भी कुछ कहने को तैयार नहीं, मगर इस के बारे में कुछ सत्य ऐसे हैं जिन से किसी को इनकार नहीं। यह बेल हर प्रकार की कष्ट देने वाली धरती में भी जड़ पकड़ लेती है। धूप, आंधी और तूफान का डट कर सामना करती है, इस में चुमने वाले काँटे भी उतने ही होते हैं, जितने रंग बिरंगे, कागजों जैसी नाजुक पत्तियों वाले फूल और सुगंध नहीं होती। भीनी भीनी दुर्गंध होती है। एक साहिब का कहना है—बस इस लता का चेहरा और चरित्र ठीक आज की राजधानी के जीवन का सही आईना है।

## चौधरी साहब की वापसी

सन् 1969 में उन्होंने वैंगस रेस्तरां में दिल्ली की जनता और स्थानीय राजनीति से अवकाश प्राप्त किया था। अब 1982 में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उन्होंने घोषणा की—‘अब मैं दिल्ली की राजनीति में पुनः प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं लौट आया हूँ’। नहीं, अपना इशारा लोकदल के नेता चौधरी चरणसिंह की ओर



नहीं दिल्ली के एक समय के लौह पुरुष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री—जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे—चौधरी ब्रह्मप्रकाश की ओर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी साहेब की दो पुरानी राजनीतिक संगिनियाँ कुमारी शांता वशिष्ठ और श्रीमती सुमद्रा जोशी भी उपस्थित थीं। चौधरी साहेब ने बताया कि पहले तो उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र का फैसला किया था, फिर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में आ कर बिहार चले गये, तब की संपूर्ण क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। परिणाम यह कि अब बिहार के लोग मुझे दिल्ली के लोगों से अधिक जानते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले 30 साल के बाद पहली बार उन्होंने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की पदयात्रा की। पहले वह मोटर गाड़ी में दोरे करते थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पैदल चल कर ही उन्हें भागती हुई महंगाई और गाँव के दरिद्र नारायण के दुःख और पीड़ा का ज्ञान हुआ।

यह भी आभास हुआ कि इलाज उन की बीमारी का केवल ‘कांग्रेस’ के पास है—शरद पवार वाली, जिस की दिल्ली प्रदेश कमेटी के चौधरी साहब अब स्वयं अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया—‘अब हम सहविचारी व्यक्तियों को संगठित कर रहे हैं। सुना गया है कि इस सिलसिले में चौधरी साहेब ने अपने दल के दस बारह नेताओं की एक बैठक दिल्ली में बुलायी थी। ऐसा माना गया है कि उन के कुछ मित्र कुछ दलों के विलय की चुन में भी हैं, जिन में श्री देवराज अंस और अंबिका सोनी आदि की सहानुभूति है। सहकारी दलों में उन के कुछ साथी कांग्रेस ‘जे’, लोकदल तथा बहुगुणा जी के दल को भी मानते हैं। जब उन्होंने यह सब कुछ बताया तो कोई नहीं जानता था कि राजनीतिक विलय का ऊँट कौन सी करवट लेगा।

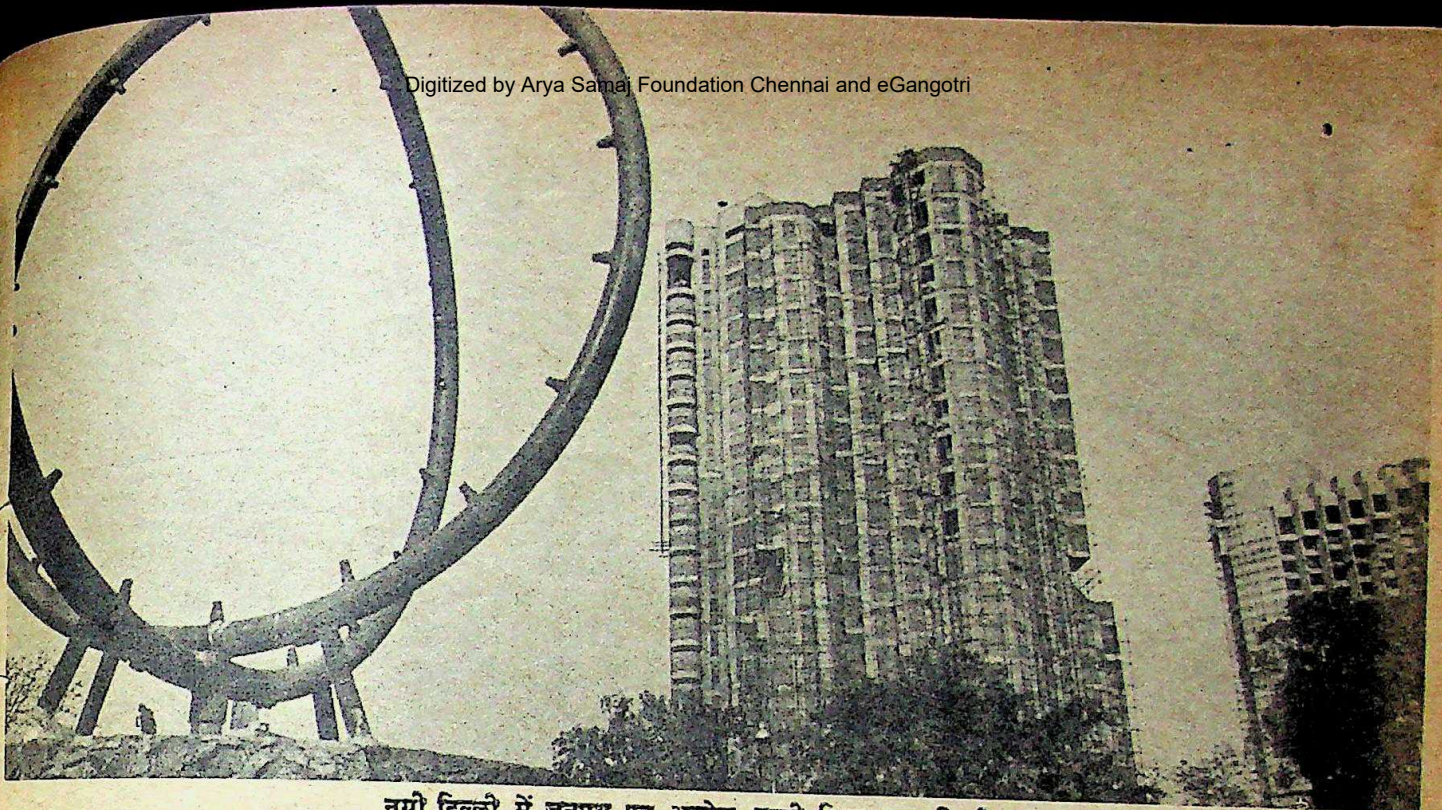
## फलाई-ओवर युग

कम से कम निर्माण के एक क्षेत्र में दिल्ली वालों की आशाएँ हाल ही के सरकारी औपचारिक और अनौपचारिक संकेतों से बंधने का प्रयत्न किया जा रहा है। एशियाई खेलों की समिति के अध्यक्ष सरदार बूटासिंह जी प्रगति मैदान में अपने एक मित्र से यह कहते सुने गये थे कि अप्रैल के अंत से राजधानी में एक अनुपम उद्घाटन लहर चलने वाली है। सब से पहले तो एक के बाद एक ‘फलाई ओवर’ उद्घाटित होंगे। सरदार बूटासिंह की विश्वास है कि जून के अंत तक एशियाई खेलों से संबंधित अधिकतम निर्माण कार्य लगभग पूरे जायेंगे।

ऐसा जान पड़ा है कि प्रबंधकों ने खेलों के दौरान बहुत से नये नये एशियाई खेल तोहफे यानी ‘सोविनियर’ भी बनवाने का फैसला किया है ताकि भारतीय और विदेशी खेल प्रेमी देखने आयें तो अपने साथ याद के लिए कुछ तोहफे ले जायें।

मगर जनसाधारण को कुछ बातें परेशान भी कर रही हैं। हालांकि खेल कर्मचारियों ने कई बार यह घोषणा की है कि एशियाई खेलों के लिए पधारने वाले अतिथियों के खाने पीने के लिए अन्न, चीनी आदि का पृथक् प्रबंध किया जा रहा है और दिल्ली के खाद्य पदार्थ कोटे पर उन का बोझ नहीं डाला जायेगा। दिल्ली के मुनाफाखोरों को कौन समझाये। साल ही में एक स्त्री बाजार में डिब्बेबंद मक्खन और पनीर खरीदने गयी तो दुकानदार ने उसे सलाह दी ‘आप कुछ स्टॉक कर लीजिए। ये चीजें अब बाजार में मिलेंगी नहीं। हम लोग इन्हें एशियाई खेलों के लिए स्टॉक कर रहे हैं’।





नयी दिल्ली में जनपथ पर अशोक यात्री विहार का निर्माण

## आवरण कथा

भारतीय पर्यटन विकास निगम

# एशियाड के बाद होटलों के सात हजार कमरों का क्या होगा ?

सांस्कृतिक क्षेत्र पर सब की नजरें गड़ी होती है और अक्सर ही उसे सारी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह बात सब से अधिक भारत पर्यटन विकास निगम के संबंध में चरितार्थ होती है, जो हमेशा अखबार की सुखियों में स्थान पा जाता है—चाहे वह रानी दुबे द्वारा अशोक होटल के लगभग एक लाख रुपये के बिलों का पूरा भुगतान न किये जाने की बात हो या किन्हीं असामान्य नियुक्तियों की खबर हो।

भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणादायक संस्थान के रूप में की गयी थी, जिस के लिए यह निगम प्रशंसा का पात्र है। वह ऐसे बहुत से स्थानों को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए जिम्मेदार है जो पहले पृष्ठभूमि में ही थे। इस में शामिल हैं: भारत के 33 शहरों में इस निगम के सस्ते और महंगे हर तरह के होटल हैं। एक ओर यात्री निवास और वनकुटीर हैं और दूसरी ओर चमचमाते आलीशान रहने के स्थान। उदयपुर और मैसूर में दो रजवाड़ों के महल भी इस निगम के पास हैं। इतना ही नहीं कई अन्य इकाइयाँ भी निर्माणधीन हैं। संयुक्त रूप से कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ समझौते किये गये हैं। अंतर-राष्ट्रीय टेंडर की होड़ में जीत हासिल कर के अंतरराष्ट्रीय योजनाएँ भी उस के हाथ आ गयी हैं, जिन के अंतर्गत यह निगम सिप्रस और ईराक में दो होटल बनवायेगा।

रिहाइस के अलावा भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अन्य सुविधाएँ भी जुटाता है। उस की परिवहन इकाई पूर्व नियोजित यात्राओं की व्यवस्था करती है। उस के होटलों में

मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। दिल्ली, श्रीनगर और अहमदाबाद में 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम होते हैं। बड़िया से बड़िया भारतीय, पश्चिमी और चीनी व्यंजनों के लिए रेस्तरांओं की शृंखला है। यह बात भी प्रशंसनीय है कि पहली बार होटलों की सजावट ऐसी की गयी है जो पूरी तरह भारतीय परंपरा का निर्वाह करती है। सजावट में भारतीय प्रतीक चिन्हों—ग्रामीण नमूनों, पारंपरिक चित्रकारी, मित्तिचित्रों, चूड़ियों, मोतियों, मिट्टी के बर्तनों और गद्दों का भरपूर उपयोग किया जाता है।

बहरहाल, जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं वहाँ कुछ बुराइयों का होना भी लाजमी है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन के राज्यमंत्री खुर्शीद आलम खाँ निगम के लिए वास्तुकारों की नियुक्ति के बारे में संसद में सफाई मले ही देते रहें लेकिन यह प्रश्न फिर भी बना रहता है कि यह निगम केवल 4 या 5 वास्तुकारों के प्रति पक्षपात क्यों करता है। इन में 'डिजाइनर कंबाइन' नामक संस्था प्रमुख है जिस को कहा जाता है कि इस निगम को एक भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर ने बढ़ावा दिया। दिल्ली में ही दो होटल हैं जिन का काम दो वर्ष पिछड़ा हुआ है।

'नियंत्रक और महापरीक्षक' ने इस बात की आलोचना की है कि निगम के होटलों में खाली कमरों की संख्या बहुत काफी होती है। कलकत्ता के एयरपोर्ट होटल में 1975-76 के दौरान 47 प्रतिशत कमरे भरे हुए थे 1979-80 में यह अनुपात बढ़ कर 69 प्रतिशत हो गया। बंगलूर के अशोक होटल में भी 1975-76 के दौरान 52 प्रतिशत कमरों में मेहमान थे, 1979-80 में यह प्रतिशत 81 तक बढ़ गया था। लेकिन औरंगाबाद के अशोक होटल में केवल 22 से 34 प्रतिशत कमरे ही भरे हुए पाये गये। कोवलम गूव, पाटलीपुत्र अशोक, खजुराहो अशोक,



जम्मू अशोक और महाबलीपुरम् के समुद्र तट पर अशोक की स्थापना की गई है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

अध्यक्ष एस. के. मिश्र ने अपने इस निर्णय की घोषणा की है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों में सात होटल खोले जायेंगे। इस का उद्देश्य उन्होंने सामाजिक उत्थान बताया। ठीक ही है, लेकिन क्या कोई यह बता सकता कि निगम ने अहमदाबाद के कर्णावती अशोक के प्रबंध संचालन का ठेका क्यों गँवाया?

शायद अपने विक्री पक्ष को मजबूत करने के लिए ही भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपनी यात्रा एजेंसी खोली है, जिस का नाम है 'अशोक ट्रेवल एंड टूर'। पर्यटन के विकास की अपनी भूमिका के खिलाफ निगम अब ऐसे तरीके अपना कर केवल अपनी घरेलू यात्रा संस्था के माध्यम से अपने होटलों के ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, जिस से वह सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और दलों के सदस्यों को अपने होटलों में ठहरा सके। जाहिर है कि निजी क्षेत्र के होटल इस में सरकारी होटलों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। फिर निगम विदेश के सरकारी पर्यटन कार्यालयों का भी भरपूर फायदा उठायेगा।

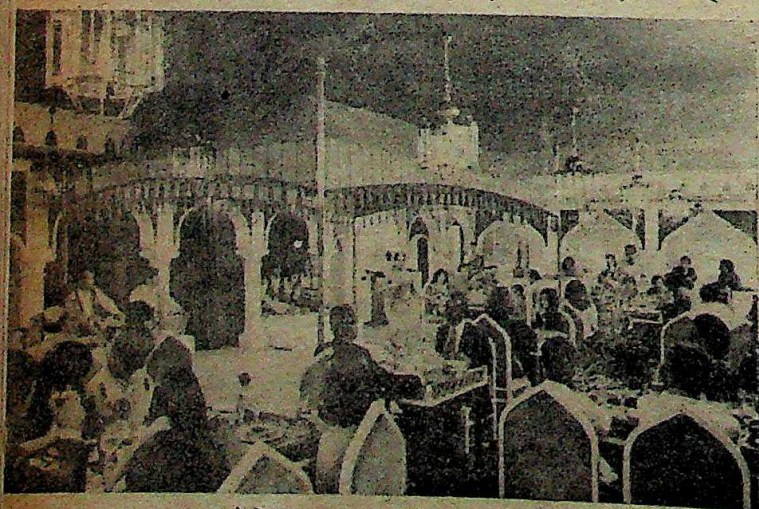
**वि**श्व के संपन्न पर्यटक, का भारत की ओर आकर्षित करने का एक विराट कार्यक्रम बनाया जा रहा है। चारों ओर 35 लाख विदेशी पर्यटकों के वार्षिक लक्ष्य की चर्चा सुनायी दे रही है। इस लक्ष्य के कितना निकट हम पहुँच पायेंगे यह तो समय ही बतायेगा मगर देश की प्रमुख सार्वजनिक पर्यटन संस्था भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के रहने लायक होटलों के विकास और निर्माण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बना चुका है। और उसी की देखा देखी अन्य होटल शृंखलाओं ने भी अपनी विकास संबंधी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। इसी वर्ष नवंबर में आयोजित होने वाले एशियाई खेल समारोह ने इस गतिविधि को उत्तेजना की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है। क्या सचमुच एशियाई खेलों में इतने लोग आयेंगे कि ये नये बनने वाले होटल नफा कमा सकें? मगर इस से भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस वर्ष नवंबर से पहले यह निर्माण-धीन होटल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार भी हो जायेंगे या नहीं। कुछ निर्माणधीन पाँच सितारा होटलों पर एक दृष्टि डालने पर यह साफ हो जायेगा कि पचास प्रतिशत से अधिक कमरे तो उस वक्त भी निर्माण-धीन ही होंगे जब कि खिलाड़ी और दर्शक देश से विदा ले रहे होंगे। तो मवाल यह पैदा होता है कि इस योजना में खराबी कहाँ है। असल में खराबी योजना में नहीं सार्वजनिक उपभोग के लिए जारी की गयी उन कहानियों में हैं जिन से यह अनुमान लगाया गया था कि सब कुछ एशियाड के लिए हो ही रहा है। सच्चाई तो यह है कि जितने भी होटल इस समय बन रहे हैं उन की आवश्यकता पहले से ही महसूस की जाती रही है। मगर अन्य (व्यवसायों की तरह होटल व्यवसाय को भी जमीन, ऋण और विदेशी मुद्रा आदि की तंगी महसूस होती है। बल्कि औरों से कहीं ज्यादा क्योंकि होटलों के लिए शहर के मध्य चुनी हुई जगह चाहिए, जो महा-

नगरों में नायाब और महँगी होती है, एशियाई खेलों ने निजी होटल व्यवसाय को एक ऐसी चुनौती का मौका दिया कि जिस में उन्हें वे सब चीजें बहुत कम कोशिश से मिली जो पहले वर्षों के प्रयास से मिलना भी मुश्किल हो रहा था। दिल्ली के बीचोबीच दो बड़े होटल बनाये जा रहे हैं जिन के मालिक अब से पहले इस उद्योग से दूर का रिश्ता भी नहीं रखते थे। प्रसिद्ध होटल शृंखला ताज और मौर्य के अतिरिक्त अपेक्षाकृत कम ज्ञात होटलों को भी फैलाव का मौका दिया गया। इस से यह आभास लगा कि जैसे यह सभी अतिरिक्त कमरे एशियाई खिलाड़ियों के दर्शकों के लिए होंगे। सारा मामला महत्वपूर्ण जमीन हथियाने का ही था। इस बात का संकेत सब से महत्वपूर्ण और बड़ी होटल शृंखला ओबेराय से मिलता है। ओबेराय ने इस होड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की। देश और विदेश में 26 पाँच और चार सितारा होटल चलाने वाले इस संगठन को अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं थी। वर्तमान ओबेराय इन्टरकांटिनेंटल के ठीक पीछे कुछ जमीन खाली पड़ी है जिस पर यह संगठन भविष्य में एक और होटल बनाने की योजना बना चुका है या वर्तमान होटल को ही विस्तार दिया जा सकता है। क्योंकि सभी पाँच सितारा होटलों का उद्देश्य 1982 की एशियाई खेलों में आने वाले पर्यटकों को स्थान देना ही नहीं है अगले दस वर्षों में भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के लिए तैयारी करना है, इसलिए मोहन सिंह ओबेराय ने जल्दबाजी में होटल ज्वर से पीड़ित होना स्वीकार नहीं किया है।

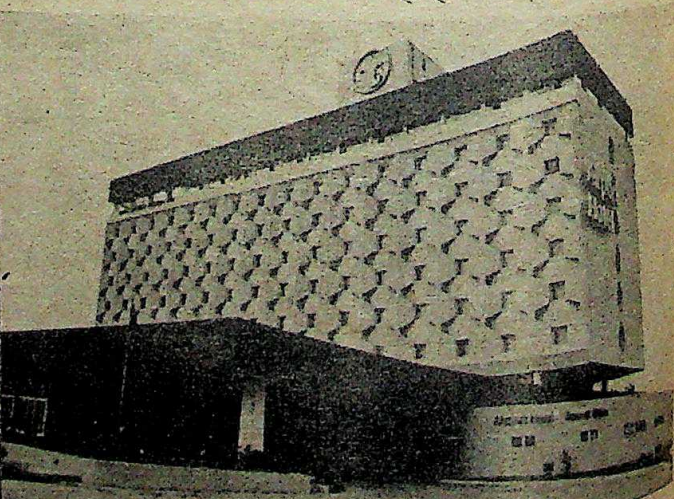
**घा**टे की प्रवृत्ति के बावजूद एशियाड के नाम पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर होटल बन रहे हैं—सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी। इस समय दस नये होटल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। एक होटल को बहुत विस्तृत किया जा रहा है और एक को अभी शुरुआत होनी है। इस से शहर में कमरों की संख्या दूनी से भी अधिक हो जायेगी इन कमरों में कितने खर्च पर कौन रहेगा?

दिल्ली के होटलों में इस समय तीन हजार से अधिक कमरे हैं, जिन में अशोक, अकबर, ताज, मौर्य शेरटन और ओबेराय इन्टरकांटिनेंटल जैसे बड़े बड़े होटलों के कमरे भी शामिल हैं। इन के अलावा रही सही कमी पूरी करने के लिए अंबेसेडर, जनपथ, इंपीरियल, लोधी, राजदूत, विक्रम और क्लैरिजेज जैसे कुछ छोटे होटल भी हैं।

जल्दी ही इन के साथ 'भारत होटल' वालों का 500 कमरों का होटल, जिस का नाम अभी तय नहीं किया गया है, ह्याट रीजेंसी दिल्ली (588 कमरे), सिद्धार्थ कांटिनेंटल (156 कमरे), मेरिडियन दिल्ली (445 कमरे), ताज पैलेस (500 कमरे) सूर्य इंटरनेशनल (260 कमरे), अशोक यात्रा निवास (527 कमरे), कनिष्क (321 कमरे), सम्राट (270 कमरे), मौर्य टॉवर (122 कमरे) भी जुड़ जायेंगे। इन सभी को निर्धारित समय में पूरा होना है—इन में से कम से कम दो होटलों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त कर लिया है और कुछेक के बारे में इस दिशा में बातचीत चल रही है।



ओबेराय टावर बम्बई का मुगल कक्ष.



कलकत्ते का एयरपोर्ट अशोक होटल

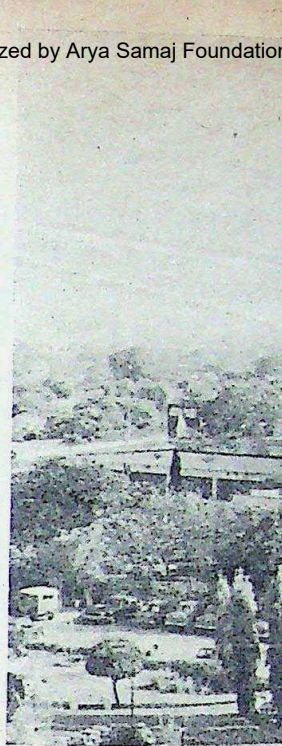
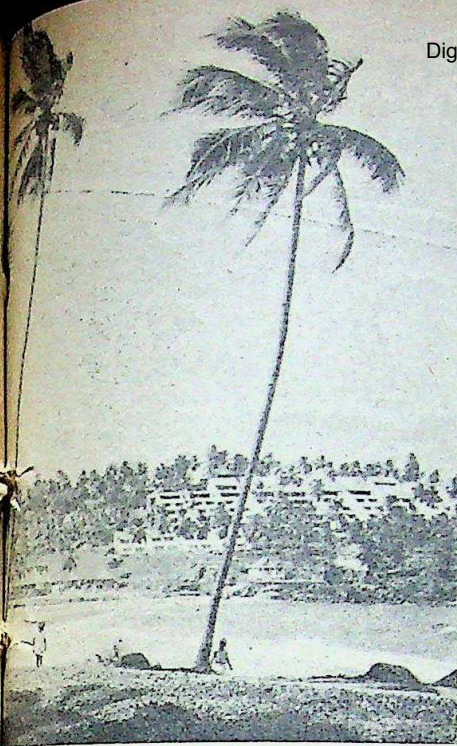


निजी होटल  
वे सब चीजें  
भी मुश्किल  
रहे हैं जिन  
नहीं रखते थे.  
कृत कम ज्ञात  
मास लगा कि  
के लिए होंगे.  
जात का संकेत  
है. ओबेराय  
विदेश में 26  
को अतिरिक्त  
ल के ठीक पीछे  
क और होटल  
विस्तार दिया  
य 1982 की  
है अगले दस  
लिए तैयारी  
होटल ज्वर से

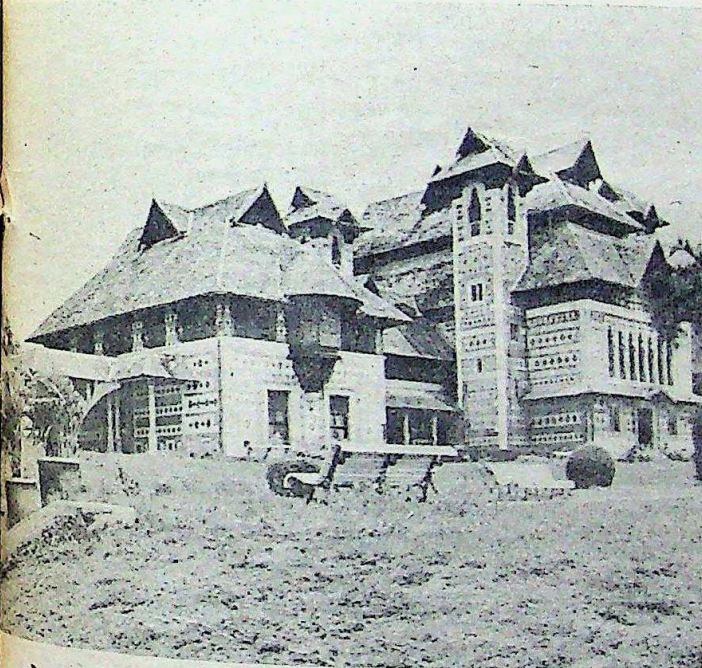
में बड़े पैमाने  
पर निजी क्षेत्र  
में हैं. एक  
अभी शुरुआत  
क हो जायेगी

क कमरे हैं.  
टरकांटिनेंटल  
गवा रही सही  
पेची, राजदूत.

00 कमरों का  
रीजेंसी दिल्ली  
डियन दिल्ली  
शनल (260  
321 कमरे),  
इ जायेंगे. इन  
म से कम दो  
और कुछेक



नयी दिल्ली का ओबेराय इंटर-  
कांटिनेंटल और इस शृंखला के  
संस्थापक एम. एस. ओबेराय



कोवलम तट और त्रिवेंद्रम में नेपियर स्पूजियम का आकर्षक भवन :  
निगम के नये पर्यटन केंद्र

**म**ात पर्यटन विकास निगम को देश में पर्यटन उद्योग का विकास करने और उस के लिए मजबूत ढांचा बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था. 1966 में इस की स्थापना के समय देश में 260000 विदेशी पर्यटक आया करते थे जिनसे देश को 23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी. अब इन की संख्या 8 लाख है और इन से वार्षिक विदेशी मुद्रा 482 करोड़ प्राप्त होती है. इस में कोई संदेह नहीं कि भारत पर्यटन विकास निगम का इस में पर्याप्त योगदान है. नयी दिल्ली के अशोक होटल ने आधुनिक होटलों की शृंखलाएँ स्थापित करने में काफी सहायता की है. यद्यपि यह भी सही है कि इस से पहले बंबई के ताज ने आधुनिक होटलों का एक आधुनिक स्तर स्थापित कर दिया था. जैसा कि प्रायः होता है हमारे देश में सार्वजनिक उद्योगों की कुछ निहित कमजोरियाँ रहती हैं जिस के कारण वे तुरंत मुनाफा कमाने की स्थिति में नहीं रहते. कुछ तो व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी कुछ सरकारी नियम और कायदे

कानून का शिकंजा और किसी हद तक सामाजिक दायित्व इसके कारण है. यह कहा जा सकता है कि निगम दो चरणों में से गुजर चुका है. 1966 से 70 तक इस का शैशवकाल था जब कि सुविधाएँ कम और लाभ नगण्य था. पर्यटन उद्योग पर इस अवधि में निगम के होटलों का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा. आठवाँ दशक निगम के होटलों के लिए विकास दशक कहा जा सकता है, जब कि इस की विदेशी मुद्रा की आय 25 लाख से बढ़ कर 15 करोड़ तक हो गयी. सारे देश में इस के होटलों के पास तीन हजार के करीब कमरे हैं, जिन में अगले दो वर्षों में 1500 कमरे और बढ़ाये जा रहे हैं. 1980 के पश्चात निगम का तीसरा चरण शुरू हो रहा है जिस में वह देश की सब से बड़ी होटल शृंखला बनने के अतिरिक्त एशिया में महत्वपूर्ण पर्यटन विकास शृंखला के रूप में उभर कर आने की कोशिश कर रहा है. इस दिशा में शुद्ध रूप से भारतीय संगठन होने के बावजूद इसने विश्व के अन्य देशों में अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं. सिप्रस में 200 कमरों वाला एक पाँच सितारा होटल, इराक में एक पर्यटन गृह इस प्रकार के उदाहरण हैं. पिछले कुछ वर्षों से अशोक समूह के होटलों ने अच्छा मुनाफा कमाना भी शुरू किया है. 21 में से अब 12 होटल मुनाफा कमाते हैं. जो नहीं कमा पाते वे प्रायः दूरदराज के पर्यटन केंद्रों में स्थित अपेक्षाकृत नये होटल हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि निगम ने हाल ही में नयी दिल्ली के जनपथ होटल के साथ 530 कमरों वाला एक अशोक यात्री निवास बनाना शुरू किया है. उद्देश्य यह है कि सामान्य बजट के भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए शहर के प्रमुख हिस्से में कम मूल्य पर एक आरामगाह स्थापित किया जाये. यदि प्रयोग सफल हुआ तो राज्यों की अन्य राजधानियों में भी इस सुविधा का विकास किया जा सकता है.

भारत पर्यटन विकास निगम अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर रहा है. मध्य एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों में तीन बड़े होटलों के निर्माण कार्य के साथ अब भारतीय पर्यटन संगठन ने एक अंतर-राष्ट्रीय होटल शृंखला स्थापित करने में शुरुआत की है. 40 करोड़ रुपये की लागत से सिप्रस और इराक में तीन बड़े होटल बनाये जा रहे हैं. सिप्रस में लिमासोल के तटवर्ती नगर में 200 कमरों का अशोक लोटस पाँच सितारा होटल अब निर्माणाधीन है. इस होटल के निर्माण का ठेका निगम को अंतरराष्ट्रीय नीलामी प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ.



भेटवार्ता

## सामाजिक दायित्व का निर्वाह

भारत पर्यटन विकास निगम

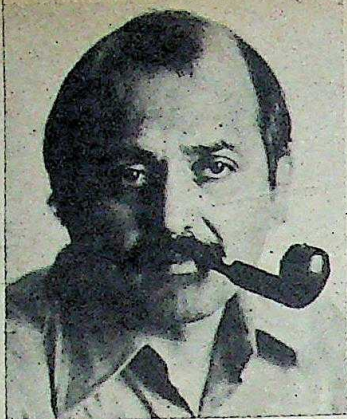
के अध्यक्ष शशिकांत मिश्र ने विनमान के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने निगम के विरुद्ध लगाये गये अधिसंख्य आरोपों का खंडन किया। श्री मिश्र से यह पूछा गया था कि महानगरों को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर निगम के होटल नुकसान पर चल रहे हैं। क्या ऐसा विपणन तकनीक के अभाव और निजी उद्योग के कड़े मुकाबले के कारण है? अध्यक्ष के अनुसार "जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भारत पर्यटन विकास निगम देश में प्रमुख रूप से पर्यटन का ढांचा स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया। निगम की वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा इस बात को भी ध्यान में रख कर होनी चाहिए क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन केंद्रों को स्थापित करना है। स्पष्ट है कि निगम की आयोजना में लाभ को ही एक मात्र मानक नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद पर्यटन निगम ने अपने जन्म से ही लगातार नफा कमाने का एक क्रम स्थापित किया है। 1969-70 में इस का लाभ 2.6 लाख रुपए था जो कि 1981-82 में सभी कर अदा करने के बाद अनुमानतः 1.40 करोड़ रुपया है। पिछले वर्षों में निगम द्वारा विकास और प्रोत्साहन संबंधी कार्य के बावजूद यह एक उपलब्धि है। 1981-82 में निगम का लाभ पिछले वर्षों की तुलना में तीन गुना है। इसका परिवहन विभाग जो लगातार नुकसान में जा रहा था अब 12 लाख रुपए लाभ कमा कर घाटे की सीमा को पार कर चुका है। पिछले वर्ष इस विभाग को 16 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था।

यह सही नहीं है कि महानगरों के कुछ ही होटल नफा कमा रहे हैं। 1981-82 में निगम के 21 महत्वपूर्ण होटलों में से 12 में लाभ हुआ। इन में निस्संदेह दिल्ली के सभी 6 होटल तो हैं, बंगलूर का अशोक होटल, हासन अशोक (कर्नाटक), लक्ष्मी विलास पैलेस उदयपुर, ललिता महल पैलेस, मैसूर, कलिंग अशोक, सुवनेश्वर भी शामिल हैं। अंतिम चार निश्चित रूप से महानगरों के होटल नहीं हैं। पिछले वर्ष 6 होटल पहली बार नफा देने लगे हैं। बाकी सभी होटलों की हानि पहले की तुलना

इसी प्रकार ईराक में मोसुल और डोकान के स्थानों पर दो पर्यटन गृह स्थापित किये जा रहे हैं। ये दोनों होटल निर्माण के पश्चात स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित संगठनों को सौंप दिये जायेंगे मगर लिमासोल होटल स्थानीय होटल संस्था के साथ एक साझा प्रयास है। इस प्रकार पहली बार भारत का कोई सार्वजनिक संगठन बड़े पैमाने पर विदेशों में अपने पांव जमाने की पहल कर रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि लोटस होटल भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विश्व के अन्य क्षेत्रों में होटलों की एक लंबी शृंखला स्थापित करने के लिए एक नामिक का काम करेगा। इसीलिए इस होटल की वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह एक केंद्रीय स्थल के इर्दगिर्द बनाया जा रहा है और पूरे होटल की छत शीशे की होगी। चारों ओर जो कमरे बनाये जा रहे हैं उनसे समुद्र, पर्वत और शहर तीनों का दृश्य साफ दिखायी देता है।

इस से पहले केवल निजी क्षेत्र के होटल संगठनों ने विदेशों में अपने व्यापार को फैलाने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में ओबेराय शृंखला महत्वपूर्ण है। हाल ही में आस्ट्रेलिया के नगर मेलबोर्न में होटल

विनमान



में कम हो गयी है। अशोक समूह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होटल है अशोक दिल्ली, जिसने पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रुपए का लाभ कमाया और अकबर दिल्ली, जिसने 66 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के होटल वास्तव में उत्प्रेरक का काम करते रहे हैं। इसने पिछले वर्षों में कई नये पर्यटन केंद्रों को चालू किया है। और जब यह केंद्र पर्यटकों के आकर्षण का स्थल बन गये तो फायदा कमाने के लिए निजी क्षेत्र के होटल आ पहुँचे।

कुछ निजी होटलों की यह शिकायत रही है कि भारत पर्यटन विकास निगम कई प्रकार से अनुचित सुविधाएँ प्राप्त करता है। इस सिलसिले में निगम द्वारा स्थापित नयी यात्रा एजेंसी का विशेष उल्लेख किया जाता है। शशिकांत मिश्र इस से भी सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार 'जहाँ तक होटलों का सवाल है भारत पर्यटन विकास निगम को किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा या लाभ नहीं दिया जाता। इस के विपरीत निगम को अपने होटलों की योजना प्रमुख रूप से सामाजिक उद्देश्यों को दृष्टि में रख कर बनानी पड़ी है, जैसे पर्यटन का विकास और देश के विशाल भू-भाग में पर्यटन उद्योग के फायदों को फैलाना। यह उसी प्रकार से कर देता है, वैसे ही मुग्तान करता है जैसे निजी क्षेत्र के होटल और उसी पंक्ति में सीमेंट, निर्माण सामग्री और अन्य नायाब सामान के लिए खड़ा हो कर बारी का इंतजार करता है जिस में निजी उद्योग के होटल खड़े होते हैं। बल्कि नशाबंदी, अतिथि नियंत्रण आदेश और यहाँ तक कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते के बारे में यह औरों से ज्यादा अच्छी तरह सरकारी नीति और नियमों का पालन करता है। होटल उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र यह दावा कर सकता है कि उसने भारतीय सज्जा, लोक हस्तकला और अन्य देशी वस्तुओं से अपने होटलों को सजाने की कार्यवाई द्वारा भारतीय सामान और कला को प्रतिष्ठित किया। भारतीय व्यंजन और वास्तविक रूप में शुद्ध देशी मनोरंजन शैलियों को प्रोत्साहित करने के सिलसिले में भारत पर्यटन विकास निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अब इसकी देखादेखी निजी क्षेत्र के होटल भी यही रास्ता अपना रहे हैं।

जहाँ तक निगम की अपनी यात्रा एजेंसी—अशोक ट्रेवल्स एंड टूरस का सवाल है यह बात याद रखने की है कि भारत में सभी प्रमुख होटल शृंखलाओं के पास अपनी यात्रा एजेंसियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ट्रेवल्स एंड टूरस यात्रा एजेंसी का प्रमुख उद्देश्य देशी पर्यटकों के समूहों को विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा कराना होगा। यह एक ऐसा काम है जो निजी क्षेत्र की एजेंसियाँ करने के लिए तैयार नहीं होती।

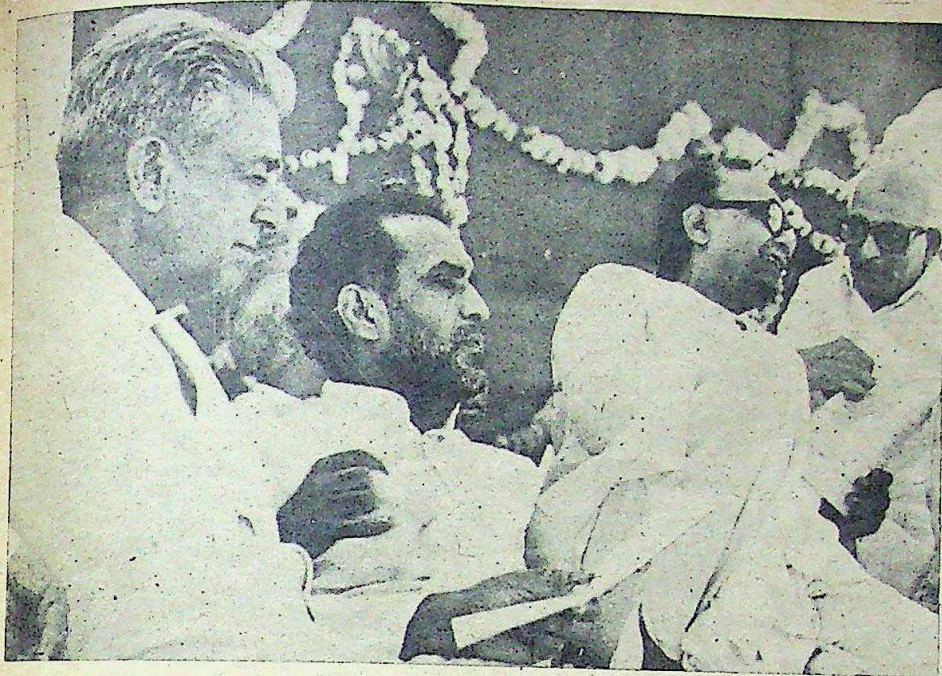
हमारे देश ने 1990 तक 35 लाख विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इतने पर्यटकों के देश में आने पर सभी यात्रा एजेंसियों के लिए पर्याप्त काम होगा, चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी।

विडसर के उद्घाटन के साथ इस शृंखला ने विश्व की प्रतिष्ठित शृंखलाओं में अपना नाम लिखाया है। विडसर होटल को विश्व के तीन सौ उच्च श्रेणी के होटलों में गिना जाता है। ओबेराय शृंखला के अन्य होटल जो इस श्रेणी में आते हैं काठमांडो का सोलटी, कोलंबो का लंका ओबेराय, इंदोनेसिया का बाली ओबेराय और मिश्र के मीना हाउस और आस्त्रान ओबेराय शामिल हैं। इस के अतिरिक्त इस शृंखला ने साऊदी अरब में दमन, श्रीलंका में क्वींस होटल, बगदाद में बेबीलोन, सिंगापुर में इंपीरियल आदि होटलों का संचालन शुरू कर दिया है। आस्ट्रेलिया में एक और होटल एडलेड में स्थापित किया जा रहा है जो इस शृंखला का एक महत्वपूर्ण होटल होगा। □

### अगले अंक में

दिल्ली में होटलों के असाधारण फैलाव पर कुछ होटल संचालकों का मत और पर्यटकों को ठहराने के लिए निजी मकानों के पंजीकरण पर एक विशेष रपट।





प्रतिपक्ष

## चंद्रशेखर चौधरी और चंडीगढ़

(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा)

**18** अप्रैल को सुबह ग्यारह के आसपास चंद्रशेखर के दिल्ली स्थित निवास (3, साउथ एवेन्यू) पर दोस्तों-समर्थकों की भीड़ पहले ही जैसी थी। फर्क सिर्फ यह था कि बाहरी कमरे में बैठे हुए दर्जन भर लोग एकदम खामोश थे। उनके निजी सहायक के आसपास जमा लोग भी कुछ बोल नहीं रहे थे। हलचल से भरी उस जगह की खामोशी स्वभाविक नहीं लगी। एक पुराने परिचित को अलग ले जा कर खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने उदास लेकिन राज मरे लहजे में कहा, "क्या बताऊँ, देवीलाल पलट रहे हैं। चंडीगढ़ की सफलता निरर्थक और बनावटी लग रही है।"

मगर क्यों? चंडीगढ़ का एकता सम्मेलन तो देवीलाल और उन के समर्थकों की इच्छा से हुआ। वही स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। फिर पलटने।

वात यह है कि चौधरी चरणसिंह हरयाणा में उनकी मुखियागिरी को मानने और तीनों की मुअत्तली (देवीलाल के अलावा बीजू पट्टनायक और कुंभाराम आर्य) के आदेश वापस लेने को तैयार हैं। लगता है कि तीनों लोकदल में वापस चले जायेंगे।

लगा कि पिछली रात लोकदल के उस मित्र ने फोन पर जो इशारा किया था, वह निराधार नहीं था। उन्होंने कहा था, 'चंडीगढ़ सम्मेलन

की खबरों के आधार पर कोई नतीजा मत निकालिए। असं साहब आ गये हैं चौधरी साहब से मिले हैं। जार्ज साहब की दौड़-धूप तेज है... मैं देवीलाल को बहुत नजदीक से जानता हूँ, ...

और इतवार को स्थिति एकदम साफ हो गयी। बहुत नाटकीय ढंग से चौधरी चरणसिंह ने न सिर्फ 8 अप्रैल को देवीलाल, बीजू पट्टनायक और कुंभाराम आर्य के विरुद्ध जारी किया हुआ मुअत्तली का आदेश वापस ले लिया बल्कि देवीलाल और डॉक्टर स्वर्णसिंह की एक समिति भी बनायी जो हरयाणा विधानसभा के उम्मीदवारों का मनोनयन करेगी। यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन नामों को ले कर दोनों में सहमति नहीं होगी उन पर अंतिम फैसला अध्यक्ष के रूप में चौधरी चरणसिंह करेंगे। तीनों नेता लोकदल में वापस चले गये।

एक संयुक्त वक्तव्य में देवीलाल, बीजू पट्टनायक, कुंभाराम आर्य, जार्ज फर्नांडीज, और कर्पूरी ठाकुर ने कहा, 'हरयाणा, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों ने हर चुनाव क्षेत्र में इंदिरा कांग्रेस के विरुद्ध प्रतिपक्ष की तरफ से सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करने का एक बड़ा प्रश्न उपस्थित कर दिया है। चौधरी चरणसिंह के नेतृत्व में एक संगठित और कृतसंकल्प लोकदल ही इस स्थिति

में प्रतिपक्षी दलों को एक साथ ला सकता है। विद्रोही मुद्रा को व्यामोह की मुद्रा में बदलने की कला राजनैतिक संस्कृति की ऐसी घरोहर है जिसके संरक्षण का श्रेय चौधरी चरणसिंह के बाद चौधरी देवीलाल को मिलना ही चाहिए।

जाहिर है कि चौधरी जी ने राजनैतिक व्यूह रचना में न केवल चंद्रशेखर यानी जनता पार्टी को गहरी मात दी है, बल्कि लोकदल को पहले से भी अधिक संगठित और सशक्त बना दिया है। देवराज अंस, कांग्रेस (स), प्रकाशसिंह बादल (अकाली) और हरिकिशन सिंह सुरजीत (माकपा) से बातचीत करने के बाद प्रतिपक्ष का वह समीकरण बदल गया है जिस की कल्पना चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के साथ लोकदल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं और कांग्रेस (स) के सहयोग से की थी। देवराज अंस की भूमिका से स्पष्ट हो गया कि शरद पवार की शिरकत के बावजूद एकता सम्मेलन की कोशिशों पर उन्होंने अपनी सहमति की मुहर नहीं लगायी थी। खंडित लोकदल और खंडित कांग्रेस (स) को मिला कर जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की आशा में चंद्रशेखर यह सोच भी नहीं पाये थे कि इन घटनाओं के कारण उनकी पार्टी की चोर दरार बन जायेगी। लोकदल और कांग्रेस (स) अपनी पूर्वस्थिति में पहुँच गये हैं। लेकिन जनता पार्टी के उनके विरोधी उनकी असफल व्यूह रचना की निंदा करते हुए उन पर राजनैतिक अपरिपक्वता का आरोप लगाते हुए उन से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की माँग कर रहे हैं।

चंडीगढ़ के एकता सम्मेलन में श्रोताओं की कमी नहीं थी। मुख्य मजमा देवीलाल का ही था। उपस्थित लोगों में जनता और समाजवादी कांग्रेस के नेताओं के अलावा असंतुष्ट त्रिगुट समेत लोकदल के 5 संसदसदस्य हरयाणा के उसके 22 में से 11 विधायक भी थे। उस में दो गैर कम्युनिस्ट गुट स्पष्ट उभर रहे थे। जनता पार्टी, समाजवादी कांग्रेस और असंतुष्ट लोकदल एक तरफ और चरणसिंह का लोकदल, जगजीवन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ सम्मेलन की समाप्ति के पूर्व एकतावादी का नेताओं को यह कहते सुना गया कि वे बहुगुण के लोकतांत्रिक समाजवादी कांग्रेस और चंद्रजीत यादव की जनवादी पार्टी—यहाँ तक कि माकपा और माकपा से भी चुनावी तालमेल बैठाना पसंद करेंगे। लोकदल के असंतुष्ट सदस्यों का खयाल था कि क्योंकि चरणसिंह का प्रभाव निरंतर कम हुआ है। अतः उन्हें अंततः निष्प्रभावी करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चंद्रशेखर की आशावादिता शिखर पर थी। उन्होंने कहा था, "विलयन के रास्ते



तही है। चुनाव के 3 महीने के भीतर 1 स्वप्न साकार ही जायेगा। उसी में एक संयुक्त कमान का गठन हुआ। पहनायक संयोजक बने। चंद्रशेखर, पवार उस के सदस्य थे। वह कमांड निरर्थक हो गया है। तथ्य यह है कि उस मौके पर बैसाई भी चंडीगढ़ में मौजूद थे। सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। क जनसभा में यह जरूर कहा था कि मैं शामिल कुछ लोग शरीर से मंच बैठे हैं लेकिन दिल से कहीं और हैं। मैंने किसी का नहीं लिया था। इशारा 1. क्या उन्हें सचमुच लोकदल के ही वास्तविक नीयत की कोई जानकारी शायद रही हो। कहा तो यह भी कि एक तरफ देवीलाल चंडीगढ़ में अपने प्रभाव को प्रमाणित कर रहे और उन के कुछ अंतरंग मित्र उसी चरण सिंह से समझौते की बातचीत भी थे। एक सूचना के अनुसार सम्मेलन के गढ़ में जाट पंचायत की एक बैठक फैसला यह हुआ था कि जाट मतदाता की जगह लोकदल के चुनाव चिन्ह वाले उम्मीदवार को ही वोट देंगे। पंचायत ने देवीलाल को दी तो उन्हें अपने प्रभाव की वास्तविकता पंचायत के फैसले के गंभीर परिणाम, अंदाजा लगा। उन की समझ में आ हरयाणा में भी चौधरी चरण सिंह कितनी गहरी हैं। इस आत्मबोध के चरण सिंह से मिलने से इनकार आत्मबोध के बाद वह चौधरी जी की सफाई देते हुए शायद यह कहा कि 1 का फैसला उन्होंने विभागी परेशानी अनियंत्रित स्थिति में अचानक कर

लिया था। चौधरी जी ने समझौते का तो थी ही। अतः उन्होंने समझौते का एक सम्मानजनक रास्ता निकालते हुए सुबह के भटके देवीलाल तथा अन्य नेताओं की शाम को घर वापस आ जाने की इच्छा का स्वागत किया।

असलियत यह है कि चंडीगढ़ में एकता सम्मेलन करने की मांग पर जार्ज फर्नांडीज और कर्पूरी ठाकुर ने भी हस्ताक्षर किये थे। लोकदल की कार्यकारिणी की पहली बैठक में शामिल न होकर इन दोनों नेताओं ने अपना असंतोष भी व्यक्त कर दिया था। लेकिन लगता है कि लोकदल को प्रभावशाली बनाये रखने की राजनैतिक अनिवार्यता जितनी चरण सिंह को है उस से कम पुराने समाजवादियों को नहीं है। पुरानी जनता पार्टी के विघटन के बाद समाजवादियों का अपना कोई मंच, अपनी कोई जमीन या अपना कोई बड़ा नेता नहीं रहा। इस तीखी वास्तविकता का अहसास जार्ज फर्नांडीज और कर्पूरी ठाकुर को जरा देर से हुआ। ये नेता खुद भी चरण सिंह की कार्यशैली से बहुत खुश नहीं रहे हैं लेकिन इस तथ्य को व्यापक हित के लिए नजरंदाज करना जरूरी हो गया। उन्हें लगा कि इस के पहले कि स्थिति काबू से बाहर हो चरण सिंह पर दबाव डालने और लोकदल को विघटन से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। उस में वे कामयाब भी हुए।

इस पूरे प्रसंग में रवि राय ने चौधरी जी के प्रति अपनी वफादारी को बरकरार रखा। लोकदल के कार्यकारी महासचिव की हैसियत से उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ सम्मेलन पार्टी विरोधी था। वह असफल सिद्ध हो गया। उसके निर्णय लोकदल के लिए निरर्थक हैं। अब लोकदल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (ज) से सीट संबंधी समझौता करेगा। अकाली (ल)

## चरणसिंह पर किसे यकीन है?

के एक अंग्रेजी पाक्षिक ऑनलुकर से बातचीत करते हुए मृतपूर्व प्रधानमंत्री श्री माई बैसाई ने कहा कि एकता बातचीत की सहमति उन्होंने दी मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि एकता होनी चाहिए। लेकिन मैंने तीन बार या कि यदि कोई एकता मेरे सिद्धांतों के मत पर होती है तो न मैं उस का वर्णन न जनता पार्टी में रहूँगा। ही कहा था। इस का मतलब क्या है? सख्त रवैया अपना कर पार्टी को नहीं चाहता था। ज़िदगी में कमी संगति बैठाने के लिए थोड़ी बहुत शर रखनी पड़ती है लेकिन आप को 1 से सौदा नहीं करना चाहिए। न था। आप को चरणसिंह का एक दिखाया गया था जिस में उन्होंने

कहा था कि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं?

मोरार जी ने जवाब दिया: "उन्होंने वह खत मुझे नहीं दिखाया। उन्होंने अपने दोस्तों को लिखा था। क्या आप का खयाल है कि उन पर यकीन किया जा सकता है?" वह अध्यक्ष होना चाहते हैं। वह प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। वह सब कुछ चाहते हैं। चंद्रशेखर और दूसरे नेताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने (चरणसिंह) बेशर्मी के साथ यह कहा कि आप प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। वह प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, वाजपेयी प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, तब, अगर मैं प्रधानमंत्री होना चाहता हूँ तो उस में क्या गलत है।"

मोरारजी भाई ने यह भी कहा कि एकता वार्ता सफल नहीं हो सकती। इसे कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

और दूसरे प्रतिपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जनता पार्टी और कांग्रेस (स) ने सम्मेलन आयोजित करते हुए पार्टी के क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर लोकदल को जानबूझ कर अलग थलग करने की कोशिश की।

ध्यान देने की बात है कि चौधरी जी ने प्रतिपक्षी दलों से चुनावी तालमेल पैदा करने के लिए रविराय, जार्ज फर्नांडीज, और सत्यपाल मलिक की एक समिति बनायी है।

फिलहाल चुनावी तालमेल और व्यूहरचना संबंधी प्रतिपक्षी नीति हर जगह एक सी नहीं है। यदि लोकदल में 19 मार्च के पहले तक वातावरण शांत रहा तो हरयाणा में उसे लाभ मिल सकता है। वह भाजपा और कांग्रेस (ज) से तालमेल की इच्छा व्यक्त कर चुका है। उसने हिमाचल की 68 सीटों में से 38 पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। साथ ही भाजपा ने भी वहीं से 40 ऐसे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है जिन्हें ले कर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरे प्रतिपक्षी दलों के नाम अभी सामने नहीं आये हैं। यदि दोनों अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो समझौता असंभव होगा। हरयाणा में भी भाजपा और कांग्रेस (ज) का प्रभाव है। केरल और पश्चिम बंगाल में सारी लड़ाई सीधे सीधे दो मोर्चों के बीच है। केरल में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच और बंगाल में वामपंथी संयुक्त मोर्चे और अन्य दलों के बीच। यहाँ पर जनता पार्टी और समाजवादी कांग्रेस के नेता इंदिरा कांग्रेस से समझौता करने के पक्ष में हैं। यानी बंगाल में वामपंथी मोर्चे से लड़ने में इंदिरा कांग्रेस का सहयोग, और उत्तर भारत में इंदिरा कांग्रेस से लड़ते हुए वामपंथियों का सहयोग। लगता नहीं है कि सीटों संबंधी समझौता इन्हें किसी पक्के किनारे पर ले जा पायेगा। वैसे भी इंदिरा कांग्रेस का भीतरी विवाद उतना बड़ा या अनुशासन में न आ सकने वाला नहीं है जितना कि प्रतिपक्षी दलों का। यह स्थिति कितनी हास्यास्पद है कि चुनाव के पहले ही आपसी लड़ाई का सार्वजनिक दृश्य प्रस्तुत करते हुए ये दल इंदिरा कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत करने के नाम पर जनता से बार बार समर्थन मांग रहे हैं। यानी बताना वे यह चाहते हैं कि जनता चुनाव पूर्व की उन की आपसी लड़ाई को महत्व न दे और यह यकीन कर ले कि चुनाव जीतने के बाद उन में आपस में कोई मतभेद नहीं होंगे। खबर तो यह है कि अर्स साहब लोकदल में और लोकदल यानी चरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

कुछ नेताओं के अनुसार '77 की भावना जनता में जागी है। प्रश्न यह है कि क्या प्रतिपक्ष जनता को अपनी एकता का यकीन दिला पाने के काबिल रह गया है?



## स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव

इंद्रजीत, संपादक : इन्फा

एक बार फिर से चुनाव प्रणाली में सुधार की बात नयी दिल्ली में उठने लगी है क्योंकि एक लघु आम चुनाव का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने कुछ कदम उठाये हैं जिन में ये चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होने के साथ-साथ निर्भय भी हो सकेंगे। इस के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी 12 अप्रैल को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पारित कर के देश का ध्यान चुनाव प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम जेठमलानी खुद इस प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस. एल. शर्मा को देने के लिए गये थे। उन के साथ दो महासचिव श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा श्री सिकंदर बख्त भी गये थे।

जनतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन। फिर भी अनुभव से यही जान पड़ता है कि वोट देने के सभी हकदार अपने मतधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। निहित स्वार्थों के द्वारा हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों को घमका कर, डरा कर वोट देने से अनेक बार रोका गया है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा अल्पज्ञात निर्णय लिया है जिस से उनके मूल अधिकार, अपने शासकों को चुनने के अधिकार की रक्षा हो सकेंगी। आयोग ने निर्णय लिया है कि हरिजन वस्तियों में मतदान उपकेंद्र बनाये जायें ताकि उन्हें अपना वोट देने के लिए बाहर न जाना पड़े। प्रायः आठ सौ मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र होता है; उपकेंद्र वहाँ बनाये जायेंगे जहाँ 100 से 200 तक हरिजन होंगे।

इसी के साथ कुछ ऐसे कदम भी उठाये जा रहे हैं जिन से हरिजनों को चुनाव के बाद अपनी इच्छा से वोट देने के कारण परेशान किये जाने से बचाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए हरयाणा में किसी जाट-प्रधान चुनाव क्षेत्र में हरिजनों को घमका कर किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए अब भी कहा जा सकता है, पर चुनाव आयोग ने तय किया है कि गिनती के समय मतदान उपकेंद्रों के मतों को अन्य मतदान केंद्र के मतों के साथ मिला दिया जायेगा। इस से कोई यह नहीं जान पायेगा कि हरिजन बस्ती ने किसे वोट दिये हैं। यह प्रणाली करोड़ों दलितों के लिए वरदान सिद्ध होगी। चुनाव आयोग ऐसी सुविधाएँ और जगहों के हरिजनों तथा कमजोर वर्गों को भी देने को तैयार है, यदि वे चाहें तो।

इस के अतिरिक्त भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग नयी सिफारिशें करता आया है। इन में से कई तो निरपवाद हैं और उन्हें लागू कर दिया जाना चाहिए। पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक के बाद दूसरी सरकारें आयीं पर किसी ने उन सिफारिशों को भी लागू करने की कोशिश न की, जिन पर पिछले कई सालों से जनता के बीच बहस हो रही है और जिन पर अब आम सहमति है। उदाहरण के लिए चुनावों की पवित्रता को अर्थ शक्ति और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से खतरा है, यह सभी मानते हैं।

आज अधिकतर लोग सहमत होंगे कि चुनावों के लिए सरकारी खर्च की व्यवस्था से पैसे की ताकत के प्रभाव को अच्छी तरह काबू किया जा सकता है। दरअसल चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए गठित संसदीय समिति ने 1973 में सिफारिशें की थीं कि सभी चुनावी खर्चों को सरकारी अर्थ विभाग की वैधानिक जिम्मेदारी माना जाना चाहिए और किसी भी उम्मीदवार या उस की पार्टी द्वारा किये जाने वाले खर्चें राज्य की जिम्मेदारी हों। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने पाँच साल की अवधि के लिए एक सौ करोड़ रुपये का चुनाव कोष बनाने की सिफारिश की। इस धन से चुनावों का वित्त प्रबंध किया जाये ताकि घनराशि के क्षयकारी प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। पर इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया हालाँकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी। अकेले एशियाई खेलों पर ही सरकार इस से कोई दस गुना खर्च करेगी।

अपने उम्मीदवार पर किया गया खर्चा भी उम्मीदवार के खाते जाना चाहिए, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में श्रीमती ग काल में संशोधन के पहले था। 1975 में जब सर्वोच्च न्याय जनसंघ नेता कँवरलाल गुप्त की याचिका पर कांग्रेस (इं) संसद अमरनाथ चावला के चुनाव को अवैध करार दिया, तब यह किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमती गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। आश्चर्य? हाँ, मैं यह बात अ पूर्वक कह सकता हूँ कि जब कांग्रेस (इं) पार्टी सरकार से बाहर कांग्रेसी इन दोनों सुधारों को पूर्ण और प्रकट समर्थन देते थे।

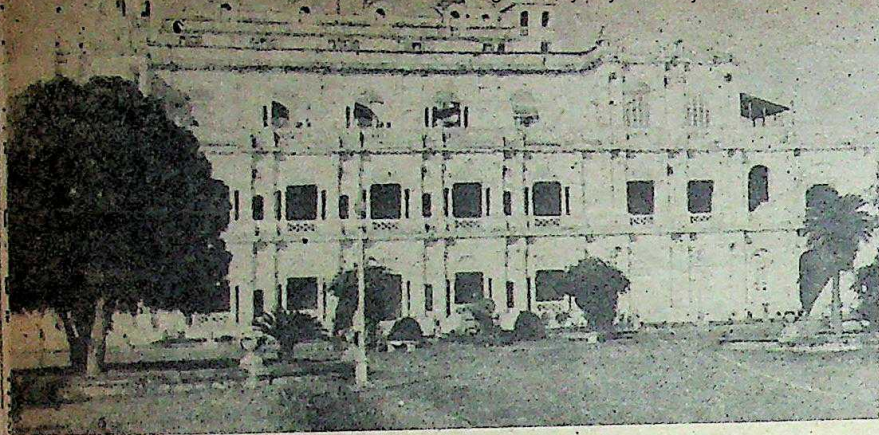
उन दिनों सी. एम. स्टीफन संरक्षण और निष्पक्ष चुनाव की आयोग के चक्कर लगाया करते थे। वरिष्ठ कांग्रेस (इं) नेता सुधारों के लिए दो कारणों से दबाव डाल रहे थे, एक तो उन्हें नहीं था कि वे चंदा उगाह भी सकेंगे और दूसरे उन्हें डर था कि प्रतिनिधित्व कानून में 1975 का सुधार उनके भी खिलाफ सकता है। दुर्भाग्य से जनता सरकार अपने ही वादों पर टिकी न बार तो श्री शर्मा ने स्वयं मंत्रिपरिषद की बैठक में आ कर सिफारिशों की व्याख्या करने और सुधारों को जल्दी लागू सहायता के लिए प्रस्ताव भी किया था। अंततः एक मंत्रिपरिषद समिति गठित की गयी जिसने मामले को लंबा खींच दिया।

यह तो साफ है कि जहाँ तक इस लघु आम चुनाव का है, ये सुधार आज ही तो लागू नहीं किये जा सकते, पर आज्ञा जारी कर के आयोग की काफी सिफारिशों को तो लागू जा सकता है। उदाहरण के लिए आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के (घासीराम बनाम दलसिंह) के आधार पर कुछ सिफारिशें उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला ने देखा कि चुनावों में कई ऐसे आचरण जा रहे हैं जो कानून की शब्दावली में 'भ्रष्ट' तो नहीं कहे जा सक आचरण 'बुरे' जरूर हैं और ये जल्दी ही खत्म किये जाने च फलस्वरूप आयोग ने उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए लिखित सिफारिशें की थीं :

(1) सदन की सामान्य समाप्ति अथवा अचानक चुनाव जाने की तिथि से छह महीने पहले किसी मंत्री के 'डिस्मिशनरी' से भुगतान पर रोक लगा दी जाये, (2) जिन कार्यों का पूरा सरकारी काम से नहीं है उन के लिए सरकारी गाड़ियों का वजित हो, (3) चुनावकार्य मंत्री के निजी स्टाफ तथा अन्य अधिकारियों के लिए कानून के अंतर्गत वजित हो, सिवाय चुनौती पर लोगों की शिकायतों पर घटनास्थल पर जाने के, (4) समाओं में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के भाषण के लिए सरकारी मंच बनाने पर कानून के अंतर्गत रोक लगे, और (5) मतदान वादों पर कानून के अंतर्गत रोक लगे।

इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने ये सिफारिशें भी की हैं मंत्रियों को चुनाव के उद्देश्य से सरकारी विमानों या गाड़ियों, डाक टिकटों तथा अन्य सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करना (2) सरकार के किसी भी सदस्य को रेडियो या दूरदर्शन पर के लिए निश्चित समय के अतिरिक्त समय न दिया जाये। (3) या सत्ता पार्टी के प्रचार के लिए सरकारी खर्च पर कोई विवर दिये जायें। (4) हेड कांस्टेबल से ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी तथा राजस्व अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश न जारी कि मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आयोग और विशेषरूप शर्मा को यदि अधिकार हो तो वह इन सिफारिशों को खुशी कर देंगे, पर जैसा कि संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं, इस मामले में असहाय है और सरकार का मुँह भर देख सकता है। इन परिधि में आयोग जो कर सकता था, उसने कर दिया है: उसने उपर सिफारिशों के आधार पर 'राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों दर्शन के लिए' आदर्श आचार संहिता प्रकाशित कर दी है।





स्वामित्व को विवाद में उलझा राजमहल

जयविलास महल

## ग्वालियर राजमहल की राजनीति

अश्विनीमोहन श्रीवास्तव

**ग्वालियर**, सिधियावंश का ऐतिहासिक जयविलास महल। यहाँ से सिधियावंश की तीन पीढ़ियों ने शासन किया। आज यहाँ के शासक हैं—सन्नाटा और संदेह। हर नवांगतुक को संदेह की नजर से देखा जाता है। पता नहीं किस का आदमी है, क्यों आया है?

श्रीमती विजया राजे सिधिया के (उन्हें अभी भी राजमाता कहा जाता है) महल में तो हद हो गयी। दरबान ने कहा कि राजमाता और आंग्रे साहब बाहर हैं। किसी जिम्मेदार आदमी से मिला दो—यह सुन कर दरबान साहब चले। उन्होंने लोहे का एक दरवाजा खोला। हमें बाहर चिलचिलाती धूप में खड़ा छोड़ उन्होंने अंदर से पट बंद कर दिये। मोड़ी देर बाद लौट कर उन्होंने फरमाया कि एडीसी साहब सीट पर नहीं हैं। आप ट्रस्ट के इफ्टर में बाबू लोगों से मिल लीजिए। बाबू लोगों ने फिर एडीसी साहब के पास भेजा। अब वह सीट पर थे। मेज पर एडीसियों का ड्यूटी चार्ट था।

“देखिए, मैं आप को कुछ नहीं दे सकता। राजमाता का फोटो भी नहीं। राजमाता के हाल के बयान की प्रति का तो सवाल ही नहीं उठता। यह सब काम आंग्रे साहब देखते हैं। मेरे पास कुछ है ही नहीं और न मैं इस सब के लिए अधिकृत अधिकारी हूँ।”

पर इस का अर्थ यह नहीं कि महल के कर्मचारी बोलते नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है उस से वे, खास तौर पर पुराने कर्मचारी, अव्यक्त दुखी हैं। वे बोलते भी हैं। पर यह विश्वास ही जाने पर कि आप किसी के आदमी नहीं हैं, सब जानना चाहते हैं और नाम नहीं देंगे।

“हम तो राजमाता और महाराज दोनों को जानते हैं। यह आग आंग्रे की लगायी हुई है।

आप अगर राजमाता साहब से मिलें तो तब मिलिएगा जब आंग्रे नहीं हो। वरना कोई फायदा नहीं। जादू सा कर रहा है उन पर।”

पता चला कि श्री जीवाजी राव सिधिया के समय आंग्रे के महल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था।

श्री जीवाजी राव के निधन के बाद अंतिम क्रिया के समय श्री आंग्रे ने महल में प्रवेश किया। श्री माधवराव सिधिया शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गये और इधर आंग्रे साहब राजमाता पर हावी हो गये।

श्री माधवराव सिधिया 1961 से 1968 तक इंग्लैंड में रहे। यह अवधि पूरा प्रभाव जमाने के लिए काफी थी।

आंग्रे का व्यक्तित्व बड़ा विचित्र है। लगभग हर आदमी, यहाँ तक कि उन के सगे भाई भी उन की निंदा करते हैं। नौकर उन के विरुद्ध कुछ कहने में संकोच करते हैं। “वरना भारतेंद्र सिंह वाला हाल हो जायेगा।”

“यह भारतेंद्र सिंह कौन है?”

“है नहीं था, राजमाता का एक विश्वास-पात्र नौकर था। उसके पास आंग्रे के बहुत से रहस्य थे। उसने महाराज से मिलना चाहा। पर महाराज ने सोचा कि आंग्रे अपना आदमी उनमें मिलाना चाहता था, इसलिए उसे नहीं लिया। रायबरेली में जब राजमाता इंदिरा जी के खिलाफ लड़ी थी तो वह रायबरेली गया था। वहाँ कैप में से गायब हो गया। आज तक पता नहीं है। सी. बी. आई. ने पूरी कोशिश की, पर कोई सबूत नहीं मिला। उसकी बीवी आंग्रे के बाड़े में रहती है।”

“आंग्रे के बाड़े में क्यों?”

“आप समझे नहीं। यह मुहल्ले का नाम है। जहाँ वाल आंग्रे (राजमाता के सचिव को इस

नाम से भी जाना जाता है) के भाई भाऊ साहब आंग्रे रहते हैं। ये आंग्रे तो महल में ही पीछे रहते हैं।”

भाऊ साहब आंग्रे ने अपने भाई के विषय में अपने एक संगीत प्रेमी मित्र से कहा, “राजमाता ने बहुत से उल्लूक रखे हैं। उन में से एक मेरा बड़ा भाई भी है।” पता चला कि वाल आंग्रे संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के बाद भाई की संपत्ति में से भी कुछ और हड़पना चाहते हैं। इसलिए भाई नाराज है।

“वैसे प्रारंभ में इनकी कोई खास संपत्ति थी भी नहीं, पर अब काफी है। दो बर्फ के कारखाने इनके हैं। काफी जमीन भी है और फिर राजमाता इनके इशारों पर नाचती हैं।” शहर के अधिकांश फोटोग्राफर उन्हें पहचानते नहीं। महल में अक्सर जाने वाले एक फोटोग्राफर ने कहा, “हो सकता है मेरे कैमरे ने उनकी तस्वीरें खींची हो पर मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। अब कोशिश करूँगा। बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं वह अब।”

राजमाता के विषय में भी बुजुर्ग कर्मचारियों के पास रोचक जानकारी है। महाराज जीवाजी राव की शादी त्रिपुरा की राजकुमारी के साथ तय हो गयी थी। पत्रिका भी बंट चुकी थी। अभी भी कुछ लोगों के पास वह पत्रिका सुरक्षित है। एक ज्योतिषी ने कहा कि यह विवाह नहीं होगा। अंततः विवाह नहीं हुआ। महाराज बनारस गये। ये वहाँ पढ़ती थीं। सागर के डिप्टी कलेक्टर की पुत्री थीं। महाराज को पसंद आ गयीं। महारानी बन गयीं।

बेचारी जमीन पर सोती हैं। पलंग तक नहीं छोड़ा। “अरे साहब, उन का पलंग ठोस चाँदी का है। नहाने का टब भी ठोस चाँदी का है। अभी जो महाराज हैं ना, उनके दादा का है।”

“सूर्या और मेनका गांधी की चर्चा भी महल में है। आंग्रे साहब अपने इस तीर की चर्चा बड़े गर्व से करते रहे हैं। प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता श्री वाकणकर से उन्होंने कहा, “अमृतेश्वर आनंद और मेनका आयीं। उन्होंने कहा: हम सूर्या बेचना चाहते हैं। हम ने खरीद ली।” वे यह भी कहते हैं कि “शिवाजी के जमाने से उन के खानदान के लोग दुश्मन की अगली चाल माँप कर अपनी चाल चलते रहे हैं।” मेनका गांधी की माँ एक समय ग्वालियर के सिधिया कन्या विद्यालय में पढ़ाया करती थीं।

**महल में क्या हो रहा है**, शहर के लोग जानते हैं। पर यह चर्चा का विषय नहीं है। होटलों या पान की दूकानों में आप लोगों को इस संबंध में बातचीत करते हुए नहीं पायेंगे। पर पूछने पर कोई भी आप को बहुत कुछ बता सकता है।

“इस में संदेह नहीं है कि झगड़े का कारण राजनीति है। झगड़ा आपात स्थिति के समय से शुरू हुआ है। जब महाराज नेपाल चले गये थे, राजमाता जेल में थीं। अब वह महाराज को



कांग्रेस (इं) में नीचा दिखाने के लिए महल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सौंपना चाहती हैं।

“स्वयंसेवक संघ को?”

“विद्याभारती क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर क्या है? आर. एस. एस. ही तो है। महल का एक बड़ा हिस्सा ‘गेट कंप्लेक्स’ ‘सरस्वती शिशु मंदिर’ के पास है। वे ट्रस्ट को एक रुपया महीना किराया देते हैं। इसी किराये पर श्री शीतला सहाय (भारतीय जनता पार्टी) ने रंगमहल ले रखा है। वहाँ वह स्कूल चलाते हैं। अब तो पूरा महल विद्याभारती को दान करने की घोषणा हो चुकी है। इतना बड़ा महल मुफ्त में मिल गया तो आर. एस. एस. का हेड क्वार्टर नम्रपुर से उठ कर ग्वालियर आ जायेगा।”

संघ के समर्थकों का दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है—“राजमाता ने 70 लाख में श्री सिधिया का सारा महल खरीद लिया है। अब वे चाहें तो दान कर दें या खोद कर फेंक दें। किसी को इस से क्या फर्क पड़ता है।”

विद्या भारती के केंद्रीय संगठन सचिव हैं।



राजमाता विजया राजे, राजपुत्र माधवराव और सरदार आंग्रे

श्री लज्जाराम तोमर। उनका कहना है कि महल के झगड़े से हमें कोई मतलब नहीं। हम तो दरबार हाल और उस के नीचे के हाल का उपयोग करना चाहते थे। इस के लिए हमने आवेदन किया था।

विद्याभारती का रजिस्टर्ड कार्यालय अभी दिल्ली में ही है—देशबंधु गुप्त रोड, देव-नगर। “यहाँ उद्घाटन 8 अक्टूबर 1981 को हुआ और नवंबर के अंत में हम लोग यहाँ चले आये।”

श्री तोमर ने बताया कि राजमाता उक्त सम्मेलन की स्वागताध्यक्ष थीं। 12 मार्च को अपने स्वागताध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सारा महल दान करने की घोषणा की। श्री तोमर ने बताया कि उन्हें इस पर आश्चर्य हुआ। इस की उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं थी।

इस भाषण की प्रतियाँ पहले से छाप कर वितरित की गयी थीं। अपने छापे हुए भाषण में राजमाता ने कहा: “विद्याभारती ने जो पावन अनुष्ठान आरंभ किया है, उसी में अपना तुच्छ योगदान समर्पित करने के लिए ही मैंने विद्या-भारती से अपना अखिल भारतीय कार्यालय

ग्वालियर में स्थापित करने का अनुरोध किया था तथा इस देश की शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए विद्याभारती ‘भारतीय विद्यापीठ’ जैसी आदर्श संस्था की स्थापना की जो योजना बना रही है उस के लिए संपूर्ण जय विलास प्रासाद को समर्पित करने का अपना विनम्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि ‘विद्याभारती’ ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपना कार्यालय यहाँ आरंभ किया तथा अगली महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित करने के भी प्रयत्न आरंभ कर दिये हैं।”

अपने इसी भाषण में श्रीमती सिधिया ने कहा, “हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि अब तो सिधिया राज परिवार का यह ऐतिहासिक राजप्रासाद ही माता सरस्वती की उपासना का मंदिर एवं विद्याभारती के माध्यम से देश में आने वाले शैक्षणिक परिवर्तन का आधार बनने जा रहा है। अपने पूर्वजों एवं कैलासवासी श्रीमंत महाराज द्वारा स्थापित की गयी आदर्श परंपराओं के अनुरूप हमारे इस राजप्रासाद का इस से अधिक अच्छा और

## अदालत में

**जी**वाजी राव सिधिया के निजी सचिव और सिधिया परिवार के पंद्रह न्यासों में न्यासी कर्नल एकनाथ त्रिंबक पाटील ने जयविलास ट्रस्ट और इस के सभी न्यासियों के विरुद्ध दिल्ली में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद एन. के. शेजवलकर और मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमादेवी सिंह (श्रीमती विजया राजे सिधिया की बहन) की न्यासी के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी है।

7 अप्रैल 1982 को प्रथम श्रेणी सब-जज एस. एल. टंडन ने जयविलास ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा न्यास की संपत्ति बेचने, दान करने, किसी और को उपयोग के लिए देने पर रोक लगा दी है।

संवाददाताओं से कहा कि यह काम उनके पुत्र के किराये के गुंडों का है। वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रसन्न कर के मंत्री बनना चाहते हैं। श्रीमती सिधिया ने यह भी कहा कि सूर्या की खरीद के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

श्री महेंद्र प्रताप का कहना है, “मुझे तो उन्होंने गुंडा कह दिया। यह बताइए मैं क्या करता? हिज हाइनेस की अनुमति के बिना कैसे इस संपत्ति का उपयोग करने देता।”

श्री माधवराव सिधिया सिर्फ इतना कहते हैं, “वह मेरी माँ हैं जो चाहें कहती रहें। मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। परंतु सत्य अधिक दिनों तक नहीं छिप सकेगा।” प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह कहते हैं “हमारा काम तो सिर्फ यह देखना है कि लट्ट नहीं चले। कानून व्यवस्था कायम रहे।”

संग्रहालय के एक कर्मचारी के अनुसार संग्रहालय देखने आने वाले लोग निराश हो रहे हैं। उन्हें अब संग्रहालय के साथ दरबार हाल और बैंकवेट हाल नहीं दिखाये जा सकते। बैंकवेट हाल में ही वह प्रसिद्ध चांदी की ट्रेन है जो चोरी हो गयी थी। नेपोलियन की प्रसिद्ध मेज और विशाल ईरानी कालीन आंग्रे साहब ने उठवा लिये हैं। संग्रहालय में कर्मचारियों के अनुसार इन वस्तुओं की कोई रसीद भी नहीं दी गयी है, जबकि इस से पूर्व श्री माधवराव सिधिया ने संग्रहालय से कुछ वस्तुएँ ली थीं पर उनकी बाकायदे रसीद दी थी।

यद्यपि मामला अदालत में है, पर यह प्रश्न उमर कर सामने आ गया है कि इस संपत्ति को राष्ट्र को सौंपा जाये या एक संस्था को। जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संस्था से संबद्ध नहीं हैं उनके विचार से तो यह संपदा राष्ट्र की ही है। अब देखना यह है कि राजमहल की राजनीति क्या गुल खिलाती है।

आदर्श उपयोग मला और क्या हो सकता था? यह तो वास्तव में कैलासवासी श्रीमंत महाराज के चरणों में हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और उन के पदचिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है।”

श्री तोमर ने कहा, “राजमाता ने पूरा महल खरीद कर उस का ट्रस्ट बना दिया। श्री माधवराव सिधिया ने किरायानामा लिखा कर ट्रस्ट को एक हजार रु. माह किराया देना आरंभ कर दिया। वैसे जो हिस्सा उन के पास है उस का किराया पच्चीस हजार रुपया प्रतिमाह होना चाहिए।”

“आप कितना किराया देते हैं?”

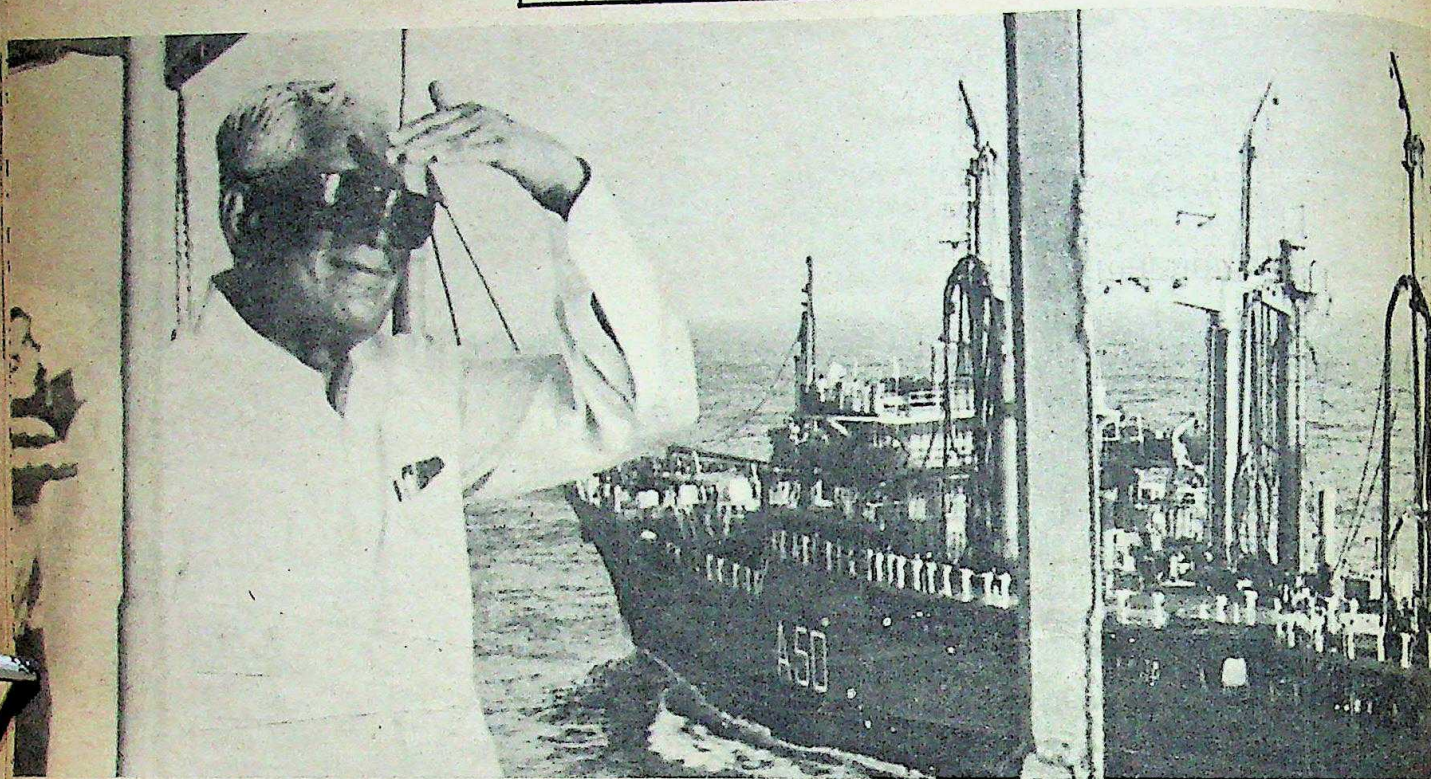
“हमारे लिए तो बिल्कुल मुफ्त है।”

थोड़ा रुक कर श्री तोमर फिर बोले, “पचास साल से इस हिस्से की पुताई नहीं हुई थी। हमने पुताई करायी।”

दान की घोषणा के बाद जब ‘विद्याभारती’ ने दरबार हाल और हाल के उपयोग की अनुमति चाही तो श्री माधवराव सिधिया के सचिव श्री महेंद्रप्रताप ने दरबार हाल सील करा दिया। इस के बाद श्रीमती सिधिया ने



# चित्रों के आईने में



भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने हाल में बंबई तट से 150 किलोमीटर हट कर 'समुद्र पर एक दिन' नामक कार्यक्रम में नौसैनिक अभ्यास किया। यह प्रदर्शन देखने के लिए रक्षामंत्री वेंकटरमण और उपरक्षामंत्री सिंहदेव, छह संसदसदस्यों के साथ, वहाँ उपस्थित थे। चित्र में रक्षामंत्री के साथ नौसेनाध्यक्ष डॉसन मौजूद हैं।

वाहनों के टायर बनाने वाली संस्था 'गुडइयर' ने स्त्रियों के लिए राजधानी में एक स्कूटर और कार रेंली का आयोजन किया। भाग लेने वाली स्त्रियाँ नयी दिल्ली के प्रगति मैदान से सोना झील के लिए रवाना हो रही हैं। (दायें) स्कूटर दौड़ में सुषमा माकिन और मोटर दौड़ में गीता डिसूजा अव्वल आयीं।

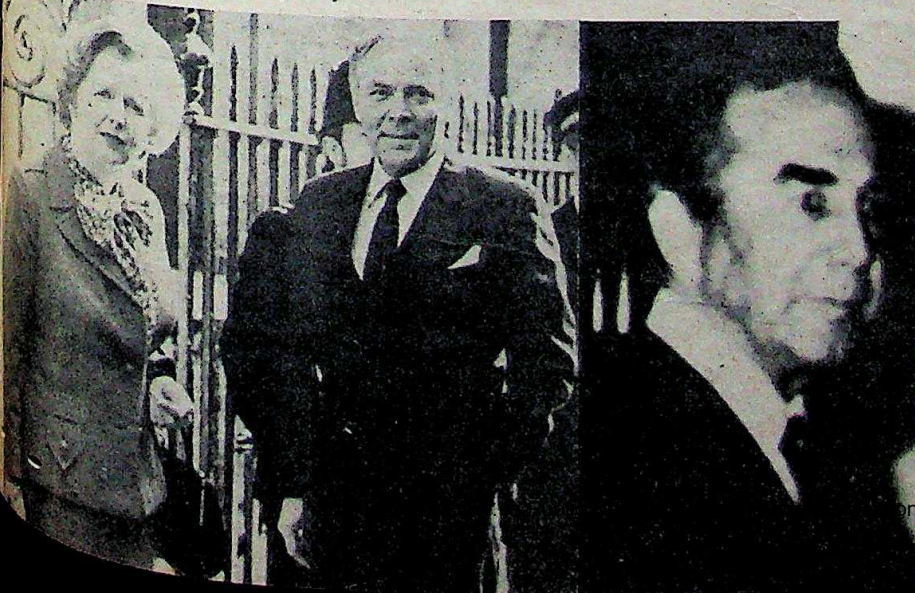
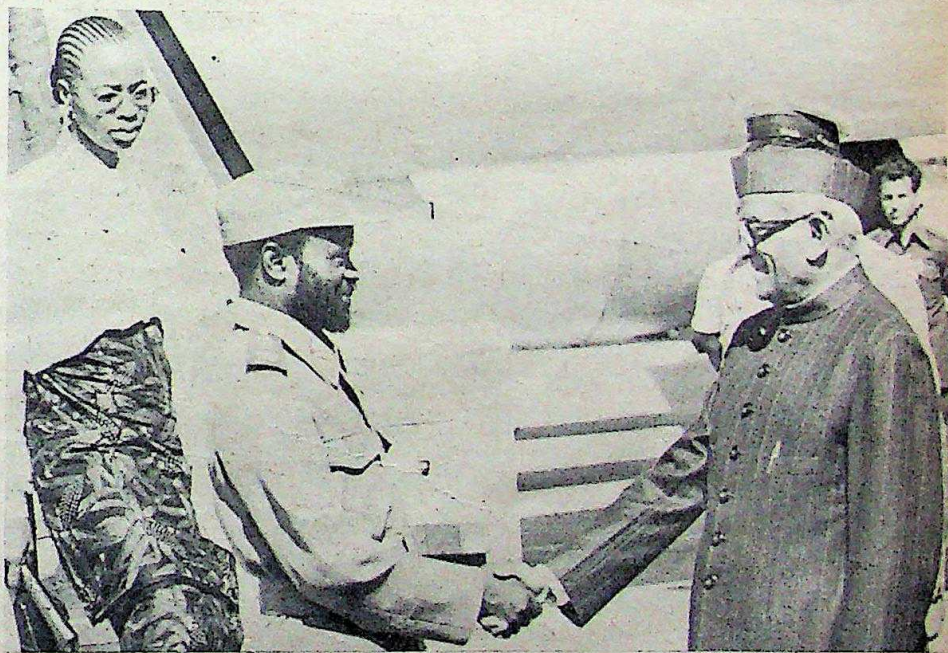


बिहार के गोरखादो गाँव से मिली खबरों के अनुसार कुछ खेतिहर मजदूरों ने जब पारिश्रमिक के बिना काम करने से इनकार किया तो उन के भस्वामियों ने उन की जम कर पिटाई करा दी। बिहार की विधानसभा में इस विषय पर ध्यान न दिये जाने से लगता है कि इस प्रदेश में ऐसी घटनाएँ आम होती जा रही हैं। इन श्रमिकों में से (बायें) देवीलाल, धनमती देवी और चित्ता देव (हरिजन), सुमित्रा देवी (सवर्ण) तथा नरेंद्र मिश्री चिकित्सा के लिए पटना मेडिकल अस्पताल में भरती हुए।





हुडोल (मध्यप्रदेश) से निर्वाचित इका के  
सदस्य दलबीर सिंह के नयी दिल्ली स्थित  
एवम्पू के मकान में 14 अप्रैल को दो  
कंधारी युवक, रामनारायण कुमार और  
कुमारस्वामी ने जबरन प्रवेश कर के पांच  
वक्तियों को बंधक बना लिया। उन्होंने बताया  
कि इस के पीछे उन का मऊसद था सरगुजा जिले  
के सदान मजदूरों की दयनीय दशा पर देश  
का ध्यान आकर्षित करना। बाद में पुलिस ने  
रामनारायण कुमार (दायें से दूसरे) और  
कुमारस्वामी (ऊपर बीच में) को दलबीर सिंह  
के घर से गिरफ्तार कर लिया।  
दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक  
संयोग की संभावनाओं पर बातचीत के  
एक मौखिक के राष्ट्रपति सामोरे माशेल  
एक दिवसीय सद्भावना यात्रा पर भारत आये।  
रात के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने  
उत्तम हवाई अड्डे पर माननीय अतिथि और  
उन की पत्नी का स्वागत किया। (दायें)



आर्हेतीना द्वारा फ्रॉकलैंड पर कब्जा किये  
जाने पर इस द्वीप के भूतपूर्व राज्यपाल रेक्स  
हंट (बायें) ने भाग कर उत्तरे (लातीनी  
अमेरिका) की राजधानी मांटेविडियो के  
कारास्को होटल में शरण ली। फ्रॉकलैंड के  
मुद्दे को ले कर जब ब्रिटेन और आर्हेतीना के  
संबंध बंद से बढतर होते गये तो अमेरिका  
मध्यस्थ बन गया। अमेरिकी विदेशमंत्री  
अलेक्जेंडर हेग ने बातचीत करने के लिए  
ब्यूनोस आयर्स और लंदन के बीच कई  
चक्कर लगाये। ब्रितानी प्रधानमंत्री के लंदन  
स्थित निवास 10, डाउनिंग स्ट्रीट पर अमेरिकी  
विदेशमंत्री और ब्रितानी प्रधानमंत्री मारग्रेट  
थाचर (धुर बायें)



तमिषनाडु

## कन्याकुमारी : तूफान अभी थमा नहीं

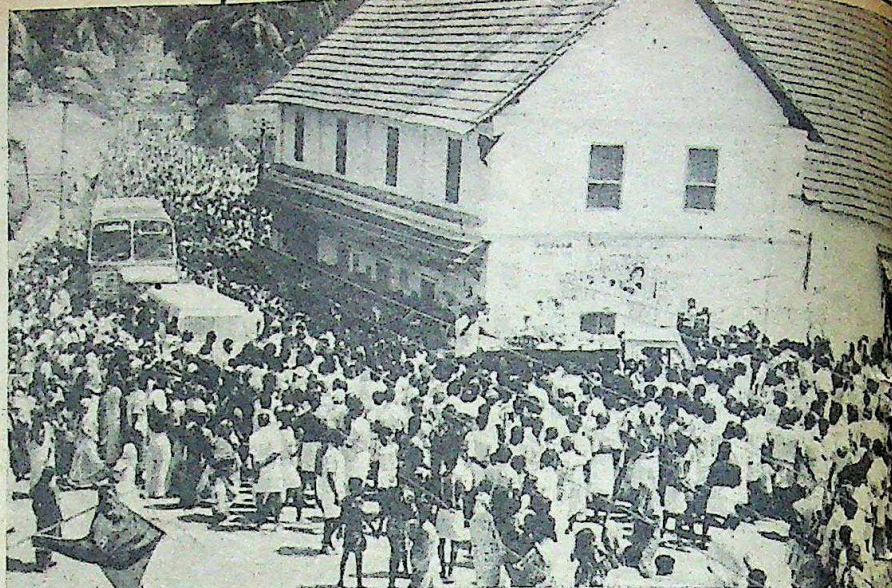
**पाँच** सप्ताह की शांति के बाद 9 अप्रैल को तमिषनाडु के मद्रास के बाद सब से छोटे जिले कन्याकुमारी में फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। उस दिन कालीमार में ईसाई मछुआरों और हिंदू नाडारों के बीच मुठभेड़ हो गयी। जिलाधीश एम. बी. प्राणेश के अनुसार दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, लेकिन किसी के प्राण नहीं गये। दंगे में एक चर्च और एक मंदिर को मामूली सा नुकसान पहुँचा और एक व्यक्ति घायल भी हुआ।

यों तो इसे एक छोटी सी वारदात कह कर नजरंदाज किया जा सकता था किंतु यह सदियों से प्रेम और सद्भाव के वातावरण में रह रहे हिंदुओं और ईसाइयों के बीच गत वर्ष दिसंबर में उमरे और इस वर्ष मार्च में विस्फोटक बने सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी घटना है अतः इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। यह घटना इस लिए भी चिंताजनक है कि इससे हिंदुओं और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने की आशंका पैदा हुई है।

तीन ओर समुद्र से घिरा और विवेकानंद स्मारक के कारण जगप्रसिद्ध कन्याकुमारी जिला (क्षेत्रफल 1684 वर्ग कि. मी.) एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग सदियों से घुलमिल कर रह रहे हैं। यहाँ अनेक परिवार तो ऐसे भी हैं जिनके कुछ सदस्य ईसाई हैं और कुछ हिंदू। इस समय एन. डेनिस लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक ऐसे ही परिवार से संबद्ध हैं। यह जिला कभी कांग्रेस नेता स्व. कामराज नाडार का भी चुनाव क्षेत्र रहा, जिन्हें हिंदू और ईसाई समान रूप से चाहते थे।

लेकिन गये वर्ष दिसंबर में क्रिसमस के आसपास जिले के अनेक स्थानों पर अचानक उपद्रव मड़क उठे थे। इन उपद्रवों में हिंदुओं और ईसाइयों ने एक दूसरे की संपत्ति को नष्ट किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों संप्रदायों के बीच फिर सद्भाव स्थापित करने के लिए शांति समिति गठित की गयी जिसमें स्थानीय सांसद एन. डेनिस, विधायक हेमचंद्र नायर, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे। समिति के प्रयास से तत्काल तो शांति स्थापना में सफलता मिली लेकिन वह तूफान के पहले की शांति सिद्ध हुई।

इस वर्ष एक मार्च को जिले के मंडकाड में स्थिति विस्फोटक हो गयी। 1 मार्च को मंडकाड में अंबन (अंबा) का मेला लगता है जिसमें दूर



कन्याकुमारी में दंगों में हुए विनाश के अवशेष

दूर से यात्री आते हैं। यह इतना प्रमुख त्योहार माना जाता है कि जिले में इस दिन छुट्टी रहती है। मंदिर के सामने एक सड़क है जो जिले के सदर मुकाम नागर कोइल से आती है और कोलाचल तक जाती है। सड़क के दूसरी ओर कोई डेढ़ फर्लांग पर एक गिरजाघर है। अंबा मेले के अवसर पर इसे भी सजाया जाता है। कुछ हिंदू यात्री यहाँ भी आते-जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो यात्री बाहर से आते हैं, उन्हें यहाँ के मछुआरे, जो ज्यादातर ईसाई हैं, स्थान तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन लोग शायद दिसंबर की घटना के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये थे और उस दिन हिंदुओं ने गिरजाघर में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर आपत्ति की। शायद उन्हें अचानक यह लगा कि उससे मंदिर में उपासना के समय व्यवधान पड़ता है। शिकायत पुलिस तक पहुँची और पुलिस लाउडस्पीकर बंद कराने लगी। पुलिस और मछुआरों के बीच कहा सुनी

पुलिस की गोली के शिकार लोगों के शबों को लेकर मौन जुलूस

हो गयी और पुलिस ने गोली चलायी जिस से 6 लोग मारे गये। वास्तव में यह पुलिस और ईसाई मछुआरों के बीच की मुठभेड़ थी किंतु इसने दोनों संप्रदायों के बीच अविश्वास तो बढ़ाया ही।

परिणामतः मछुआरों ने हिंदुओं के सप्ताह स्नान पर आपत्ति की। उन्होंने हिंदूबहुल गाँव इतामडी पर हमला किया। हिंदुओं के मकान दुकानें और फसलें तबाह हो गयीं। बदले में हिंदुओं ने पल्पम पर हमला कर के ईसाइयों के 400 घरों को और स्कूल, चर्च तथा औषधालय को क्षति पहुँचायी। इन घटनाओं से तनाव बहुत बढ़ गया और रात को मछुआरों ने गश्ती पुलिस दल पर पत्थर फेंके, शायद उन्हें यह भ्रम हुआ था कि हिंदू उन पर हमला करने आ रहे हैं। पुलिस ने गोली चलायी और दो लोग मारे गये। स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गयी कि दोनों संप्रदायों के लोग अपने अपने घर छोड़ कर सुरक्षित स्थानों में पनाह लेने के लिए बाध्य हुए।

इस घटना के बाद 15 मार्च को कन्याकुमारी से एक किलोमीटर दूर स्थित कोलम में दोनों संप्रदायों के बीच टकराव हुआ जिसमें दो लोग मारे गये। इन दंगों में देशी बमों का प्रयोग किया गया। बिजली और टेलीफोन की लाइनें काटी गयीं। डाक, जल संभरण और यातायात व्यवस्था में व्यवधान डाला गया। कुल मिला कर इन दंगों में लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति को हानि पहुँची।

लोकसभा में तमिषनाडु के इस जिले के सांसद सदस्य एन. डेनिस ने इन घटनाओं पर अपनी चिंता और दुःख व्यक्त करते हुए विनम्रता से कहा कि "मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि एक ऐसे जिले में, जहाँ साक्षरता का प्रतिशत

अधिक है, घटनाएँ हुईं। लोगों के बीच तनाव पैदा हो रहा है। तत्त्वों और समी ने मंडकाड में न्यायिक व्यवस्था ज़रूरत पड़ने पर लगे आने वाले का जो प्रचार उसे रोका जायग पर भी चाहिए।

एन. डेनिस

डेनिस की पत्नी ने तमिषनाडु के तमिल नाडु में कन्याकुमारी के एक हिंदू मछुआरे को मार दिया है। इस घटना के बाद कन्याकुमारी में दो लोगों की मौत हो गई है। दो लोगों की घायल अवस्था में है। दो लोगों की घायल अवस्था में है। दो लोगों की घायल अवस्था में है।



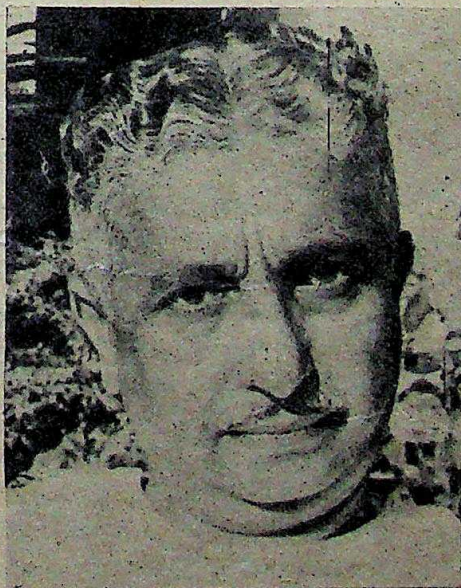
## भाषा विवाद कहीं सांप्रदायिक तनाव का कारण न बन जाये

गोकाक समिति की सिफारिशों को लागू करने की माँग को ले कर कन्नड़ भाषियों ने जो आंदोलन शुरू किया, समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलने के कारण वह उत्तरोत्तर जोर पकड़ता जा रहा है। यदि आंदोलन थमा नहीं तो राज्य के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संप्रदायों के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, गुंडूराव सरकार का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। गोकाक समिति का गठन दो वर्ष पहले इसी सरकार ने किया था और समिति की कक्षा 3 से 10 तक इसी वर्ष जून तक कन्नड़ भाषा को अनिवार्य विषय बनाने से संबंधित सिफारिश को लागू करने का निर्णय भी राव मंत्रिमंडल दो माह पूर्व ले चुका है।

अभी इस निर्णय पर अमल की प्रक्रिया पर विचार ही हो रहा था कि मुख्यमंत्री के एक निकट सहयोगी सांसद एफ.एम. खान ने गोकाक समिति की सिफारिशों को अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध बताते हुए एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। इस की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कन्नड़ भाषियों ने राज्य-व्यापी आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन में अब तक पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे जा चुके हैं और लगभग 50 लोग घायल हुए हैं।

आंदोलन का सब से दुःखद पक्ष यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. के. वी. पुटप्पा तथा अन्य अनेक लेखक-कलाकार और कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता राजकुमार भी उस का खुला समर्थन कर रहे हैं। श्री पुटप्पा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो

कु. वं. पुटप्पा : सिर्फ कन्नड़ तक!



कन्नड़ सीखना नहीं चाहते हैं वे कर्नाटक छोड़कर चले जायें। उनका यह वर्तमान सुचितित न हो कर भावनात्मक ही है क्योंकि उन्होंने गोकाक समिति की सिफारिश के इस पक्ष के दूरगामी परिणामों को नजरअंदाज कर दिया है जिस में प्रथम भाषा के लिए 150 अंक, द्वितीय भाषा के लिए 100 अंक और तृतीय भाषा के लिए 50 अंक निर्धारित किये गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कन्नड़ को प्रथम भाषा माना गया तो अन्य भाषा भाषियों को उसका केवल ज्ञान बल्कि उस में दक्षता प्राप्त करना जरूरी हो जायेगा। यह ऐसी स्थिति होगी जिस में अल्पसंख्यक भाषा समूहों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कन्नड़ फूले फले इस से हमारा कोई विरोध नहीं किंतु अन्य भाषाओं से उनका उचित स्थान नहीं छीना जाना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो कर्नाटक के बुद्धिजीवियों और कलाकारों की भूमिका न केवल प्रशंसनीय नहीं है बल्कि निंदनीय भी है। हैदराबाद से दिनमान प्रतिनिधि श्रीराम शर्मा ने बुद्धिजीवियों और कलाकारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है :

कर्नाटक के बुद्धिजीवियों, लेखकों और कलाकारों ने कर्नाटक सरकार को अति-मेत्थम दे दिया है कि यदि 20 अप्रैल तक गोकाक कमेटी की सिफारिश ज्यों की त्यों लागू नहीं की गयी तो वे असहयोग करेंगे और आगामी नवंबर में आयोजित होने वाले विश्व कन्नड़ सम्मेलन के किसी कार्य में भाग नहीं लेंगे। कर्नाटक राज्य की साहित्य अकादेमी, कला अकादेमी और संगीत नाटक अकादेमी से कवि, लेखक, संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, अभिनेता और चित्रकार त्यागपत्र दे देंगे।

कई ने तो सरकारी संगठनों से संबंध विच्छेद कर लिया है। श्रीमती गंगुबाई हंगल हिंदुस्तानी शैली के संगीत की प्रमुख गायिका हैं। वह राज्य की संगीत अकादेमी की अध्यक्ष थीं। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र ही नहीं दिया। विधान सौध के आगे विरोधस्वरूप किये जाने वाले उपवास में भी वह शामिल हुईं। श्री लक्ष्मीनारायण भट तथा अन्य लेखकों ने केवल गोकाक कमेटी के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए ही नहीं एक बड़े उद्देश्य को ले कर सरकारी संगठनों से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की है। इन लेखकों का कहना है—'कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को शपथ लेनी चाहिए कि वे 20 अप्रैल से किसी ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो कन्नड़ में, केवल कन्नड़ में लिखा या टंकित नहीं होगा।'

15 वर्ष पूर्व कर्नाटक की विधानसभा ने राजभाषा कन्नड़ स्वीकार की थी। इतनी लंबी अवधि के पश्चात् भी शासन का अधिकांश

अधिक है, धर्म और ईश्वर के नाम पर बनाएँ हुईं। इस जिले में विभिन्न धार्मिक वर्गों के लोग वर्षों से मैत्री और सद्भाव के वातावरण में रहते आये हैं। पिछले चार महीनों के वातावरण अशांत रहा और सांप्रदायिक तनाव नष्ट हुआ है। लाखों रुपये की सद्भाव कर दी गयी। पुलिस की गोली से लोगों की जानें गयीं और अनेक घायल हुए। जो बात यह है कि पुलिस समय पर उचित कार्य करने में असमर्थ रही। विभिन्न वर्गों के अतिवादी तत्त्वों और समाज के तत्त्वों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन सभी ने मिल कर यह स्थिति पैदा की। मंडकाड में गोली चलने के बाद सरकार तत्त्वयिक जाँच का आदेश देना चाहिए। जब जरूरत यह है कि विभिन्न संप्रदायों के लोगों को लेकर समितियाँ गठित की जायें और आने वाले समय में उपद्रव न होने दें। जो प्रचार विभिन्न धर्मों के नेता कर रहे उसे रोका जाना चाहिए। लाउडस्पीकों से लोगों पर भी समुचित नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।



एन. डेनिस : कल की चिंता

एन. डेनिस की पीड़ा उचित ही है। देश का वर्तमान नागरिक उनकी इस पीड़ा में बाँटा है। कन्याकुमारी की घटनाओं से सांप्रदायिक सद्भाव को भारी ठेस पहुँची। वेकावू न हो इस के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। कन्याकुमारी के दंगों ने सारे राष्ट्र को बाँटा दिया है। इन दंगों से पहले बड़े फ़क्र हम यह कहते थे कि हमारे मुल्क में दो भाषाओं के बीच कोई वैमनस्य नहीं है। दोनों सदियों से सद्भावपूर्वक साथ रहते आये हैं। ईसाई मिशनरियों की गति-विधियों को ले कर पूर्वांचल में भले ही भारी तनाव मचाया जाता रहा हो किंतु दोनों वर्गों के लोगों के बीच भाईचारा बना रहा। अंग्रेजों ने भाईचारे की इस भावना को धुंधली दी है जिस का सामना सामाजिक और राजनैतिक दोनों ही स्तरों पर किया



कार्य अंग्रेजी में हो रहा है, संस्कृत अतिरिक्त आधारभूत शिक्षा के माध्यम से अमुक घोषणा करती है कि अमुक तिथि से अमुक अमुक कार्य कन्नड़ में होने लगेंगे।

कर्नाटक के बुद्धिजीवियों और कलाकारों का वर्तमान असंतोष शिक्षा की प्रथम भाषा के बारे में सरकारी निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है। हाईस्कूल की परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रथम भाषा के रूप में कन्नड़ अथवा संस्कृत में से कोई भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ती थी। श्री देवराज अर्स जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, 1979 में अनिवार्य भाषा का विकल्प समाप्त कर दिया गया था। हाई स्कूल परीक्षा से संस्कृत की वैकल्पिक अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी थी। प्रथम भाषा की वैकल्पिक समाप्ति से उन छात्रों को बहुत कठिनाई होने लगी, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ नहीं थी। इस तरह के छात्र प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ते थे। कन्नड़ को एकमात्र प्रथम भाषा बनाने के लिए यह तर्क दिया गया कि संस्कृत में छात्रों को अधिक अंक मिलते हैं।

कर्नाटक में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जिनकी मातृभाषा कन्नड़ न हो कर तमिल, तेलुगु अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य भाषा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के दबाव के कारण वर्तमान मंत्रिमंडल ने गत शिक्षा सत्र में दोबारा कन्नड़ और संस्कृत में से किसी एक को प्रथम भाषा अपनाने की सुविधा दे दी।

श्री गुंडूराव के मंत्रिमंडल के संस्कृत वाले निर्णय ने कन्नड़ के पक्षधरों को उद्विग्न कर दिया। जब उन्होंने केवल कन्नड़ की अनिवार्यता के लिए आंदोलन आरंभ किया तो संसद सदस्य श्री खान के नेतृत्व में भाषाई अल्पसंख्यक संगठित हुए। इन लोगों ने जुलूस निकाल कर मांग की कि केवल कन्नड़ को अनिवार्य न बनाया जाये। हाई स्कूल में भाषा की पढ़ाई को ले कर जब कर्नाटक की जनता कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों के रूप में संगठित होने लगी तो मुख्यमंत्री गुंडूराव ने अंग्रेजी और कन्नड़ के प्रमुख लेखक और बेंगलूर विश्वविद्यालय के निवृत्त कुलपति श्री गोकक की अध्यक्षता में एक समिति बनायी। इस समिति ने जो सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार हाई स्कूल परीक्षा में भाषा के दो प्रश्नपत्र रखे जायेंगे। दोनों प्रश्न-पत्र 150-150 अंक के होंगे। पहला प्रश्नपत्र कन्नड़ का होगा। यह प्रश्नपत्र सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रहेगा। दूसरे प्रश्नपत्र में द्वितीय तथा तृतीय भाषा के रूप में छात्र अपनी इच्छा के अनुसार अधिकृत भाषाओं में से किन्हीं दो का अध्ययन करेगा। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत, फारसी या अरबी पढ़ी जा सकती है। तीसरी भाषा के रूप में तमिल, हिंदी, मराठी या इसी तरह की कोई आधुनिक भारतीय भाषा।

गोकक समिति ने सुझाव दिया है कि आरंभ की दो कक्षाओं में केवल मातृभाषा पढ़ाई जाये। तीसरी से कन्नड़ की पढ़ाई आरंभ हो। □

बिनमान

## अब पेड़ों को नहलाया जायेगा

गृहमंत्री ज्ञानी जैलसिंह ने यह इच्छा जाहिर की थी कि दिल्ली में अपराधों की निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ता रहना चाहिए हालांकि उन्होंने इसकी व्यावहारिकता को नजरंदाज नहीं किया था (देखें दिनमान 4-10 अप्रैल)। अब नयी दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक प्राणनाथ बहल ने घोषणा की है कि पालिका क्षेत्र के पेड़ों को नहलाया जायेगा ताकि वे तरबूत बने रहें। घोषणा चौकाने वाली हो सकती है लेकिन जब सभी नागरिकों को पीने का पानी मुहैया न हो पा रहा हो तो इस योजना को व्यावहारिक कैसे माना जा सकता है। इसी तरह पिछले बरस उन्होंने नयी दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क पानी देने की घोषणा की थी। शुल्क तो हटा नहीं, विश्वसनीयता घट गयी। कोई योजना अपने



प्राणनाथ बहल : बिन पानी सब सून

आप में बुरी नहीं होती, प्रश्न उस पर अलम का है।

पेड़ों को नहलाने और निःशुल्क पानी देने की ये योजनाएँ कल्याणकारी हैं, लेकिन तभी सफल हो सकती हैं जब बहुनिकायी दिल्ली को एक साथ ले कर चला जाये। दिल्ली के स्थानीय शासन की देखभाल नयी दिल्ली नगरपालिका के अलावा नगरनिगम और दिल्ली प्रशासन करता है। नयी दिल्ली तो अमीरों की बस्ती है। यह कैसा समाजवाद? आपत्ति सही थी। उपराज्यपाल सुंदरलाल खुराना और निगम आयुक्त प्रमोदप्रकाश श्रीवास्तव ने इस पूरी समस्या पर विचार करने के बाद श्री बहल को अपने फैसले को फिलहाल स्थगित करने का परामर्श दिया है।

नयी दिल्ली नगरपालिका का अपना तर्क है। उस के क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता कम हैं और

वाणिज्यिक उपभोक्ता अधिक। 18 आंकड़ों के अनुसार नयी दिल्ली ने जलप्रदाय से 88,790 लाख लीटर पानी लिया। इस में से 69,910 लाख लीटर बेचा जिस में से 32,190 लाख लीटर घरेलू उपभोक्ताओं ने इस्तेमाल किया कि 37,720 लाख गैलन पानी का वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा किया उपयोग के लिए शुल्क की दरें पहले लीटर के लिए 25 पैसे और उससे ऊपर के पैसे फी किलोलिटर हैं, जब कि संस्थाओं से डेढ़ रुपया फी किलो लीटर लिया जाता है (दिल्ली जल प्रदाय और उपायुक्त ऋषिदेव कपूर के अनुसार)। समय नयी दिल्ली नगरपालिका को गैलन पानी प्रतिदिन दिया जाता पानी रियायती दरों पर मिलता इस के नयी दिल्ली नगरपालिका करोड़ रुपये लेने हैं। इस प्रकार दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में लोगों को मुफ्त पानी दिया जा रहा 30 लाख रुपये ही घाटा होता जो कार्यों को देखते हुए अधिक नहीं। शहरी शहरी में भेदभाव परिलक्षित है, अतः यह योजना कार्यरूप में नहीं लेकिन श्री बहल को विश्वास है कि दिन इस योजना को अमल में लाया यह अमल होता है तो दिल्ली के लोग को खुशी ही होगी लेकिन क्या कभी यह भी सोचा है कि इससे कितना घाटा आयेगा और उसे कैसे किया जायेगा।

जहाँ तक पेड़ों को हरा रखने के लिए के छिड़काव का प्रश्न है इस की लिए महसूस की गयी ताकि नयी हरियाली को बारहों मास एक सा नवें एशियाई खेलों का निर्माण नयी दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में है निर्माण कार्य के कारण बहुत दे देने पड़े। नये पेड़ों को उगाने में लिहाजा पुराने पेड़ पतझड़ का इस लिए रोज सुबह दो घंटे नियमित पानी का छिड़काव इस काम के लिए इटली से एक लाख रुपये की लागत से खरीदी यदि इस मशीन का काम संतोषजनक और मशीनें भी खरीदी जा सकें पेड़ों को नहलाना केवल एशियाई ही सीमित रखा जायेगा? श्री बहल का कहना था कि यह उसी प्रकार जिस प्रकार नवें ओवर आदि का निरंतर इस्तेमाल यह योजना भी शहरी शहरी में सूचक नहीं? इसके उत्तर में श्री हल्का सा मुस्करा भर दिये।





रियाद में युवराज फाहद के साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी

विश्व-भारत

## देश में गैरमुस्लिम देश की स्त्री प्रधानमंत्री

श्रीमती इंदिरा गांधी की साउदी चार दिवसीय (17-20 अप्रैल, 1982) यात्रा कई तरह से महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सप्ताह के लिए एक गैर-मुस्लिम प्रधानमंत्री को कट्टरपंथी शासकों की ओर से सम्मान प्रदान करने का ऐतिहासिक उगाने में मदद मिली है। साउदी अरब के पाकिस्तान के विमानों की खरीद के लिए भारत की यात्रा की काम-काज करने वाले लोगों और टिप्पणी-कार्डों की सफल यात्रा का अफसोस हुआ होगा। श्रीमती गांधी की शान को आन बख्शी। वह अरब पहुँचीं तो पूरी बाँह का हरे रंग की बूटीदार साड़ी पहन कर सिर पर साड़ी का पल्लू हमेशा के लोगो के प्रति श्रीमती गांधी की भावनाओं को सराहा गया। यह है कि उन्हें साउदी अरब की मुलाकात करने का मौका भी मिला।

चार दिवसीय यात्रा के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति से दोनों देशों के नेताओं की ईमानदारी झलकती है। भारत ने खाड़ी के देशों की सुरक्षा और स्थिरता को मान्यता प्रदान की, साउदी अरब ने भारत की दृढ़ अरब नीति का समर्थन किया और आशा व्यक्त की कि बड़ी शक्तियाँ हिंद महासागर से अपनी सैनिक मौजूदगी जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगी। भारत ने पश्चिमेशिया के बारे में साउदी अरब की योजना का भी समर्थन किया। संयुक्त विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता की जिम्मेदारी खाड़ी के देशों की है। लिहाजा विदेशी ताकतों को उस में हस्तक्षेप करने से परहेज करना चाहिए। इस सिलसिले में खाड़ी सहयोग परिषद् के गठन का स्वागत किया गया। अफगानिस्तान के प्रश्न पर संयुक्त विज्ञप्ति में बेबाक लहजा था। अफगानिस्तान से सभी विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए न्यायोचित और व्यापक समझौता किया जाना चाहिए, किसी तरह से बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए तथा उसे गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण राजनैतिक और अंतर-राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को दृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। जहाँ

प्रधानमंत्री सम्राट खालिद और युवराज फाहद से विचारविमर्श में व्यस्त थीं वहाँ वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी और उच्च प्रतिनिधिमंडल इस बात का जायजा लेता रहा कि किस प्रकार साउदी अरब के उद्योगपति भारत में पूँजी लगा सकते हैं। इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली। निकट भविष्य में साउदी अरब के उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल उन संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत की यात्रा पर आयेगा ताकि दोनों देशों में लाम-कारी आर्थिक सहयोग संभव हो सके। दोनों देशों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पुष्ट करने के लिए भारत और साउदी अरब की संयुक्त आयोग की बैठक अक्तूबर में होगी। इस सिलसिले में संयुक्त उपक्रम शुरू किये जायेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में घन लगाया जायेगा तथा साउदी अरब में निर्माणाधीन परियोजनाओं में भारत का योगदान होगा। इस संदर्भ में प्रस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री की युवराज फाहद से 75 मिनट की ब्रेककल्लुफ बातचीत पर कयास लगाये जा रहे हैं।

बेशक साउदी अरब इस समय विश्व में अत्यंत महत्व का देश है। दुनिया में सब से अधिक तेल तो यहाँ पैदा होता ही है, मुसलमानों का यह तीर्थ स्थान है मक्का मदीना होने के नाते। हज यात्री काबा का दीदार कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 21,49,690 वर्गकिलोमीटर में फैले साउदी अरब की 76 लाख की आबादी में बहुमत सुन्नी मुसलमानों का है। 23 सितंबर 1932 से यहाँ पर निरंकुश राजशाही शासन प्रणाली है। यहाँ पर भाइयों की हुकूमत है। भारत और साउदी अरब में पुराने घने संबंध हैं। मक्का मदीना के हज के अलावा भारतीय कमी चिकित्सा की शिक्षा के लिए भी साउदी अरब जाते थे। आज निर्माणकार्य के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। भारत के स्वाधीन होने के बाद साउदी अरब के साथ उस की घनिष्ठता बढ़ी। नवंबर-दिसंबर 1955 में साउदी अरब के स्वर्गीय सम्राट इब्न साउद ने भारत की यात्रा की थी। सितंबर 1956 में जवाहरलाल नेहरू साउदी अरब गये थे। उन के 26 वर्ष बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने साउदी अरब की यात्रा की। भारत साउदी अरब से 25 लाख टन तेल सालाना खरीदता है। भारत के तेल आयात की तुलना में साउदी अरब का भारत से निर्यात एक तिहाई भी नहीं। राजस्थान नहर के लिए साउदी अरब ने 90 करोड़ रुपये दिये। इस समय साउदी अरब में 1,30,000 भारतीय काम करते हैं, ज्यादातर निर्माणकार्य में जुटे हुए हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की वर्तमान यात्रा से दोनों देशों में अधिक घनिष्ठता पैदा होगी।

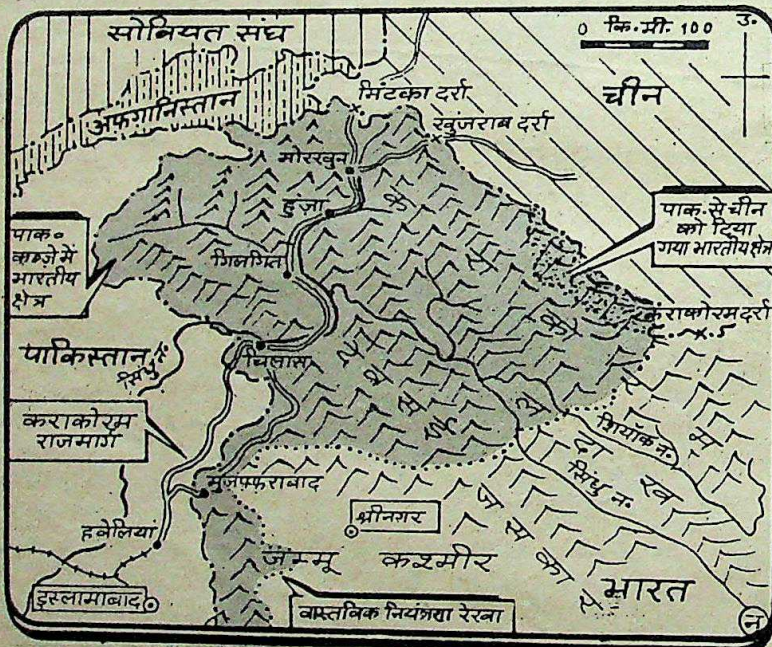


## जिया की 'उत्तरी सरहद'

राष्ट्रपति जिया उल हक ने गिलगित, हुंजा और स्कर्द पर अपना दावा जतला कर भारत और पाकिस्तान के सामान्य होते रिश्तों को फिलहाल रिसा दिया है। उर्दू के एक प्रभावशाली पत्र 'नवा-ए-वक्त' के अनुसार राष्ट्रपति जिया ने इन क्षेत्रों को 'उत्तरी सरहद' करार दिया है। जनरल जिया गिलगित, हुंजा और स्कर्द को 'आजाद कश्मीर' से बाहर मानते हैं और ऐसा पाकिस्तानी नक्शों में दिखाया भी गया है। अभी तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में इन क्षेत्रों का अलग से प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। लेकिन राष्ट्रपति जिया ने स्वनिर्मित 'भजलिसे शूरा' में सरहद के क्षेत्रों से तीन पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दोनों देशों के संबंधों में कटुता को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति जिया के इन दावों के संदर्भ में पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने

लेकिन इस का यह मतलब भी तो नहीं कि कश्मीर समस्या का समाधान भारत की इच्छा के अनुसार ही होगा। उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि अगर भारतीय प्रतिनिधि बलिराम भगत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर टिप्पणी कर सकते हैं तो आगा हिलाली ने उसी टिप्पणी के जवाब में कुछ कह दिया तो इस में परेशानी की कौन सी बात है।

जनरल जिया ने युद्ध वर्जन प्रस्ताव पर भारत की नीयत पर भी शक किया है। भारत संयुक्त आयोग और मैत्री संधि की बात करता है। इस पर राष्ट्रपति जिया की प्रतिक्रिया है: 'भारत यह तो कहे कि उसे युद्ध वर्जन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं, तब वह मैत्री संधि पर बातचीत के लिए तैयार हैं। जनरल जिया के अनुसार अगर भारत युद्ध वर्जन संधि का प्रस्ताव अस्वीकार करता है तो वह वही गलती



पाकिस्तानी विदेशमंत्रालय से स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

यहीं बस नहीं। जनरल जिया ने 'नवा-ए-वक्त' की उस भेंटवार्ता में कहा है कि पाकिस्तान भारत से सभी विषयों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उस में कश्मीर शामिल नहीं। कश्मीर को वह 'अंतरराष्ट्रीय मसला' मानते हैं। जनरल जिया उल हक ने यह कह कर कि शिमला समझौते में यह कहीं दर्ज नहीं कि इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता, अपनी भविष्य की कार्रवाइयों को शायद रेखांकित किया है। वह यह महसूस कर सकते हैं कि कश्मीर के मसले की तुलना फिलिस्तीन, नामीबिया आदि से करने से भारत को कितनी चोट लग सकती है,

दिनमान

करेगा जो पाकिस्तान ने 29 वर्ष पहले की थी।

ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तब गिलगित और स्कर्द उसी का भाग थे। ब्रितानी सरकार ने भी गिलगित और स्कर्द पर कश्मीर के महाराजा की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी। कश्मीर के महाराजा का ही चित्राल, हुंजा, नागर और पुनियाल पर भी अधिकार था। कश्मीर के भारत में विलय से कानूनी और संवैधानिक तौर पर ये सभी क्षेत्र भारत के अधिकार में आ गये।

इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालने से इन क्षेत्रों के बारे में दिलचस्प जानकारी मिलती है। 1880 में सोवियत संघ ने भारत से

‘मैं खुद ही खुले आम कहता हूँ कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ’—जनरल जिया उल हक

(यू. एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में प्रकाशित जनरल जिया से भेंटवार्ता के कुछ प्रश्नोत्तर)

प्रश्न: कुछ आलोचक कहते हैं

आपकी सरकार अस्थायी है, यह व्यक्ति की सरकार है और इसे जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। आप क्या कहना है?

उत्तर: वे ठीक कहते हैं। उन के अनुसार उन के हिसाब से ठीक हैं। अमेरिका, यू.एस. और पश्चिम जर्मनी जैसे जनतंत्र व्यवस्था पसंद लोगों के लिए सैनिक एक रहस्य है।

मैं खुद ही खुले आम कहता हूँ कि चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ। उस दृष्टि मैं अपने आप को लोगों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने चुना नहीं है। यह एक स्वग्रहीत जिम्मेदारी है और तब तक रहेगी जब तक हमें वह सब नहीं दे देते जो हम सोचते कि देश को चाहिए।

आप कह सकते हैं, “तुम कौन होते हो 840 लाख लोगों का कोई खयाल नहीं है? राजनैतिक तौर पर हम एक राष्ट्र हैं। चौतीस साल की उम्र का, राजनैतिक क्षेत्र का अधिक अनुभव नहीं है। हम हिंसा की राजनीति से ही उलझे हैं। यह हमारी अपनी ही करनी थी। हमारा देश भारत तथा सोवियत संघ से टकरा कर आधा हो गया। (1971 युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिया)।

मेरी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में मुगालते में नहीं हूँ। मैं एक सैनिक—शब्दावलि में कहें तो—तानाशाहों में पाकिस्तान का स्वयं शासक हूँ। मैं अपने पश्चिमी मित्रों को और हद तक पाकिस्तान के भीतर के मित्रों भी निवेदन करता हूँ कि वर्तमान प्रणाली की स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए। एक बार काम पूरा हो जाये तो हम यह लोगों के लिए छोड़ देंगे। मैं नहीं ले लिया कि अपनी पूरी एक ही आदमी—जिया उल हक





स्थितियों से निपटता रहेगा। ऐसा नहीं है, मेरी भूमिका सीमित है। एक बार हम लोग सही वातावरण बना लें तो फिर हम आशा करते हैं कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका देंगे और मेरा अंतिम लक्ष्य है—सेना से चुने हुए नागरिक प्रतिनिधियों में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण।

**प्रश्न: क्या आप पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक दखल से चिंतित हैं। उन से पाकिस्तान को क्या खतरा पहुंचता है?**

**उत्तर:** हम सोवियत संघ से पूछते हैं कि अफगानिस्तान में 90,000 सैनिकों को रखने की क्या जरूरत है। उन के पास न तो किसी तरह की खनिज संपदा है और न तेल संपदा। सोवियत संघ के अफगानिस्तान में घुसने के पीछे एक सोची-समझी चाल है। उस का उद्देश्य सिर्फ ईरान को घेरना और पाकिस्तान की सुरक्षा को घमकी देना ही नहीं है।

वह ज्यादा गहरी चाल चल रहा है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। इसलिए सुरक्षा की समस्याएँ पैदा हो गयी हैं। हम दो सालों से तलवार की धार पर चल रहे हैं। हम यह नहीं भूल सकते कि सोवियत संघ एक महाशक्ति है। यह ऐसी शक्ति है जो इस क्षेत्र में सक्रिय है। हमारे यहाँ एक कहावत है, 'अगर आप घूमर में रहते हैं तो शार्क मछली को भूल नहीं सकते।'।

**प्रश्न: क्या चीन के साथ पाकिस्तान को मैत्री उसे सोवियत खतरे के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा देती है?**

**उत्तर:** चीन के साथ हमारे संबंध पिछले तीस सालों से हैं। ये संबंध बहुत महत्व के हैं। यह हमारी विदेशनीति का एक आधार है और यह पारस्परिक हितों पर आधारित है। सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे मन में चीन के प्रति बहुत आदर है। मैं इतना जानता हूँ कि यदि कभी भी पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा तो चीन को खतरा नहीं रहेगा। इस बात की जो

चाहे आप व्याख्या कर सकते हैं।

**प्रश्न: क्या अन्य मुस्लिम देशों के साथ पाकिस्तान का सहयोग किसी इस्लामी सैन्य संगठन की भूमिका है?**

**उत्तर:** नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं है। इस्लाम एक धर्म है, एक मत है। यह किन्हीं भी भौगोलिक सीमाओं या राष्ट्रों में सीमित नहीं है और 'इस्लामिक गुट' जैसी चीजों में शामिल है। आज मुस्लिम देशों के पास ऐसे सैनिक साधन नहीं हैं कि वे किसी तरह की संधि में पड़ें। राजनैतिक संधि की संभावना है। आर्थिक संधि की भी संभावना हो सकती है। पर इस तरह का कोई विचार नहीं है कि इस्लामी देश एक सैनिक संधि करेंगे।

**प्रश्न: पाकिस्तान के आलोचकों का आरोप है कि आप या तो परमाणु शस्त्र बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। क्या यह सच है?**

**उत्तर:** नहीं, मैंने पूरे जोर से यह बात कही है कि पाकिस्तान न तो कहीं से परमाणु बम लेगा और न खुद बनायेगा। पर परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के अपने अधिकार को वह छोड़ेगा भी नहीं।

हमारा देश प्रगतिशील देश है। हमारे साधन सीमित हैं। हमारे पास थोड़ा-सा तेल है। थोड़ी-सी गैस है। पर थोड़ी ही है। हमें (ऊर्जा के) वैकल्पिक स्रोत की जरूरत है और सन् 2000 तक विकल्प के रूप में परमाणु प्रौद्योगिकी की ही व्यवहार्यता रहेगी, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की।

**प्रश्न: एफ-16 विमान मिलने की उम्मीद आपको कब तक है?**

**उत्तर:** अमेरिकी सरकार से अभी कोई ऐसा वादा नहीं मिला है कि वे कितनी जल्दी और कितने विमान भेज रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना को जल्दी से जल्दी नवीनतम विमान देने की बात स्वीकार की है और एफ-16 उन में निश्चित रूप से हैं। अब जो सवाल उठता है वह यह है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी उन्हें खपा लेगा। हमारे खयाल से इस में अधिक से अधिक एक साल लगेगा जबकि वे सोचते हैं कि एक साल से अधिक समय लग जायेगा।

तो, पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान अमेरिका के लिए महत्व की दृष्टि से एक छोटा-सा देश ही सही पर वह है। मेरे विचार से यह अपने मित्रों को सहायता देने की अमेरिका की साख का एक इन्तेहान है। अगर उन्होंने एफ-16 का वादा किया है तो उन्हीं के हित में होगा कि पाकिस्तान को एफ-16 मिलें। □

व्यापार के लिए बरास्त गिलगित-रास्ता खोजा। अंग्रेज फौजों की मदद से जब कश्मीर के महाराजा ने चित्राल जीत लिया तो चित्राल के मेहतार अमानुल मलिक ने 1878 में कश्मीर के महाराजा से एक संधि कर उस की प्रमुखता स्वीकार की। 1885 में कश्मीर के महाराजा ने चित्राल और गिलगित में एक सीमा निश्चित की। 1886 से पहले हुंजा और नागर पर स्थानीय मुखियाओं का शासन था लेकिन 1891 के बाद दोनों ने कश्मीर के महाराजा के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। चित्राल, हुंजा, नागर सभी क्षेत्रों पर कश्मीर के महाराजा अपने एजेंटों द्वारा शासन करते थे। ये सभी महाराजा को नजराना भेंट किया करते थे। भारत के तत्कालीन वाइसराय मिंटो ने जब कश्मीर की यात्रा की तो महाराजा ने चित्राल, हुंजा, नागर और पुनियाल के मुखियाओं को दरबार में हाजिर होने का हुकम दिया। 1946 में शेख अब्दुल्ला के 'कश्मीर छोड़ो' आंदोलन की निंदा करने के लिए महाराजा हरीसिंह ने दरबार लगाया तो इन सभी क्षेत्रों के मुखियाओं ने उस में भाग लिया। जून 1947 में चित्राल के मेहतार ने भी भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन को सूचित किया था कि चित्राल को भारत में शामिल होने की अनुमति दी जाये लेकिन उसे भारत का अंग नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने इसका हमेशा ही विरोध किया। यह विरोध तब तक चलता रहा जब तक पाकिस्तान की नियमित सेनाओं ने गिलगित और हीरानगर पर अधिकार नहीं कर लिया। इस से यह स्पष्ट है कि चित्राल का पाकिस्तान में विलय डरा घमका कर और बेमन से हुआ था। □

पश्चिमेशिया

## सिनाइ से इस्राइल जाये, हम तो नहीं जायेंगे

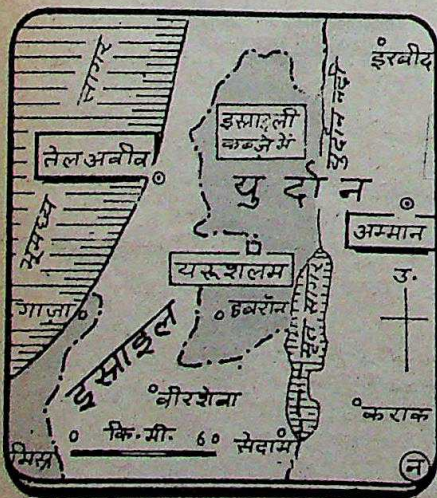
यरूशलम की मस्जिद में इस्राइलियों द्वारा गोली चलाने की घटना को लेकर अभी पिछले सप्ताह समूचे पश्चिमेशिया में एक दिन की हड़ताल रही और अब सिनाइ में बसे यहूदियों के दो धर्मगुरुओं ने घमकी दी है कि इस्राइल भले ही सिनाइ से चला जाये हम सिनाइ छोड़ने के बजाय आत्महत्या करना अधिक पसंद करेंगे। यामिथ नामक उग्रवादियों को 25 अप्रैल तक सिनाइ से चले ही जाना है। लेकिन आत्महत्या की घमकी दे कर अब सिनाइ खाली करने के इस्राइल के रास्ते में नयी पेचीदगियाँ पैदा हो गयी हैं। उधर इस्राइल के रक्षामंत्री अपने ही देश के इन उग्रवादियों को बिना किसी रक्तपात के सिनाइ छोड़ देने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं।



**अरब और मुस्लिम जगत् में आक्रोश !**  
यरुशलम की घटना को लेकर अरब और मुस्लिम देशों में व्यापक हड़ताल से खाड़ी क्षेत्र और पश्चिमेशिया के देशों में कामकाज एक दिन के लिए बिल्कुल ठप्प हो गया था। लेकिन बताया जाता है कि पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी एशिया के लिए अरब देशों से तेल की सप्लाई में कोई बाधा नहीं पड़ी। दक्षिणी लेबनान के फिलीस्तीनी शरणार्थी शिविरों में क्रोध उन्मत्त फिलीस्तीनियों को इस्राइली प्रधानमंत्री के पुतले जलाते देखा गया। सीरिया, लेबनान, यूरान, इराक, साउदी अरब, कुवैत, बहरैन, कतार और संयुक्त अरब अमीरात में तो स्कूल और जलपानगृहों के साथ साथ हवाई अड्डे भी बंद कर दिये गये थे। लेकिन दक्षिण यमन की मार्क्सवादी सरकार ने विद्रोही फिलीस्तीनियों की सहायता के लिए अपने यहाँ काम बराबर जारी रखा और कहीं कहीं तो दो दो पारी में काम हुआ।

इस्राइलियों के मस्जिद में गोली चलाने के विरुद्ध सब से अधिक आक्रोश तो तेहरान में देखा गया। एक विशाल सार्वजनिक सभा में ईरानी नेताओं ने कड़े शब्दों में इस्राइल की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि यरुशलम की मस्जिद की रक्षा की जिम्मेदारी समूचे मुस्लिम जगत् की है। यरुशलम मस्जिद की इस घटना के विरोध में तेहरान में कोई 10 लाख लोगों ने जुलूस निकाला। वॉशिंगटन स्थित इस्लामी देशों के दूतावास भी एक दिन के लिए बंद कर दिये गये थे। केवल मित्र ही ऐसा देश था जहाँ इस घटना को लेकर हड़ताल नहीं हुई।

इस्राइली उपप्रधानमंत्री श्री डेविड लेवो ने पिछले दिनों कहा था कि यदि मित्र कैप डेविड समझौते का पूरी तरह पालन नहीं करता है तो इस्राइल 25 अप्रैल तक सिनाइ से घेरे घेरे हटने की अपनी योजना छोड़ माँ सकता है। राजनैतिक सूत्रों के अनुसार इस्राइली प्रधानमंत्री बेगिन के एक निकटतम सहयोगी का यह पहला वक्तव्य है जिस में इस्राइल ने सिनाइ को खाली करने की शर्त रखी है। पहले तो इस्राइल



ने यहाँ कहा था कि वह यरुशलम को नौवें दिनांक तिथि यानी 25 अप्रैल तक सिनाइ छोड़ देगा। उधर फिलीस्तीनियों और इस्राइल के बीच परस्पर विवाद तय करने के मिश्र के प्रस्ताव को फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन अब भी एक अलग फिलीस्तीन देश की माँग पर अड़ा हुआ है। इस्राइलियों द्वारा सिनाइ खाली करने के निर्णय से भी पश्चिमेशिया की समस्या के समाधान के कोई आसार नजर नहीं आते और अरब देशों और इस्राइल के बीच टकराव की स्थिति दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। □

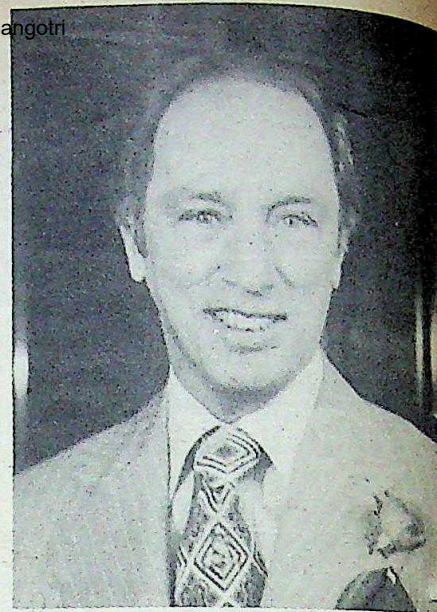
कैनाडा

## नये संविधान का स्वागत

**18** अप्रैल की रात को ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने कैनाडा और ब्रिटेन के बीच मुद्दत से चले आ रहे औपनिवेशिक संबंधों का अंतिम सूत्र खत्म कर दिया। फॉकलैंड संकट के बावजूद साम्राज्ञी ने इस अवसर पर उपस्थित रह कर 300 शब्दों के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर के कैनाडा के लिए एक नये संविधान को स्वीकृति दी। 1931 में स्वाधीन होने के बाद से यहाँ पर ब्रितानी कानूनों को ही संविधान के रूप में मान्यता मिली हुई थी। नया संविधान 18 और 19 अप्रैल के बीच रात को दो बजे से अस्तित्व में आया।

जिस समय साम्राज्ञी एलिजाबेथ कैनाडा की सरकार और राज्यों के साथ मिल कर इस अवसर पर खुशियाँ मना रही थीं उस समय क्यूबेक में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। क्यूबेक के रहने वाले और कैनाडा के रेड इंडियन नये संविधान से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि उन के खयाल में इस संविधान की धाराओं से उन की आशाएँ और आकांक्षाएँ कभी पूरी नहीं होंगी। नये संविधान के स्वागत में आयोजित उत्सव पर क्यूबेक के प्रधानमंत्री रेने लेवेस्क उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी आशंका व्यक्त कर दी थी कि नये संविधान के कारण फ्रांसीसी भाषाभाषी अलग होने की माँग करने के लिए मजबूर हो जायेंगे।

नये संविधान के लिए आवाज दो वर्ष पहले उठायी गयी थी, जब क्यूबेक में जनमत संग्रह के बाद क्यूबेक को इस पार्टी को मात खानी पड़ी थी। लेकिन इस दल ने अपनी हार को दिल से नहीं लगाया और क्यूबेक में पृथक्तावादी आंदोलन को और तूल दे दिया। प्रधानमंत्री ब्रूडो नये संविधान के लिए क्यूबेक के अलावा अन्य सभी राज्यों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। फिर भी उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं अपनी नयी भूमिका निभाते हुए वह इतनी सख्ती न कर जायें कि



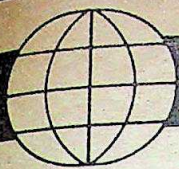
पियरे ब्रूडो : अपना संविधान

उन के शासन के पैरों तले राज्यों की भावनाएँ ही कुचल जायें। केंद्रीय शासन और राज्यों के स्वशासन के बीच संतुलन न बिगड़ने पाये, इस बारे में उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा।

कैनाडा में नया संविधान ऐसे समय में लागू हुआ है जब देश समस्याओं से घिरा हुआ है। आर्थिक मंदी, अत्यधिक बेरोजगारी, हजारों छोटे बड़े व्यवसायों का बंद होना इन सभी से जनसाधारण का ध्यान परे करने का कैनाडा सरकार के लिए यह एक अच्छा मौका है। हाल ही में एक जनमतसंग्रह से पता चला कि वर्तमान सरकार निहायत अलोकप्रिय हो गयी है। उदारवादी प्रधानमंत्री पियरे ब्रूडो हमेशा यह आशा व्यक्त करते हैं कि 'अधिकारों और स्वाधीनता के नये घोषणापत्र' से कैनाडा सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और सारा राष्ट्र एक सूत्र में आवद्ध हो सकेगा। लेकिन बहुत से कैनाडावासी ब्रूडो के इस कथन से सहमत नहीं हैं। उन को आशंका है कि नये संविधान के अंतर्गत ओटावा की सरकार अब राज्यों पर अपना शासन और कड़ा देगी और उन की ओर से लापरवाह हो जायेगी।

कैनाडा की सरकार ने नये संविधान की खुशी मनाने और ब्रितानी साम्राज्ञी एलिजाबेथ की आवभगत में जो करोड़ों डॉलर खर्च किया वह कैनाडा के कर्दातओं के लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन इस के साथ प्रधानमंत्री ब्रूडो की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ था जिस की वजह से उन्होंने देशवासियों की आर्थिक तंगी को नजरअंदाज कर दिया। साम्राज्ञी एलिजाबेथ की भी दबे स्वर में आलोचना हो रही है कि ऐसे समय उन्हें लंदन छोड़ना नहीं चाहिए था जब उन के देश को आहूँतीना से संघर्ष के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। □





एनों रुबिक अपने प्रशंसकों के साथ

## रुबिक क्यूब की लोकप्रियता

हंगरी के वास्तुशिल्प के प्राध्यापक एनों रुबिक ने कुछ दिन पहले गणित से संबद्ध एक ऐसे खेल का ईजाद किया जो आज दुनिया भर में घर घर की चीज़ हो गयी है। एक साथ गुंथे हुए कई रंगों के चौकोरों को, गणित के हिसाब से घुमा फिरा कर, कई समाधान पेश किये जा सकते हैं, जिस के लिए निश्चित ही लगन और अक्ल दोनों की ज़रूरत होती है। रुबिक क्यूब की लोकप्रियता इसी बात से आँकी जा सकती है कि एनों रुबिक विश्वविख्यात तो हुए ही, साथ ही इन की बिक्री से वह रातोंरात करोड़पति बन गये। अब वह एक साँपनुमा खेल के निर्माण की फिराक में हैं और आशा करते हैं कि वह भी रुबिक क्यूब जितना ही लोकप्रिय होगा।

## ताइवान में अमेरिकी पुर्जे

अमेरिकी सरकार द्वारा ताइवान को सैनिक साजसामान के पुर्जे दिये जाने की घोषणा का चीन ने घोर विरोध किया है। चीनी विदेश-मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर के चीन की प्रभुसत्ता पर वार किया है। इसी सिलसिले में चीन ने एक बार अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंधों के स्तर को नीचा करने की धमकी भी दी

थी, लेकिन इस पर अभी तक उस ने अमल नहीं किया है।

## चीन में परिवार नियोजन

कुछ समय पहले तक भी अपने देश में परिवार नियोजन अभियान की सफलता से संतुष्ट चीनी अब चिंतित हो उठे हैं, क्योंकि 1971 और 1979 के बीच उन के यहाँ जो जन्मदर 2.3 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत घटी थी अब फिर बढ़ने लगी है। स्पष्ट ही है कि गत दशक में सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए जो नीति अपनायी थी वह अब कारगर नहीं रह पायी है। उस समय अधिक संतान होने पर आर्थिक दंड और सीमित परिवारों के लिए सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान रखे गये थे। लेकिन लगता है पार्टी के सदस्य तक इसी नीति को नज़रअंदाज़ करते रहे, क्योंकि अब भी अधिकांश परिवारों में पुत्र की ललक बनी हुई है। गुआनडॉङ प्रदेश के एक अधिकारी को पार्टी से इस लिए निकाला गया क्योंकि कि उन की पत्नी ने छह बेटियों के बाद सातवीं बच्ची को यह सोच कर जन्म दिया कि शायद इस बार उसे बेटा प्राप्त हो जाये।

## उत्तर कोरिया के राजनैतिक बंदी

दक्षिण कोरिया के गुप्तचर विभाग के अनुसार उत्तर कोरिया के आठ शिविरों में अभी 105,000

मुकद्दमे के, पड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया के एक प्रवक्ता के अनुसार उन्हें यह खबर उत्तर से भाग कर आने वालों से मिली है। सब से बड़ा शिविर उत्तरी सीमा के पास आनसाङ में है, जहाँ 27,000 बंदी हैं। भाग के आये हुए लोगों का कहना है कि बिजली की तारों से घिरे इन शिविरों के बाहर कड़ा पहरा रहता है। इन बंदियों को सभ्यता से बिल्कुल अलग ही रखा जाता है।

## जर्मनी के बेरोज़गार

पश्चिम जर्मनी के संविधान में ऐसी एक धारा है जिस से विकास-शील देशों के लोगों को बहुत राहत मिली है। यह धारा उन सभी के जीवन की सुरक्षा और आमदनी की गारंटी देती है जो राजनैतिक,



पश्चिम जर्मनी के 'बेरोज़गार मेहमान'

धार्मिक या सामाजिक कारणों से अपने देश में सताये जाते हैं। जब से विकासशील देशों के लोगों को इस प्रावधान का पता चला है तब से भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका के बेरोज़गार बड़ी तादाद में पश्चिम जर्मनी में आने लगे हैं। अब इन की संख्या इतनी अधिक हो गयी है कि जर्मनी के पास "सताये हुए" लोगों को रोज़गार देने के साधन भी तक़रीबन चूक गये हैं। रोज़गार कार्यालयों के बाहर "मेहमान कर्मियों" की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिन के लिए अन्य देशों में जाने के बजाय, बरास्त पश्चिम बर्लिन के, इस देश में प्रवेश पाना सहज है।

## कुत्ते का मांस नहीं मिलेगा

फिलिपीन के राष्ट्रपति मार्कोस ने घोषणा की है कि वह जल्दी ही

कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देंगे। अन्य देश इस देश में कुत्ते का मांस खाये जाने की कड़ी आलोचना करते रहे हैं और इस प्रथा को बंद करने के लिए मार्कोस पर दबाव भी डालते रहे हैं। इस फ़ैसले से विदेशी भले ही खुश हों, लेकिन यहाँ कुत्ते के मांस का व्यापार करने वाले बहुत नाबुख हैं। इन व्यापारियों का तर्क है कि उन के देश में कुत्ते के मांस को स्वास्थ्यकर, पौष्टिक और कामोद्दीपक माना जाता है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि कुत्ते का खून पी कर तपेदिक की बीमारी दूर की जा सकती है।

## पुलिट्ज़र पुरस्कार

अमेरिका में कोलंबिया विश्व-विद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा हर वर्ष लेखन, संगीत और पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं के लिए दिये जाने वाले पुलिट्ज़र पुरस्कार के विजेताओं में इस बार व्यंग्यकार बुचवॉल्ड और कथालेखक अपडाइक के नाम शामिल हैं। बुचवॉल्ड को अमेरिकी समाज पर तीखी और बेवक्र टिप्पणियों तथा अपडाइक को हैरी "रैबिट" एंगस्ट्रॉम पर लिखी कथामाला के तीसरे खंड पर यह पुरस्कार दिया गया।

## 1984 के ओलंपिक

ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार 1984 में होने वाले खेलों का आयोजन लॉस एंजेलस की एक व्यावसायिक संस्था करेगी। इस से पहले यहाँ 1932 में ये खेल हुए थे।

इन खेलों को वापिस अपने यहाँ लाने की कोशिश में था। लेकिन 1972 में म्यूनिख में, 1976 में मांट्रियाल में और 1980 में मस्क्वा में आयोजित इन खेलों को विरोध प्रदर्शन का अखाड़ा बना लेने के कारण मेज़बान देशों के सामने जो दिक्कतें आयीं उन से भी सब अवगत है। इस लिए लॉस एंजेलस के रहने वालों ने कानून में परिवर्तन कर के यह फ़ैसला कर लिया कि नगर परिषद इन खेलों पर कोई खर्चा नहीं करेगा। बल्कि लॉस एंजेलस ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नामक निजी संस्था इन खेलों का आयोजन करेगी।



## खेल और खिलाड़ी

## हाँकी नकली घास पर असली खेल

1976 के मांटीयल ओलिंपिक में जब हाँकी प्रतियोगिता के लिए नकली घास (एस्ट्रो टर्फ) का इस्तेमाल 'प्रयोग' के तौर पर किया गया तब इस प्रयोग की सफलता पर कम लोगों को हो यकीन था। लेकिन यूरोपीय देशों के दिल में इस की कामयाबी पर शक की गुंजाइश कम थी। उन्हें यह मैदान रास आता था, उन के मौसम के अनुकूल था और उन के पैर, जूते और शरीर इस तरह के मैदान के आदी थे। इस में दिक्कत अलबत्ता भारत को अधिक हुई, क्योंकि वे कुदरती घास पर खेलने के अभ्यस्त थे। शुरू में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी मुश्किल पेश आयी।

नकली घास वाले मैदान पहले पहल 1965 में अमेरिका में तैयार हुए। यद्यपि वहाँ पर हाँकी नहीं खेली जाती लेकिन बेसबाल खेलने के लिए उन्हें इस तरह के मैदान की आवश्यकता महसूस हुई। अमेरिका और यूरोपीय देशों में हिमपात होता है, घास की कमी सदैव खटकती है, खुले में खेलकूद की गतिविधियों में अवरोध पैदा होता है, ऐसे



कृष्णदेव थापर (ऊपर)  
और (बगल में) अमेरिकी  
विशेषज्ञ नकली घास का  
मैदान तैयार करते हुए



मौसम में सूर्य की चमक भी कम तपिश देती है लिहाजा इन कठिनाइयों को देखते हुए अमेरिका में शुरू हुआ यह प्रयोग यूरोप भर में फैल गया।

नेताजी सुभाष खेलकूद संस्थान के उप-निदेशक कृष्णदेव थापर के अनुसार नकली घास वाला एक मैदान 15 अप्रैल 1982 को पटियाला में तैयार हो चुका है। दूसरा दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में अप्रैल के अंत तक बिछ जायेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री थापर के अनुसार नकली घास वाले इस मैदान को तैयार करने में पहले एक मीटर नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। उस

के बाद उस में रोड़ी, पत्थर, बंकोट और वजरी डाल कर खूब कूटना पड़ता है। ऐसा हो जाने पर एक बेहतरीन सतह तैयार होती है। उस पर पानी डाल कर यह देखा जाता है कि कहीं पानी ठहरता तो नहीं। यह सतह तैयार हो जाने पर नकली घास का मैदान तैयार किया जाता है। इस में चौथाई इंच मोटी प्लास्टिक और रबड़ की बुनियाद होती है और उस रबड़ पर 5/8 इंच मोटा नायलोन और रेशा चढ़ा होता है। इस तरह का एक लंबा मैदान 15 × 233 फुट का अमेरिका से तैयार कराया गया है। इस पर 51 लाख रुपए खर्च हुए। सभी तरह



## कीर्ति आजाद : 'मुझी में कोई कमी होगी'

मई से इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम की जब से घोषणा हुई है उसने सद्भाव का कम विवाद का अधिक रूप ग्रहण किया है। अभी तक यह विवाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और विभिन्न संघ इकाइयों के अधिकारियों में ही बना हुआ है।

आबू घाबी से दिल्ली लौटने के बाद कीर्ति आजाद से क्रिकेट टीम के चुनाव के बारे में जब प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन का उत्तर था : 'टीम संतुलित है, उस का अच्छा प्रदर्शन होगा, ऐसा मेरा ख्याल है।'

आपको शामिल नहीं किया गया, इस

का रंज नहीं ?

'बुरा तो लगा है। हर कोई देश के लिए खेलना चाहता है।'

आपको न लिए जाने का क्या कारण हो सकता है ?

'शायद मेरे खेल में कोई कमी होगी। मैं उस में सुधार करूँगा और अपने आप को पुनः स्थापित करने का प्रयास करूँगा। और फिर सभी स्थापित खिलाड़ियों को भी तो टेस्ट टीम में शामिल होने में समय लगता है। मैंने चार टेस्ट खेले हैं—एक न्यूजीलैंड के विरुद्ध और तीन इंग्लैंड की टीम के विरुद्ध भारत में। कुल 107 रन ही बना पाया हूँ और एक विकेट ली है बंबई टेस्ट में, जो हम उस शृंखला में एक मात्र मैच जीते थे।'

क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में किसी प्रकार की राजनीति की वृत्ति आती है ?

'देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राजनीति नहीं करता। राजनीति में मेरे पिता जी हैं (कीर्ति आजाद श्रम राज्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद के तीन पुत्रों में सबसे छोटे हैं)।'

23-वर्षीय कीर्ति आजाद ने पहला रणजी मैच 1976-77 में खेला। वर्तमान रणजी ट्राफी की ऐतिहासिक जीत

की खुमारी वह अभी भी महसूस करते हैं। अब क्या करने की योजना के उत्तर में कीर्ति ने कहा : 'आजकल रोज अभ्यास करता हूँ। इस दौरान मैं अपने खेल में ऐसा निखार लाऊँगा कि इस वर्ष नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम में स्थान पा लूँ। मदनलाल को टीम में पुनः लौटने में चार वर्ष लग गये, मुझे इतना समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा बृद्ध विश्वास है।'

क्या भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट देखने के लिए ब्रिटेन जायेंगे ?

'अभी सोचा नहीं। किसी काउंट्री से अनुबंध हो गया तो चला जाऊँगा।'

आप ने बिशनसिंह बेदी और सुनील गावस्कर दोनों की कप्तानी में खेला, आप को कौन अच्छा कप्तान और इनसान लगा ?

'दोनों के अपने अपने गुण हैं। बेशक बिशन दुनिया के महान् स्विपर हैं। उन का कोई सानी नहीं। सुनील गावस्कर भी दुनिया के महान् सलामी बल्लेबाज हैं। वह दिन अब अधिक दूर नहीं जब सुनील गावस्कर की गिनती दुनिया के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में होगी। इनसान दोनों ही भले हैं। मेरा मार्गदर्शन बेदी भी करते थे, सुनील भी करते हैं।'



के भाड़ों के बाद एक मैदान 60 लाख रुपये में तैयार होता है। भारत में दो मैदान तैयार होंगे—एक पटियाला और दूसरा दिल्ली में। नकली घास को तंगे मैदान पर नहीं बिछाया जा सकता। इस में खास किस्म की गोंद होती है जिस के लिए विशेष प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है। इस मैदान को तैयार करने के लिए कारीगर अमेरिका से बुलाये गये। मैदान को तैयार करने के बाद उस पर भारी रोलर चलाया जाता है, ताकि पानी कहीं जमने न पाये। यहाँ तक कि इस मैदान पर सभी तरह के संकेत भी मशीन की सहायता से अंकित किये जाते हैं जो स्थायी होते हैं। आम तौर पर इस तरह के मैदान का इस्तेमाल पाँच वर्ष तक हो सकता है लेकिन यदि इस का रखरखाव ढंग से किया जाये तो दस वर्ष तक आसानी से नकली घास वाले मैदान को उपयोग में लाया जा सकता है। इस के लिए आवश्यक यह है कि इस पर मिट्टी और घूल न जमने पाये। इसे ब्रश से साफ और पानी से धोना बहुत जरूरी है। इस घास के मैदान पर खिलाड़ी तंगे पैर नहीं खेल सकते। ऐसा होने से उन के पैर छिल जायेंगे। इस के लिए खास किस्म के बूटों की आवश्यकता है जिन का आयात किया जाता है। यद्यपि नकली घास वाले मैदान पर फुटबाल, बेसबाल, जिम्नास्टिक ड्रिल आदि भी संभव है तथापि भारत केवल हॉकी के लिए ही इस का इस्तेमाल करेगा। फुटबाल के लिए मंगायें गये मैदान को भी हॉकी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस समय इस तरह के मैदान पाकिस्तान, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ आदि में हैं।

—त्रि. दी.

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें। अपने विषय की विवरणी मंगाइये। कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें। विवरणी हेतु लिखें। इंस्टीट्यूट आफ जर्नेलिज्म (द), पोस्ट बॉक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। विवरणी मंगाइये। पत्रकारिता महाविद्यालय (र), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

विज्ञापन

## युवा जगत

## ‘अश्लील विज्ञापनों पर कालिख पोतिये’

विज्ञापनों में अश्लीलता और स्त्री शरीर के मौड़े प्रदर्शन के विरुद्ध पटना की युवतियों ने गत 5-6 मार्च को ऐसे सभी पोस्टरों और विज्ञापनों पर कालिख पोतने का अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत होटल मौर्य के सामने लगे एक विज्ञापन बोर्ड से की गयी। सिगरेट के इस विज्ञापन में औरत के खुले शरीर के पास गिरते एक पुरुष के हाथ में सिगरेट दिखलाया गया था। फ्रेजर रोड पर 49 फुट ऊँचाई पर लगे अफगान स्तो के विज्ञापन बोर्ड पर नग्न युवती को दिखाया गया था। इस के अतिरिक्त बजाज रेडियो तथा अन्य कई विज्ञापनों के बोर्डों पर कालिख पोती गयी।

यह अभियान 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना में एक तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया था। पहले कार्यक्रम 4, 5 और 8 मार्च को रखा गया था किंतु 5 तारीख को वर्षा हो जाने से 6 तारीख को भी यह कार्यक्रम रखा गया।

4 मार्च को मगध महिला कॉलेज जे. डी. वीमेंस कॉलेज, गंगादेवी महिला कॉलेज में छोटी छोटी सभाओं का आयोजन किया गया। इस के साथ ही चित्र प्रदर्शनी भी लगायी गयी। प्रदर्शनी वर्तमान पुरुषप्रधान समाज में औरत की स्थिति समझाने, औरतों के प्रति एक वैज्ञानिक एवं वास्तविक चेतना देने के उद्देश्य से लगायी गयी थी।

8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को कंकडबाग विस्कोमान झोपड़पट्टी के फूस के स्कूल में औरतों का सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ कॉलेज छात्राओं सहित गांधीनगर में विस्कोमान झोपड़पट्टी की ही एक स्त्री (जुगनी देवी) ने की सभा में 75 स्त्रियाँ थीं।

इस अवसर पर संघर्षवाहिनी के पटना इकाई द्वारा प्रसारित एक पर्चे में कहा गया—‘राजनैतिक आजादी के नाम पर दुनिया के अलग अलग देशों की स्थिति भिन्न है—चाहे साम्यवादी माने जाने वाले देश हों या पूँजीवादी, विकासशील, विकसित या अविकसित देश हों, हर जगह आज भी एक औरत को दूसरे दर्जे की स्वतंत्रता हासिल है। इसकी व्यवस्था करते हुए वक्ताओं ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से रूस, चीन जैसे समाजवादी माने जाने वाले देशों में बेहतर स्थिति होते हुए भी नीति और निर्णय निर्धारण में उन्हें दूसरा दर्जा मिला हुआ है। वहाँ इस तरह की अंतः विरोधों की खबरें भी आती रहती हैं। इस के अलावा एक तथ्य के अनुसार अभी भी घरेलू काम के अतिरिक्त बोझ के कारण 85 प्रतिशत अधिक

काम करना होता है। चीन में ऐसे अंतर्विरोध पर चर्चा चल रही है। आइसलैंड और डेन्मार्क में औरत विरोधी ग्रंथि काफी कम होते हुए भी समाज व्यवस्था ऐसी है कि वेश्यावृत्ति की प्रथा है। पर्चे में आगे कहा गया—उत्पादन रिश्ते की पिछड़ी इकाई में रहने के लिए समुदाय और वर्ग की औरतें मजदूर हैं।

हिंदू धर्म शास्त्र औरत को मनुष्य के नीचे की इकाई मानते हैं। इस्लाम औरतों के रुकावट में कट्टर धर्म है। इस धर्म के आड़ में महाराष्ट्र के कई शहरों में औरतों को सिनेमा हाल तक



पटना में अश्लील विज्ञापन बोर्डों को बेशकल करती हुई युवतियाँ

आने से रोक दिया गया है। औरत के विरोध में धर्म की कट्टरता को राजनैतिक हथियार बनाने का नया अध्याय ईरान और पाकिस्तान में खुला है। ईसाई धर्म में पादरी की जगह के अधिकार के लिए औरत को लड़ना पड़ता है।

युद्ध हो या दंगा आवश्यक परिणाम औरतों पर वीमत्स अत्याचार, बलात्कार में है। यौन शोषण की अफ्रीकी देशों में कड़ी बनी हुई है। कुमार लड़की को पीड़ादायक यौन अंग विच्छेद की अवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अन्य जिलों में भी यही कार्यक्रम किया गया। भागलपुर में नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम हुआ, मधुबनी में प्रदर्शन तथा नुक्कड़ सभा। सीता-मढ़ी में नुक्कड़ सभा की गयी।



साहित्य

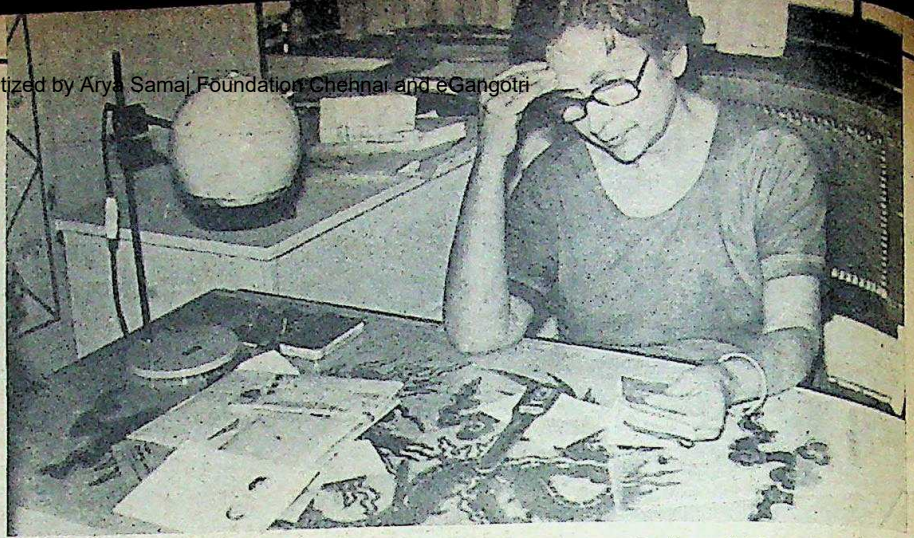
## कागज और कैनवस— शहद का एक छत्ता

नज्म कमी कागज को देखे और यूँ मुँह मोड़े  
ज्यों कागज पराया मर्ब होता है...

—अमृता प्रीतम

इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त अमृता प्रीतम का काव्यसंग्रह कागज और कैनवस 1973 में छपा था। इस संग्रह में एक ओर पंजाबी में लिखी उन की कविता है और वही उस के सामने दूसरी ओर हिंदी में। हिंदी अनुवाद शांता ने किया है। संग्रह इमरोज के नाम है। 155 पृष्ठ के इस संग्रह में निजता की जकड़ से ले कर सामाजिक राजनीतिक पकड़ तक की कविताएँ हैं। आत्मचिन्ता मानवीय चिन्ता से लिपटी हुई है।

अमृता जी की कविताओं को अलग अलग विषयों में बाँध कर के देखना उन के साथ कुछ अन्याय करना होगा। उन का काव्य संसार एक आत्मीय बातचीत के लहजे का संसार है। यह लहजा किसी ओर में नहीं है। उन की इस आत्मीय बातचीत में एक संपूर्ण औरत है—उद्दाम प्रेम से भरी हुई, अपने प्रिय को पुकारती, उस में लय होती, उस की यादों को रोशन करती और अपने चारों ओर की बिखरी दुनिया से अपने रिस्ते को बताती और उस की चोटों पर संकेत करती, चुप लगा जाती और खामोशी में भी बहुत कुछ कहती। अमृता जी मुख्यतया मानवीय प्रेम की ही गायिका हैं। इतिहास, राजनीति, शोषण, अन्याय, युद्ध सब को छू कर वह फिर वहीं लौट आती हैं जैसे बच्चा घर, आँगन, सड़क सब की दीड़ लगा कर फिर माँ की गोद में आ मुँह छिपा लेता है। उन की कविताएँ भोली कविताएँ हैं। कहीं भी बनावट नहीं है। किसी चितक या दार्शनिक का किसी सुधारक या क्रांतिकारी का 'पोज' तो दूर उस 'पोज' की हल्की सी आहट भी उन में नहीं है। उन की काव्य प्रवृत्ति ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिस के बाहर उन का कदम नहीं उठता। उन की दुनिया एक मरीपुरी प्रेम, करुणा और समता से लबरेज आजाद औरत के घर की दुनिया है जहाँ वह हर तरह की बातचीत, हर एक से कर लेने के बाद फिर अपने घर को संभालने लगती हैं। उन की कविताओं की यह सहजता, यह भोलापन, यह थिराया हुआ तनाव, यह आत्मीय स्पर्श, यह खुली हुई अपने प्यार मोहवत, दुख दर्द की बातें, यह दीन जहान की सीधी सादी चिन्ता उन्हें आधुनिक न दिखा कर रोमांटिक



'अमृता प्रीतम : 'तेरी आग की उमरिया इन अक्षरों को लागे!'

मले ही दिखाए लेकिन उन के जादू से इनकार नहीं किया जा सकता है। वह अक्सर अपनी कविता को भी एक अलग व्यक्ति की तरह देखती हैं और उसे प्यार से लिपटा लेती हैं। उन की कविता पर उन के खुले प्यार भरे व्यक्तित्व की छाप है—न उन जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व है, न उन के जैसी किसी ओर की कविता है।

ये कविताएँ एक साथ ही सारे अर्थ नहीं खोलती—अपने पास हाथ पकड़ कर बैठा लेती हैं फिर धीरे धीरे अपनी दुनिया में ले जाती हैं। उन के काव्य बिब और काव्य-प्रतीक सीधे सरल होते हुए भी कहीं गहरे और मजबूत भी हैं इसीलिए काव्यप्रेमी पहले उन की अदा पर कुर्बान होता है और फिर उनके भीतर की अर्थमय शक्तियत से वैध जाता है। कागज पर अक्षर शहद की मक्खियों की तरह हैं और कैनवस पर रंग फूलों की तरह और इस तरह कागज और कैनवस कविता की दुनिया में मधु है जिस में आप भीतर बाहर के आज के किसी भी कड़ुए से कड़ुवे सवाल को मिला कर गले के नीचे उतार सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ युग की कामना कर सकते हैं। संग्रह में उन की कविता की पूरी दुनिया दिखा देना बस की बात नहीं पर कुछ कविताएँ यहाँ पेश हैं—इस आग्रह के साथ कि संग्रह की 'भाता तुप्ता के नौ सपने' लंबी कविता पाठक जरूर पढ़ें।

—स.द.स.

### ऐ मेरे दोस्त ! मेरे अजनबी !

एक बार अचानक तू आया  
तो वक्त बिल्कुल हेरान मेरे कमरे में खड़ा  
रह गया।

साँझ का सूरज अस्त होनेको था, पर हो न सका  
और डबने की किरियत वह मूल-सा गया।  
फिर अजल के असूल ने एक दुहाई दी।  
और वक्त ने उन खड़े क्षणों को देखा  
और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा।

वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना—  
अब तुझे भी एक बड़ा आश्चर्य होता है  
और मुझे भी एक बड़ा आश्चर्य होता है।  
और शायद वक्त को भी फिर वह गलती  
गवारा नहीं,

अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है  
और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है।  
पर बीते और ठहरे क्षणों का एक सच है—  
अब तू और मैं मानना चाहें या नहीं, यह और  
बात है।

पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर  
को भागा  
और उस दिन जो खून उस के घुटनों से रिसा  
वह खून मेरी खिड़की के नीचे अमी तक जमा  
हुआ है...

### एक मुलाकात

कई बरसों के बाद अचानक एक मुलाकात  
हम दोनों के प्राण एक नज्म की तरह काँपे—

सामने एक पूरी रात थी—  
पर आधी नज्म एक कोने में सिमटी रही  
और आधी नज्म एक कोने में बैठी रही

फिर सुबह सवेरे—  
हम कागज के फटे हुए टुकड़ों की तरह मिले  
मैंने अपने हाथ में उस का हाथ लिया  
उस ने अपनी बाँह में मेरी बाँह डाली

और हम दोनों एक संसर की तरह हँसे  
और कागज को एक ठंडे मेज पर रख कर  
उस सारी नज्म पर लकीर फेर दी—

### सफरनामा

गंगाजल से ले कर वोदका तक,  
यह सफरनामा है मेरी प्यास का—  
सादा पवित्र जन्म के, सादा अपवित्र कर्म का,  
एक सादा इलाज



और किसी महबूब चेहरे को एक झलकते  
गिलास में देखने का यत्न  
और अपने पदन से एक बिल्कुल बेगाने लक्ष्म  
की भूलने की शक्ति

यह कितने तिकोन पत्थर है—  
जो किसी पानी के घूँट में गले से उतारे है  
कितने मविध्य हैं जो वर्तमान से बचाये हैं  
और शायद वर्तमान भी—मैंने वर्तमान से  
बचाया है...

सिर्फ एक ख्याल आया है  
कई बार आता है—  
ज्यों कई बार एक सारंगी का गज—  
अचानक किसी राग की छाती में चुभता है.  
या चुपचाप एक पियानो—  
काले और श्वेत दांतों में संगीत चाबता है.

एक ख्याल आता है—  
पर जैसे कोई मौत का एक घूँट मरे  
दरे, और फिर जल्दी से उस ख्याल की कं  
सी करे...  
पर मरे सीनों में भी कुछ साँस जीते हैं  
और अटके साँसों के साथ मैं कह सकती हूँ...  
कि हर एक सफ़र सिर्फ वहीं शुरू होता है  
—जहाँ यह सफ़रनामे खत्म होते हैं.

### मेरा पता

आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है  
और गली के माथे पर लगा गली का नाम  
हटाया है  
और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है  
पर अगर आपने मुझे जरूर पाना है  
तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का  
द्वार खटखटाओ  
यह एक शाप है, एक वर है  
और जहाँ भी आजाद रूह की झलक पड़े  
—समझना वह मेरा घर है.

### अमृता प्रीतम

एक दर्द था—  
जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है  
सिर्फ कुछ नश्वें हैं—  
जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी हैं.

कापल और कैनवस : अमृता प्रीतम, राजकमल  
प्रकाशन प्रा. लि., 8, फैंज बाजार, नयी  
दिल्ली-110002. संशोधित मूल्य 25 ₹.

## हिंदी से हिंदी वालों का मजाक

पिछले सात वर्षों से कलकत्ता में पुस्तक मेले  
का आयोजन किया जा रहा है. यह  
संतोष की बात है कि इस वर्ष हिंदी पुस्तकों  
की भी मेले में भारी माँग रही. लेकिन दुख  
की बात है कि हिंदी के दुर्भाग्य ने उस का  
पीछा इस वर्ष भी नहीं छोड़ा और हिंदी  
पुस्तक प्रेमियों को भारी कठिनाइयों का सामना  
करना पड़ा. हिंदी स्टालों और दुकानों पर  
उन पुस्तकों का भारी अभाव था जिन्हें हिंदी  
प्रेमी खरीदना चाहते थे. ऐसी पुस्तकों में  
शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ और किसी विषय पर  
प्रकाशित विभिन्न खंडों के सेट शामिल हैं.  
मेले में तीन सौ से अधिक प्रकाशकों और पुस्तक  
विक्रेताओं ने भाग लिया जिन में सब से कम  
संख्या हिंदी प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं  
की थी.

पिछले वर्षों की भाँति रूपांबरा ने 'हिंदी  
मंडप' का आयोजन किया था जिस में केंद्रीय  
हिंदी निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,  
नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादेमी, अनेक  
राज्य अकादेमियों और श्रेष्ठ दस प्रकाशकों  
की पुस्तकें उपलब्ध थी. लेकिन उत्तरप्रदेश  
और बिहार में परिवहन संगठनों की हड़ताल  
से केंद्रीय हिंदी निदेशालय और भारत सरकार  
से पुस्तकें मेले में पहुँच ही नहीं पायीं. केवल  
देखने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें रख दी  
गयी थीं. हिंदी निदेशालय के प्रदर्शनी अधिकारी  
अनिल कुमार सुकुल ने बताया कि पंद्रह दिन  
पहले ट्रक से पुस्तकें दिल्ली से कलकत्ता भेजी  
गयी थी लेकिन ट्रक हड़ताल से वे बीच में ही  
अटक रहे गये. वैसे निजी क्षेत्र के अन्य सभी  
प्रकाशकों की पुस्तकें दिल्ली, बंबई, वाराणसी,  
मद्रास और अन्य स्थलों से समय पर ही  
कलकत्ता पहुँच गयी थीं.

एक दिलचस्प बात यह है कि मेले में हिंदी  
वालों के बीच आपस में मिलजुल कर  
कुछ करने की कतई इच्छा नहीं होती. मेले  
का आयोजन करने वाली संस्था 'पब्लिशर्स  
& बुकसेलर्स गिल्ड' के लोग प्रबंध के मामले  
में या तो हिंदी वालों को पूछते नहीं या वे  
खुद ही इन सब 'झमेलों' से दूर रहना चाहते  
हैं. इस का नतीजा यह होता है कि मेले में  
हिंदी पुस्तकों की स्थिति के बारे में किसी को  
ठीक जानकारी नहीं मिल पाती.

मेला आयोजकों के अनुसार मेले में एक  
करोड़ रुपये से भी अधिक की किताबें बिकीं  
लेकिन इस में किस भाषा का कितना अंश है,

यह बतलाना मुश्किल है. वैसे सब से अधिक  
अंग्रेजी की और उस के बाद बंगला की पुस्तकें  
बिकती हैं. संभव है, तीसरा स्थान हिंदी का  
हो. आयोजकों के अनुसार मेले में अंग्रेजी की  
70 हजार, बंगला की 40 हजार और हिंदी  
की 10 हजार पुस्तकें प्रदर्शित थी. लेकिन  
हिंदी के विभिन्न स्टालों से जो आँकड़े बताये  
गये उन के अनुसार हिंदी की पुस्तकों की  
संख्या 30-40 हजार से कम नहीं होगी.

पुस्तक निर्यात प्रोत्साहन समिति (केंद्रीय  
निर्यात प्रोत्साहन समिति के अंतर्गत) के अध्यक्ष  
अशोक कुमार घोष ने संवाददाताओं को बताया  
कि विदेशों में भारतीय पुस्तकों की भारी माँग  
है. इस माँग में हिंदी पुस्तकों का अंश विशेष  
रूप से उल्लेखनीय है. उन के अनुसार चीन  
में प्रेमचंद, निराला और प्रसाद की पुस्तकों  
की भारी माँग है.



मेले में हिंदी मंडप के भीतर

1981-82 में लगभग दस करोड़ रुपये  
की पुस्तकों का निर्यात किया गया है जब कि  
इस से पिछले वर्ष लगभग साढ़े सात करोड़  
रुपये का ही निर्यात हुआ था. अगले वर्ष  
15 करोड़ रु. की पुस्तकों के निर्यात का लक्ष्य  
है. श्री घोष के अनुसार सरकार प्रकाशकों के  
लिए वित्त की व्यवस्था करे और 'नमूने' भेजने  
के लिए उदार नीति अपनाये तो करोड़ों रुपये  
के निर्यात में सहज ही वृद्धि हो सकती है.

अगले वर्ष फिर कलकत्ता में पुस्तक मेले  
का आयोजन होगा. हो सकता है कि वहाँ  
राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जाये  
जिस के लिए अभी से चेष्टा की जा रही है.  
लेकिन अगले वर्ष भी क्या हिंदी का दुर्भाग्य  
उस का पीछा छोड़ेगा?

—मुहम्मद इसराईल अंसारी

25 अप्रैल—1 मई '82





'उत्सवा' में श्री नरेश मेहता, अज्ञेय और दूधनाथ सिंह

## मुझे कहीं से भी यह भ्रम नहीं है कि मैं एक बड़ा रचनाकार हूँ

—नरेश मेहता

गत 13 और 14 मार्च को प्रयाग की हिंदुस्तानी अकादेमी के व्याख्यान कक्ष में एक ऐसा साहित्यिक आयोजन संपन्न हुआ जो कहने को तो श्री नरेश मेहता की षष्ठिपूर्ति के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था, किंतु उस की संपूर्ण भावना, वंदन, अभिनंदन की घिसी पिटी शैली से सर्वथा मुक्त एक गरिमायुक्त साहित्यिक अनुष्ठान की थी। सर्जनात्मकता को केंद्र में रख कर संपन्न होने वाला यह 'उत्सवा' आयोजन पहले दिन सायंकाल स. ही. वात्स्यायन 'अज्ञेय' की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। प्रयाग की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की ओर से श्री नरेश मेहता को मातृपार्षण किया गया जिन में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा. जगदीश गुप्त, जनवादी लेखक संघ के प्रतिनिधि मार्कण्डेय, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री प्रमात शास्त्री, हिंदुस्तानी अकादेमी के संयुक्त सचिव डा. राम जी पांडे, लोकभारती के दिनेश चंद्र और रमेश चंद्र के नाम उल्लेखनीय हैं। तत्पश्चात् श्री नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य संकलन 'तुम मेरा मौन हो' तथा नया उपन्यास 'उत्तर कथा' खंड दो एवं डा. कमल राय की समीक्षा पुस्तक 'नरेश मेहता : कविता की यात्रा' का विमोचन अज्ञेय जी के हाथों संपन्न हुआ।

शुभारंभ के दो शब्द अज्ञेय ने कहे : 'मैं श्री नरेश मेहता की कृति-व्यक्तित्व के प्रति प्रारंभ से ही आस्थावान और श्रद्धावान रहा हूँ। तब भी जब वे बीच में आत्मावसाद के शिकार हो गये थे, मुझे उन की सर्जनात्मक क्षमता पर

पूरा भरोसा था। मुझे प्रसन्नता है कि उस क्षणिक आत्मावसाद के घेरे से वे शीघ्र ही निकल कर सृजन के पथ पर पूरी संभावनाओं को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ते चले गये। अब मुझे विश्वास है कि उन के कृती व्यक्तित्व की मापतोल वर्षों और समय की इकाइयों से नहीं होगी वरन् वे कालजयी कृतिकार के रूप में स्मरण किये जायेंगे। मेरी दृष्टि में महत्त्व इस का नहीं है कि उन्होंने 60 वर्ष पूरे किये वरन् इस का है कि उन्होंने 61 वें वर्ष में प्रवेश किया।'

इस के पूर्व श्री नरेश मेहता ने अपनी रचनात्मक क्षमता की ओर अत्यंत विनम्र शब्दों में संकेत करते हुए कहा कि मुझे कहीं से भी यह भ्रम नहीं है कि मैं कोई बड़ा रचनाकार हूँ, परंतु मुझे इस बात का अवश्य संतोष है कि सारे संघर्षों और कठिनाइयों को झेलते हुए भी मैंने अपनी सृजनात्मक उन्मुखता को इधर उधर बहकने से लगातार बचाया है। सृजन ही मेरा मुख्य सरोकार रहा है, शेष सारी चीजें आनुषंगिक।

कहवा अंतराल के पश्चात् एक छोटी सी काव्य गोष्ठी हुई। जिस में श्री नरेश मेहता, विजय देव नारायण साही, डा. जगदीश गुप्त, उमाकांत मालवीय, लक्ष्मीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह एवं अज्ञेय ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

दूसरे दिन प्रातःकालीन गोष्ठी का विषय था 'समकालीन उपन्यास उपयोग और प्रयोग के बीच।' अध्यक्षता वात्स्यायन जी ने की तथा विषय प्रवर्तन डा. सत्यप्रकाश मिश्र ने। प्रवर्तन व्याख्यान में डा. मिश्र ने कहा कि उपन्यास की दो अतियाँ हम देख रहे हैं एक और वस्तु है जैसे मेरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास, दूसरी ओर शैली और संरचना ही सब कुछ बन जाती है जैसे निर्मल वर्मा के उपन्यास। आज के उपन्यास को इन दोनों अतियों से बच कर वस्तु और शिल्प के स्वस्थतम समन्वय की तलाश करनी होगी।

इस गोष्ठी में डा. राम स्वरूप चतुर्वेदी, मार्कण्डेय, श्रीमती भमता कालिया, डा. विपिन कुमार अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वर्मा और अज्ञेय ने अपने विचार प्रकट किये। अज्ञेय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विषय से वे सहमत नहीं हैं। 'कोई भी उपन्यास उपयोग से मुक्त नहीं होता न उसे करना उचित ही है। इसी प्रकार कोई भी उपन्यास केवल प्रयोग नहीं होता, न वह प्रयोग से मुक्त होता है। ऐसा विभाजन एक कृत्रिम विभाजन है।' विपिन कुमार अग्रवाल ने कहा कि कविता की भाषा में थोड़े से चमकते हुए शब्दों से काम चल जाता है। कविता ढेर सारे जीवन संदर्भ के शब्दों को रद्द कर के भी लिखी जा सकती है।

जैसे नरेश मेहता की काव्य भाषा की ओर उन्होंने संकेत किया। परंतु वे ही नरेश मेहता जब उपन्यास लिखते हैं तो बहुत कुछ रद्द किया हुआ शब्द भंडार उन्हें उपयोग में लाना पड़ता है। अज्ञेय ने डा. अग्रवाल की इस टिप्पणी को अधूरी टिप्पणी मानते हुए कहा कि दूसरी ओर बराबर यह भी होता है कि गद्य की भाषा से हम शब्दों को नया संस्कार दे कर कविता में बारंबार प्रयोग कर के उस में नयी अर्थ व्यंजनाएँ भरते रहते हैं।

दूसरे दिन संध्य की गोष्ठी बड़ी ही उत्तेजनापूर्ण रही। विषय था कविता की सांस्कृतिक शोध। विषय का प्रवर्तन डा. रामकमल राय ने किया। उन का कहना था कि मनुष्य का विकास जब पशुता से हुआ तो उस ने बहुत से नये गुणों को अर्जित किया तो पशु के पास नहीं थे, जैसे क्षमा, संयम, प्रेम, करुणा आदि। दूसरी ओर पशु सुलभ प्रवृत्तियाँ भी मनुष्य में बनी रहीं जैसे क्रोध, प्रतिकार, हिंसा, सेक्स, प्रतिद्वंद्विता आदि। इन प्रवृत्तियों से शुद्ध मानवीय प्रवृत्तियों की ओर विकास की दिशा ही संस्कृति की दिशा है। भाषा और फिर कविता इस सांस्कृतिक परिणति को संपन्न करने के सब से बड़े तत्त्व रहे हैं। मन के आह्लाद और शरीर की भूख को एकरस कर के सुसंस्कृत मनुष्य के निर्माण के क्रम में कविता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस स्थापना से सब से अधिक असंतोष रहा जनवादी लेखक दूधनाथ सिंह को जिन्होंने इसे 'भ्रष्ट दिमाग की भ्रष्ट उपज' की संज्ञा दी। दूधनाथ सिंह के पश्चात् लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा कि संघर्ष केवल वही नहीं है जिसे दूधनाथ सिंह समझते हैं। ईसा मसीह के जीवन में भी गहरा संघर्ष रहा है यद्यपि उन्होंने किसी से हाथापाई नहीं की। तत्पश्चात् अज्ञेय ने कहा कि संस्कृति के विषय में उन के विचार सुपरिचित हैं। संस्कृति जिन मूल्यों को ले कर बनती और विकसित होती रहती है वे यद्यपि बदलते भी हैं परंतु जब तक वे मान्य रहते हैं उन के प्रति पूर्ण निष्ठा से आग्रहशील रहना ही संस्कृति का आग्रह है। भाषा निश्चय ही मानवीय संस्कृति को सब से श्रेष्ठतम उपलब्धि है और कविता मनुष्यता को समृद्ध करने का सब से बड़ा कर्म है। अध्यक्षीय टिप्पणी में डा. जगदीश गुप्त ने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एक साफ सुथरी बात को 'भ्रष्ट दिमाग की भ्रष्ट उपज' घोषित किया गया। जगदीश जी ने पूछा—कि उदारता या करुणा से इतनी चिढ़ क्यों है? संघर्ष का इतना अवमूल्यन क्यों?

इस प्रकार श्री नरेश मेहता की षष्ठिपूर्ति के अवसर पर आयोजित यह साहित्यिक आयोजन अपनी पूरी गरिमा से समाप्त हुआ। इस आयोजन में नगर के सभी प्रमुख साहित्यकारों ने भाग लिया।



कला

## उसका नाम तो 'आज' है

हम कई मूलों और कई कमजोरियों के अपराधी हैं। लेकिन हमारा सब से बड़ा अपराध बच्चों की ओर से उदासीन होना है जो कि जीवन का स्रोत हैं। हमारी कई जरूरतें प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन बच्चा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यही वह समय है जब कि उस का शरीर रूप ग्रहण कर रहा है, उस का खून दौड़ रहा है, उस की संवेदनाएँ विकसित हो रही हैं। हम उस से यह नहीं कह सकते कि 'कल' उस का नाम तो 'आज' है—(स्व.) नोबेल मिस्त्राल। चिले की नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री की यह उक्ति पिछले दिनों रवींद्र भवन दीर्घाओं (नयी दिल्ली) में आयोजित विश्व के बच्चे नामक छायांकन की एक बड़ी प्रदर्शनी के परिचय पत्र में शामिल

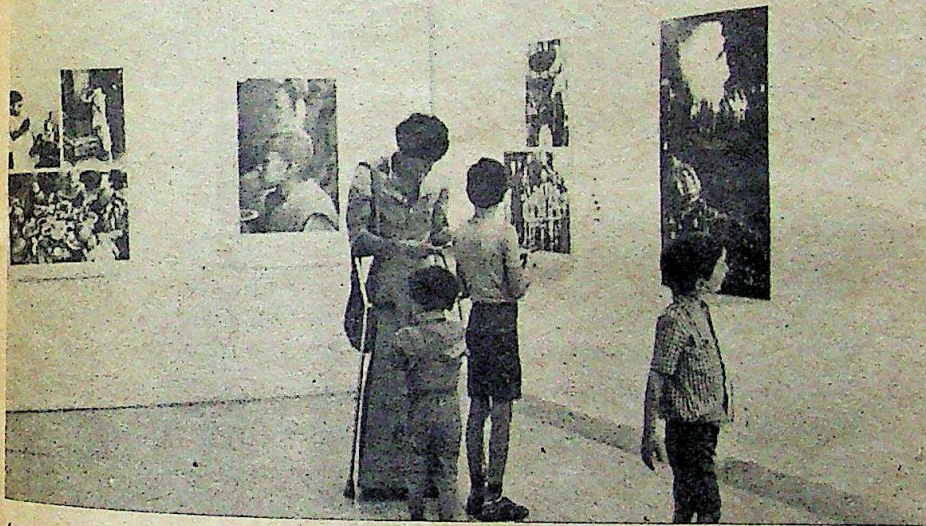
प्रेम और हमारी क्रूरता से बेखबर अपनी स्वतंत्र दुनिया बनाते हैं। खेलकूद की, उमंग की, प्रकृति के साहचर्य में जीने की, एक अद्भुत जीवनी शक्ति की।

इस प्रदर्शनी की तस्वीरें पश्चिम जर्मनी की पत्रिका 'स्टर्न' ने एकत्र की हैं और यहाँ इन को प्रदर्शित किया है मैक्स स्मूलर भवन ने। प्रदर्शनी में कुल 515 चित्र हैं। अधिकतर सादे हैं, कुछ रंगीन भी। प्रदर्शनी के परिचय पत्र में छायाकारों का नामोल्लेख तो नहीं है लेकिन कई तस्वीरों की कलात्मकता या दृष्टि यह भी बताती है कि वे 'यों ही' या बेतरतीब ढंग से खींची गयी तस्वीरें नहीं हैं। इन में कई छायाकारों की आँखों और मन का एक संवेदनात्मक स्पर्श भी है। प्रदर्शनी को कई हिस्सों में बाँटा गया है—'ये सब हमारे बच्चे हैं', 'युद्ध के शिकार बच्चे', 'श्रमिक बच्चे',

'अपंग बच्चे', 'बच्चों की दोस्ती', 'खेलते हुए बच्चे' आदि शीर्षकों में। इन तस्वीरों के बहाने कहीं वह दुनिया भी दीख जाती है जो बड़ों ने बच्चों के लिए बनायी है। और कई चित्र बड़ों की बनायी इस दुनिया पर मामूली टिप्पणी भी करते हैं। प्रदर्शनी को दरअसल दो तरह से देखा जा सकता है: एक तो इस तरह कि हम इस प्रदर्शनी के बहाने बच्चों के जीवन के विविध रूपों में प्रवेश करें, दूसरे इस तरह कि हम कुछ ऐसे चित्र चुन लें जो इस प्रवेश को अधिक अर्थपूर्ण और मर्मस्पर्शी बनाते हों। संभवतः इन दोनों ही रूपों में हम इस प्रदर्शनी को देख सकते थे। इतनी बड़ी प्रदर्शनी में जाहिर है कि बच्चों की एक बड़ी दुनिया सामने आयी। यह किसी भी दर्शक के लिए चाहे 'नयी' न हो, क्यों कि अंततः तो ये तस्वीरें जीवन से ही ली गयी हैं और बच्चे, चाहे फिर वे किसी भी देश के हों, हैं तो आखिर बच्चे ही; और बचपन की समस्याएँ भी अगर सब जगह एक जैसी नहीं होती तो कमोवेश एक जैसी तो होती ही हैं, लेकिन कई चित्र हैं जो स्मृति में अटके रह गये हैं। ऐसे चित्रों में से एक सड़क तक फैली हुई जूते सुधारने की दुकान का है, जिस में एक बच्चा अपने जूते ले कर आया है और उसी के साथ आये हैं उस के कई साथी। वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहीं फटे पुराने जूतों का अंवार भी है। एक साथ बहुत सी चीजें कह रहा है यह चित्र। एक चित्र जेल जीवन का है जहाँ पिता से मिलने बच्चे आये हैं। इसी तरह एक चित्र मृत्यु के प्रसंग का है। ये वे प्रसंग हैं जहाँ बच्चे एकाएक बड़े हो जाते हैं। श्रमिक बच्चों के चित्र तो मानों उन के बड़े होने को कई कई अर्थों में दिखाते हैं। जहाँ न केवल वे बड़ों जैसा बोझ उठा रहे हैं, बल्कि इस बोझ को उठाते उठाते मानसिक रूप से भी असमय 'वयस्क' हो रहे हैं।

प्रदर्शनी बच्चों के जीवन को इतने विविध रूपों में दिखाती है कि मानों हम एक साथ स्मृति, स्वप्नों-दुःस्वप्नों, प्रेम, कोमलता, सौंदर्य, साहस, रोग, शोक आदि के कई कई अनुभवों से गुजरते हैं। और प्रदर्शनी में ही अपने लिए फिर एक बार इस उक्ति की खोज करते हैं कि 'जब तक दुनिया में एक भी दुखी बच्चा है तब तक बड़े से बड़े आविष्कारों और विकास का कोई अर्थ नहीं है।' (अल्बर्ट आइंस्टीन)।

एक विषय को केंद्र बना कर आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों की कमी नहीं रही; लेकिन यह प्रदर्शनी कहीं यह भी बताती थी कि एक केंद्रीय विषय के रूप में यह और ऐसी ही प्रदर्शनियाँ कितनी जरूरी हैं। क्यों कि जीवन में तो हम कई बार बहुत सी चीजों को अनदेखा कर देते हैं लेकिन यहाँ जीवन के प्रतिरूपों को अनदेखा न कर सकेंगे और इन चित्रों को देखते हुए अर्थपूर्ण ढंग से फिर जीवन से ही जुड़ेंगे। □



(ऊपर) घना के एक गाँव में मिट्टी के घर की देहरी पर एक स्त्री अपने बच्चे के साथ (नीचे) प्रदर्शनी में ही: बच्चे और बच्चे

की गयी है जो कि इस संदर्भ में भी कई तरह से सटीक है।

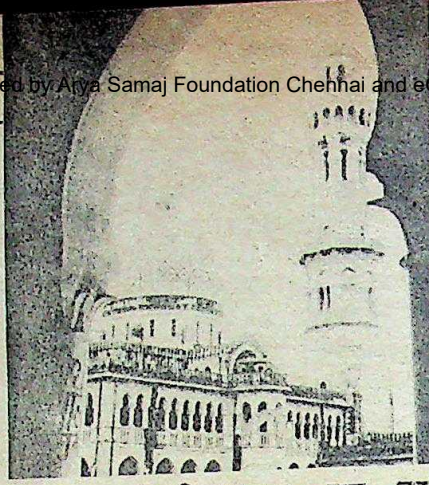
इस प्रदर्शनी में विश्व के कई देशों के बच्चों की तस्वीरें हैं। उन देशों के बच्चों की तस्वीरें जिन्हें विकसित कहा जाता है, और उन देशों के बच्चों की तस्वीरें जिन्हें विकासशील कहा जाता है या कि जिन्हें तथाकथित तीसरी दुनिया के खाने में डाल दिया जाता है। इन में से प्रायः सभी देशों के कुछ ऐसे बच्चों की तस्वीरें हैं जो उन के प्रति हमारी उपेक्षा, उदासीनता, यहाँ तक कि क्रूरता की कहानी कहते हैं। (हाँ, यह कुछ विचित्र जरूर है कि ऐसी तस्वीरें तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों से ही ज्यादा चुनी गयी हैं!) लेकिन इसी के साथ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो ममता, लगाव और उन के प्रति हमारे प्रेम को रेखांकित करती हैं। वे तस्वीरें भी हैं जिन में मानो वे हमारे





## विश्वविद्यालय में संगीत आयोजन कितने सार्थक हैं?

केशवचंद्र वर्मा



इलाहाबाद का विजयनगरम हाल जहाँ  
संगीत सम्मेलनों की शुरुआत हुई

**क्रमशः** लुप्त होती हुई अपनी गरिमा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पिछले दो तीन वर्षों में जो कष्टसाध्य जोखिम उठाये हैं—विगत 27-28 फरवरी को आयोजित संगीत सम्मेलन भी उसी क्रम की एक सामान्य कड़ी था। कुलपति और विद्यार्थियों के अखंड संघर्ष के तनावपूर्ण वातावरण में संगीत सम्मेलन किसी तरह 'निर्विघ्न' समाप्त हो गया।

तनाव का यह तृतीया स्वामाविक था कि सम्मेलन के आयोजक कान पकड़ते कि अब दुबारा वे इस आयोजन को नहीं करेंगे। हुआ भी यही। यह उस विश्वविद्यालय में हुआ जो एक समय पूरे देश में संगीत सम्मेलनों का आयोजन करने में अग्रणी ही नहीं दिशानिर्देशन करता था। कलाकारों के संबंध में इसी विश्वविद्यालय के निर्धारित किये हुए प्रतिमान पूरे देश में मान्य होते थे। उस सम्मेलन की मुहर लगे बिना किसी कलाकार को ख्याति मिलना दुष्कर था। इस सम्मेलन की गरिमा और प्रतिष्ठा निमित्त करने में देश के बड़े कलाकार, कलावंत, गुनीजन, रसिक समाज, वरिष्ठ विद्वत् समाज ही नहीं बड़े बड़े कलापारखी, राजे रजवाड़े, देशी और विदेशी अफसरशाही एक साथ शामिल होते थे और इसी संगीत सम्मेलन में टिकट खरीद कर अपनी सीटें छह हफ्ते पहले ही रिजर्व करा कर सात आठ दिन तक भारतीय संगीत के माहौल में डूबते उतराते थे।

उसी विश्वविद्यालय में अब उसी गोरव-शाली परंपरा के बावजूद इस संगीत सम्मेलन का यह आलम था कि उसी संस्थान के वरिष्ठ अध्यापक तक इस सम्मेलन में झांकने नहीं आये। कुलपति भी अपने घेराबंदी की फिर में डूबे उस माहौल से कटे हुए रहे। विद्यार्थी को अभी यह संस्कार दिया ही नहीं गया कि उसे सही संगीत सुनने की कोई महत्वाकांक्षा हो। टिकट लगाना और प्रवेश पर रोक टोक लगाना आयोजकों के लिए अग्निपरीक्षा ही होती है। सब कुछ मिला जुला कर ऐसे आयोजन करने दिनमान

वालों के लिए सरकारी भीख पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अफसरों और बाबुओं की मिलीजुली संस्कृति अपने अपने लालफीताशाही के प्रताप से ऐसे आयोजनों में पहले तो धन देने से ही इनकार करती है यदि कहीं पसीज कर कुछ दे भी दिया तो वह उखड़नी सांस के उन अंतिम क्षणों में मिलता है जब न तो उस के आधार पर किसी अच्छे कलाकार को समय रहते बुलाया जा सकता है और न बाद में उस धन का कोई दूसरा उपयोग ही संभव हो पाता है।

इस तरह के सम्मेलन एक बड़े सवाल की तरफ ध्यान खींचते हैं? क्या महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में संगीत सम्मेलनों की कोई सार्थक भूमिका है या वे केवल निरर्थक सस्ते मनोरंजन का पर्याय मात्र हैं? शिक्षा शास्त्रियों को इस दिशा में सोचना कारगर होगा कि कालांतर में सही और सार्थक संगीत सुनने का अभ्यास व्यक्ति को भीतर से कितना संस्कारवान बनाता है और उस का असर व्यक्ति की अपनी नैतिकता को गढ़ने में कितनी दूर तक सहायक होता है।

विश्वविद्यालयों के महागुरु को भरने की जिम्मेदारी आखिर किस की है? किसी बहुत बड़ी सीमा तक क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नहीं है? क्या उस का काम सिर्फ प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ या पद संख्या बढ़ाना—तथाकथित 'रिसर्च' के नाम पर उन के अनुरागियों की अभिवृद्धि और अध्यापकों की जातिगत निजी राजनीति पर 'रेवडी वांट' नीति से अपनी मान्यता की मुहर लगाना ही नहीं हो कर रह गया है? क्या विश्वविद्यालय में रहने वालों को भारतीय संस्कृति की सही पहचान कराना उस के वृहत्तर उद्देश्यों में नहीं है? क्या यह पहचान इस देश का एक सही नागरिक बनाने में सहायक नहीं होगी? यदि इस का कोई उत्तर इस के पक्ष में आता है तो ऐसे आयोजनों की कोई मान्य योजना क्यों नहीं सामने आती?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—विश्व-

विद्यालय के कानून या अधिनियम कहीं भी इसे अपनी सोच का अंश बनाते तो पहिया दूसरी तरफ घूमने लगता। आज जिन छोटे छोटे आयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के उत्साही आयोजक राजधानियों की दौड़ लगाते और चंद हजार रुपये प्राप्त करने में अपना वक्त बरबाद करते हैं वह काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमित ढंग से अधिक साधन जुटाने की एक व्यवस्थित योजना बना कर सिद्ध कर सकता है। ऐसे आयोजनों की एक शृंखला बना कर बड़े कलाकारों को बुलाया जा सकता है ताकि वे एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालय में अपनी प्रस्तुतियाँ विश्वविद्यालय के परिसर में ही प्रस्तुत कर सकें। इस में कलाकारों को भी आने में और अच्छी आर्थिक सहायता मिलने में सुविधा हो सकती है। कलाकारों को भी एक प्रदेश के—एक क्षेत्र के सांस्कृतिक जागरण से नया साक्षात्कार हो सकेगा। उन्हें यह भी बोध होना जरूरी है कि वे नयी पीढ़ी को तैयार करने में अपना योगदान कर रहे हैं, केवल पैसे की आमदनी के लिए वे नहीं दौड़ रहे हैं।

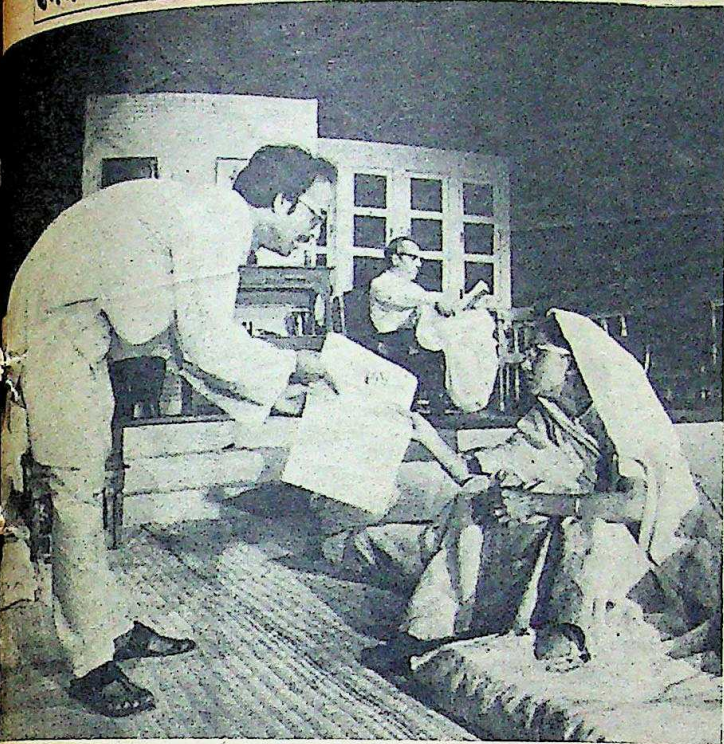
विश्वविद्यालय की अब कोई सार्वजनिक छवि नहीं रह गयी है। एकाएक हो जाने वाली हड़तालों, पथराव, आगजनी, बसों का दाह या ऐसा ही कुछ सहसा हो जाने पर नगर के लोगों को एहसास होता है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है जिस के छात्र ऐसा कुछ कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अब दुर्भाग्य से किसी भी नगर में वहाँ की सांस्कृतिक अगुवाई नहीं कर पा रहा है—न कर्म में न विचारों में और न नया कुछ रचने में! केवल महाशून्य के एहसास को और गहरा करता जाता है। इलाहाबाद का विश्वविद्यालय बहुत काल तक नगर की सांस्कृतिक चेतना का बाहक था अतः उस दिशा में किया हुआ कोई भी छोटा से छोटा प्रयत्न इलाध्य है और शाबाशी की माँग करता है।

एक बार और गहरे एवं सार्थक ढंग से कोशिश होनी चाहिए कि कैसे विश्वविद्यालय परिसर और उस के अड़ोस पड़ोस में केवल जुलूस, नारेबाजी, तोड़फोड़ और पी.ए.सी. के जवानों की स्थायी दीखने वाली द्रकों के बजाय देश के मान्य संगीतज्ञ, कलाकार, विचारक और लेखक—परिसर के अंग हो कर विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच निर्भय ससम्मान और मुक्त हो कर विचरण करते दिख पड़ें। उन की रचनात्मक प्रतिभा से साक्षात्कार ही शायद छात्रों, अध्यापकों और कुलपति को कुंठाओं से मुक्ति दे सके; और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को सही अर्थ में दे सके।



रंगमंच



महामोक्ष : (बाएँ) मुख्य मंत्री का निवास—सामने, प्रमोद माउथो (लखन) सुरेखा सीकरी (जमना बहन) पीछे, मनोहर सिंह (मुख्यमंत्री दा साहब). (ऊपर) गाँव में दलीय संघर्ष का दृश्य

## महामोक्ष जारी है

'महामोक्ष' मन्नू भंडारी के रचना लोक में ही नहीं, हिंदी उपन्यासों की दुनिया में भी एक स्वागत योग्य नया मोड़ है। इस बहुचर्चित श्रेष्ठ उपन्यास पर मन्नू भंडारी द्वारा तैयार किया गया नाटक आजकल राजधानी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल द्वारा रवींद्र भवन के घने छतनार पेड़ के तले खुले मंच पर खेला जा रहा है और अनूठी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उपन्यास और नाटक में जितना शिल्प के स्तर पर जरूरी है, अंतर है लेकिन कोशिश की गयी है कि उपन्यास के मूल कथ्य में कोई व्याघात न हो।

नाटक अमाल अलाना के निर्देशन में निसार अलाना की यथार्थवादी तामझाम वाले दो मंजिला मंच सज्जा के साथ रंगजगत के शीर्षस्थ कलाकारों द्वारा खेला जा रहा है। निर्देशन पूरी तरह सफल और त्रुटिहीन है और मंचसज्जा संभवतः निसार अलाना की अब तक की सर्वोत्तम सार्थक मंच सज्जा है। यद्यपि इस समीक्षक को इतनी खर्चीली मंच सज्जा पसंद नहीं है जो फिल्मों की बराबरी करने को आतुर हो और यथार्थ की बारीकियों से इतना उलझती हो कि दर्शक की कल्पना के लिए कोई रास्ता न छोड़े।

नाटक आज के राजनेताओं के चरित्र को उधारता है—उन के दांवपेच, ऊपर की सादगी, सिद्धांतवादिता और जन प्रेम के पीछे छिपी कुटिलताओं के निर्भय, जघन्य रूप को



'नाटक कुल मिला कर अच्छा लगा छोटी मोटी कमियों को छोड़ दें तो। उपन्यास से नाटक बनाते समय मैंने बहुत मेहनत की है। चार दिन पहले तक दृश्यों में परिवर्तन किया है, काट छांट किया है। रेस्ट हाउस का दृश्य ढीला था। चार दिन पहले फिर से लिखा गया। चरित्रों के अंतर्संघर्ष को छोड़ना पड़ा। नाटक बाह्य स्थितियों को उकेरता है वहीं तक उसे सीमित संतुलित रखना पड़ा। नाटक बनाते समय सेट की मेरी कोई कल्पना नहीं थी। उपन्यास से जितना मैं संतुष्ट थी उतनी ही नाटक से भी हूँ बल्कि नाटक से कुछ ज्यादा क्योंकि 'विजुअल' (चाक्षुष रूप) से बात और उभरती और गहरी होती है। मुझे खुशी है कि नाटक देखने छोटे बड़े राजनीतिकर्मी ही नहीं बड़े-बड़े राजनीतिक नेता पधार रहे हैं। नाटक को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच रहा है। दर्शक इसे अपना रहे हैं।'

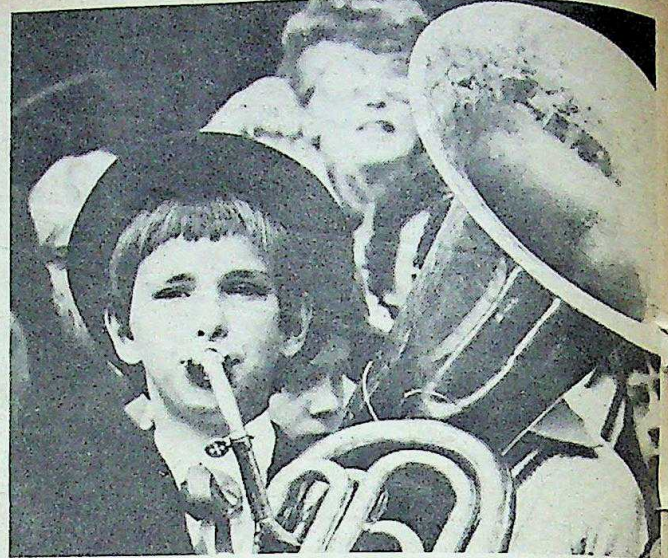
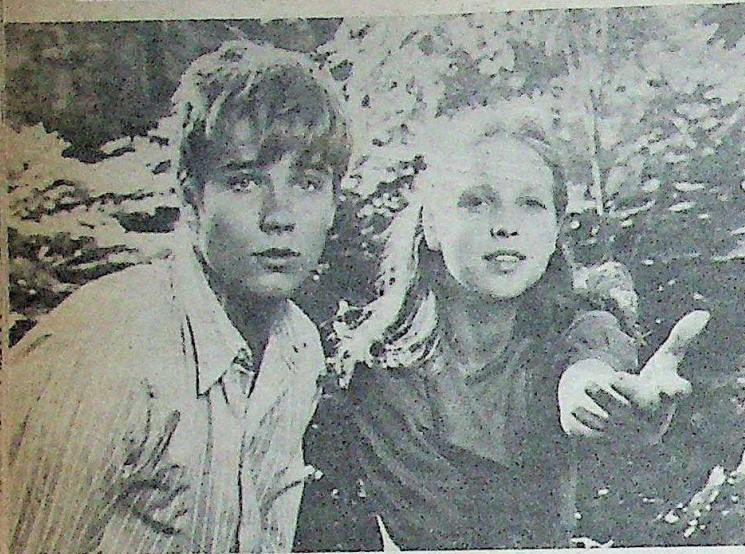
—मन्नू भंडारी

सामने लाता है और उन के हाथों में कठपुतली की तरह खेलते पत्रकारों, राजनीति कर्मियों, पुलिसवालों के स्वार्थ को और उन में से कुछ की विवशता को भी रेखांकित करता है। सत्ता हाथ में लिए एक मुख्यमंत्री सत्य के नाम पर ही सत्य को खरीदता, उस का गला घोटता और उस की नाना रूपों में किस तरह हत्या करता है यह इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक की बुनावट काफी सघी हुई है। केवल कथानक को बताने और आगे बढ़ाने के लिए उद्योषक की जरूरत नहीं थी। बिना उस के नाटक अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में सफल होता। दृश्य संयोजन, रूपाकारों की संरचना, समूह योजनाएँ सभी आकर्षक और सार्थक थे। ग्रामीण दृश्य उभरे हुए थे और नाटक अंत में सच्चे गरीब आदमी को मारे जाते और झूठे राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को चारों ओर ऐश्वर्य में डूबे भोज करने की विडंबना से दर्शक में एक यतना जगाता समाप्त होता है।

नाटक में सर्वाधिक प्रभावित किया इधुवीर यादव ने हीरा की भूमिका में—भय को निर्भयता में बदलने की एक बूढ़े की आंतरिक शक्ति का द्रवित कर देने वाला चित्रण! अन्य उल्लेखनीय कलाकार थे मनोहर सिंह (दा साहब) सुरेखा सीकरी (जमना बहन), उत्तरा बाबकर (रुक्मा) और अनिल कपूर (सुकुल बाबू)। रंगमंडली में सभी निष्णात कलाकार हैं—सब के अभिनय के सार्थक तालमेल से प्रस्तुति समृद्ध रही।

—स.व.स.





## प्राहा में नेहरू

पिछले दिनों राजधानी में चेक फ़िल्मों का एक महोत्सव आयोजित हुआ। इस में 6 कथा फ़िल्मों के अलावा अनेक लघु फ़िल्में भी शामिल थीं। नयी दिल्ली के बाद इस महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में भी किया जा रहा है। इस अवसर पर जो तीन सदस्यीय चेक फ़िल्म प्रतिनिधिमंडल भारत आया था उस में चेक फ़िल्मकार यिरी सिक्वेस भी शामिल थे। इस महोत्सव में उन की एक फ़िल्म 'वह क्षण, वह सैंकंड' भी शामिल है। लेकिन यिरी सिक्वेस का भारत आना इस लिए भी महत्वपूर्ण था कि वह पंडित नेहरू पर एक कथा फ़िल्म बनाने की योजना बना चुके हैं।

चेक सूत्रों के अनुसार प्राहा स्थित चेक फ़िल्म निदेशालय तथा दिल्ली स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच में कई तरह की फ़िल्मों के सहनिर्माण की योजनाएँ हैं। इन में नेहरू पर बनने वाली फ़िल्म सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इस फ़िल्म के कथानक के मूल में समकालीन समाज में नेहरू के विचारों की प्रासंगिकता है। इस फ़िल्म की पटकथा भारत सरकार को दी जा चुकी है और यह भी पता चला है कि इस पटकथा को ले कर कोई विवाद नहीं है।

नयी दिल्ली में पत्रकारों से अपनी बातचीत में सिक्वेस ने बताया कि नेहरू पर उन की फ़िल्म 'काफी नाटकीय' होगी। इस में 1939 से ले कर अब तक की घटनाओं को शामिल किया जायेगा। सिक्वेस के अनुसार नेहरू चेको-स्लोवाकिया की राजधानी प्राहा में एक ऐसे वक्त में गये थे जब वहाँ पर बहुत कठिनाइयों का वातावरण था। नेहरू ने वहाँ की लोकतांत्रिक शक्तियों से अपने आप को जोड़ा तथा भारत तथा विदेशों में प्रकाशित अपने अनेक

दिनमान

चेक महोत्सव : 'बारिश की बूंदों के बीच प्यार' तथा 'मेरी तो पिटाई होगी हो' के प्रसंग

लेखों में चेक जनता की आशाओं और आकांक्षाओं से संबंधित लेख लिखे।

सिक्वेस के अनुसार इस फ़िल्म में शांति और मानवता के बुनियादी मूल्यों पर जोर देते हुए समकालीन समाज में उन की प्रासंगिकता को बताया जायेगा। इस फ़िल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी का भी जिक्र आ जायेगा क्योंकि 1939 में वे भी पंडित नेहरू के साथ प्राहा गयी थीं।

सिक्वेस के अनुसार नयी पीढ़ी नेहरू की इस चेकोस्लोवाकिया यात्रा के महत्व को नहीं जानती है। न ही उसे तत्कालीन यूरोपीय राजनैतिक स्थिति की अच्छी जानकारी है।

इस फ़िल्म की शूटिंग भारत और चेको-स्लोवाकिया दोनों ही स्थानों पर होगी। इस फ़िल्म के निर्माण में किसी एक भारतीय फ़िल्मकार का सहयोग लेने का भी विचार है। इस फ़िल्म की पटकथा में एक फ़िल्म टोली नेहरू पर फ़िल्म बनाने का काम शुरू करती है। इस टोली की प्रधान एक महिला निर्देशिका है। इस प्रकार वर्तमान से शुरू हो कर यह फ़िल्म 1938 के यूरोप और चेकोस्लोवाकिया में चली जायेगी।

यह दिलचस्प बात है कि इन दिनों अनेक पूर्व यूरोपीय देश भारत से संबंधित फ़िल्में बना रहे हैं। बुल्गारिया के फ़िल्मकार रांगेल बुल्चानोव आज के भारत पर एक लंबा वृत्तचित्र बना रहे हैं। इस में उन्होंने श्रीमती गांधी से भी एक लंबी मेटवार्त्ता ली है। इस के अलावा सोवियत संघ के सहयोग से श्याम बेनेगल भी नेहरू पर एक फ़िल्म बना रहे हैं। यह फ़िल्म भारत-सोवियत संघ के सहयोग से बनेगी और कथा फ़िल्म न हो कर एक लंबा वृत्तचित्र होगी।

पिछले वर्ष ब्रितानी फ़िल्मकार रिचर्ड एटेनबरो ने जब गांधी पर हॉलीवुड और भारत सरकार के पैसे से कथाफ़िल्म की शूटिंग शुरू की थी, तो देश में काफी हंगामा हुआ था। यह फ़िल्म अभी प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है लेकिन भारत सरकार ने इस पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पैसा तो शायद यह फ़िल्म कमा लेगी पर देखने की बात यह है कि गांधी की कौन सी छवि और किस तरह से दुनिया भर को देखने को मिलेगी। पूर्व यूरोपीय देशों के सहयोग से बनने वाली फ़िल्में जाहिर हैं कि इतनी विवादास्पद नहीं होती हैं। हॉलीवुड का तंत्र प्रचार का एक जबरदस्त वातावरण बनाता है।

बहरहाल, चेक फ़िल्म महोत्सव की खासियत उस की लघु फ़िल्में थीं। चेकोस्लोवाकिया में एक वर्ष में लगभग पचास कथा फ़िल्में और 1600 लघु फ़िल्में बनती हैं। लघु फ़िल्मों के क्षेत्र में चेक फ़िल्मकारों का सचमुच मुकाबला नहीं है। ऐनीमेशन फ़िल्मों में तो उन्होंने नये नये अद्भुत प्रयोग किये हैं। इस महोत्सव में 'जॉन और मेरी की कहानी' नामक एक कथा फ़िल्म की लंबाई की ऐनीमेशन फ़िल्म थी। कथा फ़िल्मों में अब चेक फ़िल्मकार कुछ पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। कहा तो यही जाता है कि वहाँ लगभग 50 प्रतिशत फ़िल्में समकालीन समाज की समस्याओं पर गौर करती हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस महोत्सव की 6 फ़िल्मों में से एक फ़िल्म भी समकालीन समाज में हमें नहीं ले जाती। बच्चों, किशोरों की औसत अच्छी फ़िल्मों का जोर रहा। वरिष्ठ फ़िल्मकार कारेल काखीना की फ़िल्म 'बारिश के बूंदों के बीच प्यार' अवश्य एक महत्वपूर्ण और जटिल फ़िल्म है जो बाटा जैसी बड़ी कंपनी द्वारा एक मोबी के धंधे को नष्ट करने की कथन कथा बताती है।



## उपन्यास गोष्ठी

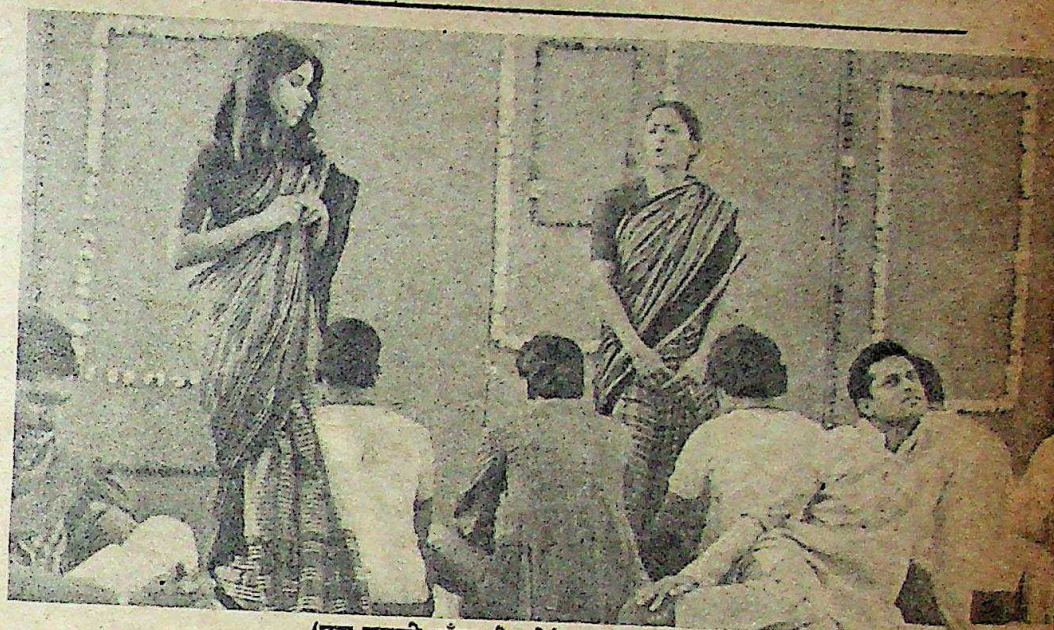
'संयुक्त प्रयास' की ओर से धीरेंद्र अस्थाना के पहले उपन्यास 'समय एक शब्द भर नहीं है' पर राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में विचार-गोष्ठी हुई, जिस में प्रदीप मांडव और राम-कुमार 'कथक' ने पर्व पढ़े। सुधीश पचौरी, डॉ. हरदयाल, कर्णसिंह चौहान, रमाकांत, केशव, योगेश गुप्त, दिविक रमेश, प्रेम जन्मेजय तथा राजकुमार गौतम ने अपने विचार व्यक्त किये। अधिकांश वक्ताओं ने तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में राजेंद्र यादव ने उपन्यास के कथानक और शिल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह 'सरोकारों का उपन्यास है, संवेदना का नहीं। बुनावट (ट्रीटमेंट) में किसी अन्वेषणात्मक दृष्टि का परिचय नहीं है।' रमाकांत को उपन्यास में वही गुण और दोष दीखे जो नक्सलवादी आंदोलन में दीखते हैं। अन्य लोगों ने उपन्यास के पठनीयता की सराहना की।—ब.

## नाटक के सात दिन

भोपाल में पिछले दिनों बड़े ताल के किनारे अवस्थापित सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन के उद्घाटन के मौके पर मध्यप्रदेश रंग मंडल ने सात दिवसीय रंगोत्सव के आयोजन के दौरान अपने सब से पहले प्रदर्शन के तौर पर नाटक प्रस्तुत किये। जयशंकर प्रसाद के लिखे 'विशाख' और विजय तेंदुलकर का 'सारीराम कोतवाल' ब. व. कारंत के सिद्ध-हस्त निर्देशन में खेले गये। (ज्ञातव्य है कि श्री भारत मध्यप्रदेश रंगमंडल के निर्देशक भी हैं।) अलख नंदन के निर्देशन में विदेशी नाटक-कारों डेनमार्क के एच. सी. ब्रेनर कृत 'जज' तथा रूसी चेखव रचित 'क्लर्क की मौत' प्रस्तुत किये गये। नाटक की शकल में निर्मल वर्मा की कहानी 'बीकानेर' को नीलम चौधरी ने बड़े पुरस्सर ढंग से प्रस्तुत किया।

इस के अलावा मध्यप्रदेश के देहाती जन-जीवन में पोषित लोक नाट्यों की कई शैलियों को मंचन भी हुए जिनमें—चार बैत, पंडवानी, अयोध्यासारिका, राई, बरेदी, करमा, माच और नाचा वगैरह शामिल हैं। 'पूर्वरंग' में लोपी वर्मा के कुशल निर्देशन में हरिशंकर प्रसाद की व्यंग्य कहानी 'एक लड़की पांच दिनों की' को भी प्रेक्षकों ने भरपूर सराहा, इसे सीधे सपाट मगर प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करने ढंग से प्रस्तुत किया गया था।

मनोरम प्राकृतिक पृष्ठभूमि लिए भारत भवन ने आधुनिक ढंग के प्रेक्षागृह बनाया तथा खुली रंगशाला 'बहिरंग' में प्रस्तुत नाटकों के इस उत्सव का औपचारिक शुभारंभ प्रख्यात रंगकर्मी शंभू मिश्र



'एक लड़की पांच दिवने' का दृश्य

के कर कमलों से हुआ। पेरिस से तशरीफ लाये जगप्रसिद्ध रंग निर्देशक पीटर ब्रुक भी इस अवसर पर मौजूद थे।

—विनोद नागर

## कथक नृत्य

राजधानी में देर से आयी गरमी की शुरुआत के पहले दिन 'शंकार' में सास्वती सेन और भास्वती मिश्र दोनों बहनों का युगल कथक नृत्य हुआ जिस में बीच बीच में एकल टुकड़े भी पियरे हुए थे। दोनों बहनों के गुरु बिरजू महाराज इस नृत्य प्रदर्शन में उपस्थित थे। ऐसा कम होता है कि बिरजू महाराज अपने हर शिष्य और शिष्याओं के नृत्य में उपस्थित हों! दोनों बहनों ने लय, गति पर पूरे अधिकार के साथ खुश कर देने वाला कथक पेश किया। यह कहना कठिन है कि इन दोनों में कौन किस कारण दूसरे से बेहतर है। दोनों की तैयारी पक्की है, त्रुटिहीन है। दोनों उस मुकाम पर पहुँच गयी हैं जहाँ गुरु का काम खत्म होता है और कलाकार को गहरायी की ओर जाना होता है और अपने कलाव्यक्तित्व का निर्माण

करना होता है। अभिनय में भी दोनों ही मजबूत हैं और दोनों ही कथक के अंगों, उपांगों और व्याकरण की बारीकियों, चुस्ती और आवेगों में पूर्ण निष्णात हैं। दोनों का साथ साथ नाचना एक अद्भुत रंजकता प्रदान करता है। और कथक युगल नृत्य में एक प्रतिमान बना सकता है। आशा की जानी चाहिए कि दोनों रूपवती बहनें साथ नाचेंगी और कथक प्रेमियों को कथक के सौंदर्य और ओज की एक नयी अनमूर्ति प्रदान करेंगी। —स.

## पैसा बोलता है

भरत नाट्य भूमि साकेत (फंजाबाद) में पिछले माह रमेश मेहता लिखित तथा बालेन घोष द्वारा निर्देशित एक अंकीय नाटक 'पैसा बोलता है' 'ग्रुप रिक्रेशन क्लब' की ओर से स्थानीय प्रेक्षागृह नरेंद्रालय में मंचित किया गया। यदि आप के पास पैसा है तो सब आप के व सब आप के हैं—यदि पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हैं, विषय पर आधारित यह नाटक पैसा बोलता है काफी रोचक था।

इस नाटक में सब से प्रभावशाली अभिनय फिल्म डायरेक्टर के रूप में यश कपूर व सुषमा के रूप में नूपुर बोस का रहा—दर्शकों के दिल पर यह अपने छोटे से चरित्र में ही छाप छोड़ गये। सुबोल गांगुली (मालिक) का अभिनय काफी संतुलित रहा। उन्होंने अपने पात्र के चरित्र के साथ न्याय किया। सारिका शर्मा (तारा) के अभिनय में कठोर परिश्रम स्पष्ट था। नायक पंचू के रूप में समरेंद्र पूर्ण, परिमल बनर्जी (बल्ली), नितिश (सुरेश), अपूर्व विश्वास (उमेश) एवं श्रीमती वर्मा (मालकिन) उल्लेखनीय थे।

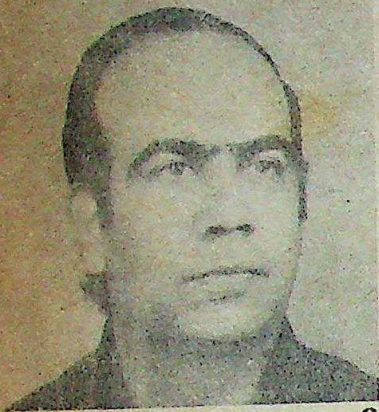
—रामतीर्थ विकल

सास्वती सेन : कुशल अभिनय





## चरित चर्चा



## कृष्ण दयाल शर्मा

पाकिस्तान में भारत के नव-नियुक्त राजदूत (उच्चायुक्त) कृष्ण दयाल शर्मा भारतीय विदेश सेवा के उन अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें एक सफल राजनयिक के रूप में प्रशंसा मिली है।

विदेश मंत्रालय के जानकार सूत्रों के अनुसार उन्होंने 26 वर्षों के अपने कार्यकाल में अपनी नियुक्ति के हर पद की मर्यादाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति संतोषजनक ढंग से की है। आतिथ्य, सद्भाव, विश्वासों के प्रति विनम्र दृढ़ता, तर्कोचित ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता, मारिचम के लॉग शर्मा माहव को आज भी याद करते हैं। उन्होंने वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में घुलमिल कर भारत और मारिचम के संबंधों को अतिरिक्त गहनता दी थी। विदेश मंत्रालय के पारंपरिक और बीसा विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने सराहनीय काम किया और तमाम दिक्कतें दूर कीं। वह जुलाई 80 में आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। फिलहाल वहाँ हैं।

पाकिस्तान में श्री शर्मा की नियुक्ति अकारण नहीं है। आगा शही की जगह विदेशमंत्री पद पर एक अवकाश प्राप्त ले. जनरल की नियुक्ति वहाँ के सैनिक शासन के चितन का संकेत देने के लिए काफी है। भारत अपने पड़ोसियों से—पाकिस्तान से खासतौर पर—रिश्तों को ठीक बनाये रखने के लिए अपनी ओर से निरंतर

विनमान

प्रयत्नशील रहा है। इस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण यह था कि भारत के विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान संबंधी मसलों को देखने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जो अधिक जानकार, योग्य और सक्षम हो। उस के लिए पाकिस्तान में भारत के राजदूत के. नटवर सिंह को उपयुक्त समझा गया। उन्होंने सचिव के रूप में पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी का दायित्व (देखें: दिनमान 11-17 अप्रैल) सौंपा लिया है। ऐसे ही एक व्यक्ति की तलाश पाकिस्तान भेजे जाने के लिए भी थी।

उम्मीद की जाती है कि एक राजदूत के रूप में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की दिशा में शर्माजी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। —रा.

## ‘दिव्य’ जी

बुंदेलखंड के साहित्यकार अंबिका प्रसाद ‘दिव्य’ 16 मार्च को 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। मध्य-प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से कस्बे अजयगढ़ में वह रहते हैं। 60 से अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की है जिन में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य-ग्रंथ सभी हैं। ‘अंतर्जगत’ खंडकाव्य और ‘गांधी पारायण’ महाकाव्य की अनेक विद्वानों ने सराहना की है—इधर उन्होंने ‘बुंदेलखंड चित्रावली’ का सृजन किया है। वृद्धावस्था में तैयार किये गये इन चित्रों की सूक्ष्मता और रंगकौशल को देख कर रामकुमार वर्मा ने इसे ‘देश दर्शन’ की संज्ञा दी है। छतरपुर में इस अवसर पर एक समारोह भी हुआ—स.



## अशोक कुमार

कई फिल्म अभिनेताओं को ‘सदाबहार नायक’ कहा जाता है। पर इस अर्थ में अशोक कुमार से अधिक उपयुक्त नाम शायद ही कोई हो। तीस के दशक के सिनेमा का यह नायक आज भी सक्रिय है। पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्रेस कांफ्रेंस में किसी ने जब उन्हें ‘बहुत पुराना’ कहा, तो उन्होंने ने अपने को सिर्फ ‘पुराना’ मानना ही उचित समझा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी के वह अध्यक्ष थे लेकिन पुरस्कारों की घोषणा के वक्त पत्रकारों की भीड़ के सामने घबराये हुए से थे। “मैं आज भी कैमरे के सामने घबरा जाता हूँ। पत्रकारों का तो इस तरह से कभी मैंने सामना ही नहीं किया है!”

कहना मुश्किल था कि पत्रकारों की भीड़ में से कितने लोग अशोक कुमार को देखने सुनने के आकर्षण के कारण उपस्थित थे (आखिर वहाँ सब फिल्म पत्रकार नहीं थे)। प्रेस कांफ्रेंस के समाप्त होने के बाद एक अघेड़ पत्रकार ने टिप्पणी की—अमाँ यार, अशोक कुमार को मैंने 7 साल की उम्र में परदे पर देखा था। आज भी वही मुस्कान दिख रही है। अद्भुत है।

एक वक्त था जब छोटे छोटे गह्रों में अशोक कुमार के नाम से रात भर के सिनेमा शां जोर शोर से हुआ करते थे। बाबू टांकीज की अपने समय की चर्चित फिल्म ‘अब्दुल कान्या’ (1936) में अशोक

कुमार और देविका रानी को जोड़ी ने भारतीय सामाजिक सिनेमा को एक नयी पहचान बनायी थी। उस समय से आज तक अशोक कुमार अपनी मोहक सिनेमाई छवि को एक खास तरह से बनाये रखने में सफल हुए हैं।

अशोक कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में बहुत विनम्रता से कहा : मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ—चाहे अभिनय के क्षण हों या जीवन के। इस वर्ष की प्रतियोगी फिल्मों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम ने पुरस्कारों का फैसला करते वक्त सिनेमा के अपने गुणों को ध्यान में रखा है। और आप देखिए कि राजनीतिक कहे जा सकने वाले सिनेमा को भी पुरस्कार दिये गये हैं—बल्कि उन में से कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सरकार को गाली दे रही हैं। (अशोक कुमार की वगल में सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे भी बैठे हुए थे!)

अशोक कुमार से जब पूछा गया कि इतनी सारी फिल्मों (कुल 80 कथाफिल्में थीं) को देख का आप आज के सिनेमा (खास तौर पर तथाकथित कला सिनेमा) के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा रुक कर नये सिनेमा की तारीफ की पर यह भी कहा कि इन फिल्मों की गति बहुत धीमी है। थोड़ी सी तेज गति हो और मनोरंजन भी हो। अच्छा सिनेमा इस तरह से सामने आयेगा।

जाहिर है अशोक कुमार को पत्रकारों का इस तरह से सामना करने की आदत नहीं रही है। थोड़ी देर में ही वे सब कुछ बताते लगे। जूरी ने सरकार को जो सुझाव दिये हैं वे भी बताने जा रहे हैं कि अचानक वसंत साठे से उन्होंने पूछा कि क्या मैं बता दूँ? अनुमति साठे ने कहा : अभी नहीं—उन्होंने सुझावों पर विचार हो रहा है।

पुरस्कारों की घोषणा के ठीक बाद लोगों से घिरे अशोक कुमार जाने कैसे वक्त निकाल कर विचार कला संगम में घूमते हुए और वहाँ की पुस्तकों की दुकान चयन में पुस्तकों को पलटते हुए देते गये। आखिर पुराने जमाने के अभिनेता हैं!—वि.



नेशनल की गौरवपूर्ण प्रस्तुति

# स्मृति-लेखा 'अज्ञेय'

स्मृति-लेखा को मात्र 'संस्मरण' नहीं कहा जा सकता। साहित्य के इतिहास में 'स्मृति' का यह एक विशिष्ट सर्जनात्मक इस्तेमाल है, जिसमें अज्ञेय जी के समकालीन कवियों लेखकों की स्मृतियों की लेखाएं हैं। 20.00

अज्ञेय जी की अन्य कृतियाँ

- 0 आलवाल 15.00
- 0 अरे यायावर रहेगा याद 12.00
- 0 संबत्सर 20.00



नेशनल  
पब्लिशिंग  
हाउस

23, दरियागंज नयी दिल्ली-110002

युवकों, छात्रों की अपनी पत्रिका हेतु आवश्यकता है, प्रत्येक डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय, शहर में प्रतिनिधियों की अनेक आकर्षक उपहार। नमूना हेतु रु. 1-25 का डाक टिकट भेजें। वार्षिक 15 रुपया। लिखें:-

**युवा यश्मि**  
हिन्दी मासिक

पोस्ट बॉक्स 7 महानगर  
लखनऊ  
22 6006

ज्ञान विज्ञान  
का  
खज़ाना

**पराग**

वचनों की  
सम्पूर्ण मासिक पत्रिका

टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन

यशस्वी उपन्यासकार  
गिरिराज किशोर का  
नया उपन्यास

**तीसरी  
सत्ता**

एक अविस्मरणीय उपन्यास जो जीवन सत्य की नयी संभावनाओं को उजागर करता है, और पाठक की चेतना को झकझोरते हुए एक बीहड़ चुनौती देता है।

87.00



नेशनल  
पब्लिशिंग  
हाउस

23, दरियागंज  
नयी दिल्ली-110002

## दिनमान

पैनल में अपना विज्ञापन दीजिये और लाभ उठाइये

विज्ञापन-दर

(आकार 5.50 सें.मी. लंबाई × 5.50 सें.मी. चौड़ाई)

प्रति पैनल प्रति बार

केवल रु. 62.00

**धर्मयुग** से पैनल प्रकाशित कराने पर दिनमान-शुल्क में 25% छूट

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कीजिए:

विज्ञापन व्यवस्थापक

**दिनमान**

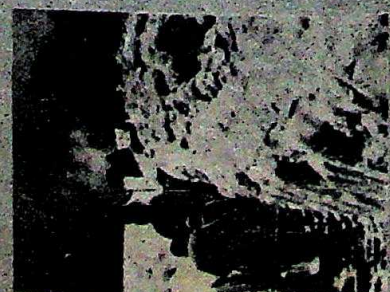
7, बहादुरशाह जंफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फोन : 270161 (10 लाइनें)



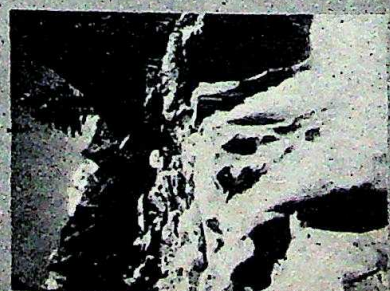
# हिमालय के रमणीय आंचल में भक्ति-भाव से भरी अस्मरणीय यात्रा बदरीनाथ • केदारनाथ • हेमकुंड

विशाल हिमालय और उसकी  
विविध तक फैली अन्य शिखर  
श्रृंखलाएं अजोय हैं। समय की  
प्रज्ञा धारा के भीति-स्वप्न  
सरीसों मोड़क शिखर, पर्वतों  
की दीवारों वाले मंदिरों पर  
फहराते लाल रंग के तिकोने  
ध्वज और लवसे सज्जित नीला  
आकाश। शक्ति बहने वाले जल  
स्रोतों की गुनगुनहट, बड़ी  
धारा में उनके मिलने की मोहक  
कल-कल, सुरभित पवन पर  
तस्ते गीत और आर्चनाओं के  
स्वर परस्पर मिलते हैं बार बार,  
अचानक। जगता है, तीर्थ यात्री  
आ गए हैं।



केदारनाथ : उत्तरा खंड गौरी  
की वास्तुकला के सुन्दरतम समूहों  
में से सदृशिव का एक अन्य  
मंदिर। यहाँ की भूमि पर  
मन्दिर का निर्माण किया गया है।

बदरीनाथ : समुद्रतल से १,११३  
मीटर की ऊँचाई पर भूमि गंगा  
और धलकनंदा के संगम पर  
स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन  
मंदिर। हिन्दुओं के चार पवित्र  
धामों में से एक।  
हेमकुंड : पांडव कालीन पवित्र  
स्थान। कहा जाता है, गुरु  
गोविन्द सिंह ने अपने किसी  
पूर्व जन्म में यहाँ साधना की  
थी। आज उस स्थान पर एक  
गुच्छारा बना है। मूलतः लक्ष्मण  
कुंड से विख्यात, रंग बिरंगे  
मनमोहक फूलों से लदा, ससार  
का सबसे ऊँचा तीर्थ-स्थल।

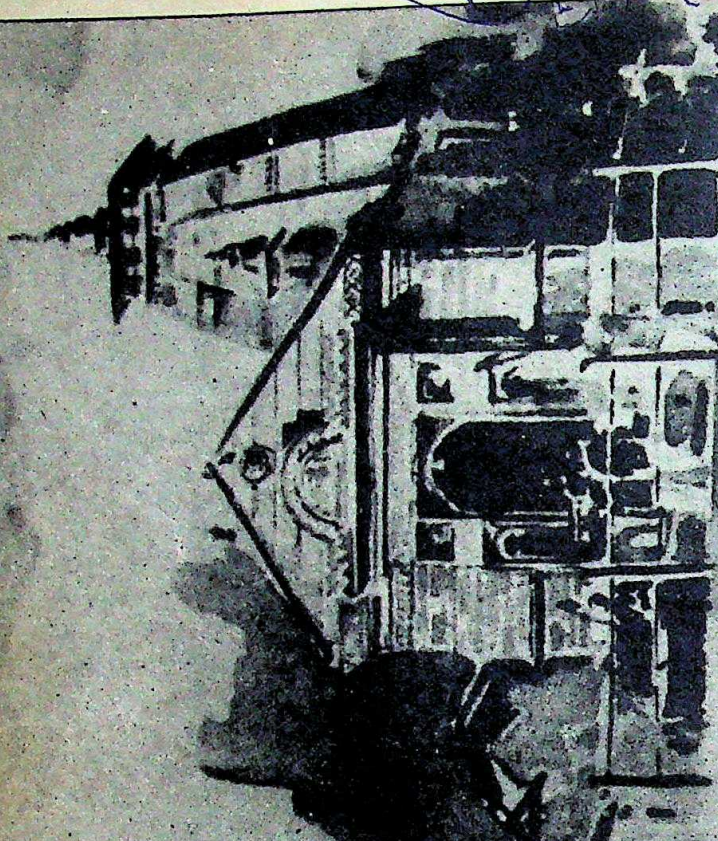


गंगोत्री : समुद्रतल से ३,०००  
मीटर की ऊँचाई पर स्थित गंगा  
मंदिर। यहाँ से भागवती गंगा  
धरती पर अवतरित होती है।



स्थित गंगा की बहिन यमुना का  
मंदिर। गर्म जल के स्रोतों से  
निर्मित पवित्र सूर्यकुंड-ग्रोलोले  
आश्चर्य की सृष्टि।

धपती यात्रा-योजना पर समुचित  
परामर्श प्रथा श्रम्य जानकारी के  
लिए कृपया उत्तर प्रदेश पर्यटन-ब्यूरो  
से निम्न पत्तों पर सम्पर्क कीजिए—  
बम्बलोक, ३६ जलपथ, नई दिल्ली,  
फोन : ३२२२११; १२-ए नेताजी  
सुभाष रोड, ब्रुसरी मॉडल, कलकत्ता,  
फोन : २२६७६८; १३-न भवानी  
बेल्गर, आश्रम रोड, महमदाबाद,  
फोन ७६६१२८; द्वारा यु० पी०  
एक्सप्रेट कार्पोरेशन, बल्लई रोड सेक्टर,  
फाऊ परदे, कोलकाता, बम्बई, एस सी  
फोन : २२६७६८; १३-न भवानी



इन चीफ रोड, मद्रास; दि माल,  
मसूरी, फोन : ६६३; पीडी, फोन :  
४१ व ६६; ललता राव ब्रिज, हरिद्वार,  
फोन : १६; महात्मा गांधी मार्ग,  
देहरादून, फोन : ३२१७; ६ सप्  
मार्ग लखनऊ, फोन : ४६२१४,  
आवास एवं कन्स्ट्रक्शंस टूर के लिए  
कृपया सम्पर्क कीजिए-नडवाल मंडल  
विकास निगम, ७४/१ राजपुर रोड,  
देहरादून, फोन : ४४०८, ६८१७,  
६८३०

यु० पी० टूरिज्म

21-ए, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ-226 001  
फोन : 45555, 49340, 32437, 45252



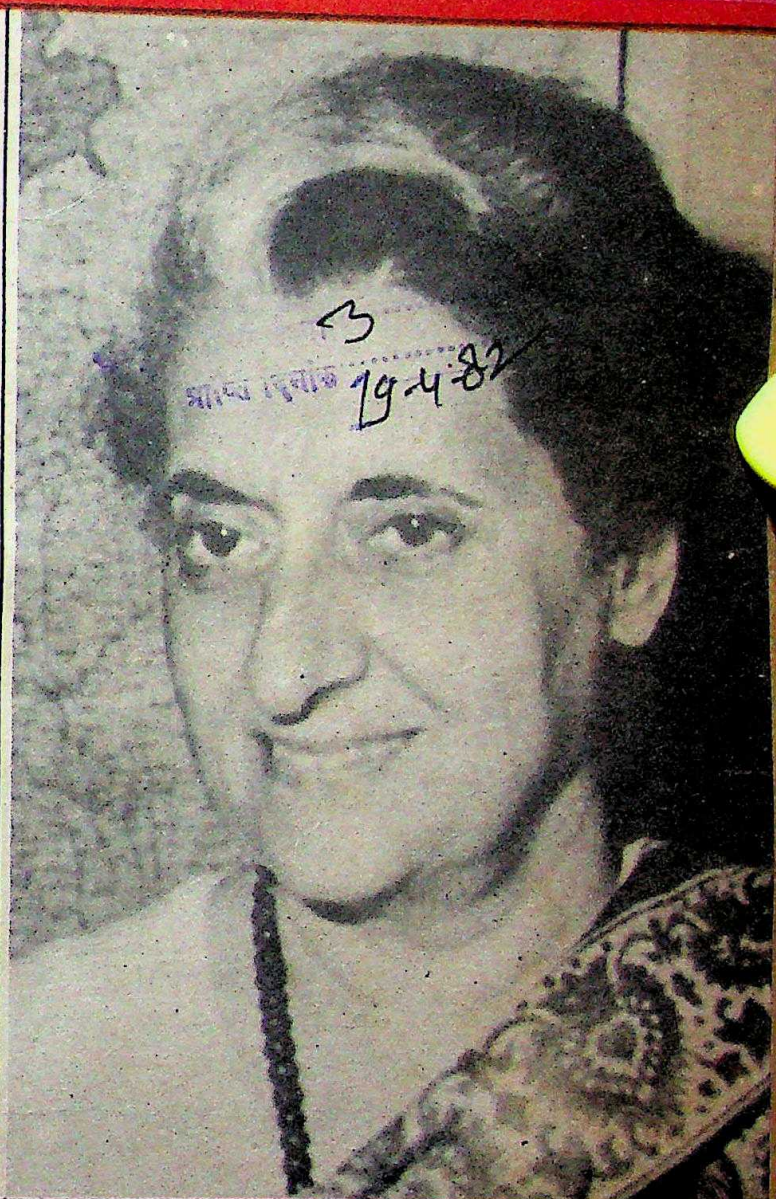
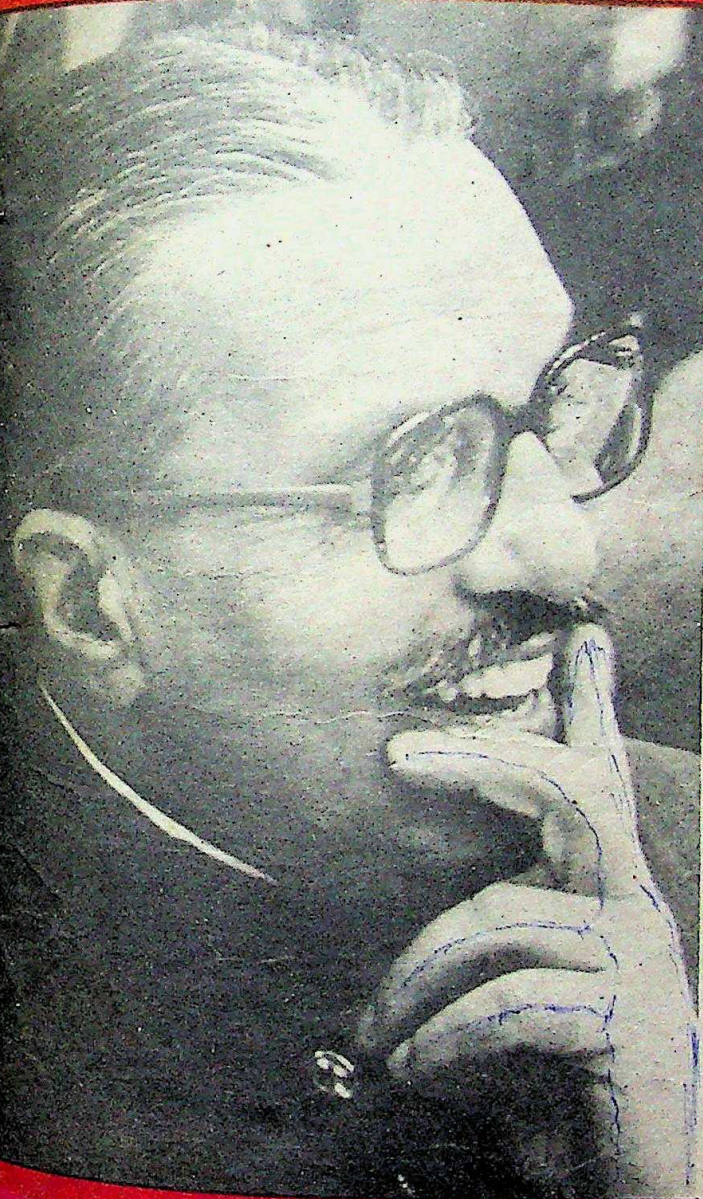
21-ए, विधान सभा मार्ग,  
नजफगढ़-226 001  
फोन-45555, 48349, 32437, 45252

पुस्तकालय और नदीनाथ के  
मन्दिरों के दूर के लिए छपया सम्पूर्ण  
कले-११-ए, विधान सभा मार्ग,  
नजफगढ़-226 001

पुस्तकालय और नदीनाथ के  
मन्दिरों के दूर के लिए छपया सम्पूर्ण  
कले-११-ए, विधान सभा मार्ग,  
नजफगढ़-226 001

पुस्तकालय और नदीनाथ के  
मन्दिरों के दूर के लिए छपया सम्पूर्ण  
कले-११-ए, विधान सभा मार्ग,  
नजफगढ़-226 001

पुस्तकालय और नदीनाथ के  
मन्दिरों के दूर के लिए छपया सम्पूर्ण  
कले-११-ए, विधान सभा मार्ग,  
नजफगढ़-226 001



भारत-पाक संबंध

## नयी संभावनाओं के सूत्र

प्रेस आयोग विवाद  
चंचल एकता और  
विधान सभा चुनाव



क्योंकि इसकी  
शुरुआत भारत में  
विश्व कप के  
आयोजन से हुई

क्योंकि इसी वर्ष  
भारत में  
एशियाई खेल  
होने जा रहे हैं

और



क्योंकि इसी वर्ष खेलों की दुनिया में  
एक और घटना होने जा रही है  
जानते हैं क्या है वह ?

जिसका लाखों पाठक अब तक इंतजार कर रहे थे. प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त.

टाइम्स आफ इंडिया की  
नयी सहयोगी पत्रिका

# खेल भारती

## खेलों की दुनिया में नया कीर्तिमान

१६ अप्रैल से  
प्रकाशित

नैट, कोलमैन एंड कं. लिमिटेड, स्वत्वाधिकारी के लिए रमेशचन्द्र द्वारा नेशनल प्रिटिंग वर्क्स. 10 बरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित व प्रकाशित.  
पंजी. कार्यालय : डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, बंबई-400001. शाखाएं : 7, बहादुरसाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-2; 139, आश्रम रोड, अहमदाबाद-38  
105/7 ए, एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-700014. कार्यालय : 13/1, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता-700069; 63, मोटियथ रोड, इम्फोर, गुवाहाटी-781002  
407-1, तीर्थ भवन, क्वार्टर गेट, पुणे-411002. 28, स्लेजिन रोड, सिकंदराबाद-500002. 28, स्लेजिन रोड, सिकंदराबाद-500002. 28, स्लेजिन रोड, सिकंदराबाद-500002. 28, स्लेजिन रोड, सिकंदराबाद-500002.



# दिनमान

समाचार साप्ताहिक

भाग 18

18-24 अप्रैल, 1982

अंक 15

28 चैत्र-4 वैशाख, 1903

## इस सप्ताह

भारत-पाक संबंध: इन्फा संपादक इंद्रजीत की विशेष रपट और हिंदी के कथाकार महीपसिंह की पाकिस्तान यात्रा की यादें 8-12. प्रेस आयोग 18. 'अगर और समय मिलता तो और परिवर्तन हो सकते थे' —लाल कृष्ण आडवाणी 20. उपेक्षित बस्तर में विद्रोह की आग 24. अल सल्वाडोर में पत्रकारों की हत्या 28. ईरान-इराक युद्ध 29. भारत लोकतंत्र का नवलिस्तान है 34.

मत और सममत 4. पिछले सप्ताह 5-6. पत्रकार संसद 7. दिल्ली के रंग 13. उनका कहना है 13. चरचे और चरखे 14. चित्रों के आईने में 22-23. दुनिया भर की 31. खेल और खिलाड़ी 32. साहित्य 35. नृत्य 35. संगीत 36. रोमंच 37. फिल्म 39. कला 40. संस्कृति समाचार 41. चरित चर्चा 42.

आवरण : भारत-पाक संबंध : जिया-उल-हक और श्रीमती इंदिरा गांधी

संपादक : कन्हैयालाल नंदन

संपादकीय सहकर्मी : जितेंद्र गुप्त (सहायक संपादक), सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (मुख्य उपसंपादक), श्यामलाल शर्मा, जवाहरलाल कोल, शुक्ला रुद्र, त्रिलोक दीप, महेश्वरदयाल गंगवार, प्रयाग शुक्ल, बनवारी, विनोद मारवाज और सुषमा पाराशर. (विशेष संवाददाता) : रामसेवक श्रीवास्तव

सज्जा : रवि शर्मा

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन  
10, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002

## पाठकों से



इन्फा संपादक इंद्रजीत

यह विडंबना ही है कि भारत और पाकिस्तान का अ-वाम युद्ध छाया तक से बचना चाहता है, युद्ध के आतंक से घबराकर युद्ध न होने की मन्त्रते मांगता है लेकिन समस्याएँ हैं कि हमें बार-बार युद्ध की कगार पर लाकर खड़ी कर देती है. जब पिछली बार भारत से पंजाबी लेखकों का एक दल पाकिस्तान गया तो यहाँ से चलने पर पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी ने मर्मभेदी आँखों से देखते हुए कहा था, "पाकिस्तान में आप गुस्ठारों के दर्शन के लिए जायेंगे ही?" "गुस्ठारों के दर्शन करने तो जरूर जायेंगे".

"तो वहाँ एक दुआ हमारी तरफ से भी कीजिएगा कि हम में आपस में अब कभी जंग न हो." (देखें पृ. 12)

पाकिस्तानी हुक्मरानों के नुमाइंदे 'नो वार' की बात करने आते हैं और कश्मीर का खरकता हुआ काँटा महसूस करके फिर स्थायी शांति स्थापना के सारे किये-करायें पर पानी फेर देते हैं. पाकिस्तानी सैन्य शक्ति का लगातार बढ़ते जाना भारत की सुरक्षा को नयी सतर्कता के लिए मजबूर कर देता है. अभी जब श्रीमती गांधी जम्मू गयीं और अपनी सेना के जवानों को संबोधित करने लगीं तो बोलीं, "भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध से बचा जाये परंतु हमें हर स्थिति का सामना करने को तैयार रहना ही है. युद्ध का खतरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और शस्त्र खरीदने की बीड़ से मामला और गंभीर हो गया है". लेकिन श्रीमती गांधी के आलोचक अक्सर कहते रहते हैं कि युद्ध का भय पैदा करना हमारा ध्यान देश की बुनियादी जरूरतों से हटाने का एक जरिया है.

अपने देश की प्रधानमंत्री की ओर से युद्ध के खतरे के उत्तरोत्तर बढ़ने का संकेत हमें इन सारी स्थितियों पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करता है. हमें याद आ रहा है दिल्ली के प्रसिद्ध पत्रकार और 'इन्फा' के संपादक श्री इंद्रजीत का हाल का एक आलेख, जिस में उन्होंने लाहौर के अपने एक लंच के दौरान पाकिस्तान के कतिपय प्रख्यात पत्रकारों से बातचीत का हवाला दिया था. उस लंच में 'पाकिस्तान टाइम्स' के प्रधान संपादक श्री जेड. ए. सुलेरी, 'नवाये वक्त' के मजीद निजामी तथा उर्दू दैनिक 'मशरिक' के मुख्य संपादक इकबाल जुवेरी भी सम्मिलित थे. बड़ी तेज बात रही थी इंद्रजीत जी ने— "मैं चाहता हूँ कि आप वास्तविकता को समझने का प्रयास करें. आज भारत में कोई माई का लाल ऐसा नहीं, जो पाकिस्तान को आसानी से कश्मीर देना मान लेगा और पाकिस्तान में भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं, जो बलपूर्वक उसे छीन सके. अतः हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और यथार्थ का सामना करना चाहिए. इसमें दोनों ही देशों का हित है."

इंद्रजीत के उस आलेख को पाकिस्तान के 'कट्टर' कहे जाने वाले अखबार 'नवाये वक्त' ने इज्जत के साथ छपा था.

दिनमान ने भारत-पाक संबंधों की नयी पेचीदगियों को खुले रूप से जाँचने-परखने के लिए इस बार श्री इंद्रजीत को ही चुना, क्योंकि न भावनाओं में बहने का समय है और न यथार्थ से आँखें मूंदकर सिर्फ युद्ध की निंदा करते रहने का. युद्ध की निंदा करते रहने मात्र से समस्याएँ कभी हल नहीं होतीं. 'दिनमान' इस बार विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहा है भारत-पाक संबंधों की संभावनाओं के नये सूत्र—समस्या के पूरे परि-प्रेक्ष्य में. साथ में हैं डॉ. महीपसिंह की पाकिस्तान यात्रा की वे यादें, जो दोनों देशों के अ-वाम की अंदरूनी चाहत का आईना हैं. हमें खुशी है कि अब इंद्रजीत जी 'दिनमान' के लिए नियमित अपनी सामयिक टिप्पणियाँ देते रहेंगे.

कन्हैयालाल नंदन



## वही दुर्गा पोखरेल जेल में है

दो साल पहले नेपाल में चल रहे विद्यार्थी आंदोलन को देखते समझने की गरज से मैं नेपाल के आंदोलित क्षेत्र में घूम रहा था। एक दिन जब मैं नेपाल के मू. प्र. प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता बी. पी. कोइराला के घर से निकल रहा था रास्ते में सरे-आम नेपाली राजशाही का विरोध करती एक चौबीस पच्चीस वर्षीय युवती से मुलाकात हुई, उसे जब यह मालूम हुआ कि मैं भारत में चल रहे समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और नेपाल के विद्यार्थी आंदोलन को समझना चाहता हूँ तो उस ने अपने घर (लाजिम पाठ) चलने का निमंत्रण दिया। वह पूरी रात उस भूत बँगले के मकान में बैठ कर हम लोगों ने बहस करते हुए बितायी। आज पता चला कि वही लड़की दुर्गा पोखरेल सेंट्रल जेल काठमांडो में नजरबंद है।

एक तरफ जहाँ राजशाही अपनी पूरी करतूत के साथ हुकूमत चला रही हो और सारे लोगों की जुबान पर ताला लगा हो, वहीं एक युवती खुलेआम राजशाही के विरोध में आग उगल रही हो, तीसरी दुनिया के किसी भी देश की औरत के लिए इतना ही काफी होता है। दुर्गा पोखरेल पर सरकार ने आरोप लगाया है कि वह 'किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह से मिल कर राजा के 9 वर्षीय सुपुत्र का अपहरण करना चाहती थी' जिस के चलते उसे सरकार ने गिरफ्तार कर नजरबंद किया है और किसी से मिलने भी नहीं देती।

दुर्गा पोखरेल को तत्काल मुक्त किया जाये। यदि सरकार को यह जानकारी है कि वह अपहरण के षड्यंत्र की योजना बना रही थी तो उन पर अदालत में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।

—चंचल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्रसभा, नयी दिल्ली।

## बांटो चाहे न बांटो, यह जमीन हमारी है

कहा जाता है कि बोधगया के महंथ और सरकार के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ है जिस के अनुसार कुछ मजदूरों में जमीन बांट दी जायेगी ताकि आंदोलन दब सके और मिट सके। इसी संदर्भ में विगत 25 मार्च को बीजा जंगल में भूमि वितरण समारोह हुआ। वस्तुतः यह वही जमीन है जिस पर मजदूरों का कब्जा पहले से है तथा मजदूर उस पर खेती कर रहे हैं। बीजा गाँव में 42-55 तथा पीपर घट्टी में 38-27 एकड़ जमीन बाँटने को थी। 21 मार्च को इस बात की आधिकारिक तौर पर जानकारी तब हुई जब सूची बनने लगी। दोनों गाँव

की आम समा में सर्वसम्मति से सूचियाँ बनायी गयीं। बीजा में 7 विधुरों, 36 स्त्रियों तथा पीपर घट्टी में 6 विधुरों, 50 स्त्रियों के नामों की सूची बना कर पेश की गयी।

पुरुष अधिकारी ने स्त्रियों की सूची मानने से इनकार कर दिया। उन का पहला सवाल था—जमीन खेती करने वालों को देने का नियम है। क्या स्त्रियाँ हल जोतेंगी? इस सवाल का जवाब आंदोलन की स्त्रियों माँजरदेवी, आशा और रमणी ने बड़ी तेज तर्रार शैली में दिया। इन का जवाब था: क्या पुरुष धान रोपेगा? क्या स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है? एक वोट पुरुष देता है एक वोट हम लोग भी देती हैं तो हमारा अधिकार पुरुषों से कम कहाँ है? अधिकारियों ने पूछा कि पुरुष के नाम से जमीन मिले या स्त्री के नाम से जमीन तो आप ही की होगी? उत्तर में स्त्रियों ने कहा कि हमारी लड़ाई जमीन की मीख की नहीं, हमारी लड़ाई अधिकार और आजादी की है।

इस के बावजूद अधिकारी महोदय अपनी जड़ पुरुष मानसिकता को सचेत न कर पाये। फलतः पीपरघट्टी गाँव की सूची स्वीकृत न हो सकी। स्त्रियाँ नारा लगाती रहीं—'नारी शक्ति जाग रही है—भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है, बांटो चाहे मत बांटो—सारी जमीन हमारी है'।

विगत 25 नवंबर को 115 पुरुषों को मू-स्वामित्व का पर्चा प्रदान करते हुए ए. डी. एम. ने 15 दिनों के अंदर प्रति पाँच व्यक्ति को वारिंग, डीजल इंजन, बैल आदि देने की घोषणा की थी जो आज तक उन्हें नहीं मिल सका। किंतु इस बार आश्वासन तक नहीं दिया गया, क्या इसी लिए कि मूस्वामित्व का पर्चा इस बार स्त्रियों को मिला है?

—प्रदीपकुमार 'दीप',

बोधगया संघर्ष का एक सैनिक, पीपरघट्टी, शेरघाटी, गया।

## क्रोमोसोम की संखला : विज्ञान की निगाह

24 मार्च: 'अब बाजी नारी के हाथ जा रही है'—यद्यपि वैज्ञानिक तथ्यों व साक्ष्यों से परिपूर्ण एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथापि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम पुरुष व स्त्री दोनों में समान होते हैं, जिन्हें आटोसोम कहते हैं। परंतु 23वाँ जोड़ा पुरुष व स्त्री में भिन्न होता है। इन को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुष में 23वाँ जोड़े के दोनों क्रोमोसोम भिन्न होते हैं व इन्हें एक्स तथा वाई क्रोमोसोम कहते हैं जबकि स्त्री में दोनों क्रोमो-

## समाजवाद के घाट का पानी

रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ बनाम गुलाब पर कर मैंने अपने आँगन में गुलाब के साथ गेहूँ उगाया था। आज गुलाब महत्त्वहीन लग रहा है। अब मुझे गेहूँ से भी अधिक मूसे की चिंता है। रामराज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, यह या तो अतिशयोक्ति है या वे शेर इतने निकम्मे थे जिन से बकरी तक नहीं डरती थी। धन्य हैं आज के शेर जिन्होंने वास्तव में पशु और मनुष्य को एक घाट पानी पिला दिया। अब मूसा गेहूँ के बराबर मूल्य का है। मूसे का भाव दो रुपये किलो है: कोई और मूसा नहीं, पशुओं का चारा। समाजवाद का इस से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता।

श. शर्मा, 1214, भगवानदास  
क्वार्टर, देहरादून।

सोम समान होते हैं व इन्हें एक्स, एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पूर्ण वय होने पर पुरुष व स्त्री में लैंगिक विकास के साथ साथ युग्मक (गैमीट्स) का निर्माण भी शुरू हो जाता है। युग्मक (गैमीट) निर्माण की प्रक्रिया में एक सामान्य कोशा से, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, चार युग्मक (आधे क्रोमोसोम संख्या सहित) बनते हैं। स्त्री में प्रत्येक युग्मक (अंड) में क्रोमोसोम की संख्या व प्रकार समान होते हैं। जबकि पुरुष में आधे युग्मकों स्पर्म्स (शुक्राणुओं) में एक्स क्रोमोसोम होते हैं व आधे में वाई क्रोमोसोम होते हैं। (ऐसा सामान्य तौर पर माना जाता है कि वाई क्रोमोसोम निष्क्रिय या खाली होते हैं अर्थात् उन में गुण संवाहक (जींस) नहीं होते हैं या यदि होते हैं तो ऐसे गुण संवाहकों की संख्या अति न्यून होती है।

गर्भाधान के फलस्वरूप पुरुष के शुक्राणु व स्त्री के अंड के संयुग्मन से संतान पैदा होती है। संतान का पुत्र अथवा पुत्री होना युग्मकों के संयुग्मन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि शुक्राणु (एक्स), स्त्री के अंड (एक्स) से संयुग्मित होता है तो पुत्री व यदि शुक्राणु (वाई) स्त्री के अंड (एक्स) से संयुग्मित होता है तो पुत्र पैदा होता है।

रजत अरोड़ा ने अपने लेख में (पृष्ठ 7) लिखा है कि इस युद्ध में जब एक्स एक्स आकार के वीर्याणु जीतते हैं तो लड़की का जन्म होता है और जब एक्स वाई वीर्याणु अथवा एक्स वाई एंटीजेन जीतते हैं तो पुत्र का। जब कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक वीर्याणु में केवल एक प्रकार का लिंग क्रोमोसोम होता है जिते एक्स या वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इसी प्रकार लेख के अंतिम पैरा (पृष्ठ 9) में वर्णित 'पारिवारिक कर्तव्यों के सामने होते पर भी कभी कभी पुरुष भी एक अद्भुत साहस एवं



1-7 अप्रैल, 1982

देश

- 1 अप्रैल : मई में इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चे द्वारा उम्मीदवारों की सूची और चुनाव घोषणापत्र निश्चित। पाकिस्तान में भारत के राजदूत नटवरसिंह द्वारा विदेशमंत्रालय में सचिव पद ग्रहण।
- 2 अप्रैल : महाराष्ट्र के कांग्रेस (इ) के असंतुष्टों को केंद्रीय नेतृत्व की चेतावनी। हरयाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रद्द।
- 3 अप्रैल : अफगानिस्तान के विदेशमंत्री शाह मुहम्मद दोस्त की नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से वार्ता। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान।
- 4 अप्रैल : जनता पार्टी द्वारा प्रतिपक्षी पार्टियों से एकता की अपील। इंदौर में जहरीली शराब पीने से 11 व्यक्तियों की मृत्यु।
- 5 अप्रैल : केंद्र सरकार द्वारा 1982-83 की आयात-निर्यात नीति की घोषणा। नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और अकाली नेताओं में ढाई घंटे की वार्ता विफल। प्रतिरक्षा मंत्री आर. वेंकटरमण द्वारा भारतीय नौसेना के कार्यों की सराहना।
- 6 अप्रैल : लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरणसिंह द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। सिख नेता संत जर्नैलसिंह भिंडरावाला की दिल्ली के शाही इमाम से वार्ता। जम्मू में प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपक्ष की विफलताओं पर प्रकाश।
- 7 अप्रैल : चार राज्य विधानसभाओं और गढ़वाल संसदीय उपचुनाव के लिए 19 मई को मतदान की घोषणा। 1981 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। दिल्ली के छह सिनेमागृहों के लाइसेंस निलंबित। दिल्ली में पांचवां त्रिवार्षिकी कला समारोह समाप्त। इनसैट छोड़ने में विलंब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले को अधिक समर्थन प्राप्त। लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा चरणसिंह से संन्यास न लेने का आग्रह।

प्रदर्शन ही कला है तो कला की स्मिता पर भी संदेह किया जा सकता है। —हर्षमणि त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय; 452 सुराना ममफोर्ड गंज, इलाहाबाद।

**कैबरे** उन के लिए नहीं है जिन को अपने खून पसीने की कमायी प्यारी है। कैबरे दरअसल उन के लिए है, जिन की तमाम जरूरतें पूरी हो गयी हैं और अब इस दौलत से उन्हें जिंदगी के मजे लूटने हैं। सम्यता की दौड़ में आगे बढ़ते जाने के लिए रोज नये नये तरीके निकाले जाते हैं। किसी समय स्कूल कालेजों में फैशन और फिल्मों की चर्चा में पिछड़े युवक-युवती पिछड़े हुए माने जाते थे और इस आठवें दशक में कैबरे से नाकमौ सिकोड़ने वाले पिछड़े माने जाने लगे हैं।

—प्रभातकुमार मिश्र, महासचिव, बे. प्रशि. शिक्षा संघ, सहरसा (बिहार)

### भूल सुधार

28 मार्च : पृष्ठ 25 पर तीसरे कालम की आठवीं पंक्ति में जोगेंद्र शर्मा ने कहा था कि कैबरे डांसर (कलाकार) वेश्या नहीं होती है। पर 'नहीं' शब्द संपादन के समय भूल से छपने से रह गया है। कृपया पाठक सुधार कर पढ़ें। —सं.

### 'इस गंवारपन को बचा रखो'

'इस गंवारपन को बचा रखो।' अच्छा लगा। हमारे गांवों में कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीके ही ज्यादा उपयुक्त हैं, यह इस लेख से साबित हो गया। गांवों में विकास व आधुनिकीकरण के नाम पर विदेशी नकल को प्रश्रय देना खतरनाक साबित होगा। —माहेश्वरी, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय, सवाई जोधपुर (राज.)

### 30 साल तक प्रतीक्षा

पिछले दो वर्षों से उ.प्र. के छात्र इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि पी. सी. एस. परीक्षा की आयु सीमा 28 वर्ष से 30 वर्ष कर दी जाये। परंतु उ.प्र. के वर्तमान मुख्यमंत्री हर बार आश्वासन दे देते हैं। इस से पी.सी.एस. परीक्षा 1980 एवं 1981 के दो अवसर हाथ से चले गये। 22 जनवरी 1982 को मुख्यमंत्री ने पी.सी.एस. परीक्षा की आयु सीमा 30 वर्ष 1982 से लागू करने का आश्वासन छात्रों को दिया, साथ ही जो उम्मीदवार पी. सी. एस. परीक्षा का 1980 एवं 1981 में अवसर खो चुके हैं, उन्हें विशेष रूप से आयु सीमा में छूट देने का भी वचन दिया। पर यह संभव होगा? —रामस्वरूप गुप्त, 23/47/92 गुप्ता लाज, अजलापुर, इलाहाबाद।

श्रमता का प्रदर्शन करता है। किंतु एक क्रोमोसोम वाले उस गरीब प्राणी की वह शेष जीवन यात्रा एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रायः असंतोष जनक ही होती है। विवरण के विपरीत पुरुष और स्त्री दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। केवल दोनों के लिंग क्रोमोसोम के गुण संवाहकों की संख्या में अंतर होता है।

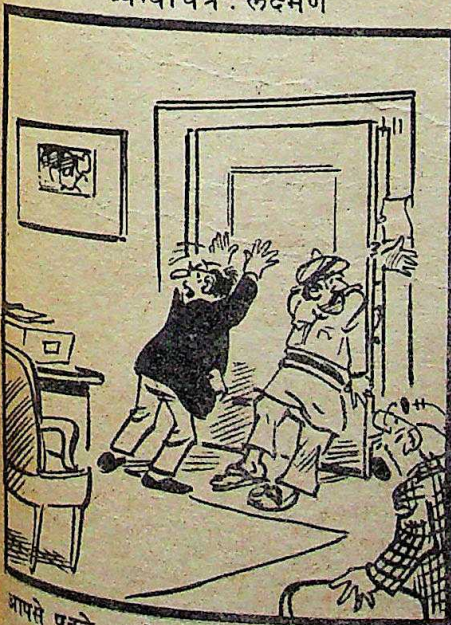
दीनानाथ श्रीवास्तव, सहायक, विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, शाखा प्रधान कार्यालय, नवीन सचिवालय भवन, नागपुर,

### कैबरे : और खून पसीने की कमायी का सवाल

28 मार्च : कैबरे के नाम पर निर्वसन नृत्य तथा मांसल प्रदर्शन पाश्चात्य दृष्टि से चाहे ठीक हो परंतु भारतीय दृष्टि से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कैबरे नवयुवकों को पयःप्रष्ट करने वाले और उन में पुरुषार्थ तथा आत्मविश्वास के स्थान पर कामुकता एवं विलासिता उत्पन्न करने वाले हैं। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई उचित एवं सराहनीय है परंतु पता नहीं वह अभी तक क्यों मौन रही? —शकुनचंद गुप्त विशारद, स्थान पो. लाल गंज, जि. रायबरेली (उ. प्र.)

**कैबरे** का प्रचलन भारतीय नारी की गौरव परिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यदि अभावग्रस्त नारी की नग्नता का

आप फरमाते हैं  
व्यंग्यचित्र : लक्ष्मण



आपसे पहले वाले फिर कुर्सी हथियाने की कोशिश में हैं

पानी

नाम गुलाब पत्र  
व के साथ सह  
नीन लग रहा है  
ने की चिता है  
एक घाट पानी  
त है या वे शेर  
होंने वास्तव में  
पानी पिला  
र मूल्य का है  
कोई और मूसा  
माद का इस में

4, भगवानदास  
गार्टर, देहरादून

म, एक्स क्रोमो-  
पुरुष व स्त्री में  
नक (गैमीट्स)  
ता है। युग्मक  
में एक सामान्य  
के फलस्वरूप  
संख्या सहित)

अंड) में क्रोमो-  
होते हैं। जबकि  
शुक्राणुओं) में  
में वाई क्रोमो-

तौर पर मान-  
क्रिय या खाली  
हक (जींस)  
ऐसे गुण संवा-

के शुक्राणु व  
पेदा होती है।  
ना युग्मकों के  
करता है। यदि  
(एक्स) से  
शुक्राणु (वाई)  
त होता है तो

में (पृष्ठ 7)  
एक्स आकार  
का जन्म होता  
यवा एक्स वाई  
व कि उपरोक्त  
पार्ण में केवल  
होता है जिसे  
इसी प्रकार  
) में वंशित  
होते पर भी  
त साहस एवं

4 अप्रैल '82



# पिछले सप्ताह

## विदेश

1-7 अप्रैल, 1982

- 1 अप्रैल : पोलस्का के एक सैनिक विमान का अपहरण कर बीएना ले जाया जाना. कैनाडा द्वारा एक सोवियत राजनयिक निष्कासित. बंगलादेश के भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री जमालुद्दीन अहमद द्वारा फौजी कानून प्रशासक के समक्ष ढाका में आत्मसमर्पण.
- 2 अप्रैल : आर्हेतीना द्वारा ब्रितानी बस्ती फॉकलैंड पर कब्जा. मेक्सिको में एक ज्वालामुखी फटने से 100 व्यक्तियों की मृत्यु.
- 3 अप्रैल : ब्रिटेन द्वारा फॉकलैंड द्वीपसमूह में भारी मात्रा में सैनिक साजसमान का भेजना. संयुक्तराष्ट्र में इस्राइल के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग.
- 4 अप्रैल : आर्हेतीना द्वारा सेंट जॉर्ज द्वीप पर अधिकार. बंगलादेश में विशेष फौजी न्यायालय गठित. लरकाना में जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र पर हजारों लोगों द्वारा श्रद्धांजलि. आबू धाबी में 'ओपेक' देशों की आपात-कालीन बैठक. ईस्टर के अवसर पर पोलस्का में कर्फ्यू में ढील की घोषणा.
- 5 अप्रैल : ब्रितानी विदेशमंत्री लॉर्ड कैरिस्टन तथा दो अन्य मंत्रियों का टैंकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र और फ्रांसिस पेयम नये विदेशमंत्री नियुक्त. किम इल सुङ उत्तर कोरिया के राष्ट्र-पति पुनर्निर्वाचित. आर्हेतीना द्वारा फॉकलैंड द्वीपसमूह के मुद्दे पर ब्रिटेन से वार्ता का प्रस्ताव.
- 6 अप्रैल : फॉकलैंड के मामले पर ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट टैचर द्वारा त्यागपत्र देने से इनकार. पोलस्का द्वारा न्यूजीलैंड में अपना दूतावास बंद करने का फैसला.
- 7 अप्रैल : मेक्सिको में एक ज्वालामुखी के फटने से पाँच हजार व्यक्तियों के मरने की आशंका. गुटनिरोधक देशों द्वारा ईरान-इराक में शांति स्थापित करने का प्रयास विफल. बंगलादेश के सात बरिष्ठ असेनिक अधिकारियों को अपने पदों से अवकाश प्रदान. फॉकलैंड की समस्या के हल के लिए अमेरिकी विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग द्वारा मध्यस्थता का एलान.

फिल्म देखने पर प्रसिद्ध क्यों नहीं?

28 मार्च : जावेद अली का पत्र पढ़ा. आश्चर्य हुआ कि श्री अली यह मानते हैं कि आज की अधिकांश हिंदी फिल्मों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, वह समाज के लिए विष है. और फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगाने की भर्त्सना करते हैं, क्यों?

फिल्मों के विरोध की बात चल पड़ी है. अतः इस विरोध के समर्थन पर एक विस्तृत दृष्टिपात की आवश्यकता है. हम अपने आस-

पास एक नजर डालें तो चारों ओर फिल्म का वातावरण बना हुआ है. छात्र स्कूल या कालेज छोड़ कर फिल्म देखने जाते हैं. मजदूर, कुली, तांगेवाले शाम होते ही सिनेमा देखने चल पड़ते हैं. घर में छोटे बच्चे भी फिल्म देखने की इच्छा प्रकट करते हैं और फिल्म आम आदमी की एक आवश्यकता बन गयी है. इस पर भी सिनेमा हाल में जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है सर्वविदित ही है.—सत्यदेव शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राजस्व लेखा शाखा, जिलाधीश कार्यालय, पाली, मारवाड़ (राजस्थान),

दिनमान 4-10 अप्रैल के अंक में वित्त राज्यमंत्री श्री सवाईसिंह सिसोदिया के बारे में कुछ आरोपों का जिक्र आया है. श्री सिसोदिया के बारे में ऐसा पढ़कर आश्चर्य हुआ. इस संदर्भ में मैंने उनसे खुलकर बातचीत की. पाठकीय उपयोगिता को ध्यान में रखकर पूरी बातचीत दिनमान को भेज रहा हूँ.

—डॉ. शिव शर्मा, सी-42, ऋषिनगर, उज्जैन



सिसोदिया जो का कहना है...

## ये आरोप राजनीतिक द्वेषवश लगाये जा रहे हैं

आप केंद्रीय मंत्री मंडल के एक महत्वपूर्ण विभाग के राज्यमंत्री हैं. फिर आप को राज्यसभा का टिकट क्यों नहीं दिया गया?

सिसोदिया: टिकट दिया जाना, न दिया जाना कांग्रेस (इ) पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है. हाईकमान की अपनी नीतियाँ हैं. मैं हर आदेश का एक सिपाही की तरह पालन करूँगा. विरोधी पार्टियों को अपने दल की दयनीय स्थिति को ठीक करने में समय अधिक देना चाहिए बजाय हमारे दल के अंदर झाँकने में, समय गंवाने में.

टिकट न दिये जाने का कारण, आप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, बताया जा रहा है?

सिसोदिया: भ्रष्टाचार के झूठे आरोप किस पर नहीं लगाये गये? कोई एक आप सप्रमाण लगाये, मैं जाँच करवाने के लिए तैयार हूँ. स्वतंत्रता पूर्व से कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही रहा हूँ. पूर्व मध्य भारत, मध्यप्रदेश में मंत्री रहा, म. प्र. कांग्रेस का महामंत्री रहा, सहकारी आंदोलन में वर्षों से जुड़ा हूँ. 29 वर्षों से राज्यसभा सदस्य हूँ. गत 37 वर्षों के राजनैतिक सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा. अब मंत्री बन जाने पर, राजनैतिक द्वेषवश झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश की गुटबंदी के कारण क्या आप का टिकट कटा?

सिसोदिया: मध्यप्रदेश में मेरा कोई गुट नहीं है. मैं कांग्रेस की एकता में विश्वास रखता हूँ. प्रादेशिक गुटबंदी में मेरा कभी नाम नहीं आता. किसी भी नेता से मेरा कोई झगडा नहीं. अतः इस बात का टिकट न मिलने से कोई संबंध

नहीं है. हमारे नेतृत्व को यह अधिकार है कि वह जिस कार्यकर्ता को चाहे जो कार्य सुपुं करे और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे निष्ठा ईमानदारी से पूरा करें.

आप के पुत्र पर भी आरोप हैं?

सिसोदिया: मेरा पुत्र वीरेंद्रसिंह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक है तथा वकालत कर रहा है —राजनीति में चरित्र हनन और कीचड़ उछालने वाली जमात ने कब किस को बख्सा है? झूठे आरोप आप किसी पर भी लगा सकते हैं. प्रमाण क्या हैं?

आप पर किसी विदेशी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है?

सिसोदिया: जो मूख से परिचित हैं, वे जानते हैं कि मैं अपने विरोधियों से भी दुर्व्यवहार नहीं करता. किसी विदेशी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार की बात मनगढ़ंत तथा सफेद झूठ है. हमारे क्षेत्र के कुछ पीत पत्रकार जो ब्लैक मेल का घंघा करते हैं, इस प्रकार के शगुफे उड़ाने में माहिर हैं. लेकिन मैं इस से डरने वाला नहीं.

आगे आप की क्या योजना है?

सिसोदिया: मैं राजनीति में योजना बना कर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ—कांग्रेस के सिद्धांतों और अपनी नेता श्रीमती गांधी पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ. मैं उन के किसी भी आदेश का अनुशासन के साथ पालन करूँगा. चरित्र हनन और झूठे आरोपों के काले बादल अधिक दिन टिकते नहीं. मैं गुटबाजी और तिकड़म में विश्वास नहीं करता. अभी तक जो काम सौंपा गया, उसे पूरी निष्ठा से पूरा करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा.



जलते प्रश्न

## पद से अधिक योग्य की नियति

काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की उपाधिप्राप्त डा. राना पी. बी. सिंह का नाम युवा भूगोलविदों में बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन उनके साथ आज तक जो सलूक किया गया उसे सुन कर सर शर्म से झुक जाता है।

ख्यातिप्राप्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज जिस तरह की गंदी राजनीति चल रही है इस की बराबरी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह की राजनीति के तहत डा. राना सिंह के साथ कई बार की तरह इस बार भी गलत व्यवहार किया गया। वह भी एक ऐसे हंसमुख और जिंदादिल इंसान के साथ जिस ने करीब आठ दशक तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही भूगोल विभाग में अस्थायी अध्यापक का कार्य किया।

इतना ही नहीं, इन के शोध कार्यों से प्रभावित हो कर अमेरिका के होनोलूलू (हवाई) विश्वविद्यालय ने इन्हें अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया।

अजिनिया टेक में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहने के बाद ओकायामा विश्वविद्यालय (जापान) में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। तब तक इन के करीब 60 शोध पत्र तथा 12 शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। पिछले दशक में इन्होंने सोवियत संघ (क्रैमलिन) में आयोजित भौगोलिक संगोष्ठी में ऐतिहासिक व्याख्यान दिये। अफ्रीका के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन के व्याख्यान आयोजित किये गये। इन सारी योग्यताओं से प्रभावित हो कर अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संगठन ने इन्हें अपना उपाध्यक्ष चुन कर सम्मानित किया। लेकिन वहशियत एवं जुल्मी इरादों के हाथों में पल रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन्हें मामूली प्रवक्ता का भी पद नहीं दे सका।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में चार रीडर तथा पाँच लेक्चरर की जगह काफी दिनों से खाली थी। डा. राना सिंह ने भी आवेदन दे रखा था। आवेदनपत्रों के प्रस्तुत होने के बावजूद कई महीने तक साक्षात्कार की गारंटी निश्चित नहीं की गयी। साक्षात्कार की गारंटी रखी गयी पिछले 16 मार्च को, जिस दिन से मेरठ विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संगठन की पाँच दिवसीय संगोष्ठी शुरू होने वाली थी। ख्यातिप्राप्त युवा भूगोल विद साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सका।

## अफगान बागियों की मदद करो

अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण को ले कर हाल ही के कुछ दिनों से पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों में काफी चर्चा है। प्रायः सभी पश्चिमी यूरोपीय समाचारपत्रों का मत है कि आक्रमण के लिए सोवियत संघ की निंदा करने से ही काम नहीं चलेगा; इस से अधिक कुछ किया जाना चाहिए। पश्चिम जर्मनी के प्रसिद्ध साप्ताहिक हानोवेशे अल्गेमाइने ने अपनी टिप्पणी में कहा है:

‘मले ही पश्चिम यूरोप अफगानिस्तान पर सोवियत आधिपत्य की निंदा कर रहा है पर इस से अफगानों की कोई मदद नहीं होगी। अफगानिस्तान के लोग अपने देश में और देश से बाहर अपनी मुक्ति के लिए कारगर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह करने वाले अफगानी गुटों को हथियार दिये जाने चाहिये, जिस से सोवियत हेलीकॉप्टरों से चलने वाली गोलियों का वे मुकाबला कर सकें। जहाँ जहाँ सोवियत सेना के खिलाफ विद्रोह हो रहा है वहाँ वहाँ सोवियत हेलीकॉप्टर और मशीनगनों उन्हें दबा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सोवियत सेनाओं का मुकाबला करने वाले अफगान सैनिकों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस के अलावा विद्रोही अफगानों को बाहर से काफी सहायता चाहिए। दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले लगभग 27 महीनों से एक देश अपने मूल अधिकारों से वंचित है और सोवियत साम्राज्यवाद का शिकार है। सोवियत संघ आसानी से अफगानिस्तान छोड़ने वाला नहीं है, मले ही उसे इस के लिए भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।



पर साथ ही अफगानिस्तान पर आक्रमण से सोवियत संघ की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है। सोवियत संघ अभी तक दुनिया में तनातनी कम करने की जिस नीति का दावा करता है उस की पोल भी खुल गयी है। निस्संदेह निकट भविष्य में तो सोवियत संघ के वहाँ से हटने की आशा नहीं की जा सकती। वह इस समस्या का राजनैतिक समाधान चाहता है और राजनैतिक समाधान का मतलब यह है कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण को मान्यता मिल सके, जिस का मतलब यही होगा कि दुनिया ने अफगानिस्तान को सोवियत संघ का एक उपनिवेश मान लिया है।

## भारतीय संस्कृति की अटूट धारा

लंदन में भारत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कला प्रदर्शनी में ब्रितानी समाचार पत्र गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। पत्रों के कला स्तंभों में कला समीक्षकों ने भारतीय कला वस्तुओं के संदर्भ में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जहाँ एक ओर सराहना की है वहाँ कलाकृतियों के चयन और प्रदर्शनी में उन के क्रम पर टीका टिप्पणी भी की है। प्रमुख ब्रितानी साप्ताहिक न्यू स्टेट्समैन ने अपने कला स्तंभ में लिखा है :

‘भारतीय सभ्यता की विशेषता है कि अनेक आक्रमणों के बावजूद विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में यही जीवित है।

‘भारत महोत्सव के अवसर पर भारतीय चित्रों और मूर्तियों की प्रदर्शनी में कला इतिहास की दृष्टि से कलाकृतियों का क्रम नहीं है और उस में सौंदर्य बोध का अभाव भी है। ईसा से पहले की दूसरी शताब्दी की कलाकृतियाँ ईसा के बाद की 11वीं शताब्दी की कला कृतियों के साथ रखी हुई है। ईसा के बाद की पाँचवीं शताब्दी की चीजें 18 वीं शताब्दी की कलाकृतियों के साथ रखी है। संयोगवश इन में से बहुत सी कलाकृतियाँ अत्यंत सुंदर हैं पर प्रदर्शनी में उन्हें देख कर दार्शनिक, धार्मिक, पौराणिक किसी भी दृष्टि से पूर्ण संस्कृति का आभास नहीं होता। किसी भी कलाकृति पर कलाकार का नाम तो नहीं है, पर कला प्रदर्शनी विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत को प्रस्तुत करने में तो सफल रही ही है।

‘चित्रों के मुकाबले मूर्तियों की संख्या अधिक है। चित्रों में अधिकतर धार्मिक जीवन का चित्रण है, जैसे कि योग, तपस्या और पौराणिक कथाएँ। पर अधिक संख्या ऐसे चित्रों की है जिन में राजदरबारों का चित्रण है।’



"हम चाहते हैं कि प्रभुसत्ता, सम्मान और गरिमा के आधार पर भारत के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो. मुझे आशा है भारत हमारी इस भावना का समादर करेगा"  
—फैसलाबाद में जनरल जिया-उल-हक; 12 अप्रैल, 1982

## भारत-पाक : युद्ध की निंदा कर देने से ही समस्या हल नहीं होती

—इंद्रजीत

पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति निरंतर बढ़ाता जा रहा है, जिस से भारत सरकार का परेशान होना स्वाभाविक है. जम्मू अपने हाल ही के एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की. श्रीमती गांधी ने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भारत-पाकिस्तान सीमा पर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखनी होगी. श्रीमती गांधी ने कहा: "भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध से बचा जाये. परंतु हमें हर स्थिति का सामना करने को तैयार रहना ही है. युद्ध का खतरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और शस्त्र खरीदने की दौड़ से मामला और भी गंभीर हो गया है".

विडंबना यह है कि पाकिस्तान में इस समय भी युद्ध की प्रबल मनोस्थिति बनी हुई है, बावजूद इसके कि वह अमेरिका से प्राप्त होने वाली 3.2 अरब डालर की सहायता के अंश के रूप में, घातक एफ-16 विमानों की मांग कर रहा है. उस ने भारत को 'युद्ध न करने के समझौते' को जो बार बार पेशकश की उस में भी उस मनोस्थिति की प्रतिच्छाया है. यह दुर्भाग्य की बात है कि उस दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो गयी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की फरवरी में जेनेवा में हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान के शिष्टमंडलों में कुछ टकराव हो गया था. गत वर्ष में दो सप्ताह के दौरे पर पाकिस्तान गया था, तो मुझे यह महसूस हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों को इस बात का भय है कि भारत की शक्ति बहुत है और उन्हें यह विश्वास है कि जितना पाकिस्तान शेष बचा है उसे भी भारत समाप्त करने पर तुला हुआ है. एक नेता ने यहाँ तक कहा था कि आधा पाकिस्तान तो उन से पहले ही छीना जा चुका है.

स्पष्ट है कि गहन अविश्वास और परस्पर संदेह के कारण भारत पाकिस्तान संबंधों में भीषण कटुता आ गयी है. दिसंबर 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया. यह एक ऐतिहासिक अवसर था, जब कि भारत और पाकिस्तान एक सामान्य खतरे के परिणामस्वरूप अपने मतभेदों को समाप्त कर सकते थे. यह बात आम तौर पर कही और मानी जाती है कि कोई भी आक्रमणकारी जब खैबर पर पहुँच जाता है तो वह वहीं पर नहीं रुकता. वह फिर पानीपत और उस से भी

आगे तक जाता है. नेहरू ने तो एक बार अपनी एक महत्वपूर्ण फाइल पर लिख दिया था कि भारतीय सुरक्षा सीमा तो सिंधु नदी के साथ है और जिस के साथ, रूस और अफगानिस्तान की सीमा लगती है.

अमेरिका यदि अपनी कूटनीति की रचना व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता के आधार पर करता तो शायद स्थिति आज से कुछ भिन्न होती. अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को घड़घड़ हथियार दिये जाने के कारण स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, भारतीय दृष्टिकोण तथा धारणा बदल गयी. इस उप-महाद्वीप के समझ जो अभूतपूर्व खतरा उभर आया था, उस की निरंतर उपेक्षा कर दी गयी. भारत में एकाएक एक ही चिंता सर्वत्र व्यक्त की जाने लगी कि पाकिस्तान भारत के लिए भीषण खतरा बनता जा रहा है. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1967 और 1971 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिये थे. हथियारों को देने का उद्देश्य यह था कि साम्यवादी प्रसार और उन के हमलों का सामना किया जाये. परंतु उन हथियारों का प्रयोग बहुत ही बुरी तरह भारत के विरुद्ध किया गया. स्वर्गीय कृष्ण मेनन ने एक बार यह कहा था कि विश्व में ऐसी बंदूक का अभी निर्माण नहीं हुआ, जो एक ही ओर चल सकती हो.

जनरल जिया भारत से 'युद्ध न करने' के समझौते की पेशकश कर रहे हैं, उस के बारे में भारत में व्यापक संदेह पाये जाते हैं. चाहिए तो यह था कि भारत के कर्णधार इस पेशकश को तुरंत स्वीकार कर लेते, क्योंकि इस्लामाबाद से जो कुछ आज कहा जा रहा है,

नयी दिल्ली में वही 1949 से ही कहा जा रहा है. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गत वर्ष जनरल जिया ने एक भारतीय पत्रकार से कहा था, "मैं युद्ध न करने के समझौते का उतना मूल्य भी नहीं समझता जितना कि उस कागज का है जिस पर कि यह लिखा होता है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इन 'युद्ध न करने' के और शांति समझौतों से अंततोगत्वा कोई लाभ नहीं होता."

भारत के अधिकांश लोगों का यह मत है कि अमेरिकामें पाकिस्तान को सैनिक सामान और एफ-16 देने का जो विरोध हो रहा है, उसे समाप्त करने के लिए "युद्ध न करने" के समझौते का ढोंग रचा जा रहा है. अमेरिका में भारत के मित्रों ने इस पर पाकिस्तान के लिए कोई समस्या नहीं पैदा की. इस बारे में सारी स्थिति का मौके पर अनुमान लगाने के लिए अमेरिका कांग्रेस की एक समिति भारत और पाकिस्तान के दौरे पर भी आयी. परिणामस्वरूप इस बारे में अंतिम निर्णय करने में काफी देर हो गयी. इस बारे में एक महत्वपूर्ण कारण और भी है, जो लोगों की दृष्टि में नहीं आया.

जनरल जिया ने यह पेशकश इसलिए भी की थी कि उन्हें पाकिस्तान के इतिहास से कुछ कटु अनुभव हो चुके हैं. 'राजनैतिक जनरल' जब भी कभी भारत के विरुद्ध सक्रिय हुए, उस पर हमला किया तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी. जिन राजनीतिज्ञों ने इन जनरलों को उकसाया और उत्तेजित किया वे लाभ में रहे. उन के हाथ में और भी अधिक सत्ता आ गयी. 1965 में अय्यूब खान के मामले में यही हुआ और 1971 में जनरल याहिया खान के साथ भी.

दोनों ही मामलों में सब से अधिक लाभ

मुद्दों को खूब मड़क विश्वास के जिया भा चाहते और भी उनकी करने का चीज है. ज बनाये हुए नहीं पड़ता समझते हैं, बुद्धि हैं. वि के मामले उनका विच पंदा कर सकती है. भारत का मुख्य क पाकिस्तान आया है. अ के प्रस्ताव शायद कि पाकिस्तान समय पाकि प्रस्तुत करते हल करो, पि करेंगे. इस ब नहीं हुआ अ पहले कश्मी क्यों और पाकिस्तानी यात्रा के दो भावनाएं अ हैं. जैसी वि रखनी चाहि सम्मेलन के विमान



जा रहा  
कि गत  
कार से  
गैते का  
कि उस  
होता है,  
युद्ध न  
तो गत्वा

मत है  
सामान  
हो रहा  
करने

मेरिका  
तान के  
बारे में  
गाने के  
भारत  
आयी.  
निर्णय  
में एक  
गों की

ए भी  
तिहास  
नैतिक  
सक्रिय  
निराशा  
ने इन  
किया  
अधिक  
मामले  
पाहिया

क लाम  
स '82

मुट्टो को मिला. उन्होंने दोनों जनरलों को खूब भड़काया था. आम धारणा के विपरीत विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जनरल जिया भारत के साथ कोई टकराव नहीं चाहते और घरेलू स्थिति से ध्यान हटाने में भी उनकी कोई रुचि नहीं है. प्रत्युत 'युद्ध न करने' का समझौता ही उनके लिए आदर्श चीज है. जो उन से सत्ता छीनने की योजनाएँ बनाये हुए हैं उनके लिए अवश्य यह अनुकूल नहीं पड़ता. लोग उनको जितना चतुर समझते हैं, उस से वह कहीं अधिक तीक्ष्ण बुद्धि हैं. विधि और व्यवस्था को लागू करने के मामले में उनका रवैया कड़ा है, क्योंकि उनका विचार है समुचित डर और आदर पैदा कर के ही कोई सरकार शासन कर सकती है.

भारत और पाकिस्तान के बीच के खिचाव का मुख्य कारण कश्मीर है. कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की नीति में मौलिक परिवर्तन आया है. अतीत में भारत के 'युद्ध न करने' के प्रस्ताव को इस लिए ठुकरा दिया जाता था क्योंकि इस से यह आभास मिलता था कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर बेच दिया है. उस समय पाकिस्तानी नेता बड़े जोर से यह तर्क प्रस्तुत करते थे कि पहले कश्मीर की समस्या हल करो, फिर हम 'युद्ध न करने' का समझौता करेंगे. इस बारे में अब कोई इस तरह का शोर नहीं हुआ और यह आवाज भी नहीं उठी कि पहले कश्मीर की समस्या हल करो.

क्यों और कैसे? इस का उत्तर एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी नयी दिल्ली की यात्रा के दौरान दिया. उन्होंने कहा, "हमारी रायनाएँ अब भी कश्मीर के बारे में वैसी ही हैं, जैसी कि पहले थीं. परंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार

नहीं किया था, जबकि हमारे एक लाख सैनिक भारत की कैद में थे और पाकिस्तान की 5,000 वर्ग मील भूमि भी भारत के ही कब्जे में थी. परंतु जब स्थिति यह बनी कि रुस खैबर पर आ गया तो सर्वत्र पाकिस्तानी लोग यह कहने लग गये कि 'देखना, कहीं कश्मीर लेते लेते, सारा पाकिस्तान ही हाथ से न खो बैठना. अतः हमें मित्र बनना चाहिए और 'युद्ध न करने' के समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए."

मैंने पूछा कि अगर पाकिस्तानी अब भी कश्मीर के लिए चिंतित हैं तो क्या फिर हथियार उठा कर (युद्ध का) वे तीसरा दौर नहीं शुरू करेंगे. पाकिस्तानी पत्रकार का उत्तर था : "हमें पागल नहीं हैं कि फिर दुस्साहसिक सैनिक अभियान के फेर न पड़ें. हमें अपनी और आपकी भी ताकत का अंदाजा है. युद्ध से भारत का तो केवल नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान नष्ट ही हो जायेगा. . . नहीं, ये मेरे ही नहीं आम लोगों के भी विचार हैं, किंतु आप हम से कश्मीर में यथास्थिति स्वीकार करने के लिए न कहें. अलबत्ता आप खुद कहते रह सकते हैं कि मामला निपट गया. अंततः समय सब कुछ निपटा देगा."

फिर भी 'युद्ध न करने' का समझौता करना उतना सरल नहीं, जितना कि कहना. भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मौलिक मतभेद हैं, जिन्हें इस तरह के समझौते में व्यक्त करना ही चाहिए. भारत सरकार की ओर से तो अयुद्ध समझौते के बारे में उन सात सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया था जो कि इसमें शामिल किये जाने चाहिए. ये सिद्धांत लगभग वही हैं जिन्हें शिमला समझौते के अंतर्गत स्वीकार किया गया था. इन्हें शांतिप्रिय सहअस्तित्व के सिद्धांत भी कहा जा सकता है. इस के अंतर्गत एक दूसरे की अखंडता, प्रमु-

सत्ता, द्विपक्षवाद और गुटनिरपेक्षता इत्यादि आ जाते हैं.

स्वयं पाकिस्तान स्वीकार करता है कि ये सिद्धांत रचनात्मक हैं और उसने भारत को यह आश्वासन भी दिया था कि वह शिमला समझौते से प्रतिबद्ध है. परंतु वह कुछ स्पष्टीकरण चाहता है कि इसके अंतर्गत स्वीकार किये गये सिद्धांतों का क्षेत्राधिकार क्या है. भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि दोनों देश अपने मतभेद और विवाद आपस में ही निपटायेंगे. शिमला समझौते के अंतर्गत यही व्यवस्था है.

**भारत का मत है कि इसके अनुसार** पाकिस्तान कश्मीर तथा कोई अन्य द्विपक्षीय मामला संयुक्तराष्ट्र संघ के मंच से नहीं उठा सकता. इस तरह के मामले किसी अन्य विश्व मंच पर भी नहीं उठाये जा सकते. परंतु इस दृष्टिकोण को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता. वह यह मानता है कि हमने यह माना है कि दोनों देश 'शिमला समझौते के अंतर्गत अपने मतभेद परस्पर बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटायेंगे.' परंतु वह यह नहीं मानता कि कश्मीर के मामले को संयुक्तराष्ट्र संघ तथा अन्य किसी विश्व मंच पर उठाया ही नहीं सकता. इस के लिए वे लोग दो तर्क प्रस्तुत करते हैं :

प्रथम यह कि शिमला समझौते के अंतर्गत 'जम्मू और कश्मीर समस्या के अंतिम हल' की व्यवस्था है. दूसरा इसमें यह भी है कि जम्मू और कश्मीर की वास्तविक नियंत्रण रेखा का, जो 17 दिसंबर, 1971 के युद्ध-विराम के बाद निर्धारित हुई थी, दोनों पक्ष आदर करेंगे, लेकिन दोनों पक्षों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. संयुक्तराष्ट्र संघ में भी कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की यही स्थिति

विमान



है और यह संयुक्तराष्ट्र संघ की कार्यसूची में दर्ज भी है। पाकिस्तान का तर्क है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को संयुक्तराष्ट्र संघ में यह बात कहने से कैसे रोका जा सकता है कि वह उपमहाद्वीप में स्थायी शांति चाहता है और आशा करता है कि दोनों के बीच के 'कश्मीर विवाद का अंतिम हल' शिमला समझौते के अंतर्गत शीघ्र ही निकल आयेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच जेनेवा के मानव अधिकार आयोग में जो झड़प हो गयी, उस का कारण यह था कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि आगा हिलाली ने तो कश्मीर का उल्लेख पारंपरिक ढंग से रस्मी तौर पर किया, परंतु भारतीय प्रतिनिधि बलिराम भगत ने इस का जो उत्तर दिया वह भारत के बंधे हुए ढर्रे के अनुसार नहीं था। पाकिस्तान 1977 से एक ही तरह की बात कश्मीर के बारे में करता चला आ रहा है और भारत भी उसी ढंग का उत्तर ही निरंतर देता रहा है।

जिस प्रश्न को दोनों के बीच सुलझाया जाना है वह यह है कि द्विपक्षवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। रोचक बात यह है कि इस शब्द का उल्लेख शिमला समझौते में कहीं नहीं है, यद्यपि मुझे यह बताया गया कि भारत में श्री कृष्ण मेनन और पाकिस्तान में श्री मुट्टो के अपने अपने विचार थे। यह भी कहा जाता है कि इस बारे में एक दो पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं।

विश्व मंच पर कश्मीर का उल्लेख करने के बारे में पाकिस्तान का अपना तर्क हो सकता है और भारत का भी इस बारे में अपना दृष्टिकोण है। वह यह कि कश्मीर के मामले को इस्लामी शिखर सम्मेलन में उठाने का क्या औचित्य था? एक स्थिति तो ऐसी भी आयी थी कि जनरल जिया ने इस्लामी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए न केवल कश्मीर का उल्लेख ही किया, वरन इसे प्राप्त करने के लिए समस्त इस्लामी समुदाय की सहायता का आह्वान भी किया।

गुटनिरपेक्षता और क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में भी दोनों देशों का अपना अपना दृष्टिकोण है। भारत सरकार का कहना है कि यदि पाकिस्तान गुट निरपेक्षता के साथ वचनबद्ध है, तो वह किसी भी विदेशी शक्ति को अपनी घरती पर सैनिक अड्डे निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकता। पाकिस्तान का कहना है कि भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी परिभाषा नहीं बना सकता। पाकिस्तान गुटनिरपेक्षता को उसी परिभाषा पर कायम है जिसे हवाना और नयी दिल्ली में स्वीकार किया जा चुका है और जो उस का मूल स्वरूप है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि गुटनिरपेक्ष देशों की स्थिति देखते हुए गुटनिरपेक्षता की वचनबद्धता की कोई अपेक्षा नहीं है। कूबा को ही लीजिए जिस की राजधानी हवाना में पिछला शिखर सम्मेलन हुआ था।

कूबा में रूसी अड्डे हैं, इथियोपिया और दक्षिण यमन में भी हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने वाले देशों में से है, जिसने इस के लिए नेहरू, नासिर और टीटो का पूरा साथ दिया था, आज उस की घरती पर भी एक लाख रूसी सेना पड़ी है। यद्यपि रूस कहता है कि रूसी सैनिकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया, परंतु जो तथ्य हैं वे तो बोल ही रहे हैं। कहा जाता है कि वे अफगानिस्तान के निमंत्रण पर वहाँ गये हैं। पाकिस्तान भारत के उन प्रयासों का स्वागत करता है, जिनका उद्देश्य यह है कि शीत युद्ध को इस क्षेत्र से दूर रखना है। परंतु इस का यह मतलब नहीं कि वह अमेरिका से सहायता न ले, जबकि उस के पड़ोस में अफगानिस्तान पर रूस का हमला हो चुका है।

**स**ब झगड़ों की जड़ और भारत तथा पाकिस्तान के बीच अविश्वास का कारण यह है—भारत का विचार है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के 'विशेष' संबंध हैं जबकि पाकिस्तान की धारणा यह है कि भारत रूस की ओर अत्यधिक झुका हुआ है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अब भी 1959 का समझौता कायम है जिस के अंतर्गत साम्यवादी या साम्यवाद प्रेरित हमला होने पर वह अमेरिका से परामर्श कर सकता है। भारत को यह भय है कि पाकिस्तान अपने नये और आधुनिक बंदरगाह ग्वादर को विदेशी नौवहन अड्डे के रूप में बदल देगा।

भारत-रूस शांति और मित्रता की संधि के खंड-9 का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान कहता है कि "इस के अंतर्गत यदि दोनों में से किसी एक पर हमला होता है तो वे इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे और तुरंत ऐसी कार्यवाही करेंगे जिस से दोनों की शांति और सुरक्षा कायम रहे।"

पाकिस्तान यह भी कहता है कि रूस तो इस संधि के अंतर्गत तुरंत कार्यवाही कर सकता है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कुछ करने से पूर्व, अमेरिका को अपनी कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उस के बाद ही वह पाकिस्तान की कुछ सहायता कर सकता है। पाकिस्तान यह भी प्रयास करता रहा है कि 1959 के समझौते को एक पूरे प्रतिरक्षा समझौते में बदल दिया जाये, परंतु ऐसा हो ही नहीं सका।

अब स्थिति क्या है? प्रयास किया जाना चाहिए कि दोनों देशों में शस्त्रों की दौड़ कम हो, यद्यपि कूटनीतिक साधनों से 'युद्ध न करने' के समझौते के, तथा संयुक्त आयोग निर्माण करने के बारे में बातचीत चलती रहनी चाहिए। दोनों देश अपने साधनों का बड़ा भाग शस्त्रों

पर लगा रहे हैं, जबकि इनका प्रयोग गरीबी हटाने पर होना चाहिए। पाकिस्तान एफ-16 विमान और एम-60 टैंक मांग रहा है, जिन का आज विश्व में कोई मुकाबला ही नहीं है। अधिकृत सूत्रों का यह भी कहना है कि वह परमाणु बम भी बना रहा है।

भारत ठीक ही पूछता है कि 'आखिर ये सब शस्त्र पाकिस्तान किस लिए ले रहा है? स्पष्ट है कि इनका प्रयोग रूस के विरुद्ध नहीं होने वाला है।' पाकिस्तान इस के उत्तर में कहता है कि 'भारत जैंगुआर, मिराज, मिग और आधुनिकतम रूसी टैंक क्यों ले रहा है? ये सब चीन के विरुद्ध तो प्रयोग होंगे नहीं।' अतः इस बारे में वार्ता होनी चाहिए और हथियारों की दौड़ समाप्त होनी चाहिए। 'युद्ध न करने' के समझौते की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। इसका एक तरीका यह है कि जनरल जिया की ईमानदारी की परीक्षा लेने हेतु उन के प्रस्ताव के अनुसार, अनुपात से सेनाएँ कम कर देने का कोई जरिया खोजना चाहिए।

दोनों देशों की सेनाओं के अनुपात की बात पाकिस्तान की ओर से 1980 में कही गयी थी। पहले भारत के विदेश सचिव श्री साठे से और उस के बाद सरदार स्वर्ण सिंह से, श्री नरसिंह राव भी जब पाकिस्तान गये थे, तो उन के समक्ष भी यह प्रस्ताव रखा गया था। भारत का दृष्टिकोण था कि समय आने पर इस बात पर विचार कर लिया जायेगा।

**ज**ब मैं गत वर्ष फरवरी में इस्लामाबाद गया था तो एक प्रश्न के उत्तर में जनरल जियाने सेना को कम करने की बात मुझ से भी की थी। प्रश्न था: 'क्या दोनों देशों को टकराव से बचाने के लिए इस तरह की कोई स्थायी व्यवस्था हो सकती है?' उन का उत्तर था: 'ये सारी बातें अविश्वास से उत्पन्न होती हैं। हमें यह बात नहीं मलनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में तीन युद्ध हो चुके हैं और दोनों ने समझ लिया होगा कि इस से कोई समस्या हल नहीं होगी। युद्ध से राजनैतिक समस्याएँ हल नहीं होतीं। 1981 में जिस की लाठी उस की मंस वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें न केवल लोगों के बीच ही विश्वास का निर्माण करना है, बल्कि दोनों सरकारों के बीच भी करना है।'

उन्होंने मुझे बताया: 'मैंने सरदार स्वर्ण सिंह से यह पूछा था: बताइए सरदार साहब कि हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिए सेना चाहिए या नहीं? क्या भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए सेना रखेगा अथवा नहीं? यदि आप इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखनी चाहिए तो आप ही अपने (सैनिक) विशेषज्ञों से यह पूछ कर हमें बता दें कि हमें अपनी भौगोलिक सीमाएँ देखते हुए कितनी सेना रखनी चाहिए। हम इस पर



कोई विवाद नहीं करेंगे और उन की बात मान लेंगे।

"अगर आप कहेंगे कि ठीक है, पाकिस्तान की इतनी और भारत को उतनी सेना की जरूरत है तो मैं कहूंगा कि आप चाहे सेना रखें, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन जब 18 डिवीजन सेना पाकिस्तान की ओर मुखातिब होगी तो हम अवश्य चिंतित होंगे। हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। फिर भी मैंने प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्यवश हमारे प्रस्ताव की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बहुत बाद में जवाब आया कि 'नहीं।' यह कह दिया गया कि यह समुचित प्रस्ताव नहीं है, क्यों कि दोनों को वह करना है जो वे अपने हित में अपने लिए मुनासिब समझते हैं।

"तब मैंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जब पाकिस्तान अपनी माकूल प्रतिरक्षा आवश्यकताओं पर जोर देता है तो भारत क्यों विदकता है? फिर मैंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है तो आइए, मुझसे पूछिए। मैं बताऊंगा कि हमारे पास क्या है और आपके पास जो भी है उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। भारत बड़ा देश है, पाकिस्तान को इस का पूरा अहसास है... अतः दोनों ही देशों को यह निर्णय करना चाहिए कि हमारे हित की बात क्या है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है मैं तो यह बात निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि दोनों का हित इसी बात में है कि वे एक दूसरे का विश्वास और आदर प्राप्त करें और परस्पर मैत्री की भावना से शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करें।

"पाकिस्तान एक छोटा देश है। भारत एक बड़ा देश है। पाकिस्तान अपने को भारत का प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। हम मान भी नहीं सकते। हम 8 करोड़ हैं। भारत में 65 करोड़ हैं। वह बड़ा साझेदार है। उस की भूमिका स्पष्टतः बड़ी है, यह हम मानते हैं, लेकिन मेरा खयाल है परस्पर अधिक विश्वास और एक दूसरे को ज्यादा समझने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आगे पीछे यही होगा।"

मैंने कहा, "राष्ट्रपति महोदय, ये तो बहुत ही सुंदर विचार हैं। मुझे याद है कि जब सरदार स्वर्णसिंह स्वदेश लौटे थे तो मैंने उनसे इस विषय पर बातचीत की थी। वह और बहुत से दूसरे लोगों का भी यही विचार था कि राजनैतिक मैत्री के बाद ही दोनों देशों की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में चर्चा हो सकती है। क्या उन्होंने आप से भी यह बात कही थी? जनरल जिया ने उत्तर दिया, 'नहीं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हमने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की थी और प्रतिरक्षा सेनाओं के प्रश्न पर भी बातचीत हुई थी। परंतु मैंने अपनी ओर से उनके समक्ष यह विचार प्रस्तुत किया था। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इस तरह की सारी बातें तब ही उभर सकेंगी जब कि हमारे बीच राजनैतिक मित्रता हो

जायेगी, इसी से वैयक्तिक मित्रता भी उभरेगी और दोनों में अधिक से अधिक विश्वास पैदा होगा।"

अंततः परस्पर अस्व परिसीमन और 'युद्ध न करने' के समझौते के बाद भी यह जरूरी नहीं कि स्थायी शांति का बंदोबस्त हो जायेगा। भारत को हर हालत में सचेत तो रहना ही होगा। मामला संयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध की निंदा कर देने से ही समस्या हल नहीं होती। शिमला समझौते से पहले भी कई समझौते हुए, जिनमें युद्ध की निंदा की गयी थी।

घोषणा के पहले ही पैरा में यह कहा गया है: भारत की प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों ओर से प्रयास किये जायेंगे कि भारत और पाकिस्तान में पड़ोसियों जैसे सुखद संबंध बनें, जैसा कि संयुक्तराष्ट्र के घोषणापत्र में कहा गया है। इस के अंतर्गत वे अपना दायित्व समझते हैं कि परस्पर विवादों को सुलझाने में बलप्रयोग न किया जाये। शांतिपूर्ण ढंग से ही उन्हें निपटाया जाये।"

भारत-पाकिस्तान की बातचीत भी दोनों

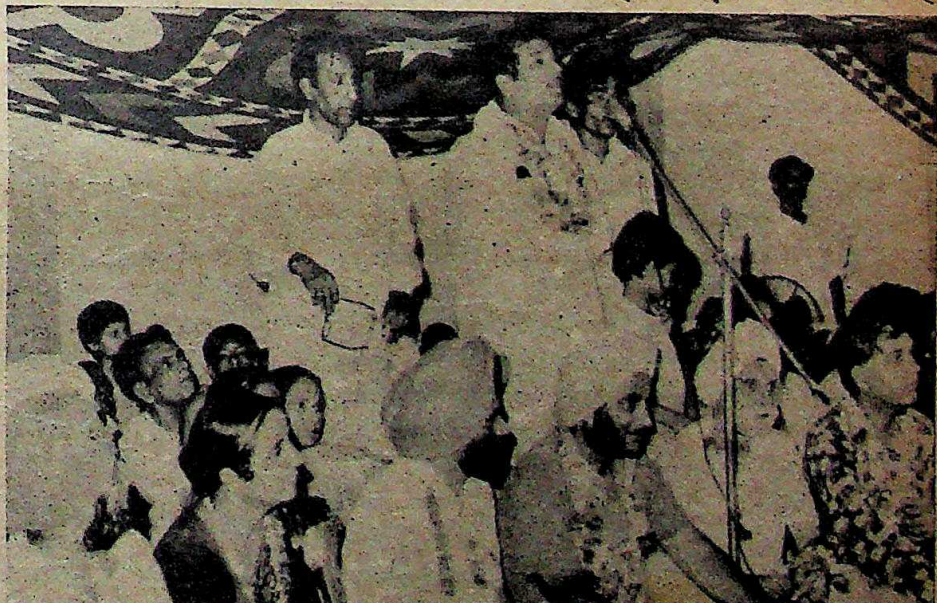
पाकिस्तान यात्रा की यादें

## दुश्मना कीजिए कि हम में फिर जंग न हो

डॉ. महीपसिंह

आम हिंदुस्तानी में पाकिस्तान का नाम आते ही अजीब सी संकल्पना उपजती है। एक ऐसा देश जिस से हमारी सदियों पुरानी लड़ाई है, हालाँकि इस नाम के देश को अस्तित्व में आये अभी पैंतीस वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। ऊपर मैंने 'हिंदुस्तानी' शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा होगा कि मैं इस के स्थान पर 'हिंदू' शब्द का प्रयोग करूँ, क्योंकि प्रायः लोग भारत

और पाकिस्तान के मध्य के तनाव को सदियों से चले आ रहे 'हिंदू-मुस्लिम' तनाव की परिधि में घसीट लाते हैं। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो भी प्रायः अपने भाषणों में पाकिस्तान और भारत के संघर्ष को हजार वर्ष पुराना बताया करते थे। इसलिए पाकिस्तान की चर्चा आते ही आम हिंदुओं में (सिखों में भी) दुश्मनी, जंग, मारकाट, दहशत, डर, नफरत और पता नहीं



जडियाला शेरखा (जिला शोहपुरा) में भारतीय लेखकों का स्वागत : डॉ. सविंद्र सिंह उप्पल, सुरजीत कौर, जगतार सिंह, डॉ. महीपसिंह, डॉ. हरनामसिंह शान और डॉ. विश्वनाथ तिवारी



कितने भाव गडमड हो कर उमरने लगते हैं। कुछ महीने पहले मैं अपनी पत्नी और कुछ लेखक मित्रों के साथ पाकिस्तान गया था। यह सुना अवश्य था कि भारत के लोग (विशेष रूप से सिख) जब कभी पाकिस्तान जाते हैं, तो वहाँ की जनता द्वारा उन का भरपूर स्वागत होता है। फिर भी इसे स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है कि मेरी मानसिकता एक आम भारतीय की मानसिकता से बहुत भिन्न नहीं थी।

परन्तु पाकिस्तान का जनता अद्भुत है। वह आप के सारे आतंक, भय और शंका को कुछ ही क्षणों में धो-पोछ कर साफ कर देती है और वातावरण अत्यंत आत्मीय जनों के वियोग के बाद मिलने की भाव-विह्वलता में बदल जाता है। आप को देख कर लाहौर या रावलपिंडी के हर आदमी की आँखों में एक कण्ठ चमक उमर आती है। मुसकराता हुआ हर चेहरा आप को अपनी ओर निमंत्रित करता हुआ सा लगता है। आप कहीं खड़े हों तो बच्चे, बूढ़े, जवान आप को चारों ओर से घेर लेते हैं। और तब उन्हीं में एक अघेड़ आयु का व्यक्ति अपनी झिझक को झटकता हुआ आप की ओर बढ़ आता है और पूछता है—'आप कहां से आये हैं?' आप के घर में सब अच्छी तरह तो हैं? चलिए, मेरे साथ एक प्याला चाय पी लीजिए... चाय नहीं... अच्छा तो कोका-कोला...' आप ना ना कहते रहते हैं और इतनी देर में कितने ही हाथ शीतल पेय की बोतलें लिये आप को घेर लेते हैं। आप को लगता है, इस संबंध में हल्की सी ना-नुकर इन सभी के दिलों को गहरा आघात पहुँचायेगी, क्योंकि आप की ओर टकटकी लगाये हर आँख कहीं अंदर तक आप को नम नज़र आती है।

जिस समय मैं पाकिस्तान गया था, भारत में पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी हथियारों की खरीद को ले कर काफी उत्तेजना थी। 'एफ-16' राजनेताओं के भाषणों से ले कर अखबारों की सुखियों और संवादकीयों तक से गुजरता हुआ काफी हाउसों की बहनों में भी शामिल हो गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य नये युद्ध की अटकलें लग रही थीं, और कितने प्रबुद्ध राजनीतिकों और पत्रकारों को यह (दुर्भाग्यपूर्ण) दिन कुछ महीनों के अंतराल में ही दिखाई दे रहा था।

परन्तु पाकिस्तान में यह उत्तेजना हमें कहीं नहीं दिखाई दी। लोगों के चेहरों पर हमें युद्धोन्माद के तनाव की जगह सहज मानवीय संवेदना नज़र आयी। ऐसा नहीं कि लोग दो देशों के मध्य के इस तनाव से परिचित नहीं हैं। परन्तु पता नहीं क्यों हमें हर चेहरा इस तनाव को झुठलाता, इस से कतराता था इस से बचने की दुआ करता हुआ नज़र आया।

दुआ की बात से मुझे एक और बात याद आती है। नयी दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास के एक कमरे से जब हम वीजा की मोहर लगे अपने पासपोर्ट ले कर चलने लगे तो दूतावास

के एक अधिकारी ने पूछा—'पाकिस्तान में आप गुरुद्वारों के दर्शन के लिए तो जायेंगे ही?' डॉ. सविंद्रसिंह उप्पल बोले—'गुरुद्वारों के दर्शन करने तो जरूर जायेंगे'।

उस अधिकारी ने अंदर तक मेद जाने वाली गहरी आँखों से हमें देखा और बोला—'वहाँ एक दुआ हमारी तरफ से भी कीजिएगा, हम में आपस में जंग न हो'।

पाकिस्तान में यही उद्गार हमें कितने ही व्यक्तियों से सुनने को मिले। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार के उच्च अधिकारियों ने हमारे लिए 'पंजा साहब' जाने की विशेष व्यवस्था की, क्योंकि वहाँ का वीजा हमारे पास नहीं था। यह निश्चित हुआ था कि वहाँ जाने के आज्ञापत्र के साथ ही एक अधिकारी हमारे साथ 'पंजा साहब' जायेगा, जिस से कि हमें कोई असुविधा न हो। दूसरे दिन प्रातः हम सभी गृहमंत्रालय पहुँचे, मंत्रालय के एक डिप्टी सेक्रेटरी अपने कमरे में सभी जरूरी आदेशपत्रों सहित हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उस अधिकारी से हमारा परिचय कराया जिसे हमारे साथ जाना था। मंत्रालय के उक्त उपसचिव विभाजन से पूर्व दिल्ली के करोलबाग में रहते थे, इसलिए हम से मिल कर वह बहुत भावुक हो उठे थे। वह हमें छोड़ने के लिए 'लिफ्ट' तक आये और वहाँ मेरा हाथ पकड़ कर आँखों में आँसू भर बड़े विह्वल स्वर में बोले—'पंजा साहब में हमारी तरफ से भी दुआ कीजिएगा कि हम में फिर से जंग न हो?'

**मैं** और मेरे मित्र अपने देश के ऐसे तनिक भी अधिकार संपन्न या नीति निर्धारण में थोड़ा भी महत्त्व रखने वाले व्यक्ति नहीं थे जिन के चाहने या न चाहने से, दुआ या बद्दुआ से दोनों ही देशों के मध्य युद्ध होने या रुकने वाला हो। ये सूत्र तो दोनों ही देशों में किन्हीं और हाथों में हैं। हम तो लेखक के रूप में पाकिस्तान गये थे। मुझे याद है, दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी ने हम से एक और बात कही थी कि जब हम पाकिस्तान से लौट कर आये तो उस देश के विषय में कुछ अच्छा-अच्छा लिखें। पाकिस्तान में हमारा एक लेखक के रूप में अथवा सामान्य भारतीय के रूप में स्वागत सत्कार हुआ। परन्तु जो बात हमें सदा विह्वल करती रही, वह थी उस देश की सर्वसाधारण जनता की भारत से युद्ध न करने और भारत से अच्छे संबंध बनाने की सद्भावना की व्यापक अभिव्यक्ति।

शेखूपुरा जिले के जँडियाला शेरखाँ गाँव में हम पंजाबी सूफी कवि सैयद वारिस शाह की मजार पर उस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गये। वहाँ दूरदराज से कई हजार व्यक्ति आये हुए थे। कुछ भारतीय लेखकों के आगमन की सूचना पा कर वहाँ की भीड़ और भी बढ़ गयी थी। वहाँ के संस्मरणों को मुलाना मानवीय संवेदन को नकारने जैसा है, हमें अधिक से

अधिक सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से जैसे सारे गाँव में होड़ सी लगी हुई थी। अनेक बूढ़ी औरतें हमें घेर कर हमारे घर बार और परिवार की हम से इस तरह कुशलक्षेम पूछ रही थीं, जैसे हम उसी गाँव से निकल कर गये हों। और एक बूढ़ा बड़ी भरी आवाज में मेरे कंधे पर हाथ फेरती हुई बुदबुदा रही थी—'उह बेला किझा चंगा से जदो असी रलके रहिदे हुंदे सा (वह समय कितना अच्छा था जब हम मिल कर रहा करते थे)'।

आम तौर पर किसी भी देश की अफसर-शाही बहुत हृदयहीन होती है। भारत और पाक के मध्य पर्यटकों या यात्रियों के संबंध में जिस प्रकार का समझौता है, वह दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए किसी यातना से कम नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे देश के नागरिकों को दो या तीन स्थानों का ही वीजा देते हैं। जिस शहर का वीजा हो वहाँ पहुँच कर पुलिस कार्यालय में अपनी आमद दर्ज करानी होती है और जब उस शहर को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना हो तो उसी कार्यालय से रवानगी का परवाना लेना होता है। यह सारी प्रक्रिया किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए बेहिसाब पेचीदगियों से भरी होती है। इस दृष्टि से मुझे और मेरे साथियों को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उसका एक कारण तो यह था कि हमारे पाकिस्तानी लेखक बंधु (विशेष रूप से जनाब सिबतउल हसन जैगम) सदा हमारे साथ होते थे और स्वयं ही सारी कार्रवाई करते रहते थे। परन्तु उससे भी आगे बढ़ कर पुलिस अधिकारियों, गृहमंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का इतना स्वागत और तत्परतापूर्ण रख हमारे लिए होता था कि समय-असमय के हमारे लिए 'आमद-रवानगी' की कार्रवाईयाँ करते थे, इस कार्य को करते समय अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते थे और हमारे लिए जलपान की भी व्यवस्था करते थे।

पाकिस्तानी जनता का यह सद्भाव न तो आकस्मिक है और न ही तात्कालिक। हमें बार बार यह महसूस होता रहा कि भारत और पाकिस्तान के नाम से घरती जरूर बँटी है, दिल नहीं बँटे हैं। हमें लगा, हर पाकिस्तानी भारत आने के लिए तरसता है। वह दिल्ली लखनऊ और बंबई जाना चाहता है। मुझे तो यह भी लगा कि आज की पाकिस्तानी युवा पीढ़ी के लिए भारत भ्रमण का आकर्षण यूरोप या अमेरिका के भ्रमण से बढ़ कर है।

कुछ महीने पहले कुछ पाकिस्तानी लेखक हमारे निमंत्रण पर दिल्ली आये और हमारे मेहमान रहे। यहाँ से जाते समय उन सभी की आँखें नम थीं। उन के अनुभव भी लगभग हमारे जैसे थे। इन अनुभवों के मध्य जब दोनों देशों के युद्धोन्माद का समाचार मिलता है तो वह एकदम झूठा और बनावटी लगता है।

इसके बावजूद हम कई बार लड़ चुके हैं आगे नहीं लड़ेंगे इस की भी कोई गारंटी नहीं है। □



वपानों का बिथावान

एक साहेब ने कहा—जहाँ राजधानी की  
गलियों में फूल मुरझाते हैं, वहाँ इस बयानों  
का बियाबान शूल सदा खिलते हैं। बात उन की  
च है। मेनका गांधी के अपने बयान, वे बयान  
तो उस के विरोधियों और समर्थकों आदि ने  
देये और शायद आगे चल कर भी देंगे तो  
राजनैतिक बयानों के नमूने हैं, पर यहाँ तो  
संसार का कोई विषय ऐसा होगा, जिस पर

न तो  
में बार  
न और  
है, दिल  
भारत  
खनऊ  
लो लगा  
के लिए  
मेरिका  
लेखक  
हमारे  
मी की  
हमारे  
देशों के  
एकदम  
आगे  
□  
'82

लड़ाई राशन की

दिल्ली को देश के अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक गेहूँ, चीनी आदि राशन का कोटा मिलता है। ऐसा हाल ही के कई सरकारी वक्तव्यों में कहा गया। विश्वस्त सूत्रों के आधार पर यह ठीक है मगर जनता के अनुभव के आधार पर यह भी ठीक है कि दिल्ली के लाखों लोगों को या तो राशन मिलता ही नहीं या पूरा नहीं मिलता और ठीक नहीं मिलता। राशन की दुकान पर चीनी लेने जाओ तो चावल नहीं। चावल आ गये तो गेहूँ गायब। प्रायः राशन की दुकानें किस दिन कब खलती

हैं या बंद होती हैं यह रहस्य न तो उपभोक्ता हल कर पाये हैं और न प्रशासन के अधिनायक। राशन की दुकानों वाले और उन से गहरी सहानुभूति रखने वाले कुछ जाने पहचाने स्थानीय राजनैतिक नेताओं ने बार बार यह तर्क दिया है कि बेचारे राशन के दुकानदार 10 वर्ष से ऊपर हो गया है बस एक पैसा प्रति किलो के कमीशन पर काम कर रहे हैं। इस महँगाई के जमाने में उन का गुजारा कैसे हो? दिल्ली के कई क्षेत्रों से तो हाल में ये समाचार मिले हैं कि कहीं कहीं जहाँ उपभोक्ताओं ने राशन के दुकानदार की धाँधली से तंग आ कर संबंधित कर्मचारियों से शिकायत कर दी तो शिकायत पर कार्रवाई तो उसी सरकारी चींटी चाल से होती रही मगर राशनी राजाओं के गगनों ने बेचारे उपभोक्ताओं

\* मैं श्रीमती गांधी के प्रति वक्रादार हूँ अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पी. बी. एन. पांडे साबित कर दें कि श्री बहुगुणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई और मेरा हमदर्द है तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दंगा।

—अकबर अहमद

\* श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी, और श्रीमती गांधी के परिवार के प्रति मेरी वफ़ादारी अटूट है। उस पर कोई उँगली नहीं जठा सकता।

—रुखसाना सल्लाना

\* यदि अनेक (केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अब्दुल गनी खाँ चौधरी) लोग गुंडा-गर्दी पर न उतरें तो सब ठीक रहेगा।

पश्चिम बंगाल में कानून व व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री ज्योति बस,

\* सरकार का समाचारपत्रों से कोई झगड़ा नहीं है वह तो इसे जन-संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानती है लेकिन समाचारपत्रों की स्वाधीनता का यदि दुरुपयोग होता है तो लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा और किसी न किसी रूप में तानाशाही आ जायेगी।

—सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे

\* समाचारपत्र और पत्रिकाओं में ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए. पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और अंधविश्वास तथा मायवाद में उन की आस्था समाप्त करने के लिए इस स्तंभ को समाप्त करना आवश्यक है. ऐसे अंधविश्वास का जो धार्मिक भावना से असंबद्ध है तथा शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर है उद्‌ड कर विरोध करना चाहिए.

—प्रेस आयोग की रपट का एक अंश

\* मैं आज की राजनीति से तंग आ गया हूँ. 90 प्रतिशत राजनीतिज्ञ स्वार्थी हैं. युवाओं को मेरी सलाह है वे इस बात को अच्छी तरह समझें. अपने पुत्र को मैंने बहुत पहले सलाह दी थी तुम इस में मत पड़ना. वह इंजीनियर बन कर अच्छी जिवनी बिता रहा है. आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कुछ राजनैतिक नेताओं के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करूंगा. राजनीति में रहने की वजह से ही शायद अब तक मुझे उन के साथ बैठना पड़ रहा था.

—राजनीति से संन्यास लेने पर अपने अनुयायियों के निर्णय बदलने के आग्रह पर चरणसिंह का जवाब

\* "मैं काम सँभालने को तैयार हूँ बशर्ते कि तुम इंदिरा को हटा कर  
मझे उस की कुर्सी पर बिठाओ."

—राजनीति से संयास लेने का फैसला वापस लेने की माँग करने वाले अपने समर्थकों को चरणसिंह का जवाब





## पुरस्कार बंट गये समझिए

राजस्थान के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया. देश के विख्यात फोटोग्राफरों की एक प्रतियोगिता राजस्थान पर्यटन विभाग ने आयोजित की थी. ये फोटोचित्र उसी से चुने गये थे. पुरस्कार विजेताओं में एक विदेशी फोटोग्राफर भी थी. सभी विजेता उद्घाटन समारोह पर पुरस्कार प्राप्त करने आये. मुख्य अतिथि थे केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री खुशद आलम खान साहेब. मंत्री महोदय बोलते कम हैं. छोटा सा भाषण दिया. फिर एक कर्मचारी ने पुरस्कार विजेताओं की लंबी चौड़ी सूची पढ़ी. अब पुरस्कार विजेता और मंत्री एक दूसरे को देख रहे थे और चुप थे. पुरस्कार जयपुर से आये नहीं थे क्योंकि वहाँ सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हो गयी थी. खान साहेब को शायद याद आ गया कि राजधानी में कभी ऐसे अवसर भी आये हैं कि मुख्य अतिथियों और अध्यक्षों को मौके की नज़ाकत देखते हुए इस प्रकार कहना पड़ा—'भाषण दे दिया गया समझिए. या प्रस्ताव पास हो गया समझिए. एक बार तो यों भी हुआ था कि एक भोजन और भाषण के साझे सम्मेलन में भाषण बहुत हुए और भोजन की व्यवस्था न हो पायी तो घोषणा हुई—भोजन खा लिया गया समझिए. खान साहेब ने खामोशी तोड़ी और कहा, 'पुरस्कार बंट गया समझिए'. बाद में पुरस्कार आ गये थे और बंटे भी थे.

## आखिरी बात

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के बारे में एक हल्की फुल्की चर्चा में यह सुना गया—भाई जान पड़ता है कि, अंतुले साहेब अब भी कुछ करने पर तुले हैं.

## कस्बई दिमाग

'मेनका गांधी प्रकरण को लेकर देश के सारे छोटे बड़े अखबार इस तरह जूझ रहे हैं जैसे कोई महामुद्द छिड़ गया हो, जिस से सारी मानवता सारा भारतीय जीवन विनाश के कगार पर आ गया हो।' पिछली शाम शर्मा जी अखबार पटक कर बोले.

'इस में इतना बुरा लगने की बात क्या है? सारी दुनिया के अखबार सत्ताधारियों के घर में जो कुछ होता है उस की खोज खबर रखते हैं, उसे छापते हैं, सामने लाते हैं क्योंकि उस का असर राजनीति पर पड़ता है.' स्तंभकार ने कहा.

'सरासर झूठ है. सारी दुनिया को मत घसीटो. केवल अमेरिकी अखबार, ब्रितानी अखबार यह करते हैं. समाजवादी देशों के अखबारों से ले कर तीसरी दुनिया के अखबारों में कहीं यह नहीं होता. ब्रिटेन में ही होता है कि प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी के पूर्व के दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे व्योरे छपे और भारत के सभी राष्ट्रीय अखबार उन्हें दोहराते रहे. कोई कारण नहीं था भारतीय अखबारों के लिए कि रोज का व्योरा छापते लेकिन वे छापते थे और जगजाहिर करते थे कि भारत उन का उपनिवेश रह चुका है और अपने मालिकों के प्रति वैसी ही भक्ति आज भी उन में है. दुनिया के और सारे अखबार तो उसे नहीं छाप रहे थे?'

'आप अति पर जाते हैं.'

'नहीं, सच्चाई पर जाता हूँ. सच्चाई यह है कि भारतीय पत्रकारिता को सनसनीखेज कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ चाहिए, वह समृद्ध देशों के चोंचले अपनाता है. गरीब देशों का धर्म नहीं अपनाता. सवालियों और उन के संभावित समाधानों, संघर्ष और तनावों की ओर से ध्यान हटा कर दूसरी ओर ले जाता है. इस के पीछे कोई बड़ा पड्यंत्र न भी माना जाये तो यह तो माना ही जा सकता है कि यह कस्बई दिमाग है. देखा है गाँव-कस्बे के लोगों को? अपने घर की चिंता नहीं होगी, दूसरों के घरों की चिंता उन्हें घेरे रहेगी. अँधेरे में भूखे पड़े आपस में यही बात करते आप उन्हें सुन सकते हैं—'चौबे जी की बहू दुई साल होय गये समुराल से नाहीं लौटी. आज कल तिवारी जी के घर मा ठनी है. कहो! उन के इहाँ ई चार मनई कहाँ से आये हैं? रही न मेहरारू ओकरे पास, देख लियो एक दिन भाग जाई, केस चलति रही झमक झमक. आजकल मैया नदी किनारे रोज जात हैं कोनो बात है. काव कहीं जब बहू के घर से निकारिन तो गहना कपड़ा लत्ता सब घै लिहिन, छूछे अधीरात में

निकारि दिहिन. निकारि काव दिहिन ओह कर कहीं और चक्कर चलत रहा'. बस ऐसी ही बातें उन्हें घेरे रहती हैं. प्रपंच करते रहते हैं. अब बताइए अपने घर में बैठे बैठे दूसरों के घरों की चिंता क्यों है जब कि उस से आप का कुछ सरोकार नहीं? किस के बहू की नथनी सास ने उतरवा ली, इस की चिंता करता रहता है कस्बई दिमाग. इस की चिंता नहीं करता कि उस की बहू की नाक में नथनी है या नहीं. जिस समाज में जितना ही बतरस है वह उतना ही पतन के गर्त में जा रहा है, यह समझ लो. इंदिरा गांधी और मेनका गांधी का यह आपसी मामला था. इस की इतनी कहानी, इतना बतंगड़ बनाने और बनाते रहने की जरूरत नहीं थी. सूचना काफी थी. इसे ले कर कोई बड़े राजनीतिक संदर्भ जुड़ें, उन की चर्चा कर लीजिए. पर इसे चटखारे की तरह तो भारतीय पत्रकारिता को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए.

'तो आप को इस प्रकरण से नहीं, उसे चटखारे के रूप में पेश करने से ऐतराज है?'

'जी हाँ, घटनाओं में चटखारा लेना और उसे चटखारा ले लेकर सुनाना ही कस्बई दिमाग है. एक चीज और है—कस्बई दिमाग का लक्षण है कि वह कभी यह नहीं मानता कि कोई आदमी खुद भी कोई निर्णय ले सकता है. वह गाँठ जोड़ने में बड़ा माहिर होता है—'बात ई है कि चौवाइन का साथ आजकल ठकुराइन का है. ठकुराइन बहुत चालू है, ओह के समझाय होई तबहि बहू के निकारि दिहे होई हैं. ऊ मैया! ओकरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं. अपने मास्टरजी हैं जोन ऊ कहत है तीन ऊ करत हैं.' कस्बई दिमाग यह मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी अपने दिमाग से भी कुछ कर सकता है, कोई निर्णय ले सकता है, कोई कदम उठा सकता है. सो सारा देश यही सोच रहा है कि इंदिरा जी को किस ने भड़काया होगा, मेनका को किसने बरगलाया होगा और अखबार इन अटकलों से भरे रहते हैं! किसी को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नजर आते हैं. किसी को दूसरी ओर राजनारायण, जार्ज फर्नांडीस और न जाने कौन कौन? अरे, भई अखबारों में किस्सेवाजी, अटकलवाजी न करो, कस्बई दिमाग से बचो, काम की बातें करो. 'ई बतरस में काव रखा है'. पर हर अखबार यही कर रहा है—'कहाँ बंटी, कहाँ रही, किस रंग की साड़ी थी. कहाँ से पैसा आ रहा है. कितना हँस रही थी. कितना उदास थी, जिस से मिल रही है, किस से छिटक रही है—बस यही अखबार अलाप रहे हैं. हम गाँव कस्बा छोड़ शहर आये थे कि इस से मुक्ति मिलेगी पर यहाँ तो राष्ट्रीय स्तर पर सब हो रहा है. अब इस कस्बई दिमाग से घबरा कर कहाँ जायें?'



राष्ट्र

चुनाव

## अपने हिस्से की धूप

(हमारे विशेष शंवावदाता द्वारा)

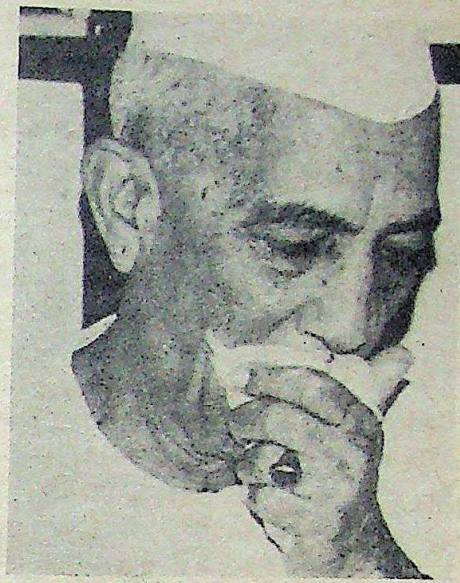
कुछ विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा ने राजनैतिक दलों की अपने हिस्से की धूप पा लेने की फिक्र को बढ़ा दिया है। अपने ही हिस्से की क्यों, फिक्र तो दूसरों के हिस्से की धूप पा लेने की है।

इसी फिक्र ने चंडीगढ़ सम्मेलन के संभावित नतीजों से विचलित चौधरी चरणसिंह से राजनीति से संन्यास ले लेने की घोषणा करायी। इसी फिक्र ने उन के समर्थकों-अनुयायियों के दबाव में उन्हें यह कहने को मजबूर किया कि 'मैं काम संभालने की तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम इंदिरा को हटा कर मुझे उसकी कुर्सी पर बैठा दो।'

इस फिक्र की तीव्रता कितनी गहरी है कि 'राजनैतिक स्थितियों से निराश होने, 90 प्रतिशत राजनीतिक नेताओं के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को जानने और राजनीति को भले आदमियों की जगह न मानने' के बावजूद चौधरी साहब देश सेवा करते रहने के लिए अपने ही दल में चौथी फुट की कुरूपता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। गैरकम्युनिस्ट प्रतिपक्षी दलों की एकता की पहल करने वाले चौधरी साहब की इस उपलब्धि को भी पहचानपूर्ण मानना चाहिए।

इस फिक्र का जो सिलसिला जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से जुड़ता है उस पर जनतंत्र की मर्यादा और मानव मूल्य की सुरक्षा का सट्टा मजबूती से लगा है। चंद्रशेखर जी, चौधरी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन उन्हें लगता है कि "चौधरी जी ने सारे राजनैतिक प्रश्नों को व्यक्तिगत प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। वह हर विवाद में एक ही पहलू सामने लाना चाहते हैं कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान परिस्थिति में यह सवाल बेमानी है। 'सवाल सिर्फ कुछ मूल्यों की रक्षा का है, जो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसके हाथों राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता। कुर्सी का भय और कुर्सी पाने का लोभ दोनों मनुष्य को समान रूप से निर्बल बनाते हैं। इस इसे समझ नहीं पाते, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति हमारे आचरण द्वारा होती है, उस से स्थिति हास्यास्पद बन जाती है।'

माकपा के श्री बासवपुनैया की निगाह में उस धूप की सुब मे बड़ी दुश्मन श्रीमती गांधी की तानाशाही है जिस से संघर्ष के लिए माकपा के बंगाल, त्रिपुरा और केरल में जनवादी मोर्चे



चरणसिंह : नाक की चिता

की अग्रिम चौकियाँ बना रखी हैं। तीसरा विकल्प बनने के दावे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के ही हाथ मजबूत कर रही है। प्रतिपक्ष की अन्य पूँजीवादी सामंतवादी पार्टियों में दुलमुल यकीनी और हिचकिचाहट जारी है।

माजपा उस धूप के अपने हिस्से के विस्तार के प्रति अधिक आश्वस्त है। पश्चिम बंगाल और केरल में अपने को तीसरी और उत्तर भारत में इंदिरा कांग्रेस के विरुद्ध एकमात्र दूसरी शक्ति मान लेने के बाद उसकी कोई दिलचस्पी एकता में नहीं रही है। सुविधा के हिसाब से वह दूसरे दलों से चुनावी तालमेल कर सकती है। यह मान कर चल रही है कि राष्ट्रीय दल के रूप में वह देश के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति का अहसास कराने में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।

लेकिन यदि प्रधानमंत्री निवास के सामने का दृश्य देखा जाये तो लगेगा कि सारी धूप इंदिरा कांग्रेस की है। हरयाणा की 90 सीटों के लिए वहाँ से आये कांग्रेसी टिकटार्थियों की संख्या देख कर लगता है कि सारे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व दे देने के बाद भी कुछ के लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा 19 मई को हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव कराये जाने की घोषणा के बाद तात्कालिक सवाल यह पैदा हुआ है कि प्रतिपक्षी दल इंदिरा कांग्रेस से लड़ने के लिए किस व्यूहरचना का इस्तेमाल करें। संभावनाओं की तलाश जारी है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्यामलाल शक्थर के अनुसार अगर आंध्रप्रदेश और कर्नाटक की विधानसभाएँ 15 अप्रैल तक विघटित हो

गयी होती तो उन राज्यों में भी चुनाव इसी के साथ हो सकते थे।

19 मई के चुनाव में चार विधानसभाओं के अतिरिक्त गढ़वाल (उत्तरप्रदेश) लोकसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के अलावा लोकसभा की 6 और 8 अन्य राज्यों में विधानसभा की रिक्त 15 सीटों का भी चुनाव किया जायेगा। असम में विधानसभा चुनाव इस लिए नहीं कराये जा सकते क्यों कि वहाँ बहिरागतों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी तरह जम्मू, मेघालय और त्रिपुरा की कुछ सीटों का चुनाव इस लिए नहीं हो पा रहा है क्यों कि मतदाता सूची अभी तैयारी की अवस्था में है।

इस लघु आम चुनाव के साथ लोकसभा की जिन सीटों के चुनाव हो रहे हैं उन में लोहरदगा (बिहार), जबलपुर (म.प्र.), ठाणे (महाराष्ट्र), बयाना और उदयपुर (राजस्थान) तथा डायमंड हारबर (बंगाल) की सीटें हैं। अन्य राज्यों की जिन सीटों पर विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं उन में जलालपुर और साहबगंज (बिहार), आंध्रोल (गुजरात), होशाधुरगा (कर्नाटक), मेंडसो, नेवापुर और उमरगा (महाराष्ट्र), फरीदकोट, नांगल (पंजाब), सरदार शहर (राजस्थान), करछवा (उ.प्र.), बनलाईफाई, खाहल, सटेक और फुलडुगसी (मिज़ोरम) की सीटें हैं। विज्ञप्ति के अनुसार नामांकन 24 अप्रैल तक, जाँच पड़ताल 26 अप्रैल तक और नाम वापसी की तिथि 2 मई तक है। चुनाव 19 मई को होंगे। और मतों की गणना 20 मई से शुरू हो जायेगी। हरयाणा में विधानसभा की कुल सीटें 90 (मतदाता संख्या 71.40 लाख), हिमाचल में 68 (मतदाता संख्या 12.11 लाख), केरल में 140 (मतदाता संख्या 129.66 लाख) और बंगाल में 294 (मतदाता संख्या 300 लाख) हैं।

वास्तविकता यह है कि राजनैतिक दल अभी भी अपनी चुनावी व्यूहरचना को कोई अंतिम रूप नहीं दे पाये हैं। प्रयास जारी है। लेकिन कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं। प्रमाण के लिए पश्चिम बंगाल और केरल की राजनैतिक स्थिति उत्तर भारत के हिमाचलप्रदेश और हरयाणा से भिन्न है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चे की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही है। निश्चय ही उसने अपने जनाधार को विस्तृत किया है। यह मानने के कारण हैं कि वामपंथी मोर्चे के विभिन्न घटकों में समन्वय और समझदारी रही है इसीलिए वे राजनैतिक प्रबंध में काफी कुशल सिद्ध हो रहे हैं। इनकी लोकप्रियता या विश्वसनीयता के विकास में इंदिरा कांग्रेस की कुछ

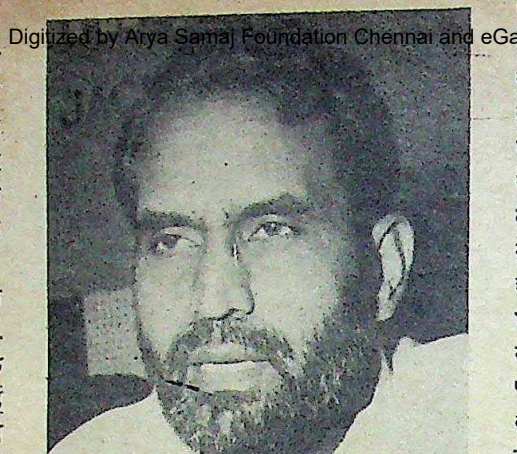


मूले भी सहायक हुई हैं। स्थानीय हितों की रक्षा की बात बार बार करते हुए मोर्चे ने हमेशा जनता को यह बताना चाहा कि केंद्र उन के अनुकूल नहीं है। इस का एक असर पड़ा है। मतदाता सूची की गलतियों को ले कर इंदिरा कांग्रेस ने जो कदम उठाया उसे भी वामपंथी मोर्चे ने अपने राजनैतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया।

केरल की राजनैतिक स्थितियों में भी पिछले दिनों काफी परिवर्तन देखने को मिला। इंदिरा कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे में 12 पार्टियाँ हैं जब कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में काम करने वाली 8 पार्टियाँ हैं। केरल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दो गुट हो गये हैं। वामपंथी मोर्चे ने खास तौर पर बेरोजगार युवकों के मन में एक आशा जगायी थी। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था कर के। लेकिन उस की अमलदारी नहीं हो सकी। वामपंथी मोर्चे का विरोध करने वालों ने उस का प्रचार इस रूप में किया कि मार्क्सवादी और उनके सहयोगी यह जानते थे कि वैसी व्यवस्था संभव नहीं होगी लेकिन उस के बावजूद केवल राजनैतिक आकर्षण पैदा करने के लिए उन्होंने वैसा कदम उठाया। दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चे में न केवल वर्ग और जाति के आधार पर अपने प्रभाव का विस्तार किया है बल्कि श्री एंटनी जैसे लोगों के इंदिरा कांग्रेस के नज़दीक आने से स्थिति गुणात्मक ढंग से बदल गयी। पिछले कुछ वर्षों में केरल में नवघनिकों का एक ऐसा तबका भी तेजी के साथ उभरा है जिस की दिलचस्पी अभावप्रस्तता के जमाने में साम्यवाद और उस के मूल्यों में थी, लेकिन अब संपन्न होने के बाद उसे अपने हितों की रक्षा की फ़िक्र ज्यादा है।

उल्लेखनीय यह है कि इस राज्य में विधानसभा के 25-30 मतदान क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुछ प्रभाव पैदा किया है। वह प्रभाव नगण्य नहीं है। उस का प्रमाण यह है कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा और वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा दोनों ही उसे मनाने की अनिवार्यता महसूस कर रहे हैं।

भाजपा उत्तर भारत में विशेष कर हरयाणा और हिमाचलप्रदेश में तो अपने को दूसरी शक्ति मानती ही है। इन दोनों राज्यों में इंदिरा सरकार का शासन है। जनवरी '80 में हरयाणा में भजनलाल जनता पार्टी के 37 विधायकों को तोड़ कर इका में शामिल हुए। ऐसा ही हिमाचल में ठाकुर रामलाल ने 6 विधायकों को साथ ले कर किया। दोनों की सरकारें दलबदल के आधार पर बनीं और किसी न किसी रूप में चलती रहीं। दोनों ही जगहों पर इंदिरा कांग्रेस के पुराने सदस्यों और नये सदस्यों के बीच मतभेद की रेखाएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष के बीच मतभेद है।



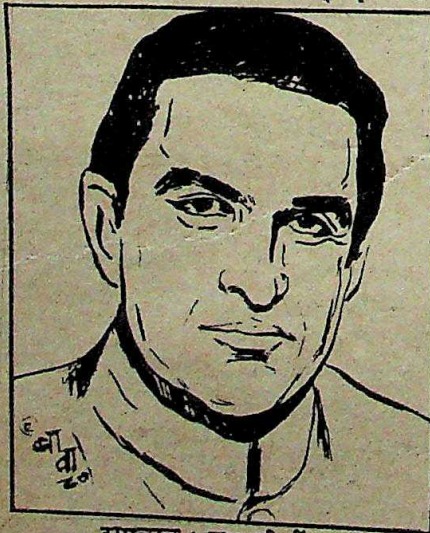
चंद्रशेखर : चंडीगढ़ के मायने

टिकटार्थियों के चुनाव में यह मतभेद और तीखे हो सकते हैं। दोनों पक्षों की कोशिश अपने अनुयायियों को टिकट दिलवाने में होगी।

कुछ दिनों पहले डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने हरयाणा के कांग्रेसियों को यह आश्वासन दिया कि जो लोग जनता काल में श्रीमती गांधी के प्रति वफादार रहे और जिन्होंने उस के बाद 20-सूत्री कार्यक्रम में काम किया उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। यह स्थिति इका में '80 के आसपास शामिल होने वालों के अनुकूल नहीं भी पड़ सकती है।

दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को अधिक सक्रिय बनाने की फिराक में है। हिमाचलप्रदेश में तो इंदिरा कांग्रेस की मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही है। प्रायः सभी मतदाता क्षेत्रों में कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों के चुनाव की समस्या है। मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल दोनों मोर्चों पर ज़रूरत से ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं।

ऐसे वक्त में जब कि प्रतिपक्षी दलों में इंदिरा कांग्रेस में विकसित प्रस्तुत करने के लिए एकता होनी चाहिए थी। लोकदल चौथे विघटन का शिकार हुआ है। एकता वार्ता की शुरुआत चौधरी चरणसिंह ने ही की थी और उसे खंडित करने के भी जिम्मेदार वही है। जनता



रामलाल : कल की चिंता

पार्टी, शरद कांग्रेस और लोकदल के बीच विघटन की समस्याएँ काफी अच्छी थीं लेकिन समस्या नयी पार्टी के नेतृत्व को ले कर पैदा हो गयी। चौधरी जी नेतृत्व स्वयं चाहते थे। लोकदल के अध्यक्ष के रूप में एकतरफा तरीके से समन्वय समिति को मंग करने के फैसले के बाद लोकदल के अनेक सदस्यों को खुद ही यह महसूस हो गया कि चौधरी जी के तानाशाही रवैये में कोई अंतर नहीं आया है। यह भी कि उनके होते हुए एकता वार्ता सफल नहीं हो सकती। कुछ लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि जनता पार्टी, समाजवादी कांग्रेस और लोकदल के एकता समर्थक नेताओं की एक बैठक चंडीगढ़ में होनी चाहिए। समाचार सुनने के साथ चौधरी चरणसिंह ने पहले तो राजनीति से संन्यास ले लेने की घोषणा की फिर अपने समर्थकों के दबाव में फैसले पर पुनर्विचार करने का वादा किया। इसी के साथ चौ. देवा-लाल, बीजू पटनायक और कुंभाराम आर्य को मअत्तल कर देने से विघटन अंतिम रूप से सामने आया है। दूसरी तरफ जनता पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य रामधन और कृष्णकांत समेत पाँच और नेताओं ने तीनों दलों की एकता में बाधा डालने वाले नेताओं की आलोचना करते हुए प्रतिपक्षी नेताओं से अपील की है कि वे सत्ताधारी इंदिरा कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए एकता के प्रयासों का नफल बनायें।

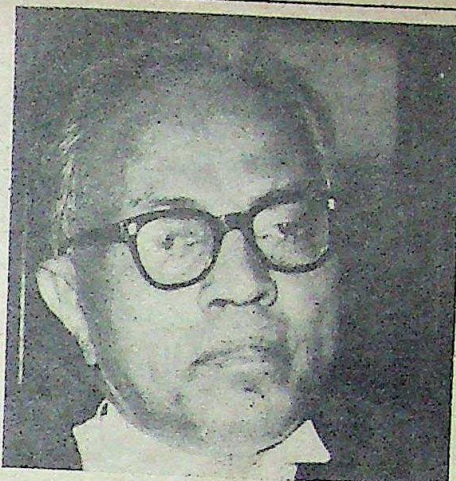
बाबू जगजीवन राम (कांग्रेस-ज) विलयन की जगह साझेदारी को महत्त्व देते हैं। 'साझेदारी रही होती तो जनता पार्टी टूटी नहीं होती।' भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई मोह उनके मन में नहीं है। संभव है कि वह चौधरी साहब के लोकदल के साथ हरयाणा में सीटों संबंधी समझौता करें।

कुछ प्रतिपक्षी दल 1977 की जन भावना के पुनर्जागृत होने का सपना देख रहे हैं, हालाँकि वे यह भूल रहे हैं कि अनेकता में बदल जाने वाली प्रतिपक्ष की एकता अब इंदिरा कांग्रेस का उतना नुकसान नहीं कर पायेगी।

फिलहाल उत्तर भारत में इंदिरा कांग्रेस, भाजपा, जपा, सका और लोकदल के चौधरी विरोधी लोग तथा लोकदल मुख्य राजनैतिक शक्ति के रूप में मैदान में आयेंगे। कांग्रेस (ज) चौधरी जी के साथ हो सकती है। भाजपा सीटों संबंधी कुछ तालमेल से अधिक कोई समझौता नहीं करेगी। बंगाल में चुनाव परिणाम लगभग निश्चित माने जा रहे हैं। केरल में मार्क्सवादियों के नेतृत्व में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा और इंदिरा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच लड़ाई केंद्रित हो गयी है। भाजपा केरल और बंगाल दोनों राज्यों में अपने ही बल पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। चुनाव घोषणापत्रों में जनता को आकर्षित करने की सभी कोशिशें इस्तेमाल में लायी जा रही हैं।



# उद्योग से सुक्ति का सवाल



न्यायमूर्ति मैथ्यू : स्वतंत्र प्रेस

न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू की अध्यक्षता में प्रेस आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं। आयोग की रपट बहुमत से जारी की गयी, क्योंकि कुछ सदस्यों ने कई सिफारिशों के सिलसिले में असहमति व्यक्त की। असहमति के मुद्दे सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन और अखबारों को अन्य उद्योगों से अलग करने के प्रस्तावों पर व्यक्त की गयी। आयोग ने अपनी लंबी रपट में सुझाव दिया है कि सरकारी गोपनीयता कानून को संशोधित किया जाये ताकि इस से समाचारपत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की हानि न हो। इस सिलसिले में ब्रिटेन के सूचना स्वतंत्रता विधेयक को आदर्श माना गया है। आयोग के अनुसार इस विधेयक के महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन कर के गोपनीयता कानून में उचित संशोधन करना जरूरी है। जहाँ तक व्यक्तिगत गोपनीयता का सवाल है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, घरेलू संबंधों और ऐसे निजी मामलों को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि ये मामले सार्वजनिक हित में प्रकाश में लाना जरूरी नहीं। इस सिलसिले में एक सदस्य के. आर. गणेश ने असहमति व्यक्त की है। उन के अनुसार सरकारी गोपनीयता को किसी भी रूप में छेड़ा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 1978 में प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक को फिर से विचाराधीन बनाने का भी विरोध किया। आयोग के अनुसार जानकारी के स्रोत की गोपनीयता का कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। सामान्यतया पत्रकार से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह जानकारी के स्रोत को खोले। मगर यदि जरूरी हो तो उसे खोलने पर मजबूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ सदस्यों ने असहमति व्यक्त करते हुए यह कहा है कि जानकारी के स्रोत की गोपनीयता का पूर्ण अधिकार पत्रकार को मिलना चाहिए, स्रोत को खोलने का आदेश केवल एक न्यायाधीश ही दे सकता है अगर यह राष्ट्र की सुरक्षा या सार्वजनिक संबंधी गतिविधि को रोकने के लिए अनिवार्य माना जाये।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि समाचार पत्रों को अन्य उद्योगों से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। आयोग के अनुसार देश के बड़े दैनिक ऐसे नियंत्रण में हैं जो समाचार पत्र

प्रकाशित करने के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित है। इसलिए एक लाख या उस से अधिक प्रतिपां छापने वाले समाचार-पत्रों के स्वामित्व को अन्य उद्योगों से मुक्त किया जाना चाहिए। इस से समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर दबाव कम होगा और समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार समाप्त हो जायेगा। इस मुद्दे पर टाइम्स आफ इंडिया के संपादक गिरिलाल जैन और तीन अन्य सदस्यों ने असहमति व्यक्त की।

तीसरी सिफारिश विज्ञापन और अखबारी कागज उपलब्ध कराने के सिलसिले में हैं। आयोग के अनुसार ऐसी पत्रिकाओं को कम मूल्य पर अखबारी कागज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जो यौन संबंधी विषयों या सिनेमा से संबंधित हों।

इसी प्रकार सरकारी विज्ञापनों के वितरण के सिलसिले में एक विज्ञापन नीति बनायी जानी चाहिए जिस की प्रतियाँ संसद और विधानसभाओं में रखी जानी चाहिए। दृश्य व श्रव्य प्रचार निदेशालय का विभाजन होना चाहिए और विज्ञापन वितरण के कार्य के लिए एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। यह केंद्रीय संगठन हो सकता है। और इसी के नमूने पर राज्यों में भी कार्यवाई की जानी चाहिए।

छोटे समाचार पत्रों की सुविधा के लिए पत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की गयी। वर्तमान ढाँचा हटा कर इसे पूर्ण रूप से सूचना एवं समाचार कार्यालय के रूप में बदला जाना चाहिए जो रातदिन काम करे और जिस की सूचनाएँ जिलों और देहाती इलाकों में प्रकाशित समाचारपत्रों को मिलती रहें। इसी सिलसिले में छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के विकास के लिए एक विकास निगम का सुझाव दिया गया है। आयोग ने पृष्ठ मूल्य प्रणाली के सिलसिले में एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है। इस

संशोधन की आवश्यकता इसलिए आ पड़ी है कि सरकार की इस नीति के विरोध में मालिकों ने जो चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दी थी उस में मालिकों अधिकारों के आधार पर न्यायालय ने मालिकों की शिकायत को स्वीकार किया है। इसलिए जरूरी है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि अखबारों में मूल्य और पृष्ठों के बीच एक सही अनुपात स्थापित किया जाये।

एक और सुझाव यह भी दिया गया है कि समाचारपत्र मालिकों को इस बात के लिए मजबूर किया जाये कि वे प्रेस परिषद और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। मालिकों का यह अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छा के संपादक नियुक्त करें मगर यह जरूरी होगा कि ऐसा व्यक्ति पत्रकारिता के सिलसिले में महत्वपूर्ण स्तर का हो जो अखबार को सार्वजनिक हित चलाने में में समर्थ हो।

यह स्पष्ट है कि जानकारी के अधिकार का आश्वासन दिलाने वाले सुझाव का श्री के. आर. गणेश को छोड़कर सभी ने स्वागत किया। गणेश पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि दो पत्रकार प्रतिनिधियों गिरिलाल जैन और राजेंद्र माथुर ने अन्य दो गैर पत्रकार सदस्यों के साथ अखबारों को अन्य उद्योगों से अलग करने के सुझाव का जोरदार विरोध किया है। जानकारी की स्वतंत्रता का सुझाव देते समय यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध जानबूझ कर इस प्रकार के तथ्य छापने की शिकायतों का प्रेस परिषद जाँच करती रहेगी जिन से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से परेशानी या बदनामी का शिकार होना पड़े।

प्रेस आयोग की रपट पर सदस्यों में मतभेद तो है ही वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तियों में भी मतभेद नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गयी हैं।

भूतपूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री लाल-कृष्ण आडवाणी (जो स्वयं पत्रकार रहे हैं) का कहना है कि जिस रूप में प्रतिवेदन समाचार पत्रों में छपा है उस से तो लगता है कि सरकार की नीति बड़े अखबारों को पंगु बनाने की है। इसी प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक का कहना है कि आयोग ने प्रेस पर मालिकों के दबाव के बारे में सिफारिशें तो की हैं मगर सरकारी दबाव का कोई जिक्र ही नहीं किया है। यह दबाव अधिक व्यापक और घातक होता है। सरकार के पास संचार माध्यम में आलोचकों को दबाने के लिए जरूरत से ज्यादा अधिकार है। ऐसे ही अवसरों पर बड़े अखबार औरों के मुकाबले इस दबाव को



सहने की अधिक क्षमता रखते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के संपादक प्रभाष जोशी के अनुसार—

बड़े समाचारपत्रों को सफल बनाने का एक कारण उन के वित्तीय साधन भी हैं और यदि उद्योगों से मुक्ति का उद्देश्य इन साधनों से

Digitized by Arya Samaj Education Centre, Meerut

मुक्ति है तो वह प्रेस को अखबारों जैसी तरह तो उन की हालत भी छोटे अखबारों जैसी हो जायेगी जो सरकारी विज्ञापनों पर ही निर्भर रहते हैं। यह ठीक है कि उद्योगपति प्रायः अपने औद्योगिक हितों का ध्यान रखते हुए प्रेस को किसी न किसी रूप में नियंत्रित

हैं मगर निरंकुश सरकार निरंकुश उद्योग से अधिक खराब है। उद्योग तो कम से कम जनमत की पूरी अवहेलना नहीं कर सकता क्योंकि उसी पर अखबार की बिक्री का दारोमदार है।

जहाँ तक छोटे समाचारपत्रों के अस्तित्व

## जानकारी का मौलिक अधिकार

डॉ. आर. मानकेकर के लिए प्रेस की स्वतंत्रता संपादकीय स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं। प्रेस आयोग की रपट में बहुमत और अल्पमत के विचारों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छेड़ा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि अखबारों के मौलिक अखबारों को उद्योग के शिकंजे से मुक्त करने का विरोध करें। उन का निहित स्वार्थ है मगर यह समझना बड़ा मुश्किल है कि संपादक अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मत व्यक्त करें। यह तर्क किसी भी रूप में उचित नहीं लगता कि इस कदम से समाचारपत्रों की स्वतंत्रता कम हो जायेगी और वे सरकार के रहमो-करम पर टिके रहेंगे। अखबारों को उद्योगों के प्रभुत्व से मुक्त रखने से स्वतंत्रता कैसे जायेगी यह अकल्पनीय है। मौलिक सरकार पर निर्भर करते हैं। क्योंकि उन के पास कई उद्योग होते हैं। और वे यह हरगिज नहीं चाहते कि उन के समाचारपत्र का संपादक सरकार और प्रशासन के विरुद्ध ऐसी खरी खरी बातें बताये कि सरकार उद्योगपति के अन्य उद्योगों के रास्ते में रुकावटें डाले। उन के आयात लाइसेंस, निर्यात सुविधा, सामान, मशीनें, कच्चा माल, बिजली, जमीन सभी तो सरकार के हाथ में हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की मिसाल इस सिलसिले में सब से अच्छी मिसाल है। जब एक संपादक हिम्मत के साथ सरकारी नीतियों का डट कर पर्दाफाश करने पर तुल गया तो मौलिक ध्वरा गया। और संपादक की छुट्टी हो गयी। सरकार मौलिकों के कान मरोड़ती है यह कोई छिपी बात नहीं है। बरसों पहले श्रीमती गांधी ने पत्रकारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे मौलिकों को बुला कर तुम लोगों की खबर ले सकती हूँ। इस लिए अगर समाचार पत्रों को मौलिकों और उन के प्रतिनिधि प्रबंधकों से मुक्त करने का कोई कदम उठाया जाता है तो प्रेस के हित में है और आम लोगों के भी हित में।

क्या इस का मतलब यह नहीं होगा कि मौलिकों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाने के लिए समाचारपत्रों के प्रशासन में लोकतांत्रिक पद्धति अपनायी जानी चाहिए।

वैशक और इस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पश्चिम के बहुत से समाचार-



पत्रों में ऐसा होता है। फ्रांस के प्रतिष्ठित पत्र ल मांड में कर्मचारियों का ही एक मंडल पूरा प्रशासन चलाता है जिस में 35 प्रतिशत प्रतिनिधित्व संपादकीय विभाग को होता है। इसी तरह एक ओर प्रतिष्ठित ल फ़िगरो में भी संपादकीय विभाग और संचालक विभाग के बराबर बराबर प्रतिनिधि बैठ कर पूरी नीति तय कर लेते हैं।

हमें यह कहने की आदत पड़ गयी है कि देश में समाचारपत्रों पर कोई अंकुश नहीं। संपादक जो मन में आता है लिख लेता है। मगर संपादकीय स्वतंत्रता की परीक्षा सामान्य समय में नहीं, संकट में होती है। कोई भी संचालक या मौलिक दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर संपादक को निर्देश नहीं भेजता। जब वह ऐसा करता है तब उस के अपने हितों पर संकट आने की आशंका पैदा होती है। और यही वह मौके होते हैं जो देश और जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही मौकों पर यदि संपादकीय स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं किया गया तो प्रेस की स्वतंत्रता का दावा खोखला होगा।

सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के सिलसिले में श्री मानकेकर का कहना है कि हमारे देश में गोपनीयता का कोई कानून ज़रूरी नहीं है। यदि है तो मौलिक जानकारी के अधिकार का कानून, अमेरिका में भी ऐसा ही है। पत्रकार का यह अधिकार है कि वह प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का

प्रयास करे। यह अलग बात है कि सरकार कुछ बातों को 'वर्गीकृत' कर के गोपनीय घोषित करती है जैसे सेना के रहस्य। भारत भी यही कर सकता है। जानना मौलिक अधिकार है मगर जहाँ जानकारी से राष्ट्रीय हानि होने का खतरा हो वहाँ उस से इनकार किया जा सकता है। गोपनीयता कानून बनाने का मतलब यह होगा कि जानकारी के स्रोतों को ही छिपाया नहीं जायेगा जानकारी प्राप्त करने वाले को भी दंडित किया जा सकता है। यह ज़रूर है कि व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए।

प्रेस आयोग में कुछ लोगों ने पृष्ठ मूल्य पद्धति का विरोध किया है। बड़े समाचारपत्र इस के पीछे हैं। क्योंकि बड़े समाचारपत्र बहुत अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के बाद उतने ही मूल्य में पचास पृष्ठ का समाचार पत्र दे सकते हैं जितने मूल्य में एक छोटा समाचारपत्र आठ पृष्ठ भी न दे पाये। और यदि इस नीति को चलने दिया गया तो यह संभव है कि कोई एक समाचारपत्र संगठन किसी क्षेत्र में पूरे प्रेस जगत पर हावी हो। तथाकथित राष्ट्रीय समाचारपत्रों के लिए इसी आधार पर छोटे समाचारपत्रों का गला घोटना और उन का अस्तित्व मिटाना असंभव नहीं। उदारण के लिए बंबई में केवल चार बड़े समाचारपत्र हैं जिन में से दो की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरे समाचारपत्र संगठन को बंबई के सभी समाचारपत्रों को खरीदने से कौन रोक सकता है। यह खतरा इस लिए और भी अधिक हो गया है कि समाचारपत्रों का मूल्य उत्पादन व्यय के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है और छोटे समाचारपत्रों की हालत खस्ता हो गयी है। यह सही है कि केवल अखबारी कागज के उचित वितरण या सरकारी विज्ञापन में प्राथमिकता के आधार पर ही छोटे समाचार पत्र पनप नहीं सकते। मगर इन बातों को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। सरकारी विज्ञापन पर किसी किसी मामले में बड़े समाचार पत्र भी उतने ही निर्भर हैं जितने कि छोटे समाचारपत्र। नीलामी की सूचनाएँ या अन्य सार्वजनिक सूचनाओं की परवाह बड़े समाचारपत्र मले ही न करें संघ लोकसेवा आयोग और प्रादेशिक लोकसेवा आयोगों के विज्ञापनों के बिना बड़े समाचारपत्र भी लड़खड़ा जायेंगे क्योंकि यह केवल समाचार ही नहीं होते हजारों पाठकों के लिए अनिवार्य जानकारी भी होते हैं।



का सवाल है उन के लिए विकास निगम का मुकाबला उचित है मगर छोटे पत्रों के नाम पर जो धाँवली होनी चाहिए उसे रोकना जरूरी है। कौन नहीं जानता कि नामों के पंजीकरण का एक कुचक्र चल रहा है और ऐसे पत्रों के नाम पर भी अखबारी कागज बाँटा जाता है जनता वजूद ही नहीं।

श्री जोशी के अनुसार जहाँ सरकारी गोपनीयता के नाम पर प्रेस को जानकारी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए वहीं यह भी जरूरी है कि नागरिक के व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए। मृत शकुओं या अपराधी नारियों की नंगी तस्वीरें छापना अशोभनीय और क्रूर काम है।

## भेंटवात

## डॉ. स्वामीनाथन : मेरा राजनीतिक नेतृत्व और सूचना माध्यम का आभार

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आठ वर्ष कृषि भवन और दो वर्ष योजना भवन रहने के बाद अब फिर से अनुसंधान की निया में लौट गये हैं। अब वह मनीला स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं।

मनीला रवाना होने के पूर्व एक विशेष पत्र में उन्होंने बताया : 'मेरी असली जगह अनुसंधान के क्षेत्र में है। उस से मैं अधिक दिन नहीं रह सकता। मैंने जो कुछ किया है उस पर राजनीतिक नेतृत्व और समाचारपत्रों तथा जनसंचार माध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका वर्ना इतना कुछ संभव नहीं था। दूसरे विकासशील देशों में विज्ञान का विकास प्रकाश के सहयोग के अभाव में नहीं हो रहा है।'

### किस तरह का सहयोग ?

डॉ. स्वामीनाथन : स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के विज्ञान प्रेम के बारे में जितना कहा गया वह कम है। मुझे याद है कि एक बार डॉ. नेहरू ने पूसा में गुलाबों की एक प्रदर्शनी लगायी। जब डॉ. पाल ने गुलाब प्रदर्शनी का निमंत्रण भेजा तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन्हें तीन बजे आना था पर वह चार बजे आये और इस के दो घंटे तक विभिन्न प्रकार के गुलाबों को देख रहे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे। किसी प्रकार का तनाव उन के चेहरे पर नहीं था। पर जब हम ने दूसरे दिन का कार्यक्रम देखा तो आश्चर्यचकित रह गये। दो दिन के अखबार गोवा की आजादी की खबर से भरे हुए थे।

हम लोग वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हैं और इन का सारा जीवन इसी कार्य में लगा है। ग्रामीण क्षेत्र के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा। सब से अधिक रोजगार यही क्षेत्र देता है। अमेरिका ने इस साल 45 बिलियन डालर के खाद्यान्न का निर्यात किया है। हमारे देश में अमेरिका से कहीं अधिक क्षमता है क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य साल भर कृपा बनाये रखता है। अब आप चावल अनुसंधान के क्षेत्र में जा रहे हैं। इस संबंध में कुछ कहेंगे?

### और मीडिया?

डॉ. स्वामीनाथन : जिन दिनों कृषि अनुसंधान के बारे में समाचारपत्रों में लगभग कुछ नहीं छपता था तब श्री एच. वाइ. शारदाप्रसाद 'योजना' के संपादक थे। उन्होंने लगातार अनेक अंकों में हमारे काम को प्रमुखता से छापा। योजना के वे अंक आज भी पठनीय हैं।

मीडिया का कितना महत्व है यह मुझे स्वर्गीय डॉ. विक्रम सारा भाई ने समझाया। उन्होंने किसानों तक उन्नत कृषि तकनीक पहुँचाने में टेलीविजन के उपयोग पर जोर दिया। आज दूरदर्शन पर जो कृषिदर्शन कार्यक्रम है वह वास्तव में उन्हीं की देन है।

बहुत कुछ मैंने किसानों से भी सीखा है। जब किसान पूसा आते थे तो मैं उन्हें 'विजिटिंग प्रोफेसर' कहा करता था। मेरा तर्क यह था कि हम लोग तो प्रयोगशाला में काम करते हैं

हम लोग वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हैं और इन का सारा जीवन इसी कार्य में लगा है। ग्रामीण क्षेत्र के विषय में एक बात और कहना चाहूंगा। सब से अधिक रोजगार यही क्षेत्र देता है। अमेरिका ने इस साल 45 बिलियन डालर के खाद्यान्न का निर्यात किया है। हमारे देश में अमेरिका से कहीं अधिक क्षमता है क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य साल भर कृपा बनाये रखता है। अब आप चावल अनुसंधान के क्षेत्र में जा रहे हैं। इस संबंध में कुछ कहेंगे?

भारत के लिए इस का काफी महत्व है, क्योंकि 28 प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सब से आगे हैं पर उत्पादन की दृष्टि से चीन। जब मैं कटक स्थित चावल अनुसंधान केंद्र गया तो वहाँ आधे क्षेत्र में जापानी तरीके से खेती होती थी और आधे में चीनी तरीके से। मैंने कहा भारतीय पद्धति से भी काम होना चाहिए और इस के बड़े अच्छे परिणाम निकले। चावल पर दक्षिणपूर्व एशिया का भविष्य निर्भर करता है और भारत का भी।

खाद्यान्न की दृष्टि से मानवता के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं?

आने वाला समय कठिनतर होगा। वैज्ञानिकों को उस के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। वैज्ञानिकों को हमेशा एक दशक आगे रहना चाहिए।

और अंततः इस संस्था के निदेशक नियुक्त हुए। उन के अनुसंधान के विषय विविध रहे हैं। उन्होंने भारत में गेहूँ की बौनी नस्ल का विकास किया और इसी तरह की ऐसी कई फसलें उगायी जाने की शुरुआत की जिन से भरपूर पैदावार प्राप्त हो सके।

ब्रिटेन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त 57 वर्षीय वैज्ञानिक डॉ. स्वामीनाथन की उपलब्धियों को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है, जिन में से कुछ हैं चेकोस्लोवाकिया का मेंडेल शतवार्षिकी पुरस्कार, फिलिपीन का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत के शांति स्वरूप भटनागर और बीरबल साहनी पुरस्कार 8 वर्ष तक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में सचिव रहने के बाद डॉ. स्वामीनाथन को 1980 में इस पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया और तब से वह आयोजना आयोग के सदस्य हैं। हाल ही में उन का चुनाव संयुक्तराष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन की उस परिषद के सर्वोच्च पद के लिए हुआ है जो इस संगठन की गतिविधियों का संचालन करती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है।

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डा. मोनकोबु सांवासिवन स्वामीनाथन भारत की 'हरित क्रांति' के जनक माने जाते हैं। 1966 में उन्होंने, अपने सह-वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, देश को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया था। भारत की कृषि व्यवस्था से उन का संबंध बहुत पुराना है—वह 1947 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाले रहे





# अगर और समय मिलता तो और परिवर्तन हो सकते थे

मू. पू. सूचना एवं प्रसारणमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से महेश्वरदयालु गंगवार की बातचीत

“मैं राजनीतिक स्थिति पर कुछ नहीं कहूंगा। कल कार्यकारिणी की बैठक है अतः उस से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा।” बात शुरू करने के पहले ही मू. पू. सूचना तथा प्रसारणमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बातचीत की सीमा बांध दी। (11 अप्रैल को उनसे यह बातचीत हुई और 12-13 अप्रैल को मा. ज. पा. कार्यकारिणी की बैठक थी) और उनकी बांधी सीमा का ध्यान रखते हुए हमने 11 अप्रैल के दिनमान में आकाशवाणी पर छपे आलेख में उठाये गये मुद्दों जैसे प्रसारण का स्वरूप, उस के प्रति विश्वास, आम आदमी से उसकी दूरी, विश्वसनीयता आदि तक ही अपनी बातचीत को सीमित रखा।

प्र: सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में सरकारी प्रसारण माध्यमों के तंत्र के बारे में आपके क्या अनुभव रहे?

उ: सन् 77 में जब जनता सरकार आयी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मेरे सुपुर्द किया गया तो मेरे सामने प्राथमिक कार्य यह था कि प्रसार माध्यमों में जो विकृतियाँ आ गयी थी उन्हें दूर कर के उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाये। मैं मानता हूँ कि जनता शासन के कार्यकाल में उन विकृतियों को दूर करने में हमें काफी सफलता मिली और प्रचार साधनों में, आकाशवाणी और दूरदर्शन में जनता का विश्वास बढ़ा। अगर और समय मिलता तो और परिवर्तन हो सकते थे।

हमने जो परिवर्तन किये उन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा कि विपक्ष को आकाशवाणी और दूरदर्शन से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया गया। यह ऐसा परिवर्तन था जिसे हमारे बाद वाली सरकार ने भी स्वीकार किया। इस व्यवस्था को समाप्त करना आसान भी नहीं है। फिर आपत्काल में लगाये गये प्रतिबंधों को हटा कर हमने अधिकारियों के मन से भय दूर किया। इस से प्रसारणों की एकरसता टूटी और वे विश्वसनीय बनें।

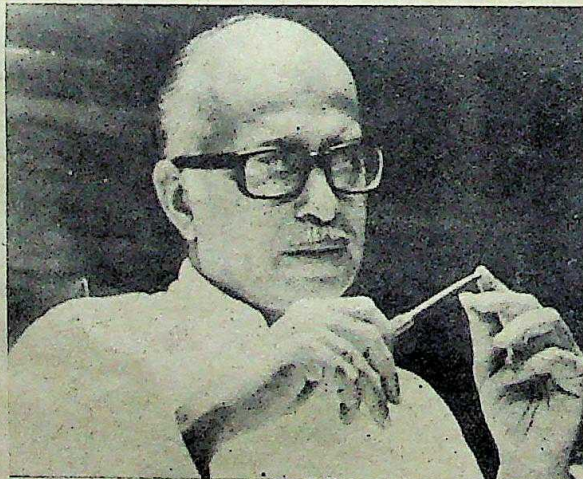
प्र: आकाशवाणी और दूरदर्शन से अब प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है?

उ: इधर मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत कुछ अलग थलग रहा। मुझे उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी, जो कार्यक्रम सुनता और देखता हूँ उनसे यह तो

लगता ही है कि उनमें अभी सुधार की काफी गुंजाइश है और सुधार का यह काम तभी हो सकता है जब कि अधिकारियों के दिल से सरकार का भय दूर हो।

प्र: इस भय को दूर करने के लिए आपने अपने कार्यकाल में कौन से कदम उठाये?

उ: हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तशासी निगम बनाने चाहे थे और इसके लिए एक विधेयक भी तैयार किया था। हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे। अतः विधेयक के गुणावगुण के विवेचन के लिए हमने उसे एक प्रवर समिति को सौंपा। अभी समिति उस पर विचार कर रही थी कि जनता पार्टी की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ गया। अगर महीने-दो महीने का समय और मिलता तो निश्चय ही हम उस विधेयक



लालकृष्ण आडवाणी : विश्वसनीयता का प्रश्न प्रसारण में संतुलन से जुड़ा है

को पारित कर के स्वायत्तशासी निगमों का गठन कर देते।

प्र: अब विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों लामोश है?

उ: हमने नयी सरकार का गठन होने के बाद इसकी माँग की थी। किंतु सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि वह आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं है। और जब हम जानते हैं कि इस सरकार के रहते ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो माँग करने से क्या फायदा?

प्र: क्या यह आरोप सही है कि विपक्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन को ले कर

तभी संसद में ही हल्ला मचाता है जब समाचार बुलेटिन में उसे पर्याप्त स्थान नहीं मिलता? वह कार्यक्रमों में आम सुधार की बात क्यों नहीं उठाता?

उ: यह आरोप एकदम सही नहीं है। हमने समय समय पर प्रसारणों में आम सुधार की बात भी उठायी है।

प्र: एक आरोप यह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन मंत्रियों तथा राजनीतिकों के भाषणों के प्रसारण पर अधिक जोर देते हैं जिस के कारण ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम छूट जाते हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए सटीक और अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। क्या यह आरोप सच है?

उ: यह बात एक हद तक सच है लेकिन प्रसारित भाषण या वक्तव्य आमतौर पर सत्ता-रुद्ध दल से संबद्ध व्यक्तियों तक ही सीमित होते हैं, विपक्ष को बहुत कम समय मिलता है। तभी विपक्ष उस के विरोध में आवाज उठाता है। उदाहरण के लिए श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने असम समस्या के समाधान के लिए एक सात सूत्री कार्यक्रम सुझाया था। किंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों में उसे स्थान नहीं मिला। अगले दिन गृहमंत्री जैल सिंह के उस

बयान को अलबत्ता प्रसारित किया गया जिस में श्री वाजपेयी के सुझाव को अव्यावहारिक कहा गया था। प्रश्न यह है कि जब एक कोई बयान समाचारपत्रों के लिए समाचार होता है तो वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचार क्यों नहीं बनता? इसीलिए न कि सरकार के विरुद्ध कुछ प्रसारित करने का साहस अधिकारियों में नहीं है। और अगर कोई ऐसा साहस करता है तो उसे सरकार का कोपमाजन बनना पड़ता है। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गयी है कि अगर कांग्रेस कोई रैली भी करती है और

उसको प्रसारणों में मनचाहा स्थान नहीं मिलता तो संबद्ध अधिकारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

प्र: ऐसी आम धारणा है कि आकाशवाणी की तुलना में बी. बी. सी. के प्रसारण कहीं अधिक विश्वसनीय है। आपकी क्या राय है?

उ: मैं ऐसा नहीं मानता। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार भी विश्वसनीय होते हैं। इस संदर्भ में विश्वसनीयता का प्रश्न प्रसारण में संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब ये माध्यम समाचारों के प्रसारण में एकतरफा



रवैया अपनाते हैं यानी सत्तापक्ष से जुड़े समाचारों को ही महत्व देते हैं, जैसा कि अब हो रहा है और जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले हो रहा था, तब उनकी विश्वसनीयता कम हो जाना स्वामाविक ही है। बी. बी. सी. पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। वह स्वतंत्र निगम है और ब्रितानी सरकार की गलत नीतियों की भी वह खुली आलोचना कर सकता है, करता है, तो निश्चय ही इस से उस की विश्वसनीयता बढ़ती है।

हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। विश्वसनीयता का संकट वास्तव में समाचारों के प्रसारणों में संतुलन से जुड़ा है। सरकारी नियंत्रण के रहते यह असंतुलन दूर होने वाला है नहीं। हमने अपने कार्यकाल में इस ओर ध्यान दिया था और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे समाचार प्रसारण के लिए निष्पक्ष नीति अपनायें। ऐसा उन्होंने किया भी और इस से उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी थी।

प्र: केंद्र निदेशकों के हाल के सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री वसंत साठे ने सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रसारण पर अधिक जोर देने की बात कही। आपकी इस बारे में क्या राय है?

उ: प्रसार माध्यमों का दायित्व तीन क्षेत्रों में बाँटा है—सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। उन के कार्यक्रमों में इन तीनों बातों का समावेश होने के साथ ही संतुलन भी हो। सूचनात्मक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ ही शिक्षात्मक कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। दूरदर्शन से इस कार्य की अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसका क्षेत्र सीमित है। आकाशवाणी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है।

प्र: क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हमारे सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है? पश्चिम का अंधानुकरण ही अधिक होता है।

उ: यह बात सच है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ही नहीं सारे सरकारी तंत्र का चिंतन पश्चिम से प्रभावित है। उसकी मानसिकता बदली नहीं है। जब तक वह नहीं बदलती, आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती।

प्र: दूरदर्शन के एक भूतपूर्व निदेशक नंदलाल चावला का कहना है कि इन प्रसार माध्यमों में आम आदमी से संबंधित मसलों को नजरंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आपकी क्या राय है?

उ: चावला साहब ने कहा है तो ठीक ही होगा। वह अनुभवहीन है।

प्र: एक आरोप यह भी है कि इन सरकारी प्रसारण माध्यमों में नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं मिलती, बलीय

निष्ठा तथा इतर आधारों पर मिलती है। आपके कार्यकाल में भी यह आरोप बोहराया गया था। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?

उ: पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। किंतु जहाँ तक मेरे कार्यकाल का प्रश्न है, यह आरोप अवश्य लगाया गया था कि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भरती किया है। मेरे बाद दो मंत्री हुए और उन दोनों ने ही इस बात की जाँच करायी कि क्या ऐसी भरती हुई है। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बात उन्होंने मुझसे भी कही, जहाँ तक मेरी जानकारी है एक भी कर्माचारी इस आरोप के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला गया है।

### ज्ञानपीठ पुरस्कार

## अमृता प्रीतम

जैसे घने छतनार दरस्तों के पीछे एक मकान की ऊपरी मंजिल में रोशनी उस दिन भी देर रात तक जलती रही जिस दिन अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी। छरहरा बदन, सुंदर मुख जो अब उम्र की मार से तप कर कुछ और भी कहने लगा है, इस जानदार कवयित्री को आज भी साहित्यकारों की भीड़ में अलग दिखा देता है। अमृता प्रीतम खुली हवा का नाम है और उन की कविता लवरेज छलकते प्रेम के पैगाम का। दोनों की पहचान एक बेहद लंबे अरसे से पंजाबी के ही नहीं हिंदी के पाठकों को भी रही है और भारतीय भाषाओं से ले कर समाजवादी देशों में वह गहरी और आत्मीय होती गयी है। 1981 का यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उन की कविता पुस्तक कागज ते कनवास (1973) पर दिया गया।

पुरस्कार से खुश हो कर इतराने का स्वभाव अमृता प्रीतम का नहीं है। अब उम्र के उस मुकाम से वह आगे ही यात्रा कर रही हैं जहाँ अपनी रचना पर विश्वास जिंदगी के और नये नये अर्थों की तलाश में बदलता जाता है। उन का उपन्यास 49 दिन मृत्यु और पुनर्जन्म की दास्तान है। अमृता प्रीतम को हिंदी में उन के गद्य लेखन से अधिक जाना गया है। प्रतीक के युग से ही हिंदी पाठक 'पिंजर' उपन्यास से परिचित रहे हैं और पिछले दिनों उन की आत्मकथा रसीदी टिकट ने एक खुली, मजबूत और साहसी औरत की उन की तस्वीर उभारी है। प्रेम की इस गायिका में पंजाबी साहित्य की लोक आत्मा की गंध मरी हुई है और वह रंग भी जो जमाने के बड़े से बड़े सैलाब में उतरता नहीं।

अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919

को गुजरानवाला (पाकिस्तान) में हुआ— पिता का नाम कर्तारसिंह हितकारी। विवाहिता हैं—एक पुत्र, एक पुत्री। पर एक लंबे अरसे से अपने साहित्य के साथ रह रही हैं। पंजाबी में 16 काव्य संग्रह, 20 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह उन के प्रकाशित हो चुके हैं। इधर इस संख्या में और वृद्धि हुई है। हिंदी में उन के उपन्यास, कहानियाँ, और कविताएँ काफी संख्या में प्रकाशित हैं। पिछले 16 वर्षों से वह पंजाबी में साहित्यिक पत्रिका नागमणि निकाल रही हैं। 1956 में उन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार से, 1969 में पद्मश्री की उपाधि से, 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी. लिट. से उन्हें सम्मानित किया गया।

ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसी पंजाबी साहित्यकार को दिया गया है। पुरस्कार की



राशि अब बढ़ा कर डेढ़ लाख कर दी गयी है। पुरस्कार निर्णायक मंडल में विदेशमंत्री पी. वी. नरसिंह राव (अध्यक्ष), आर. के. वास गुप्त, मसूब हुसैन, नारायण मेनन, देवेन्द्रनाथ शर्मा, एम. केवल, गुरुवचन सिंह तालिब, के. बी. जैगन्नाथ, श्रीमती दुर्गा जैन और लक्ष्मीचंद्र जैन थे।

अमृता प्रीतम को पुरस्कृत किया जाना पंजाबी पाठकों के लिए ही नहीं हिंदी प्रेमियों और पाठकों के लिए भी प्रीतकर है। यह पुरस्कार इंसान की उस आग को है जो आदिम काल से आदमी के अंदर जलती है और जब तक दुनिया है जलती रहेगी—'परछाईयाँ पकड़ने वाले, दिल में जलती आग की कोई परछाई नहीं होती'। दिनमान अमृता जी को बहुत बहुत बधाई देता है और उनके कृतित्व की समृद्धि और दीर्घ जीवन की कामना करता है।

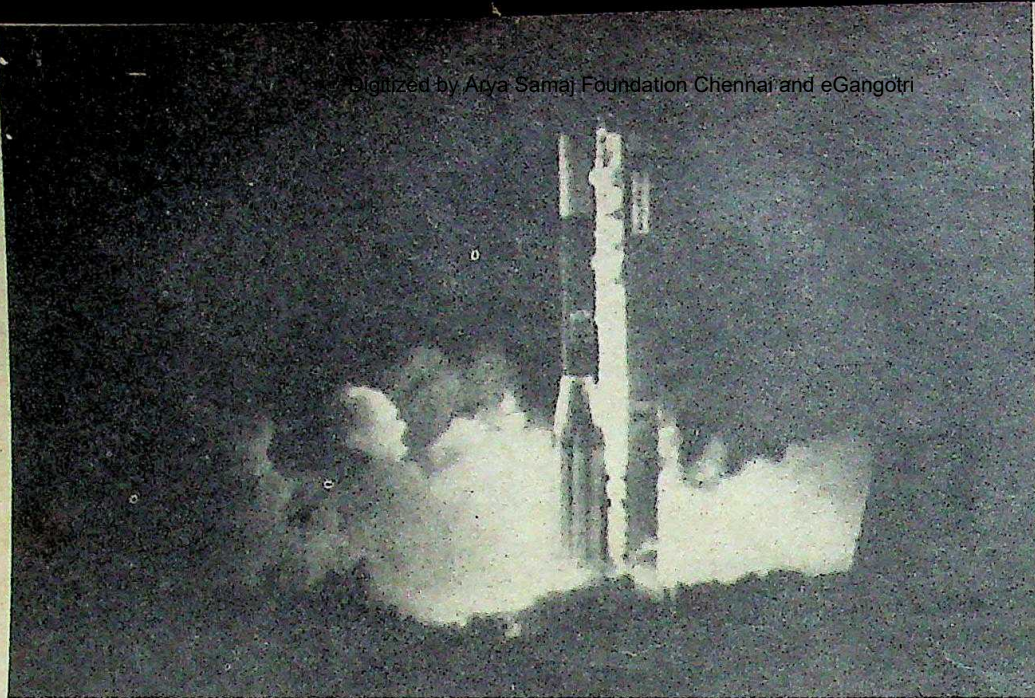
—स. द. स.

अगले अंक में:

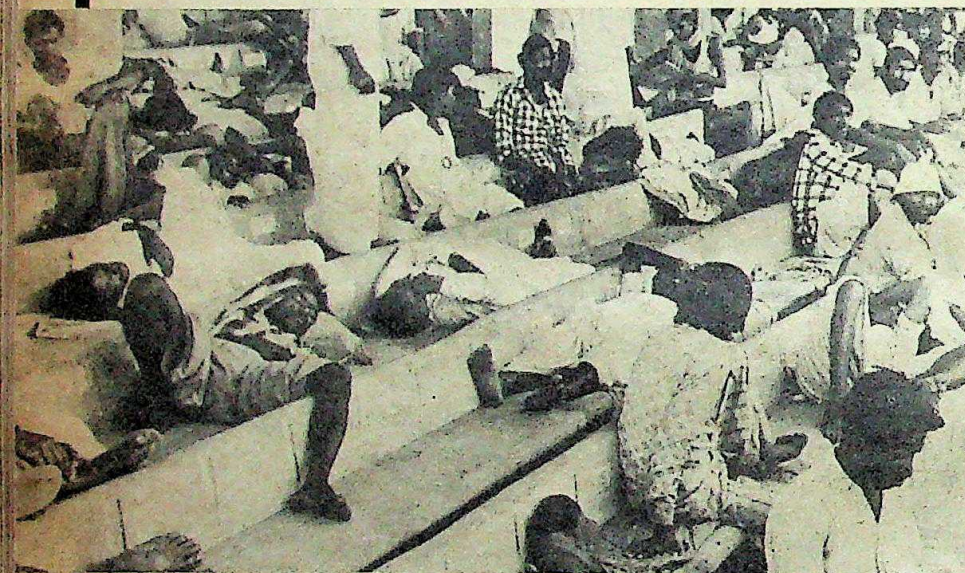
अमृता प्रीतम के पुरस्कृत

काव्यसंग्रह की चर्चा





भारत का बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट, 10 अप्रैल को, अमेरिका के केप कैनावेरल से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 'सी' बंड एंटेना में खराबी के बावजूद उसे मस्थायी कक्षा में स्थापित करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली। यह उपग्रह भारत के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम में लाया जायेगा।



पश्चिम बंगाल के सब से पिछड़े जिले पुरुलिया के रहने वालों की मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुरुलिया से कलकत्ता तक की एक गण पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के समापन पर स्वयंसेवकों ने कलकत्ता के रणजी स्टेडियम की सीढ़ियों पर लेट-वैठ कर अपनी थकान उतारी।



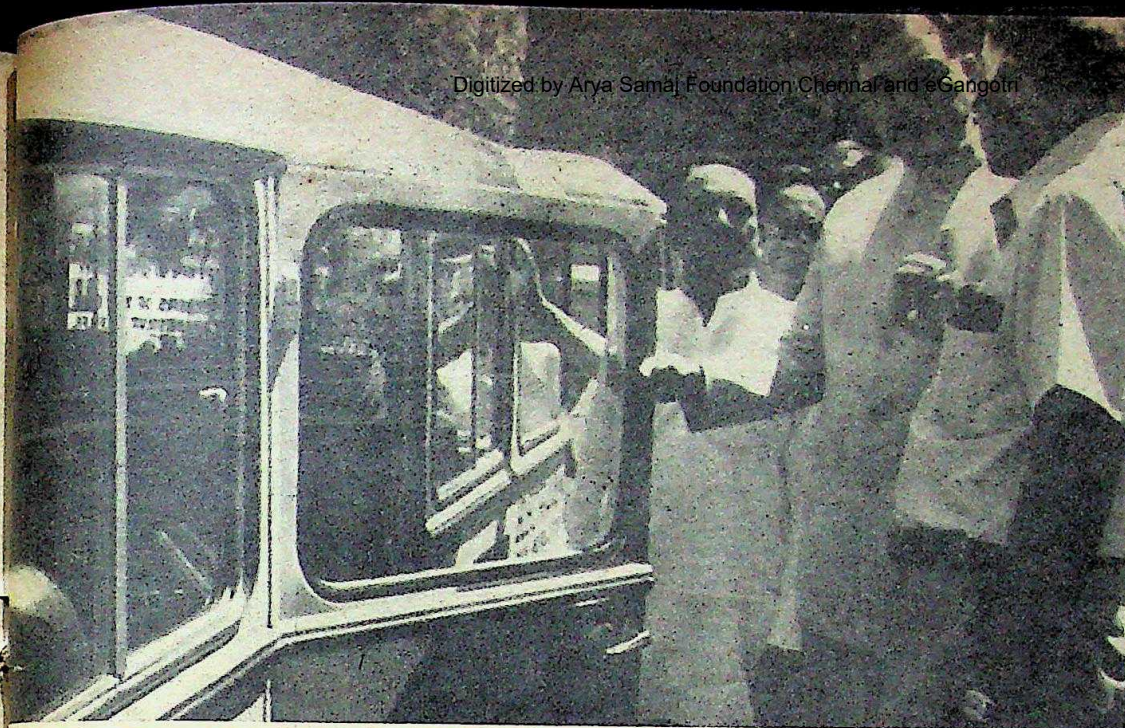
अल साल्वाडोर के उत्तरी प्रदेश चालाटेनागो में, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच होने वाली गोलीबारी में चार डच पत्रकार मारे गये। सान साल्वाडोर के एक मूर्दाघर में इन चारों पत्रकारों के शव रखे गये।





रिक्ष  
ती  
आबी

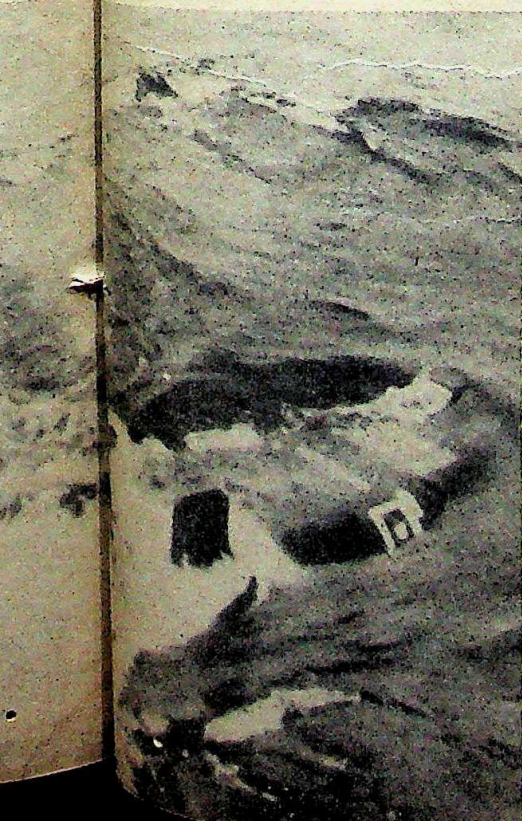
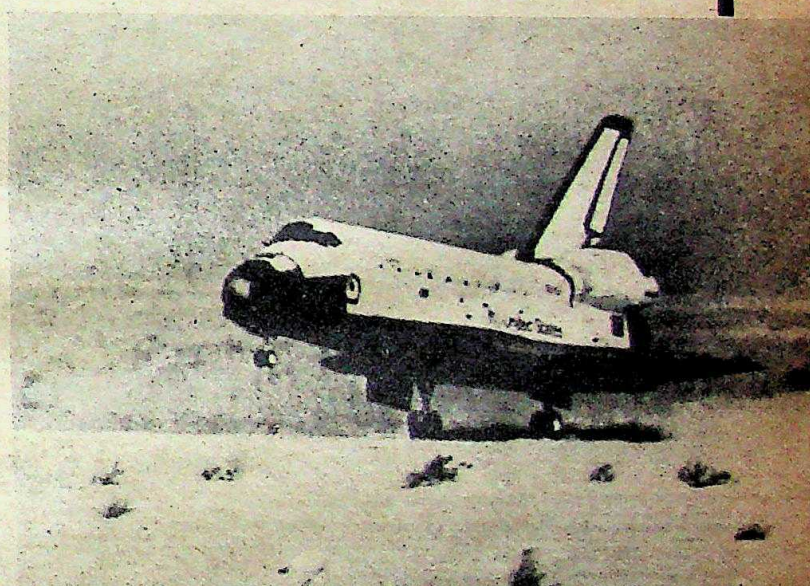
त  
र  
को पूरा  
म



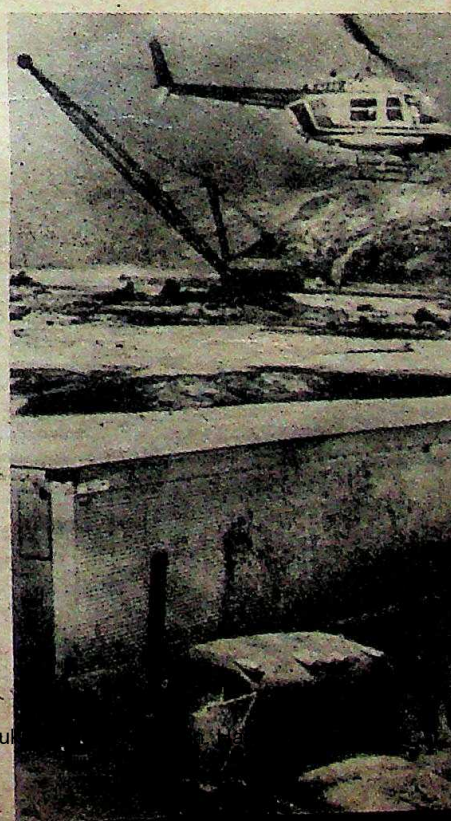
8 अप्रैल को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के राज्यमंत्री सी.पी.एन. सिंह ने लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ को दो ऐसी गाड़ियाँ भेंट कीं जिन को डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं है। फ़िलहाल, परीक्षण के तौर पर, संसद सदस्य इन का इस्तेमाल नॉर्थ और साउथ एवेन्यू के अपने घरों से संसद भवन जाने और वहाँ से वापस घर लौटने के लिए करेंगे।



(बायें) जकत्ता (इंदोनेसिया) में चुनाव प्रचार के दौरान सरकार समर्थित गोल्कर पार्टी और मुसलमानों के बीच पथराव के बाद अस्त्रों से लैस पुलिस अपनी बख्तरबंद गाड़ी के साथ बाज़ार के एक सिनेमा घर की पहरेदारी कर रहा है। (दायें) अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया तीसरी बार एक सप्ताह की उड़ान के बाद रेगिस्तानी इलाक़े के नॉर्थरूप पट्टी पर उतरा।



ब्रितानी नौसेना कुछ दिनों से आयरलैंड के उत्तर-पूर्वी तट पर एक रहस्यपूर्ण पनडुब्बी की खोज में थी। नौसेना अधिकारियों के अनुसार यह रूस की अत्याधुनिक मारक पनडुब्बी विकटर-3 है, जो समुद्र तल में सुनने के गोपनीय उपकरणों की टोह लेने की कोशिश में है। ब्रितानी वायुसेना के गश्ती वायुयान निमरॉड ने इसका चित्र लिया।



(बायें) वॉशिंगटन (अमेरिका) के सेंट हेलन पर्वत में विस्फोट के कारण टूटल नदी के उत्तरी मुहाने पर एक निर्माणाधीन बांध मलबे के नीचे दब कर तहसनहस हो गया, जिस का जायजा लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर उस टुक और ट्रैलर पर सँडराता रहा जो कभी यहाँ कार्यरत थे।



## प्रदेश

मध्यप्रदेश

उपेक्षित बस्तर में  
विद्रोह की आग

वर्षों से शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित बस्तर जिले के आदिवासियों ने राज्य शासन के वन विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध संगठित हो कर सरकार को परेशानी में डाल दिया है। इन दिनों सरकार उन के 'सशस्त्र विद्रोह' और 'समानांतर सरकार' की खबरों से काफी विचलित है, यहाँ तक कि, उन्होंने बस्तर के राष्ट्रीयकृत वनों से वृक्षों की कटाई और इमारती लकड़ी की निकासी पर भी रोक लगा दी है।

आदिवासियों के इस विद्रोह के पीछे दो मुख्य कारण बताये जाते हैं। एक तो बस्तर जिले में नक्सलवादियों की सक्रियता, दूसरे बाबा बिहारीदास का प्रभाव। हालाँकि बाबा बिहारी दास उर्फ कंठी वाले बाबा का प्रभाव उतार पर है, फिर भी उच्चाधिकारियों का विचार है कि बाबा इन आदिवासियों की कल्पना को प्रभावित करने वाले किसी आधारभूत मुद्दे को उठाने में सफल हो गये हैं।



पनघट से वापसी

फोटो : रमेश नैयर

विनमान

पिछले दिनों बस्तर जिले की कोंडागांव तहसील के मदपाल वन क्षेत्र में तीर कमान और अन्य पारंपरिक हथियारों से लैस लगभग 300 आदिवासियों ने लकड़ी लाद कर ले जा रहे 10-12 ट्रकों को रोक कर ट्रक कर्मचारियों को लकड़ी उतार देने के लिए बाध्य किया। एक वन संरक्षक जिद पर अड़ा रहा तो उसे नंगा कर दिया गया। आदिवासियों का यह आक्रामक रुख देख कर अधिसंख्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। उसी दिन जब एक पटवारी ग्रामीण आवास योजना के लिए कुछ मूखंड काटने के लिए उस क्षेत्र में पहुँचा, तो उसे रोक कर आदिवासियों ने जमीन नापने के सारे औजार छीन लिये। उन्होंने वन विभाग की लकड़ी ढोने वाले 5 ट्रकों को रोक कर सारी लकड़ी उतरवा ली।

इस मिनी विद्रोह के सिलसिले में पुलिस ने कई गिरफ्तारियाँ कीं। नतीजा : पुलिस द्वारा गोलीबारी, उस की मजिस्ट्रेट के द्वारा जाँच और विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य विधानसभा में हंगामा।

बस्तर की वन संपदा के दोहन (कानूनी और गैरकानूनी) के प्रति आदिवासियों की जागरूकता में नक्सलवादियों की कुछ न कुछ भूमिका अवश्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि आदिवासी अर्थव्यवस्था में वृक्ष उन के विस्तार का एक बहुत बड़ा साधन हैं, वृक्षों से ही उन्हें भोजन, जलाऊ लकड़ी और झोपड़ी बनाने की सामग्री मिलती है। परंतु जंगलों की कटाई की प्रक्रिया भी वर्षों से बदस्तूर है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 1958 के पूर्व बस्तर जिले की मात्र दो तहसीलों में 15 करोड़ रु. मूल्य के वृक्ष काटे गये थे जब कि 1958 से 1965 के बीच के मात्र 7 वर्षों में 35 करोड़ रु. मूल्य के वृक्ष काटे गये। अब हालत यह है कि जंगल के 'असली मालिकों' अर्थात् इन आदिवासियों को भोजन पकाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिल पा रही है, और इसीलिए वे काफी क्षुब्ध हैं।

राज्य के गृह विभाग को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आंध्रप्रदेश के कुछ नक्सलवादियों ने बस्तर में घुसपैठ कर आदिवासियों का विश्वास जीत लिया है। ये नक्सलवादी आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व बस्तर के 300 कि. मी. सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं। वहाँ इन्होंने एक 'सुरक्षा क्षेत्र' बना लिया है। ये लोग आदिवासियों से सद्भाव भी स्थापित कर चुके हैं और अब उन्हें संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्थिति यह हो गयी है कि आदिवासी इन से प्रेम करते हैं और पुलिस से नफ़रत। वे नक्सलवादियों को 'रात में घूमने वाली पुलिस' कहते हैं और



तकलीफ की हालत में उन से मदद माँगते हैं, जो इन्हें तुरंत मिलती है।

इन नक्सलवादियों की संख्या 200 से अधिक नहीं है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में 8 'दलम्' कार्यरत हैं। क्षेत्र को आठ भागों में बाँटा गया है। एक दलम् में 6 से 15 तक लोग होते हैं। एक दलम् की नेता एक स्त्री बतायी जाती है। इनमें से अधिसंख्य शिक्षित हैं और आंध्र के होने के बावजूद वे तेलगू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं और उन में से कुछ तो डोरला जनजाति की भाषा डोली भी जानते हैं।

ये नक्सलवादी आंध्रप्रदेश के सीतारमैया गुट से संबंधित बताये जाते हैं। चंद्रपुला रेड्डी का गुट भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। गोपालपल्ली बसूर और भोपालपटनम के जंगलों में छुपने वाले इन नक्सलवादियों ने आदिवासियों से संपर्क बढ़ा कर उन्हें उन्हीं की बोली में समझाया कि उन का शोषण कौन और कैसे कर रहा है। बाद में शोषकों की इस पहचान को राजनीतिक सिद्धांतीकरण का जामा पहना दिया गया। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को अपना पहला निशाना बनाया और राजस्व विभाग को भी नहीं बख्शा। उन्होंने उनके समक्ष यह स्पष्ट किया कि उनका शोषक साहूकार या व्यापारी नहीं है, बल्कि वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। यही वे लोग हैं जो कि अस्तित्व के हर स्तर पर उनका शोषण करते हैं। यही वे लोग हैं जो उन्हें (आदिवासियों को) शारीरिक यातनाएँ देते हैं। यही वे लोग हैं जो उनको मुर्गियों, भेड़ों, बकरियों और पशुओं से वंचित करते हैं। यही वे लोग हैं जो बहुत से बहानों से उन से पैसा ऐंठते हैं। यही वे लोग हैं जो उन की औरतों का देहशोषण करते हैं।



करा कर इन नक्सलवादियों ने उन की उचित मजदूरी के लिए लड़ना शुरू किया और उन्होंने तेंदू पत्ते के ठेकेदार को उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक बाध्य किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर आदिवासियों को संगठित करने की कोशिश भी की। उन से 5 रु. प्रतिदिन मजदूरी से कम पर काम न करने के लिए कहा। कुछ ठेकेदार मजदूरों को भुगतान न करने पर नक्सलवादियों के हाथों पिटे भी।

कुछ महीनों पूर्व नक्सलवादियों ने किस्तराम गांव में वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को पकड़ा, क्योंकि उस ने गरीब आदिवासियों से 50 किलो घी इकट्ठा किया था। उन्होंने उस से वह घी आदिवासियों को वापस दिलवाया। पिछले महीने उसी डिप्टी रेंजर और एक अन्य रेंजर को पकड़ कर उन्होंने आदिवासियों को वनों में किये गये कार्य की मजदूरी दिलवायी और उन्हें सबक सिखाने के लिए सारे गांव के सामने उन्हें पीटा। पामेद गांव में वन विभाग के एक कर्मचारी को उन्होंने पकड़ा क्योंकि उस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बस्तर के संभागायुक्त के लिए 40 बकरियाँ आदिवासियों से ऐंठ ली थीं। वे बकरियाँ उन्होंने वापस आदिवासियों को लौटा दीं और इसलिए सरकार नक्सलवादियों के प्रति काफी चिंतित हो गयी है।

आदिवासियों की इस जागरूकता के पीछे जो दूसरा कारण बताया जाता है वह है बाबा बिहारीदास का प्रभाव। कहा जाता है कि बाबा बिहारीदास के सशस्त्र समर्थकों ने कोंडागांव तहसील को कई क्षेत्रों में बांट दिया है। उन्होंने खुद के 'प्रशासनिक अधिकारी' नियुक्त कर दिये हैं। लोगों को सरकार को कर चुकाने से उन्होंने मना कर दिया है और खुद की कर वसूली शुरू कर दी है। स्थानीय झगड़े सुलझाने के लिए उन्होंने साप्ताहिक बैठकें भी शुरू कर

गांवों में आने वाले वन विभाग के कई अधिकारी उन के दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं और पिटे भी हैं।

आदिवासियों के गुरु बाबा बिहारीदास का व्यक्तित्व भी अपने आप में काफी विवादास्पद है। 1969-70 में बस्तर में बाबा का पदार्पण हुआ। आते ही उन्होंने अपने चेलों को कंठियां बांटना शुरू कर दिया और उन्हें शराब और मांस का सेवन न करने की प्रेरणा दी। कंठियों के बदले प्राप्त 'दान' की राशि से उन के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। बाबा का प्रभाव इस हद तक बढ़ गया कि भोलेभाले सरल चित्त आदिवासी उन्हें बस्तर के भूतपूर्व महाराजा एवं उनकी कुलदेवी दंतेश्वरी के प्रमुख पुजारी प्रवीरचंद्र भंजदेव का अवतार समझने लगे हैं। उनके शिष्य समझते हैं कि बाबा के सीने पर जो निशान हैं वे उन गोलियों के हैं जो जगदलपुर के महल में पुलिस गोलीबारी में उन्हें प्रवीरचंद्र भंजदेव के रूप में लगी थीं। उनका यह भी कहना है कि जैसे ही महाराजा प्रवीरचंद्र का शव चिता पर रखा गया वह धुआं बन कर आकाश में गायब हो गया। इन आदिवासियों ने इस कहानी को पूरी तरह से पचा लिया है।

मध्यप्रदेश के न्यायालयों में बाबा के विरुद्ध कई प्रकरण लंबित पड़े हैं और उन के समर्थक इन मामलों को वापस लेने के लिए समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। फिलहाल बाबा बिहारीदास मध्यप्रदेश सरकार की कार्यवाहियों से बचने के लिए मध्यप्रदेश और ओडिसा की सीमा पर स्थित एक गांव में निवास कर रहे हैं और लगता है कि इस लिए शक्ति प्रदर्शन के मूड में पुनः आ गये हैं कि शायद सरकार उन के विरुद्ध लंबित प्रकरण वापस ले ले और वह पुनः बस्तर आ सकें।

## पश्चिम बंगाल

### मोर्चे के विरुद्ध मोर्चा

'अब कोई गाज गिरने पर ही चुनाव टल सकते हैं,' निर्वाचन आयोग द्वारा 19 मई को राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की घोषणा पर मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। 'इंका फिर अपना पुराना खेल खेलना चाहती है,' उनकी यह प्रतिक्रिया थी राज्य इंका अध्यक्ष आनंदगोपाल मुखर्जी के इस बयान पर कि 'कई जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि इंका चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में सोच सकती है।' बहरहाल, चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनैतिक सरगमियां बढ़ गयी हैं।

मोर्चे के विरुद्ध मोर्चा गठित होने की संभावना पर कलकत्ते से दिनमान प्रतिनिधि ने लिखा है :



ज्योति बसु : चुनाव के लिए सन्नद्ध

पूर्ण रूप से सन्नद्ध वामपंथी मोर्चे के विरुद्ध एक गैर वामपंथी मोर्चा गठित करने में कितनी सफलता मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ऐसा मोर्चा बन भी गया तो उसे लोहे के चने चवाने पड़ेंगे, इस का कारण यह है कि माकपा के, जिस के हिस्से में 12 सीटें आयी हैं, शामिल हो जाने से माकपा द्वारा नियंत्रित वामपंथी मोर्चा पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। इस के विपरीत इंका जिस गैर वामपंथी मोर्चे को गठित करने की चेष्टा कर रही है उस के सिपहसलार अभी तक बिखरे हैं, फिर यह भी कि देश में कहीं उन के बीच एकता और कहीं टकराव के कारण वह मोर्चा अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं होगा। उदाहरणार्थ, जनता पार्टी और कांग्रेस स्थानीय कारणों से पश्चिम बंगाल में तो इंका से सहयोग करने के लिए तैयार हैं किंतु अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर उन के बीच टकराव है।

इस बीच वामपंथी मोर्चे ने आपस में सीटों का बँटवारा लगभग पूरा कर लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नये घटक के रूप में मोर्चे में शामिल हुई है और सब से बड़े घटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कोटे से उसे मिली लगभग सारी सीटें उपलब्ध करायी हैं। यही कारण है कि मोर्चे की एकता बढ़ गयी है। माकपा ने कुल 209 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है जब कि पिछले निर्वाचन में उस ने 224 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फारवर्ड ब्लाक को भी 1977 की 37 सीटों के मुकाबले इस बार 34 सीटें ही प्रदान की गयी हैं। अन्य दलों की स्थिति इस प्रकार है : क्रांतिकारी समाजवादी दल-23, भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी-4, मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लाक-3, विप्लवी बंगला कांग्रेस-2, गणतान्त्रिक समाजवादी-3, पश्चिम बंगाल समाजवादी दल-5 और माकपा-12। राज्य विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 294 है।



स्व. प्रवीरचंद्र भंजदेव: मर कर भी जीवित

दिनमान



माक्सवादी नेता सरोज मुखर्जी ने सीटों के बँटवारे के संबंध में निर्णय के बाद बताया कि 1977 में माकपा के मोर्चे से अलग होने के कारण वामपंथी वोट कहीं कहीं बँट गये, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने पायेगा।

पश्चिम बंगाल प्रदेश इंका के अध्यक्ष आनंदगोपाल मुखर्जी ने दिनमान को बताया कि 'हमारी कोशिश यह होगी कि गैर वामपंथियों के वोट बिल्कुल न बँटने पायें और सभी 294 सीटों पर एक एक उम्मीदवार ही खड़े किये जायें।' उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि 'अगर ऐसा संभव हो सका तो वामपंथी मोर्चे को हर सीट के लिए एड़ी चोटी का लगाना पड़ेगा तब भी उसकी विजय संदिग्ध हो रहेगी।'

इस मोर्चे में जनता पार्टी और कांग्रेस (स) के अलावा अन्य सभी दल छोटे छोटे होंगे जो पाँच से दस सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। कुछ तो दो एक सीट भी जीत सकेंगे, इस में संदेह है। इस मोर्चे के छोटे दलों में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, गोरखा लीग, अखिल भारतीय फ़ारवर्ड ब्लाक, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और झारखंड

Digipedia by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो दल किसी मोर्चा में शामिल नहीं होंगे उन में भारतीय समाजवादी एकता केंद्र और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख हैं। स्थिति जो भी हो राज्य में अधिसंख्य सीटों पर सीधी टक्कर की संभावनाएँ बढ़ गयी हैं।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रदेश इंका के अध्यक्ष मुखर्जी को गैर वामपंथी मोर्चा गठित करने की अनुमति दे दी है। श्री मुखर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री की स्वीकृति से ही राज्य में उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी और यह कि प्रस्तावित मोर्चे में सर्वाधिक सीटें इंका को मिलेंगी। राज्य के विभिन्न इंका नेताओं के अनुसार उन की पार्टी कम से कम 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शेष 94 सीटों का ही अन्य दलों में बँटवारा होगा।

चुनाव की गतिविधि तेज होने के साथ ही राज्य में हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि होने की आशंकाएँ बढ़ रही हैं। इंका, कांग्रेस (स) और जनता पार्टी ने शिकायत की है कि उनके कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों पर समाजविरोधी तत्त्वों के हमले बढ़ गये हैं।

## राजस्थान

### आर्थिक प्रलोभनों की राजनीति

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल सरकार से समझौता हो जाने के बाद 23 दिन चल कर 9 अप्रैल को समाप्त हो गयी। कर्मचारी अपनी अधिकांश माँगें मनवाने में सफल हुए और समझौते के फलस्वरूप सरकारी कोष पर 78 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बोझ उठाना माथुर सरकार की मजबूरी थी क्योंकि सत्तारूढ़ दल आंतरिक कलह से इतना अधिक ग्रस्त है कि वह कर्मचारियों की नाराजी का बोझ नहीं उठा सकता था। श्री पहाड़िया जाते जाते श्री माथुर के लिए यों ही बहुतेरे काँटे बो गये हैं। जयपुर से दिनमान प्रतिनिधि ने लिखा है:

अपने व्यक्तित्व, कार्यक्षमता और प्रशासनिक कुशलता से राज्य में अपना राजनैतिक वर्चस्व बनाये रखने के प्रयास में असफल हो जाने पर एक अंतिम प्रयास भू. पू. मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने यह किया था कि बहुत से विधायकों को नगर विकास न्यासों और राज्य स्तरीय निगमों एवं मंडलों आदि में लाभ के पद दे दिये। आर्थिक प्रलोभनों के आधार पर विधायकों को तोड़ने की यह कोशिश भी श्री पहाड़िया के लिए कारगर साबित नहीं हुई। श्री पहाड़िया की नितांत प्रभावहीन व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री पद से विदा हो गये पर उनके बाद राज्य के शासन की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अब तक भी आर्थिक प्रलो-

भनों से घिरे इन विधायकों से मुक्त होने का रास्ता तलाश करने की कोशिश में फँसे हुए हैं।

श्री पहाड़िया ने इंका विधायक दल के 28 लोगों को सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों का अध्यक्ष बनाया था। 3 विधायक नगर विकास न्यास के अध्यक्ष बनाये गये और 9 विधायक जिन में प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखने वाले कुछ विधायक, जैसे जनार्दनसिंह गहलौत, रामदेवसिंह, मेरूलाल भारद्वाज आदि शामिल हैं, राज्य स्तरीय निगमों के अध्यक्ष बना दिये गये।

इस संबंध में रोचक तथ्य यह है कि सहकारी मनोनयन के बाद दूसरी जरूरी औपचारिकताओं का, जैसे प्रतिनिधिमंडलों के गठन, सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका और सारी स्थिति स्वार्थों की राजनीति में उलझ कर रह गयी। इन गठित मंडलों में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रबंध संचालकों के रूप में नियुक्त हुए, किंतु अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही प्रतिनिधि समितियों का गठन न होने के कारण कार्य संचालन जनतांत्रिक विधि से होने की संभावनाएँ तो रही ही नहीं, मात्र सरकारीकरण ही देखने को मिल रहा है। विधायकों की इन नियुक्तियों का जनमात्स पर यह प्रभाव पड़ा कि ये सभी विधायक मुँह बंद रखने के लिए नियुक्त किये गये हैं। ऐसे

अधिसंख्य विधायकों की छवि जनमानस में प्रलोभन प्रिय राजनीतिक की बनी और वे हीनभावना से ग्रस्त हो गये। उन की इस धूमिल छवि और हीनभावनाओं का लाभ संबद्ध प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंध संचालक आदि खुले तौर उठा रहे हैं, और अपने अपने निगमों, मंडलों और बैंकों के मनोनीत अध्यक्षों के आदेशों आदि की खुली अवमानना कर रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि न्यासों, निगमों, मंडलों आदि के अध्यक्ष बने विधायक मुख्यमंत्री माथुर को अपने संस्थानों की प्रगति की जानकारी देने के बजाय मात्र उन के पास अपने से

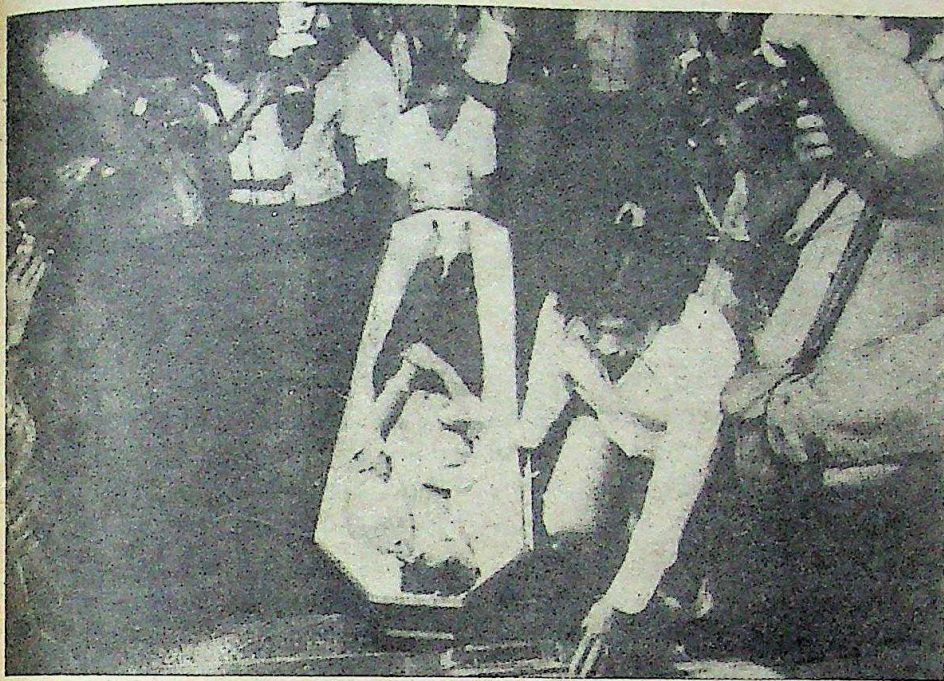
श्री पहाड़िया तो नितांत प्रभावहीन व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री पद से विदा हो गये पर उनके बाद राज्य के शासन की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अब तक भी आर्थिक प्रलोभनों से घिरे इन विधायकों से मुक्त होने का रास्ता तलाशने की कोशिश में फँसे हैं।

संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायतें ले कर पहुँच रहे हैं और जिस विभाग के अध्यक्ष का किसी अधिकारी से तालमेल नहीं बैठ पा रहा, मुख्यमंत्री से अपने संस्थान से उस अधिकारी का स्थानांतरण कहीं और कर देने की माँग कर रहा है।

श्री शिवचरण माथुर इन विधायकों से छुटकारा पाने के बारे में इन दिनों गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ऐसी राजनैतिक क्षेत्र में आम चर्चा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के सलाहकारों द्वारा एक संभावित रास्ता यह बताया जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं के विधिवत नये चुनाव करा दिये जायें ताकि बहुत से विधायक जो इन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, स्वतः हट जायें।

दिनमान प्रतिनिधि ने जब ऐसे कुछ अध्यक्ष विधायकों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें पदों से हटाने की कोशिश की गयी तो दलीय स्तर पर माथुर सरकार का विरोध शुरू हो जायेगा। कुछ ने यह संभावना भी व्यक्त की कि माथुर सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये गये तो विपक्षी दलों के कुछ लोग भी चुनाव जीत कर आ सकते हैं जो इंका के लिए लाभप्रद नहीं रहेगा क्योंकि स्थिति जो भी हो अमी तो कम से कम शासक दल के ही विधायक इन संस्थानों के अध्यक्ष बने हुए हैं। इन में कुछ प्रभावकारी विधायकों ने, जो अब खुले तौर पर माथुर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यह विचार व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री को सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के निर्णय में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस निर्णय को कुछ समय के लिए और टालना ही मुख्यमंत्री माथुर के हित में होगा।





अल साल्वाडोर में टी. वी. पत्रकार हॉस लॉग का शव वाहन में रखते हुए

अल साल्वाडोर

## डच टी. वी. पत्रकार हमले के शिकार

राजनैतिक अस्थिरता के देश अल साल्वाडोर में लगता है सभी क्षेत्र अराजकता के दायरे में घूम रहे हैं। कहीं भी कुछ भी सामान्य नहीं लगता। बेशक पिछले दिनों आम चुनाव हुए लेकिन इन्हें भी 'दोनाली की नोंक' पर संपन्न करार दिया गया। उस समय अलबत्ता विश्व भर में आक्रोश और क्रोध की लहर दौड़ गयी जब डच टेलीविजन के चार पत्रकारों की संदिग्ध स्थितियों में हत्या की खबर छपी। विश्व भर के प्रेस संगठनों ने इन टी वी पत्रकारों की हत्या की जाँच की माँग की। जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन ने बेबाक लहजे में कहा कि 'इन चारों पत्रकारों की सरकारी सेनाओं ने हत्या की है।'

लेकिन सरकार के अपने ही तर्क हैं। उस के अनुसार सेना और छापामारों में 'नियमित गोलीबारी के आदानप्रदान' के कारण ये चार टी वी पत्रकार मारे गये। सरकार ने तो अपनी पीठ स्वयं ही ठोकते हुए कहा कि वर्तमान छापामार युद्ध के दौरान जिस प्रकार अल साल्वाडोर में विदेशी पत्रकारों को प्रवेश की छूट है उस के लिए बेशक वह बर्बाद की पात्र हैं जब कि निकारागुआ की वामपंथी सरकार ने विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन एक अन्य तबके के अनुसार सरकार द्वारा तैयार की गई घाट उतारे जाने वाले लोगों की सूची में 34 पत्रकारों का नाम दर्ज है जिस में

20 अमेरिकी हैं। बहरहाल, इन चार डच टी वी पत्रकारों की हत्या के कारणों की जाँच का दायित्व अल साल्वाडोर स्थित हॉलैंड के राजदूत को सौंपा गया है।

ब्रितानी साप्ताहिक 'न्यू स्टैसमैन' के अनुसार जिन चार डच टी वी पत्रकारों की हत्या हुई वे एक डच टी वी कंपनी 'इकोन' से संबद्ध थे। यह कंपनी, अपने स्रोतों और उन पत्रकारों से जो अल साल्वाडोर छोड़ गये हैं, से जाँच और बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुँची है कि इन की हत्या सेना ने घात लगाकर की है न कि सेना और छापामारों के बीच गोलीबारी के आदान प्रदान के कारण हुई है। उन की जाँच के अनुसार कूस कोस्टर को, जो लातीनी अमेरिका में पिछले दस वर्षों से काम कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बुला कर पूछताछ की गयी थी। इस के फलस्वरूप टी. वी. पत्रकारों ने अपनी कार्य में चौकसी बरतने का निश्चय किया। बाद में अपनी पूर्वयोजना के अनुसार चालाटेनागो प्रांत में 'मुक्त क्षेत्र' में एक परिवार से मिलने के लिए टैक्सी तय करने का फैसला किया। लेकिन कोई भी टैक्सी ड्राइवर उन्हें चालाटेनागो ले चलने को राजी नहीं हुआ। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद कोस्टर सहित सभी टी. वी. पत्रकारों के चित्र अगले दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिये गये थे। लिहाजा टैक्सी ड्राइवर उन्हें ले जाने का अर्थ जानते थे,

मृत्युदंड.

बाद में जर्मनी के एक रेडियो संवाददाता अर्मिन वर्टज ने उन्हें और उन के दो साल्वाडोरियाई संपर्क सूत्रों को अपनी गाड़ी में ले जाने की हामी भरी। जब वह 17 मार्च की दोपहर को राजधानी से निकले तो क्या देखते हैं कि एक काली चैरोकी जीप उन का पीछा कर रही है। पत्रकारों का माथा ठनका। लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। 'मुक्त क्षेत्र' के परिवार से मिलने के लिए निश्चित स्थल से कुछ गज पहले ही चैरोकी जीप आँखों से ओझल हो गयी। वर्टज ने जब टी वी पत्रकारों को निश्चित स्थान पर छोड़ा तो उन्हें लेने के लिए चार छापामार उपस्थित थे। वे हल्के हथियारों से लैस थे। जब शाम 5-10 बजे वर्टज लौटा तो उसे अलबत्ता हैरत हुई कि न तो पुलिस और न ही सेना ने उन्हें रोका है जो आम बात नहीं थी।

चौबीस घंटे बाद एक अमेरिकी चित्रकार जॉन होगलैंड सान साल्वाडोर के मध्य में स्थित चर्च के अहाते में घूम रहा था कि अचानक उस की तजर पाँच अच ठकी लाशों पर पड़ी। इस चर्च के बारे में कई प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। उसने बारीकी से शवों को देखा। शायद इन शवों को दफनाने के लिए वहाँ रखा गया था। इन पाँच में चार टी वी पत्रकारों के शव थे और एक संपर्क सूत्र का। होगलैंड की यह खोज खबर बन गयी। उसने अमेरिकी दूतावास को सतर्क कर दिया। दो डच रेडियो संवाददाता चालाटेनागो प्रांत गये और सांता रीता के निकट 16 गोलियों के खोखे और खून से सने कपड़े मिल जिन्हें डच संवाददाताओं ने पहचान लिया। यह वही स्थान था जहाँ वर्टज उन पत्रकारों और संपर्क सूत्रों को छोड़कर आया था। उस क्षेत्र के किसानों ने उस सरकारी व्याख्या को गलत बताया जिसमें उसने सेना और छापामारों में 40 मिनट तक गोलीबारी के आदानप्रदान की बात कही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पाँच बजे के करीब गोलियाँ चलने की आवाज जरूर सुनाई दी थी लेकिन यह वाक्फा पाँच से दस मिनट से अधिक का नहीं था। पत्रकारों का मानना है कि ज्यों ही वर्टज उन्हें छोड़ कर मुड़ा एक निचली पहाड़ी के पीछे छुपी सेना ने गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं। दो टी वी पत्रकार और चार छापामारों की मृत्यु तुरंत हो गयी। दो पत्रकार नदी की ओर भागे। उन्हें दूसरी तरफ से गोलियाँ लगीं।

दो छापामार भाग निकलने में सफल हुए। डच रेडियो संवाददाता यान रिमेटड को उन के बारे में पता है। वह शायद राजदूत की इस मामले में मदद कर रहे हैं। फारबुदा भारती नामक छापामार गिरोह का मानना है कि उस के तीन सदस्यों को उसी स्थान पर दफना



न तो मृत पत्रकारों का कैमरा और उस से संबंधित साजसामान मिला और न ही कोस्टर का कैसेट जिस में उन्होंने मेटवार्ताएँ रिकार्ड की थीं. टी वी पत्रकारों की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलिस ने जेल के उन आठ लोगों का कठोर यातनाएँ दीं जिन के या तो चित्र थे या मेटवार्ता रिकार्ड थीं. इन में से एक राजनैतिक कैदी की हालत गंभीर है. पुलिस से पूछताछ के बाद कोस्टर ने हॉलैंड स्थित कार्यक्रम निदेशक को जो संदेश भेजा उस में लिखा था: 'मेरा खयाल है कि हम लोग खतरनाक मोड़ पर हैं.'

अमेरिकी सूत्रों के अनुसार कोस्टर की पुलिस थाने में पूछताछ के बाद उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी. सेना अधिकारियों का यह निश्चित मत था कि ये टी वी पत्रकार 'दूसरी क्रांतिकारी फिल्म' बना रहे हैं. इस से पहले जो वृत्तचित्र बना था उस का नाम है 'अल साल्वाडोर: मृत्यु या क्रांति'. लेकिन उस टी वी टीम में ये चारों—कोस्टर, कुईपेर, विलियम्सी, याग टेर लॉग—शामिल नहीं थे. कोस्टर सब से अनुभवी संवाददाता थे. वे जानते थे कि उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इस से पहले वह चोले, निकारागुआ और गुआतेमाला की घटनाओं पर भी महत्वपूर्ण फिल्में बना चुके हैं. 1980 में दूसरी बार उन्हें चोले में बंदी बनाया गया था.

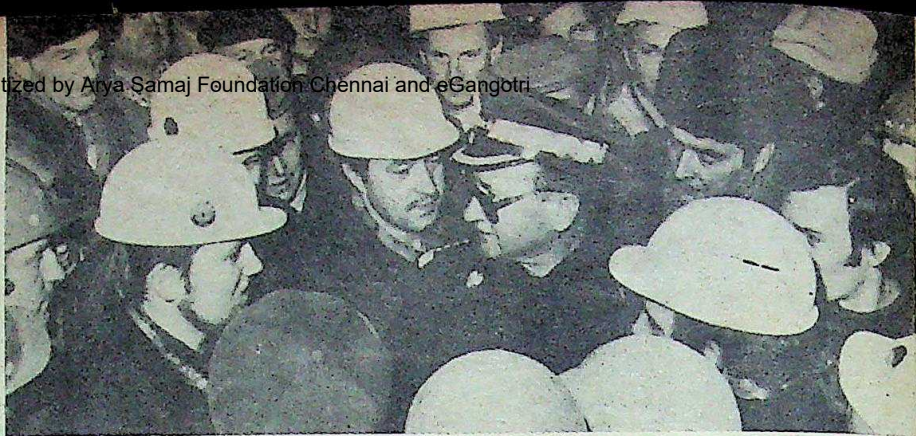
पोल्स्का

प्रशस्तिगान की स्वतंत्रता

## प्रशस्तिगान की स्वतंत्रता

ऐसा नहीं है कि तथाकथित 'यथार्थ अस्तित्व मान समाजवाद' के देशों में प्रेस की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है. स्वतंत्रता है, पर केवल तत्कालीन सत्ताधारी नेता के प्रशस्तिगान की. इन देशों में 'यथार्थ अस्तित्वमान समाजवाद' से तात्पर्य है 'ठीक इस समय सत्ता में विद्यमान नेता की मनपसंद का मार्क्सवाद.' सारा बल 'इस समय विद्यमान' पर होता है. इसीलिए ब्रेज़नेव के सत्ताकाल में खुश्चेव की या यारुजेल्स्की के समय में कानिया की प्रशंसा करना घोर अपराध है.

पोल्स्का के बहुत सारे पत्रकार यही अपराध कर बैठे. वे कानिया के 'सामाजिक नवीकरण'



बेलशादो विद्युत संयंत्र के कर्मचारियों का यारुजेल्स्की (चश्मेधारी) का घेराव

और जनरल यारुजेल्स्की के 'सामाजिक नवीकरण' को एक ही चीज मान बैठे, इसलिए 13 दिसंबर के बाद से या तो जेलों की हवा खा रहे हैं या फिर सड़कों की खाक छान रहे हैं. 'हम से यह समझने में भूल हुई', पश्चिम बर्लिन भाग से आये एक पोल पत्रकार ने कहा, 'कि एक, श्रमिकों के सहयोग से समाज का नवीकरण करने की सोच रहा था, जब कि दूसरा सैनिकों के सहयोग से समाज के नपुंसीकरण की बात कर रहा था.'

'सामाजिक नवीकरण' बनाम 'नपुंसीकरण' की इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र श्रम संघ सॉलिदारनोश्च को तो अवमर्याद कर ही दिया गया था. मार्च के मध्य में पोल्स्की पत्रकार संघ को भी मंग कर दिया गया. सारे देश के दस हजार से अधिक पत्रकारों की इस अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था का अस्तित्व राजधानी वरशावा के नगराध्यक्ष के एक आदेश के साथ तुरंत मिट गया. उस की जगह सरकार भक्तों का एक नया पत्रकार संघ बनाया गया है. पुराने पत्रकार संघ 'एस. डी. पी.' की कार्यकारिणी के सभी सदस्य गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले चार महीनों से भूमिगत हैं. केवल उस के अध्यक्ष स्तेफान ब्राकोव्स्की भूमिगत नहीं हुए, पर सरकार के आगे घुटने टेकने से भी इनकार करते रहे. सरकार को जब कोई सुयोग्य कठपुतली नहीं मिली तो उसने सारे पत्रकार संघ पर ही ताला लगा दिया. ब्राकोव्स्की और उन के अधीनस्थ कार्यकारिणी को पत्रकार संघ के सदस्यों ने 1980 में हुए एक विशेष अधिवेशन में मारी बहुमत से चुना था.

कम से कम 60 पत्रकार 13 दिसंबर के दिन ही—यानी पोल्स्का में युद्धस्थिति की घोषणा के दिन ही—गिरफ्तार कर लिये गये थे. बाद में कितने और जेल या हवालात में पहुँचे, कुछ ठीक पता नहीं. पुराने पत्रकार संघ के भूमिगत हो गये सदस्यों का अनुमान है कि देश भर में अब तक कोई 15 प्रतिशत पत्रकारों की या तो छंटनी कर दी गयी है, या फिर उन्हें निर्लंबित, बलात सेवानिवृत्त, स्थानांतरित या किसी और तरीके से दंडित किया गया है. ये सभी पत्रकार न केवल समाजवाद समर्थक हैं, बल्कि बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और किसी समय सरकार के चहेते भी रह चुके हैं.

उन का अपराध इतना ही है कि वे समाजवाद को मार्क्स के तराजू पर तोलते हुए मजदूर वर्ग की तानाशाही मानते हैं, न कि सैनिक वर्ग की.

पोल्स्का या किसी भी समाजवादी देश में बिना आधिकारिक अनुमति के कोई पत्र-पत्रिका निकालना तो क्या विवाह का निमंत्रण पत्र या मुलाकाती कार्ड तक छपवाना संभव नहीं. इतने व्यापक सरकारी नियंत्रण के बावजूद युद्ध स्थिति की घोषणा होते ही पोल्स्का के सभी दैनिक समाचारपत्रों का प्रकाशन सरकार ने कई दिनों तक रोके रखा. लगभग एक सप्ताह तक पूरे देश में एक भी पत्र या पत्रिका नहीं छपी. बाद में जैसे जैसे संपादकीय कार्यालयों में भरती, तलाशी और सरकार भक्ति के शपथपत्रों पर हस्ताक्षर कराने का काम पूरा होता गया, बंद पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी क्रमशः शुरू हुआ. पार्टी मुखपत्र 'त्रिबूना लूद' (जन ट्रिब्यून) को सब से पहले पुनर्प्रकाशन की अनुमति मिली. देश के सब से लोकप्रिय दैनिक 'ज़ियची वर्शावी' (वरशावा का जीवन) को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी. स्वयं उपप्रधानमंत्री राकोव्स्की द्वारा संपादित और अपनी साहसिक आलोचनाओं के लिए प्रसिद्ध 'पोलीतिका' का पुनर्प्रकाशन लगभग तीन महीने तक अघर में लटका रहा. इस बीच यह पत्रिका पुनः प्रकाशित होने लगी है. उपप्रधानमंत्री राकोव्स्की अब भी उसके मुख्य संपादक हैं. पर एक सहायक संपादक और दस उपसंपादकों की छट्टी हो गयी है.

युद्धस्थिति की घोषणा के पहले ही दिन जो पत्रकार गिरफ्तार कर लिये गये, कहते हैं, उन में सरकारी टेलीविजन सेना की 'ब्रोक्वाव स्टूडियो' के करीब सब के सब पत्रकार शामिल थे. पिछले दिनों 'ज़ियची वर्शावी' के 'नीकरी चाहिए' स्तंभ के अंतर्गत छपे एक निजी विज्ञापन की वरशावा से बाहर भी बड़ी चर्चा रही. विज्ञापन था: 'ईमानदारी का काम चाहिए, याचेक मज्जीरास्की, टेलीफोन 236670.' मज्जीरास्की 12 दिसंबर 1981 तक राजधानी वरशावा का एक सब से प्रसिद्ध और लोकप्रिय पत्रकार था. पोल्स्का की दीनदशा के बारे में उस के लेख और टिप्पणियाँ अगस्त 1980 के बाद से मुख्यतः 'कुल्तूरा' नाम के एक साप्ताहिक



में छपा करती थी। यह साप्ताहिक 13 दिसंबर के बाद से फिर नहीं छपा।

किंतु मजोरस्की के इस छोटे से विज्ञापन का मूल अर्थ यह नहीं है कि उस जैसे पहुँचे हुए कुलमवीर को भी आज नौकरी के लाले पड़ गये हैं, नहीं, उस का मूल अर्थ है: 'ईमानदारी का काम चाहिए। बेईमानी भरा काम तो उसे यारुजेल्स्की के पोलस्का में हर समय मिल सकता है।' बहुत से ऐसे पत्रकारों ने, जो सरकार भक्ति की शपथ ले कर बेईमानी करने को तैयार नहीं थे, स्वयं ही अपनी नौकरियाँ छोड़ दीं। उन में से एक इस समय वरशावा में टैक्सी चला रहा है। एक दूसरा फूल बेच रहा है।

चोरी छिपे अवैध रूप से प्रकाशित होने वाले पत्रों में हाल ही में कुछ भूतपूर्व पत्रकारों ने लिखा कि आर्थिक गतिविधियों के पत्र 'ज़ियची गोश्पोदाशों' के चार वर्षास्त साथियों ने बड़ईगिरी का काम शुरू कर दिया है। चारों ने मिल कर अपना बड़ईगिरी का एक छोटा सा कारखाना खोला है। बड़ई को सत्ताधारियों की बापलूमी भी नहीं करनी पड़ती और किसी पत्रकार से कम कमाई भी नहीं होती।

वरशावा टेलीविजन के एक युवा संपादक ने अपनी पैनी बुद्धि का परिचय देने में शायद सब को पछाड़ दिया है। उसने स्वयं ही टेलीविजन की नौकरी छोड़ दी और एक विज्ञापन के माध्यम से नाइजीरिया के दूतावास में बैरा बन गया। नाइजीरियाई दूतावास में जब भी कोई समारोह होता है, वह ब्रितानी राजघरानों के बरों जैसी पोशाक में अतिथियों को शैंपेन और ब्रांडी पिलाता है, अतिथियों में अक्सर ऐसे सरकारी और पार्टी पदाधिकारी भी होते हैं, जो अन्यथा शायद उसे हवालत में देखना अधिक पसंद करते।

अकेले ग्दांस्क शहर में ही कोई 300 में से 16 पत्रकारों को पत्रकारिता करने की अनुमति नहीं रही। उनकी न केवल नौकरी ही छीन ली गयी है, वे पत्रकार के तौर पर अब काम ही नहीं कर सकते। वहाँ के 6 रेडियो और 12 टेलीविजन संपादकों को भी अपनी रोखी रोटी हाथ धोना पड़ा है। 4 जेल में बैठे हैं। 9 न तो किसी पार्टी पत्र में काम कर सकते हैं और न ही और कोई प्रमुख संपादकीय पद संभाल सकते हैं। 18 को समय से पहले ही पेंशन दे दी गयी है। यह सारे आँकड़े केवल ग्दांस्क की स्थानी कहते हैं। चेर्नोबिल के बारे में सुनने में आया है कि वहाँ पुराने पत्रकार संघ के सभी सदस्यों को किसी न किसी रूप में दंडित किया गया है।

अपने विरोधियों से सस्ते में छुट्टी पाने के लिए वे श्रमिक नेता लेख वावेसा से ही नहीं, बल्कि लोगों से भी कह रहे हैं कि वे विदेश क्यों चले जाते। इस समय कोई 40 हजार पोलिश लोग यूरोप के देशों में शरणार्थी बने बैठे हैं।

इन शरणार्थियों में कुछ बहुत ही चौका देने वाले नाम भी हैं—जैसे कि वर्तमान उप-

प्रधानमंत्री राकोव्स्की की पहली पत्नी और पुत्र। दोनों इस समय पश्चिम जर्मनी में हैं। पुत्र पहले आया पत्नी बाद में। एक टेलीविजन अंतरवात्ता में उन की इस गायिका पत्नी ने, जो विवाह विच्छेद के बाद से उन के साथ नहीं रह रही थी पर उन से संबंध बनाये हुए थी, उन के बारे में कहा कि उन की समझ में नहीं आता कि राकोव्स्की जैसा आदमी भी सत्तासुख के लिए कैसे अपनी अंतरात्मा की अनसुनी करने लगा है। वह पोलस्का में चल रहे दमन का विरोध करना अपना परम कर्तव्य समझती है। उपप्रधानमंत्री राकोव्स्की की वर्तमान पत्नी भी सॉलिदारनोश्च की सदस्य रह चुकी हैं और वह भी श्रमिकों के दमन से समझौता करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। राकोव्स्की ने एक ब्रितानी पत्र के साथ बातचीत में स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें सब से अधिक अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

जनरल यारुजेल्स्की के बारे में पोलस्का के आम आदमी का रहा सहा भ्रम भी उस समय दूर हो गया, जब अपनी पहली मक्खा यात्रा के समय उन्होंने पोलस्का के पहले रक्षामंत्री की समाधि पर भी फूल चढ़ाये। पोलस्का के पहले रक्षामंत्री एक रूसी नागरिक थे। स्टालिन ने उन्हें इस पद पर बिठाया था। 1956 के दंगों में स्टालिनवादी बिरुद्ध सरकार का पतन हो जाने पर वह पुनः मक्खा चले गये और बाद में वहीं मरे। यही नहीं, जनरल यारुजेल्स्की ने उस रूसी की समाधि पर भी फूल चढ़ाये, जिसने रूसी गुप्तचर सेवा के. जी. बी. की ओर से पोलस्की गुप्तचर सेवा की स्थापना की थी। □

—रामनारायण यादव

## ईरान-इराक

### निर्णायक प्रहार पर प्रसन्नता

'हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बहोदुर' जवानों की मदद कर यह जीत बख्सी। इसे वर्तमान समय का चमत्कार करार दिया जायेगा। उन के पास (इराक) बड़ी शक्ति से प्राप्त आधुनिक हथियार थे, बावजूद इस के उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। या तो वे भाग गये, या आत्मसमर्पण कर दिया या मारे गये।' ये शब्द 81 वर्षीय क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला खुमैनी ने अपनी सेना की जीत पर 3 अप्रैल को क्रांति के समारोह में आयोजित एक विशेष सभा में कहे थे। 18 मास से चले आ रहे इराक-ईरान युद्ध में पहली बार ईरानी

सैनिकों ने पश्चिम ईरान के क्षेत्र में स्थित शुश-देजफुल में सफलता प्राप्त की थी। सितंबर 1980 से शुरू युद्ध के पहले दौर में इराकी सैनिक ईरान के 40 मील भीतर तक पहुँच गये थे लेकिन ईरानी सैनिकों के वर्तमान प्रहार से बेशक उन का पस्त हौसला बुलंद हुआ है। इस से जहाँ ईरान के इस्लामी गणराज्य के शासकों में विश्वास की भावना जगी है वहाँ उस के आसपास के देश अधिक सतर्क हो गये हैं। वास्तव में सिवाय सीरिया के अरब जगत का कोई भी देश ईरान के वर्तमान सत्ताधारियों को रास नहीं आता।

एक अनुमान के अनुसार दक्षिण-पश्चिम के इस प्रहार में 16,000 इराकियों को पकड़ा गया। इराकी युद्धबंदियों से भरे ट्रकों को तेहरान की सड़कों से ले जाया गया ताकि लोगों को इस जीत में भागीदार बनाया जा सके। इस में ईरानी शासकों को सफलता भी मिली। लोगों ने खुल कर और फुसफुसा कर भी इन इराकी युद्धबंदियों पर फट्टियाँ कसीं। अपनी इस जीत के बाद ईरानी सैनिक अब कुजेस्तान स्थित तेल क्षेत्रों की वापसी में जुट गये हैं। एक बड़े और निर्णायक प्रहार की योजना की चर्चा है। लेकिन इराक के नेताओं ने ईरान द्वारा प्रचारित इस जीत को अपनी 'खुशफहमी' करार देते हुए कहा है कि अभी भी उस के कब्जे में पाँच शहर हैं। इस के उत्तर में ईरान पहली बार जीते हुए क्षेत्रों को दिखाने के लिए विदेशी पत्रकारों को सीमाओं पर ले गया। अयातुल्ला खुमैनी और राष्ट्रपति अहमद खुमैनी ने अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा कि इराक की ज़मीन पर उस की नज़र नहीं। जब वे इराक के कब्जे से अपना सारा इलाका खाली करा लेंगे, वे युद्धक्षेत्र से हट जायेंगे। हमला तो इराक ने किया था, ईरान ने नहीं।

ईरान के दृष्टिकोण में आने वाले इस परिवर्तन का भी बड़ी बारीकी से अध्ययन हो रहा है। इस के कई कारण बताये जा रहे हैं: एक, लगातार युद्ध के कारण उस की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो गयी है, विकासकार्य ठप्प पड़ गये हैं और लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। अपने इस आत्मविश्वास में भागीदार बनाने के लिए उन्होंने यूरोप और बेस्त स्थित पत्रकारों को अपनी जीत का चश्मदीद गवाह बनाया। जिन पत्रकारों पर कमी प्रतिबंध लगा दिया गया था उन्हें भी ईरान की इस महान् विजय का भागीदार बनाया गया। जीते हुए क्षेत्र में टी 54 और टी 62 की बस्तरबंद गाड़ियाँ थीं। कुछ अन्य सोवियत साजसामान इधर उधर छितरा पड़ा था। लेकिन हर मोर्चे पर और ईरानी सेना के हर केंद्र पर मुल्ला अवश्य विद्यमान थे। कुछ मुल्ला कहते पाये गये कि इस्लामी गणराज्य के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति के लिए 'बलिदान' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा बल्कि एक 'लक्ष्य' माना



ईरान की इस सफलता से इराक ही नहीं आसपास के देश भी परेशान हैं. अरब देशों में राजनैतिक और सैनिक स्तर पर वार्ताओं के दौर शुरू हो गये हैं. कुवैत में गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरो ने भी ईरान-इराक में युद्ध समाप्ति की सिफारिश की थी. साउदी अरब के प्रतिरक्षामंत्री राजकुमार मुलतान विन अब्दुल अजीज ने बगदाद की अचानक यात्रा कर राष्ट्रपति सहाम हुसैन से बातचीत की. इस समय ईरान विरोधी अरब देशों में जो डर समायो हुआ है क्या वह उन्हें करोड़ लायेगा और वे अपने सतही मतभेद मुला कर इस चुनौती का मिल कर सामना करेंगे, अवश्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. साउदी अरब के सक्रिय होने का कारण दोनों देशों के संबंधों में व्याप्त कटुता है. पिछले वर्ष मक्का के तीर्थस्थान पर साउदी अधिकारियों और ईरानी शिया तीर्थयात्रियों में झड़पों के फलस्वरूप दोनों देशों में अविश्वास की भावना गहराती जा रही है. साउदी अरब को यह डर है कि ईरानी अपनी 'क्रांति का निर्यात' कर रहे हैं खास कर उन देशों में जहाँ शिया संप्रदाय के लोग हैं. खाड़ी के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ शासक तो सुन्नी हैं लेकिन आबादी शिया है. ऐसे लोगों में ईरानी क्रांतिकारियों का माकूल असर हो सकता है. बहरैन में इस समय 70 लोगों पर मुकद्दमा चल रहा है क्योंकि उन्होंने देश में ईराननुमा क्रांति करने का विफल प्रयास किया था. युर्दान के शाह हुसैन ने इराक को अपना समर्थन देने की गर्ज से प्रतीकात्मक तौर पर कुछ कार्यकर्त्ता उस की सीमाओं पर भेजे हैं. ईरानी जीत की खबर से शाह हुसैन अपनी फिक्क साहेम हुसैन से बाँटने के लिए पहुँचे. बहरहाल, ईरानी शासक यदि अपनी वर्तमान जीत को संतुलन और संयम से ग्रहण करें तो उन के विरोधी देरसबेर मंत्री का हाथ बढ़ा सकते हैं. ऐसा होने पर ही ईरान में विश्वास लौटेगा और आम लोगों के साथ साथ पड़ोसियों की भी वह सद्भावना अर्जित करने में सफल होंगे. हाल ही में इस तरह के संकेत जो मिल रहे हैं उन से उम्मीदी का दामन ही पुख्ता होता दिखाता है.

दिनमान

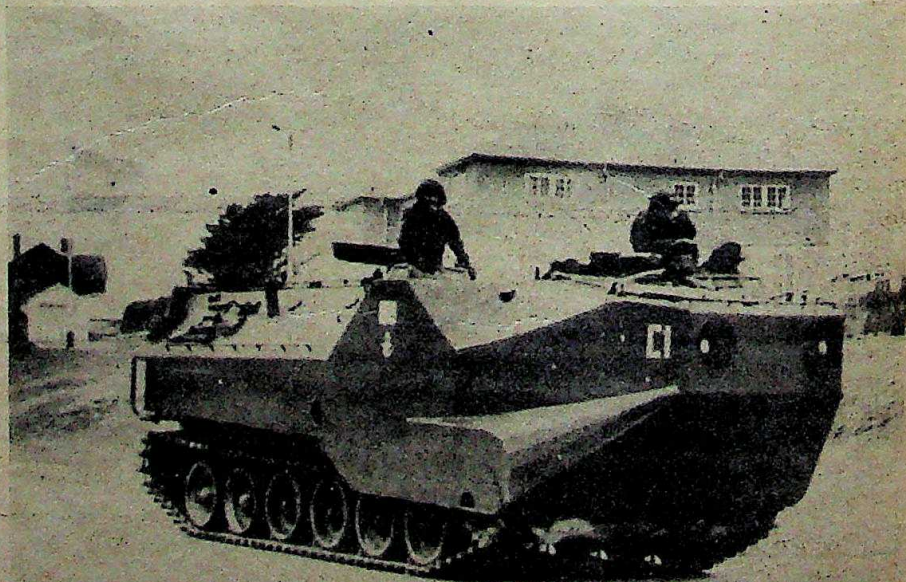
अहंतीना

## समझौते की कोई सूरत निकलेगी ही

जब ब्रिटेन का जंगी बेड़ा फॉकलैंड से एक सप्ताह दूर था तभी आहंतीना ने थोड़े सैनिकों के अलावा अपनी सेना और युद्धपोत वापस बुला लिये. अमेरिका के विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग से राष्ट्रपति लियोपोल्ड गलतियेरी की पहली मुलाकात के बाद आहंतीना के इस कदम से संघर्ष की संभावना टल गयी है. युद्ध में आहंतीना बहुत कमजोर पड़ता है और खून खराबे के बाद भी ब्रिटेन को कुछ ठोस हासिल होता यह सोच पाना मुश्किल है. फिर कोई जरूरी नहीं कि सीधी भिड़ंत होती ही. दूसरे यदि फॉकलैंड की घेराबंदी लंबे समय तक करनी पड़ती है तो ब्रिटेन से रसद और कुमुक पहुँचाने की समस्या उठ खड़ी होती है. अभी तो ब्रिटेन ने चेतावनी ही दी है कि फॉकलैंड के चारों ओर 200 मील तक दुश्मन का कोई भी पोत दीखा तो वह डुबा दिया जायेगा.

ब्रिटेन और आहंतीना दोनों ही यह बात समझ रहे हैं कि अंततः समझौते की कोई सूरत निकलनी ही है तो फिर क्यों खूनखराबे के चक्कर में पड़ा जाये. दोनों पक्षों ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है क्योंकि दोनों के ही अमेरिका से अच्छे संबंध ही नहीं, विशेष संबंध हैं. लेकिन आहंतीना की कूटनीति ने अमेरिका को असमंजस में डाल दिया है. एक नैटो का सदस्य है तो दूसरा लातीनी अमेरिका में कम्युनिस्ट विरोधी गठबंधन का सदस्य और अमेरिकी नीतियों का समर्थक है. आक्रमण की स्थिति में वह 1947 की रियो द जैनेरो संधि के तहत अमेरिका की सहायता

पोर्ट स्टैनली की सड़कों पर आहंतीना के सैनिकों की गश्त



माँग सकता है.

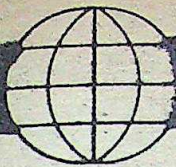
अब अमेरिका की चिंता यह है कि दोनों मित्र देशों के झगड़े को वह इस तरह निपटारे कि दोनों से उस की दोस्ती बनी रहे. यह तभी हो सकता है जब किसी भी पक्ष की इज्जत पर बट्टा न लगने पाये.

श्री हेग जिन प्रस्तावों पर रजामंदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ ये हैं: (1) ब्रिटेन का फॉकलैंड पर वैसा ही अधिकार हो जैसा हाइकाइ पर है. (2) मामला निपटने तक द्वीपसमूह संयुक्तराष्ट्र संघ के नियंत्रण में रहे व (3) फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और आहंतीना, तीनों का प्रशासन हो. अभी तो इन में से कोई भी प्रस्ताव किसी भी संबद्ध पक्ष को स्वीकार्य नहीं है.

कम्युनिस्ट देशों ने आहंतीना के पक्ष का समर्थन कर के स्थिति के विरोधाभास का लाभ उठाना चाहा है. रूस चीन के समर्थन का अर्थ है कि आहंतीना के शासक बिना कुछ पाये आसानी से समझौता कर सकें और अल साल्वाडोर में अमेरिका का साथ देने की पूरी कीमत वसूलें. अंत में जो फैसला हो, साम्यवादी देशों का कोई नुकसान नहीं होगा—वे एक विकासशील देश का समर्थन कर के तीसरी दुनिया की सहानुभूति ही अर्जित करेंगे.

लेकिन आहंतीना ने कार्रवाई के लिए यह अवसर क्यों चुना. फॉकलैंड के बारे में 1967 से आहंतीना और ब्रिटेन में बातचीत चल रही थी तो आहंतीना ने थोड़ी और प्रतीक्षा क्यों नहीं की. एक तो इस लिए कि बातचीत की गति बहुत धीमी थी. दूसरे, यह कार्रवाई कर के आहंतीना के शासकों ने अपने शासन की उम्र कई वर्ष बढ़ा ली है, क्योंकि देश की खस्ता आर्थिक स्थिति आसानी से सुलझने वाली नहीं है.





## मुनिगल संरचना

अब पहले से अधिक अमेरिकी नागरिक सरकार से अपनी आमदनी छुपाने में विश्वास करने लगे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1981 में 87 अरब डॉलर की आमदनी का राज छुपा रहा और उस से सरकार को, कर के रूप में, कोई आमदनी नहीं हुई। अमेरिकी कानून के अनुसार कर देने वाले स्वयं ही अपनी आमदनी घोषित करते हैं। लेकिन संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वाले बड़ी आसानी से सरकार की आँखों में धूल झाँक सकते हैं। गत वर्ष घोषायी गयी रकम में से केवल 1.84 प्रतिशत का रहस्योद्घाटन करने में आय कर विभाग सफल हो सका और कर की चोरी के लिए केवल 7,785 व्यक्तियों को सजा दी गयी।

तीन में से एक करदाता शोकाकर करता है कि उसने अपनी आमदनी का व्योरा देते-ए सच नहीं बोला है। कर कानून को कई खामियाँ उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। हर अमेरिकी नागरिक को एक सामान्य सुरक्षा अंक दिया जाता है, जिस की सहायता से उस की आमदनी की जाँच पड़ताल की जा सकती है। लेकिन 1979 में घोषा गया कि आमदनी के हर पाठ व्योरों में एक से यह अंक छुपाया था। व्यक्तियों से भी बढ़ कर बड़ी संस्थाओं के लिए करों की चोरी और भी आसान काम पंजी निवेश पर करों में जो छूट मिलती है उस का उपयोग करने के लिए शौचालयों से लेकर बड़की, दरवाजों पर लगायी गयी पंजी का भी एक से अधिक बार उल्लेख रहता है। महँगाई और मुद्रास्फीति ने करदाताओं को कर की चोरी करने के लिए प्रेरित किया है और 'भूमिगत व्यवस्था' घड़िले से पनप रही है।

आय कम बताने वालों के लिए

कड़ी सजाओं के प्रस्ताव रखे गये हैं। सेनेट सदस्य डोल और ग्रासली के सुझाव हैं कि हर छह महीने में करदाताओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए और देर से कर देने पर ब्याज लिया जाए। अधोषित आमदनी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लिया जाए।

## रात के तरबूज

रात में खेती करने के फायदों से लगभग सभी किसान अवगत हैं, कि जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो रात में ही उसे काटना फायदेमंद रहता है, लेकिन इस से भी बढ़ कर कुछ अमेरिकी कृषक ऊर्जा के खर्च में कटौती करने के लिए भी रातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में तरबूज, खरबूजा, जैसे फल उगाने वालों को अपना उत्पादन बाजार में भेजने से पहले उसे ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस इलाके की तपती धूप में पेड़ों पर से उतारा जाता है। आँकड़े बताते हैं कि मध्य आकार के 5000 एकड़ खेत में उगे फलों के मौसम में उन्हें ठंडा करने के लिए 50,000 डॉलर की बिजली खर्च की जाती है। रात की ठंडी हवा में तोड़े जाने पर, इन फलों को ठंडा करने के लिए, 30 प्रतिशत बिजली कम इस्तेमाल करनी पड़ती है।

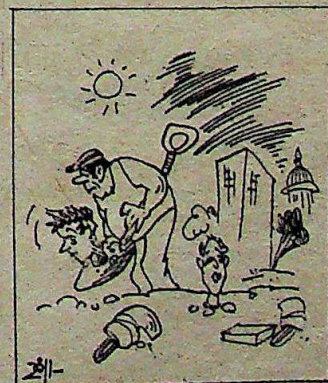
रात की खेती के और भी फायदे हैं। अधिक तापमान में तोड़े गये तरबूज और खरबूजे जल्दी सड़ जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि 100 डिग्री तापमान तक पहुँचने के पहले यदि इन फलों को तोड़ लिया जाये तो दुकानों में अधिक समय तक बिक्री के लिए रखे जा सकते हैं। फिर रात की ठंडक में काम करने वालों का शरीर और दिमाग भी ठंडा रहता है। एक कृषक, जिन्होंने 90 प्रतिशत तरबूज की खेती रात को ही की, कहते हैं कि "श्रमिकों का काम के प्रति रवैया ही बदल जाता है, जब उन्हें रात

को फल तोड़ने को कहा जाता है।" यही शायद एक ऐसी पारी है जहाँ रात को काम कर के भी मजदूर खुश होते हैं।

## रोमन साम्राज्य की वापसी!

स्पेन के टारागोना क्षेत्र के निवासी इस बात पर गर्व करते हैं कि देश भर में उन के यहाँ का मौसम सब से बढ़िया है और उन के यहाँ के ग्रामीण नजारे कोई सानी नहीं रखते। यहाँ के वांशिदे खासे संपन्न हैं, अच्छा खाते पीते हैं और आपस में भाईचारा निभाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें संतोषजनक जीवन बिताना चाहिए, लेकिन एक ऐसी समस्या उन्हें सालती रहती है जिस की शुरुआत रोमन साम्राज्य के दिनों में हुई थी। टारागोना में इस साम्राज्य के चिन्ह जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं, जिन्हें हमेशा अलग देख पाना संभव नहीं होता और ऐसा हो चुका है कि समय गुजरने के साथ साथ एक इमारत पर कई इमारतों का निर्माण हुआ। रोमन कैथलिकों का ऐसा ही एक गिरजा यहाँ पर है, जो आज ऐसे मस्जिद पर खड़ा हुआ है जो कभी गिरजा हुआ करता था और उस से भी पहले यहीं पर रोमन लोगों का एक प्रार्थनागृह था। रोमन साम्राज्य से आमनासामना किये बिना यहाँ कोई नींव नहीं खोदी जा सकती, जमीन के नीचे पाइप नहीं बिछाया जा सकती।

फ्रांको के शासन काल में पुरातात्विक खोजों को हमेशा संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता था। भूमि को समतल बनाते हुए रोमन साम्राज्य के न जाने कितने निर्माण मिट्टी में मिल गये और



सरकार ने उन्हें बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

लेकिन अब टारागोना विश्वविद्यालय और पुरातत्त्व के विद्यार्थी निर्माणस्थलों पर नजर रख रहे हैं और कोई दिलचस्प अवशेष मिलने पर काम वहीं रुकवा देते हैं।

## सोने के सालख में

मनीला के दक्षिण में स्थित नेलरोज द्वीप का छोटा सा नगर हिनोबा ऐन कुछ समय पहले तक भी नींद की शांति में खोया हुआ था। लेकिन अचानक ही इस वर्ष के आरंभ में शोर उठा कि यहाँ से पाँच मील की दूरी पर बहने वाली नदी के दोनों तटों पर सोना पाया जाता है। सोने की चकाचौंध देखने को हजारों मनीलावासी अपने फावड़े ले ले कर यहाँ दौड़े आये और इस भगदड़ में कम से कम छह लोगों ने अपनी जानें गँवायीं।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि रातोंरात अमीर बनने की धुन में महीने भर में कम से कम 100,000 लोग, धूल भरी सड़कों पर से सफर करते हुए, हिनोबा ऐन पहुँचे, जिन में अमेरिकी और जापानी भी थे। कुछ खुशकिस्मत लोगों को थोड़ा खोदने पर काफी कुछ हाथ लगा और सोने के भाव आसमान को छूने लगा। सोने की खरीद फरोख्त यहाँ अभी तक जारी है और महामारियाँ और बीमारियाँ श्लेष्म कर भी यहाँ से लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं।

इस क्षेत्र का इतिहास बताता है कि जब यह द्वीप स्पेन का उपनिवेश था। यहाँ सोना इस्तेमाल किया जाता था। 1975 में भी फिलीपीन की सरकार को खबर मिली थी कि हिनोबा ऐन के इर्दगिर्द कई धातुओं की खानें हैं, जिन में सोना भी शामिल है। लेकिन तीन वर्ष पहले दो व्यापारियों ने सोने का असली पता लगाया, लेकिन इसे राज ही रहने दिया। गत दिसंबर में, यहाँ से जाने से पहले, उन्होंने अपने सहायक को खोद खोद कर सोना जमा करते रहने के आदेश दिये, जिस ने उन दोनों के न लौटने पर कुछ सोना बेच दिया और वहीं से बात ऐसी फैली कि उस की सरगर्मी अभी तक बनी हुई है। □



## खेल और खिलाड़ी

क्रिकेट

### चेहरे की मायूसी दिल की बात बता देती है

जब जब भी टीमों का चुनाव होता है उन की आलोचना होना कोई अनहोनी बात नहीं। लेकिन तीखी आलोचना अलबत्ता अनहोनी बात होती है। आलोचना करने वाले लोगों में यदि टीम चुनने वाले बोर्ड की राज्य इकाइयाँ शामिल हों जायें तो यह अवश्य गंभीर मसला होता है। कुछ इसी प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया इंग्लैंड का दौरा करने वाली क्रिकेट टीम के चुनाव पर हुई। टीम की घोषणा पहली अप्रैल को की गयी। यद्यपि चुनाव समिति के अध्यक्ष और भूतपूर्व कप्तान पाली उमरीगर ने इस टीम को संतुलित बताया, लेकिन कुछ खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने इस टीम

उन्होंने जिन चार खिलाड़ियों के नाम गिनाये वे हैं: मोहिंदर अमरनाथ, राकेश शुक्ल, वेदराज और रोजर बिन्नी। उन के अनुसार चयनकर्ता इसे 'सर्वसम्मत' फैसला करार देते हैं, और इस की उन्हें बेहतर जानकारी भी होगी, लेकिन एक समय ऐसा तो आता ही है कि खूले आम होते अन्याय को खामोशी से सहन नहीं किया जा सकता। हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी फाइनल के ऐतिहासिक रण में जिस प्रकार दिल्ली के खिलाड़ियों का प्रदर्शन था उस की अवहेलना ही हुई है, इस बात की उन्हें आशंका भी थी। अनुशासन के नाते खिलाड़ी कुछ बोल नहीं सकते लेकिन उन के चेहरे की मायूसी उन के दिल की बात कह देती है।

इन अधिकारियों ने अपने तर्कों और तुलनात्मक आंकड़ों से चुने गये और छोड़े गये खिलाड़ियों की व्याख्या प्रस्तुत की। बोर्ड

की कथनी और करनी को सतह पर लाया गया। यदि बोर्ड का उद्देश्य युवाओं का चुनाव है तो सुरु नायक और गुलाम पार्कर को किस आधार पर चुना गया। दोनों 27 वर्ष के हैं। इस के उलट मनिंदरसिंह और गुरशरणसिंह जैसे होनहार खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मनिंदर को रवि शास्त्री से बेहतर स्पिन गेंदबाज माना जाता है। कुछ लोग उसे 'भविष्य का बेदी' भी करार देते हैं। गुरशरण की बल्लेबाजी लाजवाब है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जिस घुआधार बल्लेबाजी से उस ने शतक दागा था उस की याद आज भी ताजा है (उस दिन बोर्ड की ओर से नियुक्त सुनील गावस्कर मैदान में नहीं थे)। यदि अनुभव की दुहाई दी जाती है तो मोहिंदर अमरनाथ और राकेश शुक्ल नायक और पार्कर से कहीं अधिक अनु-

### खिलाड़ियों के टेस्ट कीर्तिमान

| आयु              | टेस्ट | रन | विकेट |     |
|------------------|-------|----|-------|-----|
| सुनील गावस्कर    | 33    | 75 | 6718  | 1   |
| गुडप्पा विश्वनाथ | 33    | 81 | 5746  | 1   |
| दिलीप वेंगसरकार  | 26    | 48 | 2675  | —   |
| प्रणव राय        | 25    | 2  | 71    | —   |
| संदीप पाटील      | 26    | 13 | 730   | —   |
| यशपाल शर्मा      | 28    | 22 | 1071  | —   |
| अशोक मलहोत्रा    | 25    | 2  | 31    | —   |
| सैयद किरमानी     | 34    | 54 | 1774  | —   |
| कपिल देव         | 23    | 38 | 1468  | 147 |
| मदन लाल          | 32    | 22 | 497   | 43  |
| रवि शास्त्री     | 21    | 9  | 188   | 27  |
| दिलीप दोषी       | 35    | 24 | 99    | 44  |
| गुलाम पार्कर     | 27    | —  | —     | —   |
| रणधीर सिंह       | 27    | —  | —     | —   |
| शिवलाल यादव      | 25    | 15 | 207   | 41  |
| सुरू नायक        | 27    | —  | —     | —   |

को 'अति असंतुलित' करार दिया। कुछ प्रेक्षकों का तो यहाँ तक आरोप था कि टीम के चुनाव में धुरक्षेत्रीयता की भावना बरती गयी है। यद्यपि खेल की दुनिया से क्षेत्रवाद को अलग रखना चाहिए (इस तरह की बात भी सभी कहते हैं) तथापि किसी न किसी रूप में क्षेत्रवाद की घुसपैठ हो ही जाती है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबद्ध जिन तीन इकाइयों ने टीम के चुनाव की आलोचना की है, वे हैं दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, पंजाब क्रिकेट संघ और रेलवे खेलकूद कंट्रोल बोर्ड। इन संघों के तीनों अधिकारियों—कमलेश शर्मा, आई. एस. बिंदरा और पी. मोतीलाल—ने बिना छुपव्वल कहा कि कम से कम चार खिलाड़ियों के न्यायोचित दावों की अनदेखी की गयी है।

विनमान

## खेल भारती

दिनमान में सोलह साल तक 'खेल और खिलाड़ी' स्तंभ के लोकप्रिय लेखक योगराज यानी अब इसी टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली नयी पत्रिका खेल भारती का संपादन कर रहे हैं। पत्रिका के प्रवेशांक (16-30 अप्रैल) का विमोचन पिछले दिनों राजधानी के त्रिवेणी सभागार में राजा भालिंदरसिंह, रामनिवास मिर्धा और रमेश जैन तथा भारी संख्या में उपस्थित खेलप्रेमियों और खेल कमियों के सम्मुख नवें एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सरदार बट्टासिंह ने किया और कहा कि यह पत्रिका खेल जगत की रुचि में ही नहीं खेल की एक राष्ट्रीय भाषा के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योग देगी। सोलह वर्षों में खेल समीक्षक के रूप में खेल भाषा और खेल दृष्टि के लिए योगराज यानी ने काफी काम किया है और अब संपादक के रूप में और अधिक कर सकेंगे इस

योगराज यानी 'खेल भारती' का प्रवेशांक बट्टासिंह को सेंट करते हुए साथ में राजा भालिंदर सिंह और रामनिवास मिर्धा



का आभास इस प्रवेशांक से मिलता है। सुरुचि संपन्न सज्जा के साथ यह प्रवेशांक एक काफी बड़ी परिधि में खेल संसार को प्रस्तुत करता है जिस में एशियाई खेलों के विवाद और विश्वास के अतिरिक्त हॉकी, क्रिकेट, कुस्ती के बारे में ऐसी बातें कही गयी हैं, ऐसे सवाल उठाये गये हैं और ऐसी जानकारियाँ दी गयी हैं जो दुर्लभ रही हैं। अपने नाना स्तंभों में बोलती यह पत्रिका कहा जा सकता है कि हर तरह के खेलप्रेमियों के लिए एक संपूर्ण पत्रिका है—जानकारी देना, सवाल उठाना और मन बनाना तीनों परतों पर पत्रिका सजग है और अपनी इस सजगता को दिन प्रति दिन सघन और दीप्त करती जायेगी इस की आशा यह प्रवेशांक जगाता है। जल्दी ही यह पत्रिका हर खेलप्रेमी के हाथ में होगी उन्हें और अधिक समझ से भरती, सतर्क करती और समर्थ बनाती। दिनमान की शुभकामनाएँ 'खेल भारती' के साथ हैं।

स.द.स.

मवी और  
वेदराज  
ही सघे हु  
हैं। गुलाम  
इन अ  
खेलप्रेमियों  
जब विशा  
क्षेत्र के खि  
खिलाड़ी  
गावस्कर  
का अधिक  
होनी घटन  
है कि बेह  
केवल रा  
खेल में उ  
जिस सुरु  
ट्रॉफी औ  
योग्य नही  
के योग्य  
टिप्पणीका  
देखते हुए  
गेंद को 'ि  
वह अन्य  
उसे अपने  
मिला है।

स

कहानी-कल  
पत्रकारिता  
दीवी लेखन  
करें। अपने  
कहानी-लेख  
अम्बाला-छ

अपनी अप्रे  
पत्राचार पा  
लिखें। इस्टी  
शक्स 358

पत्राचार  
जा पूरा  
विवरणी में  
(द), जी-7  
110024.

पत्राचार  
पत्राचार  
पत्राचार  
पत्राचार  
पत्राचार



वेदराज 34 वर्षीय सैयद किरमानी की तरह ही सघे हुए बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों हैं. गुलाम पार्कर में ऐसे गुणों का अभाव है.

इन अधिकारियों के अलावा कुछ अन्य खेलप्रेमियों ने बड़े बेबाक लहजे में कहा कि जब विश्वसिंह बेदी कप्तान थे तो उत्तरी क्षेत्र के खिलाड़ी चुने जाते थे. एक बार तो पांच खिलाड़ी उत्तरी भारत के थे. अब जब सुनील गावस्कर कप्तान हैं तो बंबई के खिलाड़ियों का अधिक संख्या में चुना जाना कौन सी अन-होनी घटना है. लेकिन एक अन्य वर्ग का माना है कि बेहतर हो कि क्षेत्रवाद की भावना को केवल राजनीति तक ही सीमित रखा जाये. खेल में उस के प्रवेश से जगहसाई ही होगी. जिस सुरु नायक को कभी ईरानी ट्राफी, देवघर ट्राफी और दलीप ट्राफी प्रतियोगिताओं के योग्य नहीं समझा जाता था उसे अब टेस्ट के योग्य कैसे समझ लिया गया. एक अन्य टिप्पणीकार के अनुसार इंग्लैंड के मौसम को देखते हुए मोहिंदर अमरनाथ में जिस प्रकार गेंद को 'स्विंग' करने की महारत हासिल है वह अन्य किसी खिलाड़ी को नहीं. यह गुण उसे अपने पिता अमरनाथ से विरासत में मिला है.

—त्रिलोक दीप

## संक्षिप्त विज्ञापन

### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें. अपने विषय की विवरणी मंगाइये. कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें. विवरणी हेतु लिखें. इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), पोस्ट बॉक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. विवरणी मंगाइये. पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

### रिक्त स्थान

काशवाणी, रंगमंच, सांस्कृतिक क्षेत्र को संपूर्ण भारत वर्ष में अवैतनिक जादूदाता चाहिए. आवेदन पत्र हेतु लिखें: राष्ट्रीय श्रोता समाचार, 27 जवाहर नगर, इलाहाबाद.

## फोरहॅन्स दाँतों के डॉक्टर का बनाया हुआ दूधपेस्ट



दाँतों को साफ करने के साथ-साथ  
मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है

मसूड़ों की तकलीफ से स्वस्थ दाँत भी गिर सकते हैं



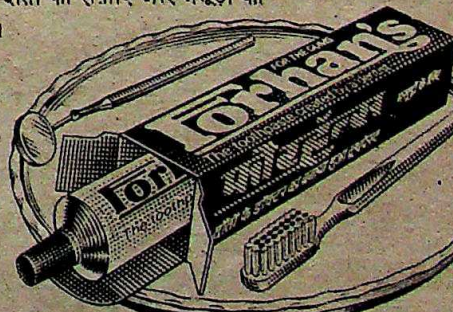
दाँतों के डॉक्टर कहते हैं कि दाँतों को ठीक से साफ न किया जाय तो कीटाणुओं की अदृश्य परत, जिसे प्लाक कहते हैं, दाँतों और मसूड़ों पर जमा होने लगती है। आगे चलकर यह टारटर बन जाती है जो मसूड़ों की कमजोर बनाकर उन्हें सिकोड़ती है जिससे स्वस्थ दाँत भी गिर सकते हैं। मसूड़ों की तकलीफ से तन्दुरुस्ती भी खराब हो सकती है।

फोरहॅन्स-मसूड़ों की रक्षा के लिए



डॉक्टर फोरहॅन्स का विशेष फ़ॉर्मूला अपने असरकारक एस्ट्रिजेंट के कारण मसूड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें तकलीफ से दूर रखने में आपकी मदद करता है।

इसलिये फोरहॅन्स दूधपेस्ट और फोरहॅन्स डबल एक्शन दूधपेस्ट से अपने दाँतों की सफ़ाई और मसूड़ों की मालिश कीजिये।



फोरहॅन्स  
मसूड़ों के लिए

Regd. T.M. Geoffrey Manners & Co. Ltd.

267F-222 HIN



## ‘भारत लोकतंत्र का नखलिस्तान है’

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएँ खारिज कर दीं। उसने अपने फैसले में कहा है कि “भारत लोकतंत्र का एक नखलिस्तान है। समकालीन इतिहास का एक तथ्य जो न्यायालयों से माँग करता है कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बुद्धिमत्ता और समझ से इस्तेमाल करें। यह दायित्व न्यायालयों का है कि वे लोकतंत्र के विकास के लिए गठित सभी संवैधानिक संस्थानों की गरिमा को बचायें और सुरक्षित रखें। ऐसे मुकद्दमों में, जिन का उद्देश्य विधायी संस्थानों के चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराना हो कोई निषेधाज्ञा जारी करने के सिलसिले में उच्च न्यायालयों को अपने अधिकारों पर अनिवार्यतः एक स्वयं-रोपित सीमा लगानी चाहिए। कारण : ऐसे संस्थान संविधान को चलाने और लोकतंत्र की नींव के मूल तत्त्व हैं।”

ध्यान देने की बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 28 मई को खत्म हो रहा है। बंगाल सरकार ने उसके पहले ही विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव पास किया। इंदिरा कांग्रेस समेत 7 अन्य दलों ने निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार करायी गयी मतदाता सूची में गलतियों का आरोप लगाते हुए चुनाव कानूनों के कुछ प्रावधानों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायधीश सत्यसाची मुकुर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर देने की निषेधाज्ञा जारी कर दी। उच्चतम न्यायालय में उस के विरुद्ध याचिकाएँ दाखिल हुईं और सुनवायी के बाद पाँच न्यायामूर्तियों की संविधान पीठ इस नतीजे पर पहुँची कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावी प्रक्रिया को चलाते रहना जरूरी है। यदि उच्च न्यायालय मतदाता सूची की गलती को आधार बना कर चुनाव से ठीक पहले दाखिल की गयी याचिकाओं में निषेधाज्ञा जारी करेंगे तो फिर चुनाव हो ही नहीं पायेंगे। न्यायालय ने कहा :

‘हमें आशा और विश्वास है कि वादियों द्वारा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप जनता के मन में यह भावना पैदा नहीं करेंगे कि पिछले 30 वर्षों में आयोग के निर्देशन, निगरानी और नियंत्रण में जो चुनाव कराये गये वे एक मखौल और बहाना रहे हैं। जनता के मन में वादियों द्वारा लगाये गये आरोप निराशा पैदा

कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतदाता को मतपेटी में अपना मत अवश्य डालना चाहिए... हमारे ख्याल से इस आरोप में कोई दमखम नहीं है कि निर्वाचन अधिकारियों ने उन गणनाकारों की मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ की जो किसी खास राजनैतिक दल से जुड़े थे। अधिकतर गणनाकार शिक्षक और सरकारी कर्मचारी थे। यह मान पाना कठिन है कि स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी वे अपने काम की सही पहचान में अक्षम हैं। सुरक्षा की कुंजी उन सक्षम और निष्पक्ष उच्च अधिकारियों के हाथ में हैं जिन्हें मतदाता सूची की आपत्तियों पर फैसला करना है... ऐसा नहीं लगता कि वह सुरक्षा इस मुकद्दमे में अंतर्धान हो गयी है...’

ताज्जुब है कि वादियों की तरफ से हमारे सामने 1950 और 1951 के चुनाव कानूनों और नियमों की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर कोई तर्क नहीं रखा गया। याचिका के बड़े हिस्से में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गयी थी लेकिन उसके समर्थन में कोई तर्क नहीं दिया गया। निश्चय ही इस लिए कि उस चुनौती में कोई दम नहीं है। हमने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले तथ्य का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसी तरह की याचिका में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका को कानूनी जामे में प्रस्तुत किया गया लेकिन मोलानाथ सेन के अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। श्री सेन ने 1960 के कानून के 26वें नियम का जिक्र करते हुए शिकायत की थी कि उस में मतदाता को अपनी शिकायत के साथ दस पैसे की फीस लगानी होती है। श्री सेन के अनुसार हर मतदाता दस पैसे नहीं दे सकता। ऐसे तर्क को अस्वीकृत कर ही दिया जाना चाहिए क्योंकि उस में कोई दम नहीं है। उस में भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी का अभाव है। हमारे देश में ऐसा कोई मतदाता नहीं है जिस के पास दस पैसे न हों या जो दस पैसे का इंतजाम अपनी शिकायतें सामने लाने के लिए न कर सके।

हम याचिका दाखिल करने वालों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने संविधान या 1950 और 1951 के चुनाव कानून या 1960 के पंजीकरण नियम का उल्लंघन किया है। मुकद्दमे की परिस्थितियों को देखते हुए निर्देशों को जिस रूप में अमल में लाया गया उसे अनुचित नहीं माना जा सकता। जनता को संवैधानिक संस्थानों के कार्यकलापों की विश्व-

सनीयता में यकीन दिलाने में एक मुद्दा लगती है। न्यायालयों का दायित्व उन सभी संस्थाओं की गरिमा की रक्षा और बचाव करना है जिन का गठन लोकतंत्र के विकास के लिए हुआ है। जब उन के संचालन के तरीके को चुनौती दी जाती हो—और जिस का अधिकार एक नागरिक को है—तो न्यायालयों को आरोपों की जाँच सामान्य से अधिक सावधानी से करनी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवायी के लिए स्वीकार करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम किया। लेकिन उस ने 12 और 19 फरवरी को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की और 25 फरवरी के फैसले में उस की पुष्टि की।

यह उचित नहीं था। वैसी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उस के सामने दस्तावेज नहीं थे। आरोप अस्पष्ट और सामान्य किस्म के थे अतः उन के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती... किसी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुकद्दमों में अंतरिम या अन्यथा ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन में उचित ढंग से आसन्न चुनावों को स्थगित करने की अर्जी दी गयी हो। चुनाव प्रक्रिया की आसन्नता ऐसा तथ्य है जिसे अनिवार्य तौर पर न्यायालय के निर्णय को निर्देशित और नियंत्रित करना चाहिए, जितना ही आसन्न वह चुनावी प्रक्रिया होनी उतनी ही बड़ी हिचकिचाहट न्यायालय को ऐसा कुछ करने में होनी चाहिए जिस से वह प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो या ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाये जिस में राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया ही न जा सके।

उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि उस ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को संपुष्ट करते हुए चुनावी प्रक्रिया में आधिकारिक ढंग से हो सकने वाले न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या दल मतदाता सूची के गलत ढंग से तैयार किये जाने के आरोप के सहारे आसन्न चुनावों को स्थगित नहीं कर सकेगा।

लोकतांत्रिक संस्थानों के बचाव और सुरक्षा की अनिवार्यता उस के निर्णय में मुखर हुई है। जन प्रतिनिधित्व कानून के कुछ प्रावधानों और नियमों की वैधता को चुनौती देते हुए वादी दल शायद उस के संभावित परिणामों की कल्पना नहीं कर पाये थे। प्रसन्नता की बात है कि उस की गंभीरता का ध्यान उन्हें आया और उन्होंने खुद ही उस की खोद विनोद नहीं की। न्यायालय खुद इस नतीजे पर पहुँचा कि उन के पास कोई तर्क नहीं था।

—रामसेवक श्रीवास्तव



## आहटें आसपास

पंकज सिंह की कविताएँ आतंक के पहाड़ों में दबी, आत्मा के ठिठुरते धुंध भरे सन्नाटे में, सपनों को बारूद में बदलने की आकांक्षा की कविताएँ हैं। वे स्वयं विद्रोही स्वभाव के, आत्मीय रिश्ते खोजते, ऊपर से उद्धत लेकिन भीतर से शालीन व्यक्ति हैं। उन को समझने में जितनी गलती की जा सकती है उतनी ही उन की कविताओं को समझने में भी। आतंक, सन्नाटा और सपने इन तीनों से रचनात्मक घरातल पर वह एक साथ जूझते हैं, रचते हैं। तीनों का एक साथ होना उन की कविताओं को सब से अलग ज़रूर करता है लेकिन तीनों में से किसी एक की साफ़ साफ़ पहचान नहीं बनने देता। विद्रोह, लड़ाई, हमला आज की अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ़ जब उन की कविताओं में उभरता दीखने लगता है तभी आत्मा के सन्नाटे को उस की ठिठुरन और धुंध को भरने के लिए वह प्रकृति का सौंदर्य, नानवीय रिश्तों में प्रेम, ममता किसी गहरी आत्मीयता को खोजने लगते हैं और भाषा अपनी शालीनता के कारण पुरानी काव्य भाषा के अनुरूप ही लिखने लगते हैं, उस से झगड़ नहीं पाते, न उसे बदल पाते हैं। इस तरह कविताएँ किसी एक बिंदु पर अपनी गहरी छाप नहीं बना पातीं। उन्हीं की तरह सही समर्थन लगती हुई भी भटकती, भटकाती रहती हैं। उन्हें न आप पूरी तरह स्वीकार पाते हैं न अस्वीकार।

समग्रता का भाव कवि की दृष्टि में होना जरूरी है लेकिन किसी एक कविता की तुलावट में उसे पिरोना कविता को कमजोर करना है। प्रेम, प्रकृति, विद्रोह सब पर तत्सम शब्दों का मोह छोड़ आज की दी टुक, खरी भाषा में अलग अलग सार्थक कविता लिखी जा सकती है।

ऐसा जिन कविताओं में उन्होंने किया है जैसे, 'बच्चे की हंसी' 'पानी का बर्तन' आदि वे उन की काव्य सामर्थ्य की साफ़ सुंदर पहचान बनाती हैं। पंकज सिंह एक अच्छे इंसान, एक अच्छे कवि हैं लेकिन व्यक्तित्व और कविता दोनों में ही किसी एक की पूरी पकड़ और दूसरे को उस क्षण छोड़ देने का निर्मोह उन में नहीं है। जीवन में इसे कोई जरूरी न भी माने पर कविता में यह बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हर कविता में अच्छी कविता की 'आहटें आसपास' ही रह जाती हैं।—स.द.स.

आहटें आसपास, पंकज सिंह, संभावना प्रकाशन, रेवती कुंज, हापुड़ 245101, मू. पच्चीस शायी।

मार्च 82

## गीत्यात्मक कथक

'नृत्य में गंभीरता है, हल्कापन नहीं। याने शोरगुल भड़ भड़ तड़ तड़। होना वह भी चाहिए कभी कभी। आडिऐंस को उस की ज़रूरत होती है'।

—दुर्गालाल

'समझदारी है। सौंदर्यबोध के स्तर पर अच्छा है। तकनीकी दृष्टि से भी विकास कर रही है,'

—डागर बंधु

'अलग तरह का कथक है'—सोनल मानसिंह

पिछले दिनों राजधानी के श्रीराम कला संस्कृति केंद्र में रश्मि बाजपेयी के कोमल सरस कथक नृत्य के बाद कुछ लोगों ने जो तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की वह ऊपर दी गयी है। दिल्ली में ऐसे नृत्य प्रदर्शन कम होते हैं जिन में सभी कला विधाओं के प्रमुख लोग—साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, नृत्यकार—काफी संख्या में दर्शकों में हों। इस दृष्टि से रश्मि बाजपेयी की नृत्य संध्या समृद्ध थी। इन अलग



रश्मि बाजपेयी

अलग संवेदन क्षेत्र को लोगों को उन का नृत्य अच्छा लगा और सभी ने उसे सराहा।

रश्मि बाजपेयी के कथक को गीत्यात्मक कथक कहा जा सकता है। इस दिशा में रानी कर्णा जैसी कुछ और नृत्यांगनाएँ काम कर रही हैं। जिन का उद्देश्य कथक को श्रेष्ठ साहित्य से जोड़ना, उस के सरस रूप को उभारना और नृत्य के बीच बीच में पढ़त तथा भाषण, निवेदन आदि के गद्यात्मक व्यवधान को समाप्त करना है। रश्मि बाजपेयी यह काम बहुत ही खूबसूरती से कर रही हैं और अपने नृत्य में कथक के सभी अवयवों की सूक्ष्म बारीकियों को, सौंदर्यमूलक तत्वों को पिराये रहती हैं। अलग अलग टुकड़ों में न दिखा कर सब समग्रता में वह दिखाती हैं। उन की प्रस्तुति में अभी काफी कुछ चीजें दोहरायी जा रही हैं (यह लगभग सभी नृत्य

विधाओं की नृत्यांगनाओं में है) लेकिन कुछ नयी चीजें कार्यक्रम में जोड़ते जाना जरूरी है। इस से ही रसज्ञ दर्शक संतुष्ट नहीं होता कि वही चीजें अब और कितना निखर कर और संगीत के सही तालमेल से और समृद्ध हो कर आयी हैं। रश्मि का नृत्य पहले से और अधिक निखरा है और संगीत इस बार पहले से और अच्छा था। रश्मि ने 'चतुरंग' बड़ी सुंदरता और निपुणता से पेश किया। विभिन्न रागों का गुंफन इसे खूबसूरती देता है। जयदेव के 'कुरु यदु नंदन' में भाव और खुलने चाहिए थे। अन्य कार्यक्रम आशानुकूल थे। कथक की गीत्यात्मकता को साधने के बाद अब रश्मि को उस के ओज तत्व को भी समोने का रचनात्मक प्रयास करना चाहिए। यही विकास यात्रा होगी। इस के आगे जैसा बिरजू महाराज कहते हैं—'सब कुछ पूरी तरह पक्का कर लेने के बाद कलाकार का अपना काम शुरू होता है—वह है गहरे जाना। गुरु का काम खतम, उस का काम शुरू'।



याको अब यक्षिणी

## यक्षिणी

साधारणतया विदेशी जब भारतीय नृत्य करते हैं तो उन का नृत्य यांत्रिक लगता रहता है। वह लय गति के अनुरूप तो चल लेते हैं पर मन से आत्मा से उस में खुद लय नहीं हो पाते। इस दृष्टि से पिछले दिनों जापान की नृत्यांगना याको ने जो अब यक्षिणी हैं, एक निराला अनुभव दिया। बिना देखे यह यकीन करना मुश्किल होता कि नृत्य की प्रस्तुति में वह एक सौ एक प्रतिशत भारतीय हैं। पश्चिमी नृत्य की यह प्रख्यात नृत्यांगना तोक्यो में एक पश्चिमी नृत्य सिखाने का बड़ा स्कूल चलाती है। अचानक उसे कथक ने बांध लिया। अब वह सब छोड़ कथक करती है और खूब करती है। कथक उस ने विजय शंकर से सीखा है जो स्वयं बहुत अच्छे



कथक नर्तक हैं लेकिन जिन्हें कुछ दुर्भाग्य से कुछ अपने सीधेपन से, कुछ विशुद्ध कलाकार होने के नाते आत्मप्रदर्शन से दूर भागने के संकोची स्वभाव से और कुछ नृत्यजगत की राजनीति से उतनी ख्याति और लोकप्रियता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। यक्षिणी को बनाने में विजयशंकर का बहुत बड़ा हाथ है और यक्षिणी ने अपने गुरु से बड़ी कुशलता से वह सब ग्रहण कर लिया है जो इस नृत्य के लिए जरूरी है—मंच पर समझ, आत्मविश्वास के साथ मुक्त, सहज, विभोर होकर नाचना, ताल-लय-मात्राओं की जटिल से जटिल बुनावट को पूरी तरह साधना और कथक के दुरुह व्याकरण को अपने नृत्य व्यक्तित्व में सरसता और

निपुणता से प्रदर्शित करना—नृत्य-आश्चर्यजनक अधिकार हो गया है—नृत्य-भाषा और गायन की भाषा की समझ—ठीक शब्दों पर ठीक भावाभिव्यक्ति, अभिनय, हाथ, कलाईयों, पैरों, घुंघरूओं का काम, टुकड़े, तोड़े, परन, आमद, चक्कर सब में सटीक और तन और भावों में शुद्ध भारतीय लचक और कसक की अभिव्यक्ति। यक्षिणी आगे चल कर भारतीय कथक नृत्यांगनाओं में अपना अच्छा स्थान बना सकेगी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है—'सीखते और नाचते समय में जापानी कहाँ रहती हूँ, मैं भारतीय हूँ,' यक्षिणी कहती है।

—स.द.स.

## संगीत

### अलाउद्दीन खां की स्मृति में

किसी बड़े कलाकार की याद में संगीत नृत्य समारोह का आयोजन आजकल आम बात हो गयी है। पिछले दिनों मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भी एक समारोह संपन्न हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादेमी भोपाल का यह निःशुल्क त्रिदिवसीय आयोजन था। कलाकारों के प्रदर्शन का स्तर और श्रोताओं की भीड़ ही अगर मापदंड हो तो निःसंदेह यह एक सफल आयोजन था। लेकिन उ. अलाउद्दीन खां जैसे आकाशधर्मा संगीत गुरु की स्मृति में उन के मजार के पास उन्हीं के नगर में कोई उत्सव हो और उत्सवधर्मिता के अलावा उस का कोई उद्देश्य न हो तो प्रयासों की निरर्थकता ही उजागर होगी। कम से कम इस समारोह में प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ साथ ऐसी उभरती प्रतिभाओं को ज्यादा पेश किया जाना चाहिए

था, जिन्हें अच्छे मंच की सख्त तलाश है। ऐसा नहीं कि समारोह में उभरते या नये नाम थे ही नहीं। लेकिन जो थे, उन में प्रतिभाशाली केवल नंदिता पटनायक और समता नायक (युगल ओडिसी नृत्य), मालविका सरकार (कथक नृत्य) और उ. अली अकबर खां के बड़े पुत्र आशीष खां (सरोद) को ही माना जाना चाहिए। प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी संयुक्ता पाणिग्रही की शिष्या नंदिता पटनायक और समता नायक ओडिसी शैली में जिस भावात्मकता का विकास कर रही हैं, वह इस शैली के भविष्य के प्रति आशा जगाता है। भंगिमा और नेत्र संचालन की पटुता से दोनों संपन्न हैं।

सामंतशाही के जाने के बाद से कथक नृत्य लगातार संकट के दौर से गुजरता रहा है।

अपवादों को छोड़ कर पिछली पीढ़ी के कथक नर्तक अभिनय पक्ष की उपेक्षा कर के प्रायः ताल के साथ पैर पीटने और ताल पर आघात गणितीय चमत्कार दिखाने में ज्यादा मशगूल नजर आते थे। लेकिन पिछले दिनों कथक की कुछ नयी प्रतिभाओं ने कथक को इस पतन के दौर से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है। ऐसी नर्तकियों में से एक हैं स्व. पं. लच्छू महाराज की सुयोग्य शिष्या मालविका सरकार जिन का विस्मयकारी नृत्य इस समारोह में देखने को मिला। मालविका का कहना है कि कथक नृत्य की दो धाराएँ हैं—एक हिंदू संस्कृति से प्रभावित और दूसरी मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित। वह दोनों को अलग अलग पेश करती हैं। यहाँ उन्होंने केवल हिंदू संस्कृति से प्रभावित कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। मालविका के वदन में लय ताल के अंदरूनी पहलू पूरी चुस्ती से अभिव्यक्ति पाते हैं। हस्ताभिनय में सूक्ष्म परिपक्वता है। तालबद्ध टुकड़ों के मध्य व अंत में सम पर आने की उन की मुद्रा बहुत अविचलित होती है।

अलाउद्दीन खां स्मृति समारोह में उ. अलाउद्दीन खां परिवार के केवल एक सदस्य ने हिस्सा लिया और वह थे बाबा के बड़े पौत्र आशीष खां। लगा आशीष को सरोद वादन में केवल अली अकबर खां के गणित पक्ष की शुष्क तालीम मिली है, स्वरलय की जटिल बुनावट में भाव लोक का अस्तित्व भी होता है, इस की जानकारी उन्हें नहीं। तार पर कोण के तीव्र आघात कर के लतीफ अहमद की तबला संगति के साथ सम पर आना संवेदनाओं के लिए एक आतंक था। एक प्रस्तुति में चार बार तार टूटना इस आतंक का गवाह है। काश अपनी अच्छी तैयारी को आशीष सही दिशा में मोड़ने की सोच पाते!

मेहर के श्रोता प्रायः शांत हैं। लेकिन वादन और नृत्य की तुलना में गायन में उन की रुचि बहुत कम है। किराना घराने के नियाज अहमद फैयाज अहमद को इसी लिए श्रोताओं का कोप-भाजन बनना पड़ा। वैसे यह मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि अहमद बंधु प्रस्तुति के



लक्ष्मीशंकर



नंदिता पटनायक और समता नायक



आशीष खां



कथक के प्रायः आधा-ज्यादा दिनों तक को इ संकल्प स्व. पं. ललितिका स समा-कहना है एक हिंदू मुस्लिम अलग संस्कृति न किया अंदरूनी हैं हस्ता-द टुकड़ों की मुद्रा में उ. सदस्य ने बड़े पीत्र वादन में की शुष्क ल बनावट है, इस की के तीरे ला संगति लिए एक तार टूटना नी अच्छी मोड़ने की केन वादन की रुचि राज अहमद का कोप-में संकोच प्रस्तुति के

समय की परिस्थितियों को परखने की ओर ध्यान नहीं देते. रात-भर चलने वाले समारोह में पांच कलाकारों के बाद आने वाले कलाकार लंबे आलापों को झेल पाना वैसे भी सामान्य शक्ति के बाहर की बात है. ठीक यही कम-होरी सज्जनलाल भट्ट के गायन कार्यक्रम में भी दिखायी दी. इस किस्म का व्यावसायिक चातुर्य यक्ष्मीशंकर से सीखा जाना चाहिए. वह प्रातः सुबह चार बजे आयीं और केवल 45 मिनट में राग वसंत के ख्याल गायन के बाद होरी, कबीर के दोहे और भजन भी गा कर चली गयीं. भावात्मकता और वैविध्य इतना कि अनुभव हुआ जैसे बहुत देर से सुन रहे हों. गंगूबाई हंगल अब ज्यादा वृद्ध हो चली हैं. फिर भी स्वर लगाव की जड़ में कहीं संवेदना है, ऐसा अनुभव जरूर होता है.

इस समारोह में तीनों दिन बाबा के मंहर बंड को सुनने का मौका मिला. बंड बहुत श्रमपूर्ण स्थिति में है. बाबा कहते थे—“ऐसा बंड संपूर्ण पृथ्वी पर दूसरा नहीं है”. लेकिन वर्तमान में सुन कर लगता है बंड के पास कोई तास कलात्मक उपलब्धियाँ नहीं रही. साजों में बाबा के जमाने का नलतरंग आज भी बजाया जा रहा है जो बेहद बेसुरा हो गया है. बंड के एक वादक के अनुसार सभी वाद्य इसी नलतरंग के स्वरों से मिलाये जाते हैं. इसीलिए पूरा वाद्यबंद बेसुरा सुनायी पड़ता है. लेकिन इस में संदेह नहीं कि इस बंड का ऐतिहासिक महत्व है. एक महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों को लेकर बाबा ने इस की रचना की थी. इसलिए मंहर भूमि के सामाजिक वातावरण को संगीतमय बनाने में इसकी भारी भूमिका रही है.

समारोह में हरिप्रसाद चौरसिया (बांसुरी) शिवकुमार शर्मा (संतूर) और बिस्मिल्लाह खान (शहनाई) के कार्यक्रम भी थे. बिस्मिल्लाह खान का कार्यक्रम मंहर में इस से पहले कभी नहीं सुना गया. अतः श्रोताओं में खां साहब के प्रति भारी उत्सुकता थी. यही कारण है कि उन की शहनाई आखिरी दिन सुबह हो जाने के बाद भी सुनी जाती रही. शमीम अहमद के सितार वादन को रविशंकर शैली का वादन माना जाना चाहिए जिस में मिठास है, क्लिष्टता है और व्यक्तिकारी का खेल है.

स्थानीय कलाकारों में केशव प्रसाद चौरसिया (सितार) एस. डी. डेविड (सरोद) और सुबाबासा त्रिपाठी (वायलिन) के नाम उल्लेखनीय हैं. इन सभी के पास तालीम है, लेकिन शायद अवसर और परिस्थितियों के अभाव में उस में चमक पैदा नहीं हो पायी है. एक विदेशी कलाकार श्री स्मिथ के बांसुरी वादन का कार्यक्रम भी शामिल किया गया था. वेस के मुकाबले स्मिथ द्वारा प्रस्तुत गायन रचना ज्यादा संवेदना भरी और सुपुण थी.

—मुकेश गर्ग



‘लोक शाकुंतल’ में हेमा सहाय (शकुंतला) और मीपम ओत्सल (दुष्यंत)

रंगमंच

## लोक शाकुंतल

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्रों ने पिछले दिनों कालिदास कृत ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ पर आधारित यक्षगान शैली में लोक शाकुंतल किया. रूपांतर तथा निर्देशन के. बी. सुब्बण्णा का था और कन्नड़ से हिंदी अनुवाद एस. बालूराव, अक्षर के वी, अनुल तिवारी का. प्रस्तुति के पूर्व क्षात्र उडीपी (कर्नाटक) गये थे और वहाँ उन्होंने यक्षगान का राष्ट्रीय उत्सव (8 से 18 जनवरी 82) देखा था और अनेक विद्वान गुरुओं के निर्देशन में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था.

लोक शैलियों में विदूषक का इस्तेमाल हमेशा किसी भी पुरानी कथा को समसामयिक सवाल से जोड़ता रहता है और नाटक युगों पुराने या पौराणिक कथाओं के हो कर भी सम-सामयिक अर्थ ग्रहण करते रहते हैं और प्रासंगिक बने रहते हैं ‘लोक शाकुंतल’ में भी विदूषक भाषा, आर्थिक विपन्नता, असमानता, भ्रष्टाचार से ले कर उपस्थित दर्शकों तक से नाटक को जोड़ता, उसे अर्थमय और जीवंत करता चलता है. अपने वाक्चातुर्य, व्यंग्य और हास्यमय गतियों, मुद्राओं के सहारे, विदूषक नाटक की जीवंत घड़कन बन जाता है और उस के लोकरंग को प्रेक्षक के भीतर उतारने का काम करता है. उस का कौशल ही नाटक की सफलता है. वह शैली के कसाव को भी बड़ी निपुणता से दिखाता है और इस से मुक्ति को भी बड़ी सहजता से रेखांकित करता रहता है. दोनों काम एक साथ बड़ी दक्षता मांगते हैं. ‘लोक शाकुंतल’ में विदूषक की भूमिका में बामन केंद्रे राव ने इसे बखूबी किया. और पूरे नाटक को अर्थमय मनोरंजकता से बांधे रखा.

यह प्रशंसनीय है कि छात्रों ने इतने अल्प समय में यक्षगान शैली सीखकर इतनी कुशलता से उसे प्रस्तुत किया. प्रस्तुति रंगों, मुद्राओं, ध्वनियों और नृत्य गतियों से समृद्ध थी. यथार्थवादी नाटक करने वाले ये छात्र

वाचिक अभिनय से हट कर पूरे वदन से भावों को अभिव्यक्त करने, तटस्थ रूप से संवाद कहने तथा नृत्यगति, संगीत से दर्शकों को रचनात्मक स्तर पर स्पर्श करने में काफी हद तक सफल रहे. निश्चय ही वह सहज भीतरी आवेग जो लोक कलाकारों में होता है, जो एक हद तक उन की आस्था से जुड़ा होता है और मंच पर उन्हें रूपांतरित कर देता है, और जिस की वजह से कलाकार शैलीगत सीमाओं के भीतर असंमित होने का प्रभाव छोड़ता है, वह नहीं था. यह अहसास निरंतर बना रहा कि ये साफ सुथरी लोकशैली पेश करने वाले छात्र लोक कलाकार नहीं हैं. उस के लिए लोक रीतियाँ नहीं लोकमन ग्रहण करना होता है जो निश्चय ही इन छात्रों के लिए कठिन था. फिर भी नाटक अपनी रंगारंग प्रस्तुति से सराहनीय छाप छोड़ गया.

विदूषक के अतिरिक्त शकुंतला के रूप में हेमा सहाय ने सुंदर अभिनय किया. हेमा सहाय के अभिनय में पूर्ण कायिक अभिनय का संतुलन और नृत्य की विशेषता जो यक्षगान में आवश्यक होती है, थी. उस की उपस्थिति का अहसास निरंतर बना रहा. इसी भूमिका में जी. एस. सुंदर थी का अभिनय और नृत्य पक्ष भी सराहनीय था. प्रियंवदा (विष्मा सिंघ) अनुसुया (डायना ठाकुर) हिरण (बानी शरव) दुष्यंत (मीपम ओत्सल/चिदांबरराव जांबे) राक्षस (अनामिका हक्सर) और हंस-पादिका (हिमानी भट्ट) सभी के अभिनय सराहनीय थे. पूरी प्रस्तुति शैलीगत सफाई से पूर्ण थी और सभी छोटे बड़े पात्रों ने अपनी भूमिकाएँ सफलता से निभायीं. भागवत (कार्तिक अवस्थी) अपने गायन और संवादों से लोक अंदाज को बनाये रखने में सफल रहे और अपनी गायन सीमा को भी अपने पक्ष में परिवर्तित कर सके. यह आत्मविश्वास लोकगत शैलियों की अपनी खास विशेषता होती है.

अंत में छात्रों की लगन के साथ-साथ निर्देशक सुब्बण्णा, मृदंगवादक मंजुनाथ प्रभु तथा चंडावादक गोपाल गार्गिंगा की इस प्रस्तुति के लिए सराहना जरूरी है. —स. व. स.





# भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी में कानूनी पुस्तकें

## (क) हिंदी में पाठ्य पुस्तकें

1. प्राइवेट (निजी) अन्तर्राष्ट्रीय विधि (प्राइवेट इन्टरनेशनल लॉ)  
लेखक—डा. पारस दीवान मूल्य छात्र संस्करण 6.25 रुपये, सजिल्द 7 रुपये.
2. उत्तर प्रदेश भू धृति विधि (उत्तर प्रदेश लैंड टेन्योर लॉ)  
लेखक—उमेश कुमार—मूल्य 5 रु.
3. मध्य प्रदेश भू-विधि (मध्य प्रदेश लैंड लॉ)  
लेखक—शिवदयाल श्रीवास्तव—मूल्य 10-50 रु.
4. निर्णय लेखन (जजमेंट राइटिंग)  
लेखक—भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी—रेक्सन की पक्की जिल्द—मूल्य 11 रुपये.
5. वंड विधि के साधारण सिद्धांत (लॉ आफ क्राइम)  
लेखक—डा. रामचन्द्र निगम—पूरे कपड़े की पक्की जिल्द—मूल्य 19 रुपये.
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन)  
लेखक—डा. प्रयाग सिंह—मूल्य 23.80 रुपये.
7. प्रशासनिक विधि (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ)  
लेखक—डा. कैलाश चन्द्र जोशी—मूल्य 16.50 रुपये.
8. चिकित्सा, न्याय शास्त्र और विष-विज्ञान (मेडिकल ज्यूरिस्ट्रूडेंस एंड टोक्सिकोलोजी)  
लेखक—डा. सी. के. पारिख, अनुवादक—डा. नरेन्द्र कुमार पटोरिया—मृष्ठ सं. 1042 तथा 287 चित्रों सहित, पूरे कपड़े की पक्की जिल्द—मूल्य 70 रुपए मात्र.
9. श्रम विधि (लेबर लॉ)  
लेखक—गोपीकृष्ण अरोड़ा—मूल्य 24.20 रुपये.
10. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व (कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया सेलिक्ट फीचर्स)  
लेखक—डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी—मूल्य 36.50 रुपये.
11. मुस्लिम विधि (मुस्लिम लॉ)  
लेखक—प्रो. हफीजुल रहमान—मूल्य 16.50 रुपये.
12. साक्ष्य विधि (लॉ आफ एविडेन्स) (द्वितीय संस्करण)  
लेखक—आर. जी. त्रिवेदी—मूल्य 33.60 रुपये.
13. वंड प्रक्रिया संहिता  
लेखक—न्यायमूर्ति महावीर सिंह—मूल्य 46.50 रुपये.
14. अपकृत्य विधि के सिद्धांत (लॉ आफ टार्ट्स) (द्वितीय संस्करण)  
लेखक—शर्मन् लाल अग्रवाल (प्रेस में)
15. कम्पनी विधि  
लेखक—सुरेन्द्र नाथ (प्रेस में)
16. संविदा विधि  
लेखक—आर.जी. चतुर्वेदी (प्रेस में)

## (ख) मासिक विधि निर्णय पत्रिकाएं (हिंदी में लॉ रिपोर्ट्स)

1. उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका  
(सुप्रीम कोर्ट लॉ रिपोर्ट) प्रथम प्रकाशन अप्रैल, 1968; वार्षिक मूल्य ६५ रुपये, एक प्रति 6 रुपये.
2. उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (हाई कोर्ट लॉ रिपोर्ट)  
प्रथम प्रकाशन जनवरी 1969—वार्षिक मूल्य ७५ रुपये, एक प्रति 7 रुपये.  
एक साथ दोनों पत्रिकाओं का ग्राहक बनने पर संयुक्त वार्षिक चंदा 120 रुपये.



विधि छात्रों के लिए प्रमाण-पत्र देने पर विशेष रियायती मूल्य—दोनों पत्रिकाओं का 95 रुपये (अग्रिम संदाय) पिछले अंक उपलब्ध हैं।

### (ग) निर्णय सार (डाइजेस्ट)

1. उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका पंच-वर्षीय (1968-72) निर्णयसार  
मूल्य 14 रुपये (भाग 1 और 2)
2. उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका सप्तवर्षीय (1969-75) निर्णयसार  
मूल्य 24 रुपये (भाग 1 और 2)

### (घ) अन्य पुस्तकें :—

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (एलैक्शन मैनुएल)  
नवीनतम हिन्दी संस्करण; मूल्य 10.00
2. अनुपूरक (सप्लोमेंट) अक्टूबर, 1979 तक  
अध्यतन पृष्ठ सं. 85, मूल्य 3.75  
कुल मूल्य 13.75
3. विधि शब्दावली (लोगल ग्लासरी)  
नवीनतम संशोधित संस्करण (मुद्रणाधीन)

(ङ) केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण) सिविल प्रक्रिया संहिता—1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882, माल विक्रय अधिनियम 1930 सहित लगभग 150 पाठ उपलब्ध हैं।

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक

## विधि साहित्य प्रकाशन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
इंडियन लाॅ इन्स्टीट्यूट बिल्डिंग  
भगवान दास रोड (सुप्रीम कोर्ट के सामने)  
नई दिल्ली-110001.  
दूरभाष-389671.

ए की पी 596(9)/81.

## महोत्सवों के दुष्चक्र में फँसी फिल्में



निर्णायकमंडल के  
अध्यक्ष अमिनेत्री  
अशोक कुमार

29 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए शशि कपूर और श्याम बेनेगल जैसी बड़ी हस्तियों के कतार में होते हुए नये निर्देशक गौतम घोष को उन की बंगला फिल्म दखल के लिए स्वर्णकमल पुरस्कार की घोषणा कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित रही है। राजधानी के कुछ पत्रों ने जिस प्रकार गौतम घोष के लिए 'एक अज्ञात निर्देशक' शब्द का प्रयोग किया है उस से भी यह आश्चर्य एक सीमा तक प्रकट होता है। इस वर्ष निर्णायक मंडल में अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा के सम्मिलित होने की वजह से भी इस वर्ष किसी बड़ी हस्ती को, जो व्यावसायिक सिनेमा से संबंध रखती हो, पुरस्कृत किये जाने की संभावना ही अधिक व्यक्त की जा रही थी।

गौतम घोष की यह दूसरी फिल्म है। इस से पूर्व वह श्वेत श्याम में एक फिल्म और बना चुके हैं। निर्णायकमंडल के एक सदस्य के अनुसार वामपंथी विचारधारा से प्रभावित गौतम घोष की फिल्म दखल बंगला फिल्माकाश पर एक अन्य सत्यजित राय के उदय की संभावना व्यक्त करती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार दूसरा रजतकमल पुरस्कार भी मलयाली फिल्म पोक्कुवेइल के लिए निर्देशक एम. अरविंदम को दिया गया है।



सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अपर्णा सेन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेखा

हिन्दी फिल्म आधारशिला को निर्देशक की पहली फिल्म का प्रथम पुरस्कार दिये जाने के निर्णय की आलोचना भी कई क्षेत्रों में की जा रही है। आलोचना का आधार '36 चौरंगी लेन' फिल्म है। उम्मीद की जा रही थी कि स्वर्णकमल न सही निर्देशक की पहली फिल्म का पुरस्कार तो इस फिल्म को ही मिलेगा। अपर्णा सेन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। निर्णायकमंडल के अनुसार अपर्णा सेन के निर्देशन में 'अधिक परिपक्वता' थी। 36 चौरंगी लेन को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्मकारी के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। आधारशिला पुणे संस्थान से प्रशिक्षित अशोक आहूजा की पहली फिल्म है। फिल्म निर्देशक को केंद्र में रख कर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। स्वर्गीय गुरुदत्त की प्रसिद्ध फिल्म 'कागज के फूल' का विषय भी निर्देशक ही था। लेकिन आधारशिला के माध्यम से पहली बार एक नये फिल्म निर्देशक की समस्याओं को जानने का मौका मिल सकेगा। बंबई के व्यावसायिक सिनेमा के हस्तक्षेप का लाभ वस्तुतः अमिनेत्री रेखा को मिला है। ऐसा सुना गया है कि 36 चौरंगी लेन में जेनीफर कपूर और अंबारखा (मराठी) में स्मिता पाटिल के अभिनय पर



निर्णायक मंडल के मत समान रूप में विभाजित थे। लेकिन व्यावसायिक सिनेमा के मतों के कारण रेखा को उमराव जान में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए चुन लिया गया है। इस के अतिरिक्त उमराव जान को सर्वश्रेष्ठ कला और संगीत निर्देशन के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार आशा भोंसले को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओम पुरी को श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण में एक शोषित किसान की भूमिका के लिए दिया गया है।

तेलुगु फिल्म सत्यपदी को राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनय के लिए बाल कलाकार लेखिंदर सिंह (मणिपुरी फिल्म इमागीनिंगथम) को पुरस्कृत किया गया है। सत्यजित राय को दूरदर्शन फिल्म सद्गति के लिए निर्णायक का विशेष पुरस्कार दिया गया है। परिवार नियोजन और बाल फिल्मों का पुरस्कार किसी भी फिल्म को नहीं दिया गया। क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी पंजाबी और असमी भाषा में किसी भी फिल्म को पुरस्कार योग्य नहीं समझा गया।

क्षेत्रीय भाषाओं में जिन फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है उन की सूची यहाँ दी गयी है—हिंदी: आरोहण (नि. श्याम बेनेगल) बंगला: अदालत ओ एकटि मेये (नि. तपन सिन्हा), अंग्रेजी: 36 चौरंगी लेन (नि. अपर्णा सेन), कन्नड़: बारा (नि. एम. एस. सथू), मलयालम: एलीपशयम (नि. ए. गोपाल कृष्ण), मणिपुरी: इमागी निंगथम (नि. अरीवम श्याम शर्मा), मराठी: अंबारथा (नि. जब्बार पटेल), ओडिया: सीतारति (नि. मनमोहन महापात्र), तमिल: थनीर थनीर (नि. के. बालाचंदर), तेलुगु: सीता कोका चिलाका (नि. भारती राजा)।

राजधानी में आगामी 27 अप्रैल से प्रारंभ फिल्मोत्सव के अवसर पर पुरस्कार वितरण और पुरस्कृत फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा, लेकिन अच्छी फिल्मों में रुचि रखने वाले दर्शक को इस उत्सव के बाद पुरस्कृत फिल्में देखने का मौका शायद ही मिल पाता हो। पुरस्कृत फिल्मों के व्यावसायिक प्रदर्शन की समस्या बनी ही रहती है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यदि यह जरूरी समझता है कि जिन फिल्मों के निर्माण पर वह पैसा लगाता है, जिन्हें हर वर्ष पुरस्कार मिलते हैं, देश विदेश में जिन फिल्मों की चर्चा होती है वे फिल्में इस देश के दर्शक तक भी पहुँचें तो इन फिल्मों को महोत्सवों के दुश्चक्र से निकालना बहुत जरूरी है। उन के व्यावसायिक प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी फिल्म विकास निगम पर आ जाती है। इस दिशा में अभी तक जो भी प्रयत्न किये गये हैं वे निश्चय ही नाकाफी हैं। केवल बंबई में ही एक दो सिनेमाघरों का प्रबंध इन फिल्मों के प्रदर्शन के लिए किये जाने से ही तो यह समस्या हल नहीं हो जाती।

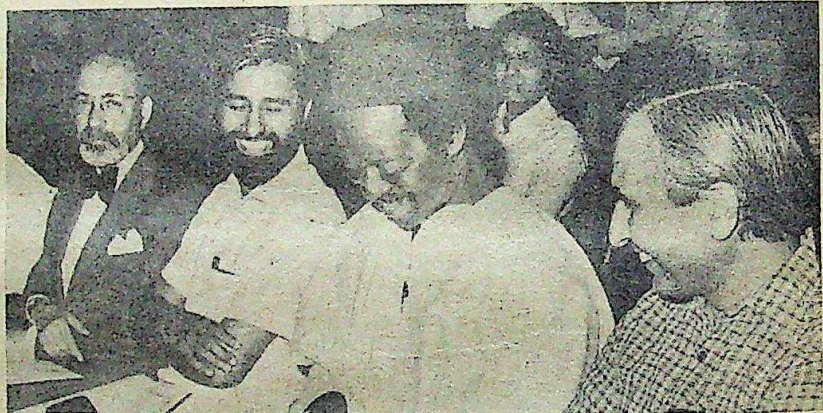
दिनमान

## कला

### त्रैवाषिकी समापन

## धूल भी कुछ कह रही थी

5 वीं त्रैवाषिकी के उद्घाटन की शाम कलाकार और कलाप्रेमी जितनी बड़ी संख्या में प्रगति मैदान (नयी दिल्ली) में उपस्थित हुए थे त्रैवाषिकी के समापन समारोह वाली शाम (7 अप्रैल) उपस्थित नहीं हुए। किसी हद तक तो यह शायद स्वामाविक भी था, क्योंकि उद्घाटन की शाम बाहर से भी बहुतेरे कलाकार आये थे। लेकिन कहीं यह भी दीख पड़ा कि त्रैवाषिकी अंत तक अपने आकर्षण को बनाये नहीं रख सकी। ललित कला अकादेमी के अध्यक्ष श्री हेब्बार के स्वागत भाषण के बाद जब पुरस्कार वितरण की वारी आयी (पुरस्कार वितरण सूचना एवं प्रसारणमंत्री वसंत साठे ने किया) तो त्रैवाषिकी में पुरस्कृत



समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में : (बायें से) जूनियान कसादो (स्पेन) ब्रह्मप्रकाश, ओनो ब्राकपेया बूस (नाइजीरिया) और वेद नायर

आठ कलाकारों और तीन अनुसंसित कलाकारों (दिनमान : 28 मार्च) में से केवल चार कलाकार पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित थे, जिन में दो तो भारत के ही थे: ब्रह्म प्रकाश (पुरस्कृत) और वेद नायर (अनुसंसित)। दो अन्य कलाकार थे जूनियान कसादो (स्पेन) और ओनो ब्राकपेया बूस (नाइजीरिया)। अन्य कलाकारों के पुरस्कार संबद्ध देशों के दूतावासों के अधिकारियों ने ही ग्रहण किये। समापन समारोह के बाद दिल्ली के ही कुछ कलाकार प्रदर्शनी स्थल की ओर बढ़े और प्रदर्शनी स्थल को सूना नहीं रहने दिया। फिर भी दर्शकों का अभाव तो खटक ही रहा था। इस की बात तो क्या ही करें कि वैसा कोई वातावरण नहीं था जो इतनी बड़ी प्रदर्शनी को फिर या अंतिम बार और देख लेने की ललक से बनता है।

यह तो शायद अच्छा ही था कि त्रैवाषिकी एक ही जगह लगी, लेकिन प्रगति मैदान का हॉल संख्या 7 कला प्रदर्शनियों के लिए बहुत उपयुक्त

तो नहीं लगता, क्यों कि उस की छतें ज्यादा ही ऊँची हैं। (और यह तथ्य तो गौरतलब है ही कि त्रैवाषिकी के बजट का एक बड़ा हिस्सा किराये के रूप में चला गया) त्रैवाषिकी का सब से अधिक लाभ दिल्ली और दूसरे शहरों के कला छात्रों और स्वयं कलाकारों और कला अध्यापकों ने ही उठाया, जो फिर भी इसे एकाधिक बार देखने आये। आम दर्शक इस की ओर आकृष्ट नहीं हुए। इस सवाल पर एक युवा कलाकार की दो टूक टिप्पणी थी: 'हम इसे एक बड़ी घटना बनाने से स्वयं चूक गये हैं। शहर में त्रैवाषिकी के पोस्टर ही कहाँ दीख रहे हैं। अन्य माध्यमों से भी इसे ठीक से विज्ञापित कहाँ किया गया है? अगर शहर की बात करें तो उसे इस की खबर ही कहाँ अच्छी तरह से मिली कि इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हो रही है?'

अंतिम दिनों में कुछ मूर्तिशिल्पों के ऊपर जम आयी धूल को कलाकार-दर्शक ही पोंछते

हुए दिखायी पड़े। (यह धूल कहीं इस के प्रति एक तरह की 'उदासीनता' का प्रतीक लगती थी)। उद्घाटन और समापन समारोह को छोड़ दें तो स्वयं प्रदर्शनी स्थल पर कला संबंधी अन्य आयोजन हुए ही नहीं।

चूँकि 81 के अंत में होने वाली यह प्रदर्शनी '82 में हुई, इस लिए अगली त्रैवाषिकी, जो 84 में होनी है, के लिए कुछ समय पहले ही गँवाया जा चुका है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि चौथी त्रैवाषिकी की तरह छठी त्रैवाषिकी के आयोजन के लिए अलग से एक सेल (विभाग) बनेगा (जो पाँचवीं के लिए नहीं था)। त्रैवाषिकी के आयोजन के महत्त्व को तो कला जगत में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह सवाल भी कलाकार ठीक ही उठाते हैं इस के माध्यम से आम दर्शक और कला जगत के बीच संवाद कहीं अधिक बढ़ना चाहिए। ऐसे संवाद या आदान-प्रदान के अभाव में यह जरूरी आयोजन अगर बिल्कुल निरर्थक नहीं तो फीका जरूर लगता है।





नरेंद्र कोहली (बोलते हुए) तथा नारायणदत्त, नारायण गणेश गोरे और गणेश मंत्री

## रामकथा : समता के लिए संघर्ष

लोहिया के 72वें जन्म दिवस 23 मार्च '82' को गोरेगांव (बंबई) में समता अध्ययन न्यास द्वारा 'रामकथा और समता के लिए संघर्ष' पर एक गोष्ठी आयोजित की गयी। आयोजकों ने इस अवसर पर रामकथा को आधार मान कर चार अलग उपन्यास लिखने वाले लेखक नरेंद्र कोहली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। गोष्ठी की अध्यक्षता राजनेता और मराठी लेखक नारायण गणेश गोरे ने की। दिलचस्प बात यह भी है कि नाना साहब गोरे 'रावणायण' भी लिख रहे हैं।

गणेश मंत्री द्वारा औपचारिक आभार-परिचय के पश्चात विषय प्रवर्तन के क्रम में नारायण दत्त ने रामकथा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यह प्रश्न उठाया कि क्या रामकथा में समता जैसी आधुनिक अवधारणाओं का कोई अस्तित्व है? अपने तर्क के पक्ष में अनेक उदाहरण रखते हुए श्रोताओं को, खास कर समता प्रेमी लोहियावादी श्रोताओं को उन्होंने विचलित कर दिया। उन की मान्यता थी कि 'रामकथा में वर्णित राम रावण युद्ध वास्तव में सुख और भोग की अंतिम सीमा तक जीवन को मानने वाले राक्षसों तथा शोषित एवं पिछड़ी जनजातियों के बीच समता के लिए लड़ी गयी लड़ाई थी'। इसी प्रसंग में उत्तरकांड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'रावण वध तक राम कथा एक दिशा में चल रही थी, किंतु बाद में उत्तरकांड में किन्हीं कारणों से चितन धारा दूसरी दिशा में बह चली है'।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राम या राम-कथा उत्तर कांड में ही विवादास्पद बनती है।

इस विवाद को नाना साहब गोरे उत्तर कांड के पूर्व से उठाते हैं। उन की दृष्टि में 'राम न उत्तर दक्षिण की एकता के प्रतीक थे, न ही राम रावण युद्ध आर्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति का युद्ध था। समता की अवधारणा उन की दृष्टि में उस काल में नहीं थी और इसी कारण पुरुष राम स्त्रियों और वानरों को समान नहीं मानते थे। लगभग 200 से अधिक श्रोताओं में डा. धर्मवीर भारती, मधु लिमए तथा अनेक पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन हुआ।

—ज. शा.

## टेपा सम्मेलन

हास्य व्यंग का बारहवां अ. भा. आयोजन पहली अप्रैल, मूर्ख दिवस पर उज्जैन में संपन्न हुआ। स्थानीय टेपों में संभागायुक्त शरद-चंद्र बहार, जिलाधीश अजीत रायजादा,

लाला अमरनाथ और मंजुश्री



पुलिस अधीक्षक हीरेंद्र प्रताप सिंह, नगर-निगम प्रशासक सरदार सिंह, फिल्म निर्माता सौभाग्यमल जैन, जैसी रमेश साबू, संपादक राजेश जैन को प्रशस्तियों उपाधियों और ट्राफियों से विभूषित किया गया। सिने तारिका मंजुश्री, माधुरी संपादक विनोद तिवारी मुरैना की कवयित्री इंदिरा इंदु, धर्मयुग के मनमोहन सरल इस में सम्मिलित थे। पद्मश्री गोपाल-प्रसाद व्यास को उन की हास्य व्यंग की सेवाओं के लिए रुपये 2500 का काशीराम स्मृति पुरस्कार दिया गया। पहली राज्यस्तरीय व्यंग रचना स्पर्धा का प्रथम पुरस्कार भोपाल के डा. ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया। हुडदंगी कवि सम्मेलन में सुश्री इंदिरा इंदु, सरोजनी प्रीतम, पद्मश्री गोपालप्रसाद व्यास, बालकवि वैरागी ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन किया डा. शिव शर्मा ने। —शि. श.

## दिल्ली नाट्य संघ

दिल्ली नाट्य संघ ने विश्व नाट्य दिवस के अवसर पर राजधानी में इस वर्ष छह नाट्य कर्मियों को सम्मानित किया। ये हैं—जे. एन. कौशल, परेशदास, इंदर राजदां, भगवानदास वर्मा, रघुवीर सिंह तथा रामदुलारे। सम्मान, सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे के द्वारा किया गया। जे. एन. कौशल ने जो नाट्य



वसंत साठे, कौशल को पुरस्कृत करते हुए

आलोचक, अनेक विश्वविख्यात पश्चिमी नाटकों के अनुवादक और निर्देशक हैं इस अवसर पर बादल सरकार के ख्यात नाटक सगोना महतो प्रस्तुत किया। नाटक की उन की परिकल्पना और निर्देशन सराहनीय था। दिल्ली नाट्य संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। दिल्ली की अनेक नाट्य संस्थाएँ इस से संबद्ध हैं। वर्तमान अध्यक्ष रेवतीशरण शर्मा की अध्यक्षता में यह संस्था नाट्य जगत की समस्याओं में सक्रिय रुचि लेती रही है लेकिन इसे और अधिक गतिशील बनाने की जरूरत है। —स.



## चरित चर्चा



## धनराज भगत

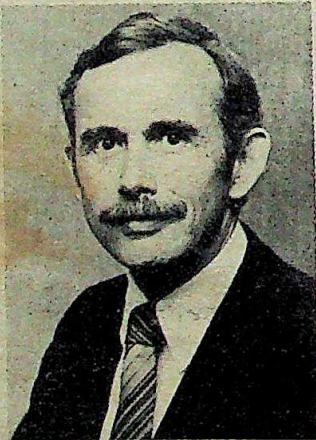
“चिड़ियां आती हैं तारों पर बैठती हैं, आंगन में फुदकती हैं—लगभग दिन भर बैठा बैठा उन्हें देखता रहता हूँ। मेने उन्हें कभी इतने निकट से नहीं देखा था। वे जैसे बाहर की दुनिया से भी मुझे जोड़े रहती हैं”। वरिष्ठ मूर्ति-शिली कला जगत में निविवाद रूप से सम्मानित, सब के प्रिय 65 वर्षीय धनराज भगत इन दिनों काफी अस्वस्थ रहते हैं। अब मूर्तिशिल्प नहीं बनाते लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सैकड़ों की संख्या में रेखांकन बनाये हैं जिन में से अधिकतर चिड़ियों को ले कर ही हैं—ये रेखांकन प्रायः एक या दो रंगों में हैं और अपने सहज, आत्मीय और अर्थमय अंकन में प्रभावित करने वाले हैं। इस बार की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जब उन्हें विशेष अतिथि कलाकार के रूप में आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कुछ बड़े आकार में चिड़ियों के रेखांकन ही भेजे। (चिड़ियों को ले कर बनाये गये उन के रेखांकन विभिन्न आकारों में हैं) भगत जी उन कलाकारों में से हैं जिन्हें काम किये बिना चैन नहीं मिलता। 6-7 वर्ष पहले तक कुछ अस्वस्थता के बावजूद वह मूर्तिशिल्प भी तराशते रहे हैं। लाहौर से अपने कला जीवन का आरंभ करने वाले भगत जी ने जीवन का एक बड़ा भाग दिल्ली में ही बिताया है और साउथ एक्स्टेंशन स्थित उन के घर में उन से मिलना और उन के चारों ओर छिपे रेखांकनों के बीच उन्हें देखना अपने में एक अनुभव है।

परिवारजन कहते हैं ‘बस कला-कार आ जायें तो फिर बातों और प्रसन्नता का इन के लिए (भगत जी के लिए) अंत नहीं’। —प्र.

## प्रो. राबर्ट एल हार्डग्रेव

‘मैं निजता के अधिकार का कायल हूँ, यह कहना है टैंक्सस विश्वविद्यालय, अमेरिका के प्रो. राबर्ट एल. हार्डग्रेव (जूनियर) का। प्रो. हार्डग्रेव नागरिक अधिकारों के विशेषज्ञ हैं और इस बारे में उन्होंने व्यापक अनुसंधान कार्य किया है। हाल में दिल्ली पत्रकार संघ के तत्वावधान में आयोजित एक गोष्ठी में उन्होंने कहा कि ‘प्रेस का लिखने और छापने अधिकार वस्तुतः जनता के जानने के अधिकार में निहित है। और इसी लिए प्रेस जनता के प्रति उत्तरदायी है’।

इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि ‘प्रेस को सूचना प्राप्त करने का अधिकार’ है लेकिन कानून



की दृष्टि में ‘विशेषाधिकार प्राप्त संवाददाता और साधारण नागरिक के बीच’ कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि प्रेस के ‘सूचना प्राप्त करने के अधिकार’ और आम आदमी के ‘निजता के अधिकार’ को ले कर द्वंद्व लगातार बढ़ रहा है। क्या राजनीतिकर्मी को भी निजता का अधिकार है? इस के उत्तर में उन्होंने कहा कि ‘आम आदमी और राजनीतिकर्मी के बीच अंतर करना एक मुश्किल काम है’।

प्रो. राबर्ट की दक्षिणेशिया, विशेषकर भारत की राजनीति में विशेष रुचि है। सामाजिक आंदोलनों और सार्वजनिक कानून का उन्होंने गहन अध्ययन किया है। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से 1966 में राजनीतिशास्त्र में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी। 1960-61 में वह नयी दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में भी अध्ययन कर चुके हैं। —म.

## बच्चू प्रसाद सिंह

शिक्षा शास्त्र !!!

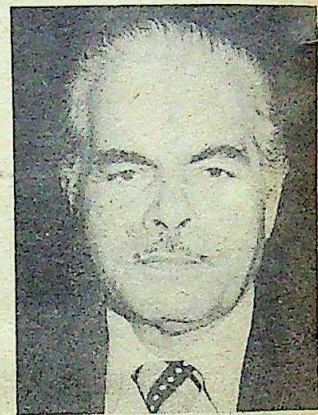
आशुन, आशुन और वह बंगला में शुरू हो गये। तभी एक अफसर आ गये। भोजपुरी में कहा: “रउवां एतना बड़वर खबर अवहिन ले छिपा के रख लीं?”—आप ने इतनी बड़ी खबर अभी तक छिपाये रखा?

बोले—“बबुआ, ई काम चना-चुरमुरा बेचले कै नाई ह नूँ। ई राजनय है। चुप्पी साधे पड़ेला”।

—(भई यह काम चना चुरमुरा बेचने का नहीं, राजनय का है। इस में चुप्पी साधनी पड़ती है) खबर थी उन के सूरी नाम में राजदूत नियुक्त किये जाने की। बंगाली मित्र के शिक्षा साजब—दफ्तर में बी. पी. सिन्हा, हिंदी भाषियों में बच्चू प्रसाद सिंह और दोस्तों में बच्चू बाबू हैं। दोस्तों का कहना है कि बच्चू बाबू को दोस्त बनाने का रोग है। वेमोसम सावन के महीने में पेट के रोगी अपने किसी दोस्त के लिए बोरा भर पका बढ़िया बेल जुटा कर अचरज पैदा कर सकते हैं। पहली दूसरी मुलाकात में परिचय का वर्षों पुराना अहसास करा कर मिलने वाले को पानी पानी कर सकते हैं। माहिर आयोजक हैं। पहले खुद साहित्य-कार थे अब साहित्य प्रेमी कहलाने में सुख अनुभव करते हैं। कुछ पुस्तकें लिखी हैं। कुछ का अनुवाद हुआ है। कुछ का किया भी है। स्वर्गीय दिनकर जी के जीवनकाल में उन के बहुत निकट थे। संस्मरणों का एक

मंडार है। कोई तार छू जाने पर बोलना शुरू करते हैं तो विराम देर से आता है। अक्सर कहते हैं, “अच्छा साहित्यकार होने के लिए अच्छा आदमी होना जरूरी है”।

जिंदगी पत्रकारिता से शुरू की थी। कुछ दिन कलकत्ता में अध्यापन भी किया। सरकारी सेवा में 1956 में आये। दिनकर जी केंद्रीय गृह मंत्रालय में हिंदी परामर्शदाता हो कर आये तो



उन्हें साथ काम करने का अवसर मिला। फिर प्रधानमंत्री सचिवालय से जुड़े। विदेश मंत्रालय में पिछले 15 वर्ष से हैं। इस वक्त विशेष अधिकारी के रूप में हिंदी और समन्वय के जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री से ले कर अन्य अनेक प्रतिनिधि मंडलों के साथ सारी दुनिया देख चुके हैं। देश विदेश के हिंदी विद्वानों से निकट से परिचित हैं। विदेश मंत्रालय में हिंदी के काम का पर्याप्त विस्तार कराया है। प्रथम और द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभायी थी।

बच्चू बाबू, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य पर बहुत अधिकार से बात करते हैं लेकिन सूरीनाम में भोजपुरी मूल के लोगों की संख्या काफी है। चूँकि बच्चू बाबू का भी मूल संबंध भोजपुरी क्षेत्र से ही है, अतः आशा की जानी चाहिए कि एक राजदूत के रूप में वह सूरीनाम के लोगों के बीच संवाद और संप्रेषण की स्थिति को बेहतर बनाने में अपने दोस्त बनाने वाले रोग का सर्वाधिक फायदा उठावेंगे। —रा.



सभी प्रकार की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय हिन्दी मासिक

## प्रगति मंजूषा

के

अप्रैल व मई 82 अंक

सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी परीक्षा

विशेषांक 1982

(सामान्य अध्ययन संबंधी विविध विषयों पर पंद्रह सौ से अधिक वस्तुपरक प्रश्नोत्तर)

प्राप्ति के लिए संपर्क करें—

निकटतम बुक स्टालों से अथवा

436, ममफोडगंज, इलाहाबाद

युवकों, छात्रों की अपनी पत्रिका हेतु आवश्यकता है, प्रत्येक डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय, शहर में प्रतिनिधियों की अनेक आकर्षक उपहार। नमूना हेतु रु. १-2५ का डाक टिकट भेजें। वार्षिक १५ रुपया। लिखें :-

**युवा यश्मि**  
हिन्दी मासिक

पोस्ट बॉक्स 7 महानगर

लखनऊ  
22 6006

ज्ञान विज्ञान  
का  
खजाना

**पराधा**

वच्चों की  
सम्पूर्ण मासिक पत्रिका

टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन

नेशनल की गौरवपूर्ण प्रस्तुति

**स्मृति-लेखा**  
'अज्ञेय'

स्मृति-लेखा को मात्र 'संस्मरण' नहीं कहा जा सकता। साहित्य के इतिहास में 'स्मृति' का यह एक विशिष्ट सर्जनात्मक इस्तेमाल है, जिसमें अज्ञेय जी के समकालीन कवियों लेखकों की स्मृतियों की लेखाएं हैं। ३०-०

अज्ञेय जी की अन्य कृतियाँ

○ आलवाल १५.००

○ अरे यायावर रहेगा याद १८.००

○ संवत्सर 2०.०.०



नेशनल  
पब्लिशिंग  
हाउस

२३, दरियागंज नयी दिल्ली-११०००२

यशस्वी उपन्यासकार  
गिरिराज किशोर का  
नया उपन्यास

**तीसरी  
सत्ता**

एक अविस्मरणीय उपन्यास जो जीवन सत्य की नयी संभावनाओं को उजागर करता है, और पाठक की चेतना को सक्रिय करते हुए एक बीहड़ चुनौती देता है।

४८.००

प्रत्येक धार्मिक परिवार के लिए आवश्यक

**अठारह पुराण**

बढ़िया कागज, मोटा टाइप, कपड़े की पक्की अठारह जिल्दों में सरल तथा शुद्ध हिन्दी पाठ। 30 अप्रैल 1982 तक पूरा सैट 12४०/- की बजाए 600/- अग्रिम भेजकर घर बैठे प्राप्त करें। डाकखर्च माफ

धर्मग्रन्थ प्रकाशन, कमलानगर, दिल्ली-110007

**खेलभारती**

खेल जगत की सबरंग पाक्षिकी

दो लाख से भी अधिक पाठकों की प्रिय पत्रिका जो देश विदेश के समस्त खेलों का विस्तृत विवरण देकर पाठकों का मन जीत रही है।

अनेक विज्ञापनदाता इन कालम में अपना संदेश देकर लाभ उठा रहे हैं।

एक पैनल का शुल्क केवल रु. 175.00

सम्पर्क करें : विज्ञापन प्रबन्धक

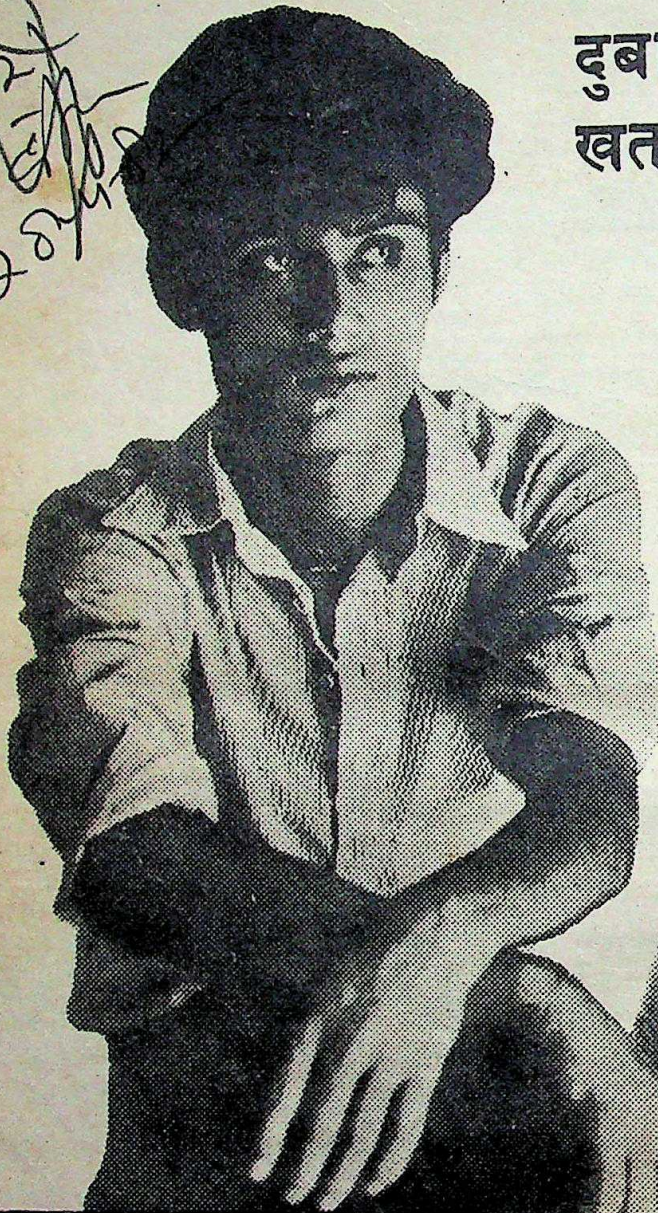
**खेलभारती** 7, बहादुरसाह जंकर मार्ग, नई दिल्ली-110002

नेशनल  
पब्लिशिंग  
हाउस

२३, दरियागंज  
नयी दिल्ली-११०००२



क्या आप अपनी पत्नी के  
दुबारा गर्भवती होने का  
खतरा मोल ले सकते हैं?



बिल्कुल नहीं, इसी में आपकी भलाई है



बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए, पहले चार वर्ष महत्वपूर्ण हैं।  
इसके लिए आवश्यकता है-देखभाल, प्यार, पोष्टिक भोजन और कपड़े इत्यादि की।  
इन सब के लिए चाहिए पैसा, जिसे जुटाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है।  
जब तक आप आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो जाते, अगले बच्चे के जन्म को रोक सकते हैं।

निरोध इस्तेमाल करें उच्च कोटि का भरोसेमन्द गर्भ निरोधक

वितरक : ब्रुक वांड, लिपटन, हिन्दुस्तान लीवर, आई. टी. सी., टाटा आयल मिल्स, यूनियन कार्बाइड, आई. डी. पी. एल., स्मिथ स्टेनस्ट्रीट,  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और अरमन माचिस उद्योग.



## दिनमान

टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन  
11-17 अप्रैल, 1982 • 21-27 चैत्र, 1903

‘मैं आप  
से कीड बैंक  
चाहता हूँ’

—सूचना और  
प्रसारण मंत्री

आकाशवाणी: बेचेदारी का रंग



‘विश्वसनीयता  
का सीमित अर्थ नहीं  
होना चाहिए’

—महानिदेशक, आकाशवाणी





क्या आप अपनी पत्नी के  
दुबारा गर्भवती होने का  
खतरा मोल ले सकते हैं?



बिल्कुल नहीं, इसी में आपकी भलाई है



बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए, पहले चार वर्ष महत्वपूर्ण हैं।  
इसके लिए आवश्यकता है-देखभाल, प्यार, पोष्टिक भोजन और कपड़े इत्यादि की।  
इन सब के लिए चाहिए पैसा, जिसे जुटाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है।  
जब तक आप आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो जाते, अगले बच्चे के जन्म  
को रोक सकते हैं।

**निरोध इस्तेमाल करें** उच्च कोटि का भरोसेमन्द गर्भ निरोधक

वितरक : शुक बांड, लिपटन, हिन्दुस्तान लीवर, आई. टी. सी., टाटा आयल मिल्स, यूनिन कार्बाइड, आई. डी. पी. एल., स्मिथ स्टेनस्ट्रीट,  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और अरसन माचिस उद्योग.



भाग 18 11-17 अप्रैल, 1982  
अंक 14 21-27 चैत्र, 1903

## इस सप्ताह

बेचेहरगी का रोना: आकाशवाणी;  
'मुझे आप से फीड बैंक चाहिए'—बसंत साठे,  
'विश्वसनीयता का सीमित अर्थ नहीं होना चाहिए'—  
कृष्णचंद्र शर्मा 7-9. दिल्ली के रंग 11. मनोरंजन 13. राज्य-सभा चुनाव के नतीजे 15. भारतीय उपग्रह: अंतरिक्ष मंच 16 आंध्रप्रदेश में अभिनेता ने नयी पार्टी क्यों बनायी 24. राजस्थान में कर्मचारी हड़ताल क्यों 25. बड़े शेर ने युद्ध की तैयारी की है: ब्रिटेन-अर्जेंटीना 29. बीएतनाम में जनरल गियाप का पतन 27. कैदखाना, मस्जिद या कब्रिस्तान: ईरान 28. मत और सम्मत 4. पिछले सप्ताह 5. पत्रकार संसद 6. उन का कहना है 11. चरखे और चरखे 12. दुनिया भर की 31. खेल और खिलाड़ी 32. पुरातत्त्व 34. नृत्य 35. कला 36. रंगमंच 37. साहित्य 39. फिल्म 40. संस्कृति समाचार 41. चरित चर्चा 42.



आवरण: आकाशवाणी: बेचेहरगी का रोना (पृ. 7-9)

### संपादक : कन्हैयालाल नंदन

संपादकीय सहकर्मी : जितेंद्र गुप्त (सहायक संपादक), सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (मुख्य उपसंपादक), इय्यामलाल शर्मा, जवाहरलाल कौल, शुक्ला रुद्र, त्रिलोक वीथ, महेश्वरदयाल गंगवार, प्रयाग शुक्ल, बनवारी, विनोद भारद्वाज और सुषमा पाराशर.

विशेष संपादकाता : रामसेवक श्रीवास्तव

सज्जा : रवि शर्मा

टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन

10, बरियागंज, नयी दिल्ली-110002

दिनमान

## पाठकों से

**आ**काशवाणी के केंद्र निदेशकों का जब 46वां सम्मेलन नयी दिल्ली में हुआ तो एक केंद्र निदेशक ने कहा: "होना हुवाना क्या है. इसी बहाने दिल्ली में मिश्रों से मिलने जुलने का बहाना मिल गया. चले आये." लेकिन इस चले आने से ज्यादा गहरी समस्याएँ इस बार के सम्मेलन में उभरीं. सब से बड़ा सवाल सरकारी नियंत्रण में होने के कारण आकाशवाणी की सर्वमान्य विश्वसनीयता का है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे कहते हैं कि प्रस्तुतीकरण 'संतुलित' होना चाहिए. यह संतुलन बनाकर चलना कितना मुश्किल है इस को जितना केंद्र-निदेशक जानते हैं और कोई नहीं जान सकता, जिन से मंत्री महोदय भी 'फीडबैक' चाहते हैं. 'दिनमान' ने इस समस्या को इस बार गहराई से जाँचने की कोशिश की. हिंदी के प्रख्यात पत्रकार श्री बालस्वरूप राही दिनमान के लिए आवरण-कथा प्रस्तुत करते हुए आकाशवाणी के महानिदेशक तक भी पहुँचे जिन्होंने 'विश्वसनीयता' के सवाल पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश की. लेकिन क्या इस से आकाशवाणी के 'बेचेहरा' होने का आरोप धुल सकेगा या उस का 'रोना' रक जायेगा? इस बार प्रस्तुत है आकाशवाणी से जुड़े कुछ ज्वलंत सवाल और इसी संदर्भ में अगले अंक में होगी भूतपूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से एक खुली बातचीत.

● लखनऊ सम्मेलन और उस में मेनका गांधी की उपस्थिति क्या इतनी स्वाभाविक, इतनी निश्छल थी जितनी कि मेनका गांधी या उन के समर्थकों द्वारा घोषित की गयी? यह सवाल उन लोगों के विभागों में कुलबुलाता रहा है जो इस प्रकरण के किसी भी पक्ष के साथ नहीं हैं. इस की छानबीन के लिए हमारे विभाग के एक वरिष्ठ सहयोगी जवाहर लाल कौल लखनऊ में उस समय भी राजनीति के हर रंग को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब अकबर अहमद सम्मेलन में मासूमियत के साथ मेनका की सहज उपस्थिति को रेखांकित कर रहे थे. लखनऊ से लौटने के बाद अब प्रस्तुत है उन की विशेष रपट और साथ में समूचे प्रकरण पर दिल्ली से एक तटस्थ विवेचन: 'दिल्ली अब मेनका गांधी की अगली चाल की प्रतीक्षा कर रही है.' आखिर उस के पीछे किस का विभाग काम कर रहा है और 'यह बगावत की हवा कितनी दूर जायेगी?' (पृष्ठ 17-18)

● पुरातत्त्व की चौकाने वाली एक गहरी समस्या पर भी इस बार हमने गहरी छानबीन की. पता चला कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के पास 1902 से लगाकर अब तक के करीब एक लाख 20 हजार फोटो निगेटिव हैं और वे पूरी तरह सुरक्षित रखे जा रहे हैं. तब फिर इस खबर के पीछे क्या आधार था कि 50 हजार फोटो निगेटिव राष्ट्रीय संग्रहालय के तलघर में और 50 हजार दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में रखरखाव की असावधानी से नष्ट हो गये हैं. प्रयाग शुक्ल ने अधिकारियों से मिलने के बाद उक्त स्थानों का निरीक्षण किया, जाँचा-परखा और जिस नतीजे पर पहुँचे वह भी इस अंक में आप के सामने है. (पृष्ठ 34)

● इसी के साथ प्रस्तुत है 'एक उत्तेजक और सार्थक अनुभव' नाट्य कलाकार विश्व विख्यात रंग निर्देशक पीटर ब्रुक के सानिध्य में मोपाल में संपन्न एक चार दिवसीय कार्यशाला का. 'कार्यशालाओं' के धिसेपिटे नुस्खों से अलग तरह के इस अनुभव को दिनमान के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं देश के प्रख्यात नाट्य समीक्षक श्री नेमिचंद्र जैन: 'इस का श्रेय पीटर ब्रुक की अपनी सूझबूझ और रंगकला से गहरे लगाव को ही दिया जाना चाहिए कि यह अत्यंत अल्पकालीन कार्यशाला भी अधिकांश सहभागियों और पर्यवेक्षकों के लिए इतनी सार्थक, उत्तेजक और अविस्मरणीय अनुभव बन गयी.' (पृष्ठ 37)

*Handwritten signature: दिनेश कुमार*



## छात्र क्या करे

14 मार्च : अंग्रेजी में लिखे पत्र पर 'जी आप ने कुछ कहा?' टिप्पणी ठीक है, पर अघूरी. लेखक ने देश में चल रही शिक्षा पर अंग्रेजियत के उस दबाव और उस की मानसिकता को छोड़ दिया है जिस के चलते इस रूआब की भाषा को कमोबेश रटना ही पड़ता है.—विजय मलिक, 204, डालमिया छात्रावास, का. हि. वि.वि., वाराणसी

**आ**ज भी मेधावी व ज्ञानपिपासु विद्यार्थियों को अच्छी, स्तरीय व विदेशी विद्वानों की पुस्तकों के अध्ययन के लिए अंग्रेजी में छपी पुस्तकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. न जानते हुए भी अंग्रेजी लिखना पढ़ना मजबूरी है —दिनेश, स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य, राजकीय, महा-विद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

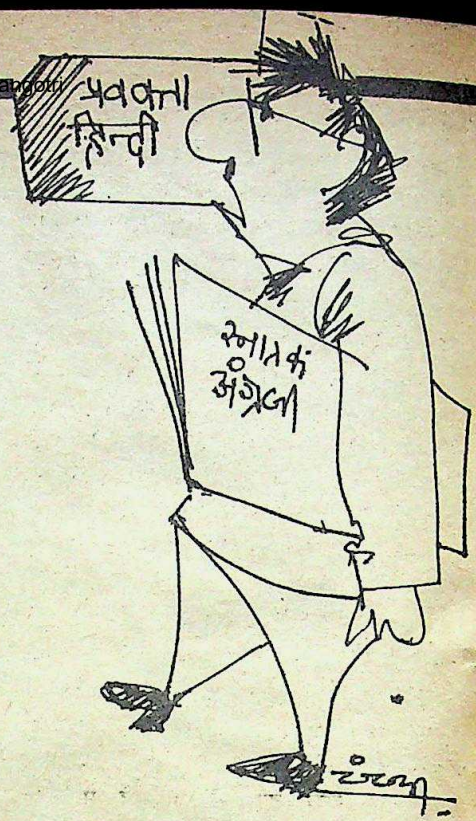
## प्रवक्ता हिंदी का, स्नातक अंग्रेजी में

14 मार्च : जयपुर विश्वविद्यालय के एक अनामधारी छात्र की अंग्रेजी भाषा में लिखी चिट्ठी और उस पर सत्यप्रिय मित्र की टिप्पणी छपी है.

काशी विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिंदी के प्रवक्ता के लिए हाल ही में एक विज्ञापन दिया है जिस के अनुसार उसे अंग्रेजी में स्नातक होना जरूरी है. इस से अधिक और क्या दुर्भाग्य होगा कि हिंदी के लिए अंग्रेजी जानना ही योग्यता है. —रामकृष्ण चौबे, अध्यक्ष छात्रसमा, अफलातून, छात्र युवा संघषवाहिनी काशी हि.वि.वि., 286, बिड़ला छात्रावास, का. हि.वि.वि.

## दिनमान का विज्ञापन अंग्रेजी में ?

मेरे ख्याल से तो उस विद्यार्थी ने अंग्रेजी में (यह और बात है कि वह बेचारा शुद्ध अंग्रेजी भी न लिख सका) पत्र लिख कर आप का



## एक पत्र उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम

प्रिय मुख्यमंत्री जी,

मैं अपनी बात अपने साथ घटी घटना से आरंभ करूँ. मैं अपने एक व्यवहारी के साथ 15 मार्च को इलाहाबाद से लखनऊ मुगलसराय पैसंजर से गया. भीड़ बहुत थी. यात्रा की भीड़ पर रोक करने के कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए जिस में यह प्रतिबंध होना चाहिए कि घर की निर्धारित संख्या में निर्धारित संख्या के व्यक्ति निर्धारित समय में यात्रा करें. इस नियम को तोड़ने पर बड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए. किराया बढ़ाने पर तो यह दुष्ट जनता यात्रा करने से मानती नहीं. यातायात सुविधा बढ़ाने से शासन को असुविधा ही असुविधा होगी. हाँ, ऐसे कार्यक्रम में पुलिस कर्मचारी की आय बढ़ेगी, उस की आमदनी बढ़ने से उस की कार्यकुशलता बढ़ेगी ही.

बहरहाल सारी गाड़ी का चक्कर काटने पर एक डिब्बे में उछोड़ सी देखी. चढ़ गये उस में. तो कुछ ही देर में क्या देखते हैं कि एक लड़का सा बिना वर्दी के सादा कपड़ों में एक लंबे डंडे के साथ बंदूकों के सिपाहियों के साथ उस डिब्बे में आया. उस ने हुक्म दिया कि वह डिब्बा खाली किया जाये. यात्रियों की प्रतिक्रिया मिश्र मिश्र थी ही. कुछ लोग मारे डर के मांग निकले. कुछ चिंतोरी करने लगे. कुछ निकलने की वजह पूछने लगे और कुछ न निकलने को मना करने लगे और कहने लगे कि सारा डिब्बा दो चार सिपाहियों के लिए खाली कराने की क्या तुक है. इस प्रकार कहने वालों के साथ ये सिपाही सख्ती करने लगे. मेरा व्यवहारी भी इस श्रेणी में आ गया था. सिपाही कान पकड़ और धक्का दे कर निकालने लगे और जब यह नौबत मेरे व्यवहारी के साथ आने लगी तो मैंने उसे समझाया कि कहीं मुठभेड़ की घोषणा न हो जाये और उस के साथ मैं भी न पिस जाऊँ. अतः मेरे कहने पर ही मेरे साथ निकल चले. यह बात उस की समझ में आ गयी और हम लोग निकल आये. बगल में सामान का डिब्बा था. उस में चले गये. यह बात दूसरी है कि और डिब्बों से यही डिब्बा सुविधाजनक देखा. फिर हम ने देखा कि उस डिब्बे में सिपाही रुपये ले ले कर यात्रियों को बिठा रहे हैं. इस प्रकार का आरक्षण मिश्र था. ऊपर सोने के

10/- नीचे बैठने के 5/- और नीचे फर्श पर बैठने के 2/- इस प्रकार 12 यात्री तो ऊपर सुलाये गये. 50 के करीब सीटों पर और करीब 30-40 नीचे फर्श पर. इस आरक्षण के पश्चात दो बंदूकधारी सिपाही उस में रह गये. बाद में हम को यह भी देखने को मिला कि उस डिब्बे पर खड़िया से जी. आर.पी. भी लिखा है.

हम ने उन सिपाहियों से यह कहा था कि हम लोग इस घटना की शिकायत करेंगे. अतः इस से वचनबद्ध हो कर यह शिकायत कर रहे हैं. घटना शिकायत करने पर अनेक प्रकार के विचार आये. कितना जोखिम उठा रहे हैं यह शिकायत कर के. इस घटना पर सिपाहियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होने की नहीं, उल्टे हम लोगों के ही नाम मुठभेड़ के रजिस्ट्रों में दर्ज न हो जायें. लेकिन अब तो हम राजा हरिश्चंद्र बन ही गये हैं. इस जोखिम को उठायेंगे ही. इस प्रक्रिया के बदलने की संभावना तो है नहीं. यही समझ कर हमारा मुझाव है कि इस प्रकार के आरक्षण के लिए सभी रेलगाड़ियों में सभी डिब्बों का आरक्षण पुलिस को सौंप दिया जाये. उस के लिए उन को उस आमदनी का ठेका दे दिया जाये. इस से अनेक लाभ होंगे. पहला तो यह होगा कि किराये के अलावा ठेकों से अरबों रुपये इकट्ठे होंगे. पुलिस की आमदनी बढ़ेगी. वह सरकार की अधिक वफादार होगी. दूसरे, इस आरक्षण के लिए हर डिब्बे में दो चार बंदूकधारी सिपाही रखने होंगे. डिब्बों में लूटपाट में कमी आयेगी. यह बात दूसरी है कि कभी कभी ये सिपाही भी लूटपाट कर लिया करेंगे. डरपोक और नादिहंद यात्री यात्रा करना छोड़ देंगे. बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हो जायेगा. मुठभेड़ भी हो जायेगी, उस से जनसंख्या कम होगी. इस व्यवस्था के लिए लागू होने पर मान सम्मान का प्रश्न भी समाप्त हो जायेगा. कितने लाभ गिनाये जायें, क्योंकि इस में लाभ ही लाभ है. मुठभेड़ का एक दूसरा फंट खुलने पर अपने एक अन्य प्रिय पुलिस अधिकारी को महानिरीक्षक बनाने का अवसर मिल सकेगा.

मन्वीय

प्रसाद

प्रयागदास, एडवोकेट, बुलबुलहर, (उ.प्र.)



अनुसरण ही किया है। प्रायः टाइम्स आफ इंडिया में दिनमान का विज्ञापन अंग्रेजी में होता है।  
—असलम नवाब, संजय सिंह, बलबीर सिंह, मुबोध पवार, धर्म चाहल, संडे बाजार बेरमो, गिरीडीह, बिहार

### पतन का लक्षण

अंग्रेजी में छपा पत्र न तो शर्म का विषय है न सोचने का ही। वरन् यह हमारे अधःपतन का लक्षण है। शहर से ले कर गाँव तक जब हर व्यक्ति अपने बच्चों से मम्मी, डैडी, कहलाने में मुख का अनुभव कर रहा है, तो इस प्रवृत्ति में सांस्कृतिक दोगलेपन का परिचय मिल जाता है। —प्रमोद मिश्र,

75, ममफोर्ड गंज, पुराना इलाहाबाद

### प्रोफिट-रिलीफ

मेरा एक दोस्त भी अंग्रेजी बोलने की आदत का शिकार है। हालांकि उसे अंग्रेजी बहुत कम आती है। एक बार मेरे पैर में घाव हो गया। शाम को मैं बरामदे में बैठा था कि वह आ कर पूछने लगा—घाव में कुछ प्रोफिट है। रिलीफ (आराम) की जगह प्रोफिट (लाभ) शब्द अधिकचरी जानकारी का ही परिणाम है। —भानुचंद्र, छोटी खगोल,

पत्रालय—खगोल, जिला पटना, बिहार

### झूठी शान है

एकमात्र छात्र के पत्र से पूरे जयपुर विश्व-विद्यालय का मूल्यांकन एवं तुलना किया जाना सर्वथा गलत एवं नियमों के परे है। हालांकि यह सत्य है कि कई छात्र झूठी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं—मारत जारौली, जारौली सदन, नीमच

आप फरमाते हैं

व्यंग्यचित्र : लक्ष्मण



‘शुक्र है कि मेरे पति के खिलाफ इस तरह के कोई आरोप नहीं हैं। उन पर तो केवल अप्रत्याचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।’

### आपने कैबरे नर्तकी को क्यों छापा

28 मार्च : ‘दिल्ली में कैबरे और कानून की टक्कर’ नामक लेख से इस महत्वपूर्ण पत्रिका के तीन पृष्ठ भर दिये गये। लेख सुंदर हो सकता है लेकिन पृ. 16 पर ‘पुलिस ने मुझे निर्वसन किया था’ शीर्षक के साथ गहरी लिपिस्टिक लगी कैबरे नर्तकी का फोटो छापने का क्या उद्देश्य है, नहीं समझ पाया। विश्वास है कि दिनमान सस्ती खूबसूरत तस्वीरों की पत्रिका नहीं बनेगी। —विपिनप्रताप गौतम, प्रबन्धक—राजशास्त्री विभाग, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलंदशहर, (उ.प्र.)

### कैबरे पर रोक क्यों

दिल्ली में कैबरे और कानून संबंधी लेख पढ़ा। यह लेख अपूर्ण एवं एकतरफा है। सामाजिक पहलू पर प्रश्नचिन्ह लगा कर छोड़ दिया गया। बात वही है चाहे वेश्यावृत्ति हो चाहे कैबरे और चाहे फिल्मों में अश्लीलता एवं नग्नता। जितना रोक लगायेंगे, उतना ही आकर्षण बढ़ेगा। —अरुण कुमार, 113, ए, रेलवे कालोनी, मिर्जापुर (उ.प्र.)

### कर्तव्यपरायण अधिकारी की हत्या

गोंडा (उ.प्र.) में पुलिस उप अधीक्षक और प्रतिभाशाली जनोन्मुख लेखक कृष्ण-प्रताप सिंह का 15 मार्च, 82 को गोली लगने से निधन हो गया। समाचारपत्रों में प्रकाशित विवरण के अनुसार वह डाकुओं से मुठभेड़ में मारे गये लेकिन उन की पत्नी के वक्तव्य के अनुसार, जो गोंडा में ही कोषाधिकारी हैं, यह षड्यंत्र गोंडा के कुछ पुलिसकर्मियों ने रचा था और इस साजिश को उच्चस्तरीय सरकारी एवं पुलिस संरक्षण प्राप्त था। श्री सिंह की ईमानदारी और कर्तव्य-परायणता वर्तमान पुलिस तंत्र के जन विरोधी स्वरूप के आड़े आती थी। कुछ दिन पहले जब लखनऊ के कुछ पत्रकार और साहित्यकार गोंडा एक कार्यक्रम में भाग लेने गये थे तो स्वर्गीय सिंह ने बताया था कि पुलिस व प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी मेरा विरोध कर रहे हैं और उन की शह पा कर मेरे अधीनस्थ भ्रष्ट पुलिस कमचारी मुझे अलग थलग कर देना चाहते हैं।

इस हत्याकांड तथा मुठभेड़ के नाम पर उत्तरप्रदेश में जारी तमाम जघन्य हत्याकांडों की निष्पक्ष जांच करायी जाये। दोषी पुलिस अधिकारियों व राजनीतिज्ञों को कठोर दंड दिया जाये। —राकेश,

शकील सिद्दीकी, वीरेंद्र यादव, मंगलेश डबराल, प्रवीणकुमार, सुभाष धुलिया, मोहन थपलियाल, अजयसिंह, अनिल सिन्हा, परमानंद पांडेय, कौशल किशोर, मो. मसूद, उ.प्र.

## पिछले सप्ताह

25-31 मार्च 1982

### देश

- 25 मार्च : संसद सदस्यों द्वारा नौसेना को सशक्त बनाने की लोकसभा में माँग। बंबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु। कुतुब मीनार की दुर्घटना के बारे में जाँच रपट सरकार को प्रस्तुत। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज ठप्प।
- 26 मार्च : संसद सदस्य खुशवंतसिंह द्वारा साहित्य अकादेमी में होने वाले घोटाले का राज्यसभा में पर्दाफाश।
- 27 मार्च : लंदन में भारत उत्सव में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली वापस। राज्यसभा के लिए कर्नाटक के सभी स्थानों पर कांग्रेस (इं) और पश्चिम बंगाल में वामपंथी उम्मीदवारों की जीत। प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ सम्मेलन पार्टी विरोधी करार। राजमंगल पांडे कांग्रेस (एस) से मुअत्तल।
- 28 मार्च : लखनऊ में श्रीमती मेनका गांधी द्वारा स्वर्गीय संजय गांधी के पाँच सूत्री कार्यक्रम की याद में आयोजित सम्मेलन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्मुख नहीं बताना। माहे नदी में एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 व्यक्तियों के डूबने की आशंका।
- 29 मार्च : श्रीमती मेनका गांधी का पुत्र वरुण के साथ प्रधानमंत्री निवास-स्थान का त्याग। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस (इं) द्वारा 47 स्थान प्राप्त। सी. राजेश्वरराव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पुनः निर्वाचित। नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने की घोषणा। रणजी ट्राफी के फाइनल में दिल्ली की विजय।
- 30 मार्च : श्रीमती मेनका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री निवासस्थान छोड़ने को पारिवारिक कारण करार देना। राजस्थान सरकार द्वारा 354 कर्मचारी गिरफ्तार।
- 31 मार्च : विदेशमंत्री पी.वी. नरसिंहराव द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल का परस्पर संबंधों पर वार्ता के लिए नयी दिल्ली के दौरे का एलान। बंगलूर में भारतीय वायुसेना द्वारा जागुआर की सफल परीक्षण उड़ान।



# पिछले सप्ताह

25-31 मार्च 1982

## विदेश

- 25 मार्च : ब्रितानी सरकार द्वारा भारतीय आर्थिक सहायता में कटौती की बहाली का निश्चय. बंगलादेश में जनजीवन सामान्य. अबामो लीग नेता हसीना शेख वाजेद घर में नजरबंद. फ्रांसीसी नगरपालिकाओं के चुनाव में द गॉलवादी दक्षिणपंथियों की जीत.
- 26 मार्च : बंगलादेश के भूतपूर्व मंत्रियों की खोज जारी. दक्षिण कोरिया द्वारा एकीकरण की वार्ता शुरू करने का उत्तर कोरिया से पुनः आग्रह. इराक द्वारा 16,000 ईरानियों को मारने का दावा.
- 27 मार्च : सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश अब्दुल मुहम्मद एहसानुद्दीन चौधरी द्वारा बंगलादेश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण. अखिल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के सेमि-फाइनल में भारत के प्रकाश पादुकोण चीन के लुआन जिन से पराजित. सूरीनाम में फौजी कानून समाप्त करने का निर्णय.
- 28 मार्च : ढाका के महापौर अबुल हसनत गिरफ्तार. अल साल्वाडोर के चुनाव में हिंसा के कारण 11 व्यक्तियों की मृत्यु.
- 29 मार्च : अल साल्वाडोर के चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त करने में विफल. अमेरिकी प्रशासन द्वारा दक्षिण अफ्रीका को अस्त्रशस्त्रों की बिक्री की पुष्टि.
- 30 मार्च : अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया की सफुल्ल वापसी. अल साल्वाडोर में मिलीजुली सरकार गठित करने के प्रयास जारी. इराक द्वारा युद्ध मोर्चे से अपने सैनिकों को हटाये जाने का आदेश. इस्राइल में व्यापक नागरिक प्रदर्शन. पेरिस में अल्जीरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिन विल्ला द्वारा स्वदेश वापसी की संभावना व्यक्त.
- 31 मार्च : वीएनएम के शक्तिशाली नेता जनरल न्गुयेन गियाप का सत्तारूढ़ पोलितब्यूरो से हटाया जाना. सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेज्नेव इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल. अल साल्वाडोर के दक्षिणपंथियों द्वारा 60 प्रतिशत मत प्राप्त कर सरकार बनाने का दावा.

## पत्रकार संसद

### लंदन के पत्रों में भारत महोत्सव का राजनैतिक रंग

लंदन के भारत महोत्सव के अवसर पर एक प्रमुख ब्रितानी समाचार पत्र ने नेहरू काल से लेकर अब तक की भारतीय राजनीति का विश्लेषण प्रकाशित किया तो एक और विख्यात ब्रितानी पत्र ने इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी का चरित चित्रण किया. लंदन महोत्सव मूलतः भारतीय कला और संस्कृति से ब्रितानी जनता को अवगत कराने का प्रयत्न है पर श्रीमती गांधी की इस महोत्सव में उपस्थिति से समाचारपत्रों का इसे राजनैतिक रंग देना स्वाभाविक ही था. टाइम्स लंदन ने अपना संपादकीय ही भारत की सन् '50 के दशक की राजनीति से शुरू किया. श्री नेहरू का स्मरण कराते हुए पत्र ने लिखा :—

“सन् 1950 के दशक में फ्रांसीसियों ने हालाँकि हिंद चीन के क्षेत्रों से हटना शुरू कर दिया था पर श्री नेहरू ने सही अर्थों में इसे कंबूजिया की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं माना था. उन का कहना था कि फ्रांसीसी पूरी तरह हिंद चीन से गये नहीं हैं. पीकिङ की अपनी यात्रा के दौरान वह कंबूजिया के ग्रामीण क्षेत्रों से हो कर गुजरे थे. तब उन्हें यह देख कर प्रसन्नता हुई कि कंबूजिया की प्राचीन संस्कृति में हिंदू संस्कृति की झलक साफ नजर आती है. किसी जमाने में यहाँ हिंदू संस्कृति छा गयी होगी. समय के साथ साथ इस के चिन्ह भी मिटते गये पर परंपराओं के रूप में बहुत कुछ रहा. श्री नेहरू ने इतिहास को जीवित पाया और श्री नेहरू ने दिल्ली आते ही स्वतंत्र कंबूजिया की सरकार को मान्यता दे दी.

संस्कृति राजनीति को प्रभावित करे ऐसी घटनाएँ कम ही होती हैं. उदाहरण के तौर पर 19वीं शताब्दी की जापानी कला और दस्तकारी से यूरोप को जापान में परिवर्तनों का आभास मिला. कोई साठ वर्ष पहले ब्रिटेन में चीनी चित्रकला की एक प्रदर्शनी से ब्रितानियों की क्रांति के बाद चीन के मूल परिवर्तनों की जानकारी मिली.

भावुकता संस्कृति से अधिक जुड़ी होती है. अभी पिछले वर्ष जापान की छोटी मोटी कला संस्थाओं द्वारा लंदन में एक जापानी कला और चित्र प्रदर्शनी से जापान के बारे में ब्रितानियों की उत्सुकता और जाग उठी. अब लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में दो प्रधानमंत्रियों—भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी और ब्रिटेन की श्रीमती टेंचर—की उपस्थिति में भारतीय संगीत कार्यक्रम से लंदन के भारत महोत्सव का उद्घाटन हो रहा है जो लगभग आठ महीने चलेगा. प्राचीन भारत की संगीत और मूर्तिकला से लेकर आज के भारत की झलक ब्रितानी और यूरोपीयों को इस समारोह में मिलेगी. भारत पर ब्रितानी शासन की झलक भी ब्रितानियों को इस में मिल जायेगी. ब्रितानियों में से आज आधे ऐसे हैं जिन्हें भारत पर ब्रितानी शासन की याद भी नहीं होगी पर जो ब्रितानी शासन से जुड़े भी होंगे उन्हें भी ऐसी झाँकी न मिली होगी जो इस भारत उत्सव में मिल रही है.

इस सांस्कृतिक समारोह की आवश्यकता थी क्यों कि एशिया का प्राचीन युग दो भागों में बँटा हुआ है एक चीन और दूसरा भारत. हम सब के लिए उसे जानना बहुत आवश्यक है. फिर अब तक भारत की परिभाषा और स्वरूप का ज्ञान हमें उन ब्रितानी शासकों के माध्यम से होता रहा है जिन का संपर्क भारत में सिर्फ अंग्रेजी दौ लोगों में रहता था. कला तो इन सब सीमाओं से परे होती है. संगीत, नाटक, कला, प्राचीन हो या वर्तमान हम से सीधे बात करती है. भारत उत्सव के जरिए भारत अपने को प्रस्तुत कर रहा है, इस की सराहना पूर्वाग्रहों से मुक्त रह कर होनी चाहिए.”

प्रमुख ब्रितानी पत्र आजर्बर ने महोत्सव के उद्घाटन से कुछ ही पहले एक विशेष लेख में कहा था—

“लंदन के भारत महोत्सव में ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती टेंचर और प्रिंस ऑफ वेल्स जैसी हस्तियाँ होंगी. पर प्रमुख आकर्षण तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ही हैं. श्रीमती गांधी एक करिश्मा हैं. अपने इसी करिश्मे के बल पर वह अपने देश पर शासन करती हैं. अपने देश के अपार जनसमूह को ऊँचे और विशाल मंच पर से जब वह संबोधित करती हैं तो देश के किसानों और मजदूरों के लिए ही उन के मुँह से सहानुभूति के शब्द निकलते हैं. महज उन्हें मरोसा दिलाने के लिए कि उन का भी कोई हमदर्द है. अपनी सहज मुस्कराहट और आँखों की चमक से वह अपनी बातचीत में लोगों का मन जीत लेती हैं. यह उन की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है कि अंदर की घनी पीड़ा उन के चेहरे पर नहीं झलकती. संजय गांधी की आकास्मिक मृत्यु की घटना इस का एक जीता जागता प्रमाण है. अपने राजनैतिक जीवन को बरकरार रखने के लिए उन्हें राजीव गांधी को राजनीति में लाने की आवश्यकता पड़ी तो वह उन्हें विमान संचालन छोड़ा कर राजनीति में ले आयीं. श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को अत्यंत कल्पनाशील और सपने संजोने वाली लड़की बताया था पर जब तक उन्हें अपने देशवासियों का विश्वास प्राप्त है तब तक उन्हें कहीं कोई खतरा नहीं है.”



# आकाशवाणी: बेचेहरणी का रोना

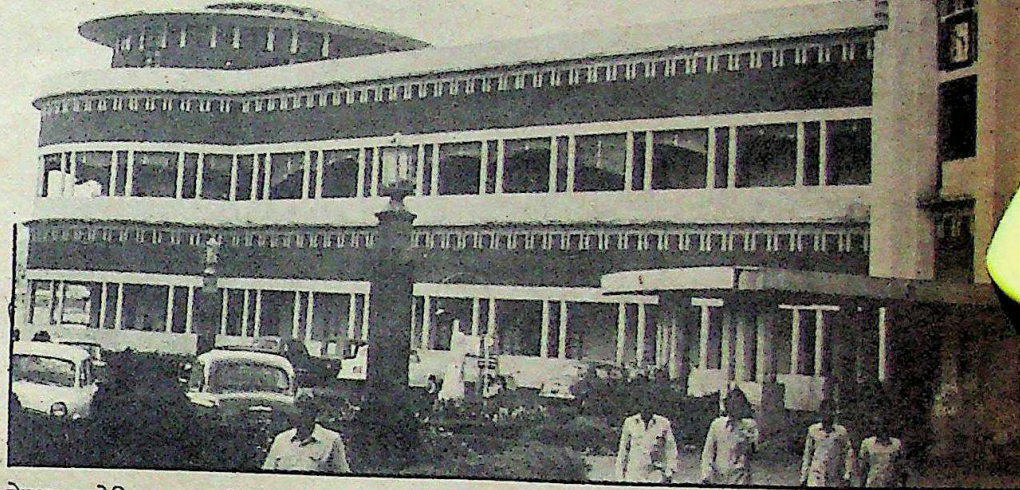
बालस्वरूप राही

**मार्च 19, 20, 21 :** विज्ञान भवन, नयी दिल्ली : हर बार की तरह वह वार्षिक अनुष्ठान फिर संपन्न हुआ जिसमें आकाशवाणी के 85 केंद्रों के केंद्र निदेशकों ने भाग लिया और काफी कुछ सुन कर, थोड़ा-बहुत कह कर अपने अपने स्टेशन की राह ली। फिर भी इस बारे में गनीमत यह थी कि यह सम्मेलन हमेशा की तरह औपचारिक होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषताएँ लिये था जिन्हें उपलब्धि नहीं तो कम से कम उल्लेखनीय तो कहा ही जा सकता है। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे अहम सवाल उठाये गये जो सैद्धांतिक मलेही हों, लेकिन कवचधारी अधिकारियों के कान खड़े करने की ताकत रखते हैं।

मिसाल के तौर पर अल्पसंख्यक आयोग के सचिव डॉ. गोपालसिंह ने आकाशवाणी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा — 'आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त भाषा आडंबर, बनावटी, पंडिताऊ और बर्बर होती है—हिंदी के समाचारों में भी, जो एक दिन हमारी राष्ट्रभाषा बनने वाली है... हिंदी फिल्मों का उदाहरण हमारे सामने है। अगर कोई फिल्म रेडियो की भाषा में बना दी जाये तो जिस दिन वह जारी हो उसी दिन उस का फ्लॉप हो जाना तय है।'

प्रश्न केवल भाषा का ही नहीं, उच्चारण का भी है। एक दौर वह था जब आकाशवाणी के उद्घोषकों और नाट्य-कलाकारों का उच्चारण कसौटी माना जाता था और श्रोता उसके अनुरूप अपने उच्चारण को सुधारते थे। एक दौर यह है, आकाशवाणी सुनिए और सिर घुनिए। आकाशवाणी को बालिंग हुए जमाना हुआ किंतु हाल ही के एक प्रसारण में एक उद्घोषिका बड़े आत्मविश्वास के साथ वयस्क का उच्चारण 'वयस्क' करती रहीं।

सम्मेलन में पढ़े गये अपने पर्व 'राष्ट्रीय अखंडता और रेडियो' में डॉ. गोपालसिंह ने एक बुनियादी सवाल और उठाया जो विषय-वस्तु को लेकर था। भारतीय मानसिकता पर प्रश्न-चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा—'हम अपने लगभग सारे तौर-तरीके पश्चिम से ले रहे हैं जहाँ स्वयं उथल-पुथल मची हुई है और जो आध्यात्मिक अथवा मानसिक आश्रय पा सकने में असमर्थ हो जाने के कारण टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। जो भी हमारी स्वस्थ सामाजिक रीतियों की, हमारे आध्यात्मिक और नैतिक लोकाचार की, हमारी राज्य-व्यवस्था और आर्थिक प्रगति की घजियाँ उड़ाता है, वही पश्चिम का और परिणामतः हमारा भी नायक बन जाता है। जो व्यक्ति



केवल उत्तेजित या उद्दीप्त करने, विवाद या भर्त्सना करने की आकांक्षा रखता है, वही हमारे लिए कला, साहित्य, दर्शन, जीवन-पद्धति आदि में आधुनिकता की मूर्ति बन जाता है। हत्या और सेक्स—ये दो प्रकट विषय हैं हमारे साहित्य के; नैराश्य और उथल-पुथलवाद कला के प्रमाण-चिह्न हैं। तिरस्कार और विरोध ध्यान खींचते हैं, अतः समाचार बन जाते हैं। यदि हम इन प्रकृतियों को प्रोत्साहन देते हैं, तो इसके साथ साथ अपने वातावरण और अपने भविष्य में मनुष्य की आस्था को बढ़ावा देने की आशा नहीं कर सकते।'

**सारगमित माड़ में, ऊटपटांग सिरसाथे:** आकाशवाणी हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक आध्यात्मिक, साहित्यिक गतिविधियों का आईना मानी जाती है। इस 'आईने' में कौन-से अक्स उतर पाते हैं और कौन से नहीं, इसे स्पष्ट करते हुए डॉ. गोपाल सिंह ने अपने अनुभव सुनाये—'नयी दिल्ली के एक सिख विद्यालय में मैंने सिख लड़कियों को खास मुस्लिम लिबास में इतने मँजे हुए अंदाज में कव्वाली गाते सुना कि मैं देख कर हक्का-बक्का रह गया। मुझे उम्मीद थी कि वह टी.वी. पर दिखाया जायेगा। पर नहीं दिखाया गया। पिछले साल हमने विज्ञान भवन में दुनिया भर से आये संतों की एक गोष्ठी आयोजित की। राष्ट्रीय अखंडता से संबद्ध कैसे कैसे सुंदर विचार रूपकों के द्वारा अभिव्यक्त किये गये कि सर्वाधिक वर्जनावादी तक प्रेरित हो उठें! रेडियो पर एक शब्द भी नहीं आये—दिन नयी दिल्ली या अन्यत्र भारत के अन्य भागों से पधारे विख्यात वक्ता विभिन्न मंचों से

बोलते रहते हैं। लेकिन उन के शोध निबंध कितने ही मौलिक और सारगमित क्यों न हों, रेडियो पर उन की कोई सुनवाई नहीं होती। मंत्रियों और राजनीतिक हस्तियों के उद्घाटन भाषण और ऊटपटांग वक्तव्य रेडियो पर छाये रहते हैं, मगर उन की कोई पूछ नहीं जो सुचितित समर्थ बोलते हैं और जिनके पास कहने के लिए कोई बात होती है।'

**बेहद जरूरी सवाल चर्चा नदारद :** यहीं वह बुनियादी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आकाशवाणी आखिर लोकवाणी कब बनेगी? कब उस का आम आदमी से सीधा रिश्ता जुड़ेगा और कब वह खास आदमियों की भड़ास से मुक्त होगी? आज हमारे देश के सामने वास्तविक समस्याएँ क्या हैं और उन के समाधान ढूँढ़ने या कम से कम उन के प्रति श्रोताओं को सचेत और जागरूक रखने में आकाशवाणी की भूमिका है? आज की ज्वलंत समस्याओं से आकाशवाणी की रिश्तेदारी का मुद्दा उठाते हुए अपने अभिभाषण में डॉ. गोपालसिंह ने कहा—'असमी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उत्तर-पूर्ववासियों या आदिवासियों के निजी पहचान खोने के भय को दूर करने के लिए हमने क्या किया है? पंजाब उद्वेलित क्यों है? क्या उन का कोई शिकवा ध्यान देने लायक नहीं है? राज्यों को अधिक स्वायत्तता का अभिप्राय क्या है? इस दिशा में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं—राष्ट्रीय एकता को दाँव पर लगाये बगैर? तमिषनाडु में चल रहे ब्राह्मण-अब्राह्मण विवाद का मूल क्या है? एक के बाद एक स्थानीय दल क्यों उभरते आ रहे हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हुए? क्या नदी-विवाद राजनैतिक स्तर





## ‘मैं आपसे ‘फ्रीड बैंक’ चाहता हूँ’

सूचना तथा प्रसारणमंत्री वसंत साठे

**वि**विध योजनाओं की पूर्ति में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन तक विकास-संदेश पहुँचाने ही होंगे और इस तरह हम पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों और उन की सफलताओं को तो उजागर करना ही है, कठिनाइयों और परेशानियों पर भी बल कम नहीं किया जाना चाहिए। लोगों की शिकायतें एक सकारात्मक तथा रचनात्मक ढंग से उजागर की जा सकती हैं। आप सरकार और जनता के बीच द्विमासी संप्रेषण मुहैया कर सकते हैं। मैं आप से ‘फ्रीड बैंक’ चाहता हूँ।

मैं आप से यह इच्छा नहीं रखता कि आप कुछ दवायें या किसी मुद्दे को कोई खास रंग दें। अगर आप सच्चाई से हटेंगे, तो विश्वसनीयता की क्षति होगी—आप भी विफलता की ओर संकेत करें कि एक रचनात्मक रूप में आवश्यकता तो बस एक संतुलित रूप में प्रस्तुतीकरण की है। आप को लोगों में विश्वास उत्पन्न करना है।

आप जो कुछ भी करें कल्पनापूर्वक करें। इस तरह की शिकायतें रही हैं कि आप के प्रसारणों में सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की मात्रा कम होती जा रही है। उदाहरणतः कुछ स्टेशनों पर संगीत 60 प्रतिशत से घट कर 40 प्रतिशत रह गया है और कुछ स्टेशनों पर तो 30 प्रतिशत तक पहुँच गया है। आप को यह जरूर याद रखना चाहिए कि देश के गरीब लोग मनोरंजन के मुख्य स्रोत के रूप में रेडियो का मुँह ताकते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय इस पक्ष को ध्यान में रखा जाये कि वे केवल सूचनाप्रद ही न हों, मनोरंजक भी हों।

कार्यक्रमों की तैयारी लचकीली और अनायास हीनी ही चाहिए ताकि स्थानीय स्टेशन स्थानीय समुदाय की वाणी के रूप में काम करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। केंद्र निदेशक सम्मेलन-82 के उद्घाटन भाषण के अंश।

पर हल किए जाने के बजाय निष्पक्ष व्यापक मध्यस्थता द्वारा सुलटाये नहीं जा सकते? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मिलावट से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इतने असहाय हैं?”

इसे आकाशवाणी केंद्र निदेशकों के 46वें सम्मेलन की सार्थकता माना जाना चाहिए कि स्वयं आकाशवाणी के मंच से वे प्रश्न उठाये गये जो लोगों के दिलों-दिमाग में हैं। और गाढ़े-बगाढ़े पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उठाये जाते रहे हैं। यों एक और दिलचस्प पहलू यह है इस स्थिति का कि अधिकतर पत्र-पत्रिकाओं में आकाशवाणी और दूर-दर्शन के बारे में वे ही लोग लिखते हैं जो इन संस्थाओं में उच्च पदों पर रह चुके हैं। इस से भी अधिक रोचक तथ्य की ओर संकेत किया दूरदर्शन के मृतपूर्व अतिरिक्त महानिदेशक और संप्रति ‘इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन’ के निदेशक एन.एल. चावला ने। उन के पेपर-का विषय था ‘रेडियो के समक्ष सामाजिक चुनौतियाँ’। चावला साहब ने रेडियो और राजनीतियों के पारस्परिक संबंध को इन शब्दों में उद्घाटित किया—“मैं यह कहने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा कि संसद में प्रसारण पर बहस तभी गर्म होती है जब चर्चा किसी बहाने मीडिया पर सरकारी नियंत्रण या उस में सरकारी दखल के विषय पर आ जाये। ज्यादातर दखल-अंदाजी और नियंत्रण की बात संसद में भी उससे बाहर दिये गये भाषणों के समाचार बुलेटिनों में उल्लेख से जुड़ी होती है और सरकार (जो भी सत्ताह्व होता) पर आरोप यह होता है कि सरकार विरोध पक्ष के नेताओं के विचार और वक्तव्य दबा देती है।” यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे जनप्रतिनिधि आकाशवाणी के ‘लोकवाणी’ रूप की कल्पना किस रूप में करते हैं। आकाशवाणी की ‘विश्वसनीयता’ से उन का अभिप्राय क्या है?

**समाज की कीमत पर राजनीति :** चावला साहब ने स्पष्ट किया कि उन्हें एतराज इस बात पर नहीं है कि आकाशवाणी के प्रसारणों में राजनीतिक चर्चाओं और समाचारों को खास दर्जा और महत्त्व दिया जाता है; उन्हें खेद है तो इस बात का कि ‘यह (राजनीति-चर्चा) अन्य समस्याओं पर विचार-विनिमय की कीमत पर किया जाता है, खास तौर से व्यापक संदर्भों से जुड़ी उन समस्याओं की कीमत पर जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने हैं। उन मसलों को नजरंदाज करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिन से आम आदमी का रोजमर्रा का बड़ा नजदीकी ताल्लुक है और जो भारतीय समाज से, उस के समग्र रूप में जुड़े हैं। ऐसे राष्ट्रीय हित भी अवहेलित हो रहे हैं जो राष्ट्र को एकजुट बनाये हुए हैं।’

आकाशवाणी के विस्तार को व्यक्त करने के लिए यह दावा बार बार किया जाता रहा है

## विश्वसनीयता का सीमित अर्थ नहीं होना चाहिए

आकाशवाणी के महानिदेशक कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु से बालस्वरूप राही की बातचीत

बहुत से केंद्र निदेशक न स्थानीय संस्कृति से परिचित होते हैं, न भाषा से। ऐसे अधिकारी कार्यक्रमों के बारे में क्या निर्देश दे सकते हैं ?

**महानिदेशक :** आकाशवाणी की नौकरी अखिल भारतीय सेवा है। अतः कौन कहां काम करेगा, इस का निर्णय क्षेत्रीय आधार पर नहीं किया जाता। भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान तो अर्जित किया जाता है। केंद्र निदेशक से पहली अपेक्षा तो यही की जाती है कि वह अपने क्षेत्र की भाषा और वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करे। सर्वेक्षण होते ही रहते हैं।

अपनी ही बात कहें। मुझे नगालैंड भेजा गया तो मैंने वहां की समस्याओं और संस्कृति का सावधानी और रुचि के साथ अध्ययन किया। नवागत व्यक्ति स्थानीय परिस्थितियों और परिवेश में स्थानीय व्यक्ति से कुछ अधिक ही रुचि लेता है, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति तो उन का अभ्यस्त हो चुका होता है और उस की उत्सुकता निश्चेष हो जाती है। मैंने श्रोताओं की जीवन परिस्थितियों का अध्ययन किया तो पाया कि वहां तपेदिक बहुत आम है—संक्रामक होने की सीमा तक। इस का सब से बड़ा कारण तो यही है कि वहां के लोग इसे एक कलंक मानते हैं, इसे छिपाते हैं और ठीक से इलाज नहीं कराते। मैंने एक अभियान इस रोग और इस मनोवृत्ति के विरुद्ध छेड़ा। आकाशवाणी के माध्यम से उन का मनोबल बनाने और आत्मविश्वास जाग्रत करने का प्रयास किया। आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तपेदिक सिर्फ एक बीमारी है, किसी पाप का फल नहीं है। यह बीमारी असाध्य नहीं है, किंतु संक्रामक अवश्य है। पाप है इस का इलाज न करा कर इसे अपने आस-

कृष्णचंद्र शर्मा : ‘विकास की खबरें’





इस मुहिम का असर पड़ा और इस बीमारी को ले कर उन की निराशा भावना में कमी आयी और उन में स्वास्थ्य कामना जाग्रत हुई.

दूसरी बात यह है कि निदेशक भले ही बाहर के हों, प्रोड्यूसर तो स्थानीय भाषा भाषी ही होते हैं. आरम्भिक रूपरेखा तो क्षेत्रीय प्रोड्यूसर ही तैयार करते हैं, निदेशक तो केवल नेतृत्व प्रदान करता है. कृषि कार्यक्रमों की रूपरेखा कृषि विशेषज्ञ, जो एम. एस.सी. होता है, ही तैयार करता है. प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की भर्ती भी आवश्यकता के अनुरूप ही की जाती है. जिस प्रोग्राम के लिए आदमी की जरूरत होती है, उसी विषय का आदमी लिया जाता है.

सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बाहर से आया निदेशक स्थानीय प्रभावों से मुक्त होता है, उस के निहित स्वार्थ नहीं होते. इसलिए वह और भी पक्षपातहीन तथा कारगर तरीके से काम कर सकता है. फिर एक क्षेत्र का अनुभव दूसरे क्षेत्र में भी काम तो आता ही है. कूप-मंडूक हो कर तो कार्यक्रमों की समृद्धि में योगदान किया नहीं जा सकता.

मोडिया की बात चलने पर विश्वसनीयता का प्रश्न उठना अनिवार्य है. क्या आकाशवाणी को निष्पक्ष माना जा सकता है? बुलेटिनों के लिए समाचार का चुनाव किस नजरिए से किया जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि समाचारपत्रों के प्रथम पृष्ठ पर स्थान पाने वाले कई समाचार रेडियो समाचार बुलेटिनों से जायब हो जाते हैं?

विश्वसनीयता का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण होता नहीं जितना बना दिया जाता है. विरोधी दल वालों को खास शिकायत होती है, हालांकि उन के खास समाचार समाचार बुलेटिनों में पूरी तरह शामिल किये जाते हैं. ले दे कर 15 मिनट की तो बुलेटिन होती है. सभी समाचार तो उस में समा नहीं सकते.

'डैवलपमेंटल न्यूज' जिसे कहते हैं, वह समाचारपत्रों में प्रायः देखने को नहीं मिलती. जनमाध्यम के रूप में आकाशवाणी का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने बुलेटिनों में इस तरह के समाचारों का समावेश करे जिन से नागरिकों का आत्मसम्मान जागे और उन्हें अपने राष्ट्र पर अभिमान हो. राष्ट्र की प्रगति समुचित ज्ञान उन में आत्मविश्वास की भावना को बल देता है. देश में होने वाले रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा कर आकाशवाणी अपनी यथार्थ भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकती है?

विश्वसनीयता का संबंध सरकार की बालोचना से जोड़ा जाता है. क्या बालोचना ही विश्वसनीयता का आधार है. आकाशवाणी में सरकार की बालोचना के लिए भी गुंजाइश है. 'करेंट एफेयर्स', 'चर्चा' का विषय है जैसे कार्यक्रमों में विरोधी विचार भी श्रोताओं के सामने रखे

जाते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व की विविधता पर जोर दिया जाता है.

रेडियो की भूमिका न सत्तापक्ष की है न विरोधी पक्ष की. रेडियो तो समाजोत्थान का उपकरण है. हमारे कई फीचर ऐसे होते हैं जो कटु यथार्थ को सामने लाते हैं. उनके माध्यम से आम आदमी अपना रोष भी प्रकट करता है. हमारे रूपक विभाग ने एक रूपक पेश किया था—'भारतमाता ग्रामवासिनी'. श्री रमानाथ अवस्थी द्वारा पेश किये गये इस रूपक में गांवों की वास्तविक परिस्थितियों का निष्पक्ष निरूपण था, जैसा भी वहाँ के लोग महसूस करते हैं. जिन अभावों को वे सहते हैं, उन्हें बगैर लाम लपेट के पेश किया गया.

मेरी दृष्टि में विश्वसनीयता का सीमित अर्थ नहीं लेना चाहिए. यदि आकाशवाणी की विश्वसनीयता न होती तो भारत में हरित क्रांति लाने में वह अपना महत्वपूर्ण योग कैसे दे पाती? 'फार्म स्कूल ऑफ द एयर' के माध्यम से किसानों को जो प्रशिक्षण दिये गये उन के ठोस नतीजे सामने आये. बेहतर उपकरणों और उर्वरकों की जानकारी और प्रयोग से बेहतर फसलें हासिल की जा सकीं. यदि आकाशवाणी की बात मान कर लोग अपने तौर तरीके बदलने को तैयार हो जाते हैं तो क्या इसे आकाशवाणी की विश्वसनीयता नहीं मानना चाहिए.

हाँ, यह और बात है कि जो किसी विचार धारा विशेष से जुड़ा है, वह तो आकाशवाणी के प्रति संदिग्ध बना ही रहेगा इस का तो कोई इलाज है ही नहीं. आकाशवाणी की एक नियमावली है. उस का एक नियम है कि किसी भी पार्टी की बालोचना उस का नाम ले कर ब्राडकास्ट नहीं की जायेगी. इस नियम का पालन तत्परता के साथ किया जाता है.

एक मिसाल दूँ. एक राज्य में सत्तादल की सरकार थी. उसी दल के एक मुख्यमंत्री ने एक पार्टी की उस का नाम लेकर बालोचना की. उसे नहीं जाने दिया गया.

क्या आप वह प्रसारित करने में विश्वास करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, या वह जो आप उन्हें सुनाना चाहते हैं?

लोग अपराध क्वाएँ सुनना चाहते हैं, तो क्या हम अपराध क्वाएँ प्रसारित करने लगे? लेकिन इस का मतलब यह तो नहीं है कि हम लोगों से कुछ छिपाते हैं. क्या हम यह कहते हैं कि रेलों की दुर्घटना कभी नहीं होती?

समस्या यह है कि त्याग, उत्सर्ग, उपलब्धि और उन्नति की यशोवाचाओं में लोग उतनी रुचि नहीं लेते, जितनी कलंक कथाओं में. गौरव वाचाओं पर लोग यकीन करे न करें. निंदा कथाओं पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं. यह भी एक पक्ष है विश्वसनीयता का. यह मानव स्वभाव है, क्या कीजिए इस का.

हम समाचार का चुनाव उसके महत्व के आधार पर करते हैं. जो समाचार राष्ट्रीय महत्व का होता है, उसे लेते हैं. अगर बालोचना ही विश्वसनीयता का आधार है, तो बात दूसरी है.

साहित्य और संगीत के विशेषज्ञ आकाशवाणी छोड़ कर क्यों चले गये? आकाशवाणी में विशेषज्ञों की घटती तादाद का सबब क्या है?

विशेषज्ञता से आप का अभिप्राय क्या है? रेडियो की विशेषज्ञता साहित्य आदि की विशेषज्ञता से भिन्न होती है. रेडियो विशेषज्ञ के रूप में नाम लिया जा सकता है. एस. एस. एस. ठाकुर का. उन की विशेषज्ञता रेडियो से ही उपजी थी. बड़े साहित्यकारों के पास वैचारिक संपदा होती है, प्रभावकारी अभिव्यक्ति होती है, उन का लाम आकाशवाणी को मिलता तो है किन्तु उन्हें रेडियो विशेषज्ञ तो नहीं कहा जा सकता! पंत जी ने काव्य रूपक लिखे. वह महाकवि थे, उन के रूपकों की अपनी जगह है और महत्ता है. किन्तु क्या उन के पहले काव्य रूपक नहीं लिखे गये?

जब तक आप थोता से सोचें मुचातिब नहीं होते और औपचारिक बने रहते हैं तब तक आप कैसे उसे अपने से जोड़ सकेंगे? आप के कार्यक्रमों का चरित्र और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं की छवि और पहचान कैसे बनेगी?

अनौपचारिकता और औपचारिकता का संबंध कार्यक्रम के स्वरूप और प्रस्तुति से है. जैसे बच्चों के कार्यक्रमों में या कृषि कार्यक्रमों में. वार्ता में अनौपचारिकता कहाँ से जायेगी? इसी तरह किसी बी. आई. पी. से इंटरव्यू भी औपचारिक ही होगा. हाँ, जहाँ दो समान स्तरों के व्यक्ति 'इन डिस्कशन विद' जैसे कार्यक्रमों में आपस में बातचीत करते हैं, कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेता, वहाँ पूरी बेतकलुफी मौजूद रहती है. वहाँ तक प्रस्तुतकर्ता की अपनी छवि या पहचान बनने का सवाल है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता निजी तौर पर शामिल रहता है, वहाँ उस की भी अपनी लोकप्रियता और छवि बनती है. मिसाल के तौर पर लोहार्सिंह और रमई काका के प्रोग्राम लिये जा सकते हैं लेकिन जो प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम के पीछे रहते हैं, जैसे नाट्य प्रस्तुतकर्ता वगैरह, उन के आकाशवाणी स्टार बनने की गुंजाइश नहीं है? लेकिन जो लोग कार्यक्रमों में स्वयं भाग लेते रहे हैं उन की निजी छवि भी बनी है. जिन की बालाब लोग रेडियो पर सुनते हैं उन्हें पहचानते भी हैं. देवकीनंदन पांडेय इस का उदाहरण है.

सभी विदेशी कार्यक्रम भी अनौपचारिक नहीं होते. आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी प्रस्तुतीकरण की प्रकृति के अनुसार अनौपचारिकताका जगान नहीं है.



कि वह भारत की 90 प्रतिशत आबादी तक पहुँचती है। इस संदर्भ में एन.एल. चावला ने एक उपेक्षित पक्ष की ओर भी संकेत किया—“सवाल यह है कि हम गाँव अथवा दूरदराज के इलाकों में आखिरी आदमी तक पहुँचते हैं कि नहीं? अगर 68 करोड़ आबादी वाले देश में 3 करोड़ रेडियो सेट हों भी, तब भी औसतन 25 व्यक्तियों के हिस्से में एक सेट आता है। लेकिन हालत उतनी अच्छी है नहीं, जितनी दिखाई पड़ती है; क्योंकि अधिकतर सेट शहरी इलाकों और कुछ क्षेत्रों तथा राज्यों में केंद्रीकृत हैं। ओडीसा, म.प्र. और बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ लगभग 100 व्यक्तियों के बीच एक ही रेडियो सेट है।”

**नैतिक जिम्मेदारी:** आकाशवाणी की सामाजिक भूमिका के संदर्भ में चावला साहब ने उद्बोधन किया—“प्रसारण-व्यवस्था की यह एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वह संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति लोगों में जाग्रति का संचार करे। केवल कर्तव्यों की दुहाई देते रहने से प्रसारण माध्यम प्रभावकारी नहीं बनते। प्रसारण माध्यम को सामाजिक अन्यायकर्त्ताओं को झटका देना होगा। लोगों के जमीनों को झकझोरना होगा।” किंतु क्या ऐसा करते समय प्रभुता प्राप्त वर्गों की दखल-अंदाजी और जोर-जबर्दस्ती से बचा जा सकता है? चावला साहब का जवाब हाँ में है और अपनी बात सिद्ध करने के लिए उन्होंने जम्मू-श्रीनगर रेडियो केंद्र के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘जूना डब’ का हवाला दिया, जो भारत-पाक संघर्ष के उपरांत 1965 में शुरू हुआ था और आज तक प्रसारित होता चला आ रहा है। उस कार्यक्रम की खूबी बताते हुए चावला साहब ने कहा, “किसी भी सामाजिक-समस्या को विचार-विनिमय से परे नहीं रखा गया। चाहे वह सरकारी प्रणाली या प्रशासन की किसी शाखा पर चोट ही क्यों न करती हो।”

**लगाव या अलगाव:** बात उठती है आकाशवाणी को लोकवाणी बनाने की, लेकिन यह खूबसूरत मकसद सिर्फ बार बार दुहराया जाने वाला नारा बन कर क्यों रह गया है? सारे कार्यक्रम घरे के घरे रह जाते हैं और सारा भारत बदस्तूर विविध भारतीय कार्यक्रम सुने जा रहा है? यहाँ तक कि यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या रेडियो सीलोन की लोक-प्रियता से आतंकित हो विविध भारतीय शुरू कर आकाशवाणी ने अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी नहीं मारी है? आकाशवाणी में जन-मागीदारी का नारा भी वैसा ही असहाय और घिसा-पिटा हो कर रह गया है, जैसे भारतीय राजनीति में समाजवाद का नारा।

सूझबूझ और दूरदर्शिता की बात अगर छोड़ भी दी जाये, तब भी कार्यक्रम निर्माताओं के लिए दो चीजें तो सब से जरूरी हैं ही—कार्यक्रम के प्रति ईमानदारी और लगाव। मगर स्थिति यह है कि आकाशवाणी रेल की पटरियों

की तरह हो कर रह गयी है जिस पर कार्यक्रम ढकेल दिये जाते हैं। सब से बड़ी कमी है व्यावसायिक रवैये की। लोग बी.बी.सी. क्यों सुनते हैं? बी.बी.सी. तो फ़िल्मी गीत नहीं बजाता। वह कौन-सी जरूरत है जो भारतीय श्रोताओं को बी.बी.सी. सुनने पर बाध्य करती है? बी.बी.सी. की कामयाबी के लिए जिम्मेदार है व्यावसायिकों का संयुक्त प्रयास—टीम वर्क। बी.बी.सी. के कार्यक्रम में गुणात्मकता को तरजीह दी जाती है। यहाँ के प्रस्तुतकर्त्ता परिमाण और ऊपर से प्राप्त छुने हुए आदेशों की पूर्ति कर संतुष्ट हो जाने के लिए बाध्य हैं। वे कार्यक्रमों का ‘सृजन’ नहीं, ‘उत्पादन’ कर पा रहे हैं। वे ‘रचनाकार’ से ज्यादा ‘प्रोड्यूसर’ हैं और अपने पद को चरितार्थ कर रहे हैं। दूसरी ओर आदेशकर्त्ताओं को आकाशवाणी की कार्य-पद्धति का व्यावहारिक और सम्यक् ज्ञान नहीं है। कुछ यथार्थ आवश्यकताएँ हैं आकाशवाणी की—जैसे बेहतर मशीनों की जरूरत। क्या केंद्र निदेशकों के इस सम्मेलन में बेहतर मशीनों और पिटी-पिटार्ड मशीनों की बदली की समस्या का प्रश्न किसी ने उठाया? अगर नहीं, तो क्यों?

स्टाफ आर्टिस्टों-प्रोड्यूसर वगैरह, और नियमित कर्मचारियों के अधिकारियों के बीच संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि धीरे धीरे साहित्य, नाटक, संगीत के विशेषज्ञों की जमात आकाशवाणी में समाप्त होती जा रही है। दूसरी ओर नियमित कर्मचारी के सिर पर तबादले की तलवार टँगी रहती है। पदोन्नति एक साथ वरदान और शाप बन कर आती है। पदोन्नति का अर्थ होता है स्थानांतरण। इस वजह से नियमित केंद्र वाले विशेषज्ञता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। वे एक स्टेशन की परिस्थितियों, स्थानीय कलाकारों, वात्ताकारों आदि, श्रोताओं, संभावनाओं-सीमाओं को समझ कर लगन के साथ कार्यक्रमों की बेहतरी के लिए सक्रिय होते ही हैं कि उन के तबादले के आदेश आ जाते हैं और उन्हें फिर अजनबी लोगों और हालात में नये सिरे से काम शुरू करना पड़ता है। विशेषज्ञता हासिल करने का मौका ही नहीं मिलता। विशेषज्ञता को बनाये रखने के लिए अधिकारीगण क्या सोच रहे हैं? क्या कभी इस मसले पर किसी ने गौर किया है कि आने वाले 5 सालों में कितने प्रोड्यूसर रह जायेंगे और कार्यक्रम-अधिकारी

### अगले अंक में



म. पू. सूचना  
और प्रसारण मंत्री  
लालकृष्ण आडवाणी  
से दिनमान की  
बातचीत

कितने स्थानापन्न हो सकेंगे? साथ ही रेडियो माध्यम के विशेषज्ञ—संगीत, नाटक, साहित्य से संबद्ध तैयार करने की दिशा में काम किया जाना बेहद जरूरी है। क्या इस दिशा में परिचर्चा में कोई विचार-विनिमय हुआ?

**न पुरस्कार न तिरस्कार:** रेडियो कर्मचारी यह भी महसूस करते हैं कि पुरस्कार और तिरस्कार अवश्यभावी होने चाहिए। रेडियो में ज्यादातर लोग खिड़कियों और रोशनदानों से ही भीतर घुसे हैं, दरवाजों से तो बहुत कम लोग अंदर आये हैं। इस का नतीजा यह है कि लोगों की गदियाँ बनी हुई हैं। कई ऐसे हैं जो दिल्ली में रहेंगे ही रहेंगे: चाहे वे काम करें या न करें। और कुछ लोगों की नियति यह है कि या तो वे अपने वर्तमान पदों पर सड़ते रहें या भूले-भटके तरक्की हो भी जाये तो शहर-बंदर कर दिये जायें। एक लगातार भटकन और मशीनी सक्रियता के सिवा आकाशवाणी में कुछ भी नहीं। हर आदमी जैसे अजनबी होता जा रहा है आकाशवाणी में, खोता जा रहा है अपनापन, अपनी पहचान। एक उच्च अधिकारी के अल्फाज में “आकाशवाणी ‘बेचेहरा’ का रोना” है।” एक शेर याद आता है के. के. नैयर साहब का जो उन्होंने जाने किस संदर्भ में कहा होगा, पर जो इस संदर्भ में बड़ा ही मौजू है: भीड़-सी बेचेहरा लोगों की लगी है दूर तक, वो भी होंगे इनमें जो मिलते थे अक्सर, देखना!

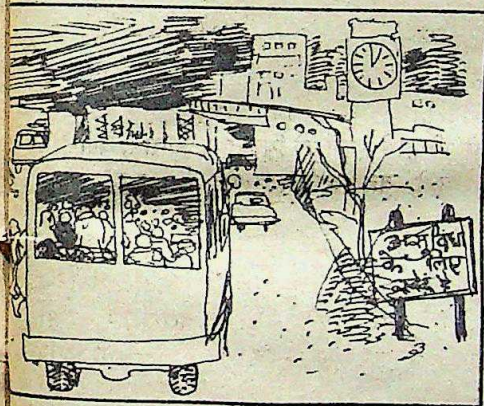
यही वह आकाशवाणी है, जहाँ कभी सआदत हुसन मंटो, किशन चंदर, राजेंद्रसिंह बेदी, उपेंद्रनाथ अशक और दूसरी ओर सुमित्रानंदन पंत, उदयशंकर मट्ट, इलाचंद जोशी, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवतीचरण वर्मा आदि के उत्फुल्ल स्वर गूँजा करते थे और आज जहाँ नाउम्मीदी का सन्नाटा छाया रहता है। आकाशवाणी के लोग अतीत जीवी हो गये हैं क्योंकि न उन का वर्तमान है न भविष्य। नौजवान लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि पहले आकाशवाणी की बात ही और थी। सारी अनौपचारिकता औपचारिकता में बदल चुकी है। सब कुछ तैशुदा है, बँधा-बँधायी है। रोज़दारी के सिवा कुछ भी नहीं। बी.बी.सी. सुनिए, आप को लगेगा जैसे कोई दोस्त आप से मुखातिब है। मगर क्या कभी आप ने आकाशवाणी के कार्यक्रम में बेतकल्लुफ़ दोस्ताना गुप्तगू का लुप्त पाया है? रेडियो सुनते समय क्या हम यह मूल जाते हैं कि यह आवाज़ एक यंत्र में से आ रही है, जिस का नाम है रेडियो? स्थानीय समस्याओं और स्थानीय आम आदमी से सीधा रिश्ता कायम किये बगैर क्या आकाशवाणी समाज में अपनी सही जगह हासिल कर सकती है? क्या आकाशवाणी की सार्थकता इस में नहीं है कि वह लोकवाणी बने? लोगों का भरोसा प्राप्त किये बिना वह अपनी सही भूमिका कैसे अदा कर सकती है?

उम्मीद है कि केंद्र निदेशकों के अगले सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी विचार होगा।



## मौसम बदल रहा है

कालीदास जीवित होते और सौभाग्यवश दिल्ली के नागरिक होते तो उन्हें नया ऋतु संहार रचना पड़ता. न तो दिल्ली का मौसम और न यहाँ की सड़कें ही आजकल किसी प्रकार का अनुबंध स्वीकार करने को तैयार हैं. शीतकाल में वर्षा पधारी तो जाने का नाम ही न लिया. जिस दिन मौसम पंडितों ने कहा, 'आज मौसम साफ रहेगा'. उसी दिन घटा छाया, बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा हुई. यह समाचार मिला कि हिमाचल की पहाड़ियों और कश्मीर की घाटियों में बर्फ गिरी. मार्च का अंत होने को आया मगर गरमी का नाम नहीं था और ठिठुरन को विराम नहीं. मगर अब मौसम बदल रहा है भौतिक भी तथा सामाजिक और राजनैतिक भी. लगता है कि बंद डबियों से अब माचिस की तीलियाँ निकलने लगी हैं और कुछ चमकीली और कुछ मड़कीली चिनगारियाँ अब फूटेंगी राजधानी में.



## असुविधा के लिए खेद है

घुप निकली तो राजधानी में जगह जगह पर दो प्रकार के चेतावनी चिन्ह साफ दिखाई देने लगे. एक 'सावधान, आदमी काम कर रहे हैं' और दूसरा 'असुविधा के लिए खेद है'. ये खबरदारी के वाक्य आप को मक्समूलर मार्ग, लोधी मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग वगैरह दिल्ली की सभी सड़कों पर टंगे दिखायी देते हैं. कहीं लाल, कहीं नीले और कहीं काले अक्षरों में. कारण यह कि हर जगह सड़कों की खुदाई हो रही है. कहीं मरम्मत का काम चल रहा है तो कहीं नाले, पाइप और बिजली, टेलीफोन या डाक वालों के तार बिछाये जा रहे हैं. मजे की बात यह है कि कई स्थानों पर तो महीनों से खुदाई, ठुकाई और पुताई हो रही है. सरकार और ठेकेदार उसी मद चाल से सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगे हैं, जैसे 50 वर्ष या सौ वर्ष पूर्व. वही इक चाल बेइंगी जो पहले थी सो अब भी है. काश! यह सिलसिला बदले. निर्माण कार्य से असुविधा कम और

## उन का कहना है

हम ने डांगेवाद के भूत को वाराणसी कांग्रेस में दफना दिया है.—एक वरिष्ठ भाकपा नेता राज्य प्रणाली वही होगी, जो जनता तय करेगी.—बांग्लादेश में सैनिक सत्ता परिवर्तन के बाद जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद.

25 वर्ष के आदमी को बेहोशी की हालत में देखना एक कष्टनाजनक स्थिति है. अगले बुधस्वतिवार को ई.ई.सी. (यूरोपीय इकनॉमिक कम्युनिटी) की 25 वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है, उस पर एक दृष्टि निस्तब्धता छाई हुई होगी.—ई.ई.सी. पर इकामॉमिस्ट की टिप्पणी.

क्या कर्नाटक का मुख्यमंत्री मेरे चाचा का बेटा है?—वलराम जाखड़, अटलबिहारी वाजपेयी के इस आरोप के जवाब में कि वह सीमेंट स्केंडल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं. विरोधी दलों ने आरोप लगाया है कि असम में घोड़ों का व्यापार (हास ट्रेड) हो रहा है. मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधायकों की तुलना घोड़ों से करना अच्छी बात है?—लोकसभा में गृहमंत्री जैलसिंह

हमारे देश में ऐसा कोई मतदाता नहीं है जिस के पास मतदाता सूची में संशोधन की अर्जी देने के लिए 10 पैसे न हों या वह 10 पैसे का इंतजाम न कर सकता हो. (इंका के) कुछ वकीलों की यह शिकायत काल्पनिक है और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है.—पश्चिम बंगाल चुनाव के सिलसिले में इंका की याचिका रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ.

अगर प्रधानमंत्री की निगाह में संजय गांधी का पांच सूत्री कार्यक्रम सचमुच अच्छा था जिस पर कि संजय गांधी को इतना गौरव मंडित किया जाता रहा तो फिर उन्हें नाराज होने या तल्ल होने के बजाय लखनऊ सम्मेलन का न सिर्फ स्वागत करना चाहिए था बल्कि उसे अपना आशीर्वाद भी देना चाहिए था.—पत्रकार सम्मेलन में अटलबिहारी वाजपेयी.

मुझे कुछ नहीं कहना है. यह टेलीफोन टैप किया जाता है. इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकती. अगर बात करना चाहते हैं तो बाहर कहीं संपर्क करें.—प्रधानमंत्री भवन से मेनका गांधी. मेनका गांधी की मदद के बिना इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में न पहुँच पातीं.—राजनायक लखनऊ में

अकबर अहमद का यह कथन कि उस ने संजय गांधी के कहने पर काफी मात्रा में हाजी मस्तान से चंदा वसूला था, संजय गांधी के प्रति गद्दारी है.—उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह. राजीव गांधी की उम्र काफी हो चुकी है. वह 39 साल के हैं जब कि देश को जवान नेता की जरूरत है; मेनका गांधी जैसे किसी नेता की.—संजय गांधी विचार मंच के अध्यक्ष टी. एस. बेदी का वक्तव्य.

मैं हमेशा अपनी सास से पूछ कर ही कोई काम करती हूँ. मेरे मन में उन के प्रति निष्ठा के अलावा कभी कोई बात नहीं आती.—30 मार्च 1982 को दिल्ली में मेनका गांधी.

विडंबना यह है कि फ्रांसीसी स्त्री की समस्या बिल्कुल दूसरी है : वह है उस की सफलता. फ्रांस में बहुत कम ऐसे कानून रह गये हैं, जिन्हें नारी मुक्ति आंदोलन बदलने की माँग कर सकता है. उन के कुछ नेता अपने आप को बड़ी उलझन में पाते हैं क्योंकि सरकार वही बातें करती नजर आती है जिन की माँग आंदोलन के नेता कर सकते हैं.—फ्रांस की नारी मुक्ति आंदोलन समर्थक पत्रकार मार्टिन स्टोटी.

सुविधा अधिक होनी चाहिए. कोई उन्हें समझाये, जिधर जाओ अब आँखों में धूल पड़ती है. ठेकेदारों द्वारा लापरवाही से फेंकी कीलें लोगों के पाँवों में चुभती हैं और नर, नारी, बूढ़े, शिशु सभी घायल होते हैं जिस मित्र ने दिल्ली का चित्र यों खींचा है 'धूलमरी नगरी, शूल भरी सड़कें' कुछ ठीक ही खींचा है.

## बसों में शिष्टाचार

दिल्ली परिवहन की बसों में दुर्व्यवहार कोई नयी बात नहीं मगर शिष्टाचार जरूर नयी बात है. दिल्ली परिवहन ने अब एक

शिष्टाचार और सद्व्यवहार आंदोलन अपनी बसों में आरंभ किया है. कुछ नमूने जो नीले अक्षरों में बसों के भीतर अंकित किये गये हैं. 'जो मनुष्य मुस्कान से दे सकता है वह मुष्ठी प्रहार से नहीं.'

'फुटबोर्ड पर यात्रा करना मृत्यु की सीढ़ी है. 54 व्यक्ति इसी प्रकार मौत का शिकार हो चुके हैं. क्या आपके घर में कोई आप की प्रतीक्षा नहीं कर रहा?'

और मिनी बसों वाले भी पीछे क्यों रहने लगे. कुछ उन की परिवहन रचनाएँ पेश हैं जो यात्री प्रतिदिन बसों में लिखी पढ़ते हैं. 'देखो मगर प्यार की नजरों से'



‘आना, तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले खुशियाँ मना रहे हैं गाड़ी चलाने वाले’ और एक बस के इंजिन की बोनट पर लिखा है, ‘मुझ पर पाँव मत रखिए, मेरा मिजाज बहुत गरम है.’

### भगतसिंह की डायरी

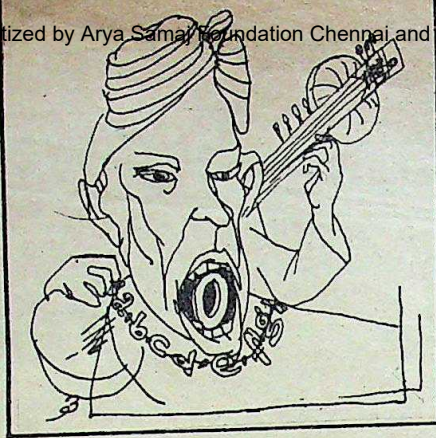
‘शहीदे आजम भगतसिंह न केवल महान, क्रांतिकारी ही थे, पत्रकार और लेखक भी थे’। ऐसा हाल में ही प्रकाशित भगतसिंह के विषय में कुछ अभी तक अप्रकाशित तथ्यों के एक संग्रह के लेखक श्री के.के. खुल्लर का कहना है। संग्रह का विमोचन दिल्ली में 23 मार्च को भगतसिंह की पुण्यतिथि पर हुआ। खुल्लर साहेब का कहना है कि उन्होंने अपने अनुसंधान और पुराने दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भगतसिंह एक अच्छे लेखक और पत्रकार भी थे। जहाँ वह हिंदी के दैनिक ‘वीर अर्जुन’ और उर्दू के दैनिक ‘प्रताप’ के प्रतिनिधि रहे वहाँ उन्होंने अपना एक पत्र ‘कीर्ति’ भी निकाला था। पहले पंजाबी में और फिर उर्दू में—अमृतसर से। वह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में तो अच्छा लिखते ही थे, बंगला भी मली मांति जानते थे। आसफअली ने भगतसिंह का मुकद्मा लड़ा था। उन के अनुसार अपनी सफाई में अंग्रेजी का प्रसिद्ध वयान जो अंग्रेज की अदालत में पेश हुआ वह भगतसिंह ने स्वयं लिखा था। वह केवल उत्तरी भारत में ही नहीं देश भर में अपने जीवनकाल में ही महान क्रांतिकारी नेता माने जाते थे। उन को फाँसी होने के तुरंत बाद हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलूर, कराची और मद्रास जैसे नगरों में भी उन के अनयायियों ने विरोध समारोह किये। उन की जीवनियाँ मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगू और सिंधी में छपीं।

खुल्लर साहेब का कहना है कि साहित्य में भगतसिंह की बड़ी रुचि थी और फाँसी लगने से एक ही दिन पहले उन्होंने एक मॅट करने वाले से एक पुस्तक के विषय में कहा था : ‘मैंने इस पुस्तक की समीक्षा हाल ही में ‘दिव्यन’ में पढ़ी है। कृपया मुझे वह पुस्तक ला दें। मैं पढ़ना चाहता हूँ.’

भगतसिंह अपनी एक डायरी भी लिखा करते थे जिस के पन्ने बाद में बिखर गये और नष्ट हो गये। खुल्लर साहेब का खोज से यह जान पड़ता है कि हो सकता है कि उन में से कुछ पन्ने कहीं न कहीं किसी न किसी के पास सुरक्षित हों।

### आखिरी बात

दिल्ली के एक महानुभाव किसी कारण थाने से पिट कर घर लौटे तो उन्होंने फरमाया ‘अनंत मृत्यु यही है कि इस देश में सरकार किसी की भी हो राज सदा थानेदार का चलेगा। मैंने जनता सरकार में भी यही भुगता और अब भी यही भुगत रहा हूँ.’



## चरचे और चरखे

### अंग्रेजी में तारीफ

संगीत नाटक अकादेमी के पुरस्कारों की पुस्तिका सामने है—सुदर्शन पुस्तिका लेकिन अंग्रेजी में। पुरस्कार वितरण समारोह के दिन इसी पुस्तिका से अंग्रेजी में प्रशस्ति पाठ सुन कर अचरज हुआ। हर बार यही होता है। अंग्रेजी में प्रशस्ति पाठ किस के लिए? क्योंकि पुरस्कृत कलाकारों में से आधे तो ऐसे थे ही, हमेशा होते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते। क्या देश की संस्कृति की भाषा अंग्रेजी है? साहित्य अकादेमी अपना प्रशस्ति पाठ हिंदी में करती है और उस की अंग्रेजी प्रतियाँ वितरित कर दी जाती हैं उन लोगों के लिए जो शायद हिंदी न जानते हों। भाषा को ले कर अगर कोई झगड़ा होता तो साहित्य अकादेमी में होता? फिर वहाँ सभी पुरस्कृत लेखक अंग्रेजी जानते भी हैं। लेकिन संगीत नाटक अकादेमी जो देश के कोने कोने से क्षेत्रीय सांस्कृतिक कलाकारों को खोज कर लाती है, जो क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, उन का प्रशस्ति पाठ अंग्रेजी में करती है! क्या अकादेमी का ख्याल है इस से पुरस्कार की गरिमा बढ़ती है—पुरस्कार पाने वाला सोचता है ‘देखो, देखो अंग्रेजी में हमारी तारीफ की जा रही है?’ इस स्तंभकार का खयाल है कि देश की संस्कृति की पोषक, उन्नयक यह संस्था यही सोचती है कि अंग्रेजी से ज्यादा असर पड़ता है। शायद वह यह भी मानती है कि देश के कलाकारों का दिमाग अभी औपनिवेशिक है। यदि यह अतिरंजना लगती हो तो यह स्तंभकार सीधा आरोप अकादेमी पर यह लगा सकता है कि अकादेमी के अधिकारियों का दिमाग जरूर औपनिवेशिक है—कम से कम इस प्रशस्ति पुस्तिका से उस का स्पष्ट आभास मिलता है।

अब देखिए, एक पुरस्कृत कलाकार है राधारानी जिन्हें मणिपुरी कीर्तन गायन पर पुरस्कार दिया गया। उन की प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि उन्हें वचपन में गायन पर जिले के

कलेक्टर ने जो आयरिश था विशेष प्रमाणपत्र प्रदान किया था। चलिए मान लिया, किसी की कला का गुण बताने के लिए आप जिला कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत होना एक महत्वपूर्ण बात मानते हैं और अकादेमी पुरस्कार पाने के लिए यह एक आधार देता है (अगर इस पर हँसी आये तो भी इसे फिलहाल मान लीजिए) लेकिन वह जिला कलेक्टर आयरिश था—यह क्या हुआ? यदि आयरिश न होता भारतीय होता तो उस के द्वारा पुरस्कृत होना कोई मतलब नहीं रखता? उस का पुरस्कार इसी लिए महत्वपूर्ण है कि वह आयरिश था? यही है औपनिवेशिक दिमाग, जो अभी भी मानता है कि अंग्रेज बहादुर के नाम से जोड़ देने से गरिमा बढ़ती है और उस की भाषा से जोड़ देने से शोभा!

इतना ही नहीं कलाकारों के प्रशस्ति पाठ में कहीं कहीं इस बात का जिक्र है कि उन्होंने विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। जैसे कलाकार की कला के मूल्यांकन में विदेशों में कला का प्रदर्शन कोई खास मतलब रखता हो! विदेश जाना तो अब सर्व सुलभ है कि नये से नया, अदने से अदना कलाकार वहाँ चक्कर लगा आता है—ट्रेप में संगीत भर कर नाच गा आता है। फिर वहाँ कौन भारतीय कला के पारखी बैठे हैं? विदेश में नाच-गा आना कोई बड़ा गुण नहीं है। पर आज हर जगह इस का बखान होता है! विदेशों में तो अक्सर लोग घरों में नाच गा आते हैं। पुरस्कृत कलाकार का जीवन चरित्र तो आप लिख नहीं रहे। उस के नृत्य के क्या विशेष गुण हैं, नृत्य के क्षेत्र में क्या काम किया उस ने जिस के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, यह बताना ही प्रशस्ति पाठ का उद्देश्य होता है। यद्यपि प्रशस्ति पाठ यह भी बताता है लेकिन कुछ विदेश वर्ग रह से जोड़ देने को क्यों इतना जरूरी मानता है, यह समझ में नहीं आता।

यह स्तंभकार चाहता है और माँग करता है कि अगले वर्ष से साहित्य अकादेमी की तरह प्रशस्ति पाठ हिंदी में किया जाये और उस की अंग्रेजी प्रतियाँ वितरित कर दी जायें और कलाकारों के विदेशों में कला प्रदर्शन का बखान न किया जाये—कोई वहाँ बस गया हो और स्कूल चला रहा हो, संगीत नृत्य की शिक्षा दे रहा हो तो बात दूसरी है। और हाँ, अंग्रेज बहादुरों द्वारा दिये गए पुरस्कारों को कलाकार के गुणों की चर्चा करते समय इतनी अहमियत न दी जाये। यदि यह अकादेमी की नीयत नहीं केवल चूक और असावधानी है तो यह स्तंभकार कमलादेवी चट्टोपाध्याय और श्रीमती कपिला वात्स्यायन से अनुरोध करता है कि वह अपने अधिकारियों को प्रशस्ति पाठ तैयार करते समय और सावधान रहने की ताकीद करें, प्रशस्ति पाठ तो हिंदी में शुरू करवायें ही—आखिर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का मुख्य अंग होती है।



## महंगे सिनेमाघर, खामोश प्रशासन

मार्च के आखिरी हफ्ते में जब दिल्ली के कई सिनेमाघरों ने अपनी टिकट दरें बढ़ायीं, तब पिछले ढाई बरस में यह चौथा मौका था, जब सिनेमाघर-मालिक अपनी मनमानी दरें लागू करने में कामयाब रहे और प्रशासन कुछ न कर सका। ताजा बढ़ोतरी से, पिछले ढाई बरस में, टिकटों की दरें करीब ढाई गुनी बढ़ चुकी हैं और कोई इस बात की गारंटी देने को तैयार नहीं है कि दरों में फिर जल्दी ही कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के एक सिनेमाघर में सब से महंगी टिकट आठ रुपये की हो गयी है। इस सिनेमाघर का नाम है गोलचा और इस महंगे सिनेमाघर की सब से सस्ती टिकट है पाँच रुपये की। सन् 1979 में इस सिनेमाघर की सब से महंगी टिकट 3 रुपये 20 पैसे की हुआ करती थी और सब से सस्ती टिकट एक रुपये 24 पैसे की थी। बाकी सिनेमाघरों की भी यही हालत है। सन् '79 के बाद सभी ने अपनी टिकट की दरें ढाई गुना बढ़ा दी हैं।

सिनेमाघरों की टिकट दरें बढ़ने से भी ज्यादा अहमियत रखने वाली बात यह है कि निचली क्लास की सीटों के टिकट एक तरफ जहाँ महंगे कर दिये गये हैं, वहीं सीटों की तादाद भी बहुत कम कर दी गयी है। गोलचा की ही मिसाल देख लेना शायद काफी हो। इस सिनेमाघर में सन् '79 में सब से निचली क्लास की सीटों की संख्या थी 170। अब यह संख्या है सिर्फ 72 यानी सीधे सीधे करीब सौ सीटों की कटौती। इसी तरह कमल सिनेमाघर में निचली क्लास की सीटें जहाँ सन् '79 में 188 थीं वहीं अब वे सिर्फ 88 रह गयी हैं। दक्षिण दिल्ली के पारस सिनेमाघर में सन् '79 में निचली क्लास में 219 सीटें हुआ करती थीं। अब उन की तादाद 90 है। मिनर्वा और सपना जैसे कई सिनेमाघरों ने तो सब से निचली क्लास खत्म ही कर दी है।

इस तरह, दरें बढ़ा कर आम लोगों को मनोरंजन के फिल्म-साधन से दूर रखने की कोशिश तो की गयी है, उन के लिए जगह भी घटा दी गयी है। यह एक तरह से आम दर्शक पर दुहरा प्रहार है। महंगी टिकटें और सीटें भी कम।

और बेहिसाब मुनाफाखोरी के इस सिलसिले की शुरुआत होती है, सन् '79 से। तब तक दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार था कि वह अपने राज्य के सिनेमाघरों की टिकटों की

दरें नियंत्रित रख सकते हैं। उन्हीं दिनों सिनेमाघरों के मालिकों ने सन् 68 से चली आ रही दरों में बढ़ोतरी की माँग और तेजी से शुरू कर दी। दरअसल यह माँग सन् '79 से चल रही थी, लेकिन इसे माना नहीं गया था। आपात-काल के दिनों में सिनेमाघरों की टिकटों की कीमतें दस प्रतिशत और कम कर दी गयी थीं। सन् '79 में सिनेमाघरों के मालिक अदालत में चले गये और अदालत ने फैसला दिया कि सिनेमाघरों की टिकट दरें नियंत्रित करने का संघ प्रशासित दिल्ली राज्य की सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में लागू होने वाला कानून भी रद्द कर दिया गया।

फिर क्या था सिनेमाघर मालिकों की बन आयी और वे टिकटों की कीमतें अपने अपने हिसाब से बढ़ाने लगे। सरकार ने तब पंजाब में लागू सिनेमा टिकट नियंत्रण कानून दिल्ली में भी लागू किया। सन् 81 की शुरुआत में जब इस कानून पर अमल शुरू हुआ तो सिनेमाघर के मालिक अदालत से स्थगन आदेश ले



‘पुताई के लिए भी पैसे नहीं होते’

जोगेंद्र सिंह साहनी ‘प्लाजा’ के मालिक हैं। उन्होंने एक डेढ़ महीने पहले बालकनी की टिकट दरों में 30 पैसे की वृद्धि की है। उन का कहना है कि निचली क्लासों को हम ने छुआ तक नहीं है और बालकनी की टिकट भी कोई खास महंगी नहीं की है।

हर रोज पंद्रह-बीस सीटों के कटने से श्री साहनी बेहद परेशान हैं और उन का कहना है कि लोग ब्लेड से रेन्जीन काट जाते हैं और हम मरम्मत कराते कराते परेशान हैं। सभी सिनेमाघरों का यही हाल है।

उन्होंने कहा—“आप को लगता भले हो कि सिनेमाघर से बड़ी आमदनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो बरस पहले तक तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि सिनेमाघर की पुताई करवा सकें।”

आये। तब से मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन सिनेमाघरों की टिकट दरों में बढ़ोतरी होती रही है। बिना इजाजत टिकट दरों में वृद्धि के आधार पर राजधानी के शीला सिनेमाघर का लायसेंस 3 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद 4 अप्रैल को सिनेमाघर फिर खुल गया।

फिलहाल सिनेमा की टिकटों पर सरकार 60 प्रतिशत मनोरंजन कर वसूल रही है, लेकिन मनोरंजन कर और बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर गुपचुप तरीके से विचार हो रहा है। इस तरह, आने वाला समय भी संभवतः सिनेमा की दरों में भारी बढ़ोतरी का ही होगा। 60 लाख से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली में 60 से ज्यादा सिनेमाघर हैं लेकिन अब वे आम लोगों की पहुँच से बाहर के होते जा रहे हैं। महंगी टिकटें, सिनेमाघरों के भीतर मिलने वाली खाने-पीने की महंगी चीजें, जरूरी सुविधाओं की कमी, तिस पर टिकटों की काला-बाजारी और असामयिक तत्वों की हरकतों ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है।

सिनेमाघरों के मालिकों का कहना है कि टिकट अगर आठ रुपये हो तो हमारे पल्ले तो पाँच रुपये ही पड़ते हैं। फिर एयर कंडीशनर से लगा कर बिजली, पानी और रंग रोगन की दरों में भारी वृद्धि हो गयी है। कर्मचारियों को तनखाह भी अब पहले से बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, ऐसे में जबकि पिछले दस वर्षों से सभी चीजों के दाम ढाई सौ से तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गये हों, अगर सिनेमा की टिकटों में भी ‘थोड़ी बहुत’ वृद्धि हो गयी तो वह आपत्ति-जनक क्यों है? दर्शक परेशान हैं।

अजंता सिनेमा के मालिक श्री शिवगोपाल ने टिकट दरों में बढ़ोतरी के अर्थशास्त्र की व्याख्या इस प्रकार की कि 1975 से 1980 के बीच कर्मचारियों की तनखाह में 33 प्रतिशत, बिजली की दरों में 43 प्रतिशत, प्रचार खर्च में 115 प्रतिशत, एयरकंडीशनर के खर्च में 150 प्रतिशत और बिजली के उपकरणों को बदलने के खर्च में 511 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी है। सिनेमाघर के रखरखाव पर इन पाँच वर्षों में 280 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। टाचें और सेल के खर्च तक में 114 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। सन् '75 में कार्बन की 100 छड़ें 220 रुपये में आती थीं अब वे 706 रुपये में आती हैं। एक शो में 14-15 छड़ें इस्तेमाल होती हैं। इस हिसाब से टिकट दरें तो बढ़ेंगी ही। नटराज सिनेमाघर के मालिक एच. आर. त्यागी स्वीकार करते हैं कि टिकटों की कालाबाजारी में सिनेमाघरों





### फंसले के बाव कुछ करेंगे

सिनेमाघरों को लायसेंस देने और उन की टिकट दरें तथा विभिन्न वर्गों में सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के लायसेंस विभाग को है। पुलिस उपायुक्त राजन मिश्र इस विभाग के प्रभारी हैं। उन के साथ हुई बातचीत के अंश :

आप दरें नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे ?  
'मामला अदालत में चल रहा है। सिनेमाघर मालिक स्थगन आदेश ले आये हैं। इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं कि मामले की सुनवाई जल्दी हो जाये।'

उन का (सिनेमा मालिकों) कहना है कि हर चीज के दाम बढ़े हैं तो टिकटें महँगी क्यों न हों? 'दाम बढ़े हैं, पर इतने नहीं। फिर सिनेमाघर मालिकों को कोई घाटा नहीं है। वे तो सिनेमाघर किराये पर वितरक को दे देते हैं। फिल्म चले न चले, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। टिकटें बाकई बहुत महँगी हो गयी हैं। महीने में एक बार से ज्यादा तो मैं भी अब अपने परिवार को सिनेमा नहीं दिखा पाता।'

सीटों का बर्गीकरण? 'वह भी होना चाहिए। निचली क्लास में सब से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। पर उल्टा हो रहा है। अदालत का फैसला क्या होता है, यह देखने के बाव ही अगला कदम उठा पायेंगे।'

के कर्मचारी भी कभी कमार शामिल रहते हैं। 'लेकिन उन के खिलाफ कुछ करना मुश्किल है। वे यूनियनबाजी शुरू कर देते हैं।'

### 'टिकटों की ब्लैक पुलिस करवाती है'

बिजय नारायण सेठ दिल्ली राज्य सिनेमाघर मालिकों की एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे तीन सिनेमाघरों के मालिक हैं।

बार बार टिकट दरें क्यों बढ़ रही हैं? यह पूछे जाने पर बोले—यह बीमारी सरकार ने खुद फैलायी है। जब फिल्म महोत्सव हुआ तो सरकार ने 25 रुपये की टिकट रखी। सरकार के लिए तो फिल्म महोत्सव भी मुनाफा कमाने की चीज हो गया और हम अपना खर्च निकालने के लिए भी टिकट दर न बढ़ायें। पर यह तो अंधाधुंध बढ़ोतरी है। गरीब आदमी क्या करेगा? 'गरीब आदमी की सरकार को चिंता कहाँ है? इतना मनोरंजन कर वसूलती है सरकार तो सब पैसा इकट्ठा करें और एक सिनेमा घर चला कर देखें। सस्ती टिकटें रखें। न हो तो सिनेमाघर को अनुदान दें। सिनेमाघर बनाने के

लिए मूखंड की नीलामी खत्म होती है एक करोड़ रुपये पर। एक करोड़ रुपये और सिनेमाघर बनाने पर लग जाते हैं। फिर टिकटें महँगी न हों तो क्या हो?

लेकिन यह टिकटों की कालाबाजारी... 'पुलिस करवाती है।'

सिनेमाघरों के कर्मचारी भी तो शामिल होते हैं। 'सरासर झूठ है। पुलिस न चाहे तो ब्लैक हो ही नहीं सकती। हम तो कहते हैं पुलिस खुद टिकट बाँट ले। हम सारी सुविधाएँ देने को तैयार हैं। तो टिकट दरों के नियंत्रण में भी सरकार से कुछ सहयोग कीजिए न? 'टिकट दरें ज्यादा नहीं हैं। सिनेमाघर का मालिक टिकट के पैसे का अकेला हकदार नहीं होता। उस के अलावा फिल्म वितरक फिल्म निर्माता और फिल्म में पैसा लगाने वाले भी उस पैसे के हकदार होते हैं। सन् 68 में शीतलपेय की बोलत 24 पैसे की आती थी, अब सवा रुपये की मिलती है। दो बरस पहले जो खखार



एन. आर. त्यागी



शिव गोपाल



सुरजीत सिंह



बिजयनारायण सेठ

### 'फाइवस्टार होटल से तो सस्ता है'

एम. सी. गोलचा, दिल्ली के सब से महँगे सिनेमाघर के मालिक हैं। यह सिनेमाघर है गोलचा, श्री गोलचा देश के अन्य शहरों के कुछ सिनेमाघरों के मालिक भी हैं।

आप को नहीं लगता कि आप के यहाँ टिकट दरें बहुत ज्यादा हो गयी हैं?

'हम तो 1954 की दरें भी लागू करने को तैयार हैं। हमें तब की दरों पर बाकी सुविधाएँ विलवा देगी सरकार?'

'जाने-प्यारे की चीजें भी बहुत महँगी मिलती हैं आप के सिनेमाघर में?'

'फाइव स्टार होटलों से सस्ती है—मेरे सिनेमाघर की साफ-सफाई और साज सज्जा फाइव स्टार होटल से कम नहीं है।'

30 पैसे का था, अब वह 70 पैसे का है। सिनेमा टिकटों की दरें ही नहीं बढ़ी हैं।'

पुलिस ब्लैक करवाये,

इस का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त श्री सुरजीत सिंह को इस बात का अफसोस है कि लोग बिना जाँच पड़ताल किये हर मामले में पुलिस को दोषी मान लेते हैं। 'पुलिस पर आरोप लगाना आसान जो है।'

'तो फिर जब सिनेमाघर पर टिकटों की ब्लैक होती है। रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती पुलिस?' इस और अन्य सवालों पर उन का कहना था:

'करती है। जनवरी में ही 70 ऐसे काला-बाजारिये पकड़े थे।'

सिनेमाघरों के कुछ मालिक तो कहते हैं

कि ब्लैक पुलिस ही करवाती है और पुलिस चाहे तो ब्लैक हो ही नहीं सकती।

'हमारे पास तो एक भी सिनेमा मालिक की तरफ से ऐसी शिकायत नहीं आयी कि पुलिस कर्मचारी टिकटों की ब्लैक करवा रहे हैं। पुलिस ब्लैक करवाये, इस का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर पुलिस में 30 हजार आदमी हैं। एकाध ऐसा वैसा भी हो सकता है। शिकायत आती है तो कार्रवाई भी होती है।'

सन् 80 में 17 अक्तूबर को लिबर्टी सिनेमा पर ब्लैक करने वालों ने एक सिपाही देवेन्द्रसिंह को मार डाला था। उस ने टिकटों की ब्लैक रोकने की कोशिश की। हत्यारे पकड़ लिये गये हैं। मामला चल रहा है अदालत में। लेकिन आप यह बताइये कि ब्लैक रोकने में पुलिस को सहयोग देता है कोई?

उस सिपाही की शवयात्रा में एक भी सिनेमाघर मालिक शामिल हुआ?

'क्या सिनेमा मालिकों को मालूम नहीं होता कि कौन हैं वे लोग जो रोज थोक में टिकटें ले जाते हैं। फिर रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं वे? हम तो अपनी तरफ से ब्लैक न होने देने की पूरी कोशिश करते ही हैं, लेकिन दर्शक और सिनेमा मालिक भी तो कुछ सोचें।'



राष्ट्र

राज्यसभा

## छियालीस गये सैंतालीस आये

**चौदह** राज्यों से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के जो परिणाम मिले उन से यह स्पष्ट हो गया कि अनुशासन का संकट न सिर्फ सत्ताधारी इंदिरा कांग्रेस में है बल्कि उस के कोटाणु प्रतिपक्षी खेमे में भी विद्यमान हैं। वे भी एकता की कोशिशों की दुंदुभी वजाने के बावजूद वायदा खिलाफी के अभियोग से मुक्त नहीं हो सकते। पर्याप्त बहुमत के बाद भी कई राज्यों में इंदिरा कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों का पहली गणना में ही विजयी न हो पाना या आशा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के सुंदरसिंह भंडारी की पराजय इसी तीखी वास्तविकता की द्योतक हैं।

234 सदस्यों की राज्यसभा में रिक्त 73 सीटों में से 63 के चुनाव हुए। असम की दो, केरल की तीन और दिल्ली की एक सीट इन राज्यों की विधानसभाओं के न होने से खाली है। शेष चार सीटों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं।

इंदिरा कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों का कार्यकाल समाप्त हुआ था। उन की जगह पर उस के 47 उम्मीदवार विजयी हुए। शरद कांग्रेस, जनता पार्टी, अकाली दल, नेशनल कांफ्रेंस, फारवर्ड ब्लाक के एक-एक सदस्य आये। एक सीट निर्दलीय को मिली। भाजपा के 2, माकपा

के 3 और माकपा के 2 सदस्य विजयी हुए। इस प्रकार सदन में इंदिरा कांग्रेस के कुल 120, शरद कांग्रेस के 5, जनता पार्टी के 15, भारतीय जनता पार्टी के 14, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 15, लोकदल के 14, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 5, अकाली दल के 3, नेशनल कांफ्रेंस के 3, फारवर्ड ब्लाक के 2, अन्नाद्रमुक के 9, द्रमुक के 4 सदस्य हैं। 8 निर्दलीय हैं। मनोनीत सदस्यों समेत अन्य की कुल संख्या 17 है।

इंदिरा कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी अनुशासन की चिंता न करते हुए कई राज्यों में दूसरे दलों के उम्मीदवारों को मत दिया। आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उत्तरप्रदेश में यह स्थिति एकदम साफ हो गयी। आंध्र में उसे अपने बल पर 6 सीटें पानी चाहिए थीं। एक सीट निकल गयी। उस के 16 विधायकों ने जनता पार्टी के उम्मीदवार को मत दिया।

14 अन्य विधायकों ने एक अन्य दल के उम्मीदवार को मत दिया। महाराष्ट्र में उस के पाँचों उम्मीदवार जीत अवश्य गये लेकिन वाणी देशपांडे को समर्थन देने के बावजूद जीत नसीब नहीं हुई। उन की जगह शरद कांग्रेस के सुरेश कलमाडि जीते। उन्हें निश्चित रूप से इंदिरा

कांग्रेस के 7 विधायकों के मत मिले थे। उस के उम्मीदवार श्री भंडारे का छठवीं गणना के बाद किसी प्रकार जीत पाना, इसी का एक परिणाम है। कर्नाटक में भी उस के चारों उम्मीदवार जीत गये लेकिन कुछ पार्टी विधायकों का मत दूसरे उम्मीदवारों को मिलने के कारण उस का एक उम्मीदवार पहली गणना में विजयी नहीं हो सका।

प्रतिपक्षी दलों के खोखलेपन का प्रमाण यह है कि उन्होंने वायदा तो अपने मतों को केंद्रित करने का किया था, लेकिन कई राज्यों में काम एक दूसरे के विरुद्ध किया। राजस्थान में भाजपा के सुंदरसिंह भंडारी को समर्थन देने का वायदा जनता, लोकदल और शरद कांग्रेस ने किया था। वैसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में शरद कांग्रेस और जनता पार्टी में नहीं बनी। अपवाद सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उस से जुड़े वामपंथी मोर्चे के दल हैं। बंगाल में उस ने पाँचों सीटें जीत लीं। दिलचस्प तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में राजनारायण को हराने में इंदिरा कांग्रेस और प्रतिपक्षी दलों में एकता जरूर पायी गयी।

इंदिरा कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों में राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्याम लाल यादव, केंद्रीय मंत्री मोहम्मद नारायण सिंह और राज्य-मंत्री उस्मान आरिफ़, तथा प्रतिपक्षी दलों में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी तथा शरद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश कलमाडि के नाम उल्लेखनीय हैं।

**राजस्थान** से राज्यसभा की तीनों रिक्त सीटों पर कांग्रेस (इ) के प्रत्याशियों की विजय ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है।

राज्यसभा के इन रिक्त पदों के लिए काफी राजनैतिक सरगर्मी थी। जिन तीन उम्मीदवारों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वे स्थान रिक्त हुए थे वे थे—केंद्रीय कृषि उपमंत्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़, दिनेश स्वामी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बरकतउल्ला खां की पत्नी श्रीमती उषा खां।

मोहम्मद उस्मान आरिफ़ केंद्र में मंत्री पद प्राप्त करने में सफल होने के बाद राज्य की राजनीति में भी किसी न किसी प्रकार अपना प्रभाव बनाये रखने में जुटे रहे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के सत्ताकाल में दिनेश स्वामी उन के प्रमुख समर्थक के रूप में राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे थे। पर सत्ता परिवर्तन के साथ उन का प्रभाव भी लगातार कम होता गया और अंततः हुआ यह कि माथुर सरकार के सत्ता

## वायदे काम नहीं आये

में आने के बाद तो पहाड़िया गुट ने भी उन्हें समर्थन देने के बजाय जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया को ही कांग्रेस (इ) प्रत्याशी बनाये जाने के लिए अपनी भागदौड़ जारी रखी। श्रीमती उषा खां के लिए तो कहीं कोई समर्थन था ही नहीं।

श्रीमती शांति पहाड़िया के लिए समर्थन जुटाने में माथुर सरकार में कृषि मंत्री श्रीमति कमला के साथ ही खेतसिंह राठौर, फूलाराम, हनुमान प्रसाकर और हरसहाय मीणा आदि काफी सक्रिय दिखायी दे रहे थे। दोनों पक्षों की जयपुर से दिल्ली तक की भागदौड़ होती रही और जब स्पष्ट हो गया कि शांति पहाड़िया को टिकट नहीं मिल रहा है तो पहाड़िया गुट हताश होने के साथ साथ निष्क्रिय भी हो गया। कांग्रेस (इ) प्रत्याशियों के लिए दो और नाम उभरे। मुख्यमंत्री के विश्वस्त एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य भुवनेश चतुर्वेदी और नत्थासिंह अंत में श्री आरिफ़ के साथ वे दोनों भी प्रत्याशी घोषित किये गये।

अपने बहुमत के आधार पर कांग्रेस (इ) के दो प्रत्याशियों की जीत निश्चित थी पर तीसरे उम्मीदवार नत्था सिंह के लिए पर्याप्त मत जुटाने की समस्या थी क्योंकि दोनों साम्यवादी दलों को छोड़ कर चारों विपक्षी दलों ने भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था।

कांग्रेस (इ) हाईकमान द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री राव वीरेंद्रसिंह और केंद्रीय उपमंत्री चौधरी दलबीर सिंह जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री और उन के प्रमुख सहयोगियों के रूप में राजस्व मंत्री परसराम मदेरणा और वित्तमंत्री चंदनमल बंद के साथ साथ प्रांत की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका रखने वाले विधायक जनार्दनसिंह गहलौत भागदौड़ करते रहे। कांग्रेस (इ) को विपक्ष के 13 और मत प्राप्त हुए। मोहम्मद उस्मान आरिफ़ को प्रथम वरीयता के 53, भुवनेश चतुर्वेदी को 54 और नत्था सिंह को 53 मत प्राप्त हुए जब कि विपक्षी दलों के घोषित प्रत्याशी भाजपा के सुंदरसिंह भंडारी केवल 36 मत मिले।

विनमान



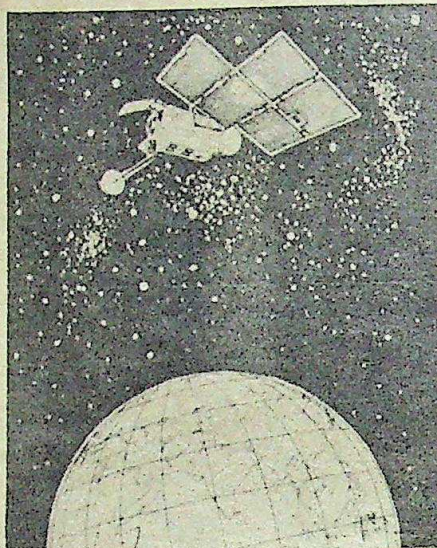
# भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह : एक मंच आकाश में

**सूचना** प्रसार और संचार व्यवस्था भौतिक और राजनैतिक विकास की आधार शिला है। विश्व की संचार आवश्यकताएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और साथ ही जटिल भी होती जा रही हैं। इसीलिए विश्व के विकसित देशों ने दूर दराज इलाकों को जोड़ने के लिए परंपरागत माध्यमों को अपर्याप्त मान कर उपग्रह संचार व्यवस्था का सहारा लेना शुरू किया। असल में मौसम के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त करना, दूर के इलाकों में दूरदर्शन प्रसारण की सुविधा देना, बिना तारों के जटिल जाल के ही पूरे देश को टेलीफोन से जोड़ना, समुद्र और वनों के साथ ही बीहड़ों और रेगिस्तानों के बारे में सही सही अनुमान लगाना, सभी काम वास्तव में संचार व्यवस्था के विस्तृत कार्यक्षेत्र में आते हैं। जानकारी आधुनिक विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है।

सोवियत संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया ही ऐसे देश हैं जिन्होंने संचार व्यवस्था और दूरदर्शन के लिए अपने उपग्रहों का इस्तेमाल किया है। रूस के प्रसारण उपग्रह अति उच्चस्तर तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा और जापान में भी इस प्रकार के उपग्रह गैर परंपरागत 'बैंड' का इस्तेमाल कर के काफी उपयोगी काम कर रहे हैं। मगर भारत ने अभी तक इस दिशा में जो भी काम किया है उस का आधार दूसरों द्वारा बनाये गये या दूसरों से उधार लिये हुए उपग्रह ही रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह शृंखला स्वावलंबी बनने का पहला प्रयास है।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जिसे इनसेट-1 कहा जाता है वास्तव में एक बहुमुखी उपग्रह है। जो अन्य देशों के उपग्रहों के विपरीत केवल दूरदर्शन प्रसारण का ही काम नहीं करेगा बल्कि यह संचार व्यवस्था के प्रायः सभी आयामों को छू लेगा, चाहे वह मौसम की भविष्यवाणी हो, भूगोलीय सर्वेक्षण हो या टेलीफोन सुविधा प्रदान करना। एक ही उपग्रह में ये सब सुविधाएँ समायी जायें इसके लिए यह जरूरी था कि उपग्रह बनाने से पहले व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण किये जायें। वास्तव में 1968 से 1978 के बीच भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में इस प्रकार के दो महत्वपूर्ण प्रयोग किये गये।

पहला प्रयोग उपग्रह शिक्षा दूरदर्शन प्रयोग था। 'साइट' नाम के इस प्रयोग में अमेरिकी उपग्रह ए टी एस-6 का इस्तेमाल किया गया। इस का उद्देश्य देश के ऐसे क्षेत्रों में उपग्रह के



इनसेट-1: आकाश से निगरानी

माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण पहुँचाना था जो दूरदर्शन केंद्रों से काफी दूर स्थित हैं। इस सिलसिले में कार्यक्रम राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार और ओडीसा के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाये गये। दूसरा प्रयोग था उपग्रह दूरसंचार प्रयोग (स्टेप) इस में पश्चिम जर्मनी के 'सिफोनी' उपग्रह का इस्तेमाल किया गया। इन सफल परीक्षणों के पश्चात ही भारत सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण करवाया कि एक ही छोटे उपग्रह से ये सभी काम एक साथ लिये जा सकते हैं कि नहीं। अलग अलग से देश के विभिन्न विभागों ने जो नतीजे निकाले उन्हीं नतीजों पर कुछ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संचार संगठन भी पहुँचे और इस प्रकार भारत के पहले बहुमुखी संचार मौसम और दूरदर्शन उपग्रह के जन्म की तैयारियाँ शुरू हो गयीं।

जुलाई 1978 में अमेरिका की फोर्ड एरो-स्पेस एंड कम्युनिकेशन कारपोरेशन के साथ इनसेट के निर्माण का समझौता हुआ। इस के अंतर्गत दो उपग्रह बनाये जायेंगे जिन्हें इनसेट-1 और इनसेट-2 भी नाम दिया गया। पहला उपग्रह 9 अप्रैल को अमेरिका के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जा रहा है। इस में थॉर-डेल्टा 3910 प्रक्षेपण उपकरण का इस्तेमाल किया जायेगा। इस तरह अंतरिक्ष में छोड़ने का तरीका अपेक्षाकृत मंहगा है। मगर संभवतः पहले उपग्रह के लिए इसे ही उपयुक्त समझा गया है। दूसरे उपग्रह के लिए अंतरिक्ष परिवहन पद्धति का ही इस्तेमाल किया जायेगा जो बड़े उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल की जाती है।

परियोजना निदेशक डॉ. प्रमोद काले के निर्देशन में विकसित 1150 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह में 12 चैनल होंगे, जिन का इस्तेमाल दूरसंचार के लिए किया जा सकता है। इसी तरह दो विशेष चैनल दूरदर्शन प्रसारण के काम आयेंगे। पृथ्वी को जाँचने के लिए इस में एक विशेष उपकरण रखा जायेगा जो सामान्य प्रकाश और इनफ्रा रेड दोनों स्थितियों में उपयोगी होगा। इस उपग्रह को भूस्थायी कक्षा में स्थापित किया गया है, जिस का मतलब यह होता है कि यह उपग्रह पृथ्वी से 36 हजार किलोमीटर ऊँचाई पर परिक्रमा कर रहा है। इस ऊँचाई पर इस उपग्रह को पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में पूरे 24 घंटे लगेंगे। पृथ्वी और इस उपग्रह की तुलनात्मक स्थिति हरदम एक जैसी रहेगी, और इसलिए यह पृथ्वी से एक ही स्थान पर स्थिर दिखायी देगा। यह स्थान अरब सागर में मिनीकाय द्वीपसमूह के ऊपर होगा। इनसेट-1 की मुख्य काया चौकोर है, जिस में दोनों ओर से दो एंटेना हैं जो दूरसंचार और दूरदर्शन प्रसारण के लिए जरूरी हैं। उपग्रह के दक्षिणी भाग में सिलिकोन कोशाओं की पट्टियाँ हैं जो वास्तव में उपग्रह का ऊर्जा भंडार हैं। इन सौर कोशाओं से ही ऊर्जा बनती रहती है जो उपग्रह को 900 वाट बिजली प्रदान करती है। उत्तरी हिस्से में एक सौर पतवार है जो उपग्रह को सही दिशा में संतुलित करती रहती है। इस के अतिरिक्त ऊँचाई, दिशा, गति को सुधारने के लिए भी अलग अलग उपकरण रखे गये हैं। एक रेडीयधर्मी प्रशीतन यंत्र विभिन्न यंत्रों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

थॉर-डेल्टा पद्धति से उपग्रह वास्तविक कक्षा में नहीं पहुँच पाता इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि द्वितीय चरण में वास्तविक कक्ष में पहुँच जाये। अंतरिक्ष में पड़ने वाले विभिन्न दबाव को नियंत्रित करने के लिए उपग्रह में ऐसे उपकरण हैं जो भूकेंद्रों से आदेश पालन करते हैं। अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भूनियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

संचार मंत्रालय और डाक तार विभाग देश भर में 28 भूमि केंद्रों की स्थापना कर रहा है। इस के अतिरिक्त कई छोटे छोटे केंद्र भी स्थापित किये जायेंगे। इन केंद्रों का काम उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करना होगा। कुछ भू-केंद्र केवल टेलीफोन विकास के काम में आयेंगे कुछ दूरदर्शन प्रसारण के। दिल्ली के पास

एक बड़  
में मौसम  
इसे वि  
विभाग  
सूचना  
सुविधा  
से देश  
सरकार  
बनाया  
दायिक  
किये ज  
केंद्र स्था  
मौसम वि  
और ना  
के अति  
मंच भी  
उपग्रह  
दूरदर्शन  
पहुँचाने  
संचार के  
समझा उ  
वावजूद  
संबंधी  
नहीं है।  
संचार  
हैं। डाक  
से लड़ा  
संचार व्य  
मौसम के  
पर निर्भर  
ऊँचे पहा  
दबाव के  
उपग्रह ही  
क्योंकि ज  
करती वा  
हो सकता  
अचूक सा  
इस उ  
12 करोड़  
उपग्रह पर  
मान है। इ  
स्थापित  
आवश्यकत  
इस के लि  
की गयी है।  
इनसेट  
पाल रहेग  
तक केने  
छोड़ा जा  
इस प्र  
में प्रवेश  
देश होगा  
उपग्रह सं  
देशों में  
ऐसा देश  
विनमान



एक बड़ा भूकेंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें मौसम संबंधी जानकारी ग्रहण की जायेगी। इसे विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए डाकतार विभाग उपयुक्त संचार व्यवस्था करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपग्रह से प्राप्त सुविधा का लाभ उठाते हुए दूरदर्शन प्रसारण से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम पहुँचायेगा। सरकार द्वारा इस सिलसिले में यह कार्यक्रम बनाया गया है जिस में बड़ी संख्या में सामुदायिक और वैयक्तिक दूरदर्शन सेट वितरित किये जा रहे हैं। दिल्ली में जो मौसम संबंधी केंद्र स्थापित हो रहा है उस का नियंत्रण केंद्रीय मौसम विभाग करेगा जिस की सहायता पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग भी करेगा। इस के अतिरिक्त एक सौ ऐसे सूचना ग्रहण मंच भी स्थापित किये जायेंगे जो जगह जगह से उपग्रह द्वारा भेजे गये आँकड़े इकट्ठे करेंगे।

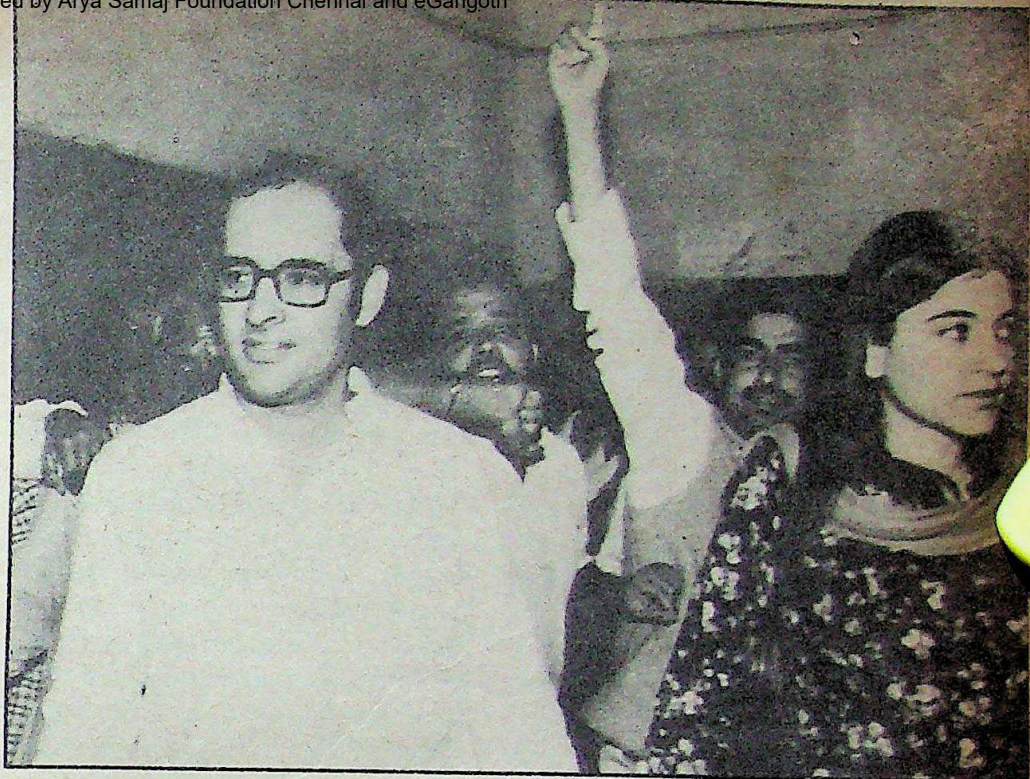
दूरदर्शन की सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने की संभावनाएँ तो स्पष्ट हैं मगर दूर-संचार के महत्व को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। लघुतरंगों के उपयोग के बावजूद देश के विशाल भू-भाग में टेलीफोन संबंधी संपर्क स्थापित करना आसान नहीं है।

संचार तरंगों को मौसम के दबाव सहने पड़ते हैं। डाक तार महानिदेशक के अनुसार उपग्रह से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक टेलीफोन संचार व्यवस्था आसान हो जायेगी। इसी प्रकार मौसम के बारे में अग्रिम जानकारी इस बात पर निर्भर करती है कि समुद्र के ऊपर से या ऊँचे पहाड़ों के पार बादलों की स्थिति क्या है, दबाव के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। इस के लिए केवल उपग्रह ही संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि जहाँ सामान्य प्रकाश तरंगों का काम नहीं करती वहाँ इनफ्रा रेड तरंगों का इस्तेमाल हो सकता है, जो बादलों की ऊँचाई मापने का अच्छा साधन है।

इस उपग्रह के मौसम संबंधी प्रयोगों पर ही 12 करोड़ रुपया खर्च आयेगा। लेकिन सारे उपग्रह पर 113 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस के अतिरिक्त विभिन्न भू-केंद्रों को स्थापित करने के लिए 70 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। छठी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए 1211 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इनसेट-1 ए अंतरिक्ष में करीब सात साल रहेगा। इनसेट-एक बी अगले वर्ष के अंत तक केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा जायेगा।

इस प्रकार भारत अंतरिक्ष संचार युग में प्रवेश कर चुका है। विश्व में यह पाँचवाँ देश होगा जिस के पास स्वतंत्र रूप से अपनी उपग्रह संचार व्यवस्था होगी। विकासशील देशों में भारत के अतिरिक्त इंदोनेशिया ही ऐसा देश है।



मेनका

## यह बगावत की हवा कितनी दूर जायेगी

जवाहरलाल कौल

उत्तर प्रदेश में इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वंभरनाथ पांडे जब नयी दिल्ली में मेनका गांधी को समझाने में सफल नहीं हुए कि लखनऊ जाना किस प्रकार पार्टी, प्रदेश और प्रधानमंत्री के विरुद्ध होगा तो पांडे जी द्वारा यह कहने पर भी कि मेनका का 'जाना अभी निश्चित नहीं है', यह स्पष्ट हो चुका था कि लखनऊ से बगावत का परचम खुले आम फहराया ही जायेगा जिस की शुरुआत संजय गांधी की विधवा ने अपनी सास के विरुद्ध कुछ समय पहले की थी। इस के साथ ही यह भी साफ हो गया था कि अब इंदिरा गांधी को कोई निर्णायक कार्रवाई करनी ही होगी क्योंकि मेनका ने प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ही युद्ध का एलान कर दिया था। एक प्रताड़ित बहू की भूमिका निभाने के लिए मेनका ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने इंदिरा जी को एक ऐसे कोने में धकेला जहाँ से वह जो भी कदम उठाती वह मेनका को राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर स्थापित करने वाला ही होता।

तेज रफ्तार घटनाक्रम चालू होने के लिए प्रधानमंत्री के लंदन से लौटने भर की देर थी। मेनका लखनऊ पहुँची और साथ ही पहुँचा इंदिरा जी का उच्च स्तरीय अमला। विश्वंभरनाथ पांडेय का तो प्रदेश का मामला था। अरुण नेहरू और विश्वासपात्र मन्मथलाल

फोतेदार भी मोर्चा संभालने के लिए वहाँ मौजूद थे।

28 मार्च को मेनका गांधी सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो रही थीं कि कार्लटन होटल लखनऊ के 22 नंबर सूट में एक संदेशवाहक आ पहुँचा। प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र मेनका को दिया गया। आयोजक उत्तेजना और घबराहट में अंदर बाहर होने लगे। किसी ने फुसफुसाया कि इंदिरा जी ने मेनका के साथ संबंध तोड़ने की चेतावनी दी है। मगर लगता है कि मेनका और उन के साथियों को इस से अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के इन्का हलकों में एक दिन पहले ही खलबली मच गयी थी, उसने एक अप्रिय शांति का रूप ले लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने भाई की तेरहवीं से पहले ही इलाहाबाद से लखनऊ चले आये। एक आपत्कालीन बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि अकबर-मेनका के इस विद्रोह से कैसे निपटा जाये। और यह तय पाया गया कि युवा कांग्रेस के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया जाये। विरोधी खेमे की ओर से फिर भी सम्मेलन के आयोजक आश्वस्त नहीं थे। लखनऊ की कैसरबाग बारादरी में यद्यपि उन्होंने निमंत्रण पत्रों से अपने वफादार कार्यकर्ताओं को ही प्रवेश देने का फैसला



दिया था फिर भी लोगों का हुजूम कार्यकर्त्ताओं का बंधन तोड़ने में कामयाब हो गया। और इस उठापटक में बारादरी के कुछ शीशे भी चकनाचूर हो गये।

अकबर और मेनका ने सम्मेलन में जो कुछ कहा उस में केवल इतना ही महत्वपूर्ण था कि दोनों ने अपने ऊपर ऋणायें गये आरोपों का खंडन किया कि जनता पार्टी के विरुद्ध लगातार संघर्ष करने वाले लोगों पर कोई कैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बहुगुणा की शह पर काम करने का आरोप लगा सकता है। अकबर की शिकायत यह नहीं है कि वर्तमान सरकार संजय गांधी के पाँच सूत्री कार्यक्रमों को नहीं मानती, बल्कि यह है कि उन पर इतना जोर नहीं दिया जा रहा है कि जितना संजय गांधी के जमाने में दिया जाता था। मगर असल शिकायत तो यह है कि संजय की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने इस प्रकार की नीति चाल की जिस में संजय गांधी के सभी समर्थकों को पीछे धकेल दिया गया। असल में यह शिकायत सत्ताकेंद्रों के इर्द गिर्द इंदिरा कांग्रेस के हावी होने वाले अलग अलग गुटों का संघर्ष है। उत्तरप्रदेश में संजय गांधी के समर्थकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और इसीलिए उत्तरप्रदेश के वर्तमान विधायकों में एक तिहाई विधायक ऐसे हैं जो अपना राजनैतिक महत्व संजय गांधी से ही प्राप्त कर चुके हैं। संजय की मृत्यु के बाद पार्टी संचालक और प्रशासन के तीर तरीकों में फर्क आया। शायद इसलिए कि जो भूमिका संजय गांधी की उग्र आंदोलनकारी राजनीति की सत्ता से बाहर थी, सत्ता प्राप्त करने के बाद वही नहीं हो सकती। आम तौर पर संजय समर्थकों की अबहेलना का उत्तरदायित्व राजीव गांधी पर डाला जाता है। मगर वास्तविकता यह है कि राजीव गांधी के राजनैतिक मंच पर आने से पहले ही ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गयी थीं जिन में संजय गांधी के समर्थकों की भूमिका नगण्य हो गयी थी। राजीव के राजनीति में आने से उस की गति तेज हो गयी। अमेठी में संजय के नाम पर मत प्राप्त करने के प्रयास में राजीव गांधी ने भले ही उन सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया हो जिन्हें संजय गांधी ने शुरू किया था। मगर यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि चुनाव अभियान का संचालन करने वालों में संजय समर्थकों का कोई योगदान स्वीकार नहीं किया गया। अकबर के अनुसार 'मुझे और मेरे साथियों को अमेठी के बदले पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया।' स्वयं संजय सिंह भी एक विधान-सभा क्षेत्र का संचालन करने के अतिरिक्त इका प्रत्याशी के साथ प्रत्यक्ष अभियान में कहीं दिखाई नहीं दिए।

मेनका गांधी का इस प्रकार राजनीति में आना एक आकस्मिक घटना दिखाई देता है मगर वास्तव में इस के पीछे अपना एक इति-

हास भी है। संजय की मृत्यु के बाद मेनका गांधी ने अपने मित्रों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि वह राजनीति में आना चाहती हैं (हालांकि वह अब भी कहती हैं कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती।) और कुछ प्रभावशाली मित्रों ने सार्वजनिक रूप से उन की वकालत की थी। मगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मेनका गांधी का राजनीति में आकर महत्वपूर्ण बनना इसलिए उपयोगी नहीं लगा कि मेनका पर श्रीमती गांधी का विश्वास नहीं था। यह माना जाता रहा है कि श्रीमती मेनका गांधी के पीछे जो तत्त्व हैं वे इंदिरा गांधी के राजनैतिक स्वार्थों के लिए उपयोगी नहीं हैं। राजीव की राजनीति में आने के बाद से मेनका की कुंठा बढ़ना स्वाभाविक था। जिस का परिणाम यह हुआ कि श्रीमती गांधी के साथ अलगाव बढ़ता ही गया। उन की शिकायत यह है कि न केवल उन्हें राजनीति में आने नहीं दिया गया बल्कि किसी भी रूप में उन के सार्वजनिक प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश की गयी। इस सिलसिले में सूर्या पत्रिका का उदाहरण दिया जाता है। संजय के बाद कुछ समय तक सूर्या आर्थिक रूप से स्वावलंबी रही मगर शीघ्र ही उस का राजस्व घटने लगा। जिस का कारण यह था कि जो लोग संजय के जीवन में बड़े बड़े विज्ञापन दिया करते थे उन्होंने हाथ खींच लिया। बल्कि यहाँ तक आरोप लगाया जाता है कि ऊपर से इशारा पाने पर कुछ महत्वपूर्ण उद्योगपतियों ने ऐसे विज्ञापन वापस ले लिए जिनका वह स्पष्ट वायदा कर चुके थे। अकबर के शब्दों में "कमल नाथ और सागर सूरि जैसे कुछ लोग रह गह थे जो इस पत्रिका की सहायता करते रहे। इतना ही नहीं प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेताओं ने पत्रिका के विरुद्ध मान हानि के अभियोग दायर कर दिए। यह परोक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि इस पत्रिका को जीवित नहीं रहने दिया जायेगा।" इसलिए श्रीमती मेनका गांधी ने सूर्या को चुपचाप बंद करने के बदले इस से श्रीमती गांधी की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर वार करने का फैसला किया है। वैसे मेनका जी का दावा है कि मेरी माँ ने सूर्या बेचने से पहले मुझसे कोई चर्चा नहीं की और श्रीमती विजयराजे सिंधिया की लड़की वसुंधरा से मेरी दोस्ती का इस से कोई संबंध नहीं है।

मेनका की बगावत इंदिरा गांधी के विरुद्ध है मगर उसका सीधा लक्ष्य राजीव गांधी हैं। मेनका के एकमात्र प्रवक्ता डम्पी का कहना है कि राजीव में संजय जैसी कर्मठता नहीं कि वह अपने आप को 'नेता सिद्ध करे' तो मैं उनके पीछे चलूंगा। इस स्थिति में राजीव को युवा कांग्रेस में अपना प्रभाव बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना ही होगा। यह काम वह युवा कांग्रेस के वर्तमान नेता गुलाम रसूल आजाद के माध्यम से करना चाहते हैं। यही उनकी शैली है।

उत्तर प्रदेश की बगावत शुरू करने के लिए

उपयुक्त क्षेत्र चुना गया है। तो केवल इसलिए कि उत्तरप्रदेश में वर्तमान शासन को हिलाने की संभावनाएँ अधिक हैं क्योंकि संजय समर्थक विधायकों की संख्या अधिक है। राज्य इतना बड़ा है कि किसी एक समय में भी एक चौथाई विधायक हर समय असंतुष्ट पाये जाते हैं। अकबर अहमद के अतिरिक्त यदि कोई विधायक खुल कर सामने नहीं आया तो केवल इसलिए कि वर्तमान सुविधाओं को छोड़ने का साहस आसान नहीं है। मगर मेनका की इस कार्रवाई ने उन सब विधायकों को संदिग्ध बना दिया है जिन्हें संजय गांधी के कारण टिकट मिला। इन विधायकों ने खुले रूप में मेनका गांधी का समर्थन किया हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक मायने में अकबर अहमद और मेनका गांधी ने संजय समर्थक इन विधायकों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि या तो वे गुमनामी के आलम में सदा के लिए पड़े रहे या खुल कर बाहर आये। एक वरिष्ठ इका विधायक के अनुसार इस बात में कोई संदेह नहीं कि संजय समर्थक विधायकों को दोबारा टिकट नहीं दिया जायेगा। और इसलिए आगामी चुनावों से पहले इस बात की आशंका पैदा हो जायेगी कि काफी बड़ी संख्या में इका विधायक और उन के समर्थक मेनका के झंडे के तले आवाज उठावें।

जिस शासन में पूरे प्रशासन और नीति का स्रोत केवल एक व्यक्ति हो उस प्रशासन में उस के इर्द-गिर्द सलाहकारों की मंडली में महत्वा-पूर्ण स्थानों के लिए संघर्ष स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री के सलाहकारों में भी यह संघर्ष छद्मरूप से देखा जा सकता है। श्रीमती गांधी न तो मंत्रिमंडल में और न अपने सचिवालय में अपने सलाहकारों को स्थायी रूप से स्थापित करती हैं। उन्हें बदलते रहने की नीति शुरू से ही श्रीमती इंदिरागांधी की कार्यशैली का एक हिस्सा रहा है। इसलिए एक विशेष वर्ग का प्रभावक्षेत्र यदि संजय की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। और यह भी स्वाभाविक है कि संजय के समर्थक अकबर अहमद और कुछ हद तक मेनका गांधी श्रीमती गांधी के वर्तमान सलाहकारों अरुण नेहरू और फोतेदार आदि से नफरत करते हैं।

दिल्ली और लखनऊ के सत्ता केंद्रों पर परोक्ष रूप से जो भी प्रभाव पड़े, मेनका गांधी अपनी बगावत को अन्य राज्यों तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी। यह महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के अतिरिक्त महाराष्ट्र के कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति लखनऊ सम्मेलन में सब से अधिक थी। इसलिए मेनका गांधी द्वारा पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में अपने समर्थकों के सम्मेलन आयोजित करना अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की एक सुनियोजित कोशिश है।

दो  
नि  
न  
प्र  
हुई  
के  
थी  
की  
श्रीमती  
इस्तेमाल  
कुछ  
यह  
अपने  
वरुण  
चारिक  
घटना  
यों  
वारिक  
और  
श्रीमती  
ही  
भूमिका  
प्रतिप  
पूर्वक  
कि  
उन  
LOO  
MY NE  
दिनमान



# दो गांधियाँ का एक निजी सार्वजनिक नाटक

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उन की निर्वासित बहू मेनका गांधी दो मंजी हुई अभिनयकुशल कलाकारों की तरह दुनिया के रंगमंच पर अभिनय कर रही हैं—यह टिप्पणी थी सेंट्रल हाल में एक दिल जले राजनीतिक की. "लगता है कि पिछले दो सालों से बड़ी श्रीमती गांधी जिन राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं, छोटी श्रीमती गांधी कुछ ही महीनों में उन में सिद्धहस्त हो गयी हैं." यह एक और टिप्पणी थी, सरकारी निवास से अपने बोरिया बिस्तर और दो वर्षीय पुत्र वरुण के साथ श्रीमती मेनका गांधी के अनौपचारिक, पर सार्वजनिक प्रस्थान की नाटकीय घटना पर.

यों तो यह सास-बहू का एक नितांत पारिवारिक मामला था, पर पूरे देश का ध्यान इस ओर इसीलिए गया कि इस के मुख्य पात्र श्रीमती गांधी के परिवार के लोग हैं. ये दोनों ही अखबारों और भावी पीढ़ियों के लिए भूमिकाएँ निभा रही हैं.

प्रतिपक्षी नेता इन घटनाओं पर उत्सुकता पूर्वक चर्चा करते हैं, पर वे यह भी नहीं चाहते कि उनकी बातों को कहीं उद्धृत किया जाये.

मम्मी, मेरे नये काम का कमाल तो देखो!



सत्ता पार्टी के लोग इन घटनाओं पर सार्वजनिक रूप में बात या निंदा करने से बच रहे हैं. पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी और महासचिव आदि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर सब कुछ छोड़ दिया गया है कि वे श्रीमती मेनका गांधी और उन से संबद्ध 'श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनैतिक व व्यक्तिगत स्तर पर विरोध करने वाली शक्तियों' से निपटें.

मेनका गांधी अपने आहत भोलेपन से अब भी चीख रही हैं कि 'मैं राजनीति में नहीं हूँ और न मेरी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं. फिर भी उन के लखनऊ सम्मेलन में शामिल होने की स्वर में स्वर मिला कर निंदा की जा रही है.

बाद में मेनका ने अखबार वालों को बताया, "मैं तो उस सम्मेलन में सिर्फ उन लोगों के निमंत्रण पर गयी हूँ जो मेरे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि मेरा खयाल था कि मुझे आमंत्रित कर के उन लोगों ने अपने आप को आपत्ति में डाल दिया है."

पर इस पूरे मामले में मेनका गांधी के दो व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं. एक ओर तो वह क्रुद्ध और आहत हैं तो दूसरी ओर नम्र और सहयोग के लिए तत्पर. उन्होंने साफ साफ आरोप भी लगाये कि 'मेरे पति संजय गांधी की मृत्यु के बाद' से ही किस तरह श्रीमती गांधी उन के साथ दुर्व्यवहार करती रही हैं फिर भी वह अपने परिवार, गांधी परिवार के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहना चाहती. एक अखबार वाले को उन्होंने बताया कि श्रीमती गांधी ने उन्हें जो पत्र लिखा था उस का जवाब देते हुए उन्होंने पहली पंक्ति में यही लिखा कि 'मैं भी एक गांधी (परिवार की

सदस्य) हूँ, जैसा कि आपने भी मुझे लिखे अपने पत्र में लिखा है.' पर साथ ही मेनका ने श्रीमती गांधी को जो गुस्सेभरा पत्र लिखा उस की प्रति अगले दिन अखबार वालों को दे दी.

दोनों के पास अपनी-अपनी कार्यवाहियों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए तर्क भी तैयार हैं. इस में किसी तरह का भावनात्मक आवेग नहीं है बल्कि सोच समझ कर कदम उठाये जा रहे हैं. क्योंकि उन के खयाल से घटनाक्रम के आगे बढ़ने के साथ साथ पारिवारिक संबंधों में दरार गहराती जायेगी. अगर वे गुस्से में आ जाती हैं तब भी वे सचेत खिलाड़ियों की तरह स्वर पर नियंत्रण रखती हैं ताकि पूर्वानुमान करते हुए अगली चाल के लिए अपने को तैयार रख सकें.

कुछ लोग मेनका के प्रति सहानुभूति का वातावरण तैयार करने के लिए चिल्ला रहे हैं कि एक जवान विधवा को आधी रात उस के वैध घर से निकाल दिया.

श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था. मला अपने ही घर से अपने तथा पार्टी के विरोध में होने वाली गतिविधियों को कैसे चलने दे सकती थी? यह तर्क था एक कांग्रेसी नेता का. एक दूसरे नेता का कहना था कि जर्मन चांसलर विली ब्रांट का क्या हाल हुआ था जब उन का एक निजी सहायक पकड़ाई में आया था. एक और कांग्रेसी का सवाल था कि आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का कोई और भी उद्देश्य हो सकता है? वह दरअसल दूसरों को नहीं, अपने ही अंतःकरण को समझाने की कोशिश कर रहे थे.

क्या लखनऊ सम्मेलन या उस में मेनका की उपस्थिति इतनी स्वाभाविक और निश्चल थी, जैसा कि मेनका गांधी और उन के प्रशंसकों का दावा है? यह श्रीमती इंदिरा गांधी और उन की राजनीतिक योजनाओं का सोच विचार कर चालाक ढंग से किया गया विरोध था. मेनका गांधी को राजनैतिक अस्तित्व में लाने के लिए यह जो दुस्साहसी दांव लगाया गया है, वह इंदिरा गांधी के क्रोध को निमंत्रण देने का ही काम था. इस नाटक की पूरी पटकथा उस घटना में से ली गयी है जब जून 1969 से पहले की नम्र और असहाय श्रीमती इंदिरा गांधी एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो गयी थीं.

जून 1968 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बेंगलूर अधिवेशन से पहले वे असहाय थीं और कई शक्तिशाली पार्टी प्रबंधकों के प्रभुत्व में थीं. वे लोग सोचते थे कि उन्हें कभी भी चलता कर देंगे. जब बेंगलूर में उन्होंने अलग तरह के विचार रखे और एक तरह का दांव लगाया तो पार्टी के प्रबंधक नाराज हो गये. पर यह दांव चल गया और वह एक सर्वशक्तिमान तथा निर्विवाद नेता बन गयीं.



तब उन्होंने तथा उन के आयोजकों ने हर चाल का अनुमान लगा लिया था और उन के जवाब के लिए भी तयारी कर ली थी। उन्हें अपने विरोधियों की ताकत तथा कमजोरी का पता था और कमजोरी का उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया।

मेनका गांधी को "उस घर में जितने अपमान और शारीरिक व मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा उसे कोई भी इन्सान सहन नहीं कर सकता। मैं फिर कहूँगी, कोई भी इन्सान सहन नहीं कर सकता। जैसे ही संजय की मृत्यु हुई, अपने हर संभव तरीके से मुझे यंत्रणा देना शुरू कर दिया था।" यह उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम लिखे अपने पत्र में लिखा। अगर उन के साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहा था तो फिर वे अपनी सास के इन कृत्यों का विरोध करने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करती रहें। यह एक सवाल हो सकता है। अपने राजनैतिक अस्तित्व के दावे का दुस्साहसी दांव जो उन्होंने लगाया है, उस के लिए यही समय क्यों चुना गया, यह सवाल भी यहीं से निकलता है, इस से यह माना जा सकता है कि उन का सम्मेलन में भाग लेने अपने पति के उस मित्र की सहायता करने का मासूम निर्णय नहीं था जिस ने उन्हें आमंत्रित कर के अपने को कठिनाइयों में डाल दिया था। न इस से उन के राजनैतिक इरादे न होने की बात ही सिद्ध होती है।

दोनों में से किसी भी कलाकार ने तब इस की खबर न होने दी जब अकबर अहमद द्वारा बुलाये गये सम्मेलन पर बातचीत हुई और उस पर असहमति प्रकट की गयी। फिर भी 26 मार्च को जिस कारखेट पार्क से श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम लिखे अपने पत्र में मेनका ने दावा किया है कि वे मेनका को किसी निर्णय पर पहुँचने में कोई मदद नहीं दे रही हैं।

मेनका ने श्रीमती इंदिरा गांधी के ब्रिटेन के एक हफ्ते के दौरे से लौटने से तीन दिन पहले ही घर छोड़ दिया था। सम्मेलन में भाग लेने के उन के निर्णय को 26 मार्च को श्रीमती गांधी के वापस लौटने से एक दिन पहले प्रकाशित किया गया। 26 मार्च को हालाँकि मेनका जिस कार्वेट पार्क में भविष्य को योजनाएँ बना रही थीं, पर उन के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र उसी दिन दोपहर बाद नहीं दिल्ली में बाँटा जा रहा था, पार्क में ही श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम लिखा गया उन का पहला पत्र अगले दिन सुबह लखनऊ के अखबार वालों तक पहुँच गया था। हालाँकि तब तक वह श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं मिला था। मेनका ने अनुमान लगा लिया था कि वे अब जल्दी ही घर छोड़ देंगी। दरअसल वह तो यह सोच रही थी कि सम्मेलन खत्म होने के बाद लखनऊ से लौटने पर उन के लिए प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे ही नहीं खुलेंगे। तब लिये एक गाड़ी भी तैयार रखी गयी थी ताकि उन के लिए प्रधानमंत्री निवास के

दरवाजे न खुलने पर उस का उपयोग हो सके।

श्रीमती इंदिरा गांधी के सलाहकार चाहते थे कि राज्यसभा के चुनाव, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निपट जायें, फिर वह मेनका से घर छोड़ने के लिए कहें। इस का पहले से अनुमान था, मेनका के अपने एक मित्र को दिये संकेतों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, उन्होंने अपने एक मित्र जे. डी. सिंह से रात नौ बजे प्रधानमंत्री निवास से आने के लिए कहा था। वह जानती थी कि देर रात से पहले वे घर नहीं छोड़ेंगी। सारी नाटकीय चालें तय कर ली गयी थीं और पूर्वाम्यास भी कर लिया गया था।

प्रधानमंत्री निवास छोड़ने के बाद मेनका रात में अपनी माँ के घर नहीं गयीं। उन्होंने एक होटल में ठहरना बेहतर समझा जो दिन में पहले ही उन के लिए किराये पर ले लिया गया था। अगले दिन उन्होंने बताया कि अपनी माँ के साथ न ठहरने का उन का निर्णय एक पारंपरिक हिंदू विवाहिता का निर्णय था जिस के लिए "विवाह के बाद माँ का घर अपना नहीं रह जाता।"

मेनका इस समय एक ऐसी असहाय स्त्री की भूमिका निभा रही है जिसे घर से निकाल दिया गया है और जो एक घर की तलाश में है। महारानी बाग में तीन कमरों का एक एक-मंजिला मकान एक महीना पहले ही सज्जित कर दिया गया था। इसे संजय गांधी ने उन्हें उपहार के रूप में दिया था। पिछले कुछ महीनों से अकबर अहमद इस में रह रहे थे, पर उन्होंने वहाँ जाना भी पसंद नहीं किया। उन के मुँह से निकलने वाला एक-एक शब्द, लिखा गया एक-एक वाक्य और एक-एक कदम पहले से ही सोच-समझ कर तय कर लिया गया था ताकि उस का अधिकतम मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया जा सके। इंदिरा गांधी खेमा भी लगता है इस का पूर्वानुमान लगा चुका है और हर चाल की काट उस के पास तैयार रखी है।

मेनका के पीछे किस का दिमाग काम कर रहा है? यह सवाल कई दिमागों में कुलबुला रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इस नाटक की पटकथा सिर्फ अकबर अहमद ने तयार की हो। कांग्रेसी नेता इस नाटक के पीछे बहुगुणा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ बता रहे हैं। पर इस नाटक के लिए जितनी प्रतिभा की जरूरत है उतनी बहुगुणा या कुल मिला कर रा. स्व. सं. के पास भी कम पड़ेगी! कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि इस के पीछे बंबई से कोई हाथ है जो मेनका गांधी को प्रकाश में लाने के लिए लखनऊ भी आया था। अब तो यह भविष्य ही बता पायेगा कि "जनता के बीच इस निजी नाटक" को सफलतापूर्वक खेलने के पीछे किन कलाकारों, तकनीशियनों और किस निर्देशक का दिमाग और चालाकी काम कर रहे थे।

## राजनैतिक दल

### चरणसिंह का संन्यास



विपक्षी दलों में एकता स्थापित करने के प्रयास में अनेक अवरोधों का मुकाबला करते हुए लोकदल अध्यक्ष चौधरी चरणसिंह अंत में इस नतीजे पर पहुँच गये हैं कि राजनीति उन के काबू से बाहर हो गयी है। जिस समय जनता पार्टी के कार्यालय में देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर सहित अनेक लोकदल नेता राजनैतिक एकता की रूपरेखा पर बहस कर रहे थे उसी समय चौधरी चरणसिंह ने अपने घर से सक्रिय राजनीति से पूर्ण संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। चौधरी साहब फिलहाल लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे।

अपने वयान में उन्होंने कहा है, "अवकाश ग्रहण करते समय मुझे इस बात का अफसोस बना रहेगा कि यद्यपि राजनैतिक स्वतंत्रता को 35 वर्ष हो गये फिर भी उन में से कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाया जो मेरी पीढ़ी के ऐसे लोगों के मन में अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए पनपे थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस के विपरीत हमारे राजनैतिक तंत्र में, विशेष रूप से 1980 के बाद नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, और आर्थिक क्षेत्रों में गंभीर विकार पैदा हो गये हैं—ऐसे विकार जो राष्ट्र के मूल तत्त्वों को ही नष्ट कर रहे हैं।"

इस संदर्भ में चरणसिंह से बातचीत के बाद क्षितींद्रमोहन श्रीवास्तव लिखते हैं—

6 अप्रैल को शाम लगभग चार बजे जब जनता पार्टी के कार्यालय में हरियाणा के भूत-पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवीलाल संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, दो संवाद समितियों के कार्यालयों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह के निवास से फोन किया गया। "जरूरी न्यूज है तुरंत आ जाइये।"

पहुँचे। भव्य बैठक में सोफे पर बिठाया मया। सामने दीवार पर भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। दूसरी संवाद समिति के संवाद-



दाता की प्रतीक्षा थी। वे भी आये और हमें बरामदे में होकर एक छोटे कमरे में ले जाया गया। जूते उतार कर हम लोग जब कमरे में पहुँचे तो चौधरी साहब को अपने परिवार के सदस्यों और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठा पाया। स्त्रियाँ एक ओर, पुरुष दूसरी ओर।

श्री चरणसिंह लकड़ी की एक पीठिका के पीछे बैठे थे। हमारे पहुँचते ही वे मुस्कराये और एक फाइल खोल कर उन्होंने कहा, "एक छोटा सा वयान है। पर दो ही कापियाँ हैं।"

हमारा अनुमान था कि श्री चरणसिंह अवहेलना करने वाले पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की घोषणा करेंगे। कोई 'कारण बताओ' नोटिस होगा, या निलंबन का आदेश होगा। पर वयान में ऐसा कुछ नहीं था। वयान में था सक्रिय राजनीति से संन्यास।

आप ने यह फैसला क्यों किया? क्या पार्टी के लोगों की माँग थी?

"नहीं, कोई दबाव नहीं था और न कोई माँग थी। अपनी मर्जी से किया है"। श्री चरणसिंह ने कहा। बगल में बैठी उन की पुत्री ने इस बात की पुष्टि की और सबूत के तौर पर अप्रैल 1980 का एक पत्र दिखाने लगी। चौधरी साहब ने उन्हें रोक दिया— इस की कोई ज़रूरत नहीं, वयान में सब है।

क्या आप लोकसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र देंगे?

"नहीं, मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन से नहीं। अभी दूसरे कामों में फँसा होने के कारण मैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाता था अब लिया कहूँगा। पार्टी के पदों से हट जाऊँगा।"

कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे?

"हाँ, किसान ट्रस्ट का काम देखूँगा।"

क्या आप सोचते हैं कि आप के हट जाने से विपक्ष की एकता हो जायेगी?

"जो बच जायेंगे, तय करें।"

आप तो श्री जगजीवनराम के साथ मिल कर काम करने वाले थे?

"नहीं, छापने वालों ने गलती की है। उन के सेक्रेटरी का पत्र आया था कि मैं उन के जन्म-दिवस के कार्यक्रम में भाग लूँ। मैंने स्वीकृति दे दी और इसलिए मैं गया भी। इस से अधिक कुछ नहीं था।"

पुत्री ने बताया।

"चौधरी साहब किताब लिख रहे हैं।"

विषय क्या है—आत्मकथा या आर्थिक नीति?

"नहीं, नहीं, अभी सोच रहा हूँ।"

चौधरी साहब के सोच का क्या नतीजा निकलेगा यह देखना अभी शेष है क्योंकि कुछ लोग तो इसे अभी एक विशेष शैली भर मानते हैं या फिर पार्टी के भीतर के कलह में उन की एक समर नीति।

विनमान,

## व्यक्तिचित्र

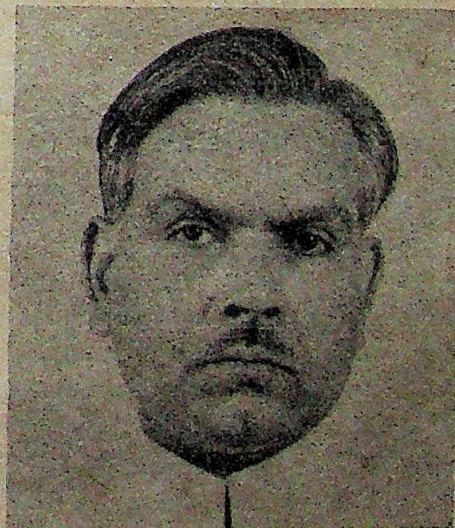
# 'मुझ में पढ़ने का ऐब है'

—के. नटवर सिंह

कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के. नटवर सिंह की विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राष्ट्रकुल विभाग के सचिव पद पर नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। युद्ध वर्जन संधि की वातचीत के पाकिस्तान के राजनैतिक उद्देश्यों को जानने और उस में गतिरोध पैदा हो जाने के बावजूद शांति और सहअस्तित्व की इच्छुक भारत सरकार रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। उस प्रयत्न को सही दिशा देने के लिए व्यापक और गहरी राजनयिक सूझबूझ वाले ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो समस्याओं और मुद्दों की वारीकियों तथा पाकिस्तान के जनमानस और सैनिक शासक दिमाग की समझ रखता हो। भारतीय विदेश सेवा के 29 वर्षों में के. नटवर सिंह ने पीकिङ, पोलैंड और पाकिस्तान से ले कर लंदन, वाशिंगटन और संयुक्तराष्ट्र में विभिन्न पदों पर काम किया है।

अनुभव और कार्य की सूची बहुत लंबी है। खास बात यह है कि उन की क्षमता और योग्यता पर प्रधानमंत्री को यकीन है। भारत-पाक संबंधों के इतिहास के एक नाजुक दौर में विदेश मंत्रालय में उन की नियुक्ति उन के लिए एक चुनौती भी है।

लेकिन श्री सिंह के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी है जिस का संबंध विदेश मंत्रालय के दोस्तों द्वारा प्रशंसा की उलटबासी शैली में उन्हें 'शिक्षितों के बीच अर्द्धशिक्षित' रूप में संबोधित करने से है। यानी 'अर्द्धशिक्षित' नटवर सिंह विदेश सेवा की व्यस्तताओं के बावजूद साल भर में कम से कम सौ पुस्तकें



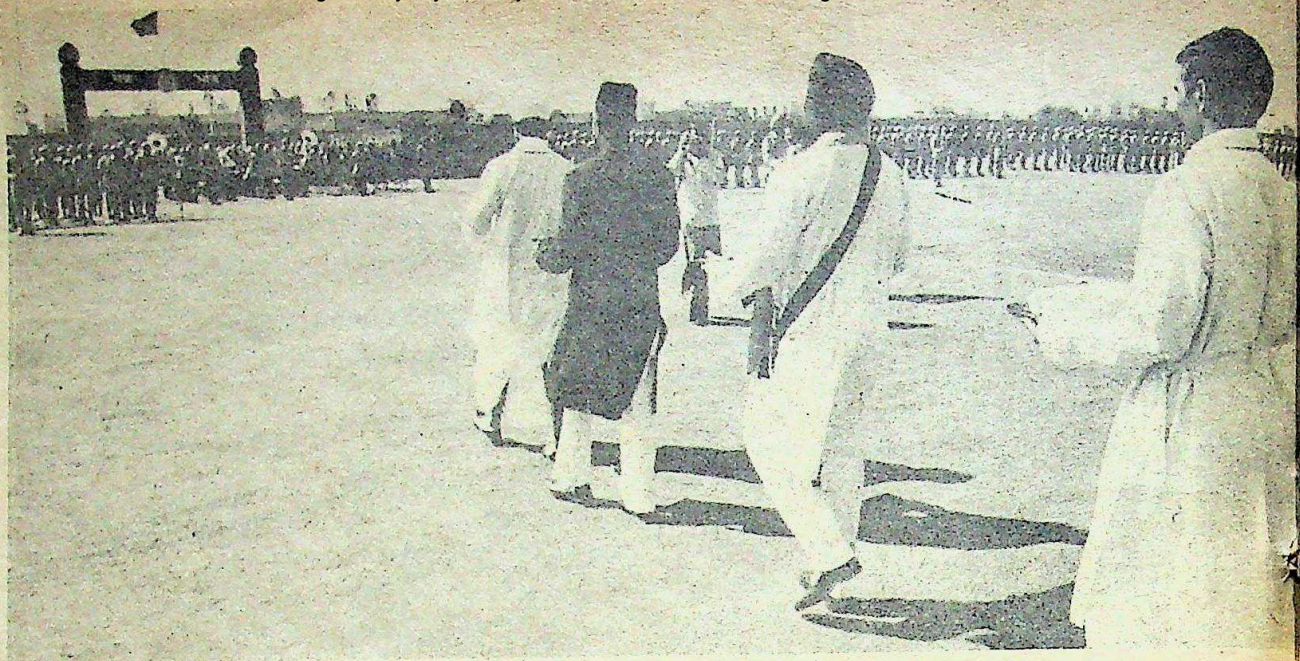
पढ़ लेते हैं। 6 हजार से अधिक किताबों का उन का अपना संग्रह है। "ऐब और तरह के हो सकते हैं लेकिन सिगरेट, शराब और दावत-पार्टी का शौक नहीं है। जो दावत पार्टी अनिवार्य है उसे तो देखना ही है लेकिन आमतौर पर 12-1 वजे तक चलने वाली पार्टियों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। दूसरा दिन भी खराब हो जाता है। मैं उस वक्त का इस्तेमाल पढ़ने में करता हूँ।"

'कंपलसिव रीडर' श्री सिंह ई.एम. फोरस्टर : ए ट्रिब्यूट (न्यूयार्क 1964) द लिगेसी आफ नेहरू (न्यूयार्क 1965) टेल्स फ्रॉम माडर्न इंडिया (न्यूयार्क 1966, ओस्लो 1967, मिलान : 1968 और वारसा : 1972), स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, (लंदन : 1971) और महाराजा सूरज मल (1707-1763) : हिज लाइफ एंड टाइम्स (लंदन 1981) शीर्षक पुस्तकों के रचयिता हैं। महाराजा सूरज मल एक बृहद शोध ग्रंथ है जो उन की ऐतिहासिक सूझबूझ का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इन दिनों 'आफ डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेट्स' एशिया, अफ्रीका और तीसरी दुनिया के विदेश सेवा के आकांक्षी युवकों को ध्यान में रख कर लिख रहे हैं।

'द लिगेसी आफ नेहरू' की रायल्टी नेहरू स्मारक निधि को अर्पित कर एक विशेष संतोष का अनुभव करने वाले श्री सिंह की पढ़ने लिखने में दिलचस्पी तो बचपन से ही थी। सेंट स्टीफेंस, दिल्ली से प्रथम श्रेणी में बी.ए. (ऑनर्स) करने के बाद केंब्रिज (1952-74) जाने पर पेंसेज टु इंडिया के प्रसिद्ध लेखक ई. एन. फोरस्टर से मुलाकात हुई। 'उन के व्यक्तित्व का, पुस्तकों का बहुत असर मन पर पड़ा। न्यूयार्क में राजाराम, शांताराम आदि के साथ उन पर एक किताब लिखने का फैसला हुआ। मुल्कराज आनंद और अहमद अली ने भी लिखा। वह किताब बहुत कामयाब हुई। 40-50 अच्छी समीक्षाएँ छपीं। भारतीय कहानियों के संग्रह भी बहुत कामयाब हुए। उस का प्रकाशन, नार्वे, इटली, इंग्लैंड और भारत में हुआ। मद्रास विश्व-विद्यालय ने उसे पाठ्यक्रम में रखा। '25 वर्षों से न्यूयार्क टाइम्स, सेंटडॉरिव्यू, सेंडे टाइम्स, न्यू स्टेट्समैन, फाइनेंशियल टाइम्स तथा भारत के टाइम्स आफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में समीक्षाएँ लिखता आ रहा है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा लेखक हूँ लेकिन सजग हूँ। कहान, कि पढ़ने का शौक है। उस के बगैर नहीं रह सकता। चीनी भी जानता हूँ। एक साल पीकिङ विश्वविद्यालय में पढ़ा था। हमारी प्रधानमंत्री भी बहुत पढ़ती हैं। जब कभी विदेशों से आता हूँ उन के लिए भी कुछ किताबें ज़रूर लाता हूँ।'



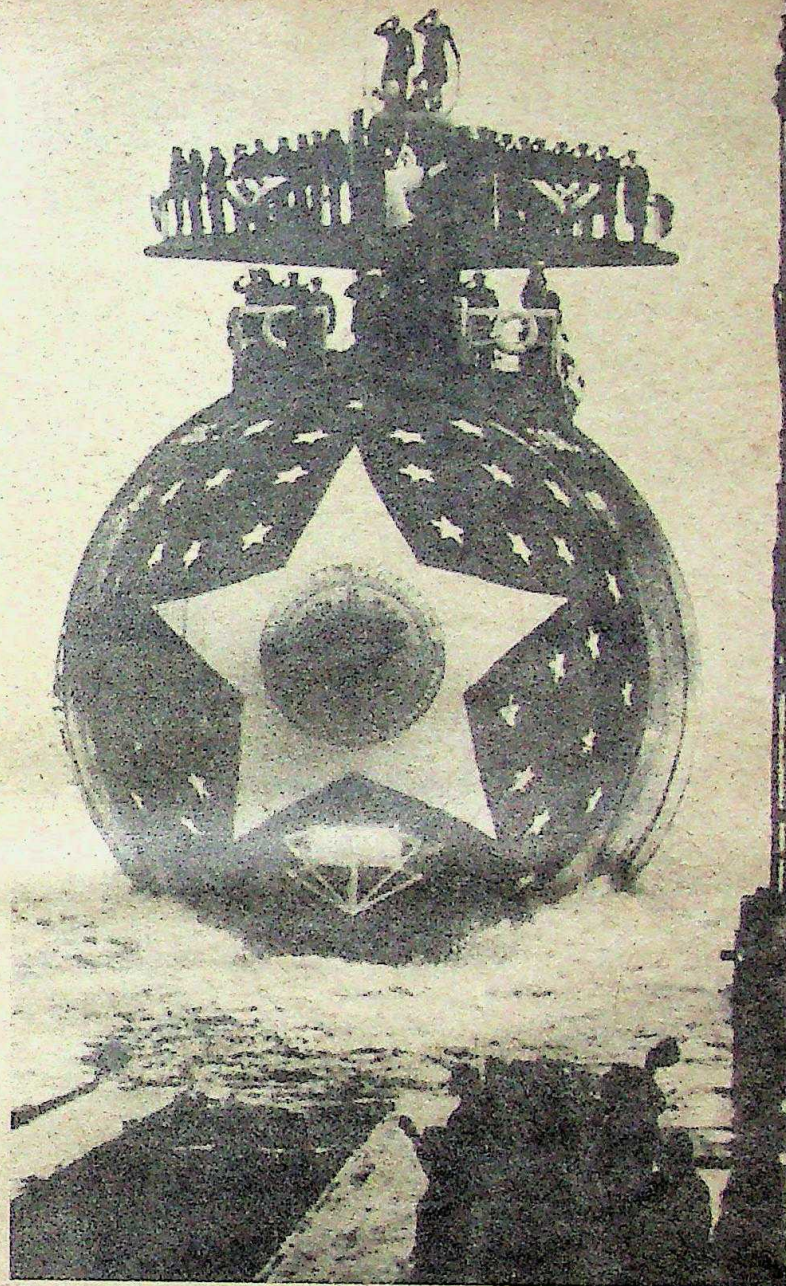
# विश्वों के आईने में



(ऊपर) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की तीन विशिष्ट बटालियन, विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों के समय शांति स्थापित करने के लिए, गठित की गयी हैं। इन में से एक बटालियन को कर्म निष्ठा की शपथ दिलाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और मसीही धर्मगुरु अग्रसर हो रहे हैं। (बीच में बायें) नकली दवाइयों का एक कारखाना 25 मार्च को दिल्ली की गांधीनगर बस्ती में पकड़ा गया। फी घंटे 5000 गोलियाँ और कैस्पूल बनाने वाली एक विद्युत चालित मशीन तथा ढेरों नकली दवाइयाँ दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बरामद कर लीं। (बीच में दायें) नागरिक अधिकार रक्षा समिति (पी. यू. सी. एल.) और अंग्रेजी पत्रिका 'इंडिया टुडे' द्वारा सम्मिलित रूप से दिये गये 'मानवाधिकार के लिए पत्रकारिता' पुरस्कार के विजेता स्वामी त्रिवेदी। मध्यप्रदेश के इस युवा हिंदी पत्रकार को सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी अच्युत पटवर्धन के हाथों पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला। (दायें) नकल कर के परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करने वालों में दिल्ली का यह छात्र भी है, जिस की सख्त गतिविधियों के कारण जब उसे स्टेटर उतारने के लिए मजबूर किया गया तो नीचे कमीज पर जीवविज्ञान की किताब के पन्ने सिले हुए थे।







(ऊपर बायें) युर्दान नदी के पश्चिमी तट पर स्थित इस्त्राइल अधिकृत नेबलस क्षेत्र का रोता बिलखता स्थानीय युवक इस्त्राइली हवाबाज के कब्जे में. इस का कसूर था कि यह इस्त्राइली सैनिकों पर पत्थर बरसा रहा था. (बीच में बायें) इटली में अमेरिकी सेनानायक डोजियर के अपहरण के मुकद्दमें में अभियुक्त 'रेड ब्रिगेड' के सदस्य सजारा दि लोनार्वो और अलबर्तो बिलियातो, मुकद्दमें के फंसले की इंतजार में, अभियुक्त कक्ष में सैंडविच खाते रहे. उन्हें क्रमशः 27 और 17 वर्ष की सजाएँ सुनायी गयीं. गत वर्ष 17 दिसंबर को जनरल डोजियर को गायब कर दिया गया था और इस वर्ष 28 जनवरी को इटली की पुलिस ने उन्हें मुक्त कराया. (बायें) 'हरित शांति' (ग्रीन पीस) संगठन के सदस्यों द्वारा चलाये गये 'सील बचाओ' अभियान के दौरान कनाडा की पुलिस ने नीदरलैंड के जोस बॉन ह्यू मान को गिरफ्तार किया, क्योंकि उस ने एक शिशु सील मछली को हरे रंग से रंग दिया था. इस संगठन के सदस्य सील की नस्ल को खत्म होने से बचाना चाहते हैं, जिस के लिए वे शिशु सील पर रंग छिड़क कर उन्हें बिक्री के लिए बेकार कर देते हैं. (ऊपर) अमेरिका की सब से आधुनिक तत्क्षण आक्रमण करने वाली पनडुब्बी 'यू. एस. अलबूकर्क' को जब पानी में छोड़ा गया तो उस के कमियों ने हाथ हिला कर उस की यात्रा शून्य होने की कामना की.



प्रदेश

आंध्रप्रदेश

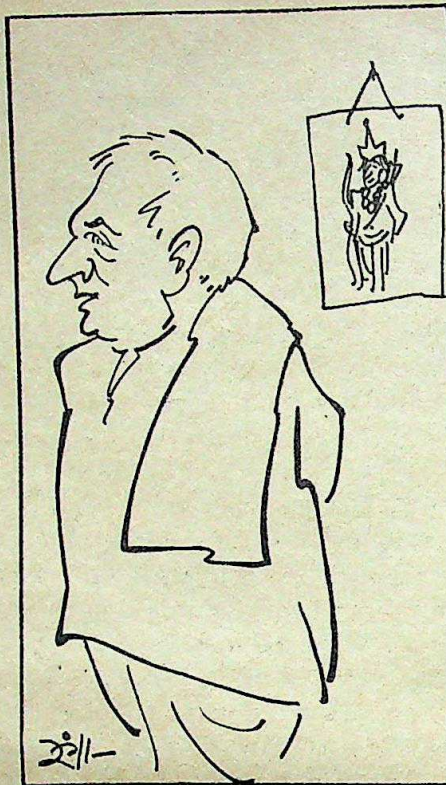
## ‘तेलुगू देशम’ के पीछे कौन लोग हैं

यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है कि तेलुगू फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता एन. टी. रामाराव ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया और ‘तेलुगू देशम’ के नाम से एक क्षेत्रीय राजनैतिक दल का गठन भी कर लिया है। उधर श्री अंजैया ने भी एक पंचायती संगठन के माध्यम से समाज सेवा करने की घोषणा की है। साथ ही पाँच इंचा विधायकों ने इंचा पर पिछड़े वर्गों की भलाई न करने का आरोप लगाते हुए दल से इस्तीफा दे दिया है। लगभग एक साथ घटी इन घटनाओं ने इंचा आला कमान में हलचल मचा दी और इस स्थिति से निजात पाने के लिए अब मई में आंध्रप्रदेश में भी मध्यावधि चुनाव कराये जाने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है।

गत दो वर्षों से इस बात की संभावना प्रकट की जा रही थी कि आंध्र में क्षेत्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन की स्थापना होगी। नये संगठन के निर्माण की प्रेरणा तमिऴनाडु से मिली है।

आंध्रप्रदेश में इंचा पर ऐसे लोगों का अधिकार है, जो वस्तुतः यहाँ की उपजाऊ भूमि के मालिक हैं। जमीन के बँटवारे के लिए यहाँ जितने प्रयास हुए हैं, उन्हें कांग्रेस पर अधिकार रखने वाले लोगों ने सदा विफल बनाया है। कांग्रेस के ही कुछ प्रभावशाली लोग यह अनुभव करते रहे हैं कि जब कभी उन का संगठन प्रगतिशील रुख अपनाये तब प्रदेश में एक ऐसा संगठन हो जो जमींदारों और समृद्ध लोगों की सहायता से सत्ता पर अधिकार कर ले। एन. टी. रामाराव के नये संगठन के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, उन से प्रदेश के लोग अपरिचित नहीं हैं। इंचा प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करते हुए भी सदा इस बात की कोशिश करती रही कि कृष्णा-गोदावरी क्षेत्र में बसने वाले समृद्ध जमींदार उस से अलग न हो जायें। अब तक यदि तमिऴनाडु की तरह आंध्र में क्षेत्रीय राजनैतिक संगठन नहीं बन सका तो उस का कारण समृद्ध जमींदारों का यह भय रहा है कि कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों के लोग हावी न हों और साम्यवादी दल सर्वहारा की सहायता से उन के विरुद्ध अपना अभियान और तेज न कर दे।

श्री अंजैया के त्यागपत्र के पीछे जो तत्त्व काम करते रहे, उन पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ा है, वास्तविकता यह थी कि इंचा आला



एन. टी. रामाराव

कमान अंजैया जी के खुलेपन या यों कहिए भोलपन से जितना परेशान थी, उस से अधिक परेशानी उसे दंग व्यक्तित्व के घनी कोना प्रभाकर राव से थी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते अनुशासन मंग करने वाले कांग्रेसियों को दुस्त करने पर तुले हुए थे। जिला परिषदों तथा विधान परिषद् के चुनाव में जिन कांग्रेसियों ने दल के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध किया था, उन्हें कोना प्रभाकर राव ने तो कांग्रेस को प्राथमिक सदस्यता से निर्वित कर दिया। इस प्रक्रिया में जो लोग दल से निर्वित किये गये उन में अंजैया मंत्रिमंडल के सदस्य सी. दास और चंद्राबाबू नायडू भी थे।

श्री चंद्राबाबू नायडू, एन. टी. रामाराव के दामाद हैं। सी. दास चंद्राबाबू के साथ अपने गुट के लोगों के लिए इंचा के अनुशासन को धता बताते रहे। जब श्री वेंकटराम के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना तो प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में भी फेरबदल कर दिया गया। कोना प्रभाकर राव वित्तमंत्री बनाये गये और सी. दास प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। इंचा आला कमान को शायद अनुशासन पसंद नहीं था। तभी तो सी. दास प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए और चंद्रा बाबू नायडू मंत्रिमंडल में बहाल किये गये। कोना प्रभाकर राव ने जो अनुशासनात्मक कार्रवाईयाँ कीं, उन्हें सी. दास ने निरस्त कर दिया। बड़े जमींदारों के सामने इंचा ने जल्दी ही हथियार डाल दिये।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सी. दास को प्रदेशाध्यक्ष बना कर जिस वर्ग के समर्थन की आशा की गयी उस वर्ग का ध्यान मुख्यमंत्री के चयन में भी रखा गया। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वेंकटराम अभिनेता एन. टी. रामाराव के सहपाठी रहे हैं। शपथ-ग्रहण के दिन मुख्यमंत्री श्री रामाराव को अपने साथ ले गये थे।

एन. टी. रामाराव आंध्रप्रदेश के सब से अधिक ऐश्वर्यशाली लोगों में गिने जाते हैं। शहर के सब से महँगे वावर आविद रोड पर उन की करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति है। 1947 में उन्होंने फिल्मों में अभिनय शुरू किया था। तेलुगू भाषी जनता विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, अर्जुन आदि देवता तथा महा-पुरुषों की छवि एन. टी. रामाराव के चेहरे में देखती रही है। यदि वह कहीं खड़े हों तो अनायास हजारों लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि राजनैतिक मंच पर आने से लोग उन से अधिक आकर्षित होंगे, उन्हें इस बात की शायद कल्पना नहीं है कि आंध्र तमिलनाडु की तरह फिल्म अभिनेताओं को स्नेह तो दे सकता है किंतु विश्वास नहीं। —श्रीराम शर्मा

बिहार

## अंधूरे पुल का उद्घाटन क्यों कराया गया

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब पटना के निकट गंगा पर बने दुनिया के सब से लंबे (5,575 मीटर) महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन करने गयीं तो उन्हें यह खबर जरूर रही होगी कि वह उस पर होकर नदी पार नहीं कर सकेंगी। फिर भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से आधे अंधूरे पुल का उद्घाटन किया, भले ही इस के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को फटकारा हो।

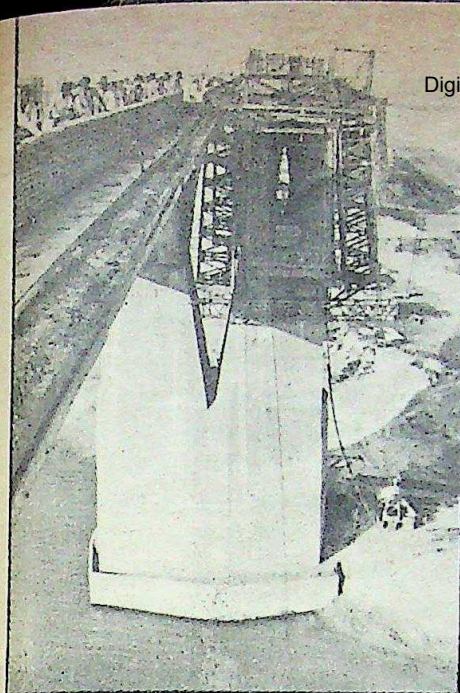
यद्यपि 19 मार्च को हल्के वाहनों के लिए और 30 मार्च को भारी वाहनों के लिए भी यह पुल खोल दिया गया, लेकिन इस का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वह अब भी निर्माणाधीन है। 19 मार्च को जब पुल खोल कर मुख्यमंत्री ने 2 मार्च को दिया गया अपना वचन पूरा अवश्य किया किंतु विशेषज्ञों की नजर में यह पुल अभी यातायात के लायक नहीं है।

सच तो यह है कि पुल की पूरी परियोजना और अतीत विडंबनाओं से भरा है। बिहार सरकार ने 15 जून 1969 को वर्तमान सेतु

(ऊपर)  
रेलिंग  
अभिकों

स्थल से  
गंगा पुल  
की अनु  
दी थी।  
और दो  
समय य  
पर अल  
पुलों के  
था। ले  
के अच्छे  
इस योज  
वाद में  
समिति  
पूर्वस्थल  
गया। य  
लाख रु  
19 जून  
उसी दि  
वाग में  
वाद 10  
योजना  
गैमन ई  
कि 18  
हो जाये  
और रा  
पुल नि  
प्रतिवेदन  
रहित वि  
रंग लाय  
विभाग  
सब एक  
पुनरीक्ष  
का और  
46 करे  
विनमान





(ऊपर) अधूरा निर्माण कार्य और कच्ची रेलिंग (ऊपर दायें) निर्माण कार्य में मृत 16 श्रमिकों के कुछ परिजन जिन्हें 10-10 हजार रु० दिये गये.

स्थल से 16 किलोमीटर पूर्व संभलपुर के पास गंगा पुल निर्माण के लिए 25 करोड़ 40 लाख की अनुमानित रकम की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी. यहाँ पर गंगा दो धाराओं में विभक्त है और दोनों के बीच राधोपुर दिया है. उस समय योजना बनायी गयी कि दोनों धाराओं पर अलग अलग दो पुलों का निर्माण कर दोनों पुलों के बीच दिया रा में सड़क बनाने का प्रस्ताव था. लेकिन 69 की बाढ़ में राधोपुर दिया रा के अच्छे खासे हिस्से को काटते हुए गंगा ने इस योजना का स्वप्न भी भंग कर दिया. बाद में बिहार विधान परिषद की 15 सदस्यीय समिति ने वर्तमानस्थल को उपयुक्त माना. पूर्वस्थल की तुलना में यह सस्ता भी माना गया. यहाँ अनुमानित व्यय 23 करोड़ 50 लाख रु. आँका गया. इसे बिहार सरकार ने 19 जून 1970 को स्वीकृति दी—और उसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुलजार बाग में पुल का शिलान्यास किया. दो वर्ष बाद 10 मई 72 को पटना गंगा पुल परियोजना के मुख्य पुल के निर्माण का ठेका गैमन इंडिया को इस शर्त के साथ दिया गया कि 18 जून, 78 तक निर्माण कार्य समाप्त हो जायेगा. इस के बाद समाप्ति की तिथि और राशि दोनों बढ़ती गयीं. पटना गंगा पुल निर्माण संबंधी विधानसभा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 'इकरारनामे में सीमा रहित विस्तार का प्रावधान था. यह प्रावधान रंग लाया. गैमन इंडिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के रंग बदल गये—सब एक रंग हो गये. इकरारनामे के तुरंत बाद पुनरीक्षित प्राक्कलन 36 करोड़ 53 लाख रु. का और 1978 में तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन 46 करोड़ 47 लाख रु. का बनाया गया

विनयाने



और समाप्ति की तिथि 31 दिसंबर 81 तय की गयी.

बिहार विधानसभा की यह तीन सदस्यीय समिति 24 अप्रैल 81 को गठित की गयी थी. कारण था लोकदल विधायक मुंशीलाल राय द्वारा 15 दिसंबर 80 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिस पर एक लंबा विवाद छिड़ा. विवाद का अंत इस सीमिति के गठन से हुआ, जिस में मुंशीलाल राय के अतिरिक्त कांग्रेस (इं) के विधायक संकटेश्वरसिंह और सरयू मिश्र का मनोनयन अध्यक्ष राधानंदन झा ने किया. बिहार राज्य वित्तीय निगम के अध्यक्ष सरयू मिश्र समिति के संयोजक थे. समिति का प्रतिवेदन पुल की विडंबनाओं का दस्तावेज है. समिति को निम्नलिखित जाँच का कार्य सौंपा गया था :

● गंगा पुल की सामग्री और संयंत्रों का

इस्तेमाल दूसरी जगह किया जा रहा है.

● जो हाइड्रेशन स्टील वायर खरीदा गया है, उस के संबंध में 5 लाख रुपये से अधिक भुगतान किया गया है या नहीं,

● प्रथम प्राक्कलन 23 करोड़ 50 लाख रुपए का था, वह किस परिस्थिति में 36 करोड़ और पुनः 46 करोड़ रु. से ऊपर हो गया.

● अधिसूचना में अंकित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव.

● जाँच के क्रम में उत्पन्न अन्य बिंदुओं पर हुए वाद विवाद की तिथि 20 दिसंबर 80 तक गंगा पुल का कार्य कितना प्रतिशत हुआ.

समिति का अपना प्रतिवेदन गठन के बाद होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करना था. लेकिन समिति ने प्रतिवेदन अध्यक्ष को 22 मार्च 82 को दिया. समिति की विडंबना यह रही कि उस के प्रतिवेदन प्रस्तुति के पूर्व ही गंगा पुल का उद्घाटन हो चुका था.

## हरयाणा

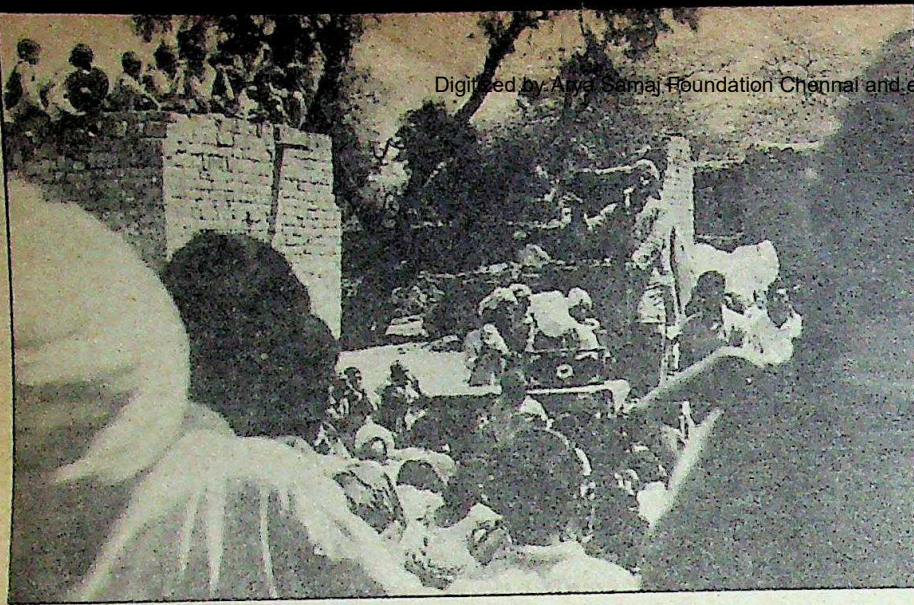
### चरित्रहीनता से बचो

हरयाणा के 20 हजार आबादी वाले उस बड़े गाँव फरमाणा की आबादी को देखते हुए वह सभा 'बड़ी' नहीं थी. लगभग 1 हजार लोग गाँव के एक किनारे मैदान में जमा थे और मंच पर कुछ भगवा कपड़े पहने हुए वृद्ध, सादे कपड़े पहने हुए जवान और उस गाँव के बुजुर्ग बैठे हुए थे. कई मायनों में यह एक अनोखी सभा थी. भाषण और बीच बीच में भजन तथा रागनियों की तर्ज पर गीत—उन को सुनते हुए लोग जैसे सभा के उद्देश्य के बारे में पूरी तौर पर आश्वस्त हों, इस तरह शांत और गंभीर बैठे थे. यह सभा आर्य युवक परिषद की सभा थी. मंच से दिये जा रहे भाषण और बीच-बीच में आने वाले भजनियों का विषय शराब और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों की निंदा करना था पर यह बात एक क्षेपक के तौर पर ही आती थी—विस्तार में दोहराया जा रही थी हरयाणा की अतीत गाथा. चीनी यात्री फाह्यान से ले कर अंग्रेजों के जमाने तक हरयाणा की घरती के दूध और अनाज से भरे

हुए रहने और दुर्व्यसनों को दूर रखने के अनेक लेकिन वही किस्से हर आदमी दोहरा रहा था और फिर बताता था कि आजादी मिलने से इस क्षेत्र में गलत नीतियों के कारण नयी कुरीतियाँ जड़ जमाने लगी हैं. अतीत

आर्य युवक परिषद के लगभग डेढ़ सौ युवक हिसार से सोनीपत की लगभग 180 कि. मी. लंबी पदयात्रा पर थे. यह पदयात्रा लोगों को यह समझाने के लिए आयोजित की गयी कि शराब और दहेज जैसी प्रथाएँ समाज को भीतर से तोड़ रही हैं और भ्रष्ट कर रही हैं. एक नये सामाजिक आंदोलन की जरूरत है जिस में सार्वजनिक चरित्र पतन के इस दौर को रोका जा सके. आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष जगवीर सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा के दो महीने बाद जब फसल कट जायेगी और किसान अपेक्षाकृत फुसंत से होंगे, वे लोग सामाजिक कानून बनवाने के लिए निकलेंगे और परंपरागत पंचायतों के जरिये लोगों को इन बुराइयों के विरुद्ध संगठित किया जायेगा. हरयाणा में





फरमाणा की सभा में स्वामी इंद्रवेश

पिछले वर्ष राज्य को शराब की बिक्री से 50 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ जिस का मोटा हिसाब यह है कि लगभग 100 करोड़ रुपये की शराब बिकी. इसी से शराब के बढ़ते हुए खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है. इस साल 1 अप्रैल से शराब के नये ठेके दिये जा रहे हैं और बिक्री के लक्ष्य को दुगुना किया जा रहा है. इस के खिलाफ एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा होता दीखता है. कुरुक्षेत्र के पास एक गाँव में एक शराब के ठेके को बंद हो जाना पड़ा है क्यों कि लोगों ने पंचायती फेसला कर लिया था कि कोई शराब नहीं खरीदेगा.

हरयाणा अपने परंपरागत पंचायती संगठन के लिए विख्यात है. इस की एक झलक फरमाणा की बैठक में मिल गयी थी जहाँ गाँव के बुजुर्गों ने बताया कि पड़ोस के गाँव समेत इस क्षेत्र की माजरा पंचायत ने हाल ही यह फेसला

#### राजस्थान

### कर्मचारी हड़ताल : माथुर सरकार का नया सिर दर्द

बेरी आयोग की सिफारिशें लागू करने और महंगाई भत्ते की बकाया चार किस्तों का नकद भुगतान करने की माँगों को ले कर राज्य सरकार की लगभग तीन लाख कर्मचारी 18 मार्च से हड़ताल पर हैं. उत्पादन वर्ष में उन की यह हड़ताल मले ही विकास में बाधा पहुँचाने वाली कही जाये किंतु उस से यह प्रश्न तो उठता ही है कि यदि वेतन संबंधी आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना था तो फिर उस का गठन ही क्यों किया गया?

मुख्य सचिव एम. एम. के. वली के अनुसार कर्मचारियों की माँगें मानने पर राजकोष पर 73 करोड़ रु. प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बेरी आयोग की सिफारिशें लागू करने पर प्रतिवर्ष 43 करोड़ रु. का अतिरिक्त भार

किया है कि गाँवों में कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ेगा नहीं वरना उस के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह के सामाजिक नियम शराब और दहेज के बारे में बनाने की पहल भी कुछ इलाकों में की जा रही है. फरमाणा की सभा में मुख्य अतिथि थे संसद सदस्य इंद्रवेश जिन्होंने 14 वर्ष पहले इसी तरह की एक पदयात्रा का नेतृत्व किया था. अब वह लोकदल में शामिल हो गये हैं और उन के भाषण में अगले चुनाव के लिए लोकदल का प्रचार भी जगह पा गया था. अलवत्ता यह पदयात्रा न सिर्फ हरयाणा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आर्य समाज आंदोलन के लिए भी जिस में जान डालने की आर्य युवक परिषद एक छोटी सी कोशिश कर रही है. सन् 83 में दिल्ली में एक शिविर लगाने की योजना है जिस में 20 हजार लोगों के मांग लेने की उम्मीद की जा रही है.

राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा जब कि सरकार 25.50 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय ही उठा सकती है और इस के लिए कर्मचारी नेताओं से बातचीत के दौरान पेशकश भी की गयी. इसी तरह महंगाई भत्ते के नकद भुगतान के मुद्दे पर भी राज्य सरकार ने आधी राशि (15 करोड़ रु.) ही नकद देने का प्रस्ताव किया. यानी 15 करोड़ रु. का भुगतान फिलहाल रोक लिया जायेगा. कर्मचारी इस के लिए सहमत नहीं हुए.

सरकार की मुख्य परेशानी यह है कि वह पहले ही 380 करोड़ रु. का 'ओवर ड्राफ्ट' ले चुकी है जब कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि 'ओवर ड्राफ्ट' 340 करोड़ रु. से अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि को 1982-83 के लिए राज्य की वार्षिक योजना

राशि में समायोजित कर लिया जायेगा. अब यदि सरकार कर्मचारियों की माँगें मानती है तो उसे 'ओवर ड्राफ्ट' के रूप में अतिरिक्त धन लेना पड़ेगा जिस के कारण योजना राशि में कमी होगी जो अंततः विकास कार्यों को प्रभावित करेगी.

उधर कर्मचारी अपनी माँगें मनवाने के लिए कटिबद्ध हैं और इस प्रश्न पर उन के बीच कोई मतभेद नहीं है. कर्मचारी संघों के दोनों गुटों ने मिल कर हड़ताल का आह्वान किया जिस के कारण उस का प्रभाव भी काफी व्यापक रहा.

इस हड़ताल ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भारी परेशानी में डाल दिया है. वह हड़ताल शीघ्र समाप्त कराने के पक्ष में हैं. इस के लिए उन्होंने जहाँ एक ओर कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए राजस्वमंत्री परसराम मदेरणा, वित्तमंत्री चंदनमल वैद और श्रममंत्री



शिवचरण माथुर : नया सिरदर्द

बृजसुंदर शर्मा को ले कर एक उपसमिति गठित की, दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा भी की है. अस्थायी कर्मचारियों के बारे में तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन की जगह पर नये लोग भरती कर लिये जायेंगे.

हड़ताल लंबी खिंचने के पीछे एक मनोरंजक तथ्य यह बताया जा रहा है कि राज्य सरकार मार्च के अंत तक कर्मचारियों से समझौता इस लिए टालती रही कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले यदि लगभग 50 करोड़ रु. की प्रशासनिक खरीद न हुई तो यह धन-राशि बच जायेगी. साथ ही राज्य कर्मचारियों के वेतन के 84 लाख रु. प्रतिदिन बच रहे हैं क्योंकि अभी तक सरकार ने यही कहा है कि हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं दिया जायेगा.

रोजमर्रा का सरकारी काम तो इस हड़ताल से प्रभावित हुआ ही, शिक्षा कार्य पर भी उस का दुष्प्रभाव पड़ा है. स्कूलों में परीक्षाएँ चल रही हैं. शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण होमगार्डों और बेरोजगारों को दैनिक भजदूरी पर भरती करके जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है जिस के फलस्वरूप अनेक परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएँ होने की शिकायतें मिली हैं.



## वीएतनाम : गियाप का गिरना



युद्ध मोर्चे पर अस्त्र ले जाती हुई वीएतनामी स्त्रियाँ. (ऊपर) गियाप : कुशल संन्य संचालन

आँकड़ा) वीएतनाम हिंदचीन के पूर्वी प्राय:द्वीप में स्थित है. उस के उत्तर में चीन, पूर्व और पश्चिम में दक्षिण चीन सागर तथा पश्चिम में कंबुजिया और लाओस स्थित हैं. वीएतनाम सदैव युद्ध का अखाड़ा रहा है—ईसा सन् से पूर्व और बाद में भी. ईसा से पूर्व वीएतनाम टोंकिन कहलाता था. बाद में मध्य चीन से वीएत लोगों को यहाँ पर ला कर बसाया गया. घीरे घीरे इस का नाम वीएतनाम पड़ गया. 1288 में वीएतनाम ने काबुली खान की फौजों को हराया. 1858 में वीएतनाम फ्रांस का संरक्षित प्रदेश था जो 1884 तक रहा. 1940 में वीएतनाम जापान के कब्जे में रहा. लेकिन हो ची मिन्ह के नेतृत्व में गठित छापामार जापानी साम्राज्य के विरोधी रहे. अगस्त 1945 में हो ची मिन्ह की सूझबूझ से वह जापानियों को अपने देश से बेदखल करने में सफल हुए. 1946 में फ्रांस ने वीएतनाम पर अधिकार जमाना चाहा. इस के विरोध में 1946-1954 तक युद्ध चला. 1 जुलाई 1949 को बाओ दी नाम से एक नया देश अस्तित्व में आया जिसे बाद में दक्षिण वीएतनाम का नाम दिया गया. दूसरे वीएतनाम (उत्तर) पर हो ची मिन्ह का अधिकार रहा. इन दोनों राज्यों को कभी शांति नसीब नहीं हुई. निरंतर युद्ध चलता रहा. अंततः 27 जनवरी 1973 को दोनों वीएतनाम का एक बार फिर विलय हो गया.

जनरल वो न्युगेन गियाप को सत्तारूढ़ पोलितब्यूरो से हटा दिया गया है. क्यों? स्पष्ट कारण नहीं बताया गया लेकिन अटकलें अलबत्ता लग रही हैं. कुछ लोग उन को हटायें जाने का कारण गिरता स्वास्थ्य मानते हैं. वह काफी समय से कैंसर से ग्रस्त हैं. उन के पेट या गले में कैंसर है. पिछले दिनों सोवियत संघ में उन का इलाज भी हुआ था. गियाप को सत्ता से दूर रखने का एक कारण अन्य वयोवृद्ध नेताओं से मतभेद बताया जाता है. हाल में संपन्न पाँचवीं कांग्रेस में भी वह अधिक सक्रिय नहीं थे. गियाप के अलावा न्युगेन दुई त्रिन्ह को भी नवगठित पोलितब्यूरो में शामिल नहीं किया गया. 1980 में मंत्रिमंडल के फेरबदल में इन दोनों नेताओं को अपने अपने पदों से मुक्त कर दिया गया था. तब गियाप प्रतिरक्षामंत्री थे और त्रिन्ह विदेशमंत्री. दोनों ही खासे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं. शायद यही उन का कसूर था. दिलचस्प बात यह है कि पिछले 55 वर्ष से जिन लोगों ने वीएतनामी कम्युनिस्ट आंदोलन को दिशा दी इस समय भी वही लोग सत्ता में हैं. वे भी बुढ़ा गये हैं. गियाप 72 और त्रिन्ह 80 वर्ष के हैं जब कि पोलितब्यूरो के लिए चुने गये सदस्यों की उम्र है: ली दुआन 74, वूआङ्ग चिन्ह 75, प्रधानमंत्री फाम वान डाङ्ग 76 और डॉ. हेनरी कीसिंगर के साथ वीएतनाम युद्ध संबंधी वार्ता कर नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले ली डक थो 72 वर्ष.

जनरल गियाप वीएतनाम युद्ध में इतिहास पुरुष बन गये थे. उन की सूझबूझ और समर-नीति के कारण ही तत्कालीन दक्षिण वीएतनाम के सैनिकों और अमेरिकी सलाहकारों को घुटने देखने के लिए मजबूर होना पड़ा. गियाप पहले स्कूल अध्यापक थे. उन्होंने दोएनबीएनफू में फ्रांसीसी सैनिकों को पराजित कर पहले पहल अपने सैनिक कौशल का परिचय दिया था. 73 सदस्यीय पोलितब्यूरो में जो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हुए वे हैं: महासचिव ली दुआन, राज्य परिषद् अध्यक्ष वूआङ्ग चिन, प्रधानमंत्री फाम वान डाङ्ग, ली डक थो आदि. ली दुआन के वक्तव्य का यह अंश अलबत्ता महत्त्वपूर्ण है: 'पार्टी को संगठित और स्वच्छ रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी अवसरवादियों और उन लोगों को पार्टी से यथासंभव निष्कासित किया जाये जिन की क्रांतिकारी भावना कुंद हो गयी है और जिन पर भ्रष्टाचार, शोषण, तस्करी, अटकलबाजी और जनता पर दमन करने के आरोप हैं'. क्या गियाप और त्रिन्ह पर भी ली दुआन की यह टिप्पणी लागू

होती है इस का पता तो बाद में ही लगेगा. लेकिन राजनीति में मोहरे तो लोग बनते ही हैं.

वीएतनाम इस समय एक बार फिर संकट के दोराहे पर है. जब से कंबुजिया के भूतपूर्व राज्याध्यक्ष राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक ने लाल रुमेर के साथ फिर से मेल करने पर सह-मति व्यक्त की है तब से वीएतनामी नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. वर्तमान कंबुजिया तो उन का 'अपना' है. सिंहनुक को चीन के अलावा एशियाई संघ के सदस्यों (एसियान) के कुछ देशों का भी समर्थन प्राप्त है.

इस के अलावा वीएतनाम में भीतरी घुटन भी है. उस घुटन का कारण कंबुजिया को निरंतर सहायता प्रदान करने से उस का अपना दिवालिया होना है. वीएतनाम की इस जर्जर अर्थव्यवस्था से आम लोगों की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. यह बात दीगर है कि साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में लोगों को कहने-पुनने की गुंजाइश कम रहती है. इस के अलावा अनाज की पैदावार कम होने से भी सरकार और लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं. वीएतनाम के 90 प्रतिशत लोग किसान हैं और चावल उपजाते हैं. वीएतनाम के सैनिकों और शासकों के युद्ध के खतरे के कारण (चीन और चीन के समर्थन से कंबुजिया के लाल रुमेर द्वारा) बजट का बहुत बड़ा भाग सशस्त्र सेनाओं के रखरखाव पर ही खर्च हो जाता है. इन सभी खामियों को ध्यान में रखते हुए वीएतनामी नेता एसियान के साथ किसी न किसी स्तर पर सहयोग बनाने की जुगाड़ में हैं. अपने तर्कों द्वारा वीएतनामी नेता मलयेसिया और इंडोनेसिया को लगता है प्रभावित करने में सफल हो गये हैं कि इस क्षेत्र को वास्तविक खतरा चीन से है और किसी दिशा या देश से नहीं.

वीएतनाम की इस समय सब से बड़ी दिक्कत युवा नेतृत्व विकसित करने की है. पिछले पैंतीस वर्ष से वीएतनाम पर हमले होते रहे हैं. पहले जापान, और उस के बाद, फ्रांसीसी और अमेरिकी सेनाओं ने वीएतनाम को रौंदा. इन हमलों में युवा लोग बड़ी संख्या में मारे गये. इस समय युवा के तौर तर विदेश मंत्री न्युगेन को थाच (49 वर्ष) और पोलितब्यूरो के सदस्य और उपप्रधानमंत्री फाम हङ्ग (64) हैं. कुछ अन्य युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो पाँच से सात वर्ष तक सत्ता के निकट आने योग्य होंगे.

वीएतनाम का क्षेत्रफल 126,436 वर्गमील है और जनसंख्या 42,650,000 (1973 का



विश्व •

आर्हेतीना

## बूढ़े शेर ने युद्ध की तैयारी की है

संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के आर्हेतीना विरोधी प्रस्ताव के बावजूद आर्हेतीना के राष्ट्रपति जनरल गालतियेरी का कहना है कि ब्रिटेन न जाने किस मुंह से हमारा विरोध कर रहा है—उसने 1833 में बलपूर्वक हमारे फॉकलैंड द्वीपसमूह पर कब्जा किया था। आर्हेतीना पर अगर ब्रिटेन हमला करेगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। प्रतिरक्षामंत्री का कहना है कि 'आर्हेतीना ने जो कदम उठाया है उसे वह पीछे नहीं हटायेगा—ब्रितानी मूल के जो दो हजार निवासी वहाँ हैं उन के अधिकारों का सम्मान किया जायेगा।'

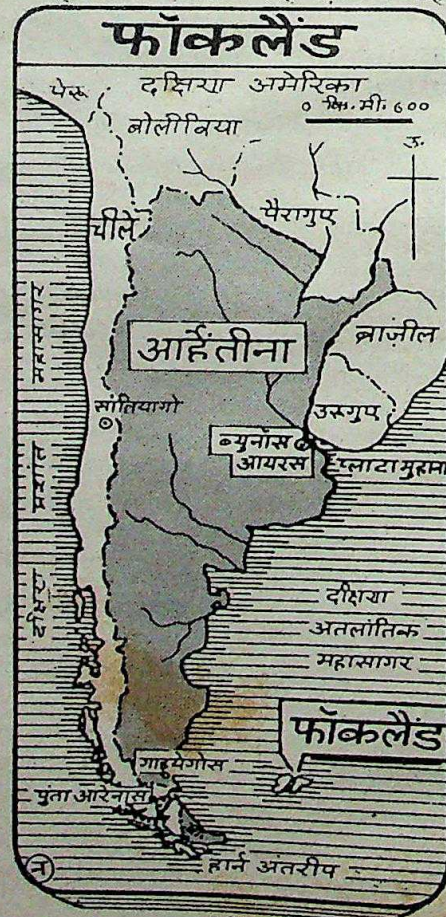
सुरक्षा परिषद ने कहा है कि आर्हेतीना फॉकलैंड से, जिस के आसपास खनिज तेल पाये जाने की संभावना है, अपनी फौजें हटा ले। आशंका थी कि चीन या सोवियत संघ कहीं निषेधाधिकार का प्रयोग न कर बैठें, क्योंकि इन का रुख यही था कि ये द्वीप हैं तो आर्हेतीना के ही। अनेक विकासशील देशों ने आर्हेतीना का पक्ष लिया, हालांकि भारत बलप्रयोग से नहीं, बातचीत द्वारा मामला निपटाए जाने के पक्ष में है।

ब्रिटेन ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में ग्रहण किया है और करीब 40 जलपोतों का शक्तिशाली नौसेनिक बेड़ा फॉकलैंड रवाना कर दिया है जो 12,874 किलोमीटर चल कर 15 अप्रैल के आसपास वहाँ पहुँचेगा। यह बेड़ा आर्हेतीना के नौसेना से दूना ताकतवर है। अंततः फैसला युद्ध से नहीं होगा—बातचीत से ही होगा जिस में जरूरी नहीं कि ब्रिटेन की जीत ही हो।

**फॉकलैंड** आर्हेतीना के आक्रमण और उसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में लेने की खबर से ब्रिटेन में तहलका मच गया है। विदेशमंत्री लॉर्ड कैरिंगटन और उनके साथ दो कनिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफे भी दे दिये हैं ब्रितानी प्रधानमंत्री मारग्रेट टैचर ने फॉकलैंड पर आर्हेतीना के आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा के साथ साथ अपने देशवासियों को वचन दिया है कि आर्हेतीना से इस का बदला जरूर लिया जायेगा। ब्रितानियों का कहना है कि वहाँ के लोग ब्रितानी संस्कृति, परंपरा और भाषा को अपना चुके हैं और अब किसी भी हालत में इस द्वीपसमूह को अपने से अलग नहीं होने देगे। ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट टैचर स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुकी हैं कि फॉकलैंड पर ब्रितानी प्रभुसत्ता सर्वमान्य है और इस स्थिति को आर्हेतीना

सरकार का आक्रमण किसी भी हालत में बदल नहीं सकता। ब्रितानी प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि आर्हेतीना सरकार विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा तय करने पर सहमत हो गयी थी। लेकिन अचानक उसने बलप्रयोग किया और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन की सलाह की परवाह भी नहीं की। ब्रितानी प्रधानमंत्री के विचार में फॉकलैंड द्वीपसमूह के लोग ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। आर्हेतीना सरकार उन पर अपनी इच्छा लाद रही है।

**फॉकलैंड पर आर्हेतीना का अधिकार :** पिछले सप्ताह आर्हेतीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से घोषणा की गयी कि सरकार ने सफल सैनिक कार्रवाई के जरिए फॉकलैंड द्वीपसमूह पर पूर्णरूप से अधिकार कर लिया है। साथ ही आर्हेतीना सरकार की ओर से द्वीप समूह के नागरिकों से अपील की गयी कि पिछले लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चले आ रहे ब्रितानी शासन को समाप्त करने में वे इस समय राष्ट्रीय भावना से काम लें। वास्तव में यह द्वीपसमूह आर्हेतीना का है। सन् 1833 से यह ब्रितानी अधिकार में है। ब्रिटेन ने आर्हे-



तीना से यह द्वीप छीन लिया था। द्वीपसमूह के इतिहास के इस संदर्भ में ही आर्हेतीना सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्वीपसमूह को वापस लेने के लिए आर्हेतीना सेना ने वहाँ प्रवेश किया। साथ ही यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में कोई खूनखराबा नहीं हुआ। लेकिन गैरसरकारी सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोग हताहत हुए हैं। कार्रवाई का व्यौरा देते हुए ब्यूनस आयर्स के समाचार पत्रों में कहा गया था कि सब से पहले आर्हेतीना के छापामारों ने हाई अड्डे पर कब्जा किया और द्वीपसमूह का कब्जा लेने के लिए जहाजों तथा हवाई जहाजों से वहाँ सेनाएँ उतार दी गयीं। आर्हेतीना से प्रसारण में कहा गया कि यह कार्रवाई द्वीपसमूह पर आर्हेतीना के उचित अधिकार को वापस लेने के लिए की जा रही है।

**द्वीप निवासियों द्वारा विरोध :** ब्यूनस आयर्स से प्राप्त रायटर के समाचारों में कहा गया है कि फॉकलैंड द्वीपसमूह में कोई एक हजार नागरिकों ने आर्हेतीना के आक्रमण का शस्त्रों द्वारा विरोध किया है। पता चला है कि फॉकलैंड द्वीपसमूह के प्रसारण में लोगों से अपील की गयी कि वे आर्हेतीना के आक्रमण का विरोध करें।

ब्रितानी प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट टैचर ने फॉकलैंड पर आर्हेतीना के आक्रमण के मामले पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। श्रीमती टैचर ने आर्हेतीना से माल के आयात पर तत्काल ही पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन में आर्हेतीना की संपत्ति को जब्त करने का एलान पहले ही किया जा चुका है और आर्हेतीना के लिए ब्रितानी हथियार भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्हेतीना के लिए रवाना ब्रितानी नौसेना बेड़े को सहायता पहुँचाने की तैयारियाँ जोरों से की जा रही हैं। कहा जाता है कि ईंधन तथा माल की सप्लाई के लिए ब्रितानी व्यवसायिक जहाजों को भी लगाया जा रहा है।

**टाइम्स और डेली टेलीग्राफ** इन दो ब्रितानी प्रमुख समाचारपत्रों ने खबर दी है कि फॉकलैंड पर आक्रमण करने की आर्हेतीना की गुप्त योजना के बारे में जानकारी लंदन में कोई 10 दिन पहले ही मिल गयी थी।

ब्यूनस आयर्स से प्राप्त समाचारों में कहा गया है कि आर्हेतीना ने हवाई जहाजों द्वारा अपने कुछ और सैनिक फॉकलैंड भेजे हैं। स्टेनले बंदरगाह पर सेना और सैनिक साज सामान भारी मात्रा में पहुँचाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अंग्रेज रहते हैं वहाँ आर्हेतीना के सैनिक टैंक दिखायी पड़ने लगे हैं।

रायटर के एक समाचार में कहा गया है कि ब्रिटेन ने एक प्रसारण में आर्हेतीना के ब्रितानी नागरिकों से, भावी संकट को ध्यान

दिनमान •



## फॉकलैंड पर एक दृष्टि

फॉकलैंड द्वीपसमूह दक्षिण अतलांतिक में केपहार्न के 480 मील (772.5 कि.मी.) उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 200 द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल कोई 4,700 वर्गमील (12,173 वर्ग कि.मी.) का है। दो बड़े द्वीपसमूह हैं: पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड। 31 दिसंबर 1978 तक यहाँ की आबादी 1,867 थी। सभी ब्रितानी मूल के हैं। 80 प्र.श. द्वीपसमूह में ही जन्मे हैं। स्टेनले यहाँ की राजधानी है।

फॉकलैंड का वर्तमान संविधान 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। प्रबंध परिषद की सहायता से गर्वनर यहाँ का शासन चलाता है। प्रबंध परिषद में दो सदस्य अपने पद के नाते, दो गर्वनर द्वारा नामजद और दो विधान परिषद से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में दो सदस्य पद के नाते और छह चुने होते हैं। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच फॉकलैंड द्वारा शासित होते हैं। फॉकलैंड सरकार इन दोनों द्वीपों के लिए कानून बनाती है। साउथ जॉर्जिया में किंग एडवर्ड नामक स्थान पर एक मजिस्ट्रेट रहता है। यहाँ 1909 से सरकार का एक केंद्र है। लगभग 120 वर्ष से फॉकलैंड पर ब्रिटेन का आधिपत्य है और वही उस का शासन चला रहा है।

में रखते हुए आर्हेतीना से चले आने को कहा है। ब्रितानी विदेश विभाग के अनुरोध पर यह अपील बी.बी.सी. की विदेश सेवा से प्रसारित की गयी है।

आर्हेतीना सरकार फॉकलैंड संकट पर कुछ उदारता का संकेत दे रही है लेकिन प्राप्त समाचारों के अनुसार ब्रिटेन का रवैया और भी सख्त हो गया है। पता चला है फॉकलैंड के आसपास के एक बहुत इलाके को ब्रिटेन ने युद्धक्षेत्र घोषित कर दिया है। उबर अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने विदेशमंत्री अलेक्जेंडर हेग से कहा है कि वह फॉकलैंड संकट को निपटाने के लिए सुरत लंदन और न्यूनस आयरस जायें।

आर्हेतीना और ब्रिटेन दोनों ही देशों की राजधानियों में सरगर्मी है। ब्रितानी मंत्रिमंडल की आपात्कालीन बैठक 10, डाउनिंग स्ट्रीट श्रीमती टैचर के निवासस्थान पर हुई। ब्रिटेन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आर्हेतीना अपनी सेनाएँ फॉकलैंड से नहीं हटा लेता तब तक फॉकलैंड के प्रश्न पर वह बातचीत करने को तैयार नहीं है। उधर आर्हेतीना के विदेशमंत्री ने अमेरिकी विदेशमंत्री श्री हेग से मिलने के बाद आशा व्यक्त की है कि शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा समस्या का कोई हल निकल आयेगा।

दिनमान.

ईरान

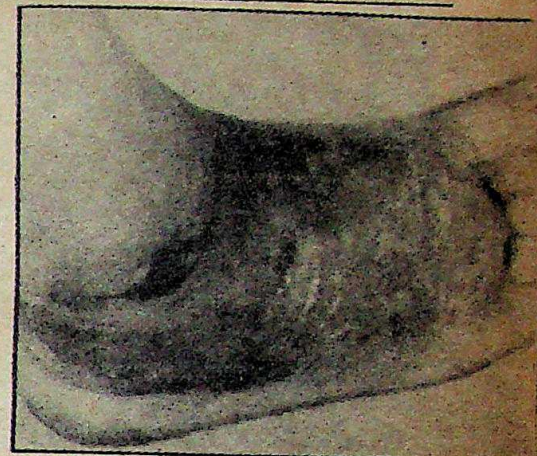
## कैदखाना, मस्जिद या कब्रिस्तान

इमाम खुमेनी इराक में बैठे अपने भाषणों में कहते थे, ईरान में कैदखाना और कैदी नाम की चीज का वजूद नहीं रहेगा, मगर पूरा ईरान आज एक बड़ा कैदखाना है जिस की विभिन्न कोठरियों में पीड़ित जनता हाहाकार मचाये हुए है। यातनाओं का न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इस समय कुल 45 हजार कैदी हैं जिस में से 30 हजार सियासी हैं एक-एक कोठरी में 18-19 लोग ठूसे जाते हैं। इस से अधिक आप से मैं क्या कहूँ—विश्वास नहीं होता है तो नारे लिखीं ये दीवारें देख लें।

उस की बातों में सच्चाई थी, जिंदा इनसान खामोश हो रहे थे और मुर्दा दीवारें बोल रही थीं। घुटन का अजदहा जो सारे ईरान को निगलने के लिए आतुर नजर आ रहा था। वह शाह के दौर की याद दिला रहा था। एक विद्यार्थी ने कहा, 'विश्वविद्यालय बंद हैं, काम है नहीं, कुल 40 लाख ईरान में बेकार हैं। महंगाई है, कोई भविष्य में आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। जवान खोलो तो गर्दन कटती है।

दीवारों पर लिखे अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। किसी लेखक ने कहा था कि किताबें, समाचारपत्र, पांडुलिपियाँ, सब जल कर खत्म हो गयी हैं। क्या हो रहा है ईरान में। इसे समझने के लिए हमें दीवारों पर लिखे गये नारों की तलाश रहती है। सामने लिखा था 'मस्जिदें आप की मोर्चा हैं, उन्हें सुरक्षित रखें,' 'इस्लाम की रक्षा के लिए जासूसी अनिवार्य है,' या 'न पूर्व न पश्चिम, हर दो पर लानत' पार्टी केवल हिजबदुल्लाह इत्यादि।

एविन जेल के सामने औरतों मर्दों की भीड़ थी। किसी को कुछ पता न था क्या होने वाला है। एक औरत जिस का 12 वर्ष का बेटा अंदर था, बोली 'पहले तो मार कर ये कब्रों का नंबर दे देते थे, नाम टी. बी. से बोल देते थे, मगर अब—कुछ पता नहीं है कैसे कैसे जवानों को मारा है। मेरे बेटे का क्या दोष था? यहीं सड़क पर पड़ा एक पर्चा उठा कर पढ़ने लगा था।' जेल से आयी एक लड़की ने बताया कि 'जेल में वही यातनाएँ हैं जो शाह के समय में थीं। तारों से पैरों पर मार, बलात्कार, शोच आदि के लिए न जाने देना, बिजली के झटके, नाखून घसीटना, सोने न देना, खाना न देना, उल्टा लटका कर मारना, सीने को इस्त्री से जलाना, सारे बदन पर जलती सिगरेट चुभोना, एक दूसरे के सामने गोली मारना या फाँसी पर लटकाना, आँखें निकालना, कान काटना, बदन का कोई भी अंग उड़ा देना, बहुत देर तक आँखें बंद रखवाना, फिर धूप में खड़ा रखना,



(ऊपर) एविन जेल में यातना के प्रतीक एक 17 वर्षीय लड़की के पैर (नीचे) यातना मशीन 'अपोलो' का क्रांतिकारियों पर प्रयोग जवान बाहर खींचना, चेहरे बदन पर धूसे मारना—एकदम से दुखी हो कर बोली—'मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। पैरों पर कोड़ों के निशान थे, लंबे बाल इतने उन्होंने खींचे कि मैंने उन्हें काट दिया—आँखों से अब बहुत कम दिखता है।

एक दूकानदार ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा 'आप का कहना ठीक है कि हम ने ही इनकलाब को आगे बढ़ाया था इस उम्मीद पर कि पहली व्यवस्था के जाल से हम मुक्त होंगे। मगर क्या कुछ न बदला, आर्थिक व्यवस्था समाप्त है, बैंक खाली हैं, इस्लामी संस्थाओं में पैसा मरा हुआ है। हम व्यापारियों का दिया हुआ धन पहले था अब भी है। इमाम का 'हिस्सा' कर के जो धन उन के नाम से निकाला जाता है उस



कोष में 30 अरब डॉलर हैं। यह छोड़ें, आज हम एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। कच्चा माल है नहीं कि कारखाने चलें, ग्राहक हैं नहीं कि सामान बिके। एक साबुन जो एक-डेढ़ रुपया की थी अब 12 रुपये का है। गोشت एक किलो 180 रुपये का है। चावल एक किलो 50 रुपये का—अमी देश का 50 टन सोना स्विट्जरलैंड में बिका है। 8 करोड़ डॉलर के नोट छपे हैं। इन सारी बातों पर आलोचना करो तो वही हाल होता है जो मुजाहिदीनों तथा साम्यवादियों का है। पल भर में गोली से उड़ा दिये जाते हैं।

सूचना संचारमंत्रालय में किसी से मिलना था, गयी। कोई सीट पर न था। मालूम हुआ सब नमाज पढ़ने गये हैं। मेरी मित्र का इंटरव्यू था। उस से पूछा कैसा हुआ, नौकरी मिलने की आशा है? बोली मालूम नहीं। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि क्या बताऊँ। उदाहरणतः 'कफन के कितने टुकड़े होते हैं। मुर्दा नहलाते समय धर्म के कौन से उसूलों पर ध्यान देते हैं? या आप केवल नौकरी के लिए अपने को धार्मिक बता कर रही हैं या हैं भी?'

हमारी बातें सुन कर एक पत्रकार हँस पड़ा। कहने लगा 'ईरान एक बहुत बड़ी मस्जिद में बदल गया है और मस्जिदें थाने में—हर दफ्तर में नमाज का कमरा है, प्रश्न, लेखन, हिसाब सब में धर्म का हस्तक्षेप है। अब मस्जिदों से राशन कार्ड, तेल व अन्य सामानों के कूपन लाइसेंस मिलते हैं। पासदार रात दिन हर मोहल्ले पर कड़ी नजर रखते हैं। कहीं किस घर में क्या हो रहा है। लोगों को तेल, चावल, गोشت, नौकरी की आवश्यकता है, सो हर जुल्म को सह रहे हैं मगर कब तक?'

स्वयं इस्लामी गणतंत्र पार्टी में फूट है और अयातुल्लाहों में भी। ईरान में लगभग 50,000 मौलवी हैं। प्रसिद्ध लोकप्रिय मुल्लाओं के बीच 'विलायत फकीक' (धार्मिक नेता) को ले कर मतभेद इमाम खुमैनी के ईरान में आते ही आरंभ हो गये थे। इस्लामी कानून के हिसाब से 'विलायत फकीक' की सत्ता केवल धर्म के मामले में होती है मगर कुछ चाहते थे कि ईरान की पूरी सत्ता की बागडोर इमाम को दे दी जाये, हुआ भी वही। अयातुल्लाह शरयतमदारी आलोचना करने के बाद कुम शहर में नजरबंद कर दिये गये। अयातुल्लाह तालगानी की हत्या कर दी गयी। अन्य मौलवी जो वास्तव में उदार इस्लामी विचारों के थे शांत हो गये। तीसरा मतभेद अमेरिका समर्थक तथा विरोधी दलों का है। इमाम खुमैनी अमेरिका विरोधी हैं जब कि अयातुल्लाह गुलपायगानी अमेरिका समर्थक। ऐसी हालत में यदि देश की हर प्रकार की व्यवस्था बरबाद हो गयी है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 'इमाम ने ईरान को वीरान कर दिया। फसल और नस्ल दोनों को तबाह कर रहा है। आज इमाम खुमैनी का ईरान एक विस्तृत

काब्रिस्तान है जो हर दिन 'वोमुनी' रसोई के ईरान में फैल रहा है। छह मास में 8,000 लोग खड़े खड़े मूने गये हैं जिन में 81 लोग प्रसिद्ध इनकलाबी थे। इस इनकलाब के लिए 70,000 लोगों ने अपने को बलिदान किया था। शाह के शत्रुओं के नाम पर, जो भागे नहीं थे, उन में 5,000 लोगों को खलखोली ने मरवाया था और अब—इस काब्रिस्तान को देखें हर रोज नौजवान शहीद हो रहे हैं। घुटन है, कोई जबान नहीं खोल सकता। इस कलम व जबान की स्वतंत्रता के लिए लोग 50 वर्ष तक संघर्षरत रहे थे। एक समाजशास्त्री ने कहा। पास बैठे उन के मित्र ने कहा, 'इमाम का कहना है यदि 10 लाख भी मुसलमान जो सच्चे हैं, पवित्र हैं, बच जायें तो काफी है यानी बाकी 3.6 करोड़ ईरानियों का मरना महत्वपूर्ण नहीं है।'

दो मास रह कर लगता है कि इनकलाब से लोगों की कितनी आशाएँ थी मगर वह आशा निराशा में बदल गयी और ईरान केवल कैदखाना, मस्जिद, काब्रिस्तान की चहारदीवारों में घिर गया है।

## अल्जीरिया

## बेन बिल्ला अब क्या करेंगे

अल्जीरिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति 66 वर्षीय अहमद बेन बिल्ला को 5 जुलाई 1979 को 15 वर्ष की जेल के बाद जब रिहा किया गया तो अरब जगत के अलावा पश्चिमी देशों में भी उन की अगली कार्यवाही पर अटकलें लगनी शुरू हो गयी थीं। तब उन्होंने न तो कोई सार्वजनिक वक्तव्य दिया और न ही अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संकेत ही। इस के कारण भी थे। रिहा होने के बावजूद उन पर नजर रखी जा रही थी, टेलीफोन टेप किये जाते थे और डाक सेंसर। दो वर्ष की इस 'अर्द्ध जेल' की जिंदगी से मुक्त हो कर जब वह पेरिस पहुँचे



बेन बिल्ला : वापसी की प्रतीक्षा

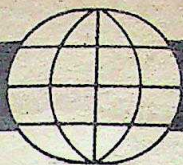
उन की गतिविधियाँ कुछ अधिक तेज हुईं। पिछले दिनों तो उन्होंने अपने मन की बात जबान पर लाते हुए कहा: "मेरी राजनैतिक वापसी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि आम लोग मेरी वापसी की इंतजार में हैं लेकिन मैं राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का चाहवान नहीं हूँ। अगर मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बन भी गया तो ऐसा बहुत कम समय के लिए होगा।"

बेन बिल्ला आज भी अल्जीरिया की घड़कन हैं, आज भी उन्हें 'युग पुरुष' माना जाता है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष जेलों में काटे—15 वर्ष अल्जीरिया में फ्रांसीसी शासन के दौरान और 15 ही वर्ष बूमैदियेन के शासनकाल में। बूमैदियेन ने ही 19 जून 1965 में एक रक्तहीन क्रांति में उन्हें सत्ता से हटाया था। लेकिन 27 दिसंबर 1978 को राष्ट्रपति बूमैदियेन की मृत्यु के बाद उन पर सख्ती कम हुई। अपने निधन से पहले तक बूमैदियेन हमेशा यही सोचा करते थे कि बेन बिल्ला की रिहाई का मतलब अपनी कब्र खुद खोदना तो नहीं। उसी उधेड़बुन में बेन बिल्ला संबंधी वह कोई फैसला न ले सके यद्यपि टीटो और कास्त्रो ने उन पर लगातार दबाव डाला। बेन बिल्ला की लोकप्रियता के प्रति बूमैदियेन अच्छी तरह परिचित थे। वह जानते थे कि औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को तोड़ने के लिए जो लोग स्वाधीनता संग्राम में कूदते हैं उन की यादें अमिट होती हैं। इस बात को बूमैदियेन भी जानते थे और उन के उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति चादली भी।

लेकिन चादली ने बूमैदियेन द्वारा ओडी एमी भय की मनःस्थिति को तोड़ कर पहले बेन बिल्ला की रिहाई की घोषणा की। लेकिन रिहाई की यह खबर अल्जीरियाई समाचारपत्रों में नहीं छपी, विदेशी पत्रों द्वारा ही अल्जीरिया के जागरूक लोगों तक पहुँची। प्रेक्षकों के अनुसार आम आदमी को आज भी यह नहीं मालूम कि बेन बिल्ला हिरासत में हैं या रिहा हो चुके हैं। लेकिन जब उन के वर्तमान विचार अल्जीरिया पहुँचे तो इस खबर पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई।

राजनैतिक नेताओं की वापसी में आज पहले जैसी ताजगी नहीं रह गयी है। यूनान में 10 साल के सैनिक शासन के बाद कांस्तांतीन करामानलिस को पेरिस से बुला कर गद्दी सौंपी गयी थी। ईदी अमीन के पतन के बाद डॉ. मिल्टन ओबोटे को पुनः उगांडा का शासन सौंपा गया था। ये दोनों ही अमी तक सत्ता में बने हुए हैं। बेन बिल्ला ने निस्संदेह द गॉल के शासनकाल में अल्जीरिया को स्वाधीन कराने के लिए यातनाएँ झेलीं। उस को आज भी याद किया जाता है। लेकिन सत्तासूद होने पर जिस प्रकार निरंकुश शासन शैली उन्होंने अपनायी उस की याद भी लोगों के मन में है। इसी निरंकुश शैली के कारण ही उन के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री बूमैदियेन ने उन्हें सत्ता से हटाया था। अपने 14 साल के शासन में वह भी बेन बिल्ला से कम निरंकुश साबित नहीं हुए।





# दुनिया भर की



## अंधेरे दिनों की कला

पेंसिल से बना हुआ 'शब्द रहित' शीर्षक वाला यह चित्र उन चित्रों में से है जो तात्सी अत्याचारों के पीड़ितों द्वारा बनाये गये थे. इस तरह के 30,000 चित्रों में से 350 का चयन कर के जेनेट ब्लैटर और सिविल मिल्टन ने उन्हें एक पुस्तक का रूप दे दिया है. 'आर्ट ऑफ द हॉलोकॉस्ट' (अंधेरे दिनों की कला) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यातना शिविरों में बितायी जाने वाली जिंदगी की गाथा सुनाती है. ये चित्र उन हताश कलाकारों की मानसिक स्थिति के सर्वोत्तम परिचायक हैं. इन कलाकारों ने इन्हें रचने और अपनी मनःस्थिति को इन में बचा रखने के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल किया. कलम, स्याही, रंग जैसे पारंपरिक साधन जब चोरी छिपे हाथ नहीं लगते थे तो वे जेल की कोठरियों की बलियों पर लगा जंग और दीवारों पर लगी कालिख का चित्रों के लिए इस्तेमाल करते थे और बाल, घास फूस और पक्षियों के पंखों का इस्तेमाल ब्रश की जगह. खाने के लिए इस्तेमाल न कर के सब्जियों से रंग निचोड़ कर कई कलाकारों ने अपने चित्रों में रंग

भरे. इन कलाकारों में से एक कैरल कानेकजनी का कहना है, 'मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी उन हालातों को समझ पाये, ताकि वे भविष्य में कभी वैसी परिस्थितियाँ आने ही न दें.'

## भूले बिसरे चीनी

हाल में पीकिङ सरकार ने ऐसे 4237 बंदियों को रिहा करने की घोषणा की है जो 33 वर्षों से चीन के विभिन्न श्रम शिविरों में पड़े हुए हैं. ये सभी 1949 में माओ त्से तुङ्ग के सत्ता में आने से पहले गैरसाम्यवादी सरकार में छोटी-मोटी नौकरियों पर तैनात थे. चीनी जनता को यह मालूम भी न था कि गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद साम्यवादी सरकार ने इतने लंबे असें तक परास्त शासकों के वफादारों को मुक्त नहीं किया है. इधर सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार अब ये बंदी पश्चाताप के दौर से गुजर चुके हैं और लंबी शिक्षा और सुधार की चेष्टाओं के बाद जीवन को नये सिरे से शुरू करने को तैयार हो गये हैं, जिस के लिए उन्हें 60 डॉलर सरकार की ओर से दिये जायेंगे. अगले छह महीनों में लगभग सभी बंदी मुक्त हो

जायेंगे और जिन में अभी तक काम करने की क्षमता बची हुई है उन्हें नौकरियाँ दी जायेंगी. जो कुओमिन्ताङ सरकार द्वारा शासित ताइवान जाना चाहेंगे उन पर भी कोई मनाही नहीं होगी और उन्हें सरकार की ओर से गाड़ी भाड़ा दिया जायेगा. लेकिन ताइवान इन लोगों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति देगा या नहीं, यह अभी निश्चित नहीं, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने साम्यवादी सरकार द्वारा रिहा किये गये चीनियों को अपने देश में अभी तक आने नहीं दिया है.

इन लोगों की इतनी लंबी कैद का कारण स्पष्ट नहीं है. 1975 में साम्यवादी सरकार ने



पिछली सरकार के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को रिहा कर दिया था. ये छोटे अधिकारी शायद वर्तमान सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे होंगे, इस लिए उन के भविष्य के बारे में फुर्सत से ही सोचना उस ने उचित समझा होगा.

## ओपेक की बराबरी

तेल उत्पादक देशों की तरह अब टीन उत्पादक देश भी एकजुट हो कर विश्वबाजार में इस धातु के भाव पर अपना नियंत्रण रखने की बात सोच रहे हैं. इस दिशा में पहल मलयेसिया ने की. यहाँ के प्रधानमंत्री दातुक मोहम्मद ने बताया कि वह थाईलैंड, इंडोनेसिया और बोलिविया से बातचीत कर के इस धातु को

सीधे बाजार में बेचने की व्यवस्था करेंगे. टीन के प्रमुख खरीदार देश इस बारे में चिंतित हैं, क्योंकि इस धातु के भाव इस समय भी पहले से कई गुना बढ़े हुए हैं और बहुत से उद्योगों में इस का इस्तेमाल कम होने लगा है, या इस के विकल्प खोजे जा रहे हैं. ब्रिटेन और अमेरिकाने मलयेसिया के इस फैसले का विरोध किया है कि अगले वर्ष से टीन का उत्पादन 25 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा, जिस से टीन के विश्वबाजार की 'अराजकता' को खत्म किया जा सके.

अमेरिका ने इस के विरोध में अपने उस टीन के विशाल भंडार का दरवाजा खोल देने की घोषणा की है जो उस ने युद्ध के साज सामान बनाने में इस्तेमाल के लिए जमा किया था. यह टीन खुले बाजार में आ जाने से इस धातु के भाव को कुछ समय तक नियंत्रण में रखा जा सकेगा.

## संयुक्तराष्ट्र और

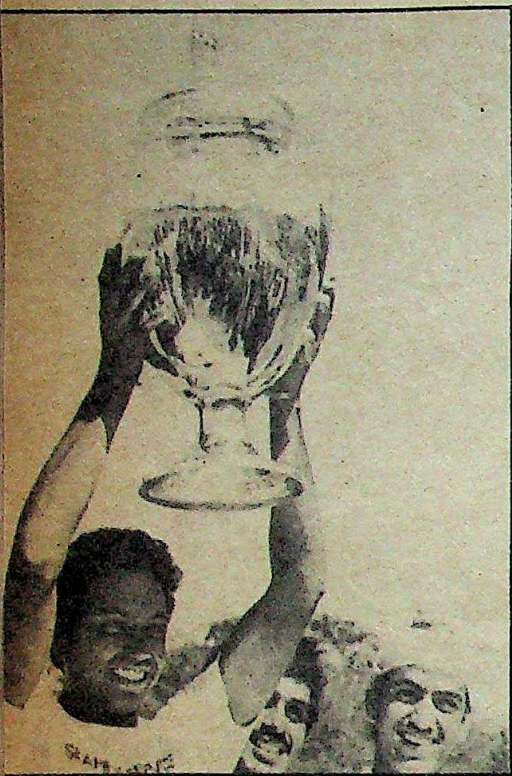
## स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड एक मात्र ऐसा प्रभुसत्तासंपन्न देश है जो स्वेच्छा से संयुक्तराष्ट्र से बाहर रहा है. लेकिन अब वह बहुत दिनों तक ऐसा कर नहीं पायेगा. यहाँ की सरकार ने संयुक्तराष्ट्र में प्रवेश के लिए संसद से अनुमति माँगी है और उन तर्कों के खंडन संसद के सामने रखे गये हैं जिन की वजह से स्विट्जरलैंड अब तक संयुक्तराष्ट्र का सदस्य नहीं बना था.

संयुक्तराष्ट्र का सदस्य बनने के पक्ष में प्रमुख तर्क यही दिया जा रहा है कि विश्व के उथल-पुथल में अपनी आवाज सुनवाने के लिए यही एक मात्र मंच है. संयुक्तराष्ट्र की सदस्यता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इस से स्विट्जरलैंड की विशिष्ट तटस्थ स्थिति में फर्क पड़ जाएगा. तटस्थ और संयुक्तराष्ट्र से बाहर होने के नाते ऐसे कई झगड़ों और मतभेदों में अंतिम फैसले का हक स्विट्जरलैंड को दिया जाता रहा है जिन्हें सुलझाने में संयुक्तराष्ट्र असफल रहा.



## खेल और खिलाड़ी



मोहिंदर और मनिंदर : दो कप्तान

क्रिकेट

## रराजी ट्राफी का ऐतिहासिक ररा

**29** मार्च को फिरोजशाह कोटला मैदान में जब दिल्ली की टीम ने कर्नाटक को हरा कर रणजी ट्राफी का ऐतिहासिक रण जीता तो दिल्ली के सिपहसलार मोहिंदर अमरनाथ का चेहरा गर्व से चमक गया था। यह निस्संदेह चमत्कार था जो आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में देखने में आया। कर्नाटक की टीम जब अपनी पहली पारी में 705 रन बटोर कर आउट हुई तो मान लिया गया कि इतने रन दिल्ली के लिए बना पाना आसान काम नहीं है। इस के कारण भी थे : एक तो तीन दिन तक चमचमाती धूप में क्षेत्र रक्षण, दूसरे गेंदबाजों की गेंदों की बड़ी बेरहमी से पिटाई और तीसरे मानसिक और शारीरिक थकान से उत्पन्न मनो-वैज्ञानिक प्रभाव।

इस तरह के तनाव के साथ जब दिल्ली के सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे तो एक तो मैदान में दर्शक बहुत कम रह गये थे और दूसरे कर्नाटक के खिलाड़ी कुछ अधिक ही आश्वस्त दिखायी दे रहे थे। कर्नाटक के चार खिलाड़ियों ने शतक दागे थे : रोजर बिन्नी (115), वृजेश पटेल (124), सैयद किरमानी (116) और रणजीत कानविलकर

(114)। कप्तान विश्वनाथ सिंघर पर ही बच्चा खिलाड़ी मनिंदरसिंह की गेंद पर आउट हो गये। लेकिन दिल्ली के सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान और रमण लांबा ने जिस तरह से खेल की शुरुआत की उस की उम्मीद अल-बत्ता कर्नाटक को नहीं थी। पहला विकेट 95 रन पर गिरा। पहले दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो दिल्ली के तीन विकेट पर 302 रन बने थे। गुरशरणसिंह ने दशक (101) दागा था और कप्तान मोहिंदर जब अपने भाई सुरिंदर के अस्वस्थ हो जाने के कारण खेलने आये 64 रन पर खेल रहे थे। बेशक दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए यह संतोषजनक खेल था और कर्नाटक को माकूल जवाब भी। जो दर्शक नीरस खेल की कल्पना कर मैदान छोड़ कर चले गये थे दूसरे दिन वह सुबह ही दिल्ली का खेल देखने के लिए मौजूद थे। 27 मार्च को रविवार होने से भीड़ कुछ ज्यादा भी थी, बेशक टेस्ट जैसा ज्वर नहीं था।

मोहिंदर का हौसला बुलंद था लेकिन विश्वनाथ की पेशानी से परेशानी और पसीने की बूंदें झलक रही थीं : कुछ मौसम की गरमी की वजह से और कुछ अपनी असफल रणनीति के कारण। अस्वस्थ सुरिंदर को तो कर्नाटक आउट करने में सफल हो गया लेकिन मोहिंदर दूसरे दिन भी कर्नाटक के गेंदबाजों से आउट नहीं हो पाये। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मोहिंदर 181 रनों पर खेल रहे थे और दिल्ली की कुल रन संख्या 543 थी और उस के केवल छह ही खिलाड़ी आउट हुए थे।

अब विश्वनाथ के घबराने की बारी थी। पांच दिन का मैच एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। जब कोई टीम दोनों परियाँ खेल कर निर्णायक निर्णय पर नहीं पहुँचती तो पहली बार की बढ़त पर ही मैच तय होता है। दिल्ली के अभी चार खिलाड़ी आउट होने बाकी थे। लिहाजा खेल में जान और दिलचस्पी दोनों बरकरार थी। यह मोहिंदर भी जानते थे, विश्वनाथ भी, दर्शक भी और चयन समिति द्वारा नियुक्त सुनील गावस्कर भी जो एक दिन मेरठ में बिताने के बाद फिरोजशाह कोटला मैदान में आ बिराजे थे। खेल के छठे दिन जब मोहिंदर 185 रन पर आउट हुए और मदनलाल भी 48 रनों के बाद मैदान छोड़ कर चले गये तो एक बार फिर विश्वनाथ में विश्वास जागा और अपनी पीठ स्वयं ही थपथपाई जो उन के लिए मृगमरीचिका ही साबित हुई। जिस प्रकार पिछले वर्ष इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय खिलाड़ियों ने अंत तक अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था उसी प्रकार दिल्ली के भी 'दुमी' खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि उन की बल्लेबाजी किसी भी प्रतिष्ठित बल्लेबाज से उन्नीस नहीं। इस का

## 'मुझे सुरक्षित सूची के योग्य ही समझा गया'

मोहिंदर अमरनाथ ने जब रणजी ट्राफी को अपने दोनों हाथों में पकड़ कर ऊपर उठाया तो उस के चेहरे पर एक अजब तरह की दमक थी और आँखों में एक विशेष तरह की उम्मीद और चमक। एक प्रश्न के उत्तर में मोहिंदर ने कहा : 'यह तो अविस्मरणीय है। मैं तो सारी जिंदगी इस जीत को नहीं भूल सकता। सोचिए 705 रन की चुनौती कोई आसान बात होती है। लेकिन हम ने उसे स्वीकारा। जम कर और जिम्मेदारी से खेले और फल हमारे सामने है।'

'इस का श्रेय आप किसे देते हैं?'

'इस जीत के श्रेय के पात्र सभी खिलाड़ी हैं। न तो मैं अकेला और न ही दो-चार खिलाड़ी हैं। पूरी टीम का ही महत्वपूर्ण और प्रभावी योगदान रहा है।'

उस दिन मोहिंदर बहुत खुश थे। जितने ही 29 मार्च को वह खुश थे पहली अप्रैल की शाम को वह उतने ही गमगीन। इंग्लैंड का दौरा करने वाली जिस टीम की घोषणा

परिचय राकेश शुक्ल और लंबे छरहरे बदन के राजेश पीटर ने दिया। जब राजेश पीटर ने अपनी विजय स्ट्रोक लगा कर 702 रन बनाये तो उस की खुशी लगता था शरीर के हर अंग से बाहर निकलने को हो रही थी।

बेशक रणजी ट्राफी का मैच गरमी शुरू होने से पहले के महत्वपूर्ण मैचों में माना जाता है। इस के बाद या तो क्रिकेट खिलाड़ी विदेशों में खेलने की तैयारी करते हैं या कामकाज करने की। यदि दिल्ली की टीम संयम और संतुलन से न खेलती तो उस के हारने के आसार अधिक थे। इसीलिए तो उस की जीत को चमत्कार माना जाता है। 705 रन बहुत होते हैं। इस का श्रेय कप्तान मोहिंदर अमरनाथ को जाता है जिन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें अंतर-राष्ट्रीय मैचों के लिए न चुन कर कितनी गलती करता रहा है। उन के खेल में अभी भी दमखम है बावजूद इस के इंग्लैंड का दौरा करने वाली टीम में इस बार भी मोहिंदर को नहीं चुना गया है। इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि जिस खिलाड़ी के खेल में अभी इतनी जान हो उस की अवहेलना हो।

दिल्ली ने रणजी ट्राफी तीसरी बार जीती है जब कि बंबई 28 बार जीत चुका है। बड़ीदा और होलकर चार चार बार, महाराष्ट्र और कर्नाटक दो दो बार तथा हैदराबाद, पश्चिम-भारत, बंगाल और मद्रास एक एक बार इस ट्राफी को जीत चुके हैं। त्रिलोक वीप



हुई थी उस के पहले सोलह खिलाड़ियों में मोहिंदर का नाम नहीं था. दिल्ली की विजयी टीम से केवल मदन लाल लिए गये थे. चेतन चौहन, कीर्ति आजाद और सुरिंदर अमरनाथ का किसी भी सूची में नाम नहीं था. मोहिंदर और राकेश शुक्ल सुरक्षित सूची में थे. मनिंदर वेस्ट इंडीज जाने वाली स्कूली बच्चों की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. इंग्लैंड के दौर पर जाने वाली टीम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बड़ी ही बुद्धी आवाज में मोहिंदर ने कहा: ठीक है, मुझे तो सुरक्षित सूची के उपयुक्त ही समझा गया. इस के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ.

इंग्लैंड का दौरा करने वाली टीम के लिए जो खिलाड़ी चुने गये हैं उन के नाम हैं: सुनील गावस्कर (कप्तान) विश्वनाथ (उपकप्तान), प्रणव राय, गुलाम पार्कर, दिलीप वेंगसरकार, यशपाल शर्मा, अशोक मलहोत्रा, संदीप पाटील, कपिल देव, मदनलाल, रवि शास्त्री, सुख नायक, सैयद किरमानी, (विकेटकीपर), दिलीप दोषी, शिवलाल यादव और रणधीर सिंह. जिन खिलाड़ियों को सुरक्षित सूची में रखा गया है वे हैं: अरुण लाल, मोहिंदर अमरनाथ, राकेश शुक्ल, गोपाल शर्मा और जुल्फिकार पार्कर (विकेटकीपर).

## अब स्कूली टीम की बारी

अब तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही अपनी किशोर क्रिकेट टीम बाहर भेजा करता था, लेकिन पहली बार भारतीय स्कूल खेल संघ भी अपनी स्कूली टीम विदेश भेज रहा है. यह 16-सदस्यीय टीम वेस्ट इंडीज जायेगी, जहाँ वह अपने तीन सप्ताह के दौरे में 3 तीन दिवसीय टेस्ट और 4 एक दिवसीय मैच खेलेगी.

16 सदस्यीय भारतीय स्कूली क्रिकेट टीम की घोषणा पिछले दिनों लखनऊ में की गयी. टीम की घोषणा के पूर्व तीन सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था. यह शिविर लखनऊ में दो स्थानों पर लगा. पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में फिर बाद में के.डी. सिंह 'बाबू' स्टेडियम में. स्पोर्ट्स कॉलेज में वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाने वाली स्कूली टीम के खिलाड़ी: भविष्य की आशा

पर अभ्यास किया. टर्फ क्रिकेट पर अभ्यास के लिए उन्हें 'बाबू' स्टेडियम में आना पड़ा. प्रशिक्षण के दिनों में इन लड़कों से 'वार्मिंग एक्सरसाइज' करवाई गयी जब कि प्रातः 8 बजे के बाद और सायंकाल के बीच अभ्यास के अलावा कई मैचों को खेलने का अवसर दिया गया.

शिविर के मुख्य प्रशिक्षक प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी चंदू बोर्डे थे. उन के सहायक के रूप में भारतीय स्कूल खेल संघ ने चंडीगढ़ के देशप्रेम आजाद की सेवाएँ ली थीं. देशप्रेम आजाद के बारे में क्रिकेट से वास्ता रखने वाले सभी को पता है कि विश्व विख्यात कपिलदेव ने उन्हीं से सब कुछ सीखा है. कपिल के अलावा भारतीय क्रिकेट को उन्होंने अशोक मलहोत्रा भी दिया है. अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर पहले तो इस शिविर के लिए 55 खिलाड़ियों का चयन किया गया, लेकिन नौ दिन बाद ही इन की संख्या घटा कर 30 कर दी गयी जो अंत तक रहे. दोनों ही प्रशिक्षक बोर्डे तथा आजाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट थे, लेकिन उन का कहना था कि यह संख्या बहुत अधिक थी. उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे खिलाड़ी अपनी परीक्षाओं में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाये. लेकिन दो खिलाड़ियों मनिंदरसिंह (दिल्ली) तथा शिवराम कृष्णन् (तमिषनाडु) को बाद में शिविर में लिया गया. ये खिलाड़ी उन दिनों अपने राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी मैचों में खेल रहे थे.

19 वर्ष से कम उम्र के इन स्कूली लड़कों के चयन के लिए भारतीय स्कूल खेल संघ के अध्यक्ष पी.आर. चौहान की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय चयन समिति गठित हुई थी. चयन समिति के अन्य सदस्य थे—चंदू बोर्डे (महाराष्ट्र), हरी नारायण डोंगर (उत्तरप्रदेश), डी.पी. शास्त्री (गुजरात) और देशप्रेम आजाद.

10 अप्रैल को पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँचने वाली स्कूली टीम का कप्तान दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले 17-वर्षीय मनिंदरसिंह को बनाया गया है. बाल भारती एयर फोर्स स्कूल का 12वीं का छात्र मनिंदर वामहस्त स्पिनर है. क्रिकेट के ज्ञाता उस में बेदी का भविष्य देख रहे हैं. उस के सहायक के रूप में महाराष्ट्र

के एस.जे. कल्याणी का चयन हुआ है. इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी महाराष्ट्र के हैं, तीन चंडीगढ़, तीन गुजरात और दो-दो दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश एवं तमिषनाडु व बिहार का एक-एक खिलाड़ी है. चुनी गयी पूरी टीम इस प्रकार है: मनिंदरसिंह (कप्तान दिल्ली), अशोक ठाकुर (दिल्ली), हेमंत अशोक टिपनिस, एन. चूरी, रनडोल्फ मॉरिस डेनियल्स व एस.जे. कल्याणी (सभी महाराष्ट्र), अनुराग श्रीवास्तव व राज दीपक भारद्वाज (दोनों उत्तरप्रदेश), सैय्यद शबा करीम (बिहार), राजेंद्रसिंह, चेतन शर्मा व संजीव अग्रवाल (सभी चंडीगढ़) राजू जडेजा, एम. मेहता, बी. गुजारा (सभी गुजरात) और शिवराम कृष्णन् (तमिषनाडु). टीम के साथ पी.आर. चौहान मैनेजर के रूप में और चंदू बोर्डे प्रशिक्षक के रूप में जायेंगे.

इस टीम के चार स्पिनर मनिंदरसिंह, हेमंत अशोक टिपनिस, अनुराग श्रीवास्तव और शिवराम कृष्णन् हैं वहीं तीन मध्यम गति के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा, राजू जडेजा और आर. डेनियल्स हैं. संजीव अग्रवाल, एम. मेहता और बी. गुजारा प्रारंभिक बल्लेबाज हैं. चुनी गयी टीम पर टिप्पणी करते हुए प्रशिक्षक चंदू बोर्डे ने कहा कि इन लड़कों में काफी क्षमता और सूझबूझ है. यह सिर्फ स्कूली क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रह जायेंगे बल्कि कई खिलाड़ी आगे भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की प्रगति की रफ्तार यही रही तो कुछ वर्षों में इन में से दो या तीन मध्यमगति के और दो स्पिनर भारतीय टेस्ट टीम में स्थान पाने में सफल होंगे. उन्हें स्पिनर मनिंदर सिंह व शिवराम कृष्णन् से ढेर सारी आशाएँ हैं.

—वीरेंद्र शुक्ल

## संक्षिप्त विज्ञापन

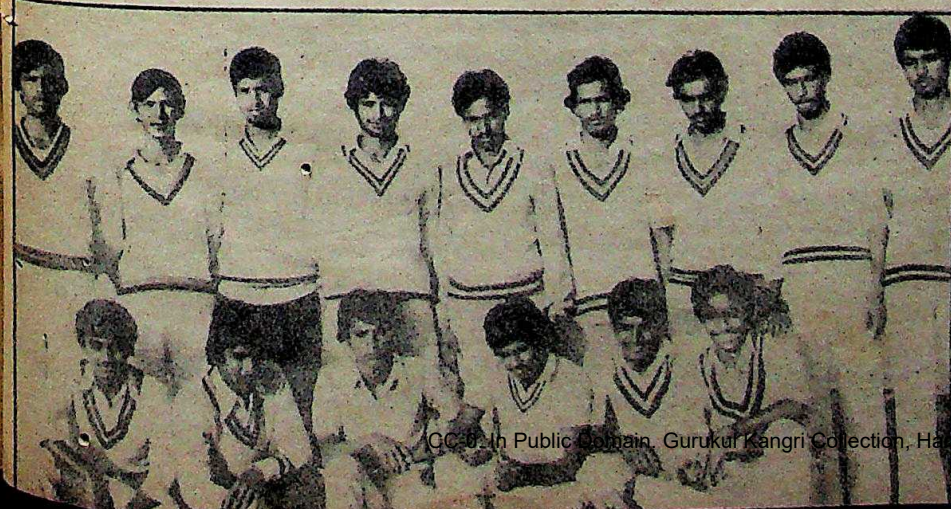
### शिक्षा संबंधी

कहानी-कला, लेख-रचना, प्रैक्टिकल इंगलिश, पत्रकारिता, पत्रिका-संचालन और पटकथा व टीवी लेखन का घर बैठे पत्राचार द्वारा अध्ययन करें. अपने विषय की विवरणी मंगाइये. कहानी-लेखन महाविद्यालय, रजि. (द), अम्बाला-छावनी-133001.

अपनी अंग्रेजी सुधारें, हमारे 'अच्छी अंग्रेजी' पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लें. विवरणी हेतु लिखें. इंस्टीट्यूट आफ जर्नलिज्म (द), पोस्ट बाक्स 3583, नयी दिल्ली-110024.

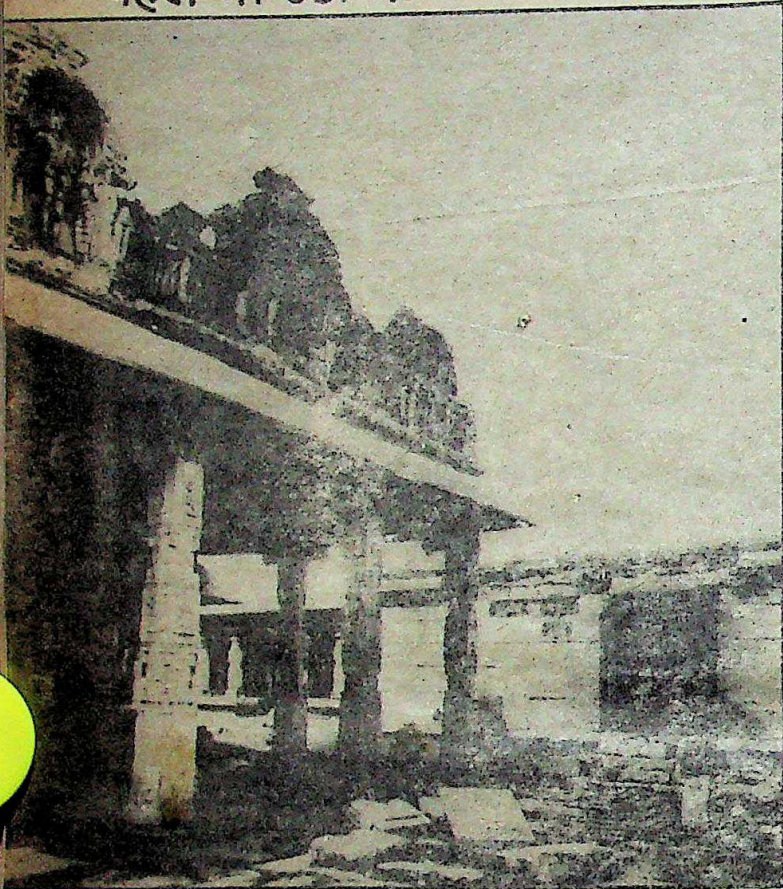
हमारे पत्राचार पाठ्यक्रम से आप पत्रकारिता का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. विवरणी मंगाइये. पत्रकारिता महाविद्यालय (द), जी-75, लाजपत नगर-1, नयी दिल्ली-110024.

11-17 अप्रैल '82





## फोटो निगेटिव नष्ट होने का सवाल पहले भी उठा था



बेल्लारी: विजय नगरम  
(कमलापुरम) का  
रामास्वामी मंदिर :  
महामंडप और यज्ञ-  
शाला : 1902 में  
खींचा गया यह  
चित्र पुरातत्व विभाग  
के फोटो अलबम  
निगेटिव संख्या 24  
से है.

**भारतीय** पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास 1902 से लगा कर अब तक के कोई एक लाख बीस हजार फोटो निगेटिव हैं। ये निगेटिव विभिन्न स्मारकों, कला स्थलों, कला-वस्तुओं और विभिन्न जगहों में खोजपूर्ण कार्यों के सिलसिले में की गयी खुदाई से संबंधित हैं। इनमें से कोई 50 हजार निगेटिव पुराने हैं और 72 हजार के करीब नये हैं। पिछले दिनों बंबई स्थित अंग्रेजी के एक साप्ताहिक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई कि करीब 50 हजार फोटो निगेटिव दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के तलघर में और कोई 50 हजार दिल्ली के ही सफदरजंग मकबरे में रख रखाव की असावधानी से नष्ट हो गये हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी। इस से पहले भी नवंबर 1978 में लोकसभा में संसद सदस्य ओमप्रकाश त्यागी ने यह सवाल उठाया था कि क्या छह हजार फोटो निगेटिव असावधानी से नष्ट हो गये हैं या हो जाने दिये गये हैं? एक प्रश्नोत्तर में तत्कालीन, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा. प्रतापचंद्र चंदर ने बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास पुराने स्मारकों के कोई 50 हजार फोटो निगेटिव हैं। और उन की देखरेख अच्छी

तरह की जा रही है। समय समय पर यह जाँचा जाता है कि उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुँची। इसी तरह की जाँच के दौरान अब तक (यानी 1978 तक) यह पाया गया कि 300 निगेटिव जरूर ऐसे हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और उन का पुनरुद्धार कठिन है। लेकिन यह क्षति किसी अधिकारी या सर्वेक्षण की असावधानी के कारण नहीं हुई बल्कि समय के साथ हुई है। कई निगेटिव अत्यंत पुराने हैं और समय की मार से ही उन्हें क्षति पहुँची है। तब उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि इन पुराने और मूल्यवान निगेटिवों को अच्छी तरह सहेज कर रखा जाये। इस सिलसिले में मंडारण की सुविधाएँ और बढ़ायी जायेंगी।

मंडारण की क्या सुविधाएँ बढ़ायी गयी हैं, और क्या वास्तव में इन पिछले चार वर्षों में एक बहुत बड़ी संख्या में वे फोटो निगेटिव नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गये हैं? जब दिनमान ने इस की खोजबीन शुरू की तो ये तथ्य प्रकाश में आये कि इन पिछले चार वर्षों में पहले के तीन सौ के अतिरिक्त और कोई फोटो निगेटिव नष्ट नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दरअसल बंबई की परमा फिल्म्स को पुराने फोटो निगेटिवों के संजीवन का काम सौंपा गया है (जिन्होंने इस काम के लिए सफदरजंग मकबरे में ही एक विशेष लैबोरेटरी भी बनायी है।) और यह व्यावसायिक संस्था पुराने फोटो निगेटिवों को भविष्य में क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विशेष तकनीकी उपायों से सहेज रही है। दरअसल यह काम इस संस्था को इन फोटो निगेटिवों को संजीवन देने के लिए ही सौंपा गया है। लेकिन संभवतः केवल इतनी खबर से कि बंबई की यह संस्था इन्हें संजीवन दे रही है यह भ्रम पैदा हुआ कि वे फोटो निगेटिव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन्हीं वरिष्ठ अधिकारी ने, जो पुरातत्व विभाग में दो दशक से भी अधिक समय से सेवारत हैं, यह जानकारी भी दी कि 'वस्तुस्थिति तो यह है कि न केवल सभी फोटो निगेटिव सुरक्षित हैं बल्कि उन सभी के फोटो अलबम भी हमारे पास सुरक्षित हैं। जिन्हें देश विदेश के शोधकर्ता और विद्वान समय समय पर अपने काम के लिए उपयोग में भी लाते रहते हैं। अगर एक क्षण के लिए यह मान भी लें कि कभी फोटो निगेटिव नष्ट हो भी जायें तो भी इन फोटो अलबमों के माध्यम से नयी फोटो प्रतिकृतियाँ और फिर उन से निगेटिव भी बनाये जा सकते हैं। इसलिए साप्ताहिक समाचार पत्र की यह आशंका भी सही नहीं है कि ऐसे पुराने स्मारक जो नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनके साक्ष्य के लिए सर्वेक्षण के पास अब कोई चित्र भी उपलब्ध नहीं हैं। सभी निगेटिव सफदरजंग मकबरे में शीतताप नियंत्रित कमरों में रखे जायेंगे।'

भारतीय पुरातत्व विभाग के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'सर्वेक्षण इस तरह की चीजों के रखरखाव के प्रति पूरी तरह से सचेत है। उसका अपना एक फोटो विभाग तो है ही जो नये-पुराने फोटो-चित्र निगेटिव बनाता सहेजता है, बल्कि जो खुदाइयाँ पिछले वर्षों में हुई हैं उन्हें लेकर कुछ लघु फिल्मों में भी सर्वेक्षण के ही फोटो विभाग ने तैयार भी की हैं। ये फिल्में विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं में दिखायी भी जाती रही हैं।'

राष्ट्रीय संग्रहालय से संपर्क किये जाने पर वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'मले ही वे निगेटिव हमारे यहाँ रखे हुए हों लेकिन उन के रखरखाव की जिम्मेवारी तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है और उन से संबंधित जानकारी तो वही लोग दे सकते हैं।' और फोटो निगेटिव नष्ट हुए हैं या नहीं इस पर टिप्पणी न करते हुए भी उन्होंने यह टिप्पणी तो कर ही दी कि 'अगर ऐसा सचमुच होता तो उस की कोई खबर तो हम लोगों तक भी पहुँचती।'

—प्र. शु.



नृत्य

## कथक में ओज का सौंदर्य

दरअसल निगेटिवों (जिन्होंने ही एक और यह टिप्पणी को के लिए रही है. न फोटो र से कि रही है टिव बुरी वरिष्ठ न में दो भारत हैं, तो यह रक्षित हैं भी हमारे शोधकर्ता के लिए क क्षण के निगेटिव लवमों के और फिर इसलिये शंका भी नष्ट या ए सर्वेक्षण डब नहीं करवरे में मायेंगे.

एक अन्य क्षण इस पूरी तरह विभाग निगेटिव पिछले फलमें भी र भी की संस्थाओं जाने पर कि 'भले' में लेकिन भारतीय उन से सकते हैं. इस पर टिप्पणी होता तो तक भी प्र. शु. प्रैल '82

शोभना नारायण के नृत्य का सौंदर्य ओज और उद्दामता का सौंदर्य है. वह मंच पर पहाड़ी जल प्रपात की तरह नाचती हैं. युवा कथक नृत्यांगनाओं में इस दृष्टि से वह सर्वश्रेष्ठ हैं. इतनी द्रुत गतिमयता किसी और में नहीं. बिजली और बवंडर की तरह वह आती हैं और लंबे से लंबे कार्यक्रम में भी अंत तक वैसी ही बनी रहती हैं. पुरुष कलाकारों में यह उद्दाम रूप दुर्गालाल में मिलता है. लय, गति, समझ और गणित में पूरा खरापन उन में मौजूद है, टुकड़े, परन, तोड़े, सब निखर कर दमकते हैं—साफ सुथरे तराशे हुए. जितने अच्छे संगतकार होंगे उन का नृत्य उतना ही चमकेगा. 31 मार्च को राजधानी के फिक्की हाल में आयोजित उन के नृत्य कार्यक्रम में इस दिशा में कमी रह गयी थी. केवल ज्वाला प्रसाद का गायन ही उमर कर साथ दे रहा था. शोभना नारायण का नाचने का ढंग पुरानी ही परंपरा का है. नाच के बीच पड़ंत वह करती हैं. उन के नृत्य के लिए यह शीक भी है. यद्यपि कई नृत्यांगनाएँ अब इस से रचनात्मक स्तर पर मुक्त हो रही हैं. लेकिन शोभना नारायण का झुकाव नृत्य की गीत्यात्मकता की ओर नहीं है, यदि वह इस ओर वही तो वह उन के नृत्य की प्रकृति से मेल नहीं खायेगा. अपने नृत्य के इस उद्दाम रूप को उन्हें बनाये रखना है और ऐसी ही चीजें नाचने के लिए चुननी हैं जिन में यह रूप सुरक्षित रहे. वह प्रयोगशील भी हैं. यह उन का दूसरा गुण है. हर जीवंत कलाकार प्रयोगशील होता है. पुरानी ठुमरियाँ छोड़ कर इस बार उन्होंने 'अदा' और 'चाँद' दो नृत्य पेश किये,—दोनों ही भावामिव्यक्तियाँ थीं. 'अदा' में उर्दू के शेर गूँथे गये थे और 'चाँद' में मूर, वचन से ले कर जायसी तक की कविताओं से चाँद संबंधी टुकड़ों की झाला पिरोई गयी थी. दोनों नृत्यों में अभिनय और लास्य अंग की जरूरत थी. अभिनय काफी कुछ शोभना नारायण निभा ले गयीं और भावानुकूल गीत्यात्मक कोमलता अपने नृत्य में वह नहीं पिरो सकीं. इस का कुछ कारण नृत्य संरचनाओं की परिकल्पना में भाव की कमी भी थी. दोनों और संक्षिप्त भी चाहिए थीं. कुछ शेर और कम किये जा सकते थे. वैसे शोभना नारायण जैसी स्तरीय नृत्यांगना के लिए यह जरूरी है कि साहित्य को चुनाव, ठीक करें. हल्के शेर न चुन, उस्तादों को बेहिया कलाम ले. 'चाँद' में भी स्थिति को सघनतर करते जाने वाले काव्यांश और उनके चुनाव में भाषा की एकरूपता पर ध्यान देना जाना चाहिए था जिस से यह नृत्य



ऊपर श्रुतिगुप्ता: निष्ठावान शिष्या (दाहिने) शोभना नारायण: समर्थ गुरु और प्रतिभाशाली कलाकार



रचना पूरा अपेक्षित प्रभाव छोड़ती. प्रस्तुति में काफी कमी तो फिक्की हाल में माइक्रोफोन की गड़बड़ी थी और कुछ प्रकाश नियोजक का प्रकाश नृत्य! थिर समरूप प्रकाश भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहली शर्त है. इन बाहरी कमियों के होते हुए भी शोभना नारायण अपने सहज नृत्यावेग, विशुद्ध व्याकरण तथा मात्राओं की सटीक अन्विति, धुंधलकों के अंदाज तथा खुले मुक्त भाव से युक्त अपनी कला के प्रदर्शन से दर्शकों पर सुंदर छाप छोड़ गयीं.

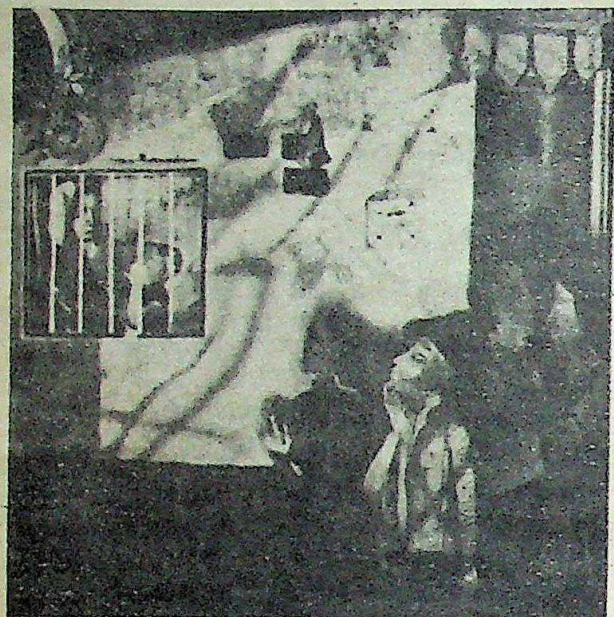
तीसरी विशेषता उन का गुरु रूप है. उन के नृत्य के पूर्व उन की शिष्या श्रुति गुप्ता के काम से यह पता चलता है. श्रुति का मंच पर यह पहला अवतरण था. सुंदर देहयष्टि, गरिमापूर्ण मंच उपस्थिति, पूर्ण आत्मविश्वास और स्वयं आनंद लेते हुए बेझिझक अपना काम पेश करते श्रुति को देखना उस के भविष्य के प्रति आश्चस्त होना ही था. काफी कुछ सफाई उस के काम में है. शोभना से ओज और मंच पर खुलापन उस ने बखूबी सीखा है.

अभिनय पक्ष भी उस का मजबूत है. अपने इस प्रथम प्रदर्शन में उस ने आश्चर्य चकित किया और भविष्य में एक बड़ी नृत्यांगना की प्रतीक्षा जगा दी. अच्छा ही है कि कोई कलाकार खुद को और साथ साथ दूसरों को रचता निखारता चले.

शोभना नारायण की चौथी विशेषता को जानना नृत्य प्रेमियों के लिए जरूरी नहीं है. लेकिन इसे जानकर उनके कला व्यक्तित्व और नृत्य के प्रति उनकी अटूट लगन, उनकी साधना और समर्पण को समझा जा सकता है. वह भारतीय लेखा परीक्षा सेवा (आए.ए. ए.एस.) डिप्टी डाइरेक्टर (आडिट) हैं और उन्हें अपने कार्यालय के काम में भी पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त है. दो दिरीत रास्तों को संतुलन से निभा सकने की सामर्थ्य शोभना नारायण को एक विवेकशील निष्ठावान कलाकार के ही रूप में प्रतिष्ठित नहीं करता है, एक समर्पित कला व्यक्तित्व की गरिमा से भी संहित करता है.

—स.व.स.





(ऊपर-बायें से) सुरचि  
चाँद की चित्रकृति :  
'गुजरात के एक गाँव में  
ब्रितानी पर्यटक' और  
जोगेन चौधरी का एक  
रेखांकन

## अपने रंगों की बात

समूह प्रदर्शनियाँ कुछ मामलों में बराबर दिलचस्प होती हैं। एक तो यही कि कई कलाकारों का काम एक साथ प्रदर्शित हो कर उन्हें एक विविधता दे देता है, दूसरे यह कि कलाआस्वाद को बढ़ाने वाली कुछ जरूरी तुलनाएँ उन के बहाने सुलभ हो जाती हैं। पिछले दिनों घुमीमल गैलरी ने एक समूह प्रदर्शनी आयोजित की। इस में जामिनी राय से ले कर जोगेन चौधरी तक का काम था। यह दिल्ली की सब से पुरानी गैलरी है और जामिनी राय, शैलोज मुखर्जी, हुसैन, सूजा, सतीश गुजराल, ज. स्वामीनाथन, शांति दवे से ले कर हिम्मतशाह, परमजीत सिंह, अपिता सिंह, विकास मट्टाचार्य और मनजीत बाबा, अमिताभ दास, जय झरोटिया जैसे युवा चित्रकार इस से जुड़े रहे हैं।

हाल ही में आयोजित समूह प्रदर्शनी में भी पुरानी नयी पीढ़ी के कोई बीस कलाकारों का काम था। इस प्रदर्शनी के माध्यम से—भले ही कुछ कम उदाहरणों से—समकालीन भारतीय कला के पिछले कई दशक आँखों के आगे आ जाते हैं। और फिर जो बात सब से अधिक उभर कर सामने आती है वह यही कि समकालीन भारतीय कला को कुछ निरा पश्चिम प्रेरित व्याघातों से छुटकारा मिलता गया है। और वह अब निश्चय ही अपनी जमीन पर भी खड़ी मालूम होती है। जाहिर है कि इस में जामिनी राय, शैलोज मुखर्जी जैसे चित्रकारों का हाथ तो शुरू से रहा लेकिन बाद की

पीढ़ियाँ भी उन तथाकथित अंतरराष्ट्रीय मुहावरों से छुटकारा पाती गयीं जो बीच में कुछ असें के लिए समकालीन भारतीय कला में एक अंधड़ की तरह आ गये थे। (इनसे पूरी तरह छुटकारा मिल गया हो ऐसी बात नहीं लेकिन कम-से-कम कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों ने उनसे 'छुटकारा' दिलाया जरूर है)। यह सवाल कई अंग्रेजी समीक्षक अब भी उठाना पसंद करते हैं कि समकालीन भारतीय कला भले ही अब अपनी जमीन पर खड़ी दीख पड़ती हो लेकिन विश्व कला के स्तरों से जाँचें तो उस के पास बड़े नाम और बड़े काम कम ही दिखायी पड़ेंगे।

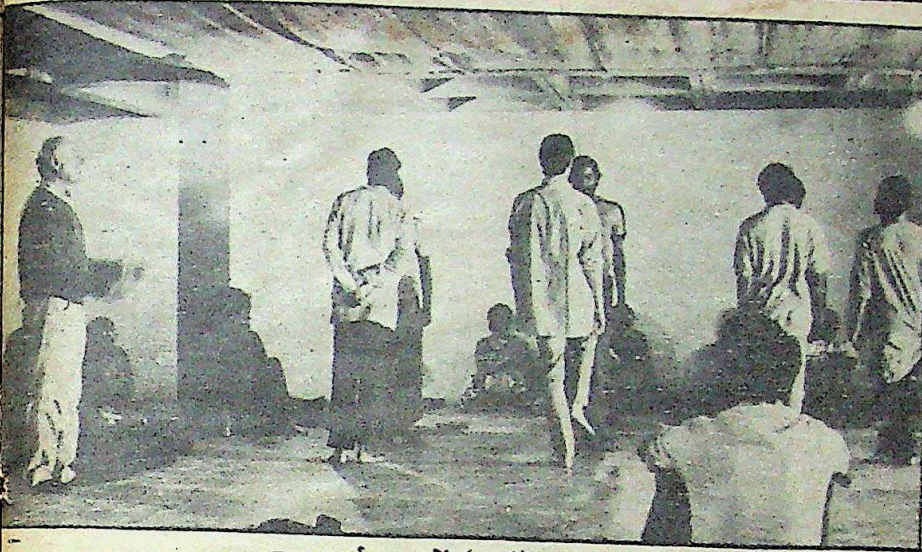
हम समझते हैं कि यह कहना सवाल को गलत सिरे से उठाना है और अपने को कुछ जबरदस्ती प्रतियोगी बनाना है। क्योंकि सवाल तो कला में और कलाकृतियों में बराबर यही होता है या होना चाहिए कि वे किन्हीं रचनात्मक शक्तों को पूरा कर रही हैं या नहीं—वे अपने को किसी रचनात्मक संघर्ष में डाल रही हैं या नहीं। (वैसे इसका यह आशय नहीं कि विश्व कला के संदर्भ में हम अपने को कमी देखें ही नहीं)। इस दृष्टि से देखें तो इस समूह प्रदर्शनी की सभी कृतियों के बारे में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वे इन शक्तों को पूरी तरह से पूरा करती हैं लेकिन निश्चय ही कुछ कलाकृतियाँ अपने को उन जीवन स्थितियों, परंपराओं, परिवेश से जोड़ रही हैं जिस के बीच वे रंची गयी हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा साक्ष्य तो वह रंगव्यवहार ही है जिसे अगर 'भारतीय' न भी कहना चाहें, तो उसे उसी आकाश के नीचे का

कहेंगे जिस के भीतर भारत की भौगोलिक और जलवायु संबंधी सीमाएँ आती हैं।

दिल्ली की श्रीवराणी गैलरी में बंबई की कलाकार श्रीमती सुरचि चाँद के चित्रों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई। उन के चित्रों पर टिप्पणी करने से पहले उन के चित्रों में प्रयुक्त कई तत्वों-रूपों का विवरण सामने रखना अच्छा होगा। अपने आकृतिमूलक चित्रों में वह लोकप्रिय, लोक, नागर, आधुनिक रूपों को जैसे एक साथ रखती मालूम होती हैं। और कुछ पारंपरिक शैलियों को भी—जैसे कि मिनीयेचर चित्रों के कुछ शैली तत्वों को। वह कहीं इस सदी को भी सामने रखती हैं। उन के चित्रों में हनुमान हैं तो वैज्ञानिक आइंस्टीन भी और हनुमान के हाथ में भी संजीविनी न हो कर आणविक ईंधन है। जाहिर है कि प्रत्यक्षतः वह काल की दूरियों को भी रखना चाहती हैं और उस की निरंतरता को भी जिस में कि कई मानवीय व्यापार घटित होते हैं। सुप्रसिद्ध चित्रकार सूजा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि 'ये चित्र काल में नष्ट होने वाली चीजों और फिर भी न नष्ट होने वाली चीजों के बारे में हैं'।

लेकिन चित्रता गुणों का सवाल बचा रहता है। मस्तिष्कीय सक्रियता जरूरी नहीं कि रचनागत सक्रियता भी बन जाये। एक बौद्धिक व्यायाम के रूप में और कहीं कहीं अपने एक सहज और ऐंद्रिक (रंगों के मामले में) अंकन के लिए, ये चित्र कहीं कहीं आकर्षित करते जरूर हैं लेकिन तब इन दोनों स्थितियों के बीच जो दूरी है वह एक फाँक की तरह फिलहाल इन चित्रों में बनी भी हुई है।





नाट्य कार्यशाला में (बाएं) पीटर ब्रुक

## एक उत्तेजक और सार्थक अनुभव

नेमिचंद्र जैन

पिछले दिनों मोपाल में भारत भवन के द्वाटन के अवसर पर होने वाले विभिन्न लाओं के समारोह के अंतर्गत नाट्यकला चार दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित हुई। इस के संचालक थे विश्व विख्यात रंग दशक पीटर ब्रुक और उस में मौजूद थे देश से, विशेष कर हिंदी क्षेत्र के, अनेक प्रति- त और उदीयमान निर्देशक, अभिनेता, रंग- ल्पी, नाटककार, समीक्षक आदि—कुछ कय सहभागियों के रूप में और कुछ केवल वेक्षक की हैसियत से।

निस्संदेह समकालीन भारतीय रंग जगत लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। पीटर ब्रुक जैसे दुनिया भर में अपने कल्पना- ल और साहसिक रंगकार्य तथा मौलिक रंग चिंतन के लिए बहुचर्चित नाट्य निर्दे- भारतीय रंगकर्मियों के साथ अपने बहु- री सर्जनात्मक अनुभव की सक्रिय भागी- के लिए आये। किसी हद तक यह सर्वथा साविक ही था कि देश की सभी भाषाओं रंगकर्मियों को ऐसे आदान-प्रदान के लिए करने की पहल हिंदी रंग क्षेत्र की ओर से और यह तो लगभग अनिवार्य ही था ऐसा आयोजन मोपाल में हुआ, क्योंकि देश की श्रेष्ठ सर्जनात्मक चेतना के रूपों और माध्यमों को एक साथ लाने उन के आंतरिक संबंधों को पहचानने का पिछले कई वर्षों से होता ही रहा है। अब भवन की स्थापना के साथ वह कलाओं विप्रमुख बहुआयामी केंद्र के रूप में पूरी कता और साधन संपन्नता के साथ उभर है। यह मोपाल में ही संभव था कि कार्य- की प्रारंभिक आम बैठक में प्रमुख

रंगकर्मियों के अलावा देश के अनेक चित्र- कार, मूर्तिकार, गायक, नर्तक, कवि, लेखक आदि भी सम्मिलित हुए।

चार दिन में कार्यशाला की सात बैठकें हुई—पहले तीन दिन दोपहर को भोजन के लिए अवकाश के साथ दो दो और अंतिम दिन सबेरे से शाम तक लगातार एक, इन में से पहली बैठक में, जैसा पहले जिक्र किया गया, अनेक दर्शक भी मौजूद थे। बाकी में केवल सहभागी ही रहे। साथ ही कुछेक ऐसे लोगों को भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गयी जो सारी बैठकों में मौजूद रहने को तैयार थे—यानी जिन्हें कार्यशाला की पूरी प्रक्रिया से गहरा लगाव तो था, पर जो किसी न किसी कारण उस के कार्यक्रमलाप में सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे। पीटर ब्रुक का आग्रह था कि निरे शौकिया दर्शकों की उपस्थिति पूरे मनोयोग और लगाव से काम करने में बाधक होती है।

कार्यशाला की अवधि निस्संदेह बहुत कम थी। चार दिन में तो रंगसृष्टि के किसी छोटे से छोटे और प्रारंभिक सूत्र का भी कोई सार्थक अन्वेषण या परीक्षण असंभव है। इस के अलावा उस के सहभागी रंगकर्मियों की रुचियों के क्षेत्र, रंगकार्य के अनुभव, शिल्पगत निपुणता और सर्जनात्मक चेतना तथा समझ के स्तर में इतनी असमानता थी कि प्रायोगिक कार्य का कोई सामान्य सूत्र या रूप इतनी जल्दी तय कर पाना मुश्किल था।

एक अन्य बुनियादी कठिनाई भाषा की थी। भाग लेने वालों में हिंदी के अतिरिक्त बंगला, मराठी, कन्नड़, उड़िया आदि कई भाषा क्षेत्रों के लोग थे। जिस के कारण व्यावहारिक

कार्य में कई बार अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया। ऐसी अम्यासिक- ताओं को सारे सहभागी भी पूरी तरह नहीं समझ सकते थे, पीटर ब्रुक स्वयं तो कोई भारतीय भाषा जानते ही नहीं हैं। साथ ही अनेक सहभागी इतनी अंग्रेजी नहीं जानते थे कि उस में अपने विचार या प्रतिक्रियाएँ भी ठीक से जाहिर कर सकें, जिस के कारण विचारों के स्तर पर भी आदान प्रदान में पूरी सहजता नहीं हो सकती थी। सर्जनात्मक स्तर पर संप्रेषण या समझ पाने के लिए कोई दूसरे उपाय करना भी समय की कमी को देखते हुए मुमकिन न था।

इन सब सीमाओं के बावजूद, पीटर ब्रुक ने विभिन्न देशों के रंगकर्मियों के साथ काम करने के अपने व्यापक अनुभव के आधार पर बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ ऐसे बिंदु से काम की शुरुआत की कि सर्जनात्मक रंगकर्म के कुछ बुनियादी तथा सभी रंगकर्मियों के लिए प्रासंगिक सवाल पर ध्यान केंद्रित हो सका। इसी लिए उन से गुजरकर या उन का सामना कर के अगर पुराने और अनुमेवी रंगकर्मियों को ताजगी और एक तरह के कायाकल्प का अहसास हुआ, तो युवा रंग- कर्मियों को अपनी अपनी पहचान के लिए कुछ नए रास्ते दिखायी पड़े। दूसरे, पीटर, ब्रुक ने अपनी कार्यपद्धति में क्रिया और विचार का मिश्रण करते हुए हर मुद्दे पर व्यावहारिक अम्यासिका से शुरू कर के उस के विश्लेषण तथा सहभागियों के बीच बेझिझक विचार विनिमय पर आग्रह किया। इस के फलस्वरूप अम्यासिकाओं में निहित उद्देश्य और उस की सार्थकता को एक हद तक, कम से कम सर्जना- त्मक कार्य की एक जरूरी अवधारणा के रूप में, रेखांकित किया जा सका। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यह बेझिझक कहा जा सकता है कि इतनी छोटी अवधि का इस से अधिक सार्थक उपयोग नहीं हो सकता था।

कार्यशाला में मुख्यतः दो तरह की अम्या- सिकाएँ हो गयीं—एक वे जो पहले दो दिनों में स्वयं पीटर ब्रुक ने किसी विशेष पक्ष को उद्घाटित करने के लिए कुछ सहभागियों से करवायीं। दूसरी वे जिन्हें बाद में विभिन्न सहभागी निर्देशकों ने अपनी पसंद के अभि- नेता चुन कर उन के साथ पहले अलग से तैयार किया और फिर उन्हें सब के सामने प्रस्तुत किया। दोनों ही प्रक्रियाओं में पीटर ब्रुक ने अपने सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा रंगकार्य में सर्ज- नात्मकता के एक न एक तत्व को स्पष्ट किया।

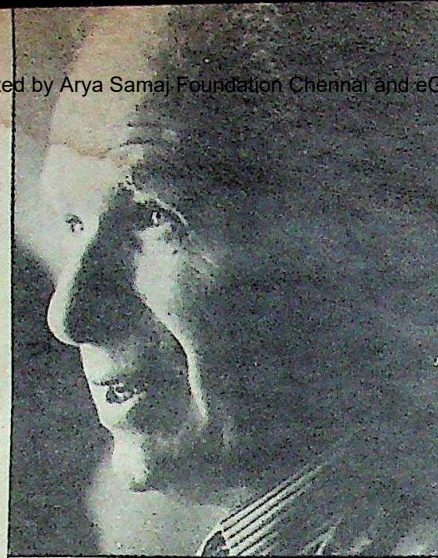
पीटर ब्रुक ने इस बात पर कई प्रकार से जोर दिया कि अभिनेता दर्शक को उतना ही और वही अर्थ संप्रेषित कर सकता है और कर पाता है जितना और जो उस ने स्वयं



हासिल किया हो, अनुभव किया हो। कार्यशाला की प्रारम्भिक बैठक में ही उन्होंने वहाँ मौजूद एक प्रकार से शेक्सपीयर के किसी नाटक की कोई पंक्तियाँ पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में ऐसे बोलने को कहा कि उन का अर्थ श्रोताओं तक पहुँच सके। उस ने विख्यात नाटक हैमलेट की सुपरिचित पंक्ति 'टु बी आर नाट टु बी दैट इज दि क्वेश्चन' पंक्ति चुनी और उसे कई प्रकार से बोल कर प्रस्तुत किया। इस कोशिश के बड़े संवेदनशील और पने विश्लेषण द्वारा पीटर ब्रुक ने यह उजागर किया कि किसी महान नाटक की अत्यंत अर्थगर्भित पंक्तियों को भी यदि अभिनेता यांत्रिक ढंग से या अतिरंजित नाटकीयता के साथ बोलेंगे तो वह यांत्रिकता या अतिरंजित नाटकीयता ही संप्रेषित होगी, उन पंक्तियों का कोई गहरा अर्थ नहीं। अभिनेता यदि किसी घिसी पिटी गति, भंगिमा अथवा वाक् शैली का व्यवहार करता है तो इस का मतलब यही है कि वह किसी और की अभिव्यक्ति को यांत्रिक रूप में दोहरा भर रहा है, उस गति, भंगिमा या वाक् शैली का अर्थ स्वयं अनुभव नहीं कर रहा। इसी लिए उस का दर्शक पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत ही सतही प्रभाव पड़ता है। किसी भी अन्य कला की भांति रंगसृष्टि भी उसी हद तक सर्जनात्मक और प्रभावी हो सकती है जिस हद तक उस में चालू मुहाविरों या नुस्खे से बच कर अपने निजी अनुभव को पहचानने और उसी को गति, भंगिमा या वाक् शैली का आधार बनाने की कोशिश होती है।

इसी तरह एक सहभागी से घड़ी की टिक-टिक जैसी आवाज निकालने के लिए और उसी के साथ दो अन्य से लगभग तीस सैकंड की अवधि में मिल कर किसी नाटकीय स्थिति की रचना के लिए कहा गया। किंतु इस अभ्यासिका के दौरान पाया गया कि इतनी कम अवधि को भी पूरी तरह अर्थ-सघन, विशिष्ट और आकर्षक बनाये रखना कितना कठिन होता है, और यदि अभिनेता को सर्जनात्मक दृष्टि तथा निरंतर चयन की क्षमता सक्रिय न हो तो अनेक अनावश्यक शब्द, भंगिमाएँ, शारीरिक क्रियाएँ या गतियाँ हमारी अभिव्यक्ति में जुड़ती चली जाती हैं। रंग सृष्टि में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, और अभिनेता अपने पूरे मनोयोग, एकाग्रता तथा आंतरिक सच्चाई द्वारा ही प्रत्येक क्षण को जीवंत और सार्थक बनाये रख सकता है।

रंग-सृष्टि में प्रत्येक क्षण को जीवंत रखने और निर्भरतापूर्वक सभी गैरजरूरी, अतिरिक्त और चालू, घिसी पिटी भंगिमाओं, क्रियाओं, गतियों आदि को निकालने की अनिवार्य आवश्यकता को बाद में कुछ और अभ्यासिकाओं द्वारा भी रेखांकित किया गया। जैसे, तीन अभिनेताओं को किसी एक संरचना में



पीटर ब्रुक : गहरे अर्थों की खोज

विशेष भंगिमा के साथ स्थिर कर के अलग अलग निर्देशकों से पूछा गया कि इस दृश्य स्थिति से कौन सा क्या बिंब उन के मन में उमरता है। फिर उन से अपने ही बिंब के अनुसार एक ऐसी नाट्य-स्थिति तैयार करने को कहा गया जो तीस सैकंड पहले से शुरू होती हो और फिर दो हुई संरचना से गुजर कर आगे तीस सैकंड तक चली जाती हो।

इस अभ्यासिका में कई निर्देशकों ने भाग लिया और बार बार यह पाया गया कि इस एक डेढ़ मिनट के दृश्य व्यापार को भी पूरी कलात्मक सतर्कता और आत्मानुशासन के बिना जीवंत, मौलिक और घिसी पिटी युक्तियों से मुक्त नहीं रखा जा सकता।

मगर इन तथा इसी प्रकार ध्वनि संरचनाओं के साथ की गयी अभ्यासिकाओं का कुछ और भी लक्ष्य था। प्रत्येक गति, भंगिमा या ध्वनि में अनेक भाव-बिंबों की संभावनाएँ मौजूद हैं और अभिनेता उन के प्रति संवेदनशील हो कर ही अपनी कल्पना और आंतरिक सच्चाई के आधार पर किसी एक भाव या विचार के लिए उन का इस्तेमाल कर सकता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक ध्वनि के प्रति ऐसी संवेदनशीलता के बिना जीवंत अभिनय और रंग सृष्टि संभव नहीं। कार्यशाला के दो दिनों के पहले चरण में ऐसी ही अनेक छोटी छोटी कार्यमूलक अभ्यासिकाओं के माध्यम से सहभागियों ने रंगकर्म को कुछ मूलभूत चुनौतियों और संभावनाओं से साक्षात्कार किया।

एक अन्य प्रकार की प्रक्रिया विभिन्न निर्देशकों द्वारा तैयार की गयी चार पांच मिनट की आशु रचनाओं (इंप्रोवाइजेशन) की प्रस्तुति और विश्लेषण की थी। कार्यशाला के दूसरे चरण में अंतिम दो दिन में ऐसी सात आठ रचनाएँ प्रस्तुत हुईं जिन्हें तैयार करने वालों में प्रतिष्ठित और नये सभी तरह के निर्देशक थे। जाहिर है सभी रचनाएँ एक ही स्तर की अथवा सर्जनात्मक कलात्मक दृष्टि से

पूरी तरह सफल नहीं थीं पर उन की असफलता या कमजोरी से भी रंगसृष्टि की—किसी न किसी बुनियादी जरूरत या चुनौती पर रोशनी पड़ी।

विशेषकर दो नये युवा निर्देशकों के काम ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बंबई के युसुफ मेहता ने अपनी रचना का शीर्षक दिया 'भागलपुर - 1981' और उस में रीतिबद्ध शैली में बाद्य संगीत की लय के साथ देश की इस अत्यंत विक्षोभकारी घटना की एक निजी प्रतिक्रिया को प्रस्तुत किया। रचना में एक प्रकार की संपूर्णता थी और पारंपरिक शैली की गतियों, भंगिमाओं आदि का बड़ा संयत, कल्पनाशील और सर्जनात्मक प्रयोग था। रचना अभिनेताओं के सहयोग और कौशल के अलावा मुख्यतः निर्देशक की सूझबूझ को जाहिर करती थी।

बंबई के ही एक युवा निर्देशक महेंद्र जोशी की रचना दो अवकाशप्राप्त वृद्ध रंगकर्मियों को ले कर थी—एक अभिनेता और एक नर्तक इस में एक प्रदर्शन देखने के बाद इन दोनों के विभिन्न मनोभावों को प्रस्तुत किया गया था। रचना में अभिनेता की संवादमूलक और नर्तक की गतिमूलक प्रतिक्रियाओं की विसदृशता (कंट्रास्ट) के कुशल उपयोग के अलावा नर्तक द्वारा अपने सक्रिय गौरवपूर्ण दिनों की याद तथा ललक, वर्तमान अक्षमता से उत्पन्न असहायता की कठुणा आदि भावों की व्यंजना बड़ी सूक्ष्म, ब्यौरेवार और विविधतापूर्ण थी। इस रचना की परिकल्पना में भी नाटकीय संपूर्णता मौजूद थी।

जहाँ पहली रचना परंपरा के सर्जनशील अन्वेषण को रेखांकित करती थी, वहीं दूसरी में अभिनय की जीवंतता के लिए अनुभव की यथार्थता और अभिव्यक्ति की समृद्ध मूर्तता की अनिवार्यता उजागर होती थी।

एक अन्य रचना अभिज्ञान शंकुतल के प्रथम अंक की एक अत्यंत संक्षिप्त सी स्थिति के अन्वेषण पर आधारित थी, जिसे पहले विजया मेहता ने ही अलग अलग अभिनेत्रियों कलकत्ते की चेतना जालान तथा पीटर ब्रुक की पत्नी नाटाशा—के साथ और फिर सत्यदेव दुबे ने केवल नाटाशा के साथ प्रस्तुत किया। इस अभ्यासिका का महत्व एक स्त्री के रूप में शंकुतल की मानसिकता के ऐसे अन्वेषण में था जो उस की सामान्यतः स्वीकृत पारंपरिक लगभग रीतिसम्मत प्रतिमा से हट कर एक ऐसा रूप प्रस्तुत कर सके जो समकालीन संवेदना और चेतना के अधिक समीप भी हो और पूरी तरह मानवीय भी, मौलिक, अप्रत्याशित तथा विशिष्ट भी और विश्वसनीय भी। कुछ अतिरिक्तपूर्ण प्रयोगशीलता की आशंका के बावजूद अभ्यासिका से यह बात रेखांकित हुई कि मिथकीय, क्लासिकी अथवा परिचित से परिचित चरित्र के अभिनय को



असफलता  
—किसी न  
सीती पर

के काम  
के युक्त  
क दिया  
रीतिवद्  
य देश को  
एक निजी  
में एक  
रेक शैली  
डा संयत,  
योग था.  
र कोशल  
सबूझ को

हेंद्र जोशी  
रंगकर्मियों  
एक नर्तक  
दोनों के  
गया था.  
और नर्तक  
विसदृशता  
अलावा  
दिनों की  
से उत्पन्न  
नियंजना  
पूर्ण थी.  
नाटकोप

सर्जनशील  
ही दूसरी  
नुभव की  
द्व मूर्तता

कुतल के  
सी स्थिति  
जसे पहले  
भिनेत्रियों  
पीटर ब्रुक  
और फिर  
थ प्रस्तुत  
एक स्त्री  
के ऐसे  
स्वीकृत

मा से हट  
जो सम-  
वक समीप  
मौलिक,  
विश्वस-  
शीलता की  
यह बात.  
की अथवा  
मिनय को  
अप्रैल '82

भी जीवंत, मौलिक और विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिनेता पूर्वग्रह से मुक्त हो कर चरित्र के भीतरी व्यक्तित्व की अनेक प्रकार से पड़ताल करे.

कार्यशाला में हर अभ्यासिका के बाद अनेक रूपों में सहभागियों के बीच और पीटर ब्रुक के साथ संवाद द्वारा रंगकला के बहुत से मूल्यवान सूत्र बार बार उभरते रहे. इसी कारण समय की कमी के बावजूद उपलब्धि का अहसास बना रहा. अनेक सहभागियों ने अनुभव किया और कहा भी कि कार्यशाला के अनुभव से या तो उन्हें ताजगी महसूस हुई, या उन के पूर्वग्रह कुछ ढीले हुए, या काम के लिए नयी राहें दिखायी पड़ीं.

इस कार्यशाला के सहभागियों की ऐसी प्रतिक्रियाएँ इस लिए और भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारे देश में, विशेष कर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, कार्यशाला का भी—मले ही वह चार, छह या आठ हफ्ते चले—एक तरह का घिसा-पिटा नुस्खा—जैसा बन गया है, जिस में या तो बे-सिरपैर के अथवा अधकचरे तथाकथित प्रयोग होते हैं, या बहुत ही सामान्य कोटि की प्रस्तुतियाँ तैयार की जाती हैं. इस का श्रेय पीटर ब्रुक की अपनी सूझबूझ और रंगकला से गहरे लगाव को ही दिया जाना चाहिए कि यह अत्यंत अल्पकालीन कार्यशाला भी अधिकांश सहभागियों और पर्यवेक्षकों के लिए इतनी सार्थक, उत्तेजक और अविस्मरणीय अनुभव बन गयी.

### कार्यशाला के सहभागी

बंबई से विजया मेहता, मन्थदेव बुने, हेंद्र जोशी, मुनील ग्रामबाग, यूसुफ मेहता, फिरोज खान.  
कलकत्ता से रघु प्रसाद सेन गुप्ता, चेतना जालान, सास्वर,  
दिल्ली से एम.के. रैना, बेरी जान, रोबिन दास, पंकज सक्सेना, सफ़र हाशमी,  
तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र.  
मध्यप्रवेश से प्रभात मांगुली, कमल वशिष्ठ, शशांक मुखर्जी, प्रतिभा मुखर्जी,  
धीरेन्द्र परमार, पापिया दास गुप्त, विमूर्ति मा, एन.जी. बोडस.

### पर्यवेक्षक

शमभित्र, (कलकत्ता), कुमुद मेहता (बंबई), इकबालमसूद जिलानी (बंबई), कमलेश दत्त त्रिपाठी (उज्जैन) राहुल शारपुते (इंदौर), विष्णु चिंचालकर (इंदौर), विमल कुमार (रायपुर), विजय बापट (ग्वालियर), उदय प्रकाश (गोपाल), तेमिचंद्र जैन (दिल्ली).

विनयान

### साहित्य

## कविताओं की गृहस्थी

‘दी हुई दुनिया’ भगवत रावत (जन्म: 1939) का दूसरा कविता संग्रह है. पहला कविता संग्रह ‘समुद्र के बारे में’ 1977 में प्रकाशित हुआ था. भगवत रावत ने अपने नये संग्रह को चार उपशीर्षकों में बांटा है: हवा में उड़ती हुई दुनिया और घरती के बीच, छपे हुए फूल पर झीना कागज रख कर, आसमान सफ़रते की हालत में था और जोड़जाड़ कर जुटी घरेलू दुनिया. कह सकते हैं कि अंतिम उपशीर्षक ही उन की प्रायः सभी कविताओं के अधिक निकट है या कि वह उन की कविताओं की दुनिया को अधिक अच्छी तरह संकेतिक करता है. एक जगह पर कवि-स्वभाव निश्चय ही उस गृहस्थ स्त्री की तरह होता है जो दिन भर अपने कामों में लगी रहती है और कामों के सिलसिले में ही घर के कोनों अंतरों को छान मारती है. दिनचर्या के साथ साथ घर के भीतर-बाहर के प्रकाश और अँधेरे की कई रंगतें देखती है. जिन चीजों पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता उन की ओर ध्यान देती है. यह सूची और लंबी की जा सकती है लेकिन उस लंबा न कर के संक्षेप में यही कहें कि दिनचर्या को बहुत कर के वही बहुतेरे अर्थों में अपने और दिनचर्या के निकट जोती है. और इसी अर्थ में हमने उस से कवि स्वभाव के साम्य की बात की थी. कवि स्वभाव भी चीजों के निकटतर ही रहना चाहता है. भगवत रावत की कविता के संदर्भ में इस निकटता का एक और भी अर्थ है बल्कि चाहें तो कह लें कि एक शाब्दिक अर्थ भी है. उन की अधिकतर कविताएँ न केवल दिनचर्या से जुड़ी हुई कविताएँ हैं बल्कि बहुतेरे अर्थों में गृहस्थी की कविताएँ भी. लेकिन इस का यह अर्थ नहीं कि उन की कविताओं के आशय केवल गृहस्थी तक सीमित हैं. आशय और अर्थ तो हमारे समय को घेरने वाले हैं और इसी अर्थ में उन की कविताएँ आत्मीय भी हैं और अपने में वह जरूरी पीड़ा छिपाये हैं जो आज के किसी भी संवेदनशील आदमी के मन की होगी—अगर वह अपने समय की विडंबनाओं, क्रूरताओं को जानता-महचानता भी हो. उन की एक कविता सुबह होती हुई से एक उदाहरण लें: वह इसी तरह सोयेगी/हर रोज/बेखबर/नींद में डूबी उस की पलकें/बंद रहेंगी और पुतलियाँ/चलती रहेंगी/अंदर ही अंदर/सारा घर बुहारती.

और एक पूरी ही कविता यह है ‘उस की थकान’: ‘कोई लंबी कहानी ही/बयान कर सके शायद/उसकी थकान/जो मुझ से/दो बच्चों की दूरी पर/न जाने कब से/क्या क्या सिलते सिलते/हाथों में/सुई घागा लिए हुए ही/सो गयी है’.

हम समझते हैं कि ऊपर की ये कविताएँ



भगवत रावत

अपने आप में इतनी मुकम्मल हैं कि इन पर अलग से किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है. हाँ, संग्रह की कविताओं को ले कर एक बात हम कहना चाहेंगे कि भगवत रावत की लंबी कविताएँ शब्द, अर्थ और लय की निकटता में ठीक उसी तरह से नहीं जीतीं जैसे कि उन की छोटी कविताएँ, जैसे कि ऊपर की कविता ‘उस की थकान’. लंबी कविताओं में वह जैसे कुछ घीरज खो बैठते हैं और बीच बीच में इस तरह की पंक्तियाँ भी पढ़ने को मिल जाती हैं: ‘उम्र के पहाड़ को किसी न किसी तरह/सब को काटना है/पेट की खाइयों को किसी न किसी तरह/सब को पाटना है.’ (नरक-उधार कविता से).

भगवत रावत की इन कविताओं को पढ़ने का अर्थ फिर उन कुछ अनुभवों के निकट जाना है जो हमें हुए थे और जिन्हें फिर हम ने इन में आत्मीय अर्थों में जाना और पाया. उन की अच्छी कविताएँ फिर यह याद दिलाती हैं कि मनुष्य की हालत पर बयान या वक्तव्य जितना कुछ नहीं कह पाते कविता उस से अधिक कहती है और मानवीय संवेदनाओं को बचाने और विकसित करने का आधार बनती है. ‘चिड़ियों को पता नहीं’ कविता की अंतिम पंक्तियाँ: ‘न सही कविता में/पर हर रोज/पेड़ से उतर कर/घर में/दो चार बार/जरूर आओ जाओ/या जब कभी मैं कविता की पंक्तियाँ: ‘जब कभी मैं पास जा कर/उस से बोड़ी माँग कर पीता हूँ/उस की आँखों में और उजली हो जाती है मेरी कमीज’. और इसी तरह और भी कविताएँ इस सिलसिले में हम यहाँ याद कर सकते हैं. उन के पिछले कविता संग्रह ‘समुद्र के बारे में’ से ले कर ‘दी हुई दुनिया’ तक की कविताओं ने न केवल अपने अनुभव संसार को और प्रगाढ़ किया है, उसे उत्तरोत्तर संवेदनात्मक और संघर्षशील भी बनाया है.—प्र.शु.

दी हुई दुनिया : भगवत रावत; प्रकाशक : प्रकाशन संस्थान, ब्यू-22 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032; पृष्ठ 117; मूल्य 30 रु.



## फिल्म

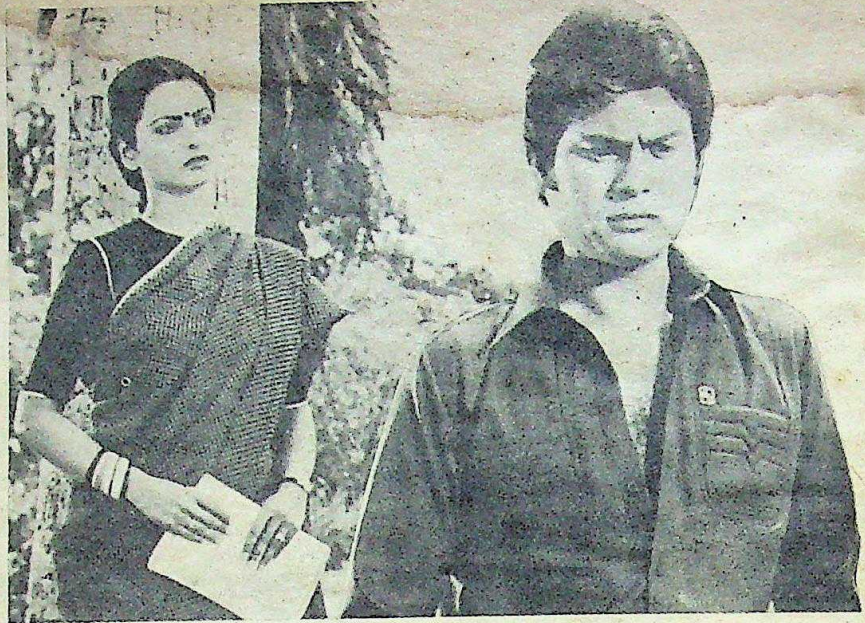
## जीवनहीन 'जीवनधारा'

'बसुन्त' और 'उमराव जान' में रेखा का सशक्त अभिनय देखने के बाद जीवनधारा में उन से काफी हद तक निराशा होती है। अभिनय के नाम पर या तो वह दूसरे सभी पात्रों को हैडमास्टरनी की तरह डाँटती डपटती रहती हैं या आँसुओं से भरी उन की आँखें परदे पर बार बार दिखायी जाती हैं। कर्मयोगिनी नायिका के चरित्र को उभारने के लिए अन्य सब पात्रों को जिस ढंग से जान बूझ कर कमजोर दिखाया गया है उस ने भी पूरी फिल्म को अस्वाभाविकता ही प्रदान की है।

जीवनधारा में रेखा को देखते समय बार बार राखी का 'तपस्या' का सशक्त अभिनय आँखों के सामने आता रहता है। वैसे तो राखी को केंद्र में रख कर पिछले दिनों कई अन्य फिल्में भी बनी हैं। जिन में अपनी अभिनय क्षमता के बल पर वह दर्शक को प्रभावित करती हैं। लेकिन 'तपस्या' से इस फिल्म की तुलना यहाँ इसलिए जरूरी हो गयी है कि दोनों फिल्मों की कहानी का आधार एक ही है—कर्मयोगिनी नायिका। निर्देशक टी. रामाराव ने थोड़ी नाटकीय परिस्थितियों में उसी चरित्र को फिर से प्रस्तुत किया है।

फिल्म की शुरुआत जिस ढंग से होती है लगता है व्यावसायिक सिनेमा पर कलात्मकता कहीं कहीं असर करने लगी है। प्रारंभ में अमोल पालेकर को दिखाया गया है। वह नायिका के घर में 'पेइंगगेस्ट' की हैसियत से रहते हैं। और फिल्म कथा के सूत्रधार का काम करते हैं। इस के अलावा आधी से अधिक फिल्म में नायिका के भय से सहमे सभी पात्रों के साथ साथ दर्शक को हँसाने का काम भी सफलता से संपन्न करते हैं। डा. राही मासूम रजा के संवादों की खूबी भी फिल्म के इसी हिस्से में उमर कर आती है। दर्शकों से सीधे बात करने का जो तरीका इस फिल्म में अपनाया गया है, इस से पूर्व एक दो अन्य हिंदी फिल्मों में भी उसे हम देख चुके हैं। लेकिन केतन मेहता ने अपनी गुजराती फिल्म 'भवनी भवाई' में यह प्रयोग काफी सफलतापूर्वक किया था। इस फिल्म की भी बस यही एक उपलब्धि कही जा सकती है।

कर्मयोगिनी नायिका के इर्द गिर्द चार पुरुष हैं। एक तो, सूत्रधार—जिन से आप का परिचय हो चुका है। दूसरा पात्र अशोक है—नायिका का शराबी, आवारा, काम-चोर भाई। जिस के पत्नी, बच्चों की परवरिश का दायित्व भी नायिका ही उठा रही है। इन के अतिरिक्त नायिका का प्रेमी और उस की फर्म का मैनेजिंग डाइरेक्टर शराबी भाई, जिस की भूमिका राज बब्बर ने बखूबी निभायी



रेखा और कंवलजीत सिंह : नायिका के आदेश की प्रतीक्षा

है, के अतिरिक्त अन्य सभी जिस ढंग से नायिका के हाथों कठपुतली बने रहते हैं, लगता है उन का अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। इसीलिए केवल उन कुछ दृश्यों को छोड़ कर जिन में नायिका और उस के शराबी भाई के बीच टकराव की स्थिति होती है, अन्य सभी दृश्य बेहद नाटकीय हो गये हैं। नायिका का अमीर प्रेमी, जो अपनी कार रोज बस स्टॉप के सामने छोड़ कर बस में उस के साथ लटक कर यात्रा करने में सुखद अनुभूति महसूस करता है, उस के एक बार कहने से ही उस की विधवा बहन से विवाह कर लेता है। कहीं कोई विरोध नहीं! जैसे वही एक मात्र रास्ता रह गया हो। इस से हास्यास्पद विधवा बहन का व्यवहार दिखाया गया है जो अपनी बहन के प्रेमी को देखते ही उस से प्रेम करने लगती है। जब कि फिल्म के पहले दृश्य से ही दर्शक को यह बात मालूम हो जाती है कि सूत्रधार महोदय नायिका की

बहन से प्रेम करते हैं। नायिका के चरित्र को उभारने के लिए एक आधुनिका सहेली भी है। अंत में जिस का विवाह नायिका मानसिक रूप से टूटे हुए सूत्रधार से करवा देती है। और अंतिम दृश्य में नायिका के विवाह के दिन उस के भाई (जो अब सुधर गया है) की अचानक गुंडों द्वारा हत्या का प्रसंग तो कतई उबा देने वाली स्थिति में पहुँचा देता है।

एक या दो पात्रों की अस्वाभाविकता को परिस्थिति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे नायिका का पिता घर की जिम्मेदारी से भाग कर संन्यासी हो गया है। भाई पिता का अंकुश न होने की वजह से आवारा हो गया जैसा कि फिल्म में बार बार भाई के मुँह से कहलवाया गया है। लेकिन एक कर्मयोगी पात्र की कल्पना करते समय क्या जरूरी है कि उस के आसपास आवारा, अपंग या कमजोर लोगों की जमात ही खड़ी कर दी जाये। —सु.

## राष्ट्रपति का अपहरण

'द किडनैपिंग ऑफ द प्रेसीडेंट' से पूर्व भी अमेरिकी राष्ट्रपति को 1967 में 'द प्रेसीडेंट्स एनालिस्ट' और 1976 में 'ऑल द प्रेसीडेंट्स मैन' फिल्मों का मुख्य पात्र बनाया जा चुका है। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्टून, नाटकों, उपन्यासों का विषय अक्सर बनाया ही जाता रहा है।

इस फिल्म में एक मार्क्सवादी आतंकवादी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के अपहरण की योजना और उसे दिये गये कार्यरूप को बारीकी से दिखाया गया है। अपहरणकर्ता एक पत्रकार के वेश में राष्ट्रपति का अपहरण करता है। फिरोती के रूप में 10 करोड़ डालर के हीरे और ब्राह्मर निकलने के लिए सुरक्षित व्यवस्था की माँग करता है। अपनी जैकेट पर डाइनामाइट की 20 नलियाँ लपेट कर भौड़ भरे चौराहे पर विश्व के सब से शक्तिशाली पुरुष को हथकड़ी लगा कर सारी सुरक्षा व्यवस्था को आश्चर्य में डाल देता है। राष्ट्रपति उसी चौराहे पर बैक की डाइनामाइट लगी गाड़ी में कैद हैं लेकिन अपहरणकर्ता के अलावा कोई उसे खोलने का तरीका नहीं जानता। उस गाड़ी में राष्ट्रपति के 9 घंटे की कैद के दौरान एक ओर सारी सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी ओर राजनीति जिस ढंग से अपना काम करती है, वह देखना स्वयं में एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ तक कि फिल्म के हर तनाव और क्षण को दर्शक उस चौराहे पर, जहाँ राष्ट्रपति गाड़ी में अपहृत हैं, खड़ी भीड़ की तरह उसके साथ-साथ जीता है।



## संस्कृति समाचार



पत्रकार और समाज पर गोष्ठी

## स्मृति

स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना कार्य क्षेत्र उत्तरप्रदेश बनाने के पहले गुना जिले की घरती मुगावली में जहाँ संस्कारों को संवारा, उसी कस्बायी बस्ती ने उन का शहादत दिवस 25 मार्च '82 को मनाया। गणेश शंकर विद्यार्थी शताब्दी 1990 में किस रूप में मनायी जाये, उन का स्थायी स्मारक, संग्रहालय-शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया जाये यह प्रस्ताव आधी अधूरी बहस के बाद रख छोड़ा गया। यह अवश्य महसूस किया गया कि मध्यप्रदेश, भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी पत्रकारों की शौर्य-गाथाएँ संग्रहालय में सुरक्षित हों। स्मृति समारोह में प्रदेश के मूर्धन्य आंचलिक पत्रकारों और राजनेताओं ने भाग लिया और आंचलिक देहाती जनता का भारी सैलाव उमड़ा। 'पत्रकार और समाज' विषय पर रोचक बहस हुई। पत्रकार किस तरह समाज के पार्श्व में रह कर एक समुन्नत समाज की कल्पना करता है, विषमताओं को उधेड़ता है और समाज की न्यायिक संघर्ष को गति देता हुआ व्यवस्था और राजनेताओं को निरंकुश होने से बचाने का जोखिम ओढ़ता है।

मध्यप्रदेश की साहसिक पत्रकारिता भी बहस से ओझल नहीं हुई। श्री लज्जाशंकर हरदोनिया ने स्पेन और चिले का उदाहरण ले कहा—गणेश शंकर विद्यार्थी का पैगाम भी जातीयता का विष वमन करने वालों को बेनकाब करना था और ऐसा करने में ही वे सांप्रदायिक वहशी व्यक्ति के छुरे का शिकार हुए। पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' ने राज्याश्रय की लालसा की ढीका करते हुए पत्रकारों को विद्यार्थी जी की सादगी, जुझारूपन और देश के प्रति आसक्ति की भावना सशक्त करने को कहा। उन्होंने बताया सरदार भगत सिंह भी 'प्रताप' के सहायक संपादक थे। महा-विद्यालयीन शिक्षा राज्यमंत्री श्री मोती लाल जोशी का कहना था कि स्वस्थ पत्रकारिता के

विकास की अच्छी गुंजाइश है। सुविधाभोग की गौण कर जनसमस्याओं को मुखर करना समय की अपेक्षा है। पत्रकारिता का लक्ष्य समाज, खास कर सर्वहारा वर्ग की खुशहाली होना चाहिए। श्री विजयदत्त श्रीधर, श्री कुंदन-लाल वरया, श्री आनंद पालीवाल, श्रीरामनाथ शुक्ल तथा प्रदेश के युवा पत्रकारों ने शहादत दिवस परिचर्चा में भाग लिया तथा पत्रकारों के लिए गठित कल्याण कोष की स्थापना के लिए आंचलिक पत्रकार संघ के प्रयासों को शुभ लक्षण बताया। समापन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के साथ हुआ।—भरत चंद्र नायक

## नुकड़ नाटक

आगरा का 'रंगकर्म', प्रकाश श्रीवास्तव कृत नाटक 'कामधेनु' की निरंतर नुकड़ प्रस्तुतियाँ अनिल शुक्ला के निर्देशन में कर रहा है। नाटक की पटकथा वर्तमान राजनीति से पल्टूराम जैसे निकम्मे नेताओं का घनासेठों के हाथों में खेल कर आम जनता के ऊपर जुलम ढाना और फिर अपनी सत्ता में इस तरह मत्त हो जाना कि घनासेठ, जिन्होंने उसे बनाया था, उन्हीं को मूल बैठना और फिर असंतुष्ट घनासेठों के द्वारा पल्टूराम जैसे दूसरे नेताओं को गद्दी पर बैठाना और उतारना है। नाटक के अंत में जनता द्वारा पुर्जे को बदलने की इच्छा शक्ति को चुनौती देते हुए पूरी व्यवस्था के ढाँचे को बदलने की कामना की गयी है।

अभिनय करने वाले मुख्य पात्रों में पल्टूराम (प्रकाश), सिपाही (रमेश गुरुवानी), सेठ (राजेंद्र सार्थी) ने बढ़िया अभिनय किया। अन्य पात्रों में मनीषा शुक्ला, अभिनय प्रसाद, ललित, कुलश्रेष्ठ आदि ने भी अपने छोटे-छोटे किंतु भावपूर्ण अभिनयों के जरिये आम जनता को खूब प्रभावित किया।—दयाकृष्ण जोशी

## सड़क पर कामधेनु



## नृत्य नाट्य

ग्वालियर में विगत दिनों संपन्न चार विदसीय 'बैले महोत्सव' में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप ने तीन नृत्य नाटिकाएँ 'चतुर बंदर', 'मधुशाला' तथा 'पशुतंत्र' का प्रदर्शन किया। चतुर बंदर बिल्कुल नयी प्रस्तुति थी। सभी नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन प्रभात गांगुली का था।

'चतुर बंदर' पंचतंत्र की प्रसिद्ध 'बंदर तथा मगर' की कहानी पर आधारित है जिस में नये प्रयोगों, कल्पनाशीलता तथा देह छंदों



## 'चतुर बंदर' का एक दृश्य

का अच्छा उपयोग किया गया। यह नृत्य नाट्य एक अजीब व्यवस्था रचना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। हिरनों की छलांगें, तितलियों का मँडराना, बगुलों के लंबे हाथों का आसमान पर तैरना, खरगोशों की उछल-कूद, शेर की चौकस आँखें तथा हाथी का मस्त झूमना कल्पनाशील संयोजन को उद्घाटित करने के साथ ही बैले की उत्कृष्टता की ओर पहुँचाता था। कुछ भावुक दृश्य भी बांधे गये हैं।

नाटिका में देह और लय के गीत, तालों में गुंफित होते हुए उत्तरोत्तर नये धरातल को छूते हैं। ये सारी गतिविधियाँ जंगल व्यवस्था को आज की व्यवस्था से जोड़ती हैं। अधिकांश दृश्य कथ्य से अलग होते हुए भी जुड़े हुए लगते हैं।

रानु वर्धन के संगीत की लयकारी चमत्कृत करती है। जंगल की चपलता तेज और मधुर प्राकृतिक आवाज बड़ी कुशलता से संयोजित किये गये थे। प्राचीन नाट्य परंपराओं की भी 'बैले' में बड़ी कलात्मकता से निर्देशक ने पिरोया है।

—प्रभातरंजन उपाध्याय





अकबर अहमद

1960 में दून स्कूल से निकलने के बाद संजय गांधी से अकबर की मुलाकात हुई तो संजय की तूफानी राजनीति का अभी अभी जन्म हो रहा था। शहरयात्र अमिताभ बच्चन तथा अकबर के साथ दोस्ती तब की थी जब संजय केवल एक रईस जादा ही था। संजय गांधी की शादी हुई तो उस में शामिल होने वाले थोड़े से अंतरंग मित्रों में अकबर अहमद भी था। तब शायद पहली बार वह 1-सफदरजंग रोड आया और बरसों तक उस परिवार के निकटतम मित्रों में गिना जाने लगा। मगर तभी तक जब तक कि संजय गांधी जिंदा थे।

“फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे लिए उस घर का व्यवहार एकदम बदल गया। मैडम मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी मगर अचानक मुझे पता चला कि मैं एक अवांछित व्यक्ति हो गया हूँ। यह कैसे हुआ, इस का जवाब मेरे पास नहीं है। फोतेदार से पूछिए भाई साहब, मखनलाल फोतेदार प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने ‘मैडम’ को मेरे विरुद्ध कर दिया। मेरा दोष यही है न कि मैं संजय जी का बफादार था और अब भी हूँ।”

अकबर अहमद को इस बात पर आश्चर्य है कि जिन लोगों को संजय ने गद्दी वापस दिलायी वे ही उस के नाम से डर रहे हैं। शायद यह डर मेनका गांधी से हो। “मगर मेनका जी से इतना परहेज क्यों? इस पडयंत्र की गहराई तो मैं नहीं समझ पाया हूँ कि संजय जी की मृत्यु के तुरंत बाद से उन के समर्थकों को घकेलने का कार्यक्रम क्यों अपनाया गया। कुछ मित्रों के सम्मेलन के प्रति सरकार

ने ऐसी मोर्चाबंदी की है कि जैसे कोई हमला होने वाला हो।”

इस लिए कि आप बहुत दिनों से मुख्यमंत्री के लिए परेशानी पैदा करते रहे हैं।

‘बहुत दिनों से?’ भाई साहब सब से पहला कारण बताओ नोटिस तो मुझे पिछले वर्ष अगस्त में मिला था। संजय के साथियों के प्रति बुरा सलूक और डंपी को नोटिस, ये सब बातें संजय की मौत के कुछ महीनों के भीतर ही हुई, पहले नहीं। बहुत दिनों की बात नहीं है। बुरे दिनों की बात है।

आजमगढ़ के ताल्लुकेदार परिवार में जन्मे अकबर अहमद के पिता इस्लाम अहमद उ. प्र. के पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं। घर में अकबर और उन के बड़े भाई को बचपन में हम्पटी डम्पटी कहते थे। मालूम नहीं कब डम्पटी डंपी रह गया। छोटी सी दाढ़ी (परंपरागत खत में) के साथ अविवाहित, चार्टर्ड एकाउंटेंट, जमींदार डम्पी खूबसूरत नौजवानों में गिना जा सकता है। उन के कम उम्र दोस्त उन्हें ‘भाई साहब’ कहते हैं और ‘भाई साहब’ उन का अपना तफियाकलाम भी है। राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर उन के पाँव अभी अस्थिरता से पड़ रहे हैं। बातों में विरोधाभास है। ‘मैडम’ को सर्वोच्च नेता मानने के बावजूद वह इस बात से बेखबर बनने की कोशिश करते हैं कि मेनका गांधी को इंदिरा जी के मुकाबले खड़ा करना इंदिरा भक्ति तो नहीं कहला सकता। “मुझे नहीं मालूम कि मैडम और मेनका जी में कोई गंभीर मतभेद रहे हैं।” फिर भी ‘भाई साहब’ आप तो जानते ही हैं (हालांकि मैं नहीं जानता था) कि सूर्या को पैसे पैसे का मोहताज बनाने के लिए कोई कोरकसर नहीं रखी गयी। तो बताइए कैसे रहती जिंदा वह पत्रिका?

यह विरोधाभास शायद इस लिए है कि अभी अकबर और मेनका ने इंदिरा गांधी से अलगाव का निर्णायक कदम नहीं उठाया। शायद तैयारी पूरी नहीं। फिलहाल उन के एक उत्साही समर्थक के अनुसार डम्पी को ‘डम्प’ करना इतना आसान नहीं है। —ज.



रान थामसन

मांडलिन, गिटार, बैजो के कुशल वादक और अमेरिका के लोक गायक रान थामसन जो “ड्राई ब्रांच फायर स्क्वाड” की पाँच सदस्यीय लोक गायक मंडली के साथ राजधानी के दर्शकों को अपने गायन वादन से ही नहीं अपने मजाकिया खुले स्वभाव से भी प्रस्तुति के दौरान प्रभावित कर गये कहते हैं कि भारतीय लोक संगीत उन्होंने “सुना है और बहुत अच्छा लगता है। संसार के सभी देशों के लोक संगीत की आत्मा एक है, वही तो हमें एक करता है। आप के यहाँ लोक संगीत विभिन्न बोलियों में बँटा हुआ है। अमेरिका में ऐसा

नहीं है। भाषा एक है उस में फर्क नहीं है हाँ बोलने-गाने के ढंग (एक्सेंट) में फर्क हो जाता है। थामसन को दो हजार से अधिक लोक गीत याद हैं। ये परंपरागत पुराने लोकगीत हैं—‘पहाड़ों जितने पुराने’ जो पूर्वी अमेरिका के पर्वत प्रदेशों में गाये जाते हैं। पुरानी लोक धुनों पर “मैं ने कुछ नये गाने भी रचे हैं जिन्हें गाता हूँ। अभी कुछ वर्ष पहले मैं नदी के किनारे घूम रहा था। वह वर्जीनिया की नदी थी—ड्राई ब्रांच रिवर—वस वहीं से मंडली का नाम ‘ड्राई ब्रांच’ मिल गया। ‘स्क्वाड’ तो है ही, ‘फायर’ जोड़ दिया।”

लोक गायकों की सरलता, गायन वादन कौशल, हँसने हँसाने की क्षमता और गाते बजते समय पूरी तरह मजा लेते हुए मंच पर होना उन की प्रस्तुति कला को निखारता है जहाँ वह व्यंग्य, चुटकुलेबाजी सब करते हैं किसी को नहीं वशते। न अपनी साथी गायक वादकों को न अमेरिकी समाज को—“मैं अमेरिका से आया जरूर हूँ पर कैलीफोर्निया को ही जानता हूँ जिसे समुद्र में ढकेल दिया है।” —स.

## फ्रेड फ्रेस

पाँचवीं त्रैवाषिकी —भारत के अवसर पर जो विदेशी कलाकार समीक्षक दिल्ली आये थे, उन्हीं में एक मिलनसार, हंसमुख बातचीत के लिए तत्पर आस्ट्रेलियाई चित्रकार फ्रेड फ्रेस भी थे। भारत से उन का जन्म का संबंध है। और अपना बचपन भी उन्होंने भारत में बिताया। पूना में 1938 में जन्मे फ्रेड फ्रेस 1948 में ब्रिटेन चले गये थे। 1962 में वह आस्ट्रेलिया गये और आज वहाँ के प्रमुख



चित्रकारों में गिने जाते हैं। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित कर चुके हैं और कई समूह प्रदर्शनियों में भी उनके काम प्रदर्शित हुए हैं। त्रैवाषिकी में फ्रेड फ्रेस को विशेष अनुशंसा का सम्मान भी मिला। फ्रेस उन अमूर्त चित्रकारों में लगते हैं, जिन्होंने अमूर्त को किसी ‘आसान रास्ते’ के लिए नहीं अपनाया। कैनवास पर बरस पड़े से रंग उन के यहाँ आकस्मिक न हो कर एक रचनात्मक विचार प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। कई लोगों को दिल्ली की ठंड में शाल लपेटे देख कर उन्होंने कई बार कहा: ‘मैं भी इसे अपनाता चाहता हूँ। यह गरम भी है और कितना खुला खुला भी। और यह भी कितना अच्छा है मानों हममें कोई प्रिय रंग लपेट रखा हो।’ —प्र.



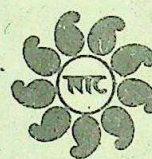
१६. अप्रैल से  
प्रधानीयत



# बढ़िया कपड़े, सस्ते दाम फैशन की दुनिया में मशहूर नाम एन. टी. सी.



112 मिलों से  
बनाये गये विभिन्न  
प्रकार के कम  
कीमत वाले बढ़िया  
कपड़े



नेशनल  
टेक्सटाईल  
कॉर्पोरेशन  
लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

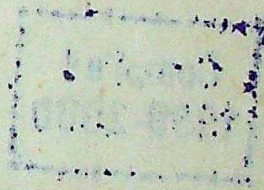
रजिस्टर्ड ऑफिस:

8 वीं मंजिल, सूर्य किरण,  
19, कस्तूरबा गाँधी मार्ग,  
नई दिल्ली-110 001

एन. टी. सी.-

राष्ट्र के वस्त्रप्रदाता







Completed  
1999-2000







